आर्थिक समीक्षा

सत्यमेव जयते
Government of India

2023-24

सत्यमेव जयते

आर्थिक समीक्षा
2023-24

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
आर्थिक प्रभाग
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली–110001
जुलाई, 2024

विषय सूची

	vii	*प्रस्तावना*
	xiii	*आभारोक्ति*
	xv	*संकेताक्षर*
	xxxiii	*तालिकाओं की सूची*
	xxxv	*चार्टों की सूची*
	xliii	*बॉक्स की सूची*
अध्याय सं.	**पृष्ठ सं.**	**अध्याय का नाम**
1		**अर्थव्यवस्था की स्थिति: निरंतर आगे बढ़ते हुए**
	1	वैश्विक आर्थिक परिदृश्य
	8	एक लचीली घरेलू अर्थव्यवस्था
	15	वृहद आर्थिक स्थिरता विकास सुरक्षा
	29	समावेशी विकास
	31	परिप्रेक्ष्य
2		**मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता: स्थिरता ही मूलमंत्र**
	33	परिचय
	34	मौद्रिक विकास
	38	वित्तीय मध्यस्थता
	38	बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन और ऋण उपलब्धता
	56	भारतीय पूंजी बाजार में रुझान
	66	बीमा क्षेत्र में विकास
	69	पेंशन क्षेत्र में विकास
	74	मूल्यांकन और दृष्टिकोण
3		**कीमतें और मुद्रास्फीति - नियंत्रण में**
	75	परिचय
	77	घरेलू खुदरा मुद्रास्फीति
	79	महामारी के बाद की दुनिया में कोर मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव
	83	खाद्य मुद्रास्फीति
	87	खुदरा मुद्रास्फीति में अंतरराज्यीय अंतर
	88	दृष्टिकोण और समाधान
	91	अनुलग्नक 1
4		**बाह्य क्षेत्र: समृद्धि के बीच स्थिरता**
	93	प्रस्तावना
	94	वैश्विक व्यापार की गतिशीलता में बदलाव
	96	भारत का व्यापार: वैश्विक उथल-पुथल के बीच लचीलापन
	120	अनुकूल चालू खाता शेष
	125	पूंजीगत खाता शेष
	136	अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति

137 स्थिर विदेशी ऋण की स्थिति
138 संभावनाएं और चुनौतियां

5 **मध्यम अवधि परिदृश्य : नए भारत के लिए विकास दृष्टि**
141 सन्दर्भ निर्धारित करना
144 अल्प से मध्यम अवधि में नीतिगत फोकस के प्रमुख क्षेत्र
151 अमृत काल के लिए विकास रणनीति
162 मध्यम अवधि में संभावना

6 **जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण: समझौताकारी सामंजस्य**
165 परिचय
169 भारत की जलवायु कार्रवाई की वर्तमान स्थिति
170 भारत के लिए अनुकूलन महत्वपूर्ण है
173 निम्न कार्बन विकास और ऊर्जा संरचना
186 कार्बन की कीमत तय करने के लिए बाजार : भारतीय कार्बन बाजार
189 जलवायु वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ : घटनाक्रम
191 जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के समाधान के लिए भारत की अंतरराष्ट्रीय पहल
193 निष्कर्ष

7 **सामाजिक क्षेत्र: कल्याण जो सशक्त करे**
195 परिचय
197 विकास को सशक्त कल्याण के साथ जोड़ना
232 महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण
239 ग्रामीण अर्थव्यवस्था: विकास इंजन को गति देना
249 ग्रामीण शासन: जमीनी स्तर पर डिजिटल परिवर्तन की कहानी
253 निष्कर्ष और आगे का मार्ग

8 **रोजगार और कौशल विकास: गुणवत्ता की ओर**
255 परिचय
256 वर्तमान रोजगार परिदृश्य
259 युवा और महिला रोजगार
272 भारत में नौकरियों का विकसित परिदृश्य
279 2036 तक रोजगार सृजन की आवश्यकता
290 कौशल निर्माण में विकास और प्रगति
297 निष्कर्ष और आगे की राह

9 **कृषि और खाद्य प्रबंधन : यदि हम सही कर लें तो कृषि में बढ़ोत्तरी अवश्य है**
299 परिचय
301 कृषि उत्पादन: प्रदर्शन और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना
315 संबद्ध क्षेत्र: पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन महत्वपूर्ण विकास उत्प्रेरक हैं
318 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र (एफपीआई): प्रसंस्करण क्षमता
320 खाद्य प्रबंधन: खाद्य सुरक्षा के लिए सामाजिक जाल
321 निष्कर्ष

10 **उद्योग: मध्यम एवं लघु दोनों अपरिहार्य**

323 परिचय

326 प्रमुख क्षेत्रों का प्रदर्शन और संबंधित मुद्दे

338 क्रॉस-कटिंग थीम

347 निष्कर्ष एवं दृष्टिकोण

11 **सेवाएँ: विकास के अवसरों को बढ़ावा देना**

349 परिचय

350 सेवा क्षेत्र के निष्पादन का अवलोकन

355 सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के लिए वित्तपोषण स्रोत

356 प्रमुख सेवाएँ: क्षेत्रवार निष्पादन

375 चुनौतियाँ और अवसर

376 निष्कर्ष और भावी परिदृश्य

12 **अवसंरचना: संभावित विकास को प्रोत्साहन**

379 परिचय

380 अवसंरचना वित्तपोषण: सार्वजनिक व्यय को बढ़ावा देना

384 अवसंरचना क्षेत्रों में विकास

414 चुनौतियाँ और अवसर

416 सुविधा प्रदान करना और बाधाओं को दूर करना

419 निष्कर्ष और दृष्टिकोण

13 **जलवायु परिवर्तन और भारत: हमें इस समस्या को अपने नजरिए से क्यों देखना चाहिए**

421 परिचय

423 वर्तमान दृष्टिकोण दोषपूर्ण क्यों है?

433 पश्चिमी पद्धतियों को अपनाने से विकासशील दुनिया पर नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा

439 भारतीय पद्धति: एक संधारणीय जीवनशैली

445 निष्कर्ष

प्रस्तावनाः समझौतों और आम सहमति के माध्यम से देश का संचालन

अर्थव्यवस्था का विस्तार जारी है

अप्रैल में हमने नया वित्त वर्ष शुरू किया। मई में हमें पता चला कि वित्त वर्ष 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर 8.2% रहने का अनुमान है। जून में नई सरकार ने कार्यभार संभाला है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार तीसरे कार्यकाल के लिए ऐतिहासिक जनादेश के साथ सत्ता में लौटी है। उनका अभूतपूर्व तीसरा लोकप्रिय जनादेश राजनीतिक और नीतिगत निरंतरता का संकेत देता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर स्थिति में है, जो भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन प्रदर्शित करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने नीति निर्माताओं - राजकोषीय और मौद्रिक - दोनों के साथ आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ कोविड के बाद की रिकवरी को मजबूत किया है। फिर भी, उच्च विकास आकांक्षाओं वाले देश के लिए परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है। सुधार को कायम रखने के लिए घरेलू मोर्चे पर कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि व्यापार, निवेश और जलवायु जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर सहमति बनाना असाधारण रूप से कठिन हो गया है।

वित्त वर्ष 24 में उच्च आर्थिक वृद्धि पिछले दो वित्तीय वर्षों में क्रमशः 9.7% और 7.0% की वृद्धि दर के बाद आई है। मुख्य मुद्रास्फीति दर काफी हद तक नियंत्रण में है, हालांकि कुछ विशिष्ट खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति दर बढ़ी हुई है। वित्त वर्ष 24 में व्यापार घाटा वित्त वर्ष 23 की तुलना में कम था, तथा वर्ष के लिए चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.7% है। वस्तुतः, चालू खाते में वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में अधिशेष दर्ज किया गया। विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त है। सार्वजनिक निवेश ने पिछले कई वर्षों में पूंजी निर्माण को बनाए रखा है, जबकि निजी क्षेत्र ने अपनी बैलेंस शीट की गिरावट को दूर किया है और वित्त वर्ष 22 में निवेश करना शुरू कर दिया है। अब, इसे सार्वजनिक क्षेत्र से कमान लेनी होगी और अर्थव्यवस्था में निवेश की गति को बनाए रखना होगा। संकेत उत्साहवर्धक हैं।

राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से पता चलता है कि गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र के पूंजी निर्माण, जिसे वर्तमान मूल्यों में मापा जाता है, में वित्त वर्ष 21 में गिरावट के बाद वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 23 में जोरदार वृद्धि हुई। तथापि, विशेष रूप से, मशीनरी और उपकरणों में निवेश में लगातार दो वर्षों, वित्त वर्ष 20 और वित्त वर्ष 21 में गिरावट आई, तथा उसके बाद इसमें जोरदार उछाल आया। वित्त वर्ष 24 के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि निजी क्षेत्र में पूंजी निर्माण का विस्तार जारी रहा, लेकिन धीमी दर से।

विदेशी निवेशकों की रुचि बनाए रखने के लिए प्रयास की आवश्यकता होगी

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विश्लेषण का बड़ा विषय है, किंतु रुका हुआ है। भारत के भुगतान संतुलन पर भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि नई पूंजी के डॉलर अंतर्वाह के संदर्भ में मापी गई बाहरी निवेशकों की निवेश रुचि वित्त वर्ष 2024 में 45.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि वित्त वर्ष 23 में यह 47.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। यह मामूली गिरावट वैश्विक रुझान के अनुरूप है। आय का पुनर्निवेश वही रहा है । वित्त वर्ष 23 में विदेशी निवेश का प्रत्यावर्तन 29.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष 24 में 44५5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कई निजी इक्विटी निवेशकों ने भारत में तेजी से बढ़ते इक्विटी बाजारों का लाभ उठाया और लाभ कमाते हुए बाहर निकल गए। यह एक स्वस्थ बाजार परिवेश का संकेत है जो निवेशकों को लाभदायक निकास प्रदान करता है, जिससे आने वाले वर्षों में नए निवेश आएंगे। जैसा कि कहा गया है, आने वाले वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए माहौल कई कारणों से बहुत अनुकूल नहीं है।

विकसित देशों में ब्याज दरें कोविड के वर्षों के दौरान और उससे पहले की तुलना में बहुत अधिक हैं। इसका अर्थ न केवल वित्तपोषण की उच्च लागत है, बल्कि विदेश में निवेश करने के अवसर की लागत भी अधिक होती है। दूसरा, उभरती अर्थव्यवस्थाओं को विकसित अर्थव्यवस्थाओं की सक्रिय औद्योगिक नीतियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जिसमें घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करने वाली पर्याप्त सब्सिडी शामिल होगी। तीसरा, पिछले दशक में की गई प्रभावशाली प्रगति के होने के बावजूद, अंतरण मूल्य निर्धारण, करों, आयात शुल्कों और गैर-कर नीतियों से संबंधित अनिश्चितताओं और व्याख्याओं का समाधान किया जाना अभी भी बाकी है। अंत में, भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं, जो बढ़ रही हैं, भारत में निवेश को प्राथमिकता देने के अन्य कारणों के बावजूद, पूंजी प्रवाह पर अधिक प्रभाव डालेंगी।

रोजगार पर संरचनात्मक ताकतों का नहीं बल्कि झटकों का असर पड़ा है

रोजगार सृजन के संबंध में, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शहरी रोजगार संकेतकों पर त्रैमासिक और ग्रामीण भारत सहित पूरे देश के लिए वार्षिक आंकड़े उपलब्ध कराता है। कृषि रोजगार में वृद्धि ग्रामीण भारत में रिवर्स माइग्रेशन (महानगरों और शहरों से गाँव एवं कस्बों की ओर होने वाले पलायन से है) और श्रम बल में महिलाओं के प्रवेश द्वारा आंशिक रूप से समझाई गई है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में लगभग 2५0 लाख भारतीय कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के आंकड़े उपलब्ध हैं। 2013-14 और 2021-22 के बीच फैक्ट्री

कुल संख्या में सालाना 3ण6% की वृद्धि हुई। कुछ अधिक संतोषजनक बात यह रही कि छोटी फैक्टरियों (सौ से कम श्रमिकों को रोजगार देने वाली फैक्टरी) की तुलना में बड़ी फैक्टरियों (सौ से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली फैक्टरी) में रोजगार में 4ण0% की तेजी से वृद्धि हुई। छोटे कारखानों में वार्षिक वृद्धि दर 1ण2% थी। इस अवधि में भारतीय कारखानों में रोजगार की कुल संख्या 1ण04 करोड़ से बढ़कर 1ण36 करोड़ हो गई है। भारत में अभी तक सेवाओं से संबंधित कोई वार्षिक सर्वेक्षण नहीं किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों - कृषि, विनिर्माण और सेवाओं सहित उद्योग - में वार्षिक अंतराल पर भी सृजित (औपचारिक और अनौपचारिक) नौकरियों की पूर्ण संख्या पर समय पर आंकड़ों की उपलब्धता का अभाव, उच्च आवृत्तियों की तो बात ही छोड़िए, देश में श्रम बाजार की स्थिति के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण को रोकता है।

2022-23 के लिए असमाविष्ट उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण की तुलना जब 'भारत में असमाविष्ट गैर-कृषि उद्यमों (सन्निर्माण को छोड़कर) के प्रमुख संकेतकों' के एनएसएस 73वें दौर के परिणामों से की जाती है, तो पता चलता है कि इन उद्यमों में कुल रोजगार 2015-16 में 11ण1 करोड़ से घटकर 10ण96 करोड़ हो गया। विनिर्माण क्षेत्र में 54 लाख श्रमिकों की कमी आई, लेकिन व्यापार और सेवाओं में कार्यबल के विस्तार से नौकरियों में वृद्धि हुई, जिससे इन दो अवधियों के बीच असमाविष्ट उद्यमों में श्रमिकों की संख्या में कुल कमी लगभग 16ण45 लाख तक सीमित हो गई। यह तुलना विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों में आये बड़े उछाल को छुपाती है जो 2021-22(अप्रैल 2021- मार्च 2022) और 2022-23 (अक्तूबर 2022-सितम्बर 2023) के बीच हुई प्रतीत होती है।

भारत को शीघ्रता से दो बड़े आर्थिक झटके लगे हैं। बैंकिंग प्रणाली में अशोध्य ऋण और उच्च कॉर्पोरेट ऋणग्रस्तता इनमें से एक थे। इसे नियंत्रण में लाने में वर्तमान सरकार के पहले कार्यकाल से अधिक का समय लग गया। कोविड महामारी दूसरा झटका था और पहले झटके के तुरंत बाद ऐसा घटित हुआ। इसलिए, यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रोजगार सृजन की क्षमता संरचनात्मक रूप से कमजोर है। फिर भी, आगे बढ़ते हुए, यह कार्य कठिन है।

जनवरी 2023 में प्रकाशित पिछले आर्थिक सर्वेक्षण और इस सर्वेक्षण के बीच भू-राजनीतिक परिवेश में बड़े बदलाव हो रहे हैं। 2047 में विकसित भारत की ओर भारत के कदम बढ़ाने की वैश्विक पृष्ठभूमि, 1980 से 2015 के बीच चीन के उदय के दौरान की पृष्ठभूमि से अधिक भिन्न नहीं हो सकती। तब, वैश्वीकरण अपने लम्बे विस्तार के शिखर पर था। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भू-राजनीति काफी हद तक शांत हो गई थी, तथा पश्चिमी शक्तियों ने चीन के उदय और विश्व अर्थव्यवस्था में उसके एकीकरण का स्वागत किया तथा उसे प्रोत्साहित भी किया। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंताएं तब इतनी व्यापक या गंभीर नहीं थीं जितनी कि अब हैं। चौथा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन से सभी कौशल स्तरों - निम्न, अर्ध और उच्च - के श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अनिश्चितता की एक बड़ी छाया उत्पन्न हो गई है। ये आने वाले वर्षों और दशकों में भारत के लिए सतत उच्च विकास दर के मार्ग में बाधाएं और रुकावटें पैदा करेंगे। इन पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र के बीच एक महागठबंधन की आवश्यकता है।

रोजगार सृजन निजी क्षेत्र के लिए वास्तविक लक्ष्य है

यह बात दोहराना उचित होगा कि रोजगार सृजन मुख्यतः निजी क्षेत्र में होता है। दूसरा, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कई (सभी नहीं) मुद्दे तथा उनमें की जाने वाली कार्रवाई राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो, भारतीयों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने तथा 2047 तक विकसित भारत की यात्रा पूरी करने के लिए भारत को त्रिपक्षीय समझौते की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है।

एक से अधिक मामलों में, कार्रवाई निजी क्षेत्र के हाथ में है। वित्तीय कार्य-निष्पादन के संदर्भ में कॉर्पोरेट क्षेत्र का प्रदर्शन इतना अच्छा कभी नहीं रहा। 33,000 से अधिक कंपनियों के नमूने के परिणाम बताते हैं कि वित्त वर्ष 20 और वित्त वर्ष 23 के बीच के तीन वर्षों में भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र का कर-पूर्व लाभ लगभग चार गुना हो गया। इसके अलावा, अखबारों की सुर्खियों ने हमें बताया कि कॉर्पोरेट मुनाफे और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात वित्त वर्ष 24 में 15 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया। बिजनेसलाइन ने बताया, "निफ्टी-500 यूनिवर्स के लिए कॉर्पोरेट लाभ पिछले वित्त वर्ष में 30 प्रतिशत बढ़कर ₹14ण11 लाख करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 23 में ₹10ण88 लाख करोड़ था। नोमिनल जीडीपी साल-दर-साल 9ण6 प्रतिशत बढ़कर ₹295 लाख करोड़ (₹269 लाख करोड़ से)[1]" हो गई। नियुक्ति और मुआवजे में वृद्धि शायद ही इसके साथ हो। लेकिन, काम पर रखना और श्रमिक मुआवजे में वृद्धि करना कंपनियों के हित में है।

केंद्र सरकार ने पूंजी निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए सितंबर 2019 में करों में कटौती की। क्या कॉर्पोरेट क्षेत्र ने इस पर प्रतिक्रिया दी है? वित्त वर्ष 19 और वित्त वर्ष 23 के बीच, निजी क्षेत्र के गैर-वित्तीय सकल स्थिर पूंजी निर्माण (**GFCF**) में संचयी वृद्धि मौजूदा कीमतों में 52% है। इसी अवधि के दौरान, सामान्य सरकार (जिसमें राज्य भी शामिल हैं) में संचयी वृद्धि 64% है। यह अंतर बहुत ज्यादा नहीं लगता।

1ण 'निवेश लागत में कमी के कारण कॉर्पोरेट लाभ जीडीपी के मुकाबले 15 साल के उच्चतम स्तर पर', बिजनेसलाइन, 11 जून 2024 (https://www.thehindubusinessline.com/economy/corporate.profit.to.gdp.hits.15.year.high.as.input.cost.moderates/article68277319.ece)

हालाँकि, जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो एक अलग तस्वीर सामने आती है। मशीनरी एवं उपकरण तथा बौद्धिक संपदा उत्पादों में निजी क्षेत्र के जीएफसीएफ में वित्त वर्ष 23 तक के चार वर्षों में संचयी रूप से केवल 35% की वृद्धि हुई है। इस बीच, 'आवास, अन्य भवन और संरचनाओं' में इसके जीएफसीएफ में 105% की वृद्धि हुई है। यह कोई अच्छा मिश्रण नहीं है। दूसरा, मीडिया एवं मनोरंजन तथा बौद्धिक संपदा उत्पादों में निवेश की धीमी गति से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने के भारत के प्रयास में देरी होगी, भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार में देरी होगी, तथा उच्च गुणवत्ता वाली औपचारिक नौकरियों की संख्या में कमी आएगी।

फिर भी, आंकड़ों में एक सकारात्मक बात भी है। वित्त वर्ष 21 के बाद से दो वर्षों में निजी क्षेत्र द्वारा जीएफसीएफ में तेजी से वृद्धि हुई है। सामान्य सरकार जीएफसीएफ में वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 23 के बीच संचयी रूप से 42% की वृद्धि हुई। गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र के समग्र जीएफसीएफ में 51% की वृद्धि हुई; मशीनरी एवं उपकरण तथा बौद्धिक संपदा उत्पादों में निवेश में 38% की वृद्धि हुई। इसलिए, निजी क्षेत्र के जीएफसीएफ के इन दो महत्वपूर्ण उप-घटकों में वृद्धि सामान्य सरकार के समग्र जीएफसीएफ के समान है। यह एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर गौर करना जरूरी है। उन्हें निवेश जारी रखना चाहिए। ऐसा करने के लिए उन्हें मांग की स्पष्टता की आवश्यकता है। यह रोजगार और आय वृद्धि से आता है।

हाल ही में प्रकाशित एक लेख[2] में, द इकोनोमिस्ट में स्वतंत्र शोध का हवाला दिया है, जिसमें अगले दशक में भारत के सेवा निर्यात में धीमी गिरावट की भविष्यवाणी की गई है। हालांकि दूरसंचार में तेजी और इंटरनेट के उदय ने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन प्रौद्योगिकी विकास की अगली लहर इसमें रुकावट डाल सकती है। इस परिवेश में, कॉर्पोरेट क्षेत्र की जिम्मेदारी जितनी स्वयं के प्रति है उतनी समाज के प्रति भी है , कि वह इस बारे में अधिक गंभीरता से सोचे कि किस प्रकार 'एआई' श्रमिकों को विस्थापित करने के बजाय श्रम को बढ़ाएगा। पिछले दो वर्षों में आईटी क्षेत्र में भर्ती की गति काफी धीमी हो गई है। हमारे पास देश में नियमित आधार पर समग्र कॉर्पोरेट नियुक्ति की पूरी जानकारी नहीं होती है। किसी भी मामले में, पूंजी-प्रधान और ऊर्जा-प्रधान एआई को लागू करना संभवत: उन अंतिम मदों में से एक है, जिसकी बढ़ती हुई निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था को आवश्यकता है।

जून 2024[3] में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक स्टाफ चर्चा नोट में कहा गया है कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बड़े पैमाने पर श्रम व्यवधानों और असमानता के बारे में गहरी चिंताएं जताई हैं। आईएमएफ एसडीएन ने देशों के बीच स्वचालित सूचना विनिमय के बेहतर प्रवर्तन और पूंजीगत लाभ पर संवर्धित कराधान के माध्यम से पूंजी पर अच्छी तरह से डिजाइन किए गए अतिरिक्त कॉर्पोरेट लाभ करों और उच्च व्यक्तिगत आय करों की सिफारिश की है। हालाँकि, रोजगार का संबंध सिर्फ उससे मिलने वाली आय से नहीं है, बल्कि इसका संबंध गरिमा, आत्म-मूल्य, आत्म-सम्मान, स्वाभिमान तथा परिवार और समुदाय में प्रतिष्ठा से है। यही कारण है कि अत्यधिक लाभ कमाने में लगे भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए यह उचित है कि वह रोजगार सृजन की अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से ले। बेशक, इसके लिए सही दृष्टिकोण और कौशल वाले लोगों को ढूंढना होगा।

इसके लिए एक और त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता है - सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत के बीच। इस समझौते का उद्देश्य भारतीयों को तकनीकी विकास के साथ तालमेल बिठाने और उससे आगे निकलने के लिए कौशल और सुसज्जित करने के मिशन को पुनर्जीवित करना है। इस मिशन में सफल होने के लिए, सरकारों को उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों को इस विशाल कार्य में अपनी-अपनी भूमिका निभाने के लिए स्वतंत्र करना होगा। उदाहरण के लिए, वर्षों से कई संशोधनों के बावजूद, देश में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षुता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षुता अधिनियम अभी भी प्रगति पर है। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की उच्च शिक्षा को नियामक निगरानी से मुक्त कर बाजार निगरानी की ओर ले जाने का प्रस्ताव करती है। एक कॉर्पोरेट क्षेत्र जो पाठ्यक्रम, मूल्यांकन मानकों और संकाय के लिए उपयोगी जानकारी के साथ उच्च शिक्षा के डिजाइन को आकार देने में मदद करता है, वह उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो बाजार की प्रतिस्पर्धा लाएगा और नियामक निगरानी का स्थान लेगा। द इकोनॉमिस्ट के एक अन्य लेख[4] में चीन के विज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनने की सराहना की गई है, जो कि कॉर्पोरेट क्षेत्र और शिक्षा जगत के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में एकजुट होकर कार्य करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा होनी चाहिए।

वास्तविक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

कॉर्पोरेट क्षेत्र की भूमिका आज से पहले कभी इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व के दो अन्य क्षेत्रों का यहां उल्लेख करना उचित होगा। महामारी के दौरान भारतीय खुदरा निवेशक बाजार स्थिरता के आधार के रूप में उभरे हैं। दीर्घावधि के लिए निवेश की प्रवृत्ति

2ण 'क्या सेवाएँ दुनिया को समृद्ध बनाएंगी?', द इकोनॉमिस्ट, 24 जून 2024
(https://www.economist.com/finance.and.economics/2024/06/24/will.services.make.the.world.rich)

3ण 'जनरेटिव एआई से लाभ का विस्तार: राजकोषीय नीतियों की भूमिका', स्टाफ चर्चा नोट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जून 2024
(https://tinyurl.com/39dy7dv3)

4ण 'चीन एक वैज्ञानिक महाशक्ति बन गया है', द इकोनॉमिस्ट, 12 जून 2024
(https://www.economist.com/science.and.technology/2024/06/12/china.has.become.a.scientific.superpower)

को पोषित और कायम रखना होगा। विकसित देशों में वित्तीय नवाचारों के नाम पर छिपे तौर पर लीवरेज दांव से प्रेरित बाजार प्रथाओं का, कम प्रति व्यक्ति आय वाले विकासशील देश में कोई स्थान नहीं है। दूसरा, जिस प्रकार कॉर्पोरेट मुनाफा बढ़ रहा है, उसी प्रकार भारतीय बैंकों का शुद्ध ब्याज मार्जिन कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यह अच्छी बात है। लाभ कमाने वाले बैंक ज्यादा उधार देते हैं। अच्छे समय को बनाए रखने के लिए, पिछले वित्तीय चक्र की मंदी के सबक को न भूलना जरूरी है। बैंकिंग उद्योग को दो एनपीए चक्रों के बीच के अंतराल को बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसे ग्राहकों की कीमत पर अल्पकालिक लाभ कमाने के प्रलोभन का भी विरोध करना चाहिए। उत्पाद की गलत बिक्री इतनी व्यापक है कि इसे कुछ अति उत्साही विक्रय कर्मियों की गलती मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। यही बात बीमा उद्योग के बारे में भी कही जा सकती है। बीमा दावों का शीघ्र और उचित निपटान तथा अस्वीकृति दर में कमी बीमा पैठ बढ़ाने के लिए आवश्यक है। गलत बिक्री और गलत बयानी की स्वीकृति और परिणामी नुकसान की भरपाई करना एक अच्छा व्यवसाय अभ्यास है, जो स्टॉकब्रोकिंग, फंड प्रबंधन, बैंकिंग और बीमा फर्मों के लिए अनिवार्य है।

रोजगार और आय वृद्धि से उत्पन्न उच्च मांग से कॉर्पोरेट को लाभ होता है। घरेलू बचत को निवेश उद्देश्यों के लिए उपयोग करने से वित्तीय क्षेत्र को लाभ होता है। आने वाले दशकों में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परिवर्तन निवेश को पूरा करने के लिए इन संबंधों को और मजबूत और लंबे समय तक चलना चाहिए। अल्पकालिकता इन संबंधों को कमजोर कर सकती है।

भारत की कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या को लाभकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, बैठे रहने की आदतें और अस्वास्थ्यकर भोजन एक घातक मिश्रण है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और उत्पादकता को कमजोर कर सकता है और भारत की आर्थिक क्षमता को कम कर सकता है। आदतों के इस जहरीले मिश्रण में निजी क्षेत्र का योगदान बहुत ज्यादा है, और यह निकट दृष्टिक है। भारतीयों की उभरती हुई खाद्य उपभोग की आदतें न केवल अस्वास्थ्यकर हैं, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी असंतुलित हैं। भारत की पारंपरिक जीवनशैली, भोजन और व्यंजनों ने सदियों से यह दिखाया है कि प्रकृति और पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए स्वस्थ तरीके से कैसे रहा जाए। भारतीय व्यवसायों के लिए इनके बारे में जानना और इन्हें अपनाना व्यावसायिक दृष्टि से उचित है, क्योंकि उनके पास एक वैश्विक बाजार है, जिसका नेतृत्व करने की आवश्यकता है, न कि इसका दोहन करने की।

सरकारें अपनी ओर सेण्ण्ण

नीति निर्माताओं को - चाहे वे निर्वाचित हों या नियुक्त को भी चुनौतियों का सामना करना होगा। मंत्रालयों, राज्यों तथा संघ और राज्यों के बीच बातचीत, सहयोग, सहभागिता और समन्वय होना चाहिए। सरकार के बाहर बहुत कम लोग भारत जैसे (जनसंख्या) आकार, (भौगोलिक) विस्तार तथा सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता वाले राष्ट्र को लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर संचालित करने और बदलने की जटिलता को समझ सकते हैं। जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ और सिविल सेवा के साथ-साथ जिलों, राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ अपने संपर्क के कारण, राजनीतिक वर्ग के पास इस जटिलता को (कम से कम) आंशिक रूप से समझने का बेहतर मौका होता है। वे सहज रूप से जानते हैं कि विशिष्ट दृष्टिकोणों और द्विआधारी विकल्पों के लिए कोई स्थान नहीं है, जो कि निरर्थक चर्चाओं और वार्तालापों का मुख्य आधार हैं। उदाहरणार्थ, शहरी बनाम ग्रामीण, विकास बनाम समानता या विकास, तथा विनिर्माण बनाम सेवाएं। वे सहज रूप से जानते हैं कि भारत को विकास के लिए कई रास्ते अपनाने की जरूरत है। यह अच्छी बात है। लेकिन यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। इस पैमाने पर नहीं। समय-सीमा में नहीं और अशांत वैश्विक वातावरण के बीच भी नहीं। इस प्रयास में सफलता पाने के लिए सरकारों, व्यवसायों और सामाजिक क्षेत्रों के बीच आम सहमति बनाना और उसे कायम रखना आवश्यक है।

कृषि विकास का इंजन बन सकती है यदिण्ण्ण

कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके लिए इस तरह के अखिल भारतीय संवाद की आवश्यकता है। कृषि और किसान किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। अधिकांश देश समझते हैं कि भारत भी इसका अपवाद नहीं है। भारत उन्हें पानी, बिजली और उर्वरक पर सब्सिडी देता है। पहले दो चीजें लगभग मुफ्त दी जाती हैं। उनकी आय पर कर नहीं लगता। सरकार 23 चुनिंदा वस्तुओं के लिए उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान करती है। पीएम-किसान योजना के माध्यम से किसानों को मासिक नकद सहायता प्रदान की जाती है। भारतीय सरकारें - राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय - किसानों के ऋण माफ कर देती है। इसलिए, भारत में सरकार किसानों की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए पर्याप्त संसाधन खर्च करती है। फिर भी, यह तर्क दिया जा सकता है कि मौजूदा और नई नीतियों में कुछ बदलाव करके उन्हें बेहतर सेवा दी जा सकती है।

राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय सरकारों द्वारा एक-दूसरे के विपरीत उद्देश्यों के लिए काम करने वाली नीतियों के कारण किसानों के हितों को नुकसान पहुंच रहा है, मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो रही है, भूजल स्तर घट रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन से नदियां और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, फसलों को पोषक तत्वों से वंचित किया जा रहा है और फाइबर और प्रोटीन के बजाय चीनी और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार

के कारण लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है। यदि हम कृषि क्षेत्र की नीतियों में व्याप्त गांठों को खोल दें तो इसका लाभ बहुत अधिक होगा। किसी भी अन्य बात से अधिक, इससे सामाजिक-आर्थिक लाभ के अलावा, राष्ट्र को बेहतर भविष्य की ओर ले जाने में राज्य के आत्मविश्वास और क्षमता में विश्वास बहाल होगा।

पहले के विकास मॉडलों में अर्थव्यवस्थाओं को कृषि से शुरू होकर औद्योगिकीकरण और फिर मूल्य-संवर्धित सेवाओं की ओर विकास यात्रा में आगे बढ़ते हुए दिखाया गया था। तकनीकी प्रगति और भूराजनीति इस पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दे रही है। व्यापार संरक्षणवाद, संसाधन-जमाखोरी, अतिरिक्त क्षमता और डंपिंग, उत्पादन को स्थानीय स्तर पर ले जाना तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का आगमन, देशों के लिए विनिर्माण और सेवाओं से विकास को बाहर निकालने की गुंजाइश को कम कर रहा है। यह हमें पारंपरिक ज्ञान को उलटने के लिए मजबूर कर रहा है। क्या कृषि क्षेत्र उद्धारक हो सकता है? खेती के तौर-तरीकों और नीति निर्माण के मामले में जड़ों की ओर लौटना, कृषि से उच्च मूल्य संवर्धन उत्पन्न कर सकता है, किसानों की आय बढ़ा सकता है, खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात के अवसर पैदा कर सकता है और कृषि क्षेत्र को भारत के शहरी युवाओं के लिए फैशनेबल और उत्पादक बना सकता है। वर्तमान नीति विन्यास के कारण पिछले कुछ वर्षों में उत्पन्न उपरोक्त समस्या क्षेत्रों का समाधान हो जाने पर वे भारत की शक्ति के स्रोत बन सकते हैं तथा शेष विश्व -विकासशील एवं विकसित दोनों के लिए एक आदर्श बन सकते हैं ।

छोटे उद्यमों को उन्मुक्त करना

एक अन्य क्षेत्र जहां नीतिगत इरादे अभी तक वांछित परिणामों में प्रकट नहीं हुए हैं, वह है लघु, मध्यम और बड़े उद्यम। पहले कई उत्पाद लघु उद्योगों के लिए आरक्षित थे। लेकिन बाद में इसे समाप्त कर दिया गया क्योंकि इससे न तो लघु उद्योगों को लाभ हो रहा था और न ही समग्र अर्थव्यवस्था को। हाल ही में उन्हें औपचारिक बनाने के लिए किए गए ठोस प्रयासों से प्रगति हो रही है। वित्त तक पहुंच के मामले में प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है। क्रेता और ऋणदाता पुरानी मानसिकता और प्रथाओं को इतनी धीमी गति से त्याग रहे हैं कि इन उद्यमों को इसका प्रभाव महसूस नहीं हो पा रहा है। हालांकि, इन उद्यमों को कानून अनुपालन के बोझ से अधिकतम राहत की आवश्यकता है जिसका वे सामना करते हैं। कानून, नियम और विनियमन उनके वित्त, क्षमताओं और सीमा को बढ़ाते हैं, या शायद उन्हें बढ़ने की इच्छा से वंचित करते हैं।

सफल ऊर्जा संक्रमण एक ऑर्केस्ट्रा है

ऊर्जा परिवर्तन और गतिशीलता जैसी अन्य प्राथमिकताएं, कृषि क्षेत्र की नीतियों को सही ढंग से लागू करने की जटिलता की तुलना में फीकी पड़ सकती हैं। फिर भी, उनमें एक बात समान है। उन्हें कई मंत्रालयों और राज्यों में कई कामों को संरेखित करने की आवश्यकता होती है । यह सूची बहुत लंबी है।

ऊर्जा संक्रमण और गतिशीलता के मुद्दों पर निम्नलिखित क्षेत्रों में ध्यान देने की आवश्यकता है:

(क) शत्रुतापूर्ण राष्ट्रों पर संसाधन निर्भरता;

(ख) तकनीकी चुनौतियाँ जैसे विद्युत उत्पादन में रुकावट, अक्षय ऊर्जा स्रोतों और बैटरी भंडारण से उत्पादन में उतार-चढ़ाव के बीच ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करना।

(ग) भूमि की कमी वाले देश में भूमि प्रबंधन के अवसर लागत की पहचान;

(घ) राजकोषीय निहितार्थ जिसमें अक्षय ऊर्जा उत्पादन और ई-मोबिलिटी समाधानों के लिए सब्सिडी के लिए अतिरिक्त व्यय, जीवाश्म ईंधन की बिक्री और परिवहन से वर्तमान में प्राप्त कर और माल ढुलाई राजस्व की हानि शामिल है;

(ङ) तथाकथित 'संकटग्रस्त परिसंपत्तियों' से बैंक बैलेंस शीट को होने वाली हानि और

(च) वैकल्पिक गतिशीलता समाधानों जैसे सार्वजनिक परिवहन मॉडल आदि के गुणों की जांच।

अन्य देशों की नीति प्रथाओं का अनुकरण करना न तो व्यवहार्य है और न ही वांछनीय, क्योंकि उन तरीकों और स्थानों से समाधान नहीं निकल सकता, जिन्होंने पहली बार समस्याएं पैदा की थीं।

जाने देना अच्छे शासन का हिस्सा है

आगे आने वाली चुनौतियों पर विचार करते समय किसी को भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक भारत का सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एक उल्लेखनीय सफलता की कहानी है। हमने एक लंबा सफर तय किया है। अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 93 में लगभग 288 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 3൦6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। भारत ने प्रति डॉलर ऋण पर अन्य तुलनीय देशों के संबंध में अधिक वृद्धि की है। घोर गरीबी लगभग समाप्त हो गई है। मानव विकास सूचकांक में सुधार हुआ है और

अधिक भारतीय, विशेषकर महिलाएँ शिक्षित हो रही हैं। अपनी सभी खामियों और कमियों के बावजूद, इस प्रणाली ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सार्वजनिक संवाद के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित की है, जहाँ कभी-कभार परिपक्व टिप्पणियाँ कारगर साबित होती हैं। हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

हालांकि, देश को चलाने के लिए एक प्रणाली को मजबूत न करना एक खोया हुआ अवसर होगा, जैसा कि अतीत में कई बार हुआ है, क्योंकि हमारा भविष्य अत्यधिक अनिश्चित हो गया है। वैश्विक स्तर पर लगभग आठ दशकों की सापेक्षिक शांति के बाद, विश्व दीर्घकालिक प्रभाव वाले एक बड़े एवं व्यापक संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। भारतीय राष्ट्र अपनी क्षमता को उन्मुक्त कर सकता है तथा अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है, ताकि वह उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सके, जहां उसे ऐसा करना आवश्यक है, तथा इसके लिए उसे उन क्षेत्रों पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करनी होगी, जहां उसे ऐसा करना आवश्यक नहीं है। लाइसेंसिंग, निरीक्षण और अनुपालन संबंधी आवश्यकताएं, जो सरकार के सभी स्तरों द्वारा व्यवसायों पर लागू की जाती हैं, एक भारी बोझ है। इतिहास के सापेक्ष, बोझ हल्का हो गया है। लेकिन जहां होना चाहिए था, उसके सापेक्ष, यह अभी भी बहुत भारी है। इसका बोझ उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ता है जो इसे उठाने में सबसे कम सक्षम हैं - छोटे और मध्यम उद्यम। यह उन्हें पीछे धकेलता है, उनकी आकांक्षाओं को बाधित करता है और इस प्रक्रिया में देश को भी पीछे धकेलता है। पहली नजर में, ऐसा लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आर्थिक विकास दर अच्छी है और प्रगति के स्पष्ट संकेत भी हैं। लेकिन, हम कभी भी इसके विपरीत नहीं जान पाएंगे: "यह क्या हो सकता था"।

ईशोपनिषद हम सभी को अपनी संपत्ति छोड़ देने (त्यागने), स्वतंत्र होने और उस स्वतंत्रता का आनंद लेने का आदेश देता है:

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।।

सत्ता सरकारों की एक बेशकीमती संपत्ति है। वे कम से कम कुछ हद तक इसे छोड़ सकते हैं और शासक और शासित दोनों में इसके द्वारा पैदा होने वाले हल्केपन का आनंद ले सकते हैं।

अंत में,णणण

उभरती हुई अभूतपूर्व वैश्विक चुनौतियों के बीच इस देश को विकसित राष्ट्र बनने के लिए जिस त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता है, वह है सरकारें भरोसा करें और जाने दें, निजी क्षेत्र दीर्घकालिक सोच और निष्पक्ष आचरण के साथ भरोसे का प्रतिदान करें तथा जनता अपने वित्त और शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लें।

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में अपने कई अध्यायों में ऊपर चर्चित अनेक मुद्दों को शामिल किया गया है, इसके अलावा पाठकों को सरकारी नीतियों और उनके प्रदर्शन, उनके प्रभावों, नवाचारों, विकास और अनुकरणीय सफलता की कहानियों से भी अवगत कराता है। पहले की तरह, सर्वेक्षण की मुख्य विषय-वस्तु वे अध्याय हैं जो कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचे और सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों का मूल्यांकन करते हैं।

'आर्थिक कार्य विभाग' के 'अर्थशास्त्र प्रभाग' में हमारे लिए, आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करना तथा उसे आपके हाथों या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक पहुंचाना, पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि आनंद के लिए किया जाने वाला कार्य है। समीक्षाधीन वर्ष में देश की प्रगति को रिकार्ड करना और साझा करना तथा इस बात पर विचार करना कि अपेक्षित प्रगति प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए एक सीखने का अनुभव है। ऐसा करते समय, हो सकता है कि हमने कुछ गलतियाँ की हों। कृपया हमें बताएँ। हम वादा करते हैं कि हम इसे और बेहतर बनाने का वादा करते हैं। आखिरकार, यही वह सब है जो हम सभी कर सकते हैं हमें करना चाहिए।

(वी. अनंत नागेश्वरन)
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मत्रांलय, भारत सरकार

आभारोक्ति

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 सामूहिक प्रयास का परिणाम है। सर्वेक्षण को माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की टिप्पणियों और अंतर्दृष्टि से लाभ मिला है। सर्वेक्षण में माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव डॉण् टीण् वीण् सोमनाथन, सचिव आर्थिक कार्य विभाग श्री अजय सेठ, सचिव डीआईपीएएम श्री तुहिन कांता पांडे, सचिव डीपीई श्री अली रजा रिजवी, सचिव वित्तीय सेवाएं श्री विवेक जोशी और राजस्व सचिव श्री संजय मल्होत्रा के सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया गया है।

आर्थिक प्रभाग और आर्थिक कार्य विभाग के अन्य प्रभागों से सर्वेक्षण में योगदानकर्ताओं में शामिल हैं: चांदनी रैना, एंटनी सिरिएक, अनुराधा गुरु, अनुपा एस नायर, कोकिला जयराम, सैयद जुबैर नकवी, धर्मेंद्र कुमार, सीमा जोशी, हरीश कुमार कलेगा, दीपिका श्रीवास्तव, अमित श्योराण, श्रेया बजाज, मेघा अरोड़ा, दीक्षा सुप्याल बिष्ट, मनोज कुमार मिश्रा, रितिका बंसल, मोहम्मद आफताब आलम, प्रद्युत कुमार पायने, ईशा स्वरूप, राधिका गोयल , हरीश यादव, राजेश शर्मा, मृत्युंजय कुमार, अमित कुमार केसरवानी, दीपद्युति सरकार, अजय ओझा, केण चंद्र शेखर, रोहित कुमार तिवारी, हेमा राणा, अपराजिता त्रिपाठी, सोनाली चौधरी, भारद्वाज आदिराजू, सुरभि सेठ, मीरा उन्नीकृष्णन, आकाश पुजारी, रोशन यादव, रोहित त्रिवेदी, सत्येन्द्र किशोर, एस रामकृष्णन, विशाल गोरी, कुणाल बंसल, रितेश कुमार गुप्ता, धृति अरोड़ाद्य मुना साह तथा बृजपाल अधिकारियों के निजी कर्मचारी हैं।

उपर्युक्त के अलावा, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में टिप्पणियों और इनपुट के साथ योगदान दिया। उनमें शामिल हैं: राजीव मिश्रा, सोलोमन अरोकियाराज, बलदेव पुरुषार्थ, प्रवाकर साहू, अजय कुमार सूद, अलीशा जॉर्ज, गौरव मसलदान, ई श्रीनिवास, नीतीश सूरी, नीलांभुज शरण, कामखेंथांग गुइटे, एमण्जीण जयश्री, धृजेश कुमार तिवारी, अवदेश कुमार चौधरी, शेफाली ढींगरा, आरण राजेश, योगेश सूरी, कुसुम मिश्रा, बिजय कुमार बेहरा, एण सृजा, पीण्केण अब्दुल करीम, सीण वनलालरामसंगा, रेणुका मिश्रा, माणिक चंद्र पंडित, गायत्री नायर मनोज मधोलिया, सुरजीत कार्तिकेयन, विष्णुकांत पीबी, कपिल पाटीदार, जयपाल, अनुश्री राहा, चितवन ढिल्लन, लीना कुमार, उपदेश शर्मा, प्रभात कुमार सिंह, धरम प्रकाश, दलीप कुमार, अखिलेश शर्मा, एसएन मिश्रा, अंशुमन कामिला, इशिता गांगुली त्रिपाठी, लालसंगलूर, राजश्री रे, अंशू भारद्वाज, राजनाथ राम, ऋषिका चोरारिया, मनीषा सेनसारमा, फैज अहमद किदवई, फ्रैंकलिन एल खोबुंग, ए। प्रतिभा, इंदु बुटानी, वीण्एसण सहरावत, कुशवंत कुमार, राजेश कुमार, साबरी बिन कासिम, शांता शर्मा, राहुल मीना, पुनीत भाटिया, अभय बाकरे, धीरज कुमार श्रीवास्तव, जेण राजेश कुमार, अजय माथुर, अमित प्रोथी, अल्पना साहा, प्रिंस धवन, एंसी मैथ्यू एनण्पीण, एणआरण रॉय, अश्विनी कुमार, राजकुमार, प्रमोद कुमार आर्य और सुभाष चंद।

हमें कई विशेषज्ञों, उद्योग निकायों, सार्वजनिक संस्थानों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं से भी मदद मिली, जिनमें सेबी, आरबीआई, आईबीबीआई, आईएफएससीए, पीएफआरडीए, आईआरडीएआई, तीर्थंकर पटनायक, संगीता गुप्ता, तनय दलाल, वृंदा बंसोडे, भुवन आनंद, शुभो रॉय, आरण सुब्रमण्यम, सुचिता दत्ता और प्रसन्ना तंत्री शामिल हैं।

मनोज सहाय, अपर्णा भाटिया, जसबीर सिंह, सुश्रुत सामंत, दलीप कुमार, सुनील कुमार गुप्ता, पंकज कुमार, दवेन्द्र कुमार, नवनीत पाठक, राहुल गोयल तथा आर्थिक कार्य विभाग के अन्य कर्मचारियों द्वारा कार्यक्षम प्रशासनिक सहयोग दिया गया है ।

सर्वेक्षण का हिंदी अनुवाद आर्थिक कार्य विभाग के हिंदी अनुभाग के लेफ्टिनेंट कर्नल एमण्केण सिंह, डॉण पूरन सिंह, हरीश सिंह रावत, रजनीश कुमार, अनुपम आर्य, समता रानी, बबीता गुंजियाल, जिंटू कुमार मंडल, विनय कुमार, कमलेश धमुनया, अर्चना सिंह, माया मीना, शियो पूजन चौधरी, नीरज मिश्रा, गौरव भाटिया, रीना कुमारी मीना, सुरभि, शिखा और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के जय वीर, मीनाक्षी वर्मा, मनीष भटनागर, मनोज कुमार, राजीव कुमार सिंह, दिवाकर शुक्ला, रवीश रंजन, धर्मेंद्र कुमार द्वारा किया गया। सर्वेक्षण का हिंदी संस्करण मिंटो रोड स्थित मुद्रण निदेशालय के अनिल बजाज, हिमांशु शर्मा, जिया लाल मैठाणी, दिनेश दीवान द्वारा टाइप किया गया।

सर्वेक्षण का कवर पेज इज्जुर रहमान के द्वारा डिजाइन किया गया। सिग्नेचर प्रिंटर्स के इज्जुर रहमान, दीपक अग्रवाल, गौतम हलदर और मोहम्मद सुहैल ने सर्वेक्षण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों की पेज सेटिंग की।

आर्थिक सर्वेक्षण इसकी तैयारी में शामिल सभी लोगों के परिवारों के प्रति उनके धैर्य और सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

वी. अनंत नागेश्वरन
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मत्रांलय
भारत सरकार

संकेताक्षर

एएजीआर	औसत वार्षिक विकास दर
एएआई	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
एएयू	समनुदिष्ट राशि इकाइयां
एएवाई	अंत्योदय अन्न योजना
एबीसी	अकादमिक ऋण बैंक
एबीडीएम	आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
एबीएचए	आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता
एबी-पीएमजेएवाई	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
एबी-आरपीवाई	आत्मनिर्भर भारत रोजगार प्रोत्साहन योजना
एबीआरवाई	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
एबीएस	स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग
एसीसी	एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एडीपी	आकांक्षी जिला कार्यक्रम
एईएस	उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ
एएफएचसी	किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक
एजीईवाई	आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना
एएचआईडीएफ	पशुपालन अवसंरचना विकास निधि
एआई	आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस
एआई	आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस
एआईआईपी	कृत्रिम बुद्धिमत्ता बौद्धिक संपत्ति
एआईबीपी	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
एआईएफ	वैकल्पिक निवेश कोष
एआईएफ	कृषि अवसंरचना कोष
एआईआईएमएस	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
एआईआरएडबल्यूएटी	एआई अनुसंधान विश्लेषण और ज्ञान प्रसार प्लैटफार्म
एआईएसएचई	अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण
एआईटीआईजीए	आसियान- भारत माल व्यापार समझौता
एकेआरएसपी	आगा खान ग्रामीण सहायता कार्यक्रम
एएमसीएस	परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां
एएमआई	कृषि विपणन अवसंरचना
एएमआरआईटी	उपचार के लिए सस्ती दवाइयां और विश्वसनीय प्रत्यारोपण
एएमआरयूटी	कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन
एपीएआर	स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री
एपीआई	एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
एपीआईएस	एक्टिव फर्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स
एपीएलएम	कृषि उपज और पशुधन विपणन

एपीएमसीएस	कृषि उत्पाद विपणन समितियों
एपीएमआर	कृषि उत्पादन विपणन विनियमन
एपीवाई	अटल पेंशन योजना
एआरसीएस	संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां
एआरजी	स्वचालित वर्षामापी
एआरएचसी	अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज
एआरआईएमए	ऑटोरेग्रेसीव इंटेग्रटेड मुविंग एव्रेज
एएसबीए	ब्लॉक किए गए खाते द्वारा समर्थित एप्लिकेशन
एएसआई	उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण
एस्ट्रोसैट	अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला
एटीएफ	एविएशन टरबाईन फ्यूल
एटीपी	स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा
एयूएम	प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां
एडबल्यूसी	आंगनवाड़ी केंद्र
एडब्ल्यूएस	स्वचालित मौसम स्टेशन
बीबीएसएसएल	भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड
बीडीआई	बाल्टिक शुष्क सूचकांक
बीई	बजट प्राक्कलन
बीएफएसआई	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा
बीएफटी	बेयर फूट तकनीशियन
बीएचईएल	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
बीआईएम	बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मोडलिंग
बीआईएस	अंतर्राष्ट्रीय निपटान के लिए बैंक
बीओपी	भुगतान संतुलन
बीपीएम	कारोबार प्रक्रिया प्रबंधन
बीपीओ	बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग
बीआरओ	सीमा सड़क संगठन
बीआरएसआर	व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट
बीएसएफ	ब्लैक सोल्जर फ्लाईज
बीटीएस	बेस ट्रांसीवर स्टेशन
सीएसीपी	कृषि लागत और मूल्य आयोग
सीएडी	चालू खाता घाटा
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
सीएजीआर	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
कैपेक्स	पूंजीगत व्यय
सीबीजी	संपीड़ित जैव गैस
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीबीएम	कोल बेड मीथेन
सीबीएसई	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सीसी	क्लियरिंग कॉर्पोरेशन
सीसीएस	कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज

सीसीटी	कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम
सीसीयूएस	कार्बन कैप्चर उपयोग एवं भंडारण
सी–डैक	प्रगत संगणन विकास केंद्र
सीडीएम	स्वच्छ विकास तंत्र
सीडीआरआई	आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन
सीडी	जमा प्रमाणपत्र
सीईसीपीए	व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता
सीईपीए	विस्तृत आर्थिक भागीदारी समझौता
सीईआरएस	प्रमाणित उत्सर्जन कटौती
सीईटी–1	कॉमन इक्विटि टियर – 1
सीएफपीआई	उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक
सीजीए	महा लेखानियंत्रक
सीजीएस	ऋण गारंटी योजना
सीजीटीएमएसई	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना
सीएचसी	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
सीएचसीएस	कस्टम हायरिंग सेंटर
सीआईसी	चलन में मुद्रा
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड
सीआईपी	केंद्रीय निर्गम मूल्य
सीआईआरपी	कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया
सीआईएस	ग्राहक सूचना पत्र
सीकेएम	सर्किट किलोमीटर
सीएमआईई	भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र
सीएमएम	कोयला खदान मीथेन
सीएनडी	उपभोक्ता गैर–टिकाऊ वस्तुएं
सीएनजी	संपीडित प्राकृतिक गैस
सीओटू	कार्बन डाइऑक्साइड
सीओपी	पार्टियों का सम्मेलन
सीओपीएस	पार्टियों का सम्मेलन
सीओआरएसआईए	अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीआई–सी	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–संयुक्त
सीपी	वाणिज्यिक पत्र
सीपीएसई	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
सीपीएसयू	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सीक्यूजीआर	चक्रवृद्धि तिमाही वृद्धि दर
सीआरएआर	कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशिओ
क्रिसिल	क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीआरओपीआईसी	फसलों के वास्तविक समय का अवलोकन और तस्वीरों का संग्रह
सीआरपी	कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन

सीआरआर	नकद आरक्षित अनुपात
सीएसआईआर	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीएसएल	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
सीएसओ	नागरिक समाज संगठन
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय
सीएसपी	क्लाउड सेवा प्रदाता
सीएसआर	कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी
सीएसएस	केंद्र प्रायोजित योजना
सीवी	विचलन का गुणांक
सीडब्ल्यूएस	वर्तमान साप्ताहिक स्थिति
सीडब्लूएसएन	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
डीए-एफडब्ल्यू	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
डीएएचडी	पशुपालन और डेयरी विभाग
डीएपी	डाइ-अमोनियम फॉस्फेट
डीएवाई-एनआरएलएम	दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
डे-एनयूएलएम	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
डीबीएफओटी	डिजाइन - बिल्ड ख्र फाइनेंस - ऑपरेट - ट्रान्सफर
डीबीआई	डायवर्सन-आधारित सिंचाई
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीडीयू-जीकेवाई	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
डीईएच	निर्यात केंद्र के रूप में जिले
डीएफसी	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
डीएफआई	डिजिटल वित्तीय समावेशन
डीएफआई	किसानों की आय दोगुनी करने की रिपोर्ट
डीजीसीए	नागर विमानन महानिदेशालय
डीजीक्यूआई	डेटा गवर्नेंस गुणवत्ता सूचकांक
डीआईईटी	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान
डीआईकेएसएचए	ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना
डीआईएससीओएम	वितरण कंपनियाँ
डीआईएसएचए	जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समितियां
डीओपी	डाक विभाग
डीपीआई	डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
डीपीआईआईटी	उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
डीआरआई	आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना
डीआरआईपी	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना
डीआरटी	ॠण वसूली न्यायाधिकरण
डीएसटी	प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली
डीटीएच	डायरेक्ट टू होम
ईएईयू	यूरेशियन आर्थिक संघ
ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधार
ईसीबी	यूरोपीय सेंट्रल बैंक

ईसीसीई	आरंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा
ईसीटीए	आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता
ईएफटीए	यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ
ईआई	इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग
ई–एलओजीएस प्लैटफॉर्म	इज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेस प्लैटफॉर्म
ईएमसी	इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर
ईएमडीई	उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
ईएमई	उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाएँ
ईएमआई पेमेंट	समान मासिक किश्त भुगतान
ईएमआई/ईएमसी	विद्युतचुंबकीय हस्तक्षेप/विद्युतचुंबकीय अनुकूलता
एनएएम	राष्ट्रीय कृषि बाजार
ई–एनएएम	ई– राष्ट्रीय कृषि बाजार
ईपीएफ	कर्मचारी भविष्य निधि
ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीओएस	इलेक्ट्रोनिक बिक्री केंद्र
ईआर–डी	उद्यम, अनुसंधान, और विकास
ईआरयू	उत्सर्जन घटौती इकाइयाँ
ईएसजी	पर्यावरणीय, सामाजिक और शासनिक
ईएसएस	ऊर्जा भंडारण प्रणाली
ईटीसीए	आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौता
ईटीएफ	एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड
ईयू	यूरोपीय संघ
ईयू–ईटीएस	यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार योजना
ईवीज	इलेक्ट्रिक वाहन
ईएक्सआईएम	निर्यात–आयात बैंक
एफएडीए	फेडेरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन
एफएओ	खाद्य एवं कृषि संगठन
एफएटीएफ	वित्तीय कार्रवाई कार्यबल
एफसीआई	भारतीय खाद्य निगम
एफसीआरए	वायदा संविदा विनियमन अधिनियम
एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफईडी	फेडरल रिजर्व
एफईआर	विदेश मुद्रा भंडार
एफआईडीएफ	मत्स्य–पालन अवसंरचना विकास निधि
एफएलएफपीआर	महिला श्रम–बल सहभागिता दर
एफएलएन	आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान
एफएमसी	वायदा बाजार आयोग
एफओएमसी	फेडरल ओपन मार्केट कमेटी
एफपीआई	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
एफपीआई	विदेश पोर्टफोलियो निवेश
एफपीओ	कृषक उत्पादक संगठन

एफपीएस	उचित मूल्य की दुकान
एफआरबी	विदेशी पुनर्बीमा शाखाएं
एफएसए	वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन
एफएसएपी	वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफएसआर	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
एफएसएसए	वित्तीय प्रणाली स्थिरता मूल्यांकन रिपोर्ट
एफएसएसआई	फाइनेंसियल सिस्टम स्ट्रेस इंडिकेटर
एफटीए	मुक्त व्यापार समझौते
एफटीके	फील्ड परीक्षण किट
एफटीटीएच	फाइबर टू द होम
एफवाई	वित्त वर्ष
एफवाई	वित्त वर्ष
जीबीएस	जेंडर बजट स्टेटमेंट
जीबीएस	सकल बजटीय सहायता
जीसीए	सकल फसली क्षेत्र
जी.सी.सी.	वैश्विक क्षमता केंद्र
जीसीपी	ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम
जीसीटी	गतिशक्ति मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीईसी	ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर
जीईएम	गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस
जीईआर	सकल नामांकन अनुपात
जीईआरडी	अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय
जीएफसी	वैश्विक वित्तीय संकट
जीएफसीएफ	कुल स्थिर पूंजी निर्माण
जीएचई	स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय
जीएचजी	ग्रीन हाउस गैसें
जीआई क्लाउड	गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाउड
जीईएफटी–सिटी	गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक–सिटी
जीआईआई	वैश्विक नवाचार सूचकांक
जीएनआई	सकल राष्ट्रीय आय
जीएनपीए	सकल अनर्जक आस्ति
जाओआई	भारत सरकार
जीओवीटी.	सरकार
जीपी	ग्राम पंचायत
जीपीएआई	कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर वैश्विक साझेदारी
जीपीडीपी	ग्राम पंचायत विकास योजना
जीपीजी	ग्राम पंचायतें
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसएलवी	भू–समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान

जीएसटी	माल और सेवा कर
जीएसटी	ग्लोबल स्टॉकटेक
जीटी	सकल टनभार
जीटीआर	सकल कर राजस्व
जीवीए	सकल मूल्य वर्धित
जीवीए	सकल मूल्य वर्धित
जीवीसी	वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ
जीडब्ल्यू	गीगावाट
जीडब्ल्यू इक्विवेलेंट	गीगावाट समतुल्य
जीडब्ल्यूएमआर	भूजल प्रबंधन एवं विनियमन
जीडब्ल्यू	गीगा वाट
एचएएल	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
एचएएम	हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल
एचसीईएस	पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण
एचईआई	उच्च शिक्षा संस्था
एचएफसी	आवासीय वित्त कंपनियाँ
एचएचआई	हर्शमैन-हर्फिंडाल इंडेक्स
एचकेकेपी	हर खेत को पानी
एचएमएल	सुसंगत सूची
एचएनआई	हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल
एचआर	मानव संसाधन
आईबीए	भारतीय बैंक संघ
आईबीसी	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता
आईबीपी मार्ग	इंडो-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट
आईसीएओ	अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आईसीडीआर	पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं
आईसीडी	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ
आईसीआरआईईआर	भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद
आईसीटी	सूचना व संचार प्रौद्योगिकी
आईडीआरसीएल	इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड
आईईबीआर	आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन
आईईटी	अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार
आईएफआरएस	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक
आईएफएससी	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र
आईएफएससी जीआईएफटी सिटी	इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी
आईएफएससीए	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
आईएचएचएल	भिन्न-भिन्न घरेलू शौचालय
आईआईई	भारतीय उद्यमशीलता संस्थान
आईआईजी	भारतीय निवेश ग्रिड
आईआईपी	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति

आईआईपी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आईआईपीडीएफ	भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईआईटीएम	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
आईएलआईएमएस	एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली
आईएमसी	इंदौर नगर निगम
आईएमईसी	भारत मध्य-पूर्व यूरोप कोरिडोर
आईएमईएस	अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम
आईएमऍफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
इंडिया-डब्ल्यूआरआईएस	भारत - जल संसाधन सूचना प्रणाली
इन्फ्रा	अवसंरचना
आईएन-एसपीएसीई	भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र
आईएनएसटीसी	अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा
आईएनवीआईटीज	अवसंरचना निवेश न्यास
आईओटी	इंटरनेट ऑफ थिंग्स
आईपीओ	इनिशियल पब्लिक ऑफर
आईआर	भारतीय रेल
आईआरसीटीसी	भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड
आईआरडीएआई	भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
आईआरएफसी	भारतीय रेल वित्त निगम
आई आर आई एस	लचीले द्वीपीय राज्यों के लिए अवसंरचना
आईएसए	अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन
आईएसएएम	एकीकृत कृषि विपणन योजना
आईएसआरओ	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीआई	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आईटीएमओज	अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित शमन परिणाम
आईवीए	स्वतंत्र सत्यापन अभिकरण
आईडब्ल्यूएआई	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
आईडब्ल्यूटी	अंतर्देशीय जल परिवहन
जेएएम	जन धन-आधार-मोबाइल
जेईई	संयुक्त प्रवेश परीक्षा
जेजेएम	जल जीवन मिशन
जेएलजी	संयुक्त देयता समूह
जेएसएस	जन शिक्षण संस्थान
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
केएलडी	किलोलीटर प्रति दिन
केपी	क्योटो प्रोटोकोल
कृषि-डीएसएस	कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली
केडब्ल्यूएच	किलोवाट्ट घंटा
एलएंडटी	लार्सन एंड टुब्रो

एलएएमए	लॉग एनलिटिक्स एंड मॉनिटरिंग एप्लीकेशन
एलएएमपी	वृहत क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सोसायटी
एलसीएएफ	लोअर कार्बन एविएशन फ्यूल्स
एलसीओई	बिजली की स्तरीकृत लागत
एलसीआर	चलनिधि कवरेज अनुपात
लीडआईटी	लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन
एलईएडीएस	लोजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स
एलईडी	प्रकाश उत्सर्जक डायोड
एलईडीपी	आजीविका एवं उद्यम विकास कार्यक्रम
एलएफपीआर	श्रम बल भागीदारी दर
एलएचएंडीसी	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण
एलआईएॅफई	पर्यावरण के लिए जीवनशैली
एलएमटी	लाख मीट्रिक टन
एलपीएआई	भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण
एलपीजी	तरल पेट्रोलियम गैस
एलपीआई	लॉजिस्टिक परफोर्मेंस इंडेक्स
एलटी	लाख टन
एलटीडी.	लिमिटेड
एलटी-एलईडीएस	दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति
एलवीएम3	प्रक्षेपण यान मार्क-3
एम एंड ए	विलय और अधिग्रहण
एमएएचएसआर	मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल
एमएआईएस	बाजार पहुँच पहल योजना
एमएएम	मध्यम तीव्र कुपोषण
एमएएनएएस	मानसिक स्वास्थ्य और सामान्य स्थिति संवर्धन प्रणाली
एमसीए	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
एमसीए	मॉडल कन्सेशन अग्रीमेंट
एमसीएक्स	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज
एमईडीपी	सूक्ष्म उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम
एमईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्थाएं
एमएफ	म्यूच्यूअल फंड
एमजीएनआरईजीए	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमआईएफ	सूक्ष्म सिंचाई निधि
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएमएलपी	मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क
एमएमटी	मिलियन मीट्रिक टन
एमएनआरई	बहुराष्ट्रीय उद्यम
एमओएएफडब्ल्यू	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
एमओई	शिक्षा मंत्रालय

एमओएचयूए	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
एमओओसी	व्यापक खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम
एमओपी	म्यूरियेट ऑफ पोटाश
एमओआरटीएच	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एमओएसपीआई	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओवीसीडीएनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
एमपीसी	मौद्रिक नीति समिति
एमपीसीई	प्रति व्यक्ति मासिक व्यय
एमपीआई	बहुआयामी निर्धनता सूचकांक
एमआरएल	प्रमुख रेल संपर्क
एमआरएल	प्रमुख ग्रामीण संपर्क
एमआरओ	मरम्मत अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल
एमएससीएस	बहु-राज्य सहकारी संस्थाएं
एमएसएफ	सीमांत स्थायी सुविधा
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमएसपी	खनिज सुरक्षा भागीदारी
एमटीसीओ2ई	मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य
एमटीएम	विपणन हेतु चिह्नित
एमटीओई	मिलियन टन तेल समतुल्य
एमटीपीए	मिलियन टन प्रति वर्ष
एमवीए	मेगा वोल्ट एम्पीयर
एमडब्लूईक्यू	मेगा वाट समतुल्य
एमडब्ल्यू	मेगा वाट
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएडीसीपी	राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
नेफेड	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ
एनएपीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना
एनएपीएस	राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना
एनएआरसीएल	राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लि.
एनएएस	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी
एनएएस	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण
एनएएसएससीओएम	नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज
एनएवीएलसी	नेवीगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसीज	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एनसीएपी-2016	राष्ट्रीय नागर विमानन नीति
एनसीसीएफ	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ
एनसीडीसी	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम

एनसीडीईएक्स	नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज
एनसीईएल	राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
एनसीएफ-एसई	विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा
एनसीआईपी	राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम
एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
एनसीओएल	राष्ट्रीय सहकरी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
एनसीक्यूजी	नया सामूहिक प्रमात्रीकृत लक्ष्य
एनसीआर	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनसीआरएफ	राष्ट्रीय ऋण ढांचा
एनसीएस	राष्ट्रीय कैरियर सेवा
एनसीटीएफ	राष्ट्रीय व्यापार सुविधाकरण समिति
एनसीवीईटी	राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद
एनडीए	अप्रकटीकरण अनुबंध
एनडीसी	राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान
एनडीएलएम	राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन
एनडीटीएसपी	राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्ट-अप नीति
एनईईआर	नामिक प्रभावी विनिमय दर
एनईईटी	राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा
एनईपी	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एनईपी	राष्ट्रीय बिजली योजना
एनएफए	शुद्ध विदेशी परिसंपत्तियां
एनएफएचएस	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनएफएसए	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एनएफएसएम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
एनएफएसएम-ओएस-ओपी	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- तिलहन एवं पाम ऑयल
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
एनएच	राष्ट्रीय राजमार्ग
एनएचए	राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा
एनएचएआई	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
एनएच	राष्ट्रीय राजमार्ग
एनआईडीएचआई	राष्ट्रीय एकीकृत आतिथ्य उद्योग डेटाबेस
एनआईईएसबीयूडी	राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान
एनआईआई	शुद्ध ब्याज आय
एनआईएम	शुद्ध ब्याज उपांत
एनआईपी	नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन
एनआईटीआई	नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
एनएलबीसी	नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल
एनएलएम	राष्ट्रीय पशुधन मिशन
एनएलपी	राष्ट्रीय रसद नीति

एनएमसीई	नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज
एनएमसीजी	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
एनएमएचएस	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनएमपी	राष्ट्रीय मुद्रीकरण प्रक्रिया
एनएमएसए	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन
नॉन-कन्वेंशनल	गैर-पारंपरिक
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीडीडी	राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम
एनपीके	नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम
एनपीपी	राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन योजना
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनएसडीएल	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
एनएसआईएल	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड
एनएसक्यूएफ	राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा
एनएसएसओ	नेशनल सिंगल साइन-ऑन
एनएसटीआई	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान
एनएसवीए	नारी शक्ति वंदन अधिनियम
एनटीआर	गैर-कर राजस्व
एनडब्ल्यूज	राष्ट्रीय जलमार्ग
ओएंडएम	प्रचालन और रखरखाव
ओसीईएन	ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क
ओसीएमएस	ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली
ओडीए	शासकीय विकास सहायता
ओडीएफ	खुले में शौच से मुक्ति
ओडीओपी	एक जिला एक उत्पाद
ओडीआर	ऑनलाइन विवाद समाधान
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन
ओईएम	मूल उपकरण विनिर्माता
ओएफसी	ऑप्टिकल फाइबर केबल
ओएफपीओ	ऑफ-फार्म उत्पादक संगठन
ओएफएसटीईडी	ऑफिस फॉर स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन, चिल्ड्रन सर्विसेज एंड स्किल्स
ओआई	अन्य मध्यक्षेप
ओएनडीसी	ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स
ओएनजीसी	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम
ओएनओआरसी	एक राष्ट्र एक राशन कार्ड
ओओआई	अन्य प्रचालनिक आय
ओएसओडब्लूओजी	एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड
ओटीसी	ओवर-द-काउंटर
पीए	अनंतिम वास्तविक आंकड़े
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

पीएआर	परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी रिपोर्टिंग
पीएआरएकेएच (परख)	परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनलिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डवलपमेंट
पीएआरआईवीईएसएच (परिवेश)	प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉंसिव फेसिलिटेशन बाइ इंटरैक्टिव, वर्चुअस एंड एन्वायरनमेंट सिंगल विंडो हब
पीएटी	कर के बाद लाभ
पीएटी	निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार
पीएटी	पोषण भी पढाई भी
पीसीआई	प्रति व्यक्ति आय
पीडीएमसी	पर ड्रॉप मोर क्रॉप
पीई	अनंतिम अनुमान/प्राक्कलन
पीएफसीई	निजी अंतिम उपभोग व्यय
पीएफएम एस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीएफआरएआई	भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पीएचएच	प्राथमिकता वाले परिवार
पीआईबी	पत्र सूचना कार्यालय
पीकेवीवाई	परम्परागत कृषि विकास योजना
पीएलएफएस	आवधिक श्रम-बल सर्वेक्षण
पीएलआई	उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन
पीएलआई योजना	उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना
पीएलआईएसएफपीआई	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना
पीएम-पोषण	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण
पीएम-स्वनिधि	प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि
पीएम-आशा	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान
पीएम-आवास	प्रधानमंत्री आवास योजना
पीएमएवाई-यू	प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी
पीएमईजीपी	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पीएमएफबीवाई	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
पीएमएफएमई	पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण
पीएमजी	परियोजना निगरानी समूह
पीएमजीकेएवाई	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
पीएमजीकेवाई	पीएम गरीब कल्याण योजना
पीएमजीएस-एनएमपी	पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान
पीएमजीएसवाई	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पीएमआई	क्रय प्रबंधक सूचकाकं
पीएमजेजेबीवाई	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
पीएमजेजेवाई	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना
पीएम-किसान	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
पीएमकेएमवाई	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
पीएमकेएसवाई	प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना
पीएमकेएसवाई	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
पीएम-केयूएसयूएम् (कुसुम)	प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान

पीएमकेवीवाई	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
पीएम-पीआरएएनएएम (प्रणाम)	पीएम-धरती माता के पुनरुद्धार, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार कार्यक्रम
पीएमएसबीवाई	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
पीएम-श्री	उभरते भारत के लिए प्रधानमंत्री स्कूल
पीएम-एसवाईएम	प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन
पीओएल	पेट्रोलियम, तेल और ल्यूब्रिकेंट
पीपीपी	सार्वजनिक-निजी भागीदारी
पीपीपीएसी	सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति
पीआरएजीएटी(प्रगति)	सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन
पीआरएएसएडी (प्रसाद)	तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान
पीआरएवाईएजी (प्रयाग)	यमुना, गंगा और उनकी सहायक नदियों के वास्तविक समय विश्लेषण के लिए मंच
पीएसएफ	मूल्य स्थिरीकरण कोष
पीएसएलवी	ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान
पीएसपी	पम्प्ड स्टोरेज परियोजना
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
पीवी	फोटोवोल्टिक
पीवीटीण	निजी
पीवीटीजी	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
क्यूआईपी	अर्हित संस्थागत प्लेसमेंट
आरएंडडी	अनुसंधान एवं विकास
आरएडी	वर्षा-सिंचित क्षेत्र विकास
आरबीसीएफ	जोखिम-आधारित पूंजी ढांचा
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरबीएसएफ	जोखिम-आधारित पर्यवेक्षी ढांचा
आरसीएस	क्षेत्रीय संपर्क योजना
आरडीएन	पोषक तत्वों की अनुशंसित खुराक
आरडीएसएस	पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना
आरई	अक्षय ऊर्जा (नवीकरणीय ऊर्जा)
आरई	संशोधित अनुमान
आरईईआर	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर
आरईई	रेयर अर्थ एलिमेंट्स
आरईआईटी	रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट
आरईएन21	21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क
आरईआरए	भूसंपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम
आरएफ परीक्षण	रेडियो आवृत्ति परीक्षण
आरएफआईडी	रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन
आरजीएम	राष्ट्रीय गोकुल मिशन
आरआईएस	अनुसंधान और सूचना प्रणाली
आरकेएम	मार्ग किलोमीटर
आरकेवीवाई	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
आरएमबीएस	आवासीय बंधक-समर्थित प्रतिभूतियाँ

आरएमएस	रबी विपणन सीजन
आरओए	परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ
आरओई	इक्विटी पर लाभांश
आरपीएल	रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग
आरआरटीएस	रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम
आरएसईटीआई	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
आरटीसी	चौबीस घंटे
एसएएएस	सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर
एसएटीएचआई	आतिथ्य उद्योग के लिए मूल्यांकन, जागरूकता और प्रशिक्षण प्रणाली
एसए एफ	संधारणीय विमानन ईंधन
एसए एम	गंभीर तीव्र कुपोषण
एसएएमएआरटीएच	ताप विद्युत संयंत्र में कृषि-अवशेषों के उपयोग पर संधारणीय कृषि मिशन
एसएपीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना
एसएआरएफएईएसआई	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन
एसबीएम-जी	स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एससीएम	स्मार्ट सिटी मिशन
एस सी ओ	शंघाई सहयोग संगठन
एस सी आर ए	प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम
एसडीएफ	स्टैंडिंग डिपाजिट फैसिलिटी
एसडीजी	संधारणीय विकास लक्ष्य
एसडीएससी-एसएचएआर	सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा
एसईबीआई	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
एसईडब्ल्यूए	स्व-नियोजित महिला संघ
एसईजेड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएफएसी	लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ
एसएफबी	लघु वित्त बैंक
एसएफटी	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन
एसएचसी	सेकेंडरी हेल्थकेयर सेंटर
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसएचजी-बीएलपी	एसएचजी-बैंक लिंकेज प्रोग्राम
एसआईबी	व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक
एसआईडीबीआई	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एसआईआईसी	स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर
एसकेयू	स्टॉक कीपिंग यूनिट्स
एसएलआर	सांविधिक तरलता अनुपात
एसएमएएम	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन
एसएमआर	स्माल मॉड्यूलर रिएक्टर
So_2	सल्फर डाइऑक्साइड
एसपी	विशेष परियोजनाएँ
एसपीईसीएस	इलेक्ट्रॉनिक अवयव और सेमीकंडक्टर विनिर्माण संवर्द्धन योजना

एसपीएस	सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी
एसपीएसई	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
एसपीवी	विशेष प्रयोजन वाहन
एसआरबी	जन्म के समय लिंगानुपात
एसआरओ	स्व-विनियामक संगठन
एसआरएस	स्पेक्ट्रम विनियामक सैंडबॉक्स
एसएसई	सोशल स्टॉक एक्सचेंज
एसएसएलवी	लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान
एसटीएआरएस	राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणामों को सुदृढ़ करना
एसटीईएम	विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित
एसटीपी	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
एसटीटी	अल्पकालिक प्रशिक्षण
एसवीएएमआईटीवीए	गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण
एसवीईपी	स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम
एसडब्ल्यएएमआईएच	किफायती और मध्यम आय वाले आवासन के लिए विशेष विंडो
एसडब्ल्यूएवाईएएम	स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स
एसडब्ल्यूआईएफटी	व्यापार की सुविधा के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस
टीएएस	लेन-देन सलाहकार
टीबीटी	व्यापार में तकनीकी बाधाएँ
टेलीकॉम	दूरसंचार
टीईपीए	व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता
टीएचई	कुल स्वास्थ्य व्यय
टीआईईएस	निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना
टीपीए	त्रिपक्षीय समझौता
टीपीडी	टन प्रति दिन
टीआरईडीएस	व्यापार प्राप्य छूट परिदान प्रणाली
टीटीडीआई	यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक
यूएई	संयुक्त अरब अमीरात
यूडीएएन (उडान)	उड़े देश का आम नागरिक
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूएचडब्ल्यूसी	शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र
यूजेएएलए	सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति
यूएलबीएस	शहरी स्थानीय निकाय
यूएलआईपी	एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म
यूएलएलएएस	समाज में सभी के लिए आजीवन अधिगम बोध
यूएलपीआईएन	विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या
यूएमएएनजी	नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
यूएनसीटीएडी	संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनईएससीएपी	एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग

यूएनएफसीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन
यूएनएफपीए	जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष
यूनिसेफ	संयुक्त राष्ट्र बाल कोष
यूपीएचसी	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
यूआर	बेरोजगारी दर
यूआरपी	उद्यम पंजीकरण पोर्टल
यूएसडी	संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर
यूएसओएफ	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि
यूटी	संघ राज्यक्षेत्र
यूवी	उपयोगिता वाहन
वीबीएसवाई	विकसित भारत संकल्प यात्रा
वीसीएम	स्वैच्छिक कार्बन बाजार
वीजीएफ	वायबिलिटी गैप फंडिंग
वीआईजेड	विडेरे लिसेट (अर्थात)
वीआरआर	परिवर्तनीय रेपो दर
वीआरआरआर	वेरियबल रेट रिर्वस रेपो
डबल्यूएएसएच	जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य
डब्ल्यूईएफ	विश्व आर्थिक मंच
डब्ल्यूईओ	वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक
डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
वाई–फाई	वायरलेस फिडेलिटी
डबल्यूआईएनडीएस	मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम
डब्ल्यूआईपीओ	विश्व बौद्धिक संपदा संगठन
डबल्यूआईएसई–केआईआरएएन	विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएँ – अनुसंधान उन्नति में ज्ञान की भागीदारी
डब्ल्यूआईटीई–जोन	वायरलेस परीक्षण क्षेत्र
डब्ल्यूआईटीएस	विश्व एकीकृत व्यापार समाधान
डब्ल्यूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यूपीआर	कामगार जनसंख्या अनुपात
डब्ल्यूक्यूएमआईएस	जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली
डब्ल्यूएसए	मार्ग–पार्श्विक सुविधाएं
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन
येस–टेक	प्रौद्योगिकी के आधार पर उपज का अनुमान
वाईओवाई	वर्ष–दर–वर्ष
जेडसीजेडपी	जीरो कूपन जीरो प्रिन्सिपल

तालिकाओं की सूची

तालिका सं.	तालिका	पृष्ठ सं.
तलिका I.1	महामारी से प्रेरित संकुचन के बाद से तेज वृद्धि	15
तलिका I.2	केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय का व्यापक आधार पर परिनियोजन (मान हजार करोड़ रुपये में)	20
तालिका II.1	घरेलू ऋण और जमा दरों में संचरण में तेजी	38
तालिका II.2	वित्तीय समावेशन और वित्तीय शिक्षा के संकेतकों में भारत का प्रदर्शन	50
तालिका II.3	वित्तीय समावेशन और वित्तीय शिक्षा पैरामीटरो की क्रास-कंट्री तुलना	50
तालिका II.4	भारत में दूसरा सबसे बड़ा माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र है	54
तालिका II.5	विभिन्न देशों में बाजार पूंजीकरण से सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात	59
तालिका IV.1	भारत के व्यापार के प्रमुख पहलू	97
तालिका IV.2	सेवा व्यापार का लचीला प्रदर्शन	107
तालिका IV.3	भारत के प्रमुख विदेशी ऋण संकेतक: स्थिरता का संक्षिप्त विवरण	138
तालिका VI.1	भारत में कार्बन बाजार की संस्थागत संरचना	186
तालिका VII.1	सामान्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवा व्यय में रुझान	196
तालिका VII.2	प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएं	206
तालिका VII.3	भारत में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	211
तालिका VII.4	स्कूली शिक्षा में सरकारी पहल	219
तालिका VII.5	स्कूल के बुनियादी	223
तालिका VII.6	विभिन्न श्रेणियों से उच्च शिक्षा में नामांकन	226
तालिका VII.7	ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता	239
तालिका VII.8	एमजीएनआरईजीएस पर प्रमुख संकेतक	241
तालिका VIII.1	भारतीय कारखाने प्रतिस्पर्धी प्रति-श्रमिक स्थान मानकों को अपनाकर अधिक श्रमिकों को काम पर रख सकते हैं	270
तालिका VIII.2	कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रगति	291
तालिका X.1	कोयले के उत्पादन, खपत और आयात में वृद्धि	329
तालिका X.2	फेम योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत प्रोत्साहित वाहनों की संख्या	338
तालिका X.3	ऋण परिनियोजन में उद्योग-वार वृद्धि	344
तालिका X.4	भारत में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथ्य: वित्त वर्ष 19 से वित्त वर्ष 21 औसत	345
तालिका XI.1	यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, 2024 में भारत की रैंकिंग 39 हुई	363
तालिका XII.1	अवसंरचना से संबंधित एफडीआई: प्रमुख अनुपात	383

चार्ट की सूची

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट I.1	विकास: संदर्भ मायने रखता है वैश्विक अर्थव्यवस्था की व्यापक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति	2
चार्ट I.2	वैश्विक अर्थव्यवस्था द्वारा मजबूत वृद्धि दर्ज किया जाना	3
चार्ट I.3	सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं महामारी-पूर्व जीडीपी स्तर को पार कर चुकी है	4
चार्ट I.4	वैश्विक पीएमआई भी मजबूत विकास गति की पुष्टि करता है	4
चार्ट I.5	वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला दबाव में कमी	5
चार्ट I.6	अक्टूबर 2023 से भू-राजनीतिक जोखिम धारणाएं नरम हो गई हैं	5
चार्ट I.7	विभिन्न देशों में मुद्रास्फीति का दबाव कम हो रहा है	5
चार्ट I.8	नीतिगत दरें ऊंची रही	5
चार्ट I.9	वैश्विक कमोडिटी सूचकांकों में नरमी	6
चार्ट I.10	अमेरिकी यील्ड कर्व का उलटा होना, जो ब्याज दरों में कटौती की बढ़ी हुई उम्मीद को दर्शाता है	7
चार्ट I.11	अमेरिका में राष्ट्रीय वित्तीय स्थितियाँ बेहतर हुई हैं	7
चार्ट I.12	विभिन्न देशों में राजकोषीय घाटा बढ़ा	7
चार्ट I.13	2023 में वैश्विक ऋण में बढ़ोतरी	7
चार्ट I.14	2023 में व्यापारिक वृद्धि में गिरावट आई	8
चार्ट I.15	एफडीआई प्रवाह में भी कमजोर वृद्धि दर्ज की गई	8
चार्ट I.16	आर्थिक विकास में गति को आगे बढ़ाना	9
चार्ट I.17	व्यापक-आधारित विकास	9
चार्ट I.18	निवेश से विकास को बढ़ावा मिलने के कारण निजी खपत स्थिर	9
चार्ट I.19	महामारी के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों की बिक्री में अच्छी वृद्धि हुई है	10
चार्ट I.20	उत्पादक क्षमता निर्माण पर सामान्य सरकार का अधिक ध्यान	11
चार्ट I.21	निजी पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि	11
चार्ट I.22	भौतिक परिसंपत्तियों के रूप में घरेलू बचत में वृद्धि	11
चार्ट I.23	शीर्ष 8 शहरों में रिकॉर्ड आवास बिक्री	11
चार्ट I.24	निवेश मांग को पूरा करने वाले एससीबी	12
चार्ट I.25	बड़ी कंपनियां कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार का लाभ उठा रही है	12
चार्ट I.26	जीडीपी में महामारी से पहले की स्थिति में सुधार	13
चार्ट I.27	प्रवृत्ति से अंतर में लगातार कमी	13
चार्ट I.28	उत्पादन क्षमता में कोई स्थायी हानि नहीं	13
चार्ट I.29	कोई स्थायी उपभोग हानि नही	13
चार्ट I.30	निवेश में उछाल आया है	14
चार्ट I.31	औद्योगिक जीवीए महामारी से पहले की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है	14
चार्ट I.32	सेवाओं का जीवीए पिछड़ रहा है	14
चार्ट I.33	लगातार घटता घाटा अनुपात	16
चार्ट I.34	राजकोषीय घाटे का विघटन निवेश उन्मुखीकरण में वृद्धि दर्शाता है	16
चार्ट I.35	कर और गैर-कर राजस्व दोनों से प्रेरित राजस्व प्राप्तियों में लगातार वृद्धि	16
चार्ट I.36	मजबूत प्रत्यक्ष कर वृद्धि से सकल कर राजस्व में जीडीपी अनुपात में वृद्धि	16
चार्ट I.37	वित्त वर्ष 23 और कोविड-पूर्व स्तर की तुलना में करों में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई	17
चार्ट I.38	मजबूत ई-वे बिल उत्पादन मजबूत आर्थिक विकास गति की पुष्टि करता है	17
चार्ट I.39	व्यय का विवेकपूर्ण प्रबंधन	18

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट I.40	केंद्र सरकार के प्रभावी पूंजीगत व्यय और जीडीपी अनुपात में वृद्धि	18
चार्ट I.41	उत्पादक व्यय को प्राथमिकता देना	19
चार्ट I.42	व्यय की गुणवत्ता में सुधार	19
चार्ट I.43	राज्य का जीएफडी जीडीपी के 3 प्रतिशत के निशान से नीचे	21
चार्ट I.44	राज्यों के व्यय की गुणवत्ता में सुधार	21
चार्ट I.45	राज्यों की कुल बकाया देनदारियाँ सकल घरेलू उत्पाद का % की दर से घट रही है	21
चार्ट I.46	राज्यों को अंतरण की प्रगतिशील प्रकृति	22
चार्ट I.47	राज्यों के कर संबंधी प्रयास	22
चार्ट I.48	राज्यों का कुल व्यय	22
चार्ट I.49	राज्यों का राजकोषीय घाटा	22
चार्ट I.50	सामान्य सरकारी देनदारियों और जीडीपी का अनुपात वित्त वर्ष 21 में अपने चरम से नीचे आ गया	23
चार्ट I.51	प्राथमिक घाटा कम हुआ, तथा विकास-ब्याज दर अंतर सकारात्मक बना रहा	23
चार्ट I.52	घटती हुई मुख्य मुद्रास्फीति लेकिन अस्थिर खाद्य मुद्रास्फीति	24
चार्ट I.53	भारत एक उच्च-विकास और निम्न-मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था है	24
चार्ट I.54	वित्त वर्ष 2024 में सीएडी घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 0०7 प्रतिशत रह गया	26
चार्ट I.55	एफपीआई प्रवाह ने सीएडी को वित्तपोषित करने और विदेशी मुद्रा भंडार बनाने में सहायता की	26
चार्ट I.56	अप्रैल 2023 से जून 2024 तक रुपया सबसे स्थिर मुद्राओं में से एक था	26
चार्ट I.57	लगभग 11 महीने के आयात को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार	26
चार्ट I.58	बाह्य अनिश्चितता में वृद्धि के बावजूद मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में कमी	27
चार्ट I.59	विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत उनकी शुरुआत से लाभार्थियों की संख्या	30
चार्ट I.60	बेरोजगारी दर में गिरावट और श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में सुधार	30
चार्ट I.61	ग्रामीण-शहरी असमानता में कमी	31
चार्ट I.62	बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा दर्शाई गई जनसंख्या का प्रतिशत घट गया है	31
चार्ट II.1	आरक्षित मुद्रा (एम0) में वृद्धि में नरमी	35
चार्ट II.2	ब्रॉड मनी (एम3) में वृद्धि	36
चार्ट II.3	वित्त वर्ष 24 में उच्च मनी मल्टीप्लायर, जो बाजार में अधिक तरलता का संकेत देता है	36
चार्ट II.4(क)	तरलता की स्थिति	37
चार्ट II.4(ख)	पॉलिसी कॉरिडोर और ओवरनाइट कॉल मनी दर	37
चार्ट II.5	एससीबी द्वारा ऋण वितरण में दोहरे अंकों की वृद्धि	39
चार्ट II.6	विभिन्न क्षेत्रों में बैंक ऋण में व्यापक वृद्धि	41
चार्ट II.7(क)	एससीबी के जीएनपीए में गिरावट	42
चार्ट II.7(ख)	सीआरएआर आवश्यक मानदंडों से काफी ऊपर	42
चार्ट II.8(क)	परिसंपत्तियों पर रिटर्न (वार्षिकीकृत)	43
चार्ट II.8(ख)	इक्विटी पर रिटर्न (वार्षिकीकृत)	43
चार्ट II.9	एससीबी का उच्च शुद्ध ब्याज मार्जिन	43
चार्ट II.10(क)	अनुमोदित समाधान योजना के माध्यम से सुलझाए गए मामलों की संख्या	46
चार्ट II.10(ख)	लेनदारों द्वारा वसूली	46
चार्ट II.11	ग्रामीण एमएफआई उधारकर्ताओं की बढ़ती हिस्सेदारी	55
चार्ट II.12	पिछले कुछ वर्षों में एमएफआई द्वारा ऋण वितरण में वृद्धि	55
चार्ट II.13	भारतीय शेयर बाजार का उल्लेखनीय प्रदर्शन	58
चार्ट II.14	एसआईपी निवेश में वृद्धि	61
चार्ट II.15	भारतीय वित्तीय प्रणाली में तनाव में कमी एफएसएसआई में परिलक्षित हुई	73

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट II.16	वित्तीय क्षेत्रों में तनाव के स्तर में व्यापक गिरावट	73
चार्ट III.1	2023 में भारत की मुद्रास्फीति ईएमडीईएस से कम	76
चार्ट III.2	ईएमडीईएस की तुलना में एई की मुद्रास्फीति कम होती है	76
चार्ट III.3	भारत अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य के करीब है	74
चार्ट III.4	भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य से सबसे कम औसत विचलन (2021-2023) है	74
चार्ट III.5	महामारी के बाद से खुदरा हेडलाइन मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 24 में सबसे कम थी	78
चार्ट III.6	हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति में गिरावट की प्रवृत्ति	78
चार्ट III.7	'वस्त्र और जूते' और 'ईंधन और बिजली' समूहों ने वित्त वर्ष 24 में मुद्रास्फीति दर में पर्याप्त गिरावट देखी	79
चार्ट III.8	वित्त वर्ष 24 में घटता वैश्विक ऊर्जा सूचकांक	79
चार्ट III.9	कीमत में कटौती/सब्सिडी के कारण एलपीजी मुद्रास्फीति दर में कमी	79
चार्ट III.10	कीमत में कमी के उपयों के कारण पेट्रोल और डीजल की मुद्रास्फीति दर में गिरावट	79
चार्ट III.11	कोर मुद्रास्फीति का इसके घटकों में विभाजन	80
चार्ट III.12	वित्त वर्ष 2024 में कोर मुद्रास्फीति 4 साल के निचले स्तर पर आ गई	80
चार्ट III.13	कोर मुद्रास्फीति को कम करने में मौद्रिक नीति संचालन स्पष्ट है	80
चार्ट III.14	वित्त वर्ष 2024 में कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति का योगदान महामारी से पहले की तुलना में कम रहा	81
चार्ट III.15	कम आवास किराया के कारण कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति 9 वर्ष में सबसे कम	81
चार्ट III.16	।ॅ में लगातार कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति का जोखिम	82
चार्ट III.17	उपभोक्ता टिकाऊ मुद्रास्फीति पूर्व-महामारी स्तर लेवल पर बंद	82
चार्ट III.18	सोने और कपड़े की कीमतों में वृद्धि ने टिकाऊ वस्तुओं में मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया	82
चार्ट III.19	(क) और (ख): परिवहन घटक में गिरावट के कारण कोर उपभोक्ता गैर-टिकाऊ मुद्रास्फीति में कमी आई	83
चार्ट III.20	खाद्य मुद्रास्फीति में खाद्य पदार्थों का योगदान	84
चार्ट III.21	सब्जियों, दालों और मसालों में बढ़ी हुई मुद्रास्फीति दर	84
चार्ट III.22	वैश्विक और घरेलू खाद्य तेल की कीमतों का सह-संचलन	86
चार्ट III.23	चीनी पर निर्यात प्रतिबंध से भारत में चीनी की कीमतें स्थिर हो गई	86
चार्ट III.24	वित्त वर्ष 24 में खुदरा मुद्रास्फीति (%) में अंतरराज्यीय बदलाव	87
चार्ट III.25	वित्त वर्ष 24 में ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति अंतर में अंतरराज्यीय बदलाव	88
चार्ट III.26	ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति दर में अंतरराज्यीय भिन्नताएं अधिक है	88
चार्ट III.27	उच्च मुद्रास्फीति दर वाले राज्य व्यापक ग्रामीण-शहरी अंतर दिखाते हैं	88
चार्ट III.28	2025 में वैश्विक वस्तु की कीमतों में प्रत्यशित गिरावट	89
चार्ट IV.1	वैश्विक वस्तु व्यापार में वृद्धि: वास्तविक और पूर्वानुमान	95
चार्ट IV.2	बढ़ती व्यापार खुलापन संबंधी संकेतक	97
चार्ट IV.3	वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी	98
चार्ट IV.4	पिछले दस वर्षों में भारत का समग्र व्यापार प्रदर्शन	98
चार्ट IV.5	भारत का वस्तु व्यापार प्रदर्शन	99
चार्ट IV.6	विभिन्न वर्गीकरणों में वस्तु निर्यात की संरचना	100
चार्ट IV.7	भारत के खिलौनों के निर्यात और आयात में रुझान	101
चार्ट IV.8	बढ़ता रक्षा निर्यात	102
चार्ट IV.9	फुटवियर निर्यात में रुझान	102
चार्ट IV.10	बढ़ता घरेलू उत्पादन, घरेलू मांग ओर स्मार्टफोन का निर्यात	103
चार्ट IV.11	भारत के निर्यात लक्ष्य	104
चार्ट IV.12	विभिन्न वर्गीकरणों में व्यापारिक वस्तुओं के आयात की संरचना	105
चार्ट IV.13	पिछले दस वर्षों में भारत के सेवा व्यापार का उल्लेखनीय प्रदर्शन	106

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट IV.14	भारत में जीसीसी की उल्लेखनीय वृद्धि	108
चार्ट IV.15	सकल व्यापार में जीवीसी से संबंधित व्यापार की बढ़ती हिस्सेदारी	111
चार्ट IV.16	जीवीसी से संबंधित व्यापार में विभिन्न विनिर्माण उप-क्षेत्रों की हिस्सेदारी	111
चार्ट IV.17	जीवीसी से संबंधित व्यापार में विभिन्न सेवा उप-क्षेत्रों की हिस्सेदारी	112
चार्ट IV.18	शुद्ध पिछड़ी जीवीसी भागीदारी की हिस्सेदारी में वृद्धि	112
चार्ट IV.19	भारत के डवेल टाईम में कमी	120
चार्ट IV.20	वित्त वर्ष 24 के दौरान सीएडी में सुधार	121
चार्ट IV.21	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाता शेष: भारत बनाम चुनिंदा देश	121
चार्ट IV.22	भारत 2023 में विश्व में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता के रूप में उभरा	122
चार्ट IV.23	उच्चतर प्रेषण से माल व्यापार घाटे की भरपाई होगी और सीएडी स्थिर होगा	123
चार्ट IV.24	आगे इस सहसंबंध की पुष्टि करती है, क्योंकि तेल की कीमतों में वृद्धि की अवधि उच्च प्रेषण से जुड़ी होती है	124
चार्ट IV.25	भारतीय रुपये/अमेरिकी डालर और प्रेषण का सकारात्मक संघ	124
चार्ट IV.26(क)	भारत में निवल एफपीआई प्रवाह	125
चार्ट IV.26(ख)	वित्त वर्ष 24 के दौरान उभरते बाजार के साथियों के बीच निवल इक्विटी प्रवाह	125
चार्ट IV.27(क)	प्रत्यावर्तन में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 24 में निवल एफडीआई प्रवाह में कमी	126
चार्ट IV.27(ख)	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निवल एफडीआई प्रवाह में गिरावट	126
चार्ट IV.28	उद्योग और सेवाओं दोनों में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में प्रवृत्ति	127
चार्ट IV.29(क)	कुल एफडीआई में वास्तविक और डिजिटल एफडीआई का हिस्सा	128
चार्ट IV.29(ख)	टेक स्टार्ट-अप में वैश्विक पूंजी प्रवाह	128
चार्ट IV.30(क)	भविष्य के एफडीआई अंतर्वाह के भविष्यवक्ता के रूप में निवेश का लक्ष्य	128
चार्ट IV.30(ख)	एफडीआई प्रवाह और सभी क्षेत्रों के एफडीआई की एकाग्रता के बीच सकारात्मक सहसंबंध	128
चार्ट IV.31	भारत ने वित्त वर्ष 24 में विदेशी मुद्रा भंडार रिजर्व में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है	132
चार्ट IV.32	भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता: अंतर-राष्ट्र परिप्रेक्ष	132
चार्ट IV.33	रुपया/अमेरिकी डालर विनिमय दर की अस्थिरता	133
चार्ट IV.34	वित्त वर्ष 24 में अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में अन्य देशों की विनिमय दर में अस्थिरता	133
चार्ट IV.35	वित्त वर्ष 24 के दौरान आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्राओं की निवल खरीद (+) और बिक्री (-) संबंधी रुझान	134
चार्ट IV.36	40-मुद्रा एनईईआर और आरईईआर (व्यापार-आधारित भार) के सूचकांक का उतार-चढ़ाव	134
चार्ट IV.37(क)	निवल आईआईपी और जीडीपी के प्रतिशत के रूप मे	137
चार्ट IV.37(ख)	आस्ति देनदारियों का अनुपात	137
चार्ट IV.38	स्थिर भारत की विदेशी ऋण स्थिति और सुगम संकेतक	138
चार्ट VI.1	ईंधन स्रोतों के संदर्भ में 2022-23 में भारत का प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति मिश्रण और 2024 में स्थापित विद्युत क्षमता	174
चार्ट VI.2	2017 में भारत में कुल 37,000 पेटाजूल (पीजे) ऊर्जा प्रवाह	175
चार्ट VI.3	नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) की चौबीसों घंटे (आरटीसी) आपूर्ति	176
चार्ट VI.4	भारत में प्रति व्यक्ति भूमि जी-20ए 2021 में सबसे कम है	181
चार्ट VI.5	महत्वपूर्ण खनिज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का भौगोलिक वितरण, 2023	183
चार्ट VI.6	2020 और 2023 में देश द्वारा परिष्कृत सामग्री उत्पादन का हिस्सा	183
चार्ट VI.7	पिछले कुछ वर्षों में मैग्नेट रेयर अर्थ्स का भौगोलिक संकेन्द्रण	184
चार्ट VII.1(क)	भारत में वार्षिक सीएसआर व्यय	202
चार्ट VII.1(ख)	कुल सीएसआर व्यय	202
चार्ट VII.2(क)	बहुआयामी गरीबी का हैडकाउंट अनुपात	204

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट VII.2(ख)	बहुआयामी गरीबी की तीव्रता	204
चार्ट VII.3	बहुआयामी गरीब आबादी में अभावों में कमी	204
चार्ट VII.4	एमपीसीई में सीएजीआर: 2011-12 से 2022-23	206
चार्ट VII.5(क)	कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय और जेब से किया गया व्यय	214
चार्ट VII.5(ख)	कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सुरक्षा व्यय और निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय	215
चार्ट VII.6	उच्च शिक्षा में कुल छात्रों का नामांकन	225
चार्ट VII.7	2014-15 और 2021-22 के बीच उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन में वृद्धि (प्रतिशत)	226
चार्ट VII.8	अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय	230
चार्ट VII.9	नेचर इंडेक्स में शीर्ष दस देशों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले शोध पत्रों में योगदान	231
चार्ट VII.10	सरकार, व्यवसाय उद्यम और उच्च शिक्षा क्षेत्र की भागीदारी, 2020	231
चार्ट VII.11	ग्रामीण गतिविधि का समग्र संकेतक	241
चार्ट VII.12	राज्यों को जारी की गई एमजीएनआरईजीएस निधि का अनुपात और उनकी गरीब आबादी का अनुपात	243
चार्ट VII.13	बेरोजगारी दर (प्रति 1000) और वित्त वर्ष 23 में जारी एमजीएनआरईजीएस फंड	244
चार्ट VII.14	वर्षों से नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रदर्शन	245
चार्ट VII.15	एसडीजी में भारत की प्रगति	251
चार्ट VII.16	वर्षों से नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्सपर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रदर्शन	252
चार्ट VIII.1(क)	वार्षिक श्रम बाजार संकेतकों में सुधार	256
चार्ट VIII.1 (ख)	वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु	257
चार्ट VIII.2	तिमाही शहरी बेरोजगारी दर में गिरावट	257
चार्ट VIII.3	व्यापक उद्योग प्रभागों द्वारा श्रमिकों का वितरण, 2022-23	258
चार्ट VIII.4	व्यापक श्रेणीवार रोजगार की स्थिति में रुझान	258
चार्ट VIII.5	स्वरोजगार में महिला कार्यबल की हिस्सेदारी	259
चार्ट VIII.6	युवा रोजगार संकेतक	259
चार्ट VIII.7	ग्रामीण भारत महिला एलएफपीआर में वृद्धि	260
चार्ट VIII.8	संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार की प्रवृत्ति	261
चार्ट VIII.9	प्रति कारखाना रोजगार में रुझान	261
चार्ट VIII.10	प्रति श्रमिक मजदूरी में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	261
चार्ट VIII.11	कारखानों और रोजगार की संख्या में शीर्ष छह राज्य	262
चार्ट VIII.12	पांच वर्षों (FY18.FY22) में शीर्ष छह राज्यों में कारखानों में रोजगार में वृद्धि	262
चार्ट VIII.13	छोटे कारखानों की प्रधानता जबकि बड़े कारखाने अधिक रोजगार पैदा करते हैं	263
चार्ट VIII.14	बड़े कारखाने बेहतर मजदूरी का भुगतान करते हैं	263
चार्ट VIII.15	बड़े कारखानों में उच्च रोजगार वृद्धि	264
चार्ट VIII.16	वित्त वर्ष 22 में फैक्ट्री रोजगार में हिस्सेदारी	264
चार्ट VIII.17	5 वर्षों में रोजगार में कुल वृद्धि: वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 22	265
चार्ट VIII.18	बढ़ती ईपीएफओ सदस्यता	265
चार्ट VIII.19	म्न्ध्य्न्न् में निवल पेरोल वृद्धि	266
चार्ट VIII.20	एनसीएस के जरिये जुटाई गई रिक्तियां	266
चार्ट VIII.21	भारत में ओवरटाइम वेज प्रीमियम अधिक है	269
चार्ट VIII.22	राज्यों में महिलाओं के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों की संख्या	270
चार्ट VIII.23(क)	ग्रामीण मजदूरी में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि, पुरुष (वर्तमान मूल्यों पर)	272
चार्ट VIII.23(ख)	ग्रामीण मजदूरी में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि, पुरुष (स्थिर मूल्यों पर)	272

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट VIII.24	गैर-कृषि रोजगार सृजन के लिए वार्षिक आवश्यकता 2024-2036	279
चार्ट VIII.25	पिछले 10 वर्षों में अनुबंधित कर्मचारियों के कार्यबल की बढ़त	280
चार्ट VIII.26	2023 में फ्लेक्सी कार्यबल का क्षेत्रीय वितरण	281
चार्ट VIII.27	बाल देखभाल तक पहुंच की कमी का प्रभाव: एक वैचारिक मॉडल	285
चार्ट VIII.28	औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 15-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के प्रतिशत में वृद्धि	290
चार्ट VIII.29	विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत	290
चार्ट IX.1	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि	300
चार्ट IX.2	प्रमुख खरीफ फसलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकता तुलना	301
चार्ट IX.3	प्रमुख फसलों का उत्पादन	302
चार्ट IX.4	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का (जीसीएफ) एवं जीसीफ की कृषि जीवीए में वृद्धि प्रतिशता के रूप में	303
चार्ट IX.5	प्रमुख फसलों के लिए प्रति टन खाद्यान्न जल उपयोग भारत और विश्व औसत	305
चार्ट IX.6	2021-22 से 2023-24 तक प्रमुख फसलों का एमएसपी	309
चार्ट IX.7	अनाज और पोल्ट्री उत्पादों की वृद्धि	315
चार्ट IX.8	प्रमुख राज्यों द्वारा पंजीकृत एकल राज्य और बहु-राज्य सहकारी समितियों की संख्या	317
चार्ट IX.9	विनिर्माण जीवीए में एफपीआई की हिस्सेदारी और प्रतिशत में एफपीआई की वृद्धि	319
चार्ट IX.10	जारी की गई खाद्य सब्सिड	321
चार्ट X.1	कुल जीवीए में उद्योग और उसके घटकों का हिस्सा	324
चार्ट X.2	उद्योगों और उसके घटकों की वार्षिक वृद्धि	324
चार्ट X.3	भारत विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक	324
चार्ट X.4	स्थिर मूल्यों पर विनिर्माण जीवीए के घटकों में औसत वार्षिक वृद्धि	324
चार्ट X.5	वित्त वर्ष 14 से वित्त वर्ष 23 के बीच कुल जीवीए में निर्मित उत्पादों के जीवीए के हिस्से में परिवर्तन	325
चार्ट X.6	सीमेंट उद्योग की स्थापित क्षमता, उत्पादन क्षमता उपयोग	326
चार्ट X.7	तैयार इस्पात की औसत वार्षिक वृद्धि	327
चार्ट X.8	वित्त वर्ष 24 में तैयार इस्पात की वार्षिक वृद्धि	327
चार्ट X.9	भारत पिछले 5 वर्षों में से 4 वर्षों में तैयार इस्पात का निवल निर्यातक रहा	328
चार्ट X.10	घरेलू खपत के प्रतिशत के रूप में कोयला उत्पादन	329
चार्ट X.11	वित्त वर्ष 24 में फार्मा क्षेत्र का कारोबार, निर्यात और आयात	331
चार्ट X.12	फार्मा क्षेत्र में घरेलू कारोबार वृद्धि	331
चार्ट X.13	कुल कपड़ा (परिधान सहित) जीवीए में गैर-कॉर्पोरेट जीवीए का हिस्सा	333
चार्ट X.14	वस्त्र उत्पादों का कुल निर्यात	333
चार्ट X.15	इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार में वृद्धि	335
चार्ट X.16	ऑटोमोटिव पार्ट्स उद्योग का प्रदर्शन	337
चार्ट X.17	विभिन्न श्रेणियों के ऑटोमोबाइल के उत्पादन में वार्षिक वृद्धि	337
चार्ट X.18	पीएलआई योजना के तहत वास्तविक क्षेत्रवार निवेश	339

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट X.19	सीजीटीएमएसई के तहत स्वीकृत गारंटियों में काफी वृद्धि हुई	340
चार्ट X.20	वित्त वर्ष 19 और वित्त वर्ष 23 के बीच सीपीएसई के प्रदर्शन में सुधार	343
चार्ट X.21	लाभ कमाने वाले सीपीएसई की संख्या में सुधार हुआ है	343
चार्ट X.22	उद्योग में सकल बैंक ऋण के परिनियोजन में वृद्धि	344
चार्ट X.23	भारत में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास व्यय में उप-क्षेत्रों की हिस्सेदारी: वित्त वर्ष 19 से वित्त वर्ष 21	345
चार्ट XI.1	सेवा क्षेत्र में जीवीए की बढ़ती प्रवृत्ति	350
चार्ट XI.2	सेवा क्षेत्र जीवीए में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि में मजबूत गति	350
चार्ट XI.3	कोविड के बाद समग्र जीवीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में मजबूती	351
चार्ट XI.4	सेवा क्षेत्र में व्यापक-आधारित वृद्धि	351
चार्ट XI.5	सक्रिय कंपनियों का आर्थिक गतिविधि-वार विकास	352
चार्ट XI.6	वैश्विक उतार-चढ़ाव के बीच वित्त वर्ष 24 में पीएमआई सेवाओं ने नई उंचाईयों को छुआ	353
चार्ट XI.7	सेवाओं के अंतर्गत चार प्रमुख उप-क्षेत्रों का निर्यात में योगदान	354
चार्ट XI.8	वित्त वर्ष 24 में मजबूत बैंक ऋण निर्माण और वृद्धि	355
चार्ट XI.9	सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में नरमी	356
चार्ट XI.10	रेलवे माल यातायात में निरंतर प्रगति	358
चार्ट XI.11	कोविड के बाद रेलवे यात्री यातायात में सुधार	358
चार्ट XI.12	पोत परिवहन टन भार में निरंतर वृद्धि	359
चार्ट XI.13	हवाई माल यातायात में वृद्धि	360
चार्ट XI.14	हवाई यात्री यातायात में तीव्र वृद्धि	360
चार्ट XI.15	भारत की रैंकिंग में लगातार प्रगति	361
चार्ट XI.16	अंतरर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (आईटीए) की लचीली बहाली	361
चार्ट XI.17	आतिथ्य सांख्यिकी	362
चार्ट XI.18	व्यक्तिगत गृह ऋण में वृद्धि	364
चार्ट XI.19	कार्यों के अनुसार जीसीसी के उरराजस्व का विभाजन	368
चार्ट XI.20	भारत के टेक स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में डीपटेक का उपयोग मुख्यधारा में आ रहा है	370
चार्ट XII.1	केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय और सीपीएसई और राज्य सरकारों के लिए इसकी सहायता में काफी विस्तार हुआ है	381
चार्ट XII.2	राज्य सरकारों के संयुक्त पूंजीगत व्यय में भी जोरदार विस्तार होता है	381
चार्ट XII.3	इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बकाया क्रेडिट: मार्च 2024	382
चार्ट XII.4	मार्च 2020 से मार्च 2024 तक औसत वार्षिक वृद्धि दर	382
चार्ट XII.5	मार्च 2020 से मार्च 2024 तक बकाया ऋण में परिवर्तन में हिस्सा	382
चार्ट XII.6	अवसंरचना क्षेत्रों में विदेशी वाणिज्यिक उधार का अंतर्वाह	382
चार्ट XII.7	घरेलू पूंजी बाजार ऋण स्रोतों के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्रों का वित्तपोषण	383
चार्ट XII.8	इक्विटी जारी करने के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्रों का वित्तपोषण	383
चार्ट XII.9	वित्त वर्ष 24 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में एफडीआई इक्विटी इनफ्लो	383

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट XII.10	सड़क परिवहन में निवेश के लिए कुल पूंजी परिव्यय	385
चार्ट XII.11	छभ नेटवर्क - लेन ऑग्मेंटेशन	385
चार्ट XII.12	रेलवे पर पूंजीगत व्यय	388
चार्ट XII.13	कोच, लोकोमोटिव और वैगनों का वर्षवार उत्पादन	389
चार्ट XII.14	वंदे भारत ट्रेनें और कोचों का उत्पादन	389
चार्ट XII.15	रेलवे विद्युतीकरण की गति	390
चार्ट XII.16	चालू ट्रैक लंबाई	390
चार्ट XII.17	बंदरगाहों, पोत परिवहन और जलमार्गों के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय	391
चार्ट XII.18	प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता	391
चार्ट XII.19	सागरमाला के तहत प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर परियोजना लागत का हिस्सा	392
चार्ट XII.20	सागरमाला के तहत प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित परियोजनाओं का हिस्सा	392
चार्ट XII.21	तटीय शिपिंग और आई डब्ल्यू टी	394
चार्ट XII.22	नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश	398
चार्ट XII.23	ऊर्जा भंडारण क्षमता आवश्यकता	400
चार्ट XII.24	बिजली की स्थापित क्षमता में विभिन्न स्रोतों की प्रतिशत हिस्सेदारी	401
चार्ट XII.25	बिजली उत्पादन में प्रतिशत हिस्सेदारी	401
चार्ट XII.26	अमृत 1.0 और 2.0 के लिए कुल परिव्यय	407
चार्ट XII.27	स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पूरी की गई परियोजनाओं का मूल्य	408
चार्ट XII.28	स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या	408
चार्ट XIII.1	विभिन्न खाद्य उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन	424
चार्ट XIII.2	प्रणाली परिवर्तन की ऊर्जा तीव्रता	425
चार्ट XIII.3	भंडारण लागत से नवीकरणीय ऊर्जा जीवनचक्र लागत बढ़ती है	426
चार्ट XIII.4	डेटा केंद्रों की ओर से बिजली की मांग और अन्य बड़े लोड	428
चार्ट XIII.5	प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अपने कुल और प्रति व्यक्ति जीएचजी उत्सर्जन के साथ	430
चार्ट XIII.6	निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्थाएं और उनका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन	430
चार्ट XIII.7	विभिन्न विचारों के प्रति प्रतिबद्धता वाली अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएँ	433
चार्ट XIII.8	'खाद्य, चारा और खाद्य प्रसंस्करण' के लिए उपयोग की जाने वाली फसल का औसत अंश (1964-1968)	435
चार्ट XIII.9	'खाद्य, चारा और खाद्य प्रसंस्करण' के लिए उपयोग की जाने वाली फसल का औसत अंश (2009-2013)	435
चार्ट XIII.10	लाईफ थीम्स	440
चार्ट XIII.11	प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 2025	443

बाक्स की सूची

बाक्स सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
बॉक्स I.1	जीडीपी, जीवीए और उनके घटकों में वृद्धि सुनिश्चित करती है कि मांग और उत्पादन में कोई स्थायी नुकसान नहीं होता है	13
बॉक्स I.2	सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करना	27
बॉक्स II.1	औपचारिकीकरण के माध्यम से एमएसएमई को बैंक ऋण का प्रवाह बढ़ाना	40
बॉक्स II.2	ठप्प पड़ी रियल एस्टेट परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने और घर खरीदारों के अधिकारों को मजबूत करने में आईबीसी की भूमिका	48
बॉक्स II.3	प्रौद्योगिकी और भारतीय पूंजी बाजार का तालमेल: विकास और दक्षता को बढ़ावा देना	59
बॉक्स II.4	भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज: प्रगति कर रहे हैं	63
बॉक्स III.1	उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति के लिए अत्यधिक जोखिम	81
बॉक्स III.2	वित्त वर्ष 24 में खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक उपाय	85
बॉक्स IV.1	निर्यात बढ़ाने की उत्पाद विशिष्ट सफलता की कहानियाँ	100
बॉक्स IV.2	भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों का सफर	107
बॉक्स IV.3	भारत की जीवीसी भागीदारी और क्षेत्रीय संरचना में परिवर्तन की प्रवृत्ति	110
बॉक्स IV.4	निर्यात हब के रूप में भारतीय जनपद	114
बॉक्स IV.5	प्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक	123
बॉक्स IV.6	चीन प्लस वन रणनीति	130
बॉक्स IV.7	विनिमय दर के व्यापार और वित्तीय चैनल	135
बॉक्स V.1	चीनी विनिर्माण प्रभावशाली शक्ति: ईएमई के लिए खतरा	148
बॉक्स V.2	भारत की बढ़ती मोटापे की चुनौती: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य से अवलोकन सर्वेक्षण	150
बॉक्स V.3	किसान-हितैषी नीतिगत ढांचा	153
बॉक्स V.4	बाजार वित्त का लाभ उठाना: भारत द्वारा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का उत्प्रेरक उपयोग	157
बॉक्स V.5	भारत में राज्य क्षमता निर्माण के लिए मिशन कर्मयोगी का समग्र दृष्टिकोण	160
बॉक्स VI.1	सूक्ष्म सिंचाई पर केस स्टडी- समुदाय-नेतृत्व वाली जल प्रशासन की भूमिका	172
बॉक्स VI.2	ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए उठाए गए कदम	176
बॉक्स VI.3	नवीकरणीय ऊर्जा की चौबीसों घंटे आपूति	179
बॉक्स VI.4	महत्वपूर्ण और दुर्लभ मृदा खनिजों का भौगोलिक संकेन्द्रण	182
बॉक्स VI.5	भारत के लिए संभावित नेट-जीरो की ओर ऊर्जा संक्रमण को समन्वित करने पर रिपोर्ट: सभी के लिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा	184
बॉक्स VI.6	कार्बन बाजारों का विकास	187
बॉक्स VI.7	लाइफ इन एक्शन भारत का अभिनव ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम	188
बॉक्स VII.1	भारत में डेटा गवर्नेंस में बदलाव: डीजीक्यूआई 2ण0 और उससे आगे	199
बॉक्स VII.2	बारामूला और गुमला की 'आकांक्षा' से 'परिवर्तन' की ओर प्रगति	200
बॉक्स VII.3	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व - लाभ और उद्देश्य के बीच सेतु का निर्माण	202
बॉक्स VII.4	स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम और ऋण बाजार के परिणामों पर प्रभाव	216
बॉक्स VII.5	'पोषण भी पढ़ाई भी' : आंगनवाड़ियों में प्री-स्कूल नेटवर्क की स्थापना	218
बॉक्स VII.6	विद्यांजलि: एक स्कूल स्वयंसेवी कार्यक्रम	222
बॉक्स VII.7	भारत की ऑनलाइन शिक्षण संरचना	228
बॉक्स VII.8	महिला सशक्तीकरण के लिए रोजगार की प्रमुखता: कृष्णगिरि की लड़कियां वित्तीय स्वतंत्रता की स्याही से अपनी किस्मत खुद लिख रही हैं	237
बॉक्स VII.9	क्या मनरेगा व्यय ग्रामीण संकट का सूचक है?	242
बॉक्स VII.10	ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली पहल	247
बॉक्स VII.11	ग्रामीण शासन में सुधार के लिए डिजिटलीकरण पहल	250

बाक्स सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
बॉक्स VIII.1	रोजगार सृजन और श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने की पहल	266
बॉक्स VIII.2	रोजगार को बढ़ावा देने के लिए श्रम विनियमों का पुनर्संतुलन	269
बॉक्स VIII.3	रिकार्डो की धुरी और तकनीकी विकल्पों की केंद्रीयता	274
बॉक्स VIII.4	भारत में फ्लेक्सी जॉब मार्केट	280
बॉक्स VIII.5	कृषि-प्रसंस्करण में सह्याद्री की सफलता	282
बॉक्स VIII.6	बेहतर देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण	288
बॉक्स VIII.7	कौशल के लिए उद्योग के साथ साझेदारी	293
बॉक्स VIII.8	पीएम विश्वकर्मा योजना: प्रगति हो रही है	295
बॉक्स VIII.9	शिक्षुता ढांचे को पुन: अंशाकित करना	295
बॉक्स IX.1	पीएमएफबीवाई में हाल ही में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप	306
बॉक्स IX.2	भारत में कृषि जिंसों के लिए भावी बाजार	307
बॉक्स IX.3	जल प्रबंधन में सुधार के लिए नीतिगत हस्तक्षेप-राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव	311
बॉक्स IX.4	लचीला, किसान-हितैषी और पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ उर्वरक सब्सिडी: आगे बढने का सुझाया गया तरीका	312
बॉक्स IX.5	डिजिटल कृषि: डिजिटल क्रांति का मार्ग	314
बॉक्स IX.6	पैक्स के कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली को संबोधित करने के लिए पहल	317
बॉक्स X.1	इस्पात क्षेत्र की पहल	328
बॉक्स X.2	कोयला क्षेत्र में हालिया पहल, चुनौतियां और अवसर	329
बॉक्स X.3	फार्मा क्षेत्र की हालिया पहल, चुनौतियां और दृष्टिकोण	331
बॉक्स X.4	फार्मा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाने और पुनर्कल्पित करने की आवश्यकता	332
बॉक्स X.5	कपड़ा उद्योग में चुनौतियां और सहायक पहल	334
बॉक्स X.6	इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने की पहल	335
बॉक्स X.7	ऑटोमोबाइल और ई-मोबिलिटी के लिए नीतिगत समर्थन	337
बॉक्स X.8	एमएसएमई ऋण योजनाएं	340
बॉक्स X.9	विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए भवन विनियमों की पुनर्कल्पना	341
बॉक्स X.10	ओडीओपी: क्षेत्रीय गौरव और आर्थिक सशक्तिकरण का निर्माण	342
बॉक्स X.11	भारत में स्टार्टअप और नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयास	346
बॉक्स XI.1	पंजीकृत कंपनियों की संख्या में सेवा क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक बना हुआ है	352
बॉक्स XI.2	विश्वास का निर्माण: रेरा किस प्रकार रियल एस्टेट को नया आकार दे रहा है	365
बॉक्स XI.3	ओएनडीसी - डिजिटल वाणिज्य का लोकतंत्रीकरण	373
बॉक्स XII.1	सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देने लिए प्रमुख तंत्र	384
बॉक्स XII.2	सड़क संपर्क बढ़ाने वाली प्रमुख पहल	386
बॉक्स XII.3	सड़क विकास के लिए प्रमुख पहल	387
बॉक्स XII.4	रेलवे संवर्धन के लिए पहल	388
बॉक्स XII.5	रेलवे क्षेत्र में प्रमुख पहल	389
बॉक्स XII.6	बंदरगाहों में प्रमुख पहल	392
बॉक्स XII.7	नए खंड - ड्रोन, लीजिंग और एमआरओ	395
बॉक्स XII.8	पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना	396
बॉक्स XII.9	विद्युत क्षेत्र में कुछ प्रमुख पहल	397
बॉक्स XII.10	नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख कार्यक्रम, परियोजनाएं और पहल	398
बॉक्स XII.11	नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख नीतियाँ	400
बॉक्स XII.12	नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में चुनौतियाँ	400
बॉक्स XII.13	खेल क्षेत्र में प्रमुख कार्यक्रम, परियोजनाएं और पहल	402

बाक्स सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
बॉक्स XII.14	स्टील (बर्तन) बैंक: तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले का विचार	403
बॉक्स XII.15	सैलम: टिकाऊ ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए मिजोरम का एक आदर्श गांव	403
बॉक्स XII.16	प्रमुख कार्यक्रम जल संसाधन क्षेत्र	404
बॉक्स XII.17	जल प्रबंधन क्षेत्र में प्रमुख पहल	406
बॉक्स XII.18	कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन	407
बॉक्स XII.19	स्मार्ट सिटी मिशन	408
बॉक्स XII.20	स्वच्छ भारत मिशन शहरी पर केस स्टडीज	409
बॉक्स XII.21	अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी	410
बॉक्स XII.22	बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग	411
बॉक्स XII.23	भारतनेट परियोजना	412
बॉक्स XII.24	जीआई क्लाउड – 'मेघराज'	414
बॉक्स XII.25	एनएलपी का कार्यान्वयन गति पकड़ रहा है	417
बॉक्स XIII.1	जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों के सापेक्ष भारत की उपलब्धियां	422
बॉक्स XIII.2	डब्ल्युईओ आउटलुक -2023, 2030 तक दुनिया को पटरी पर लाने के लिए एक वैश्विक रणनीति का प्रस्ताव करता है	423
बॉक्स XIII.3	पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय नीतियों के लिए बदलाव करने की इच्छा और भुगतान करने की इच्छा	432

अर्थव्यवस्था की स्थिति: निरंतर आगे बढ़ते हुए

01

अध्याय

आर्थिक मोर्चे पर महामारी के प्रति भारत की नपी-तुली (कैलिब्रेटेड) प्रतिक्रिया में तीन प्रमुख घटक शामिल थे। पहला, बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक व्यय पर ध्यान केंद्रित करना, जिसने नौकरियों और औद्योगिक उत्पादन की मजबूत मांग पैदा करके अर्थव्यवस्था को बचाए रखा और निजी निवेश की धीमी लेकिन जोरदार प्रतिक्रिया को बढ़ावा दिया। इसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र की मजबूत बैलेंस शीट ने तो मदद की ही सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक दशक तक की सहायक पहलों से भी मदद मिली। दूसरा, प्रतिकूलताओं के बीच व्यावसायिक उद्यम और लोक प्रशासन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया, यानी सेवा परिदान के डिजिटलीकरण के रूप में रहा है। सार्वजनिक नीति पर फोकस और डिजिटल प्रौद्योगिकी संबंधी प्रक्रियाओं और रूपरेखाओं के पोषण ने इस अनुत्क्रमणीय और रुपान्तरकारी बदलाव में बहुत मदद की। तीसरा, आत्मनिर्भर भारत अभियान में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और आबादी के विभिन्न वर्गों को लक्षित राहत तथा संरचनात्मक सुधारों के रूप में सन्निहित है, जिससे मजबूत सुधार में मदद मिली और मध्यम अवधि की विकास क्षमता में वृद्धि हुई।

वैश्विक संकटों, आपूर्ति शृंखला में व्यवधानों और मानसून की अनिश्चितता ने बीच-बीच में घरेलू मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ाया, जिसे प्रशासनिक और मौद्रिक नीतिगत प्रतिक्रियाओं द्वारा काफी हद तक नियंत्रित किया गया I सामान्य सरकार ख्र केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर राजकोषीय संतुलन विस्तारशील सार्वजनिक निवेश के बावजूद उत्तरोत्तर बेहतर हुए हैं। प्रक्रियात्मक सुधारों, व्यय नियंत्रण और बढ़ते डिजिटलीकरण द्वारा संचालित कर अनुपालन लाभों ने पे बेहतर संतुलन को हासिल करने में भारत की मदद की। माल की कम वैश्विक मांग के कारण बाहरी संतुलन पर दबाव रहा है, लेकिन मजबूत सेवा निर्यात ने इसे काफी हद तक संतुलित किया है। वैश्विक उत्पादन 2022 की तुलना में अब कुछ हद तक अधिक लचीला है, मुद्रास्फीति के दबाव कम हो रहे हैं और व्यापार में सुधार होने लगा है, बशर्ते आगे कोई भू-राजनीतिक झटके या गतिरोध उत्पन्न न हों। हालाँकि, हाल के दिनों में भू-राजनीतिक विक्षोभ और संघर्ष की संभावनाएँ ही बढ़ी हैं।

इन घटनाक्रमों का विशुद्ध प्रभाव यह रहा है कि पिछले तीन वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है और व्यवस्थित तरीके से विस्तार हुआ है। वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 20 के स्तर से 20 प्रतिशत अधिक थी, यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसे केवल कुछ ही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने हासिल किया है, साथ ही इसने वित्त वर्ष 2025 और उसके बाद भी मजबूत वृद्धि की प्रबल संभावना बनाई है। बेरोजगारी और बहुआयामी गरीबी में कमी और श्रम बल भागीदारी में वृद्धि के साथ विकास समावेशी रहा है। कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025 के लिए आशावादी है, और व्यापक-आधारित और समावेशी विकास की उम्मीद कर रही है।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

1.1 वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिरता से भरे एक वर्ष के बाद, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2023 में अधिक स्थिरता हासिल की। जबकि प्रतिकूल भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से उपजी अनिश्चितता उच्च स्तर पर रही, वैश्विक आर्थिक विकास आश्चर्यजनक रूप से मजबूत रहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)[1] के वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ), अप्रैल 2024 के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2023 में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, यदपि, यह

1 इंटरनेश्नल मोनीटरी फन्ड, वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक, अप्रैल, 2024, पृष्ठ 10 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/04/16/world-economic-outlook-april-2024)

2022[2] और 2011-19 के औसत से मामूली रूप से कम है, लेकिन अप्रैल, 2023 के डब्ल्यूईओ के 2.8[3] प्रतिशत के अनुमान से अधिक है। जिस संदर्भ में 2023 में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की गई है वह 2011-19 की अवधि की तुलना में सपष्ट रूप से भिन्न है। मूल मुद्रास्फीति के बने रहने के कारण मुद्रास्फीति दबाव काफी अधिक रहा है। बढ़ते भू-राजनितिक तनावों, सीमा-पारीय प्रतिबंधों और उन्नत अर्थव्यस्थाओं (एई) में धीमे विकास के कारण वैश्विक व्यापार संयत रहा और आपूर्ति शृंखला दबावों में कमी के बावजूद व्यापार वृद्धि में यथा स्थिति बनी रही। इसके अलावा, विभिन्न देशों में भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और मौद्रिक नीति में बदलावों के परिणामस्वरूप निवेशकों में सतर्कता बढ़ी, जिसके कारण एफडीआई प्रवाहों में कमी आई।

चार्ट I.1: विकास: संदर्भ मायने रखता है
वैश्विक अर्थव्यवस्था की व्यापक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति

स्रोत : वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस, अप्रैल 2024, आईएमएफ, यूएनसीटीएडीस्टेट डेटाबेस, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, इकोनॉमिक पॉलिसी अनसरटेनटी ; नोट्स[4,5]

2 इंटरनेशनल मोनीटरी फन्ड, वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक, अप्रैल, 2023, पृष्ठ 12 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/10/10/world-economic-outlook-october-2023)

3 इंटरनेशनल मोनीटरी फोरम, वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक, अप्रैल, 2023, पृष्ठ 9 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/10/10/world-economic-outlook-october-2023, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/04/11/world-economic-outlook-april-2023)

4 भू-राजनीतिक जोखिम सूचकांक भू-राजनीतिक तनावों को कवर करने वाले समाचार पत्रों के लेखों की गणना पर आधारित है। दस समाचार पत्रों पर विचार किया जाता है। सूचकांक की गणना प्रत्येक महीने प्रत्येक समाचार पत्र में प्रतिकूल भू-राजनीतिक घटनाओं से संबंधित लेखों की संख्या (समाचार लेखों की कुल संख्या के हिस्से के रूप में) की गणना करके की जाती है।

5 वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक रीडिंग सूचकांक के विगत औसत से मानक विचलनों को मापती है। इसमें उच्चतर मान आपूर्ति शृंखला दबाव में वृद्धि को इंगित करता है।

1.2 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) दोनों ने एक वर्ष पहले अनुमानित वृद्धि की तुलना में 2023 में अधिक वृद्धि हासिल की। लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ 2023 में महामारी-पूर्व वास्तविक जीडीपी स्तरों को पार कर चुकी हैं। हालाँकि, विभिन्न देशों में विकास अलग-अलग रहा है, जिससे विचलन बढ़ने की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। भारत और चीन सहित कुछ अर्थव्यवस्थाओं ने 2019 के स्तरों की तुलना में 2023 में 20 प्रतिशत अधिक जीडीपी स्तर प्राप्त किया है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, अमेरिका ने निरंतर विकास गति देखी। हालाँकि, यूरो क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि धीमी बनी हुई है, यद्यपि, मंदी की तीव्रता कम हो गई है।

चार्ट I.2: वैश्विक अर्थव्यवस्था द्वारा मजबूत वृद्धि दर्ज किया जाना

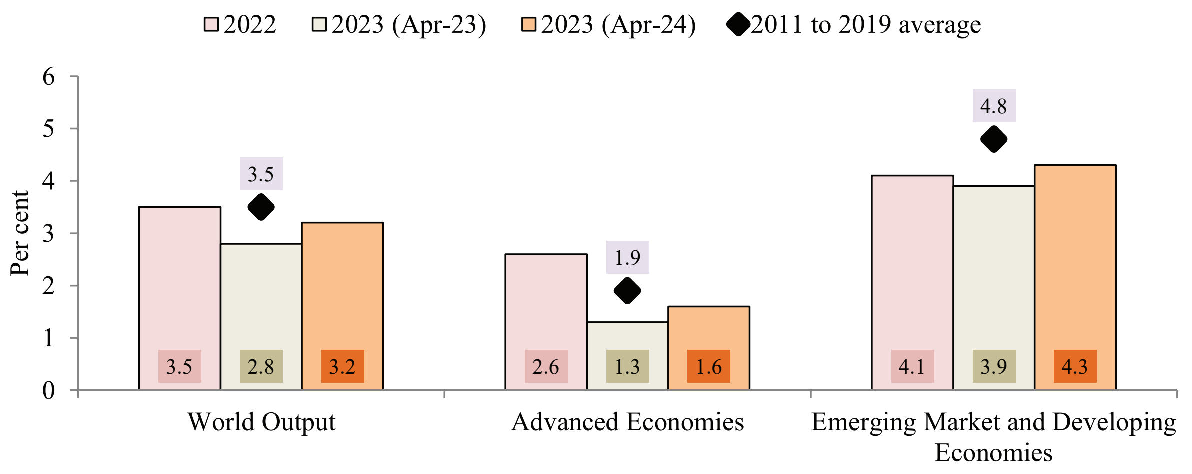

स्रोत: वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक डेटाबेस, अप्रैल 2024 और अप्रैल 2023, आईएमएफ

1.3 अलग-अलग देशों के आर्थिक निष्पादन में भारी अंतर घरेलू संरचनात्मक मुद्दों, भू-राजनीतिक संघर्षों के असमान एक्सपोजर और मौद्रिक नीति के सख्त होने के प्रभाव के कारण रहा है। रूस-यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक झटकों का यूरोप पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, जिससे जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देशों में विकास धीमा हो गया। अमेरिका को भी उच्च मुद्रास्फीति दबावों का सामना करना पड़ा और परिणामस्वरूप उसने नीतिगत दरों में काफी वृद्धि की। लेकिन, बकाया घरेलू रेहनों पर इसका असर सीमित रहा, क्योंकि फिक्स्ड-रेट रेहनों और कॉरपोरेट ऋण की उच्च हिस्सेदारी अवधि स्थिर दरों पर समाप्त हो गई[6], जिससे आर्थिक गतिविधि पर उच्च नीतिगत दरों का प्रभाव सीमित हो गया[7]। भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान तीव्र गिरावट दर्ज की, लेकिन मजबूत निजी खपत और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए सरकारी प्रोत्साहन की मदद से यह तेजी से उबर गया। दूसरी ओर, चीन में उच्च टीकाकरण दर सहित त्वरित नीतिगत कार्रवाइयों के कारण महामारी के दौरान विकास में केवल मामूली कमी आई[8], लेकिन संरचनात्मक मुद्दों के कारण बाद में विकास धीमा हो गया। महामारी के बाद जापान में विकास की गति धीमी रही, लेकिन कमजोर येन और बेहतर उपभोक्ता खर्च के कारण 2024 में इसमें सुधार आने की उम्मीद है।

6 टर्म्ड आउट एक वित्तीय अवधारणा है जिसका उपयोग अल्पकालिक ऋण को दीर्घकालिक ऋण में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, जिससे कंपनियों को अपनी कार्यशील पूंजी में सुधार करने और कम ब्याज दरों का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है।

7 डी सोयर्स, एफ., हेरेरो, जे.जी.सी., गोएर्नमैन, एन., जियोन, एस., लोफस्ट्रॉम, जी., और मूर, डी. (2024)। व्हाई इज द यूएस जीडीपी रिकवरिंग फास्टर दैन अदर एडवांस इकोनोमीज ?

8 पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना: 2021 आर्टिकल एट कंसल्टेशन प्रेस रिलीज; स्टाफ रिपोर्ट; और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक का वक्तव्य (https://tinyurl.com/5456sf94)

चार्ट I.3: सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं महामारी-पूर्व जीडीपी स्तर को पार कर चुकी हैं

	Year in which crossed pre pandemic GDP (constant prices, national currency)	Ratio of GDP (constant prices, national currency) in 2023 to corresponding level in 2019
Brazil	2021	107
China	2020	120
France	2022	102
Germany	2022	101
India	2021	120
Indonesia	2021	112
Italy	2022	103
Japan	2023	101
Mexico	2022	104
South Africa	2022	101
Thailand	2023	100
United Kingdom	2022	102
United States	2021	108

स्रोत: वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक, डेटाबेस, अप्रैल 2024, आईएमएफ, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; नोट: आईएमएफ डेटा में, भारत के लिए 2021, 2021-22 (वित्त वर्ष 22) का प्रतिनिधित्व करता है

1.4 जीडीपी अनुमानों के अलावा, अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर नजर रखने वाले अन्य संकेतक भी विकास के लचीलेपन की ओर इशारा करते हैं। प्रमुख संकेतक वैश्विक आर्थिक गतिविधि में वृद्धि का संकेत देते हैं। जेपी मॉर्गन वैश्विक समग्र पीएमआई[9] ने अक्टूबर 2023 से विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में तेज विस्तार के साथ उछाल दर्ज किया। जेपी मॉर्गन वैश्विक विनिर्माण पीएमआई में सुधार हो रहा है और मई 2024 में यह 23 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया[10]।

चार्ट I.4: वैश्विक पीएमआई भी मजबूत विकास गति की पुष्टि करता है

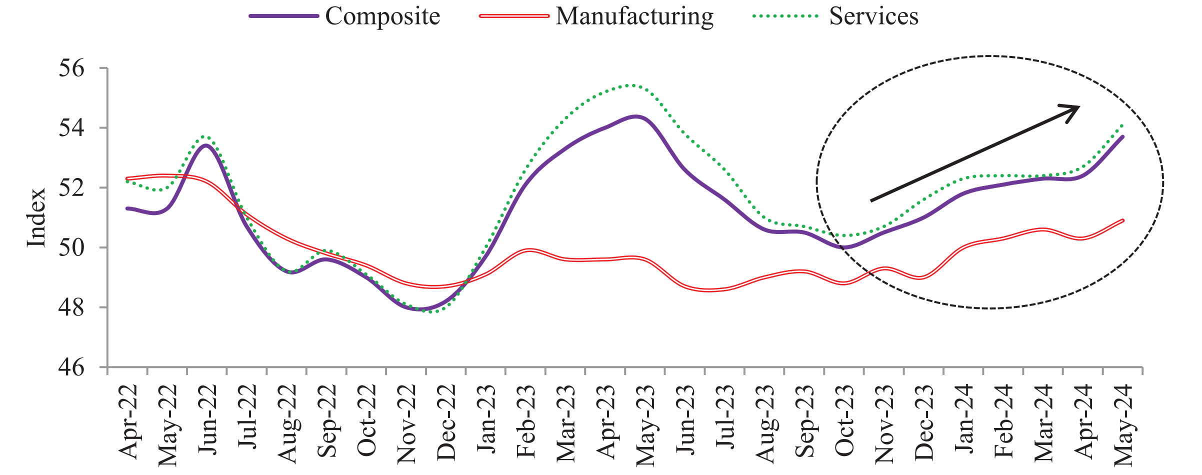

स्रोत: एसएंडपी ग्लोबल[11]

9 जेपी मॉर्गन ग्लोबल कम्पोजिट पीएमआई (https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home PressRelease/0d3865a6a27f46d18ea06fa-4de99f39b)

10 जेपी मॉर्गन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई (https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/f44f2dbe4a23430aad-13cd8105306ea9)

11 पीएमआई 0 से 100 तक होती है, 50 से अधिक मान का अर्थ है विस्तार।

1.5 अक्टूबर, 2023 में मध्य-पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के बीच लाल सागर संकट के बढ़ने से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा हुआ, जिससे वैश्विक व्यापार और संचालनों में हलचल हो गई। लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों के कारण वैश्विक परिवहन लागत में वृद्धि हुई, जिससे कार्गो का मार्ग बदलना पड़ा। हालाँकि, आपूर्ति श्रृंखला दबाव में वृद्धि क्षणिक और संयत थी। जोखिम धारणाओं में नरमी में भी इसी तरह की भावनाएँ परिलक्षित हुई। भू-राजनीतिक जोखिम सूचकांक, जो संघर्ष के बढ़ने के बाद बढ़ गया था, उसके बाद कम हो गया। हालाँकि, भू-राजनीतिक जोखिम उच्च और लगातार बने हुए हैं और आने वाले महीनों में और भी बदतर हो सकते हैं।

1.6 जैसे-जैसे आपूर्ति शृंखला पर दबाव कम हुआ और रूस-यूक्रेन संघर्ष से लगे ऊर्जा और खाद्य कीमतों के आघात हल्के हुए, सभी देशों में मुख्य मुद्रास्फीति में गिरावट आई। 2022 में चरम पर पहुंचने के बाद, 2023 में मुद्रास्फीति के दबाव में काफी कमी आई। हालांकि, कई देशों में मुद्रास्फीति अभी भी लक्ष्य से ऊपर है। 2023 में व्यापार योग्य वस्तुओं में आपूर्ति-शृंखला पर दबाव कम होने से विभिन्न देशों में वस्तुओं की मुद्रास्फीति में तेज गिरावट आई, जिससे लोजिस्टिक संबंधी चुनौतियां कम हुई। सेवाओं की मुद्रास्फीति और मजबूत श्रम बाजार के कारण, खासकर अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, मुख्य मुद्रास्फीति स्थिर बनी रही।[12]

चार्ट I.5: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला दबाव में कमी

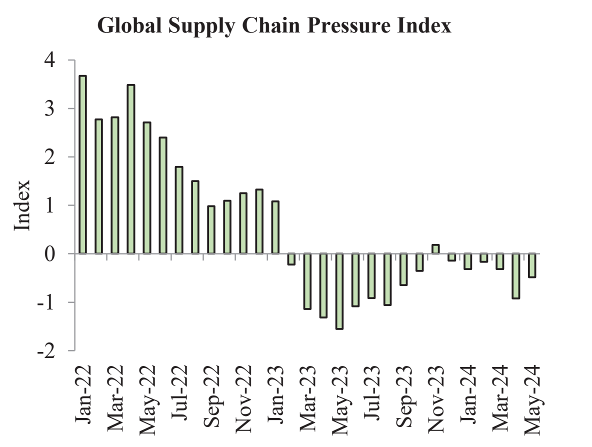

स्रोत: फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क

चार्ट I.6: अक्टूबर 2023 से भू-राजनीतिक जोखिम धारणाएं नरम हो गई हैं

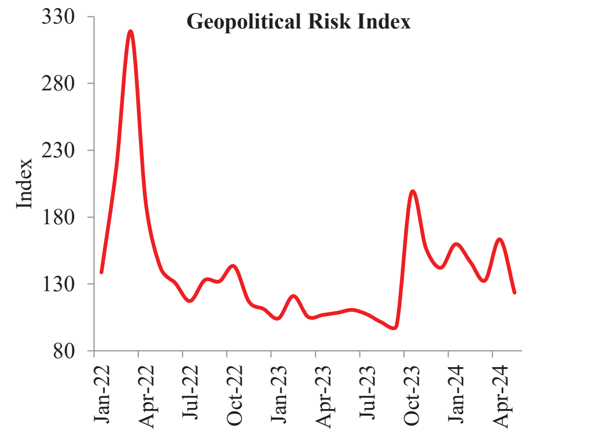

स्रोत: आर्थिक नीति अनिश्चितता

चार्ट I.7: विभिन्न देशों में मुद्रास्फीति का दबाव कम हो रहा है

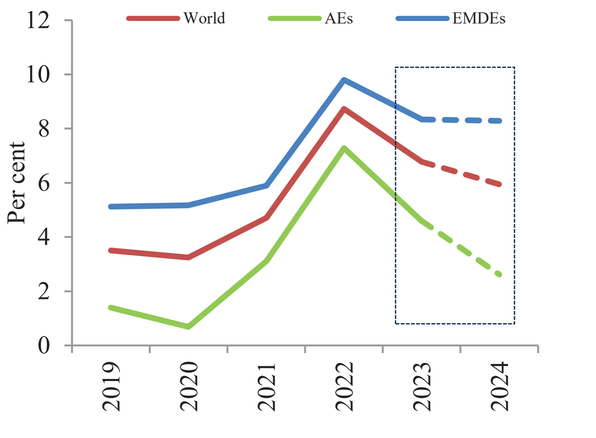

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस, अप्रैल 2024, आईएमएफ

चार्ट I.8: नीतिगत दरें ऊंची रही

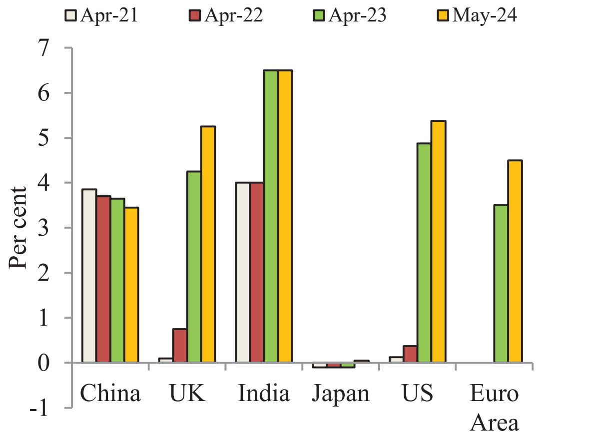

स्रोत: सेंट्रल बैंक पॉलिसी दरें, बीआईएस डेटा पोर्टल

12 बीआईएस त्रैमासिक समीक्षा, मार्च 2024 कोविड-19 के बाद की मुद्रास्फीति के अंतिम पड़ाव में क्षेत्र संबंधी कीमत गतिशीलता (https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2403.pdf)

चार्ट I.9: वैश्विक कमोडिटी सूचकांकों में नरमी

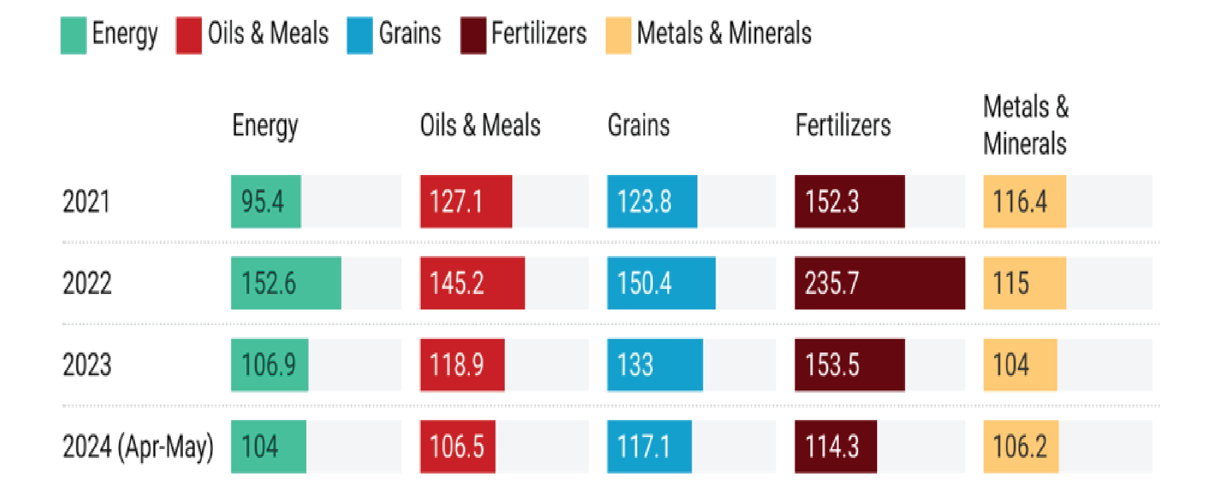

स्रोत: पिंक शीट, विश्व बैंक

1.7 कोर मुद्रास्फीति की निरंतरता ने कई केंद्रीय बैंकों को 2023 में नीतिगत दरों को उच्च स्तर पर बनाए रखने या उन्हें और बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, सिवाय चीन के, जहां सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र में परेशानियों से घिरी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन देने पर ध्यान केंद्रित किया। कई केंद्रीय बैंकों ने हाल की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठकों में ब्याज दर वृद्धि चक्र के चरम पर होने का संकेत दिया है। यूरोपीय सेंट्रल (ईसीबी) बैंक अपनी नीति दर में कटौती करने वाला पहला प्रमुख केंद्रीय बैंक बना, जिसने लगभग पाँच वर्षों में पहली दर कटौती की। ईसीबी ने जून 2024 में अपनी बेंचमार्क जमा दर में एक चौथाई प्रतिशत की कमी की। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) प्रतिभागियों के आकलन ने भी 2024 में दरों में कटौती का संकेत दिया, यद्यपि, नवीनतम एफओएमसी बैठक (जून, 2024)[13] में अनुमानित ब्याज दर में कटौती मार्च 2023 में अनुमानित कटौती से कम है। उम्मीद से अधिक मजबूत श्रम बाजार डेटा और विद्यमान मुद्रास्फीति दबाव फेडरल रिजर्व (फेड) की दरों को कम करने की अनिच्छा के पीछे प्रमुख कारक रहे हैं। जैसा कि संकेत है, जनवरी 2024 की शुरुआत से, एफओएमसी मीटिंग के विवरणों में फेड द्वारा दर्शाया गया है, कि हमें बाजार पर अतिशय आशावाद से बचना होगा। हालांकि, विभिन्न वित्तीय लिखतों के बाजार मूल्य निर्धारण पूर्ववर्ती और अत्यधिक दर कटौती में निवेशक विश्वास के बढ़ने का संकेत करता है I यह प्रतिफल वक्र के व्युत्क्रम में परिलक्षित होता है (अल्पकालिक प्रतिफल दीर्घकालिक प्रतिफल से अधिक है), जिसका अर्थ है कि भविष्य में निवेशक नीति दर में कटौती की अपेक्षा कर सकते हैं। वित्तीय बाजार सहभागियों ने भी बहुत आसान रुख पर नजर रखी है, जैसा कि मार्च 2022 की तुलना में 2023 में अमेरिका में राष्ट्रीय वित्तीय स्थितियों में महत्वपूर्ण सहजता में परिलक्षित होता है, जब फेड ने दरें बढ़ाना शुरू किया था। विस्तारवादी राजकोषीय नीति और वित्तीय स्थितियों में सहजता ने, एक हद तक, फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति की सख्ती को बेअसर कर दिया है, जिससे मुद्रास्फीति और अमेरिकी डॉलर के भविष्य के प्रक्षेपवक्र पर अनुत्तरित प्रश्न रह गए हैं।

13 एफ.ओ.एम.सी. अनुमान सामग्री, 12 जून, 2024 (https://www.federalreserve.g/v/monetarypolicy/fomcprojtabl20240612.htm)

चार्ट I.10: अमेरिकी यील्ड कर्व का उलटा होना, जो ब्याज दरों में कटौती की बढ़ी हुई उम्मीद को दर्शाता है

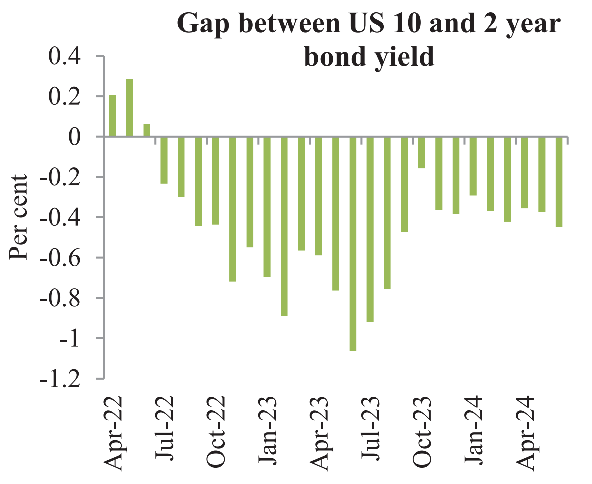

स्रोत: फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुइस

चार्ट I.11: अमेरिका में राष्ट्रीय वित्तीय स्थितियाँ बेहतर हुई हैं

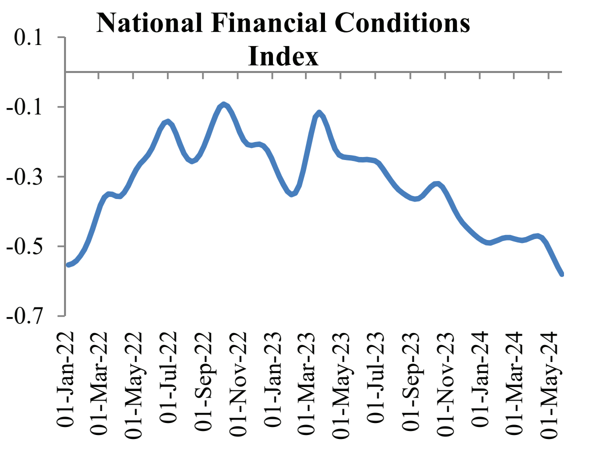

स्रोत: फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ शिकागो; नोट[14]

1.8 राजकोषीय मोर्चे पर, वैश्विक सामान्य सरकार राजकोषीय घाटा (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में औसतन 1.6 प्रतिशत अंक बढ़ा। यह वृद्धि मुख्य रूप से राजस्व में साल-दर-साल गिरावट से उपजी है क्योंकि तेल उत्पादक और कमोडिटी निर्यातक देशों के लिए मुद्रास्फीति से अप्रत्याशित राजस्व में कमी आयी है जबकि व्यय काफी हद तक स्थिर रहा (आईएमएफ राजकोषीय मॉनिटर, अप्रैल 2024)। नतीजतन, 2023 में वैश्विक सार्वजनिक ऋण में भी मामूली वृद्धि हुई।

चार्ट I.12: विभिन्न देशों में राजकोषीय घाटा बढ़ा

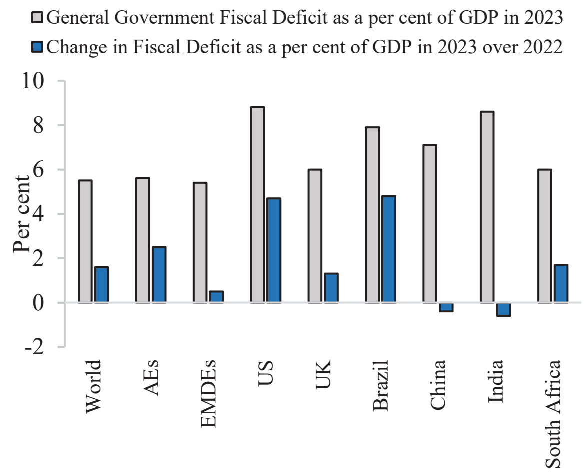

स्रोत: महान चुनाव वर्ष में राजकोषीय नीति, राजकोषीय मॉनिटर, आईएमएफ

चार्ट I.13: 2023 में वैश्विक ऋण में बढ़ोतरी

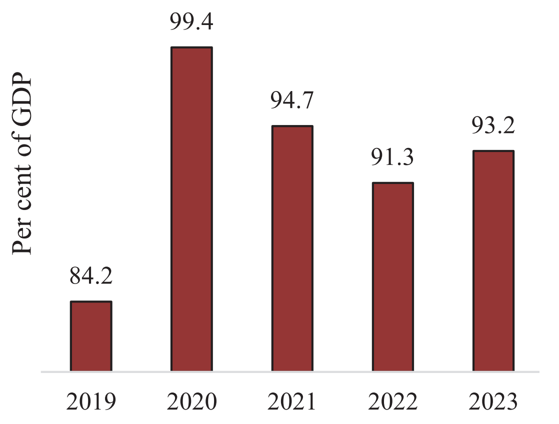

स्रोत: महान चुनाव वर्ष में राजकोषीय नीति, राजकोषीय मॉनिटर, आईएमएफ

14 एनएफसीआई का निर्माण शून्य के औसत मूल्य और 1971 तक फैली नमूना अवधि में एक के मानक विचलन के साथ किया गया है। एनएफसीआई के सकारात्मक मूल्यों को ऐतिहासिक रूप से औसत से अधिक सख्त वित्तीय स्थितियों के साथ जोड़ा गया है और इसके विपरीत भी।

1.9 डब्ल्यूईओ के आंकड़ों के अनुसार, मजबूत वैश्विक आर्थिक विकास के बावजूद , वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात की वैश्विक मात्रा में 2022 की तुलना में 2023 में 0.5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। धीमी वृद्धि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कम मांग और पूर्वी एशिया और लैटिन अमेरिका में कमजोर व्यापार के कारण हुई (यूएनसीटीएडी मार्च अपडेट 2024)। उच्च ऊर्जा की कीमतों और मुद्रास्फीति ने निर्मित वस्तुओं की मांग पर भारी दबाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप 2023 में विश्व व्यापारिक व्यापार की मात्रा में गिरावट आई। दूसरी ओर, सेवा व्यापार में विकास अधिक उत्साहजनक थे, जिसने वस्तु व्यापार में गिरावट को आंशिक रूप से समायोजन किया (डब्ल्यूईओ, डेटाबेस,[15] अप्रैल 2024)[16]। आवर्ती व्यवधान, विशेष रूप से रूस-यूक्रेन संकट और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन के बारे में बढ़ी हुई चिंता से मंदी आई। सीमापार व्यापर प्रतिबंधों के बढ़ने के साथ भू राजनीतिक रेखाओं के साथ व्यापर का पुन: आवंटन हुआ है। ग्लोबल ट्रेड अलर्ट डेटा (आईएमएफ, डब्ल्यूईओ, अप्रैल 2024) के अनुसार, 2023 में व्यापार पर लगभग 3,000 नए प्रतिबंध लगाए गए[17]।

1.10 भू-राजनीतिक संघर्ष, उच्च उधारी लागत और वैश्विक आर्थिक विखंडन से संबंधित चिंताएँ भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में कमी के रूप में परिलक्षित हुई। 2022 की तुलना में 2023 में वैश्विक प्रवाह में गिरावट आई।[18]

चार्ट I.14: 2023 में व्यापारिक वृद्धि में गिरावट आई

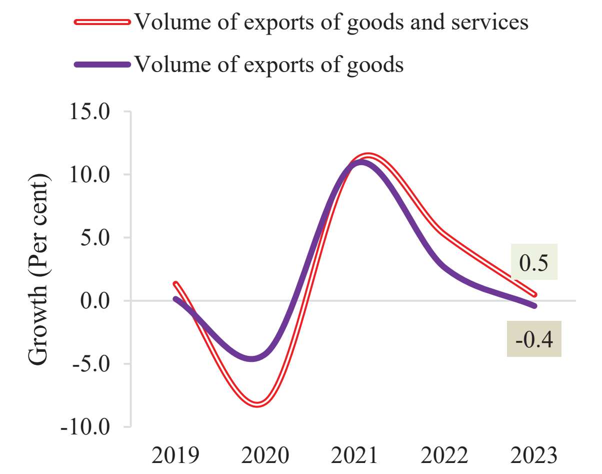

स्रोत: विश्व आर्थिक आउटलुक डेटाबेस, अप्रैल 2024, आईएमएफ

चार्ट I.15: एफडीआई प्रवाह में भी कमजोर वृद्धि दर्ज की गई

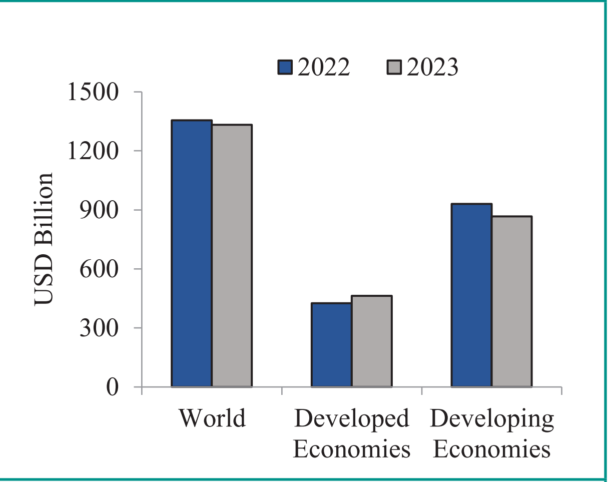

स्रोत: विश्व निवेश रिपोर्ट 2024, यूएनसीटीएडी

एक लचीली घरेलू अर्थव्यवस्था

1.11 वैश्विक और बाहरी चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 23 में जो गति बनाई थी, उसे वित्त वर्ष 24 में भी जारी रखा। समष्टि आर्थिक स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने से यह सुनिश्चित हुआ कि इन चुनौतियों का भारत की अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप, भारत की वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 24 में 8.2 प्रतिशत बढ़ी, जो लगातार तीसरे वर्ष 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज करती है, जो स्थिर उपभोग मांग और लगातार सुधरती निवेश मांग के कारण है। आपूर्ति पक्ष पर, 2011-12 की कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वित्त वर्ष 24 में 7.2 प्रतिशत बढ़ा, जबकि वृद्धि व्यापक आधार पर रही। स्थिर (2011-12) कीमतों पर शुद्ध कर वित्त वर्ष 24 में 19.1 प्रतिशत बढ़ा, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर यथोचित रूप से मजबूत कर वृद्धि और सब्सिडी व्यय को युक्तिकरण से सहायता मिली। इसके कारण वित्त वर्ष 24 में जीडीपी और जीवीए वृद्धि के बीच अंतर हुआ।

15 ग्रेट इलेक्शन ईयर में राजकोषीय नीति, राजकोषीय मॉनिटर। https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2024/04/17/fiscal monitor-april-2024)

16 ग्लोबल ट्रेड अपडेट, मार्च 2024, यूएनसीटीएडी (https://tinyurl.com/pe87zewe)

17 विश्व आर्थिक परिदृश्य, अप्रैल 2024, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मंच, पृष्ठ 14 (https://www.imf.org/en/Publications/WEO Issues/2024/04/16/world-economic-outlook-april-2024)

18 विश्व निवेश रिपोर्ट 2024, यूएनसीटीएडी (https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024)

चार्ट I.16: आर्थिक विकास में गति को आगे बढ़ाना

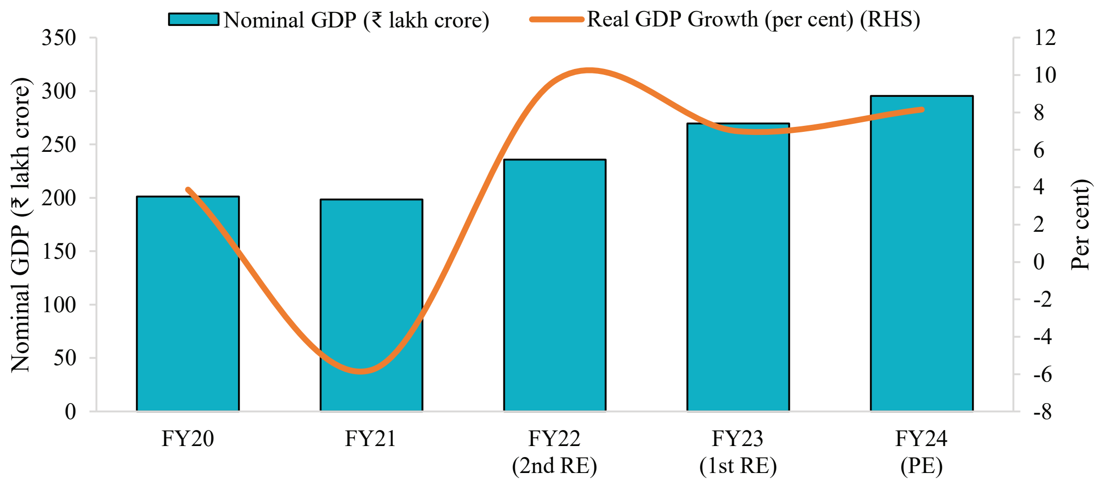

स्रोत: विवरण 13: स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का वार्षिक और त्रैमासिक अनुमान, तथा वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का वार्षिक और त्रैमासिक अनुमान 2011-12 श्रृंखला, राष्ट्रीय लेखा डेटा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

1.12 वर्तमान मूल्यों पर समग्र जीवीए में कृषि ,उद्योग और सेवा की हिस्सेदारी वित्तवर्ष 24 में क्रमशः 17.7 प्रतिशत, 27.6 प्रतिशत और 54.7 प्रतिशत थी। कृषि क्षेत्र में जीवीए में वृद्धि जारी रही, हालांकि इसकी गति धीमी रही। वर्ष के दौरान अनियमित मौसम और 2023 में मानसून के असमान स्थानिक वितरण ने समग्र उत्पादन को प्रभावित किया। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी खाद्यान्न उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन में 0.3 प्रतिशत की मामूली गिरावट में परिलक्षित होता है।[19]

चार्ट I.17: व्यापक-आधारित विकास

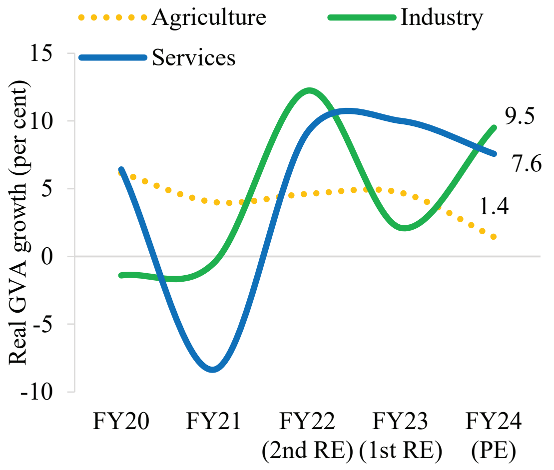

चार्ट I.18: निवेश से विकास को बढ़ावा मिलने के कारण निजी खपत स्थिर

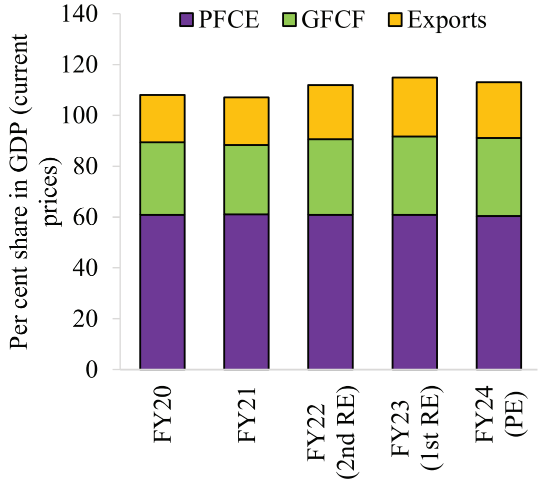

स्रोत: विवरण 12: वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का वार्षिक और त्रैमासिक अनुमान, 2011-12 श्रृंखला, और विवरण 13: स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का वार्षिक और त्रैमासिक अनुमान, 2011-12 श्रृंखला, राष्ट्रीय खाते

1.13 औद्योगिक क्षेत्र में, विनिर्माण जीवीए ने वित्त वर्ष 23 के निराशाजनक प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया और वित्तवर्ष 24 में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। स्थिर घरेलू मांग को पूरा करते हुए विनिर्माण गतिविधियों को इनपुट कीमतों में कमी का लाभ मिला। इनपुट मूल्य लाभ डब्ल्यूपीआई में धीमी वृद्धि में परिलक्षित हुआ, जिसके कारण वित्तवर्ष 24 के दौरान

19 https://tinyurl.com/2eekevhu

विनिर्माण क्षेत्र के लिए (-)1.7 प्रतिशत की गिरावट आई। निर्माताओं ने इनपुट कीमतों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को भी दिया, जो मुख्य उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में निरंतर गिरावट में परिलक्षित हुआ। विनिर्माण की मजबूती की पुष्टि विनिर्माण के लिए एचएसबीसी इंडिया परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के मजबूत प्रदर्शन से होती है, जो लगातार 50 के सीमा मूल्य से ऊपर रहा, जो भारत के विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर विस्तार और स्थिरता का संकेत देता है। निर्माण गतिविधियों ने गति पकड़ी और बुनियादी ढांचे के निर्माण और वाणिज्यिक और आवासीय अचल संपत्ति की बढ़ती मांग के कारण वित्तवर्ष 24 में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

1.14 विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतक सेवा क्षेत्र में वृद्धि को दर्शाते हैं। थोक और खुदरा व्यापार को दर्शाते हुए जीएसटी संग्रह और ई-वे बिल जारी करके दोनों ने वित्त वर्ष 24 में दोहरे अंकों की वृद्धि प्रदर्शित की। वित्तीय और पेशेवर सेवाएँ महामारी के बाद विकास का एक प्रमुख चालक रही हैं। संपर्क-गहन सेवाएँ - मुख्य रूप से व्यापार, परिवहन, रियल एस्टेट और उनकी सहायक सेवाएँ जो महामारी के दौरान सबसे अधिक प्रभावित हुई थीं, महामारी के बाद की अवधि में बहुत मजबूत होकर उभरी हैं, उनमें अधिक प्रौद्योगिकी और डिजिटल सामग्री को शामिल किया गया है और भारत में सेवा वितरण की प्रकृति को बदल दिया है। वैश्विक क्षमता केंद्रों के प्रसार ने भी भारत के सेवा निर्यात को लचीलापन प्रदान किया है, जिससे इस क्षेत्र को और बढ़ावा मिला है।

1.15 मांग पक्ष पर, निजी खपत जीडीपी वृद्धि में एक महत्वपूर्ण और स्थिर घटक रही है। वित्त वर्ष 24 में निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में वास्तविक रूप से 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। शहरी मांग की स्थिति मजबूत बनी हुई है, जैसा कि घरेलू यात्री वाहन[20] बिक्री और हवाई यात्री यातायात[21] जैसे विभिन्न शहरी उपभोग संकेतकों में परिलक्षित होता है। यह भी बताया गया है कि मार्च 2024[22] को समाप्त तिमाही के दौरान ग्रामीण उपभोग वृद्धि ने धीरे-धीरे गति पकड़ी है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार, वित्त वर्ष 24 में दोपहिया और तिपहिया तथा निजी वाहनों की बिक्री में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई।

चार्ट I.19: महामारी के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों की बिक्री में अच्छी वृद्धि हुई है

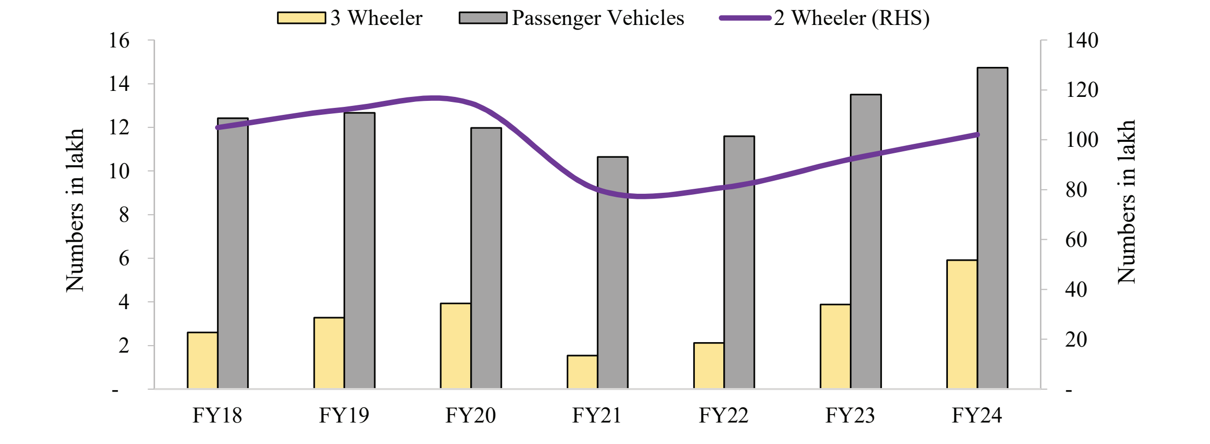

स्रोत: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन

1.16 सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) विकास के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में उभर रहा है, जैसा कि नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद में इसकी बढ़ती हिस्सेदारी से संकेत मिलता है। भारत निजी पूंजीगत व्यय चक्र के बीच में है जिसे सरकारी पूंजीगत व्यय से सहायता मिली है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2024 के विवरण 1.11 के अनुसार, निजी गैर-वित्तीय निगमों द्वारा जीएफसीएफ में वित्त वर्ष 23 में 19.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। शुरुआती संकेत हैं कि वित्त वर्ष 24 में निजी पूंजी निर्माण की गति बरकरार रही है। एक्सिस बैंक रिसर्च द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 3,200 से अधिक सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध गैर-वित्तीय फर्मों के एक सुसंगत समूह में निजी निवेश वित्त वर्ष 24 में 19.8 प्रतिशत बढ़ा है।

20 https://tinyurl.com/y2xhx5bb
21 https://tinyurl.com/4x9udsdz
22 https://tinyurl.com/yjkpdsau

चार्ट I.20: उत्पादक क्षमता निर्माण पर सामान्य सरकार का अधिक ध्यान	चार्ट I.21: निजी पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि
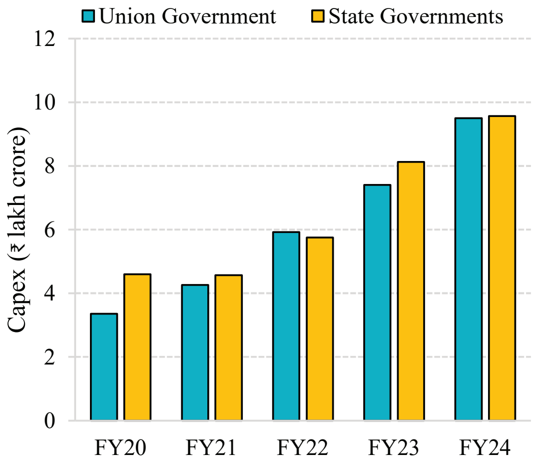	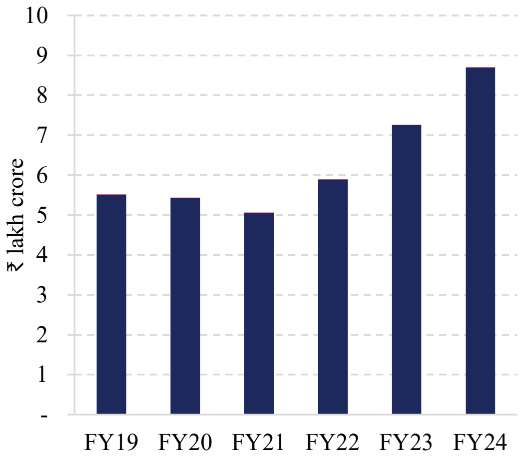
स्रोत: तालिका संख्या 95 और 102, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, आरबीआई, सीजीए[23]	स्रोत: एक्सिस बैंक रिसर्च

1.17 निजी निगमों के अलावा, परिवार भी पूंजी निर्माण प्रक्रिया में सबसे आगे रहे हैं। शहरों में आवास बिक्री में वृद्धि विशेष रूप से प्रभावशाली रही है, जो दर्शाता है कि शहरी परिवार अपनी बचत के निवेश में विविधता ला रहे हैं। 2023 में, भारत में आवासीय अचल संपत्ति की बिक्री 2013 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर थी, जिसमें 33 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देखी गई, जिसमें शीर्ष आठ शहरों में कुल 4.1 लाख इकाइयों की बिक्री हुई। नई आपूर्ति ने अब तक का उच्चतम स्तर देखा, 2023 में 5.2 लाख इकाइयाँ लॉन्च की गई, जबकि 2022 में 4.3 लाख इकाइयाँ लॉन्च की गई थीं। 2024 की पहली तिमाही में गति जारी रही, जिसमें 1.2 लाख इकाइयों की रिकॉर्ड-तोड़ बिक्री हुई, जिसमें 41 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। रियल एस्टेट रिसर्च फर्म प्रॉपटाइगर के अनुसार, 2022 की दूसरी तिमाही से नई आपूर्ति लगातार एक लाख इकाइयों से अधिक रही है, जो आवास बाजार में लगातार मांग-आपूर्ति की गतिशीलता को रेखांकित करती है।

चार्ट I.22: भौतिक परिसंपत्तियों के रूप में घरेलू बचत में वृद्धि	चार्ट I.23: शीर्ष 8 शहरों में रिकॉर्ड आवास बिक्री[24]
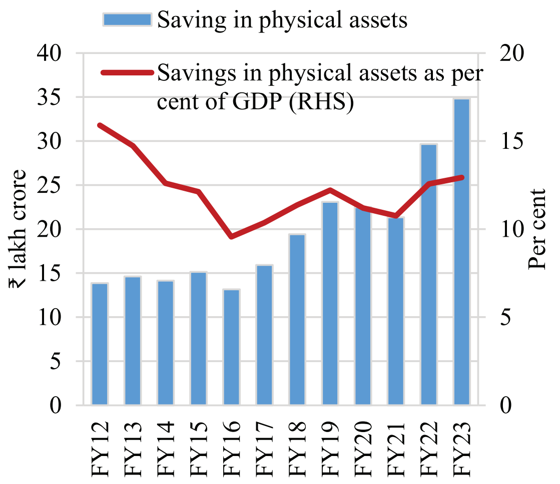	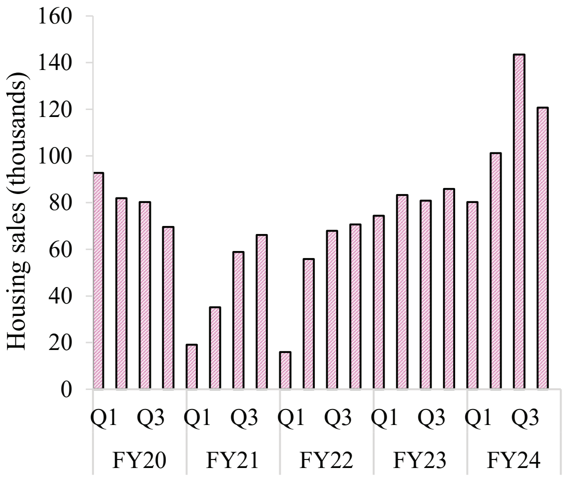
स्रोत: विवरण 1.9, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2024, MoSPI	स्रोत: विभिन्न प्रॉपटाइगर रिपोर्ट्स[25]

23 केंद्र सरकार के लिए वित्त वर्ष 24 के आंकड़े अनंतिम वास्तविक हैंद्य राज्य सरकारों के लिए वित्त वर्ष 2024 के आंकड़े बजट अनुमान हैं और वित्त वर्ष 23 के लिए संशोधित अनुमान हैं।

24 प्रॉपटाइगर रिपोर्ट में उल्लिखित आठ प्रमुख शहर अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और मुंबई एमएमआर हैं।

25 https://www.proptiger.com/guide/news-views

1.18 स्वच्छ बैलेंस शीट और पर्याप्त पूंजी बफर के साथ, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र निवेश मांग की बढ़ती वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा औद्योगिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) उद्यमों और सेवाओं को ऋण वितरण उच्च आधार के बावजूद दोहरे अंकों में बढ़ रहा है। इसी तरह, आवास की मांग में वृद्धि के अनुरूप आवास के लिए व्यक्तिगत ऋण में उछाल आया है। हालांकि, बड़े उद्योगों द्वारा ऋण उठाव कम लेकिन स्थिर गति से बढ़ रहा है। ये बड़े उद्योग कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार का दोहन करते दिख रहे हैं। वित्त वर्ष 2024 में कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करने में 70.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें निजी प्लेसमेंट कॉरपोरेट्स के लिए पसंदीदा चौनल बना रहा। मार्च 2024 के अंत तक बकाया कॉरपोरेट बॉन्ड में 9.6 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई।

चार्ट I.24: निवेश मांग को पूरा करने वाले एससीबी

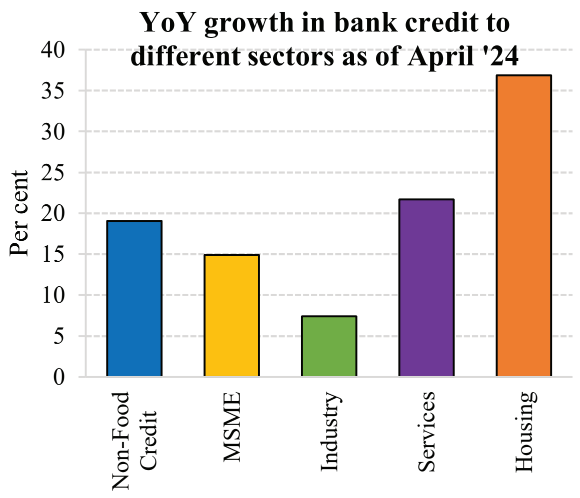

स्रोत: तालिका 170, बैंक ऋण का क्षेत्रीय परिनियोजन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, आरबीआई

चार्ट I.25: बड़ी कंपनियां कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार का लाभ उठा रही हैं

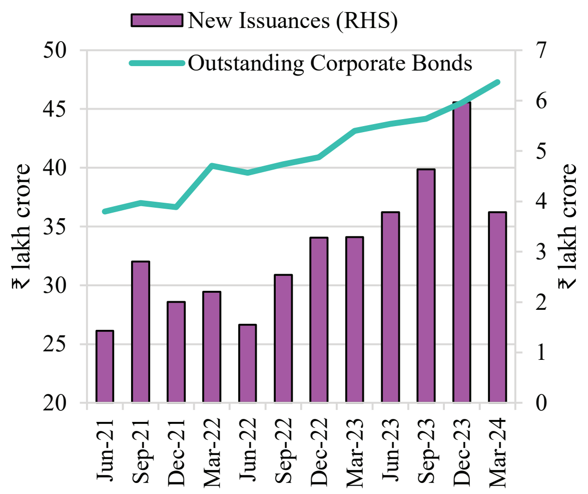

स्रोत: बकाया कॉर्पोरेट बांड, सेबी

1.19 2023 में वैश्विक व्यापार वृद्धि धीमी हो गई, जिससे व्यापारिक निर्यात वृद्धि में मामूली गिरावट आई। चूंकि व्यापारिक आयात निर्यात की तुलना में अधिक धीमा हो गया और सेवा व्यापार ने पिछले वर्ष की तुलना में बड़ा अधिशेष दर्ज किया, इसलिए सकल घरेलू उत्पाद पर शुद्ध निर्यात द्वारा लगाया गया दबाव कम हो गया। निर्यात के कम योगदान को निश्चित निवेश में वृद्धि से संतुलित किया गया, जिससे बाहरी प्रोत्साहनों की जगह घरेलू प्रोत्साहन की प्रवृत्ति जारी रही।

1.20 वित्त वर्ष 24 में जीडीपी महामारी से पहले के अनुमानित स्तरों पर पहुंच गई। बॉक्स I.1 में एक प्रवृत्ति विश्लेषण बताता है कि कैसे समग्र अर्थव्यवस्था और अधिकांश आपूर्ति और मांग-पक्ष क्षेत्रों ने उत्पादन और मांग में किसी भी स्थायी नुकसान को मिटाने के लिए एक गति से विकास किया है।

बॉक्स I.1: जीडीपी, जीवीए और उनके घटकों में वृद्धि सुनिश्चित करती है कि मांग और उत्पादन में कोई स्थायी नुकसान नहीं होता है

स्थायी उत्पादन हानि से तात्पर्य उत्पादन क्षमता में कमी के कारण देखे गए चर में नीचे की ओर होने वाले बदलाव से है। यह बॉक्स आइटम भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जीवीए, निजी खपत और जीवीए के उप-घटकों जैसे समग्र वृहद आर्थिक चरों में महामारी-पूर्व और महामारी-पश्चात के रुझानों को दर्शाता है।

चार्ट I.26: जीडीपी में महामारी से पहले की स्थिति में सुधार

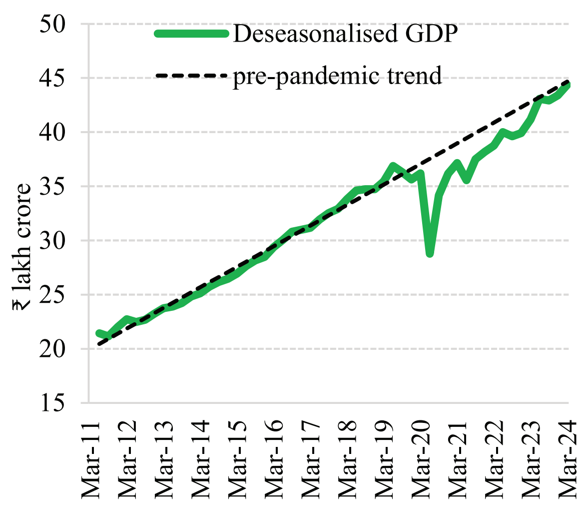

चार्ट I.27: प्रवृत्ति से अंतर में लगातार कमी

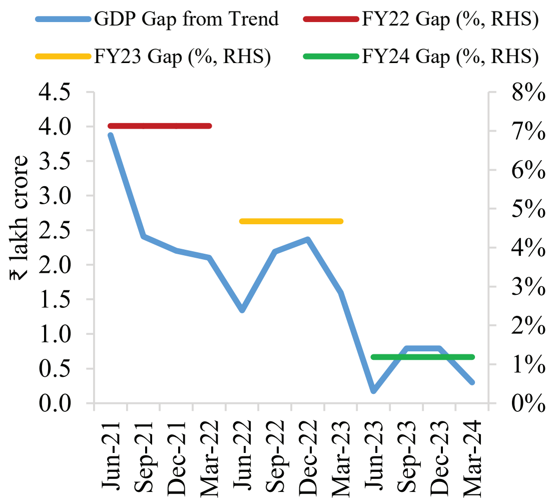

चार्ट I.28: उत्पादन क्षमता में कोई स्थायी हानि नहीं

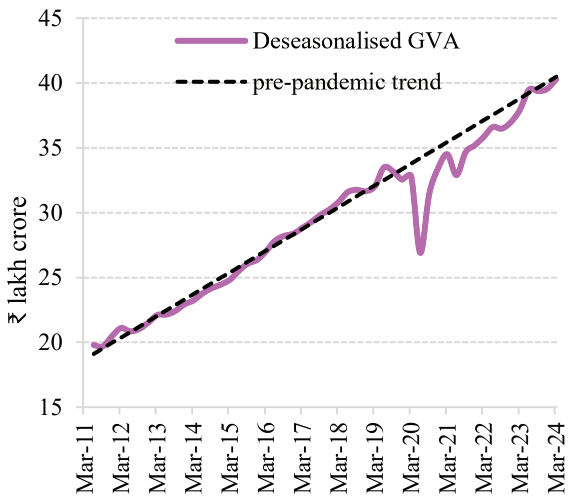

चार्ट I.29: कोई स्थायी उपभोग हानि नहीं

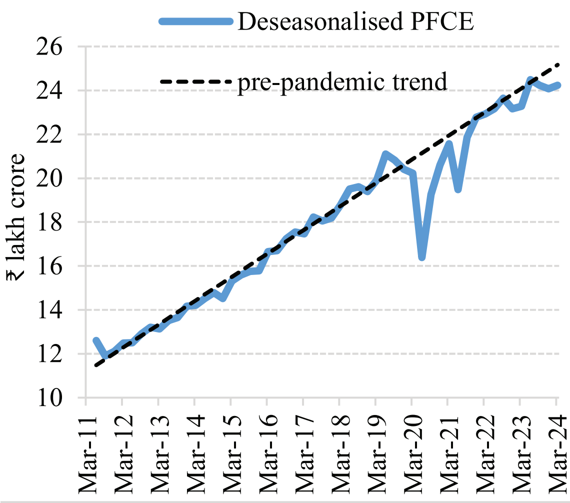

चार्ट I.30: निवेश में उछाल आया है

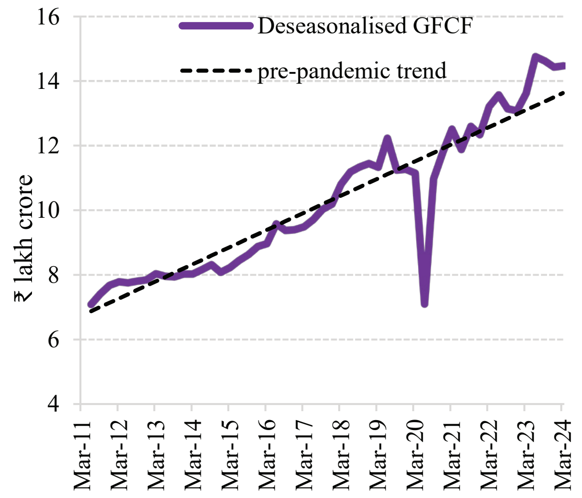

चार्ट I.31: औद्योगिक जीवीए महामारी से पहले की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है

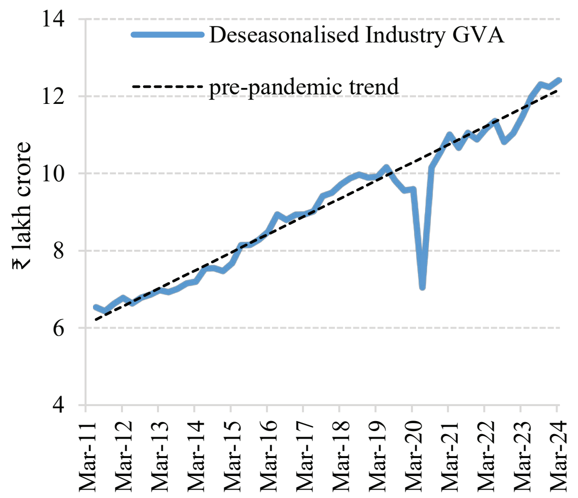

चार्ट I.32: सेवाओं का जीवीए पिछड़ रहा है

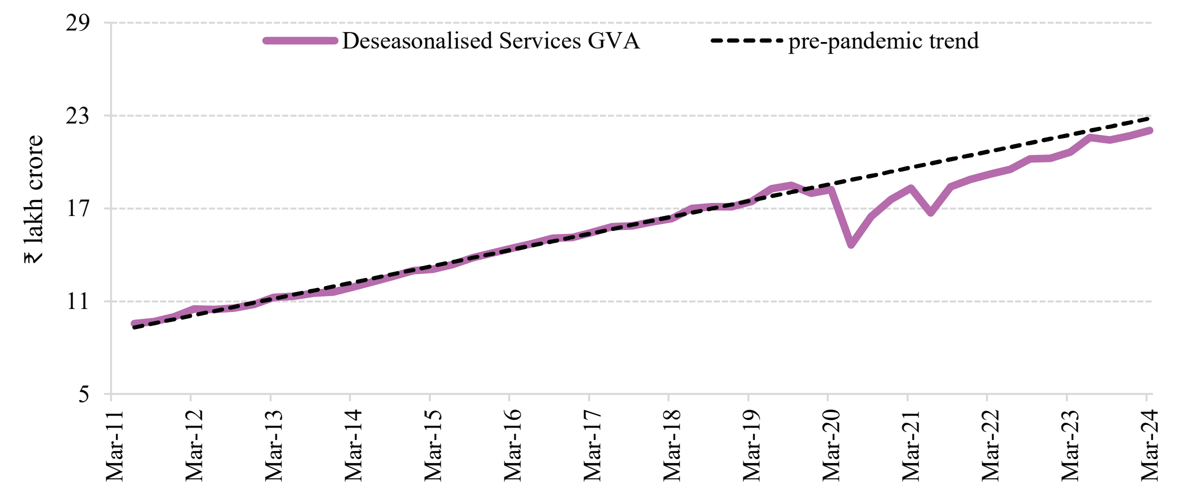

स्रोत: चार्ट I:25 से चार्ट I.31 तक कथन 13: स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के वार्षिक और त्रैमासिक अनुमान, 2011-12 श्रृंखला, राष्ट्रीय लेखा डेटा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पर आधारित गणना का उपयोग कर रहे हैं

विश्लेषण में, स्थिर (2011-12) कीमतों पर छह प्रमुख मैक्रोइकॉनॉमिक चर, यानी जीडीपी, जीवीए, पीएफसीई, जीएफसीएफ, उद्योग जीवीए, और तिमाही आवृत्ति के सेवा जीवीए को X-12 एआरआईएमए तकनीक का उपयोग करके डीसीजनलाइज्ड किया गया है जो चर को इसके रुझान, मौसमी, चक्रीय और विशिष्ट घटकों में विघटित करता है। डीसीजनलाइज्ड चर को यह समझने के लिए विजुअलाइज किया गया है कि ये चर अपने पूर्व-महामारी प्रवृत्ति अनुमानों के मुकाबले कहां खड़े हैं। जून 2011 और मार्च 2020 के बीच डी-सीजनलाइज्ड डेटा पर आधारित एक ट्रेंड लाइन तैयार की गई है और इसे मार्च 2024 तक बढ़ाया गया है। यह प्रवृत्ति जून 2020 और मार्च 2024 में प्रत्येक तिमाही में चर के अनुमानित प्रक्षेपण को दर्शाती है

विजुअलाइजेशन से पता चलता है कि जीडीपी, जीवीए, निजी खपत, जीएफसीएफ और औद्योगिक जीवीए में तेजी से सुधार हुआ है। हम देखते हैं कि इन चरों की चक्रवृद्धि तिमाही वृद्धि दर (सीजीक्यूआर) वित्त वर्ष 21 की तीसरी तिमाही से वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही की अवधि में महामारी से पहले की अवधि की सीजीक्यूआर से ज्यादा

है (तालिका I)। इसने महामारी से पहले के रुझानों द्वारा अनुमानित स्तरों तक व्यापक पकड़ बनाने में सक्षम बनाया, जिससे मांग/उत्पादन में किसी भी स्थायी नुकसान को टाला जा सका। इसके कई कारण हैं। महामारी से प्रेरित संकुचन ने एक प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति की तैनाती का अवसदिया जो पूंजीगत व्यय पर केंद्रित थी, जिससे सरकार द्वारा संचालित पूंजी निर्माण को विकास के चालक के रूप में स्थापित किया गया। इसने कई प्रक्रिया सुधारों के कार्यान्वयन और सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे की तैनाती को भी सक्षम बनाया जिसने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा दिया। महामारी से आबादी के बीच डिजिटल तकनीकों को अपनाने में भी तेजी लाई और वित्तीय समावेशन को बढ़ाया। जीएसटी और दिवालिया एवं दिवालियापन कोड (आईबीसी) ने अर्थव्यवस्था के लिए सहायक के रूप में काम किया, जिससे विकास ने गति पकड़ी।

तालिका I.1: महामारी से प्रेरित संकुचन के बाद से तेज वृद्धि

डिसीजनलाइज्ड तिमाही श्रृंखला में चक्रवृद्धि वृद्धि (% में)	सकल घरेलू उत्पाद	जीवीए	पीएफसीई	औद्योगिक जीवीए	सेवाएँ जीवीए	जीएफसीएफ
Q1FY12 – Q4FY20 के बीच	1.5	1.5	1.4	1.1	1.9	1.3
Q3FY21 – Q4FY24 के बीच	1.9	1.8	1.7	1.4	2.1	2.0

सेवा क्षेत्र का जीवीए अभी भी महामारी से पहले के रुझान के अनुमानित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। वित्त वर्ष 23 तक उपलब्ध विस्तृत आंकड़ों से पता चलता है कि यह व्यापार, होटल, सड़क और हवाई परिवहन क्षेत्रों के कारण है। इन क्षेत्रों ने मिलकर वित्त वर्ष 23 में कुल वास्तविक जीवीए में लगभग 28.5 प्रतिशत का योगदान दिया और वित्त वर्ष 20 के अपने स्तर से केवल एक प्रतिशत ऊपर थे।

चार्ट I.27 से पता चलता है कि जीडीपी और महामारी से पहले के रुझान के बीच का अंतर कम हो रहा है, और वित्त वर्ष 24 में जीडीपी वार्षिक औसत आधार पर इस प्रवृत्ति से केवल 1 प्रतिशत कम थी। यह देखते हुए कि अभी भी कुछ सुधार की गुंजाइश है, वित्त वर्ष 25 में गति खोए बिना और मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ाए बिना अर्थव्यवस्था के बढ़ने की गुंजाइश है। विकास में मौजूदा क्षण न केवल अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति के दबाव के बिना अपनी पूर्व-महामारी की प्रवृत्ति को पकड़ने की अनुमति देता है, बल्कि इसे पार करने में भी मदद करता है।

वृहद आर्थिक स्थिरता विकास सुरक्षा

1.21 भारत के लिए, वित्त वर्ष 23 की शुरुआत कई चुनौतियों के साथ हुई। यूरोप में संघर्ष के कारण घरेलू कीमतों पर दबाव बढ़ रहा था और तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण चालू खाता घाटा (सीएडी) बढ़ रहा था। कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति के दबाव से निपटने के लिए नीतिगत दरें बढ़ानी शुरू कर दीं, जिससे एई और ईएमई दोनों में ही अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि, वित्त वर्ष 23 और वित्तीय वर्ष 24 के दौरान, घरेलू और बाहरी कमजोरियों के बीच आर्थिक विकास को सुरक्षित करने के लिए व्यापक आर्थिक स्थिरता पर ध्यान देना महत्वपूर्ण था।

सार्वजनिक वित्त में सुधार

केंद्र सरकार के वित्त का समेकन

1.22 बढ़ते राजकोषीय घाटे और बढ़ते ऋण बोझ की वैश्विक प्रवृत्ति के विपरीत, भारत राजकोषीय समेकन की राह पर बना हुआ है। वर्ष 2023 में अनुकूल राजकोषीय प्रदर्शन भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता की आधारशिला बनकर उभरा है। नियंत्रक महालेखा कार्यालय (सीजीए) द्वारा जारी अनंतिम वास्तविक (पीए) आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 23 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 24 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.6 प्रतिशत पर आ गया है। लचीली आर्थिक गतिविधि और बढ़े हुए अनुपालन के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में मजबूत वृद्धि का मतलब है कि उत्पन्न कर राजस्व रूढ़िवादी बजटीय अनुमानों से अधिक है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई

से लाभांश के रूप में बजट से अधिक गैर कर राजस्व प्राप्त होने से राजस्व प्राप्तियां प्रभावित हुई है। संयमित राजस्व व्यय के साथ, इन बढ़ते राजस्वों ने कम घाटे को सुनिश्चित किया है। पिछले कुछ वर्षों में राजकोषीय घाटे के विश्लेषण से पता चलता है कि राजस्व घाटे में कमी के साथ, राजकोषीय घाटे का बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय द्वारा वहन किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि उधार लिए गए संसाधनों की उत्पादकता में सुधार हुआ है।

चार्ट I.33: लगातार घटता घाटा अनुपात

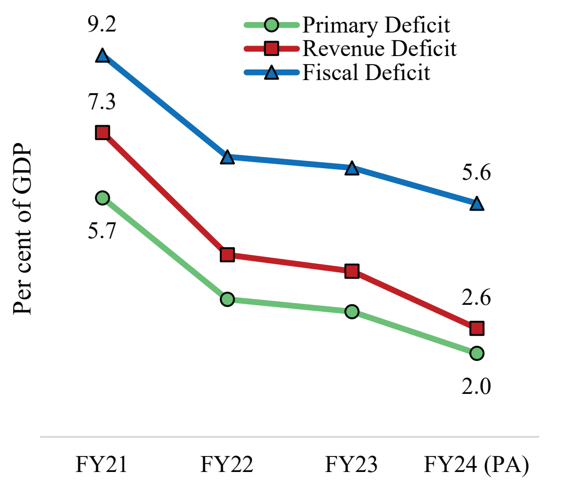

स्रोत: बजट - एक नजर में, केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 24 (अंतरिम), केंद्र सरकार के खाते पर एक नजर ख्र सीजीए का कार्यालय

चार्ट I.34: राजकोषीय घाटे का विघटन निवेश उन्मुखीकरण में वृद्धि दर्शाता है

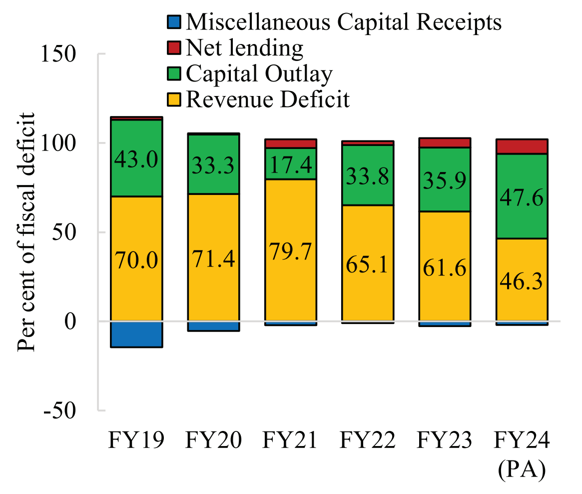

स्रोत:विभिन्न केंद्रीय बजट दस्तावेज, केंद्र सरकार के लेखा- एक नजर में ख्र सीजीए का कार्यालय

वित्त वर्ष 2024 में राजस्व में उछाल जारी है

1.23 महामारी के बाद महत्वपूर्ण राजकोषीय समेकन काफी हद तक राजस्व में उछाल के कारण हासिल किया जा सका। कर राजस्व (केंद्र को शुद्ध) और गैर-कर राजस्व (एनटीआर) से मिलकर केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां वित्त वर्ष 24 (प्रति वर्ष) में सालाना आधार पर 14.5 प्रतिशत बढ़ीं, जिसमें कर और गैर-कर राजस्व दोनों में मजबूत वृद्धि हुई।

चार्ट I.35: कर और गैर-कर राजस्व दोनों से प्रेरित राजस्व प्राप्तियों में लगातार वृद्धि

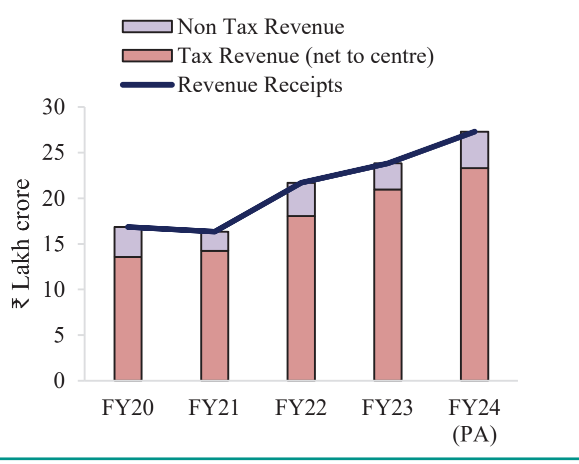

चार्ट I.36: मजबूत प्रत्यक्ष कर वृद्धि से सकल कर राजस्व में जीडीपी अनुपात में वृद्धि

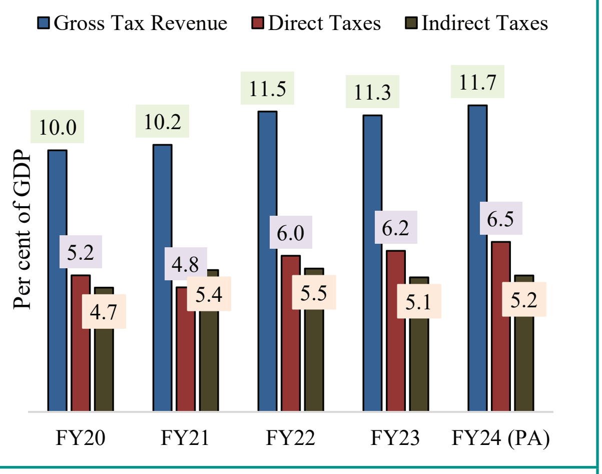

स्रोत: बजट एक नजर में, केंद्रीय बजट, वित्तीय वर्ष 22, वित्तीय वर्ष 23, वित्तीय वर्ष 24 अंतरिम बजट, केंद्र सरकार के लेखा - एक नजर में ख्र ख्र सीजीए का कार्यालय

1.24 वित्त वर्ष 24 में सकल कर राजस्व (जीटीआर) में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया, जो 1.4 के कर राजस्व उछाल में तब्दील हो गया। यह वृद्धि वित्त वर्ष 23 की तुलना में प्रत्यक्ष करों में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि और अप्रत्यक्ष करों में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई। मोटे तौर पर, जीटीआर का 55 प्रतिशत प्रत्यक्ष करों से और शेष 45 प्रतिशत अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त हुआ। पिछले कुछ वर्षों में जीटीआर में प्रत्यक्ष करों का बढ़ता योगदान, कराधान में प्रगतिशीलता बढ़ाने के सरकार के प्रयास के अनुरूप रहा है। समय के साथ कर संग्रह की दक्षता में वृद्धि हुई है, जो प्रत्यक्ष करों के संग्रह की लागत में परिलक्षित होती है जो वित्त वर्ष 20 में सकल संग्रह के 0.66 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 23 में 0.51 प्रतिशत हो गई है।[26]

चार्ट I.37: वित्त वर्ष 23 और कोविड-पूर्व स्तर की तुलना में करों में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई

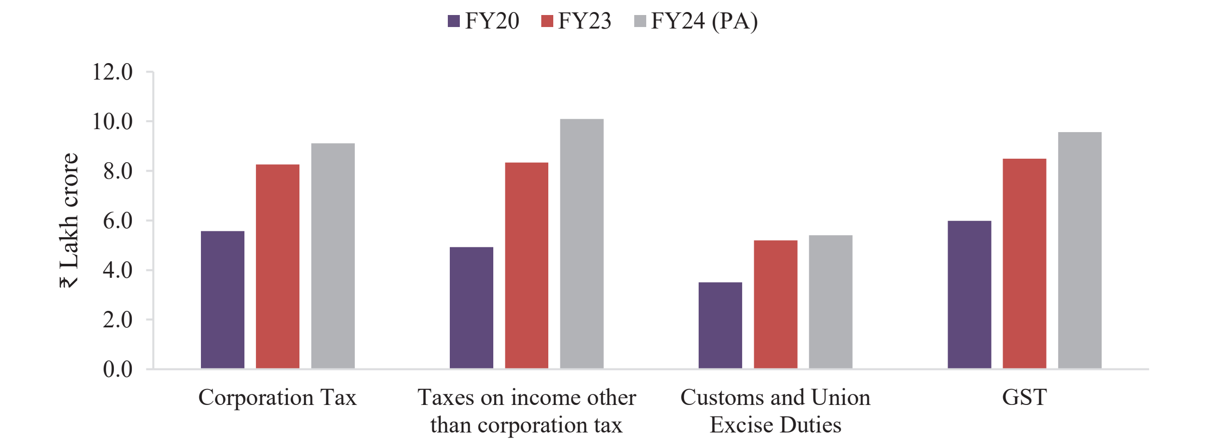

स्रोत: बजट एक नजर में, केंद्रीय बजट, वित्तीय वर्ष 22, वित्तीय वर्ष 23, वित्तीय वर्ष 24 अंतरिम बजट, केंद्र सरकार के लेखा – एक नजर में ख ख सीजीए का कार्यालय

1.25 वित्त वर्ष 2024 में अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि मुख्य रूप से जीएसटी संग्रह में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई। महामारी के बाद जीएसटी ई-वे बिल में भी वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि अन्त:राज्यीय व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार दोनों के लिए समान रूप से स्पष्ट है। जीएसटी संग्रह और ई-वे बिल निर्माण में वृद्धि समय के साथ बढ़ते अनुपालन को दर्शाती है।

चार्ट I.38: मजबूत ई-वे बिल उत्पादन मजबूत आर्थिक विकास गति की पुष्टि करता है

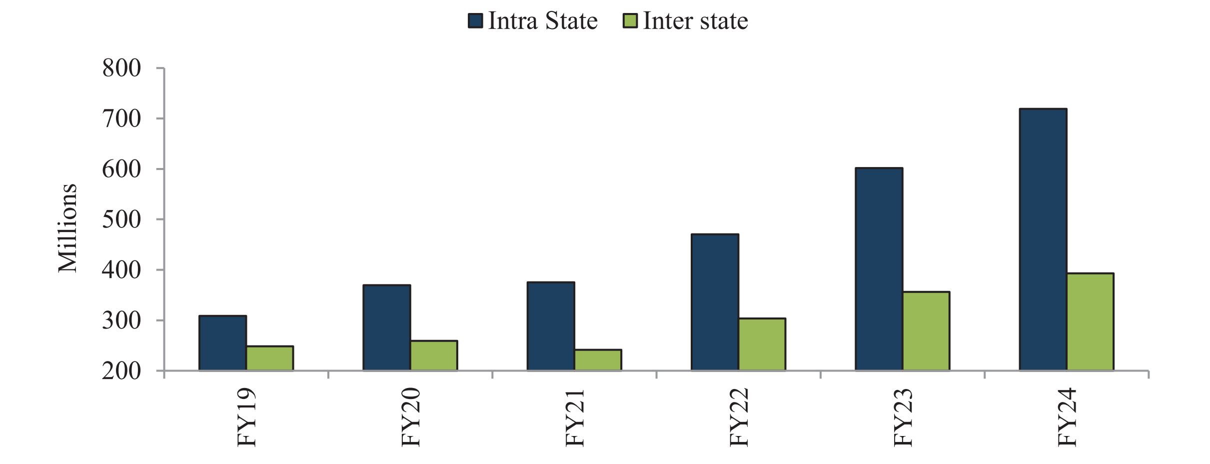

स्रोत: जीएसटी सांख्यिकी (https://www.gst.gov.in/download/gststatistics)

26 आयकर विभाग, समेकित समय (टाइम) श्रृंखला डेटा, वित्तीय वर्ष 2000-01 से 2022-23, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (https://tinyurl.com/3chx8v83)

1.26 पिछले सात वर्षों में, जीएसटी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और इस प्रक्रिया में, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए कर उछाल को बढ़ाने के माध्यम से काफी परिपक्व हो गया है। दरों की संख्या को कम करने, दर व्युत्क्रमण को समाप्त करने, समान उत्पादों के लिए ब्रॉड-बैंड दरें लागू करने तथा कर आधार का विस्तार करने के लिए दर संरचना को और अधिक युक्तिसंगत बनाने की मांग की गई है। मांगें गंभीर और कम गंभीर अपराधों के बीच अंतर करने, सामान्य गलतियों के संबंध में करदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने और विवादों के समाधान में तेजी लाने से संबंधित हैं।[27]

1.27 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) से प्राप्त आय, जिसकी घोषणा वित्त वर्ष 22 के केंद्रीय बजट में की गई थी, गति पकड़ रही है। एनएमपी में केंद्र सरकार के मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की मुख्य परिसंपत्तियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें वित्त वर्ष 22-25 की चार साल की अवधि में मुद्रीकरण के लिए 6 लाख करोड़ रुपये की क्षमता है। वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 24 के दौरान ₹4.3 लाख करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹3.9 लाख करोड़ की प्राप्तियां दर्ज की गई हैं।[28] 29 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 24 में ₹1.6 लाख करोड़ की आय में से ₹97 हजार करोड़ का योगदान दिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2025 में मुद्रीकृत की जाने वाली 33 परिसंपत्तियों की सांकेतिक सूची की पहचान की है और उसे प्रकाशित किया है। इससे निवेशकों द्वारा पूंजी आवंटन में सुधार करने में मदद मिलेगी, साथ ही सरकार को राजकोषीय समेकन के अपने प्रयास में सहायता मिलेगी।

केन्द्र सरकार के व्यय की प्रवृत्तियाँ

1.28 सरकार ने कमजोर वर्गों की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में निवेश जारी रखते हुए राजकोषीय समेकन का मार्ग अपनाया है। क्रमिक बजटों ने राजस्व व्यय में वृद्धि को नियंत्रित किया है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में कमी लाने के साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि देश में 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित कुल व्यय का हिस्सा उत्तरोत्तर बढ़ाया गया, जिससे व्यय की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 24 में सरकारी व्यय ने इस प्रवृत्ति को जारी रखा, जिसके अनुसार, अनंतिम वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, कुल व्यय वित्त वर्ष 21 में सकल घरेलू उत्पाद के 17.7 प्रतिशत से घटकर 15.0 प्रतिशत हो गया।

चार्ट I.39: व्यय का विवेकपूर्ण प्रबंधन

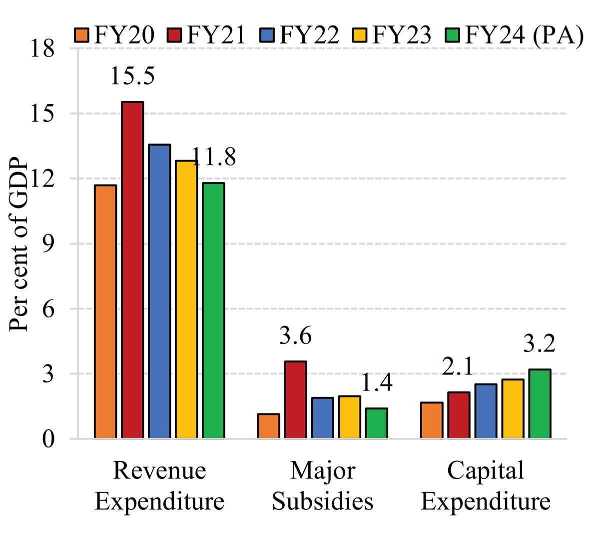

चार्ट I.40: केंद्र सरकार के प्रभावी पूंजीगत व्यय और जीडीपी अनुपात में वृद्धि[29]

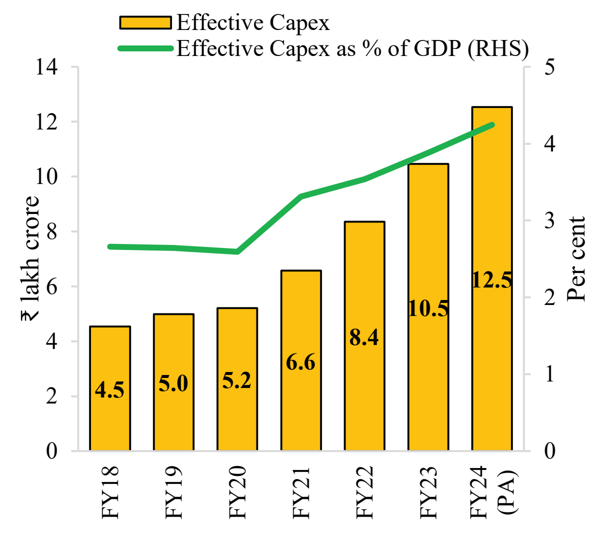

स्रोतः बजट एक नजर में, विभिन्न केंद्रीय बजट, केंद्र सरकार के खाते पर एक नजर - सीजीए का कार्यालय

27 https://tinyurl.com/2bam4ht8

28 https://tinyurl.com/d3cfceu3

29 प्रभावी पूंजीगत व्यय में पूंजीगत व्यय और पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए सहायता अनुदान शामिल हैं

चार्ट I.41: उत्पादक व्यय को प्राथमिकता देना

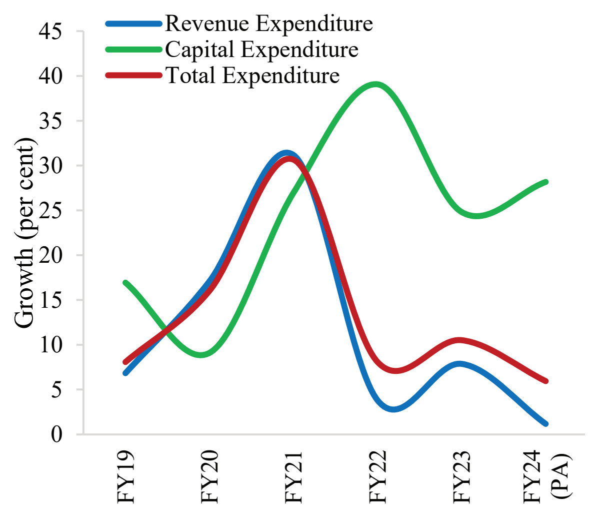

चार्ट I.42: व्यय की गुणवत्ता में सुधार

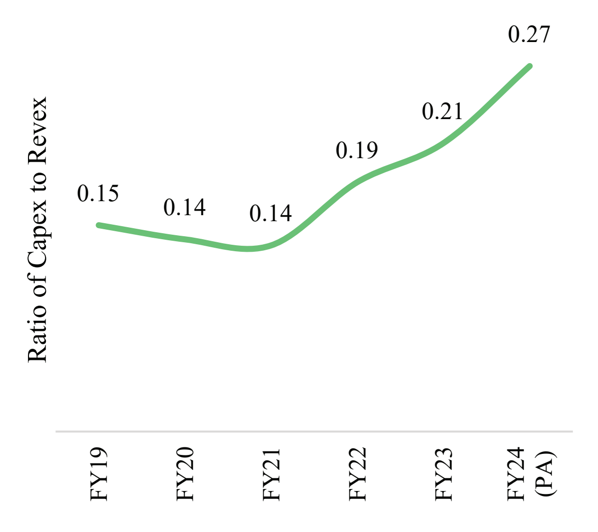

स्रोत: बजट एक नजर में, विभिन्न केंद्रीय बजट, केंद्र सरकार के खाते पर एक नजर ख्र सीजीए का कार्यालय

पूंजीगत व्यय ने अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाया है; अब निजी क्षेत्र के लिए कमान संभालने का समय आ गया है

1.29 पीए से पता चलता है कि वित्त वर्ष 24 के लिए पूंजीगत व्यय ₹9.5 लाख करोड़ रहा, जो साल दर साल आधार पर 28.2 प्रतिशत की वृद्धि है और वित्त वर्ष 20 के स्तर से 2.8 गुना अधिक है। अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय पर जोर आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक रहा है।

1.30 पूंजीगत व्यय का फोकस व्यापक रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग, रेलवे, रक्षा सेवाओं और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में खर्च करने से रसद (लॉजिस्टिक) संबंधी बाधाओं को दूर करके और उत्पादक क्षमताओं का विस्तार करके विकास को उच्च और दीर्घकालिक गति मिलती है। जैसा कि इस अध्याय में पहले चर्चा की गई है, केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में भी निजी निवेश शामिल होने लगा है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार राज्यों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान-सहायता वितरित करती रहती है, जिससे उन्हें अपने उत्पादक व्यय को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

1.31 इस समय, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बुनियादी ढांचे के विकास को सुविधाजनक बनाना और रसद चुनौतियों का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन निजी क्षेत्र पर यह दायित्व है कि वह अपने दम पर और सरकार के साथ साझेदारी में पूंजी निर्माण की गति को आगे बढ़ाए। वित्त वर्ष 19 और वित्त वर्ष 23 के बीच, समग्र जीएफसीएफ में निजी गैर-वित्तीय निगमों की हिस्सेदारी केवल 0.8 प्रतिशत अंक बढ़कर 34.1 प्रतिशत से 34.9 प्रतिशत हो गई। इसका मुख्य कारण आवासों, अन्य भवनों और संरचनाओं के अतिरिक्त भंडार (स्टॉक) में उनकी तेजी से बढ़ती हिस्सेदारी थी। मशीनरी और उपकरणों के मामले में पूंजी स्टॉक के अलावा उनका हिस्सा वित्त वर्ष 2022 से ही मजबूती से बढ़ना शुरू हुआ है, एक प्रवृत्ति जिसे उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा करने के लिए उनकी सुधरती हुई बॉटम-लाइन और तुलन पत्र (बैलेंस शीट) के बल पर बनाए रखने की जरूरत है।

तालिका I.2: केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय का व्यापक आधार पर परिनियोजन (मान हजार करोड़ रुपये में)			
क्षेत्र	**वित्त वर्ष 23**	**वित्त वर्ष 24 (पीए)**	**वृद्धि**
सड़क परिवहन और राजमार्ग	206.0	263.9	28.1%
रेलवे	159.3	242.6	52.3%
रक्षा सेवाएँ (पूंजीगत परिव्यय)	142.9	154.3	7.9%
राज्यों को अंतरण	92.7	122.9	32.5%
दूरसंचार	54.7	59.4	8.5%
आवासन एवं शहरी मामले	26.9	26.4	-1.6%
परमाणु ऊर्जा	13.8	14.5	5.1%
रक्षा (सिविल)	8.0	10.3	29.5%
पुलिस	8.2	9.7	18.7%
अंतरिक्ष	4.3	4.4	3.4%

स्रोत: व्यय प्रोफाइल का विवरण 3, केंद्रीय बजट 2024-25 (अंतरिम), केंद्र सरकार का लेखा एक नजर में ख्र सीजीए का कार्यालय

राजस्व व्यय वृद्धि नियंत्रित है

1.32 पीए से पता चलता है कि बजट विहित अनुमानों की तुलना में वित्त वर्ष 24 के लिए कुल व्यय की राशि ₹60.6 हजार करोड़ कम है। तथापि, बजट विहित अनुमानों से कम इन अनुमानों के कारण राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे ग्रामीण विकास और शिक्षा, जहां आवंटन बजट विहित अनुमानों से काफी अधिक है, पर कोई समझौता नहीं हुआ है। कम उधारी लागतों की सहायता से प्रभावी व्यय प्रबंधन से वित्त वर्ष 24 में ब्याज के भुगतान पर बजटीय व्यय का सीमान्त निम्नवर्ती परिशोधन हुआ है।

1.33 तथापि, भले ही ब्याज भुगतान पर व्यय बजटीय व्यय से कम हुआ है, लेकिन यह वित्त वर्ष 24 (पीए) में राजस्व व्यय का 30.4 प्रतिशत है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण और निजीकरण से राजस्व के साथ मिलकर मध्यावधि में राजकोषीय समेकन हेतु प्रतिबद्धता, राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान की हिस्सेदारी को कम करने के लिए आवश्यक होगी ताकि अधिक से अधिक राजकोषीय गुंजाइश पैदा की जा सके।

1.34 वित्त वर्ष 2024 में उर्वरक और खाद्य सब्सिडी[30] में क्रमशः 24.6 प्रतिशत और 22.4 प्रतिशत की कमी होने के कारण प्रमुख सब्सिडी पर व्यय में सालाना आधार पर 22.1 प्रतिशत की गिरावट आई। रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण वित्त वर्ष 2023 में उर्वरकों की कीमतों में भारी वृद्धि देखी गई थी, जिससे इसकी सब्सिडी के लिए अधिक व्यय हुआ। हालांकि, वित्त वर्ष 2024 में आपूर्ति शृंखलाओं ने अनुकूलित किया और परिणामस्वरूप उर्वरकों की कीमतें मोटे तौर पर संघर्ष-पूर्व स्तरों पर लौट आई हैं। इससे उर्वरक सब्सिडी पर होने वाला व्यय कम हो गया। आबादी के कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए स्थापित अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी भी धीरे-धीरे मजबूत हो रही है।

राज्य सरकार के वित्त का अवलोकन

1.35 वित्त वर्ष 24 में राज्य सरकारों ने अपने वित्त में सुधार जारी रखा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रकाशित 23 राज्यों[31] के वित्त के प्रारंभिक अलेखापरीक्षित अनुमानों के आधार पर यह सुझाया जाता है कि इन 23 राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा बजटीय आंकड़े ₹9.1 लाख करोड़ से 8.6 प्रतिशत कम था। इसका मतलब है कि इन राज्यों के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा बजटीय 3.1 प्रतिशत के मुकाबले 2.8 प्रतिशत रहा। राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही खर्च की गुणवत्ता में भी काफी सुधार हुआ।[32]

30 उर्वरक सब्सिडी में पोषक तत्व आधारित उर्वरक सब्सिडी और यूरिया सब्सिडी शामिल है

31 प्रमुख राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

32 आरबीआई के ई-स्टेट्स डेटाबेस और राज्य वित्त रिपोर्ट के अध्ययन से उपलब्ध बजटीय आंकड़े (https://tinyurl.com/ywv3wvdr)

चार्ट I.43: राज्य का जीएफडी जीडीपी के 3 प्रतिशत के निशान से नीचे	चार्ट I.44: राज्यों के व्यय की गुणवत्ता में सुधार

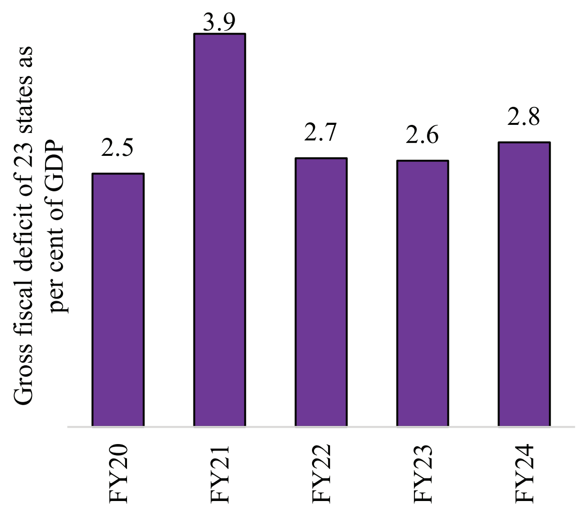

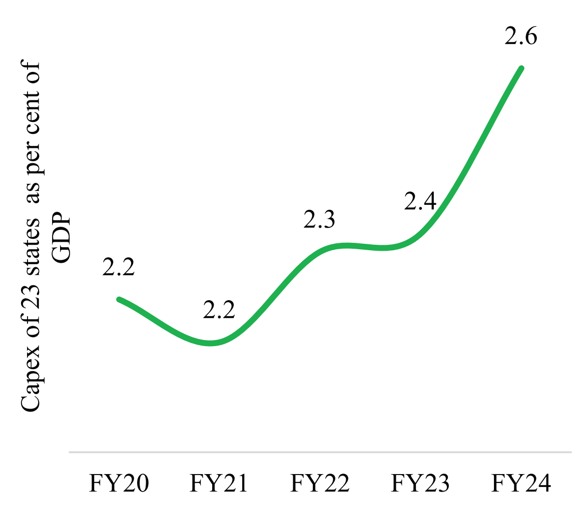

स्रोतः राज्य लेखा रिपोर्ट, सीएजी; नोट ख्र वित्त वर्ष 24 के आंकड़े प्रारंभिक वास्तविक आंकड़े हैं

चार्ट I.45: राज्यों की कुल बकाया देनदारियाँ सकल घरेलू उत्पाद का % की दर से घट रही हैं

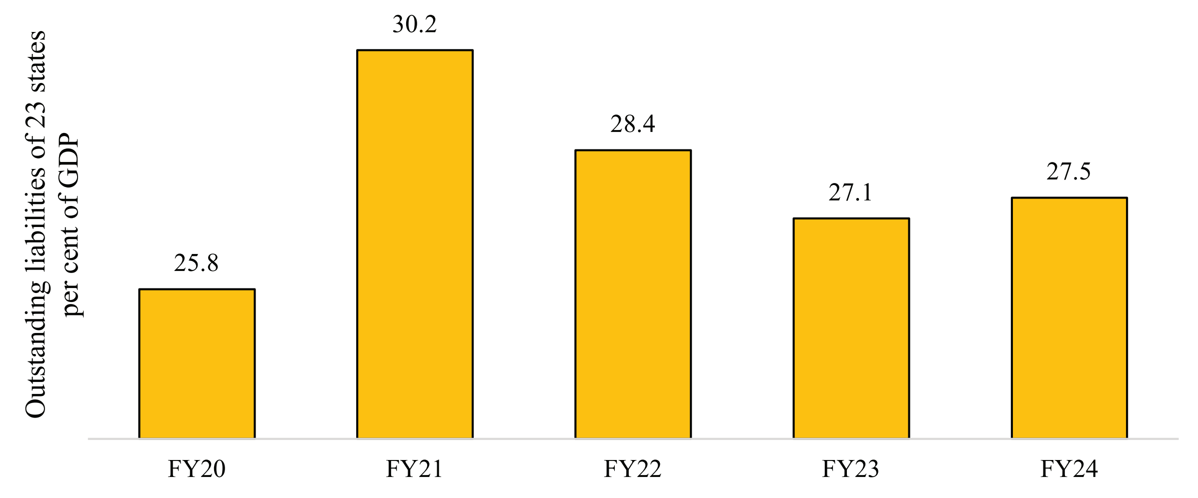

स्रोतः विवरण 19: राज्य सरकारों की कुल बकाया देनदारियाँ, राज्य वित्तः बजट का एक अध्ययन, आरबीआई

1.36 चार्ट I.46 से I.49 राज्यों के वित्त को संक्षेप में प्रस्तुत किया है।[33] केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को किए जाने वाले अंतरण अत्यधिक प्रगतिशील हैं, जिन राज्यों का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) कम है, उन्हें उनके जीएसडीपी के सापेक्ष अधिक अंतरण प्राप्त हो रहा है। तथापि, राजस्व के दृष्टिकोण से, कुछ अपवादों को छोड़कर, अमीर राज्य अपने जीएसडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा करों के रूप में जुटाने में सक्षम हैं। प्राप्तियों के पक्ष में इन गतिशीलता का संयुक्त परिणाम यह है कि भारत में राजकोषीय अंतरण की प्रणाली के तहत गरीब राज्य अपने जीएसडीपी के सापेक्ष अधिक सार्वजनिक व्यय करने में सक्षम हैं। विकास और वृद्धि को प्रोत्साहित करने में सार्वजनिक व्यय के महत्व को देखते हुए, यह देश में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए अपरिहार्य है।

33 चार्ट I-46 से I-49 वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 23 के लिए संबंधित चरों के औसत पर आधारित हैं। कुल 17 राज्यों, यानी आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए ग्राफ तैयार किए गए हैं। वित्त वर्ष 23 के लिए महाराष्ट्र के जीएसडीपी और पीसी जीएसडीपी को महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से लिया गया है।

चार्ट I.46; राज्यों को अंतरण की प्रगतिशील प्रकृति

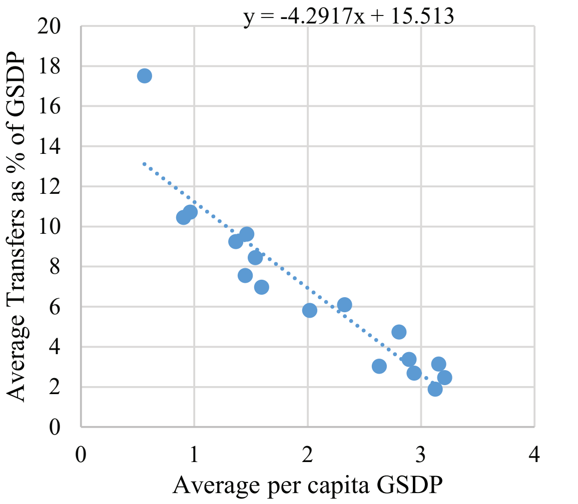

चार्ट I.47: राज्यों के कर संबंधी प्रयास

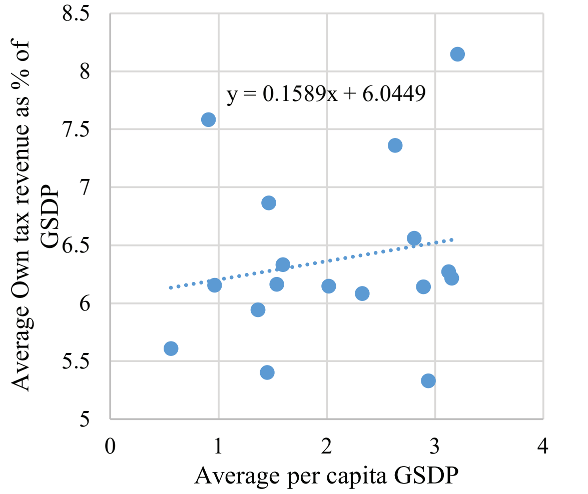

चार्ट I.48: राज्यों का कुल व्यय

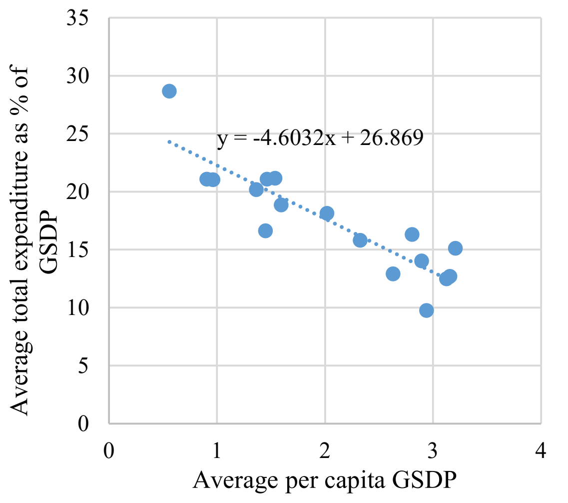

चार्ट I.49: राज्यों का राजकोषीय घाटा

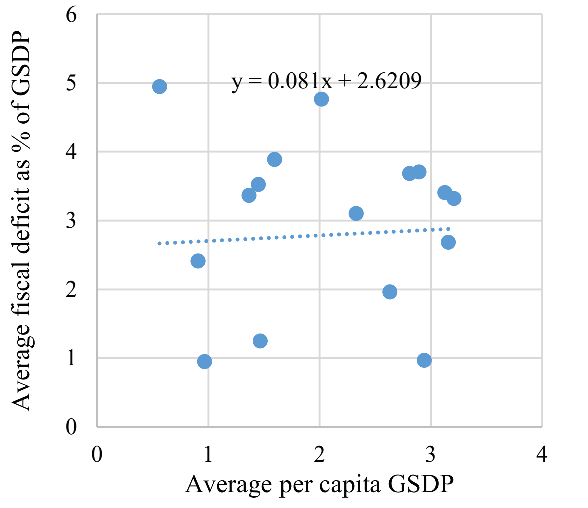

स्रोत: राज्य लेखा रिपोर्ट, सीएजी

सामान्य सरकारी ऋण

1.37 कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने आम तौर पर राजकोषीय समेकन पर ध्यान केंद्रित किया है, जो वित्त वर्ष 23 तक सरकार के घटते ऋण प्रक्षेपवक्र में परिलक्षित था। प्राथमिक घाटे में गिरावट होने के बावजूद वित्त वर्ष 24 में सामान्य सरकारी ऋण से जीडीपी अनुपात थोड़ा बढ़ा क्योंकि मौद्रिक सख्ती के कारण ब्याज दरों में उछाल आया, जबकि मुद्रास्फीति के दबाव में गिरावट के परिणामस्वरूप बजट से कम नाममात्र जीडीपी की वृद्धि हुई। हालांकि, मौद्रिक नीति में ढील की बढ़ती संभावनाओं के साथ-साथ थोक मूल्य मुद्रास्फीति (डब्ल्यूपीआई) में तेजी और राजकोषीय समेकन के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता के साथ, ऋण अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति फिर से शुरू होने की संभावना है।

चार्ट I.50: सामान्य सरकारी देनदारियों और जीडीपी का अनुपात वित्त वर्ष 21 में अपने चरम से नीचे आ गया

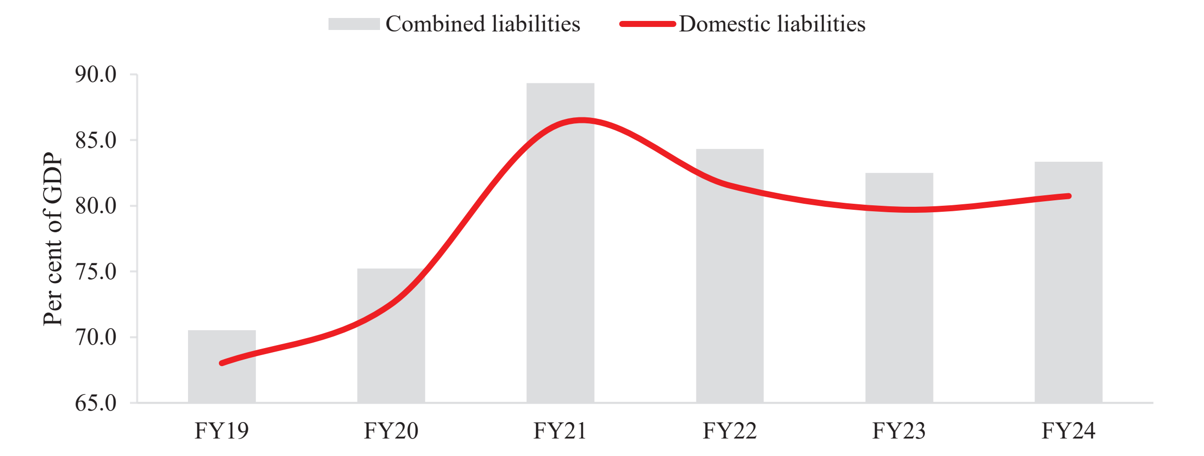

स्रोत: तालिका 112, केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त देनदारियाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, आरबीआई। नोट्स[34]

चार्ट I.51: प्राथमिक घाटा कम हुआ, तथा विकास-ब्याज दर अंतर सकारात्मक बना रहा

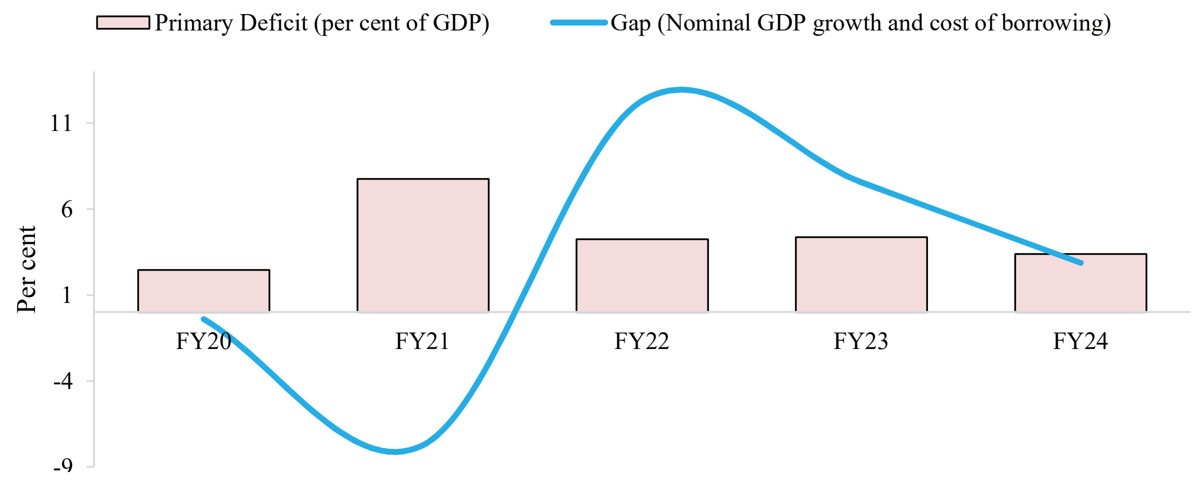

स्रोत: प्राथमिक घाटा - भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस, आरबीआई; नाममात्र जीडीपी वृद्धि - वित्त वर्ष 24 के लिए अनंतिम अनुमान, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, एमओएसपीआई; उधार लेने की लागत - भारतीय अर्थव्यवस्था पर आरबीआई डेटाबेस, बजट पर एक नजर।[35]

1.38 केंद्र सरकार के ऋण की विशेषता कम मुद्रा और ब्याज दर जोखिम है। ऐसा ऋण पोर्टफोलियो में बाहरी ऋण की कम हिस्सेदारी और लगभग सभी बाहरी उधार आधिकारिक स्रोतों से होने के कारण है। केंद्र सरकार के ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल के क्रमिक विस्तार से रोलओवर जोखिम कम हो रहा है। हाल के वर्षों में पाँच वर्ष से कम अवधि में परिपक्व होने वाली दिनांकित प्रतिभूतियों के अनुपात में लगातार गिरावट देखी गई है। केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक की भारित औसत परिपक्वता मार्च 2011 के अंत में 9.6 वर्ष से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 12.5 वर्ष हो गई है।[36]

1.39 राजकोषीय मीट्रिक में निरंतर सुधार की प्रक्रिया एक शुरुआत है जिसका असर भारत की क्रेडिट रेटिंग पर पड़ने लगा है। 13 वर्षों में पहली बार, एस-पी ग्लोबल रेटिंग्स ने मजबूत आर्थिक विकास, मजबूत आर्थिक बुनियादी बातों और

34 वित्त वर्ष 23 के लिए संयुक्त देनदारियों के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं, और वित्त वर्ष 24 के आंकड़े बजट अनुमान हैं। जीडीपी के आंकड़े वित्त वर्ष 21, वित्त वर्ष 22, वित्त वर्ष 23 के लिए संशोधित अनुमान और वित्त वर्ष 24 के लिए पीई हैं।

35 उधार लेने की लागत की गणना अवधि (टी) और (टी-1) के औसत ऋण के प्रतिशत के रूप में कुल ब्याज भुगतान के रूप में की जाती है।

36 पीडीएमसी तिमाही रिपोर्ट की तालिका 4.2 (जनवरी - मार्च 2024) (https://tinyurl.com/mrxaf4kw)

सरकारी खर्च की बेहतर संरचना के आधार पर मई 2024 में भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को श्स्थिरश से श्सकारात्मकश में अपग्रेड किया गय। एस एंड पी ने उल्लेख किया कि सतर्क मौद्रिक और राजकोषीय नीति जो आर्थिक लचीलापन में सुधार करते हुए सामान्य सरकारी ऋण और ब्याज के बोझ को कम करती है जिससे अगले 2 वर्षों में उच्च रेटिंग का कारण बन सकती है। उन्होंने आगे यह भी संकेत दिया कि इस तरह के अपडेट के लिए राजकोषीय समेकन हेतु निरंतर प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी, जो संरचनात्मक आधार पर सामान्य सरकारी घाटे को 7 प्रतिशत से कम कर दे। अगर ऐसा होता, तो भारत की 10-वर्षीय बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड 30 से 50 आधार अंकों के बीच गिर जाएगी। बेंचमार्क उधार लागत में गिरावट से सामान्य रूप से ब्याज की दरों में गिरावट आएगी, जिससे परिवारों और व्यवसायों के लिए उधार लेने की कुल लागत कम हो जाएगी। यह अपने आप में एक राजकोषीय प्रोत्साहन होगा।

मुद्रास्फीति दबाव में कमी

1.40 वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बावजूद, वित्त वर्ष 24 में घरेलू मुद्रास्फीति का दबाव कम हुआ। वित्त वर्ष 23 में औसतन 6.7 प्रतिशत के बाद, वित्त वर्ष 24 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.4 प्रतिशत हो गई। यह सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किए गए उपायों के संयोजन के कारण हुआ है। केंद्र सरकार ने खुले बाजार में बिक्री, विनिर्दिष्ट दुकानों में खुदरा बिक्री, समय पर आयात, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर की कीमतों में कमी और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती जैसे त्वरित उपाय किए। आरबीआई ने मई 2022 और फरवरी 2023 के बीच नीतिगत दरों में कुल 250 बीपीएस की वृद्धि की। इसने नकदी के स्तर को भी कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया और बाजार सहभागियों के साथ लगातार और सुसंगत संपर्क बनाए रखा। भले ही उच्च नीतिगत दरें प्रणाली के माध्यम से प्रेषित की जाती हैं, आरबीआई पर्याप्त नकदी के साथ विकास का समर्थन करना जारी रखता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मुद्रास्फीति टिकाऊ आधार पर 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। इन उपायों के प्रभाव सीपीआई मुद्रास्फीति - हेडलाइन के नवीनतम आंकड़ों में परिलक्षित होते हैं। सीपीआई मुद्रास्फीति जून 2024 में 5.1 प्रतिशत पर पहुंच गई, और मुख्य मुद्रास्फीति घटकर 3.1 प्रतिशत हो गई। नतीजतन, भारत अपने समकक्षों के बीच एकमात्र ऐसा देश था जिसने वित्त वर्ष 22 - वित्त वर्ष 24 की अवधि में उच्च-विकास और निम्न-मुद्रास्फीति पथ पर कदम रखा (चार्ट I.53)। यह इस तथ्य के बावजूद है कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण खाद्य मुद्रास्फीति के मोर्चे पर दबाव था।

चार्ट I.52: घटती हुई मुख्य मुद्रास्फीति लेकिन अस्थिर खाद्य मुद्रास्फीति

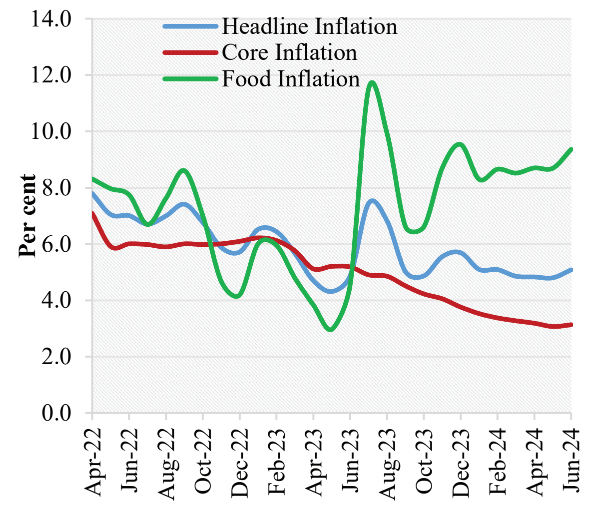

स्रोतः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वेयरहाउस पर जारी आंकड़ों पर आधारित गणना

चार्ट I.53: भारत एक उच्च-विकास और निम्न-मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था है

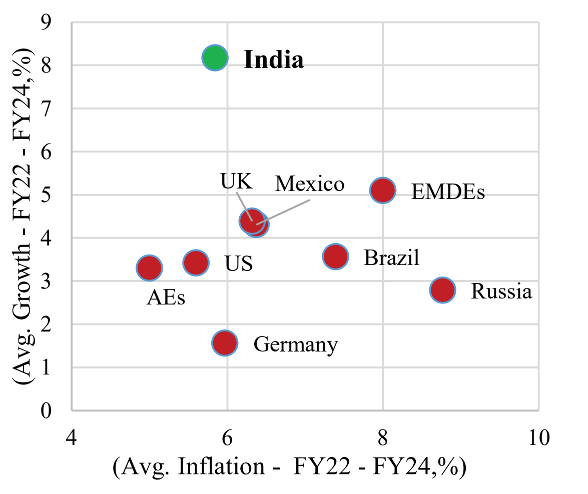

स्रोतः आईएमएफ डब्ल्यूईओ डेटाबेस (अप्रैल 2024), एमओएसपीआई

वित्तीय प्रणाली लचीली बनी हुई है

1.41 बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली पर आरबीई की सतर्कता और इसकी त्वरित विनियामक कार्रवाइयां यह सुनिश्चित करती हैं कि प्रणाली किसी भी समष्टि आर्थिक या प्रणालीगत झटके का सामना कर सके। आरबीई की जून 2024 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के डेटा से पता चलता है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (जीएनपीए) अनुपात मार्च 2024 में घटकर 2.8 प्रतिशत हो गया, जो 12 वर्ष का निचला स्तर है। आरबीई द्वारा जोखिम भारों के अनिवार्य संशोधन के कारण प्रणाली-व्यापी पूंजी से लेकर जोखिम-भारित आस्ति अनुपात में (सीआरएआर) में वित्त वर्ष 24 की तुलना में 37 आधार अंकों (बीपीएस) की मामूली गिरावट आई, लेकिन विनियामक सीमा से यह काफी ऊपर रहा। मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार एससीबी की लाभप्रदता इक्विटी पर रिटर्न और संपत्ति पर रिटर्न अनुपात क्रमशः 13.8 प्रतिशत और 1.3 प्रतिशत पर स्थिर रही। समष्टिमूलक दबाव परीक्षणों से भी पता चलता है कि एससीबी गंभीर दबाव परिदृश्यों में भी न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

1.42 आरबीआई विनियामक कार्रवाई करने में सक्रिय रहा है। अप्रतिभूत ऋण श्रेणी में अत्यधिक वृद्धि को विनियमित करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के उपाय के रूप में, आरबीआई ने इस पोर्टफोलियो के लिए मानदंड कड़े कर दिए हैं। अप्रतिभूत ऋणों में वृद्धि समग्र ऋण की वृद्धि से अधिक रही है। इस समस्या से निपटने के लिए, आरबीआई ने निर्देश दिया कि बैंकों और एनबीएफसी के लिए उपभोक्ता ऋण जोखिम पर पहले के 100 प्रतिशत की तुलना में 125 प्रतिशत का जोखिम भार लगेगा। बैंकों और गैर-बैंक वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) द्वारा क्रेडिट कार्ड ऋणों के लिए जोखिम भार पहले के 125 प्रतिशत और 100 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमशः 150 प्रतिशत और 125 प्रतिशत तय किया गया। त्वरित विनियामक कार्रवाई बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को प्रतिकूल घटनाक्रमों से बचाती है और बाजार सहभागियों में विश्वास पैदा करती है। बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता उत्पादक अवसरों के वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी और वित्तीय चक्र को लंबा करेगी, जो दोनों ही आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

भारत का विदेशी क्षेत्र काफी अनिश्चितताओं के बावजूद भी सुरक्षित रूप से अग्रसर हो रह है

1.43 विदेशी मोर्चे पर, वित्त वर्ष 24 के दौरान व्यापारिक निर्यात में नरमी जारी रही, जिसका मुख्य कारण कमजोर वैश्विक मांग और लगातार भू-राजनीतिक तनाव है। हालांकि, वस्तु की कीमतों में गिरावट के कारण भारत के व्यापारिक आयात में तेज गिरावट के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 24 में व्यापार घाटा कम हुआ। हालाँकि, भारत का सेवा निर्यात मजबूत बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 24 में 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2024 में निर्यात (माल और सेवाएँ) में 0.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि घरेलू बाजार में मजबूत मांग के बावजूद कुल आयात में 4.9 प्रतिशत की गिरावट आई।[37] निवल निजी अंतरण, जिसमें ज्यादातर विदेश से विप्रेषित धन शामिल है जो वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 106.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। परिणामस्वरूप, चालू खाता घाटा (सीएडी) वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 0.7 प्रतिशत पर रहा, जो वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.0 प्रतिशत के घाटे से बेहतर है।

1.44. भारत की विकास गाथा, प्रगतिशील नीति सुधार, आर्थिक स्थिरता, राजकोषीय विवेक और आकर्षक निवेश अवसरों के बारे में आशावाद द्वारा समर्थित, भारत ने वित्त वर्ष 24 में मजबूत एफपीआई प्रवाह देखा, जिसने सीएडी को वित्तपोषित करने और आरबीआई को पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाने में सहायता की। पिछले दो वर्षों में निवल बहिर्वाह के मुकाबले वित्त वर्ष 24 के दौरान निवल एफपीआई प्रवाह 44.1 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। हालांकि, बढ़ते संशयवाद के कारण एफडीआई प्रवाह में गिरावट की वैश्विक घटना के एक हिस्से के रूप में निवल एफडीआई प्रवाह में काफी हद तक कमी देखी गई। भारत में निवल एफडीआई प्रवाह वित्त वर्ष 23 के दौरान 42.0 बिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर वित्त वर्ष 24 में 26.5 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया। हालांकि, वित्त वर्ष 24 में सकल एफडीआई प्रवाह में केवल 0.6 प्रतिशत की कमी देखी गई। निवल प्रवाह में यह संकुचन मुख्य रूप से प्रत्यावर्तन/विनिवेश में उछाल के कारण हुआ।

37 तालिका 132. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका, आरबीआई https://tinyurl.com/yne8sbw7

चार्ट I.54: वित्त वर्ष 2024 में सीएडी घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत रह गया

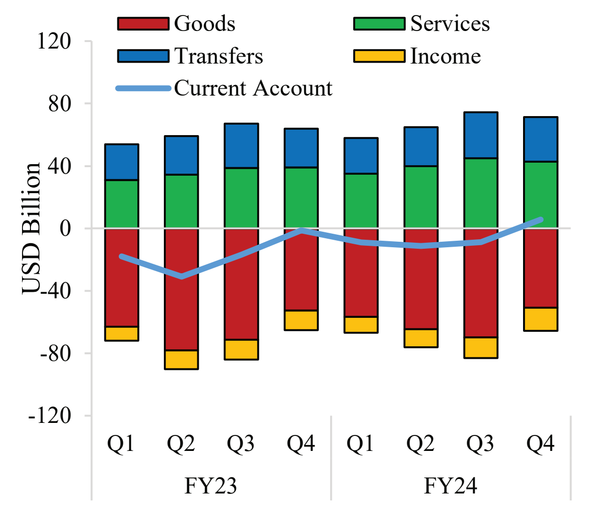

स्रोत: तालिका 196, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी नियम पुस्तिका, आरबीआई

चार्ट I.55: एफपीआई प्रवाह ने सीएडी को वित्तपोषित करने और विदेशी मुद्रा भंडार बनाने में सहायता की

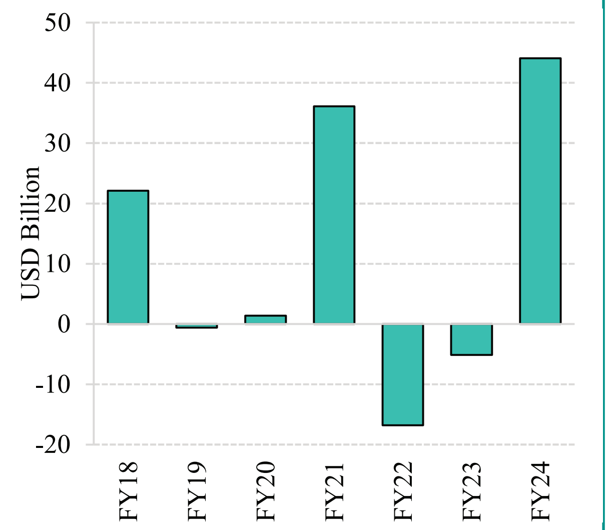

स्रोत: तालिका 130 भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी नियम पुस्तिका, आरबीआई

1.45 कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के वैदेशिक क्षेत्र को सुविधाजनक विदेशी मुद्रा भंडार और स्थिर विनिमय दर के साथ कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जा रहा है। मार्च 2024 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने के अनुमानित आयात और कुल वैदेशिक ऋण के 100 प्रतिशत से अधिक को कवर करने के लिए पर्याप्त था। वित्त वर्ष 24 में उभरते बाजार के अपने समकक्षों के बीच ₹ सबसे कम अस्थिर मुद्राओं में से एक रहा है। भारत के वैदेशिक ऋण सुभेद्यता संकेतक भी बेहतर बने रहे। मार्च 2024 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में वैदेशिक ऋण 18.7 प्रतिशत के निम्न स्तर पर रहा। मार्च 2024 तक कुल ऋण के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात 97.4 प्रतिशत रहा।

चार्ट I.56: अप्रैल 2023 से जून 2024 तक रुपया सबसे स्थिर मुद्राओं में से एक था

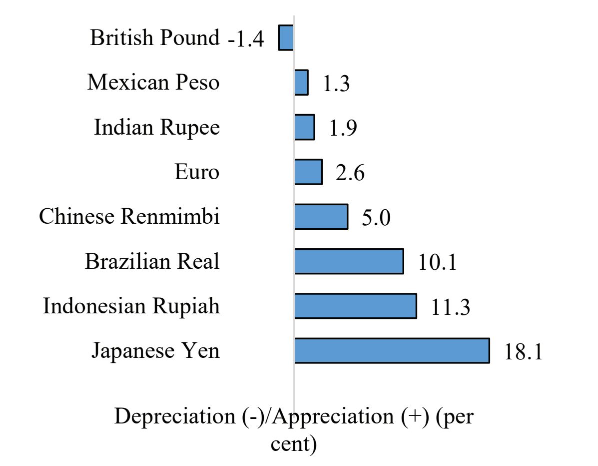

स्रोत: द्विपक्षीय विनिमय दरें, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स

चार्ट I.57: लगभग 11 महीने के आयात को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार

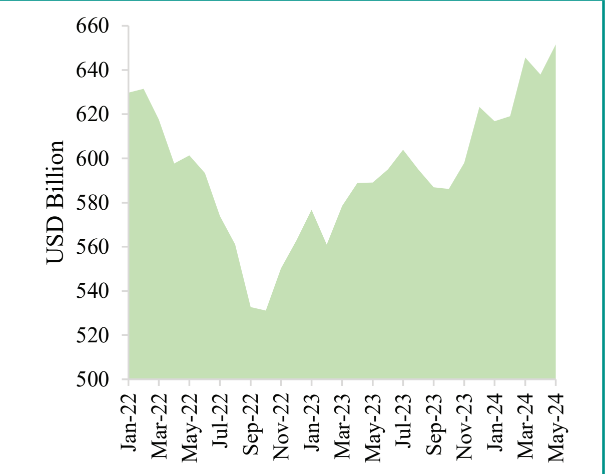

स्रोत: तालिका 205, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, भारतीय रिजर्व बैंक।

समष्टिगत सुभेद्यता (मैक्रो वल्नरेबिलिटी) में कमी

1.46 कुशल और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के माध्यम से राजकोषीय समेकन की अपनी खोज में, सरकारराजकोषीय ग्लाइड पाथ पर टिकी हुई है। सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत तक गिरने या उससे कम होने की उम्मीद है। इस प्रतिबद्धता ने सॉवरेन ऋण को टिकाऊ बनाए रखने में मदद की है, जिससे सॉवरेन बंधपत्र आय और कीमत ख़लागत अंतर पर नियंत्रण बना हुआ है। इन सभी कारकों ने मिलकर मैक्रोइकॉनोमिक वातावरण को स्थिर रखा है और टिकाऊ विकास के लिए एक मंच प्रदान किया है। यह मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स (समिष्टि आर्थिक भेद्यता सूचकांक) के नीचे की ओर जाने वाले प्रक्षेपवक्र से प्रतिबिंबित होता है – यह सूचकांक भारत के राजकोषीय घाटे, चालू खाता घाटे और मुद्रास्फीति को मिलाकर बनाया गया है।

चार्ट I.58: बाह्य अनिश्चितता में वृद्धि के बावजूद मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में कमी

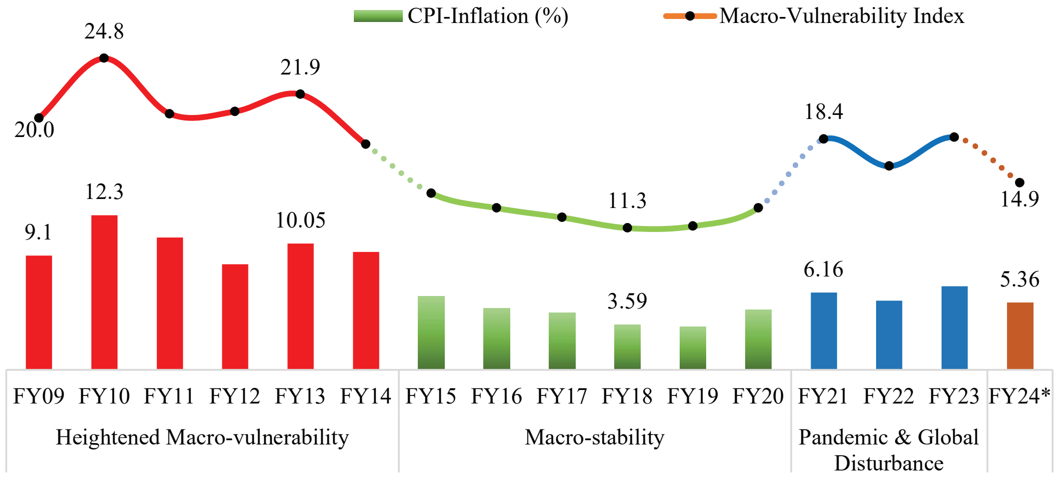

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित चालू खाता घाटा और केंद्रीय बजट दस्तावेजों में प्रकाशित राजकोषीय घाटे के आंकड़ों का उपयोग करके गणना की गई। नोट[38]

बॉक्स I.2: सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करना

एक सुदृढ़ और गतिशील सांख्यिकीय प्रणाली सुविज्ञ नागरिकों, डेटा-संचालित नीतियों और निर्णय लेने की आधारशिला होती है। सरकारी सांख्यिकी सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार प्रशासनिक और सर्वेक्षण सांख्यिकी को मजबूत करने, क्षमता निर्माण और डेटा की गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार करने के उद्देश्य से कई कदम उठा रही है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आधारशिला

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली के नियोजित और एकीकृत विकास के लिए नोडल मंत्रालय है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सकल घरेलू उत्पाद, मूल्य एवं मात्रा सूचकांक तथा समष्टि आर्थिक एवं क्षेत्रीय महत्व के देशव्यापी सर्वेक्षण प्रकाशित करके मुख्य सांख्यिकी तैयार करता है। मंत्रालय ने विभिन्न नए सर्वेक्षण शुरू किए हैं, जैसे कि असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण, समय का उपयोग सर्वेक्षण और सेवा क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के लिए प्रायोगिक -अध्ययन शुरू किया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की आवृत्ति बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तिमाही अनुमानों के सृजन को बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहा है। बेहतर डेटा एकत्र और प्रसंस्करण के लिए आधुनिक सूचना

38 वित्त वर्ष 2009 से वित्त वर्ष 2012 तक खुदरा मुद्रास्फीति श्रम ब्यूरो द्वारा जारी 'औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' पर आधारित है। और वित्त वर्ष 2013 से वित्त वर्ष 2024 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी सीपीआईसंयुक्त पर आधारित है; वित्त वर्ष 2023 के लिए सकल राजकोषीय घाटे का डेटा एक संशोधित अनुमान है, और वित्त वर्ष 2024 के लिए बजट अनुमान है।

प्रौद्योगिकी उपकरणों को अपनाया जा रहा है। प्रशासनिक डेटा के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, एक राष्ट्रीय मेटाडेटा संरचना भी विकसित की जा रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक केंद्रीकृत डेटाबेस और भंडारण प्रणाली बनाने के उद्देश्य से एकीकृत डेटा पोर्टल परियोजना की परिकल्पना की है। मंत्रालय अधिक सूचनाप्रद नीतिगत निर्णय लेने के लिए विभिन्न सर्वेक्षणों की आवृत्ति बढ़ाने के लिए भी पहल कर रहे हैं। भारत के 2047 लक्ष्यों को देखते हुए, विकास नीति के लिए यह महत्वपूर्ण है कि (क) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पास वांछित गुणवत्ता, नियमितता और समयबद्धता के साथ सभी आवश्यक आंकड़े तैयार करने और एकीकृत करने की पूरी क्षमता हो और (ख) संबंधित मंत्रालयों के प्रशासनिक और लेन-देन संबंधी आंकड़ों की गुणवत्ता और समयबद्धता को ऐसे स्तर पर लाया जाए जिससे समयबद्ध सुधार की पूरी सुविधा मिल सके।

सांख्यिकी डेटाबेस को मजबूत करने के लिए आगे उठाये जाने वाले कदम

क) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में महत्वपूर्ण आर्थिक सांख्यिकी के बेस रिविजन के लिए व्यापक अभ्यास किया जा रहा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 2012 से 2024 में बदलने की कवायद शुरू की गई है। सकल घरेलू उत्पाद के लिए आधार वर्ष तय करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर एक सलाहकार समिति गठित की गई है। यह महत्वपूर्ण है कि सकल घरेलू उत्पाद, विभिन्न मूल्य सूचकांक और आईआईपी जैसे मात्रा सूचकांक जैसी महत्वपूर्ण डेटा श्रृंखलाओं के 'आधार वर्ष' को जल्द से जल्द सबसे हाल के व्यवहार्य वर्ष में अद्यतन किया जाए। वस्तुओं और सेवाओं के लिए उत्पादक मूल्य सूचकांक के निर्माण के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाई जा सकती है, ताकि लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति की घटनाओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके। आईआईपी जैसे सूचकांकों के राज्य-स्तरीय संस्करण उभरते भौगोलिक स्वरुप को समझने में मदद करेंगे। नियमित अंतराल पर निजी क्षेत्र के पूंजी निर्माण को समझने में मदद करने वाले सर्वेक्षण डेटा से नीति निर्माण में भी मदद मिलेगी।

ख) विभिन्न विभागों द्वारा एकत्र की गई आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लिए उच्च आवृत्ति मूल्य निगरानी डेटा को इस तरह से जोड़ा जा सकता है कि खेत से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक प्रत्येक चरण में कीमतों का निर्माण गणना योग्य और निगरानी योग्य हो। इससे आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा 'प्रशासनिक कार्रवाई की प्रभावशीलता' में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

ग) 1.3 करोड़ से अधिक संस्थाएँ माल और सेवा कर के तहत पंजीकृत हैं और रिटर्न दाखिल करती हैं। यदि वस्तु एवं सेवा कर के विस्तृत आंकड़े उपलब्ध करा दिए जाएं, तो इससे व्यवसायों की स्थिति का विश्लेषण करने, ऋण आवेदनों की जांच करने, नकदी प्रवाह आधारित ऋण के लिए सहायता प्रदान करने तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं को गहराई से समझने में सहायता मिलेगी।

घ) XV वें वित्त आयोग ने कहा है, "भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे लगभग सभी राज्यों के लिए लेखा संकलन और अंतिम रूप देने की भूमिका निभाने का दायित्व सौंपा गया है, साथ ही वह संघ और राज्यों दोनों का लेखा परीक्षक भी है, पहले से ही समान राजकोषीय डेटा मानक स्थापित करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। इससे अंततः संघ और राज्यों का राजकोषीय सांख्यकी ग्रैन्युलैर लेवल डेटा भी सार्वजनिक वेब पोर्टल के माध्यम से मानकीकृत डेटा के रूप में उपलब्धता हो सकेगा जिसका उपयोग पूर्व लेखापरीक्षित राजकोषीय डेटा और चालू वर्ष के लिए उच्च आवृत्ति वाले राजकोषीय डेटा दोनों के लिए डाउनलोड करने योग्य डेटाबेस प्रारूपों में किया जा सकेगा।"[39] केंद्र और राज्यों के लेखापरीक्षित खातों की डेटाबेस प्रारूपों में ग्रैनुलर टाइम सीरीज राजकोषीय विश्लेषण और नीति को बहुत आसान बना देगी।

ङ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में उत्पादन और रोजगार की गतिशीलता के लिए नियमित संकेतक आवश्यक होते हैं, क्योंकि इनमें विकास और रोजगार सृजन की क्षमता होती है।

39 https://tinyurl.com/2dbutsvt

च) उद्योग-वार बैंक ऋण के सकल संवितरण (वर्तमान में उपलब्ध बकाया ऋण के आंकड़ों के विपरीत), घरेलू और बाहरी इक्विटी और ऋण मार्गों और अन्य वित्तपोषण स्रोतों के माध्यम से उद्योग-वार मासिक सकल वित्तीय प्रवाह पर जानकारी प्रकाशित की जा सकती है।

छ) बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय प्रवाह और विभिन्न बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में प्राप्त भौतिक प्रगति – क्षेत्रीय और भौगोलिक रूप से वर्गीकृत को कम से कम वार्षिक आधार पर समेकित करने के लिए एक नियमित तंत्र की भी आवश्यकता है।

ज) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसी योजनाओं द्वारा उत्पन्न डेटा की बड़ी मात्रा, जो अस्पताल में भर्ती होने, रोगियों के चिकित्सा इतिवृत या जनसांख्यिकीय विवरण जैसे विवरण दर्ज करती है। इनका उपयोग रोग निगरानी, निवारक चिकित्सा आदि के लिए किया जा सकता है।

झ) श्रम ब्यूरो को श्रमिकों और रोजगार से संबंधित पांच सर्वेक्षण करने का भी काम सौंपा गया है। डेटा की सावधानी, समयबद्धता और उपयोगकर्ता-अनुकूलता सुनिश्चित करना और इसे डेटाबेस प्रारूपों में उपलब्ध कराना विश्लेषण और नीति बनाने में सहायता करेगा।[40]

साक्ष्य को महत्त्व देने से यह भी आवश्यक हो जाता है कि केंद्र और राज्य सरकारों और विश्वविद्यालों में प्रक्रिया और प्रभाव मूल्यांकन क्षमताओं का पोषण किया जाए और समयबद्ध तरीके से परिपक्वता की ओर ले जाया जाए।

समावेशी विकास

कल्याण के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव

1.47 भारत के सामाजिक कल्याण दृष्टिकोण का इनपुट-आधारित दृष्टिकोण से परिणाम-आधारित सशक्तिकरण की ओर बदलाव हो गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति को अनिवार्य माना गया है, जिससे कई प्रमुख पहलों को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाना, जन धन योजना के तहत बैंक खाते खोलना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर बनाना जैसी सरकारी पहलों ने वंचित वर्गों की क्षमताओं में सुधार किया है और उनके अवसरों को बढ़ाया है।

1.48 इस दृष्टिकोण में अंतिम छोर तक सेवा प्रदान करने के लिए सुधारों का लक्षित कार्यान्वयन भी शामिल है, ताकि "कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे" के सिद्धांत को सही मायने में साकार किया जा सके। इनमें 2018 में शुरू किया गया आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी शामिल है, जिसका उद्देश्य सबसे पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसकी सफलता ने 2023 में शुरू किए जाने वाले आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को प्रेरित किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए जीवंत गांव कार्यक्रम; और हाल ही में, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें 15 नवंबर 2023[41] से शुरू होने वाले दो महीनों में 15 करोड़ लोगों की भागीदारी देखी गई। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शासन के डिजिटलीकरण से खर्च किए गए प्रत्येक रुपये के लाभ को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना और जन धन योजना-आधार-मोबाइल (जेएएम) त्रिक राजकोषीय दक्षता को बढ़ावा देने और लीकेज को कम करने में सहायक रही है, 2013 में इसकी शुरूआत के बाद से डीबीटी के माध्यम से 36.9 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं (डीबीटी पोर्टल[42])।

40 https://tinyurl.com/5xrrja3c

41 दो महीनों में 15 करोड़ प्रतिभागी, विकसित भारत संकल्प यात्रा ने कई राज्यों में भारी भीड़ जुटाई, 17 जनवरी 2024 (https://tinyurl.com/55xae4b3)

42 https://dbtbharat.gov.in/

चार्ट 1.59: विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत उनकी शुरुआत से लाभार्थियों की संख्या

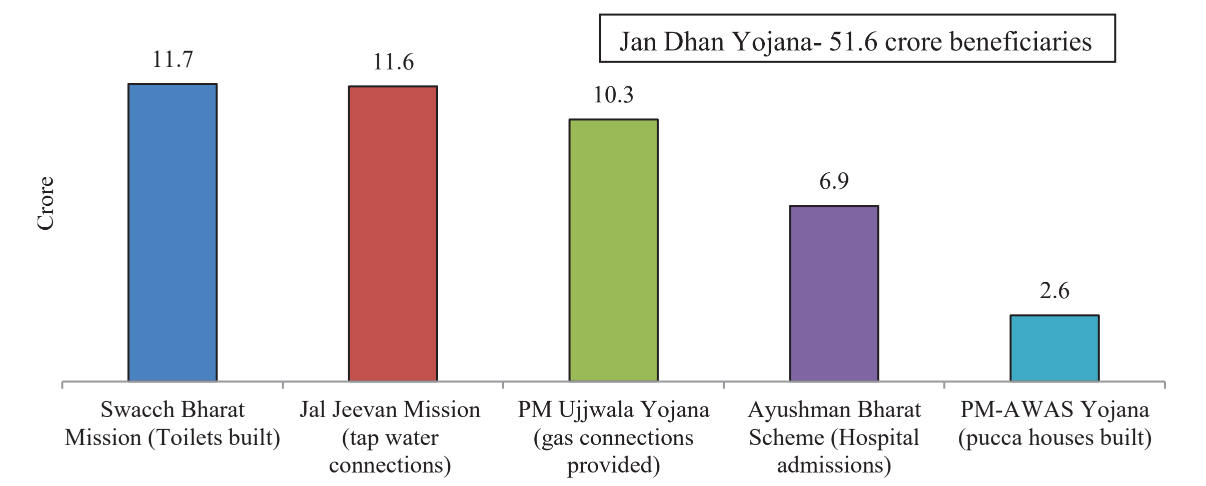

स्रोतः विभिन्न प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस विज्ञप्तियाँ

1.49 रोजगार के मोर्चे पर, वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर (यूआर) (सामान्य स्थिति के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति) महामारी के बाद से घट रही है। इसके साथ ही श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक-जनसंख्या अनुपात में भी वृद्धि हुई है। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के अपेक्षाकृत कड़े मानकों के अनुसार भी, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी की अवधि से रोजगार में सुधार हुआ है। पुरुष-महिला अनुपात के नजरिए से, महिला श्रम बल भागीदारी दर छह वर्षों से बढ़ रही है, अर्थात वित्त वर्ष 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2022-23 में 37 प्रतिशत तक, जो मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से प्रेरित है।

चार्ट 1.60: बेरोजगारी दर में गिरावट और श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में सुधार

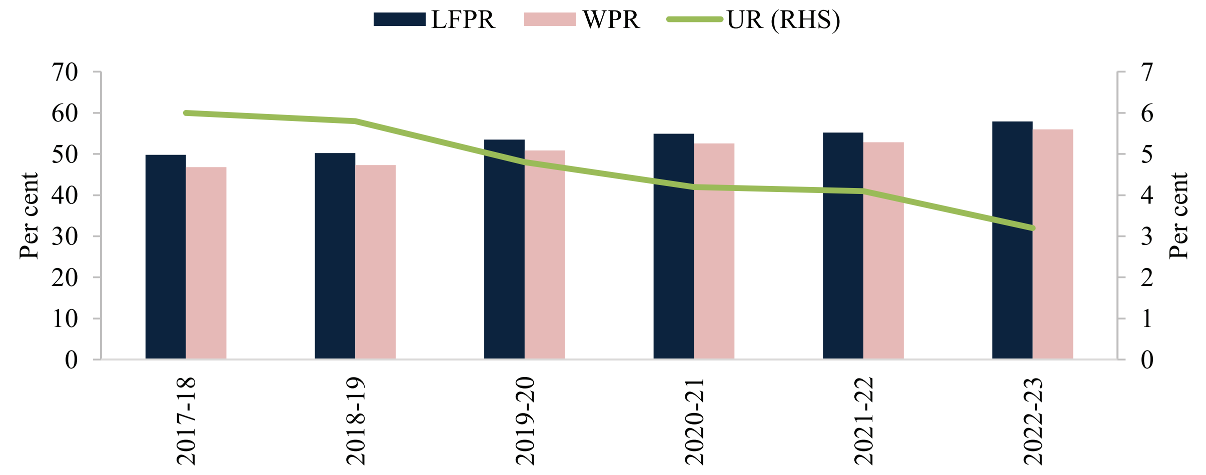

स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, जुलाई 2022 - जून 2023, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

1.50 व्यक्तिगत अभावों को दूर करने पर व्यवस्थित रूप से ध्यान देने के परिणामस्वरूप, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों में उल्लेखनीय कमी आई है। नीति आयोग की भारत में बहुआयामी गरीबी पर रिपोर्ट के अनुसार, यह वित्त वर्ष 2015-16 और वित्त वर्ष 2022-23 के बीच बहुआयामी गरीबों की संख्या अनुपात में भारी गिरावट में परिलक्षित होता है।[43]

43 नीति आयोग का चर्चा दस्तावेज 'वर्ष 2005-06 से भारत में बहुआयमी गरीबी', 2023 (https://tinyurl.com/4yvmrcax)

1.51 सामाजिक क्षेत्र में की गई पहलों ने उपभोग व्यय में भी वृद्धि की है, जैसा कि वित्तीय वर्ष 23 के नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के परिणामों से स्पष्ट है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण ने पिछले दशक में समावेशी विकास पर कई आश्वस्त करने वाले निष्कर्ष निकाले हैं। 2022-23 में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय 2011-12 की तुलना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वास्तविक रूप से बढ़ा है। प्रतिशत के लिहाज से ग्रामीण और शहरी मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के बीच का अंतर भी कम हुआ है।

चार्ट 1.61: ग्रामीण-शहरी असमानता में कमी

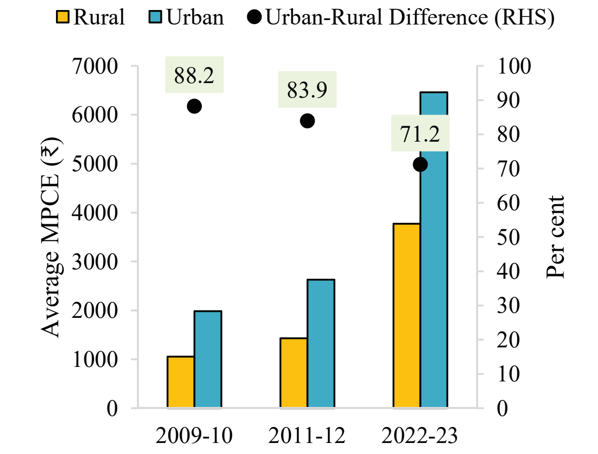

स्रोत: घरेलू उपभोग व्यय पर सर्वेक्षण: 2022-23, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; नोट[44]

चार्ट 1.62: बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा दर्शाई गई जनसंख्या का प्रतिशत घट गया है

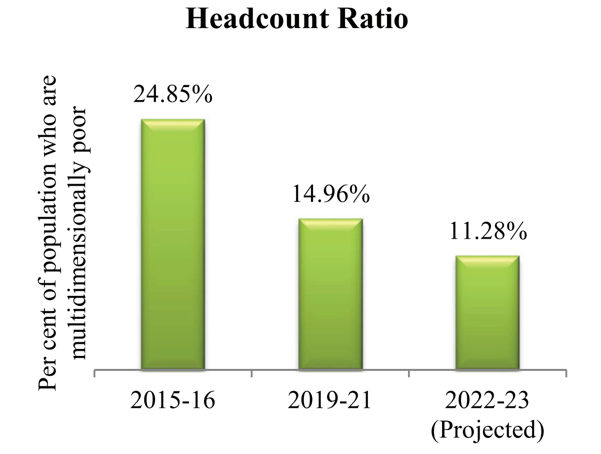

स्रोत: 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी - एक चर्चा पत्र, नीति आयोग

परिप्रेक्ष्य

1.52 भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी से तेजी से उबर रही है , वित्त वर्ष 24 में इसका वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कोविड-पूर्व वित्त वर्ष 20 के स्तर से 20 प्रतिशत अधिक रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि महामारी के कारण वित्त वर्ष 21 में 5.8 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद वित्त वर्ष 20 से 4.6 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हुई है। इस अध्याय में विश्लेषण से पता चलता है कि वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद स्तर वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में महामारी-पूर्व प्रक्षेपवक्र के निकट रहा है। वित्त वर्ष 2020 में समाप्त होने वाले दशक के दौरान, भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रही, जो कमोबेश अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को दर्शाती है। यह वह पृष्ठभूमि है जिसके आधार पर हम वित्त वर्ष 25 की संभावनाओं को देख सकते हैं।

1.53 आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.2 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, जिसमें जोखिम मोटे तौर पर संतुलित होंगे। वित्त वर्ष 2020 को समाप्त होने वाले दशक के दौरान औसत वार्षिक वैश्विक वृद्धि 3.7 प्रतिशत थी। वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट और आपूर्ति श्रृंखला दबावों में कमी के साथ अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति का दबाव कम हो गया है। हालांकि, मुख्य मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और उच्च सेवा मुद्रास्फीति द्वारा संचालित है। कई केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दर वृद्धि चक्र के चरम पर पहुंचने का संकेत दिया है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने पहले ही नीति दर में कटौती कर दी है, जबकि फेड ने 2024 में दर कम करने का संकेत दिया है। यदि अर्थव्यवस्थाओं में सेवाओं की मुद्रास्फीति तेजी से कम होती है, तो इससे केंद्रीय बैंकों को वर्तमान में अनुमानित समय से पहले मौद्रिक नीति सहजता चक्र को आगे लाने की अनुमति मिल सकती है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों, विशेष रूप से फेड द्वारा नीतिगत दरों में संभावित कटौती से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों के लिए रास्ता खुलेगा, जिससे पूंजी की लागत में कमी आएगी।

44 शहरी - ग्रामीण अतंर की गणना एम.पी.सी.ई की प्रतिशतता के अंतर के अनुसार की जाती है।

1.54 नकारात्मक पक्ष यह है कि 2024 में भू-राजनीतिक संघर्षों में किसी भी तरह की वृद्धि से आपूर्ति में अव्यवस्था, पण्य-वस्तु की कीमतों में वृद्धि, मुद्रास्फीति के दबाव में वृद्धि और पूंजी प्रवाह के लिए संभावित नतीजों के साथ मौद्रिक नीति में ढील की स्थिति पैदा हो सकती है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के रुख को भी प्रभावित कर सकता है। 2024 के लिए वैश्विक व्यापार का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, 2023 में मात्रा में संकुचन दर्ज करने के बाद माल व्यापार में तेजी आने की उम्मीद है। इसके विपरीत, भू-राजनीतिक सीमाओं के साथ बढ़ता विखंडन और संरक्षणवाद पर नए सिरे से जोर माल व्यापार की वृद्धि को विकृत कर सकता है, जिसका भारत के वैदेशिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ सकता है। वैश्विक वित्तीय बाजारों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, जिसमें निवेशक वैश्विक आर्थिक विस्तार पर दांव लगा रहे हैं। हालांकि, वित्तीय बाजार के ऊंचे मूल्यांकन में किसी भी सुधार का घरेलू वित्त और कॉर्पोरेट मूल्यांकन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे विकास की संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वित्त वर्ष 24 में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भर्ती में काफी कमी आई है और अगर भर्ती में और गिरावट नहीं भी आती है, तो भी इसमें उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना नहीं है। हालांकि, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का लाभ उठाते हुए और उभरते बाजारों में अप्रयुक्त क्षमता को लक्षित करते हुए, व्यापार, परामर्श और सूचना प्रौद्योगिकी-क्षम सेवाओं के निर्यात का विस्तार किया जा सकता है। मुख्य मुद्रास्फीति दर 3 प्रतिशत के आसपास होने के बावजूद, भारतीय रिजर्व बैंक ने, एक नजर समायोजन वापस लेने पर तथा दूसरी नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर रखते हुए, काफी समय से ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है, तथा अपेक्षित ढील में देरी की गई है।

1.55 अनिश्चित वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद घरेलू विकास प्रेरकों ने वित्त वर्ष 24 में आर्थिक विकास को समर्थन दिया है। बेहतर बैलेंस शीट से निजी क्षेत्र को मजबूत निवेश मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। यहाँ सावधानी बरतने की जरूरत है। पिछले तीन वर्षों में अच्छी वृद्धि के बाद अतिरिक्त क्षमता वाले देशों से सस्ते आयात की आशंका के कारण निजी पूंजी निर्माण थोड़ा अधिक सतर्क हो सकता है। जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में विकास की संभावनाओं में सुधार के साथ व्यापारिक निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है, वहीं सेवाओं के निर्यात में भी आगे वृद्धि होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सामान्य वर्षा का पूर्वानुमान और अब तक दक्षिण-पश्चिम मानसून का संतोषजनक प्रसार कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार और ग्रामीण मांग के पुनरुद्धार का समर्थन करने की संभावना है। हालांकि, मानसून को अभी भी कुछ समय तय करना है। माल और सेवा कर और आईबीसी जैसे संरचनात्मक सुधार भी परिपक्व हो चुके हैं और अपेक्षित परिणाम दे रहे हैं। इन कारकों पर विचार करते हुए, सर्वेक्षण में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.5-7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें जोखिम को संतुलित रखा गया है, तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखा गया है कि बाजार की अपेक्षाएं उच्च स्तर पर हैं।

****

02

अध्याय

मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता: स्थिरता ही मूलमंत्र

भारत के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों ने वित्त वर्ष 24 में शानदार प्रदर्शन किया है। बैंक ऋण में दोहरे अंकों और व्यापक आधार वाली वृद्धि, सकल और निवल गैर-निष्पादित आस्तियां कई वर्षों के निचले स्तर पर हैं, और बैंक आस्ति गुणवत्ता में सुधार एक स्वस्थ और स्थिर बैंकिंग क्षेत्र के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। पूंजीगत बाजार भारत की विकास कहानी में प्रमुख बन रहे हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी, नवाचार और डिजिटलीकरण के बल पर पूंजी निर्माण और निवेश परिदृश्य में हिस्सेदारी बढ़ रही है। भारतीय शेयर बाजार सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक रहा है, जिसमें वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत का निफ्टी 50 इंडेक्स 26.8 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि यह वित्त वर्ष 23 के दौरान (-)8. 2 प्रतिशत बढ़ा था। भारतीय शेयर बाजार के बाजार पूंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है,जिसमें बाजार पूंजीकरण जीडीपी अनुपात दुनिया में पांचवां सबसे बड़ा है। विनियामक उपायों और 'वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा' हासिल करने के दृष्टिकोण से समर्थित, भारत अगले पांच वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक के रूप में उभरने के लिए तैयार है। पेंशन क्षेत्र में ग्राहकों और प्रबंधनाधीन आस्तियों में मजबूत वृद्धि देखी गई है।

भारत के वित्तीय क्षेत्र के लिए संभावनाएं उज्ज्वल दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर आगे ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की उल्लेखनीय वृद्धि पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अति आत्मविश्वास के कारण सट्टेबाजी और अधिक रिटर्न की उम्मीद की संभावना है, जो वास्तविक बाजार स्थितियों के अनुरूप नहीं हो सकती है, यह एक गंभीर चिंता का विषय है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए, वित्तीय क्षेत्र को बैंकिंग क्षेत्र का समर्थन करने और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक पूंजी की कमी को पूरा करने की आवश्यकता है। इसलिए, वित्तीय क्षेत्र को ऐसी गति से विस्तार करना चाहिए जो आर्थिक विकास के साथ तालमेल बिठाए। विशेष रूप से, भारत अपने वर्तमान विकास चरण में अर्थव्यवस्था पर वित्तीयकरण का जोखिम नहीं उठा सकता है।

वित्तीय बाजारों में खुदरा बिक्री में वृद्धि की भागीदारी और वित्तीय उत्पादों से परिचितता भारत के विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के साथ ही बढ़ने लगी है। इसलिए, बैंकिंग, बीमा और पूंजीगत बाजारों में काम करने वाली फर्मों को उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखना चाहिए और निष्पक्ष बिक्री, प्रकटीकरण, पारदर्शिता, विश्वसनीयता और जवाबदेही के माध्यम से अपनी सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। उनकी आंतरिक मूल्यांकन और प्रोत्साहन प्रणाली इन विचारों के अनुरूप होनी चाहिए। यह उनके और राष्ट्र के हित में है कि वे दीर्घावधि में अपने वाणिज्यिक लक्ष्यों के अनुकूल हैं।

परिचय

2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्रों ने निरंतर भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद मजबूत प्रदर्शन किया है। केंद्रीय बैंक ने पूरे वर्ष एक स्थिर नीति दर बनाए रखी, जिसमें समग्र मुद्रास्फीति दर नियंत्रण में रही। रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद मौद्रिक सख्ती के प्रभाव बैंकों के बीच ऋण और जमा ब्याज दरों में वृद्धि में स्पष्ट हैं। बैंक ऋणों में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और व्यापक वृद्धि देखी गई, जिसमें व्यक्तिगत ऋण और सेवाएं सबसे आगे रहीं।

2.2 पूंजी बाजारों ने भी प्रभावशाली परिणाम दिखाए हैं, जिसमें भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण जीडीपी अनुपात में वैश्विक स्तर पर पांचवें स्थान पर रहा है।[1] एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) की विद्यमानता और

1 वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज (डब्ल्यूएफई) के अनुसार

बैंकों और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) की अधिक भागीदारी से वित्तीय समावेशन में सुधार करने में योगदान मिला है। बीमा और पेंशन क्षेत्र भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा कि उनके व्यय कवरेज से प्रदर्शित होता है।

2.3 इस पृष्ठभूमि में, अध्याय को दो भागों में विभाजित किया गया है- मौद्रिक विकास और वित्तीय मध्यस्थता। मौद्रिक विकास भाग अर्थव्यवस्था की मौद्रिक और तरलता स्थितियों को प्रस्तुत करता है।

2.4 वित्तीय मध्यस्थता भाग विभिन्न वित्तीय संस्थानों और वित्तीय बाजार लिखतों की स्थिति पर चर्चा करता है जो भारत में वित्तीय बाजार परिवेश का हिस्सा हैं। इस भाग का खंड I देश के बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन को प्रस्तुत करता है, जो वित्तीय मध्यस्थता परिदृश्य का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। खंड II संकटग्रस्त आस्तियों का निपटान करने के लिए सरकार के तंत्र और इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी/कोड) दिवालिएपन का समाधान करने में एक गेम-चेंजर के रूप में उभरी है। खंड III में डिजिटल वित्तीय समावेशन और डेटा सुरक्षा पर अधिक जोर देने के साथ वित्तीय समावेशन के प्रति सरकार के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई है। खंड IV में वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में एमएफआई की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। खंड V में प्रतिभूति बाजारों पर चर्चा की गई है, जो कॉर्पोरेट क्षेत्र और सरकार के लिए संसाधन जुटाने का एक वैकल्पिक और कुशल साधन बनने के लिए एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। प्रौद्योगिकी और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करने में भारत के प्रतिभूति बाजारों का वैश्विक कद गर्व की बात है। खंड VI में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी (आईएफएससी जीआईएफटी सिटी) और यह कैसे एक वैश्विक वित्तीय और आईटी सेवा हब के रूप में उभर रहा है, के बारे में बताया गया है। खंड VII और VIII में बीमा और पेंशन क्षेत्रों में विकास प्रस्तुत किया गया है। खंड IX में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, नियामक समन्वय और समग्र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के तंत्र पर चर्चा की गई है। खंड X में आगे बढ़ने के लिए प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख करते हुए, वित्तीय क्षेत्र के लिए एक समग्र निष्कर्ष और दृष्टिकोण प्रदान किया गया है।

मौद्रिक विकास

2.5 मौद्रिक नीति आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति और निवेश जैसे व्यापक आर्थिक संकेतकों पर अपने प्रभाव के माध्यम से किसी देश की आर्थिक स्थितियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। मौद्रिक नीति की विभिन्न लिखतें, जैसे बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर), केंद्रीय बैंक के खुले बाजार संचालन और ऋण की सीमा निर्धारित करना आदि, केंद्रीय बैंक द्वारा इस समग्र उद्देश्य की दिशा में उपयोग किए जाते हैं। अध्याय का यह खंड अर्थव्यवस्था में हाल के मौद्रिक विकास को प्रस्तुत करता है, जो उभरती हुई तरलता स्थितियों और बैंकों की उधार और जमा दरों के संदर्भ में मौद्रिक नीति संचरण पर ध्यान केंद्रित करता है।

मौद्रिक और ऋण शर्तें

2.6 वर्ष के दौरान मौद्रिक और ऋण की स्थिति मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप विकसित हुई, जिससे घरेलू आर्थिक गतिविधि को सहायता मिली है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने वित्त वर्ष 24 में नीतिगत रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर यथास्थिति बनाए रखा। इसने यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजन वापस लेने पर ध्यान केंद्रित किया है कि मुद्रास्फीति धीरे-धीरे लक्ष्य के अनुरूप हो और विकास को समर्थन मिले। मई 2022 और फरवरी 2023 के बीच किए गए 250 आधार अंकों (बीपीएस) की संचयी नीति रेपो दर वृद्धि के साथ, अर्थव्यवस्था में अपना काम करते हुए, एमपीसी ने फरवरी 2023 से नीति रेपो दर को स्थिति की मांग होने पर उचित और समय पर नीतिगत कार्रवाई करने के लिए तत्परता के साथ बिना परिवर्तन के 6.5 प्रतिशत पर रखा गया है।

2.7 वित्त वर्ष 24 के दौरान मौद्रिक और ऋण स्थितियों के विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक, ₹2,000

बैंक नोटों की वापसी (मई 2023)[2] एचडीएफसी बैंक के साथ एक गैर-बैंक एचडीएफसी का विलय (जुलाई 2023), और वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) का अस्थायी अधिरोपण (अगस्त 2023) थे। बैंकिंग प्रणाली में जमा के रूप में ₹2,000 बैंक नोटों के एक बड़े हिस्से की वापसी के कारण आरक्षित धन और प्रचलन में मुद्रा (सीआईसी) में विस्तार धीमा हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, प्रचलन में ₹2,000 के बैंक नोटों का कुल मूल्य 19 मई 2023 (जब ₹2,000 के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा की गई थी) तक ₹3.56 लाख करोड़ से घटकर 28 जून 2024 तक ₹7,581 करोड़ रह गया है, जो दर्शाता है कि ₹2,000 मूल्यवर्ग के 97.87 प्रतिशत बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में[3] वापस आ गए हैं। इसने और सावधि जमा दरों में वृद्धि ने कुल जमा और व्यापक धन (एम3) में तेजी लाने में योगदान दिया। प्रचलन में मुद्रा (सीआईसी) में वृद्धि पिछले वर्ष के 7.8 प्रतिशत से घटकर 4.1 प्रतिशत हो गई, जो ₹2,000 के बैंक नोटों को वापस लेने के प्रभाव को दर्शाती है।

2.8 रिजर्व मनी (एमओ) ने 29 मार्च 2024 तक 6.7 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष (वाईओवाई) वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष यह 9.7 प्रतिशत थी। सीआरआर में बदलावों के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजित एमओ ने एक साल पहले 7.4 प्रतिशत की तुलना में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। एमओ में वृद्धि मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2024 के दौरान शुद्ध विदेशी परिसंपत्तियों (एनएफए) द्वारा संचालित थी।

चार्ट II.1: आरक्षित मुद्रा (एम0) में वृद्धि में नरमी

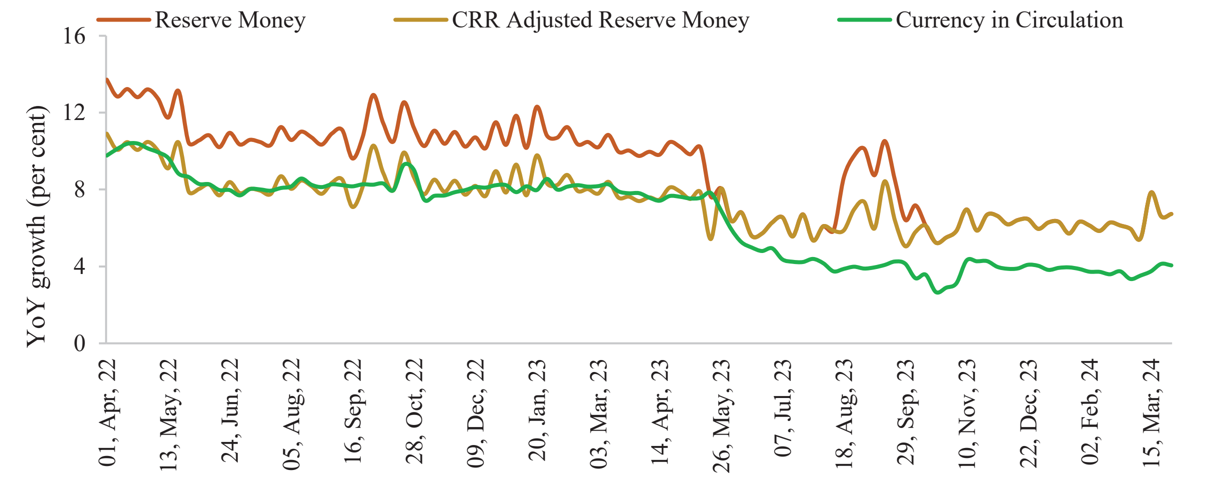

स्रोत: रिजर्व मनी: घटक और स्रोत, प्रकाशन, साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक, आरबीआई

2.9 एचडीएफसी बैंक के साथ एचडीएफसी के विलय (1 जुलाई 2023 से प्रभावी) के प्रभाव को छोड़कर ब्रॉड मनी (एम3) में वृद्धि 22 मार्च 2024 तक 11.2 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) थी, जबकि एक साल पहले यह 9 प्रतिशत थी। घटकों के मामले में[4] सबसे महत्वपूर्ण घटक, कुल जमा (एडी) ने एम3 के विस्तार में सबसे अधिक योगदान दिया। स्रोतों में, वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण ने एम3 में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसकी हिस्सेदारी 22 मार्च 2024 तक

2 19 मई 2023 के परिपत्र https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=55707 के तहत, आरबीआई ने ₹2000 के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की है क्योंकि (i) ₹2000 मूल्यवर्ग के लगभग 89% बैंक नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और अब उनका अनुमानित जीवन काल 4-5 वर्ष पूरा होने वाला है; (ii) प्रचलन में इन बैंक नोटों का कुल मूल्य 31 मार्च 2018 तक अपने चरम पर ₹6.73 लाख करोड़ (प्रचलन में नोटों का 37.3%) से घटकर ₹3.62 लाख करोड़ हो गया है, जो 31 मार्च 2023 तक प्रचलन में नोटों का केवल 10.8% है; (iii) इस मूल्यवर्ग का लेन-देन के लिए सामान्यत: उपयोग नहीं किया जाता है, और (iv) अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक जनता की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त बना हुआ है।

3 आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 1 जुलाई, 2024, '2000 रुपये के मूल्यवर्ग के नोटों के निकासी-स्थिति', https://www.rbi.org.in/scripts/BS,pressReleaseDisplay.aspx?prid=58199

4 व्यापक मुद्रा के घटक = जनता के पास मुद्रा+ कुल जमा (बैंको के पास मांग जमा + बैंकों के पास समय सीमा के लिए जमा +रिजर्व बैंक के अन्य डिपॉजिट)

67.1 प्रतिशत थी, जिसे सरकार को दिए गए निवल बैंक ऋण (29.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी[5]) द्वारा पूरक बनाया गया।

चार्ट II.2: ब्रॉड मनी (एम3) में वृद्धि

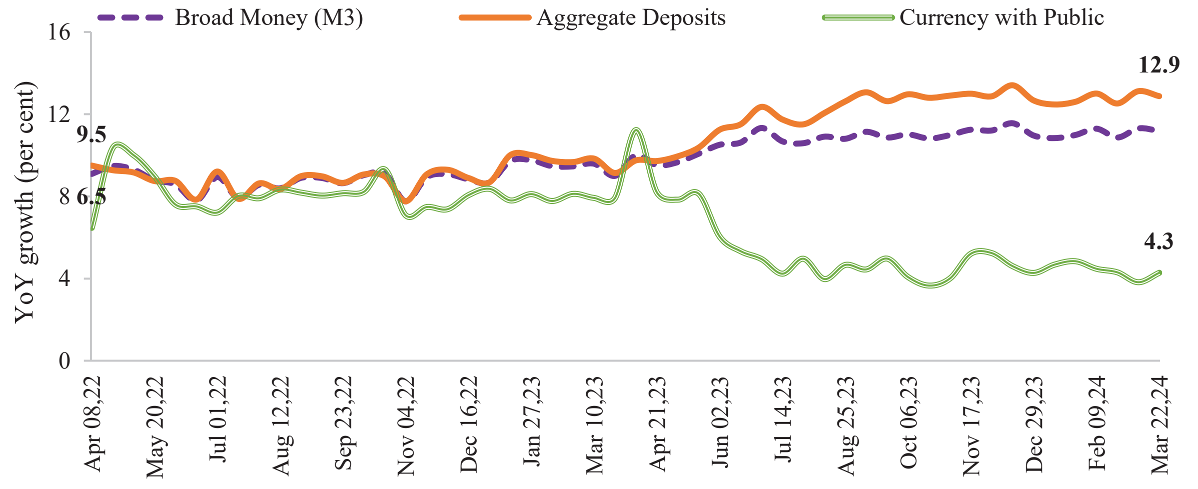

स्रोत: मनी स्टॉक: घटक और स्रोत, प्रकाशन, साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक, आरबीआई

चार्ट II.3: वित्त वर्ष 24 में उच्च मनी मल्टीप्लायर, जो बाजार में अधिक तरलता का संकेत देता है

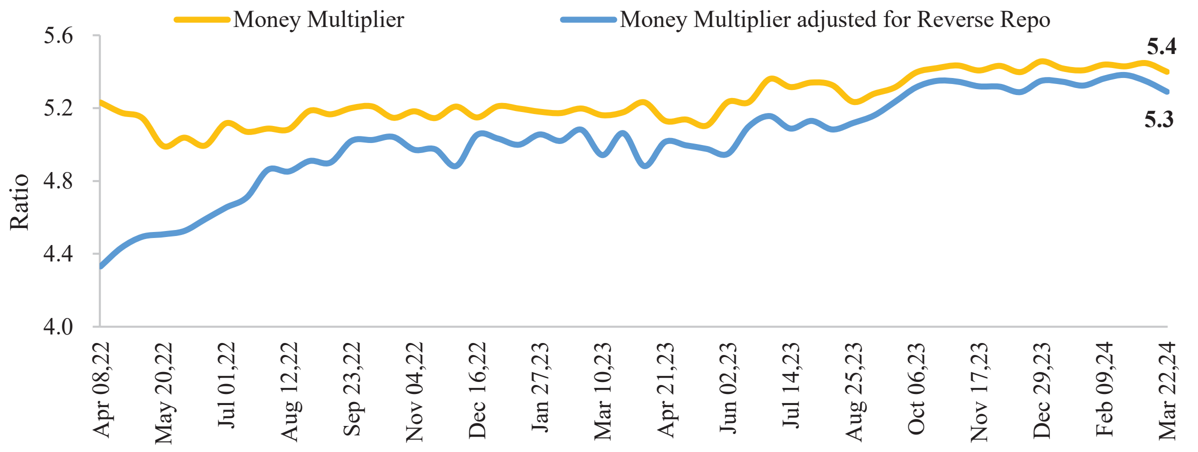

स्रोत: मनी स्टॉक: घटक और स्रोत, प्रकाशन, साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक, आरबीआई
आरक्षित धन: घटक और स्रोत, प्रकाशन, साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक, आरबीआई

2.10 22 मार्च 2024 तक, मुद्रा गुणक (एमएम) एक साल पहले 5.2 के मुकाबले 5.4 था। केंद्रीय बैंक के पास बैंकों की जमाराशियों के विश्लेषणात्मक रूप से समान रिवर्स रेपो राशियों के लिए समायोजित, मार्च 2024[6] तक समायोजित एमएम मामूली रूप से कम होकर 5.3 पर था।

नीति दरों में तरलता की स्थिति और रुझान

2.11 आरबीआई के तरलता प्रबंधन में तरलता की स्थिति में बदलाव के जवाब में दो-तरफा संचालन शामिल थे। वित्त वर्ष 2024 के दौरान, 17 पाक्षिक परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामी और सात परिवर्तनीय दर रेपो

5 व्यापक मुद्रा के स्रोत = सरकार को निवल बैंक ऋण + वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण + बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां + जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएँ - बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध गैर-मौद्रिक देयताएँ)

6 मनी मल्टीप्लायर (एमएम) एम 3 की उस राशि को संदर्भित करता है जो बैंक अपने पास उपलब्ध एमओ के प्रत्येक रुपये से उत्पन्न करता है। यह मौद्रिक आधार और अर्थव्यवस्था की मुद्रा आपूर्ति के बीच के संबंध को दर्शाता है, जो यह दर्शाता है कि बैंक की उधार गतिविधि से मुद्रा आपूर्ति कितनी तेजी से बढ़ेगी। एमएम का मूल्य जितना अधिक होगा और इसके विपरीत बाजार में तरलता उतनी ही अधिक होगी।

(वीआरआर) नीलामी प्राथमिक संचालन के रूप में की गई। इसके अलावा, मौद्रिक नीति रुख के साथ संरेखण में तरलता की स्थिति को संशोधित करते हुए, 49 फाइन-ट्यूनिंग ऑपरेशन (25 वीआरआरआर और 24 वीआरआर) कुछ अंतराल पर किए गए। सख्त तरलता स्थितियों के बीच, बैंकों ने सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) का भी सहारा लिया। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत अधिशेष निधियों के व्यापक उपयोग और एमएसएफ के एक साथ उपयोग को देखते हुए, एसडीएफ और एमएसएफ दोनों के तहत चलनिधि सुविधाओं को 30 दिसंबर 2023[7] से सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान भी वापस लेने की अनुमति दी गई।

2.12 अतिरिक्त तरलता से मूल्य और वित्तीय स्थिरता को होने वाले जोखिम और अन्य बातों के साथ-साथ बैंकिंग प्रणाली में 2,000 रुपये के नोट वापस आने के कारण अधिशेष तरलता में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने 10 अगस्त 2023 को 10 प्रतिशत का अस्थायी आई-सीआरआर घोषित किया। आई-सीआरआर, जिसने बैंकिंग प्रणाली से लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपये जब्त किए, की 8 सितंबर 2023 को समीक्षा की गई और 7 अक्टूबर 2023 को समाप्त होने वाले चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया। इस प्रकार जब्त की गई राशि 10 अगस्त 2023[8] को विकासात्मक और नियामक नीतियों की घोषणा के अनुरूप त्यौहारी सीजन से पहले बैंकिंग प्रणाली को जारी कर दी गई। इन कार्रवाईयों के परिणामस्वरूप बैंकिग प्रणाली की तरलता धीमी हो गई, जिससे सितम्बर के मध्य में घाटा हो गया, जो वित्त वर्ष 2024 के दौरान जारी रहा।

तरलता की स्थिति में नरमी

चार्ट II.4(क): तरलता की स्थिति

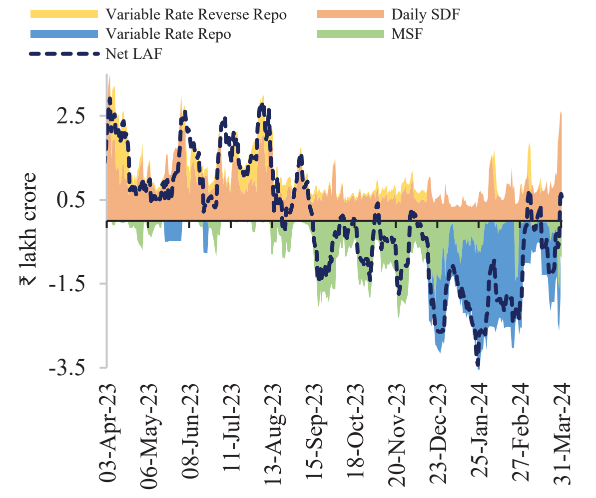

स्रोत: आरबीआई द्वारा तरलता संचालन, प्रकाशन, साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक

चार्ट II.4(ख): पॉलिसी कॉरिडोर और ओवरनाइट कॉल मनी दर

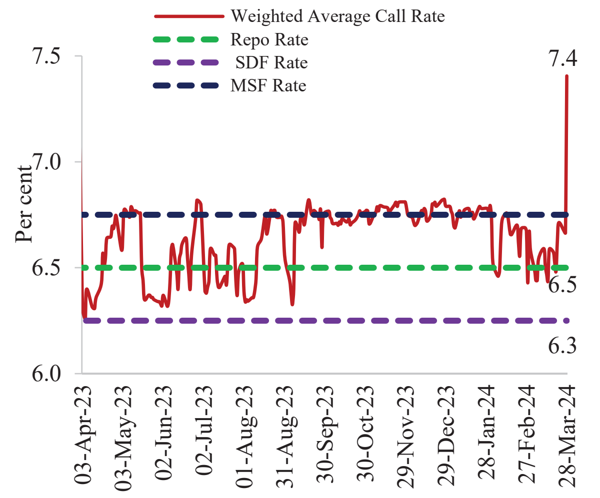

स्रोत: मनी मार्केट, डेटा और सांख्यिकी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)

मौद्रिक नीति संचरण

2.13 वित्त वर्ष 2024 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की उधार और जमा दरों में अधिक वृद्धि हुई, जो मई 2022-फरवरी 2023 के दौरान नीतिगत दरों में वृद्धि, ऋण मूल्य निर्धारण की बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दर प्रणाली और अधिशेष तरलता के संयम के विलंबित प्रभाव को दर्शाती है। मौजूदा सख्त चक्र के दौरान, अर्थात मई 2022 से मई 2024 तक, बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दर और एक वर्षीय औसत सीमांत-लागत-निधि-आधारित उधार दर में क्रमश: 250 बीपीएस और 175 बीपीएस की वृद्धि हुई। नीतिगत दरों में वृद्धि का उधार और जमा दरों पर संचरण तालिका II.1 में दिया गया है।

7 इस उपाय की समीक्षा छह महीने बाद या जरूरत पड़ने पर पहले भी की जाएगी।]

8 आरबीआई गवर्नर का बयान: 10 अगस्त 2023, पैरा 18, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay-aspx?prid=56175

तालिका II.1: घरेलू ऋण और जमा दरों में संचरण में तेजी

	मई-2022 से मई-2024	अप्रैल-2023 से मार्च-2024
डब्लूएएलआर- बकाया रुपया ऋण	1.14	0.11
डब्लूएएलआर - नया रुपया ऋण	1.88	0.05
डब्लूएडीटीडीआर- बकाया रुपया जमा	1.90	0.73
डब्लूएडीटीडीआर - नया रुपया जमा	2.44	0.14

स्रोत: एससीबी की उधार और जमा दरें, आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति (विभिन्न अंक)
नोट: डब्ल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर
डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर

वित्तीय मध्यस्थता

2.14 वित्तीय विकास और आर्थिक वृद्धि एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं, और वित्तीय मध्यस्थता वह मार्ग है जिसके माध्यम से पूर्व को उत्तरार्द्ध में परिवर्तित किया जाता है। वित्तीय मध्यस्थता सीमित संसाधनों के कुशल आवंटन में मदद करती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जोसेफ शम्पीटर का मानना था कि वित्तीय मध्यस्थों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जैसे बचत जुटाना, ऋण देना, आस्तियों का भंडारण करना, उन्हें बढ़ाना, जोखिम प्रबंधन करना और लेन-देन को सुविधाजनक बनाना, जो तकनीकी नवाचार और आर्थिक विकास[9] के लिए आवश्यक थीं। वित्तीय मध्यस्थता विदेशी पूंजी प्रवाह को भी सुविधाजनक बनाती है और प्रोत्साहित करती है। अनुभवजन्य अध्ययनों[10] से पता चलता है कि कुशल और विकसित वित्तीय बाजार बचत के आवंटन और उपयोग में सुधार करके और कमजोर समूहों और छोटे और मध्यम आकार की फर्मों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए वित्त तक पहुँच सुनिश्चित करके बढ़ी हुई और समावेशी आर्थिक वृद्धि हो सकती हैं।

2.15 वित्तीय विकास के मापदंड न केवल सुदृढ़ होने चाहिए, बल्कि वे समग्र रूप से प्रणाली की वित्तीय स्थिरता भी सुनिश्चित करते हैं। इसके लिए जोखिम के लिए पूंजी (भारित) आस्ति अनुपात (सीआरएआर), जमाराशियों के लिए तरल संपत्ति और अल्पकालिक ऋण जैसे संकेतकों को प्रबंधनीय सीमाओं के भीतर होना चाहिए। इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र के विकास का एक अनिवार्य हिस्सा सभी वित्तीय बाजार संस्थाओं, बाजार के किरदारों और वित्तीय लिखतों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए मजबूत नीतियों को लागू करना है। इस संबंध में नियामकों के बीच समन्वय सर्वोपरि है।

बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन और ऋण उपलब्धता

2.16 भारत के बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता और समुत्थानशील आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार, अशोध्य ऋणों के लिए बेहतर प्रावधान, निरंतर पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदता में वृद्धि द्वारा समर्थित है। ऋण वृद्धि मजबूत बनी हुई है, जो मुख्य रूप से सेवाओं और व्यक्तिगत ऋणों को उधार देने से है। जैसा कि पैरा 2.9-2.10 में उल्लेख किया गया है, पिछली दर वृद्धि के संचरण के कारण जमा वृद्धि ने भी गति पकड़ी है, जिसके परिणामस्वरूप जमाओं का पुनर्मूल्यन हुआ है और सावधि जमाओं में वृद्धि हुई है। व्यक्तिगत ऋण और उद्योग को ऋण के कारण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण देने में तेजी आई है और उनकी आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

9 शुम्पीटर, जोसेफ ए. आर्थिक विकास का सिद्धांत, (कैम्ब्रिज, एमए: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1911)।

10 एरेस्टिस, पी., और डेमेट्रिएड्स, पी. (1997)। वित्तीय विकास और आर्थिक वृद्धि: साक्ष्य का आकलन। द इकोनॉमिक जर्नल, 107(142), 783-799; अजियाकपोनो, एम. जे. (2011)। वित्तीय विकास और आर्थिक वृद्धि: सिद्धांत और साक्ष्य का सर्वेक्षण। अर्थशास्त्र और अर्थमिति में अध्ययन, 35(1), 15-43।; कैलडरॉन, सी., और लियू, एल. (2003)। वित्तीय विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच कार्य-कारण की दिशा। जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, 72(1), 321-334।

चार्ट II.5: एससीबी द्वारा ऋण वितरण में दोहरे अंकों की वृद्धि

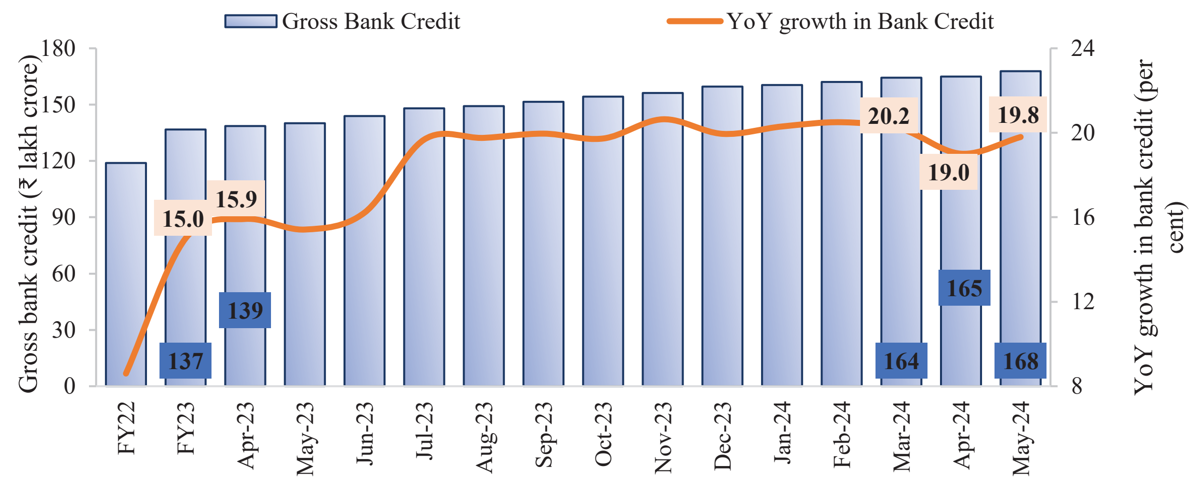

स्रोत: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा बैंक ऋण की नियुक्ति, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, तालिका संख्या 170, आरबीआई

टिप्पणी: इन आंकड़ों में बैंकों के साथ नॉन बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

2.17 वित्त वर्ष 2024 के दौरान बैंक ऋण वृद्धि ने गति बनाए रखी है, जिसमें सभी क्षेत्रों में व्यापक आधार पर वृद्धि हुई है। मार्च 2024 के अंत में एससीबी द्वारा ऋण वितरण 20.2 प्रतिशत से बढ़कर 164.3 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च 2023 के अंत में यह 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रहा। यह प्रवृत्ति वित्त वर्ष 2025 में भी जारी रहने की उम्मीद है, जैसा कि अप्रैल और मई 2024 में बैंक ऋण में 19 और 19.8 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि से पता चलता है।

क्षेत्रीय ऋण वृद्धि

2.18 कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण में वृद्धि दोहरे अंकों में रही। कृषि ऋण वित्त वर्ष 2021 में 13.3 लाख करोड़ से लगभग 1.5 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 20.7 लाख करोड़ हो गया। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना ने किसानों को समय पर और अवरोध मुक्त ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमं वर्ष 2023 के अंत तक[11] 7.4 करोड़ से अधिक सक्रिय केसीसी खाते हैं। कृषि क्षेत्र को ऋण वितरण में वृद्धि अप्रैल और मई 2024 में जारी रही, जिसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बैंक ऋण में 19.7 प्रतिशत और 21.6 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) क्रमश: की वृद्धि हुई।

2.19 वित्त वर्ष 2024 की दूसरी छमाही में औद्योगिक ऋण वृद्धि में तेजी आई, जो एक साल पहले 5.2 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2024 में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो छोटे और बड़े उद्योगों को बैंक ऋण में वृद्धि के कारण थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण वितरण में वृद्धि को आपातकालीन ऋण संबद्ध गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 100 प्रतिशत ऋण गारंटी के साथ संपार्श्विक-मुक्त ऋण की उपलब्धता द्वारा समर्थित किया गया है। इसके अलावा, समृद्ध और समय पर ऋण डेटा की उपलब्धता और डिजिटल ऋण अवसंरचना के तेजी से कार्यान्वयन से ऋणदाताओं के विश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। बॉक्स II.1 में एमएसएमई को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने और उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा की गई है। भविष्य में, ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (ओसीईएन)[12] जैसी नई तकनीकों के विकास से एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

11 वित्त मंत्रालय की पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27 दिसंबर 2023, https://shorturl.at/EqWwK

12 ओसीईएन एक विकेन्द्रीकृत खुला ऋण नेटवर्क है जो उधारकर्ताओं, उधारदाताओं और ऋण वितरकों के बीच ऋण के प्रवाह को मानकों के एक सामान्य सेट के तहत संहिताबद्ध करता है। इससे देश के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को और मजबूत करने की उम्मीद है

बॉक्स II.1: औपचारिकीकरण के माध्यम से एमएसएमई को बैंक ऋण का प्रवाह बढ़ाना

एमएसएमई क्षेत्र को कम लागत पर ऋण प्रवाह में सुधार करना सरकार और आरबीआई की नीतिगत प्राथमिकता रही है। इस संबंध में विभिन्न पहलें की गई हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है[13]

- **व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) की शुरूआत:** टीआरईडीएस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो तरलता और कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई वित्तपोषकों- बैंकों और एनबीएफसी- के माध्यम से एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों की छूट की सुविधा प्रदान करता है। कुल मिलाकर, टीआरईडीएस प्लेटफार्मों पर 2.9 लाख करोड़ की राशि के 98.9 लाख इनवॉइस पर 31 मार्च, 2024 तक छूट मिली हैं, जिससे एमएसएमई को बेहतर तरलता और कार्यशील पूंजीगत प्रबंधन के लिए सहायता मिली है।

- **एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव:** 1 जुलाई 2020 से, एमएसएमई को टर्नओवर और संयंत्र और मशीनरी/ उपकरण में निवेश के समग्र मानदंडों के अनुसार परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, इससे बड़ी संख्या में उद्यमियों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र के दायरे में लाने की परिकल्पना की गई है, जिससे उद्योग को रियायती दरों पर ऋण का प्रवाह सुगम होगा।

- **उद्यम पोर्टल पर एमएसएमई का पंजीकरण:** एमएसएमई मंत्रालय ने 1 जुलाई 2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) लॉन्च किया और तब से इसने खुद को व्यापार करने में आसानी के लिए एक आवश्यक प्रवर्तक के रूप में स्थापित किया है, क्योंकि यह नि:शुल्क, सरल और ऑनलाइन है। यह उद्यमियों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र के दायरे में लाने के लिए किया गया था, जिससे एमएसएमई को रियायती दरों पर ऋण का प्रवाह सुगम होगा। हालांकि, यूआरपी के साथ एक चुनौती अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) का पंजीकरण है। जो संख्या में काफी है। 73वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2016 में 6.3 करोड़ अनिगमित गैर-कृषि संस्थाएं मौजूद थीं, जो मुख्य रूप से सूक्ष्म उद्यम थे चूंकि आईएमई के पास पैन/जीएसटी नहीं है, इसलिए वें यू आर पी पर पंजीकरण नहीं करा सकते और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते। ऐसे उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने भारतीय लघु उद्योग और भारतीय विकास बैंक (सिडबी) के सहयोग से 11 जनवरी 2023 को उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म (यूएपी) लॉन्च किया। औपचारिकता के माध्यम से अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को विभिन्न सुविधाओं, जैसे; बाजारों और ऋण तक पहुंच आदि से जोड़ा जाएगा। जून 2024 तक, 1.86 करोड़ आईएमई यूएपी पर शामिल हो चुके हैं। 3 जून 2024 तक यूआरपी और यूएपी पर 4.5 करोड़ से अधिक उद्यम पंजीकृत हो चुके हैं।

- **एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) का पुनरुद्धार:** केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 23 में, एमएसई के लिए 2 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण की सुविधा के लिए आवश्यक धनराशि के साथ सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सीजीएस के पुनरुद्धार की घोषणा की गई थी। तदनुसार, एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कोष में 9,000/- करोड़ रुपये की समावेशन से सीजीएस का पुनरूद्धार किया गया था। इसके बाद, उक्त योजना के तहत ऋण सीमा को ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया, जिसमें न्यूनतम वार्षिक गारंटी शुल्क 0.37 प्रतिशत प्रति वर्ष था। परिणामस्वरूप, चार वर्षो में ₹2 लाख करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 के दौरान ₹3 लाख करोड़ की ऋण गारंटी स्वीकृत की गई। वित्त वर्ष 2023 के दौरान, ₹1.04 लाख करोड़ की गारंटी में से, ₹16,373 करोड़ और ₹2,750 करोड़ क्रमश: महिलाओं और एससी/एसटी के स्वामित्व वाले उद्यमों को दिए गए। वित्त वर्ष 2024 में ₹2.02 लाख करोड़ की गारंटी दी गई, जिसमें से क्रमश: ₹32,223 करोड़ और ₹5,393 करोड़ महिलाओं और एससी/एसटी के स्वामित्व वाले उद्यमों को दिए गए।

13 यह बॉक्स राइट अप एमएसएमई मंत्रालय और यूडीवाईएएम पोर्टल, https://www.msme.gov.in/, https://udyamregistration.gov.in/ से प्राप्त जानकारी/ डेटा पर आधारित है।

आईएमई को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, 14 फरवरी 2024 से एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसई के लिए मौजूदा सीजीएस के तहत एक विशेष प्रावधान किया है जिसके तहत यूएपी पर पंजीकृत आईएमई प्राथमिक सुरक्षा के बिना और 85 प्रतिशत गारंटी कवरेज और कम वार्षिक गारंटी शुल्क के साथ 20 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय संस्थानों को गारंटी लागू करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता नहीं है।

2.20 एनबीएफसी को ऋण वृद्धि में मंदी के बावजूद सेवा क्षेत्र को बैंक ऋण वितरण लचीला रहा। सेवा क्षेत्र के भीतर, वित्त वर्ष 24 की दूसरी छमाही में 'वाणिज्यिक अचल संपत्ति' और 'व्यापार' उप-क्षेत्रों को ऋण वितरण में सुधार हुआ है। बैंकों द्वारा वितरित ऋण में व्यक्तिगत ऋण और एनबीएफसी का सबसे बड़ा हिस्सा है। व्यक्तिगत ऋणों के भीतर, आवास ऋण में, अप्रैल और मई 2024 में वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2024 के दौरान सीमित रही।

चार्ट II.6: विभिन्न क्षेत्रों में बैंक ऋण में व्यापक वृद्धि

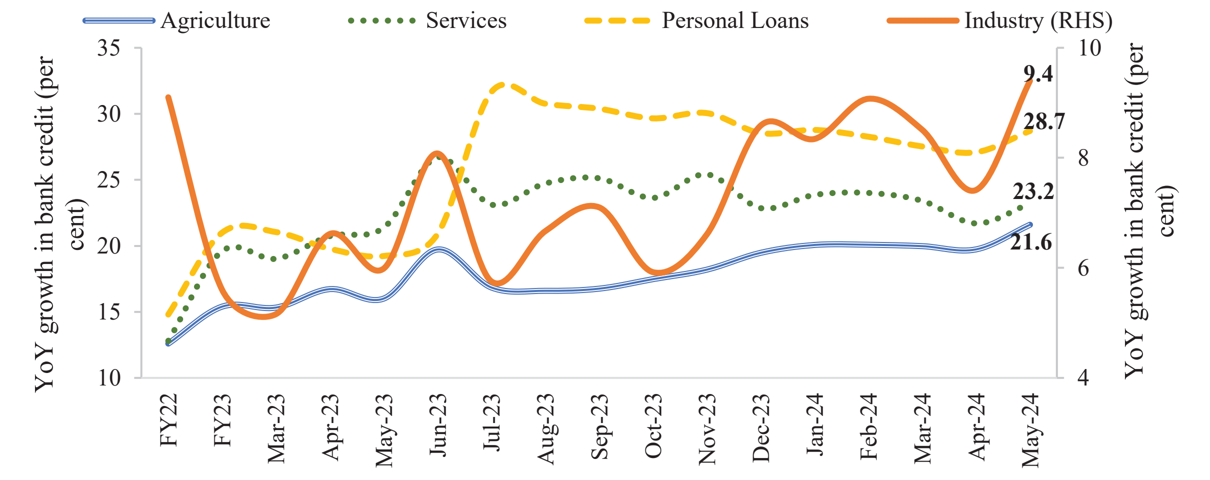

स्रोत: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा बैंक ऋण की नियुक्ति, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, तालिका संख्या 170, आरबीआई
टिप्पणी: इन आंकड़ों में बैंक के साथ नॉन बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

2.21 आवास ऋण के लिए ऋण वितरण मार्च 2023 में ₹19.9 लाख करोड़ से बढ़कर मार्च 2024 में ₹27.2 लाख करोड़ हो गया। व्यक्तिगत ऋणों में ऋण वृद्धि का श्रेय पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण डिजिटलीकरण को दिया जा सकता है, जिसमें तेजी से निर्णय लेने, डेटा संग्रह और सत्यापन और ई-कॉमर्स लेनदेन के लिए क्रेडिट ब्यूरो का उपयोग बढ़ गया है। हालांकि, दिसंबर 2023 के बाद व्यक्तिगत ऋण वृद्धि में कमी आई, क्योंकि आरबीआई ने अप्रत्याभूत व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड और एनबीएफसी को ऋण देने के लिए पूंजी आवश्यकताओं को 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत[14,15] कर दिया।

बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार

2.22 बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका कारण उधारकर्ताओं का बेहतर चयन, अधिक प्रभावी ऋण वसूली और बड़े उधारकर्ताओं[16] के बीच ऋण जागरूकता में वृद्धि है। विनियामक पूंजीगत और तरलता आवश्यकताओं के अलावा, गुणात्मक मैट्रिक्स जैसे कि बेहतर प्रकटीकरण, मजबूत आचार संहिता और पारदर्शी शासन संरचना ने भी बैंकिंग प्रदर्शन में सुधार किया है।

---

14 आरबीआई अधिसूचना, 'एनबीएफसी को उपभोक्ता ऋण और बैंक ऋण के लिए नियामक उपाय', दिनांक 16 नवंबर 2023, https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12567&Mode=0

15 आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार

16 वही 15

2.23 एससीबी के सकल गैर-निष्पादित आस्ति (जीएनपीए) अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही, जो वित्त वर्ष 2018 में 11.2 प्रतिशत के अपने शिखर से मार्च 2024 के अंत में 2.8 प्रतिशत के 12 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। कम स्लिपेज और वसूली, उन्नयन और राइट-ऑफ के माध्यम से बकाया जीएनपीए में कमी के कारण यह कमी आई। एससीबी की आस्ति गुणवत्ता में सुधार व्यापक आधार पर हुआ है। कृषि क्षेत्र का जीएनपीए अनुपात मार्च 2024 के अंत में 6.5 प्रतिशत के साथ उच्च स्तर पर बना हुआ है, लेकिन इसमें वित्त वर्ष 2024 की दूसरी छमाही के दौरान लगातार सुधार दर्ज किया गया है। व्यक्तिगत ऋण खंड में जीएनपीए अनुपात सभी श्रेणियों में सुधरा है। वाहनों और परिवहन उपकरणों को छोड़कर औद्योगिक क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण उप-क्षेत्रों में आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

चार्ट II.7(क): एससीबी के जीएनपीए में गिरावट

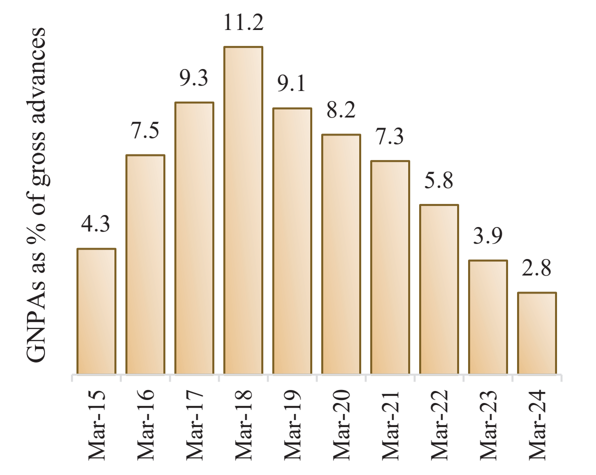

स्रोतः भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा और बैंकिंग पर सांख्यिकी पुस्तिका, एससीबी के सकल और शुद्ध एनपीए-समूहवार, आरबीआई

चार्ट II.7(ख): सीआरएआर आवश्यक मानदंडों से काफी ऊपर

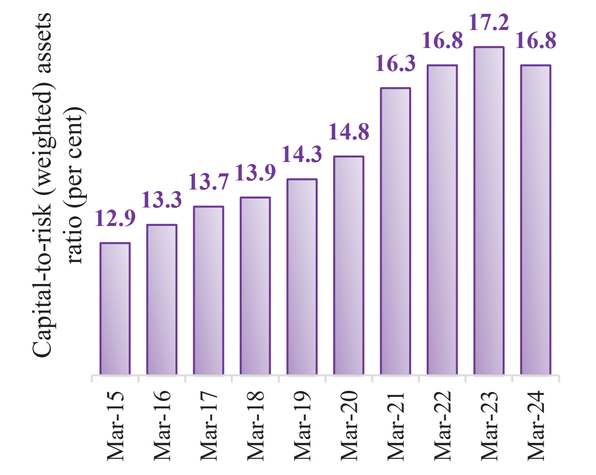

स्रोतः भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा और बैंकिंग पर सांख्यिकी पुस्तिका, सीआरएआर द्वारा एससीबी का वितरण, आरबीआई

2.24 चूंकि एससीबी ने उच्च लाभ से प्राप्त भंडार को पूंजीकृत करके और नई पूंजी जुटाकर अपने पूंजी आधार को मजबूत किया है, इसलिए मार्च 2024 के अंत तक, 16.8 प्रतिशत हो गया है। सभी बैंकों ने इसे पूरा कर लिया है और साथ ही 13.9 प्रतिशत की सीईटी-1 अनुपात[17] आवश्यकता को भी पूरा कर लिया है, जो नियामक न्यूनतम से काफी ऊपर है।

2.25 मार्च 2024 में एससीबी का शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 3.6 प्रतिशत पर मजबूत रहा। निवल ब्याज आय और अन्य परिचालन आय में वृद्धि के साथ और अतिरिक्त प्रावधानों की आवश्यकता कम होने के कारण, परिचालन व्यय में बड़ी वृद्धि के बावजूद, मार्च 2024 में उनके कर पश्चात लाभ (पीएटी) में 32.5 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई। लाभप्रदता संकेतक मजबूत रहे, इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) और आस्तियों पर रिटर्न (आरओए) अनुपात मार्च 2024 में दशक के उच्चतम स्तर को छू गए। मौद्रिक नीति दर वृद्धि के संचरण के विलंबित प्रभावों और तरलता स्थितियों में बदलाव के कारण वित्त वर्ष 2024 में आस्तियों पर प्रतिफल में 75 आधार अंकों की वृद्धि के मुकाबले निधियों की लागत में 100 आधार अंकों की वृद्धि हुई है। ब्याज दरों में वृद्धि के कारण आस्तियों पर प्रतिफल में और सुधार हुआ।

2.26 यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2021-22' पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, आईबीआई ने पाया कि उच्च एनआईएम वित्तीय स्थिरता के साथ नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध है। फिर भी, वह सीमा जिसके ऊपर उच्च एनआईएम वित्तीय स्थिरता के लिए प्रतिकूल है, जो 5 प्रतिशत है। एससीबी का एनआईएम उससे काफी नीचे है। यह वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 3.9 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिसके बाद मार्च 2024 तक यह 3.6 प्रतिशत पर आ गया।

17 कॉमन इक्विटी टियर 1 का तात्पर्य सामान्य शेयरों (गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) और स्टॉक अधिशेष, प्रतिधारित आय, अन्य व्यापक आय, अर्हक अल्पसंख्यक हित और विनियामक समायोजन के योग से है

प्रदर्शन संकेतकों में लगातार सुधार

चार्ट II.8(क): परिसंपत्तियों पर रिटर्न (वार्षिकीकृत)

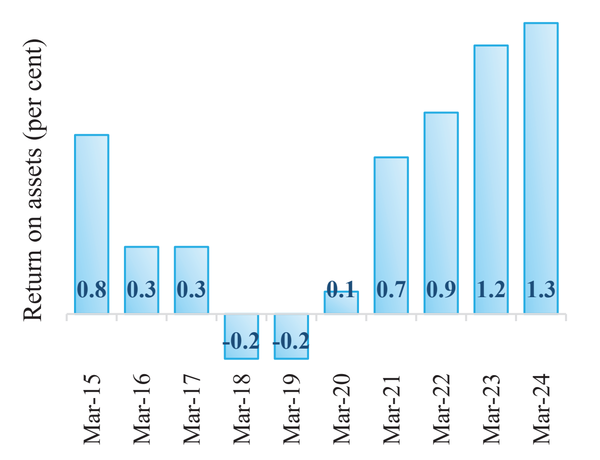

चार्ट II.8(ख): इक्विटी पर रिटर्न (वार्षिकीकृत)

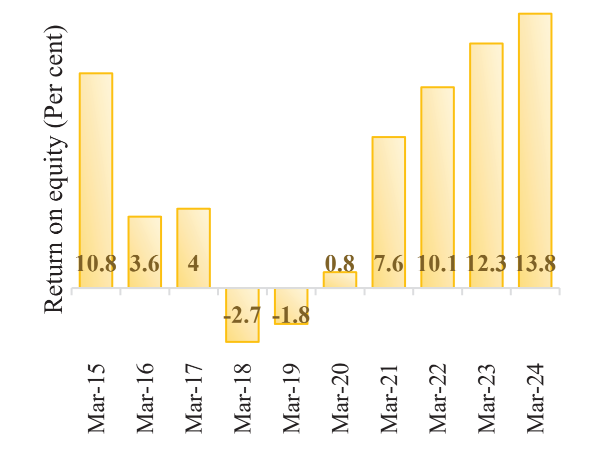

स्रोत: आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का अध्याय II, 'वित्तीय संस्थान: सुदृढ़ता और लचीलापन' (विभिन्न मुद्दे)

चार्ट II.9: एससीबी का उच्च शुद्ध ब्याज मार्जिन

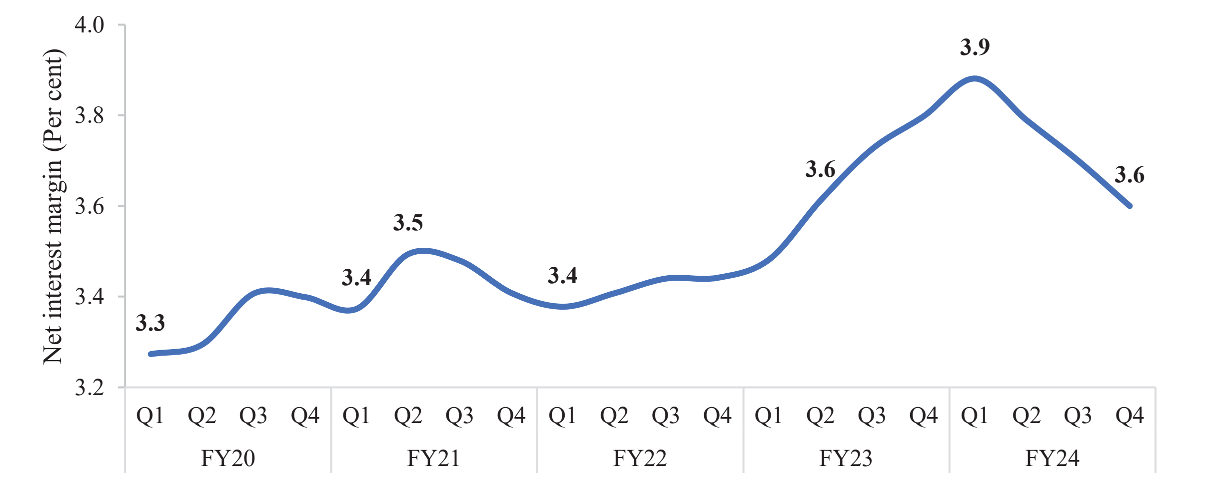

स्रोत: आरबीआई

2.27 भारत के बैंकिंग क्षेत्र ने उल्लेखनीय मजबूती दिखायी है। हाल के वर्षों में आरबीआई और सरकार द्वारा किए गए मैक्रो-और माइक्रो-विवेकपूर्ण उपायों ने जोखिम अवशोषण क्षमता को बढ़ाया है, जिससे बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता में सुधार हुआ है। आरबीआई के बुनियादी सांख्यिकीय रिटर्न 2 (एससीबी के पास जमा) से पता चलता है कि मार्च 2024 तक, भारत की 56.9 प्रतिशत जमा राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पास है। कुल जमा राशि का 61.1 प्रतिशत उन परिवारों के पास है जिन्हें स्टिकी रिटेल ग्राहक माना जाता है; इसलिए, किसी प्रतिकूल घटना की स्थिति में, इस श्रेणी में जमा निकासी सीमित रहने की संभावना है। दूसरा, आस्ति आकार में शीर्ष 10 भारतीय बैंकों के लिए, ऋण उनकी कुल आस्तियों का 50 प्रतिशत से अधिक है, जिससे बैंक बढ़ती ब्याज दर चक्र से प्रतिरक्षित हैं। तीसरा, पिछले वर्षों के दौरान पुनर्पूंजीकरण और बैंक बैलेंस शीट के परिशोधन के एक चरण के बाद, विभिन्न बैंकिंग संकेतकों में स्पष्ट सुधार हुआ है। शीर्ष 10 एससीबी (आस्ति आकार के आधार पर) के लिए सीआरएआर बेसल III मानदंडों से काफी ऊपर रहा है। चौथा, भारत में ब्याज दर चक्र काफी प्रमुख रहे हैं, जो आरबीआई की वित्तीय स्थितियों और

आर्थिक स्थिरता बनाए रखने तथा मुद्रास्फीति के दबावों को प्रबंधित करने के लक्ष्य के साथ संरेखित हैं। नियमित ब्याज दर चक्रों के संपर्क ने भारतीय बैंकों को चक्रों को संभालने के लिए अच्छी तरह से तैयार किया है।

2.28 ऊपर वर्णित विश्लेषण के आधार पर, यह देखा गया है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली उच्च पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात, बेहतर आस्ति गुणवत्ता और मजबूत आय वृद्धि द्वारा समर्थित, सुदृढ़ और लचीली बनी हुई है। एससीबी की लाभप्रदता में सुधार की प्रवृत्ति, जो वित्त वर्ष 2020 में शुरू हुई थी, वित्त वर्ष 2024 में लगातार पांचवें वर्ष जारी रही। इसमें उच्च आय और कम प्रावधान और आकस्मिकताओं से सहायता मिली है।

संकटग्रस्त परिसंपत्तियों से निपटना

2.29 बाजार में संकट को दूर करने की क्षमता अर्थव्यवस्था की मजबूती का एक माप है, और आर्थिक मंदी के दौर में ऐसा करने की क्षमता अर्थव्यवस्था के लचीलेपन का एक अनिवार्य संकेतक है। पिछले दशक में भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को एनपीए के भारी बोझ के कारण संकट का सामना करना पड़ा। मार्च 2016 तक, सार्वजनिक क्षेत्र का जीएनपीए अनुपात 14.5 प्रतिशत था। इसका दूसरा पहलू बैंक ऋण का स्थिर होना था, जिसने कारपोरेट लाभ में वृद्धि को बढ़ावा दिया, जिससे दोहरी बैलेंस शीट समस्या पैदा हुई। सबसे अधिक दबाव उद्योग और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में था।

2.30 सरकार ने पिछले दशक में बैंकों और निगमों में दबाव को दूर करने पर पूरा ध्यान दिया है। बैंकिंग विनियामक ढांचे को मजबूत करने, वसूली कानूनों में संशोधन करने, व्यापक दिवाला और दिवालियापन कानून बनाने और सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना जैसे उपायों को लागू किया गया। इन उपायों ने ऋण क्षेत्र को फिर से स्वस्थ बनाया है और मार्च 2024 में जीएनपीए अनुपात घटकर 2.8 प्रतिशत रह गया है।

2.31 बाजार की ताकतों के प्रचालन और उसके बाद व्यापार/उद्यम विफलताओं के कारण बाजार में दबाव का उभरना एक सक्रिय और गतिशील अर्थव्यवस्था का संकेत है। चूँकि बैंक भारत में व्यवसायों के लिए वित्त का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख स्रोत हैं, इसलिए बैंकों को संकटग्रस्त आस्तियों के प्रवाह से निपटने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, और बाजारों को ऐसी संपत्तियों के पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार में निवेश करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।

2.32 बैंकिंग विनियमन संकटग्रस्त आस्तियों की निगरानी और समय पर पहचान के लिए प्रावधान करते हैं, और आरबीआई ने अपने विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं। विनियमन ऋणों के पुनर्गठन और पुनर्निर्धारण के माध्यम से दबाव को उसके प्रारंभिक चरणों में समाधान करने के उपाय भी प्रदान करते हैं। इन विकल्पों की व्यापक रूपरेखा बैंकों के जोखिम प्रबंधन टूल किट का एक हिस्सा है। बैंकिंग विनियमन रक्षा की पहली पंक्ति और संकट का समाधान करने के उपाय हैं। आरबीआई उन्हें बाजार की जरूरतों और आर्थिक स्थितियों के जवाब में अपडेट करता है।

पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के पारंपरिक चौनल

2.33 रिकवरी रूट अर्थात, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 2002, दबाव को दूर करने के लिए उपलब्ध उपायों की दूसरी पंक्ति बनाते हैं। वित्त वर्ष 2023 के दौरान, एससीबी के जीएनपीए में लगभग 45 प्रतिशत की कमी वसूली और उन्नयन के कारण हुई।[18]

2.34 एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के तहत विनियमित आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी)[19] एफपीआई सहित निवेशकों के लिए बैंकों द्वारा धारित एनपीए/संकटग्रस्त आस्तियों तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक चौनल के रूप में उभर रही हैं। वित्त वर्ष 2023 के दौरान, 28 एआरसी बाजार[20] में परिचालन कर रही थीं। इस तरह का अधिग्रहण प्रतिभूति रसीदें (एसआर) जारी करके किया जाता है, और एआरसी को जारी किए गए एसआर का कम से कम 15 प्रतिशत या

18 भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर आरबीआई की रिपोर्ट वर्ष 2023, पृष्ठ 80, https://shorturl.at/dOXt1

19 एआरसीएस आरबीआई के साथ पंजीकृत संस्थाएँ हैं और उन्हें पुनर्निर्माण के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण, अग्रिमों, बांड, गारंटी और ऋण पत्र सहित वित्तीय आस्तियां प्राप्त करने की अनुमति है।

20 https://tinyurl.com.56vmwnkv

जारी किए गए कुल एसआर का 2.5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, लेने का अधिकार है। नियामक ढांचे ने एआरसी को कुछ शर्तों के अधीन आईबीसी प्रक्रिया के तहत समाधान आवेदकों के रूप में भाग लेने की अनुमति दी है। इसने आस्ति पुनर्निर्माण के दो बाजार चौनलों की सहक्रियाओं और पूरकताओं का दोहन करने की अनुमति दी है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान, एससीबी के जीएनपीए के पिछले वर्ष के स्टॉक का 9.7 प्रतिशत एआरसी को बेचा गया, जबकि वित्त वर्ष 2022 में यह केवल 3.2 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2023 के दौरान अंततः भुनाए गए एसआर की संख्या में वृद्धि हुई, जो इस माध्यम से बढ़ी हुई वसूली का संकेत देता है।

2.35 एनपीए के लिए एक कुशल बाजार के लिए आवश्यक शर्तें हैं कि यह गहन, प्रतिस्पर्धी हो और इसमें पर्याप्त तरलता हो। बाजार में पर्याप्त निवेशक होने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एनपीए की कीमत संबंधी खोज कुशल हो। बैंकों से अधिग्रहण का समर्थन करने और आस्तियों के टर्न-अराउंड का समर्थन करने के लिए इसमें पर्याप्त तरलता होनी चाहिए। जीएनपीए को कम करने के लिए किए गए प्रत्यक्ष उपायों के अलावा, सरकार एक बैड बैंक की स्थापना और दिवालियेपन और दिवालियापन पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करके तरलता और प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए बाजार-आधारित पहलों के साथ बाजार में प्रणालीगत ताकत का निर्माण कर रही है।

2.36 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने संकटग्रस्त आस्तियों के बाजार में तरलता में सुधार के लिए कई उपाय लागू किए हैं। (एफपीआई) को समाधान के दौर से गुजर रही कंपनियों द्वारा जारी ऋण लिखतों और एआरसी द्वारा जारी एसआर में निवेश करने की अनुमति है। इन निवेशों के लिए एफपीआई पर कोई न्यूनतम निवेशक सीमा या अवशिष्ट परिपक्वता आवश्यकता नहीं लगाई गई है। इन उपायों से वित्त वर्ष 2022[21] के दौरान एआरसी द्वारा जारी एसआर में एफपीआई निवेश लगभग ₹10,000 करोड़ से बढ़कर ₹14,482 करोड़ हो गया है। सेबी ने संकटग्रस्त आस्ति बाजार में भाग लेने के लिए वर्ष 2022 में एक विशेष मार्ग, विशेष स्थिति कोष, वैकल्पिक निवेश कोष का एक उप-घटक भी खोला। इसने इन निवेश साधनों को एआरसी द्वारा जारी एसआर में निवेश करने तथा कुछ शर्तों के अधीन आईबीसी प्रक्रिया के तहत समाधान आवेदक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी। धन तक पहुंच बढ़ने से, बाजार सहभागियों द्वारा अधिक एनपीए/संकटग्रस्त आस्तियों में निवेश किए जाने की संभावना है, तथा बैंकों के लिए वसूली दर अधिक होने की उम्मीद है।

संकटग्रस्त आस्ति बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा

2.37 संकटग्रस्त आस्ति बाजार को और अधिक मजबूत करने के लिए, सरकार ने जुलाई 2021 में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) और इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (आईडीआरसीएल) की स्थापना की। एनएआरसीएल बैंकों से आस्तियों प्राप्त करती है, और सरकार इन आस्तियों के विरुद्ध जारी किए गए एसआर की गारंटी देती है। इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (आईडीआरसीएल) के पास एनएआरसीएल द्वारा अधिग्रहित आस्तियों के समाधान के लिए एनएआरसीएल के साथ एक विशेष व्यवस्था है। आईडीआरसीएल को आस्ति के लिए उपयुक्त समाधान रणनीति की पहचान करने और इष्टतम समाधान परिणामों में एनएआरसीएल की सहायता करने का अधिकार है। एनएआरसीएल द्वारा अर्जित आस्तियां बैंक बैलंस शीट को तुरंत क्लियर करती हैं, ताकि आगे उधार देने के लिए पूंजी मुक्त होती है।

2.38 एनएआरसीएल ने अब तक लगभग ₹92,000 करोड़[22] के ऋण जोखिम वाले 18 खातों का अधिग्रहण किया है, जिसमें समाधान आवेदकों के रूप में रुग्ण एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड का अधिग्रहण शामिल है। जबकि ₹1.25 लाख करोड़ की आस्तियों पर प्रस्ताव अधिग्रहण के विभिन्न चरणों में हैं, लगभग ₹40,000 करोड़ की आस्तियों के लिए सम्यक उद्यम और मूल्यांकन चल रहा है। संकटग्रस्त आस्तियों के एकत्रीकरण और समाधान के लिए सरकार द्वारा समर्थित कंपनी की स्थापना से बाजार में तरलता और प्रतिस्पर्धा में और सुधार होगा।

21 भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर आरबीआई की रिपोर्ट वर्ष 2021-2022, https://shorturl.at/yx9n4
22 वित्तीय सेवा विभाग के आंकड़े।

दिवालियापन समाधान के माध्यम से संकटग्रस्त आस्तियों का समाधान

2.39 आईबीसी को दोहरी बैलेंस शीट समस्या के लिए एक प्रभावी समाधान के रूप में मान्यता दी गई है, जहां बैंक एनपीए के दबाव में हैं, जबकि कारपोरेट अत्यधिक ऋणग्रस्त हैं और अपने ऋण को चुकाने में असमर्थ हैं। कोड समय रहते वित्तीय संकट को दूर करने का प्रावधान करता है। यह दिवालियापन पेशेवर को दिवालियापन प्रक्रिया का संचालन करने और संकटग्रस्त कारपोरेट क्षेत्र के प्रचालन के लिए अधिकृत करता है। साथ ही, लेनदारों की समिति प्रक्रिया और सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को संचालित करती है, इस प्रकार प्रक्रिया के दौरान मूल्य के और अधिक क्षरण को कम करती है। डिजाइन और संचालन के द्वारा, कोड सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को संतुलित करता है। आईबीसी ने कॉर्पोरेट देनदारों को अपने ऋण का समाधान करने और असफल व्यावसायिक प्रयासों से सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलने का एक रास्ता प्रदान किया है, इस प्रकार व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा दिया है और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया है। कोड ने जीएनपीए को महत्वपूर्ण रूप से कम करके और असफल कारपोरेट देनदारों को बचाने में मदद करके बैंकों के दबाव को दूर करने के लिए एक प्रभावी सहायता से समाधान के रूप में खुद को स्थापित किया है। इसने वित्तीय बाजारों के रिकवरी सेगमेंट और रियल सेक्टर में विफल/संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण को नई गति प्रदान की है। 2016 से अब तक के आठ वर्षों में, मोर्च 2024 तक ₹13.9 लाख करोड़ मूल्य के 31,394 कारपोरेट देनदारों का निपटान किया जा चुका है (प्रवेश-पूर्व मामले निपटान सहित)। समाधान प्रक्रिया में प्रवेश के तुरंत बाद नियंत्रण खोने के कारण देनदारों ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में आवेदन दाखिल करते ही लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है। एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ₹10.2 लाख करोड़ के अंतर्निहित डिफॉल्ट का प्रवेश-पूर्व चरण[23] में ही समाधान किया गया था। देनदार व्यवहार में यह बदलाव बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं के लिए एक बड़ा वरदान रहा है। संहिता ने लेनदार-देनदार संबंधों में स्पष्ट और पारदर्शी व्यवहार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक इष्टतम प्रोत्साहन-निराशाजनक मिश्रण बनाया है।

आईबीसी के अंतर्गत निपटाए गए मामलों और ऋणदाताओं द्वारा वसूली में उल्लेखनीय प्रगति

चार्ट II.10(क): अनुमोदित समाधान योजना के माध्यम से सुलझाए गए मामलों की संख्या

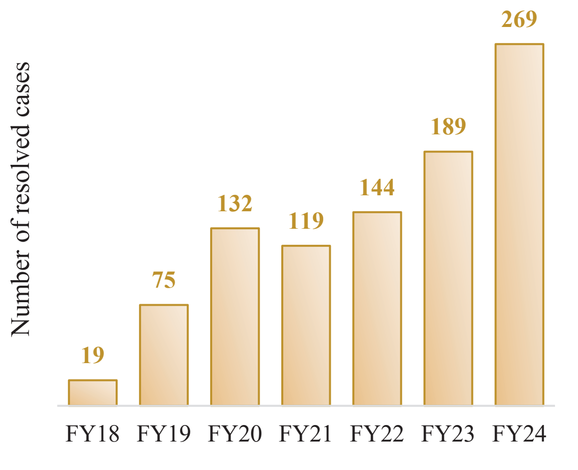

चार्ट II-10(ख): लेनदारों द्वारा वसूली

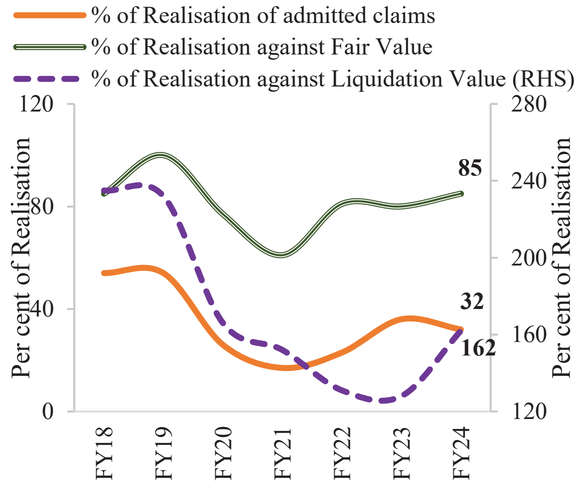

स्रोत: भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा जारी त्रैमासिक समाचार पत्र (विभिन्न अंक)

2.40 संहिता संकटग्रस्त परिसंपत्ति का समाधान करने के सर्वोत्तम साधनों की पहचान करने के लिए कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाओं (सीआईआरपीएस) का उपयोग करती है। इसने मार्च 2024 तक 4,131 सीआरआरपीएस को सफलतापूर्वक बंद करने में मदद की है। 3,171 कॉर्पोरेट देनदारों को बचाया गया है, जिनमें से 947 मामलों को अनुमोदित

23 स्रोत: आईबीबीआई न्यूजलेटर, जनवरी-मार्च 2024
https://ibbi.gov.in/uploads/publication/21aa7620a9e809f7a20b432eec89888b.pdf

समाधान योजनाओं के माध्यम से हल किया गया है, जिससे ₹3.36 लाख करोड़ का वसूली योग्य मूल्य प्राप्त हुआ है। हल किए गए मामलों में, लेनदारों ने अपने दावों का लगभग 32 प्रतिशत वसूल किया। यह उचित मूल्य का 85 प्रतिशत और परिसंपत्तियों के परिसमापन मूल्य का 162 प्रतिशत वसूल हुआ।

2.41 वित्तीय बाजारों की सामान्य स्थिति पर आईबीसी का प्रभाव स्पष्ट है क्योंकि यह आज एससीबी के लिए प्रमुख वसूली माग[24] है। भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति पर आबीआई की रिपोर्ट, वर्ष 2022-23 के अनुसार, आईबीसी ने वित्त वर्ष 2023 में एससीबी द्वारा वसूल की गई कुल राशि का 43 प्रतिशत हिस्सा धारित किया। वित्त वर्ष 2018 के बाद से छह वर्षों में, आईबीसी ने एससीबीएस के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वसूली को सक्षम बनाया है, जो कि लोक अदालतों, डीआरटी और एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के माध्यम से वसूल की गई राशि से अधिक है।

2.42 रियल सेक्टर के लिए अधिक महत्वपूर्ण यह है कि 3,000 से अधिक व्यवसाय सीआईआरपी से विकसित हुए हैं, निरंतर व्यावसायिक संचालन से इन कॉर्पोरेट देनदारों में वित्तीय संकट के कारण फंसे संसाधनों का उत्पादक उपयोग बढ़ रहा है। भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा किए गए एक अध्ययन[25] में बताया गया है कि संहिता के तहत समाधान प्रक्रिया से गुजरने वाली समाधित (रिजाल्व्ड) फर्मों ने समाधान-पूर्व अवधि की तुलना में समाधान-पश्चात अवधि में मूर्त आस्तियों और औसत पूंजीगत व्यय में वृद्धि के संदर्भ में अपने प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार देखा है, समाधान-पूर्व चरण में समाधित फर्मों का कुल बाजार मूल्यांकन लगभग 2 लाख करोड़ से बढ़कर समाधान-पश्चात चरण में ₹6 लाख करोड़ हो गया। समाधान के बाद के तीन वर्षों में समाधानित फर्मों (सूचीबद्ध) में कुल रोजगार में पर्याप्त वृद्धि हुई है और औसत कर्मचारी खर्च में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि है।

2.43 मार्च 2024 तक, परिसमापन में समाप्त होने वाले कुल सीआईआरपीएस 2,476 थे। इन कॉर्पोरेट देनदारों में से लगभग 77 प्रतिशत प्रक्रिया की शुरुआत में निष्क्रिय थे और औसतन, उनका मूल्य बकाया ऋण का 7 प्रतिशत था। परिसमापन प्रक्रिया, सुनाम प्रतिष्ठान की बिक्री/समझौता/व्यवस्था के माध्यम से परिसंपत्ति के पुनरुद्धार के लिए अवसर की अंतिम विंडो प्रदान करती है ताकि बचाए गए मूल्य को अधिकतम किया जा सके। इस अंतिम उपाय से लगभग 50 व्यवसायों को बचाया गया है। परिसमापन प्रक्रिया के अंत में 586 फर्मों को भंग कर दिया गया, जिससे वैकल्पिक उपयोगों के लिए जो भी संसाधन आवश्यक थे, उन्हें जारी कर दिया गया।

2.44 आईबीसी के तहत समाधान के लिए आरबीआई द्वारा संदर्भित बारह बड़े खातों[26] में से नौ का समाधान किया गया है। इन कॉर्पोरेट देनदारों के लिए समाधान योजनाओं ने स्वीकार किए गए दावों का 54 प्रतिशत प्राप्त किया। इन देनदारों में इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड, भूषण स्टील लिमिटेड, मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड, एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड आदि जैसी स्टील और बिजली की बड़ी कंपनियाँ शामिल थीं, और उनके समाधानों ने स्टील क्षेत्र के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आईबीसी की धारा 227 के तहत रूपरेखा वित्तीय सेवा प्रदाताओं के समाधान के लिए प्रावधान करती है, और वर्तमान में, 500 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति वाले आवास वित्त कंपनियों सहित एनबीएफसी को कवर किया जाता है। इस रूपरेखा के तहत दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के समाधान को संभव किया है। प्रत्येक मामले में, लेनदारों ने लगभग 42 प्रतिशत दावों की वसूली की है। बॉक्स-II.2 रियल एस्टेट कंपनियों के वित्तीय दबाव के समाधान हेतु आईबीसी प्रक्रिया की भूमिका पर चर्चा करता है।

24 यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संहिता का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य तनावग्रस्त कॉर्पोरेट देनदारों का समाधान करना है। दावों की वसूली समाधान की प्रक्रिया का एक हिस्सा मात्र है।

25 आईआईएम अहमदाबाद की रिपोर्ट, 'समाधान प्रक्रिया की प्रभावशीलता: आईबीसी के बाद के परिणामों से', https://ibb.-gov.in/uploads/resources/59f737b213b4700cc16428aefd62869a.pdf

26 आईबीसी के तहत समाधन के लिए आरबीआई द्वारा संदर्भित कारपोरेट ऋण प्राप्तकर्ताओं का पहला सेट।

बॉक्स II.2: ठप्प पड़ी रियल एस्टेट परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने और घर खरीदारों के अधिकारों को मजबूत करने में आईबीसी की भूमिका

वर्ष 2016 से पहले, घर खरीदने वालों के लिए एकमात्र उपाय, जिनकी आवासीय परियोजनाएं विभिन्न कारणों से रुकी हुई थीं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित उपभोक्ता फोरम के माध्यम से उपलब्ध था। वित्त वर्ष 24 में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 5,50[27] से अधिक मामले दर्ज किए गए, और लगभग 21 प्रतिशत आवास क्षेत्र से संबंधित थे। हालांकि, उपभोक्ता निवारण मार्ग के माध्यम से हल किए गए मामलों की संख्या न्यूनतम रही है। यह अनुमान लगाया गया था कि 4.1 लाख करोड़ रुपये की रियल एस्टेट परियोजनाओं में 4.1 लाख आवासीय इकाइयाँ संकट[28] में थीं।

वर्ष 2016 में रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 (रेरा अधिनियम) का अधिनियमन हुआ। इसने पीड़ित घर खरीदारों को एक समर्पित शिकायत निवारण तंत्र और चूककर्ता रियल एस्टेट ठेकेदारों और कंपनियों पर लगाम लगाने का एक साधन प्रदान किया। उसी वर्ष आईबीसी के बाद के अधिनियमन ने एक और चौनल खोला और तीन उपलब्ध उपायों में से यह सबसे पसंदीदा रहा है। मार्च 2024 तक, 1500 से अधिक रियल एस्टेट कंपनियों को आईबीसी के तहत दिवालियेपन समाधान प्रक्रिया में भर्ती कराया गया था, जो कुल प्रवेश का 21 प्रतिशत था। प्रवेश के बाद निपटाए गए चार मामलों में से एक भी इसी क्षेत्र से था। हल किए गए 891 कॉर्पोरेट देनदारों में से 133 रियल एस्टेट कंपनियाँ थीं, जो हल की गई कंपनियों का 15 प्रतिशत था।

रियल एस्टेट कंपनियों के दिवालियेपन समाधान ने मानकीकृत कॉर्पोरेट दिवालियेपन प्रक्रिया के लिए चुनौतियों का एक अनूठा समूह पेश किया। रियल एस्टेट कंपनियों के पास भौगोलिक क्षेत्रों में फैली कई परियोजनाएँ, निर्माण के विभिन्न चरणों में परियोजनाएँ और विविध व्यवसाय मॉडल हैं। इन परियोजनाओं में घर खरीदने वालों की बड़ी संख्या का मतलब था कि हजारों घर खरीदने वालों के दावे जिन्हें इस प्रक्रिया में शामिल करने की आवश्यकता थी। न्यायपालिका, सरकार और बाजार ने इन कठिनाइयों को पहचाना है और इन परियोजनाओं के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एकजुट कदम उठाए हैं। दो नए उपचारात्मक मार्गों की उपलब्धता ने प्रणाली में कलह और टकराव को जन्म दिया।

दिवाला कानून समिति ने अपनी मार्च 2018[29] की रिपोर्ट में रियल एस्टेट क्षेत्र की खासियत का संज्ञान लिया। इसने सुझाव दिया कि घर खरीदने वालों से जुटाई गई राशि को वित्तीय ऋण माना जाना चाहिए क्योंकि यह जुटाई गई राशि में महत्वपूर्ण योगदान देता है और उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव होता है। इसने घर खरीदने वालों को लेनदारों के एक प्रतिष्ठित वर्ग और लेनदारों की समिति का हिस्सा बनाकर सीआईआरपी में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिससे उन्हें निर्णय लेने में प्रत्यक्ष भागीदारी करने में सक्षम बनाया गया। हजारों घर खरीदने वालों के बहुमत के मतदान के माध्यम से निर्णय लेने और प्राप्त करने की एक प्रणाली भी तैयार की गई, ताकि अधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में दिवाला पेशेवरों को पेश किया जा सके। आगे के संशोधनों ने एक ही परियोजना के तहत कम से कम 100 आवंटियों या कुल आवंटियों की संख्या के कम से कम 10 प्रतिशत के संयुक्त आवेदन द्वारा दिवाला शुरू करने में सक्षम बनाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि झूठे आवेदन दायर नहीं किए जाते हैं। चूंकि घर खरीदने वालों के लिए एक उपाय के रूप में आईबीसी के उपयोग पर स्पष्टता सामने आई है, इसलिए यह भी निर्धारित किया गया कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए अनुमोदित समाधान योजनाएं अनिवार्य रूप से आरईआरए अधिनियम के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे क्षेत्र की इष्टतम निगरानी के लिए अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय कानून और क्षेत्रीय नियामक को प्राथमिकता मिल सके।

---

27 https://cms.nic.in/ncdrcusersWeb/dashboard.do\method=loadDashBoardPub पर सीओएनएफओएनईटी डैशबोर्ड, जैसा कि 21 मई 2024 को दर्शाया गया है

28 मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज 2016 नगर एवं देश नियोजन संगठन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/report(1).pdf

29 कारपोरेट कार्य मंत्रालय की मार्च 2018 की, दिवाला कानून समिति की रिपोर्ट। https://ibbi.gov.in/ uploads/resources/ILRReport2603 03042018.pdf

आर्थिक कानून में नवाचार के माध्यम से, न्यायपालिका ने रियल एस्टेट कॉरपोरेट देनदारों के समाधान में समाधान का मार्ग प्रशस्त किया। लेनदारों के एक वर्ग के रूप में, इसने घर खरीदारों को समाधान आवेदक के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया। इसने "रिवर्स सीआईआरपी" नामक एक प्रक्रिया को मंजूरी दी, जहाँ कॉरपोरेट देनदार समाधान प्रक्रिया के दौरान भी परियोजना को पूरा करने के लिए उपाय कर सकता था। न्यायपालिका ने परियोजना-विशिष्ट समाधान योजनाओं की अनुमति दी है, जो एक ही कॉरपोरेट देनदार के तहत प्रभावित परियोजना को लक्षित करती है। इस उपाय ने कॉरपोरेट देनदारों और विभिन्न परियोजनाओं के आवंटियों को राहत दी, और बाजार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

कई रियल एस्टेट कंपनियों ने ठप्प पड़ी हुई परियोजनाओं का सफलतापूर्वक हल निकालकर उन्हें आगे बढ़ाने हेतु सक्षम बनाया है। वैल्यू इंफ्राकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, समाधान प्रक्रिया ने लेनदारों को दावा मूल्य का 98 प्रतिशत और परिसंपत्ति के परिसमापन मूल्य का 189 प्रतिशत प्रदान किया।

आशियाना लैंडक्राफ्ट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और अनुदान प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के मामलों में, समाधानों ने परिसंपत्तियों के परिसमापन मूल्य का लगभग 2.5 गुना प्राप्त किया। जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड जैसे सेक्टर के बड़े कॉरपोरेट देनदारों का समाधान लेनदारों के लिए 88 प्रतिशत की वसूली के साथ किया गया है, और परिसंपत्तियों को परिसमापन मूल्य के 114 प्रतिशत[30] से अधिक पर अधिग्रहित किया गया है।

आईबीसी के तहत समाधान की गति बढ़ने के बावजूद, इन संकटग्रस्त परियोजनाओं में निवेश को चैनल/रीडायरेक्ट करने की आवश्यकता बनी हुई है। इस महत्वपूर्ण अंतर को दूर करने के लिए, सरकार ने 2019 में ₹12,500 करोड़ के लक्ष्य कोष के साथ किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो (एसडब्लूएएमआईएच) की स्थापना की। यह एक पेशेवर रूप से प्रबंधित वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) है जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट देनदारों और संहिता के तहत समाधान प्रक्रिया से गुजरने वाली परियोजनाओं सहित ठप्प पड़ी आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता ऋण वित्तपोषण प्रदान करना है। अप्रैल 2024 तक, एसडब्लूएएमआईएच फंड ने 32,000 से अधिक घर वितरित किए हैं और अगले तीन वर्षों के लिए हर साल 20,000 घरों की डिलीवरी का लक्ष्य रखा जा रहा है।

आईबीसी के तहत मामलों के निर्बाध समाधान और प्रगति तथा एआईएफ के माध्यम से तरलता में सुधार का प्रभाव बैंकों के अच्छे तुलन पत्र में परिलक्षित होता है, जिससे उनकी आगे और अधिक उधार देने की क्षमता बढ़ जाती है।

2.45 सरकार ने दिवालियापन पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इसने बुनियादी ढांचे के संबंध में एनसीएलटी को मजबूत किया है, रिक्तियों को भरकर और एक एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव देकर इसकी ताकत बढ़ाई है। बाजारों की जरूरतों और न्यायिक घोषणाओं में प्रगति के अनुरूप नियमों में संशोधन किया गया है। आईबीसी ने खुद को आस्ति परिसंपत्ति वसूली और पुनर्निर्माण बाजार के एक अपरिहार्य घटक के रूप में स्थापित किया है। इस प्रक्रिया में, इसने देश में ऋण बाजार परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया है।

वित्तीय समावेशन पहुंच के भीतर है; डिजिटल वित्तीय समावेशन अगला लक्ष्य है

2.46 वित्तीय समावेशन सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि सतत आर्थिक विकास, असमानता में कमी और गरीबी उन्मूलन के लिए एक साधन भी है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने वित्तीय समावेशन को 2030 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में अन्य विकास लक्ष्यों के एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में स्थान दिया है। शैक्षणिक साक्ष्य बताते हैं कि वित्तीय समावेशन समग्र आर्थिक विकास को बढ़ा सकता है और विभिन्न एसडीजी की उपलब्धि को सुगम बना सकता है।

2.47 सरकार ने अंतिम छोर तक वित्तीय सेवाएँ पहुँचाने को प्राथमिकता दी है। 2008 में वित्तीय समावेशन और औपचारिक पहचान के निम्न स्तर को देखते हुए, एक दशक से थोड़ा पहले भारत के सामने चुनौतियों की मात्रा बहुत बड़ी थी। विश्व बैंक के वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस के अनुसार, भारत ने पिछले दस वर्षों में अपने वित्तीय समावेशन लक्ष्यों में उल्लेखनीय प्रगति की है। औपचारिक वित्तीय संस्थान में खाता रखने वाले वयस्कों की संख्या 2011 में 35 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 77 प्रतिशत हो गई। वित्तीय संस्थान में बचत करने वाले और औपचारिक स्रोतों से उधार

30 आईबीबीआई द्वारा जारी परिणामों में दर्शाएं गए आंकड़ों के अनुसार, (https:/ibbi.gov.in/en/claims/cd-summary

लेने वाले वयस्कों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। अमीर और गरीब के बीच उपलब्धता के अंतर में कमी आई है। इसके अलावा, वित्तीय समावेशन के मामले में लैंगिक विभाजन भी कम हुआ है। जबकि वित्तीय समावेशन में लैंगिक आधार पर प्रगति हुई है, यह भी स्पष्ट है कि भारत के युवाओं को भी वही लाभ मिल रहे हैं (तालिका II.2)। दक्षिण एशियाई और विश्व औसत की तुलना में, भारत का प्रदर्शन विशिष्ट संकेतकों में बेहतर है (तालिका II.3)।

2.48 बैंक खाते के आंकड़ों और प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ संबंध के आधार पर, एक मोटा अनुमान यह है कि अगर भारत पूरी तरह से पारंपरिक विकास प्रक्रियाओं [31]पर निर्भर होता, तो 80 प्रतिशत वयस्कों के पास बैंक खाता होने में 47 साल लग जाते।

तालिका II.2: वित्तीय समावेशन और वित्तीय शिक्षा के संकेतकों में भारत का प्रदर्शन

क्र.सं.	वित्तीय समावेशन के संकेतक	2011	2021
1.	औपचारिक वित्तीय संस्थान में खाता रखने वाले वयस्क (%, आयु 15+)	35	77
2.	डिजिटल भुगतान किया या प्राप्त किया (% आयु 15+)	22'	35
3.	औपचारिक वित्तीय संस्थान से उधार लिया, अधिक उम्र वाले (% आयु 15+)	8	12
4.	खाता, सबसे गरीब 40% (% आयु 15+)	27	78
5.	खाता, सबसे अमीर 60% (% आयु 15+)	41	77
6.	खाता, महिला (% आयु 15+)	26	78
7.	खाता, पुरुष (% आयु 15+)	44	78
8.	युवा (आयु 15-24 वर्ष) जिन्होंने डिजिटल भुगतान किया या प्राप्त किया	19'	30

स्रोत: विश्व बैंक का वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस

नोट: 'डेटा 2014 का है, क्योंकि 2011 का डेटा उपलब्ध नहीं है

तालिका II.3: वित्तीय समावेशन और वित्तीय शिक्षा पैरामीटरो की क्रास-कंट्री तुलना

	औपचारिक वित्तीय संस्थान में खाता रखने वाले वयस्क (%, आयु 15+)	वित्तीय संस्थान में बचत करने वाले वयस्क (25+ आयु वर्ग के %)	औपचारिक वित्तीय संस्थान से उधार लिया गया, अधिक आयु (25 वर्ष से अधिक आयु का%)
विश्व	76	29	32
दक्षिण एशिया	68	11	12
ब्राजील	84	23	42
चीन	89	45	42
भारत	78	13	13
इंडोनेशिया	52	20	15
दक्षिण अफ्रीका	85	37	20

स्रोत: विश्व बैंक का वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस, 2021 का डेटा (नवीनतम उपलब्ध)

2.49 हाल ही में, देश में वित्तीय समावेशन रणनीति का फोकस 'हर घर' से 'हर वयस्क' की ओर स्थानांतरित हुआ है, जिसमें इन खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रवाह को बढ़ाकर खातों के उपयोग पर अतिरिक्त जोर दिया गया है, रूपे कार्ड, यूपीआई आदि का उपयोग करके डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया गया है। आईबीआई ने मार्च 2022 में फीचर फोन के लिए यूपीआई भुगतान करने के विकल्प के रूप में यूपीआई 123 पे लॉन्च किया, और नेशनल

31 बीआईएस पेपर संख्या 106: डिजिटल वित्तीय अवसंरचना का डिजाइन: भारत से सबक, डेरिल डी'सिल्वा, जुजाना फिल्कोवा, फ्रैंक पैकर और सिद्धार्थ तिवारी द्वारा, मौद्रिक और आर्थिक विभाग, दिसंबर 2019, (https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap106.pdf

पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने यूपीआई लाइट पेश किया, जो चुनिंदा बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑन-डिवाइस वॉलेट सेवा है जो बीएचआईएम ऐप के माध्यम से 200 तक के कम मूल्य के लेनदेन की अनुमति देती है। ये नवाचार भारत में डिजिटल अपनाने की प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में कदम हैं, जो एक अधिक समृद्ध और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर आबादी के बड़े हिस्से को समायोजित कर सकते हैं। भारत राष्ट्रीय और सीमा पार भुगतान प्रणालियों में अधिक दक्षता लाने के लिए कई देशों के साथ सहयोग भी कर रहा है।

2.50 आरबीआई भारत के फास्ट पेमेंट्स सिस्टम (एफपीएस), अर्थात यूपीआई को सीमा पार व्यक्ति से व्यक्ति (पी 2 पी) और व्यक्ति से व्यापारी (पी 2 एम) भुगतान के लिए अपने संबंधित एफपीएस के साथ जोड़ने के लिए विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग कर रहा है। आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल किया है, जो घरेलू एफपीएस को जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है। नेक्सस का उद्देश्य चार एशियन देशों (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड) और भारत के एफपीएस को जोड़ना है, जो इस मंच के संस्थापक सदस्य और पहले प्रस्तावक देश होंगे। इस आशय के एक समझौते पर 30 जून 2024[32] को बीआईएस और संस्थापक देशों के केंद्रीय बैंकों ने हस्ताक्षर किए है। इस प्लेटफॉर्म के 2026 तक लाइव होने की उम्मीद है। एक बार कार्यात्मक होने के बाद, नेक्सस से सीमा पार खुदरा भुगतान को कुशल, तेज और अधिक लागत प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

2.51 वित्तीय समावेशन के लिए आरबीआई की रणनीति के मुख्य घटक लक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण, बाजार विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, नवाचार और प्रौद्योगिकी, अंतिम-मील वितरण, उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय साक्षरता और जागरूकता[33] रहे हैं। इस रणनीति के अनुसरण में, वित्तीय समावेशन पर अब तक की प्रगति नीचे प्रस्तुत की गई है:

भारत में वित्तीय समावेशन संबंधी प्रगति

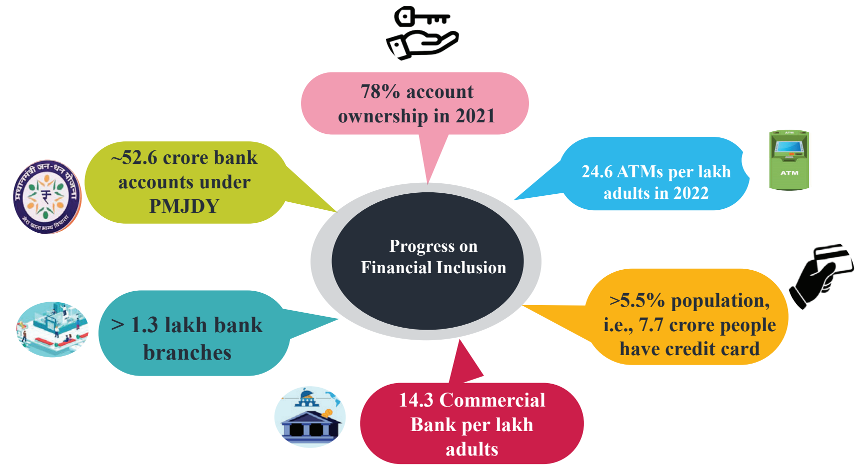

स्रोत: प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) वेबसाइट, पीआईबी और आरबीआई
नोट: जुलाई 2024 तक का डेटा

डिजिटल वित्तीय समावेशन

2.52 वित्तीय समावेशन अभियान का एक प्रमुख प्रवर्तक वित्तीय प्रणाली का डिजिटलीकरण रहा है, जिसने दुनिया भर में वित्तीय सेवाओं के परिदृश्य के परिवर्तन को उत्प्रेरित किया है। अब जब वित्तीय सेवाएँ डिजिटल उपकरणों पर आसानी से उपलब्ध हैं, तो अगली बड़ी चुनौती शडिजिटल वित्तीय समावेशन (डीएफआई)' सुनिश्चित करना है। डीएफआई में

32 दिनांक 1 जुलाई, 2024 को जारी बीआईएस प्रेस विज्ञप्ति, प्रोजेक्ट नेक्सस घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को विश्व स्तर पर जोड़ने के लिए व्यापक खाका पूरा करना है और लाइव कार्यान्वयन की दिशा में काम करने की तैयारी करना।
https://ww.bis.org/press/p240701.htm

33 आरबीआई ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2019-2024 शुरू की, जिसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में सभी हितधारकों को शामिल करते हुए कार्यों के व्यापक अभिसरण के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का विस्तार और उसे बनाए रखने में मदद करना है। इस रणनीति का उद्देश्य औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक सस्ती पहुँच प्रदान करना, वित्तीय समावेशन को व्यापक और गहरा बनाना तथा वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना है।

वर्तमान में वित्तीय रूप से वंचित और अल्पसेवित नागरिकों तक उनकी जरूरतों के अनुरूप औपचारिक वित्तीय सेवाओं की एक श्रृंखला पहुँचाने के लिए लागत प्रभावी डिजिटल साधनों की व्यवस्था करना शामिल है। डीएफआई के आवश्यक घटकों में ग्राहकों को भुगतान करने या प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए डिजिटल लेनदेन प्लेटफॉर्म की उपलब्धता और उपकरण इस प्रकार के ट्रांजेक्शन करने के लिए शामिल हैं। इन खुदरा एजेंटों के पास डिजिटल डिवाइस और डिजिटल लेनदेन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय सेवाएँ हैं।

2.53 जबकि भारत में वित्तीय सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में कदम उठाए जा रहे थे, कोविड-19 महामारी ने इस प्रक्रिया को और गति दी, जब सबसे कमजोर और वंचित नागरिक गंभीर रूप से प्रभावित हुए। तद्नुसार, सरकार ने नवाचार को प्रोत्साहित किया और एक अच्छी तरह से तैयार डिजिटल बुनियादी ढाँचा और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली विकसित की। यह एक समावेशी, लागत-कुशल और जिम्मेदार डीपीआई के रूप में विकसित हुआ है।

2.54 भारत को एक फिनटेक राष्ट्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से, सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन, मेक-इन-इंडिया आदि जैसी कई प्रमुख योजनाएँ शुरू की हैं। डीपीआई के निर्माण पर अधिक जोर दिया गया है जैसे आधार, ई-केवाईसी, आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली, यूपीआई, भारत क्यूआर, डिजीलॉकर, ई-साइन, अकाउंट एग्रीगेटर, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क आदि। इन डीपीआई का उपयोग विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा साझा आधार पर किया जा सकता है ताकि इष्टतम परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। इससे पारदर्शिता, बड़े पैमाने पर संचालन और जनता को वित्तीय सेवाओं की समय पर डिलीवरी हुई है।

2.55 भारत के मजबूत डीपीआई ने देश के डिजिटल परिवर्तन को सक्षम करने, नागरिक-केंद्रित और पारदर्शी शासन सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की तेजी से बढ़ती आबादी, विश्व स्तरीय डीपीआई और सक्रिय विनियमन ने फिनटेक उद्योग के विकास को आधार प्रदान किया है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक बाजारों में से एक है, जिसे तीसरी सबसे बड़ी बढ़ती फिनटेक अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है।

भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: अर्थव्यवस्था के पहिये को गति देना

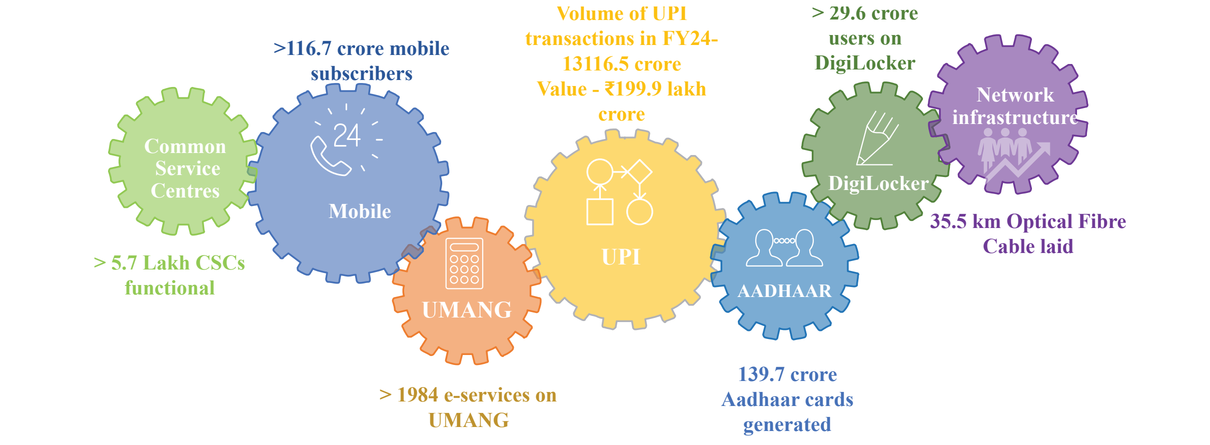

नोट: जुलाई 2024 तक के आंकड़े,
स्रोत: संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों का डैशबोर्ड

2.56 डीएफआई में प्रगति ने औपचारिक और विशाल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में लाखों लोगों को भुगतान स्वीकार करने, चालान का निपटान करने और देश में कहीं भी कुछ स्क्रीन टैप के साथ धन हस्तांतरित करने में सक्षम बनाया है। ये प्रगति इंडिया स्टैक, एक व्यापक डिजिटल पहचान, भुगतान और डेटा-प्रबंधन प्रणाली पर आधारित है। इंडिया स्टैक में तीन परस्पर जुड़ी परतें हैं जो हर भारतीय को आसान, लागत-मुक्त, मोबाइल-प्रथम डिजिटल लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हुए एक डिजिटल पहचान प्रदान करती हैं। इंडिया स्टैक के[34] तीन महत्वपूर्ण घटक पहचान स्तर, भुगतान स्तर और डेटा शासन स्तर हैं। पहचान स्तर के संबंध में, आधार भारत के प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने में सहायक रहा

34 विश्व बैंक का ब्लॉग, 'भारत का डिजिटल परिवर्तन आर्थिक विकास के लिए गेम-चेंजर हो सकता है', दिनांक 2डीएफ10 जून 2023, https:/shorturl.at/Z2rL9

है। इसने केवाईसी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया है, ई-केवाईसी करने की लागत को 12 अमेरिकी डॉलर से घटाकर 6 सेंट कर दिया है जिससे करोड़ो भारतीयों तक बैंकिंग सुविधा का विस्तार हुआ और वित्तीय समावेशन में सुधार हुआ है। भुगतान के स्तरों में, यूपीआई ने देश की भुगतान प्रणाली में क्रांति ला दी है। 31 मार्च 2024[35] तक 116.5 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन ग्राहकों के साथ भारत में स्मार्टफोन के उपयोग के विस्तार से यूपीआई की सफलता में वृद्धि हुई है। यूपीआई प्लेटफॉर्म पर किए गए लेन-देन का मूल्य वर्ष 17 में ₹0.07 लाख करोड़ से कई गुना बढ़कर वर्ष 2024[36] में ₹200 लाख करोड़ हो गया है। डेटा गवर्नेंस स्तर उपयोगकर्ता डेटा पर स्वामित्व और नियंत्रण को उसके सही स्वामियों तक सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

2.57 डिजिटल ऋण व्यक्तियों और फर्मों को आर्थिक अवसरों को विकसित करने के लिए सशक्त बनाकर सतत और समावेशी विकास के लिए एक शक्तिशाली एजेंट हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के शोध के अनुसार, भुगतान के डिजिटल वित्तीय समावेशन में वृद्धि से औसत आर्थिक विकास में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि होती है, जो संभवतः उपभोग चौनल और उच्च औपचारिकता[37] के माध्यम से संचालित होती है।

माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं: वित्तीय समावेशन को सुगम बनाना

'औपचारिक वित्त तक पहुँच से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सकता है, आर्थिक उतार-चढ़ाव के प्रति अरक्षितता कम हो सकती है और मानव पूंजी में निवेश बढ़ सकता है। वित्तीय सेवाओं तक पर्याप्त पहुँच के साथ, व्यक्ति और फर्म अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए वित्त के महंगे अनौपचारिक स्रोतों पर भरोसा कर सकते हैं। व्यापक स्तर पर, अधिक वित्तीय समावेशन से सभी के लिए सतत और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास का हेतु सहायता मिल सकती है।'

- वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2019-24, आरबीआई

2.58 माइक्रोफाइनेंस का तात्पर्य उन परिवारों, छोटे व्यवसायों और उद्यमियों को छोटे-मूल्य के ऋण सहित वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है, जिनकी औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच नहीं है। यह वित्तीय समावेशन के लिए एक प्रभावी साधन है, जिसमें गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को सामाजिक समानता और सशक्तीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए माइक्रोफाइनेंस और संबंधित सेवाएँ स्थायी रूप से प्रदान करना शामिल है। माइक्रोफाइनेंस किफायती डोरस्टेप सेवाएँ प्रदान करके कम आय वाले परिवारों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में एक आवश्यक भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बीमा, धन प्रेषण, वित्तीय साक्षरता आदि जैसी अन्य वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने में भी भूमिका निभाई है। माइक्रोफाइनेंस वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक के रूप में उभरा है।

2.59 भारत में एमएफआई क्षेत्र के विकास को आरबीआई के सहायक नियामक ढांचे के साथ-साथ स्व-नियामक संगठनों (एसआरओ) द्वारा उद्योग आचार संहिता के निर्माण से काफी सुविधा हुई है। क्षेत्र में बदलती गतिशीलता ने सा-धन[38] द्वारा उत्तरदायी उधार के लिए संहिता के विकास को भी आवश्यक बना दिया है, जो माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में काम करने वाले सभी उधारदाताओं के लिए एक स्वैच्छिक संहिता है। सा-धन के साथ, एमएफआईएन[39] यह एमएफआई क्षेत्र के लिए एक एसआरओ है जो माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के विकास की दिशा में काम करता है। 14 मार्च 2022 को माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के लिए आरबीआई द्वारा जारी माइक्रोफाइनेंस ऋणों के लिए नया नियामक ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि माइक्रोफाइनेंस

35 भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की रिपोर्ट, '31 मार्च 2024 तक दूरसंचार सदस्यता डेटा', पृष्ठ संख्या 6, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/PR_No.23of2024_0.pdf.

36 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, https://www.npci.org.in/what-we-do/upi/product-statistics

37 आईएमएफ वर्किंग पेपर, जून 2021, 'क्या डिजिटल वित्तीय समावेशन विकास को अनलॉक कर रहा है', https://tinyurl.com/2russwem

38 सा-धन को आरबीआई द्वारा वर्ष 2015 में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के लिए एक एसआरओ के रूप में मान्यता दी गई थी ताकि एमएफआई की प्रभावी निगरानी, नियमों के अनुपालन और ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में आचार संहिता के लिए उद्योग के नियमों, उपकरणों और प्रदर्शन मानकों को प्रशासित किया जा सके। एसआरओ के रूप में, सा-धन एमएफआई की प्रभावी निगरानी, नियमों के अनुपालन और ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में आचार संहिता के लिए उद्योग के नियमों, उपकरणों और प्रदर्शन मानकों को तैयार करने और प्रशासित करने में सबसे आगे रहा है। सा-धन भारतीय माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र को पेशेवर, स्वस्थ और नैतिक तर्ज पर विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है

39 https://mfinindia.org/

क्षेत्र में काम करने वाली सभी संस्थाएं समान नियमों के अध्यधीन हों, सभी के लिए समानता का दृष्टिकोण सृजित करता है तथा उधारकर्ताओं के हित की रक्षा करता है।

2.60 वैश्विक स्तर पर, भारतीय माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या अगले सबसे बड़े बाजार अर्थात इंडोनेशिया से लगभग तीन गुना है। भारतीय माइक्रोफाइनेंस कवरेज (स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)) 50 प्रतिशत से अधिक घरों और भारतीय जनसंख्या[40] के 10 प्रतिशत से अधिक है।

तालिका II.4: भारत में दूसरा सबसे बड़ा माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र है

देश	बचतकर्ता (लाखों में)	उधारकर्ता (लाखों में)	बकाया ऋण (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)
बांग्लादेश (जून 2022)	66.4	44.6	17.4
कंबोडिया (दिसंबर 2022)	2.7	2.1	9.7
फिलीपींस (दिसंबर 2020)	-	17.0	7.6
इंडोनेशिया (दिसंबर 2019)	-	56.8	2.1
पाकिस्तान (मार्च 2023)	98.1	9.25	1.8
भारत (मार्च 2023)			
एसएचजी	161	83	23.5
एमएफआई	-	73	44

स्रोत: उद्योग संघों, केंद्रीय बैंक की वेबसाइटों और शैक्षणिक प्रकाशनों जैसे विभिन्न स्रोतों से एकत्रित डेटा

2.61 2023 भारत माइक्रोफाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार, एमएफआई भारत के 28 राज्यों, पांच संघ राज्य क्षेत्रों और 646 से अधिक जिलों में काम करते हैं। वित्त वर्ष 23 तक भारत में दो सौ तेरह एमएफआई काम करते हैं, जिनकी 25,790 शाखाओं का नेटवर्क है और जिसमें 2.2 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। साथ में, वे माइक्रो-क्रेडिट[41] के तहत ₹1.8 लाख करोड़ के कुल ऋण बकाया के साथ 532 लाख से अधिक ग्राहकों तक पहुँच चुके हैं। नए ग्राहकों का जुड़ना इस क्षेत्र के निरंतर समावेशन संबंधी प्रयासों को दर्शाता है और दूरस्थ और कम सेवा वाले भौगोलिक क्षेत्रों के लिए उम्मीद जगाता है। 31 मार्च 2023 तक, एमएफआई के पास बकाया ऋण वाले ग्राहकों की संख्या, जिसमें 179 दिनों से अधिक बकाया वाले ग्राहक भी शामिल हैं, 571 लाख थी। इनमें से, एमएफआई द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले सक्रिय ग्राहक (179 दिनों से अधिक बकाया वाले ग्राहकों को छोड़कर) 532 लाख थे, जो कि वर्ष दर वर्ष 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

2.62 यद्यपि एमएफआई ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीबों की सेवा करते हैं, लेकिन वे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर अधिक उन्मुख हैं। कुछ समय के लिए शहरी उधारकर्ताओं का प्रभुत्व था, और उद्योग में बड़े निवेशक, जैसे बंधन और अन्य एमएफआई जो बैंक/लघु वित्त बैंक (एसएफबी) बन गए, एमएफआई क्षेत्र का हिस्सा थे। ग्रामीण क्षेत्र की ओर एक निश्चित बदलाव हुआ है, और यह पिछले चार वर्षों से जारी है। ग्रामीण ग्राहकों की वर्तमान हिस्सेदारी 74 प्रतिशत है।

40 समावेशी वित्त भारत रिपोर्ट, 2023, एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज, https://inclusivefinanceindia.org/wp-content/uploads/2023/12/IFI-Report-2023.pdf

41 भारत माइक्रोफाइनेंस रिपोर्ट, 2023, सा-धन, https://rb.gy/hnq8zo

चार्ट II.11: ग्रामीण एमएफआई उधारकर्ताओं की बढ़ती हिस्सेदारी

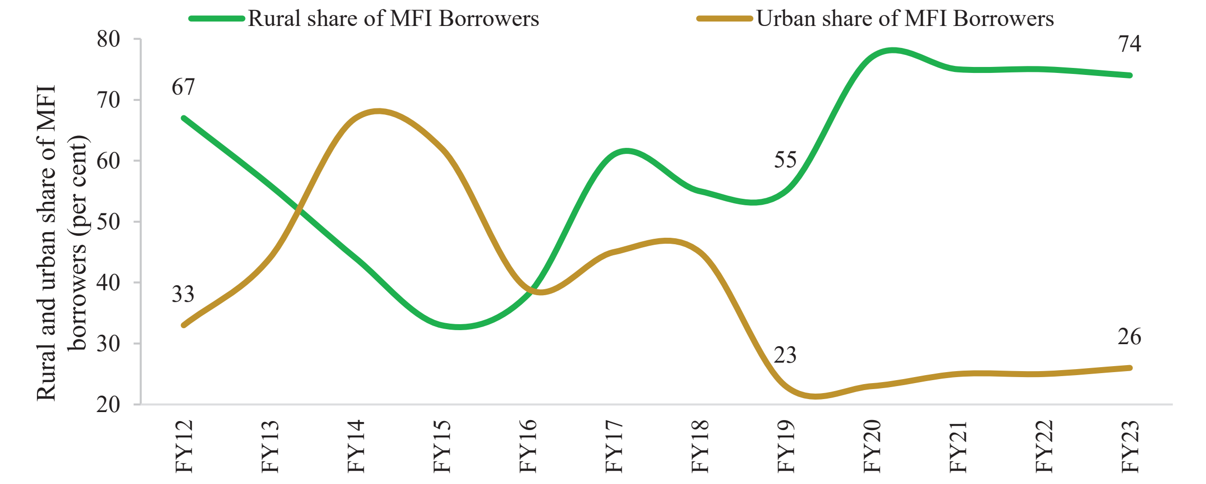

स्रोत: भारत माइक्रोफाइनेंस रिपोर्ट 2023, सा धन (पृष्ठ 16, चित्र 2.8)

2.63 माइक्रोफाइनेंस मुख्यत: महिला-केंद्रित गतिविधि है। भारत में, एमएफआई के कुल ग्राहकों में से 98 प्रतिशत महिलाएँ हैं। इसके अलावा, यह अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अल्पसंख्यकों जैसे अन्य कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों को भी महत्वपूर्ण तरीके से सेवा प्रदान करता है। एससी/एसटी उधारकर्ताओं का एक बड़ा हिस्सा अर्थात 23 प्रतिशत ग्राहकों है।

चार्ट II.12: पिछले कुछ वर्षों में एमएफआई द्वारा ऋण वितरण में वृद्धि

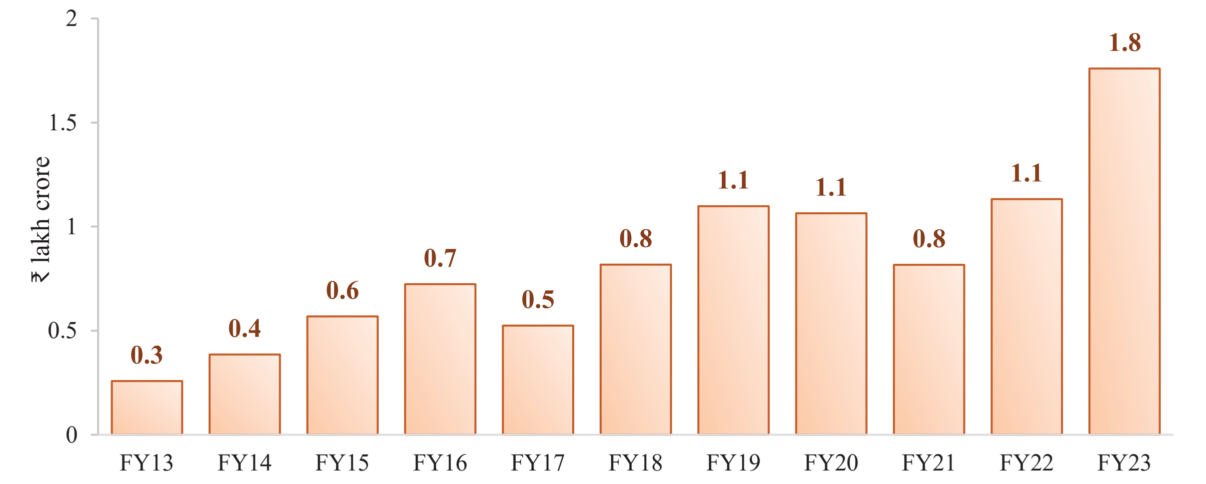

स्रोत: भारत माइक्रोफाइनेंस रिपोर्ट 2023, सा धन (पृष्ठ 28, चित्र 2.18)

2.64 एमएफआई द्वारा ऋण वितरण में कोविड-19 महामारी जैसी बाह्य घटनाओं के कारण कुछ वर्षों को छोड़कर पूरे वर्ष स्थिर वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 23 के दौरान, माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र ने जोरदार वापसी की, तथा पिछले वर्ष की तुलना में 55 प्रतिशत अधिक ₹1.8 लाख करोड़ का कुल वितरण प्राप्त किया।

2.65 वित्त वर्ष 23 के दौरान एमएफआई के प्रदर्शन और लाभप्रदता अनुपात उद्योग के अच्छी स्थिति और बेहतर संभावनाओं की तस्वीर पेश करते हैं। उद्योग ने प्रचालन लागत में कटौती करने में कामयाबी हासिल की, जबकि वित्त लागत को पिछले वर्षों की तरह कमोबेश उसी स्तर पर बनाए रखा। वित्त वर्ष 2023 के अंत में एमएफआई की कुल संपत्ति ₹1.5 लाख करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक थी। पिछले कुछ वर्षों से यह क्षेत्र कुछ बाह्य घटनाओं के कारण बीच में एक या दो साल को छोड़कर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 23 में,

सभी एमएफआई के लिए आरओए और आरओई 2.5 प्रतिशत और 12.2 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में सुधार को दर्शाता है। आईबीआई के नियामक मानदंडों के अनुसार, एनबीएफसी-एमएफआई को अपनी जोखिम-भारित आस्तियों का कम से कम 15 प्रतिशत पूंजी के रूप में बनाए रखना होगा। यद्यपि अन्य कानूनी रूपों के लिए कोई शर्त नहीं है, लेकिन एनबीएफसी एमएफआई के बराबर पूंजी रखना वांछनीय है। भारतीय एमएफआई की पूंजी पर्याप्तता निर्धारित मानदंडों से काफी ऊपर है, यहां वित्त वर्ष 23 के लिए औसत सीएआर 26.5 रहा।

2.66 वित्त वर्ष 23 के दौरान, पोर्टफोलियो गुणवत्ता बढ़ाने में अच्छी प्रगति हासिल की गई है। एमएफआई चूक से बचने, वसूली में सुधार करने और निपटान और राइट-ऑफ के माध्यम से पुराने मामलों से निपटने में सक्षम रहे हैं। एमएफआई के लिए प्रदर्शन और जवाबदेही रिपोर्टिंग (पीएआर) 30+ अनुपात कोविड-पूर्व स्तरों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी वित्त वर्ष 19 में हासिल किए गए न्यूनतम अपचारी (डेलिंक्वेंसी) अनुपातों से कम हैं। सीआरआईएफ-हाईमार्क विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 23 के दौरान, एमएफआई 30, 60 और 90-दिवसीय पीएआर के मामले में एक बकेट से दूसरे में ह्रासित ऋणों[42] के आगे के प्रवाह को कम करने में सक्षम थे। हालांकि, एमएफआई और बैंकों[43] के लिए 91 से 180-दिवसीय बकेट में आगे के प्रवाह में वृद्धि हुई।

2.67 ग्रामीण भारत में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र की सफलता को कई संकेतकों का उपयोग करके मापा जा सकता है। सबसे व्यापक माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम, एसएचजी-बैंक लिंकेज प्रोग्राम (एसएचजी-बीएलपी) ने वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 23 में बैंकों के पास बकाया ऋण वाले एसएचजी की संख्या और राशि के माध्यम से महामारी के बाद के पुनरूत्थान को दर्शाया है। वित्त वर्ष 23 के दौरान, एसएचजी-बीएलपी के तहत ऋण वितरण ₹1.5 लाख करोड़ था, जो 45.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता करता है। वित्त वर्ष 23 के दौरान ऋण से जुड़े एसएचजी की संख्या वित्त वर्ष 22 में 34 लाख से बढ़कर 43 लाख हो गई। मार्च 2023 तक, बैंकिंग प्रणाली में 24.7 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि के साथ ₹58,893 करोड़ की एसएचजी बचत थी, जिसमें प्रति एसएचजी औसत बचत ₹43,940 थी[44]। आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक में मार्च 2023 के 60.1 से मार्च 2024 में 64.2 तक सुधार, भारत में वित्तीय क्षेत्र[45] की पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता के क्षेत्र में की जा रही प्रगति को दर्शाता है।

भारतीय पूंजी बाजार में रुझान

2.68 भू-राजनीतिक जोखिम बढ़ने, ब्याज दरों में वृद्धि और कमोडिटी की अस्थिर कीमतों के बावजूद, भारतीय पूंजीगत बाजार वित्त वर्ष 24 में उभरते बाजारों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक रहे हैं, जो भारत की उज्ज्वल आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। पूंजीगत बाजार भारत की विकास गाथा में महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, प्रौद्योगिकी, नवाचार और डिजिटलीकरण के बल पर पूंजी निर्माण और निवेश परिदृश्य में उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। निम्नलिखित खंड भारत में प्राथमिक बाजारों, द्वितीयक बाजारों और संस्थागत निवेश में महत्वपूर्ण रुझान प्रस्तुत करते हैं।

प्राथमिक बाजार

2.69 स्वस्थ घरेलू आर्थिक प्रदर्शन और अनुकूल निवेश माहौल के बीच, प्राथमिक बाजार वित्त वर्ष 24 के दौरान मजबूत रहे, जिससे ₹10.9 लाख करोड़ का पूंजी निर्माण हुआ (जो वित्त वर्ष 23 के दौरान निजी और सार्वजनिक निगमों के

42 बिगड़ा हुआ ऋण एक ऐसा ऋण है जो समझौते की मूल शर्तों के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर रहा है।

43 माइक्रोफाइनेंस ऋण पर सीआरआईएफ त्रैमासिक प्रकाशन का खंड XXIII, 'माइक्रोलेंड', मार्च 2023, https://www.crifhighmark.com/media/2921/crif-microlend-vol-ñiii_mar-2023.pdf

44 भारत में माइक्रोफाइनेंस की स्थिति 2022-23, https://shorturl.at/BlzynA

45 एफआई-इंडेक्स की अवधारणा एक व्यापक सूचकांक के रूप में तैयार की गई है, जिसमें सरकार और संबंधित क्षेत्रीय विनियामकों के परामर्श से बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक, साथ-साथ ही पेंशन क्षेत्र का विवरण शामिल है। एफआई-इंडेक्स में तीन व्यापक पैरामीटर (कोष्ठक में दर्शाए गए भार) शामिल हैं, अर्थात, एक्सेस (35 प्रतिशत), उपयोग (45 प्रतिशत), और गुणवत्ता (20 प्रतिशत), इनमें से प्रत्येक में विभिन्न आयाम शामिल हैं, जिनकी गणना कई संकेतकों के आधार पर की जाती है।

सकल स्थिर पूंजी निर्माण का लगभग 29 प्रतिशत है), जबकि वित्त वर्ष 23 में यह ₹9.3 लाख करोड़ था। वित्त वर्ष 24 में जुटाई गई कुल राशि में से 78.8 प्रतिशत ऋण निर्गमों के माध्यम से जुटाई गई थी। तीनों तरीकों, अर्थात इक्विटी, ऋण और हाइब्रिड के माध्यम से निधियों का संग्रहण पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 24 में क्रमशः 24.9 प्रतिशत, 12.1 प्रतिशत और 513.6 प्रतिशत बढ़ा।

2.70 आरंभिक सार्वजनिक निर्गमों (आईपीओ) की संख्या वित्त वर्ष 24 में 66 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 23 के 164 से वित्त वर्ष 24 में 272 हो गई, जबकि जुटाई गई राशि वित्त वर्ष 23 की तुलना में 24 प्रतिशत बढ़ी (वित्त वर्ष 23 में ₹54,773 करोड़ से वित्त वर्ष 24 में 67,995 करोड़) थी। एक्सचेंजों पर एसएमई प्लेटफॉर्म पर वित्त वर्ष 24 के दौरान अत्यधिक गतिविधियाँ देखी गई क्योंकि एसएमई के आईपीओ/एफपीओ की संख्या 1.6 गुना बढ़ गई (वित्त वर्ष 23 में 125 से वित्त वर्ष 24 में 196 तक), जबकि जुटाई गई इसी राशि में पिछले वर्ष की तुलना में ढाई गुना से अधिक की वृद्धि हुई (वित्त वर्ष 23 में ₹2,333 करोड़ से वित्त वर्ष 24 में ₹6,095 करोड़ तक)। ईएण्डवाई ग्लोबल आईपीओ ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय एक्सचेंज आईपीओ लिस्टिंग में वैश्विक अग्रणी थे। भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़कर 2023 में 17 प्रतिशत हो गई, जो 2021 और 2022 में क्रमशः 6 प्रतिशत और 11 प्रतिशत थी[46]। बाजार की सकारात्मक परिस्थितियों को दर्शाते हुए, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी)[47] वित्त वर्ष 24 के दौरान कारपोरेट्स के लिए एक महत्वपूर्ण इक्विटी फंड जुटाने के तंत्र के रूप में उभरे। राइट्स इश्यू के माध्यम से संसाधन जुटाना वित्त वर्ष 24 के दौरान दोगुना से अधिक बढ़कर ₹15,110 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह ₹6,751 करोड़ था।

सार्वजनिक ऋण निर्गम

2.71 भारत में कॉर्पोरेट ऋण बाजार लगातार मजबूत होता जा रहा है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान, कारपोरेट बंधपत्र जारी करने का मूल्य पिछले वित्त वर्ष के 7.6 लाख करोड़ से बढ़कर ₹8.6 लाख करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2024 में कारपोरेट बंधपत्र सार्वजनिक निर्गमों की संख्या किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए अब तक की सबसे अधिक थी, जिसमें जुटाई गई राशि (₹19,167 करोड़) चार साल के उच्चतम स्तर पर थी। कॉरपोरेट्स के लिए निजी प्लेसमेंट पसंदीदा चौनल बना रहा, जो बॉन्ड मार्केट के माध्यम से जुटाए गए कुल संसाधनों का 97.8 प्रतिशत था। निवेशकों की बढ़ती मांग और बैंकों से उधार लेने की लागत में वृद्धि ने इन बाजारों को कॉरपोरेट्स के लिए वित्तपोषण आवश्यकताओं के लिए अधिक आकर्षक बना दिया है। मार्च 2024 के अंत में बकाया कारपोरेट बंधपत्र की मात्रा साल-दर-साल 5.5 प्रतिशत बढ़कर ₹45 लाख करोड़ (यानी, जीडीपी का 15.5 प्रतिशत) हो गई।

आरईआईटी और इनविट्स

2.72 वित्त वर्ष 24 के दौरान, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इनविट्स) द्वारा 39,024 करोड़ रुपये जुटाए गए, जो वित्त वर्ष 23 की तुलना में पांच गुना से अधिक है, जिसे अवसंरनचा के विकास पर सरकार द्वारा दिए गए बल के जोर से समर्थन मिला।

द्वितीयक बाजार

भारत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बाजारों में शामिल

2.73 वित्त वर्ष 23 में अत्यधिक अशांत वैश्विक माहौल को झेलने के बाद, वैश्विक शेयर बाजारों ने वित्त वर्ष 24 के दौरान सुधार किया और अच्छा प्रदर्शन किया। चीन और हांगकांग को छोड़कर सभी प्रमुख बाजारों ने पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि के दौरान बेहतर रिटर्न दिया। भारतीय शेयर बाजार सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से

46 19 फरवरी 2024 को 'भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 2023 में आईपीओ की संख्या के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर' पर ई एंड वाई प्रेस विज्ञप्ति, https://shorturl-at/Lj6Z3

47 क्यूआईपी की शुरुआत सेबी ने वर्ष 2006 में की थी, जिसके तहत भारतीय सूचीबद्ध कंपनियाँ इक्विटी शेयर, पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर या सेबी द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के तहत उल्लिखित किसी भी अन्य प्रतिभूति को जारी करके धन जुटा सकती हैं। सूचीबद्ध कंपनियाँ सेबी को प्री-इश्यू फाइलिंग जमा करने जैसी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किए बिना भी पूंजी जुटा सकती हैं।

एक रहा, जिसमें भारत का निफ्टी 50 इंडेक्स वित्त वर्ष 24 के दौरान 26.8 प्रतिशत चढ़ा, जबकि वित्त वर्ष 23 के दौरान (-)8.2 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 24 में वैश्विक बाजारों में अमेरिका, ब्राजील और जापानी बाजारों से शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। एआई के नेतृत्व में टेक स्टॉक में उछाल के सबूत मिले, जिसमें वित्त वर्ष 23 में भारी नुकसान के बाद वित्त वर्ष 24 के दौरान टेक-हैवी यूएस नैस्डैक इंडेक्स में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चार्ट II.13: भारतीय शेयर बाजार का उल्लेखनीय प्रदर्शन

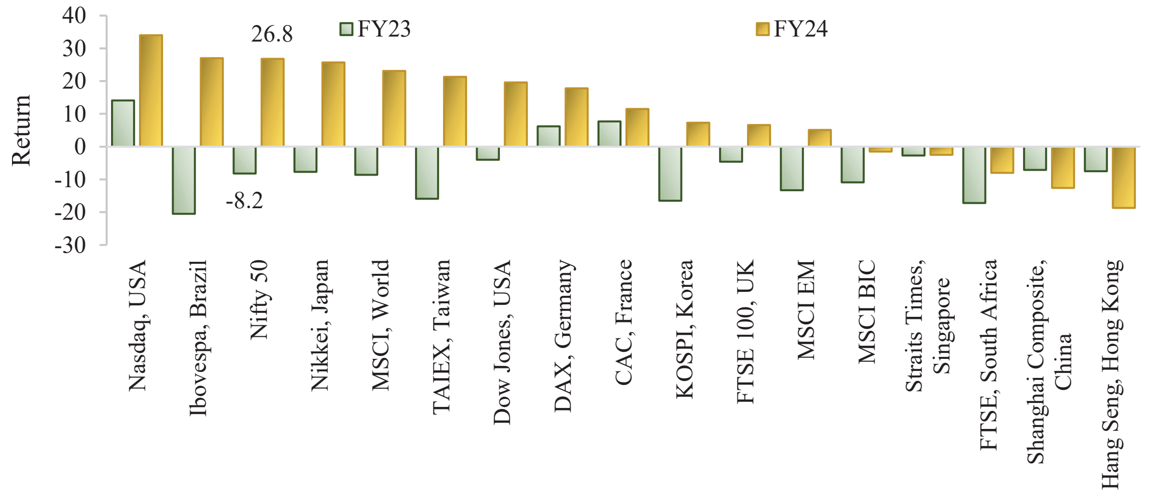

स्रोतः सूचकांक मूलयों के लिए रिफाइनिटिव

2.74 पिछले कुछ वर्षों में दुनिया और उभरते बाजारों की तुलना में भारतीय शेयर बाजार के शानदार प्रदर्शन का श्रेय मुख्य रूप से वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक उतार-चढ़ावों के प्रति भारत की समुत्थानशीलता, इसके ठोस और स्थिर घरेलू समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण और घरेलू निवेशक आधार की मजबूती को दिया जा सकता है। भारतीय बाजारों के सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाते हुए, एमएससीआई-ईएम सूचकांक में भारत का भार 23 अप्रैल के अंत में 13.7 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 24 के अंत में 17.7 प्रतिशत हो गया है, जो सूचकांक में ईएम के बीच दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है।

2.75 भारतीय शेयर बाजार के बाजार पूंजीकरण में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। आकर्षक निवेश स्थल के रूप में भारतीय शेयर बाजार में घरेलू और वैश्विक निवेशकों की उल्लेखनीय रुचि और निरंतर आईपीओ गतिविधि ने वित्त वर्ष 24 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारतीय बाजार को दुनिया में पांचवें स्थान पर पहुंचा दिया। भारत का बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात पिछले पांच वर्षों में काफी सुधरकर वित्त वर्ष 24 में 124 प्रतिशत हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 19 में यह 77 प्रतिशत था, जो चीन और ब्राजील जैसी अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं अधिक है। सावधानी बरतना जरूरी है। हालांकि, बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात जरूरी नहीं कि आर्थिक उन्नति या विकास का संकेत हो। वित्तीय आस्तियों वास्तविक वस्तुओं और सेवाओं पर दावे हैं। यदि वास्तविक अर्थव्यवस्था पर इक्विटी बाजार के दावे अत्यधिक उच्च हैं, तो यह बाजार की समुत्थानशीलता के बजाय बाजार की अस्थिरता का अग्रदूत है।

2.76 वित्त वर्ष 2024 के दौरान निवेशकों की बढ़ती भागीदारी और सकारात्मक बाजार रुझानों के साथ मुद्रा डेरिवेटिव को छोड़कर एक्सचेंजों में सभी खंडों में कारोबार मूल्य में वृद्धि हुई,। वित्त वर्ष 2024 में कमोडिटी डेरिवेटिव कारोबार में 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो ऊर्जा खंड के विकल्प अनुबंधों के कारोबार में वृद्धि से प्रेरित थी।

तालिका II.5: विभिन्न देशों में बाजार पूंजीकरण से सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात (प्रतिशत)

	भारत	चीन	ब्राजील	जापान	दक्षिण कोरिया	यूनाइटेड किंगडम	संयुक्त राज्य अमेरिका
दिसम्बर-19	77	60	65	121	89	106	159
दिसम्बर-20	95	79	68	129	122	92	197
दिसम्बर-21	113	80	50	136	127	108	208
दिसम्बर-22	105	65	42	126	96	91	158
दिसम्बर-23	124	61	44	147	114	71	179

नोट: 'जीडीपी के आंकड़े वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज (डब्ल्यूएफई) से लिए गए हैं, और बाजार पूंजीकरण की गणना एनएएसडीएक्यू और एनवाईएस के बाजार पूंजीकरण के योग के रूप में की जाती है।
स्रोत: सीईआईसी डेटाबेस, विश्व बैंक, डब्यूएफई

2.77 बॉक्स II.3 प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से पूंजी बाजार को मजबूत करने के लिए की गई पहलों पर चर्चा करता है, जिन्होंने उनके प्रदर्शन और दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बॉक्स II.3: प्रौद्योगिकी और भारतीय पूंजी बाजार का तालमेल: विकास और दक्षता को बढ़ावा देना

भारतीय पूंजी बाजारों में विभिन्न उप-बाजारों में व्यापक विस्तार देखा गया है, देश का इक्विटी बाजार पूंजीकरण मई 2024 में 415 लाख करोड़ (यूएसडी 5.0 ट्रिलियन) तक पहुंच गया है, जिससे यह वैश्विक रैंकिंग में पांचवीं स्थान पर है।

प्रौद्योगिकी का प्रसार दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं को बदलने में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक रहा है, और भारतीय पूंजीगत बाजार इसका अपवाद नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में लगातार बदलाव हुए हैं, विकास और दक्षता को सुविधाजनक बनाने के लिए तकनीकी प्रगति का लाभ उठाया गया है। प्रौद्योगिकी बाजार नियामक सेबी के तीन लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है: बाजार विनियमन, निवेशक संरक्षण और बाजार विकास।

आज व्यक्तिगत निवेशकों की संख्या साढ़े नौ करोड़ से अधिक है और उनके पास लगभग 2500 सूचीबद्ध कंपनियों के माध्यम से बाजार का लगभग 10 प्रतिशत प्रत्यक्ष स्वामित्व है, जो मार्च 2024 तक लगभग 36 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के बराबर है, इसके अलावा इक्विटी म्यूचुअल फंड में अप्रत्यक्ष स्वामित्व है, जिनकी प्रबंधन के तहत संपत्ति 28 लाख करोड़ रुपये है। इस तरह, प्रौद्योगिकी एक्सचेंजों को फर्मों और लाखों बाजार निवेशकों को पूंजी आवंटित करने में मदद करती है ताकि वे उन कंपनियों में निवेश कर सकें, जहां वे कभी नहीं गए और उनकी दीर्घकालिक सफलता और धन सृजन में भाग ले सकें। कुल मिलाकर, पिछले तीन दशकों में भारत में बाजार पूंजीकरण 100 गुना से अधिक बढ़ गया है।

इंडिया स्टैक और विनियामक उपायों जैसी तकनीकी प्रगति ने खुदरा निवेशकों की भागीदारी और गतिविधि में अभूतपूर्व वृद्धि को बढ़ावा दिया है। उपयोगकर्ता के अनुकूल ट्रेडिंग ऐप्स, मोबाइल-फ्रेंडली शैक्षिक संसाधनों और वित्तीय बाजार मार्गदर्शन के प्रचलन और प्रसार ने पूंजीगत बाजारों[48] तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना दिया है। प्रौद्योगिकी के निर्बाध उपयोग ने निवेशकों को मिनटों में ऑनलाइन ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलने, अपने घरों में आराम से व्यापार करने, निवेश रिपोर्ट तक पहुंचने और कुशलतापूर्वक ऑनलाइन पूछताछ करने का अधिकार दिया है। निवेशक शिकायत

48 समझाया गया: भारतीय शेयर बाजार में खुदरा भागीदारी में वृद्धि का कारण क्या है? लाइवमिंट (2024), लिंक यहां उपलब्ध है: https://tinyurl.com/3xetmuvt

समाधान के लिए मंच, सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (एससीओआरईएस) तथा निवेशक शिक्षा के लिए कार्यक्रम, सिक्योरिटी मार्केट ट्रेनर (एसएमएआरटीएस) जैसी पहलें, बाजार सहभागियों, विशेषकर पहली बार निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करने में सहायक रही हैं।

बाजार के विकास में प्रौद्योगिकी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की अनूठी डिजिटल वास्तुकला ने पूंजीगत बाजार नियामक को ''टी+1 निपटान व्यवस्था'' को आराम से अपनाने का आत्मविश्वास दिया है, यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसका अनुसरण दुनिया भर[49] के बहुत कम देश कर रहे हैं। क्लियरिंग कॉरपोरेशन (सीसी) के बीच ''इंटरऑपरेबिलिटी'' की शुरूआत ने स्टॉक एक्सचेंजों और सीसी के बीच उम्मीद से अधिक संबंध बनाए, जिसने प्रतिभागियों[50] के बेहतर मार्जिन उपयोग और पूंजी संसाधनों के माध्यम से ट्रेडिंग लागत को कम किया। भारतीय पूंजीगत बाजारों ने द्वितीयक बाजार में ब्लॉक किए गए खाते द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए) ''सुविधा को भी प्रायोगिक आधार पर अपनाया है, जो निवेशकों को व्यापार की पुष्टि होने तक अपने बैंक में धन को अवरुद्ध करने की अनुमति देता है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की हाल ही में एनएसडीएल-सीएएस नामक पहल ने कई खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो[51] में डीमैट प्रारूप में रखी गई आस्तियों का एक समग्र दृश्य प्रस्तुत करके निवेशकों के जीवन को और आसान बना दिया है।

विकास, निवेशक सुरक्षा और बाजार विकास से परे, आज व्यापार निरंतरता पूंजी बाजारों का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गई है। वर्ष 2022 में शुरू किया गया, "डीआर45" ढांचा न्यूनतम स्विचिंग टाईम[52] के साथ अप्रत्याशित घटनाओं के मामले में मौजूदा कनेक्टिविटी मापदंडों का उपयोग करके व्यापार जारी रखने की अनुमति देता है। सेबी के परामर्श से, स्टॉक एक्सचेंजों और ब्रोकरों ने स्टॉकब्रोकर्स के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ियों को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है, जैसे कि ''एलएएमए[53] (लॉग एनालिटिक्स और मॉनिटरिंग एप्लिकेशन) रिपोर्टिंग'' एपीआई, जो आईटी संरचना का अवलोकन करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है। इसके अतिरिक्त, एनसीएल और आईसीसीएल[54] जैसे क्लियरिंग कॉरपोरेशन ने अप्रत्याशित सॉफ्टवेयर विफलताओं[55] को प्रबंधित करने के लिए 'एसएएएस' (सॉफ्टवेयर ऐज ए सर्विस) मॉडल के रूप में संचालित होने के लिए दो-तरफा पोर्टेबिलिटी पर काम किया है।

जबकि प्रौद्योगिकी और पूंजीगत बाजारों के तालमेल ने महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किए हैं, उभरती चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। गोपनीयता संबंधी चिंताएँ, साइबर सुरक्षा जोखिम और आबादी में बढ़ता डिजिटल विभाजन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर भी, नियामक यह महसूस करते हुए कि प्रौद्योगिकी और पूंजीगत बाजारों के समन्वय से अधिकतम क्षमता को अनलॉक करना भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास और विकास के लिए आवश्यक है, अपने दृष्टिकोण में दृढ़ रहे हैं।

पूंजी बाजार में खुदरा भागीदारी

2.78 भारतीय पूंजीगत बाजारों में पिछले कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष (अपने खातों के माध्यम से बाजारों में व्यापार) और अप्रत्यक्ष (म्यूचुअल फंड के माध्यम से) चैनलों के माध्यम से खुदरा गतिविधि में उछाल देखा गया है। इक्विटी कैश सेगमेंट टर्नओवर में व्यक्तिगत निवेशक की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 24 में 35.9 प्रतिशत थी। दोनों डिपॉजिटरी के साथ डीमैट खातों की संख्या वित्त वर्ष 23 में 1,145 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 1,514 लाख हो गई। बाजार में व्यक्तिगत

49 भारतीय इक्विटी बाजारों ने सीमित तरीके से एक ही दिन के निपटान चक्र (''टी+ओ'') में भी बदलाव किया है, ऐसा करने वाला यह पहला देश बन गया है। छोटे निपटान चक्रों में बदलाव ने दक्षता बढ़ाई है और निपटान जोखिम कम किया है।

50 क्लियरिंग कॉरपोरेशन के बीच अंतर-संचालन, पीडब्लूसी (2019)

51 प्रौद्योगिकी और शिक्षा के माध्यम से निवेशक केंद्रित सेवाओं को बढ़ाना, एआईबीआई शिखर सम्मेलन (2022)

52 https://www.nseindia.com/trade/disaster.recovery.faqs

53 एलएएमए रिपोर्टिंग: विफलता कोई विकल्प नहीं है, आईटीआरएस ब्लॉग (2023)

54 नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड; इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

55 एनएसई क्लियरिंग आर्काइव दिनांक 29 मार्च, 2023

निवेशकों की आमद का यह प्रभाव एक्सचेंजों के साथ नए निवेशक पंजीकरण, कुल कारोबार मूल्य में उनकी हिस्सेदारी, उनके निवल निवेश और सूचीबद्ध कंपनियों में उनके स्वामित्व में भी परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए, एनएसई में पंजीकृत निवेशक आधार मार्च 2020 से मार्च 2024 तक लगभग तिगुना बढ़कर 31 मार्च 2024 तक 9.2 करोड़ हो गया है, जिसका संभावित अर्थ यह है कि अब 20 प्रतिशत भारतीय परिवार अपनी घरेलू बचत को वित्तीय बाजारों में लगा रहे हैं।

म्यूचुअल फंड: पूंजी बाजार में वित्तीय बचत और खुदरा भागीदारी में तेजी लाना

2.79 म्यूचुअल फंड के द्वारा अप्रत्यक्ष चैनल के माध्यम से खुदरा भागीदारी में वृद्धि अधिक महत्वपूर्ण और स्थिर थी। वित्त वर्ष 2024 म्यूचुअल फंड (एमएफ) के लिए एक शानदार वर्ष रहा है क्योंकि एमएफ की 'प्रबंधन के तहत आस्ति' (एयूएम) वित्त वर्ष 2024 के अंत में ₹14 लाख करोड़ (वार्षिक आधार पर 35 प्रतिशत की वृद्धि) बढ़कर ₹53.4 लाख करोड़ हो गई, जिसे मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) लाभ और उद्योग के विस्तार से बढ़ावा मिला। वित्त वर्ष 23 के अंत में फोलियो की कुल संख्या 14.6 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 24 के अंत में 17.8 करोड़ हो गई। आय/ऋण-उन्मुख योजनाओं को छोड़कर, एमएफ योजनाओं की सभी श्रेणियों में निवल निवेश हुआ। विकास/इक्विटी-उन्मुख और हाइब्रिड योजनाओं में निवेश एमएफ में निवल निवेश का 90 प्रतिशत से अधिक था। निष्क्रिय योजनाओं में, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) (गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड के अलावा) में निवल आस्तियों में 37 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

2.80 भारतीय एमएफ सेगमेंट में वर्तमान में लगभग 8.4 करोड़ व्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी)[56] खाते हैं, जिनके माध्यम से निवेशक नियमित रूप से योजनाओं में निवेश करते हैं। पिछले तीन वर्षों में वार्षिक निवल एसआईपी प्रवाह दोगुना हो गया है, जो वित्त वर्ष 21 में ₹0.96 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में ₹2 लाख करोड़ हो गया है। इक्विटी-उन्मुख योजनाओं के लिए कुल एसआईपी एयूएम एमएफ उद्योग के एयूएम का लगभग 35 प्रतिशत है। इसने 31 दिसंबर 2023 तक भारतीय इक्विटी में एमएफ के स्वामित्व को 9.2 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है, जबकि 31 दिसंबर 2021 तक यह 7.7 प्रतिशत था।

चार्ट II.14: एसआईपी निवेश में वृद्धि

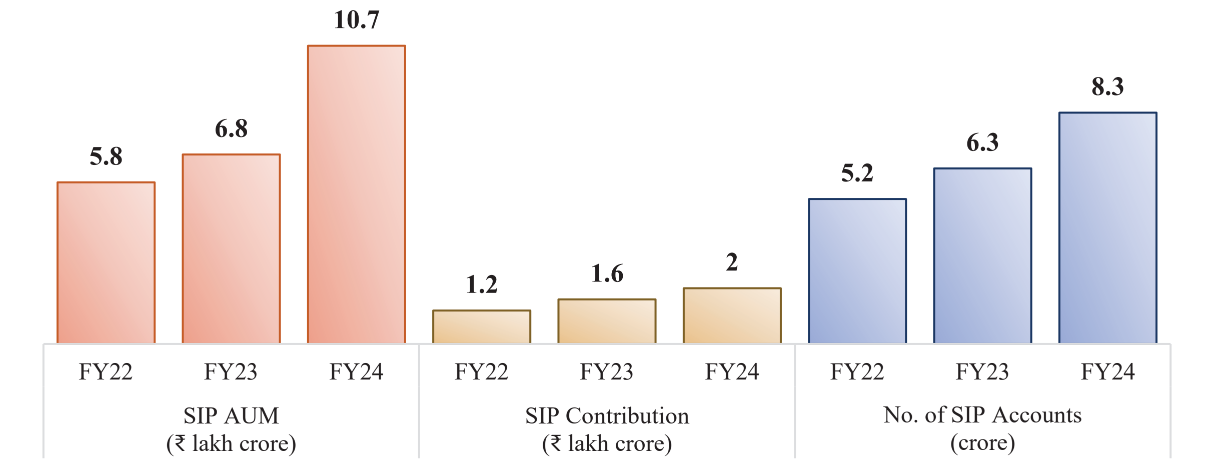

नोट: बकाया एसआईपी खाते और एसआईपी एयूएम की रिपोर्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में दी जाती है। एसआईपी योगदान एसआईपी खातों के माध्यम से वार्षिक सकल योगदान से संबंधित है।
स्रोत: एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई)

2.81 महामारी की अवधि और उसके बाद निवेशकों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने वाले कुछ कारकों में निर्बाध तकनीकी एकीकरण, वित्तीय समावेशन के लिए सरकारी उपाय, डिजिटल अवसंरचना का विकास, तेजी से स्मार्टफोन की पहुंच, कम लागत वाली ब्रोकरेज का उदय, वैकल्पिक स्रोतों से आय उत्पन्न करने की खोज और रियल

56 एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक व्यवस्थित तरीका है, जिसमें नियमित अंतराल पर बाजार में निवेश के लिए एक छोटी पूर्व-निर्धारित राशि आवंटित की जाती है।

एस्टेट और सोने जैसे पारंपरिक आस्ति वर्गों द्वारा उत्पन्न कम लाभ शामिल हैं। हालांकि, खुदरा निवेशकों ने वित्तीय बाजारों में अपने लाभ को भुनाया है और वास्तविक आस्तियों में निवेश कर रहे हैं। यह स्मार्ट पोर्टफोलियो विविध ीकरण है। कम ब्याज दरों, कोविड-19 के बाद ठोस रिकवरी, उच्च मुद्रास्फीति और सहायक नीति पृष्ठभूमि के रूप में अनुकूल आर्थिक माहौल ने भी पूंजीगत बाजार आस्तियों के खुदरा संचय को बढ़ावा दिया। इसके अलावा, निवेशकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले निरंतर निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों ने प्रतिभूति बाजारों में व्यक्तिगत भागीदारी की निरंतर वृद्धि में योगदान दिया है। अगस्त 2023 में, सेबी ने ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) की शुरुआत की, जो प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिए ऑनलाइन सुलह और ऑनलाइन मध्यस्थता को जोड़ती है। वित्त वर्ष 24 में शुरू किया गया एक और महत्वपूर्ण उपाय निवेशक की मृत्यु के मामले में रिपोर्टिंग और सत्यापन के लिए केंद्रीकृत तंत्र था, जिससे कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरण प्रक्रिया सुचारू हो गई। निवेशक सुरक्षा कोष[57] और निपटान गारंटी कोष[58] में वृद्धि और निपटान चक्र को छोटा करने से भारतीय बाजारों में सुरक्षा और सुरक्षा की धारणा में सुधार हुआ है। फिर भी, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि खुदरा निवेशक इन फंडों को अपने नुकसान को कम करने और बैकस्टॉप प्रदान करने के तंत्र के रूप में न समझें।

2.82 एनएसई पर पंजीकृत अद्वितीय कर आईडी की संख्या वित्त वर्ष 19 में 2.7 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 9.2 करोड़ हो गई। भारतीय पूंजीगत बाजार में खुदरा निवेशकों की बढ़ी हुई भागीदारी बेहद स्वागत योग्य है और पूंजीगत बाजार को स्थिरता प्रदान करती है। इसने खुदरा निवेशकों को अपनी बचत पर अधिक लाभ अर्जित करने में भी सक्षम बनाया है। अधिकांश नए खुदरा निवेशक संभवतः युवा हैं और उनमें जोखिम लेने की क्षमता अधिक हो सकती है। यह खुदरा निवेशकों द्वारा डेरिवेटिव ट्रेडिंग, खास तौर पर एक्सपायरी-डे ट्रेडिंग में दिखाई गई रुचि में भी परिलक्षित होता है। जबकि डेरिवेटिव हेजिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन दुनिया भर के निवेशक इनका इस्तेमाल ज्यादातर सट्टा इंस्ट्रूमेंट के तौर पर करते हैं। भारत भी शायद इसका अपवाद नहीं है।

2.83 डेरिवेटिव ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा लाभ की संभावना होती है। इस प्रकार, यह मनुष्यों की जुआ खेलने की प्रवृत्ति को पूरा करता है और अगर लाभदायक हो तो आय बढ़ा सकता है। ये विचार डेरिवेटिव ट्रेडिंग में सक्रिय खुदरा भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं। हालाँकि, वैश्विक स्तर पर, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में निवेशकों को ज्यादातर समय नुकसान होता है। निवेशकों को जागरूक करना और निरंतर वित्तीय शिक्षा देना उन्हें डेरिवेटिव ट्रेडिंग से कम या नकारात्मक अपेक्षित रिटर्न के बारे में चेतावनी देने के लिए जरूरी है। एक महत्वपूर्ण शेयर सुधार में नुकसान हो सकता है जो डेरिवेटिव के माध्यम से पूंजीगत बाजारों में भाग लेने वाले खुदरा निवेशकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। निवेशकों की व्यवहारिक प्रतिक्रिया अदृश्य अधिक महत्वपूर्ण ताकतों द्वारा श्धोखाश् महसूस करना होगी। वे लंबे समय तक पूंजीगत बाजारों में वापस नहीं आ सकते हैं। यह उनके और अर्थव्यवस्था के लिए क्षति है।

2.84 अर्थव्यवस्थाओं का वित्तीयकरण अच्छा नहीं रहा है, यहाँ तक कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी। वर्ष 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट इसका स्पष्ट उदाहरण है। विकासशील देशों को तब दुर्बल करने वाले संकटों का सामना करना पड़ता है जब वित्तीय बाजार के श्नवाचारश और विकास आर्थिक विकास से आगे निकल जाते हैं। वर्ष 1997-98 के एशियाई संकट ने क्षेत्र की ऊंची उड़ान भरने वाली अर्थव्यवस्थाओं को लंबे समय के लिए पीछे धकेल दिया। इसलिए, भारत को वित्तीय बाजार[59] का व्यवस्थित और क्रमिक विकास करने की आवश्यकता है।

2.85 सभी हितधारकों – बाजार सहभागियों, बाजार अवसंरचना संस्थानों, विनियामकों और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूंजीगत बाजार बचत को उनके सबसे अधिक उत्पादक निवेशों की ओर निर्देशित करने की अपनी सैद्धांतिक रूप से सौंपी गई भूमिका निभाए। यह सिर्फ राष्ट्रीय हित में नहीं है। यह एक स्वार्थपूर्ण कार्य भी है।

57 निवेशक संरक्षण निधि, दावे के स्वीकृत मूल्य को पूरा करने के लिए चूककर्ताओं के खाते में अपर्याप्त पाई गई धनराशि की सीमा तक निवेशकों को मुआवजा देती है, जो सदस्यों के निष्कासन/चूक की घोषणा पर उत्पन्न होने वाले दावों के संबंध में प्रति चूककर्ता/निष्कासित सदस्य प्रति निवेशक 25 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन है।

58 निपटान गारंटी निधि का उद्देश्य स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से एक्सचेंज के सदस्यों के सभी लेनदेन के निपटान की गारंटी देना है।

59 अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें: नागेश्वरन, वी. एवं नटराजन, गुलजार. (2019), 'दा राइज ऑफ फाइनेंस: कॉजिस कॉनसिक्यूएनसिस एंड क्योर्स' कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज: सामाजिक दृष्टिकोण से वित्त का लाभ उठाना

2.86 बॉक्स II.4 में सामाजिक-विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक धन जुटाने के साधन प्रदान करके वित्तपोषण अंतर को पाटने में सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) की भूमिका पर चर्चा की गई है।

बॉक्स II.4: भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज: प्रगति कर रहे हैं

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय प्रतिभूति बाजारों की विशेषता रही है कि उन्होंने वित्त में खुदरा उपस्थिति बढ़ाने, नए तरीके से धन जुटाने और स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की विनियामक कढ़ी जांच में महत्वपूर्ण प्रगति की है। सामाजिक भलाई के लिए इक्विटी बाजारों की इस पारदर्शिता और कठोरता का लाभ उठाने के लिए, केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2020 में, सरकार ने सामाजिक कल्याण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करने वाले सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए सेबी के विनियामक दायरे में एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) बनाने की दिशा में कदम उठाने का प्रस्ताव रखा, ताकि वे भारत में इक्विटी, ऋण के रूप में पूंजी जुटा सकें।

सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता: एसएसई का उद्देश्य सामाजिक-विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक निधि-उगाहने के साधन प्रदान करके वित्तपोषण अंतर को पाटना है। एसएसई मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज का एक अलग खंड है, जो गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) जैसे सामाजिक उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से जनता से धन जुटाने में मदद कर सकता है। इस तरह, एसएसई से पारदर्शी और विनियमित वातावरण में भारत में परिणाम-संचालित लोक कल्याण के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। एसएसई स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका सृजन आदि से संबंधित सामाजिक परियोजनाओं के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और अन्य उद्यमों के रचनात्मक जुड़ाव के लिए एक मंच भी प्रदान करता है, ताकि वे सीधे निजी क्षेत्र, कॉर्पोरेट संस्थाओं और व्यक्तियों (उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों (एचएनआई) सहित) से धन जुटा सकें और विकास लक्ष्यों में योगदान दे सकें। सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेशों के लिए बढ़ती वैश्विक भूख के साथ, एसएसई इस अंतर को पाटता है और विभिन्न सामाजिक कल्याण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूंजीगत बाजारों को जनता के करीब लाता है।

एसएसई का संचालन: एसएसई पर सूचीबद्ध सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए योगदान एक अनूठी सुरक्षा के माध्यम से किया जाता है, जिसे जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल (जेडसीजेडपी) साधन के रूप में जाना जाता है क्योंकि फंडिंग की प्रकृति दान के समान होती है और इस तरह, कूपन के भुगतान या मूल राशि की वापसी का वादा नहीं करती है। इस पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए, सरकार ने हाल ही में एसएसई पर जेडसीजेडपी के माध्यम से किए गए योगदान के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के तहत कर छूट को बढ़ा दिया है। एसएसई की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इस मंच पर धन उगाहना पात्र एनपीओ द्वारा शुरू की गई विशिष्ट परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। इन एनपीओ को अपनी वर्ष-वार उपलब्धियां घोषित करने का आदेश दिया गया है, जिन्हें जनता से जुटाए गए धन से हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में, सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकता विनियम, 2018) व्यापक गतिविधियों की पहचान करना है जिनके लिए ये संस्थागत परियोजनाएं शुरू में जा सकती है, जैसे कि भूख, गरीबी, कुपोषण और असमानता का उन्मूलन; स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए आजीविका को बढ़ावा देना; आपदा प्रबंधन; तथा पर्यावरणीय स्थिरता आदि।

एसएसई पर सूचीबद्ध होने के लिए, एनजीओ/एनपीओ को अपनी पिछली सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का खुलासा करना होगा, जिसमें सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सिद्ध विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई हो। पात्रता मानदंड के रूप में, विनियामक ढांचे के लिए आवश्यक है कि एनजीओ/एनपीओ के पास सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का कम से कम तीन वर्ष का क्षेत्र अनुभव हो। इसके अलावा, फंड जुटाने वालों की फंड प्रदाताओं के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, एसईई पर फंड जुटाने वाली

संस्थाओं को वित्तीय वर्ष के अंत से 90 दिनों के भीतर एक वार्षिक प्रभाव रिपोर्ट में अपने सामाजिक और पर्यावरणीय प्रदर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी का खुलासा करना होगा, जिसका सोशल ऑडिटर[60] द्वारा विधिवत ऑडिट किया गया हो। इस प्रकार, अपनी कठोरता, पारदर्शिता और जांच के माध्यम से, एसएसई प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करता है कि दान विश्वसनीय संस्थाओं तक पहुँचे, पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास पैदा करे और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसकी मापनीयता का मार्ग प्रशस्त करे।

अब तक की प्रगति: सेबी द्वारा एसएसई के लिए विनियामक ढांचे के रोलआउट के बाद, एनएसई और बीएसई ने एसएसई का एक अलग खंड स्थापित करने के लिए सेबी की सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त की। अप्रैल 2024 तक, 51 एनपीओ बीएसई पर पंजीकृत हैं, और 50 (11 नवीनीकरण के दौर से गुजर रहे हैं) एनएसई पर पंजीकृत हैं। नौ एनपीओ ने एसएसई पर कुल ₹12.4 करोड़ की राशि जुटाई है। ये परियोजनाएँ शिक्षा, आजीविका सृजन, कौशल विकास आदि में सामाजिक परियोजनाओं तक फैली हुई हैं।[61]

जीआईएफटी आईएफएससी: भारत में वैश्विक पूंजीगत प्रवाह के लिए एक प्रमुख प्रवेशद्वार के रूप में उभर रहा है

2.87 गुजरात के जीआईएफटी सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) को भारत के अंदर स्थित एक अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्राधिकार के रूप में स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना भारत-केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा व्यवसाय को ऑनशोर करने के साथ-साथ देश में और देश से बाहर वैश्विक पूंजीगत प्रवाह को चौनेलाइज करने के लिए एक पसंदीदा प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करने के दोहरे उद्देश्य से की गई है। पिछले कुछ वर्षों में, जीआईएफटी आईएफएससी ने इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत प्रगति की है। जीआईएफटी आईएफएससी पहल वैश्विक वित्तीय सेवा व्यवसाय को आकर्षित करने और धीरे-धीरे अंतर्राष्ट्रीय वित्त में वैश्विक नेता बनने के लिए गहन, साहसिक और महत्वाकांक्षी वित्तीय क्षेत्र सुधार करने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता का एक शानदार उदाहरण है।

2.88 एक विशिष्ट और यादगार वित्तीय क्षेत्राधिकार के रूप में आईएफएससी की विशिष्टता तीन मूलभूत कारकों से उत्पन्न होती है। सबसे पहले, आईएफएससी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक गैर-निवासी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है, जिसका अर्थ है कि आईएफएससी में स्थापित संस्थाएँ पूंजी नियंत्रण प्रतिबंधों से बाहर हैं और इसलिए, ग्यारह अधिसूचित विदेशी मुद्राओं में से किसी में भी व्यवसाय कर सकती हैं।[62] दूसरा, आईएफएससी को एक समर्पित और एकीकृत वित्तीय नियामक, अर्थात आईएफएससी (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण) के विनियामक दायरे में लाया गया है, जिसे संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। सरकार द्वारा किए गए इस विनियामक हस्तक्षेप ने वैश्विक निवेशकों और वित्तीय संस्थानों के बीच आईएफएससी के आकर्षण को काफी हद तक बढ़ा दिया है, क्योंकि अब उन्हें सभी अनुमोदनों और लाइसेंसों के लिए केवल एक प्राधिकरण से निपटना पड़ता है। तीसरा, लगातार केंद्रीय बजटों के माध्यम से, सरकार ने आईएफएससी के लिए एक अलग कर व्यवस्था प्रदान की है, जो अन्य प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्रों में उपलब्ध कराये जाने वाले कर के बराबर है। प्रतिस्पर्धी कर व्यवस्था ने यह सुनिश्चित किया है कि आईएफएससी से संचालित वित्तीय सेवा संस्थान नुकसान में न रहें। जीआईएफटी आईएफएससी में कुछ प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों को देखकर देश के वित्तीय उद्योग परिदृश्य को बदलने में जीआईएफटी आईएफएससी के योगदान को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।[63]

60 वित्तीय लेखा परीक्षक वित्तीय मामलों की स्थिति पर राय जारी करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वित्तीय विवरणों और लेन-देन का लेख करता है, जबकि सामाजिक लेखा परीक्षक संगठन द्वारा समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखता है, जिसमें पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक पहलू शामिल होते हैं। सेबी सामाजिक लेखा परीक्षक को भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान (आईसीएआई) के दायरे में एक स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) के साथ पंजीकृत व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है।

61 सेबी के अनुसार

62 अमेरिकी डॉलर (USD) यूरो (EUR) जापानी येन (JPY) यूके पाउंड स्टर्लिंग (GBP) कैनेडियन डॉलर (CAD) ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD) स्विस फ्रैंक (CHF) हांगकांग डॉलर (HKD) सिंगापुर डॉलर (SGD) यूएई दिरहम (AED)) रूसी रूबल (आरयूबी)

63 डेटा जीआईएफटी सिटी से लिया गया है

2.89 **बैंकिंग क्षेत्र:** जीआईएफटी आईएफएससी में बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र विदेशी और घरेलू बैंकों के स्वस्थ मिश्रण के साथ तेजी से विकसित हो रहा है, जो मुख्य रूप से बाहरी वाणिज्यिक उधार, व्यापार वित्त आदि के माध्यम से भारतीय कारपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की विदेशी मुद्रा उधार आवश्यकताओं को पूरा करता है। इन मदों के अंतर्गत पहले सिंगापुर, दुबई, हांगकांग आदि जैसे विदेशी वित्तीय केंद्रों से किए जाने वाले लेन-देन अब जीआईएफटी आईएफएससी से किए जा रहे हैं। मार्च 2024 तक, आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) की कुल संपत्ति का आकार 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, और आईबीयू द्वारा किए गए लेन-देन का संचयी मूल्य 795 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया।

2.90 **फंड उद्योग:** जीआईएफटी आईएफएससी में मजबूत फंड उद्योग का स्टार्ट-अप इकोसिस्टम सहित भारत में वैश्विक पूंजी प्रवाह को उत्प्रेरित करने में परिवर्तनकारी प्रभाव है। पिछले तीन वर्षों में, आईएफएससीए के साथ पंजीकृत फंड प्रबंधन संस्थाओं (एफएमई) और एआईएफ में तेजी से वृद्धि हुई है। मार्च 2024 तक, पंजीकृत संचयी एफएमई और फंड सितंबर 2022 तक 39 और 33 से बढ़कर मार्च 2024 तक क्रमशः 114 और 120 हो गए। पहले, भारत में निवेश के लिए अंतरराष्ट्रीय पूंजी की पूलिंग फंड (निजी इक्विटी) के माध्यम से संरचित की गई थी, उद्यम पूंजी, हेज फंड, आदि) अपतटीय क्षेत्राधिकार में स्थापित किए गए। अब, सक्षम नियमों, एक प्रतिस्पर्धी कर व्यवस्था और संचालन की लाभकारी लागत के साथ, ळप्थ्ञ प्थ्ैब् विदेशी और भारतीय फंड प्रबंधकों द्वारा वैश्विक पूंजी के पूलिंग के लिए एक पसंदीदा क्षेत्राधिकार के रूप में उभर रहा है।

2.91 **विमान और जहाज पट्टे और वित्तपोषण:** भारतीय विमानन उद्योग भारतीय एयरलाइनों द्वारा 1500 से अधिक विमानों के मजबूत ऑर्डर बुक और 2042 तक 2,200 से अधिक विमानों की अनुमानित मांग के साथ अभूतपूर्व वृद्धि के शिखर पर है, वर्तमान में, भारतीय एयरलाइनों द्वारा संचालित अधिकांश विमान अपतटीय पट्टेदारों से पट्टे पर लिए जाते हैं, जिनके पास प्रतिस्पर्धी पूंजीगत लागत तक पहुंच होती है। विमान पट्टे और वित्तपोषण व्यवसाय, विमानन मूल्य श्रृंखला में सबसे अधिक लाभदायक खंड, पूरी तरह से विदेशी अधिकार क्षेत्र में था। विमान पट्टे और वित्तपोषण व्यवसाय की अपार संभावनाओं को पहचानते हुए, आईएफएससी ने सक्षम पट्टे ढांचे की शुरुआत की, और सरकार ने कई कर प्रोत्साहन प्रदान करके इस प्रयास का समर्थन किया। तीन वर्षों में, आईएफएससी में वृद्धि दिखाई देने लगी है, 28 से अधिक विमान पट्टेदार पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं, जिन्होंने वाणिज्यिक विमान, हेलीकॉप्टर, विमान इंजन और ग्राउंड सपोर्ट उपकरण सहित 120 से अधिक विमानन परिसंपत्तियों को पट्टे पर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि एयर इंडिया ने आईएफएससी जोन से अपने वाइड-बॉडी विमानों को पट्टे पर देना भी शुरू कर दिया है।

2.92 समुद्री और शिपिंग उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, सरकार और आईएफएससीए ने गिफ्ट आईएफएससी में एक मजबूत जहाज पट्टे और वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रारंभिक फोकस उन भारतीय शिपिंग कंपनियों को वापस लाना है जो विदेशी अधिकार क्षेत्र से बाहर जहाजों को पट्टे पर/स्वामित्व में ले रही हैं। एक सक्षम नियामक ढांचे के साथ, जहाज पट्टे पर देने वाला पारिस्थितिकी तंत्र गति पकड़ रहा है। 31 मार्च 2024 तक, IFSCA के साथ पंजीकृत जहाज पट्टे पर देने वाली कंपनियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जो समुद्री व्यवसाय के लिए वित्तीय केंद्र की बढ़ती अपील को रेखांकित करती है। इसके अलावा, इन कंपनियों ने GIFT IFSC से चार संपत्तियां हासिल की हैं और पट्टे पर दी हैं। आगे बढ़ते हुए, IFSCA एक जीवंत जहाज और विमान वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और परिसंपत्तियों के भारतीय स्वामित्व को बढ़ाने में योगदान देने के लिए IFSC बैंकिंग इकाइयों (IBU) के साथ काम करने का इरादा रखता है।

2.93 **विदेशी विश्वविद्यालयों की पहल:** आईएफएससी, एक अपतटीय क्षेत्राधिकार होने के नाते, भारत की प्रतिभा और जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के कारण भारत में उत्सुकता से खोज करने वाले शीर्ष गुणवत्ता वाले वैश्विक विश्वविद्यालयों को आकर्षित करके एक 'अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा केंद्र' बनने के लिए भी विशिष्ट रूप से स्थित है। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 23 में इस अवसर को रेखांकित किया, जिसमें कहा गया था कि 'विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को जीआईएफटी सिटी में वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में पाठ्यक्रम प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी, जो कि आईएफएससीए द्वारा वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी के

लिए उच्च-स्तरीय मानव संसाधनों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए घरेलू नियमों से मुक्त होंगे।' इस प्रयास में, आईएफएससीए ने वित्त वर्ष 24 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय आईएफएससी (अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर और अपतटीय शिक्षा केंद्र की स्थापना और संचालन) विनियमन, 2022 के तहत जीआईएफटी आईएफएससी में अपने अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर के लिए अंतिम पंजीकरण प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया। इसके अतिरिक्त, ऑस्ट्रेलिया का वोलोंगोंग विश्वविद्यालय जीआईएफटी आईएफएससी में अपने अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करने वाला दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय बन गया। जीआईएफटी आईएफएससी में दो विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश ने अन्य विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के लिए इस अवसर को देखने और एक शिक्षित और कुशल भारत के उदय में योगदान करने का मार्ग प्रशस्त किया है।

2.94 वित्तीय सेवाओं के विकास और विनियमन के दोहरे अधिदेश को प्राप्त करने की दिशा में आईएफएससी को एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कई सुधार चल रहे हैं। आईएफएससीए सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास तकनीक द्वारा समर्थित मजबूत विनियामक और पर्यवेक्षी प्रणालियों को लागू करने की प्रक्रिया में है। केंद्रीय बजट एफवाई 24 में की गई घोषणाएँ, जैसे पंजीकरण के लिए एकल खिड़की आईटी प्रणाली और दोहरे विनियमन से बचने के लिए आईएफएससीए को एसईजेड अधिनियम के तहत शक्तियाँ सौंपना, व्यापार करने में आसानी को बढ़ाएगा। आईएफएससी के देश में और देश से बाहर वैश्विक पूंजी प्रवाह के लिए एक पसंदीदा प्रवेश द्वार के रूप में उभरने की उम्मीद है।

बीमा क्षेत्र में विकास

वैश्विक बीमा बाजारों में नरमी

2.95 वैश्विक आर्थिक मंदी और मुद्रास्फीति ने बीमा कंपनियों के लिए चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। अधिक मजबूत निवेश लाभ के साथ पूंजी की लागत बढ़ रही है। उच्च मुद्रास्फीति और कोविड-19 महामारी के वर्तमान और हाल के उतार-चढ़ाव के कारण अनुकूल विकास की लंबी अवधि के क्षीण होने के कारण रिजर्व पर्याप्तता एक महत्वपूर्ण विचार के रूप में उभरी है। एक बड़ा बफर होने के बावजूद, उद्योग रिजर्व रिलीज की गति धीमी हो गई है। मौजूदा माहौल में, कई अनिश्चितताएँ व्याप्त हैं, जैसे कि विलंबित निपटान, जो उच्च आर्थिक और सामाजिक मुद्रास्फीति की अवधि में एक अधिक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में उभरता है। वस्तुओं से सेवाओं की ओर मुद्रास्फीति के बदलाव ने देयता जोखिमों को प्रभावित किया है। भविष्य में, मुद्रास्फीति के कम होने पर कम दावे और ब्याज दर-संवेदनशील निवेशों पर अधिक रिटर्न लाभप्रदता का समर्थन करने की उम्मीद है।

2.96 उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, वैश्विक बीमा बाजारों में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में संकुचन देखा गया है। विश्व बीमा वर्ष 2023 पर स्विस रे इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में कुल वैश्विक बीमा प्रीमियम[64] में वास्तविक रूप से 1.1 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि वर्ष 2021 में इसमें 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। हालांकि, गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में वर्ष 2022 में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, हालांकि यह वर्ष 2021 में दर्ज 2.6 प्रतिशत की वृद्धि से कम है, जो विकसित बाजारों में वाणिज्यिक लाइनों में दरों में सख्ती के कारण है। जीवन बीमा खंड में, वर्ष 2022 में वैश्विक प्रीमियम में 3.1 प्रतिशत की कमी आई, जबकि वर्ष 2021 में इसमें 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

भारत आने वाले दशक में सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक के रूप में उभरने के लिए तैयार है

2.97 आर्थिक विकास, मध्यम वर्ग का विस्तार, नवाचार और विनियामक सहायता ने भारत में बीमा बाजार की वृद्धि को गति दी है। वित्त वर्ष 23 में, प्रीमियम वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी कम हुई, जो कोविड-19 के बाद के युग में अभी भी प्रक्रियाधीन समायोजन को दर्शाती है। भारत में कुल बीमा निवेश[65] वित्त वर्ष 23 में थोड़ी कम होकर 4 प्रतिशत हो गई, जो वित्त वर्ष 22 में 4.2 प्रतिशत था। इसी अवधि के दौरान, जीवन बीमा खंड में बीमा निवेश वित्त वर्ष

64 स्विस री इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, विश्व बीमा बाजार 2023, https://t.ly/64ENQ

65 बीमा प्रवेश से तात्पर्य किसी विशेष वर्ष में लिखे गए बीमा प्रीमियम और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से है

22 में 3.2 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 23 में 3 प्रतिशत हो गया, जबकि गैर-जीवन बीमा खंड के लिए यह 1 प्रतिशत पर स्थिर रहा। कुल बीमा घनत्व[66] वित्त वर्ष 22 में 91 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 92 अमेरिकी डॉलर हो गया। जीवन बीमा खंड में, यह वित्त वर्ष 22 में 69 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 70 अमेरिकी डॉलर हो गया और गैर-जीवन बीमा खंड में स्थिर रहा।[67]

2.98 स्विस री इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट[68] के अनुसार, भारत में जीवन बीमा प्रीमियम की वृद्धि वित्त वर्ष 23 में 4.1 प्रतिशत (2012-2021 के दौरान 3.2 प्रतिशत के ऐतिहासिक औसत से अधिक) धीमी होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 22 में 5.9 प्रतिशत थी, क्योंकि महामारी की यादें (अर्थात जोखिम जागरूकता) कम हो गई हैं और हाई[69]-टिकट पॉलिसियों के लिए कर मानदंडों में हाल ही में हुए बदलाव ने नए प्रीमियम की वृद्धि को प्रभावित किया है। इन कारकों के कारण, वित्त वर्ष 22 की पहली तिमाही में 40 प्रतिशत की वृद्धि के बाद, नए व्यवसाय प्रीमियम चौथी तिमाही (7 प्रतिशत) में सिकुड़ गए। यह गति वित्त वर्ष 23 में भी जारी रही, जिसमें दूसरी तिमाही में नए व्यवसाय प्रीमियम में 21.2 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण समूह बीमा व्यवसाय में संकुचन था।

गैर-जीवन बीमा खंड की स्थिति

2.99 महामारी के बाद बाजार के स्थिर होने के कारण गैर-जीवन प्रीमियम वृद्धि वित्त वर्ष 22 में 9 प्रतिशत से थोड़ी कम होकर वित्त वर्ष 23 में अनुमानित 7.7 प्रतिशत हो गई (2012-2021 के दौरान 8 प्रतिशत के ऐतिहासिक औसत से कम)। महामारी के बाद उद्योग के स्थिर होने के कारण पिछले साल लगभग सभी प्रकार के व्यवसायों में वृद्धि धीमी हो गई। इस क्षेत्र को आर्थिक मंदी, उच्च ब्याज दरों और उच्च खुदरा और चिकित्सा मुद्रास्फीति जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

2.100 वित्त वर्ष 23 में दर्ज किए गए सेक्टर प्रीमियम में स्वास्थ्य का हिस्सा करीब 35 प्रतिशत है। प्रीमियम में 11 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के साथ, वित्त वर्ष 23 में सभी गैर-जीवन रेखाओं में स्वास्थ्य ने सबसे तेज वृद्धि देखी। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता, सहायक सरकारी नीतियाँ, बढ़ती चिकित्सा लागत और इंश्योरटेक में नवाचारों ने इस वृद्धि का समर्थन किया है। हालाँकि कीमत और आय की बाधाएँ निम्न आय समूहों के लिए माँग को सीमित कर सकती हैं, लेकिन मध्यम वर्ग का विस्तार और विवेकाधीन खर्च में वृद्धि से समग्र वृद्धि को समर्थन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, कम आय वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) और राज्य सरकार की विस्तार योजनाएँ लागू हैं। हाल ही में, बी-पीएमजेएवाई ने पूरे भारत में 34.2 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का मुकाम हासिल किया, जिनमें से 49.3 प्रतिशत कार्डधारक महिलाएं हैं। मध्यम अवधि में, बीमा के आकर्षण को बेहतर बनाने के लिए नियामक पहलों से कुछ सहायता मिलने के साथ, 2024-28 में स्वास्थ्य प्रीमियम में सालाना 9.7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

2.101 कृषि बीमा एक अन्य व्यवसाय है, जो गैर-जीवन बीमा बाजार का लगभग 12 प्रतिशत है। खरीफ फसल सीजन में प्रीमियम दरों में भारी गिरावट के कारण वित्त वर्ष 23 में कृषि बीमा में एकसमान वृद्धि दर्ज होने का अनुमान है। इस गिरावट की भरपाई मौसम के दौरान बीमित भूमि क्षेत्र और किसानों के नामांकन में वृद्धि से हुई। वर्ष 2024 के बाद से कृषि प्रीमियम में वृद्धि होने की संभावना है, जिसमें मध्यम अवधि में 2.5 प्रतिशत की औसत वास्तविक प्रीमियम वृद्धि होगी, जिसे फसल हानि की निगरानी के लिए मोबाइल एप्लिकेशन और रिमोट सेंसिंग जैसे बीमा अवसंरचना में सुधार द्वारा समर्थित किया जाएगा। सरकार ने फसल बीमा से जुड़ी मौजूदा चिंताओं को दूर करने के लिए कई पहल शुरू की हैं। इनमें उपग्रह आधारित उन्नत तकनीकों के माध्यम से फसल क्षति का आकलन करने के लिए वाईएस-टेक मैनुअल, डब्ल्यूआईएनडीएस पोर्टल और नामांकन ऐप एआईडीई/सहायक जैसी नई तकनीकी पहलों की शुरुआत और घर-घर जाकर नामांकन पहल के साथ कवर को और अधिक सुलभ बनाना शामिल है।

66 बीमा घनत्व से तात्पर्य जनसंख्या के प्रति बीमा प्रीमियम के अनुपात से है, अर्थात प्रति व्यक्ति बीमा प्रीमियम और इसे अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है।

67 स्विस री इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, 'भारत का बीमा बाजार: लचीलापन बनाने की पर्याप्त गुंजाइश के साथ तेजी से बढ़ रहा है', https://t.ly/tagPh

68 वही

69 इस विनियमन के तहत, 5 लाख रुपये से अधिक वार्षिक प्रीमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त कोई भी आय कराधान के अधीन है। परिणामस्वरूप, आयकर अधिनियम की धारा 10(10), जो पहले छूट प्रदान करती थी, अब इस सीमा से अधिक प्रीमियम वाली पॉलिसियों पर लागू नहीं होती है।

2.102 सरकार और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने उद्योग के विकास को सहायता देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है नवंबर 2022 में शुरू किया गया मिशन "2047 तक सभी के लिए बीमा", ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक नागरिक और उद्यम के पास उचित बीमा कवर/समाधान हो। बीमा पैठ बढ़ाने के लिए तीन प्रमुख पहल, बीमा सुगम[70], बीमा वाहक[71] और बीमा वाहक[72] एक महिला-केंद्रित बीमा वितरण चौनल है और बीमा विस्तार शुरू की गई हैं, खासकर अर्ध-शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण कस्बों और गांवों में।

2.103 आईआरडीएआई ने भारत को वैश्विक पुनर्बीमा केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए पुनर्बीमा विनियमों में संशोधन को मंजूरी दी। मूलभूत परिवर्तनों में विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं (एफआरबी) की न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को 12.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटाकर 6.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर करना और भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा पुनर्बीमाकर्ताओं को रियायत के लिए विनियामक के वरीयता क्रम को छह स्तरों से चार तक सुव्यवस्थित करना शामिल है। पुनर्बीमा प्रारूपों को सरल बनाया गया है, और बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों (आईआईओ) के ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के नियमों के साथ जोड़ा गया है।

2.104 एक व्यापक विनियामक समीक्षा की गई है, जिसमें नियम-आधारित दृष्टिकोण से सिद्धांत-आधारित वास्तुकला में परिवर्तन करते हुए एक तन्यक और मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया गया है। परिचालन को सुव्यवस्थित करते हुए, 167 परिपत्रों और 82 लाभ को निरस्त कर दिया गया है, जबकि 78 विनियमों को संशोधित, समेकित और घटाकर 28 कर दिया गया है। बीमा उत्पादों के लिए विनियामक मंजूरी प्रक्रियाओं को भी 'फाइल और उपयोग' व्यवस्था के तहत पूर्व अनुमोदन की पूर्ववर्ती आवश्यकता से बदल दिया गया है, जिसमें सामान्य और स्वास्थ्य बीमा के तहत सभी उत्पादों और अधिकांश जीवन बीमा उत्पादों के लिए श्उपयोग और फाइलश प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है, जो बीमाकर्ताओं को बाजार की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए उत्पादों को जल्दी से लॉन्च करने की सुविधा प्रदान करता है।

2.105 सभी खंडों के अंतर्गत उत्पाद पेशकशों के लिए विभिन्न विनियामक शर्तें भी हटा दी गई हैं, जिसमें स्वास्थ्य बीमा खंड पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि ग्राहकों को बेहतर कवरेज और विकल्प प्रदान किया जा सके। इसके अलावा, पॉलिसीधारकों को उनके बीमा कवरेज की गहन समझ प्रदान करने के लिए, सभी प्रकार की बीमा पॉलिसियों के लिए पॉलिसीधारकों को संक्षिप्त ग्राहक सूचना पत्र (सीआईएस) जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है।

2.106 इसके अलावा, उद्योग को भविष्य के लिए तैयार करने और वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करने के लिए, जोखिम-आधारित पर्यवेक्षी ढांचे (आरबीएसएफ), जोखिम-आधारित पूंजीगत ढांचे (आरबीसी) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आईआरडीएआई राज्य बीमा योजनाओं के माध्यम से बीमा कंपनियों और राज्य सरकारों के बीच समन्वित प्रयासों की सुविधा प्रदान करता है ताकि बीमा सेवाओं को देश के अंतिम छोर और यहां तक कि सबसे दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाया जा सके।

2.107 इन सुधारों और सतत आर्थिक वृद्धि से बीमा क्षेत्र के निरंतर विकास और उन्नति में मदद मिलने की उम्मीद है, जिसे मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते मध्यम वर्ग, नवाचार और मजबूत नीतिगत सहायता से समर्थन मिलेगा। भारतीय बीमा बाजार के लिए अनुकूल अनुमान हैं। स्विस-री इंस्टीट्यूट की जनवरी 2024 की रिपोर्ट[73] में अनुमान लगाया गया है कि अगले पांच वर्षों (2024-28) में भारत में कुल बीमा प्रीमियम वास्तविक रूप से 7.1 प्रतिशत बढ़ेगा, जो वैश्विक (2.4 प्रतिशत), उभरती अर्थव्यवस्थाओं (5.1 प्रतिशत) और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (1.7 प्रतिशत) के बाजार औसत से काफी अधिक है। इस दर पर, भारत में जी20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बीमा क्षेत्र होगा। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बीमा निवेश वित्त वर्ष 23 में 3.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 35 तक 4.3 प्रतिशत होने का

70 "बीमा सुगम" एक ऑनलाइन पोर्टल है जो बीमा खरीदने, पोर्टेबिलिटी सुविधाओं, बीमा एजेंटों को बदलने की क्षमता और बीमाकर्ताओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से जीवन, मोटर और स्वास्थ्य दावों के निपटान की सुविधा प्रदान करता है।

71 "बीमा वाहक" एक महिला-केंद्रित बीमा वितरण चौनल है

72 'बीमा विस्तार' एक सामाजिक सुरक्षा जाल है जो बीमा सुगम मंच के माध्यम से सभी के लिए सुलभ है

73 https://tinyurl.com/mryvwj9m

अनुमान है। जीवन व्यवसाय में वृद्धि (2024-28 में प्रीमियम में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि) मध्यम वर्ग द्वारा टर्म लाइफ कवर की बढ़ती मांग, देश की युवा आबादी और इंश्योरटेक को उद्योग द्वारा अपनाए जाने से समर्थित होने की संभावना है। आर्थिक विकास, वितरण चैनलों में सुधार, सरकारी सहायता और अनुकूल विनियामक वातावरण के कारण गैर-जीवन प्रीमियम में 2024-28 के दौरान वार्षिक औसत 8.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। इसके अलावा, अगले दशक (2024-34) में कुल प्रीमियम दोगुने से अधिक (मुद्रास्फीति-समायोजित) होने की उम्मीद है, और बीमा प्रवेश वर्तमान 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 2034 में 4.5 प्रतिशत हो जाएगा।

2.108 बीमा निवेश में अपेक्षित वृद्धि को साकार करने के लिए, उद्योग को अधिक ग्राहक-अनुकूल बनना होगा। वित्त वर्ष 23 के लिए आईआरडीएआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार[74], केंद्रीकृत शिकायत पोर्टल को वर्ष के दौरान दो लाख से अधिक शिकायतें मिलीं। यदि हम भारतीय जीवन बीमा निगम को छोड़ दें, तो जीवन बीमा कंपनियों के खिलाफ 50 प्रतिशत से अधिक शिकायतें अनुचित व्यावसायिक कार्यप्रणालियों के बारे में थीं, जो गलत बिक्री के लिए एक व्यंजना है। इसके अलावा, सामान्य बीमा कंपनियों के खिलाफ 66 प्रतिशत शिकायतें दावों के बारे में थीं, जिसमें विलंबित और अस्वीकृत निपटान शामिल थे। उद्योग को लंबी अवधि के लिए सोचना और काम करना होगा। बीमा निवेश नहीं बढ़ेगी। वित्त वर्ष 23 के आंकड़ों से बीमा निवेश में गिरावट देखी गई। जब वित्तीय उत्पादों की बात आती है, तो वैश्विक स्तर पर, श्सॉफ्ट-टचश विनियमन ग्राहक संतुष्टि और पैसे के लिए मूल्य[75] प्रदान करने में निरंतर अवधि में शायद ही कभी काम करते हैं। वैश्विक स्तर पर, निजी वित्तीय क्षेत्र ने बार-बार खुद को अपने लाभ के लिए सिद्धांत-आधारित विनियमों की चुनिंदा या गलत व्याख्या करने में माहिर दिखाया है।

पेंशन क्षेत्र में विकास

2.109 अधिकांश देशों की जनसांख्यिकीय संरचना में काफी बदलाव आ रहा है क्योंकि जन्म दर में गिरावट जारी है। इस विकास का पे-एज-यू-गो पेंशन व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो पिछली पीढ़ियों को प्रदत्त पेंशन को निधि देने के लिए करदाताओं की अगली पीढ़ी पर निर्भर करता है। हाल के दिनों में, मुद्रास्फीति के फिर से उभरने से भी समुदाय के इस विश्वास को नुकसान पहुंचा है कि पेंशन कार्यक्रम लंबी अवधि में पर्याप्त सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। हालाँकि कुछ अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में कमी आई है, लेकिन इसके बने रहने से वर्तमान और भविष्य के सेवानिवृत्त लोगों के लिए यह जोखिम उजागर हुआ है। साथ ही, परिभाषित लाभ से परिभाषित योगदान व्यवस्था की ओर वैश्विक बदलाव जारी है, जिसमें व्यक्ति निवेश लाभ, मुद्रास्फीति और अक्सर, दीर्घायु से संबंधित सभी जोखिम उठाते हैं। बहुत कम प्रणालियों ने व्यक्ति-आधारित डीसी संचय प्रणाली से सेवानिवृत्ति के बाद की प्रणाली में जाने की दुविधा को हल किया है जो सेवानिवृत्त लोगों को पर्याप्त और सुरक्षित आय प्रदान करते हुए उन्हें उनके कार्य वर्षों के दौरान उपलब्ध समान लचीलापन प्रदान करती है।

2.110 कई पेंशन प्रणालियों के सामने एक चुनौती यह है कि गिग वर्कर्स और अनौपचारिक श्रम बाजार में शामिल लोगों को शामिल किया जाए। कई अर्थव्यवस्थाओं में, श्रम बाजार में दरार पड़ रही है; इसलिए, स्थिर या संरचित नियोक्ता-कर्मचारी संबंध गायब हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में, पेंशन व्यवस्था को अधिक व्यक्तिगत रूप से केंद्रित और तीसरे पक्ष पर कम निर्भर होना चाहिए।[76]

भारत के पेंशन क्षेत्र का प्रदर्शन

2.111 15वें वार्षिक मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स (एमसीजीपीआई)[77] के अनुसार, भारत का समग्र वैश्विक पेंशन सूचकांक मूल्य 2022 के 44.5 से बढ़कर 2023 में 45.9 हो गया, जिसका मुख्य कारण पर्याप्तता और

74 https://tinyurl.com/98vs72dc

75 'बीमा उद्योग को नियामकीय बदलाव की जरूरत है', बिजनेस लाइन, 10 फरवरी 2024 (https://www.thehindubusinessline.com/opinion/insurance-industry-needs-a-regulatory-shake-up/article67829954.ece)

76 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 'दुनिया भर में गैर-मानक रोजगार: चुनौतियों को समझना, संभावनाओं को आकार देना', https://tinyurl.com/3uah4a4n

77 मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स दुनिया भर में 47 रिटायरमेंट आय प्रणालियों का मूल्यांकन करता है, जिसमें प्रत्येक के भीतर चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डाला जाता है। यह सूचकांक तीन उप-सूचकांकों, पर्याप्तता, स्थिरता और अखंडता से बना है जो प्रत्येक रिटायरमेंट आय प्रणाली को 50 से अधिक संकेतकों के आधार पर मापता है

स्थिरता उप-सूचकांक में सुधार है। भारत की पेंशन प्रणाली में आय-संबंधित कर्मचारी पेंशन योजना, एक निर्धारित अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और पूरक नियोक्ता-प्रबंधित पेंशन योजनाएं शामिल हैं जो अनिवार्य रूप से निर्धारित अंशदान के माध्यम से हैं। सरकार ने असंगठित क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। कार्यबल की गतिशीलता, रोजगार और पारिवारिक पैटर्न में बदलाव ने सेवानिवृत्ति के औपचारिक स्रोतों को सामने ला दिया है। जबकि निवल पेंशन प्रतिस्थापन दर और निजी पेंशन योजनाओं में भागीदारी में सुधार हुआ है, जो पर्याप्ता और सधारणीयता उप-सूचकांकों के मूल्य में परिलक्षित होता है, निजी पेंशन योजनाओं के तहत भारतीय कार्यबल का कवरेज अभी बढ़ाया[78] जाना है। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लाभ के लिए सर्वभौतिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के भाग के रूप में विभिन्न योजनाएं आरंभ की है।

2.112 राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) और हाल ही में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत के बाद से भारत के पेंशन क्षेत्र का विस्तार हुआ है। मार्च 2024 तक कुल ग्राहकों की संख्या 735.6 लाख थी, जो मार्च 2023 तक 623.6 लाख से 18 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करती है। संख्या के लिहाज से, इसमें एपीवाई का दबदबा है। एपीवाई ग्राहकों (इसके पुराने संस्करण, एनपीएस लाइट सहित) की कुल संख्या मार्च 2023 तक 501.2 लाख से बढ़कर मार्च 2024 तक 588.4 लाख हो गई। एपीवाई ग्राहक पेंशन ग्राहक आधार का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा हैं।[79]

2.113 पेंशन फंड विनियामक प्राधिकरण (पीएफआरडीए) कि अलग-अलग डेटा से पता चलता है कि एपीवाई ग्राहकों ने जेंडर मिक्स में सुधार देखा है, जिसमें महिला ग्राहकों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 17 में 37.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 48.5 प्रतिशत हो गई है। 18-25 आयु वर्ग के युवा समूह के पक्ष में आयु मिश्रण भी बढ़ रहा है, जो वित्त वर्ष 17 में 35 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 46.7 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, एपीवाई खातों का बड़ा हिस्सा, लगभग 92 प्रतिशत, ₹1,000 प्रति माह की पेंशन राशि के लिए था, इसके बाद 4.7 प्रतिशत ₹5,000 के लिए थे, और शेष 3 प्रतिशत बीच में थे। एपीवाई में ₹1,000 पेंशन का भारी हिस्सा कई कारकों के कारण हो सकता है, प्रमुख कारण यह है कि लक्षित आबादी निम्न आय वाले परिवार हैं, जहां दिन-प्रतिदिन के उपभोग व्यय को बचत[80] पर प्राथमिकता दी जाती है।

2.114 इन दो योजनाओं (एनपीएस और एपीवाई) के तहत कुल आबादी के हिस्से के रूप में आबादी की पेंशन कवरेज वित्त वर्ष 17 में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 5.3 प्रतिशत हो गई है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में एयूएम वित्त वर्ष 17 में 1.1 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 4 प्रतिशत हो गया है।

पेंशन क्षेत्र के लिए संभावना

2.115 भविष्य में, एनपीएस (निजी क्षेत्र) का तेजी से विस्तार होने की संभावना है क्योंकि कारपोरेट कर्मचारियों और अपेक्षाकृत बेहतर परिवारों की बढ़ती संख्या, उदाहरण के लिए, स्व-रोजगार और पेशेवर जैसे डॉक्टर, वकील और छोटे व्यवसाय के मालिक, एनपीएस में शामिल होने के लाभ को देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े किसानों, व्यापारियों और एकमुश्त आय वाले लोगों के लिए एनपीएस की संभावना है, क्योंकि एनपीएस के लिए मानक मासिक योगदान की आवश्यकता नहीं होती है।

2.116 भारत की प्रति व्यक्ति आय में और वृद्धि होने तथा उच्च-मध्यम आय वाले देश में तब्दील होने के कारण विकास की अपार संभावनाएं हैं। भारत की जनसांख्यिकी संरचना, जिसमें युवा लोगों का अनुपात अधिक है, संचय के चरण का पक्षधर है। चूंकि जीवन प्रत्याशा धीरे-धीरे बढ़ रही है, इसलिए वृद्धावस्था में गरीबी को कम करने के लिए एक स्थिर आय स्रोत की आवश्यकता भी बढ़ रही है। इसके अलावा, जैसे-जैसे बढ़ते शहरीकरण के साथ पारंपरिक पारिवारिक सहायता प्रणाली बदलती है, वृद्धावस्था में आय के एक स्वतंत्र स्रोत की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है।

2.117 औपचारिक वित्तीय क्षेत्र का लाभ उठाने के लिए लोगों के लिए वित्तीय साक्षरता आवश्यक हो जाती है। पेंशन साक्षरता के कई पहलू हैं; परिवार में महिलाओं के पास उनकी लंबी आयु को देखते हुए पेंशन खाता होना चाहिए; युवा

78 15वीं वार्षिक एमसीजीपीआई के अनुसार, वर्तमान में भारतीय कार्यबल का 6 प्रतिशत हिस्सा निजी पेंशन योजनाओं के अंतर्गत आता है।
79 https://www.pfrda.org.in
80 पीएफआरडीए का मासिक पेंशन बुलेटिन, https://www.pfrda.org.in

वयस्कों, विशेष रूप से छात्रों को पेंशन खाते के साथ सशक्त बनाना समझदारी है ताकि वे दीर्घकालिक बचत के वित्तीय अनुशासन को आत्मसात कर सकें।

2.118 वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण तभी पूरा होगा जब परिवार के प्रत्येक सदस्य का पेंशन खाता होगा। इस दिशा में, पेंशन उत्पाद की प्रकृति को देखते हुए, जहाँ भुगतान तत्काल नहीं होता है, सभी संबंधित पक्षों, नियोक्ताओं, मध्यवर्ती संस्थाएं, सरकार और पेंशन नियामक को लोगों, विशेष रूप से युवा वयस्कों को पेंशन योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। इसमें शामिल होने का बहुत फायदा है क्योंकि छोटे-छोटे योगदानों से, चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के कारण एक बड़ी राशि जमा की जा सकती है, जो किसी व्यक्ति के काम के बाद के जीवन में पर्याप्त स्थिर आय प्रदान करती है।

विनियामक समन्वय और समग्र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र

2.119 वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सतत आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए सर्वोपरि है। वित्तीय रूप से स्थिर प्रणाली को वृहट आर्थिक गड़बड़ी के प्रति मजबूत होना चाहिए। इसे अप्रत्याशित झटकों का सामना करना चाहिए ताकि इस बात का अत्यधिक विश्वास हो कि यह अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करना जारी रखेगी। वित्तीय स्थिरता का अर्थ न केवल वास्तविक संकट की अनुपस्थिति है, बल्कि असंतुलन को सीमित करने और प्रबंधित करने की प्रणाली की क्षमता भी है, इससे पहले कि वे उस परिमाण को ग्रहण करें जो स्वयं या आर्थिक प्रक्रियाओं को खतरे में डालता है।

2.120 वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में सरकार की भूमिका बहुआयामी और महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की सरकारें वित्तीय क्षेत्र की अखंडता और सुचारू कामकाज की रक्षा के लिए विभिन्न नीतियों, विनियमों और उपायों को लागू करती हैं। यह आकलन करना भी आवश्यक होगा कि वित्तीय अस्थिरता और वास्तविक अर्थव्यवस्था के बीच कैसे तालमेल स्थापित होता है ताकि शुरुआती झटकों के प्रभावों को बढ़ाया या कम किया जा सके। इस प्रकार, विभिन्न वित्तीय संस्थानों की निगरानी के लिए जिम्मेदार नियामकों को आपस में और कीमतों और वास्तविक अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ निकटता से बातचीत और सहयोग करना चाहिए।

2.121 भारतीय संदर्भ में, एफएसडीसी[81] एक ऐसा मंच है जो विभिन्न वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के बीच बातचीत को सुगम बनाता है। एफएसडीसी को वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर-विनियामक समन्वय, वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन, अर्थव्यवस्था के मैक्रो-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण, जिसमें बड़े वित्तीय समूहों का कामकाज शामिल है, वित्तीय क्षेत्र के निकायों (जैसे वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ), वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय इंटरफेस का समन्वय और किसी सदस्य/अध्यक्ष द्वारा संदर्भित और परिषद द्वारा विवेकपूर्ण माने जाने वाले वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और विकास से संबंधित किसी भी अन्य मामले से संबंधित व्यापक मुद्दों से निपटने का अधिकार है।

2.122 आरबीआई गवर्नर एफएसडीसी उप-समिति (एफएसडीसी-एससी) बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं, जो एफएसडीसी-एससी के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तावित एजेंडा मदों के साथ-साथ आवश्यक सहायक कार्यों पर विचार-विमर्श करते हैं। आरबीआई वित्तीय संस्थानों को विनियमित करके, प्रणालीगत जोखिमों की निगरानी करके और मौद्रिक नीति को लागू करके वित्तीय क्षेत्र की तन्यकटा को बढ़ावा देता है। वित्तीय स्थिरता और भारतीय वित्तीय प्रणाली की मजबूती के लिए जोखिमों का सामूहिक मूल्यांकन किया जाता है और मार्च 2010 से आरबीआई द्वारा प्रकाशित द्वि-वार्षिक वित्तीय[82] स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में इसकी रिपोर्ट दी जाती है।

भारत के लिए वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी)

2.123 एफएसएपी 'प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण' वित्तीय क्षेत्रों वाले देशों में आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप

81 वित्त मंत्री एफएसडीसी की अध्यक्षता करते हैं। इसके सदस्य हैं वित्त राज्य मंत्री, अन्य सभी वित्तीय क्षेत्र विनियामक निकायों (जैसे, आरबीआई, एसईबीआई, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, आईएफएससीए) के प्रमुख, (i) आर्थिक कार्य, (ii) व्यय, (iii) वित्तीय सेवाएँ, (iv) राजस्व, (v) कारपोरेट कार्य के मंत्रालय और (vi) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभागों के सचिव और वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य के विभाग का वित्तीय स्थिरता और साइबर सुरक्षा प्रभाग परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है, और प्रभाग का प्रभाग प्रमुख परिषद का सदस्य सचिव होता है।

82 आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2023, https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails-aspx?UrlPage=&ID-1248

से आयोजित एक पंचवार्षिक अभ्यास है। एफएसएपी में वित्तीय स्थिरता और वित्तीय क्षेत्र के विकास का आकलन करने के लिए देश के वित्तीय उद्योग का व्यापक और गहन विश्लेषण शामिल है। भारत ने अपना पहला एफएसएपी अभ्यास 2011-12 में और दूसरा 2017 में किया, जिसके बाद आईएमएफ-विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें वित्तीय प्रणाली स्थिरता आकलन रिपोर्ट (एफएसएसए) और वित्तीय क्षेत्र आकलन (एफएसए) रिपोर्ट शामिल थी। भारत के लिए तीसरा एफएसएपी अभ्यास 2023-24 के लिए चल रहा है। एफएसएसए और एफएसए रिपोर्ट फरवरी 2025 तक प्रकाशित की जाएंगी। एफएसबी जी20 वित्तीय नियामक सुधारों के कार्यान्वयन और प्रभावों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट[83] प्रकाशित करता है, जिसमें विभिन्न न्यायालयों में कार्यान्वयन की स्थिति का उल्लेख होता है। रिपोर्ट में रंग-कोडित टेम्पलेट एफएसबी सिद्धांतों और मानकों के क्षेत्रीय कार्यान्वयन की सीमा पर प्रकाश डालता है। निगरानी किए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में (i) बेसल-प्प्प् सुधार, (ii) मुआवजा, (iii) ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव, (iv) रिजॉल्यूशन, और (v) गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थता (एनबीएफआई) शामिल हैं।

2.124 बेसल III[84] सुधारों के कार्यान्वयन ने घरेलू और वैश्विक बैंकिंग दोनों क्षेत्रों में लचीलेपन का समर्थन किया है। बेसल प्प्प् स्तंभ सुधारों के तहत, भारत काफी हद तक अनुपालन कर रहा है क्योंकि इसने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नेट स्थिर फंडिंग अनुपात, तरलता कवरेज अनुपात, व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के लिए आवश्यकताएं और बैंक के बड़े एक्सपोजर को मापने और नियंत्रित करने के लिए पर्यवेक्षी ढांचे के प्रावधान निर्धारित किए हैं। भारत बेसल प्प्प् के तहत अन्य दो आवश्यकताओं, यानी संशोधित उत्तोलन अनुपात आवश्यकताओं और जोखिम-आधारित पूंजी ढांचे को भी लागू करने की प्रक्रिया में है।

2.125 मुआवजे के स्तंभ के लिए, भारत में पहले से ही महत्वपूर्ण बैंकों, बीमाकर्ताओं और परिसंपत्ति प्रबंधकों के लिए ठोस मुआवजा प्रथाओं (सिद्धांत और मानक) के लिए मानक मौजूद हैं।

2.126 ओटीसी डेरिवेटिव खंड के तहत, भारत ने 2022 एफएसबी मूल्यांकन से 2023 में महत्वपूर्ण प्रगति की, क्योंकि 90 प्रतिशत से अधिक ओटीसी डेरिवेटिव अब एफएसबी सिद्धांतों के तहत व्यापार रिपोर्टिंग, केंद्रीय समाशोधन और प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग आवश्यकताओं का पालन करते हैं। ओटीसी स्तंभ के तहत चौथा पैरामीटर, यानी ओटीसी डेरिवेटिव से संबंधित मार्जिन आवश्यकताएं, वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन हैं।

2.127 एनबीएफआई की लचीलापन बढ़ाना एफएसबी की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, जो प्रमुख सुधार क्षेत्र के तहत मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, प्रतिभूतिकरण और सिक्योरिटीज फाइनेंसिंग लेनदेन (एसएफटी) आवश्यकताओं के तहत रखी गई है। संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए न्यूनतम नियामक मानकों, बैंक-से-गैर-बैंक लेनदेन पर संख्यात्मक हेयरकट फर्श आदि सहित एसएफटी आवश्यकताओं के कुल अनुपालन में एफएसबी द्वारा रिपोर्ट किए गए 24 में से भारत एकमात्र क्षेत्राधिकार है। भारत ने सक्रिय रूप से प्रतिभूतिकरण और एमएमएफ सुधार किए हैं। एफएसबी सिद्धांतों के अनुरूप।

वित्तीय प्रणाली दबाव सूचक

2.128 आरबीआई ने अपने एफसीआर[85] के 26वें अंक में भारतीय वित्तीय प्रणाली में समग्र दबाव स्तर की निगरानी के लिए वित्तीय प्रणाली तनाव संकेतक (एफएसएसआई)[86] नामक एक व्यापक संकेतक संकलित करने का प्रयास किया। एफएसएसआई का उद्देश्य (क) दबाव की अवधि की पहचान करने में मदद करना, (ख) वित्तीय प्रणाली में तनाव की

83 2023 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की वार्षिक रिपोर्ट, 11 अक्टूबर 2023, 'वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना', https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P111023.pdf

84 एफएसबी कार्यान्वयन को तीन प्रमुखों के अंतर्गत वर्गीकृत करता है जहां एक क्षेत्राधिकार ने अंतिम नियम प्रकाशित और कार्यान्वित किया है, नियम प्रकाशित किया है लेकिन लागू नहीं किया है और मसौदा विनियमन प्रकाशित नहीं किया है।

85 आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 26वां अंक, दिसंबर 2022, पृष्ठ 56, https://t.ly/o_CZb.

86 एफएसएस,आई में पाँच वित्तीय बाजार खंडों- इक्विटी, विदेशी मुद्रा, मुद्रा, सरकारी ऋण और कारपोरेट ऋण बाजारों और वित्तीय मध्यस्थ खंडों के तीन समूहों, अर्थात् बैंक, एनबीएफसी और एएमसी-एमएफ के बारे में जोखिम कारक शामिल हैं। इसमें एक वास्तविक क्षेत्र घटक भी शामिल है जिसमें चुनिंदा वास्तविक क्षेत्र चर शामिल हैं जिनका वित्तीय क्षेत्र के साथ उनके मजबूत अंतर्संबंधों के कारण वित्तीय स्थिरता पर असर पड़ता है। अधिक जानकारी के लिए, देखें: https://rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay-aspx?prid=57005

तीव्रता और अवधि का आकलन करना, और (ग) वित्तीय बाजारों और मध्यस्थों की झटकों और असंतुलनों को झेलने की क्षमता का आकलन करना है।

2.129 जून 2024 के नवीनतम एफएसआर से पता चलता है कि एफएसएसआई ने वित्त वर्ष 2024 की पहली दो तिमाहियों के दौरान भारतीय वित्तीय प्रणाली में संकट में कमी देखी। दबाव के स्तर में गिरावट वित्तीय बाजारों और वित्तीय संस्थानों में व्यापक आधार पर हुई है। एफएसएसआई में गिरावट में इक्विटी बाजार का प्रमुख योगदान रहा, जिसमें उच्च निवल विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह, बेहतर प्रदर्शन और कम निहित अस्थिरता देखी गई। सरकारी ऋण बाजार में संकट भी काफी कम हो गया है, जो प्रतिशत और अस्थिरता में गिरावट के कारण हुआ है। वाणिज्यिक पत्र (सीपी), जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और ट्रेजरी बिल दरों जैसे अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखतों की दरों के बीच अंतर कम होने से मुद्रा बाजार का संकट कम हो गया। विनिमय दर और अग्रिम प्रीमियम में कम अस्थिरता ने विदेशी मुद्रा बाजार में संकट को कम करने में योगदान दिया है। आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता में सुधार ने बैंकिंग और एनबीएफसी क्षेत्रों में संकट कम किया, जबकि बढ़ते म्यूचुअल फंड अंतर्वाह ने आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के बीच दबाव को कम करने में मदद की।

चार्ट II.15: भारतीय वित्तीय प्रणाली में तनाव में कमी एफएसएसआई में परिलक्षित हुई

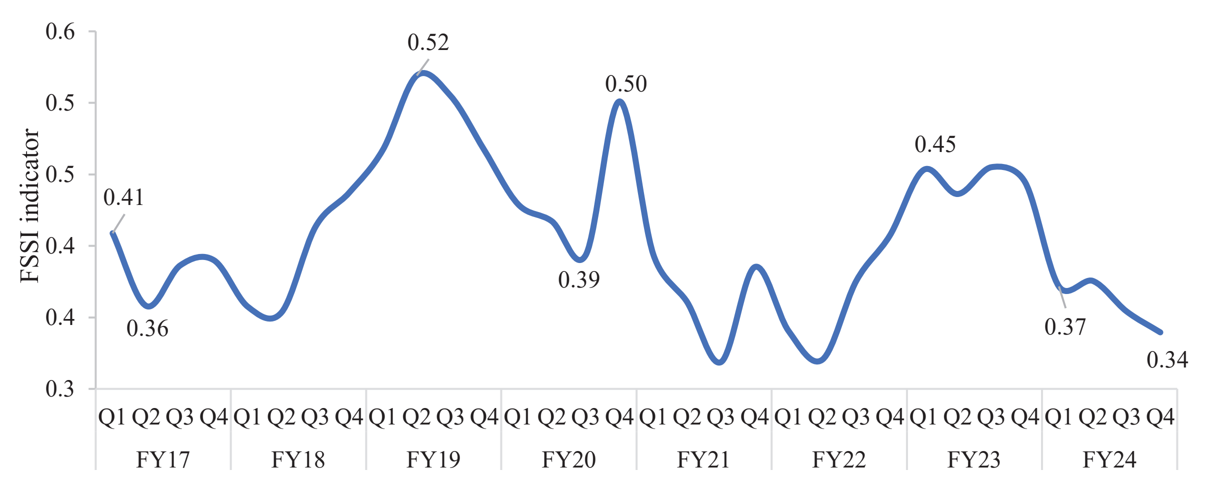

स्रोत: अध्याय I: मैक्रोफाइनेंशियल जोखिम, आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दिसंबर 2023

चार्ट II.16: वित्तीय क्षेत्रों में तनाव के स्तर में व्यापक गिरावट

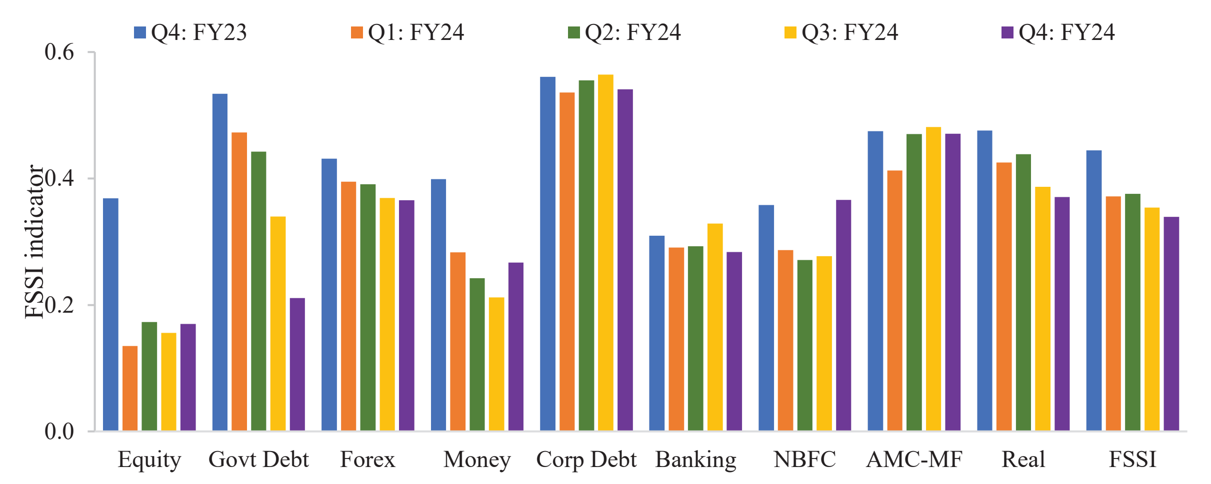

स्रोत: अध्याय I: मैक्रोफाइनेंशियल जोखिम, आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दिसंबर 2023

मूल्यांकन और दृष्टिकोण

2.130 अधिकांश मामलों में, भारत के वित्तीय उद्योग ने समय के साथ बहुत प्रगति की है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी क्षेत्र को घरेलू ऋण 2010 में 50.6 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 54.7 प्रतिशत हो गया। एससीबी के सकल और निवल एनपीए समय के साथ घट रहे हैं, साथ ही सीआरएआर, आरओए और आरओई में सुधार हुआ है। भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ने के बावजूद, भारत के शेयर बाजार स्थिर रहे हैं।

2.131 यहां तक कि जब बैंक, गैर-बैंक और कारपोरेट तुलन-पत्र की अधिकता, नई सहस्राब्दी के पहले दशक के क्रेडिट बूम और दूसरे दशक में उसके बाद आने वाली अपरिहार्य गिरावट के परिणामों से जूझ रहे थे, तब भी व्यापक उद्योग वित्तीय समावेशन और वित्तीय गहनता के कारण को आगे बढ़ाता रहा। चूंकि भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित देश बनने के विजन पर चल रहा है, इसलिए यह जरूरी है कि वैश्विक स्तर पर वित्तीय मध्यस्थता की लागत में कमी आए। भारत ने इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो कोविड के बाद की इसकी तन्यक आर्थिक रिकवरी का एक कारण हो सकता है। हालांकि, इसे वैश्विक वित्तीय अग्रणी बनाने के लिए अभी भी बहुत काम किया जा सकता है।

2.132 भारत के वित्तीय क्षेत्र का परिदृश्य उज्ज्वल दिखाई देता है। 2047 तक विकसित भारत का विजन वास्तव में समृद्ध समाज, मजबूत वित्तीय सेवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक वित्त और आर्थिक संप्रभुता के लिए एक अवसर है। एक मजबूत वित्तीय सेवा क्षेत्र के तत्वों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और व्यवहार्य बैंकिंग क्षेत्र, सभी नागरिकों के लिए बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, सबसे कम मध्यस्थता लागत, छोटे व्यवसायों के लिए ऋण और इक्विटी फंडिंग तक कुशल और त्वरित पहुंच, अत्यधिक तरल, कुशल और अच्छी तरह से विनियमित स्टॉक, बॉन्ड और कमोडिटी बाजार शामिल हैं। भारत के वित्तीय क्षेत्र को पूंजीगत निर्माण की सहायता करने और एमएसएमई में व्यापार, व्यवसाय और निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे उन्हें विस्तार करने में सक्षम बनाया जा सके। भारत की वित्तीय प्रणाली को सभी भारतीयों को बीमा सुरक्षा और सेवानिवृत्ति सुरक्षा प्रदान करने की भी आवश्यकता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में बीमा और पेंशन फंड आस्तियों की हिस्सेदारी क्रमशः 19 प्रतिशत और 5 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका में यह 52 प्रतिशत और 122 प्रतिशत और ब्रिटेन में 112 प्रतिशत और 80 प्रतिशत है।

2.133 आने वाले वर्षों में अगला बड़ा कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग (एआई/एमएल), विकेंद्रीकृत वित्त, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) आदि की ओर है, जिसमें डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करने की बहुत बड़ी क्षमता है। इसके अलावा, भारत को एक शफिनटेक राष्ट्रश के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें सबसे अधिक संख्या में फिनटेक फर्म होंगी और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना द्वारा संचालित मौजूदा कंपनियों द्वारा फिनटेक अपनाने की उच्चतम दर होगी। नियामकों में सामान्य उपयोगकर्ता डेटा, जैसे केवाईसी, के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए। मध्यम अवधि में, विशेष रूप से लघु उद्योग के लिए निर्णय-आधारित ऋण के बजाय डेटा आधारित ऋण की ओर बढ़ने के प्रयास किए जाने चाहिए, खासकर छोटे व्यवसायों के लिए। इस संबंध में, विनियामक अंतराल/अतिव्यापीताओं की पहचान करने और उन्हें सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के साथ बेंचमार्क करने के लिए निरंतर समीक्षा की आवश्यकता है। वित्तीय क्षेत्र की फर्में - सार्वजनिक या निजी स्वामित्व वाली - को ग्राहक-केंद्रित बनना चाहिए। इसके बिना, अधिकांश मात्रात्मक मीट्रिक परिहारकारी बने रहेंगे।

2.134 भारतीय वित्तीय क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ऋण के लिए बैंकिंग सहायता का प्रभुत्व कम हो रहा है, और पूंजीगत बाजारों की भूमिका बढ़ रही है। वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखने वाले देश के लिए, यह एक लंबे समय से प्रतीक्षित और स्वागत योग्य विकास है। हालाँकि, पूंजी बाजार पर निर्भर रहना और उससे जुड़े रहना अपनी चुनौतियों और समझौतों के साथ आता है। जैसे-जैसे भारत का वित्तीय क्षेत्र इस महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है, उसे संभावित संकट के लिए भी तैयार रहना चाहिए और आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप करने और बचाव करने के लिए विनियामक और सरकारी नीतिगत प्रोत्साहन (लीवर) के साथ खुद को तैयार कराना चाहिए।

****

03

अध्याय

कीमतें और मुद्रास्फीतिः नियंत्रण में

मुद्रास्फीति प्रबंधन में महामारी और उसके बाद के भू-राजनैतिक तनावों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए काफी चुनौतियां पेश कीं। महामारी के कारण आपूर्ति श्रृखंला में व्यवधान और बढ़ते वैश्विक संघर्षों के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने भारत को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया। इसके परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 23 में कोर उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि देखी गई। पिछले दो वर्षों में प्रतिकूल मौसम के कारण खाद्य कीमतें प्रभावित हुई थीं। इन घटनाओं का निवल प्रभाव वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 में उच्च मुद्रास्फीतिक दबाव था। विवेकपूर्ण मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाई और सरकार द्वारा तैयार की गई सुविचारित व्यापार नीति उपायों, उचित उत्पादन वृद्धि, वित्त वर्ष 24 में कोर मुद्रास्फीति को चार वर्ष के निचले स्तर तक कम करने में सहायक रही। गतिशील स्टॉक प्रबंधन, खुले बाजार के संचालन, आवश्यक खाद्य वस्तुओं के रियायती प्रावधान और व्यापार नीति उपायों सहित उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई से खाद्य मुद्रास्फीति को काफी हद तक कम करने में मदद मिली है। सामान्य मानसून की संभावना और प्रमुख आयातित वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में कमी से भारतीय रिजर्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत के लिए दर्शाए गए अच्छे और सीमाबद्ध मुद्रास्फीति अनुमानों को बल मिलता है। इसके अलावा, मध्यावधि से दीर्घावधिक मुद्रास्फीति दृष्टिकोण का निर्धारण मूल्य निगरानी तंत्रों और बाजार आसूचना के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ दालों और खाद्य तेलों जिसके लिए भारत की आयात निर्भरता काफी हद तक है, जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के संकेन्द्रित प्रयासों द्वारा किया जाएगा।

परिचय

3.1. कम और स्थिर मुद्रास्फीति आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकारों और केंद्रीय बैंकों को वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति को मध्यम स्तर पर बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए आर्थिक संकेतकों की सावधानीपूर्वक निगरानी तथा उचित और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार द्वारा मूल्य स्थिरता और नीतिगत कार्रवाइयों के लक्ष्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की प्रतिबद्धता के साथ, भारत ने वित्त वर्ष 24 में खुदरा मुद्रास्फीति को 5.4 प्रतिशत पर रखने में सफलता प्राप्त की, जो कोविड-19 महामारी अवधि (इसके बाद 'महामारी') के बाद से सबसे निचला स्तर है।

3.2. महामारी के बाद, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला में उत्पन्न व्यवधानों का पुनः सामना किया। वर्ष के उत्तरार्ध और वित्त वर्ष 24 में कीमतों में उतार-चढ़ाव, विशेष रूप से ऊर्जा की कीमतों में, के कम प्रभाव, साथ ही निचले स्तर पर कोर मुद्रास्फीति और मौद्रिक सख्ती के कारण वैश्विक मुद्रास्फीति में कमी आई। आईएमएफ[1] के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों द्वारा समन्वित मौद्रिक सख्ती ने इसके उच्च स्तर के तादम्यता और वैश्विक ऊर्जा माँग को कम करने पर परिणामी प्रभाव के कारण ऊर्जा की कीमतों की गिरावट में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

1 विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ), अप्रैल 2024, पृष्ठ 3-4 (विश्व आर्थिक परिदृश्य, अप्रैल 2024: स्थिर लेकिन धीमाः विचलन के बीच लचीलापन (imf.org))

भारत की खुदरा मुद्रास्फीति ईएमडीईएस और विश्व औसत से कम है

3.3. मूल्य स्थिरता को बनाए रखने के लिए अधिकांश केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति में लगातार सख्ती के बावजूद, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2023 में एक अप्रत्याशित लचीलापन देखने को मिला। यह उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एईएस) और उभरते बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीईएस) दोनों में स्पष्ट है, क्योंकि वे अपने मुद्रास्फीति लक्ष्यों की ओर लौट रहे हैं। यह प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई है। आईएमएफ[2] के आँकड़ों के अनुसार, भारत की मुद्रास्फीति दर वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में वैश्विक औसत और ईएमडीईएस की मुद्रास्फीति दर से कम थी।

3.4. अतंर-देशीय मुद्रास्फीति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के बीच एक स्पष्ट नकारात्मक संबंध है। पहले भी, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति आम तौर पर ईएमडीईएस की तुलना में कम रही है। स्थापित मौद्रिक नीतियां, आर्थिक स्थिरता, विकसित और कुशल बाजार जैसे कारक जो आपूर्ति और मांग की स्थिति को संतुलित करते हैं, मुद्रास्फीति के प्रभावी प्रबंधन में योगदान करते हैं (हा, कोसे और ओहनसर्ज, 2018)[3]।

चार्ट III.1: 2023 में भारत की मुद्रास्फीति ईएमडीईएस से कम

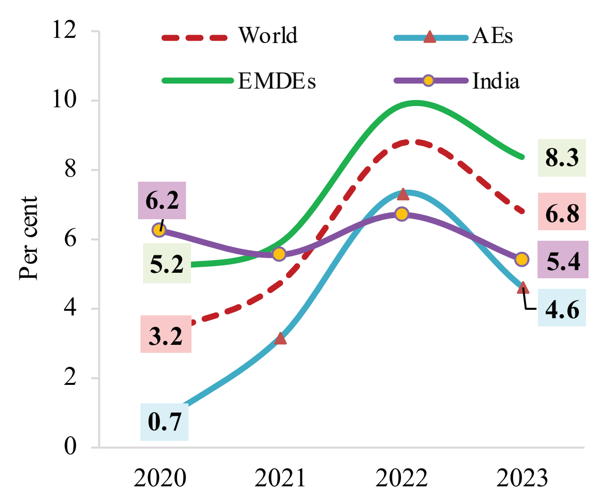

चार्ट III.2: ईएमडीईएस की तुलना में एई की मुद्रास्फीति कम होती है

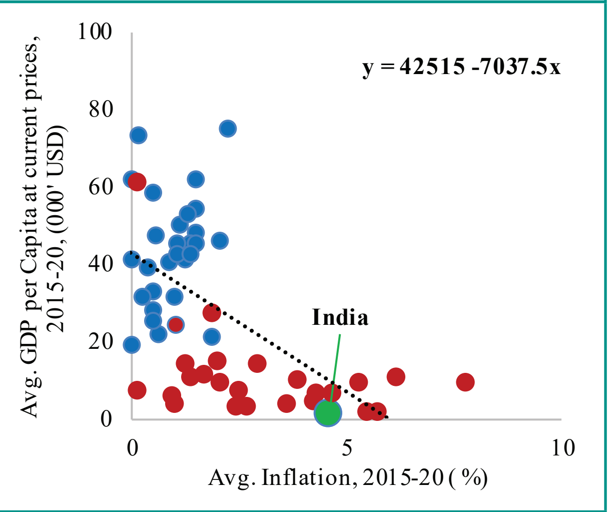

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस, अप्रैल 2024, आईएमएफ

नोट: (i) चित्र III-2 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम जीडीपी और दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति वाले देश शामिल नहीं हैं

(ii) आईएमएफ डेटा में, भारत के लिए 2023 वित्त वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष 24) का प्रतिनिधित्व करता है

(iii) एईएस के लिए नीले रंग के बिंदु और ईएमडीईएस के लिए लाल रंग के बिंदु

भारत का मुद्रास्फीति प्रबंधन इसे लक्ष्य के भीतर रखने के लिए अपेक्षाकृत बेहतर था

3.5. मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लक्ष्य के साथ, कई देशों ने विभिन्न कारकों के आधार पर अपने स्वयं के मुद्रास्फीति लक्ष्य स्थापित किए हैं जो उनके आर्थिक उद्देश्यों को बेहतर ढंग से पूरा करते हैं। आर्थिक विकास का स्तर, अर्थव्यवस्था की संरचना, वित्तीय प्रणाली की स्थिति और मुद्रास्फीति के बीच व्यापार-बंद तथा अन्य आर्थिक उद्देश्यों जैसे कारक इन लक्ष्यों (जहान, सरवत)[4] को प्रभावित कर सकते हैं। देशों द्वारा निर्धारित विशिष्ट मुद्रास्फीति लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, वे विभिन्न नीतियों और उपायों को लागू करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य के संबंध में विभिन्न विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

---

2 विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ), अप्रैल 2024, पृष्ठ 3-4 (विश्व आर्थिक परिदृश्य, अप्रैल 2024: स्थिर लेकिन धीमा: विचलन के बीच लचीलापन (imf.org))

3 हा, जोंग्रीम; कोसे, अयहान; ओहनसोर्ग, फ्रांजिस्का लिसेलोटे (2018)। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति: विकास, चालक और नीतियाँ। विश्व बैंक समूह, वाशिंगटन, डी.सी. (http://documents.worldbank.org/curated/en@749181542305098752/Inflation-in-Emerging-and-Developing-Economies-Evolution-Drivers-and-Policies)

4 जहान, सरवत. मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण: नियंत्रण बनाए रखना, अर्थशास्त्र को समझना, मूल बातों की ओर वापसी, वित्त एवं विकास, आईएमएफ (मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण: नियंत्रण बनाए रखना (imf.org))

3.6. वर्ष 2023 में, भारत की मुद्रास्फीति दर 2 से 6 प्रतिशत के लक्ष्य सीमा के भीतर थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, भारत में 2021-2023 तक त्रैवार्षिक औसत मुद्रास्फीति में अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य से सबसे कम विचलन था। वर्तमान में भू-राजनैतिक तनावों के कारण वैश्विक मांग-आपूर्ति असंतुलन से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, भारत की मुद्रास्फीति दर 2023 में वैश्विक औसत से 1.4 प्रतिशत अंक कम थी। इस पृष्ठभूमि में सर्वेक्षण में खुदरा मुद्रास्फीति के रुझानों और अभियानों और उसके घटकों - हेडलाइन, कोर और खाद्य मुद्रास्फीति, खुदरा मुद्रास्फीति में राज्यवार भिन्नता, ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति में अंतर और अध्याय में आगे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किए गए राजकोषीय नीति संबंधी उपायों पर चर्चा की गई है।

चार्ट III.3: भारत अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य के करीब है

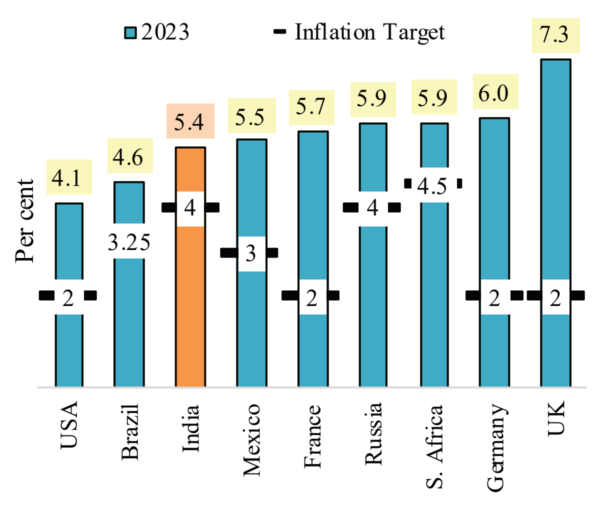

चार्ट III.4: भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य से सबसे कम औसत विचलन (2021-2023) है

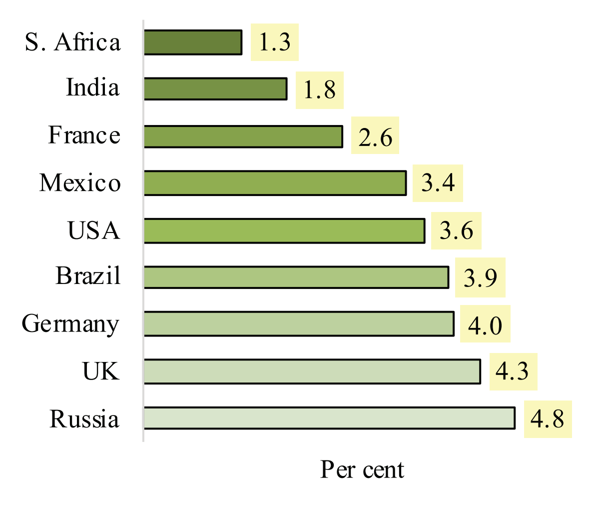

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस, अप्रैल 2024, आईएमएफ

नोट: (i) मुद्रास्फीति लक्ष्य संबंधित देशों के मौद्रिक नीति दस्तावेजों से लिया जाता है।

(ii) आईएमएफ डेटा में, भारत के लिए 2023 वित्त वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष 24) का प्रतिनिधित्व करता है

(iii) दक्षिण अफ्रीका के लिए, 4.5% को 3-6% मुद्रास्फीति लक्ष्य सीमा के मध्य बिन्दु के रूप में लिया जाता है।

(iv) ब्राजील के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य 2021 में 3.75%, 2022 में 3.5% और 2023 में 3.25% है।

घरेलू खुदरा मुद्रास्फीति

वित्त वर्ष 24 में खुदरा मुद्रास्फीति धीरे-धीरे सामान्य हुई

3.7. वर्ष 2020 से, देशों को मुद्रास्फीति नियंत्रित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वित्त वर्ष 23 में, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति मुख्य रूप से उच्च खाद्य मुद्रास्फीति से प्रभावित थी, जबकि कोर मुद्रास्फीति मध्यम रही। बाहरी रूप से, रूस-यूक्रेन युद्ध ने, जबकि घरेलू स्तर पर, गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और असमान वर्षा ने खाद्य कीमतों पर दबाव डाला।

3.8. हालांकि, मई 2022 से व्यापक रूप से, मौद्रिक नीति के अन्तर्गत रेपो दर को मई 2022 में 4 प्रतिशत से 250 आधार अंको की वृद्धि करके फरवरी 2023 में 6.5 प्रतिशत तक बढ़ाकर प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके बाद, विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ संरेखित करने के उद्देश्य से समायोजन की क्रमिक निवर्तन पर ध्यान केंद्रित करके नीति दर को अपरिवर्तित रखा गया था। इसके परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 23 में देखी गई लगातार और स्थिर कोर मुद्रास्फीति जून 2024 में घटकर 3.1 प्रतिशत हो गई।

चार्ट III.5: महामारी के बाद से खुदरा हेडलाइन मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 24 में सबसे कम थी

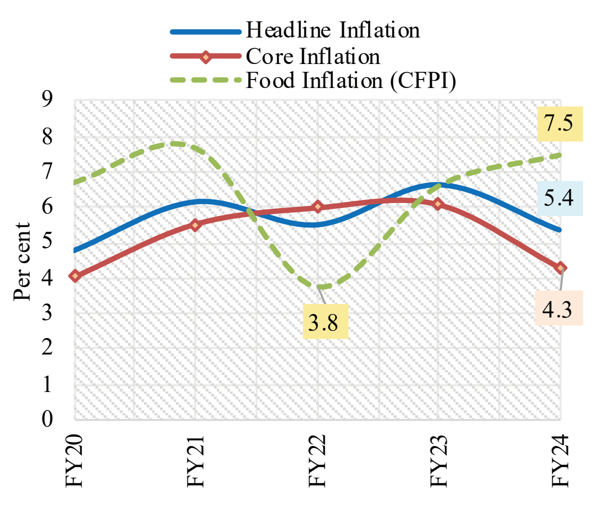

चार्ट III.6: हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति में गिरावट की प्रवृत्ति

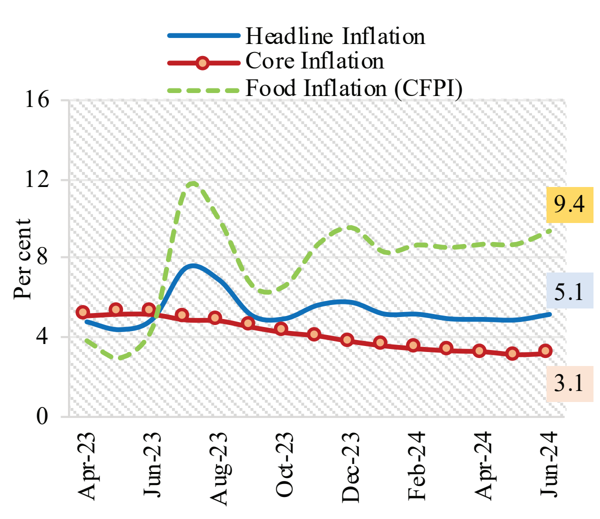

स्रोत: सीएसओ, एमओएसपीआई द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

3.9. चूंकि वैश्विक ऊर्जा मूल्य सूचकांक में वित्त वर्ष 24 में तीव्र गिरावट आयी, जिससे खुदरा ईंधन मुद्रास्फीति भी कम रही। केंद्र सरकार द्वारा एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के लिए मूल्य कटौती की घोषणा से एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पाद मुद्रास्फीति में कमी आयी। अगस्त 2023 में, देश भर के सभी बाजारों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹200 प्रति सिलेंडर कम कर दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप, एलपीजी मुद्रास्फीति दर सितंबर 2023 से डिफलेशन जोन में रही है। मार्च 2024 में, गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में प्रति सिलेंडर ₹100 की कमी पुन: एक बार की गई थी। इसी तरह मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹2 प्रति लीटर की कमी की। बाद में, वाहनों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल में खुदरा मुद्रास्फीति मार्च 2024 में डिफलेशन जोन में चली गई। इसके अतिरिक्त, 2023 में वैश्विक वस्तु की कीमतों में गिरावट आयी, जिससे आयातित मुद्रास्फीति चैनल के माध्यम से ऊर्जा, धातुओं, खनिजों और कृषि वस्तुओं में मूल्य दबाव कम हो गया। कम ईंधन और कोर मुद्रास्फीति ने वित्त वर्ष 24 में खाद्य कीमतों में अस्थिरता के बावजूद, हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट सुनिश्चित किया।

3.10. इस प्रकार, मुद्रास्फीति में नरमी काफी हद तक महामारी के बाद के आर्थिक सुधार चरण के दौरान लागू किए गए, विवेकपूर्ण प्रशासनिक उपायों और मौद्रिक नीतियों का परिणाम थी। एमओएसपीआई द्वारा जारी हालिया आकड़ों के अनुसार, जून 2024 में, खुदरा मुद्रास्फीति की दर 5.1 प्रतिशत पर पहुंच गई। इसको ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित भाग कोर और खाद्य मुद्रास्फीति में विस्तृत प्रवृत्तियों और रूवरूपों की जांच करता है।

चार्ट III.7: 'वस्त्र और जूते' और 'ईंधन और बिजली' समूहों ने वित्त वर्ष 24 में मुद्रास्फीति दर में पर्याप्त गिरावट देखी

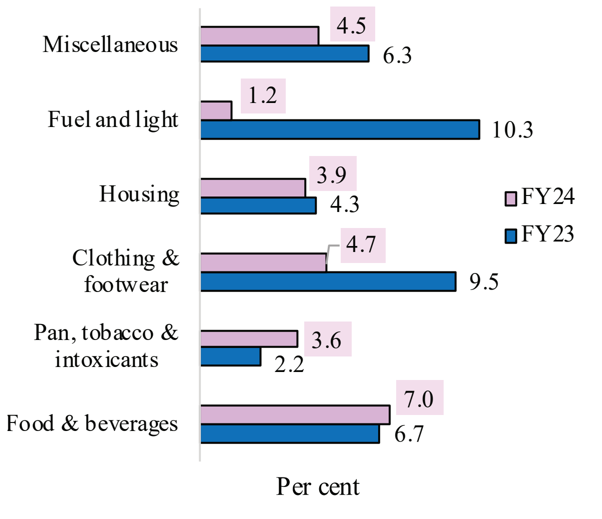

स्रोत: सीएसओ, एमओएसपीआई द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

चार्ट III.8: वित्त वर्ष 24 में घटता वैश्विक ऊर्जा सूचकांक

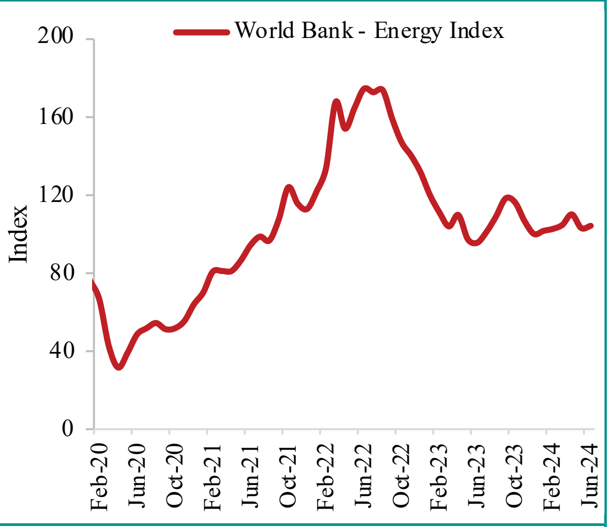

स्रोत: गुलाबी चादर, विश्व बैंक

चार्ट III.9: कीमत में कटौती/सब्सिडी के कारण एलपीजी मुद्रास्फीति दर में कमी

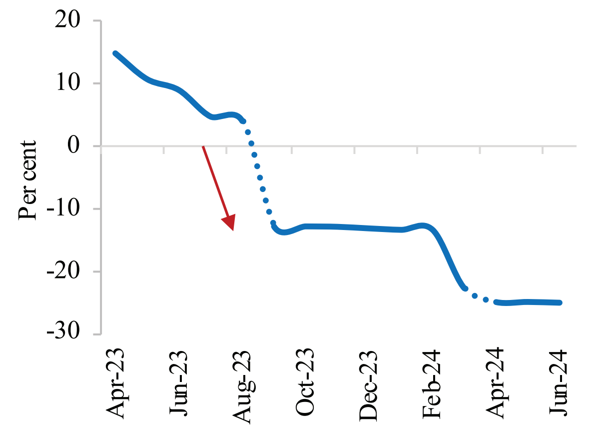

चार्ट III.10: कीमत में कमी के उपयों के कारण पेट्रोल और डीजल की मुद्रास्फीति दर में गिरावट

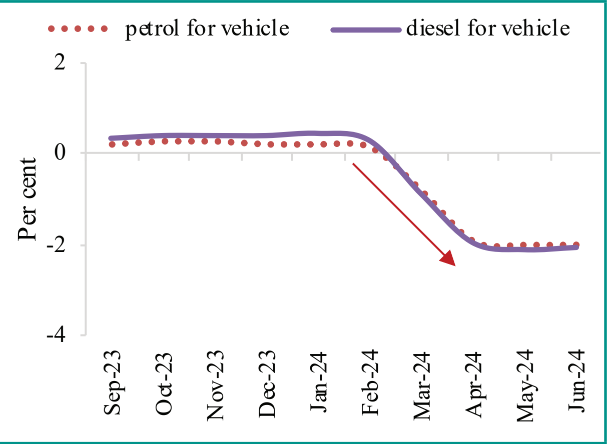

स्रोत: सीएसओ, एमओएसपीआई द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

महामारी के बाद की दुनिया में कोर मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव

वित्त वर्ष 24 में कोर मुद्रास्फीति चार साल के निचले स्तर पर रही

3.11. कोर मुद्रास्फीति को सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति से खाद्य और ऊर्जा वस्तुओं को पृथक करके मापा जाता है। यह अस्थायी आपूर्ति व्यवधानों से उत्पन्न कीमत उतार-चढ़ाव के प्रभाव को व्यापक रूप से समाप्त करके अंतर्निहित मूल्य प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करता है। निम्नलिखित चर्चा कोर मुद्रास्फीति को इसकी वस्तु और सेवाओं घटकों में विभाजित करती है। कोर वस्तुओं को आगे उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में विभाजित किया जाता है। कोर वस्तुओं और सेवाओं के सूचकांकों को अलग करने के लिए अपनाई गई विधि अनुलग्नक-1 में दी गई है। इसके घटकों में कोर मुद्रास्फीति का ब्यौरा चार्ट III.11 में दिया गया है।

चार्ट III.11: कोर मुद्रास्फीति का इसके घटकों में विभाजन

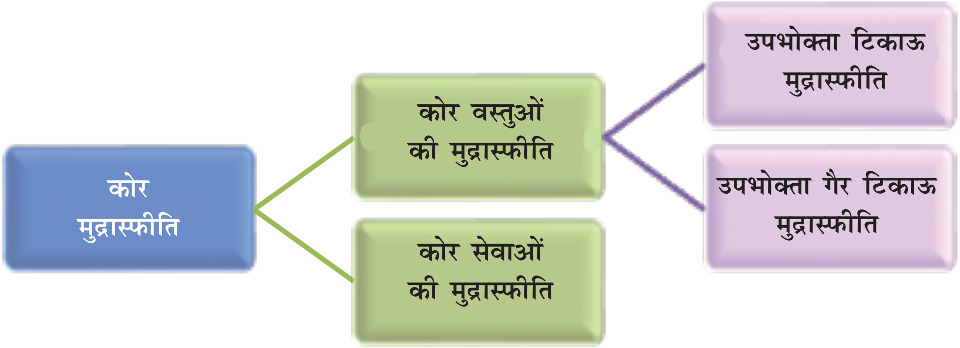

3.12. महामारी के बाद से, उच्च स्तर के खाद्य मुद्रास्फीति में कमी के कारण भारत में मुद्रास्फीतिक दबाव वित्त वर्ष 22 में कम हो गया। तथापि, कोर मुद्रास्फीति उसी समय 6 प्रतिशत तक बढ़ गई थी, जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से प्रभावित थी। जैसा कि चार्ट III.12 में दर्शाया गया है, वर्ष में कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति बढ़ी, लेकिन यह बढ़त कोर उपभोक्ता वस्तुओं की तुलना में कम थी।

3.13. वित्त वर्ष 23 में मुद्रास्फीतिक संबंधी दबाव फिर से रूस-यूक्रेन युद्ध से प्रभावित होकर बढ़ गया, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुई और खाद्य व ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई। जैसे-जैसे आर्थिक गतिविधि में तेजी आयी, कोर मुद्रास्फीति में भी थोड़ी वृद्धि हुई और यह मुख्य रूप से कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति से प्रभावित हुई क्योंकि लोगों के शहरी क्षेत्रों में लौटने के साथ घर के किराए में वृद्धि हुई (चार्ट III.15)। वित्त वर्ष 24 में, कीमतों में सुधार हुआ। कोर मुद्रास्फीति - वस्तु और सेवा दोनों में कमी के कारण सीपीआई मुद्रास्फीति में कमी आयी। वित्त वर्ष 24 में कोर सेवा मुद्रास्फीति नौ साल के निचले स्तर पर आ गई; वहीं, कोर वस्तु मुद्रास्फीति भी घटकर चार साल के निचले स्तर पर आ गई।

3.14. मौद्रिक नीति की रूपरेखा निर्धारित करने में कोर मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण हैं। मूल्य दबावों के उभरते स्वरूपों का आकलन करते हुए, RBI ने मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने के लिए मई 2022 से पुनः रेपो दर में धीरे-धीरे 250 आधार अंकों की वृद्धि की। चार्ट III.13 कोरक मुद्रास्फीति पर मौद्रिक नीति संचालन के प्रभाव को इंगित करता है, जिसमें अप्रैल 2022 और जून 2024 के बीच 4 प्रतिशत के आसपास की गिरावट आयी है।

चार्ट III.12: वित्त वर्ष 2024 में कोर मुद्रास्फीति 4 साल के निचले स्तर पर आ गई

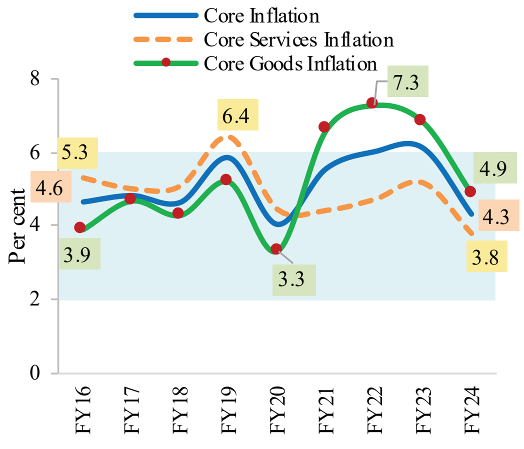

स्रोत: सीएसओ, एमओएसपीआई द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

चार्ट III.13: कोर मुद्रास्फीति को कम करने में मौद्रिक नीति संचालन स्पष्ट है

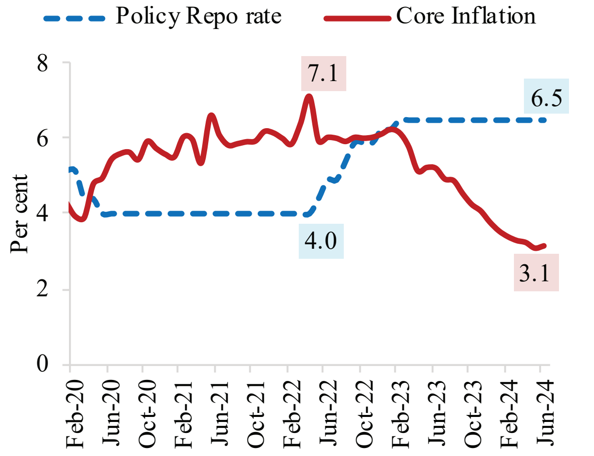

स्रोत: (i) सीएसओ, एमओएसपीआई द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, (ii) आरबीआई की विभिन्न एमपीसी रिपोर्ट

सेवा कीमतों में भारी गिरावट ने कोर मुद्रास्फीति में कमी को बढ़ावा दिया है

3.15. कोर सेवाओं की स्थिर कीमतें उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (बॉक्स III.1) के मुद्रास्फीति संबंधी दृष्टिकोण के लिए एक जोखिम कारक हैं। इसके विपरीत, भारत की कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 24 में नौ वर्ष के निचले स्तर पर पहुंच गई। इसके लिए 2023[5] में नए घरों के स्टॉक में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ आवास किराये संबंधी मुद्रास्फीति में नरमी भी जिम्मेदार थी।

चार्ट III.14: वित्त वर्ष 2024 में कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति का योगदान महामारी से पहले की तुलना में कम रहा

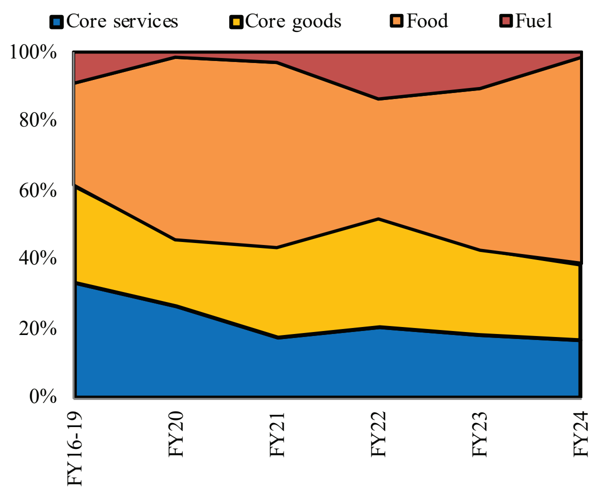

चार्ट III.15: कम आवास किराया के कारण कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति 9 वर्ष में सबसे कम

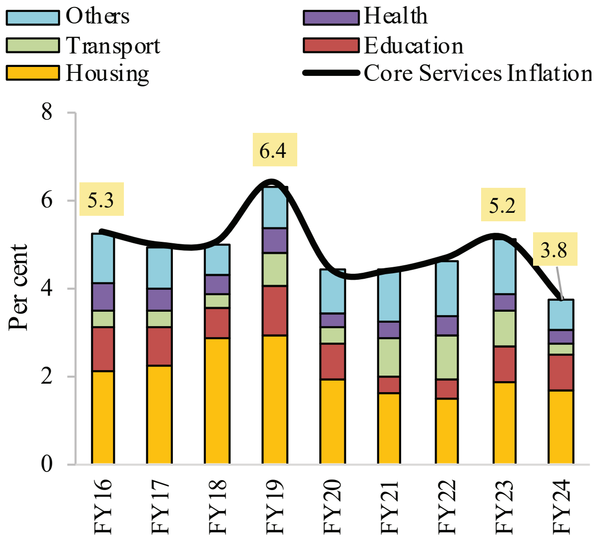

स्रोत: (i) सीएसओ, एमओएसपीआई द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
(ii) सीएसओ, एमओएसपीआई द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का उपयोग करके सर्वेक्षण की गणना

बॉक्स III.1: उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति के लिए अत्यधिक जोखिम

बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स[6] की मार्च 2024 की त्रैमासिक समीक्षा के अनुसार, 2023 में कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति अधिक रही। जबकि 2023 में आपूर्ति श्रृंखला के क्रमिक सामान्यीकरण के बाद खाद्य, ऊर्जा और कोर वस्तुओं की कीमतों में स्पष्ट वापसी हुई थी, समीक्षा से यह भी पता चला है कि कोर वस्तुओं की कीमतों में मंदी की हालिया गति पिछले मामलों से निकटता से मेल खाती है, जबकि साथ ही, सेवाओं में मूल्य वृद्धि पिछली मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक रही है। सेवा मुद्रास्फीति की लगातार प्रकृति सेवाओं में बहुत अधिक श्रम तीव्रता के कारण है। आवास की बढ़ती कीमतों ने भी इसमें योगदान दिया।

ये गतिशीलता विभिन्न देशों और क्षेत्रों में समान रूप से देखी गई है लेकिन उभरती एशियाई बाजार अर्थव्यवस्थाओं और लैटिन अमेरिका में ऐसा कम है (चार्ट III.16)। आगे बढ़ते हुए, सेवाओं की मुद्रास्फीति में दृढ़ता का उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की तुलना में एई पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेवाएं एई के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का एक बड़ा भाग हैं, जो उनके हेडलाइन मुद्रास्फीति दृष्टिकोण के लिए अधिक जोखिम भरा है।

5 https://www.proptiger.com/guide/post/new-home-sales-record-33-yoy-growth-in-2023-proptiger-com-report

6 बीआईएस त्रैमासिक समीक्षा, मार्च 2024, कोविड-19 के बाद की मुद्रास्फीति के अंतिम पड़ाव में क्षेत्रीय मूल्य गतिशीलता। (https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2403d.htm)

चार्ट III.16: AEs में लगातार कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति का जोखिम

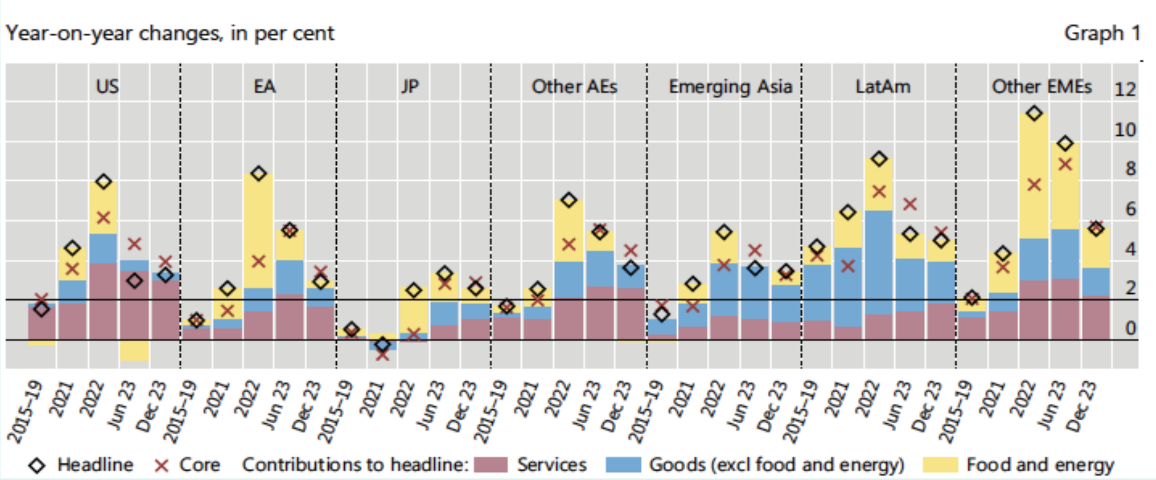

स्रोत: बीआईएस त्रैमासिक समीक्षा, मार्च 2024 से अनुकूलित, कोविड-19 के बाद के अवस्फीति के अंतिम चरण में क्षेत्रीय मूल्य गतिशीलता, ग्राफ 1

उपभोक्ता टिकाऊ मुद्रास्फीति में बढ़त बनी रही लेकिन वित्त वर्ष 24 में इसमें गिरावट हुई

3.16. उपभोक्ता टिकाऊ मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 20 और वित्त वर्ष 23 के बीच उत्तरोत्तर 5 प्रतिशत बिन्दु से अधिक बढ़ गया। वित्त वर्ष 21 में सोने की कीमतों में काफी वृद्धि देखी गई, जो सीपीआई की व्यक्तिगत देखभाल श्रेणी का एक प्रमुख घटक है। वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 23 में, उपभोक्ता टिकाऊ सूचकांक में 48 प्रतिशत भाग वाले, कपड़े, मुद्रास्फीति का एक प्रमुख घटक था। परिधान निर्माताओं, विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली प्रमुख सामग्री कपास की कीमतों में वृद्धि के कारण यह हुआ। प्रमुख कच्चे माल की आपूर्ति में सुधार के साथ, वित्त वर्ष 24 में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की मुद्रास्फीति दर में गिरावट आयी। हालांकि, फेड दर में कटौती और भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ने से सोने की रिकॉर्ड उच्च कीमतों ने समग्र टिकाऊ मुद्रास्फीति पर ऊपर की ओर दबाव डाला है।

चार्ट III.17: उपभोक्ता टिकाऊ मुद्रास्फीति पूर्व-महामारी स्तर पर बंद

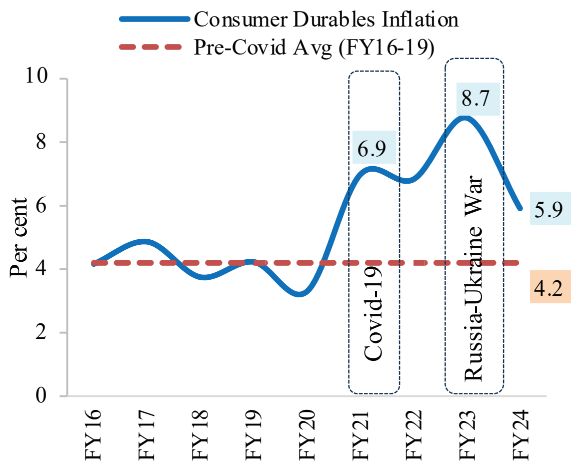

चार्ट III.18: सोने और कपड़े की कीमतों में वृद्धि ने टिकाऊ वस्तुओं में मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया

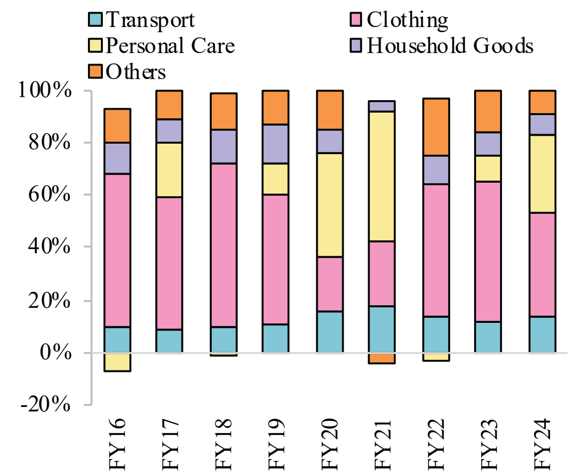

स्रोत: सीएसओ, एमओएसपीआई द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण की गणना

कोर उपभोक्ता गैर-टिकाऊ मुद्रास्फीति में भारी गिरावट

3.17. उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं (सीएनडी) के सीपीआई बास्केट में तीन घटक होते हैं – खाद्य और पेय पदार्थ, ईंधन और अन्य उपभोग की वस्तुएं (विवरण अनुलग्नक-1 में)। यह खंड केवल अन्य कोर उपभोक्ता गैर-टिकाऊ घटकों (सीएनडी की अन्य उपभोग की वस्तुएं) की जांच करता है। बाद के खंड 'खाद्य और पेय पदार्थ' की जांच करेंगे, जबकि 'ईंधन और बिजली' को पहले ही पैराग्राफ 3.9 में विस्तार से उल्लेख किया जा चुका है। जबकि कोर सीएनडी मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 20 में गिर गई, यह वित्त वर्ष 21 में बढ़ना शुरू हुई, वित्त वर्ष 22 में एक सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंच गई, और वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 में तेजी से गिर गई। इसके लिए अंतर्निहित कारण मुख्य रूप से परिवहन घटकों की लागत में परिवर्तन रहा है।

चार्ट III.19: (क) और (ख): परिवहन घटक में गिरावट के कारण कोर उपभोक्ता गैर-टिकाऊ मुद्रास्फीति में कमी आई

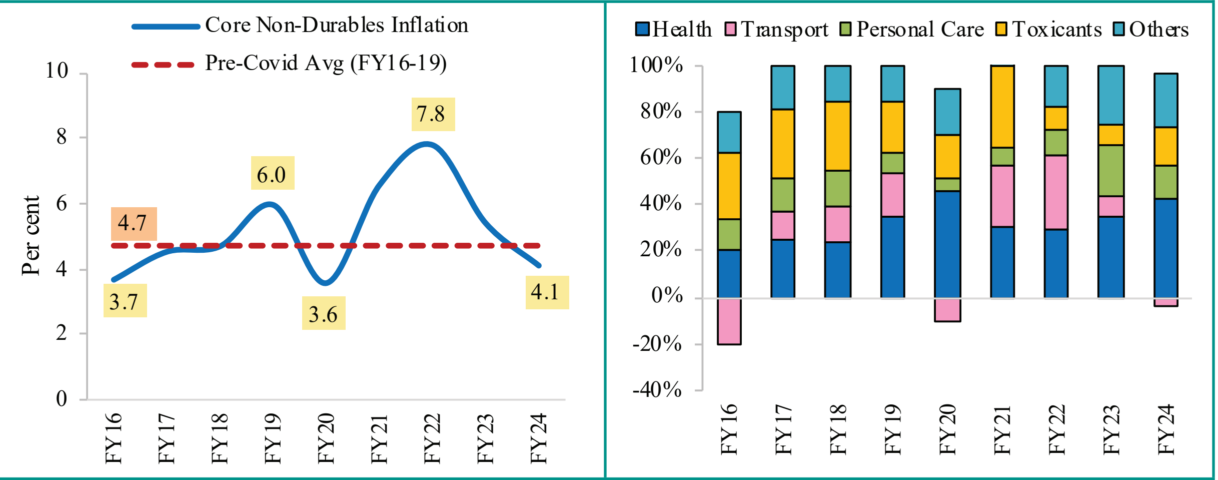

स्रोत: सीएसओ, एमओएसपीआई द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण की गणना

खाद्य मुद्रास्फीति

प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों पर दबाव

3.18. पिछले दो वर्षों में खाद्य मुद्रास्फीति एक वैश्विक घटना रही है। अनुसंधान[7] जलवायु परिवर्तन के लिए खाद्य कीमतों की बढ़ती सुभेद्यता को इंगित करता है – गर्म हवाएं, असमान मानसून वितरण, बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि, मूसलाधार वर्षा और ऐतिहासिक शुष्क स्थितियां (पात्रा, जॉन एंड जॉर्ज, 2024)। वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 में, कृषि क्षेत्र प्रतिकूल मौसम, जलाशय के कम स्तर और क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित हुआ जिससे कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ा। इसलिए, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 22 में 3.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 6.6 प्रतिशत और वित्त वर्ष 24 में 7.5 प्रतिशत हो गई।

7 पात्रा, एम.डी., जॉन, जे., और जॉर्ज, ए.टी. (2024)। क्या खाद्य कीमतें भारत की मुद्रास्फीति का 'असली' मूल हैं? आरबीआई बुलेटिन, 78(1): 87-98 (RBIBULLETINJANUARY2024EC59F69FFEA5447B9A75C33E7CA8CB26-PDF)

चार्ट III.20: खाद्य मुद्रास्फीति में खाद्य पदार्थों का योगदान (%)

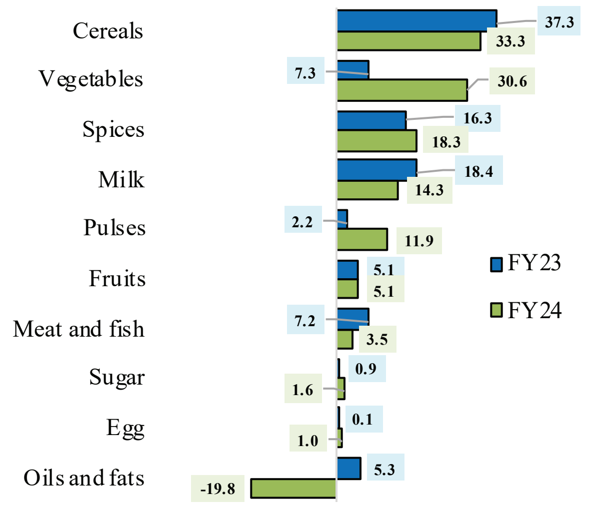

स्रोतः सीएसओ, एमओएसपीआई द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण की गणना

चार्ट III.21: सब्जियों, दालों और मसालों में बढ़ी हुई मुद्रास्फीति दर (%)

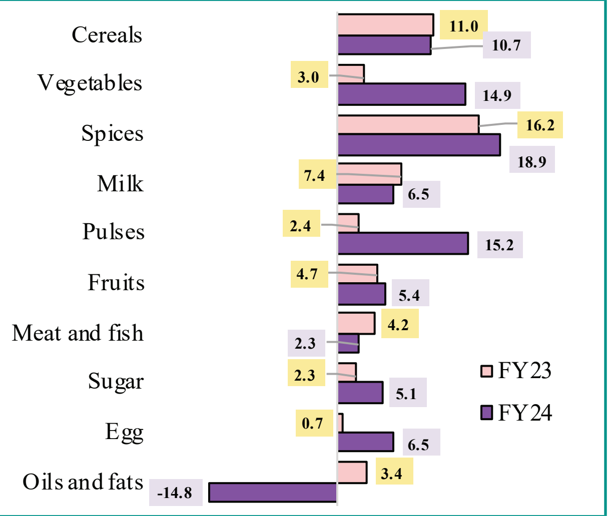

स्रोतः सीएसओ, एमओएसपीआई द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

प्रमुख खाद्य वस्तुओं में कीमत वृद्धि के कारण

3.19. सब्जियों और दालों की उत्पादन संभावनाएं विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति से प्रभावित हुई। जुलाई 2023 में टमाटर की कीमतों में वृद्धि फसल उत्पादन में मौसमी बदलाव, वाइट फ्लाई के संक्रमण जैसी क्षेत्र-विशिष्ट फसल रोगों और देश के उत्तरी भाग में मानसून के जल्दी आगमन के कारण हुई थी। भारी बारिश के कारण अलग-अलग क्षेत्रों में रसद सेवाओं में भी व्यवधान आया। प्याज की कीमतों में तेजी कई कारकों के कारण आयी है, जिसमें पिछले कटाई सत्र के दौरान बारिश का रबी प्याज की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव होना, खरीफ सत्र के दौरान बुवाई में देरी, लंबे समय तक सूखे की अवधि से खरीफ उत्पादन प्रभावित होना और अन्य देशों द्वारा किए गए व्यापार संबंधी उपाय शामिल हैं।

3.20. दालों, विशेष रूप से तुअर की कीमतों में वृद्धि पिछले दो वर्षों में प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण कम उत्पादन की वजह से हुई है। रबी सीजन में धीमी बुवाई और दक्षिणी राज्यों में जलवायु संबंधी परिवर्तन के कारण उड़द का उत्पादन प्रभावित हुआ था। पिछले रबी सीजन की तुलना में चने का क्षेत्र और उत्पादन भी कम रहा।

3.21. वर्ष 2023 की शुरुआत से दूध की कीमत में बढ़ोतरी रही है। यह महामारी के चरम दिनों के दौरान कृत्रिम गर्भाधान में कमी के साथ-साथ पशु आहार की उच्च लागत के कारण हुआ था है। दूध सहकारी समितियों ने बढ़ी हुई लागत के कारण दूध और दूध उत्पादों की कीमत में वृद्धि की। दूध की कीमत में वृद्धि वित्त वर्ष 24 के अंत तक कम हो गई।

3.22. हालांकि, सरकार ने आवश्यक खाद्य पदार्थों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खुले बाजार में बिक्री, निर्दिष्ट दुकानों में खुदरा बिक्री और समय पर आयात सहित त्वरित कार्रवाई की (बॉक्स III.2)। इसके अतिरिक्त, गरीबों हेतु खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है, को जनवरी 2024 से शुरू होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।

बॉक्स III.2: वित्त वर्ष 24 में खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक उपाय

गेहूं/आटा

- गेहूं के आटे, मैदा और सूजी के निर्यात को अगस्त 2022 से निषिद्ध श्रेणी में रखा गया था।
- जमाखोरी और बेईमानी को रोकने के लिए, जून 2023 से मार्च 2024 तक गेहूं पर स्टॉक सीमा लगाई गई थी।
- नवंबर 2023 में, सरकार ने उपभोक्ताओं हेतु इसे किफायती बनाने के लिए ₹27.50 प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर भारत आटा की शुरूआत की।
- खुले बाजार में बिक्री के लिए केन्द्रीय पूल से समय-समय पर गेहूं और चावल को निकाला जाता है।

चावल/धान

- सरकार ने क्रमशः सितंबर 2022 और जुलाई 2023 में टूटे चावल और गैर-बासमती चावल के निर्यात को निषिद्ध श्रेणी के तहत रखा।
- बासमती चावल की आड़ में होने वाले गैर-बासमती चावल के निर्यात को रोकने के लिए, बासमती चावल के निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य अक्टूबर 2023 में तय किया गया था।
- पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने और घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए, सरकार ने 31 मार्च 2024 तक पारसेला चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया।
- फरवरी 2024 में, सरकार ने व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर/मिलरों द्वारा चावल/धान के स्टॉक की स्थिति घोषित करने के लिए अनिवार्य किया।
- फरवरी 2024 में, सरकार ने एनएएफईडी, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के माध्यम से ₹29 प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर भारत चावल बेचना शुरू किया।

दालें

- उपभोक्ताओं को उपलब्धता और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए दालों के बफर स्टॉक से पर्याप्त सूझबूझ से रिलीज की जा रही है।
- घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और दालों की कीमतों को कम करने के लिए, अरहर और उड़द के आयात को 31 मार्च, 2025 तक 'मुक्त श्रेणी' के तहत रखा गया है। मसूर पर मूल आयात शुल्क 31 मार्च, 2024 तक घटाकर शून्य कर दिया गया था।
- सरकार ने अत्यधिक रियायती दर पर खुदरा निपटान के लिये चना स्टॉक को चना दाल में बदलने के लिये जुलाई 2023 में भारत दाल की शुरुआत की। बाद में, भारत दाल को मूंग दाल और मूंग साबूत को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था।
- इसके अलावा, भारत ने वित्त वर्ष 24 में काफी मात्रा में अरहर (मुख्य रूप से मोजाम्बिक, म्यांमार, तंजानिया, सूडान और मलावी से), मसूर (मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रूस से) और उड़द (मुख्य रूप से म्यांमार से) आयात किया।

प्याज

- पीएसएफ के तहत प्याज बफर वित्त वर्ष 21 में 1.00 एलएमटी से बढ़ाकर वित्त वर्ष 24 में 7.00 एलएमटी कर दिया गया था। यह स्टॉक खुदरा बिक्री, ई-नाम नीलामी और थोक बाजारों में थोक बिक्री के माध्यम से जारी किया गया था।
- सरकार ने अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 तक प्याज की विशिष्ट किस्मों पर न्यूनतम निर्यात मूल्य रखा।
- दिसंबर 2023 में, प्याज की निर्यात नीति को 31 मार्च, 2024 तक 'मुक्त' से 'निषिद्ध' श्रेणी में संशोधित किया गया था।

खाद्य तेल

- कच्चे पाम तेल, कच्चा सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। तेल पर कृषि उपकर को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। जनवरी 2024 में, इस शुल्क संरचना को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया गया था।
- रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड सूरजमुखी ऑयल और रिफाइंड पाम ऑयल पर घटी बेसिक ड्यूटी स्ट्रक्चर को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
- रिफाइंड पाम तेलों के मुक्त आयात को अगले आदेशों तक बढ़ा दिया गया था।

चीनी

- अक्टूबर 2023 में, सरकार ने चीनी (कच्ची चीनी, सफेद चीनी, परिष्कृत चीनी और जैविक चीनी) के निर्यात पर प्रतिबंधों की तारीख को 31 अक्टूबर, 2023 से आगे अगले आदेश तक बढ़ा दिया।

वैश्विक खाद्य कीमतें और घरेलू मुद्रास्फीति

3.23. भारत में, खाद्य तेल बाजार बहुत हद तक आयात पर निर्भर करता है, जिसमें कुल खाद्य तेल आवश्यकता का 50 प्रतिशत से अधिक आयात[8] किया जाता है, जिससे यह वैश्विक कीमतों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) खाद्य तेल मूल्य सूचकांक में उतार-चढ़ाव इन वैश्विक मूल्य रुझानों का एक प्रमुख संकेतक है। इस सूचकांक में हाल की गिरावट की प्रवृत्ति मोटे तौर पर भारत में घरेलू खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट के साथ सहसंबद्ध है। इसके परिणामस्वरूप सरकार उपभोक्ताओं के लिए रियायती दर पर खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक बाजार प्रवृत्तियों की गहन निगरानी करती है। वैश्विक मूल्य अस्थिरता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए आयातों को घरेलू उत्पादन के साथ संतुलित करने के प्रयास भी किए जाते हैं। इस संदर्भ में, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम का उद्देश्य आयात बोझ को कम करने के लिए घरेलू कच्चे पाम तेल उत्पादन को बढ़ाना है।

3.24. चीनी के मामले में, सरकार ने जून 2022 में निर्यात पर प्रतिबंधों की घोषणा की ताकि पर्याप्त स्थानीय आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और इस प्रकार चीनी मुद्रास्फीति का प्रबंधन किया जा सके। इन निर्यात प्रतिबंधों ने वास्तव में घरेलू चीनी की कीमतों को स्थिर करने में भूमिका निभाई है। इसके परिणामस्वरूप, भले ही वैश्विक चीनी मूल्य सूचकांक बढ़ गया है और फरवरी 2023 से अस्थिरता दिख रहा है, किंतु घरेलू चीनी की कीमतें बहुत कम अस्थिर रही हैं।

चार्ट III.22: वैश्विक और घरेलू खाद्य तेल की कीमतों का सह-संचलन

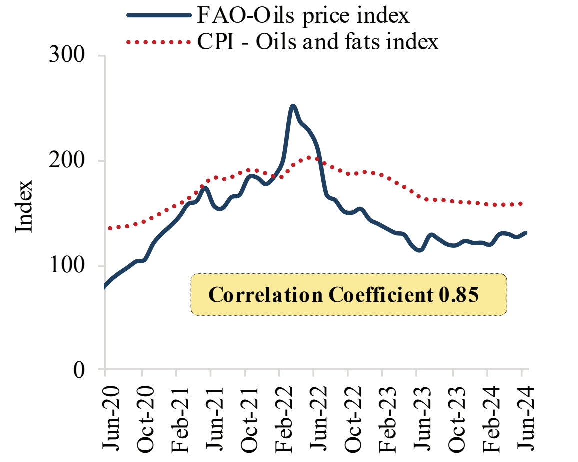

चार्ट III.23: चीनी पर निर्यात प्रतिबंध से भारत में चीनी की कीमतें स्थिर हो गईं

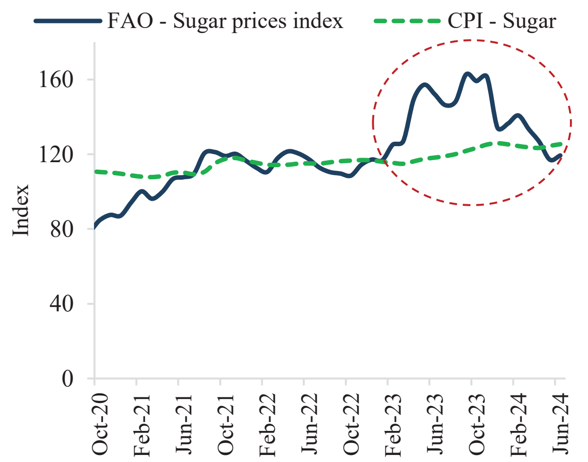

स्रोत: (i) CSO, MoSPI द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ii) FAO द्वारा जारी खाद्य मूल्य सूचकांक डेटा

8 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, दिनांक 14 मार्च 2024 की पीआईबी विज्ञप्ति। (pib.gov.in/PressReleaseIframePage-aspx?PRID=2014554)

खुदरा मुद्रास्फीति में अंतरराज्यीय अंतर

3.25. वित्त वर्ष 24 में अखिल भारतीय औसत खुदरा मुद्रास्फीति दर में गिरावट के अनुरूप, अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मुद्रास्फीति में गिरावट आयी। 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 29 में मुद्रास्फीति की दर 6 प्रतिशत से कम थी।

चार्ट III.24: वित्त वर्ष 24 में खुदरा मुद्रास्फीति (%) में अंतरराज्यीय बदलाव

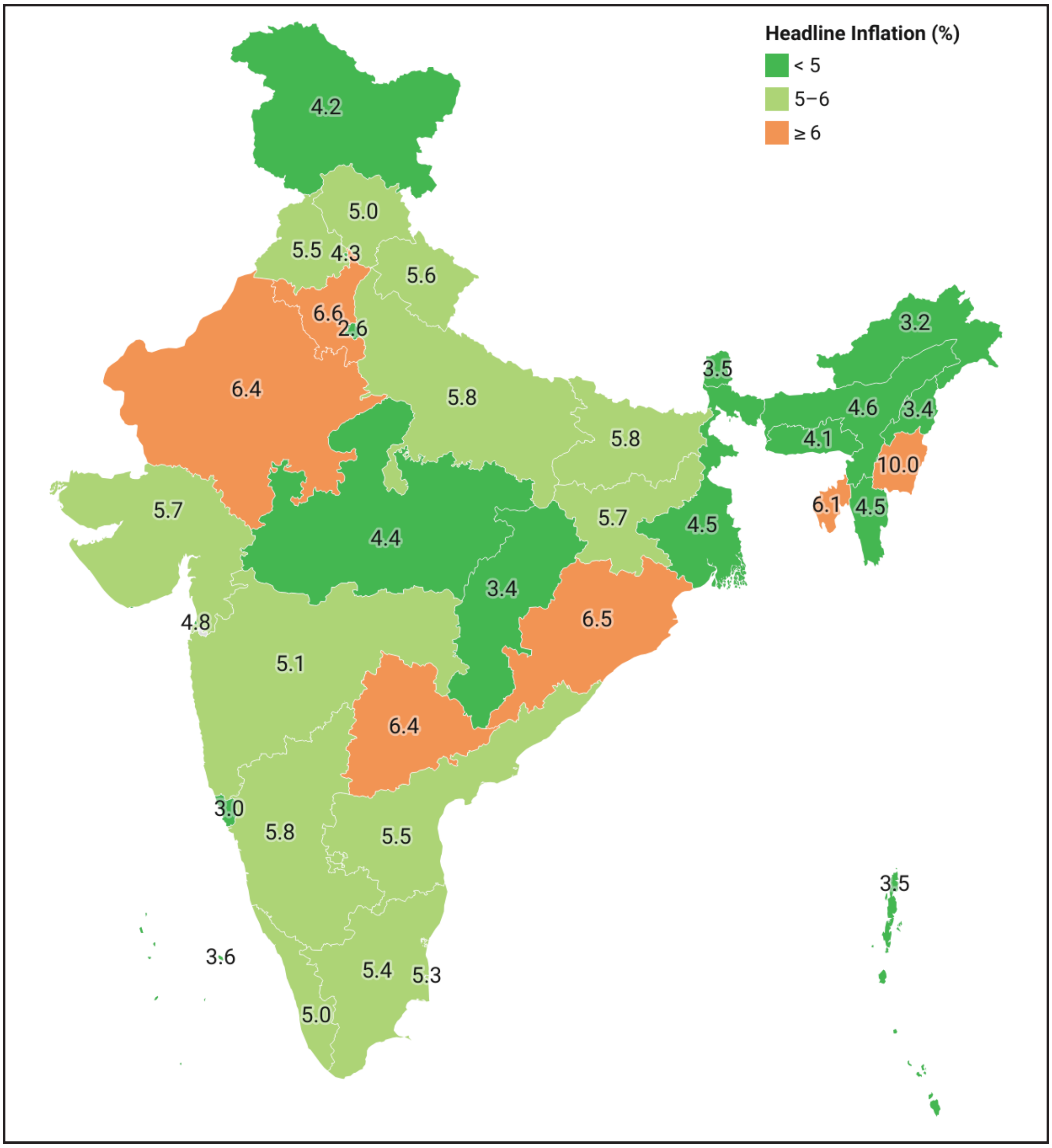

स्रोत: सीएसओ, एमओएसपीआई द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों से तैयार

ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति में अंतरराज्यीय अंतर अधिक स्पष्ट हैं

3.26. उपभोग बास्केट में शहरी (29.6%) की तुलना में ग्रामीण खाद्य पदार्थों का बहुत अधिक भार (47.3%) है। इसलिए, पिछले दो वर्षों में, जिन राज्यों में खाद्य कीमतें बढ़ी हैं, उन्होंने भी उच्च ग्रामीण मुद्रास्फीति का अनुभव किया। यह भी पाया गया है कि मानक विचलन के माध्यम से परिकलित अंतर-राज्यीय भिन्नता शहरी मुद्रास्फीति की तुलना में ग्रामीण में अधिक है। इसके अलावा, उच्च समग्र मुद्रास्फीति वाले राज्यों में भी ग्रामीण से शहरी मुद्रास्फीति का व्यापक अंतर प्रदर्शित होता है और ग्रामीण मुद्रास्फीति शहरी मुद्रास्फीति से अधिक है। विभिन्न राज्यों के लिए उनके

ग्रामीण-से-शहरी मुद्रास्फीति अनुपात की तुलना में समग्र मुद्रास्फीति का बिखराव एक सकारात्मक सहसंबंध दर्शाता है। उदाहरण के लिए, हरियाणा में ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के बीच का अंतर गोवा की तुलना में बहुत व्यापक था, जिसमें अपेक्षाकृत कम मुद्रास्फीति थी।

चार्ट III.25: वित्त वर्ष 24 में ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति अंतर में अंतरराज्यीय बदलाव (उच्चतम और निम्नतम अंतर वाले शीर्ष 5 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश)

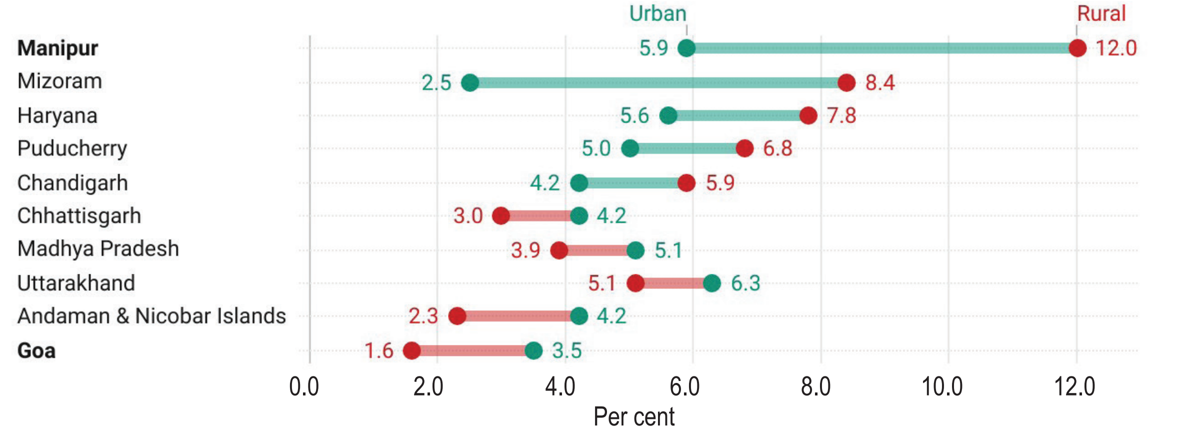

स्रोत: सीएसओ, एमओएसपीआई द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

चार्ट III.26: ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति दर में अंतरराज्यीय भिन्नताएं अधिक हैं

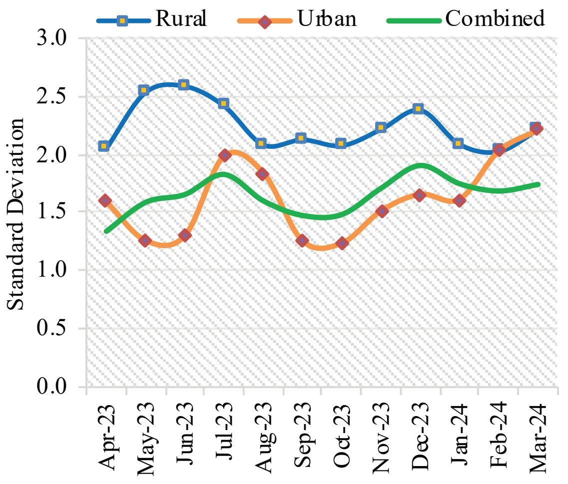

चार्ट III.27: उच्च मुद्रास्फीति दर वाले राज्य व्यापक ग्रामीण-शहरी अंतर दिखाते हैं (वित्त वर्ष 24)

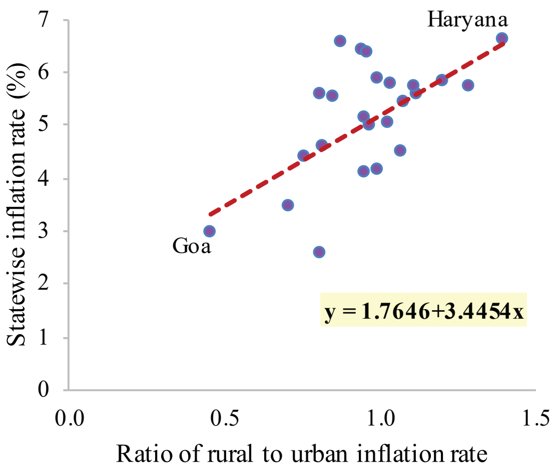

स्रोत: सीएसओ, एमओएसपीआई द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
नोट: स्कैटर प्लॉट 23 प्रमुख राज्यों और दिल्ली के एनसीटी के उप-नमूने पर आधारित है

दृष्टिकोण और समाधान

3.27. आरबीआई और आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 26 में मुद्रास्फीति लक्ष्य की ओर उत्तरोत्तर संरेखित होगी। सामान्य मानसून और आगे कोई बाहरी या नीतिगत बदलाव नहीं मानते हुए, आरबीआई[9] को उम्मीद है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 25 में 4.5 प्रतिशत और वित्त वर्ष 26 में 4.1 प्रतिशत

9 मौद्रिक नीति रिपोर्ट, अप्रैल 2024, पृष्ठ 7 (MPRAPRIL20248665551409840 6BA610767D0E792E87.PDF (rbi.org.in)

होगी। आईएमएफ[10] ने भारत के लिए 2024 में 4.6 प्रतिशत और 2025 में 4.2 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया है।

3.28. विश्व बैंक[11] को उम्मीद है कि वस्तुओं की वैश्विक आपूर्ति में वृद्धि होगी, और इसलिए बेहतर औद्योगिक गतिविधि और व्यापार वृद्धि के कारण उनकी मांग बढ़ेगी। इसे 2024 में वस्तु मूल्य सूचकांक में 3 प्रतिशत की कमी और 2025 में 4 प्रतिशत की कमी का अनुमान है, जो मुख्य रूप से ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक की कम कीमतों से प्रेरित है। इस वर्ष कोयले और प्राकृतिक गैस की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट के कारण ऊर्जा मूल्य सूचकांक में गिरावट की उम्मीद है। उर्वरक की कीमतों में कमी होने की संभावना है, लेकिन ये मजबूत मांग और निर्यात प्रतिबंधों के कारण 2015-2019 के स्तर से ऊपर बनी हुई हैं। मूल धातु की कीमतों में वृद्धि का अनुमान है, जो वैश्विक औद्योगिक गतिविधि और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि को दर्शाती है। सामान्यत: भारत द्वारा आयातित वस्तुओं के मूल्यों में मौजूदा अधोमुखी उतार-चढ़ाव घरेलू मुद्रास्फीति दृष्टिकोण के लिए सकारात्मक है।

चार्ट III.28: 2025 में वैश्विक वस्तु की कीमतों में प्रत्यशित गिरावट

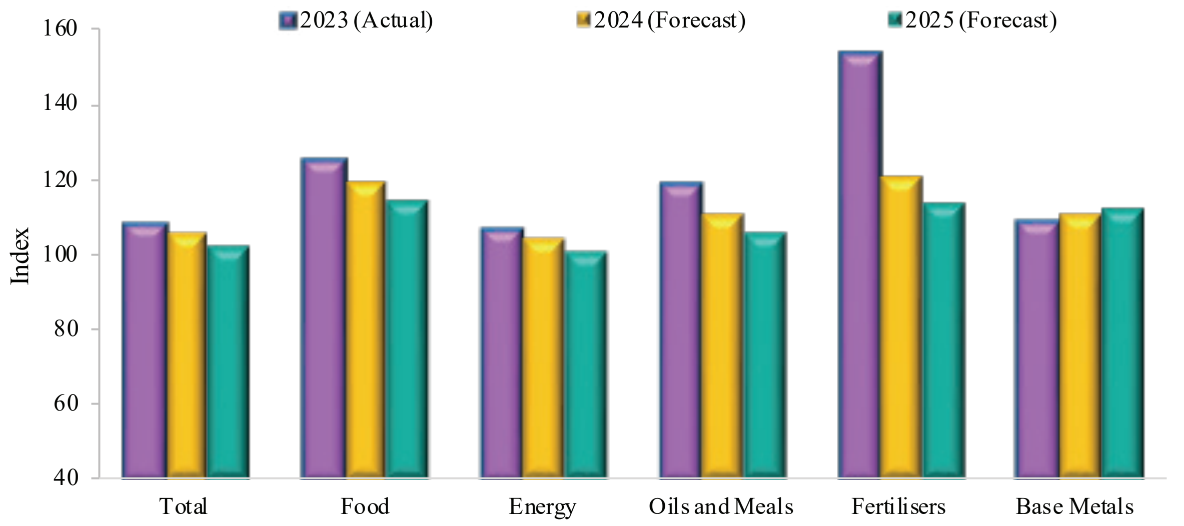

स्रोत: विश्व बैंक कमोडिटी मूल्य पूर्वानुमान अप्रैल 2024 में जारी किया गया

टिप्पणी: (i) कुल मूल्य सूचकांक ऊर्जा और गैर-ऊर्जा मूल्यों (बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर) से बना होता है जो 2002-04 के निर्यातों में उनके हिस्से के भारांक से युक्त होता है।

(ii) ऊर्जा मूल्य सूचकांक में कोयला (ऑस्ट्रेलिया), कच्चा तेल (ब्रेंट), और प्राकृतिक गैस (यूरोप, जापान, अमेरिका) शामिल हैं।

(iii) धातुओं और खनिजों में लौह अयस्क, एल्यूमीनियम, तांबा, सीसा, निकल, टिन और जस्ता शामिल हैं।

3.29. कुल मिलाकर भारत के लिए अल्पकालिक मुद्रास्फीति दृष्टिकोण सामान्य है। हालांकि, दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता के दृष्टिकोण से, निम्नलिखित विकल्पों का पता लगाया जा सकता है।

- खाद्य तेलों की घरेलू खपत उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ रही है। इस स्वरूप को उलटने और घरेलू कीमतों को स्थिर करने के लिए, सूरजमुखी तथा रेपसीड और सरसों जैसे प्रमुख तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्रित प्रयास करना और राइस ब्रान तेल और मकई के तेल जैसे गैर-पारंपरिक तेलों के महत्व का पता लगाना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के दायरे को ताड़ के तेल के अलावा अन्य प्रमुख तिलहनों तक बढ़ाने की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए।
- भारत दालों में लगातार कमी और इसके परिणामस्वरूप कीमत दबावों का सामना कर रहा है। दालों का उत्पादन देश के कुछ राज्यों और जिलों में केंद्रित है और जैविक तथा अजैविक दबावों के प्रति संवेदनशील है। अधिक जिलों और चावल परती क्षेत्रों में दलहनों, विशेष रूप से मसूर, अरहर और उड़द के तहत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए और

10 विश्व आर्थिक परिदृश्य, अप्रैल 2024, पृष्ठ 36 (विश्व आर्थिक परिदृश्य, अप्रैल 2024: स्थिर लेकिन धीमा: विचलन के बीच लचीलापन (imf.org))

11 विश्व बैंक की अप्रैल 2024 की कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट (कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक (अप्रैल 2024) (worldbank.org))

अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं वाले क्षेत्रों में उड़द और मूंग की ग्रीष्मकालीन खेती को बढ़ावा देने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

- सब्जियों के लिए भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। टमाटर और प्याज जैसी सब्जियों के मूल्यों में लगातार मौसमी उछाल को ध्यान में रखते हुए, ऐसी विशिष्ट फसलों के लिए अनुकूल आधुनिक भंडारण सुविधाओं को विकसित करने में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना और ऐसी सुविधाओं की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है जिनकी सेवाओं की अत्यधिक मौसमी मांग है।
- वित्त वर्ष 24 में विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से निपटने के लिए सरकार द्वारा तेज और प्रभावी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। यह 500 से अधिक केंद्रों पर कीमतों की दैनिक निगरानी पर आधारित था। संभावित रूप से, एक महत्वपूर्ण कारक जो इस तरह की कार्रवाई की तेजी और प्रभावशीलता में सुधार कर सकता है, वह कीमतों और उनके सूचकांकों पर पूर्ण स्पष्टता है। इस मोर्चे पर, निम्नलिखित क्षेत्रों में चल रही कार्रवाई को ठीक करना और तेज करना महत्वपूर्ण हो सकता है।
  - विभिन्न विभागों द्वारा एकत्र किए गए आवश्यक खाद्य पदार्थों के लिए उच्च आवृत्ति मूल्य निगरानी आंकडों को इस तरह से जोड़ा जा सकता है कि खेत से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक प्रत्येक चरण में कीमतों का निर्धारण मात्रात्मक और निगरानी योग्य हो।
  - वस्तुओं और सेवाओं हेतु उत्पादक मूल्य सूचकांक बनाने के लिए चल रहे प्रयासों में तेजी लायी जा सकती है, ताकि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के प्रकरणों को बेहतर समझा जा सके। इसके अलावा, इस बात को ध्यान में रखते हुए एमओएसपीआई के परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, 2022-23 के परिणाम उपलब्ध हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को नए भार और आइटम बास्केट के साथ शीघ्रता से संशोधित करना उचित होगा।

अनुलग्नक 1: कोर मुद्रास्फीति के घटकों के लिए व्युत्पन्न उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का समूह और उनके वजन

					कोर वस्तुएं			
	कोर सेवाएँ		कोर वस्तुएँ		कोर उपभोक्ता गैर-टिकाऊ		कोर उपभोक्ता टिकाऊ	
प्रमुख समूह/उप-समूह	मदों की संख्या	कुल वजन	मदों की संख्या	कुल वजन	मदों की संख्या	कुल वजन	मदों की संख्या	कुल वजन
पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ	–	–	16	2.4	16	2.4	–	–
कपड़े और जूते	2	0.5	25	6.0	–	–	25	6.0
घरेलू सामान और सेवाएं	4	0.9	44	2.9	8	1.7	36	1.2
स्वास्थ्य	4	1.8	3	4.1	2	4.0	1	0.1
परिवहन और संचार	13	4.6	8	4.0	3	2.4	5	1.6
रिक्रिएशन और मनोरंजन	8	1.1	9	0.6	1	0.2	8	0.4
शिक्षा	3	3.5	2	1.0	2	1.0	–	–
व्यक्तिगत देखभाल और उससे संबंधित वस्तुएं	1	0.6	15	3.3	7	2.1	8	1.3
आवास	10	10.1	–	–	–	–	–	–
कुल	**45**	**23.0**	**122**	**24.3**	**39**	**13.7**	**83**	**10.6**

स्रोत: सीएसओ, एमओएसपीआई द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों से गणना की जाती है

नोट: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मुख्य वस्तुओं और सेवाओं का कुल भार 47.3 प्रतिशत है, जो मुख्य वस्तुओं और मुख्य सेवाओं का कुल भारांश है। उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के कुल भार का योग मुख्य वस्तुओं के कुल भारों में होता है।

****

यह पृष्ठ खाली छोड़ दिया गया है

04

CHAPTER

बाह्य क्षेत्रः समृद्धि के बीच स्थिरता

स्थिर मुद्रास्फीति के साथ चल रही भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत का बाह्य क्षेत्र मजबूत रहा। हालांकि प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की कम मांग के कारण व्यापारिक निर्यात कम हो गया, लेकिन सेवाओं का निर्यात बेहतर रहा, जिससे समग्र व्यापार घाटा वित्त वर्ष-23 में 121.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से वित्त वर्ष-24 में 78.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। आयातित वस्तुओं जिसमें कच्चा तेल भी शामिल था की कम कीमतों ने भी मदद की।

व्यापारिक आयात में कमी और सेवा निर्यात में बढ़ोतरी से भारत के चालू खाता घाटे (सीएडी) में सुधार हुआ है। सेवाओं के निर्यात में सॉफ्टवेयर/आईटी सेवाओं ने समग्र निर्यात में वृद्धि को प्रेरित किया है; साथ ही, व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात भी बढ़ रहा है, जिसे भारत के वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के केंद्र के रूप में उभरने से समर्थन मिला है।

भारत वैश्विक मूल्य शृंखला (जीवीसी) को आगे बढ़ा रहा है, सकल व्यापार में जीवीसी से संबंधित व्यापार की हिस्सेदारी 2019 में 35.1 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 40.3 प्रतिशत हो गई है। जीवीसी भागीदारी में सुधार पश्चगामी निवल जीवीसी भागीदारी में वृद्धि में भी परिलक्षित होता है। व्यापार में सुविधा और लाजिस्टिक लागत में कमी संबंधी सरकारी उपायों के कारण, विश्व बैंक के लोजिस्टिक परफॉरमेंस इंडेक्स में 139 देशों में भारत की रैंक छह अंकों में सुधार के साथ 2018 में 44वें से 2023 में 38वें स्थान पर पहुंच गई।

भारत ने वित्त वर्ष-24 में 44.1 बिलियन अमरीकी डालर का सकारात्मक निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) इन्फ्लो दर्ज किया, जो मजबूत आर्थिक विकास, एक स्थिर कारोबारी माहौल और निवेशकों के विश्वास में वृद्धि के कारण है। बढ़ते एफईपीआई इन्फ्लो ने भारतीय रुपये को वित्त वर्ष-24 में 82 से 83.5/अमरीकी डॉलर की सीमा में रखा। वित्त वर्ष-24 में अपने उभरते बाजार साथियों और कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच रुपया सबसे कम अस्थिर मुद्रा के रूप में चमका। भारत के बाह्य क्षेत्र की चुनौतियों के अवरोधक - विदेशी मुद्रा भंडार, स्थायी बाह्य ऋण संकेतक, या बाजार-निर्धारित विनिमय दर, वैश्विक चुनौतियों को कम करने के लिए मौजूद हैं।

भविष्य में, भारत के निर्यात समूह की बदलती संरचना, व्यापार अवसंरचना में वृद्धि, निजी क्षेत्र में गुणवत्ता जागरूकता और उत्पाद सुरक्षा संबंधी चिंताओं में वृद्धि और स्थिर नीतिगत परिवेश से वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

प्रस्तावना

4.1 कोविड-19 महामारी के बाद से, वैश्विक अर्थव्यवस्था को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा रूस-यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में हुए परिवर्तनों और लाल सागर संकट, जिससे कई वस्तुओं की आपूर्ति अव्यवस्था और कई देशों में मुद्रास्फीति में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, लगभग 64 देशों (साथ ही यूरोपीय संघ) के नागरिक, जो विश्व की जनसंख्या का लगभग 49 प्रतिशत है, 2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आव्रजन नीतियों के संदर्भ में नीतिगत अनिश्चितता बढ़ जाती है। विदेशी निवेश, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य को संचालित करते हैं, हाल ही में विकसित दुनिया में उच्च ब्याज दरों और विकसित देशों द्वारा सक्रिय औद्योगिक नीतियों की खोज जैसी अनिश्चितताओं के कारण धीमें हो गए हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त

राज्य अमेरिका के इंफलेशन रिडक्शन ऐक्ट ने न केवल निवेश पूंजी को देश मे ही बनाए रखने में मदद की, बल्कि अन्यत्र से भी पूंजी को आकर्षित किया।[1]

4.2 व्यापार एवं विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के अनुसार, वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)[2] वर्ष 2023 में 2 प्रतिशत घटकर 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2022 में 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। वैश्विक व्यापार भी धीमी गति से चल रहा है, वर्ष 2023 में विश्व वस्तु व्यापार के मूल्य में 5 प्रतिशत की गिरावट आई है। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बाह्य ऋण वर्ष 2012 में 26.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023 में 29.8 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2022 में चालू खाता शेष में घाटे के बाद, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) ने वर्ष 2023 में अधिशेष देखा। ईएमडीई के लिए, चालू खाता शेष वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में अधिशेष में रहा है, हालांकि यह वर्ष 2022 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.6 प्रतिशत है।[3]

4.3 इस पृष्ठभूमि में, अध्याय बाहरी क्षेत्र से संबंधित मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन से संबंधित है। खंड 1 में प्रचलित वैश्विक व्यापार गतिशीलता और व्यापार पर चल रहे भू-राजनीतिक विपरीत परिस्थितियों के प्रभाव पर चर्चा की गई है। खंड 2 भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र पर केंद्रित है, जो उन उद्योगों पर कुछ विशिष्ट केस स्टडी प्रस्तुत करता है जिन्होंने सामान्य रुझानों पर ध्यान देते हुए उल्लेखनीय निर्यात दर्शाया है। यह भारत के कुछ नवीनतम मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के परिणामों को भी दर्शाता है। यह खंड विभिन्न देशों से आयातों के लिए हमारे निर्यात के जोखिम और किसी भी बाहरी अप्रत्याशित आपूर्ति चुनौतियों के मद्देनजर तैयारी की आवश्यकता की कुछ विश्लेषणात्मक समझ प्रस्तुत करता है। खंड 3 में देश में पूंजी प्रवाह की प्रवृत्तियों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है और प्रवृत्तियों से कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की गई है। खंड 4 देश के भुगतान संतुलन (बीओपी) की स्थिति को प्रस्तुत करता है और इसकी तुलना कुछ समकक्ष देशों से करता है। यह हमारे विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर) और अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) को भी दर्शाता है, जो अर्थव्यवस्था को अनिश्चित बाहरी वातावरण से प्रतिकूल रूप से प्रतिरोध करता है। खंड 5 भारत के बाहय ऋण प्रवृत्तियों और इसे कैसे विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंधित किया गया पर आधारित है। खंड 6 प्रमुख चुनौतियों का समाधान की जाने का उल्लेख करते हुए बाहरी क्षेत्र के संभावना के साथ समाप्त होता है।

वैश्विक व्यापार की गतिशीलता में बदलाव

4.4 व्यापार एक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो निवेश, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और जीवन स्तर के बेहतरी को प्रेरित करता बनाता है। वैश्विक व्यापार पैटर्न में पुनः परिवर्तन हो रहे हैं। मेक्सिको, वर्ष 2023 में, चीन और कनाडा को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका का सबसे बड़ा माल व्यापार भागीदार बन गया, जिसका कुल व्यापार 798 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।[4] चीन और अमेरिका के साथ वियतनाम के व्यापार में हाल ही में वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2017 में वियतनाम से अमेरिकी आयात 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना होकर वर्ष 2023 में 114 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसी दौरान, चीन से वियतनाम का आयात 58 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 111 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।[5] अन्य उदाहरण में, यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं अपने ऊर्जा आयात को रूस से नॉर्वे और अमेरिका में स्थानांतरित कर रही हैं। वर्ष 2021 में रूस से यूरोपीय संघ की पाइपलाइन गैस का आयात 150.2 बिलियन क्यूबिक मीटर से घटकर वर्ष 2023 में 42.9 बिलियन क्यूबिक मीटर हो गया।[6] इसी दौरान, अमेरिका से इसकी पाइपलाइन गैस आयात 18.9 बिलियन क्यूबिक मीटर से बढ़कर 56.2 बिलियन क्यूबिक मीटर हो गया। ये बदलाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नई प्रथाओं के उद्भव

1 कैसे अमेरिका ने कोविड के बाद से वैश्विक पूंजी प्रवाह का एक तिहाई हिस्सा जुटायाश, ब्लूमबर्ग, 16 जून 2024 (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-16/how-the-us-mopped-up-a-third-of-global-capital-flows-since-covid & accessed 22 June 2024)

2 UNCTAD वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024-इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट; https://unctad.org/system/files/official&document/wir2024_overview_en.pdf

3 आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस के अनुसार

4 भारत-मेक्सिको व्यापार और वाणिज्यिक संबंध, पैरा 3, https://tinyurl.com/5h4v96jp

5 स्रोत: वियतनाम सीमा शुल्क कार्यालय और अमेरिकी जनगणना ब्यूरो, https://www.customs.gov.vn/index.jsp\pageId=4964, https://www.census.gov/en.html

6 स्रोत: ENTSO-G और Refinitiv पर आधारित यूरोपीय आयोग, https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-gas-supply/#0

जैसे कि 'डिकपलिंग', 'डीरिस्किंग', 'रीशोरिंग', 'नियरशोरिंग', और 'फ्रेंड शेयरिंग' और डी-ग्लोबलाइजेशन की बढ़ती कहानी को दर्शाते हैं।[7]

4.5 एक तर्क यह है कि वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यापार की वृद्धि रुक गई है हालांकि, वैश्विक व्यापार की मंदी इसकी पहले की तेज वृद्धि के बाद एक स्वाभाविक विकास प्रतीत होती है (चार्ट IV.2)।[8] डी-ग्लोबलाईजेशन की प्रवृत्तियां देशों में अत्यधिक विषम हैं। अमेरिका और चीन धीरे-धीरे वैश्विक बाजारों पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं, जबकि यह दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए सच नहीं लगता है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस) के शोध से पता चलता है कि अपनी नीतियों के बावजूद, अमेरिका चीन के इनपुट पर निर्भर है।[9] वास्तव में, मेक्सिको और वियतनाम के माध्यम से व्यापार में वृद्धि चीनी फर्मों द्वारा इन देशों के माध्यम से अपनी आपूर्ति को री-रूट करने (या इन देशों में खुद को स्थापित करके) का परिणाम है। इसके अलावा, संसाधित महत्वपूर्ण खनिजों और एनर्जी ट्रांसिसन के लिए सामग्रियों की आपूर्ति में चीन का प्रभुत्व के कारण दोनों देशों के बीच डिकपलिंग न तो सरल है और न ही इसकी संभावना है।

चार्ट IV.1: वैश्विक वस्तु व्यापार में वृद्धि: वास्तविक और पूर्वानुमान

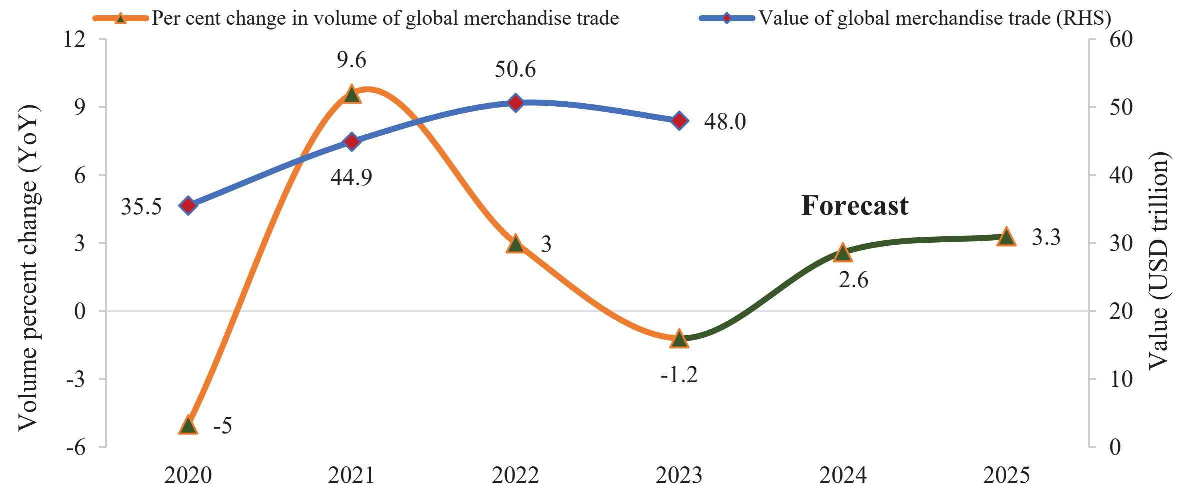

स्रोत: विश्व व्यापार संगठन, यूएनसीटीएडी

4.6 जैसा कि चार्ट IV.1 में देखा जा सकता है, रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद, 2022 में 3 प्रतिशत विस्तार दर्ज करने के बाद 2023 में वैश्विक व्यापार की मात्रा में 1.2 प्रतिशत की गिरावट आई।[10] वर्ष 2023 में विश्व वस्तु व्यापार का मूल्य 5 प्रतिशत से गिर गया, जो कम कीमतों के प्रभाव को दर्शाता है। इस गिरावट की भरपाई मुख्य रूप से वाणिज्यिक सेवाओं के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि से हुई, जो वर्ष 2023 में 9 प्रतिशत बढ़कर 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। वाणिज्यिक सेवाओं के व्यापार में वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय यात्रा की पुनः प्रारंभ करके और डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं में वृदधि के कारण हुई । वर्ष 2023 में डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का वैश्विक निर्यात 9 प्रतिशत बढ़कर 4.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वस्तुओं और सेवाओं के विश्व निर्यात का 13.8 प्रतिशत है।

4.7 वर्ष 2023 में प्रतिकूल व्यापार वातावरण इस वर्ष और अगले वर्ष कुछ हद तक कम होने और वर्ष 2024 और वर्ष 2025 में माल व्यापार में वृद्धि होने की उम्मीद है।[11] विश्व व्यापार की मात्रा वर्ष 2024 और वर्ष 2025 में क्रमशः

7 विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, मित्र-शोरिंग व्यापार के प्रवाह में व्यवधान से बचने के लिए राजनीतिक और आर्थिक रूप से सुरक्षित या कम जोखिम वाले देशों को आपूर्ति श्रृंखलाओं को फिर से शुरू करने को संदर्भित करता है। नियरशोरिंग से तात्पर्य एक कंपनी से है जो व्यवसाय संचालन को पड़ोसी देश, जिसके साथ सीमा साँझ होती हो, में स्थानांतरित करता है। रीशोरिंग तब होती है जब कोई व्यवसाय अपने देश में संचालन को पुनः स्थानांतरित करता है।

8 गोल्डबर्ग, पीके, और रीड, टी. (2023)। क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण हो रहा है? और यदि हां, तो क्यों? और आगे क्या है? (संख्या w31115)। राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो, https://www.nber.org/papers/w31115

9 किउ, एच., शिन, एचएस, और झांग, एलएसवाई (2023)। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के पुनर्गठन का मानचित्रण (संख्या 78)। अंतर्राष्ट्रीय निपटान के लिए बैंक

10 विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी (अप्रैल 2024), https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_outlook24_e.pdf

11 उपरोक्त टिप्पणी 10

2.6 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि व्यापारिक वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। यूएनसीटीएडी द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट में वर्ष 2025 में वैश्विक व्यापार में उछाल के प्रमाण दिखाई दे रहे हैं।[12] रिपोर्ट के अनुसार, 2024 की पहली तिमाही में वैश्विक व्यापार रुझान सकारात्मक हो गए, जिसमें वस्तुओं के व्यापार का मूल्य तिमाही-दर-तिमाही लगभग 1 प्रतिशत और सेवाओं में लगभग 1.5 प्रतिशत बढ़ा। यह वृद्धि मुख्य रूप से चीन (9 प्रतिशत), भारत (7 प्रतिशत) और अमेरिका (3 प्रतिशत) से निर्यात में वृद्धि के कारण हुई। हालांकि, भू-राजनीतिक तनाव और नीतिगत अनिश्चितता किसी भी व्यापार में परिवर्तन के दायरे को सीमित कर सकती है। जबकि कई अर्थव्यवस्थाओं में निर्यात वृद्धि में सुधार होने की उम्मीद है क्योंकि माल की बाहय मांग बढ़ी है, भू-राजनीतिक घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य और ऊर्जा की कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं। इसके अलावा, कई देशों द्वारा अपनाई गई प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहारों से कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला निरंतर से जटिल हो गई है।[13]

4.8 वैश्विक व्यापार के लचीलेपन का परीक्षण दुनिया के दो प्रमुख शिपिंग मार्गों, पनामा नहर और स्वेज नहर में व्यवधानों द्वारा किया जा रहा है। पनामा नहर वैश्विक व्यापार का 6 प्रतिशत और अमेरिका से होने वाले 70 प्रतिशत से अधिक का संचलन करता है। यह वर्तमान में ताजे पानी की कमी के कारण अपनी आंशिक क्षमता पर काम कर रही है, जिस पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लागू रहने की संभावना है। इस बीच, स्वेज नहर के जरिए वैश्विक व्यापार लगभग 12 प्रतिशत हो रहा है एशिया और यूरोप के बीच लगभग एक तिहाई कंटेनर शिपिंग भेजे जा रहे हैं।[14] लाल सागर और केप ऑफ गुड होप के आसपास से यातायात मोड़ ने एशिया-यूरोप की यात्रा में दस दिन की वृद्धि की है, जबकि ईंधन की लागत भी बढ़ रही है। हालांकि वैश्विक शिपिंग लागत पिछले साल के मध्य तक महामारी से पहले के स्तर पर लौट आई हैं, कंटेनर शिपिंग दरें फिर से बढ़ गई हैं। इसके अलावा, स्वेज नहर प्राधिकरण ने पनामा नहर से गुजरने वाले जहाजों के लिए पारगमन शुल्क में 5-15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है।[15]

4.9 मौजूदा भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, भारत को अन्य देशों के साथ अपने मजबूत व्यापार संबंधों से लाभ होने की उम्मीद है, जैसा कि बाद के खंडों में विश्लेषण से पता चलता है। भारत के एशिया, यूरोप और अमेरिका के साथ व्यापक और विविध व्यापारिक संबंध हैं। निम्नलिखित खंड में भारत के व्यापार प्रदर्शन पर चर्चा की गई है।

भारत का व्यापार: वैश्विक उथल-पुथल के बीच लचीलापन

4.10 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने भारत के आर्थिक विकास में योगदान दिया है। समय के साथ-साथ व्यापार बढ़ाने के लिए ठोस सुधारों और सुविधाजनक उपायों के जरिए सकल घरेलू उत्पाद में व्यापार (वस्तुओं एवं सेवाओं) के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ट्रेड ओपननेस इंडिकेटर[16], जो वित्त वर्ष 05 में 37.5 से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 45.9 हो गया, ने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है क्योंकि इसने तुलनात्मक लाभ के माध्यम से संसाधनों के कुशल आवंटन की सुविधा प्रदान की है।जीडीपी में व्यापार की हिस्सेदारी (पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात और कच्चे तेल के आयात को छोड़कर) वित्त वर्ष 2005 में 32.3 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 40.8 हो गई। भारत का व्यापार वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है, जैसा कि नीचे चार्ट IV.2 में दर्शाया गया है।

---

12 यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट, '2024 की पहली तिमाही में वैश्विक व्यापार वृद्धि फिर से शुरू होगी' https://tinyurl.com/3hefazed

13 वर्ल्ड बैंक ब्लॉग दिनांक 22 फरवरी 2024, 'वैश्विक व्यापार लगभग सपाट हो गया है। लोकलुभावनवाद विकास पर भारी पड़ रहा है', https://blogs.worldbank.org/en/voices/global-trade-has-nearly-flatlined-populism-taking-toll-growth

14 उपरोक्त टिप्पणी 10

15 जीईपी इंटेलिजेंस ड्राइव इनोवेशन ब्लॉग 'लाल सागर संकट: कैसे रीरूटिंग शिपिंग लागत को प्रभावित कर रहा है', https://www.gep.com/blog/mind/red-sea-crisis-how-rerouting-is-impacting-shipping-costs

16 व्यापार खुलापन सूचक की गणना नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के योग को लेकर की जाती है।

चार्ट IV.2: बढ़ती व्यापार खुलापन संबंधी संकेतक

स्रोत: विश्व बैंक डेटाबेस, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत
नोट: विश्व के लिए डेटा 2022 तक है, और भारत के लिए 2023 तक है

तालिका IV.1: भारत के व्यापार के प्रमुख पहलू (कैलेंडर वर्षवार)

	2020	2021	2022
निर्यात प्रदर्शन (प्रतिशत में)			
विश्व वस्तु निर्यात में हिस्सेदारी	1.6	1.8	1.8
विश्व वाणिज्यिक सेवा निर्यात में हिस्सेदारी	4.1	4.0	4.4
विश्व वस्तु प्लस सेवा निर्यात में हिस्सेदारी	2.1	2.2	2.4
आयात प्रदर्शन (प्रतिशत में)			
विश्व वस्तु आयात में हिस्सेदारी	2.1	2.5	2.8
विश्व वाणिज्यिक सेवा आयात में हिस्सेदारी	3.3	3.5	4.0
विश्व वस्तु प्लस सेवा आयात में हिस्सेदारी	2.3	2.7	3.0
विश्व व्यापार में भारत का रैंक			
मरचंडाईज वस्तु निर्यात	21.0	18.0	18.0
मरचंडाईज वस्तु आयात	14.0	10.0	9.0
सेवा निर्यात	7.0	8.0	7.0
सेवाओं का आयात	10.0	10.0	8.0

स्रोत: डीजीएफटी, विदेशी व्यापार सांख्यिकी पर मासिक बुलेटिन, अप्रैल 2024

4.11 चार्ट IV.3 दर्शाता है कि भारत वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक निर्यात में बाजार हिस्सेदारी हासिल कर रहा है। वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में इसकी हिस्सेदारी वित्त वर्ष 24 में 1.8 प्रतिशत थी, जबकि यह वित्त वर्ष 16 से वित्त वर्ष 20 के दौरान औसतन 1.7 प्रतिशत थी। इसी तरह, वैश्विक सेवाओं के निर्यात में इसकी हिस्सेदारी वित्त वर्ष 23 में बढ़कर 4.3 प्रतिशत हो गई, जो वित्त वर्ष 16 से वित्त वर्ष 20 के दौरान औसतन 3.3 प्रतिशत थी।

चार्ट IV.3: वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी

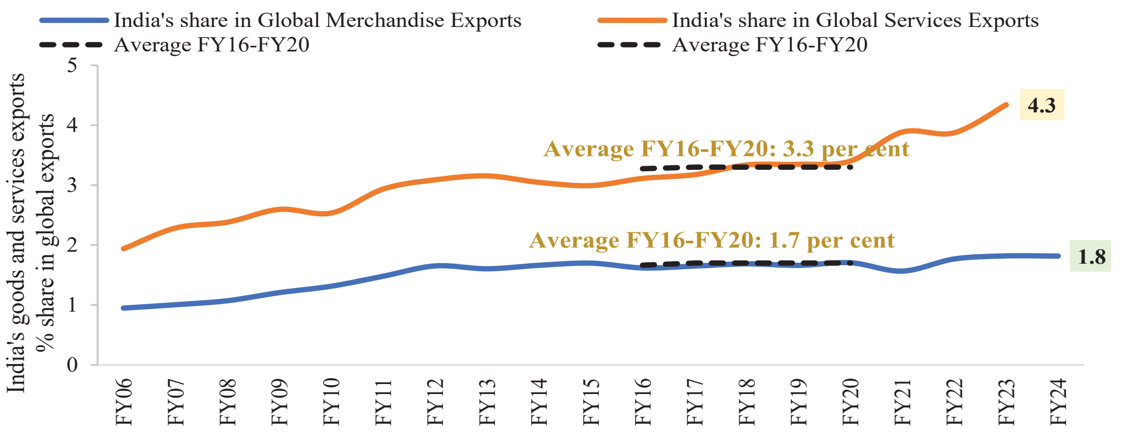

स्रोत: यूएनसीटीएडी

भारत का समग्र व्यापार

4.12 वित्त वर्ष-17 से भारत का कुल निर्यात (वस्तुओं और सेवाओं) लगभग तीन वर्षों से समान आधार पर बढ़ रहा है। हालांकि, वित्त वर्ष-20 में आर्थिक मंदी देखी गई, जो वैश्विक महामारी के प्रकोप से बढ़ गई, जिसने इस प्रवृत्ति पर रोक लगाई। वित्त वर्ष-22 एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। भारत के कुल आयात (वस्तुओं और सेवाओं) में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई है। सकारात्मक वृद्धि वित्त वर्ष-23 में भी देखने को मिली, जिसमें भारत का कुल निर्यात 776 बिलियन अमरीकी डालर को पार कर गया। वित्त वर्ष-22 में 760.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष-23 में कुल आयात भी बढ़कर 898 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। लगातार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, वित्त वर्ष-24 में कुल निर्यात वित्त वर्ष-23 के रिकॉर्ड को पार कर गया, इसमें 0.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और मजबूत घरेलू मांग के बावजूद वित्त वर्ष-24 में कुल आयात में 4.9 प्रतिशत की गिरावट आई। वित्त वर्ष-25 के पहले दो महीनों के दौरान कुल निर्यात बढ़कर 133.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 122.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसी अवधि के दौरान कुल आयात भी 136.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 149. 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिससे कुल व्यापार घाटा 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 16.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

चार्ट IV.4: पिछले दस वर्षों में भारत का समग्र व्यापार प्रदर्शन

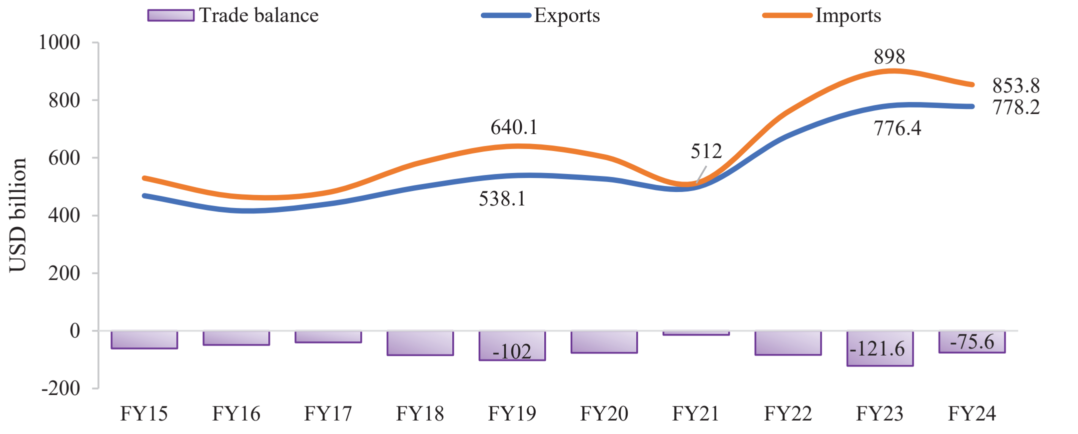

स्रोत: निर्यात आयात डेटा बैंक (वार्षिक), व्यापार सांख्यिकी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सेवाओं में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आरबीआई

पण्य व्यापार: वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना

पण्य निर्यात

4.13 भारत के व्यापारिक निर्यात में वित्त वर्ष-23 की दूसरी छमाही और वित्त वर्ष-24 की पहली छमाही में चल रहे भू-राजनीतिक तनावों के कारण कमी देखी गयी। हालांकि, वित्त वर्ष-24 की दूसरी छमाही में ट्रेंड रिवर्सल हुआ, जिसमें पण्य निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। बॉक्स IV.1 में उन क्षेत्रों पर चर्चा की गई जिनमे पिछले कुछ वर्षों में अपने निर्यात प्रदर्शन के साथ चमकते रहे हैं। बढ़ते निर्यात के साथ, आयात में भी वित्त वर्ष-24 की दूसरी छमाही में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। वित्त वर्ष-24 की दूसरी छमाही में सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने के बावजूद, वित्त वर्ष-23 की तुलना में वित्त वर्ष-24 में वस्तु निर्यात और आयात में कमी देखी गई। कई देशों द्वारा बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किए गए मौद्रिक सख्ती के पश्च प्रभाव के अलावा थी। व्यापारिक निर्यात में गिरावट मुख्य रूप से भारत के प्रमुख निर्यात भागीदारों (विशेष रूप से यूरोपीय संघ, जिसकी वास्तविक जीडीपी 2022 में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2023 में मुश्किल से 0.6 प्रतिशत बढ़ी) में मंदी के कारण कमी। जबकि वित्त वर्ष-24 में आयात की मात्रा में कमी नहीं आई, लेकिन वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में गिरावट के कारण वस्तु आयात का समग्र मूल्य में कमी आयी है । निर्यात की तुलना में आयात में बड़ी गिरावट के कारण, पिछले वर्ष में 264.9 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में वित्त वर्ष -24 में वस्तु व्यापार घाटा 238.3 बिलियन अमरीकी डालर तक सीमित हो गया। गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न और आभूषण व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात ने पिछले कुछ महीनों में निरंतर वृद्धि के साथ लचीलापन दिखाया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष-24 में 320.2 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.5 प्रतिशत अधिक है। इसी समय, गैर-पेट्रोलियम, गैर-रत्न और आभूषण आयात (सोना, चांदी और कीमती धातुओं) में वित्त वर्ष-24 में (-) 3.5 प्रतिशत की कमी देखी गयी।

चार्ट IV.5: भारत का वस्तु व्यापार प्रदर्शन

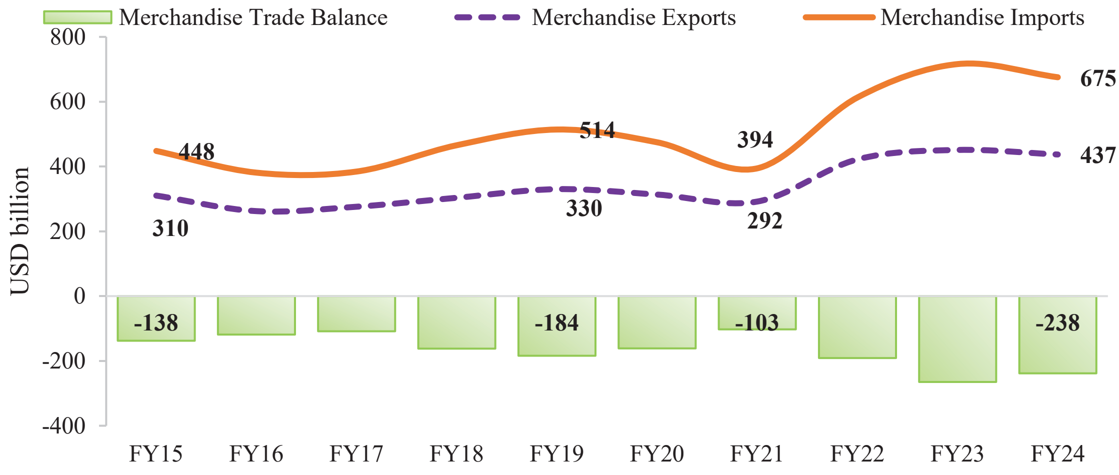

स्रोत: निर्यात आयात डेटा बैंक (वार्षिक), व्यापार सांख्यिकी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

4.14 वित्त वर्ष-25 के पहले दो महीनों उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के दबाव में कमी के कारण वैश्विक निर्यात मांग में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष-25 के के अप्रैल- मई के दौरान भारत का पण्य निर्यात बढ़कर 73.1 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 69.6 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

चार्ट IV.6: विभिन्न वर्गीकरणों में वस्तु निर्यात की संरचना

स्रोतः डीजीसीआई एंड एस[17]

4.15 वित्त वर्ष-23 से वित्त वर्ष-24 तक, विभिन्न वर्गीकरणों में निर्यात की संरचना में बदलाव दिखाई देता है। विशेष रूप से, पण्य निर्यात में पूंजीगत वस्तुओं की हिस्सेदारी वित्त वर्ष-23 में 16.3 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष-24 में 18.9 प्रतिशत हो गई। यह वृद्धि भारत की मशीनरी, उपकरण और उत्पादन प्रक्रियाओं में उपयोग की जाने वाली अन्य टिकाऊ वस्तुओं की बेहतर आपूर्ति को दर्शाती देती है, जो इसकी औद्योगिक क्षमताओं में संभावित विस्तार या उन्नयन को दर्शाती है। इसके विपरीत, पण्य निर्यात में उपभोक्ता वस्तुओं की हिस्सेदारी वित्त वर्ष-23 में 48.9 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष-24 में 47.5 प्रतिशत हो गई, जो प्रत्यक्ष उपभोग के लिए तैयार उत्पादों के निर्यात में मामूली गिरावट को दर्शाती देती है। मध्यवर्ती वस्तुओं की हिस्सेदारी भी 30.2 प्रतिशत से घटकर 28.4 प्रतिशत हो गई।

बॉक्स IV.1: निर्यात बढ़ाने की उत्पाद विशिष्ट सफलता की कहानियाँ

सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों से उत्पाद-विशिष्ट निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सफलता के कुछ कहानियों का उल्लेख नीचे किया गया है: -

खिलौना निर्यातः भारत के खिलौना उद्योग ने लंबे समय से वैश्विक व्यापार परिदृश्य में चुनौतियों का सामना किया है, जो लगातार कई वर्षों से खिलौनों का निवल आयातक रहा है। हालांकि, इस उद्योग द्वारा निर्यात में वर्ष 2023 में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया। वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय डीजीसीआईएस के आंकड़ों के अनुसार, भारत के खिलौना निर्यात ने वृद्धि की प्रवृति रही है, जिसमें वित्त वर्ष-13 और वित्त वर्ष-24 के बीच 15.9 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई है।[18] बढ़ते निर्यात के साथ-साथ घटते आयात ने भारत को खिलौनों के व्यापार में घाटे से अधिशेष राष्ट्र में बदल दिया। एक दशक से अधिक समय से, भारत अपने खिलौनों के आयात के लगभग 76 प्रतिशत के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर था। चीन से खिलौनों के लिए भारत का आयात बिल वित्त वर्ष-13 में 214 मिलियन अमरीकी डालर से घटकर वित्त वर्ष-24 में 41.6 मिलियन अमरीकी डालर हो गया, जिससे भारत के खिलौना आयात में चीन की हिस्सेदारी वित्त वर्ष-13 में 94 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष-24 में 64 प्रतिशत हो गई, जो अंतरराष्ट्रीय खिलौना बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाती है।[19] वर्ष 2014 से वर्ष 2020 की अवधि में, सरकार के केंद्रित प्रयासों के परिणामस्वरूप विनिर्माण इकाइयों की संख्या दोगुनी

17 6-अंकीय एचएस स्तर पर वस्तुओं का वर्गीकरण विश्व एकीकृत व्यापार समाधान (डब्लूआईटीएस) से 'मानक उत्पाद समूहों' और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (यूएनएसडी) से 'व्यापक आर्थिक श्रेणियों (बीईसी संशोधन 5)' से लिया गया है। कुछ अवर्गीकृत वस्तुओं को समान उत्पाद समूहों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कुल मिलाकर, वर्गीकृत वस्तुएँ वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 दोनों में निर्यात समूह का 99.9 प्रतिशत और आयात समूह का 99.8 प्रतिशत कवर करती हैं।

18 व्यापार डेटा एचएस कोड 9503, 9504 और 9505 के लिए रिपोर्ट किया गया है

19 व्यापार डेटा एचएस कोड 9503 के लिए रिपोर्ट किया जाता है, क्योंकि चीन से खिलौनों के आयात में इसका 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है

हो गई, आयातित इनपुट पर निर्भरता 33 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत हो गई, सकल बिक्री मूल्य 10 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ गया, और श्रम उत्पादकता में समग्र वृद्धि हुई।[20]

खिलौना उद्योग के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में 21 विशिष्ट कार्रवाई बिन्दुओं के साथ खिलौनों हेतु एक व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करना, खिलौनों पर आधारभूत सीमा शुल्क में वृद्धि, घटिया आयातों को नियंत्रित करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा प्रत्येक आयात खेप का नमूना परीक्षण, खिलौनों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करना और क्लस्टर आधारित पद्धति के माध्यम से सहायता करना शामिल है। खिलौना निर्यातक राष्ट्र के रूप में भारत के उभरने का श्रेय वैश्विक खिलौना मूल्य श्रृंखला में इसके एकीकरण और संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया जैसे महत्वपूर्ण देशों में घरेलू स्तर पर निर्मित खिलौनों के लिए शुल्क रहित बाजार पहुंच को दिया जा सकता है।[21]

चार्ट IV.7: भारत के खिलौनों के निर्यात और आयात में रुझान

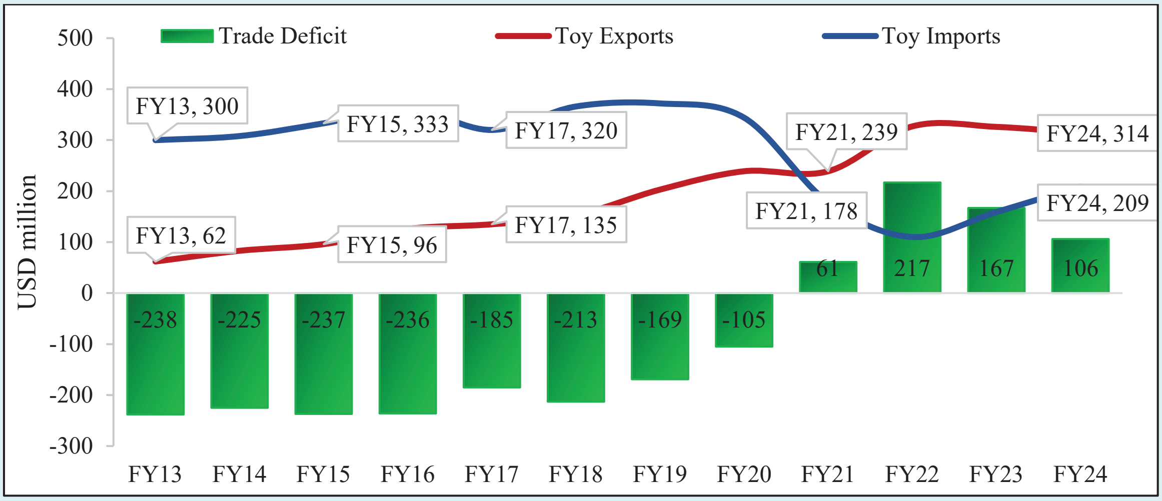

स्रोत: निर्यात आयात डेटा बैंक (वार्षिक), व्यापार सांख्यिकी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

रक्षा निर्यात: भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष-17 में ₹74,054 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष-23 में ₹108,684 करोड़ हो गया, जिससे रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिला।[22] वर्ष 2015 और वर्ष 2019 के बीच, भारत ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक होने का गौरव प्राप्त किया। हालाँकि, यह परिस्थिति बदल गयी है। भारत अब हथियार आयातक से पारगमन कर रहा है और शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों की सूची में एक स्थान पाया है। निजी क्षेत्र और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) सहित रक्षा उद्योग ने अब तक के सबसे अधिक रक्षा निर्यात को प्राप्त करने के लिए जबरदस्त प्रयास किए हैं। इसके अलावा, रक्षा निर्यातकों को जारी किए गए निर्यात प्राधिकारों की संख्या में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष-23 में 1,414 निर्यात प्राधिकारों से, संख्या वित्त वर्ष-24 में बढ़कर 1,507 हो गई है। लगभग 100 घरेलू कंपनियां रक्षा उत्पादों और उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्यात कर रही हैं, जैसे डोर्नियर -228 जैसे विमान, आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर, रडार, सिमुलेटर और बख्तरबंद वाहन, लगभग 100 घरेलू कंपनियों द्वारा निर्यात किए जा रहे हैं।

रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने पिछले दस वर्षों में कई नीतिगत पहल की हैं। निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और उद्योग के अनुकूल बनाया गया है, जिसमें एंड-टू-एंड ऑनलाइन निर्यात प्राधिकार देरी को कम करता है और व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा, आत्मनिर्भर भारत पहल ने रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण को प्रोत्साहित करके देश की मदद की है, जिससे लंबे समय में आयात पर निर्भरता कम हुई है।

20 वाणिज्य मंत्रालय की 4 जनवरी 2024 की पीआईबी विज्ञप्ति, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1993109
21 उपरोक्त
22 रक्षा मंत्रालय की 24 फरवरी 2024 की पीआईबी विज्ञप्ति, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID-2008632

चार्ट IV.8: बढ़ता रक्षा निर्यात

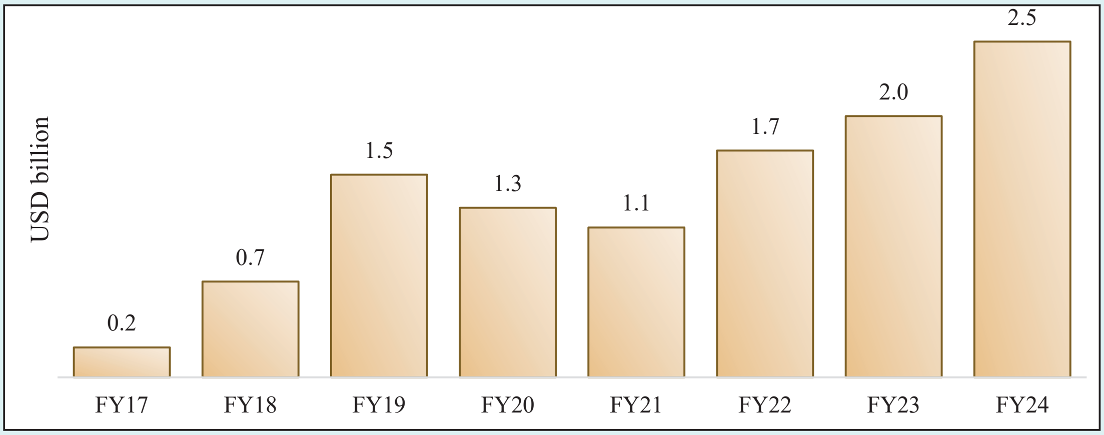

स्रोतः रक्षा मंत्रालय

फुटवियर निर्यातः भारतीय फुटवियर और चमड़ा उद्योग एक महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जक है। चीन के बाद भारत फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है, जो वैश्विक फुटवियर उत्पादन का 13 प्रतिशत और वैश्विक निर्यात का 2.2 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है। भारत नौवां सबसे बड़ा वैश्विक फुटवियर निर्यातक है।[23] DGCIS के अनुसार, भारत का फुटवियर निर्यात वित्त वर्ष-21 में 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष-24 में 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।[24]

चार्ट IV.9: फुटवियर निर्यात में रुझान

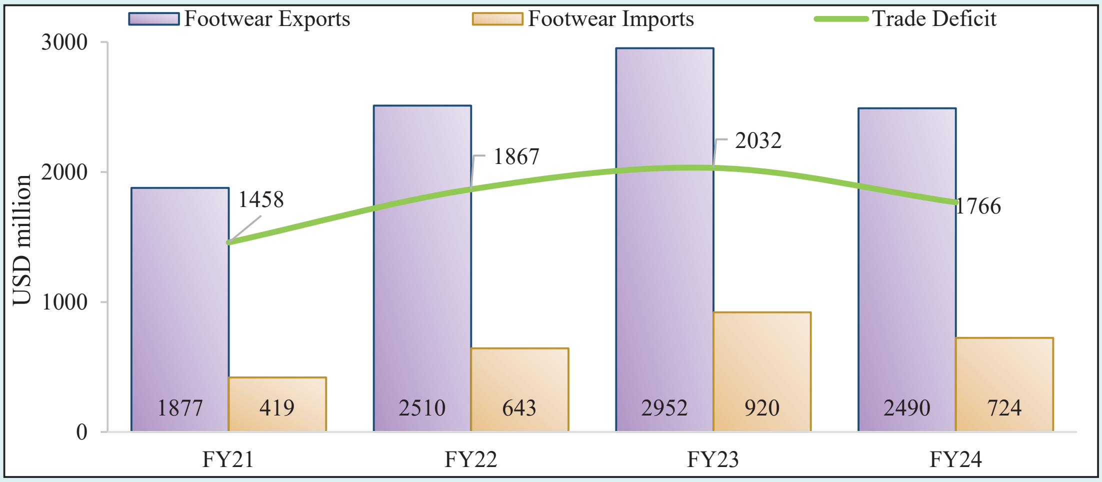

स्रोतः निर्यात आयात डाटा बैंक (वार्षिक), व्यापार सांख्यिकी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

सरकार ने फुटवियर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें भारतीय मानक ब्यूरो के परामर्श के बाद फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए तीन गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करना, कम बार किए जाने वाले अधिकांश परीक्षणों की आउटसोर्सिंग की अनुमति देकर परीक्षण सुविधाओं के निर्माण में छूट, पूरे भारत में फुटवियर के फुटवियर निर्माताओं के बीच जागरूकता पैदा करना शामिल है। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक श्भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रमश् को जारी रखने की मंजूरी दी है। चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत निर्यात संवर्धन योजनाओं और मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम, ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम,

23 जीटीआरआई की रिपोर्ट, 'भारत की फुटवियर क्रांतिः 90 बिलियन डॉलर के भविष्य की ओर अग्रसर', https://tinyurl.com/yvbzadwr.

24 HS Code-6401, 6402, 6403, 6404, 6405 and 6406

इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम आदि के तहत प्रदान किए गए अन्य लाभों का लाभ उठा सकता है।[25] भारतीय फुटवियर बाजार जो 26 बिलियन अमरीकी डालर का है, वर्ष 2030 तक 90 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने की उम्मीद है। यह वृद्धि गैर-चमड़े के जूते की मांग में वृद्धि और चमड़े के जूते के उत्पादन में लघु पैमाने के कुटीर उद्योगों से बड़े कॉरपोरेट्स में संभावित बदलाव से प्रेरित होगी।[26] बदलते बाजार की गतिशीलता, जो मुख्य रूप से खरीदारी की आदतों में बदलाव, तेजी से शहरीकरण, अधिक ब्रांड जागरूकता, खुदरा परिसरों/मॉल के विकास और बढ़ते विवेकाधीन बजट से बढ़ा है इस प्रवृत्ति में योगदान करते हैं।

स्मार्टफोन निर्यात: भारत का घरेलू उत्पादन और स्मार्टफोन का निर्यात लगातार बढ़ रहा है, विशेष रूप से वर्ष 2020 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के लॉन्च के बाद से महत्वपूर्ण बदलाव हासिल किए गए हैं। वित्त वर्ष-20 ने पहली बार घरेलू उत्पादन घरेलू मांग को पार कर लिया, और स्मार्टफोन भारत की शीर्ष निर्यात श्रेणियों में से एक बन गया। निर्यात अब इस क्षेत्र के विकास के लिए प्राथमिक प्रोत्साहन प्रदान करता है। वित्त वर्ष-24 (वर्षानुवर्ष वार-आधार पर) में निर्यात में 42.2 प्रतिशत की वृद्धि ने स्मार्टफोन को छह अंकों की एच एस उत्पाद श्रेणियों में भारत की शीर्ष पांच निर्यात वस्तुओं के रैंक में स्थापित करने में सक्षम बनाया।[27]

चार्ट IV.10: बढ़ता घरेलू उत्पादन, घरेलू मांग और स्मार्टफोन का निर्यात

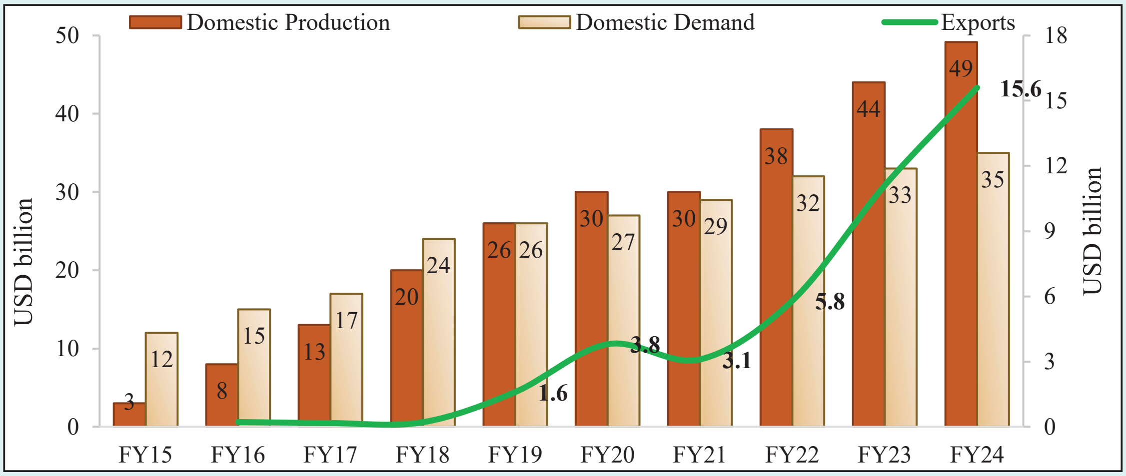

स्रोत: आईसीईए, निर्यात आयात डाटा बैंक (वार्षिक), व्यापार सांख्यिकी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

भारत ने वर्ष 2014 में 23वें सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्यातक से वर्ष 2022 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक भी बन गया।[28] इस उच्च निर्यात वृद्धि के कारण निर्यात और उत्पादन के अनुपात में वृद्धि हुई है, जिसमें वित्त वर्ष-24 में भारत में स्मार्टफोन का निर्यात कुल उत्पादन के 31 प्रतिशत से अधिक रहा है।

4.16 भारत अधिक निर्यात गंतव्यों को जोड़ रहा है जो की निर्यात के क्षेत्रीय विविधीकरण का संकेत है। डीजीसीआईएस डेटा के आधार पर गणना से पता चलता है कि भारत के पण्य निर्यात में शीर्ष 10 देशों की हिस्सेदारी में गिरावट की प्रवृत्ति दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 2000 में 61.9 प्रतिशत से गिरकर वित्त वर्ष 24 में 50.5 प्रतिशत हो गई है। इसके अलावा, शीर्ष 10 देशों के लिए क्षेत्रीय हर्फिंडाहल इंडेक्स (देशों में निर्यात की एकाग्रता का अनुमान)[29] वित्त वर्ष- 2000 में 0.071 से घटकर वित्त वर्ष-24 में 0.046 हो गया।

25 डीपीआईआईटी राज्यसभा अतारांकित प्रश्न 1818 का उत्तर 4 अगस्त 2023 को दिया गया, https://tinyurl.com/yumj98fb

26 ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट (GTRI) की 7 जनवरी 2024 की रिपोर्ट-भारत की फुटवियर क्रांति: 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भविष्य की ओर अग्रसर, https://tinyurl.com/bd7rdub5

27 (एचएस 6 कोड-851713)-स्मार्टफोन

28 आईटीसी ट्रेड मैप पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार

29 क्षेत्रीय/क्षेत्रीय हर्फिंडाल सूचकांक (आरएचआई) =∑Si2, जहां Si क्षेत्रीय विविधीकरण के मामले में भारत की निर्यात टोकरी में देश/क्षेत्र श्पश के हिस्से को संदर्भित करता है

चार्ट IV.11: भारत के निर्यात लक्ष्य

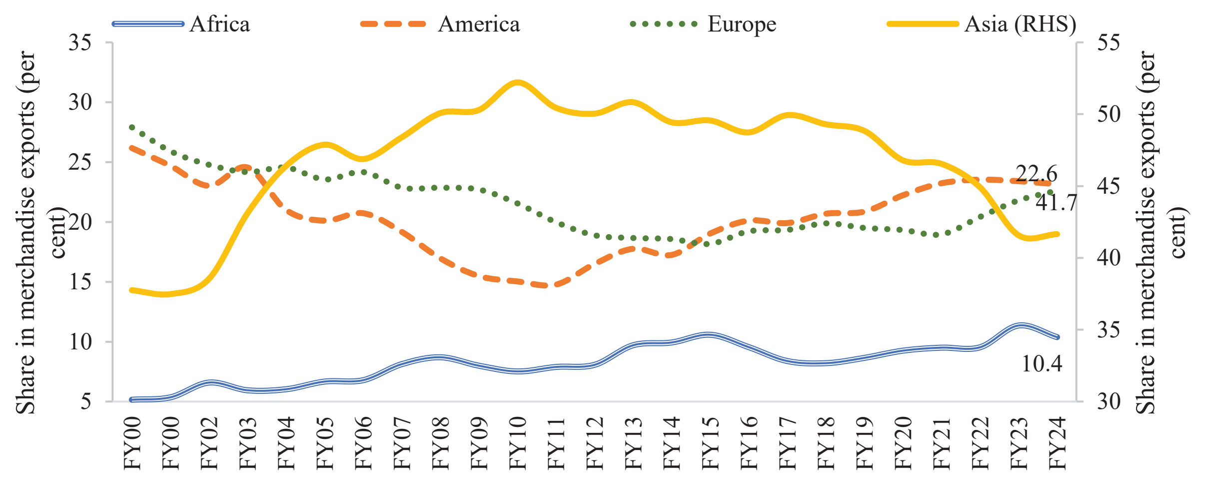

स्रोत: निर्यात आयात डेटा बैंक (वार्षिक), व्यापार सांख्यिकी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

4.17 वित्त वर्ष 2000 के बाद, एशियाई, अफ्रीकी और मध्य पूर्वी राष्ट्र, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, हांगकांग और चीन, यूके, जर्मनी, बेल्जियम आदि जैसे पारंपरिक निर्यात भागीदारों की जगह निर्यात गंतव्यों के रूप में उभरे हैं। विकासशील क्षेत्रों अर्थात् एशिया और अफ्रीका का निर्यात में कुल हिस्सा वित्त वर्ष-2000 में लगभग 42.9 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष-24 में 52 प्रतिशत हो गया। वित्त वर्ष-24 में, यूएई, सिंगापुर, चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रमुख निर्यात भागीदार के रूप में उभरे हैं।

क्षेत्रीय रुझान

4.18 पीओएल और गैर-पीओएल उत्पादों में पण्य निर्यात के विभाजन से पता चलता है कि वित्त वर्ष-24 में दोनों श्रेणियों में निर्यात में गिरावट आई है। पीओएल निर्यातों में गिरावट का मुख्य कारण वैश्विक पेट्रोलियम उत्पाद मूल्यों में गिरावट को माना जा सकता है। भले ही पीओएल निर्यात की मात्रा वित्त वर्ष-23 में 99 मिलियन टन से बढ़कर वित्त वर्ष-24 में 108 मिलियन टन हो गई, लेकिन निर्यात का मूल्य इसी अवधि के दौरान 97.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 13.5 प्रतिशत घटकर 84.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। हालांकि, पिछले छह वर्षों में, पीओएल निर्यात वित्त वर्ष-19 में 46.6 बिलियन अमरीकी डालर से 80.7 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष-24 में 84.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया, इसके साथ ही वैश्विक पीओएल निर्यात (एचएस 2710 से 2713) निर्यात में हिस्सेदारी वर्ष 2018 में 4.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022 में 4.8 प्रतिशत हो गई।[30]

4.19 गैर-POL उत्पादों के तहत इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान और ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात वित्त वर्ष-24 में वर्षानुवर्ष वार के आधार पर बढ़ गया। इसके विपरीत, कृषि और संबद्ध उत्पादों, रसायन, प्लास्टिक और वस्त्रों के निर्यात में गिरावट देखी गई है। पिछले छह वर्षों में, इन श्रेणियों में निर्यात की संरचना बदल गई है। वित्त वर्ष-2019 में इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात सबसे अधिक रहा और कुल निर्यात में इसका योगदान 25.3 प्रतिशत रहा। यह प्रवृत्ति बनी रही, वित्त वर्ष-24 में इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 109.3 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया, जिसमें हिस्सेदारी 25 प्रतिशत पर समान बनी रही। कृषि और संबद्ध उत्पादों ने भी स्थिर हिस्सेदारी बनाए रखी। वित्त वर्ष-19 में 36.6 बिलियन अमरीकी डालर से, उनका निर्यात वित्त वर्ष-23 में 52.7 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया, वित्त वर्ष-24 में थोड़ा घटकर 48.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया, और इसका पण्य निर्यात में लगभग 11 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। रासायनिक और प्लास्टिक निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष-19 में 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष-24 में 37.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। मूल्य में इस वृद्धि के बावजूद, उनकी हिस्सेदारी वित्त वर्ष-19 में 9.4 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष-24 में 8.6 प्रतिशत हो गई। कपड़ा क्षेत्र में प्रमुखता में सापेक्ष गिरावट देखी

30 आईटीसी व्यापार मानचित्र पर आधारित

गई। वित्त वर्ष-19 में उनके निर्यात में 37.5 बिलियन अमरीकी डालर से वित्त वर्ष-24 में 34.8 बिलियन अमरीकी डालर की गिरावट के साथ, कुल निर्यात में उनका हिस्सा भी इसी अवधि के दौरान 11.4 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक काफी गिर गया। यह कटौती, भारत के निर्यात ढांचे के भीतर बदलती प्राथमिकताओं और उभरते क्षेत्रों को प्रतिबिंबित करने के अलावा, इस क्षेत्र में अंतर्निहित चुनौतियों को भी प्रतिबिंबित करती है जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।

4.20 विश्व इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत की हिस्सेदारी (एचएस अध्याय 84, 85 और 90 को शामिल करके) वर्ष 2018 में 0.63 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022 में 0.88 प्रतिशत हो गया है।[31] इस प्रकार, भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में वर्ष 2018 में 28वें से बढ़कर वर्ष 2022 में 24वें स्थान पर पहुंच गया। भारत के पण्य निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की हिस्सेदारी वित्त वर्ष-19 में 2.7 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष-24 में 6.7 प्रतिशत हो गई।

4.21 भारत ने ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बनाए रखी। वित्त वर्ष 2019 में 5.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 6.4 प्रतिशत हो गया, निर्यात वित्त वर्ष 2019 में 19.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 27.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

पण्य आयात

4.22 भारत की अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत मजबूत वृद्धि के कारण उच्च घरेलू मांग के बावजूद, वित्त वर्ष-24 में पण्य वस्तुओं का आयात 5.7 प्रतिशत तक संकुचित हो गया, जो वित्त वर्ष-23 में 716 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर वित्त वर्ष-24 में 675.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पण्य आयात में नरमी मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कच्चे तेल और उत्पादों, उर्वरकों, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों और कपड़ा धागे के कपड़े से प्रेरित थी। घरेलू मांग में वृद्धि के कारण, अप्रैल-मई 2024 के दौरान पण्य आयात 106.5 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-मई 2024 के दौरान 116 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

चार्ट IV.12: विभिन्न वर्गीकरणों में व्यापारिक वस्तुओं के आयात की संरचना

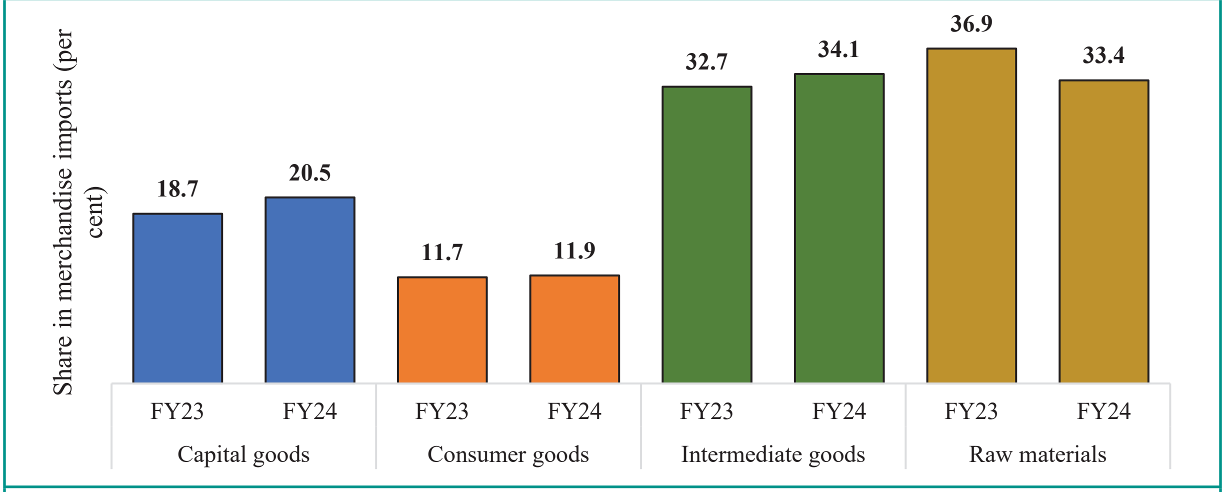

Source: DGCI&S[32]

4.23 वित्त वर्ष-23 और वित्त वर्ष-24 के बीच आयात की संरचना में कई बदलाव देखे जा सकते हैं। पूंजीगत वस्तुओं के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई जो की प्रशसनीय है क्योंकि यह उत्पादन प्रक्रियाओं में उपयोग की जाने वाली मशीनरी, उपकरण और अन्य टिकाऊ वस्तुओं की बढ़ती मांग को इंगित करता है, जो औद्योगिक बुनियादी ढांचे में संभावित निवेश या तकनीकी उन्नयन का सुझाव देता है। पण्य वस्तु आयात में उपभोक्ता वस्तुओं की हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि प्रत्यक्ष उपभोग के लिए तैयार उत्पादों के आयात में स्थिर लेकिन सीमित वृद्धि को दर्शाती है। पण्य आयात में मध्यवर्ती

31 आईटीसी व्यापार मानचित्र पर आधारित

32 उपरोक्त टिप्पणी 17

वस्तुओं का हिस्सा भी वित्त वर्ष-24 में थोड़ा बढ़ गया, जो आगे की विनिर्माण प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाने वाले अर्ध-तैयार उत्पादों, घटकों या सामग्रियों की निरंतर आवश्यकता को दर्शाता है।

निर्यात में चमकते सितारे के रूप में सेवाएं

4.24 अमेरिकी डॉलर टर्म्स में भारत का सेवा निर्यात पिछले 30 वर्षों (वर्ष 1993 और वर्ष 2022 के बीच) में 14 प्रतिशत से अधिक की मजबूत सीएजीआर से बढ़ा, जो भारत के पण्य निर्यात वृद्धि (10.7 प्रतिशत) और विश्व सेवाओं के निर्यात में वृद्धि (6.8 प्रतिशत) से काफी अधिक है। तदनुसार, विश्व सेवा निर्यात में भारत के सेवा निर्यात की हिस्सेदारी वर्ष 1993 में 0.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022 में 4.3 प्रतिशत हो गई है। भारत अब वैश्विक स्तर पर सातवां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है, जो वर्ष 2001 में अपने 24 वें स्थान से अभूतपूर्व वृद्धि की है। भारत दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में दुनिया में 2 वें स्थान पर, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवाओं के निर्यात में 6 वें, अन्य व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में 8 वें, परिवहन सेवाओं के निर्यात में 10 वें और यात्रा सेवाओं के निर्यात में 14 वें स्थान पर है। जैसा कि आरबीआई ने उल्लेख किया है, सेवा निर्यात में स्वस्थ और स्थिर वृद्धि ने देश के व्यापारिक व्यापार घाटे के एक महत्वपूर्ण हिस्से को ऑफसेट करके भारत की बीओपी स्थिति को मजबूत किया है।[33]

चार्ट IV.13: पिछले दस वर्षों में भारत के सेवा व्यापार का उल्लेखनीय प्रदर्शन

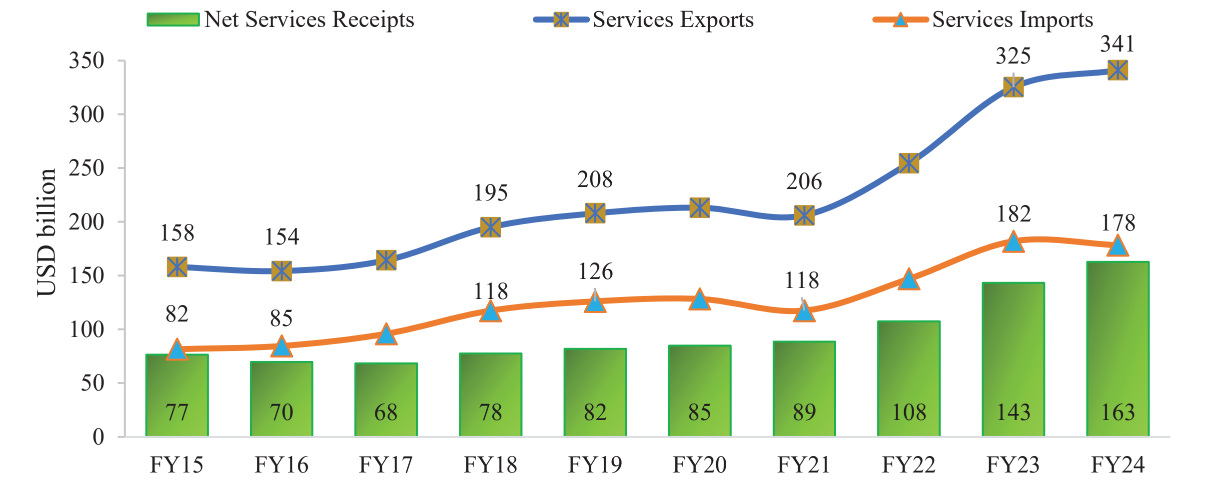

स्रोत: सेवाओं में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आरबीआई

4.25 वैश्विक सॉफ्टवेयर उद्योग की मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के गहरे एकीकरण ने इसकी सेवा निर्यात बास्केट की संरचना में बदलाव किया है। जबकि वर्ष 2000 के दशक की शुरुआत बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) की अवधि थी, जो लागत-कटौती बैक-एंड आईटी सेवाएं प्रदान करती थी, भारत अब ऐसी सेवाओं से परे देखता है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत वर्ष 2010 में कानून, आईटी और प्रबंधन में बैक-एंड सेवाएं प्रदान करने से वर्ष 2020 तक इन क्षेत्रों में अपस्ट्रीम और उच्च-मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए चला गया।[34] रूस-यूक्रेन संघर्ष और वैश्विक मुद्रास्फीति के दबाव वाले वेतन ने वैश्विक खिलाड़ियों को अपने लागत मॉडल को संतुलित करने के लिए अपने बैक-ऑफिस संचालन स्थापित करने के लिए भारत की ओर देखने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के अचानक प्रसार को जन्म दिया। जीसीसी में वृद्धि सेवा बीओपी में परिलक्षित होती है, जिसमें आईटी सेवाओं (46.2 प्रतिशत) के बाद अक्टूबर-दिसंबर 2023 (25.4 प्रतिशत) में सेवा निर्यात में 'अन्य व्यावसायिक सेवाएँ' दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। जीसीसी में वृद्धि सेवा बीओपी में परिलक्षित होती है, आईटी सेवाओं (48 प्रतिशत) के बाद वित्त वर्ष 2014 में सेवाओं के निर्यात में 'अन्य व्यावसायिक सेवाएं' (26 प्रतिशत) दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। समग्र सेवा निर्यात में अन्य व्यावसायिक सेवाओं के बढ़ते योगदान को वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 24

33 भारत के सेवा निर्यात को क्या प्रेरित करता है?' आरबीआई बुलेटिन दिनांक 22 अप्रैल 2024, https://tinyurl.com/4vjerjex
34 एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस 2021, 'वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को बनाए रखना', https://inyurl.com/yfzj6tkm

के बीच 18 प्रतिशत की सीएजीआर प्राप्त करने से दर्शाया गया है। समग्र सेवा निर्यात में सॉफ्टवेयर निर्यात की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2011 में 50 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2014 में 48 प्रतिशत हो गई।[35] बॉक्स IV.2 में जीसीसी के विकास पर चर्चा की गई है।

तालिका IV.2: सेवा व्यापार का लचीला प्रदर्शन (मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्षेत्रों	वित्त वर्ष-23		वित्त वर्ष-24 (अ)	
	Exports	Imports	Exports	Imports
कुल सेवाएं	325.3	182.0	341.1	178.3
अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	1.5	0.2	1.4	0.1
रखरखाव और मरम्मत सेवाएं एन.आई.ई..	0.2	1.9	0.2	1.5
परिवहन	36.1	40.6	29.2	29.3
यात्रा	27.0	28.4	33.7	33.7
निर्माण	3.8	2.8	4.6	2.8
बीमा और पेंशन सेवाएं	3.3	2.3	3.3	2.9
वित्तीय सेवाएं	7.8	5.7	8.1	4.6
बौद्धिक संपदा के उपयोग के लिए प्रभार अर्थात	1.3	10.6	1.6	15.0
दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	152.3	19.8	163.6	20.9
अन्य व्यावसायिक सेवाएं	80.4	59.7	88.6	59.3
व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवाएं	3.9	5.5	4.4	6.3
सरकारी वस्तुएं और सेवाएं एन.आई.के.	0.7	1.0	0.6	1.1
अन्य एन.आई.ई.	7.1	3.4	1.8	0.8

स्रोत: सांख्यिकी, भारत का समग्र भुगतान संतुलन-अमेरिकी डॉलर, आरबीआई
नोट: पी का मतलब अनंतिम है

बॉक्स IV.2: भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों का सफर

जीसीसी की उत्पत्ति: पिछले कुछ वर्षों में, 150 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने जीसीसी स्थापित किए हैं।[36] वर्ष 1985 में बेंगलुरु में अपना कार्यालय स्थापित करके टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा ऑफशोरिंग की अथम शुरुआत के साथ शुरू होकर, भारत जीसीसी विकास के उपरिकेंद्र में होने का एक लंबा सफर तय कर चुका है।[37] 1990 के दशक में, अन्य कंपनियों ने अनुकरण किया, और कई एयरलाइंस और प्रौद्योगिकी कंपनियों ने भारत में अपना परिचालन शुरू किया। इन्हें पहले 'कैप्टिव सेंटर' कहा जाता था और अब इन्हें जीआईसी (ग्लोबल इन-हाउस सेंटर) या जीसीसी के रूप में संबोधित किया जाने लगा है। वर्ष 2012 में, लगभग 760 जीसीसी भारत से बाहर काम कर रहे थे। वर्ष 2016 में, यह संख्या 1000 से अधिक हो गई और मार्च 2023 तक, भारत में 1,600 से अधिक जी.सी.सी. थें।

35 आरबीआई के तिमाही भुगतान संतुलन (बीओपी) आंकड़ों पर आधारित
36 जून 2023: नैसकॉम और जिनोव: भारत वैश्वीकरण की रूपरेखा को पुनर्परिभाषित कर रहा है। https://tinyurl.com/3za5cj3j, https://tinyurl.com/mvcx8tdm
37 https://tinyurl.com/mvcx8tdm

चार्ट IV.14: भारत में जीसीसी की उल्लेखनीय वृद्धि

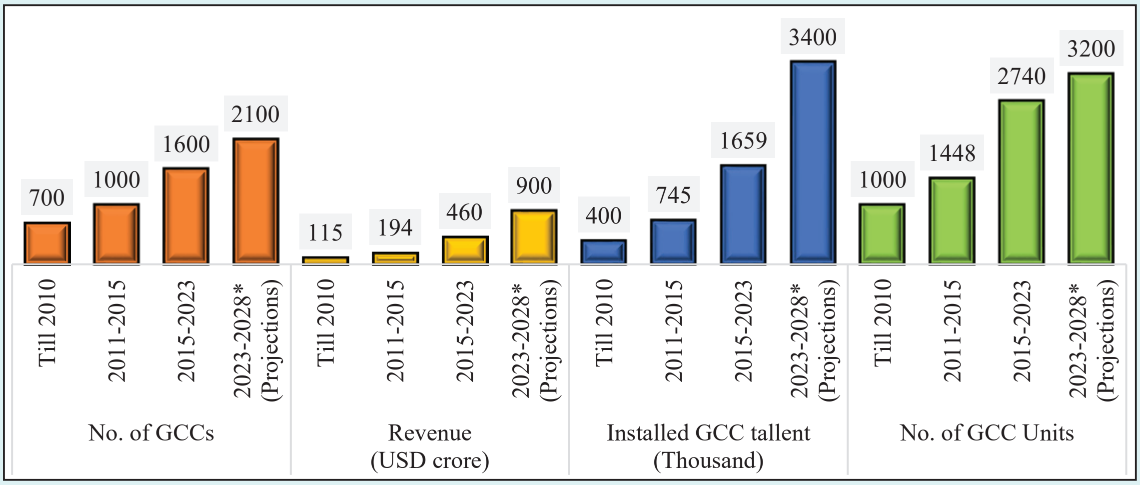

स्रोतः पीडब्ल्यूसी रिपोर्ट 'भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र बाजार को बढ़ाने के लिए छह अनिवार्यताएं'

विभिन्न एजेंसियों ने अनुमान लगाया है कि आने वाले वर्षों में जीसीसी की संख्या बढ़ेगी, जिससे नौकरियां भी उत्पन्न होंगी। पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2028 तक, देश में 2100 जीसीसी होने की ओर अग्रसर है, जिसमें केंद्रों का बाजार आकार 90 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच जाएगा।[38] विजमैटिक के एक अध्ययन के अनुसार, जीसीसी वर्तमान में 32 लाख लोग, मुख्य रूप से इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को रोजगार देते हैं।[39] उन्होंने वर्ष 2023 में 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संयुक्त राजस्व उत्पन्न किया और वर्ष 2030 तक 121 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल राजस्व उत्पन्न करने का अनुमान है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.5 प्रतिशत है। इसमें से 102 बिलियन अमरीकी डालर निर्यात आय का प्रतिनिधित्व करेगा।

जीसीसी की भूमिकाः जीसीसी संचालन, उत्पाद विकास और नवाचार में बीस्पोक सेवाएं प्रदान करते हैं। आज, जीसीसी सभी आईटी, बीपीओ, इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास सेवा लाइनों में काम करते हैं, जटिल कार्य प्रदान करते हैं जिसके लिए व्यावसायिक संदर्भ और अनिवार्यताओं की महत्वपूर्ण समझ की आवश्यकता होती है। उन्होंने एयरोस्पेस, मोटर वाहन, तेल और गैस, स्वास्थ्य सेवा और फार्मा में बढ़ती एकाग्रता के साथ बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, सॉफ्टवेयर, दूरसंचार और अर्धचालक जैसे प्रमुख उद्योग कार्यक्षेत्रों में एक छाप छोड़ी है।

जीसीसी के लिये सरकारी सहायताः 'डिजिटल इंडिया' जैसी विभिन्न पहलों के तहत रणनीतिक हस्तक्षेप और व्यापार करने में आसानी के लिए नीतियों ने जीसीसी के लिए ऑनलाइन अनुमोदन और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है। जीसीसी की स्थापना के लिए विदेशी कंपनियों के लिए सुव्यवस्थित कर नियम और अनुपालन प्रक्रियाएं, लचीले श्रम कानून और तेजी से अनुमोदन के लिए एकल-खिड़की निकासी प्रणाली जैसी पहलों ने व्यापार प्रक्रिया को आसान बना दिया है। बेहतर डिजिटल बुनियादी ढांचा (हाई-स्पीड इंटरनेट, डेटा सेंटर) जीसीसी संचालन के लिए एक वरदान रहा है।

विभिन्न राज्य उच्च क्षमता वाले उद्योगों की पहचान करके जीसीसी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने राज्यों में ऑटो और इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और जीवन विज्ञान जैसे क्षेत्रों में जीसीसी परिदृश्य का विस्तार करने के लिए अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) नीतियां शुरू की हैं। इन नीतियों का उद्देश्य मौजूदा उद्योग उपस्थिति और शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाकर राज्यों में नवाचार हब विकसित करना है। उदाहरण के लिए, तेलंगाना भारत के फार्मा उत्पादन में 30 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है और 1,000 से

38 पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट 'भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र बाजार को बढ़ाने के लिए छह अनिवार्यताएं', https://tinyurl.com/4ehuhu6m tw
39 द इकोनॉमिस्ट (23 मई 2024), 'वैश्विक कंपनियां भारत के श्रमिकों का पहले की तरह उपयोग कर रही हैं', https://tinyurl.com/37psdw3s

अधिक जीवन विज्ञान कंपनियों और 200 से अधिक एफडीए-अनुमोदित साइटों का घर है, जो नवीन और जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करते हैं।[40] कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन (केडीईएम)[41] का उद्देश्य वर्ष 2026 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में राज्य के योगदान को बढ़ाकर 300 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाना है, जो उद्योग के खिलाड़ियों के साथ साझेदारी को गहरा करके और उच्च योगदान प्राप्त करने के लिए राज्य की राजधानी से परे तकनीकी समूहों को विकसित करके तकनीकी क्षेत्रों और स्टार्ट-अप के समग्र विकास को सक्षम करता है। नतीजतन, प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों ने मैसूरु, मैंगलोर और हुबली समूहों में परिचालन शुरू कर दिया है, जिससे 5,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न हुआ है।

वैश्विक प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी: नैसकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, जीसीसी भारत के महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास सेवा प्रदाता समुदाय है, इसके परिपक्व स्टार्ट-अप और इसके सहकर्मी-जीसीसी पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने भारतीय स्टार्ट-अप के साथ सहयोग चलाने के लिए 15 से अधिक इनक्यूबेटर, 40 से अधिक त्वरक और कई भागीदार कार्यक्रम स्थापित किए हैं।[42] हेल्थकेयर और फार्मा जीसीसी ने नई तकनीक तक पहुंचने के लिए स्टार्ट-अप और शिक्षाविदों के साथ साझेदारी में वृद्धि देखी है। जीसीसी ने सहयोग के विभिन्न रूपों की खोज की है, जैसे नवाचार प्रयोगशालाएँ, हैकथॉन और स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर।

टियर-II शहरों में विस्तार: जीसीसी अपने परिचालन का विस्तार करने के लिये टियर-II शहरों का तेजी से मूल्यांकन कर रहे हैं, जो महामारी के दौरान देखे गए रिवर्स माइग्रेशन और ऐसे अपेक्षाकृत कम-प्रवेश वाले बाजारों द्वारा पेश किए गए लागत मध्यस्थता से प्रभावित हैं। इन शहरों में अवसंरचना के विकास पर हाल ही में दिए गए जोर ने भी उनकी अपील को जोड़ा है। सीबीआरई रिसर्च रिपोर्ट[43] के अनुसार, वर्ष 2023 की पहली छमाही के दौरान, लगभग 22 प्रतिशत जीसीसी केंद्र टियर- II शहरों में स्थापित किए गए थे, जो मौजूदा और नई प्रतिभाओं की उपलब्धता से प्रेरित थे।

भारत की बढ़ती वैश्विक मांग: अमेरिका और यूरोप स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियां लंबे समय से अपने क्षमता केंद्र स्थापित कर रही हैं, एशिया प्रशांत क्षेत्र, विशेष रूप से जापान और दक्षिण कोरिया के अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने पिछले कुछ वर्षों में भारत में अपने आरएंडडी/नवाचार केंद्र स्थापित करना शुरू कर दिया है। हालांकि जीसीसी उपस्थिति वाले अन्य देशों की हाल ही में बढ़ोतरी हुई हैं, भारत अपनी पर्याप्त प्रतिभा बंदोबस्ती और लागत लाभ के कारण अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वैश्विक वातावरण में जीसीसी पसंदीदा बना हुआ है।

भविष्य का मार्ग: आज, जीसीसी अपने मूल संगठनों की सफलता में योगदान करते हैं और भारत के आर्थिक विकास को प्रेरित करते हैं। वे देश के सकल घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं, और हिस्सेदारी आगे बढ़ने की उम्मीद है।[44] चूंकि अधिक वैश्विक कंपनी अपने जीसीसी परिचालन स्थापित करने के लिए भारत पर नजर रखते हैं, इसलिए सरकार की उनके प्रवेश को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में जीसीसी के भविष्य में साझेदारी के लिए नए व्यापार मॉडल की पहचान करने, प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाने और दूसरों के बीच विश्वास और डेटा सुरक्षा पर जोर देने आदि के लिए सरकारी समर्थन, जीसीसी के स्थापना को और भी प्रोत्साहित करेगा।

भारत की बढ़ती वैश्विक मूल्य शृंखला (जीवीसी) भागीदारी

4.26 जीवीसी अंतरराष्ट्रीय उत्पादन साझाकरण को संदर्भित करता है, जहां संचालन राष्ट्रीय सीमाओं के पार फैले हुए हैं (सटीक स्थान तक सीमित होने के बजाय) और एक जटिल उत्पाद का उत्पादन करते हैं। जिसे 'हाइपरग्लोबलाइजेशन'

40 तेलंगाना जीवन विज्ञान: विजन 2023, http://tinyurl.com/4ws4a3ub
41 कर्नाटका डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन, https://karnatakadigital.in/about-us/
42 नैसकॉम की 4 अक्टूबर 2021 की रिपोर्ट-भारत में विकसित हो रहा जीसीसी पारिस्थितिकी तंत्र, https://tinyurl.com/4y3zstj5
43 नवंबर 2023 की सीबीआरई रिसर्च रिपोर्ट-भारत के वैश्विक क्षमता केंद्र: एक नए युग की शुरुआत, https://tinyurl.com/4bmadaxy
44 एससीएमपी प्लस ब्लॉग 'सेवा क्षेत्र में तेजी के कारण भारत का 'विश्व के बैक ऑफिस' के रूप में उदय, सुर्खियों में', https://tinyurl.com/3b4wex69

की अवधि कहा जाता है, 2000 के दशक की शुरुआत में दुनिया भर में तेजी से जीवीसी विस्तार देखा गया। इससे व्यापार में घातीय लाभ, आपूर्ति श्रृंखला लागत में कमी और राष्ट्रों में व्यापार में गहरे अंतर्संबंध पैदा हुए। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद 'हाइपरग्लोबलाइजेशन'[45] से 'स्लोबैलाइजेशन'[46] में एक नाटकीय बदलाव आया। GVC के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं के बारे में चिंताओं को चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध, COVID.19 महामारी और रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसे झटकों के साथ और बढ़ा दिया गया। हाल ही में, इस प्रवृत्ति में उलटफेर दिखना शुरू हो गया है। विश्व व्यापार संगठन की जीवीसी विकास रिपोर्ट 2023[47] जीवीसी में सुधार को प्रदर्शित करती है, जो विदेशी निर्यात इनपुट की हिस्सेदारी में वृद्धि और दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ी हुई भागीदारी दरों से रेखांकित होती है।

4.27 वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप, भारत की जीवीसी भागीदारी जीएफसी से पहले 1990 और 2000 के दशक में लगातार बढ़ी, जिसके बाद इसमें गिरावट शुरू हो गई। उदाहरण के लिए, भारत के निर्यात में विदेशी मूल्य वर्धित सामग्री 1995 में 10 प्रतिशत से बढ़कर 2009 में 22 प्रतिशत हो गई (ब्रिक्स देशों में चीन के बाद दूसरी सबसे अधिक),[48] जो उत्पादन के बढ़ते विखंडन और जीवीसी में एकीकरण को दर्शाती है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के वर्षों में देखी गई खामोशी के बाद, भारत की जीवीसी भागीदारी पीएलआई, डिस्ट्रिक्ट्स ऐज एक्सपोर्ट्स हब (डीईएच) पहल योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए गए प्रोत्साहनों की बदौलत फिर से बढ़ने लगी है। बॉक्स IV.3 में भारत की जीवीसी भागीदारी की प्रवृत्ति और क्षेत्रीय संरचना में बदलाव पर विस्तार से चर्चा की गई है। बॉक्स IV.4 में डीईएच की सफलता के वृताँतों पर प्रकाश डाला गया है।

4.28 भारत की बढ़ी हुई वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भागीदारी का प्रमाण भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान और खिलौने, ऑटोमोबाइल और घटक, पूंजीगत सामान और अर्धचालक विनिर्माण में विदेशी फर्मों द्वारा किए गए बढ़ते निवेश में परिलक्षित होता है। भारत का बड़ा घरेलू उपभोक्ता बाजार यहां व्यवसाय स्थापित करने वाली फर्मों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण है। उदाहरण के लिए, Apple ने FY24 में अपने वैश्विक पचेवदमे का 14 प्रतिशत भारत में असेंबल किया। फॉक्सकॉन ने घटकों के लिए नए विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में निवेश किया।

4.29 आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव का प्राथमिक लाभार्थी एशिया है। उत्पादन सुविधाओं की स्थापना या विस्तार के संबंध में भारत में फर्मों (130 में से 28 फर्म) की ओर से सबसे अधिक रुचि देखी गई है, जिसके बाद वियतनाम, मैक्सिको, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया का स्थान है।[49]

बॉक्स IV.3: भारत की जीवीसी भागीदारी और क्षेत्रीय संरचना में परिवर्तन की प्रवृत्ति

विश्व व्यापार संगठन के विश्व एकीकृत व्यापार समाधान (डब्लूआईटीएस) डेटाबेस से पता चलता है कि भारत का जीवीसी से संबंधित व्यापार वर्ष 2010 में 62.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लगभग चार गुना बढ़कर वर्ष 2022 में 233.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।[50] भारत की जीवीसी भागीदारी को चलाने वाले आवश्यक उत्पादों में कोयला और पेट्रोलियम, व्यापार सेवाएं, रसायन और परिवहन उपकरण शामिल हैं। भारत का जीवीसी व्यापार वर्ष 2018 और वर्ष 2022 के बीच 14.6 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा। यह वर्ष 2014 और वर्ष 2018 के बीच 13.3 प्रतिशत और वर्ष 2010 और वर्ष 2014 के बीच 6.9 प्रतिशत के सीएजीआर से अधिक है।

45 सुब्रमण्यन, ए., एट अल. (2023)। व्यापार हाइपरग्लोबलाइजेशन खत्म हो चुका है। जिंदाबाद? पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वर्किंग पेपर, (23-11)। https://www.piie.com/sites/default/files/2023-11/wp23-11.pdf

46 कोनोनेंको, वी., एट अल. (2020)। धीमा करना या ट्रैक बदलना? स्लोबलाइजेशन की गतिशीलता को समझना', https://tinyurl.com/j43864ja

47 https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/gvc_dev_rep23_e.htm

48 ओईसीडी भारत नीति संक्षिप्त दिनांक नवंबर 2014, https://www.oecd.org/india/India-Enhancing-Global-Value-Chain-Participation.pdf

49 नोमुरा ग्लोबल मार्केट रिसर्च 28 May 2024, 'Asia's new flying geese'

50 WITS डेटाबेस के अनुसार, GVC-संबंधित व्यापार उस व्यापार के मूल्य को संदर्भित करता है जो एक से अधिक सीमाओं को पार करता है, https://wits.worldbank.org/gvc/gvc-output.table.html

चार्ट IV.15: सकल व्यापार में जीवीसी से संबंधित व्यापार की बढ़ती हिस्सेदारी[51]

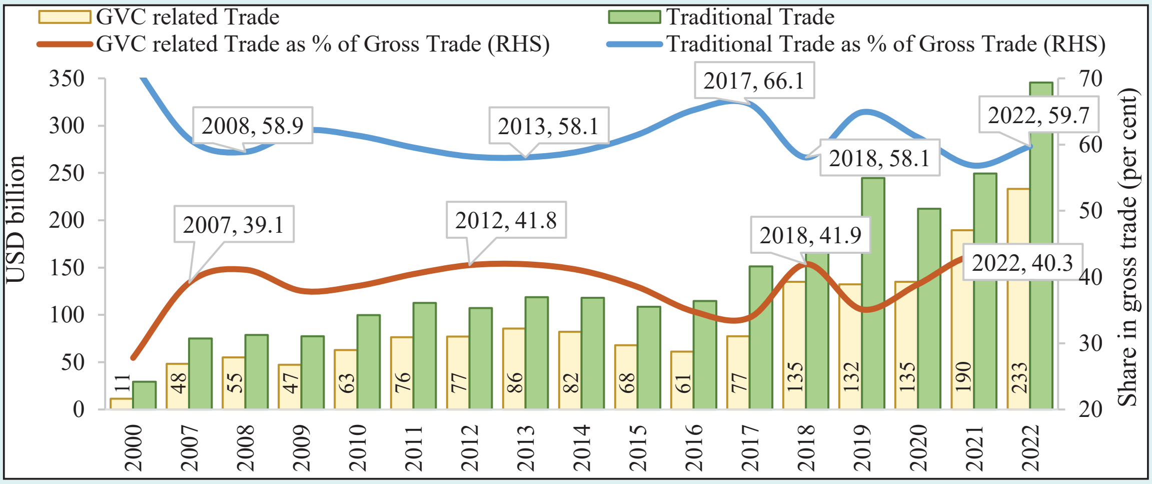

स्रोत: विश्व व्यापार संगठन डब्लूआईटीएस डेटाबेस

इन वर्षों में, भारत के जीवीसी से संबंधित व्यापार की क्षेत्रीय संरचना स्पष्ट रूप से बदल गई है। विनिर्माण क्षेत्र के भीतर, पिछले कुछ वर्षों में कम प्रौद्योगिकी विनिर्माण[52] की हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि मध्यम[53] और उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण[54] की हिस्सेदारी बढ़ रही है। मध्यम प्रौद्योगिकी विनिर्माण में वृद्धि को कोक और पेट्रोलियम, परिवहन उपकरण और प्राथमिक और गढ़े धातुओं जैसे उद्योगों की ओर बदलाव में भी देखा जा सकता है, जिनका भारत के जीवीसी से संबंधित व्यापार में महत्वपूर्ण हिस्सा है।

चार्ट IV.16: जीवीसी से संबंधित व्यापार में विभिन्न विनिर्माण उप-क्षेत्रों की हिस्सेदारी

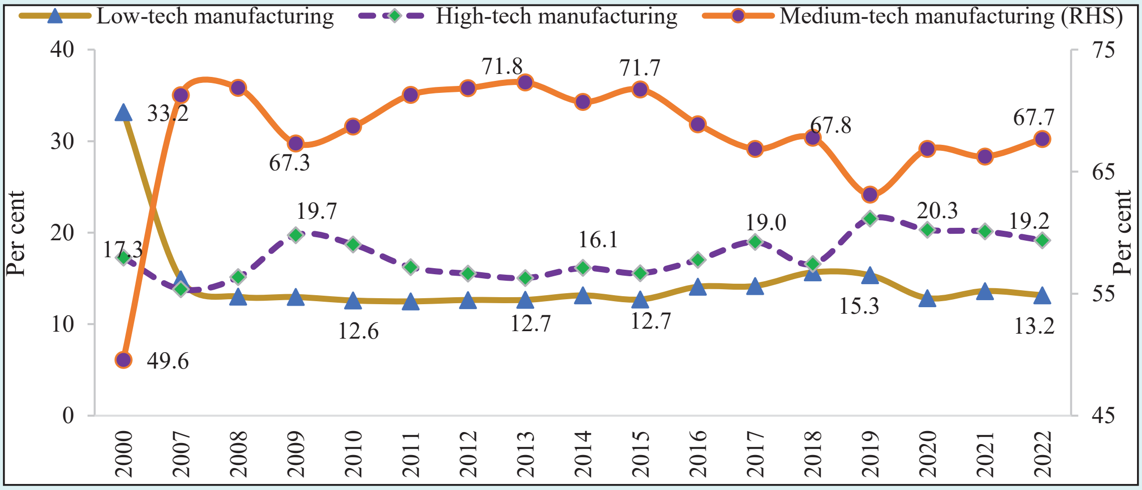

स्रोत: विश्व एकीकृत व्यापार समाधान (डब्लूआईटीएस)

51 सकल व्यापार जीवीसी-संबंधित व्यापार और पारंपरिक व्यापार का योग है। पारंपरिक व्यापार से तात्पर्य उस व्यापार से है जो केवल एक बार सीमा पार करता है

52 निम्न-प्रौद्योगिकी विनिर्माण में भोजन, पेय पदार्थ और तंबाकू शामिल हैं; कपड़ा और कपड़ा उत्पाद; चमड़ा और चमड़े के उत्पाद और जूते; लकड़ी और लकड़ी और कॉर्क और लुगदी के उत्पाद; कागज, कागज उत्पाद; मुद्रण एवं प्रकाशन

53 मध्यम-प्रौद्योगिकी विनिर्माण में कोक, परिष्कृत पेट्रोलियम और परमाणु ईंधन, रसायन और रासायनिक उत्पाद, रबर और प्लास्टिक, अन्य गैर-धात्विक खनिज, मूल धातुएं और निर्मित धातु और मशीनरी शामिल हैं।

54 उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण में विद्युत और ऑप्टिकल उपकरण, परिवहन उपकरण और विनिर्माण, एनईसी और रीसाइक्लिंग शामिल हैं।

आईटी और प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओं के निर्यात से भारत की जीवीसी सेवाओं का निर्यात होता है। इसके अलावा, सेवाओं में जीवीसी भागीदारी धीरे-धीरे कम-मूल्यवर्धित व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ) सेवाओं से उच्च-मूल्य वर्धित सेवाओं तक परिपक्व हो गई है, जैसे कि वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) द्वारा प्रदान की जाती हैं।

चार्ट IV.17: जीवीसी से संबंधित व्यापार में विभिन्न सेवा उप-क्षेत्रों की हिस्सेदारी

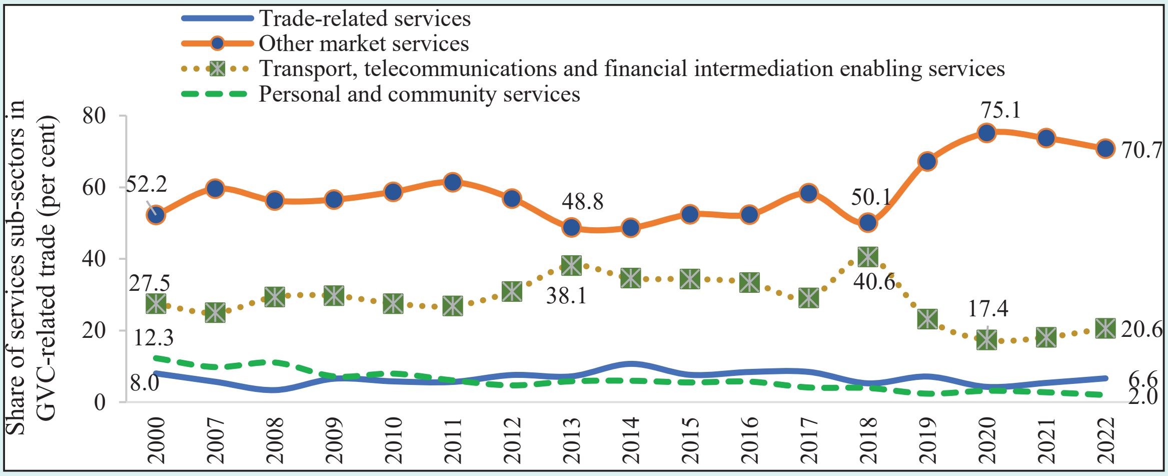

Source: World Integrated Trade Solution (WITS)

पहले, भारत के जीवीसी में उच्च स्तर की आगे की भागीदारी शामिल थी, जिसके परिणामस्वरूप देश के भीतर निर्यात के लिए कम मूल्यवर्धन हुआ था। हालांकि, हाल के वर्षों में, भारत ने डाउनस्ट्रीम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है और दुनिया के बाकी हिस्सों में तैयार माल का निर्यात किया है। इसे शुद्ध रूप से पश्चगामी जीवीसी भागीदारी की हिस्सेदारी में वृद्धि में देखा जा सकता है, जो वर्ष 2019 में 13.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022 में 16.3 प्रतिशत हो गया। खाद्य और पेय पदार्थ, विद्युत और ऑप्टिकल उपकरण और वित्तीय मध्यस्थता जैसे क्षेत्रों में पश्चगामी जीवीसी भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। यहां तक कि सख्त अनुमान से, यानी कोक, परिष्कृत पेट्रोलियम और परमाणु ईंधन को छोड़कर, सकल व्यापार में शुद्ध पश्चगामी भागीदारी का हिस्सा वर्ष 2019 में 12.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022 में 14 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत, खुदरा व्यापार, कोक, परिष्कृत और परमाणु ईंधन, रसायन और प्राथमिक और गढ़े हुए धातुओं जैसे क्षेत्रों में व्यापार में शुद्ध फॉरवर्ड जीवीसी भागीदारी (या अपस्ट्रीम भागीदारी) की हिस्सेदारी 2016 में 19.1 प्रतिशत से घटकर 2022 में 17.6 प्रतिशत हो गई है। पश्चगामी जीवीसी भागीदारी भारत के लिए अच्छा है। प्रोफेसर वीरमणि और धीर के नवीनतम शोध से पता चलता है कि अधिक पश्चगामी जीवीसी भागीदारी के परिणामस्वरूप सकल निर्यात, घरेलू मूल्य वर्धित और रोजगार का उच्च स्तर होता है।

चार्ट IV.18: शुद्ध पिछड़ी जीवीसी भागीदारी की हिस्सेदारी में वृद्धि

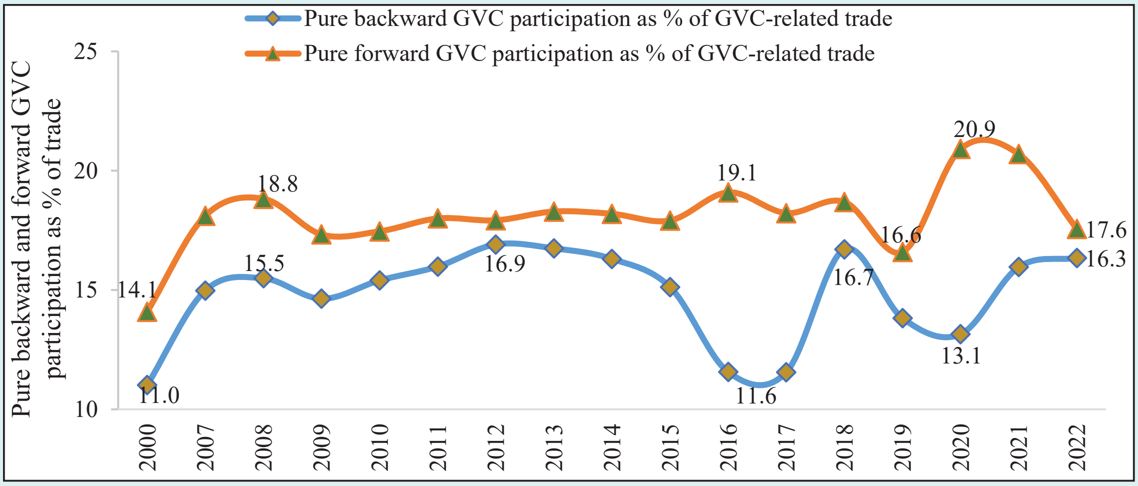

Source: World Integrated Trade Solution (WITS)

इतनी प्रगति के बावजूद, भारत की जीवीसी भागीदारी (जीवीसी से संबंधित व्यापार 2022 में सकल व्यापार के प्रतिशत के रूप में 40.3 प्रतिशत) अभी भी न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका (43.7 प्रतिशत), यूके (47.8 प्रतिशत) और जापान (46.6 प्रतिशत) जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है, बल्कि दक्षिण कोरिया (56.2 प्रतिशत) और मलेशिया (60 प्रतिशत) जैसे एशियाई समकक्षों की तुलना में भी कम है। जीवीसी को और अधिक अपनाने और भागीदारी बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता वाले व्यापार अवसंरचना को विकसित करने, जीवीसी नेटवर्क में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को एकीकृत करने, छोटे व्यवसायों के प्रवेश और निकास के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और व्यापार सुविधा उपायों की दिशा में काम करने की आवश्यकता है।

पूर्व में, भारत के जीवीसी में उच्च स्तर की आगे की भागीदारी शामिल थी, जिसके परिणामस्वरूप देश के भीतर निर्यात के लिए कम मूल्यवर्धन हुआ था। हालांकि, हाल के वर्षों में, भारत ने डाउनस्ट्रीम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है और दुनिया के बाकी हिस्सों में तैयार माल का निर्यात किया है।[55] इसे शुद्ध रूप से पिछड़ी जीवीसी भागीदारी की हिस्सेदारी में वृद्धि में देखा जा सकता है, जो 2019 में 13.8 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 16.3 प्रतिशत हो गया। खाद्य और पेय पदार्थ, विद्युत और ऑप्टिकल उपकरण और वित्तीय मध्यस्थता जैसे क्षेत्रों में पिछड़ी जीवीसी भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। यहां तक कि सख्त अनुमान से, यानी कोक, परिष्कृत पेट्रोलियम और परमाणु ईंधन को छोड़कर, सकल व्यापार में शुद्ध पिछड़ी भागीदारी का हिस्सा 2019 में 12.1 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 14 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत, खुदरा व्यापार, कोक, परिष्कृत और परमाणु ईंधन, जैसे क्षेत्रों में व्यापार में शुद्ध आगे जीवीसी भागीदारी (या अपस्ट्रीम भागीदारी) की हिस्सेदारी 2016 में 19.1 प्रतिशत से घटकर 2022 में 17.6 प्रतिशत हो गई।

पिछड़ी जीवीसी भागीदारी भारत के लिए अच्छा है। प्रोफेसर वीरमणि और धीर[56] के नवीनतम शोध से पता चलता है कि अधिक पिछड़ी जीवीसी भागीदारी के परिणामस्वरूप सकल निर्यात, घरेलू मूल्य वर्धित और रोजगार का उच्च स्तर होता है।

इतनी प्रगति के बावजूद, भारत की जीवीसी भागीदारी (जीवीसी से संबंधित व्यापार 2022 में सकल व्यापार के प्रतिशत के रूप में 40.3 प्रतिशत) अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका (43.7 प्रतिशत), यूके (47.8 प्रतिशत) और जापान (46.6 प्रतिशत) जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है, बल्कि दक्षिण कोरिया (56.2 प्रतिशत) और मलेशिया (60 प्रतिशत) जैसे एशियाई समकक्षों की तुलना में भी कम है। जीवीसी को और अधिक अपनाने और भागीदारी बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता वाले व्यापार बुनियादी ढांचे को विकसित करने, जीवीसी नेटवर्क में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को एकीकृत करने, छोटे व्यवसायों के प्रवेश और निकास के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और व्यापार सुविधा उपायों की दिशा में काम करने की आवश्यकता है।

अंत में, यह ध्यान देने योग्य है कि भारत का जीवीसी विस्तार एक ऐसे युग में हो रहा है जो जीवीसी के लिए विशेष रूप से अनुकूल नहीं है। दुनिया भर के देश व्यापारीवाद को अपना रहे हैं। बहरहाल, व्यापारिकता में वृद्धि के बावजूद, सामूहिक देश के ब्लॉकों के लिए एक दूसरे के साथ गहनता से व्यापार करने की गुंजाइश है। इस संदर्भ में, जीवीसी आत्मनिर्भरता बनाने और इन देश समूहों के बीच साझा व्यापार लाभ को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।

55 किसी देश की अग्रिम भागीदारी का तात्पर्य कच्चे माल और मध्यवर्ती इनपुट (उदाहरण के लिए, यार्न) का उत्पादन और शिपिंग करना है, ताकि अन्य देशों द्वारा आगे की प्रक्रिया और निर्यात किया जा सके (कपड़ा)। इसके विपरीत, पिछड़ी भागीदारी का तात्पर्य आयातित मध्यवर्ती इनपुट (आयातित कपड़े) का उपयोग करके निर्यात किए जाने वाले सामान (परिधान) का उत्पादन करना है।

56 वीरमणि, सी., और धीर, जी. (2022)। क्या विकासशील देशों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भाग लेने से लाभ होता है? भारत से साक्ष्य। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की समीक्षा, 158(4), 1011-1042, https://shorturl.at/jixnb

बॉक्स IV.4: निर्यात हब के रूप में भारतीय जनपद

देश का हर जिला एक छोटे देश के बराबर आर्थिक क्षमता रखता है। वे वैश्विक बाजार में अपनी विशिष्ट पहचान और संभावनाओं का उपयोग करके निर्यात केंद्र बन सकते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए, देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2019 में निर्यात केंद्र के रूप में जिले (डीईएच) पहल शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रत्येक जिले से उत्पादों का चयन, ब्रांडिंग और बिक्री को बढ़ावा देना था। डीईएच पहल के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों से विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना है, जबकि ग्रामीण इलाकों में रुचि और आर्थिक गतिविधि पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करना है। भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 ने भारत के निर्यात प्रयासों में डीईएच की भूमिका को दोहराया।

डीईएच – फोकस / 75 पहल के तहत अपनी हालिया पहल के हिस्से के रूप में, सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लक्षित सहायता प्रदान करने के लिए भारत भर में 75 जिलों की पहचान की है। प्रमुख कार्यक्रमों में वाणिज्य सप्ताह, स्थानीय निर्यातकों को शिक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से कार्यशालाओं की एक श्रृंखला और दुबई एक्सपो 2020 में भागीदारी शामिल है जहाँ भारतीय उत्पादों को वैश्विक दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया गया। एक्सपो की एक उल्लेखनीय सफलता दुबई के सुपरमार्केट में लद्दाख के खुबानी को पेश करना है। इसके अतिरिक्त, समुद्री क्रेता-विक्रेता मीट ने भारतीय समुद्री उत्पाद निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से जोड़ा, जबकि विपणन और ब्रांडिंग कार्यशालाओं ने निर्यातकों को अपने उत्पाद प्रस्तुतिकरण को बेहतर बनाने में मदद की है।

डीईएच पहल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के सभी जिलों को वैश्विक बाजार के लिए कम से कम एक वस्तु विकसित करने और इस प्रकार निर्यात को बढ़ावा देने में शामिल करने के लिए रसद और बुनियादी ढांचे के समर्थन की सुविधा प्रदान करने के लिए एक व्यापक आधार प्रदान करती है। बॉटम-अप दृष्टिकोण भारत को उत्पादन इकाइयों के बीच सीधा संबंध स्थापित करने और राष्ट्रीय निर्यात दायित्वों को पूरा करने में मदद करता है।

सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने राज्य निर्यात संवर्धन समितियों (एसईपीसी) और जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) का गठन करके एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया है। चिन्हित किए गए उत्पादों/सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने में निर्यातकों और निर्माताओं का समर्थन करने के लिए बाधाओं और आवश्यक हस्तक्षेपों की पहचान करने के लिए डीईपीसी द्वारा समय-समय पर जिला निर्यात कार्य योजनाएँ तैयार और अद्यतन की गई हैं। अब तक, 567 जिलों ने अपनी निर्यात कार्य योजनाएँ (डीईएपी) तैयार की हैं। जिलों ने देश भर में 13 क्षेत्रों में फैले 304 अद्वितीय उत्पादों की पहचान की है। उल्लेखनीय रूप से, इन 304 अद्वितीय उत्पादों में से 14 को 100 से अधिक जिलों में रणनीतिक रूप से वितरित सेवाओं के रूप में पहचाना गया है।

सरकार अपनी डीईएच पहल के माध्यम से ई-कॉमर्स निर्यात को भी बढ़ावा दे रही है, जिसमें प्रासंगिक ई-कॉमर्स भागीदारों, निर्यात संवर्धन परिषदों और संबंधित सरकारी विभागों के साथ सहयोग किया जा रहा है। यह पहल एमएसएमई को ई-कॉमर्स निर्यात के बारे में शिक्षित करने, उन्हें वैश्विक स्तर पर बेचने में सक्षम बनाने और उत्पादों की इमेजिंग और डिजिटल कैटलॉगिंग पर प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। इन सहयोगों के परिणामस्वरूप, 2024 की पहली तिमाही के दौरान फरीदाबाद, मुरादाबाद, लुधियाना, जोधपुर, बैंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई, जमशेदपुर और वाराणसी में जिलों के निर्यात आउटरीच कार्यक्रमों में 10 आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रमुख ई-कॉमर्स भागीदारों के साथ आयोजित इन कार्यक्रमों ने भाग लेने वाले व्यवसायों के लिए मूल्यवान सहायता, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सत्र प्रदान किए, जिससे उन्हें वैश्विक बाजारों में सफल होने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और समर्थन मिला।

सरकार इस योजना के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अधिक कदम उठा रही है। उदाहरण के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद) और डीईएच पहल के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक के साथ भागीदारी की है। यह सहयोग एक्जिम बैंक के अध्ययन से निकला है, जिसमें निर्यात क्षमता वाले 59 मध्यम निर्यात जिलों की पहचान की गई है। सहयोग के तहत, डीजीएफटी 20 जिलों में

एक्जिम बैंक के साथ काम करेगा। इन जिलों को एक्जिम बैंक के ग्रिड कार्यक्रम (विकास के लिए जमीनी स्तर की पहल) के माध्यम से सहायता मिलेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करना और सहायता के लिए उपयुक्त लाभार्थियों की पहचान करना है। एक्जिम बैंक का लक्ष्य सहयोगात्मक कार्यान्वयन के लिए चुनौतियों और समाधानों को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करना है।

भारत की वैश्विक व्यापार व्यवस्थाओं का बदलता परिदृश्य

4.30 वैश्विक आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनिश्चितता के एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण चरण से गुजर रहे हैं, जैसा कि ऊपर पैरा 4.4 से 4.8 में बताया गया है। इस संदर्भ में, खुला, समावेशी, पूर्वानुमेय, गैर-भेदभावपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकता है। इसी अर्थ में, भारत निःशुल्क व्यापार समझौतों (एफटीए) को व्यापार उदारीकरण की लिखत और डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का पूरक मानता है। तदनुसार, यह देश लागत-प्रतिस्पर्द्धात्मक तरीके से घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक आयातों हेतु बेहतर स्थिति सुनिश्चित करते हुए अपने निर्यात बाजारों का विस्तार करने के लिए अपने व्यापार भागीदारों/ब्लाकों के साथ जुड़ गया है।

4.31 लगभग 10 वर्षों के अंतराल के बाद, वर्ष 2021 से वर्ष 2024 तक चार नए एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं।[57] ये एफटीए मॉरीशस (फरवरी 2021 में हस्ताक्षरित), संयुक्त अरब अमीरात (फरवरी 2022), ऑस्ट्रेलिया (अप्रैल 2022) और यूरोपीय निःशुल्क व्यापार संघ या ईएफटीए (मार्च 2024) के साथ हस्ताक्षरित समझौता हैं। अंतिम एफटीए को छोड़कर सभी एफटीए लागू हो गए हैं। अधिकांश पूर्वी-एशियाई भागीदारों के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर करने के बाद, ये नए व्यापारिक सहभागिताएं पश्चिमी और अफ्रीकी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और साथ ही इससे संभावित साझेदारों के साथ व्यापार संपूरकता भी होगी।। भारत की युवा जनसांख्यिकी और बढ़ती मध्यमवर्गीय आबादी अपने पश्चिमी एफटीए भागीदारों के लिए आकर्षक बाजार के रूप में उभर रही है।

4.32 एफटीए भागीदार से जुड़ने के महत्वपूर्ण मानदंडों से एक मानदंड यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार भागीदार व्यापार पूरकता के संदर्भ में एक प्राकृतिक भागीदार है। प्राकृतिक व्यापार भागीदारों पर अकादमिक लिट्रेचर उन कारकों की पहचान करता है जो एफटीए भागीदारों के बीच मजबूत व्यापार को बढ़ावा देंगे और और यह गहन आर्थिक एकीकरण को सुगम बनाएगा।। उनमें से प्रारंभिक व्यापार मात्रा, भौगोलिक निकटता और व्यापार पूरकता प्रमुख हैं।[58]

भारत-मॉरीशस सीईसीपीए

4.33 वर्ष 2005 के बाद से, भारत मॉरीशस के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से अग्रणी व्यापारिक भागीदार रहा है। वित्त वर्ष 23 में भारत ने मॉरीशस को 462.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया था, जबकि मॉरीशस ने भारत में 91.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया था, जिससे 554.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल व्यापार हुआ। वित्त वर्ष 06 से वित्त वर्ष 23 तक पिछले 17 वर्षों के दौरान व्यापार में 168 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जब तक कि वर्ष 2019 के मध्य में मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा आपूर्ति अनुबंध समाप्त नहीं किया गया था, तब तक पेट्रोलियम उत्पाद वर्ष 2007 और वर्ष 2019 के बीच भारत के लिए सबसे बड़ी निर्यात वस्तु थे। भारत ने मॉरीशस को जिन चीजों की आपूर्ति की थी उनमें औषध, अनाज, कपास, प्रिम्प, झींगे और पशु मांस आदि शामिल हैं। मॉरीशस ने भारत को जिन चीजों की आपूर्ति की थी उनमें मुख्य रूप से वेनिला, चिकित्सा उपकरण, सुई, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, रद्दी कागज, परिष्कृत तांबा, पुरुषों की सूती कमीजें आदि शामिल हैं।[59]

4.34 भारत और मॉरीशस ने फरवरी 2021 में व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते (सीईसीपीए) पर हस्ताक्षर किए थे। सीईसीपीए किसी अफ्रीकी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है। इस समझौते में वस्तुओं

---

57 2021 से पहले, आखिरी एफटीए फरवरी 2011 में जापान के साथ हस्ताक्षर किया गया था, जो अगस्त 2011 में लागू हुआ।

58 कंडोगन, वाई. (2008)। क्षेत्रवाद बनाम बहुपक्षवाद: यूरो-भूमध्यसागरीय क्षेत्र से प्राकृतिक व्यापार भागीदार सिद्धांत के लिए साक्ष्य? जर्नल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, 23(1), 138–160, https://www.jstor.org/stable/23001115

59 भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय संबंध, https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Mauritius_2023.pdf

का व्यापार, उद्गम के नियम, व्यापारिक सेवाएं, व्यापार में उत्पन्न तकनीकी बाधाएं, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपाय आदि शामिल हैं। इस समझौते में भारत के लिए 310 निर्यात वस्तुएं शामिल हैं, जिनमें खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ, कृषि उत्पाद आदि शामिल हैं। मॉरीशस को भारत के बेहतर बाजार में संसाधित मछली, विशेष शर्करा, बिस्कुट, ताजे फल, जूस, मिनरल वाटर आदि जैसे अपने उत्पादों की आपूर्ति से लाभ होता है।

4.35 व्यापारिक सेवाओं के संबंध में, भारतीय सेवा प्रदाताओं की 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों जैसे कि पेशेवर सेवाओं, कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं, अनुसंधान और विकास, अन्य व्यावसायिक सेवाओं, दूरसंचार, निर्माण, वितरण, शिक्षा, पर्यावरण, वित्तीय, पर्यटन और यात्रा संबंधी, मनोरंजन, योग, श्रव्य-दृश्य सेवाओं और परिवहन सेवाओं से लगभग 115 उप-क्षेत्रों तक पहुंच है। भारत ने 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों में से लगभग 95 उप-क्षेत्र में व्यापारिक सेवाओं की पेशकश की है, जिसमें पेशेवर सेवाएं, अनुसंधान और विकास, अन्य व्यावसायिक सेवाएं, दूरसंचार, वित्तीय, वितरण, उच्च शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पर्यटन और यात्रा संबंधी, मनोरंजन और परिवहन सेवाएं शामिल हैं।[60]

भारत-यूएई सीईपीए

4.36 यूएई को प्राकृतिक व्यापारिक भागीदार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो पिछले दो दशकों से भारत के शीर्ष तीन व्यापार भागीदारों में शामिल है। यूएई रत्न और आभूषण, अनाज और ईंधन के लिए भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार रहा है। यूएई सीईपीए (व्यापक आर्थिक भागीदारी करार) के माध्यम से, इन श्रम-प्रधान उत्पादों को बेहतर पहुंच प्राप्त होगी।[61]

4.37 वित्त वर्ष 24 में भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार 83.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थान है, जिससे वित्त वर्ष 24 में लगभग 35.6 बिलियन अमेरिकी डालर का निर्यात हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात 18 अरब डॉलर के अनुमानित निवेश सहित भारत में आठवां सबसे बड़ा निवेशक भी है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात में अनुमानित भारतीय निवेश लगभग 85 अरब डॉलर है[62]। सीईपीए से हस्ताक्षर के पांच वर्षों के भीतर वस्तुओं में द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डालर तक बढ़ने और सेवाओं में व्यापार को 15 बिलियन अमेरिकी डालर तक बढ़ने की उम्मीद है। भारत-यूएई सीईपीए से लगभग 26 बिलियन अमेरिकी डालर के भारतीय उत्पादों को लाभ होने की संभावना है जो यूएई द्वारा 5 प्रतिशत आयात शुल्क के अध्यधीन हैं। यूएई अन्य अफ्रीकी और यूरोपीय रूझानों में भावी मूल्य वर्धित निर्यात के लिए भारत के पूंजीगत सामान और मध्यवर्ती स्रोत के लिए केंद्र भी बन सकता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी व्यापार करार में पहली बार, विकसित देश विनियामकों, अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसएफडीए), यूनाइटेड किंगडम (यूकेएमएचआरए), यूरोपीय संघ (ईएमए), और जापान (पीएमडीए) द्वारा अनुमोदित उत्पादों के लिए 90 दिनों में भारतीय औषध उत्पादों, विशेष रूप से स्वचालित पंजीकरण और विपणन प्राधिकरण तक पहुंच की सुविधा के लिए औषध पर अलग अनुबंध शामिल किया गया है।

4.38 इसके अतिरिक्त भारत ने पहली बार संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने एफटीए के दायरे में डिजिटल व्यापार को शामिल किया है जो डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स सेवाओं में भारत को लाभ उठाने में मदद करेगा। इस करार में सरकारी खरीद और डेटा उपयोग प्रावधान भी शामिल हैं। सामान्य वित्तीय नियमों और उसके अंतर्गत जारी किए गए आदेशों के प्रावधानों को पूरी तरह से सुरक्षित करते हुए इसमें 'मेक इन इंडिया' आदेश और एमएसएमई वरीयता नीतियों के लिए अधिमान शामिल है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए

4.39 संयुक्त अरब अमीरात के विपरीत, ऑस्ट्रेलिया का भारत के साथ उतना वृहत प्रारंभिक व्यापार परिणाम नहीं था। फिर भी, भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के व्यापार समूह में भारत के लिए पर्याप्त पूरकता है, इस प्रकार इसे एक प्राकृतिक

60 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 31 मार्च 2021 की पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति, https://tinyurl.com/24cjb5sv

61 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 27 मार्च 2022 की पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति, https://pib.gov.in/PressReleasePage-aspx?PRID=1810279.

62 भारत-यूएई सीईपीए (एफएक्यू), प्रश्न 3, https://www.nsez.gov.in/Resources/Trade/FAQs%20on%20CEPA.pdf

व्यापारिक भागीदार के रूप में वर्गीकृत किया गया है।[63] भारत ऑस्ट्रेलिया से संसाधनों और प्राथमिक उत्पादों का आयात करता है और तैयार माल का निर्यात करता है।

4.40 वित्त वर्ष 24 में ऑस्ट्रेलिया भारत का 13वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था और वर्ष 2023 में भारत ऑस्ट्रेलिया का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय वस्तुगत व्यापार वित्त वर्ष 22 में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।[64] भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार करार (ईसीटीए) का यह अनुमान है कि दोनों देशों के लिए व्यापार और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021 में 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 5 वर्षों में 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा।

4.41 इस कारा से भारत के विभिन्न श्रम-प्रधान क्षेत्रों को लाभ मिलने की संभावना है, जो पहले अधिकांश उत्पादों पर आस्ट्रेलिया के 5 प्रतिशत आयात शुल्क के अध्यधीन थे। इसके परिणामस्वरूप शून्य शुल्क पर 98.3 प्रतिशत प्रशुल्क सीमा तत्काल बाजार तक पहुंच होगी, जो मूल्य के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया में भारत का निर्यात 96.4 प्रतिशत है। भारत ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा सेवा निर्यात बाजार है। सेवाओं के लिए बाजार पहुंच के संबंध में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 135 उप-क्षेत्रों की पेशकश की है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 103 उप-क्षेत्रों की पेशकश की है। यह करार कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं, दूरसंचार, निर्माण, स्वास्थ्य और पर्यावरण सेवाओं में निवेश के लिए अवसर प्रदान करेगा।[65]

भारत-ईएफटीए टीईपीए

4.42 भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी करार (टीईपीए) का बल ईएफटीए देशों अर्थात्- स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन के साथ गहन आर्थिक संबंध पर है। यह किसी भी यूरोपीय देश के साथ समझौता करने वाला प्रथम भारतीय एफटीए है। विकसित देशों के इस समूह के साथ एफटीए का सफल समापन विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत है, जो विकसित और विकासशील दोनों देशों में बढ़ते संरक्षणवाद के समय व्यापार उदारीकरण के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। यह एक अभिनव और पूर्ण रूप से संतुलित करार है जो व्यापार और सेवाओं के साथ-साथ द्विपक्षीय निवेश में दो-तरफे व्यापार को जोड़कर रखता है।

4.43 इसके अतिरिक्त, भारत वर्तमान में अपने कुछ व्यापारिक भागीदारों के साथ एफटीए वार्ताओं में भी जुड़ा हुआ है। इन एफटीए वार्ताओं में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं – (i) भारत-यूके एफटीए, (ii) भारत-यूरोपीय संघ एफटीए, (iii) भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए), भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए का निर्माण, (iv) भारत-पेरू व्यापारिक करार, जिसमें माल, सेवाएं और निवेश शामिल हैं, (v) भारत-यूरेशियन आर्थिक संघ (भारत-ईएईयू) एफटीए और (अप) भारत-श्रीलंका आर्थिक और तकनीकी सहयोग करार (ईसीटीए)। सरकार व्यापक अंतर-मंत्रालयी और उद्योग परामर्शों के आधार पर एफटीए की समीक्षा करती है। तदनुसार, इसके मौजूदा निःशुल्क व्यापार करारों, नामत भारत-दक्षिण कोरिया सीईपीए और आसियान-भारत वस्तु व्यापार करार (एआईटीआईजीए) की समीक्षा शुरू कर दी गई है।

व्यापार सुविधा उपायों और लॉजिस्टिक लागत में हुई कमी के लिए सरकार की पहल

4.44 सरकार ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल लॉजिस्टिक लागतों को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात लक्ष्य निर्धारित करना और इन लक्ष्यों की निगरानी करना, सुधारात्मक कदम, अल्पावधिक और मध्यम और दीर्घकालिक निर्यात के लिए निर्यात ऋण बीमा सेवाओं का प्रावधान और बैंकों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) निर्यातकों को किफायती और पर्याप्त निर्यात ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें नए बाजारों का पता लगाने और मौजूदा उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक

63 व्यापार पूरकता सूचकांक यह दर्शाता है कि रिपोर्टर का निर्यात प्रोफाइल किस सीमा तक भागीदार के आयात रुपरेखा से मेल खाता है या उसका पूरक है। उच्च सूचकांक यह सुझाव दे सकता है कि दो देशों को बढ़े हुए व्यापार से लाभ होगा (डब्ल्यूआईटीएस, विश्व बैंक)। वर्ष 2021 में भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया और यूके टीसीआई क्रमशः 60 और 67 प्रतिशत था।

64 भारत ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए-एफएक्यू, https://commerce.gov.in/wp-content/uploads/2022/09/FAQs-for-IndAus-ECTA-2.pdf

65 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 8 जनवरी 2023 को जारी पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति, https://tinyurl.com/286udedz

रूप से विविधता प्रदान करने में सक्षम बनाना आदि शामिल है। सरकार ने तुरंत[66] कस्टम[67], व्यापार सुगमता हेतु सिंगल विंडो इंटरफेस (एसडब्ल्यू आईएफटी)[68] प्री-अराइवल डेटा प्रोसेसिंग, ई-संचित[69], समन्वित सीमा प्रबंधन आदि जैसी पहलों के माध्यम से सहयोग का संवर्धन किया है।

4.45 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी पहलें की हैं। इनमें अन्य वार्ता के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर[70] का चरणबद्ध कार्यान्वयन, भूमि सीमा शुल्क केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी को सक्षम करना, आईएफएससी कोड का ऑनलाइन जमा करना, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का उपयोग और दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रॉनिक सामानों की उपयोग सीमा को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत सेवा आउटसोर्सिंग शामिल हैं। डाक विभाग (डीओपी) ने पीबीई की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और प्रोसेसिंग के लिए पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट ऑटोमेशन सिस्टम विकसित किया है, जिसके अंतर्गत निर्यातक को विदेशी डाकघर में जाने और निर्यात पार्सल प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तनकारी साझेदारी में, सीबीआईसी और डीओपी ने हब और स्पोक मॉडल शुरू किया, निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाया, छोटे पैमाने के निर्यातकों को बढ़ावा दिया और भारत के व्यापक वैश्विक व्यापार डाक नेटवर्क का लाभ उठाया। यह योजना डिजिटल प्रौद्योगिकी और ऐप का उपयोग करते हुए 1.54 लाख डाकघरों के विशाल डाक नेटवर्क को नियंत्रित करती है और डाक सेवाओं के माध्यम से निर्बाध निर्यात मध्यवर्ती संस्थाओं को कम किया है।

4.46 दक्षता को बढ़ावा देने और लॉजिस्टिक्स को कम करने के लिए, सरकार ने क्रमशः अक्टूबर 2021 और सितंबर 2022 में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) की शुरुआत की थी। लॉजिस्टिक्स में सुधार की दिशा में किए गए यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप)[71] और लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक[72] जैसे डिजिटल सुधार अतिरिक्त उपाय हैं। रेलवे ट्रैक विद्युतीकरण, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई) द्वारा जारी समय को कम करने और पत्तन से संबंधित लॉजिस्टिक्स के लिए एनएलपी मरीन के शुभारंभ जैसी पहल भी की गई। एनएलपी के शुरुआत के बाद से, 614 से अधिक उद्योग के प्लेयरों ने यूलिप पर पंजीकरण किया है, 106 निजी कंपनियों ने गैर-प्रकटीकरण करारों (एनडीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, 142 कंपनियों ने यूलिप पर आयोजित किए जाने के लिए 382 उपयोग के मामले प्रस्तुत किए हैं और सितंबर 2023 तक 57 आवेदन लाइव किए गए हैं।[73]

4.47 इन पहलों के परिणामस्वरूप, डिजिटल और संधारणीय व्यापार सुविधा पर एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) के वैश्विक सर्वेक्षण में भारत के निष्पादन में सुधार हुआ है।[74] सर्वेक्षण में, भारत ने वर्ष 2023 में 93.5 प्रतिशत अंक हासिल किए, जबकि वर्ष 2021 में यह 90.3 प्रतिशत था। भारत ने चार प्रमुख क्षेत्रों: पारदर्शिता, औपचारिकताओं, संस्थागत व्यवस्था और सहयोग, और कागज रहित व्यापार में 100 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। इसके अतिरिक्त, देश ने 'व्यापार सुविधा में महिला' घटक के अंक में वर्ष 2021 में 66.7 प्रतिशत से वर्ष

66 'तुरंत' एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है 'शीघ्र'

67 तुरंत कस्टम्स एक संपर्क रहित सीमा शुल्क पहल है, जो सीमा शुल्क अधिकारियों और आयातकों/निर्यातकों/सीमा शुल्क ब्रोकर्स/अन्य हितधारकों के बीच वास्तविक इंटरफेस को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाती है।

68 स्वीफ्ट आयातकों और निर्यातकों को एक ही स्थान पर अपने निकासी दस्तावेज ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है।

69 ई-संचित व्यापारी को मंजूरी प्राप्त करने के लिए सभी सहायक दस्तावेजों को डिजिटल रूप से अपलोड करने की अनुमति प्रदान करता है, जिससे व्यापारी को विभिन्न समाशोधन प्राप्त करने के लिए पीजीए (भाग लेने वाली सरकारी एजेंसियों) से संपर्क करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है

70 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (ईसीएल) ने आयातक, निर्यातक या शुल्क, कर आदि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति को वर्तमान में किए जा रहे लेन-देन-वार भुगतान के बजाय सरकार के पास अग्रिम जमा करने में सक्षम बनाया है, जिसका उपयोग इस अधिनियम या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपनी देनदारियों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।

71 यूएलआईपी को पारदर्शी, एकल-विंडो प्लेटफॉर्म बनाकर भारत में लॉजिस्टिक्स की दक्षता बढ़ाने और लागत को कम करने के लिए तैयार किया गया है जो सभी हितध ारकों को कार्गो संचलन पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर सकता है।

72 लॉजिस्टिक्स आंकड़ा बैंक आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न एजेंसियों में उपलब्ध सूचनाओं को एकीकृत करता है ताकि एकल विंडो के भीतर कंटेनरीकृत एक्जिम लॉजिस्टिक्स से संबंधित विस्तृत वास्तविक समय की जानकारी प्रदान की जा सके।

73 वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 14 सितंबर 2023 की पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति, https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1957407.

74 सर्वेक्षण में डब्ल्यूटीओ व्यापार सुविधा करार (टीएफए) के साथ-साथ लगभग 60 व्यापार सुविधा उपायों का एक समूह शामिल है, जिन्हें ग्यारह उप-समूहों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात: पारदर्शिता; औपचारिकताएं, संस्थागत व्यवस्था और सहयोग; पारगमन सुविधा; कागज रहित व्यापार; सीमा पार कागज रहित व्यापार; एमएसई के लिए व्यापार सुविधा, कृषिगत व्यापार सुविधा, व्यापार सुविधा में महिला, व्यापार सुविधा के लिए व्यापार वित्त और संकट के समय में व्यापार सुविधा प्रदान करना। सर्वेक्षण धारणा आधारित होने के बजाय तथ्य आधारित है। तीन-चरणीय डेटा संग्रह और सत्यापन दृष्टिकोण का आमतौर पर पालन किया जाता है और प्रति दो वर्ष में 6 महीने की अवधि में लागू किया जाता है। कम अंक व्यापार सुविधा उपायों में सुधार दर्शाता है। https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID-1938008

2023 में 77.8 प्रतिशत तक पर्याप्त सुधार देखा गया है, जो व्यापार क्षेत्र में महिला समावेशिता और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

4.48 व्यापार सुविधा उपायों की सफलता का एक अन्य प्रमाण सीबीआईसी द्वारा आयोजित नेशनल टाइम रिलीज स्टडी (2023)[75] में परिलक्षित होता है। इस अध्ययन से यह पता चलता है कि वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में कुल औसत आयात रिलीज समय[76] में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। औसत रिलीज समय में अधिकतम सुधार बंदरगाहों में मुंद्रा (33 प्रतिशत), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी) में हैदराबाद (44 प्रतिशत) और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में तुगलकाबाद (23 प्रतिशत) दर्ज किया गया था।

4.49 लॉजिस्टिक लागत में कमी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स पर्फोर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई)[77] पर भारत की रैंक में सुधार को दर्शाती है, जो 139 देशों में से छह पायदान सुधरकर 2018 में 44वें स्थान की तुलना में वर्ष 2023 में 38वें स्थान पर पहुंच गई। कार्गो ट्रैकिंग की शुरुआत से, विशाखापत्तनम के पूर्वी पत्तन में डवेल टाइम[78] वर्ष 2015 में 32.4 दिनों से घटकर वर्ष 2019 में 5.3 दिन हो गया। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट में भारत की स्थिति 2018 में 44 से बढ़कर 2023 में 22 हो गई, जो इसके आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण प्रयासों के कारण संभव हो पाया है। भारत अवसंरचना स्कोर में पंचम स्थान और लॉजिस्टिक क्षमता और समानता में चार अंक बढ़कर 48 वें स्थान पर पहुंच गया। सरकार वर्ष 2030 तक सूचकांक जिसमें 139 देश शामिल हैं, में शीर्ष 25 देशों में अपना स्थान सुरक्षित रखना चाहती है।[79] विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक (एलपीआई) रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारतीय पत्तनों का 'मेडियन टर्न अराउंड टाइम' 0.9 दिनों तक पहुंच गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका (1.5 दिन), ऑस्ट्रेलिया (1.7 दिन) और सिंगापुर (1.0 दिन) से बेहतर है।[80]

4.50 सागरमाला योजना ने भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 14,500 किलोमीटर लंबे संभावित नौगम्य जलमार्ग और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थान का उपयोग करके पत्तन आधारित विकास को बढ़ावा दिया है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का अनुमान है कि भारत की कुल पत्तन क्षमता वर्ष 2047 तक 2,600 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) से बढ़कर 10,000 एमटीपीए से अधिक हो जाएगी।[81] जलमार्ग से अप्रैल से नवंबर 2022 में 80.4 एमएमटी की तुलना में अप्रैल से नवंबर 2023 में, 86.5 एमएमटी कार्गो की आवाजाही हुई है अर्थात् इसमें 7.5 प्रतिशत की वृद्धि।[82] सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 23 जलमार्गों को चालू करना है।

75 https://old.cbic.gov.in/resources/htdocs-cbec/implmntin-trade-facilitation/national-time-release-study15062023.pdf पर उपलब्ध है। नेशनल टाइम रिलीज स्टडी (एनटीआरएस) 2023 में चार पत्तन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 प्रमुख पत्तन के लिए आयात और निर्यात रिलीज समय को शामिल किया गया है। इस अध्ययन में 4 पत्तन, 6 एसीसीए, 3 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और 2 एकीकृत चेक पोस्ट शामिल हैं; भौगोलिक दृष्टि से अच्छी तरह से वितरित ये पत्तन कुल मिलाकर देश में दर्ज किए गए बिल ऑफ एंट्री का लगभग 80 प्रतिशत और पोत परिवहन बिलों का 70 प्रतिशत हिस्सा हैं।

76 कार्गो रिलीज टाइम आयात के मामले में सीमा शुल्क केंद्र पर कार्गो के आगमन से लेकर घरेलू निकासी के लिए उसके आउट-ऑफ-चार्ज तक और निर्यात के मामले में सीमा शुल्क केंद्र पर कार्गो के आगमन से लेकर वाहक के अंतिम प्रस्थान तक का समय है।

77 एलपीआई एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग उपकरण है, जिसे देशों को व्यापार लॉजिस्टिक पर उनके निष्पादन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने और अपने निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए वे क्या कर सकते हैं, इसकी मदद करने के लिए बनाया गया है, https://lpi.worldbank.org/sites/default/files/2023-04/LPI_2023_report_with_layout.pdf

78 विश्व बैंक एलपीआई शब्दावली के अनुसार, प्रवास समय कंटेनर के आगमन से लेकर प्रस्थान तक एक ही स्थान पर बिताए गए समय को दर्शाता है। प्रवास समय पत्तन, निर्यात, आयात या अंतर्देशीय टर्मिनल सुविधाओं पर लागू होता है। समेकित आयात और निर्यात, ठहरने का समय जहाज से उतारने (आयात) के बाद या जहाज पर कंटेनर के लादने (निर्यात) से पहले पत्तन और मध्यवर्ती अंतर्देशीय स्थानों पर प्रवास समय के योग के रूप में परिभाषित किया गया है।

79 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 17 सितंबर 2022 की पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1860230

80 आपूर्ति श्रृंखला ट्रैकिंग डेटासेट से लीड टाइम डेटा, विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स पर्फोर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के पृष्ठ 37 का परिशिष्ट https://lpi.worldbank.org/sites/default/files/2023-04/LPI_2023_report_with_layou.-pdf

81 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की दिनांक 19 अगस्त 2023 की पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति, https://tinyurl.com/2n68d6em

82 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की दिनांक 2 जनवरी 2024 की पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति, https://tinyurl.com/572j5mnn

चार्ट IV.19: भारत के डवेल टाईम में कमी

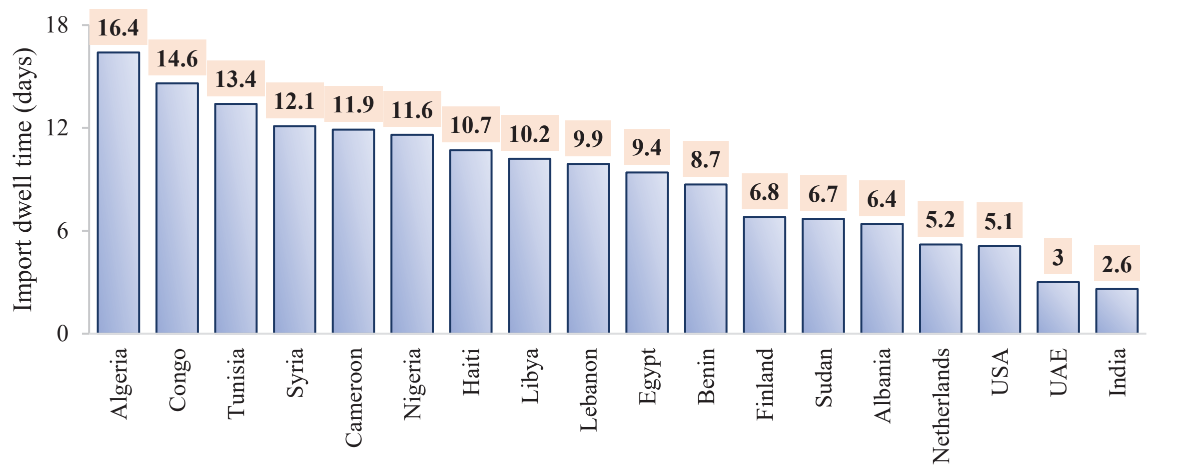

स्रोत: वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफोर्मेंस रिपार्ट: 2023

4.51 माल और सेवा कर (जीएसटी) ने लॉजिस्टिक लागत को कम करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। श्वन नेशन, वन टैक्सश व्यवस्था ने यह सुनिश्चित किया है कि ट्रकों को राज्य की सीमाओं पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता है, जिससे यात्रा का समय 30 प्रतिशत तक कम हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लॉजिस्टिक्स लागत कम हो गई है और ट्रकों की औसत यात्रा की दूरी 300-325 किलोमीटर तक बढ़ गई है जो जीएसटी से पहले 225 किलोमीटर हुआ करती थी।[83] यह बहुत बड़ा मूल्य संवर्धन है, जो व्यापारिक सुगता और देश में विनिर्माण के विकास को जोड़ता है। दिसंबर 2023 के एनसीएईआर अध्ययन से पता चला है कि अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक लागत में वित्त वर्ष 14 और वित्त वर्ष 22 के बीच जीडीपी के 0.8 से 0.9 प्रतिशत अंक की गिरावट आई है।[84]

4.52 भारत के लॉजिस्टिक्स प्रफोर्मेंस में सुधार राज्य स्तर पर भी परिलक्षित होता है। 2023 लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (एलईएडीएस) ने वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2023 में लॉजिस्टिक्स प्रफोर्मेंस सेवाओं, अवसंरचना और नियामक परिस्थिति के सभी तीन पहलुओं में हितधारकों की धारणा में सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है, जो सुविचारित निर्णय लेने और व्यापक विकास के लिए क्षेत्र-विशिष्ट[85] अंतर्दृष्टि प्रदान करके राज्य सरकारों को सशक्त बनाया है। हितधारकों की धारणा में एक सकारात्मक बदलाव का श्रेय पिछले कुछ वर्षों में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अपने लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए शुरू किए गए कई सुधार उपायों को दिया जाता है, जिसमें लॉजिस्टिक्स नीति तैयार करना, सहायक अवसंरचना का विकास और विनियामक सुगमता बढ़ाना शामिल है।

अनुकूल चालू खाता शेष

4.53 चालू खाता दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ किसी देश के अंतरराष्ट्रीय लेनदेन का रिकॉर्ड है। भारत के चालू खाते का प्रमुख घटक पण्य व्यापार है। जैसा कि पैरा 4.14 में चर्चा की गई है, वित्त वर्ष 24 में समग्र व्यापार घाटे को कम करने और प्रेषण में वृद्धि (नीचे पैरा 4.54 देखें) से सीएडी में सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 24 में भारत का सीएडी पिछले वर्ष के दौरान 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 2 प्रतिशत) से घटकर 23.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 0.7 प्रतिशत) हो गया। वित्त वर्ष 2024 में सीएडी में हुए सुधार को वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में

83 जीएसटी पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पुस्तिका, https://morth.nic.in/sites/default/files/Booklet_on_GST.pdf

84 'भारत में लॉजिस्टिक्स लागत-मूल्यांकन और दीर्घकालिक रूपरेखा पर नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट, https://www.ncaer.org/wp-content/uploads/2023/12/NCAER_Report_LogisticsCost2023.pdf

85 लीड्स हितधारकों का सर्वेक्षण है और विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक (एलपीआई) पद्धति का उपयोग करता है। यह राज्यिक एलपीआई, लॉजिस्टिक्स के प्रमुख क्षेत्रों- अवसंरचना, सेवा समयसीमा, पता लगाने की क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मकता, सुरक्षा, परिचालन वातावरण और विनियमन की दक्षता संबंधी बैठकों और ऑनलाइन सर्वेक्षणों की श्रृंखला के आधार पर हितधारक जुड़ाव के लिए मूल्य निर्धारण पद्धति का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। https://drive.google.com/drive/folders/17bWqWyvprnVwxyQUgQYpwl0KhopNuubj\usp=sharing

दर्ज किए गए सीएडी में हुए अधिशेष से समर्थन मिला है, जो व्यापारिक व्यापार घाटे में कमी, निवल सेवा निर्यात में वृद्धि और बढ़ते प्रेषण के कारण हुआ है। अन्य देशों के संबंध में भारत के सीएडी के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत का सीएडी अपेक्षाकृत कम है (चार्ट IV. 21)

चार्ट IV.20: वित्त वर्ष 24 के दौरान सीएडी में सुधार

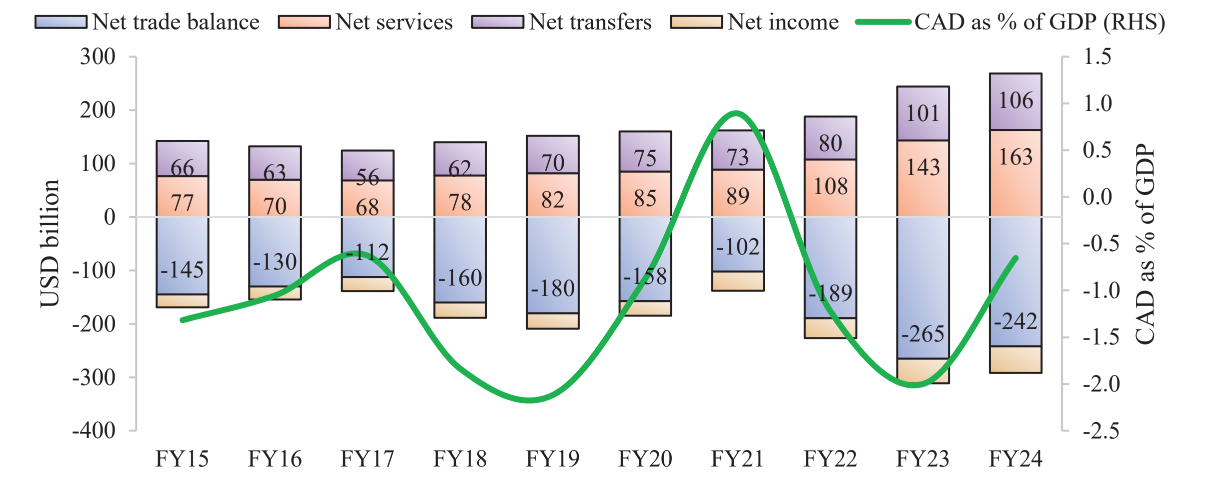

स्रोत: चार्ट संख्या 196, भारत का समग्र भुगतान संतुलन –त्रैमासिक-अमेरिकी डॉलर', बाहरी क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधी सांख्यिकी पुस्तिका, आरबीआई

चार्ट IV.21: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाता शेष: भारत बनाम चुनिंदा देश

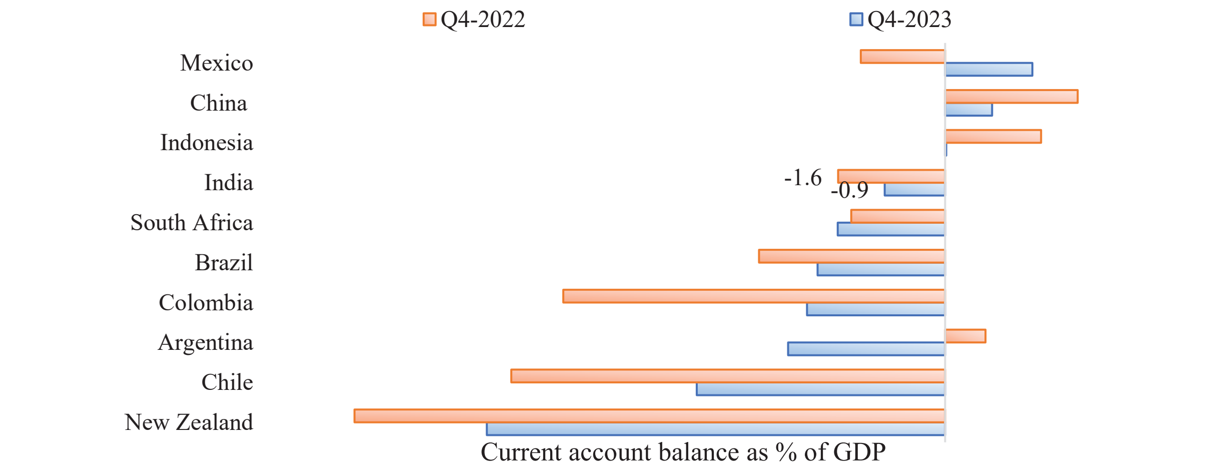

स्रोत: ओईसीडी आर्थिक आउटलुक डेटाबेस 115,

अप्रत्यक्ष

4.54 निवल सेवा प्राप्तियां वित्त वर्ष 23 के दौरान 143.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 162.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जिसका मुख्य कारण सॉफ्टवेयर, यात्रा और व्यावसायिक सेवाओं का बढ़ता निर्यात है। इसी प्रकार, निवल निजी अंतरण प्राप्तियां, जो मुख्य रूप से विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा प्रेषण को दर्शाती हैं, वित्त वर्ष 24 में यह 106.6 बिलियन अमेरिकी डालर थी, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 101.8 बिलियन अमेरिकी डालर थी। निवल सेवा निर्यात और विप्रेषण ने अप्रत्यक्ष खाते पर अधिशेष में योगदान बढ़ाया है, जिसने व्यापारिक व्यापार घाटे को कम किया।

4.55 सेवा निर्यात के बाद विप्रेषण विदेशी वित्तपोषण का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जो सीएडी को कम करने में योगदान देता है और हमेशा बीओपी का स्थायी घटक रहा है। विश्व बैंक के अनुसार, भारत में सबसे बड़ी प्रवासी आबादी है और यह सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है, जिसमें वर्ष 2023 में प्रेषण 120 बिलियन अमेरिकी डालर महत्वपूर्ण उपलब्धी रही है।[86] प्रेषण में वृद्धि मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप जो भारत के कुशल प्रवासियों के लिए सबसे बड़ा गंतव्य स्थल है और अन्य ओईसीडी गंतव्य में घटती मुद्रास्फीति और में सुदृढ़ श्रम बाजारों के कारण हुई है, और साथ ही जीसीसी देशों में कुशल और कम कुशल श्रमिकों की सकारात्मक मांग हैं (जो संयुक्त रूप से भारतीय प्रवासियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य स्थल हैं)।

चार्ट IV.22: भारत 2023 में विश्व में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता के रूप में उभरा

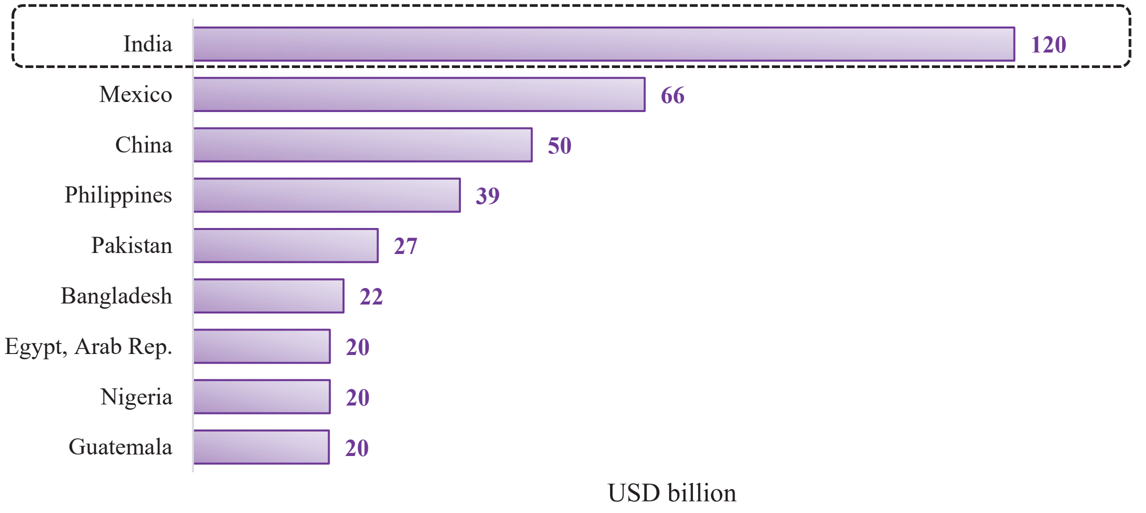

स्रोत: विश्व बैंक

4.56 सीमा पार लेनदेन के लिए दिरहम और रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ किए गए करार से भी प्रेषण प्रवाह को लाभ हुआ है। भारत में प्रेषित धनराशि वर्ष 2024 में 3.7 प्रतिशत बढ़कर 124 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2025 में 4 प्रतिशत बढ़कर 129 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। दक्षिण एशियाई प्रेषण में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2023 में बढ़कर 64.5 प्रतिशत हो गई, जो वर्ष 2022 में 63 प्रतिशत थी।[87]

4.57 प्रेषण एफडीआई से भिन्न होते हैं, जिसे कंपनियाँ वित्तीय अनिश्चितताओं के दौरान निकासी कर सकती हैं। आर्थिक मंदी के समय में, एफडीआई को चक्रीय और अस्थिर माना जाता है। प्रेषण वित्त का स्थिर स्रोत है जो अर्थव्यवस्था में बना रहेगा और प्राप्तकर्ताओं द्वारा सीधे उपयोग किया जाता है और जो देश के विकास में योगदान देता है। बीओपी के दृष्टिकोण से, प्रेषण स्थायी विदेशी मुद्रा प्रवाह हैं और वास्तविक व्यापार घाटे को वित्तपोषित करने में मदद करते हैं, जो सीएडी को कम करने में योगदान देता है। भारत जैसे निवल आयातकों के लिए उच्च प्रेषण आंशिक रूप से पण्य व्यापार घाटे की भरपाई करते हैं और सीएडी को स्थिर करते हैं।

86 प्रवासन और विकास संक्षिप्त 40, जून 2024, https://www.knomad.org/sites/default/files/publication-doc/migration-and-development-brief-40_2.pdf
87 आईवीआईडी

चार्ट IV.23: उच्चतर प्रेषण से माल व्यापार घाटे की भरपाई होगी और सीएडी स्थिर होगा

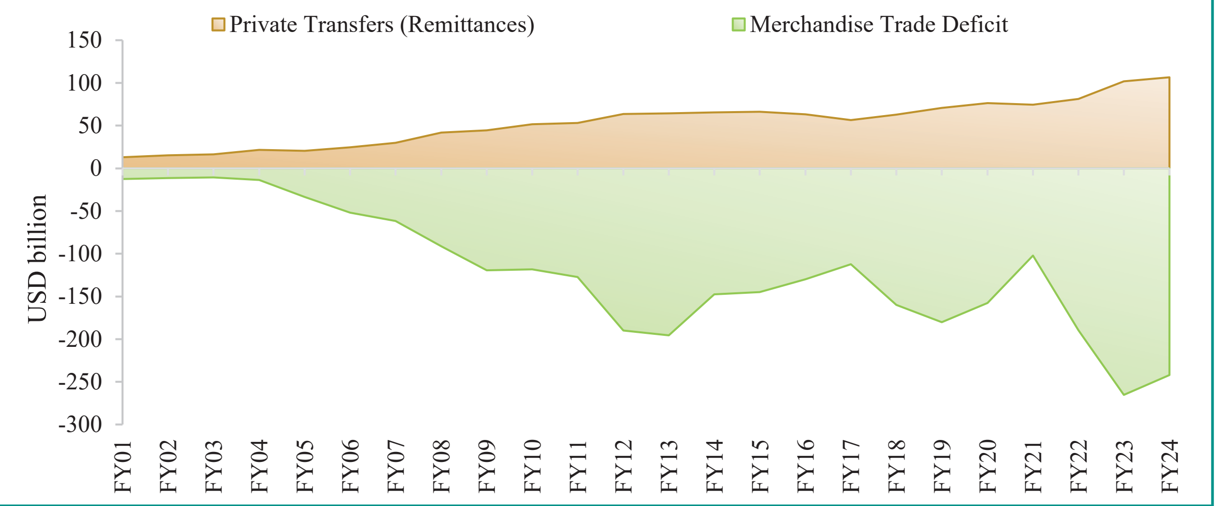

स्रोत: चार्ट संख्या 196, 'भारत का समग्र भुगतान संतुलन-तिमाही-यूएसडी डॉलर', विदेशी क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी पुस्तिका, आरबीआई चार्ट संख्या 192, 'भारत का विदेशी व्यापार-यूएसडी डॉलर', विदेशी क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी पुस्तिका, आरबीआई
टिप्पणी: आरबीआई द्वारा जारी किए गए बीओपी डेटा में निजी अंतरण को प्रेषण के रूप में माना जाता है

बॉक्स IV.5: प्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक

कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के उच्च आय वाले देशों में नौकरी बाजारों की मजबूत रिकवरी, प्रेषण का प्रमुख चालक रही है, विशेष रूप से रिकवरी के दौरान रोजगार में वृद्धि हुई थी। मूल निवासियों की तुलना में आप्रवासियों के लिए यह अधिक तीव्र है। हालाँकि, 2022 में 24.4 प्रतिशत के ऐतिहासिक शिखर की तुलना में 2023 में प्रेषण वृद्धि 7.5 प्रतिशत थी।

भारत में आने वाले धन प्रेषण की सीमा को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारकों पर नीचे चर्चा की गई है।

प्रेषण और तेल की कीमतें- भारत अपनी कच्चे तेल की मांग का एक बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है, और वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका है क्योंकि इससे सीएडी का विस्तार, मुद्रास्फीति में वृद्धि और रुपया कमजोर होता है। जैसा कि मौद्रिक नीति रिपोर्ट (अक्टूबर 2018) में बताया गया है, ष्यह अनुमान लगाया गया है कि कच्चे तेल की एक बैरल की कीमत में प्रत्येक 1 अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होने के, भारत का चालू खाता घाटा 0.8 बिलियन अमेरिकी डालर तक बढ़ सकता हैष तथापि, वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि आम तौर पर देश द्वारा प्राप्त प्रेषण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि भारत के प्रेषण का प्राथमिक स्रोत तेल निर्यातक देश हैं। प्रेषण और तेल की कीमतों पर तिमाही आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में दोनों के बीच 75.4 प्रतिशत का सकारात्मक संबंध है। मुमकिन प्रक्रिया निम्नानुसार है: तेल की कीमतों में वृद्धि (सकारात्मक झटका) भारी मात्रा में तेल राजस्व सृजित कर सकती है, जिससे तेल उत्पादक देशों में उच्च निवेश और विकास हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप, प्रवासी श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है, जिससे उच्च प्रेषण बहिर्वाह होता है।[88] दूसरी ओर, लगातार कम तेल की कीमतें (प्रतिकूल झटके) तेल राजस्व को कम करके तेल निर्यातक अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियों में बाधा डाल सकती हैं। इसके अनुरूप, प्रवासी श्रमिकों की मांग कम हो जाती है और जो इसके बदले में प्रवासी श्रमिक देशों में प्रेषण बहिर्वाह को कम कर सकती है।

88 उपरोक्त टिप्पणी 86

चार्ट IV.24: आगे इस सहसंबंध की पुष्टि करती है, क्योंकि तेल की कीमतों में वृद्धि की अवधि उच्च प्रेषण से जुड़ी होती है

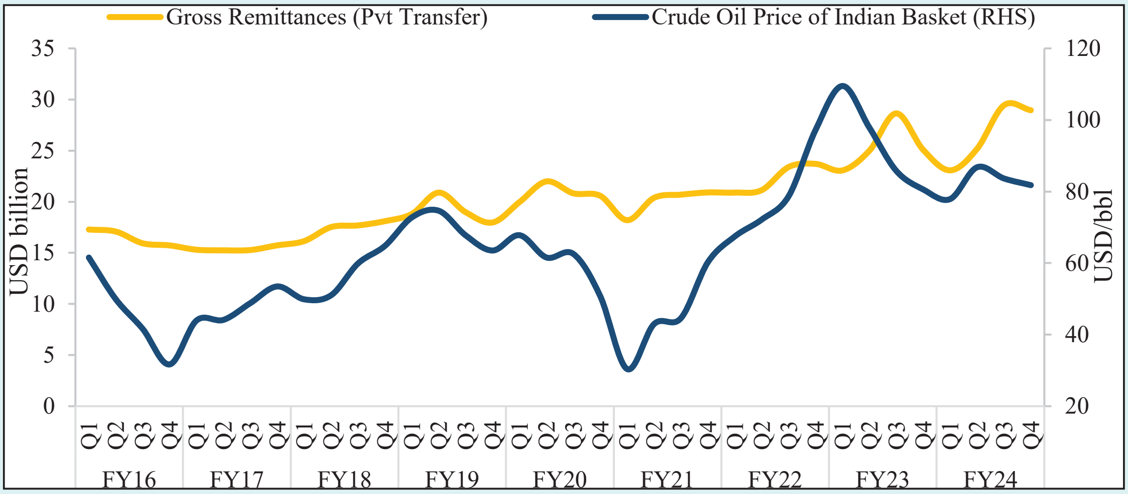

स्रोत: सारणी संख्या 196, श्भारत का समग्र बकाया भुगतान संतुलन-त्रैमासिक-अमेरिकी डालर डॉलरश, विदेशी क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी पुस्तिका, आरबीआई
कच्चे तेल एफओबी मूल्य (इंडियन बास्केट), पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी)

कच्चे तेल एफओबी मूल्य (इंडियन बास्केट), पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी)

प्रेषण और विनिमय दर- उच्च सीएडी के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है और घरेलू मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है क्योंकि फर्म और उपभोक्ता अधिक आयात करते हैं। यह विनिमय दर पर नीचे की ओर दबाव डालता है। दूसरी ओर, प्रेषकों को रुपये के संदर्भ में बेहतर मूल्य मिलता है जब यह विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में मूल्यह्रास करता है, चाहे वह संयुक्त अरब अमीरात के दिरहम, अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड या किसी अन्य मुद्रा ही क्यों न हो।

चार्ट IV.25: भारतीय रुपये/अमेरिकी डालर और प्रेषण का सकारात्मक संघ

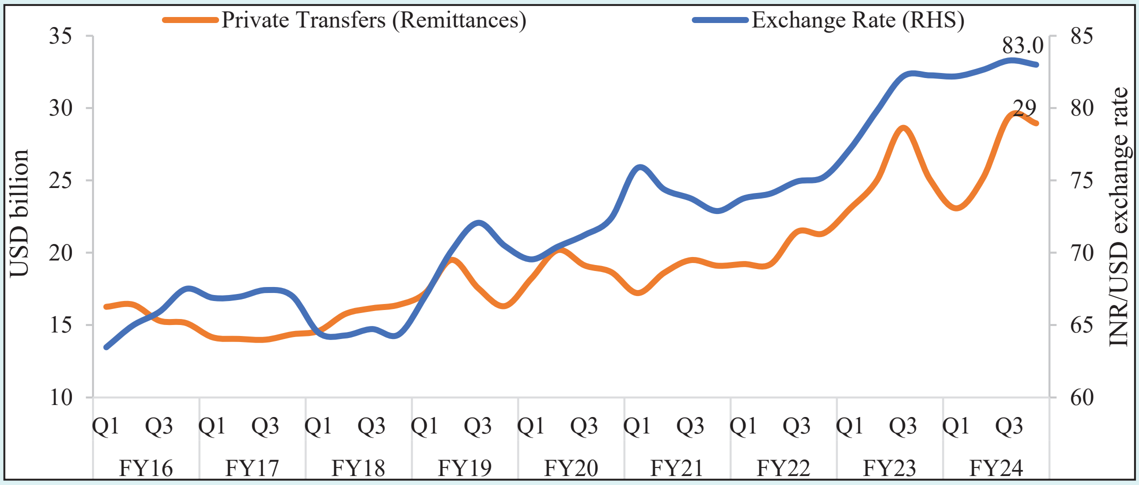

स्रोत: चार्ट संख्या 196, 'भारत का समग्र बकाया भुगतान -त्रैमासिक-अमेरिकी डालर डॉलर', विदेशी क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी पुस्तिका, आरबीआई
चार्ट संख्या 200, एसडीआर, अमेरिकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो और जापानी येन, विदेशी क्षेत्र, की तुलना में भारतीय रुपये की विनिमय दर भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी की पुस्तिका, आरबीआई

विदेश में कमाए गए प्रत्येक अमेरिकी डॉलर के लिए श्रमिक आवश्यक रूप से उस विदेशी भूमि के अनुसार राशि परिवर्तित होने के बाद बढ़ी हुई राशि पाता है जिसमें वह काम करता है। अत: विप्रेषणों में विनिमय दर में उतार-चढ़ाव

के साथ सकारात्मक संबंध देखा गया है। प्रेषण और विनिमय दर की तिमाही आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में 91 प्रतिशत का सकारात्मक सहसंबंध मौजूद है। चार्ट IV.25 में आगे इस सहसंबंध की पुष्टि करती है, क्योंकि विनिमय दर मूल्यह्रास की अवधि उच्च प्रेषण से जुड़ी होती है।

संभावना – वर्ष 2024 में भारत की धन प्रेषण संभावना मजबूत है जिससे यह उम्मीद है कि धन प्रेषण वृद्धि 3.7 प्रतिशत तक कम हो जाएगी और इससे वर्ष 2024 में धन प्रेषण का स्तर 124 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। भारत के प्रवासी पूल का उच्च आय वाले ओईसीडी बाजारों में कार्यरत अत्यधिक कुशल प्रवासियों के बड़े हिस्से और जीसीसी बाजारों में कार्यरत कम कुशल प्रवासियों के बीच विविधीकरण विदेशी झटकों की स्थिति में प्रवासियों के धन प्रेषण को स्थिरता प्रदान करने की संभावना है। संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर जैसे स्रोत देशों के साथ अपने एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को जोड़ने के भारत के प्रयासों से लागत कम होने और धन प्रेषण में तेजी आने की उम्मीद है।[89]

पूंजीगत खाता शेष

4.58 स्थिर पूंजी निरंतर अंतर्वाह सीएडी का वित्तपोषण करता है। वित्त वर्ष 24 के दौरान, निवल पूंजी प्रवाह पिछले वर्ष को 58.9 बिलियन अमेरिकी डालर की तुलना में 86.3 बिलियन अमेरिकी डालर था, जो मुख्य एफपीआई प्रवाह और बैंकिंग पूंजी (एनआरआई डिपॉजिट सहित) के निवल प्रवाह के कारण था।

4.59 निवल एफपीआई प्रवाह में वित्त वर्ष 24 में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया। आशावाद द्वारा प्रेरित भारत की विकास कहानी, प्रगतिशील नीतिगत सुधार, आर्थिक स्थिरता, राजकोषीय निर्णय और आकर्षक निवेश मार्गों के कारण भारत में वित्त वर्ष 24 के दौरान मजबूत एफपीआई प्रवाह देखा गया। निवल एफपीआई प्रवाह वित्त वर्ष 24 के दौरान पिछले दो वर्षों को निवल बहिर्वाह की तुलना में 44.1 बिलियन अमेरिकी डालर था। यह वित्त वर्ष 2015 के बाद एफपीआई प्रवाह का सबसे ऊंचा स्तर है। भारत ने वित्त वर्ष 24 के दौरान अपने साथी उभरते बाजारों की तुलना में अधिकतम इक्विटी प्रवाह प्राप्त किया। वित्त वर्ष 24 के दौरान वित्तीय सेवाएं, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, स्वास्थ्य सेवा और पूंजीगत वस्तुएं इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स-इमर्जिंग मार्केट्स में भारत के सॉवरेन बॉन्ड को हाल ही में शामिल किए जाने से भविष्य में ऋण प्रवाह में वृद्धि होने की उम्मीद है तथा इससे भारत में और अधिक निवेश की मांग में भी वृद्धि होगी।[90]

चार्ट IV.26(क): भारत में निवल एफपीआई प्रवाह

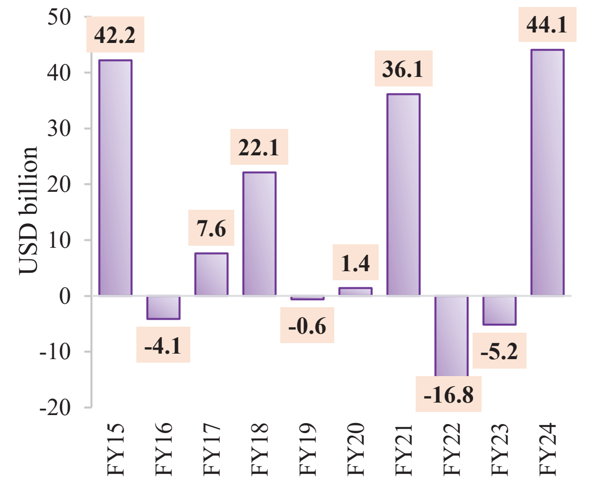

स्रोतः भुगतान संतुलन सांख्यिकी, आरबीआई

चार्ट IV.26(ख): वित्त वर्ष 24 के दौरान उभरते बाजार के साथियों के बीच निवल इक्विटी प्रवाह

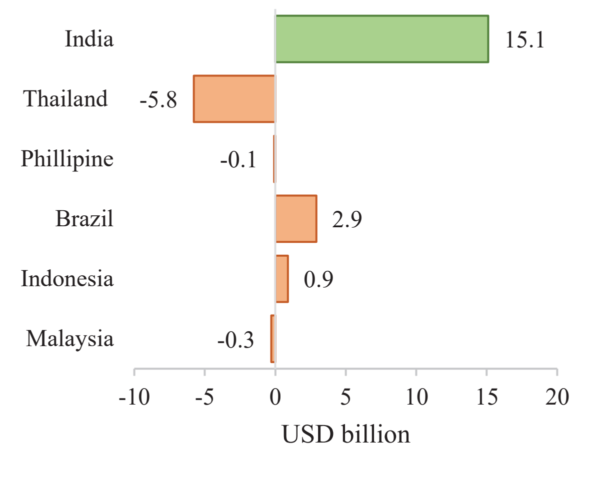

स्रोतः ब्लूमबर्ग

89 प्रवासन और विकास संक्षिप्त 40, विश्व बैंक।

90 21 सितंबर, 2023 को, जेपी मॉर्गन ने 28 जून, 2024 से अपने बेंचमार्क उभरते बाजार सूचकांक यानी जेपी मॉर्गन सरकारी बॉन्ड इंडेक्स-उभरते बाजारों में भारत सरकार के बांड को शामिल करने की घोषणा की।

4.60 यूएनसीटीएडी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024[91] में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वैश्विक एफडीआई वर्ष 2022 में 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 2 प्रतिशत घटकर वर्ष 2023 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। विकास की कम संभावनाएं, आर्थिक मंदी के रुझान, व्यापार और भू-राजनीतिक तनाव, औद्योगिक नीतियां और आपूर्ति श्रृंखला में विविधीकरण एफडीआई पैटर्न को नया रूप प्रदान कर रहे हैं, जिससे कुछ बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) विदेशी विस्तार के लिए सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त और सीमा पार विलय और अधिग्रहण (एमएंडएएस) वर्ष 2023 में विशेष रूप से कमजोर थे। विकसित देशों में मुख्यत: एफडीआई को प्रभावित करने वाले एमएंडएएस के मूल्य में 46 प्रतिशत की गिरावट आई है। अवसंरचना निवेश के लिए महत्वपूर्ण परियोजना वित्त 26 प्रतिशत नीचे था। कसी हुई वित्तपोषण की स्थिति, निवेशकों की अनिश्चितता, वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और मजबूत नियामक जांच गिरावट के प्रमुख कारण थे। तथापि, ग्रीनफील्ड निवेश परियोजना की घोषणा ने आगे का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें परियोजनाओं की संख्या में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें विनिर्माण को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया था।

चार्ट IV-27(क): प्रत्यावर्तन में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 24 में निवल एफडीआई प्रवाह में कमी

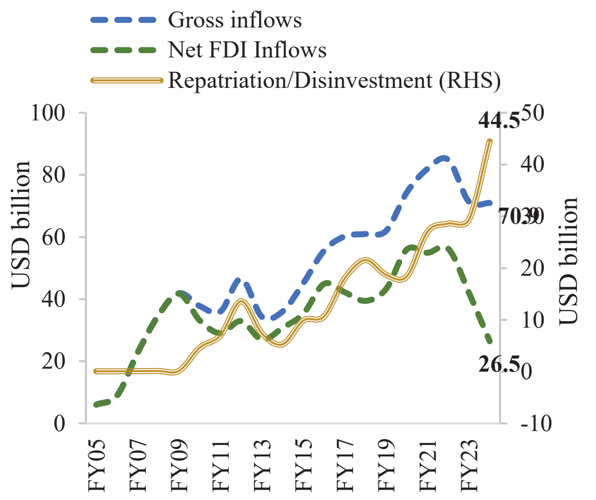

चार्ट IV.27(ख): जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निवल एफडीआई प्रवाह में गिरावट

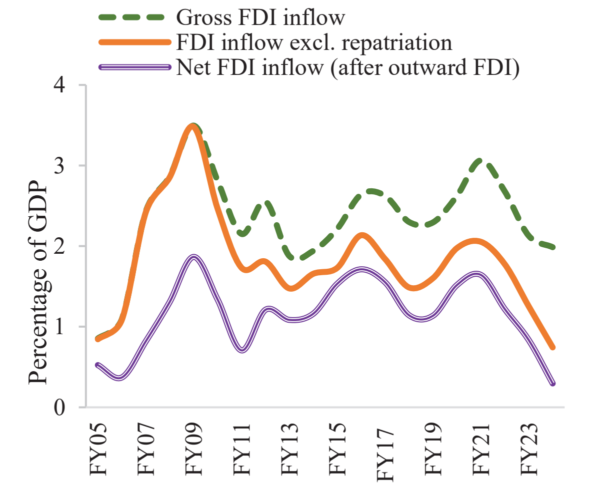

स्रोत: भुगतान संतुलन सांख्यिकी, आरबीआई[92]

4.61 वैश्विक एफडीआई प्रवाह में हुई गिरावट ने भारत की एफडीआई प्रवाह को भी प्रभावित किया है। भारत में निवल[93] एफडीआई प्रवाह वित्त वर्ष 23 के दौरान 42.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर वित्त वर्ष 24 में 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तथापि, सकल एफडीआई प्रवाह वित्त वर्ष 23 में 71.4 बिलियन अमेरिकी डालर से केवल 0.6 प्रतिशत घटकर वित्त वर्ष 24 में 71 बिलियन अमेरिकी डालर से कम हो गया। दूसरे शब्दों में, भारत में निवेशकों की रुचि में कोई बदलाव नहीं आया। निवल अंतर्वाहों में कमी मुख्यत: अनेक लाभप्रद बहिर्गमन के कारण प्रत्यावर्तन/विनिवेश में वृद्धि के कारण हुआ था। कोई बाजार जो निवेशकों को लाभ लेने और अपने निवेश से बाहर की अनुमति देता है, वह सबसे अच्छा बाजार है। यही कारण है कि निवेश का प्रत्यावर्तन वित्त वर्ष 23 में 29.3 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 44.5 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया। हाल के वर्षों में एफडीआई प्रवाह में गिरावट विकसित देशों में उच्च ब्याज दरों और तेजी से बढ़ते शेयर बाजार के कारण तथा भारत से आकर्षक निकासी के कारण भी है।

एफडीआई प्रवाह की प्रवृत्ति और संरचना में परिवर्तन की जांच

उद्योग बनाम सेवा क्षेत्र में एफडीआई

91 यूएनसीटीएडी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024-निवेश सुविधा और डिजिटल सरकार, https://unctad.org/system/files/official-document/wir2024_overview_en.pdf

92 यहां RBI डेटा का उपयोग किया गया है क्योंकि DPIIT स्वदेश वापसी/विनिवेश पर डेटा नहीं देता है

93 निवल एफडीआई प्रवाह = सकल एफडीआई प्रवाह-प्रत्यावर्तन/विनिवेश

4.62 प्रमुख क्षेत्रों में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह की गहन जांच से यह पता चलता है कि हाल के वर्षों में उद्योग और सेवा क्षेत्रों[94] में एफडीआई अंतर्वाह कमजोर हुआ है। वास्तव में, इन दोनों क्षेत्रों के लिए, एफडीआई-से-जीडीपी अनुपात पूर्व-महामारी के स्तर से नीचे गिर गया है। सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्रों की एफडीआई की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 20 में 0.62 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 24 में 0.39 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि के दौरान, सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 0.87 प्रतिशत से गिरकर 0.69 प्रतिशत हो गया।

चार्ट IV.28: उद्योग और सेवाओं दोनों में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में प्रवृत्ति

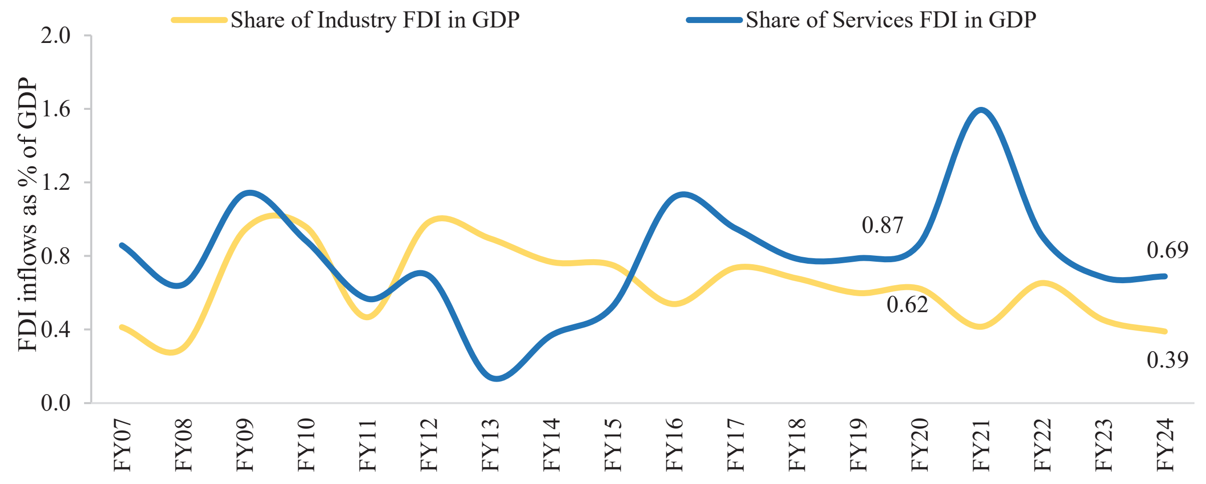

स्रोत: एफडीआई सांख्यिकी, डीपीआईआईटी

वास्तविक एफडीआई बनाम डिजिटल एफडीआई

4.63 एफडीआई प्रवाह को आगे के विश्लेषण के लिए वास्तविक और डिजिटल में विभाजित किया जा सकता है। वास्तविक एफडीआई में ऑटोमोबाइल, औषध और विनिर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जबकि डिजिटल एफडीआई में कंप्यूटर सेवाएं, दूरसंचार, परामर्श सेवाएं और सूचना और प्रसारण शामिल हैं।[95] कुछ वर्ष पहले (वित्त वर्ष 14) वास्तविक एफडीआई डिजिटल एफडीआई के मूल्य का लगभग तीन गुना था। अन्य बातों के साथ-साथ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, परामर्श सेवाओं और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण, डिजिटल एफडीआई में वृद्धि देखी गई, जबकि वास्तविक एफडीआई में सापेक्ष गिरावट देखी गई है।

4.64 नोमुरा का ग्लोबल मार्केट रिसर्च मई 2024, श्एशियाज न्यू फ्लाइंग गीजश, इस बात पर प्रकाश डालता है कि बढ़ते संरक्षणवाद और भू-राजनीतिक तनाव ने वास्तविक एफडीआई की स्थिरता से ऊपर छलांग लगाई है। इस प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला कारक अंतरराष्ट्रीय उत्पादन के गैर-इक्विटी मोड का बढ़ता प्रचलन है, जैसे कि संविदा विनिर्माण, तीसरे पक्ष की आउटसोर्सिंग या फ्रेंचाइजिंग। इन परिदृश्यों के अंतर्गत, जबकि अर्थव्यवस्थाएं जीवीसी में अधिक एकीकृत हो सकती हैं, अतः इसे एफडीआई आंकड़ों में परिलक्षित नहीं किया जा सकता है। महामारी के दौरान, घर से काम करने की संस्कृति को बढ़ने और कुशल डिजिटल अवसंरचना की उपलब्धता के कारण कुल एफडीआई में डिजिटल सेवाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, कुल एफडीआई में डिजिटल एफडीआई की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 17 में 46.6 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 21 में 69.2 प्रतिशत हो गई। तथापि, हाल के दिनों में डिजिटल और वास्तविक एफडीआई दोनों में गिरावट हो रही है। डिजिटल एफडीआई में गिरावट का टेक स्टार्ट-अप से सीधा संबंध है। महामारी के दौरान वृद्धि के बाद, टेक स्टार्ट-अप में वैश्विक प्रवाह कम हुआ है और उस प्रवाह की वैश्विक प्रवृत्ति भारत में भी देखने को मिलती है।

94 उद्योग में ड्रग्स और औषध, ऑटोमोबाइल उद्योग, रसायन, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं। सेवाओं में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, बैंकिंग और बीमा सेवाएँ, दूरसंचार, परामर्श सेवाएँ आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

95 संदर्भ: एचएसबीसी ग्लोबल रिसर्च: भारत का एफडीआई रहस्य, बदलती सीमाएं, https://www.hsbc.co.in/wealth/insights/market-outlook/india-economics/2024-01/

चार्ट IV.29(क): कुल एफडीआई में वास्तविक और डिजिटल एफडीआई का हिस्सा

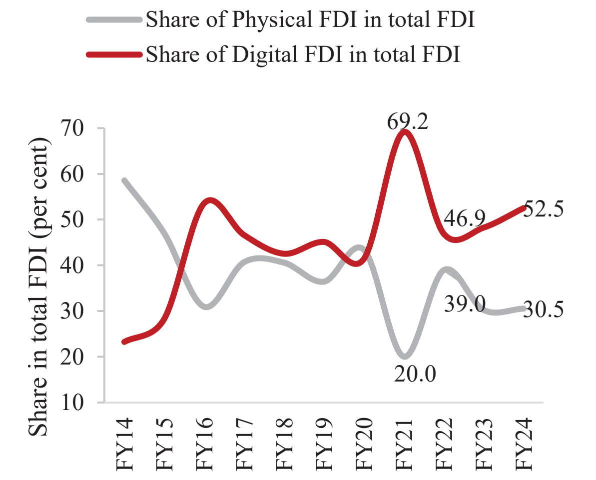

स्रोत: एफडीआई सांख्यिकी, डीपीआईआईटी

चार्ट IV-29(ख): टेक स्टार्ट-अप में वैश्विक पूंजी प्रवाह

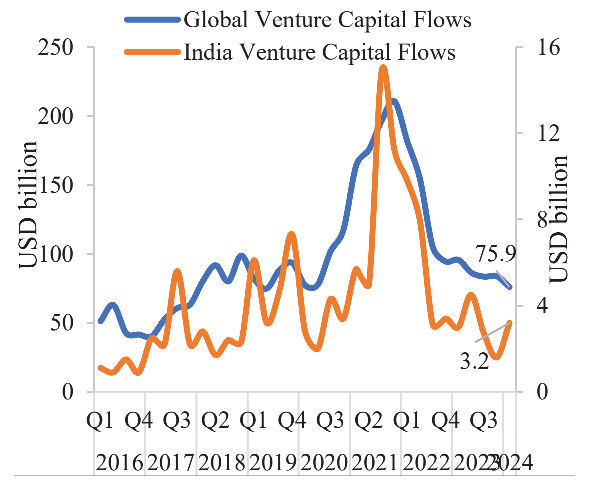

स्रोत: केपीएमजी वेंचर पल्स रिपोर्ट

वास्तविक एफडीआई बनाम लक्ष्य

4.65 भारत में घटते एफडीआई प्रवाह वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में वैश्विक व्यापार में भारत की बाजार हिस्सेदारी के लक्ष्य को करने के अनुकूल नहीं हैं। इस संदर्भ में, एफडीआई प्रवाह और निवेश अभिप्राय के बीच संबंध को समझने के लिए एक प्रयास किया गया। लक्ष्यों का अनुमान लगाने के लिए आंकड़े संबंधी दो स्रोतों का उपयोग किया गया है। पहला घोषित ग्रीनफील्ड एफडीआई परियोजनाओं पर यूएनसीटीएडी आंकड़ा है; दूसरा सीएमआईई द्वारा घोषित विदेशी निजी क्षेत्र की परियोजनाएं हैं।[96]

चार्ट IV.30(क): भविष्य के एफडीआई अंतर्वाह के भविष्यवक्ता के रूप में निवेश का लक्ष्य

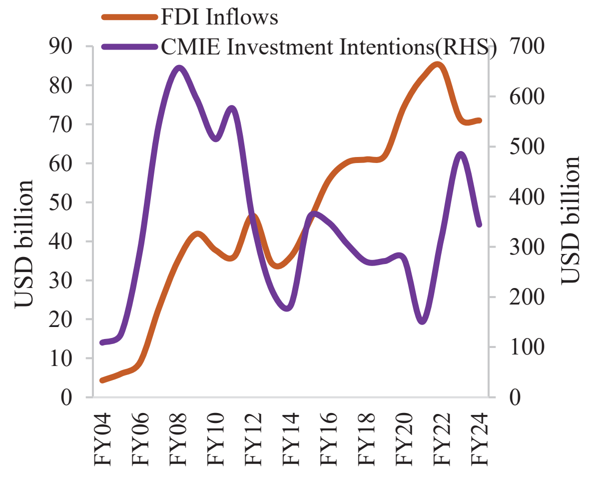

स्रोत: एफडीआई लक्ष्यों के लिए सीएमआईई, एफडीआई अंतर्वाह के लिए डीपीआईआईटी

चार्ट IV.30(ख): एफडीआई प्रवाह और सभी क्षेत्रों के एफडीआई की एकाग्रता के बीच सकारात्मक सहसंबंध

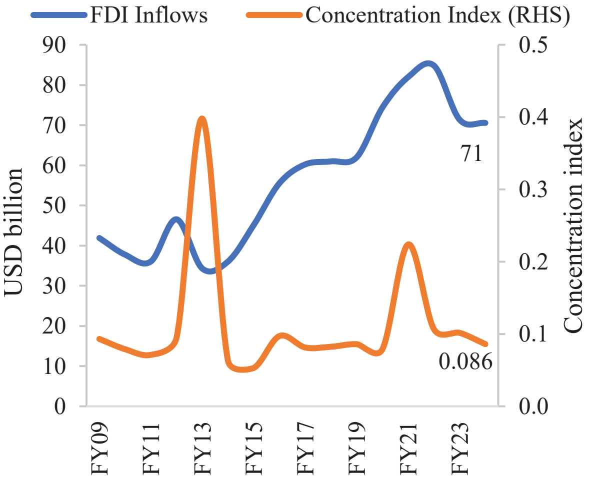

स्रोत: डीपीआईआईटी और स्वयं की गणना

96 यूएनसीटीएडी आंकड़े केवल ग्रीनफील्ड निवेशों को संदर्भित करता है, जबकि सीएमआईई डेटाबेस में विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। यूएनसीटीएडी आंकड़े तब रिकॉर्ड किए जाते हैं जब यह स्पष्ट संकेत देता है कि नौकरियां और नए पूंजीगत व्यय का सृजन होगा, जबकि सीएमआईई में आवश्यक लाइसेंस या भूमि प्राप्त/अधिग्रहित होने या वित्तपोषण तय होने से पहले की परियोजनाओं को भी शामिल किया जाता है।

4.66 समय के साथ, सभी क्षेत्रों में निवेश के लक्ष्यों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। जबकि कंप्यूटर और रसायन जैसे उद्योगों में निवेश के लक्ष्य आसान हो गए हैं, नए और भविष्य के क्षेत्रों में निवेश के लक्ष्य बढ़ रहे हैं।[97] हाल की तिमाहियों में, नए और भविष्य के क्षेत्रों में निवेश के लक्ष्यों, जैसे कि नवीकरणीय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा केंद्र, ईवीएस और बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर तेजी से बढ़े हैं। भारत वर्ष 2022 में एआई से संबंधित एफडीआई के लिए एक प्रमुख गंतव्य था, वर्ष 2022 में एआई से संबंधित 122 एफडीआई परियोजनाएँ प्राप्त हुई, जिसमें एबीबी, एसेसयोर, डेलॉयट, आईबीएम और माईक्रोसॉफ्ट जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश में निवेश की घोषणा की।[98] नैसकॉम के शोध के अनुसार, भारत अपेक्षाकृत कम परिचालन लागत और अत्यधिक कुशल एआई, मशीनी शिक्षण और बड़े आंकड़े संबंधी श्रमिकों के दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पूल के कारण एआई निवेश के लिए आकर्षक स्थान है।[99]

4.67 सीएमआईई निवेश लक्ष्यों और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर यूएनसीटीएडी संबंधी आंकड़ों की विस्तृत जांच से पता चलता है कि इन आंकड़ों संबंधी स्रोतों के बीच 56 प्रतिशत से अधिक का मजबूत सहसंबंध मौजूद है। चार्ट IV.30क यह दर्शाती है कि निवेश के लक्ष्य भविष्य के एफडीआई अंतर्वाहों के अच्छे भविष्यवक्ता रहे हैं। एफडीआई प्रवाह ने वित्त वर्ष 15 तक सीएमआईई निवेश लक्ष्यों के समान दिशा का पालन किया; तथापि वित्त वर्ष 2016 में यह प्रवृत्ति भिन्न हो गई।

4.68 हर्शमैन-हर्फिंडाहल सूचकांक (एचएचआई)[100] का उपयोग करते हुए एफडीआई एकाग्रता का अनुमान कुल एफडीआई अंतर्वाह और एकाग्रता सूचकांक के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर प्रकाश डालता है, जिसका अर्थ है कि जिन वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में एफडीआई अंतर्वाह में वृद्धि देखी गई थी, एफडीआई केवल कुछ क्षेत्रों में केंद्रित था और यह सभी क्षेत्रों में व्यापक नहीं था और इसके विपरीत था।

4.69 भारत के पास चुनिंदा क्षेत्रों अर्थात, ग्रीनफील्ड परियोजनाएं जैसे नवीकरणीय, दूरसंचार, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जैसे डिजिटल सेवाएं और परामर्श सेवाएं में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए सुव्यवस्थित अवसंरचना है तथापि, यह विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न हो सकता है। इसलिए, जहां निवेश के लक्ष्य अधिक हैं, उन क्षेत्रों को निवेश के लिए अधिक सुलभ बनाया जाना चाहिए। विशेष रूप से, उन सभी क्षेत्रों में व्यापारिक सुगमता को बढ़ाने और केवल एफडीआई के लिए आकर्षक क्षेत्रों से आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तथापि श्व्यापारिक सुगमताश के संबंध में सुलभ कार्य पिछले कुछ वर्षों में पहले ही किए जा चुके हैं, लेकिन आगे के काम सरकार के राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सभी स्तरों और विनियामकों के हाथों में हैं।

4.70 अप्रैल 2024[101] में ब्लूमबर्ग के एक लेख में कहा गया है कि भारत केवल एफडीआई आकर्षित करने के लिए अन्य विकासशील देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है। यह उन उन्नत देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है जो अब सक्रिय रूप से और आक्रामक रूप से औद्योगिक नीतियों का अनुसरण करते हैं जो व्यवसायों को सब्सिडी देकर घरेलू निवेश को विशेषाधिकार देते हैं ताकि उन्हें विदेशों में निवेश करने से रोका जा सके और अन्य विदेशी निवेशकों को लुभाया जा सके जो अन्यथा भारत जैसे उभरते देशों में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। अनुसंधान एवं विकास संस्कृति, राजनीतिक स्थिरता, नीति पूर्वानुमान और स्थिरता, उचित शुल्क और कर, विवाद समाधान तंत्र और प्रत्यावर्तन में सरलता के अलावा शिक्षित श्रमबल और कुशल कार्यबल महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इनमें से कई क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। कुछ अन्य क्षेत्रों में काम अधूरे हो सकते हैं। लेकिन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में सतत निवेशक हित और परिणामी ज्ञान और जानकारी का मार्ग बेहतर शैक्षिक और कौशल परिणामों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

4.71 बॉक्स IV.6 में यह चर्चा की गई है कि चीन से एफडीआई प्रवाह में वृद्धि कैसे निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी बढ़ाने में मदद कर सकती है।

---

97 सीएमआईई निवेश लक्ष्यों के के अनुसार आंकड़ें क्षेत्रवार है

98 एआई में एफडीआई के लिए वैश्विक प्रवृत्ति, https://www.investmentmonitor.ai/features/what-are-the-global-trends-for-fdi-in-ai/?cf-view

99 नैसकॉम रणनीतिक रिपोर्ट-पुनरुत्थान के लिए तन्यकः भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र 2022, https://nasscom.in/knowledge-center/publications/technology-sector-india-2022-strategic-review

100 हर्शमैन हर्फिंडाल इंडेक्स की गणना कुल एफडीआई प्रवाह में प्रत्येक क्षेत्र की हिस्सेदारी के वर्गों के योग को लेकर की गई है

101 'विदेशी निवेश की लड़ाई में बिडेन ने मोदी को पछाड़ा', ब्लूमबर्ग, 4 अप्रैल 2024 (https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-04-04/modi-vs-biden-why-foreign-investment-into-india-is-still-declining)

बॉक्स IV.6: चीन प्लस वन रणनीति

पिछले पाँच वर्षों में वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिसमें एप्पल और अन्य प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ चीन से खुद को 'जोखिम मुक्त' करने की कोशिश कर रही हैं, जिसे पारंपरिक रूप से 'दुनिया की फैक्ट्री' के रूप में जाना जाता था। यह बदलाव मुख्य रूप से कोविड-19 के कारण होने वाले व्यवधानों, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव और चीन में व्यापार करने की बढ़ती लागतों के कारण हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, कई कंपनियों ने उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और घटकों के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए 'चीन प्लस वन रणनीति' अपनाई है। इस दृष्टिकोण में चीन के प्रति अपने जोखिम को कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला निर्णय शामिल हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2023 में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा सर्वेक्षण किए गए उत्तरी अमेरिका के 90 प्रतिशत से अधिक निर्माताओं ने अपने कुछ या सभी उत्पादन को मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम जैसे अन्य देशों में स्थानांतरित कर दिया, जो चीन से दूर जाने का संकेत देता है।[102]

क्या भारत इस 'चीन प्लस वन' रणनीति से लाभान्वित हो सकता है? भारत का आकर्षण इसके बड़े घरेलू उपभोक्ता बाजार में निहित है, जो कंपनियों के लिए वहां परिचालन स्थापित करना आकर्षक बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में स्मार्टफोन निर्माण और असेंबली पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। कर छूट और सब्सिडी सहित सरकार की पीएलआई योजना कंपनियों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में स्मार्टफोन की घरेलू मांग में वृद्धि भी कंपनियों के वहां निवेश करने के निर्णय का महत्वपूर्ण कारक है। उदाहरण के लिए एप्पल ने वित्त वर्ष 24 के दौरान भारत में 14 बिलियन अमरीकी डॉलर के आईफोन असेंबल किए, जो इसके वैश्विक आईफोन उत्पादन का 14 प्रतिशत है।[103] फॉक्सकॉन ने कर्नाटक और तमिलनाडु में एप्पल मोबाइल फोन का उत्पादन शुरू कर दिया है।[104]

हालांकि भारत चीन से व्यापार मोड़ का तत्काल लाभार्थी नहीं हो सकता है, लेकिन समय के साथ इसके इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। पीएलआई योजना का कार्यान्वयन इस वृद्धि का प्रमुख चालक रहा है। उदाहरण के लिए, भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात यूएसए को वित्त वर्ष 17 में 0.6 बिलियन अमरीकी डॉलर के व्यापार घाटे से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 8.7 बिलियन अमरीकी डॉलर के व्यापार अधिशेष में बदल गया है, जो मूल्य संवर्धन में उल्लेखनीय वृद्धि को रेखांकित करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, जिस श्रेणी में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, वह है मोबाइल फोन, जिसका निर्यात यूएसए को वित्त वर्ष 23 में 2.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 5.7 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

जैसा कि भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में अपनी भागीदारी को बढ़ाना चाहता है और इसलिए वह पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की सफलताओं और रणनीतियों को देखेगा। इन अर्थव्यवस्थाओं ने आम तौर पर दो मुख्य रणनीतियों का अनुसरण किया है: व्यापार लागत को कम करना और विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाना। यह देखते हुए कि जीवीसी को लागत को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान जैसे देशों ने समय के साथ अपनी व्यापार लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत के लिए, लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार प्रमुख केन्द्र बिन्दु रहा है, जैसा कि विश्व बैंक के एलपीआई पर भारत के अंक में उल्लेखनीय वृद्धि से यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है (जैसा कि पैरा 4.49 में चर्चा की गई है)। निवेश सुविधा पर केंद्रित दूसरी रणनीति में विदेशी निवेश को बढ़ाने और इसे स्थिर करने के लिए कार्रवाई की गई है। उदाहरण के लिए पीएलआई योजना कंपनियों के अनुपालन हेतु बाजार से जुड़ी प्रोत्साहन प्रणाली की पेशकश करके उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करती है।

मध्यम अवधि में, भारत अपनी मूल्य शृंखला को पश्चिम के साथ एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक और भविष्य के

102 बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप का लेख, 'वैश्विक विनिर्माण में टेक्टोनिक बदलाव का उपयोग', https://tinyurl.com/bnrcrddz.
103 इंडिया ब्रीफिंग, 'भारत में एप्पल के अनुबंध निर्माता और घटक आपूर्तिकर्ता', दिनांक 17 अप्रैल 2024, https://tinyurl.com/357mv7hy
104 पूर्वोक्त

पीढ़ी के साथ दूरसंचार शामिल हैं। इस रणनीति को ऑस्ट्रेलिया-भारत मुक्त व्यापार करार और यूएस-भारत स्वच्छ ऊर्जा पहल जैसे करार के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों के भीतर व्यापार पैटर्न विकसित होने लगे हैं। उदाहरण के लिए, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी, जैसे सौर वॉटर हीटर, अपशिष्ट रीसाइक्लिंग उपकरण और पवन टर्बाइन के लिए टैरिफ वर्गीकरण से अमेरीका को निर्यात में वित्त वर्ष 20 में 199.2 मिलियन अमरीकी डालर से वित्त वर्ष 24 में 326.9 मिलियन अमरीकी डालर तक वृद्धि हुई हैं।[105] इसके अतिरिक्त, नवीकरण ीय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों, जैसे फर्स्ट सोलर, वेस्टा और स्कैटेक ने हरित प्रौद्योगिकियों की बढ़ती मांग का लाभ उठाने के लिए भारत में अपना परिचालन स्थापित किया है।

क्या चीन प्लस वन के परिणामस्वरूप व्यापारिक संबंध चीन से पूरी तरह दूर हो जायेंगे? शायद ऐसा न हो। उदाहरण के लिए, मेक्सिको, वियतनाम, ताइवान और कोरिया जैसे देशों को लें, जो चीन से अमेरिका के व्यापार विचलन के प्रत्यक्ष लाभार्थी थे। भले ही इन देशों ने अमेरिका को निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, उन्होंने चीनी एफडीआई में भी सहवर्ती वृद्धि प्रदर्शित की।[106] इसलिए, दुनिया पूरी तरह से चीन से आगे नहीं देख सकती, भले ही वह चीन प्लस वन का पीछा कर रही हो।

भारत के पास चीन प्लस वन रणनीति से लाभ उठाने के लिए दो विकल्प हैं: यह चीन की आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत हो सकता है या चीन से एफडीआई को बढ़ावा दे सकता है। इन विकल्पों में से, चीन से एफडीआई पर ध्यान केंद्रित करना अमेरिका में भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अधिक आशाजनक लगता है, जैसा कि पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने अतीत में किया था। इसके अतिरिक्त, चीन प्लस वन दृष्टिकोण से लाभ उठाने के लिए एक रणनीति के रूप में एफडीआई को चुनना व्यापार पर निर्भर रहने से अधिक फायदेमंद प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन भारत का शीर्ष आयात भागीदार है, और चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ रहा है। चूंकि अमेरिका और यूरोप अपने तत्कालिक संसाधन को चीन से दूर कर रहे हैं, इसलिए चीनी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करना और फिर इन बाजारों में उत्पादों का निर्यात करना अधिक प्रभावी है, बजाय इसके कि वे चीन से आयात करें, न्यूनतम मूल्य जोड़ें और फिर उन्हें फिर से निर्यात करें। इसके अतिरिक्त, रोडियम समूह के हालिया शोध नोट में बताया गया है, ष्इतने सारे उत्पाद श्रेणियों पर चीन का प्रभुत्व, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आर्थिक दबाव का जोखिम पैदा करता है, जहां सरकार राजनीतिक लाभ के लिए महत्वपूर्ण निविष्टि तक पहुंच को रोकती है।''[107] उसी संक्षिप्त विवरण में यह भी कहा गया है, 'ब्राजील और तुर्की ने चीनी ईवी के आयात पर बाधाएं खड़ी की हैं, लेकिन इस क्षेत्र में चीनी एफडीआई को आकर्षित करने के लिए उपाय किए हैं।' यूरोपीय देशों ने भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया है।[108] इसलिए यह जरूरी है कि भारत चीन से माल आयात करने और चीन से पूंजी (एफडीआई) आयात करने के बीच सही संतुलन बनाए।

पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार

4.72 बड़े पूंजी प्रवाह के साथ सीएडी में कमी के कारण वित्त वर्ष 24 में विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर) में वृद्धि हो पाई है। एफईआर का बफर घरेलू आर्थिक कार्यकलाप को वैश्विक उतार-चढ़ाव से बचाता है। ये भंडार आधार के रूप में कार्य करते हैं और नकदी प्रदान करते हैं और यह सुनिश्चित करते है कि भारत अपने विदेशी दायित्वों को पूरा कर सकते है। वित्त वर्ष 24 के दौरान, भारत का एफईआर 68 बिलियन अमेरिकी डालर बढ़ गया, जो प्रमुख विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में सबसे अधिक वृद्धि है। दिनांक 21 जून 2024 को एफईआर 653.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वित्त वर्ष 25 के लिए अनुमानित 10 महीने से अधिक के आयात और मार्च 2024 के अंत में बकाया कुल विदेशी ऋण के 98 प्रतिशत से अधिक को कवर करने के लिए पर्याप्त है।

105 एचएस कोड-8402, 8406 और 8414

106 2 जुलाई 2024 को एनसीईएआर, इंडिया पॉलिसी फोरम में आईएमएफ के आर्थिक परामर्शदाता और अनुसंधान विभाग के निदेशक पियरे-ओलिवियर गौरींचस द्वारा दी गई प्रस्तुति से लिया गया, 'सिस्टम में दरारें: कैसे भू-आर्थिक विखंडन दुनिया को फिर से आकार दे रहा है'

107 कैसे चीन की अत्यधिक क्षमता उभरती अर्थव्यवस्थाओं को रोकती है', रोडियम ग्रुप, 13 जून 2024, https://tinyurl-com/y9d6rpna.

108 'चीन शॉक 2-0 पर यूरोप की प्रतिक्रिया: चीन को करीब रखें', वॉल स्ट्रीट जर्नल, 23 जून 2024, https://tinyurl-com/j8trksxv

चार्ट IV.31: भारत ने वित्त वर्ष 24 में विदेशी मुद्रा भंडार रिजर्व में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है

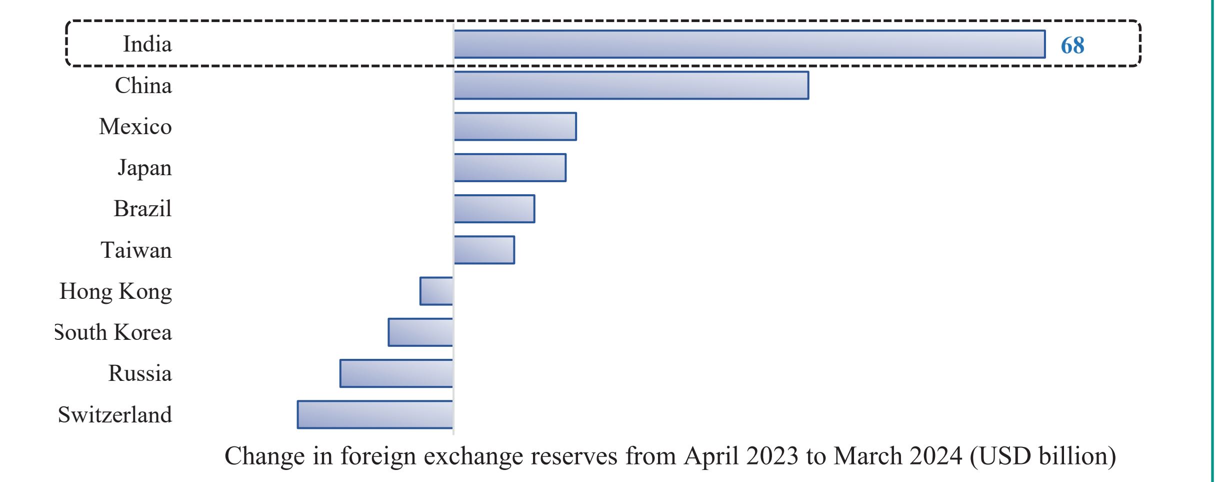

स्रोतः ब्लूमबर्ग, भारत के लिए आरबीआई (हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वीकली, आरबीआई)

चार्ट IV.32: भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता (वार्षिक आयात के महीनों की संख्या के संदर्भ में): अंतर-राष्ट्र परिप्रेक्ष्य

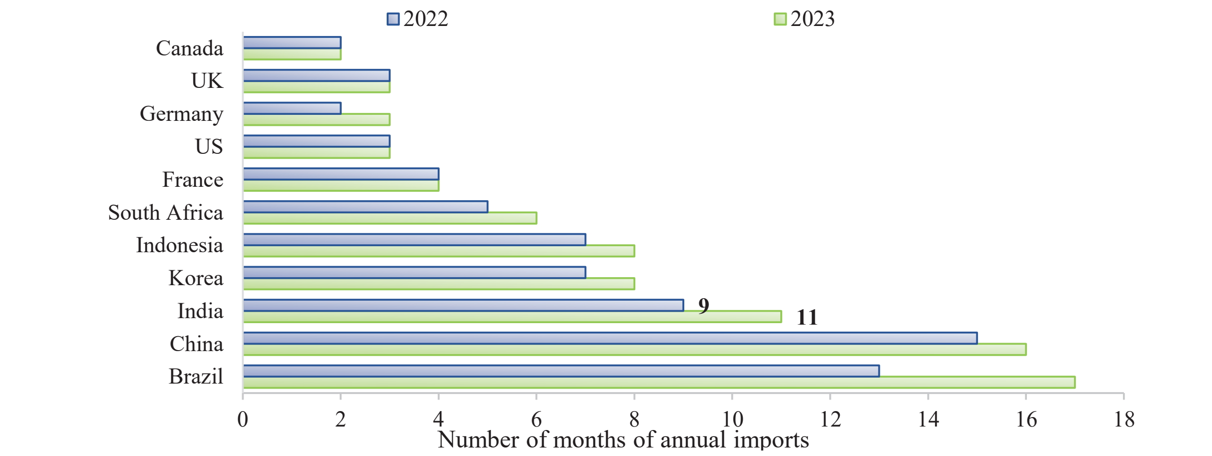

स्रोतः आईएमएफ (विदेशी मुद्रा भंडार) और विश्व व्यापार संगठन (आयात आंकड़ों के लिए)

विनिमय दरें

4.73 वित्त वर्ष 24 में भू-राजनीतिक जोखिमों, बढ़ती ब्याज दरों और अस्थिर कमोडिटी की कीमतों के बावजूद, अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने टाइट लेबर मार्केट और उत्साहित कंज्यूमर भावनाओं जैसे सकारात्मक आर्थिक संकेतकों के साथ बेहतर प्रदर्शन किया है। इन कारकों ने अमेरिकी ट्रेजरी बाजारों में वैश्विक निधि आकर्षित करने में योगदान दिया क्योंकि ग्रीनबैक ऑन सेफ-हेवन अपील की उच्च मांग थी। वित्त वर्ष 24 में, अमेरिकी डॉलर लगभग हर प्रमुख समकक्ष देशों की तुलना में अग्रणी रहा। रुपया भी अवमूल्यन दबाव में आ गया। तथापि, रुपया सबसे कम अस्थिर प्रमुख मुद्राओं में से एक था। इसके अतिरिक्त, इसने पिछले वर्षों की तुलना में वित्त वर्ष 24 में सबसे कम अस्थिरता दर्शाई। भिन्नता के गुणांक (सीवी) का उपयोग करके अस्थिरता को अनुमान से यह पता लगाता है कि सीवी वित्त वर्ष 24 के दौरान 0.58 था, जो पिछले वर्षों की तुलना में बहुत कम था। मजबूत अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में बढ़ोतरी के बावजूद रुपये की सापेक्ष स्थिरता भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत वृहद आर्थिक बुनियाद की मजबूती, वित्तीय स्थिरता और विदेशी स्थिति में सुधार को दर्शाती है। भविष्य में, मजबूत विदेशी प्रवाह और सरल व्यापार घाटे से रुपये के बेहतर स्थिति में रहने की उम्मीद है।

चार्ट IV.33: रुपया/अमेरिकी डालर विनिमय दर की अस्थिरता

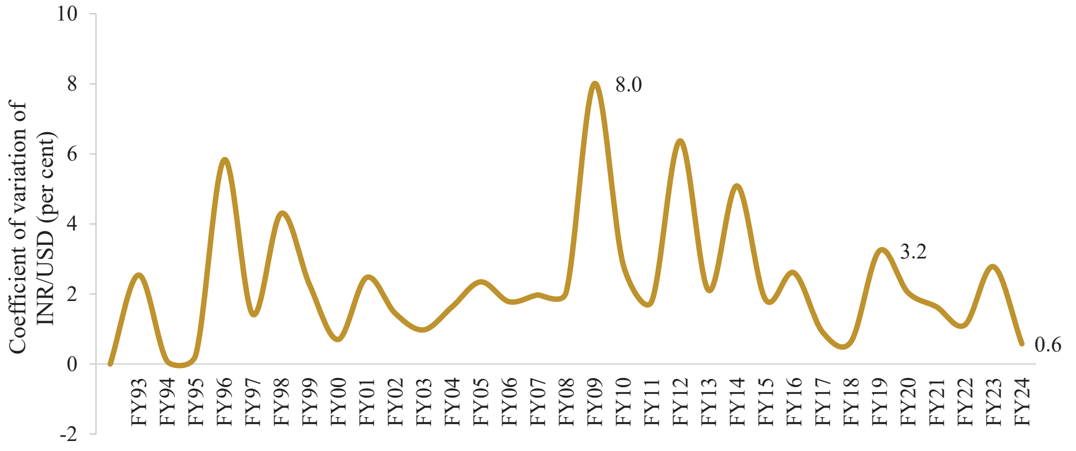

स्रोत: चार्ट संख्या 200 पर आधारित स्वयं की गणना के अनुसार, एसडीआर, अमेरिकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो और जापानी येन, विदेशी क्षेत्र की तुलना में भारतीय रुपये की विनिमय दर, भारतीय अर्थव्यवस्था सांख्यिकी की पुस्तिका, आरबीआई

चार्ट IV.34: वित्त वर्ष 24 में अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में अन्य देशों की विनिमय दर में अस्थिरता

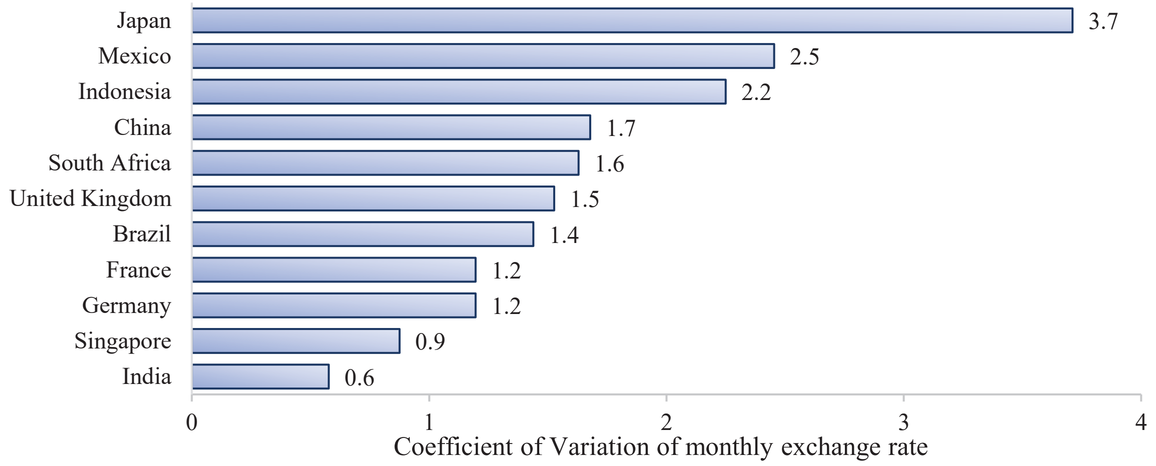

स्रोत: बीआईएस डेटा पोर्टल से द्विपक्षीय विनिमय दर पर डेटा और स्वयं की गणना
टिप्पणी: विनिमय दर की अस्थिरता की गणना परिवर्तन गुणांक का उपयोग करके की गई है

4.74 रुपया/अमेरिकी डॉलर विनिमय दर वित्त वर्ष 24 में 82-83.5 अमेरिकी डॉलर की सीमा में थी, जो वित्त वर्ष 24 के दौरान अमेरिकी डालर की तुलना में केवल 2.9 प्रतिशत कम थी। वित्त वर्ष 24 में पाउंड स्टर्लिंग और यूरो की तुलना में रुपये में क्रमशः 6.9 और 6.8 प्रतिशत की गिरावट आई। तथापि, इस अवधि में जापानी येन की तुलना में इसमें 3.5 प्रतिशत की तेजी देखी गई।

4.75 रुपये की विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित है। आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार को अपने व्यवस्थित कामकाज और विकास को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित करता है और केवल रुपये में अनुचित अस्थिरता को रोकने के लिए हस्तक्षेप करता है। यह रुपये की अस्थिरता को नियंत्रित करने और विदेशी मुद्रा बाजारों को स्थिर रखने में कामयाब रहा है। हाल ही में, इसने विनिमय दर की अस्थिरता को कम करने और वैश्विक स्पिल ओवर को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा वित्त पोषण के स्रोतों में विविधता लाने और विस्तार करने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की है। उदाहरण के लिए, ऋण प्रवाह में एफपीआई निवेश से संबंधित विनियामक व्यवस्था को भारतीय ऋण लिखतों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधित किया गया है।

चार्ट IV.35: वित्त वर्ष 24 के दौरान आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्राओं की निवल खरीद (+) और बिक्री (-) संबंधी रुझान

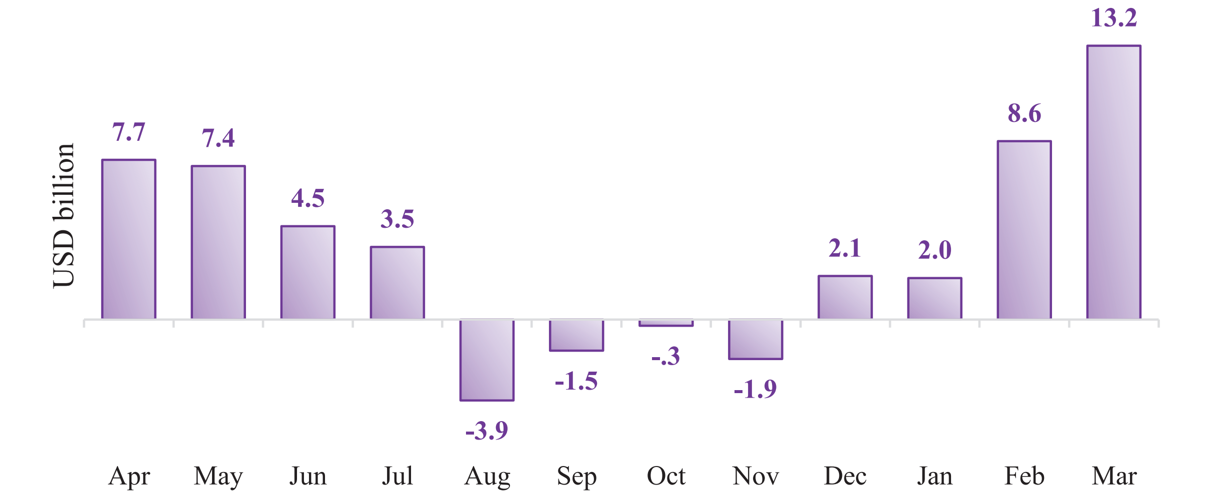

स्रोत: चार्ट संख्या 206, 'भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर की बिक्री और खरीद', विदेशी क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी पुस्तिका, आरबीआई

4.76 सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के सूचकांकों का उपयोग विदेशी प्रतिस्पर्धात्मकता के सूचक के रूप में किया जाता है।[109] वित्त वर्ष 24 में 40-मुद्रा (व्यापार-भारित) के संदर्भ में, एनईईआर में 0.6 प्रतिशत की कमी हुई है। तथापि वित्त वर्ष 24 के दौरान आरईईआर में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मई 2024 में, एनईईआर 92.2 और आरईईआर 104.7 देखी गई है जिसमें क्रमश: 0.03 प्रतिशत और 1.2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

चार्ट IV.36: 40-मुद्रा एनईईआर और आरईईआर (व्यापार-आधारित भार) के सूचकांक का उतार-चढ़ाव (आधार वर्ष 2015-16 = 100)

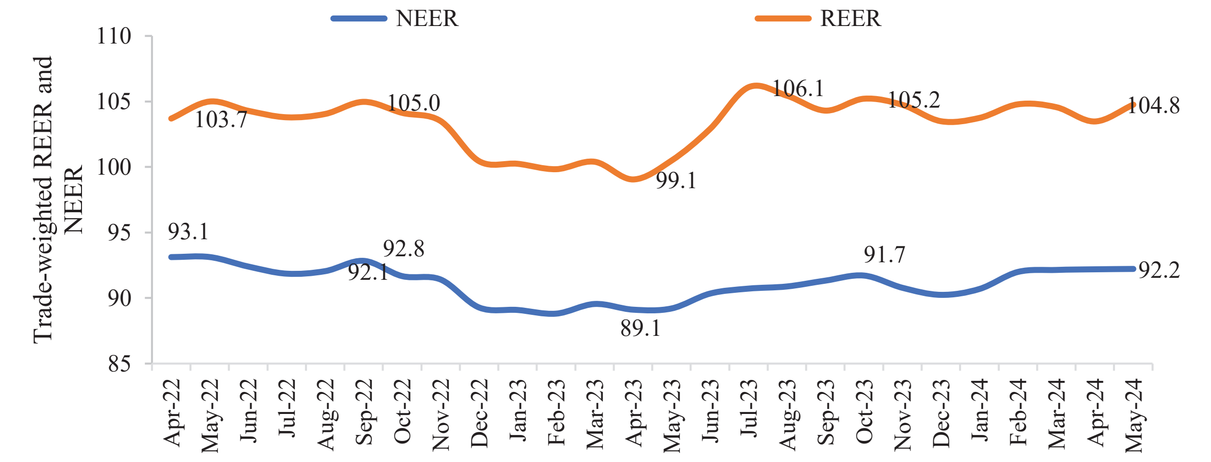

स्रोत: चार्ट संख्या 202, 'भारतीय रुपये की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) के सूचकांक (40-मुद्रा द्विपक्षीय भार, मासिक औसत), विदेशी क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी पुस्तिका, आरबीआई

4.77 नीचे दिए गए बॉक्स IV.7 में व्यापार चैनल के साथ-साथ वित्तीय चैनल के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था पर विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा की गई है।

109 एनईईआर विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में घरेलू मुद्रा की द्विपक्षीय सांकेतिक विनिमय दरों का भारित औसत है। आरईईआर को घरेलू और विदेशी देशों के बीच सापेक्ष मूल्य अंतर के लिए समायोजित सांकेतिक विनिमय दरों के भारित औसत के रूप में परिभाषित किया गया है।

बॉक्स IV.7: विनिमय दर के व्यापार और वित्तीय चैनल

ऐतिहासिक रूप से, अवमूल्यित मुद्रा निर्यात वृद्धि का एक प्रमुख चालक रही है। मार्शल लर्नर की शर्तें, यदि पूरी होती हैं, तो यह सुझाव देती हैं कि मुद्रा अवमूल्यन निर्यात लागत को कम करके और आयात कीमतों को बढ़ाकर शुद्ध निर्यात में वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकता है। भारत में विनिमय दर के इस 'व्यापार' चैनल को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है। हालाँकि, विनिमय दर 'वित्तीय' चैनल के माध्यम से बाहरी क्षेत्र को भी प्रभावित करती है। सिद्धांत बताता है कि विनिमय दर का वित्तीय चैनल संभावित रूप से व्यापार चैनल के माध्यम से किए गए लाभ (या हानि) को संतुलित कर सकता है।

कमजोर रुपया विदेशी फंडिंग की आपूर्ति और लागत को बदलकर भुगतान संतुलन (बीओपी) को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, मूल्यह्रास स्थानीय उधारकर्ताओं की ऋण-योग्यता को कम कर सकता है यदि उनके पास रुपया-मूल्यांक वाली परिसंपत्तियां हैं और वे विदेशी मुद्राओं में उधार लेते हैं। इससे विदेशी ऋण की लागत बढ़ सकती है और शुद्ध पूंजी का बहिर्वाह हो सकता है। वैश्विक स्तर पर, घरेलू मुद्राओं (डॉलर के मुकाबले) में वृद्धि ने सीमा पार बैंकिंग पूंजी प्रवाहों[110] को बढ़ा दिया है। हालांकि, केयर्न्स और पटेल (2016) दर्शाते हैं कि विनिमय दर का वित्तीय चैनल आम तौर पर ईएमई में अधिक सामर्थवान होता है, जहां अनियंत्रित विदेशी मुद्रा जोखिम मौजूद[111] होने की अधिक संभावना होती है।

पिछले दो दशकों में, भारत का एफडीआई और इक्विटी पोर्टफोलियो प्रवाह सालाना सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.5 प्रतिशत रहा है (आईएमएफ, 2023)[112]। सामान्य तौर पर, वित्त वर्ष 2014 और वित्त वर्ष 2024 के बीच पूंजी खाते में प्रवाह में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसलिए, दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ भारत के बड़े और बढ़ते वित्तीय खाते के संदर्भ में, क्या रुपया प्रतिस्पर्धी बना रहना चाहिए, यह विचारणीय प्रश्न है।

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, व्यापार-भारांकित विनिमय दर और ऋण-भारित विनिमय दर का उपयोग करके विनिमय दर के दो अलग-अलग चैनलों का प्राक्कलन किया गया था। आरबीआई द्वारा प्रदान की गई व्यापार-भारांकित नामित प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) का उपयोग व्यापार चैनल को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। वित्तीय चैनल को ऋण-भारांकित विनिमय दर (डीडब्ल्यूईआर) द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसे प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपए के अंकगणितीय औसत के रूप में तैयार किया जाता है, तथा बाह्य ऋण की संरचना में उनके हिस्से के आधार पर भारांकित किया जाता है।

सिद्धांत रूप में, शुद्ध 'भुगतान संतुलन (बीओपी)' शून्य के बराबर होना चाहिए क्योंकि व्यापार अधिशेष (घाटे) पूंजी खाता घाटे (अधिशेष) के बराबर होते हैं। हालाँकि, व्यवहार में, देश बीओपी संतुलन के दुर्लभ उदाहरणों के साथ शुद्ध बीओपी घाटे/अधिशेष की सूचित करते हैं। साहित्य 'भुगतान संतुलन' (बीओपी) असंतुलनों को मौद्रिक असंतुलन और मुद्रा की अत्यधिक आपूर्ति या मांग के परिणाम के रूप में समझाता है। इसलिए, मुद्रा के आवागमन की उपस्थिति में दो चैनल (व्यापार और वित्तीय) किस हद तक एक दूसरे का प्रतिकार करते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए, यहाँ इस्तेमाल किया जाने वाला आश्रित चर शुद्ध बीओपी होता है।

शुद्ध भुगतान संतुलन (बीओपी) पर रुपये के मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि के अलग-अलग चैनलों को कैप्चर के लिए एक ऑटो-रिग्रेसिव डिस्ट्रब्यूटिव लैग (एआरडीएल) मॉडल का उपयोग किया जाता है। त्रुटियों के स्वतः सहसंबंध की अनुपस्थिति में एआरडीएल रूपरेखा में अंतर्जातता की समस्या को नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा, 'बहुसमरेखीयता (मल्टीकोलिनेअरिटी)' भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है क्योंकि इसमें चरों के अंतराल और अंतरों का उपयोग किया जाता है।

$$\Delta lnBoP_t = \gamma_i \sum BoP_{t-1} + \delta_i \sum \Delta DWER_t + \beta_i \sum \Delta NEER_t + \theta X_t + \varepsilon_t$$

110 ब्रूनो, वी., और शिन, एच.एस. (2015). कैपिटल फ्लोज एंड द रिस्क टेकिंग चैनल ऑफ मोनीटरी पालिसी, जर्नल ऑफ मोनीटरी इकोनॉमिक्सए 71, 119-132

111 बनर्जी, आर., हॉफमैन, बी., एंड मेहरोत्रा, ए. एन. (2020). कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट एंड द एक्सचेंज रेट : द फाइनेंसियल चैनल

112 आईएमएफ, 2024 इंडियाज फाइनेंसियल सिस्टम : बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर स्ट्रांग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ

उपयोग में लाया गया डेटा वित्त वर्ष 2012 की पहली तिमाही से वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के बीच तिमाही आवृत्ति पर है। आश्रित चर नामिक शर्तों में शुद्ध भुगतान संतुलन है जिसकी गणना Ln (BoP क्रेडिट)/(BoP डेबिट) के रूप में की जाती है; डीडब्ल्यूईआर ऋण-भारांकित विनिमय दर को प्रदर्शित करता है। गुणांक δ_i और β_i, विनिमय दर के ऋण चैनल और विनिमय दर के व्यापार चैनल में परिवर्तन के प्रति शुद्ध भुगतान संतुलन की लोच को दर्शाते हैं। Xt में विश्व आयात, रेपो दर, कमोडिटी की कीमतें, घरेलू मांग, जीडीपी डिफ्लेटर और कोविड-19 वर्षों (मार्च 2020 से मार्च 2022) के लिए एक डमी जैसे नियंत्रण चर शामिल हैं। एआईसी मानदंड के अनुसार रिग्रेसर्स के लिए इष्टतम अंतरालों का चयन किया जाता है।

आश्रित चर - नेट बीओपी

रिग्रेसर्स	लॉन्ग रन इलास्टिसिटी
डीडब्ल्यूईआर	0-16*
एनईईआर	&0-7*

'*' 10 प्रतिशत के स्तर पर महत्व को दर्शाता है

परिणाम दर्शाते हैं कि भारत का व्यापार चैनल वित्तीय चैनल से अधिक मजबूत है। दीर्घावधि में, मूल्यवृद्धि का शुद्ध प्रभाव ऋृणात्मक (-0.7 + 0.16) होता है। इस प्रकार, रुपये में एक प्रतिशत की वृद्धि से भुगतान संतुलन में 0.54 प्रतिशत की शुद्ध गिरावट आती है।[113]

क्रमिक सहसंबंध और पैरामीटर स्थिरता (सीयूएसयूएम परीक्षण) के लिए अनुमान के बाद की जाँच करने के अलावा, गतिशील ओएलएस ढांचे में चर का अध्ययन करके सृदृढ़ता की जाँच की गई। सृदृढ़ता जाँच का परिणाम नीचे दिया गया है:

आश्रित चर - नेट बीओपी

रिग्रॉसर	लॉन्ग रन इलास्टिसिटी
डीडब्ल्यूईआर	0-12**
एनईईआर	&1-01**

'**' 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्त्व को दर्शाता है

परिणाम यह रेखांकित करते हैं कि प्रतिस्पर्धी रुपया भुगतान संतुलन को बढ़ावा देता रहता है क्योंकि व्यापार चैनल के माध्यम से प्राप्त लाभ वित्तीय चैनल में होने वाली लागतों से अधिक होते हैं। जैसा कि लॉन्गरिक 2022 द्वारा उल्लेख किया गया है, भारत के उच्च व्यापार खुलेपन और बाहरी ऋण की कम हिस्सेदारी का मतलब है कि मुद्रा में उतार-चढ़ाव का व्यापार चैनल प्रभाव वित्तीय चैनल प्रभाव पर हावी है। यह ब्राजील और फिलीपींस जैसी अन्य ईएमई के विपरीत है, जिनके वित्तीय चैनल प्रभाव व्यापार प्रभाव पर हावी हैं।

अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति

4.78 निवल आईआईपी[114] स्थिति यह निर्धारित करती है कि कोई देश अपनी विदेशी आस्तियों और देनदारियों के बीच अंतर को मापकर निवल लेनदार या देनदार राष्ट्र है या नहीं। मार्च 2024 के अंत तक, भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय आस्ति 1,028.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो मार्च 2023 के स्तर की तुलना में 109.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 11.9 प्रतिशत अधिक थी, जो मुख्य रूप से आरक्षित आस्ति, मुद्रा और जमा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, व्यापार ऋण और अग्रिम और ऋण में वृद्धि हुई थी। इसी अवधि में देश की आरक्षित आस्तियां 646.4 बिलियन डॉलर रहीं, जो भारत की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय आस्तियों का लगभग 62.9 प्रतिशत है।इसमें इसी अवधि के दौरान 11.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

113 उदाहरण के लिए देखें, फ्रेंकेल, जे., और मुसा, एम. (1985)। एसेट मार्केट्स, एक्सचेंज रेट्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, हैंडबुक ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम II (एडि.), रोनाल्ड जोन्स एंड पीटर केनन; जॉनसन, एच, जी. (1958)। टुवर्ड्स जनरल अ थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट।

114 आईएमएफ, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजिशन मैनुअल के अनुसार, आईआईपी सांख्यिकीय विवरण है जो किसी समय पर (क) किसी अर्थव्यवस्था के निवासियों की वित्तीय आस्तियों का मूल्य और संरचना दर्शाता है जो गैर-निवासियों का दावा है और आरक्षित आस्तियों के रूप में रखे गए सोने के बुलियन, और (ख) किसी अर्थव्यवस्था के निवासियों की गैर-निवासियों के प्रति देनदारियाँ हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था की विदेशी वित्तीय आस्तियों और देनदारियों के बीच का अंतर अर्थव्यवस्था का निवल आईआईपी है, जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है।

4.79 मार्च 2024 के अंत तक 1,390 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय देनदारियां मार्च 2023 के स्तर की तुलना में 104.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (8.1 प्रतिशत) अधिक थीं। इस वृद्धि को मुख्य रूप से पोर्टफोलियो निवेश, ऋण, प्रत्यक्ष निवेश और अन्य देय खातों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। मार्च 2024 तक कुल विदेशी देनदारियों में ऋण देनदारियों का हिस्सा 51.1 प्रतिशत था।

4.80 इस प्रकार, मार्च 2024 के अंत तक भारत में गैर-निवासियों के निवल दावों का मूल्य 361.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो मार्च 2023 के स्तर से 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर कम हो गया। मार्च 2024 के अंत तक भारत की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आस्तियों में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय देनदारियों का 74 प्रतिशत शामिल था।

मार्च 2024 के अंत में भारत की निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति में सुधार

चार्ट IV.37(क): निवल आईआईपी और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में

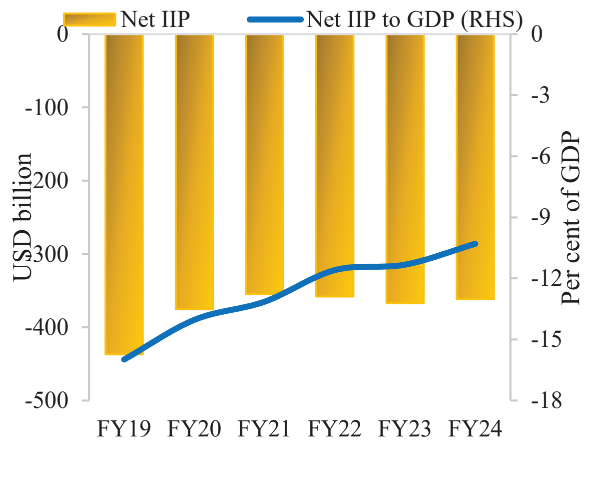

चार्ट IV.37(ख): आस्ति देनदारियों का अनुपात (प्रतिशत में)

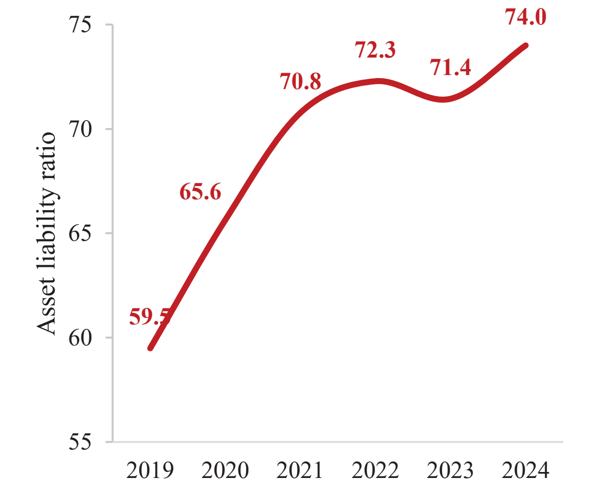

स्रोत: 'भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति', सांख्यिकी, विदेशी क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय वित्त, आरबीआई

स्थिर विदेशी ऋण की स्थिति

4.81 चालू खाते को राष्ट्रीय (सार्वजनिक और निजी दोनों) बचत और निवेश के बीच अंतर के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। अत चालू खाता घाटा निवेश के वांछित स्तर की तुलना में राष्ट्रीय बचत के निम्न स्तर को प्रतिबिम्बित कर सकता है। घरेलू बचत के पूरक के रूप में विदेशी ऋण देशों को तेजी से बढ़ने में मदद करता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, उच्च आर्थिक विकास आमतौर पर उच्च विदेशी ऋण से और विलोमत: जुड़ा होता है। तथापि, विदेशी ऋण का असंधारणीय बड़ा स्टॉक संभावित रूप से संवेदनशीलता पैदा कर सकता है और विकास की संभावनाओं को कम कर सकता है।

4.82 भारत ने चालू खाता घाटे को संधारणीय सीमाओं के भीतर रखने और विदेशी वित्त के गैर-ऋण सृजन को प्रोत्साहित करने के व्यापक उद्देश्य के साथ अपने विदेशी ऋण का विवेकपूर्ण प्रबंधन किया है। भारत का विदेशी ऋण वर्षों से संधारणीय रहा है, जैसा कि नीचे चार्ट IV.38 में स्पष्ट है। सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में विदेशी ऋण मार्च 2024 के अंत में घटकर 18.7 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2023 के अंत में 19.0 प्रतिशत था। कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण (एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता सहित) की हिस्सेदारी मार्च 2024 के अंत में घटकर 18.5 प्रतिशत हो गई, जो मार्च 2023 के अंत में 20.6 प्रतिशत थी। कुल ऋण का एफईआर अनुपात मार्च 2024 तक 97.4 प्रतिशत था।

चार्ट IV.38: स्थिर भारत की विदेशी ऋण स्थिति और सुगम संकेतक

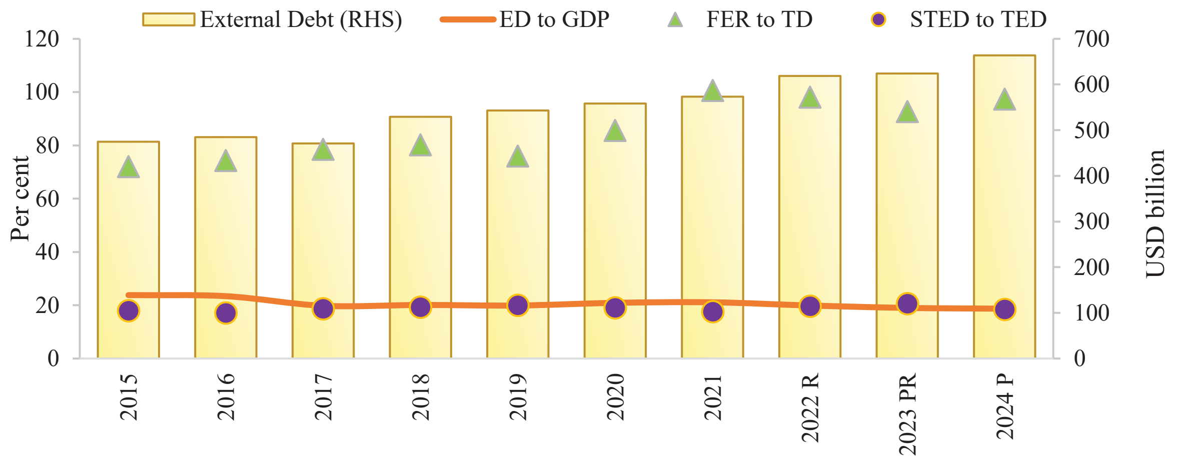

स्रोत: 'भारत का विदेशी -त्रैमासिक ऋण और भारत का विदेशी ऋण-अमेरिकी डॉलर (मार्च के अंत तक)', सांख्यिकी, विदेशी क्षेत्र, विदेशी ऋण-आरबीआई
टिप्पणी: आर-संशोधित, पीआर-आंशिक रूप से संशोधित, पी-अनंतिम; ईडी-विदेशी ऋण, एफईआर-विदेशी मुद्रा भंडार, टीईडी-कुल विदेशी ऋण, एसटीईडी-अल्पवाधिक विदेशी ऋण

4.83 वर्ष 2022 में अन्य देशों के साथ भारत के विभिन्न ऋण सुगम संकेतकों की तुलना करने से यह संकेत मिलता है कि सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) के प्रतिशत के रूप में कुल ऋण के अपेक्षाकृत निम्न स्तर और कुल विदेशी ऋण के प्रतिशत के रूप में अल्पकालिक विदेशी ऋण सहित भारत की स्थिति बेहतर है। एफईआर का पर्याप्त स्तर इसे और अधिक सुगम बनाता है।

सारणी IV.3: भारत के प्रमुख विदेशी ऋण संकेतक: स्थिरता का संक्षिप्त विवरण

(प्रतिशत, जब तक कि अन्यथा इंगित न किया गया हो)

मार्च के अंत में	विदेशी ऋण (बिलियन अमेरिकी डालर)	सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी ऋण	ऋण सेवा अनुपात	कुल ऋण के लिए विदेशी मुद्रा भंडार	कुल ऋण में रियायती ऋण	विदेशी मुद्रा भंडार में अल्पावधि ऋण	कुल ऋण में अल्पकालिक ऋण (मूल परिपक्वता)
2018	529.3	20.1	7.5	80.2	9.1	24.1	19.3
2019	543.1	19.9	6.4	76.0	8.7	26.3	20.0
2020	558.4	20.9	6.5	85.6	8.8	22.4	19.1
2021	573.4	21.1	8.2	100.6	9.0	17.5	17.6
2022 आर	618.8	19.9	5.2	98.1	8.3	20.0	19.7
2023पीआर	624.1	19.0	5.3	92.7	8.2	22.2	20.6
2024 पी	663.8	18.7	6.7	97.4	7.5	19.0	18.5

स्रोत: वित्त मंत्रालय
आर: संशोधित, पीआर: आंशिक रूप से संशोधित; अ: अनंतिम

संभावनाएं और चुनौतियां

4.84 हालांकि सतत भू-राजनीतिक ऊथल-पुथल ने भारत के व्यापारिक निर्यात को प्रभावित किया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी की कीमतों को कम करने से वित्त वर्ष 23 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में कम व्यापार घाटा सुनिश्चित हुआ।

व्यापारिक घाटे में कमी और सेवा निर्यात में वृद्धि से चालू खाते के घाटे में सुधार हुआ है, जिससे वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 0.6 प्रतिशत अधिशेष रहा। आने वाले वर्षों में, भारत के व्यापार घाटे में और गिरावट आने की उम्मीद है क्योंकि पीएलआई योजना का विस्तार किया गया है और भारत कई उत्पाद श्रेणियों में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण आधार तैयार करता है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में हस्ताक्षरित ईएफटीए से देश के निर्यात के वैश्विक बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि होने की उम्मीद है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और आरबीआई को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 24 के लिए सीएडी से जीडीपी एक प्रतिशत से कम हो जाएगा, जो बढ़ते व्यापारिक और सेवाओं के निर्यात और रेजीलिएस रेमिटेंस से प्रेरित है

4.85 तथापि वर्तमान भू-राजनीतिक तनाव और नीतिगत अनिश्चितता की निरंतरता के कारण भारत के विदेशी क्षेत्र के निष्पादन के लिए जोखिम कम हुआ है। कुछ चुनौतियों का उल्लेख नीचे किया गया है: -

- **प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मांग में गिरावट:** डीजीसीआईएस आंकड़ों के अनुसार, चीन के बाद वित्त वर्ष 24 में अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। तथापि, वर्ष 2022 में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2023 में यूएसए को कुल आयात में 1.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसने भारत सहित व्यापारिक भागीदारों में निर्यात वृद्धि को काफी प्रभावित किया।[115] बढ़ता संरक्षणवाद एक और जोखिम है जो वर्ष 2024 और वर्ष 2025 में व्यापार रिकवरी को कमजोर कर सकता है।
- **व्यापार लागत में वृद्धि:** लाल सागर में शिपिंग पर हमलों और पनामा नहर में सूखे के कारण व्यापार प्रवाह का मार्ग बदल गया है, जिससे यात्रा का समय और लागत बढ़ गई है, जैसा कि ऊपर पैरा 4.8 में बताया गया है। भारत का मर्केनडाइडेड व्यापार समुद्री व्यापार पर बहुत अधिक निर्भर करता है, इसलिए प्रमुख पोत परिवहन मार्गों में गड़बड़ी इसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। सीआरआईएसआईएल की एक रिपोर्ट[116] में कहा गया है कि लाल सागर संकट ने भारत में मध्य पूर्व के उर्वरक निर्यात को प्रभावित किया है क्योंकि जॉर्डन और इजराइल से म्यूरिएट ऑफ पोटाश का आयात प्रभावित हुआ है।
- **कमोडिटी की कीमत में अस्थिरता:** कमोडिटी विशेष रूप से तेल, धातु और कृषि उत्पादों जैसे महत्वपूर्ण आयातों की कीमतों में उतार-चढ़ाव, भारत के व्यापार संतुलन और मुद्रास्फीति के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। निराशाजनक वैश्विक विकास विशेष रूप से औद्योगिक वस्तुओं के लिए नकारात्मक जोखिम उत्पन्न कर सकता है। अतिरिक्त व्यापार प्रतिबंध खाद्य कीमतों को अधिक बढ़ा सकते हैं।
- **व्यापार नीति में बदलाव:** प्रमुख व्यापारिक भागीदारों द्वारा व्यापार नीतियों में परिवर्तन या भू-राजनीतिक घटनाक्रम भारत के निर्यात अवसरों और बाजार पहुंच को प्रभावित कर सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन की व्यापार निगरानी रिपोर्ट, नवंबर 2023[117] के अनुसार, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा नए निर्यात प्रतिबंधों के कार्यान्वयन की गति वर्ष 2020 से काफी बढ़ गई है। कोविड-19 से संबंधित 20 निर्यात प्रतिबंधों के अतिरिक्त खाद्य, चारा और उर्वरकों पर 75 निर्यात प्रतिबंध अभी भी लागू हैं। वर्ष 2023 के लिए लागू आयात प्रतिबंधों के तहत शामिल किया गया व्यापार अनुमानत 2,480 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कुल विश्व आयात के लगभग दसवें हिस्से को दर्शाता है।

4.86 यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि भारत के लिए इन बदलते प्रतिमानों का क्या अर्थ है। नीतियों को ऐसा होना चाहिए जो आर्थिक विचारों के साथ सुरक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान करे। पीएलआई और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से जटिल और विशिष्ट क्षेत्रों में विनिर्माण हेतु भारत के महत्वपूर्ण कदमों में इन लक्ष्यों को संतुलित करना शामिल है। दूसरी ओर, सेवाओं में भारत की बढ़त आने वाले वर्षों में हमारे वैश्वीकरण को बल प्रदान करेगी। पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स[118] के हालिया लेख में यह दावा किया गया है कि सेवाओं में वैश्वीकरण जारी है, भले ही हम माल में हाइपरग्लोबलाइज्ड व्यापार के युग से आगे निकल चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत के सेवा क्षेत्र के निर्यात की वैश्विक मांग बढ़ रही है।

115 ओईसीडी आर्थिक आउटलुक, मई 2024, https://www.oecd.org/economic-outlook/may-2024/ https://tinyurl.com/2xf5cb6x

116 https://tinyurl.com/2xf5cb6x

117 https://www.wto.org/english/news_e/spno_e/spno42_e.htm

118 आईबीआईडी, टिप्पणी37

4.87 भारत एक साथ लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में विकास से एकीकरण द्वारा संभावित लाभों का फायदा उठाने की दिशा में काम कर रहा है। यह व्यापार को बढ़ाने के लिए किए गए अवसंरचना के महत्वपूर्ण समझौते से स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (आईएनएसटीसी) से रूस और यूरोप में शिपमेंट के लिए व्यापार समय कम होने की उम्मीद है। एक अन्य प्रमुख संयुक्त अवसंरचना समझौता, भारत-मध्य पूर्व यूरोप गलियारा (आईएमईसी), एशिया को पत्तनों और रेलमार्गों के माध्यम से यूरोप से जोड़ेगा। इसी तरह, भौगोलिक क्षेत्रों में फैले देशों के साथ व्यापार समझौते करने की दिशा में ठोस प्रयास किया जा रहा है।

4.88 अंततः, भारत को कई उत्पाद क्षेत्रों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भारत में कृषि संबंधी वस्तुओं का बड़ा वैश्विक निर्यातक बनने की जबरदस्त क्षमता है। मजबूत क्षेत्रीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने और भारतीय वस्तुओं के लिए अधिक बाजार जोड़ने से वैश्विक मांग में उतार-चढ़ाव को कम करने में मदद मिलेगी। ऐसे युग में जब वैश्विक आर्थिक विकास भू-राजनीतिक तनाव और संरक्षणवाद से प्रभावित होने की संभावना है, वैसे में भारत के माल और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि पहले की तुलना में कठिन चुनौती होगी। निजी क्षेत्र में उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता संबंधी धारणा और सार्वजनिक क्षेत्र में नीतिगत स्थिरता संबंधी चुनौती को अवसर में बदलने के लिए निश्चित रूप से सही समय हैं।

****

मध्यम अवधि परिदृश्य: नए भारत के लिए विकास-दृष्टि

05

अध्याय

'विकसित भारत' का सीधा लाभ हमारे नागरिकों की गरिमा और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार है।"

2 जुलाई, 2024 को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय प्रधान मंत्री के उत्तर से उद्धृत

पिछले दशक में भारत की विकास की कहानी लचीलेपन की कहानी रही है। वर्ष 2014 से भारत सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधारों ने अर्थव्यवस्था को मजबूती से विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है और भारत शीघ्र ही यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। मध्यम अवधि में, यदि हम पिछले दशक में किए गए संरचनात्मक सुधारों पर काम कर सकें तो भारतीय अर्थव्यवस्था संधारणीय आधार पर 7 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ सकती है। इस पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में मुख्य नीतिगत फोकस क्षेत्रों को चिह्नित की गई है और साथ ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छह-आयामी विकास रणनीति प्रस्तुत की गई है। इस अध्याय में स्पष्ट की गई रणनीति इस जानकारी पर आधारित है कि पिछले दशक के संरचनात्मक सुधारों, जो अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष पर केंद्रित थे, को अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए मार्ग देना होगा जो मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास देने की प्रकृति में नीचे से ऊपर की ओर हैं।

सन्दर्भ निर्धारित करना

5.1. वर्ष 1993 में, भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल्य मौजूदा कीमतों पर डॉलर के लिहाज से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम था। वर्ष 2024 तक तीव्रता के साथ आगे बढ़ते हुए, यह अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 3.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। यह वर्ष 1993 और वर्ष 2024 के बीच भारतीय रुपये में सालाना लगभग 3% की गिरावट के बावजूद उल्लेखनीय 12 गुना वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा, यह देश की समग्र ऋणग्रस्तता में बड़ी वृद्धि के बिना हासिल किया गया है, जो पूंजी के कुशल उपयोग को दर्शाता है। भारत की प्रति व्यक्ति वर्तमान डॉलर जीडीपी वर्ष 1993 में 301.5 से बढ़कर वर्ष 2023[1] में 2,484.8 हो गई है, जो जीवन स्तर में पर्याप्त सुधार का संकेत देती है।

5.2. भारत एक ऐतिहासिक और पुरानी सभ्यता है। इसने ऐसे कई सवालों के जवाब दिए हैं जो मानव जाति के सामने आये हैं और अभी भी आते रहते हैं। यह एक बड़ा भूभाग और विशाल जनसंख्या वाला देश है। यह आर्थिक और अन्य दृष्टि से एक महान शक्ति के रूप में गिने जाने की आकांक्षा रखता है। चीन, जो पूर्वोत्तर में भारत का पड़ोसी है और भारत के बराबर आकार और जनसंख्या और पुरातन सभ्यता वाला देश है, एक पीढ़ी से भी कम समय में एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बन गया है। भारत ने भी अब अपने लिए वर्ष 2047 तक, स्वतंत्रता के सौवें वर्ष तक एक पीढ़ी के भीतर एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

1. विश्व बैंक, 2023 (https://tinyurl.com/yeksmbde)

5.3. आज, दुनिया कई बड़ी खामियों का सामना कर रही है। हम एक बहुध्रुवीय दुनिया में पहुँच चुके हैं। यह उस द्विध्रुवीय दुनिया से कहीं ज्यादा कठिन है, जिसके हम युद्ध समाप्त होने के बाद लगभग पांच दशकों तक आदी थे। इसलिए, आने वाले दशकों में छोटे और महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक संघर्ष होने की संभावना बनी हुई है।

5.4. सांस्कृतिक स्तर पर, उन्नत देशों में मुख्यधारा के मीडिया द्वारा जिसे 'फार राइटश कहा जाता है, का उदय, वास्तव में, वैश्विकतावादी-अभिजात वर्ग और अन्य लोगों के बीच प्राथमिकताओं का टकराव है, जिनकी नियति उनके राष्ट्रीय भूगोल के प्रति बाध्य है। प्राथमिकताओं का यह टकराव अर्थशास्त्र से परे है। इसमें सांस्कृतिक और सामाजिक प्राथमिकताएँ और मूल्य शामिल हैं। इसलिए, आर्थिक ठहराव और भू-राजनीतिक संघर्षों के साथ-साथ, उन्नत देशों में समाज भीतर से भी टूट रहे हैं। लंबे राजनीतिक, सामाजिक और सभ्यतागत चक्रों का विश्लेषण करने वाले साहित्य ने हमें सदी के मध्य तक तीन दशकों में काफी उथल-पुथल भरी चेतावनी दी है।

5.5. आर्थिक वैश्वीकरण का विचार अपना दौर पूरा कर चुका है। हो सकता है कि इसे पूरी तरह से उलटा न किया जाए, लेकिन यह चरम पर पहुंच चुका है। इसमें बाधाओं का सामना करना जारी रहेगा क्योंकि दुनिया भर में आर्थिक नीतियां राष्ट्रीय चौंपियनों को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं, जिनके कारण इतने प्रसिद्ध हैं कि उन्हें यहां दोहराना संभव नहीं है। वैश्वीकरण के चरम पर पहुंचने के साथ-साथ, राष्ट्रीय आर्थिक रणनीति में सरकार की भूमिका पर भी पुनर्विचार हो रहा है क्योंकि कोविड महामारी के बाद असमानता, गरीबी और ऋणग्रस्तता गंभीर मुद्दे बन गए हैं। इन वैश्विक और पीढ़ीगत चुनौतियों के आसान जवाबों की मांग ने समृद्ध या और अधिक समान समाज प्राप्त करने में उनके खराब अनुभवजन्य रिकॉर्ड के बावजूद हस्तक्षेपकारी नीतियों के लिए एक बहाना बनाया है।

5.6. अंततः, यह जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न संकट है। विकसित देश वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए दबाव बना रहे हैं। अपने ही देशों में उत्सर्जन में कमी लाने में उनकी नीतियों की प्रभावशीलता संदिग्ध होने के कारण, वे विकासशील देशों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। विकासशील देश अपने देशों में आर्थिक विकास को बहाल करने और गरीबी और कर्ज को कम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें से सभी को कोविड-19 महामारी ने बढ़ा दिया है। स्वच्छ ईंधन की ओर आवश्यक परिवर्तन करने के लिए उनके पास प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधनों दोनों का अभाव है। विकसित राष्ट्र वचन देने के मामले में उदार होते हैं और उनमें से किसी एक को पूरा करने में कंजूसी बरतते हैं। इसके अलावा, अगले आधे से पूरे दशक तक जलवायु परिवर्तन और उनके आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए कठोर उपायों की प्रभावकारिता के बारे में भारी अनिश्चितताएं हैं। धीमी वृद्धि, स्थिरता, या पूर्ण संकुचन सामाजिक अशांति को बढ़ावा देगा और लोगों का पश्चिम की ओर पलायन होगा।

5.7. यह अगली तिमाही सदी के लिए भारत के विकास, समृद्धि और महाशक्ति आकांक्षाओं की वैश्विक पृष्ठभूमि है। इसके विपरीत, यह अपने उत्थान के दौरान, चीन को इनमें से कई चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा और उन्होंने जो सामना किया भी, वे तुलनात्मक रूप से काफी हद तक कमजोर थीं। बदली हुई परिस्थितियों के बावजूद, भारत की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए, शुरुआत करने के लिए एक अच्छी जगह यह स्वीकार करना और पहचानना है कि इसके माध्यम से पार करने और गंतव्य तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए भूभाग बदल गया है।

5.8. भारत को अपनी आर्थिक वृद्धि दर को 25 साल तक बनाए रखना है और इसे पर्यावरण और जलवायु को ध्यान में रखते हुए संधारणीय तरीके से करना है। जल संकट और वायु प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी है। जीवन प्रत्याशा, जो पहले की तुलना में अब बहुत अधिक है, हाल के वर्षों में स्थिर हो गई है। इसे अपने युवाओं को शिक्षित और कुशल बनाना होगा ताकि वे समय के साथ आगे रह सके और उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ काम कर सके और उन पर हावी हो सके, साथ ही महामारी के कारण संचित शिक्षा और कौशल की कमी को दूर कर सके, जिससे तकनीकी प्रगति की वर्तमान स्थिति के साथ भी उत्पादकता बढ़ाना कठिन हो जाता है। उत्तर-पश्चिम और पूर्वोत्तर दोनों में अपनी सीमाओं पर

निरंतर निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के साथ, साइबर सुरक्षा बहुत अधिक महत्व और तात्कालिकता प्राप्त करती है। इसलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करना अनिवार्य है। आर्थिक विकास से समझौता किए बिना राजकोषीय संसाधनों में वृद्धि करनी होगी।

5.9. संख्या के संदर्भ में क्षमता और सक्षमता, कौशल और दृष्टिकोण के संदर्भ में राज्य का सामर्थ्य अतिरिक्त कारक हैं जो भारत के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों के परिणामों को निर्धारित करेंगे। आर्थिक नीतियों को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि वे अन्य क्षेत्रों में समस्याओं को और अधिक कठिन बनाते हुए मुद्दों का संकीर्ण या अपूर्ण रूप से समाधान न करें। भूमि उपयोग और संसाधनों के लिए विरोधी शक्तियों पर निर्भरता के लिए इसके निहितार्थों के साथ अक्षय ऊर्जा के उच्च हिस्से के लिए लक्ष्य एक उदाहरण है। जल सुरक्षा पर कृषि क्षेत्र की नीतियों का प्रभाव एक और उदाहरण है।

5.10. पहले बताई गई वैश्विक पृष्ठभूमि के कारण भारत के लिए अपने निर्यात को पूर्वी एशियाई देशों के समान गति और स्तर पर बढ़ाना संभव नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी अवधारणाओं के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में वर्ष-दर-वर्ष उतार-चढ़ाव होने की संभावना है, इसलिए भारत को अपने निवेश और विकास प्राथमिकताओं के लिए ज्यादातर घरेलू संसाधन जुटाने होंगे। भू-राजनीति बाह्य घाटे और परिणामतः बाह्य वित्तपोषण पर अपनी सीमा लगाती है।

5.11. इस पृष्ठभूमि में, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मध्यम अवधि की वृद्धि का दृष्टिकोण, जिसका विस्तृत विवरण इस अध्याय में दिया जाएगा, निम्नलिखित मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है:

- **पहला, बढ़ते भू-आर्थिक विखंडन और परिणामस्वरूप संसाधन राष्ट्रवाद का देशों पर महत्वपूर्ण विकास-सीमित प्रभाव पड़ता है।** इससे कार्यकुशलता और लचीलेपन के बीच एक ऐसा संतुलन पैदा हुआ है जो एक दशक पहले तक मौजूद नहीं था। बफर्स और स्लैक के निर्माण के माध्यम से आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने ने दक्षता की सीमाओं पर काम करने की क्षमता को बदल दिया है । श्जस्ट इन केसश ने श्जस्ट इन टाइमश को बदल दिया है।
- **दूसरा, वैश्विक विश्वास की कमी देशों को आत्मनिर्भर बनने और बाह्य झटकों खासकर रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों से बचाने पर केंद्रित नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है।** इसलिए, आगे बढ़ने के लिए अंतर्मुखी नीतियों बनाम बहिर्मुखी नीतियों के बीच संतुलन को और अधिक सूक्ष्म बनाने की आवश्यकता है;
- **तीसरा, राष्ट्रीय विकास नीति और नियोजन में जलवायु परिवर्तन रणनीतियों का एकीकरण न केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता है, बल्कि इससे भी अधिक** महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सामाजिक-आर्थिक स्थिरता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, बैंकिंग और सार्वजनिक वित्त को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण लागत अधिरोपित होता है, इसलिए नीति-निर्माताओं को जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और उत्सर्जन में कमी के बीच संतुलन बनाने की जरूरत होती है। यह एक ओर उर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक विकास और दूसरी ओर उर्जा संक्रमण के बीच दुविधा भी पैदा करता है।
- **चौथा,** अच्छे और बुरे के लिए, प्रौद्योगिकी राष्ट्रों की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करने वाले सबसे बड़े रणनीतिक विभेदक के रूप में उभर रही है। इसकी उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता संदेह से परे है, लेकिन श्रम बाजार में व्यवधान और श्रम विस्थापन के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के सामाजिक प्रभाव को शायद ही समझा जा सके। इसमें आय के पूँजी और श्रम के हिस्से को पहले के पक्ष में झुकाने की भी क्षमता है।
- **पांचवां, वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद कई संकटों को देखते हुए**, सभी देशों के पास कार्यसाधन के

लिए नीतिगत गुंजाइश सीमित हैं। इसलिए, नीति निर्माताओं के लिए ट्रेड-ऑफ की मान्यता और स्वीकृति पहले की तुलना में अधिक आवश्यक हो गई है।

- **छठा**, पिछले दशक (2014-2024) में, भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को बहाल करने, आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को दूर करके संभावित विकास को बढ़ाने और अपनी क्षमताओं को मजबूत करने पर केंद्रित बड़े पैमाने पर सुधारों को आगे बढ़ाया है, जो वर्तमान और अमृत काल में लोगों की विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है। अगला चरण यह सुनिश्चित करना है कि इन सुधारों को सही तरीके से लागू किया जाए और इसके लिए राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के साथ गहन जुड़ाव की आवश्यकता होगी। **आगे बढ़ते हुए, सरकार का ध्यान नीचे से ऊपर तक सुधार और शासन की पाइपलाइन को मजबूत करने पर होना चाहिए, ताकि पिछले दशक के संरचनात्मक सुधारों से मजबूत, संधारणीय, संतुलित और समावेशी विकास प्राप्त हो सके।**

अल्प से मध्यम अवधि में नीतिगत फोकस के प्रमुख क्षेत्र

5.12. भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, वृहद स्तर पर तथा क्षेत्रीय स्तर पर, जिसका इस सर्वेक्षण के शेष अध्यायों में विस्तार से वर्णन किया गया है, के आधार पर वर्तमान खंड नीतिगत फोकस के कुछ प्रमुख क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत का विकास निर्बाध रूप से जारी रहे, तथा शीघ्र ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मील के पत्थर को पार कर नई ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर हो।

5.13. उत्पादक रोजगार उत्पन्न करना : उत्पादक नौकरियां विकास और समावेशन के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत का कार्यबल लगभग 56.3 करोड़ होने का अनुमान है, जिसमें से 45 प्रतिशत से अधिक कृषि में, 11.4 प्रतिशत विनिर्माण में, 28.9 प्रतिशत सेवाओं में और 13 प्रतिशत निर्माण कार्य में कार्यरत हैं।[2] जबकि सेवा क्षेत्र एक प्रमुख रोजगार सृजनकर्ता बना हुआ है, निर्माण क्षेत्र हाल ही में प्रमुखता से बढ़ रहा है, जो सरकार के बुनियादी ढांचे के लिए जोर देने से प्रेरित है। हालाँकि, चूँकि निर्माण संबंधी नौकरियाँ बड़े पैमाने पर अनौपचारिक और कम वेतन वाली हैं, इसलिए कृषि छोड़ने वाले श्रम बल के लिए अवसरों की आवश्यकता है। इस बीच, खराब ऋणों की विरासत के कारण पिछले एक दशक में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन धीमा रहा है और वर्ष 2021-22 से इसमें उछाल आया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अनुमानों के अनुसार, भारत की कामकाजी आयु वर्ग की आबादी (15-59 वर्ष) 2044 तक बढ़ती रहेगी। रोजगार पर अध्याय (अध्याय 8) का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ते कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में सालाना लगभग 78.51 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। हालांकि, इतनी नौकरियां पैदा करने के लिए, कृषि के बाहर उत्पादक नौकरियों के तेजी से विकास के लिए स्थितियां बनाने की जरूरत है, खासकर संगठित विनिर्माण और सेवाओं में, जबकि कृषि में उत्पादकता में सुधार भी जरूरी है।

5.14. कौशल अंतराल चुनौती: भारत की तेजी से बढ़ती आबादी का 65 प्रतिशत हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है और उनमें से कई लोगों में आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल का अभाव है।[3] अनुमान बताते हैं कि लगभग 51.25 प्रतिशत युवा रोजगार योग्य माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में, कॉलेज से सीधे निकलने वाले दो में से लगभग एक अभी भी आसानी से रोजगार योग्य नहीं है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि

---

2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
3. भारत को भविष्य के लिए कुशल, समावेशी कार्यबल बनाने में मदद करना, विश्व बैंक, 2023 (https://tinyurl.com/2tp4xpab)
4. बर्धन ए एंड राउथ, वी. 2024 - टैक्लिंग इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम : सर्विसेज, स्किल्स एंड सिमिट्री,आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन , (https://tinyurl.com/3uudbkms)

पिछले दशक में यह प्रतिशत लगभग 34 प्रतिशत से बढ़कर 51.3 प्रतिशत हो गया है।[4] कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि "भारत में शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्थिति पर एनएसएसओ, 2011-12 (68वें दौर) की रिपोर्ट के अनुसार, 15-59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में से लगभग 2.2% ने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है और 8.6 प्रतिशत ने अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है"। वार्षिक रिपोर्ट देश में कौशल और उद्यमिता परिदृश्य में चुनौतियों का उल्लेख करती है, जैसे कि: (i) आम धारणा जो कौशल को उन लोगों के लिए अंतिम विकल्प के रूप में देखती है जो प्रगति नहीं कर पाए हैं / औपचारिक शैक्षणिक प्रणाली से बाहर निकल गए हैं (ii) केंद्र सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम जो 20 से अधिक मंत्रालयों/विभागों में फैले हुए हैं, उनका अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए किसी भी मजबूत समन्वय और निगरानी तंत्र का अभाव है (iii) मूल्यांकन और प्रमाणन प्रणालियों में बहुलता जो असंगत परिणाम देती है और नियोक्ताओं के बीच भ्रम का कारण बनती है (iv) प्रशिक्षकों की कमी, उद्योग से पेशेवरों को संकाय के रूप में नियोजित करने में असमर्थता (v) क्षेत्रीय और स्थानिक स्तरों पर मांग और आपूर्ति के बीच बेमेल (vi) कौशल एवं उच्च शिक्षा कार्यक्रमों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच सीमित गतिशीलता (vii) प्रशिक्षुता कार्यक्रमों का बहुत कम कवरेज (viii) संकीर्ण और अक्सर अप्रचलित कौशल पाठ्यक्रम (ix) महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर में गिरावट (x) कम उत्पादकता वाले प्रमुख गैर-कृषि, असंगठित क्षेत्र के रोजगार के लिए कौशल के किसी लाभांश का न होना (xi) औपचारिक शिक्षा प्रणाली में उद्यमशीलता को शामिल न करना (xii) स्टार्ट-अप के लिए मार्गदर्शन और वित्त की पर्याप्त पहुंच का अभाव (xiii) नवाचार संचालित उद्यमशीलता को अपर्याप्त प्रोत्साहन (xiv) कुशल लोगों के लिए सुनिश्चित वेतन प्रीमियम का अभाव"। रोजगार पर अध्याय (अध्याय 8) कौशल अंतराल चुनौती और उसके सुधार के लिए चल रहे प्रयासों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है।

5.15. **कृषि क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन:** भारत के विकास पथ में अपनी केंद्रीय भूमिका के बावजूद, कृषि क्षेत्र को संरचनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसका भारत के आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। इस क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चिंता खाद्य पदार्थों की कीमतों में स्वीकार्य सीमा से अधिक वृद्धि किए बिना कृषि विकास को बनाए रखना और उपभोक्ताओं को परेशानी पहुंचाए बिना किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है।[5] कृषि उत्पादों के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र में सुधार, दक्षता में वृद्धि, छिपी हुई बेरोजगारी को कम करना, भूमि जोत के विखंडन का समाधान करना और फसल विविधीकरण को बढ़ाना, साथ ही कई अन्य मुद्दों की भी आवश्यकता है। इन सभी के लिए कृषि प्रौद्योगिकी के उन्नयन, कीमतों में स्थिरता, कृषि पद्धतियों में आधुनिक कौशल का अनुप्रयोग, कृषि विपणन के अवसरों को बढ़ाना, खेती में नवाचार को अपनाना, उर्वरक, पानी और अन्य इनपुट के उपयोग में होने वाली बर्बादी को कम करना और कृषि-उद्योग संबंधों में सुधार करना आवश्यक है। कृषि पर अध्याय (अध्याय-9) में कृषि को उसकी पूरी क्षमता का दोहन करने में सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों पर चर्चा की गई है।

5.16. **एमएसएमई के समक्ष आने वाली अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं और वित्तपोषण संबंधी बाधाओं को आसान बनाना:** एमएसएमई ने जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कनाडा, चीन आदि कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक प्रक्षेपवक्र को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में, सरकार एमएसएमई क्षेत्र को भारत की आर्थिक कहानी में केंद्रीय स्थान दिलाने पर विशेष ध्यान दे रही है। हालांकि, इस क्षेत्र को व्यापक विनियमन और अनुपालन आवश्यकताओं का सामना करना पड़ रहा है और सस्ती और समय पर वित्त पोषण तक पहुंच के साथ महत्वपूर्ण

5. चाँद, आर. (2019). 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए कृषि में बदलाव, भारतीय आर्थिक संघ (आईईए) 102वां वार्षिक सम्मेलन (https://tinyurl.com/4dpu7f9e)

बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है जो मुख्य चिंताओं में से एक है। एमएसएमई को लाइसेंसिंग, निरीक्षण और अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं से निपटना पड़ता है, जो विशेष रूप से उप-राष्ट्रीय सरकारों द्वारा लगाई जाती हैं, तथा ये आवश्यकताएं उन्हें अपनी क्षमता के अनुरूप बढ़ने और रोजगार सृजन में बाधा उत्पन्न करती हैं। सीमा-आधारित रियायतें और छूट उद्यमों को सीमा से नीचे अपने आकार को सीमित करने के लिए प्रोत्साहित करने का अनपेक्षित प्रभाव पैदा करती हैं। इसलिए, सीमा-आधारित प्रोत्साहनों में समाप्ति (सनसेट) खंड होना चाहिए। इसके अलावा, कई एमएसएमई विभिन्न कारणों से अपने व्यवसाय को शुरू करने, संचालित करने या विस्तार करने के लिए आवश्यक धन सुरक्षित करने हेतु संघर्ष करते हैं, जिसमें संपार्षिवक या क्रेडिट इतिहास की कमी, उच्च ब्याज दरें, जटिल दस्तावेजीकरण आवश्यकताएं और लंबी प्रोसेसिंग अवधि आदि शामिल हैं। लोकसभा की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने 'एमएसएमई को ऋण प्रवाह को मजबूत करने' पर अपनी अप्रैल 2022 की रिपोर्ट में उल्लेख किया कि एमएसएमई क्षेत्र में ऋण अंतर लगभग 20-25 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। सरकार ने एमएसएमई को किफायती ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने में इन पहलों ने काफी आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। उद्योग पर अध्याय (अध्याय 10) में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

5.17 **भारत के हरित परिवर्तन का प्रबंधन:** भारत ने अपने ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को 33-35 प्रतिशत (2005 के स्तर से) कम करने, और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की हिस्सेदारी को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने एवं 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए वन क्षेत्र को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है।[6] हालाँकि,भारत में हरित परिवर्तन के मार्ग को (क) पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोत के बीच आवश्यक और इष्टतम ऊर्जा मिश्रण के साथ ई-मोबिलिटी नीति की स्थिरता सुनिश्चित करना; (ख) ई-मोबिलिटी को व्यापक बनाने के लिए ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करना; (ग) बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सस्ती लागत पर भंडारण प्रौद्योगिकी विकसित करना या प्राप्त करना; (घ)अक्षय ऊर्जा के लिए उपयोग की जा रही भूमि और पूंजी की अवसर लागत पर विचार करना, क्योंकि भारत की भूमि और पूंजी की जरूरतें उनकी उपलब्धता से कहीं अधिक हैं; (ङ) ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा की भूमिका और हिस्सेदारी पर निर्णय लेना; (च) महत्वपूर्ण खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता से उत्पन्न चुनौतियों को पहचानना और उनसे निपटना, जो ई-मोबिलिटी और अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चे माल हैं; (छ) बैंकों बैलेंस शीट संबंध में कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने के प्रभावों की जांच करना; (ज) भारतीय रेलवे के माल ढुलाई राजस्व पर कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के प्रभाव को पहचानना और उसका आकलन करना तथा (झ) आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों को ई-वाहनों से बदलने के प्रभावों का अध्ययन करना,विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर तथा ऐसी बिक्री से केंद्र और राज्य सरकारों के लिए राजस्व पैदा करना आखिरी बात भी महत्वपूर्ण है कि भारत को न केवल जलवायु परिवर्तन से निपटना है और ऊर्जा परिवर्तन करना है, बल्कि विकसित देशों के संरक्षणवाद से भी निपटना है। यूरोप अपने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इंग्लैंड और अमेरिका दोनों ही नियत समय में इसके संस्करण लागू करने के अलग-अलग चरणों में हैं। ये कर पेरिस समझौते की भावना के विपरीत हैं, जिसमें 'साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों' को मान्यता दी गई है।

5.18. इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अभिप्रेत अंशदान (आईएनडीसी) लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु व्यापक जलवायु कार्रवाइयों के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता

6. इन लक्ष्यों को 2015 में पेरिस में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी 21)में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी)के तहत सरकार के आशयित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अभिप्रेत अंशदान (आईएनडीसी) में व्यक्त किया गया है।

7. सिंह, वी एंड सिद्धू,जी. (2021) इन्वेस्टमेंट साईजिंग इंडियाज नेट जीरो टारगेट, कौंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (https://tinyurl.com/yfz6wzdw)

है कि भारत को अपने 2070 के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कुल निवेश समर्थन प्रति वर्ष औसतन 28 बिलियन अमरीकी डॉलर के हिसाब से 1.4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर होगा।[7] इस पैमाने पर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना एक अभूतपूर्व चुनौती है, खासकर यह देखते हुए कि भारत की जलवायु कार्रवाई को बड़े पैमाने पर घरेलू संसाधनों के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है और अंतरराष्ट्रीय वित्त का प्रवाह बहुत सीमित रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, इस बड़े वित्तपोषण अंतर को पाटने के लिए भारत के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत हरित वित्त के लिए आवंटित करना आवश्यक हो जाता है। जलवायु नीति संबंधी पहल (क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव)[8] की 2022 की रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में ग्रीन फाइनेंस का अधिकांश हिस्सा घरेलू स्रोतों से आया है, जो वित्त वर्ष 2019 और 2020 में क्रमशः 87% और 83% था। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्रोत बढ़ रहे हैं (वित्त वर्ष 2019 में 13% से वित्त वर्ष 2020 में 17% तक), वे अभी भी भारत के नेट-जीरो लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं।[9] भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में पारंपरिक स्रोतों से पर्याप्त पूंजी जुटाना बहुआयामी चुनौतियां खड़ी करता है। ईएमडीई से जुड़े कथित सार्वभौमिक जोखिम और ऐसी परियोजनाओं की पूंजी-गहन प्रकृति, योजना पूरी होने की लंबी अवधि और विकसित होते नियामक ढांचे के साथ मिलकर निवेशकों की अपेक्षाओं और परियोजना समय-सीमा के बीच मेल नहीं कर सकते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि विकासशील देशों में वैश्विक पूंजी का प्रवाह पूंजी की उच्च लागतों के कारण बाधित हुआ है। अपने ग्रीन बॉन्ड ढांचे पर अच्छी रेटिंग हासिल करने के बावजूद, भारतीय सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को निजी निवेशकों से शायद ही कोई 'ग्रीनियम'[10] मिला हो। यह 'पूंजी के प्रवाह' से ज्यादा 'पूंजी का अवरोध' है जो ईएमडीई में ऊर्जा परिवर्तन को निधि देने के लिए इंतजार कर रही है। यह सिर्फ मोबाइल नहीं है। इन सभी ने मिलकर हरित परिवर्तन परियोजनाओं के लिए वित्त के प्रवाह को गंभीर रूप से बाधित किया है। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा (अध्याय 6) अध्याय में जलवायु वित्त और भारत के हरित परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

5.19 **चीनी पहेली:** भारत-चीन आर्थिक संबंधों की गतिशीलता अत्यंत जटिल और परस्पर जुड़ी हुई है। उत्पाद श्रेणियों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चीन का वर्चस्व खासकर यूक्रेन में युद्ध के साथ आपूर्ति व्यवधान के मद्देनजर एक प्रमुख वैश्विक चिंता है। भले ही भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला जी20 देश है और अब चीन से आगे की विकास दर दर्ज कर रहा है,फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी चीन की तुलना में बहुत पीछे है। ऊर्जा संक्रमण के संदर्भ में, महत्वपूर्ण और दुर्लभ भू खनिजों के उत्पादन और प्रसंस्करण पर चीन का लगभग एकाधिकार पहले से ही वैश्विक चिंता का कारण रहा है। इसका भारत के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जो आयातित कच्चे माल पर बड़े पैमाने पर निर्भरता के कारण आरक्षित है।[11] इस पृष्ठभूमि के विपरीत, यह सोचना शायद अधिक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण नहीं होगा कि भारत विनिर्माण क्षेत्र के कुछ स्थानों को खाली करके चीन से होने वाली इस कमी को पूरा कर सकता है। वास्तव में, हाल के आंकड़ों से संदेह पैदा होता है कि क्या चीन हल्के विनिर्माण क्षेत्र को भी खाली कर रहा है। भारत के सामने ये प्रश्न हैं: (क)क्या चीन की आपूर्ति श्रृंखला में खुद को शामिल किए बिना भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल करना संभव है? और (ख) चीन से माल आयात करने और पूंजी आयात करने के बीच सही

8. भारत में हरित वित्त का परिदृश्य, जलवायु नीति पहल, 2022 (https://tinyurl.com/3p74wnb7)

9. जलवायु वित्त पर विशेषज्ञ समिति द्वारा संक्रमण वित्त पर रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, 2024 (https://tinyurl.com/465yxd63)

10. 'ग्रीनियम' या ग्रीन प्रीमियम, इस तर्क के आधार पर मूल्य निर्धारण लाभों को संदर्भित करता है कि निवेशक स्थायी प्रभाव के बदले में अतिरिक्त भुगतान करने या कम प्रतिफल स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। स्रोत - यूएनडीपी, 2022 (https://tinyurl.com/YKS7Cyr7)

11. नवीकरणीय ऊर्जा भारत-चीन संबंधों को कैसे आकार दे रही है, इंस्टिट्यूट ऑफ पीस एंड कंफ्लिक्ट स्टडीज, 2023 (https://tinyurl.com/3u6rav84)

संतुलन क्या है? जैसे–जैसे देश रीशोर और फ्रेंडशोर की कोशिश कर रहे हैं, चीन के संबंध में भारत के नीतिगत विकल्प अपेक्षा अनुरूप रहे हैं।

बॉक्स V-I: चीनी विनिर्माण प्रभावशाली शक्तिः ईएमई के लिए खतरा[12]

यह लगातार देखा जा रहा है कि उभरती अर्थव्यवस्थाएं चीनी वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगा रही हैं, साथ ही अपने घरेलू निर्माताओं की रक्षा के लिए अन्यत्र मुक्त व्यापार को बढ़ावा दे रही हैं।

चीनी उत्पादों के खिलाफ निर्देशित ये संरक्षणवादी उपाय इस खतरे के कारण उभर रहे हैं कि चीन के विनिर्माण क्षेत्र में अत्यधिक क्षमता अन्य देशों, विशेष रूप से ईएमडीई के लिए खतरा पैदा कर रही है। कमजोर घरेलू मांग और औद्योगिक क्षमता के विस्तार के कारण 2019 से चीन का विनिर्माण व्यापार अधिशेष बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में चीन में घरेलू आपूर्ति और मांग के बीच बेमेल में वृद्धि हुई है, जिसके कारण चीनी कंपनियां विदेशों में अतिरिक्त बाजार तलाश रही हैं। इससे वैश्विक स्तर पर कीमतों में गिरावट आ रही है और अन्य राष्ट्रीय उत्पादकों को कारोबार से बाहर होना पड़ रहा है, खासकर उन उत्पाद श्रेणियों में जहां चीन का दबदबा है। उदाहरण के लिए, 2021 से चीन के प्रॉपर्टी सेक्टर के खराब प्रदर्शन ने काफी अधिक्षमता पैदा की, जिससे वैश्विक स्टील कीमतों में गिरावट आई, जिससे अब भारत, वियतनाम, ब्राजील और अन्य देशों के उत्पादकों पर काफी दबाव पड़ रहा है। अनुमान बताते हैं कि चीन के स्टील उत्पाद निर्यात में पिछले साल 35% की वृद्धि के बाद 2024 में अब तक 27% की वृद्धि हुई है।

बड़ी संख्या में उत्पाद श्रेणियों पर चीन का प्रभुत्व आर्थिक दबाव का जोखिम पैदा करता है, जहाँ सरकार राजनीतिक लाभ के लिए महत्वपूर्ण इनपुट तक पहुँच को रोकती है। यह दुर्लभ भू और महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात के मामले में अत्यधिक अधिक स्पष्ट है,जो देशों के हरित संक्रमण प्रयासों में उच्च प्राथमिकता वाले हैं। चीन के प्रभुत्व ने एकाधिकार प्रथाओं को भी जन्म दिया है, जिसने नए प्रवेशकों के लिए नई विनिर्माण शक्तियों के रूप में उभरने की जगह को काफी सीमित कर दिया है। रोडियम ग्रुप द्वारा हाल ही में किए गए शोध में पाया गया है कि"चीनी सरकार कंपनियों को एक साथ साझेदारी करने, विलय करने और समेकित करने, बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए समन्वय करने, कीमतें बढ़ाने, उन उत्पादों तक पहुँच को प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है जहाँ उनके पास पहले से ही पर्याप्त बाजार शक्ति है, या अपने आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहक नेटवर्क में घरेलू फर्मों को तरजीह दे सकती है।"

यह भी ध्यान देने योग्य है कि चीन को अभी भी समृद्ध औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं से उच्च तकनीक वाले उत्पादों का आयात करने की आवश्यकता है,किन्तु वह बहुत निम्न तकनीक वाले सामान का आयात करता है,जहाँ विकासशील देशों को तुलनात्मक रूप से लाभ होगा। यह काफी हद तक जानबूझकर किए गए नीतिगत बदलावों का परिणाम है, जो हाल के वर्षों में और तेज हो गए हैं।

उपरोक्त सभी कारकों ने मिलकर ईएमडीई के विनिर्माण क्षेत्र को बाधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जबकि ईएमडीई चीनी चुनौती से निपटने के लिए नीतिगत विकल्प के रूप में आयात प्रतिबंधों का सहारा ले रहे हैं,यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कुछ चीनी सामान इतने सस्ते हैं कि कोई भी टैरिफ उनकी मूल्य प्रतिस्पधर्त्मकता को कम नहीं कर सकता है। इसके अलावा, कुछ चीनी उत्पाद इन प्रतिबंधों को बिना किसी की नजर में आए ही पार कर जाते हैं क्योंकि वे तीसरे देशों में पैक किए जाते हैं।

12. इस बॉक्स की सामग्री 23 मई, 2024 के द इकोनॉमिस्ट अंक में प्रकाशित लेख "ब्राजील, भारत और मैक्सिको चीन के निर्यात को चुनौती दे रहे हैं" (https://tinyurl.com/5hah7axh) और रोडियम ग्रुप के शोध "कैसे चीन की अत्यधिक क्षमता बैंक उभरती अर्थव्यवस्थाओं को रोक रही है" पर आधारित है, जिसे https://tinyurl.com/4kkdhctz पर देखा जा सकता है।

इस बीच, चीन ने इन आयात प्रतिबंधों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है जिसने ईएमडीई के लिए विनिर्माण परिदृश्य को और जटिल बना दिया है। उदाहरण के लिए, चीनी संस्थाओं के खिलाफ भारत की डंपिंग रोधी जांच के जवाब में, चीन चुपचाप भारत की सौर उपकरणों तक पहुंच को रोक रहा है। इसे देखते हुए, चीनी विनिर्माण की प्रभावशाली शक्ति से निपटना ईएमडीई की नीतिगत क्षमता का परीक्षण करेगा।

विकासशील देशों को चीन से आयात प्रतिस्पर्धा का सामना करने का तरीका ढूंढना होगा, तथा साथ ही, कभी-कभी चीनी निवेश और प्रौद्योगिकी के सहयोग से घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना होगा।

जैसा कि रोडियम समूह के शोध से पता चलता है, ब्राजील और तुर्की ने हाल ही में चीन से ई-वाहनों के आयात पर शुल्क बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही, इस क्षेत्र में चीनी एफडीआई को आकर्षित करने के लिए कदम भी उठाए हैं।

चीन के साथ अपने बड़े द्विपक्षीय व्यापार घाटे को देखते हुए भारत को भी ऐसा ही निर्णय लेना है। यह भारत को संभावित अचानक आपूर्ति व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाता है। चीन से कुछ अच्छी तरह से चुने गए आयातों को निवेश से बदलने से भविष्य में घरेलू ज्ञान के निर्माण की संभावना बढ़ जाती है। इसमें अन्य जोखिम हो सकते हैं, लेकिन कई अन्य मामलों की तरह, हम पहले-सर्वश्रेष्ठ दुनिया में नहीं रहते हैं। हमें दूसरे और तीसरे-सर्वश्रेष्ठ विकल्पों में से चुनना होगा।

संक्षेप में, भारतीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जोड़ने के लिए, यह अपरिहार्य है कि भारत खुद को चीन की आपूर्ति श्रृंखला में जोड़े। हम ऐसा केवल आयात पर निर्भर होकर करें या आंशिक रूप से चीनी निवेश के माध्यम से करें,यह एक ऐसा विकल्प है जिसे भारत को चुनना है।

5.20. **कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत बनाना:** आगे बढ़ते हुए, भारत के आर्थिक विकास को गति देने के लिए आवश्यक निवेश बैंक वित्तपोषण से परे वित्तपोषण के कई विकल्पों के माध्यम से होना चाहिए। भारत को घरेलू बचत के निरंतर उच्च स्तर से आवश्यक वित्त प्रदान करने के लिए बैंकों और पूंजी बाजारों दोनों की आवश्यकता है। इस संदर्भ में एक सक्रिय कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार महत्वपूर्ण हो जाता है। कम लागत और तेजी से जारी करने के समय के साथ एक कुशल कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कॉर्पोरेट्स के लिए दीर्घकालिक निधियों का एक कुशल और लागत प्रभावी स्रोत प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि, भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार का आकार, जीडीपी के हिसाब से, मलेशिया,कोरिया और चीन जैसे अन्य प्रमुख एशियाई उभरते बाजारों की तुलना में छोटा है।[13] भारतीय कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में मजबूती का अभाव है क्योंकि इसमें उच्च रेटिंग वाले जारीकर्ताओं और घरेलू संस्थाओं के सीमित निवेशक आधार का वर्चस्व है।

5.21. **असमानता से निपटना:** वैश्विक स्तर पर, बढ़ती असमानता नीति निर्माताओं के सामने एक महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौती के रूप में उभर रही है। 2022 स्टेट ऑफ इनइक्वैलिटी इन इंडिया रिपोर्ट[14] में पाया गया कि भारत में शीर्ष 1प्रतिशत का हिस्सा कुल अर्जित आय का 6-7 प्रतिशत है, जबकि शीर्ष 10 प्रतिशत का हिस्सा कुल अर्जित आय का एक-तिहाई है। सरकार इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करती है और रोजगार सृजन, अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र के साथ एकीकृत करने और महिला श्रम शक्ति का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए किए जा रहे सभी महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेपों का उद्देश्य असमानता का प्रभावी ढंग से समाधान करना है। पूंजी और श्रम आय के संबंध में कर नीतियां आने वाले वर्षों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, खासकर इसलिए क्योंकि एआई जैसी प्रौद्योगिकी के प्रयोग से रोजगार और आय पर अधिक हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

13. https://www.bis.org/review/r220824c.pdf
14. भारत में असमानता की स्थिति,इंस्टिट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस,2023 (https://tinyurl.com/8ruecubn)

5.22. **भारत की युवा आबादी के स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार:** भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अप्रैल 2024[15] में प्रकाशित भारतीयों के लिए अपने नवीनतम आहार दिशानिर्देशों में अनुमान लगाया है कि भारत में कुल रोग भार का 56.4 प्रतिशत अस्वास्थ्यकर आहार के कारण है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शर्करा और वसा से भरे अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत में उछाल,शारीरिक क्रियाकलाप में कमी और विविध खाद्य पदार्थों तक सीमित पहुंच के साथ,सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और अधिक वजन/मोटापे की समस्या को बढ़ाता है। अनुमान बताते हैं कि भारत में वयस्क मोटापे की दर तीन गुना से अधिक हो गई है, और विश्व मोटापा संघ[16] के अनुसार,बच्चों में वार्षिक मोटापा वृद्धि दुनिया में सबसे तेज है,इस मामले में भारत वियतनाम और नामीबिया से पीछे है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण,2019-2021 भारत की आबादी की स्वास्थ्य स्थिति का बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत करता है, (बाक्स V.2) । यदि भारत को अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना है,तो यह महत्वपूर्ण है कि इसकी आबादी के स्वास्थ्य मापदंडों को संतुलित और विविध आहार की ओर परिवर्तित किया जाए।

बॉक्स V.2: भारत की बढ़ती मोटापे की चुनौती: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य से अवलोकन सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5), 2019-2021

भारत की वयस्क आबादी में मोटापा एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (एनएफएचएस-5) के अनुसार, 18-69 आयु वर्ग में मोटापे से जूझ रहे पुरुषों का प्रतिशत एनएफएचएस 4 में 18.9 प्रतिशत से बढ़कर एनएफएचएस 5 में 22.9 प्रतिशत हो गया है। महिलाओं के लिए, यह 20.6 प्रतिशत (एनएफएचएस-4) से बढ़कर 24.0 प्रतिशत (एनएफएचएस-5) हो गया है। एनएफएचएस-5 बनाम एनएफएचएस-4 के अनुसार भारत की मोटापे की चुनौती का स्थानिक वितरण निम्नलिखित को प्रकट करता है:

- तमिलनाडु में, पुरुषों के लिए यह 37.0 प्रतिशत है (बनाम एनएफएचएस-4 में 28.2 प्रतिशत) और महिलाओं के लिए यह 40.4 प्रतिशत है (बनाम एनएफएचएस-4 में 30.9 प्रतिशत)।
- उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए यह दर 16.5 प्रतिशत (एनएफएचएस-4) से बढ़कर 21.3 प्रतिशत (एनएफएचएस -5) हो गई है, तथा पुरुषों के लिए यह दर 12.5 प्रतिशत (एनएफएचएस-4) से बढ़कर 18.5 प्रतिशत (एनएफएचएस-5) हो गई है।
- केरल में महिलाओं के लिए यह दर 32.4 प्रतिशत (एनएफएचएस-4) से बढ़कर 38.1प्रतिशत (एनएफएचएस-5) हो गई है, तथा पुरुषों के लिए यह दर 28.5 प्रतिशत (एनएफएचएस-4) से बढ़कर 36.4 प्रतिशत (एनएफएचएस-5) हो गई है।
- पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए यह दर 19.9 प्रतिशत (एनएफएचएस-4) से बढ़कर 22.7 प्रतिशत (एनएफएचएस-5) हो गई है, तथा पुरुषों के लिए यह दर 14.2 प्रतिशत (एनएफएचएस-4) से बढ़कर 16.2 प्रतिशत (एनएफएचएस-5) हो गई है।
- कर्नाटक में एनएफएचएस-4 की तुलना में महिलाओं के लिए वृद्धि 7 प्रतिशत अंक (30.1% बनाम 23.3 प्रतिशत) और पुरुषों के लिए लगभग 9 प्रतिशत अंक (30.9 प्रतिशत बनाम 22.1प्रतिशत) है।
- आंध्र प्रदेश में महिलाओं के लिए यह दर 36.3 प्रतिशत है (बनाम 33.2 प्रतिशत)। हालांकि, पुरुषों के लिए यह संख्या घटकर 31.1 प्रतिशत रह गई है (बनाम 33.5 प्रतिशत)।
- तेलंगाना में अधिक वजन वाली महिलाओं और पुरुषों का अनुपात क्रमश: 30.1 प्रतिशत और 32.3 प्रतिशत है, जो एनएफएचएस-4 में महिलाओं के लिए 28.6 प्रतिशत से और पुरुषों के लिए 24.2 प्रतिशत से बढ़कर हो गया है।

15. भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशा-निर्देश, आईसीएमआर - राष्ट्रीय पोषण संस्थान, 2024 (https://tinyurl.com/ts6xejc4)
16. 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जंक फूड भारत के लिए अगला स्वास्थ्य संकट पैदा कर रहा है, ब्लूमबर्ग, 2023 (https://tinyurl.com/52wtd7r9)

- महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए यह दर एनएफएचएस-4 और एनएफएचएस-5 में 23.4 प्रतिशत पर स्थिर रही है, जबकि पुरुषों के लिए यह 23.8 प्रतिशत (एनएफएचएस-4) से बढ़कर 24.7 प्रतिशत (एनएफएचएस-5) हो गई है।
- मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए यह दर 13.6 प्रतिशत (एनएफएचएस-4) से बढ़कर 16.6 प्रतिशत (एनएफएचएस-5) हो गई है, तथा पुरुषों के लिए यह दर 10.9 प्रतिशत (एनएफएचएस-4) से बढ़कर 15.6 प्रतिशत (एनएफएचएस-5) हो गई है।
- झारखंड में महिलाओं के लिए यह दर 10.3 प्रतिशत (एनएफएचएस-4) से बढ़कर 11.9 प्रतिशत (एनएफएचएस-5) हो गई है, तथा पुरुषों के लिए यह दर 11.1 प्रतिशत (एनएफएचएस-4) से बढ़कर 15.1 प्रतिशत (एनएफएचएस-5) हो गई है।
- बिहार में महिलाओं के लिए यह दर 11.7 प्रतिशत (एनएफएचएस-4) से बढ़कर 15.9 प्रतिशत (एनएफएचएस-5) हो गई है, तथा पुरुषों के लिए यह दर 12.6 प्रतिशत (एनएफएचएस-4) से बढ़कर 14.7 प्रतिशत (एनएफएचएस-5) हो गई है।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली) में मोटापे से ग्रस्त महिलाओं का अनुपात 41.3 प्रतिशत (बनाम 33.5 प्रतिशत) है, और पुरुषों के लिए यह 38.0 प्रतिशत (बनाम 24.6 प्रतिशत) है।

अखिल भारतीय स्तर पर, आंकड़ों के त्वरित अवलोकन से पता चलता है कि एनएफएचएस5 के अनुसार, मोटापे की घटना ग्रामीण भारत की तुलना में शहरी भारत में काफी अधिक है (पुरुषों के लिए 29.8 प्रतिशत बनाम 19.3 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 33.2 प्रतिशत बनाम 19.7 प्रतिशत)। कुछ राज्यों में बढ़ती उम्र के साथ-साथ मोटापा भी चिंताजनक स्थिति प्रस्तुत करता है। नागरिकों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने में सक्षम बनाने के लिए निवारक उपाय किए जाने चाहिए। यहां, यह ध्यान रखना उचित है कि एनएफएचएस-5 सर्वेक्षण कोविड-19 महामारी के साथ ओवरलैप हुआ था। इसलिए, बाहरी गतिविधियों पर प्रतिबंध और लॉकडाउन के कारण, सुस्त जीवनशैली अधिक प्रचलित हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप एनएफएचएस-5 में मोटापे का अनुपात बहुत अधिक बढ़ गया है। यदि एनएफएचएस-6 में यह प्रवृत्ति उलट जाती है तो यह एक अच्छा संकेत होगा।

अमृत काल के लिए विकास रणनीति : मजबूत, टिकाऊ और समावेशी

5.23. पिछले एक दशक में भारत सरकार द्वारा अपनाए गए नीतिगत सुधारों ने आने वाले वर्षों में निरंतर मध्यम से उच्च विकास की नींव रखी है। वर्ष 2047 या उससे अधिक तक की एक पीढ़ी के लिए विकास को बनाए रखने के लिए, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इससे लोगों का जीवन बेहतर हो तथा उनकी आकांक्षाएं पूरी हों, नीचे से ऊपर की ओर सुधार आवश्यक हैं। यह खंड एक छह-आयामी विकास रणनीति प्रस्तुत करता है जो आगे बढ़ने वाली नीचे से ऊपर की ओर सुधार प्रक्रिया का मार्गदर्शन कर सकती है।

5.24. **निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने की रणनीतिः** मशीनरी और उपकरण तथा बौद्धिक संपदा उत्पादों में भारत के निजी सकल स्थिर पूंजी निर्माण में तेजी लानी चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित किए जा सकें। सरकार का ध्यान घटक निर्माताओं की क्षमता और जानकारी के उन्नयन, प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने, संसाधन बाधाओं और नियामक बाधाओं को दूर करने आदि के लिए एक सक्षम नीति और नियामक वातावरण बनाने पर होना चाहिए। बैलेंस शीट के मुद्दों के कारण दूसरे दशक में समेकन के बाद निजी क्षेत्र में पूंजी निर्माण, कोविड के बाद ठीक होने लगा है। फिर भी, भारत के निजी निवेश को बढ़ावा देने की काफी गुंजाइश है, खासकर बुनियादी ढांचे, हरित संक्रमण आदि के क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली निवेश आवश्यकताओं के संदर्भ में । भारत सरकार ने इस

दिशा में महत्वपूर्ण पहल की हैं, जिसमें आत्मनिर्भर पैकेज, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) की शुरुआत, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत निवेश के अवसर, भारत औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस), राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस)[17] की शुरुआत आदि शामिल हैं। निजी क्षेत्र के गैर-आवासीय निवेश (उपकरण, संरचना, सॉफ्टवेयर और अनुसंधान एवं विकास सहित) को एक स्थायी आधार पर लाने के लक्ष्य के साथ इन उपायों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है ताकि यह निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 35% तक बढ़ाने की दिशा में प्रयासों को उत्प्रेरित कर सके।

5.25. **भारत के मिटेलस्टैंड के विकास और विस्तार के लिए रणनीति[18]:** भारत के एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करना आने वाले वर्षों में भारत के विकास के लिए केंद्रीय है। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो देश के जीडीपी में लगभग 30%, विनिर्माण उत्पादन का 45% योगदान करते हैं, और भारत की 11 करोड़ आबादी[19] को रोजगार प्रदान करते हैं। भारत सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने में सक्रिय रही है, जिसमें एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए ₹ 5 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का आवंटन; एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत फंड के माध्यम से ₹ 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन; एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नए संशोधित मानदंड; 5 वर्षों में ₹ 6,000 करोड़ के परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रदर्शन बढ़ाने और त्वरित करने (आरएएमपी) कार्यक्रम की शुरुआत; अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल)[20] के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औपचारिक दायरे में लाने के लिए 11.01.2023 को उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म (यूएपी) का शुभारंभ शामिल है। इन पहलों को इस क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, मुख्य रूप से समय पर और किफायती ऋण तक पहुँच के लिए। हालाँकि यह महत्वपूर्ण है, लेकिन वित्तपोषण इस क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से केवल एक है।

5.26. आगे बढ़ते हुए, मिटेलस्टैंड के विस्तार के लिए, **अविनियमन एक महत्वपूर्ण नीतिगत योगदान है।** इसीलिए आवश्यक नीतिगत परिवर्तनों पर राज्यों के साथ बातचीत के लिए संस्थागत तंत्रों का पुनरुद्धार या निर्माण आवश्यक है। अधिकांश कार्रवाई उप-राष्ट्रीय (राज्य और स्थानीय) सरकारों के स्तर पर होनी है। **भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी (औद्योगिक और माल ढुलाई गलियारे), बुनियादी ढांचे का उन्नयन और विकास, बुलेट ट्रेनों की शुरूआत,** और सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण आपूर्ति-श्रृंखला नेटवर्क और सहायक उद्योगों के विकास के माध्यम से क्षेत्र के विकास में योगदान देगा, जो सेमीकंडक्टर फैब के निर्माण और बुलेट ट्रेन की शुरूआत जैसी परियोजनाओं के प्रेरणादायक प्रभावों के अलावा उत्प्रेरित करेगा जब वे प्रचालन में होंगे। एमएसएमई उद्यमियों को उद्यम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। इन हस्तक्षेपों को लक्षित किया जाना चाहिए, प्रत्येक क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, और अकादमिक के बजाय व्यावहारिक होना चाहिए। इस तरह के प्रशिक्षण से मालिक-उद्यमियों की उत्पादकता बहुत अधिक होगी ।

5.27. निर्यात रणनीति भी सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण हिस्सेदारी बढ़ाने और देश के मिटेलस्टैंड को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण घटक है। उदाहरण के लिए, भारत और जर्मनी के बीच सहयोग 'मेक इन इंडिया मिटेलस्टैंड (MIIM)', छोटे और मध्यम आकार की जर्मन कंपनियों को भारत में निवेश और विनिर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करके नवाचार

17. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की 9 अगस्त, 2023 की पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति (https://tinyurl.com/yaxwv8xy)
18. मिटेलस्टैंड आमतौर पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विटजरलैंड में सुदृढ़ व्यावसायिक उद्यमों के समूह को संदर्भित करता है जो आर्थिक परिवर्तन और अशांति को सहन करने में सफल साबित हुए हैं। इसे आमतौर पर छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों की सांख्यिकीय श्रेणी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनका वार्षिक राजस्व 50 मिलियन यूरो तक होता है और अधिकतम 500 कर्मचारी होते हैं। https://tinyurl.com/mrxkz5sm
19. इन्वेस्ट इंडिया, 2023 (https://tinyurl.com/56393ekz)
20. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की दिनांक 7 अगस्त, 2023 की पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति (https://tinyurl.com/4m465t7c)

को बढ़ावा देने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। सितंबर 2015 में अपनी स्थापना के बाद से, एमआईआईएम कार्यक्रम ने 151 से अधिक जर्मन मिटेलस्टैंड कंपनियों का समर्थन किया है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में कुल घोषित निवेश अगस्त 2021 तक 1.4 बिलियन यूरो से अधिक है।[21] इनमें से अधिकांश निवेश ऑटोमोटिव, नवीकरणीय ऊर्जा, निर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स, रसायन और अपशिष्ट/जल प्रबंधन क्षेत्रों में आए। चीन के साथ व्यापार, चीन द्वारा निवेश और भारत की क्षेत्रीय और गैर-क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के बीच सही संतुलन बनाना भारत के मिटेलस्टैंड को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है।

5.28. **कृषि क्षेत्र में विकास की बाधाओं को दूर करने की रणनीति:** भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्व और इस क्षेत्र के सामने आने वाली बाधाओं पर साहित्य में विस्तार से चर्चा की गई है। कृषि 21वीं सदी की तीन सबसे बड़ी चुनौतियों के केंद्र में है - खाद्य और पोषण सुरक्षा को बनाए रखना, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन और शमन, तथा जल, ऊर्जा और भूमि जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों का सतत उपयोग। कृषि और बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन और डेयरी जैसे संबद्ध क्षेत्र तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसी गतिविधियाँ लाभकारी रोजगार की महत्वपूर्ण संभावनाएँ रखती हैं। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के सामने आने वाले भू-राजनीतिक और तकनीकी खतरों को देखते हुए, कृषि में छिपी हुई रोजगार क्षमता को साकार करने के लिए जो कुछ भी करना है, वह करना बहुत समझदारी पूर्ण है। भारत के लिए अगली पीढ़ी के लिए अपने प्राथमिक क्षेत्र की रूपरेखा को फिर से परिभाषित करना अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण दोनों है। आर्थिक विकास के परिपक्व होने के साथ ही भारत को कृषि से उद्योग और सेवाओं की ओर बढ़ने की पुरानी विकास पुस्तिका को त्यागना पड़ सकता है। अतीत में अन्य देशों के साथ जो हुआ है, उसके विपरीत, बदलती भू-राजनीतिक और विकसित होती जलवायु परिस्थितियों में, भारत की भौतिक, खाद्य और आर्थिक सुरक्षा में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

बॉक्स V-3: किसान-हितैषी नीतिगत ढांचा

भारतीय कृषि क्षेत्र एक सफलता की कहानी है। साठ के दशक में खाद्यान्न की कमी और आयात करने वाले देश से लेकर कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक बनने तक का देश एक लंबा सफर तय कर चुका है। साथ ही, यह पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि भारत में कृषि में मूल्य संवर्धन को बढ़ाने और कृषि-मूल्य श्रृंखलाओं में रोजगार को भारतीय युवाओं के लिए लाभदायक और आकर्षक बनाने की अच्छी गुंजाइश है। पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और पश्चिम के विकसित देशों के विपरीत, भारत को अभी भी आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान देने के लिए कृषि की क्षमता का पूरी तरह से दोहन करना बाकी है।

भारतीय कृषि अभी संकट में नहीं है, लेकिन इसमें गंभीर संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन और जल संकट बहुत बड़ा मुद्दा है। कोविड के वर्षों में रिवर्स माइग्रेशन के कारण कृषि रोजगार में वृद्धि, वित्त वर्ष 24 में कृषि में मूल्य संवर्धन की वृद्धि दर में गिरावट और 2024 की गर्मियों में देश के उत्तर-पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी के साथ जल तनाव और ऊर्जा की खपत में वृद्धि भारत की कृषि क्षेत्र की नीतियों का गंभीरता से और ईमानदारी से जायजा लेना अनिवार्य बनाती है। अगर हम इस समस्या को समझ लें, तो राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ-साथ ग्रामीण भारत में आर्थिक समृद्धि में कृषि क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उच्च और अच्छी तरह से साझा समृद्धि औद्योगिक वस्तुओं की बहुत जरूरी मांग को बढ़ाने में मदद कर सकती है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में तेजी आ सकती है। इस प्रकार, कृषि का सकल घरेलू उत्पाद पर इसके प्रत्यक्ष योगदान से कहीं अधिक गुणक प्रभाव पड़ता है।

21. इन्वेस्ट इंडिया, 2024 (https://tinyurl.com/23nsxy4b)

बढ़ती अर्थव्यवस्था में, समय के साथ कृषि का हिस्सा घटता जाता है। यह सामान्य है। इसे प्रगति माना जाता है। जैसे-जैसे परिवार की आय बढ़ती है, वे आनुपातिक रूप से अधिक भोजन का उपभोग नहीं करते हैं। उनके उपभोग व्यय में भोजन का हिस्सा कम हो जाता है, जिसे एंगेल के नियम के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि भोजन उनके कल्याण के लिए कम महत्वपूर्ण है। भोजन के भीतर, पशुधन उत्पादों (दूध और मांस), मछली, फल और सब्जियों जैसे पौष्टिक भोजन (प्रोटीन और विटामिन) पर खर्च बढ़ जाता है, जो बेनेट के नियम के रूप में जाना जाता है।

कृषि और किसान किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। अधिकांश देश इसे समझते हैं। भारत कोई अपवाद नहीं है। भारत उन्हें पानी, बिजली और उर्वरक पर सब्सिडी देता है। पहले दो को लगभग मुफ्त प्रदान किया जाता है। उनकी आय पर कर नहीं लगाया जाता है। सरकार उन्हें 23 चयनित वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान करती है। पीएम-किसान (च्ड-ज्ञ्प्ैछ) योजना के माध्यम से किसानों को मासिक नकद सहायता दी जाती है। अतीत में और कुछ मामलों में, अब भी, भारतीय सरकारों – राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय – ने उनके ऋण माफ कर दिए हैं। इसलिए, भारत में सरकारें किसानों की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए पर्याप्त संसाधन खर्च करती हैं। फिर भी, यह तर्क दिया जा सकता है कि मौजूदा और नई नीतियों के कुछ पुनर्निर्देशन के साथ उन्हें बेहतर सेवा दी जा सकती है।

कृषि उत्पाद निस्संदेह बाजार की शक्तियों के परस्पर क्रिया के अधीन हैं। यदि कुछ भी हो, तो खाद्य उपभोग की सापेक्षिक अस्थिरता उनके पक्ष में काम करती है। यह एक समस्या पैदा करता है। जब मौसम या अन्य कारक फसल पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, तो कीमतें बढ़ जाती हैं। किसान अगले वर्ष के लिए खेती के तहत क्षेत्र बढ़ाकर प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे आपूर्ति में अधिकता हो जाती है, जिससे कीमतें गिर जाती हैं। दोनों ही अवसरों पर, किसान कोई भी लाभ प्राप्त करने में विफल रहते हैं – पहले मामले में अपर्याप्त उत्पादन और दूसरे मामले में कम कीमतों के कारण।

किसानों के लिए एक और जोखिम तब होता है जब फसल के समय सूखे या भीगने के कारण उत्पादन में गिरावट आती है। कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन किसान उपज से लाभ नहीं उठा पाता क्योंकि यह अपर्याप्त है। इसलिए, खेती को बीमा की आवश्यकता है। चुनौती यह है कि किसानों के लिए बीमा और मूल्य समर्थन के सर्वोत्तम रूपों का पता लगाया जाए जो प्रोत्साहनों को विकृत न करें और अर्थव्यवस्था के लिए अन्य लागतें न बनाएँ, जैसे कि अत्यधिक जल खपत, भूजल की कमी, मिट्टी की गुणवत्ता का क्षरण और, समान रूप से, कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक खपत के अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन के माध्यम से स्वास्थ्य लागत।

सिद्धांत रूप में, यह बीमा मूल्य समर्थन या आय समर्थन के रूप में आ सकता है। मूल्य समर्थन हस्तक्षेपों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसे प्रत्यक्ष मूल्य स्तर या भावांतर भुगतान योजना जैसे मूल्य-अंतर समर्थन शामिल हैं, जिसका प्रयोग मध्य प्रदेश ने एक सीजन में किया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। पीएम किसान जैसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के रूप में आय समर्थन कई विकसित देशों में कृषि सब्सिडी का पसंदीदा रूप है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) जैसी फसल बीमा आय समर्थन का एक और रूप है, हालांकि वैश्विक स्तर पर इसका रिकॉर्ड मिला-जुला है।

मौसम की अनिश्चितताओं और कीमतों पर तुरंत प्रतिक्रिया करने की अंतर्निहित कठिनाइयों को देखते हुए, किसानों को बाजार की कीमतों के विफल होने पर समर्थन देने के लिए एक आर्थिक और नैतिक मामला है। साथ ही, किसानों को बाजार की कीमतों से लाभ उठाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जब बाजार की कीमतें उनके पक्ष में काम करती हैं।

यह अक्सर सरकारों को दुविधा में डाल देता है क्योंकि अपेक्षाकृत कम आय वाले देशों में, कम आय वाले उपभोक्ताओं के हित मायने रखते हैं। इसलिए, किसानों का समर्थन करने के अलावा, सरकारों को खुले बाजार में बिक्री, व्यापार नियंत्रण और जमाखोरी और सट्टेबाजी के खिलाफ उपायों जैसी नीतियों के माध्यम से कीमतों को स्थिर करने के

लिए बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भारत में, ये उपाय विशाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के शीर्ष पर आते हैं जो आबादी के विशाल बहुमत, विशेष रूप से गरीब और कमजोर लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को रेखांकित करता है। हालांकि, उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर किए गए ऐसे मूल्य स्थिरीकरण उपाय अक्सर किसानों के लिए आय-समर्थन नीतियों के साथ टकराव करते हैं। सरकारों के पास एक नाजुक संतुलन बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। यहां नीतियों का संयोजन महत्वपूर्ण हो जाता है। यह नीतियों के एक ऐसे समूह के बारे में है जो किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों के लिए कार्य करता है। यहां एक मजबूत मामला है कि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए, आय टॉप-अप, यानी प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण, अधिक प्रभावी हैं। प्रत्यक्ष हस्तांतरण में बाजारों को काम करने दिया जाता है।

हम किसानों के हितों में बाजारों को कैसे काम करने देते हैं? सरकारें क्या कर सकती हैं?

(1) **कीमतों में उछाल के पहले संकेत पर वायदा या विकल्प बाजारों पर प्रतिबंध न लगाकर।** ये बाजार हर समय उपभोक्ताओं या किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे प्रतिबंधों के लिए मानक इतने ऊंचे होने चाहिए कि उनका सहारा लगभग न के बराबर हो। ऐसे बाजारों का अभिज्ञ विनियामक डिजाइन कृषि वस्तुओं के वायदा बाजार में नौकरशाही के हस्तक्षेप की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।

(2) **केवल असाधारण परिस्थितियों में निर्यात प्रतिबंध लागू करके** और घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिस्थापन की अनुमति देकर, खासकर यदि विचाराधीन कृषि वस्तुएं खाद्यान्न जैसी आवश्यक उपभोग वस्तुएं नहीं हैं। यहां तक कि उन मामलों में भी, सरकार घरेलू आपूर्ति संबंधी समस्याओं का जवाब देने से पहले प्रतिस्थापन प्रभावों से लाभ उठाने की अनुमति दे सकती है। उदाहरण के लिए, यदि चीनी की कीमतें बढ़ती हैं, तो उपभोक्ता इसका कम सेवन कर सकते हैं या गुड़ का सेवन कर सकते हैं। यह उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी बात हो सकती है। सामान्य तौर पर, उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्थापन करना या खपत कम करना किसानों के लिए तदर्थ निर्यात प्रतिबंधों या भारी आयात के कारण बड़े नुकसान को सहने की तुलना में कहीं अधिक आसान है।

किसानों को उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतों से लाभ उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए। खाद्यान्न निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की सूचना भी पहले ही दे दी जानी चाहिए, अन्यथा विश्व में अन्यत्र भूखमरी और अकाल की स्थिति और अधिक खराब हो जाएगी।

(3) **मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढांचे की फिर से जांच करके।** विकासशील देशों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य पदार्थों का हिस्सा बहुत अधिक है। यह सामान्य बात है। इसलिए, जब विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक हेडलाइन मुद्रास्फीति को लक्षित करते हैं, तो वे खाद्य कीमतों को प्रभावी ढंग से लक्षित करते हैं। इसलिए, जब खाद्य कीमतें बढ़ती हैं, तो मुद्रास्फीति लक्ष्य खतरे में पड़ जाते हैं। इसलिए, केंद्रीय बैंक सरकार से खाद्य उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को कम करने की अपील करता है। यह किसानों को उनके पक्ष में व्यापार के मामले में वृद्धि से लाभ उठाने से रोकता है। भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे में खाद्य पदार्थों को छोड़कर मुद्रास्फीति को लक्षित करने पर विचार किया जाना चाहिए। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतें, अक्सर मांग से प्रेरित नहीं बल्कि आपूर्ति से प्रेरित होती हैं। अल्पकालिक मौद्रिक नीति उपाय समग्र मांग वृद्धि से उत्पन्न होने वाले मूल्य दबावों का मुकाबला करने के लिए हैं। आपूर्ति बाधाओं के कारण होने वाली मुद्रास्फीति से निपटने के लिए उनका

उपयोग करना प्रतिकूल हो सकता है। इसलिए, यह पता लगाना उचित है कि क्या भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे में खाद्य पदार्थों को छोड़कर मुद्रास्फीति दर को लक्षित किया जाना चाहिए। गरीब और कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए उच्च खाद्य कीमतों के कारण होने वाली कठिनाइयों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या उचित अवधि के लिए वैध निर्दिष्ट खरीद के लिए कूपन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है।

(4) विशेष रूप से, **भारत के संदर्भ में, कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करके।** कई राज्य राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे हैं। सिंचाई में निवेश से मानसून पर निर्भरता का कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा, लेकिन यह किसानों की आय सुरक्षा को बढ़ाएगा। इतना ही नहीं, बिजली उत्पादन संयंत्रों के मामले में जहां प्लांट लोड फैक्टर में सुधार की गुंजाइश है, भारत की सिंचाई क्षमता में भी सुधार हो सकता है। यह सतही जल के लिए केवल 30-40% और भूजल के लिए 50-60% है। इसके लिए बेहतर जल उपयोग खेती पद्धतियों और ड्रिप और फर्टिगेशन जैसी तकनीकों की आवश्यकता है। यह उत्पादकता बढ़ाने और पानी और उर्वरक के उपयोग को लगभग 50 प्रतिशत तक कम करने में मदद करेगा।

(5) इनके अलावा, **खेती को जलवायु संबंधी उद्देश्यों के अनुरूप बनाकर।** भारत बहुत अधिक खाद्यान्न और चीनी पैदा करता है, बहुत कम दालें, तिलहन और अन्य नकदी फसलें। चावल और गन्ना जैसे अनाज पानी की अधिक खपत करने वाली फसलें हैं। भारत में जल क्रांतिकता बढ़ रही है। इसके अलावा, खाद्यान्नों में, धान की खेती से मीथेन उत्सर्जन होता है। इसकी मीथेन उत्सर्जन क्षमता काफी है। कभी-कभी, और कुछ परिस्थितियों में, सीधे बीजारोपण चावल (डीएसआर) या कुछ फसलों के लिए जैविक खेती भी पानी और रासायनिक उर्वरकों को बचाने में मदद कर सकती है। यह पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि भारत ने बुनियादी खाद्यान्नों में सापेक्ष आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है और दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है (2022-23 में विश्व निर्यात का लगभग 40 प्रतिशत)। 20 मीट्रिक टन चावल निर्यात करने का मतलब है कम से कम 40 अरब क्यूबिक मीटर पानी का निर्यात करना। भारतीय खाद्य निगम के पास इस समय चावल का स्टॉक है जो बफर स्टॉक से तीन गुना से अधिक है। चावल का अत्यधिक उत्पादन सिंचाई, पानी और उर्वरकों के लिए बिजली पर बड़ी सब्सिडी के कारण होता है। अब समय आ गया है कि 'फसल-तटस्थ प्रोत्साहन संरचनाओं' को बढ़ावा दिया जाए। इसका मतलब यह होगा कि दालें, तिलहन और बाजरा जो बिजली, पानी और उर्वरकों पर बचत करते हैं, उन्हें चावल उत्पादन में निहित समान सब्सिडी से पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, समय की मांग बुनियादी खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर बढ़ना है। इसके लिए हमें दालों, बाजरा, फलों और सब्जियों, दूध और मांस की अधिक आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी मांग बुनियादी खाद्य पदार्थों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसलिए, कृषि क्षेत्र की नीतियों को 'मांग-संचालित खाद्य प्रणाली' के साथ अधिक संरेखित किया जाना चाहिए जो अधिक पौष्टिक हो और प्रकृति के संसाधनों के साथ संरेखित हो।

संक्षेप में, इन विविध विचारों के बारे में समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, ताकि सामान्य रूप से आर्थिक नीतियां और विशेष रूप से कृषि नीतियां किसानों को लाभान्वित करें और स्वास्थ्य, जल और जलवायु से संबंधित प्राथमिकताओं के अनुकूल हों।

भारत के प्राकृतिक प्रतिस्पर्धी लाभों को देखते हुए, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान करने की अपार संभावनाएं हैं। ऐसी नीतियां जो खेती की आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ाती हैं, खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं, और इसे आर्थिक, जलवायु और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ आधार पर रखती हैं, निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करेंगी और इस क्षेत्र द्वारा उच्च मूल्य संवर्धन का मार्ग प्रशस्त करेंगी, जबकि सार्वजनिक संसाधनों को स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास में लगाया जा सकेगा।

इसलिए, इस क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर व्यापक हितधारक परामर्श के साथ आम सहमति प्राप्त करने का प्रयास प्रयास के निवेश पर आर्थिक और सामाजिक प्रतिफल के मामले में बहु-लाभकारी है।

5.29. भारत में हरित परिवर्तन (ग्रीन ट्रांजिशन) के वित्तपोषण को सुरक्षित करने की रणनीति: भारत के समक्ष जलवायु वित्तपोषण की आवश्यकताओं को देखते हुए, संप्रभु धन निधि, वैश्विक पेंशन, निजी इक्विटी और अवसंरचना निधियों से वैश्विक हरित पूंजी के तेजी से बढ़ते पूल का दोहन करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के तरीकों में व्यवस्था परिवर्तन परियोजनाओं में निवेश की बाधाओं को दूर करना, एक स्थायी वित्त पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और वित्तपोषण स्रोतों में विविधता लाना शामिल है। हरित वित्त में निधि को प्रभावी ढंग से प्रवाहित करने के लिए नवोन्मेषी और अनुकूलित दृष्टिकोणों की भी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, मिश्रित वित्त, जो सार्वजनिक और निजी पूंजी को रणनीतिक रूप से एकीकृत करता है, में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने, निवेश जोखिमों को कम करने और एक टिकाऊ, निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में सफलतापूर्वक परिवर्तन (ट्रांजिशन) करने के लिए आवश्यक संसाधनों की तीव्र और मापनीय परिनियोजन को सक्षम करने की क्षमता होती है। इसके अलावा, जैसे-जैसे भारत अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कम कार्बन ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, क्षेत्र-विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं भी हरित निधि जुटाने में मदद कर सकते हैं। उनका क्षेत्र (विशेष रूप से महत्वपूर्ण (हार्ड टू अबेट) क्षेत्र) के बारे में विशेष जानकारी उन्हें व्यवस्था परिवर्तन परियोजनाओं की अनूठी आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन वित्तीय उत्पाद बनाने में सक्षम बनाता है। हरित पहलों पर निवेश को निर्देशित करके, ये संस्थाएं स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन (ट्रांजीशन) को बढ़ावा दे सकती हैं, जिससे न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करने में योगदान मिलेगा, बल्कि एक अधिक टिकाऊ और लचीले ऊर्जा भविष्य का निर्माण भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) की भूमिका को बढ़ाने की महत्वपूर्ण संभावना है, जो भारत के जलवायु वित्त अंतर (गैप) को भरने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पूंजी को आकर्षित करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है। जलवायु वित्त पर विशेषज्ञ समिति द्वारा व्यवस्था परिवर्तन (ट्रांजीशन) वित्त पर रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की गई है जो आईएफएससीए के लिए जलवायु वित्त पारिस्थितिकी तंत्र और साधन विकसित करने के लिए एक रोडमैप प्रदान कर सकती हैं। भारत बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ भी जुड़ सकता है और आवश्यक वित्त जुटाने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत नए और मौजूदा साधनों के उपयोग की संभावना तलाश सकता है जिसे भारत के हरित परिवर्तन लक्ष्यों के वित्तपोषण में वापस लगाया जा सकता है।

बॉक्स V-4: बाजार वित्त का लाभ उठाना: भारत द्वारा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) का उत्प्रेरक उपयोग

भारत की उच्च मध्यम आय की स्थिति की ओर आर्थिक प्रगति इस बात से प्रतिबिंबित होती है कि देश विश्व बैंक समूह से विकास वित्त के उपयोग में किस प्रकार विकसित हो रहा है। विश्व बैंक के संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) का प्रमुख उपयोगकर्ता बन गया - जो विश्व बैंक से रियायती वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत है। आय में वृद्धि के साथ, भारत ने आईडीए रियायती वित्तपोषण से आगे बढ़कर विश्व बैंक की अधिक वाणिज्यिक आईबीआरडी विंडो के माध्यम से वित्तपोषण प्राप्त करना शुरू कर दिया और इस प्रक्रिया में, आईडीए का एक अंशदाता बन गया। चूंकि भारत एक आईबीआरडी देश के लिए उधार लेने की सीमा के करीब पहुंच रहा है और मानव पूंजी, जलवायु परिवर्तन और बुनियादी ढांचे में नियोजित निवेश को देखते हुए, देश को अब बहुपक्षीय वित्त का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए अपने दृष्टिकोण में बदलाव करने की आवश्यकता है। आज भारत को अपने आर्थिक विकास को गति देने के लिए बड़े पैमाने पर बाजार वित्त तक पहुंच की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, भारत बहुपक्षीय वित्त के ऋणदाता के रूप में अपनी पारंपरिक भूमिका का लाभ उठाने के अलावा बाजार वित्त

का लाभ उठाने के लिए बहुपक्षीय तंत्र का उपयोग करके प्रतिस्पर्धी शर्तों पर वित्तीय बाजारों तक सीधे पहुंचने के लिए विश्व बैंक समूह की बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) का लाभ उठा रहा है।

इस राजकोषीय वर्ष में एमआईजीए के दो गारंटी ऑपरेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं। एमआईजीए ने जापान के एमयूएफज निवेश बैंक को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) को दिए गए 100 मिलियन डॉलर के वाणिज्यिक ऋण के लिए ऋण वृद्धि गारंटी प्रदान की। इससे डीएफसीसीआईएल को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) के लुधियाना-खुर्जा और कानपुर-मुगलसराय खंडों को पूरा करने तथा फ्रेट कॉरिडोर और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स टर्मिनलों के बीच अंतिम मील कनेक्टिविटी स्थापित करने में मदद मिलेगी। वाणिज्यिक वित्त का क्रियान्वयन गुजरात के गिफ्ट सिटी के माध्यम से किया जा रहा है, जहां एमयूएफजी ने एक केंद्र खोला है। इसके अतिरिक्त, एमआईजीए ने सिटी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और क्रेडिट एग्रीकोल को उनके वाणिज्यिक ऋणों के लिए कुल 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण वृद्धि गारंटी प्रदान की, जिसका उपयोग भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को दिए गए मौजूदा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आईबीआरडी ऋण को आंशिक रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए किया गया। आईबीआरडी ऋण 2016 में एसबीआई को ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप[22] प्रोग्राम के हिस्से के रूप में प्रदान किया गया था, ताकि पूरे भारत में वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों को रूफटॉप सौर प्रणाली प्रदान की जा सके।

दोनों ही ऑपरेशन भारत की हरित, आर्थिक विकास रणनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। फ्रेट कॉरिडोर सड़क परिवहन की तुलना में परिवहन का एक अधिक कुशल तरीका है और हर साल मिलियन टन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (जीएचजी) को कम करता है। एसबीआई द्वारा सौर पीवी कार्यक्रम को वित्तपोषित करने में स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध होती है, तथा तापीय उत्पादन को विस्थापित करके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है। दोनों कार्यक्रमों के लिए, भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास के प्रारंभिक चरण के वित्तपोषण के लिए आईबीआरडी ऋणों का उपयोग किया, जिससे एमआईजीए द्वारा समर्थित बाजार वित्तपोषण द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले परिचालन को वाणिज्यिक रूप से विनियोजनीय बनाया जा सके।

वास्तव में, आईबीआरडी निवेश ने बुनियादी ढांचे के निवेश को ग्रीन-फील्ड जोखिमों को पार करने में मदद की, जिससे एमआईजीए समर्थित बाजार वित्तपोषण आईबीआरडी के साथ प्रतिस्पर्धी हो गया और साथ ही आईबीआरडी फंड को नई विकास परियोजनाओं में पुनर्निवेश के लिए जारी करने की अनुमति मिली। एमआईजीए गारंटी ने डीएफसीसीआईएल को पहली बार वाणिज्यिक शर्तों के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उधार लेने की अनुमति दी, जिससे एसओई के वित्तपोषण विकल्पों में विविधता आई। एसबीआई के लिए, गारंटी से उधार लेने की लागत भी कम हुई और इसके वित्तपोषण के स्रोतों में विविधता आई। महत्वपूर्ण बात यह है कि एमआईजीए का उपयोग करके, भारत अपने जी-20 प्रेसीडेंसी के तहत लिखी गई रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों में से एक का पालन कर रहा है, जिसमें विश्व बैंक समूह से मध्यम आय वाले देशों के लिए बाजार वित्त का लाभ उठाने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया गया है।

5.30. **शिक्षा-रोजगार के बीच की खाई को पाटने की रणनीति:** कौशल विकास वैश्विक मेगाट्रेंडों के बीच शिक्षा और श्रम बाजारों में हो रहे बदलावों के केंद्र में है, जैसे स्वचालन, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई, उत्पादों और सेवाओं का डिजिटलीकरण, जो कार्य की प्रकृति और कौशल की मांग को बदल रहे हैं। सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक, जिसकी औसत आयु 28 वर्ष है, के साथ भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग रोजगार

22. एमआईजीए भारत में नवोन्मेषी सोलर रूफटॉप प्रणालियों को सपोर्ट करता है, विश्व बैंक समूह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, 2024 (https://tinyurl.com/3x3yrj42)

योग्य कौशल से सुसज्जित तथा उद्योग की आवश्यकताओं के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करके कर सकता है। कौशल के उन्नत स्तर और बेहतर मानक देशों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नौकरी बाजारों में मौजूद चुनौतियों और अवसरों को कुशलतापूर्वक सामना (नेविगेट) करने में मदद करते हैं। भारत ने न केवल अपने युवा कार्यबल की क्षमता को पहचाना है, बल्कि इतनी बड़ी आबादी को कौशल प्रदान करने से जुड़े मुद्दों को भी पहचाना है। कौशल विकास एवं उद्यमिता (एनपीएसडीई) पर राष्ट्रीय नीति का ध्यान अंतराल को पाटने, उद्योग की सहभागिता में सुधार लाने, गुणवत्ता आश्वासन ढांचा स्थापित करने, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और प्रशिक्षुता के अवसरों का विस्तार करने पर केंद्रित है। समानता को प्राथमिकता देते हुए, यह हाशिए पर पड़े समूहों को लक्षित करता है और महिलाओं के लिए कौशल विकास और उद्यमिता पर जोर देता है। उद्यमिता के क्षेत्र में, नीति संभावित उद्यमियों को शिक्षित करती है, मार्गदर्शन की सुविधा प्रदान करती है, नवाचार को बढ़ावा देती है, व्यापार करने में आसानी बढ़ाती है और सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देती है। समानता को प्राथमिकता देते हुए, यह हाशिए पर पड़े समूहों को लक्षित करता है और महिलाओं के लिए कौशल विकास और उद्यमिता पर जोर देता है। उद्यमशीलता के क्षेत्र में, नीति संभावित उद्यमियों को शिक्षित करती है, मार्गदर्शन (मेंटरशिप) की सुविधा प्रदान करती है, नवाचार को बढ़ावा देती है, व्यापार करने में आसानी को बढ़ाती है और सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देती है। यह, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के साथ मिलकर, भारत में शिक्षा-रोजगार की खाई को पाटने की जबरदस्त क्षमता रखता है। हालाँकि, कौशल शिक्षा प्रणाली, विशेषकर स्कूलों द्वारा निर्मित नींव पर अर्जित किए जाते हैं। इसलिए, स्कूली शिक्षा को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की बुनियादी आवश्यकता तथा कक्षा के अनुरूप सीखने के परिणामों की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एनईपी 2020 और एनईपी 2023 इस उद्देश्य को साकार करने के लिए एक अच्छा ढांचा प्रदान करते हैं। यह भावी पीढ़ी की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए शैक्षिक प्रणाली में सुधार हेतु प्रेरणा का काम करता है। एनईपी को लागू करना शैक्षिक परिणामों को प्राप्त करने और युवाओं को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए तैयार करने की कुंजी है। इसके अलावा, नई कौशल पहल और मौजूदा कौशल पहलों को नया रूप देना सरकार की उच्च प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। इस मामले में केवल सरकारों - संघ और राज्यों- पर भारी काम करने के लिए छोड़ने के बजाय अकादमिक संस्थाओं के साथ मिलकर पहल करने से उद्योग को ही बहुत लाभ होगा। वास्तव में, इसे विशिष्ट तरीके के साथ किया जाना चाहिए।

5.31. **राज्य की क्षमता और योग्यता निर्माण की रणनीतिः** वर्ष 2014 से भारत ने नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा प्रदान करने और प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। सिविल सेवा इन परिवर्तनकारी प्रयासों के केंद्र में रही है। नीतियों को डिजाइन करने और यह सुनिश्चित करने कि पहल सभी नागरिकों तक पहुँचे सिविल सेवा की क्षमता, इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण रही है। हालाँकि, उभरती चुनौतियों का सामना करते हुए भारत की प्रगति को बनाए रखने और तेज करने के लिए राज्य तंत्र को स्वयं को फिर से कल्पना करने, नया आविष्कार करने, फिर से सक्रिय करने और पुनः सुसज्जित करने की आवश्यकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्सी वर्षों की सापेक्ष स्थिरता के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि वैश्विक मामलों में आक्षेपपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। कूटनीति, सुरक्षा और घरेलू सामाजिक-आर्थिक विकास जैसे बहुत से क्षेत्रों को अछूता छोड़ना संभव नहीं है। वरिष्ठ स्तरों पर, देश को सामान्यज्ञों और विशेषज्ञों दोनों के संयुक्त ज्ञान, जानकारी और अनुभव की आवश्यकता होगी। सिविल सेवा पूर्व की सुविधाएं प्रदान करती है, तथा निजी क्षेत्र उत्तरार्द्ध की सुविधाएं प्रदान करता है। हाल के वर्षों में सरकार ने पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से केन्द्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ पदों पर पार्श्विक प्रवेश की दिशा में महत्वपूर्ण शुरुआत की है। इसका पर्याप्त विस्तार किया जाना आवश्यक है। यह इस अंतर को पाटने का एक तरीका है, क्योंकि आने वाले वर्षों में विविध कौशल और विचारों की दिशा की आवश्यकता बढ़ती ही रहेगी। सभी विशेषज्ञताओं में सिविल सेवकों के लिए आधारभूत और मध्य-कैरियर प्रशिक्षण का कौशल, योग्यता और दृष्टिकोण को पुनः सक्रिय और पुनर्जीवित करने के लिए

पुनः विचार किया जाएगा। वरिष्ठ पदों पर कार्य करने के लिए, उनकी मांगों के अनुरूप कार्य करने, तथा उनमें उत्पादक और उद्देश्यपूर्ण बनने के लिए कार्यकाल की अवधि भी महत्वपूर्ण है। यदि पहले से नहीं तो जल्द ही, नीतिगत परिणामों को बड़े पैमाने पर और तीव्र गति से सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही तंत्र और प्रथाएं (प्रेक्टिस) आवश्यक हो जाएंगी। वरिष्ठ स्तर पर वर्ष के शुरुआत और अंत में लक्ष्यों और माप पर वार्षिक बातचीत (कंवरशेसन) से व्यावसायिकता और जवाबदेही आएगी। हालांकि, सिद्धांत रूप में, इस तरह के अभ्यास की वांछनीयता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन इन तंत्रों और प्रथाओं (प्रेक्टिस) को स्वयं कई बार दोहराने की आवश्यकता होगी ताकि उनकी व्यवहार्यता, सीमाओं और उपयोगिता को अधिक स्थायी रूप से संस्थागत बनाए जाने से पहले बेहतर ढंग से समझा जा सके।

बॉक्स V-5: भारत में राज्य क्षमता निर्माण के लिए मिशन कर्मयोगी का समग्र दृष्टिकोण

प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) की रिपोर्ट में सिविल सेवा की क्षमता में सुधार के लिए कई बाधाओं की पहचान की गई थी। इनमें विभागों द्वारा नीतियों का अलग-अलग ढंग से क्रियान्वयन,[23] निम्न सम्प्रेषण, सख्त सूचना सीमाएं, तथा सहयोग की कमी शामिल थी, जिसके परिणामस्वरूप दोहरे प्रयास और अकुशल संसाधन आवंटन हुआ।[24] इस संरचना के अंतर्गत एक कार्मिक प्रबंधन प्रणाली थी जिसने सिविल सेवकों की कुशलतापूर्वक कार्य करने की क्षमता और प्रेरणा में बाधा उत्पन्न की। अपर्याप्त संसाधन वाले प्रशिक्षण संस्थान और अनियमित रूप से अद्यतित प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिकारियों को वह कौशल और विशेषज्ञता प्रदान नहीं कर पाए, जो उन्हें व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ने और लोक प्रशासन की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक थे।[25,26] प्रदर्शन प्रबंधन प्रणालियां मूल्यांकन करने, पुरस्कृत करने और प्रदर्शन में सुधार करने तथा अधिकारियों की क्षमताओं को प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए उचित तंत्र से सुसज्जित नहीं थीं।[27] चुनौतीपूर्ण कार्य वातावरण और मार्गदर्शन की कमी के कारण काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा कम हो गई।[28]

इन समस्याओं के समाधान के लिए एकल, निश्चित समाधान से परे देखने की आवश्यकता है। विविध समाजों में नीति-निर्माण की चुनौतियों पर अपने मौलिक शोधपत्र में, रिटेल और वेबर (1973) ने प्रस्ताव दिया है कि सार्वजनिक नीति नियोजन की समस्याएँ 'विकट' हैं: वे स्वाभाविक रूप से जटिल, बहुआयामी और सीधे समाधान के प्रतिरोधी हैं।[29] इनमें कई छोटी-छोटी समस्याएं शामिल हैं और ये कई हितधारकों से संबंधित हैं, जिनकी प्राथमिकताएं अक्सर प्रतिस्पर्धात्मक होती हैं। ऐसा कोई स्पष्ट बिंदु नहीं है जिस पर इस तरह की समस्या का समाधान हो जाए और इसके लिए कोई आदर्श समाधान नहीं है। सरकार ने मिशन कर्मयोगी शुरू करके राज्य की क्षमता निर्माण की चुनौती का जवाब दिया है, जो समस्या को अधिक सुगम उप-घटकों में विभाजित करता है।[30] यह प्रोग्राम सिविल सेवा के प्रत्येक स्तर के साथ-साथ उनके बीच संबंधों और अंत:क्रियाओं को संबोधित करने के लिए 'कार्यबल-कार्य-कार्यस्थल' फ्रेमवर्क का उपयोग करके राज्य की क्षमता बढ़ाने का प्रयास करता है। यह एक बहुआयामी समाधान प्रदान करता है जिसमें शामिल हैं:

23. प्रथम एआरसी, भारत सरकार की मशीनरी और उसकी कार्य-प्रणालियों पर रिपोर्ट, 1968, अध्याय II, खंड 2.2
24. द्वितीय एआरसी, नागरिक केंद्रित प्रशासन पर बारहवीं रिपोर्ट: द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, 2009, अध्याय 2, खंड 2.6
25. द्वितीय एआरसी, नागरिक केंद्रित प्रशासन पर बारहवीं रिपोर्ट: द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, 2009, अध्याय 2, खंड 2.6
26. द्वितीय एआरसी, कार्मिक प्रशासन के नवीनीकरण पर दसवीं रिपोर्ट, स्केलिंग न्यू हाइट्स, 2008, अध्याय 4, खंड 4.1
27. वही, अध्याय 5, खंड 5.2
28. वही, अध्याय 7, खंड 7.4
29. ''डिलेमाज इन जनरल थ्योरी ऑफ प्लानिंग,'' होर्स्ट डब्ल्यू. जे. रिटेल और मेल्विन एम. वेबर, नीति विज्ञान 4, संख्या 2 (1973): 155-169
30. ''मिशन कर्मयोगी: ए साइलेंट रिवोल्यूशन,'' - आर. बालासुब्रमण्यम, जर्नल ऑफ गवर्नेंस 25 (जुलाई 2022), (https://tinyurl.com/ysevk6ut)

- विभिन्न कैरियर चरणों में उनकी भूमिकाओं और संबंधित योग्यता आवश्यकताओं पर केंद्रित **कार्यबल** की क्षमता का निर्माण करना
- भूमिका-आधारित मानव संसाधन प्रबंधन और निर्णयन माध्यम से **कार्य** की गुणवत्ता में सुधार करना
- मार्गदर्शन, बेहतर प्रबंधकीय प्रक्रियों और बेहतर भौतिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से **कार्यस्थल** को बेहतर बनाना

कार्यस्थल की भूमिकाओं और श्रमिकों की सक्षमताओं को जोड़कर, मिशन कर्मयोगी क्षमता निर्माण और मानव संसाधन प्रबंधन प्रणालियों के बीच एक अत्यंत आवश्यक सेतु का निर्माण करता है। सक्षमताएँ वे दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान हैं जो किसी सिविल सेवक के लिए अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभाने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे-जैसे अधिकारी अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, वैसे-वैसे उनमें अपेक्षित सक्षमताएँ भी विकसित होती जाती हैं। मिशन कर्मयोगी के माध्यम से सरकार सभी सिविल सेवकों के लिए उनकी भूमिकाओं और कर्तव्यों के संदर्भ में योग्यता आवश्यकताओं को रेखांकित कर रही है, साथ ही कर्मयोगी सक्षमता मॉडल[31] में रेखांकित सिविल सेवकों के चार गुणों या व्यापक सद्गुणों को भी रेखांकित कर रही है। इसके बाद ये योग्यताएं सिविल सेवकों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाती हैं। एक बार सक्षमताओं के निर्दिष्ट हो जाने के बाद, उन्हें कार्यस्थल प्रदर्शन आकलन, डिजिटल एमआईएस सिस्टम से डेटा और सार्वभौमिक (360-डिग्री) प्रतिपुष्टि (फीडबैक) तंत्र सहित कई उपायों का उपयोग करके मूल्यांकन किया जा सकता है। इससे सरकार को कैलिब्रेटेड क्षमता-निर्माण समर्थन प्रदान करने और सरकार में सही भूमिका के लिए सही व्यक्ति की पहचान करने में मदद मिलेगी।

क्षमता-निर्माण कार्यक्रम, सेवा-पूर्व प्रशिक्षण और वर्तमान में जारी व्यावसायिक विकास दोनों के संदर्भ में, उन विशिष्ट योग्यताओं का निर्माण करने के लिए डिजाइन किए जा सकते हैं जिनकी एक सिविल सेवक को अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभाने के लिए आवश्यकता होती है। यह पारंपरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से आगे बढ़कर साक्ष्य-आधारित वयस्क अधिगम सिद्धांतों, जैसे दीक्षा कार्यक्रम, एक्सपोजर विजिट, केस स्टडीज (अमृत ज्ञान कोष के उपयोग के माध्यम से)[32] और स्व-गतिमान और प्रौद्योगिकी-सक्षम अधिगम पर आधारित दृष्टिकोणों की एक श्रृंखला का उपयोग करने के लिए स्थान बनाता है। इस लक्ष्य को बड़े पैमाने पर हासिल करने के लिए, प्रौद्योगिकी-सक्षम क्षमता निर्माण से सभी संवर्गों, राज्यों और वरिष्ठता के अधिकारियों को अपने पेशेवर विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म तेजी से एक सेंट्रल नोड के रूप में आकार ले रहा है, जो सिविल सेवकों को अनुरूपित एवं आवश्यकता-आधारित क्षमता-निर्माण मॉड्यूल तक पहुंचने, उनकी योग्यता संबंधी आवश्यकताओं और अंतर (गैप) पर नजर रखने तथा विभागों के बीच ज्ञान और शिक्षा को साझा करने में सक्षम बनाता है।

क्षमता निर्माण के साथ-साथ, मिशन कर्मयोगी एक भूमिका-आधारित मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली भी शुरू कर रहा है जो सरकार को सिविल सेवकों को उनकी योग्यताओं और भूमिका की आवश्यकताओं के आधार पर भूमिकाएं प्रदान करने की अनुमति देगा। तब तैनाती, स्थानांतरण और पदोन्नति के बारे में निर्णय लेने का कार्य सिविल सेवकों की प्रदर्शित योग्यताओं और अनुभव द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। यह मौजूदा नियम-आधारित दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो सिविल सेवकों के बीच प्रदर्शन के लिए बेहतर प्रोत्साहन उत्पन्न करेगा। क्षमता निर्माण संसाधनों की दुनिया तक पहुँच ख् जो न केवल उनके स्तर के लिए प्रासंगिक मानी जाने वाली चीजों तक ही सीमित नहीं है - सिविल सेवकों को सरकार के भीतर अपनी पेशेवर यात्रा की योजना इस तरह से बनाने में सक्षम बनाएगी जो उनकी रुचि और विशेषज्ञता के क्षेत्रों के अनुरूप हो।

31. कर्मयोगी सक्षमता मॉडल भारतीय क्षमता निर्माण आयोग द्वारा विकसित एक सार्वजनिक मानव संसाधन प्रबंधन ढांचा (फ्रेमवर्क) है। यह ढांचा चार तत्वों पर आधारित है: व्यक्ति की अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में आत्म-जागरूकता, साझा लक्ष्य के लिए विविध विचारों का सहयोग और समावेश, नियमों और विनियमन के साथ पारदर्शिता और अनुपालन, साथ ही प्रणालियों और प्रक्रियाओं का ज्ञान, और नागरिक-केंद्रितता और अपने काम के माध्यम से नागरिकों के जीवन को बदलने की प्रेरणा।

32. भारतीय क्षमता निर्माण आयोग द्वारा विकसित अमृत ज्ञान कोष सिविल सेवकों के लिए एक समर्पित ज्ञान बैंक है, जिसमें सिखाने योग्य केस स्टडी, नीति सिमुलेशन, और इंटरैक्टिव और इमर्सिव शिक्षण संसाधन शामिल हैं।

बढ़ी हुई क्षमता और अपनी भूमिकाओं के लिए बेहतर उपयुक्तता वाले सिविल सेवक उच्च प्रदर्शन करने वाली और कुशल टीम का गठन करेंगे। इसके साथ ही सिविल सेवकों के लिए बेहतरीन कार्यस्थल बनाने में निवेश किया जाएगा, जिसमें प्रेरणा, साझा उद्देश्य और विश्वास की संस्कृति होगी और मजबूत ज्ञान प्रबंधन प्रणालियों का समर्थन होगा। वरिष्ठ सिविल सेवक शुरुआती करियर वाले सिविल सेवकों को सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इनमें से कुछ पहले से ही कुछ जगहों पर हो रहे हैं, लेकिन इन प्रथाओं को और अधिक व्यापक रूप से संस्थागत बनाया जाएगा। भौतिक अवसंरचना में सुधार से सिविल सेवकों को अपने निष्पादन को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, जबकि प्रौद्योगिकी-सक्षम कार्यस्थलों से दक्षता और सहयोग में सुधार होगा। इसके अलावा, प्रौद्योगिकीय अवसंरचना, डेटा और कार्यप्रवाह प्रणालियां संस्थागत स्मृति को मजबूत करेंगी, तथा राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक कार्यनिष्पादन के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए ज्ञान का आधार प्रदान करेंगी।

मध्यम अवधि में संभावना

5.32. पिछले दशक में भारत की विकास की कहानी लचीलेपन की कहानी रही है। देश ने कई वैश्विक संकटों का सामना किया है क्योंकि सरकार ने एक ऐसी रिकवरी रणनीति बनाकर उनसे कुशलतापूर्वक निपटा है जो नागरिकों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई थी, साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि संरचनात्मक सुधारों की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से विकास की गति को बनाए रखा जाए। भारत की ताकत हमेशा से इसकी संस्थाएं रही हैं, और कई बार, संस्थागत मजबूती ने देश को कई चुनौतियों से निपटने में समर्थ बनाया है।

5.33. पिछले दशक के दौरान भारत सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधारों ने अर्थव्यवस्था को मजबूती से विकास पथ पर अग्रसर किया है, जिसकी बदौलत भारत जल्द ही अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। आईएमएफ ने अपने अप्रैल 2024 के वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक में, मजबूत घरेलू मांग और बढ़ती कामकाजी आयु वाली आबादी के आधार पर वर्ष 2024-25 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है, जिससे भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली जी 20 अर्थव्यवस्था बन गया है। यह आर्थिक वृद्धि के लिए हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप है, जैसा कि अध्याय 1 में उल्लेख किया गया है। भारत निम्न आय वाले देश से निम्न-मध्यम आय वाले देश में तब्दील हो चुका है। जैसे-जैसे यह मध्यम और उच्च-मध्यम आय की स्थिति की ओर आगे बढ़ता है, लोगों की आकांक्षाएँ बढ़ती रहती हैं। पिछली प्रगति से संतुष्टि शीघ्र ही स्मृति से गायब हो जाती है, और नई अपेक्षाएँ उसकी जगह ले लेती हैं। वर्तमान की उपलब्धियों को बढ़ती आकांक्षाओं के मुकाबले मापने से समाज व्याकुल और असंतुष्ट दिखाई देता है। लेकिन, यह रचनात्मक है, विनाशकारी नहीं। ऐसी आकांक्षाओं की अव्यक्त ऊर्जा का दोहन किया जाना चाहिए, भले ही उन्हें पूरा किया जाना हो। इसे भारत के आकार के देश में और लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर किया जाना चाहिए। इसमें जो जटिलता है, उसका अनुसरण करने के लिए कोई ऐतिहासिक मिसाल या प्रारूप उपलब्ध नहीं है। तीन दशक पहले अर्थव्यवस्था जिस स्थिति में थी, उससे आज जो स्थिति है, वह हमें अगले गंतव्य तक नहीं ले जा सकती। भारत की परिस्थितियों और उसके लक्ष्यों की अनूठी प्रकृति के बारे में जागरूकता आवश्यक है, ताकि हम इसकी सामाजिक-आर्थिक प्रगति में भाग लेने और योगदान देने के लिए खुद को तैयार कर सकें। हमारे ज्ञान और दृष्टिकोण को निरंतर विकास की दिशा में होना चाहिए ताकि हम 'विकसित भारत @2047' परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। एक खुले मन से इसकी शुरुआत करना एक उत्तम बात होगी।

5.34. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अध्याय में छह-आयामी विकास रणनीति प्रस्तुत की गई है, जो इस समझ पर आधारित है कि पिछले दशक के संरचनात्मक सुधारों, जो अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष पर केंद्रित थे, में अगली पीढ़ी के सुधारों का समावेश करना होगा जो नीचे से ऊपर (बॉटम-अप) की प्रकृति के हैं ताकि मजबूत, संधारणीय, संतुलित और समावेशी विकास प्राप्त हो सके। इन रणनीतियों में से प्राथमिक यह सुनिश्चित करना है कि निजी क्षेत्र में पूंजी निर्माण स्वाभाविक और स्थिर रूप से बढ़े, जिससे नौकरियों में अंतर्जात वृद्धि हो और श्रमिकों के लिए आय का उचित हिस्सा सुनिश्चित हो। दूसरा, भारत के लिए हरित परिवर्तन का वित्तपोषण एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सार्वजनिक-निजी भागीदारी

महत्वपूर्ण होगी। ऐसे नवोन्मेषी वित्तपोषण साधनों की आवश्यकता है जो भारत के व्यवस्था परिवर्तन (ट्रांजिशन) प्रयासों के लिए निजी पूंजी जुटाने में मदद कर सकें। तीसरा, जहां तक एमएसएमई का सवाल है, ऋण अंतर को पाटना एक महत्वपूर्ण तत्व बना हुआ है, जबकि साथ ही विनियमन, भौतिक और डिजिटल संपर्क को बढ़ाने, तथा एक निर्यात रणनीति बनाने पर भी फोकस होना चाहिए, जिससे एमएसएमई को बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने और आगे बढ़ने में मदद मिल सके। चौथा, वृद्धि, विकास और समानता का इंजन बनने के लिए कृषि की क्षमता का दोहन तर्कसंगत किसान-हितैषी नीतियों के माध्यम से किया जाना चाहिए जो पर्यावरण और जलवायु की दृष्टि से संधारणीय हों। पांचवां, भारत की शिक्षा नीतियों और कौशल-विकास नीतियों को सीखने और कौशल परिणामों पर सीधे ध्यान केंद्रित करने और उन्हें एक-दूसरे के साथ संरेखित करने की भी आवश्यकता है। हम वैश्विक अनुभवों से सीख सकते हैं कि इसे कैसे हासिल किया जा सकता है, जैसे कि यूरोपीय संघ सामंजस्य नीति।[33] अंत में, राज्य की क्षमता और सामर्थ्य को बढ़ाना महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस अध्याय में सुझाई गई विकास रणनीति फलीभूत हो। उभरती चुनौतियों के बीच भारत की प्रगति को बनाए रखने और तेज करने के लिए राज्य मशीनरी में समर्पित निवेश की आवश्यकता है ताकि उसे फिर से तैयार और पुनः अनुप्राणित किया जा सके।

5.35. जनवरी 2024 में प्रकाशित 'भारतीय अर्थव्यवस्था: एक समीक्षा' के अध्याय 2 में, हमने लिखा था कि यदि हम 2014 से किए गए संरचनात्मक सुधारों पर काम कर सकें तो अर्थव्यवस्था के लिए सतत आधार पर 7 प्रतिशत या उससे अधिक की दर से बढ़ने की काफी गुंजाइश है। बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना, दिवाला एवं शोधन अक्षमता ढांचे का निर्माण, देश भर में माल और सेवा कर की संस्थापना, और देश के भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार उनमें से कुछ हैं। इस अध्याय में प्रस्तुत कार्य-नीतियाँ इन नीतिगत पहलों पर आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं।

5.36. नई सरकार के आने से निरंतरता के साथ-साथ बदलाव भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत विकसित भारत @2047 के सामूहिक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने परिकल्पना की है, *"हमें प्रगति के रोडमैप पर चलना होगा, और यह केवल सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया जाएगा; राष्ट्र इसे आकार देगा। प्रत्येक नागरिक को अपना योगदान देना होगा और इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। 'सबका प्रयास', यानी सभी का प्रयास, एक ऐसा मंत्र है जो बड़े से बड़े संकल्प को हकीकत में बदल देता है। चाहे वह स्वच्छ भारत अभियान हो, डिजिटल इंडिया अभियान हो, कोविड-19 से निपटना हो या वोकल फॉर लोकल का विचार हो, हम सभी ने 'सबका प्रयास' की शक्ति देखी है। 'सबका प्रयास' के माध्यम से ही 'विकसित भारत' का सपना साकार होगा।"*[34]

33. कर्मयोगी सक्षमता मॉडल भारतीय क्षमता निर्माण आयोग द्वारा विकसित एक सार्वजनिक मानव संसाधन प्रबंधन ढांचा (फ्रेमवर्क) है। यह ढांचा चार तत्वों पर आधारित है: व्यक्ति की अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में आत्म-जागरूकता, साझा लक्ष्य के लिए विविध विचारों का सहयोग और समावेश, नियमों और विनियमन के साथ पारदर्शिता और अनुपालन, साथ ही प्रणालियों और प्रक्रियाओं का ज्ञान, और नागरिक-केंद्रितता और अपने काम के माध्यम से नागरिकों के जीवन को बदलने की प्रेरणा।

34. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की 11 दिसंबर, 2023 की पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति (https://tinyurl.com/yc2r4ate)

यह पृष्ठ खाली छोड़ दिया गया है

जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण: समझौताकारी सामंजस्य

06

अध्याय

दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद, भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत का केवल एक तिहाई है। भारत 2047 तक 'विकसित भारत' होने का लक्ष्य रखता है। यह उद्देश्य एवं 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति देश को एक ऐसे उच्च और मजबूत आर्थिक विकास के लिए प्रेरित करता है, जो समावेशी और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ हो। निम्न-कार्बन उत्सर्जन वाले ऐसे विकास उचित मूल्य पर ऊर्जा की स्थायी प्राप्ति की प्रतिबद्धता पर आधारित हैं तथा देश के महात्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुसार हैं। यह कार्य एक चुनौती है, यह देखते हुए कि स्वच्छ और हरित ऊर्जा स्रोतों के लिए व्यवहार्य बैटरी भंडारण तकनीकों और महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच की आवश्यकता होती है जिससे कि ये स्रोत स्थायी ऊर्जा संभव हो सके। कार्बन उत्सर्जन मार्ग के साथ विकास की जरूरतों का सामंजस्य करना एक कठिन कार्य है, विशेषकर तब जब वह निम्न घरेलू संसाधनों के माध्यम से प्रमुख रूप से वित्तपोषित हो।

परिचय

6.1 पिछले आर्थिक सर्वेक्षण के लिखे जाने के बाद से जलवायु परिवर्तन पर समर्पित सम्मेलनों, बैठकों और शिखर सम्मेलनों की कोई कमी नहीं रही है। यह दुनिया भर में नीति और अन्य चर्चाओं पर हावी रहा है। यह थिंक-टैंक, विशेषज्ञों और नीति विशेषज्ञों के लिए उचित रूप से संबद्ध प्रतीत होने के लिए एक तैयार विषय प्रदान करता है। तथापि, दुनिया को एहसास हो रहा है कि उन्नत देशों के विशेषज्ञ और नीति निर्माता किस बात का विरोध कर रहे हैं - कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इसका वर्तमान दृष्टिकोण एक बहुत ही सरल कारण से दोषपूर्ण है। यह समझौताकारी समन्वय को अनदेखा करता रहा है। लेकिन व्यावहारिक पुरुष और महिलाएं समन्वय को पहचानने से बचने में असमर्थ रहे हैं। देशों को अपनी स्वयं को समयसीमा को पीछे धकेलना पड़ा।

6.2 यूनाइटेड किंगडम ने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले को 2030 से 2035 तक के लिए पांच साल के लिए टाल दिया। जर्मनी को जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले बॉयलरों पर प्रतिबंध लगाने के अपने नियमों को पारित होने से पहले ही कम करना पड़ा। विकसित देशों में वैकल्पिक राजनीतिक दलों के उदय का श्रेय जलवायु संबंधी नियमों के प्रति जनता के प्रतिरोध को दिया जाता है, जिन्हें गरीबों और कम आय वालों के जीवन-यापन की लागत बढ़ाकर अनुचित रूप से लक्षित करने के रूप में माना जाता है। ब्लूमबर्ग के अनुसारांश, जर्मन व्यवसाय देश से बाहर स्थानांतरित होने का सबसे बड़ा कारण ऊर्जा की बढ़ती लागत को बताते हैं।[1] यही चुनौती का सारांश है जिससे सरकारें जूझ रही हैं।

6.3 वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को वहनीय बनाने के लिए राजकोषीय सब्सिडी की आवश्यकता होती है। तथापि, दुनिया भर में अधिकतर सरकारें वित्तीय रूप से तनावग्रस्त हैं, खासकर महामारी के कारण होने वाली आर्थिक और स्वास्थ्य

1. 'जर्मनीज डेज ऐज एन इंडस्ट्रीयल सुपरपावर आर कमिंग टू एन ऐंड' 10 फरवरी 2024, ब्लूमबर्ग
(https://www.bloomberg.com/news/features/2024-02-10/why-germany-s-days-as-an-industrial-superpower-are-coming-to-an-end)

अव्यवस्थाओं से निपटने के बाद। कई देश जीवाश्म ईंधन पर भी भारी कर लगाते हैं। उनके उपयोग पर रोक लगाने से सरकारें उस राजस्व को खो देंगी। भू-राजनीतिक रूप से, अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ भूमि को सुरक्षित करने की होड़ शुरू कर दी है। चीन ने खुद को इनमें से कई सामग्रियों के लिए एक अपरिहार्य स्रोत के रूप में स्थापित किया है। संकट के समय में आपूर्ति सुनिश्चित करना चिंता का विषय है। परमाणु ऊर्जा सबसे स्वच्छ और सुरक्षित विकल्प है। तथापि, कुछ देश इस पर विचार करने से हिचकते हैं क्योंकि उनके लोग दुर्लभ घटनाओं की संभावनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं, जैसा कि मनुष्य आदी होते हैं। तीन मील का द्वीप, चेरनोबिल और फुकुशिमा, लोगों के दिमाग में छाए हुए हैं। प्रोफेसर डैनियल काह्नमैन, जिनका इस साल की शुरुआत में निधन हो गया।[2]

6.4 तांबा और निकल जैसी अपेक्षाकृत आम धातुएँ दुर्लभ होती जा रही हैं। 'मैटीरियल वर्ल्डश्' में एड कॉनवे ने लिखा है कि दुनिया को अगले कुछ दशकों में तांबे की इतनी जरूरत पड़ सकती है जितनी कभी भी इंसानों को इस धातु के बारे में पता चलने के बाद से नहीं पड़ी। सिर्फ तांबा ही नहीं बल्कि अन्य धातुओं की भी कमी होगी। ऊर्जा परिवर्तन की कीमत ज्यादातर देशों के लिए बहुत ज्यादा होगी। संसाधन राष्ट्रवाद तेजी से प्रचलन में आ रहा है। यह और भी बदतर होता जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामग्री और खनिजों को निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों ने लिखा[3], "... पूर्वानुमानित पवन और सौर क्षमताओं को विकसित करने के लिए 2024-30 के दौरान ~10ईजे ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि इसी अवधि के दौरान हमारी अनुमानित वैश्विक ऊर्जा मांग वृद्धि के ~20: के बराबर है (हमारे वैश्विक ऊर्जा आउटलुक पर आधारित पूर्वानुमान) और ~1,450 मिलियन टन CO2e उत्सर्जित करेगा (औसतन ~207 मिलियन टन, जो 2022 में पाकिस्तान या अर्जेंटीना के वार्षिक उत्सर्जन के बराबर है)। इसके अतिरिक्त, वैश्विक लाइट-ड्यूटी वाहन बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुमानित प्रवेश के लिए इन ईवी को बनाने और चार्ज करने के लिए ~10ईजे ऊर्जा की आवश्यकता है।"

6.5 "दूसरा कारक समय है। दुनिया में कहीं भी इस पैमाने का ऊर्जा परिवर्तन इतने कम समय में नहीं हुआ है। वैक्लेव स्मिल ने 2014 में लिखा था[4] "... एक प्रमुख ईंधन से दूसरे में प्रत्येक व्यापक परिवर्तन में 50 से 60 साल लगे हैं... राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर ऊर्जा परिवर्तन स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक चलने वाले मामले हैं। जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में होने वाला बदलाव कोई अपवाद नहीं होगा। इसके लिए पीढ़ियों की दृढ़ता की आवश्यकता होगी। "वास्तव में, उन्होंने लिखा कि अधिक प्रभावी समाधान समग्र ऊर्जा उपयोग को कम करना था। अफसोस, यह एक ऐसी सलाह है जिसे दुनिया या तो मानने में असमर्थ है या मानने को तैयार नहीं है। विकासशील देशों को अपनी ऊर्जा खपत पर अंकुश नहीं लगाने के लिए दोषी ठहराना कठिन है। विकासशील देशों को बेहतर जीवन स्तर की अपनी आकांक्षाओं को त्यागने के लिए कहना नैतिक रूप से गलत है ताकि विकसित देश स्वच्छ वातावरण और ठंडी जलवायु में अपने जीवन जीने के तरीके को बनाए रख सकें।

6.6 तथापि, दिसंबर 2015 में हस्ताक्षरित पेरिस समझौते ने ठीक यही किया। इसने तीन महीने पहले ही तय किए गए सतत विकास लक्ष्यों को पीछे छोड़ दिया। प्रोफेसर माइक हुल्म ने लिखा[5] "... "वैश्विक तापमान को एक निश्चित संख्यात्मक सीमा के भीतर सुरक्षित रखने के लक्ष्य ने कल्याण की व्यापक महत्वाकांक्षाओं पर अग्रता ले ली, आंशिक रूप से जलवायु वैज्ञानिकों और सरकारी वार्ताकारों की सफलता के कारण जलवायु नीतियों के लक्ष्य को एक एकल और सरल

2. उनकी शोध से पता चला कि मनुष्य दुर्लभ घटनाओं की संभाव्यता का निरंतर अतिप्राक्कलन करते हैं।

3. "एनर्जी ट्रांजिशन", 18 अप्रैल 2024, ग्लोबल एनर्जी स्ट्रेटजी, जेपी मॉर्गन

4. वाक्लाव स्मिल: 'ए ग्लोबल ट्रांजिशन टू रिन्यूएबेल एनर्जी विल टेक मेनी डिकेडान', साइंटिफिक अमेरिकन, जनवरी 2014 https://www-scientificamerican.com/article/a-global-transition-to-renewable-energy-will-take-many-decades/

5. हुल्म, माइक. क्लाइमेट चेंज इजेंट एवरीथिंग: लिबरेटिंग क्लाइमेट पॉलिटिक्स फ्रॉम अलार्मिंग (पृष्ठ 51). पॉलिटी प्रेस. किंडल संस्करण.

सूचकांक के रूप में परिभाषित करने में। फिर भी,''... वैश्विक तापमान जलवायु और मानव कल्याण और पारिस्थितिक अखंडता के बीच जटिल संबंधों की पूरी श्रृंखला को पकड़ने के लिए एक गंभीर रूप से दोषपूर्ण सूचकांक है।

6.7 "वैश्विक उत्सर्जन को नियंत्रित करने को सभी आर्थिक नीतियों के शिखर पर पहुंचाने की प्रक्रिया में न केवल विकास लक्ष्यों को कमतर कर दिया गया है, बल्कि विकासशील देशों को सीमा पर कार्बन कर लगाने की धमकी भी दी जा रही है, जो कि साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित राष्ट्रीय क्षमताओं की भावना का पूर्णतः उल्लंघन है, जिसे पेरिस समझौते का आधार माना गया था।

6.8 अगर यह वास्तविक और दुखद न होता तो यह एक हास्य होती। विकसित देश कार्बन से लदे अपने देशों में आने वाले आयात पर सीमा पर कार्बन कर लगाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को मार्गदर्शन करने, उस पर कब्जा करने और प्राकृतिक बुद्धिमत्ता पर हावी होने देने के अपने जुनून के कारण ऊर्जा की मांग बढ़ा रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ। दशक के अंत में अग्रणी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक ने 2030 तक नेट जीरो हासिल करने का वादा किया था। लेकिन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उभरती हुई तकनीक पर हावी होने की होड़ ने 2023 तक इसके उत्सर्जन को 30% तक बढ़ा दिया है। अप्रैल में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट[6] में, गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों ने लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बिजली की मांग में एक पीढ़ी में नहीं देखी गई वृद्धि का अनुभव होगा, एआई और 'ट्रांसमिशन, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए प्रमुख बाधाओं में से एक, और डेटा सेंटर और एआई के जुड़ने से यह और भी बढ़ सकता है"। जलवायु परिवर्तन से निपटने के एक तर्कसंगत तरीके के रूप में ऊर्जा की मांग को प्रबंधित करने से संबंधित मुद्दे और अन्य मुद्दों की गहन जांच की गई है और एक विशेष निबंध में अध्याय XX में फोरेंसिक रूप से विश्लेषण किया गया है।

6.9. तथापि, इन घटनाक्रमों से किसी भी समझदार पाठक को यह विश्वास हो जाना चाहिए कि विकसित दुनिया ने न केवल खुद को उलझनों में उलझा लिया है, बल्कि विकासशील देशों में गरीबी और असमानता को गहरा करने और उन्हें स्थायी रूप से अविकसित स्थिति में डालने में भी योगदान दे रही है, क्योंकि वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर उत्सर्जन को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर हैं। विकसित देश, जो पिछले दो शताब्दियों से जीवाश्म ईंधन आधारित विकास कार्यनीति पर निर्भर हैं, आज जहां वे हैं, वहां पहुंचने के लिए, विकासशील देशों से उत्सर्जन में महत्वाकांक्षी कटौती की मांग कर रहे हैं, उन्हें नीतिगत उपायों, साधनों और उत्पादन और ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो कि पूर्व के विकास को बढ़ावा देने वाली कार्बन-उत्सर्जक पारंपरिक रणनीतियों से बिल्कुल अलग हैं। यह तथ्य कि ये नए रास्ते अप्रमाणित या भरोसेमंद हैं, जी7 देशों के हाल के विचार-विमर्श से स्पष्ट है कि 2030[7] की पहली छमाही में ही बिना किसी हस्तक्षेप के कोयला बिजली संयंत्रों के उपयोग को समाप्त करना है, जबकि कई दशक पहले उनका कार्बन उत्सर्जन चरम पर था। जापान और जर्मनी इस पर सहमत नहीं थे। इसके विपरीत, जर्मनी ने अपने कानून में 2038 तक कोयला संयंत्रों को बंद करने का अंतिम लक्ष्य लिखा है, जबकि जापान ने अभी तक कोई तिथि निर्धारित नहीं की है। यह अंतर-और अंतरर्राष्ट्रीय संघर्षों का नुस्खा है।[8]

---

6. 'पीढ़ीगत विकास: एआई, डेटा सेंटर और आने वाली अमेरिकी बिजली मांग में उछाल', 28 अप्रैल 2024, गोल्डमैन सैक्स इक्विटी रिसर्च

7. जी7, जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक विज्ञप्ति, (टोरिनो, 29-30 अप्रैल, 2024), https://www-meti-go-jp/press/2024/05/20240501001/20240501001-a.pdf-

8. फ्रांसेस्का लैंडिनी, जी7 2035 तक कोयले से बाहर निकलने पर हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन छूट दे सकते हैं, सूत्रों का कहना है, रॉयटर्स, (30 अप्रैल, 2024) https://www-reuters-com/business/energy/g7-ministers-agree-coal-plants-shutdown-by-2030-2035-uk-says-2024-04-29/-

6.10 जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विकासशील देशों को असमान रूप से प्रभावित करेगा क्योंकि ये देश पहले से ही कमजोर और कम लचीले हैं और उन्हें अपनी आर्थिक विकास आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। तथापि विकासशील देश समस्या का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन समाधान का हिस्सा हैं। विकासशील देशों ने पहले ही महत्वाकांक्षी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है, जैसा कि उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) से स्पष्ट है, इस शर्त पर कि विकसित देश उचित लागत पर संसाधन प्रदान करें। विकास मॉडल में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को शामिल करने के लिए, जिसे निम्न कार्बन विकास मार्ग भी कहा जाता है, खरबों डॉलर के क्रम में प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच की आवश्यकता होती है। रूढ़िवादी मानकों के अनुसारांश भी, संसाधन की आवश्यकता का अनुमान (यह मानते हुए कि सभी जरूरतों की लागत नहीं लगाई गई है) 2030 तक 5.8 - 11.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच है।[9] वित्तीय संसाधन और प्रौद्योगिकी विकासशील देशों तक वांछित गति, मात्रा या शर्तों पर नहीं पहुंच रही है, आर्थिक विकास और समृद्धि, यद्यपि स्थायी रूप से, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने की ताकत प्रदान करेगी।

6.11 वैश्विक स्तर पर, जलवायु लक्ष्यों को व्यवहार्यता और स्वीकार्यता के दायरे में लाने के लिए समन्वय को पहचानना महत्वपूर्ण है। समन्वय को पहचानने के लिए हमारे पास सही और उससे भी महत्वपूर्ण उचित प्रश्न पूछने की क्षमता होनी चाहिए।

6.12. *ऐसा ही एक सवाल है ''क्या जलवायु परिवर्तन के बिना दुनिया की कल्पना करना इतना उपयोगी है? यह लगभग बिना कहे ही स्पष्ट है कि यदि हम जीवाश्म ईंधन वाले औद्योगिकरण के लाभों को बनाए रख सकते हैं और जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक दुष्प्रभावों को दूर कर सकते हैं, तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन जो बात निर्णय लेने को इतना कठिन बनाती है, वह यह है कि अधिकांश जलवायु-संवेदनशील सामाजिक परिणामों के लिए... जीवाश्म ईंधन वाले औद्योगीकरण और तकनीकी परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव अच्छा रहा है... इस प्रकार, ''जलवायु परिवर्तन के बिना'' हमेशा सबसे प्रासंगिक काल्पनिक प्रतिरूप नहीं होता है, और अक्सर ''जीवाश्म ईंधन वाले औद्योगिकरण और तकनीकी प्रगति के बिना'' अधिक प्रासंगिक होता है। यह रूपरेखा जलवायु परिवर्तन समस्या की स्थिति की अधिक सही और समग्र तस्वीर प्रस्तुत करती है, और यह वर्तमान प्रणालियों को वास्तव में जितनी आकर्षक हैं, उससे कम आकर्षक नहीं दिखाती है। जब हम आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छे उपाय का आकलन करते हैं, तो हमें वैकल्पिक प्रणालियों की तुलना करनी चाहिए और समय के साथ वैकल्पिक ऊर्जा और कृषि प्रणालियों में संक्रमण की लागतों के विरूद्ध जलवायु परिवर्तन से बचने के लाभों का मूल्यांकन करना चाहिए। हमारे सामने आने वाले समझौताकारी तालमेल के बारे में सटीक और स्पष्ट होने का यही एकमात्र तरीका है।''*[10]

6.13 उचित रूप से, इस परिचयात्मक खंड का अंतिम शब्द माइक हुल्म पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जो चार दशकों से अधिक समय से इस घटना का अध्ययन कर रहे हैं:

"जलवायु परिवर्तन ही सब कुछ नहीं है। भविष्य की ऐसी दुनिया की कल्पना करना बहुत आसान है, जिसमें वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने पर वह मानव कल्याण, राजनीतिक स्थिरता और पारिस्थितिक अखंडता के लिए बेहतर हो, उदाहरण के लिए, उन दुनियाओं की तुलना में, जिनमें - हर तरह से और हर कीमत पर - वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा गया हो।"

6.14 जहाँ तक भारत का सवाल है, ऊपर बताई गई चुनौतियों के बावजूद, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को प्रबंधित करना और यह सुनिश्चित करना कि विकास संबंधी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित होता रहे, इसकी विकास रणनीति

9. कन्वेंशन और पेरिस समझौते के कार्यान्वयन से संबंधित विकासशील देश पक्षों की आवश्यकताओं के निर्धारण पर वित्त पर स्थायी समिति की पहली रिपोर्ट, https://tinyurl.com/5n92sppt.

10. पैट्रिक ब्राउन, ए रेटोरिकल एंबीग्विटी देट प्रोपेगेट्स क्लाइमेट मिसइंफोर्मेशन, ब्रेक थ्रू इंस्टीट्यूट, (3 जुलाई, 2024) https://thebreakthrough-journalsubstack.com/p/a-rhetorical-ambiguit-that-propagates.

की पहचान रही है। इस अध्याय में जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत की पहल और प्रदर्शन की समीक्षा की गई है, ऊर्जा परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा की गई है और बहुपक्षीय वार्ता की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया है। अध्याय का अंत और आगे के विकल्पों एवं रास्ते की खोज से समाप्त होता है।

भारत की जलवायु कार्रवाई की वर्तमान स्थिति

6.15 भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिशन-मोड दृष्टिकोण अपनाया है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी)[11] देश के विकास पथ की स्थिरता को बढ़ाने की रणनीति की रूपरेखा तैयार करता है । भारत के विकास पथ की पारिस्थितिकी स्थिरता में सुधार करते हुए उच्च आर्थिक विकास प्राप्त करने के सिद्धांतों के आधार पर, एनएपीसीसी में सौर, जल, ऊर्जा दक्षता, वन, टिकाऊ आवास, टिकाऊ कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना, जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान और हाल ही में मानव स्वास्थ्य पर मिशन को शामिल करते हुए नौ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं । जलवायु कार्रवाई के व्यापक दायरे - अनुकूलन और शमन, जिसमें मांग पक्ष प्रबंधन भी शामिल है - को कार्यक्रम के माध्यम से अपनाया जा रहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को एनएपीसीसी में रणनीतियों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन पर अपनी राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है । अब तक, 34 एसएपीसीसी चालू हैं, जो राज्य के लिए क्षेत्र-विशिष्ट और क्रॉस-सेक्टर, समयबद्ध प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों को रेखांकित करती हैं।

6.16 भारत ने जलवायु कार्रवाई पर महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2023-24 में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 15.03 गीगावाट की वृद्धि हुई, जो 30 अप्रैल 2024[12] को 82.64 गीगावाट तक पहुंच गई। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन के तहत, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड (पीएटी)[13] योजना के आठवें चक्र को जून 2023 में 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया था और इसमें एल्युमीनियम, सीमेंट, क्लोर-क्षार, लोहा और इस्पात, लुगदी और कागज, तथा कपड़ा जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जिनका कुल ऊर्जा बचत लक्ष्य 0.3370 एमटीओई (मिलियन टन तेल के समतुल्य) है। अपने विभिन्न चक्रों में पीएटी योजना के परिणामस्वरूप ऊर्जा की काफी बचत हुई है और ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी आई है (बॉक्स 2)

6.17 समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप, पहले एनडीसी के लक्ष्य काफी पहले ही हासिल कर लिए गए। उदाहरण के लिए, देश ने 2021 में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से 40 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल की और 2019 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33 प्रतिशत कम कर दिया - जो कि लक्ष्य वर्ष 2030 से क्रमशः नौ और ग्यारह वर्ष पहले है। एनडीसी को अगस्त 2022 में और अद्यतन किया गया। भारत के सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का लक्ष्य बढ़ाकर 45 प्रतिशत (पहले के लक्ष्य 33-35 प्रतिशत से) कर दिया गया । गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता का लक्ष्य 2030 तक बढ़ाकर 50 प्रतिशत (पहले 40 प्रतिशत) कर दिया गया है। 31 मई 2024 तक, स्थापित बिजली

11. जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी), अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, 01 दिसंबर, 2021, पीआईबी, https://static-pib-gov-in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/dec/doc202112101.pdf.

12. वर्षवार उपलब्धियां, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, https://mnre-gov-in/year-wise-achievement/.

13. प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) ऊर्जा-गहन उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के लिए एक विनियामक साधन है, जिसमें अतिरिक्त ऊर्जा बचत के प्रमाणीकरण के माध्यम से लागत-प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक संबद्ध बाजार-आधारित तंत्र है जिसका व्यापार किया जा सकता है। वर्तमान में, इस योजना का आठवां चक्र संचालन में है, https://beeindia.gov.in/en/perform-achieve-and-trade-pat-0.

14. पेरिस समझौते (2021-2030) के तहत भारत का अद्यतन पहला राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, (अगस्त 2022), यूएनएफसीसीसी को प्रस्तु. तिकरण, https://unfccc-int/sites/default/files/NDC/2022-08/India%20Updated%20First%20Nationally%20Determined%20Contrib.pdf.

उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 45.4 प्रतिशत तक पहुंच गई है।[15] भारत 2030 तक वृक्षों और वनों के माध्यम से 2.5 से 3.0 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें 2005 से 2019 तक 1.97 बिलियन टन CO2 समतुल्य कार्बन सिंक पहले ही बनाया जा चुका है।

6.18 यूएनएफसीसीसी के पक्षों को समय-समय पर अपने (ग्रीनहाउस गैस) उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी संवेदनशीलता और उत्सर्जन को कम करने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने के लिए उठाए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी के साथ राष्ट्रीय संचार (एनसी) प्रस्तुत करना चाहिए। भारत ने अपना तीसरा राष्ट्रीय संचार (टीएनसी)[16] प्रस्तुत किया, जिसमें भारत का पहला अनुकूलन संचार (एसी)[17] भी शामिल है। दिसंबर 2023 में यूएनएफसीसीसी को सौंपे जाने वाले प्रस्ताव पर भारत के टीएनसी ने उल्लेख किया है कि ऊर्जा क्षेत्र ने कुल मानवजनित उत्सर्जन में सबसे अधिक 75.81 प्रतिशत योगदान दिया, इसके बाद कृषि क्षेत्र ने 13.44 प्रतिशत, औद्योगिक प्रक्रिया और उत्पाद उपयोग (आईपीपीयू) ने 8.41 प्रतिशत और अपशिष्ट ने 2.34 प्रतिशत योगदान दिया। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि भूमि उपयोग, भूमि-उपयोग परिवर्तन और वानिकी (एलयूएलयूसीएफ) क्षेत्र 2019 में निवल सिंक बना रहा, जिसने 4, 85, 472 GgCO2e उत्सर्जन को हटाया। कुल उत्सर्जन और निष्कासन पर विचार करते हुए, 2019 में भारत का निवल राष्ट्रीय उत्सर्जन 26, 46, 556 GgCO2e था।

6.19 अर्थव्यवस्था में किए गए क्रॉस-सेक्टरल उपायों की अधिकता और उपभोक्ता और उत्पादक व्यवहार को संशोधित करने और ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने की कई योजनाओं का नतीजा यह हुआ है कि भारत का कुल राष्ट्रीय उत्सर्जन (एलयूएलयूसीएफ सहित) 2016 से 4.56 प्रतिशत बढ़ गया है, जो देश द्वारा अनुभव की गई वृद्धि से अनुकूल तुलना करता है। दिलचस्प बात यह है कि 2005 से 2019 के बीच भारत की जीडीपी लगभग 7 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ी है, जबकि उत्सर्जन लगभग 4 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ी है। यानी उत्सर्जन वृद्धि की दर हमारी जीडीपी की वृद्धि दर से कम है। इससे पता चलता है कि भारत ने अपने आर्थिक विकास को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से सफलतापूर्वक अलग कर लिया है, जिससे उसके जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता कम हो गई है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की हाल ही की रिपोर्ट में प्रतिबद्ध जलवायु कार्रवाई करने के भारत के प्रयासों को स्वीकार किया गया है जिसमें यह एकमात्र 2-डिग्री सेंटीग्रेट वार्मिंग वाला G20 राष्ट्र है।[19] उल्लेखनीय रूप से, ये परिणाम मुख्य रूप से घरेलू संसाधनों[20] के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं, जो मुख्य रूप से भारत की जलवायु कार्रवाई का आधार बने हैं। 2030 तक एनडीसी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनुमानित 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (2014-15 की कीमतों पर) की वित्तपोषण आवश्यकताओं को देखते हुए, बहुपक्षीय दायित्वों के अनुसारांश विकसित देशों सहित उचित लागत पर वित्त और प्रौद्योगिकी तक पहुंच आवश्यक संसाधनों पर बाधा को कम करने के लिए आवश्यक है।

भारत के लिए अनुकूलन महत्वपूर्ण है

6.20 यूएनडीपी के अनुसार[21], जलवायु परिवर्तन अनुकूलन से तात्पर्य उन कार्यों से है जो जलवायु के प्रति संवेदनशीलता को कम करने में मदद करते हैं परिवर्तन के वर्तमान या अपेक्षित प्रभाव, जैसे मौसम की चरम स्थितियां और खतरे, धीमी

15. विद्युत क्षेत्र पर एक नजर "अखिल भारतीय", विद्युत मंत्रालय, https://powermin.gov.in/sites/default/files/uploads/power_sector_at_glance_May_2024.pdf.

16. आईएसी,एनसी दस्तावेज का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय संचार, एनसी 3, भारत, (09 दिसंबर 2023), https://unfccc.int/documents/636235.

17. उक्त, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत प्रस्तुतीकरण।

18. कार्बन डाइऑक्साइड के गीगाग्राम का समतुल्य.

19. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम 2023. भारत में जलवायु निवेश के लिए मिश्रित वित्त। विश्व बैंक समूह, वाशिंगटन, डीसी। (2023), https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2023/Report-Blended-Finance-for-Climate-Investments-in-India.pdf.

20. राष्ट्रीय संचार, एनसी 3, भारत, (दिसंबर 09, 2023), https://unfccc.int/documents/636235.

21. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?, यूएनडीपी, (30 जनवरी, 2024) https://climatepromise.undp.org/news-and-stories/what-climate-change-adaptation-and-why-it-crucial

शुरुआत वाली घटनाएं जैसे समुद्र-स्तर में वृद्धि, जैव विविधता की हानिए या भोजन और पानी की असुरक्षा। निम्न-आय वाले देश जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं । रिचर्ड टोल (2024)[22] द्वारा कई अनुभवजन्य विकास अध्ययनों के मेटा-विश्लेषण के अनुसार, पूर्व-औद्योगिक समय की तुलना में 2.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग के कारण कल्याण-समतुल्य आय का नुकसान निम्न-आय वाले देशों के लिए काफी अधिक है। सपंदा एक बफर प्रदान करता है जो लचीले बुनियादी ढांचे, पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल कवरेज और अनुकूली प्रौद्योगिकियों तक पहुंच के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम कर सकता है, जिससे उच्च आय वाले देश बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं और गर्म होती जलवायु द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के अनुकूल हो सकते हैं। इसके विपरीत, निम्न-आय वाले देश जिन्हें अपनी विकास प्राथमिकताओं को प्राप्त करने की आवश्यकता है इसलिए, एक विकासशील देश के नजरिए से, निरंतर आर्थिक विकास जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सबसे अच्छा बीमा है ।

6.21 भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे संवेदनशील देशों में से एक है;[23] प्राकृतिक आवासों, वनस्पतियों और महत्वपूर्ण जैव संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए कृषि और संरक्षण प्रयासों में अनुकूलन रणनीतियों की अधिक आवश्यकता है। भारत सरकार ने इसका समाधान करने के लिए कई पहल की हैं। एनएपीसीसी में अधिकतर जोर अनुकूलन पर रहा है, जिसमें नौ में से सात मिशन इसे संबोधित करते हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना, रणनीतिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतवानी प्रणाली आदि के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और जलवायु भेद्यता के लिए भारतीय कृषि का लचीलापन बढ़ाने के लिए जलवायु लचीली कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) की शुरूआत इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण पहल हैं। भारत की अनुकूलन-प्रासंगिक कार्रवाई में स्वच्छ भारत मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना आदि जैसे विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में लचीलेपन में सुधार के लिए उठाए गए कदम भी शामिल हैं।

6.22 भारत के प्रारंभिक अनुकूलन संचार का अनुमान है कि 2021-2022 में अनुकूलन-संबंधित कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 5.60 प्रतिशत था, जो 2015-16 में 3.7 प्रतिशत की हिस्सेदारी से बढ़ रहा है, जो विकास योजनाओं में जलवायु लचीलापन और अनुकूलन के एकीकरण का संकेत देता है। यह सरकार द्वारा अनुकूलन कार्रवाई पर दिए जा रहे महत्व को दर्शाता है और साथ ही, घरेलू संसाधनों पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण दबाव को भी दर्शाता है। भारत में अनुकूलन वित्त प्रवाह में वृद्धि से संसाधन की कमी कम होगी और देश अपने दीर्घकालिक सतत विकास और आर्थिक विकास के उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगा।

6.23 भारत में तटीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। ऐसे क्षेत्रों में आर्द्रभूमि संरक्षण एक महत्वपूर्ण अनुकूलन उपाय हो सकता है। वे तूफानी लहरों और बाढ़ से बचाने के लिए एक बफर और अन्य मुकाबला करने की रणनीति प्रदान करते हैं। शहरी आर्द्रभूमि अतिरिक्त वर्षा को अवशोषित करने में मदद कर सकती है, जिससे शहरों की रक्षा होती है। इसके अलावा, मैंग्रोव एक प्राकृतिक तटीय अवरोध है जो तलछट को फँसाता है और तटीय कटाव को रोकता है, जो तटरेखा को मजबूत करता है। इसके अलावा, कई आर्द्रभूमि मत्स्य पालन, कृषि, पशुधन और ईंधन के उत्पादन का समर्थन करके स्थानीय समुदायों का जीवन निर्वाह करती हैं। वे खाद्य सुरक्षा मुद्दों के समाधान का एक हिस्सा हैं जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए, भारत ने आर्द्रभूमि और मैंग्रोव संरक्षण को प्राथमिकता के रूप में अपनाया है। 2014 से, देश भर में 56 नए आर्द्रभूमि को रामसर साइट (अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि) के रूप में नामित

22. टोल, आर.एस. (2024)। जलवायु परिवर्तन के कुल आर्थिक प्रभाव का मेटा-विश्लेषण। ऊर्जा नीति, 185, 113922, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421523005074.

23. 2019 में 10 सबसे अधिक प्रभावित देश, तालिका 1, पृष्ठ 8, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, https://www.germanwatch.org/en/19777 A

किया गया है, जिससे कुल संख्या 82 हो गई है और लगभग 1.33 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। भारत सरकार ने संरक्षित रामसर स्थलों में प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट घोषणा 2023 के हिस्से के रूप में 'अमृत धरोहर' पहल की घोषणा की, ताकि संरक्षण के मूल्य के लिए बेहतर प्रशंसा पैदा की जा सके और रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सके। मिशन सहभागिता, आर्द्रभूमि के सहभागी संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग की दिशा में एक और मील का पत्थर है, जो समुदायों को अग्रणी भूमिका में रखते हुए सामाजिक स्वामित्व दृष्टिकोण को सक्षम बनाता है। मिशन में आर्द्रभूमि स्वास्थ्य कार्ड तैयार करना, उपग्रह-आधारित डेटा के आधार पर आर्द्रभूमि की जमीनी सच्चाई का पता लगाना और इस कार्य में महिलाओं, युवाओं, स्थानीय समुदायों और निजी क्षेत्र को शामिल करके 'वेटलैंड मित्र' की अवधारणा को बढ़ावा देना शामिल है।

बॉक्स VI.1: सूक्ष्म सिंचाई पर केस स्टडी- समुदाय-नेतृत्व वाली जल प्रशासन की भूमिका [24]

नवानगर गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर तालुका में एक छोटा सा कृषि प्रधान गांव है । पिछले कुछ सालों में खेती के तरीकों की वजह से गांव का जलस्तर जमीन से 500-600 फीट नीचे चला गया है। 900 से 1100 मिलीग्राम/लीटर तक के कुल घुले हुए नमक (टीडीएस) ने पानी को खेती के लिए अनुपयुक्त बना दिया। इन कारणों से, खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा बन गई। किसान सिर्फ कपास और अरंडी जैसी एक पारंपरिक फसल ही उगा पाते थे। जल संसाधन विभाग, गुजरात और गुजरात हरित क्रांति कंपनी (जीजीआरसी) ने गुहाई बांध की नजदीकी उप-माइनर नहर से पानी खींचकर गांव के तालाब को फिर से जीवंत करने के लिए स्थानीय किसानों को संगठित किया।

'सोम सरोवर' के अंतर्गत गांव के किसानों की सहकारी समिति ने जल संचयन और संरक्षण के लिए ग्राम पंचायत की मदद से गांव के तालाब को गहरा किया। किसानों ने एक नाबदान (40 फीट व्यास गुणा 40 फीट गहराई) बनाया, गांव के तालाब से पानी खींचा, व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन लिया और नाबदान से पानी उठाने की सुविधाएं (पंप और मोटर) स्थापित कीं। किसानों ने बिजली कनेक्शन और पानी की पंपिंग/उठाने की पूरी लागत वहन की।

किसानों ने हौदी (संप) से अपने खेतों तक पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी की। किसानों के संगठन ने सभी सदस्य किसानों के लिए प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) के तहत पानी के कुशल उपयोग के लिए ड्रिप सिंचाई को अपनाना अनिवार्य कर दिया। तब से, कृषि उत्पादकता में पुनः परिवर्तन हुआ तथा 30 प्रतिशत की वृद्धि के साथ-साथ उर्वरक और बिजली की खपत में कमी और गेहूं, अरंडी, कपास आदि जैसी पारंपरिक फसलों से हटकर तरबूज, खरबूजा, सौंफ, जीरा और मिर्च जैसे फलों और सब्जियों की खेती के साथ पुनरुत्थान देखा गया है जो अधिक लाभदायक हैं। समुदाय द्वारा जल प्रशासन ने गांव को पानी की कमी से पानी की पर्याप्तता में बदल दिया, जिससे जल वितरण में समानता सुनिश्चित हुई।

24. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से प्राप्त इनपुट के आधार पर।

निम्न कार्बन विकास[25] और ऊर्जा संरचना

ऊर्जा संरचना और दक्षता

6.24 भारत की ऊर्जा जरूरतें 2047 तक 2 से 2.5 गुना बढ़ने की उम्मीद है, ताकि बढ़ती अर्थव्यवस्था की विकास संबंधी प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।[26] यह देखते हुए कि संसाधन सीमित हैं, ऊर्जा परिवर्तन की गति को जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने और सतत सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए संसाधनों पर वैकल्पिक मांगों को ध्यान में रखना होगा। 2070 तक नेट जीरो हासिल करने के लिए गैर-जीवाश्मों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ ऊर्जा स्रोतों के विविध मिश्रण में व्यवस्थित परिवर्तन और ऊर्जा उत्पादन और उपयोग दक्षता में वृद्धि की आवश्यकता है। देश के ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से शामिल करना भारत के स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के अभियान में सर्वोपरि है।

6.25 2022-23 में भारत का प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण जीवाश्म ईंधन पर आधारित था, जिसकी लगभग 84 प्रतिशत आपूर्ति कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस से की गई (चित्र 1)। तथापि, नवीकरणीय ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के कारण बिजली क्षेत्र में संरचना में काफी बदलाव आया है, जिसमें गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता की हिस्सेदारी अप्रैल 2014[27] के लगभग 32 प्रतिशत से मई 2024 तक 45.4 प्रतिशत हो जाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हाल की पहल उल्लेखनीय हैं। सबसे पहले, ₹75,021 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ शुरू की गई पीएम-सूर्य घर योजना से 30 गीगावॉट सौर क्षमता जुड़ने और 720 मिलियन टन CO_2 समकक्ष कम होने की उम्मीद है, जिससे सौर मूल्य श्रृंखला में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।[28] दूसरा, भारत की 7,600 किलोमीटर लंबी तट रेखा को देखते हुए, सरकार ने राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति को 2023 में अधिसूचित किया है।[29] इस क्षमता का दोहन करने के लिए कई अपतटीय क्षेत्रों की पहचान की गई है, और हाल ही में एक गीगावाट की प्रारंभिक क्षमता के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि की घोषणा की गई है।[30] तीसरा हाई-टू-एबेट सैक्टर में, कार्बन उत्सर्जन को कम करने में हरित हाइड्रोजन के महत्व को रेखांकित करते हुए, भारत के हरित हाइड्रोजन मिशन ने 2030 तक पांच एमएमटी हरित हाइड्रोजन का लक्ष्य रखा है।[31] यह योजना इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (एसआईजीएचटी) योजना के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के तहत हरित हाइड्रोजन उत्पादकों और इलेक्ट्रोलाइजर निर्माताओं के चयन के लिए निविदा कुल 4,12,000 टन की क्षमता के लिए प्रदान की गई है।[32]

6.26 भारत का महत्वाकांक्षी हरित हाइड्रोजन उत्पादन लक्ष्य में विभिन्न बाधाएं हैं, जिसमें आपूर्ति पक्ष – उत्पादन और वितरण की लागत, और मांग पक्ष – पारंपरिक औद्योगिक प्रक्रियाओं में हरित हाइड्रोजन का उपभोग करने की तत्परता

---

25. निम्न-कार्बन विकास को एक विकास रणनीति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास और बेहतर कल्याण सुनिश्चित करते हुए उत्सर्जन को कम करना है। यह आर्थिक विकास को प्राथमिकता देता है जबकि उत्सर्जन में कमी लाने वाली शमन कार्रवाइयां करता है।

26. नीति आयोग से प्राप्त इनपुट्स पर आधारित

27. 2014 का डेटा डवैच्च के ऊर्जा सांख्यिकी 2024 से लिया गया है, https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/EnergyStatistics_India_publication_2024N.pd

28. कैबिनेट ने पीएम-सूर्य घर को मंजूरी दी : मुफ्ती बिजली एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने की योजना , पीआईबी, (29 फरवरी, 2024), https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2010130.

29. ऑफशोर विंड एनर्जी लीज़ रूल्स, 2023, (19 दिसम्बर, 2023) https://tinyurl.com/5ssvpsk4

30. कैबिनेट ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दी, पीआईबी, (19 जून, 2024), https://pib.gov.in/PressReleasePage./aspx?PRID=2026699 -

31. राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन-भारत को कार्बन मुक्त करना, नेट-जीरो विजन हासिल करना, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पीआईबी, 10 जनवरी, 2023 को अद्यतन, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2023/jan/doc2023110150801.pdf

32. 4.12 लाख टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन और 1,500 मेगावाट प्रति वर्ष इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण के लिए निविदाएं प्रदान की गई: केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, पीआईबी, (07 फरवरी, 2024), https://tinyurl.com/mrñ6wzy3.

शामिल है। इनपुट के रूप में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइजर और नवीकरणीय ऊर्जा हरित हाइड्रोजन उत्पादन लागत के दो प्रमुख घटक हैं। पूंजी की लागत, जल आपूर्ति और शोधन, भंडारण और वितरण हाइड्रोजन को उपयुक्त व्युत्पन्न में बदलना, और एक सक्षम बुनियादी ढाँचा भी किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए हरित हाइड्रोजन की अंतिम वितरित लागत में योगदान देगा। चूंकि हरित हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को नवीकरणीय क्षेत्र की सभी सीमाएँ विरासत में मिलती हैं, जिसमें रुकावट का मुद्दा और सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक भूमि की बड़ी आवश्यकता शामिल है।

चार्ट VI.1: ईंधन स्रोतों के संदर्भ में 2022-23 में भारत का प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति मिश्रण और 2024 में स्थापित विद्युत क्षमता

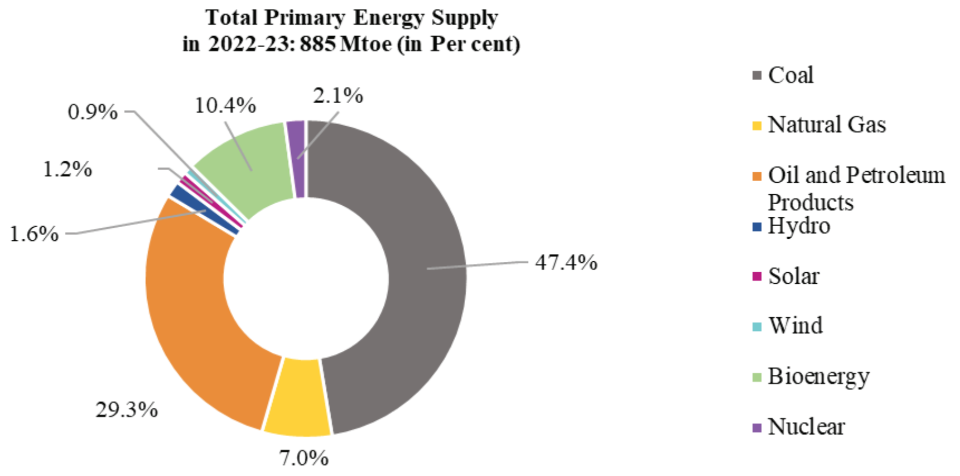

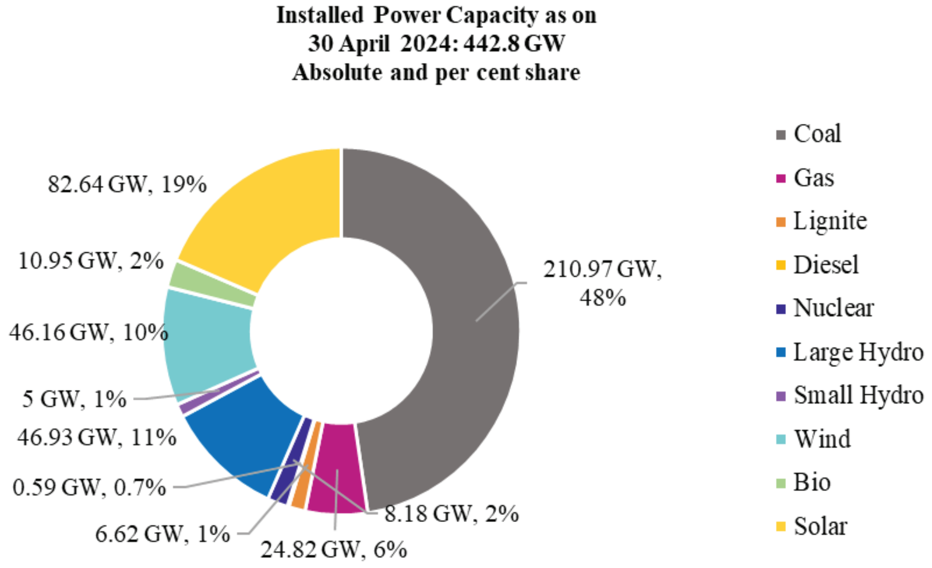

स्रोत: नीति आयोग और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्राप्त आंकड़े (ttps://cea.nic.in/instalyhbZMh&cap,lhity&report/?lang)

6.27 वर्तमान में, तीन विशिष्ट विशेषताएँ भारत के ऊर्जा उपयोग की विशेषता हैं - कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति के हिस्से के रूप में जैवभार (बायोमास) का उच्च उपयोग, जीवाश्म ईंधन (मुख्य रूप से पेट्रोलियम) के आयात की प्रध ानता और बिजली उत्पादन के लिए घरेलू कोयले का उपयोग। सौर छतों की स्थापना, सौर उपकरणों के प्रसारांश और

एलपीजी-आधारित कुकिंग के प्रसारांश के साथ बायोमास के उच्च उपयोग में महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है। पेट्रोलियम (जिसका 85 प्रतिशत आयात किया जाता है) की परिवहन, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों में विविध तापूर्ण उपस्थिति है, जो तेल की कीमतों में अस्थिरता और प्राकृतिक गैस की सीमित पहुँच को देखते हुए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है।

6.28 कुल बिजली उत्पादन में कोयले का योगदान लगभग 70 प्रतिशत है। यह स्टील, स्पॉन्ज आयरन, सीमेंट और कागज जैसे विभिन्न उद्योगों में भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जब कोयला एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत है, तब इस बदलाव पर ध्यान देना भले ही सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए प्रेरित कर रही हो, स्वच्छ कोयले और अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों की ओर एक क्रमिक आंदोलन की आवश्यकता है। सरकार ने कोयला गैसीकरण मिशन सहित कई स्वच्छ कोयला पहल शुरू की हैं। इसका लक्ष्य सतही कोयला/लग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के माध्यम से 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करना है। भारत में गैसीकरण तकनीक को अपनाने से कोयला क्षेत्र में क्रांति आ सकती है, जिससे उत्सर्जन को कम करते हुए प्राकृतिक गैस, मेथनॉल, अमोनिया और अन्य आवश्यक उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। कोल बेड मीथेन (सीबीएम) गैसों को निकालना, कोयले से हाइड्रोजन की खोज, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (सीसीएस), और वाशरी के माध्यम से कोयले का लाभकारीकरण आदि जैसी पहल उत्सर्जन को कम कर सकती हैं और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ा सकती हैं। कोयला विद्युत संयंत्रों के लिए अति-महत्वपूर्ण और अति-अति-महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों[33] को अपनाने के लिए प्रोत्साहन से उत्सर्जन में कमी आई है और दक्षता में वृद्धि हुई है।

चार्ट VI.2: 2017 में भारत में कुल 37,000 पेटाजूल (पीजे)[34] ऊर्जा प्रवाह

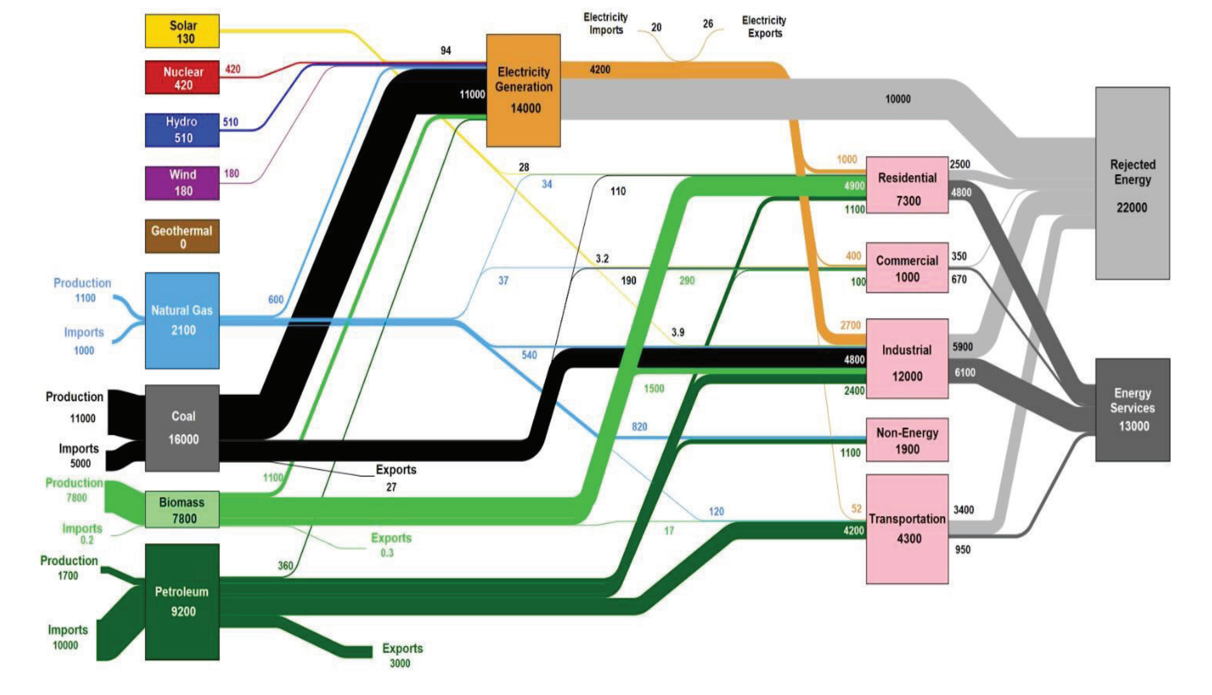

स्रोतः लॉरेंस लिवरमोर राष्ट्रीय प्रयोगशाला। https://flowcharts.llnl.gov/commodities/energy

33. ऐसे संयंत्र पानी के महत्वपूर्ण बिंदु (उस तापमान और दबाव से ऊपर जिस पर पानी के तरल और गैस चरण संतुलन में सह-अस्तित्व में रहते हैं) से ऊपर के तापमान और दबाव पर काम करते हैं। 10 अगस्त 2023 तक, 65150 मेगावाट की कुल क्षमता की 94 कोयला आधारित तापीय इकाइयाँ सुपर-क्रिटिकल/अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल तकनीकों के साथ काम कर रही हैं। [कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से हटाना और ताप विद्युत संयंत्रों में सुपर-क्रिटिकल तकनीकों को अपनाना, पीआईबी, (10 अगस्त, 2023) https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx-?PRID=1947384.)

34. 1 पेटाजूल = 1015 और 1 कैलोरी = 4.18 जूल।

6.29 नीति निर्माता ऊर्जा सुरक्षा का समर्थन करते हुए स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनों को गति देने में ऊर्जा दक्षता उपायों के महत्व को पहचानते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि पहले ग्लोबल स्टॉकटेक टेक (जीएसटी) का परिणाम 2030 तक ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को दोगुना करना है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित तरीके से और अलग-अलग राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाया जाएगा।[35] ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए देश द्वारा किए गए प्रयासों को बॉक्स 2 में प्रस्तुत किया गया है।

बॉक्स VI.2 ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए उठाए गए कदम[36]

भारत ने 2005 के आधार से 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता (ईआई) में 45 प्रतिशत की कमी लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसे प्राप्त करने के लिए, कुल उत्सर्जन को लगभग 4584 मिलियन टन CO_2 समतुल्य (MtCO2e) तक सीमित किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि एनडीसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था में कुल उत्सर्जन को 3753 MtCO2e (आधारभूत परिदृश्य पर) कम करना होगा। 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा दक्षता डोमेन के तहत क्षेत्रीय ब्योरा चित्र 3 में दिया गया है।

चित्र VI.3: 2030 तक एनडीसी प्रतिबद्धता को प्राप्त करने के लिए उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य (MtCO2e esa)

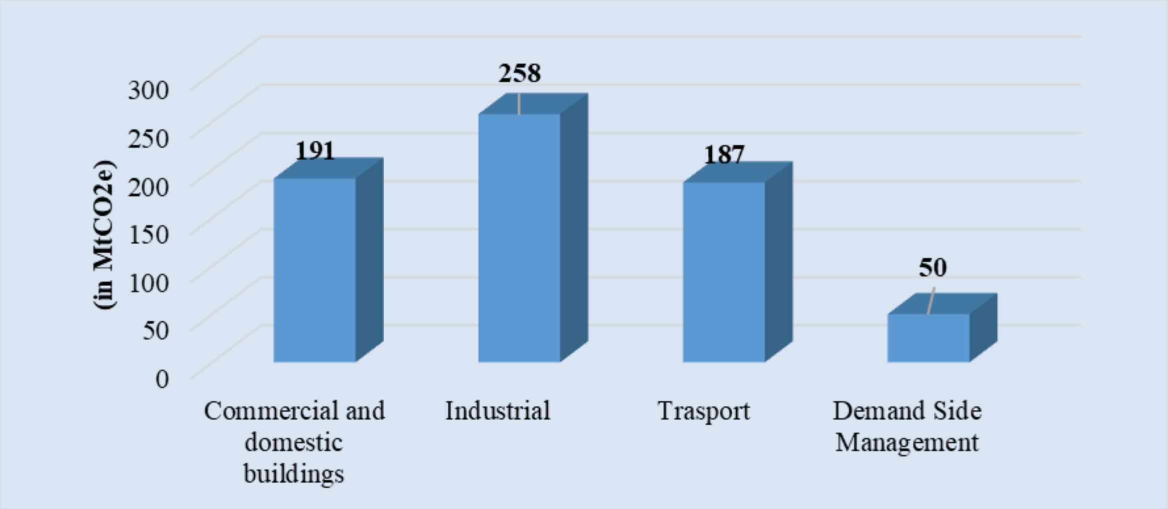

स्रोत: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित

इमारतों और उपकरणों में ऊर्जा दक्षता में सुधार भारत के लिए प्राथमिकता है क्योंकि 2030 तक 50 प्रतिशत से अधिक इमारतों का निर्माण होना बाकी है - यह स्थिति विकसित देशों[37] से मौलिक रूप से अलग है। भवन निर्माण क्षेत्र में उत्सर्जन तीव्रता में कमी लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वर्तमान में, कुल बिजली खपत का लगभग 33 प्रतिशत उपभोक्ताओं की वाणिज्यिक और आवासीय श्रेणियों में है, जिसके 2031-32 तक कुल बिजली खपत का लगभग 40 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन मानक निर्धारित करती है। मौजूदा वाणिज्यिक भवनों के लिए एक स्वैच्छिक स्टार रेटिंग कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। शून्य लेबलिंग कार्यक्रम नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग (एनजेडईबी) और नेट पॉजिटिव एनर्जी बिल्डिंग (एनपीईबी) की पहचान करता है और उनका

35. पैरा 28, निर्णय 1 सीएमए.5 (https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_16a01E.pdf\download)

36. विद्युत मंत्रालय से प्राप्त इनपुट्स पर आधारित।

37. ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, https://beeindia.gov.in/en/energy&conservation-building-code-ecbc.

स्मरण करता है। उपकरणों के लिए, मानक और लेबलिंग (एसएंडएल) कार्यक्रम शुरू किया गया था ताकि उपभोक्ताओं को व्यावसायिक रूप से बेचे जा रहे लेबलयुक्त यंत्रों/उपकरणों की ऊर्जा और लागत-बचत क्षमता के बारे में सूचनार्थक विकल्प प्रदान किया जा सके। बीईई की 2022-23 की प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अनुसारांश, एसएंडएल कार्यक्रम ने 81 बिलियन यूनिट बिजली बचाने में मदद की। सरकार ने उपभोक्ताओं को उच्च दक्षता वाले एसी प्रदान करने के लिए एक स्टार-रेटेड कार्यक्रम भी लागू किया है, और बीईई ने एक प्रोत्साहन-आधारित बाजार परिवर्तन कार्यक्रम तैयार किया है जो उपभोक्ताओं को आठ साल से पुराने एसी से 5-स्टार रेटेड मॉडल पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है।

नवंबर 2021 में ग्लासगो में सीओपी 26 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पर्यावरण के लिए जीवनशैली (लाइफ) पहल की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण क्षरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्थायी जीवन शैली को अपनाने को प्रोत्साहित करना है। भारत ने अपनी ऊर्जा संक्रमण रणनीति में कई नीतियों को एकीकृत किया है जो लाइफ के साथ संरेखित हैं।

ऊर्जा-सक्षम प्रथाओं को अपनाना लाइफ का मूल है।[38] घरेलू उपभोक्ता ऊर्जा-सक्षम उपकरणों और इमारतों, संधारणीय गतिशीलता और सद्गुणी ऊर्जा प्रबंधन को अपनाकर ऊर्जा दक्षता की व्यापक संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं। आईईए विश्लेषण के अनुसार, दुनिया भर में लाइफ क्रियाकलापों को अपनाने से – जिसमें व्यवहार में बदलाव और संधारणीय उपभोग विकल्प शामिल हैं – उपभोक्ताओं को लगभग 440 बिलियन अमरीकी डॉलर की बचत होगी और यह 2030 तक आवश्यक उत्सर्जन में कमी का पाँचवाँ हिस्सा होगा। 2030 तक मांग क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को आगे बढ़ाने के लिए G20 प्रेसीडेंसी की रणनीतिक योजना के दौरान भारत द्वारा रखे गए आधारों में व्यवहार और जीवनशैली में बदलाव भी शामिल हैं। ऊर्जा-कुशल जीवनशैली न केवल व्यक्तियों को लाभान्वित करती है, बल्कि सरकारों को ऊर्जा अवसंरचना में नए निवेश को कम करने या विलंबित करने में भी मदद करती है और देश में आवश्यक अन्य निवेशों में धन का उपयोग करने देती है।

भारत में, मिशन लाइफ को बीईई द्वारा तीन अलग-अलग चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है:

- लोगों को अपने दैनिक जीवन में सरल किन्तु प्रभावी ऊर्जा-बचत पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना,
- टिकाऊ उपभोग पैटर्न को पूरा करने के लिए उद्योगों और बाजारों को प्रभावित करना और
- बड़े पैमाने पर औद्योगिक और सरकारी नीतियों में बदलाव लाना, तथा टिकाऊ उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देना।

बीईई की दक्षता नीतियां व्यवहार परिवर्तन और उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने तक भी विस्तारित हैं। हाल ही में एयर कंडीशनर को 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट करने के अभियान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सचेत उपभोग को बढ़ावा दिया जाता है। एसी @ 24 अभियान उपभोग को अनुकूलित करने, कुशल प्रौद्योगिकियों पर स्विच करने, ऊर्जा-बचत व्यवहार में बदलाव और प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने पर आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करता है।

38. मिशन लाइफ का उद्देश्य लोगों के लिए एक जन आंदोलन का निर्माण करना है, ताकि वे अपने लिए, अपने परिवार और अपने समुदाय के लिए विचारशील उपयोग, न्यूनतम अपशिष्ट और हरित विकल्पों पर आधारित टिकाऊ जीवन शैली को अपना सकें।

औद्योगिक क्षेत्र के लिए, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना मांग प्रबंधन का एक और उपाय है जिसका उद्देश्य ऊर्जा-गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करना है। किसी विशेष चक्र के लिए, तंत्र में बेसलाइन वर्ष में विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) और लक्ष्य वर्ष में अनुमानित एसईसी का आकलन करना शामिल है। इसमें संयंत्र की सीमा में जाने वाली शुद्ध ऊर्जा और उससे निकलने वाले उत्पादों के विभिन्न रूपों को शामिल किया गया है। अब तक इस योजना के आठ चक्र शुरू किए जा चुके हैं। कार्रवाई के अगले स्तर के रूप में, विद्युत मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) शुरू की है।

परिवहन क्षेत्र के लिए, कारों, भारी-भरकम वाहनों (एचडीवी) और अन्य के लिए ईंधन खपत के मानक और मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बढ़ती संख्या को देखते हुए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 'इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर - दिशानिर्देश और मानक' अधिसूचित किए गए हैं।

मांग-पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) को पारंपरिक रूप से ऊर्जा की मांग को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में मान्यता दी गई है। यह एक बड़ी विडंबना है कि विकसित देश विकासशील दुनिया से संभावित उत्सर्जन को लेकर चिंतित हैं, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को व्यापक रूप से अपनाने से बिजली की मांग जो अमेरिका में दशकों में नहीं देखी गई स्तरों तक बढ़ने जा रही है।[39] ऊर्जा की मांग को नियंत्रित करने में विफलता और अनिच्छा और तथाकथित वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज - जीवाश्म ईंधन की तुलना में उनकी बहुत कम ऊर्जा घनत्व के साथ - वित्तीय और अन्य संसाधनों की अभूतपूर्व मांग और भू-राजनीतिक कमजोरियों और तनाव को बढ़ाती है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की विकृत प्राथमिकताओं को विकासशील दुनिया में वैध आर्थिक आकांक्षाओं की कीमत पर हासिल करने की कोशिश की जाती है।

भारत में, डीएसएम हस्तक्षेपों ने बिजली की चरम मांग को उपयोग करने और उसे कम करने तथा उत्पादन, संचरण और वितरण नेटवर्क में उच्च निवेश को टालने में मदद की है। दक्षता लाभ को सक्षम करने वाले उपाय मांग को कम करने का एक प्रभावी तरीका हो सकते हैं।[40] इनमें से कुछ उपायों में कृषि में ऊर्जा-दक्षता पंप सेट, स्थानीय निकायों की पेयजल और सीवेज जल पंपिंग प्रणालियों की दक्षता में सुधार, वितरण ट्रांसफार्मर नेटवर्क की दक्षता में सुधार और उपकरणों और घरेलू सामान की स्टार रेटिंग शामिल हैं।

उपरोक्त हस्तक्षेपों से काफी ऊर्जा बचत हुई है। कुल वार्षिक ऊर्जा बचत लगभग 51 मिलियन टन तेल के समतुल्य (एमटीओई) है - जो देश की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 6.6 प्रतिशत है। इसका अर्थ है लगभग ? 1,94,320 करोड़ की कुल वार्षिक लागत बचत और लगभग 306 मिलियन टन वार्षिक CO_2 उत्सर्जन में कमी। कार्यक्रम-विशिष्ट परिणाम इस प्रकार हैं: एसएंडएल योजना ने अब तक लगभग 60 $MtCO_2$ उत्सर्जन कम किया है, जबकि पीएटी योजना ने 110.7 $MtCO_2$ उत्सर्जन कम किया है, और ऊर्जा-कुशल लीईडी बल्बों ने 125 $MtCO_2$ की बचत की है।

ऊर्जा परिवर्तन की चुनौतियाँ

6.30 नवीकरणीय ऊर्जा में रुकावट और अनियमित आपूर्ति का सामना करना पड़ता है, जिससे बैटरी भंडारण की अनुपस्थिति में ग्रिड स्थिरता प्रभावित होती है। देश के 'विकसित भारत' के लक्ष्य के अनुरूप विकसित होने के साथ ऊर्जा

39. 'एआई, डेटा सेंटर और अमेरिका में बिजली की मांग में आने वाली बढ़ोतरी', गोल्डमैन सैक्स, 28 अप्रैल 2024

40. स्माइल, वी. (2014)। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वैश्विक परिवर्तन में कई दशक लगेंगे। साइंटिफिक अमेरिकन , 310 (1), 52-57।

की मांग में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है, और नवीकरणीय क्षमता में एक साथ वृद्धि से आपूर्ति संरचना में परिवर्तन के कारण बेस लोड दक्षता में गिरावट आ सकती है। नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर चरणबद्ध तरीके से उपयोग से ऊर्जा प्रणाली में रुकावट और प्रेषण क्षमता से जुड़े कई जोखिम पैदा होते हैं।[41] नवीकरणीय ऊर्जा के अधिक महत्वपूर्ण उपयोग के लिए इस मुद्दे का समाधान करना महत्वपूर्ण है।

6.31 कुछ अनुमानों से पता चलता है कि बिजली की स्तरीकृत लागत (एलसीओई)[42] भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इटली[43] सहित कई देशों में सौर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन की लागत जीवाश्म ईंधन से कम हो गई है। एक निवेशक के नजरिए से, एलसीओई एक कल्पित जीवनकाल में उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट संपत्ति के निर्माण और संचालन की कुल लागत को प्रस्तुत करता है। यदि एलसीओई बिजली शुल्क से कम है तो परियोजना में निवेश करना व्यवहार्य हो सकता है। तथापि, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एलसीओई में गिरावट आने के बावजूद, यह अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली कुल लागत को नहीं दर्शाता है। एलसीओई का मीट्रिक अंतरायिकता और प्रेषण क्षमता से जुड़ी लागतों को नजरअंदाज करता है। जब सूरज नहीं चमक रहा हो और हवा नहीं चल रही हो, तो नवीकरणीय ऊर्जा को एक स्थिर बिजली स्रोत द्वारा समर्थित होने की जरूरत होती है। यदि उत्पादक को बिजली को प्रेषण योग्य बनाने के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है, तो एलसीओई पर ऊर्जा खरीद उत्पादक के लिए अंतर्निहित अनुदान को दर्शाती है। इसे हल करने का एक तकनीक राउंड-द-क्लोक (आरटीसी) नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध है, जो अंतरायिकता और प्रेषण क्षमता से संबंधित जोखिमों के आंतरिकीकरण की अनुमति देता है।

बॉक्स VI.3: नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) की चौबीसों घंटे (आरटीसी) आपूर्ति

चौबीसों घंटे (आरटीसी) आपूर्ति का उद्देश्य ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से खरीदार की ऊर्जा मांग वक्र से मेल खाना है।

विद्युत मंत्रालय ने आरटीसी आपूर्ति के लिए विद्युत क्रय समझौतों (पीपीए) हेतु रूपरेखा प्रदान करने के लिए 2023 में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ ग्रिड से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से स्थिर और वितरण योग्य विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

हाल ही में हुई बोलियों के दौरान खोजे गए टैरिफ के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

- सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) के अनुसारांश अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) से जुड़ी सौर पीवी बिजली परियोजनाओं के लिए दरें 2.6 से 2.74 रुपये/प्रति किलोवाट घंटा थीं।[44] आईएसटीएस से जुड़ी पवन और सौर हाइब्रिड के लिए, यह दर 3.43 से 3.54 रुपये/प्रति किलोवाट घंटा थी।[45] आईएसटीएस से जुड़ी पवन ऊर्जा के लिए, यह 3.18 से 3.49 रुपये/प्रति किलोवाट घंटा थी।[46] आईएसटीएस से जुड़ी पवन-सौर हाइब्रिड बिजली परियोजनाओं के लिए यह दर 4.64 से 5.96 रुपये/प्रति किलोवाट घंटा थी, जिसमें अधिकतम बिजली आपूर्ति सुनिश्चित थी।[47]

41. जोखिम ऊर्जा प्रणाली की अपने आवश्यक कार्य - किफायती कीमतों और सामाजिक लागतों पर ऊर्जा की विश्वसनीय, स्थिर और टिकाऊ आपूर्ति - को पूरा करने में संभावित अक्षमता को दर्शाता है।

42. विद्युत की स्तरीकृत लागत (एलसीओई) एक जनरेटर के लिए उसके जीवनकाल में विद्युत उत्पादन की औसत शुद्ध वर्तमान लागत का माप है।

43. एम., चाइल्ड, एम., अघाहोसैनी , ए., बोगदानोव, डी., लोहरमन, ए., और ब्रेयर , सी. (2018)। 2015-2030 की अवधि के लिए जी20 देशों में नवीकरणीय, जीवाश्म ईंधन और परमाणु स्रोतों से बिजली उत्पादन लागत का तुलनात्मक विश्लेषण। जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन, 199, 687-704, https://www-sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652618321486.

44. 1500 मेगावाट आईएसटीएस-कनेक्टेड सौर पीवी पावर परियोजनाओं का चयन (एसईसीआई-आईएसटीएस-ग्प्ट), सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (18 जनवरी, 2024), https://www.seci.co.in/upload/Bidder/638532654344846316.pdf.

45. भारत में 1200 मेगावाट आईएसटीएस-कनेक्टेड पवन-सौर हाइब्रिड पावर परियोजनाओं का चयन (ट्रेंच-VIII), सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (20 फरवरी, 2024),https://www.seci.co.in/upload/Bidder/638545687623852290.pdf.

46. 1200 मेगावाट आईएसटीएस-कनेक्टेड पवन ऊर्जा परियोजनाओं का चयन (ट्रेंच-XIV), सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (20 फरवरी, 2023), https://www.seci.co.in/upload/Bidder/638233876572205236.pdf.

- रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आरईएमसीएल) की चौबीसों घंटे नवीकरणीय ऊर्जा की नीलामी से 4.25 से 4.43 रुपए प्रति/किलोवाट घंटा की दर तय हुई।[48]
- सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) लिमिटेड द्वारा की गई नीलामी के लिए सबसे कम बोली 4.38 रुपए/किलोवाट घंटा थी।[49]

उदाहरणों से पता चलता है कि आरटीसी परियोजनाओं के लिए टैरिफ, ऊर्जा भंडारण के बिना सौर और पवन परियोजनाओं के टैरिफ से अधिक है, जो कि अंतरायिक बिजली उत्पादन से संबंधित बाह्य प्रभावों के आंतरिककरण को दर्शाता है।

आरटीसी-आरई अभी प्रारंभिक अवस्था में है और इसकी तैनाती में कई चुनौतियां हैं।[50] जैसे कि उपयोगिताओं की गतिशील आवश्यकताएं और बढ़ती ऊर्जा मांगें, खासकर सौभाग्य योजनाए कृषि फीडर अलगाव, टाइम ऑफ डे (टीओडी) तंत्र, सौर छतों को बढ़ावा देने जैसी योजनाओं के संदर्भ में और उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं। इन तीव्र परिवर्तनों के कारण, वर्तमान मांग पैटर्न के लिए डिजाइन किए गए आरटीसी उत्पादों को बाद में संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है।

- कई राज्यों में फैली कई परियोजनाओं से सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को मिलाकर सबसे कम लागत वाला समाधान प्राप्त किया जा सकता है। तथापि, कई जनरेटर के साथ दीर्घकालिक पीपीए की व्यवस्था करना, कई स्थानों पर ट्रांसमिशन एक्सेस प्राप्त करना, तत्काल नियंत्रण के लिए रिमोट कंट्रोल सेंटर स्थापित करना आदि के मामले में यह एक चुनौती है।
- उच्च अग्रिम लागत, प्रौद्योगिकी जोखिम, लंबी भुगतान अवधि, और बैटरी भंडारण प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों तक सीमित पहुंच भी गंभीर चुनौतियां पैदा करती हैं। इस संदर्भ में, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की तुलना में उनके लंबे जीवनकाल के कारण, पंप भंडारण-आधारित ऊर्जा भंडारण समाधानों का उपयोग सिस्टम लागत को कम करने के लिए किया जा सकता है।

6.32 ग्लोबल नेट जीरो के लिए आवश्यक कई प्रौद्योगिकियां वर्तमान में व्यावसायिक रूप से अनुपलब्ध हैं, जैसे हाइड्रोजन-ईंधन वाले स्टील/सीमेंट, सीसीयूएस के साथ स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादन,आदि।[51] अनुसंधान एवं विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से वितरित नवीकरणीय ऊर्जा,[52] अपतटीय पवन, भूतापीय, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ईंधन, संपीड़ित बायोगैस, हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रोलाइजर और परमाणु ऊर्जा (छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) सहित) के क्षेत्र में।[53] ग्रिड स्थिरता और भंडारण के लिए ग्रिड संतुलन भी उतना ही आवश्यक है। अनुभव बताता है कि नवाचार प्रक्रिया को प्रोटोटाइप से व्यावसायीकरण तक 20 से 70 साल लगते हैं।[54] तथापि, अगले तीन दशकों के भीतर उत्सर्जन को शामिल करने की आवश्यकता को देखते हुए, इस नवाचार चक्र को आधा करने की आवश्यकता है।

---

47. भारत में सुनिश्चित पीक पावर सप्लाई के साथ 1200 मेगावाट आईएसटीएस-कनेक्टेड पवन-सौर हाइब्रिड पावर परियोजनाओं का चयन (ट्रेंच-टप), सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (02 नवंबर, 2022),https://www.seci.co.in/upload/bidder/638180388803848112.pdf.

48. आरईएमसीएल ने अपनी 750 मेगावाट नवीकरणीय परियोजनाओं के विजेताओं की घोषणा की, रिन्यूएबल वॉच, (2 फरवरी, 2024), https://renewablewatch.in/2024/02/02/remcl-declares-winners-of-its-750&mw-renewable-projects/-

49. संगीता शेट्टी, भारत की एसजेवीएन नीलामी परिणाम: भंडारण के साथ 1.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं मजबूत रुचि और प्रतिस्पर्धी टैरिफ आकर्षित करती हैं, (8 नवंबर , 2023), https://solarquarter.com/2023/11/08/indias-sjvn-auction-&results-1-5-gw-renewable-energy-projects-with-storage-draw-strong-interest-and-competitive-tariffs/

50. 2030 तक भारत के 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अक्षय ऊर्जा चौबीसों घंटे (आरई-आरटीसी) आपूर्ति का तकनीकी-आर्थिक विश्लेषण, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, (2024), https://cea.nic.in/wp-content/uploads/notification/2024/02/RE_RTC_Final_Report-pdf.

51. कार्बन कैप्चर, उपयोगिता और भंडारण (सीसीयूएस)।

52. वितरित नवीकरणीय ऊर्जा से तात्पर्य छोटे पैमाने की उत्पादन इकाइयों से है जो उपयोग के स्थानों के करीब स्थित होती हैं।

53. एसएमआर वर्तमान पीढ़ी के बेसलोड प्लांट (1,000 मेगावाट या उससे अधिक) की तुलना में छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र (300 मेगावाट या उससे कम) हैं। ये छोटे, कॉम्पैक्ट डिजाइन फैक्ट्री-निर्मित रिएक्टर हैं जिन्हें ट्रक या रेल द्वारा परमाणु ऊर्जा स्थल पर ले जाया जा सकता है। बड़ी क्षमता प्राप्त करने के लिए कई छोटी इकाइयाँ लगाकर एसएमआर आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे फैक्ट्री-निर्मित, भारत में निर्मित एसएमआर के साथ-साथ मध्यम आकार के 700 मेगावाट दबाव वाले भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) की सहक्रियात्मक तैनाती, जिन्हें मानकीकृत किया गया है और जिन्हें बेड़े मोड में तैनात किया जा रहा है, भारत में परमाणु ऊर्जा क्षमता के तेजी से विस्तार के लिए एक प्रासंगिक रणनीति हो सकती है।

6.33 नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन के विस्तार से भूमि और जल की मांग बढ़ेगी। जीवन के उच्च मानक को पूरा करने के लिए ऊर्जा की मांग में वृद्धि के भविष्य के परिदृश्यों का विश्लेषण तेजी से घटते भूमि और जल संसाधनों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भूमि-प्रधान हैं और विभिन्न ऊर्जा स्रोतों में से सबसे अधिक भूमि उपयोग आवश्यकताओं की मांग करते हैं। नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक स्केलिंग में कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें भूमि की बड़ी आवश्यकता भी शामिल है।[55] उदाहरण के लिए, एक अध्ययन के अनुसार[56], लगभग 1 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) के लिए लगभग 1-1.5 हेक्टेयर (एचए) भूमि की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए 60 गीगावाट सौर ऊर्जा के लिए अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 600-900 वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होगी। भूमि की उपलब्धता भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसकी प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता जी20 देशों में सबसे कम है (चित्र 4)। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता में अपेक्षित वृद्धि के साथ संक्रमण लागत बढ़ जाएगी।

चार्ट VI.4: भारत में प्रति व्यक्ति भूमि जी-20, 2021 में सबसे कम है

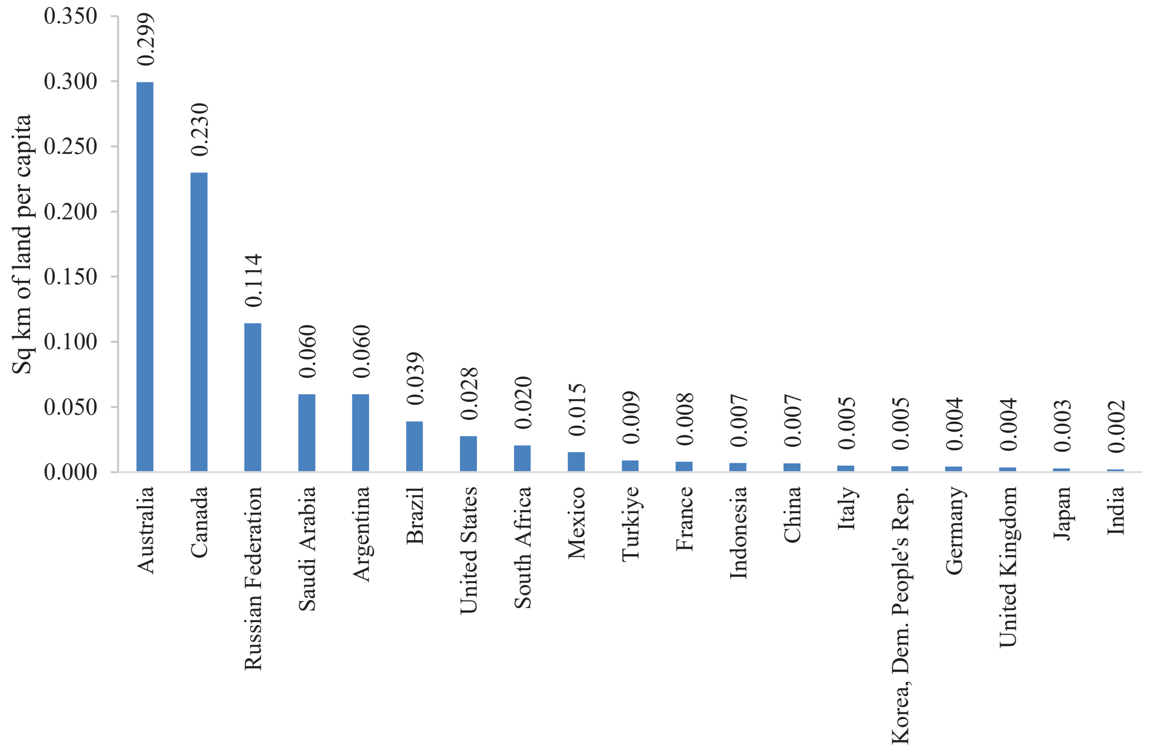

स्रोत: विश्व बैंक के आंकड़ों का उपयोग करके गणना की गई।
नोट: प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर भूमि प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में रहने वाले लोगों के व्युत्क्रम के बराबर है। जनसंख्या घनत्व विश्व बैंक (ttps://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.DNSt~) से लिया गया है।

54. ग्रॉस, आर., हन्ना, आर., गंभीर, ए., हेप्टनस्टॉल, पी., और स्पीयर्स, जे. (2018)। ऊर्जा क्षेत्रों में नवाचार और व्यावसायीकरण में कितना समय लगता है? ऊर्जा आपूर्ति और अंतिम उपयोग प्रौद्योगिकी में आविष्कार से लेकर व्यापक व्यावसायीकरण तक के समय के ऐतिहासिक केस स्टडीज। ऊर्जा नीति, 123, 682-699, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421518305901.

55. https://psa.gov.in/CMS/web/sites/default/files/publication/ESN%20Report-2024_New-21032024.pdf

56. उक्त.

6.34 नवीकरणीय अपशिष्ट पुनर्चक्रण एक और चुनौती है। वैश्विक स्तर पर, सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) अपशिष्ट 2050 तक 78 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है।[57,58] सौर पीवी पैनलों का जीवनकाल 25-30 वर्ष होता है, जिसके बाद फेंकी गई सामग्री या तो लैंडफिल में चली जाती है या फिर उसे रीसाइकिल किया जाता है। लैंडफिल में जाने वाला पहला रास्ता पुनर्चक्रण की तुलना में उल्लेखनीय रूप से सस्ता है। हालांकि इसके कारण मिट्टी में हानिकारक रसायनों और भारी धातुओं के अंश निर्धारित हो सकते हैं। स्क्रैप के रूप में पुनर्चक्रित पीवी अपशिष्ट विषाक्त धातुओं के कारण पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करता है, जिसके लिए हमें पीवी अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक व्यापक नीति की आवश्यकता है। भारत के संशोधित ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022[59], निपटान प्रथाओं के बारे में चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। तथापि, पैमाने द्वारा लगाई गई चुनौती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

6.35 नवीकरणीय ऊर्जा और बैटरी भंडराण प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता होती है। ऐसे खनिजों का स्रोत भौगोलिक रूप से केंद्रित है, विशेष रूप से ग्रेफाइट (चीन, 79 प्रतिशत), कोबाल्ट (डीआरसीए 70 प्रतिशत), दुर्लभ भूमि (चीन, 60 प्रतिशत) और लिथियम (ऑस्ट्रेलिया, 55 प्रतिशत)। प्रसंस्करण के लिए सांद्रता का स्तर और भी अधिक है, जिसमें चीन हर जगह हावी है। घरेलू क्षमता निर्माण की भारत की पहल को नवीकरणीय ऊर्जा की वर्तमान आपूर्ति श्रृंखला की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए, जो काफी विषम है। बॉक्स 4 में चर्चा की गई है कि महत्वपूर्ण और दुर्लभ मृदा खनिजों की भौगोलिक सांद्रता कैसे बढ़ रही है और इससे क्या जोखिम पैदा होते हैं। भारत हरित संक्रमण को सुचारू बनाने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच को सक्षम करने के लिए खनिज सुरक्षा भागीदारी (एमएसपी) में शामिल हुआ है । एमएलपी में 14 देश शामिल हैं जिसमें भारत एकमात्र विकासशील देश है। सरकार ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची भी जारी की है। महत्वपूर्ण खनिजों पर आधारित परियोजनाओं की कुल संख्या 2020 में 59 से बढ़कर 2023 में 123 हो गई।

6.36 इसके अलावा, खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल)[60] ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अर्जेंटीना जैसे खनिज समृद्ध देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी जी2जी साझेदारी का निर्माण करके, व्यापारिक अवसरों और रणनीतिक अधिग्रहणों या अन्वेषण और खनन में निवेश करके विदेशों में रणनीतिक खनिजों की पहचान, अधिग्रहण, अन्वेषण, विकास, खनन और प्रसंस्करण का कार्य करता है।[61]

बॉक्स VI.4: महत्वपूर्ण और दुर्लभ मृदा खनिजों का भौगोलिक संकेन्द्रण

आईईए के ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स आउटलुक 2024[62] में महत्वपूर्ण और दुर्लभ मृदा खनिजों की भौगोलिक सांद्रता में भारी उछाल को दर्शाया गया है (चित्र 5)। परिष्कृत सामग्रियों के मामले में, शीर्ष तीन उत्पादक देशों की हिस्सेदारी 2020 से बढ़ी है जैसा कि चित्र 6 में देखा जा सकता है। इसके अलावा, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई) सभी प्रमुख ऊर्जा संक्रमण खनिजों में भौगोलिक रूप से सबसे कम विविधता

57. यह 2050 में वैश्विक संचयी पी.वी. क्षमता 4,500 गीगावाट होने के लिए IRENA के अनुमान के अनुरूप है।

58. आईआरईएनए और आईईए-पीवीपीएस (2016), ष्एंड-ऑफ-लाइफ मैनेजमेंट: सोलर फोटोवोल्टिक पैनल,ष् अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी फोटोवोल्टिक पावर सिस्टम। https%@@www-irena-org@publications@2016@Jun@End&of&ykbiQ&management&Solar&Photovoltaic&Panels -

59. ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022, https://cpcb.nic.in/uploads/Projects/E-Waste/e-waste_rules_2022.pdf.

60. केएबीआईएल नाल्को, एचसीएल और एमईसीएल के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसका लक्ष्य भारत में आपूर्ति के लिए विदेशी स्थानों में रणनीतिक खनिजों की पहचान, अधिग्रहण, विकास, प्रसंस्करण और उनका व्यावसायिक उपयोग करना है। काबिल लिथियम और कोबाल्ट जैसे बैटरी खनि. जों की पहचान और सोर्सिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना में कुछ कंपनियों/परियोजनाओं के साथ जुड़ाव चल रहा है। [https://mines.gov.in/webportal/content/kabil]

61. महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केएबीआईएल की स्थापना की गई, पीआईबी, (01 अगस्त, 2019), https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1581058

62. आईईए (2024), ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स आउटलुक 2024, आईईए, पेरिस, https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2024.

वाले हैं। इनसे बने मैग्नेट का उपयोग ईवी और पवन टरबाइन मोटर्स में ऑटोमोटिव ट्रैक्शन मोटर्स के लिए उच्च ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने में किया जाता है। आईईए के अनुमानों के अनुसार ये भविष्य में भौगोलिक रूप से और भी अधिक केंद्रित हो जाएँगे (चित्र 7)। इस बीच, 2023 में अयस्कों के साथ-साथ उनके प्रसंस्करण के लिए प्रौद्योगिकियों पर व्यापार प्रतिबंध उपायों का प्रसारांश भी देखा गया, जिसका सौर पीवी, पवन टर्बाइन, ईवी और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता और पहुँच पर प्रभाव पड़ता है। खनन और प्रसंस्करण में दुर्लभ मृदा और उल्लेखनीय खनिजों की यह सांद्रता भारत सहित अधिकांश देशों के लिए नवीकरणीय और ईवी महत्वाकांक्षाओं के उपयोग पर एक महत्वपूर्ण बाधा है।

चार्ट VI.5: महत्वपूर्ण खनिज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का भौगोलिक वितरण, 2023[63]

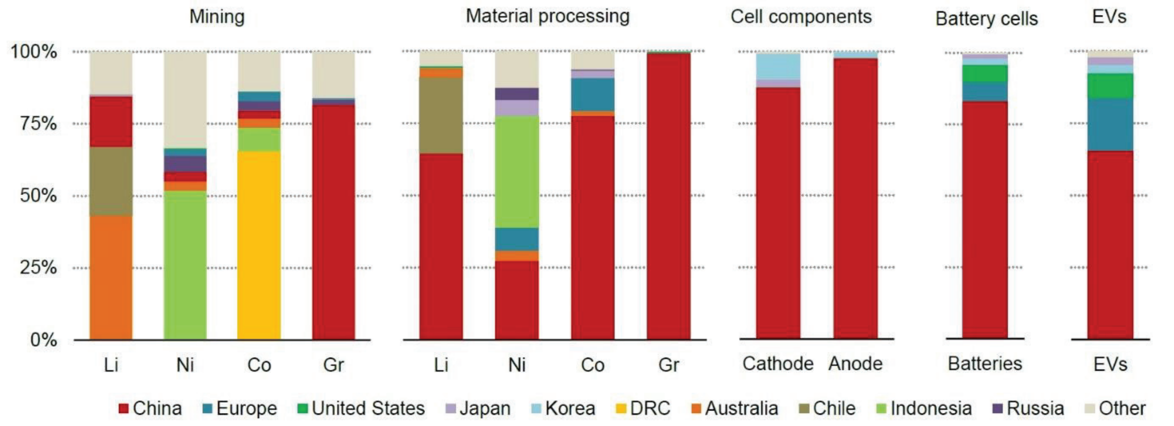

स्रोत: आईईए का ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स आउटलुक 2024

चार्ट VI.6: 2020 और 2023 में देश द्वारा परिष्कृत सामग्री उत्पादन का हिस्सा

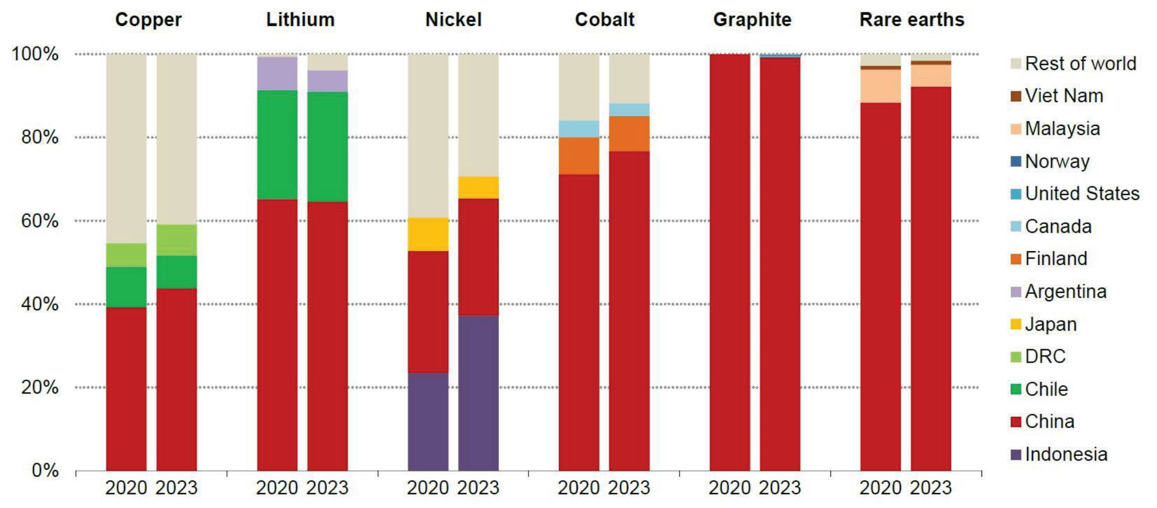

स्रोत: आईईए का ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स आउटलुक 2024

63. टिप्पणियाँ: Li = लिथियम; Ni = निकल; Co = कोबाल्ट; Gr = ग्रेफाइट; DRC = कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। भौगोलिक विखंडन उस देश को संदर्भित करता है जहाँ उत्पादन होता है। खनन उत्पादन डेटा पर आधारित है। सामग्री प्रसंस्करण शोधन उत्पादन डेटा पर आधारित है। सेल घटक उत्पादन कैथोड और एनोड सामग्री उत्पादन क्षमता डेटा पर आधारित है। बैटरी सेल बैटरी सेल उत्पादन क्षमता डेटा पर आधारित हैं। इलेक्ट्रिक कारों के उत्पादन डेटा पर आधारित ईवी। सभी खनिजों के लिए खनन और शोधन कुल उत्पादन को दर्शाता है न कि केवल ईवी में उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट शोधन केवल गोलाकार ग्रेफाइट उत्पादन को संदर्भित करता है।

चार्ट VI.7: पिछले कुछ वर्षों में मैग्नेट रेयर अर्थ्स का भौगोलिक संकेन्द्रण[64]

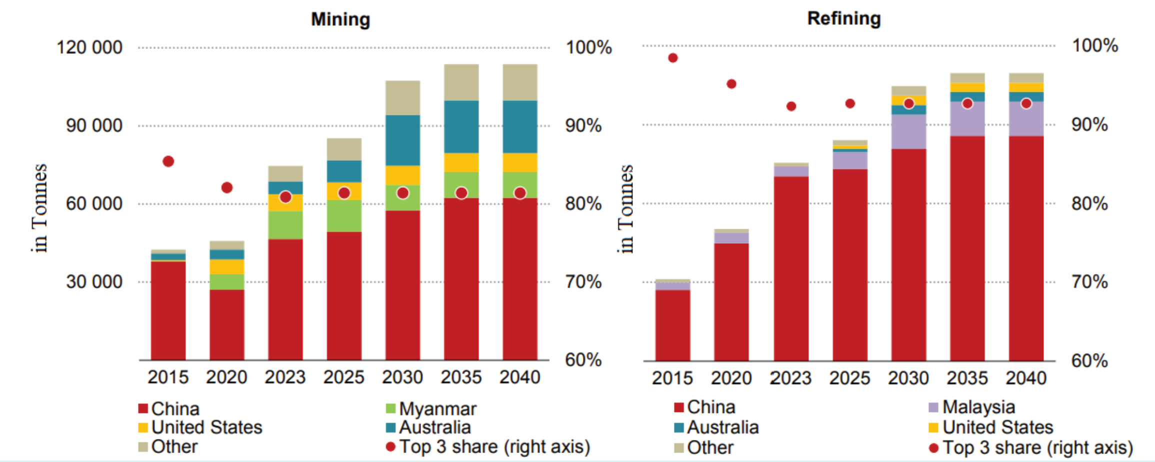

स्रोत: आईईए का ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स आउटलुक 2024

6.37 प्रौद्योगिकी और कच्चे माल तक पहुँच से जुड़े जोखिमों के अलावा, किफायती वित्त की उपलब्धता और पहुँच यकीनन भारत के कम कार्बन पथ के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। नेट जीरो घोषणा के साथ संरेखित करने के लिए भारत की ऊर्जा प्रणाली के परिवर्तन के लिए वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में कई अनुमान हैं। वे सभी एक तथ्य की ओर इशारा करते हैं - आवश्यकताएँ ट्रिलियन के क्रम की हैं। नीति (एनआईटीआई) के आईईएसएस 2047 मॉडल के अनुसार 2047 तक भारत की कुल निवेश लागत नेट-जीरो मार्गों के लिए अपनी ऊर्जा प्रणालियों को तैयार करने के लिए प्रति वर्ष ~ 250 बिलियन अमरीकी डॉलर अनुमानित है।

बॉक्स VI.5: भारत के लिए संभावित नेट-जीरो की ओर ऊर्जा संक्रमण को समन्वित करने पर रिपोर्ट: सभी के लिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा

भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के सहयोग से 'भारत के लिए संभावित नेट जीरो की ओर ऊर्जा संक्रमण को समन्वित करना: सभी के लिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा' शीर्षक से एक अध्ययन किया गया। इस रिपोर्ट में भारत की नेट जीरो 2070 घोषणाओं और सभी के लिए स्वच्छ, सस्ती ऊर्जा की पृष्ठभूमि में ऊर्जा मिश्रण के अनुमान शामिल है। रिपोर्ट में विभिन्न विकास और जलवायु प्रतिबद्धता परिदृश्यों में 2030, 2050 और 2070 के लिए अनुमानित भविष्य की ऊर्जा प्रणाली प्रस्तुत की गई है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

1. सतत् ऊर्जा परिवर्तन के लिए कई ऊर्जा स्रोतों का सह-अस्तित्व आवश्यक है।
2. अनुमान है कि कोयला अगले दो दशकों तक भारतीय ऊर्जा प्रणाली की रीढ़ बना रहेगा। यद्यपि, कोयले के इस्तेमाल से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल तकनीक (सीडीआर), जैसे कि बायोएनर्जी विद CO_2 कैप्चर एंड स्टोरेज (बीईसीसीएस) और सीसीयूएस जैसी तकनीकों की खोज की जानी चाहिए। तथापि, बिजली संयंत्रों में बीईसीसीएस/सीसीयूएस को लागू करने से होने वाले एनर्जी पेनाल्टी[65] की बारीकी से जांच की जानी चाहिए।

64. नोट: बैटरी ग्रेड के लिए ग्रेफाइट गोलाकार ग्रेफाइट पर आधारित है। दुर्लभ पृथ्वी चुंबक दुर्लभ पृथ्वी हैं।
65. ऊर्जा एनर्जी पेनाल्टी वह ऊर्जा की सीमा है जो सीसीयूएस प्रौद्योगिकियों को शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

3. ऐसा अनुमान है कि 2070 तक नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) और परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होंगे।
4. कोयले के उपयोग में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा और बैटरी भंडारण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहेगी, जब तक कि देश घरेलू स्तर पर उपलब्ध खनिज संसाधनों पर आधारित प्रौद्योगिकियों के विकास में निवेश नहीं करता है, तथा ऐसी प्रौद्योगिकियों के विकास में निवेश नहीं करता है जो महत्वपूर्ण खनिजों के पुन: उपयोग, पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण को संभव बनाती हैं।

सतत विकास के लिए वित्त

6.38 देश ने कारोबारी वातावरण को बेहतर बनाने और संसाधनों के अधिक मात्रा में जुटाव को उत्प्रेरित करने के लिए कई उपाय किए हैं। 2022 में जारी 'सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लिए रूपरेखा' ने हरित परियोजनाओं के लिए विविध निवेशकों से संसाधन जुटाने में सक्षम बनाया है जिससे बॉन्ड मार्केट को और मजबूत बनाया है। नॉर्वे स्थित सेकेंड पार्टी ओपिनियन प्रदाता सीआईसीईआरओ द्वारा फ्रेमवर्क को 'मध्यम ग्रीन' रेटिंग दी गई है, जिसमें 'गुड' गवर्नेंस स्कोर दिया गया है, जो भारत की विश्वसनीयता और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की तत्परता को दर्शाता है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए आय जुटाने हेतु जनवरी-फरवरी 2023 में ₹16,000 करोड़ की राशि के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने का बीड़ा उठाया, जो अर्थव्यवस्था के उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने के प्रयासों में योगदान देगी, इसके बाद अक्टूबर-दिसंबर 2023 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से ₹20,000 करोड़ जुटाए गए।

6.39 सेबी सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए स्थिरता रिपोर्टिंग को अपनाने वाले शुरुआती संस्थाओं में से एक रहा है और इसने 2012 से शीर्ष 100 सूचीबद्ध संस्थाओं (बाजार पूंजीकरण के हिसाब से) के लिए अनिवार्य ईएसजी-संबंधी खुलासे की आवश्यकता बताई है। पिछले कुछ वर्षों में, सेबी ने शीर्ष 500 और तथा उसके बाद शीर्ष 1000 संस्थाओं को कवर करने के लिए रिपोर्टिंग को मजबूत किया है। सेबी ने व्यवसाय उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) के तहत नई स्थिरता रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ जारी की हैं, जो 'जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश' में निहित सिद्धांतों के अनुरूप मात्रात्मक मीट्रिक के साथ अधिक विस्तृत हैं। 2022-23 से शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं (बाजार पूंजीकरण के हिसाब से) के लिए बीआरएसआर अनिवार्य था। जुलाई 2023 में, सेबी ने मूल्य श्रृंखलाओं के लिए ईएसजी खुलासे के लिए बीआरएसआर कोर भी पेश किया। वर्ष 2024-25 से, प्रकटीकरण की आवश्यकताएं शीर्ष 250 सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होंगी और वर्ष 2026-27 तक चरणबद्ध तरीके से 1000 शीर्ष-सूचीबद्ध संस्थाओं तक विस्तारित की जाएंगी। मूल्य श्रृंखला में सूचीबद्ध इकाई के शीर्ष अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम भागीदार शामिल होंगे, जो क्रमश: इसकी खरीद/बिक्री (मूल्य के अनुसारांश) का 75 प्रतिशत हिस्सा शामिल करेंगे। बीआरएसआर कोर बीआरएसआर का एक उप-समूह है, जिसमें विशिष्ट ईएसजी विशेषताओं के तहत प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई)/मीट्रिक का एक सेट शामिल है।[66]

6.40 आरबीआई ने देश में ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए विनियमित संस्थाओं के लिए ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति हेतु फ्रेमवर्क लागू किया है। इसके अलावा, आरबीआई अपने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) नियमों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देता है। आरबीआई द्वारा अधिसूचित पीएसएल नियम नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और कतिपय शमन परियोजनाओं के लिए रियायती ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। इसमें, उदाहरण के लिए, सौर-आधारित बिजली जनरेटर, बायोमास-आधारित बिजली जनरेटर, पवन चक्कियाँ और माइक्रो-हाइड्रल प्लांट जैसे उद्देश्यों के लिए उधारकर्ताओं को 30 करोड़ ₹ की सीमा तक के बैंक ऋण शामिल हैं। गैर-पारंपरिक ऊर्जा-आधारित सार्वजनिक उपयोगिताएँ, जैसे कि स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम और दूरदराज के गाँवों का विद्युतीकरण, अधिसूचना के अनुसारांश प्राथमिकता क्षेत्र वर्गीकरण के लिए भी पात्र हैं।

66. मूल्य श्रृंखला के लिए आश्वासन और ईएसजी प्रकटनों के लिए बीआरएसआर कोर-फ्रेमवर्क, सेबी, https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/jul-2023/brsr-core-framework-for-assurance-and-esg-disclosures-for-value-chain_73854.html

कार्बन की कीमत तय करने के लिए बाजार ढांचा तैयार करना: भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम)

6.41 कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस), जिसे भारतीय कार्बन बाजार भी कहा जाता है, पर विनियमन 28 जून 2023 को विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए थे। सीसीटीएस का उद्देश्य एक टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन के लिए मूल्य निर्धारण की अनुमति देना है, जो एक बाध्य इकाई को उस संसाधन की लागत को ध्यान में रखने के लिए प्रोत्साहित करता है जिसकी कीमत पहले निर्धारित नहीं की गई थी, जिससे वैकल्पिक कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। सीसीटीएस मौजूदा पीएटी योजना को समाहित कर लेगा, जहां पीएटी योजना के तहत नामित उपभोक्ता (डीसी) 2028-30 तक धीरे-धीरे सीसीटीएस में परिवर्तित हो जाएंगे। सीसीटीएस के तहत, केंद्र सरकार मौजूदा पीएटी योजना के तहत विशिष्ट ऊर्जा खपत लक्ष्यों के स्थान पर निर्गत उत्सर्जन सीमा (यानी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य) को सक्षम करने के लिए इकाई-वार ग्रीन हाउस गैस/ग्रीन गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य निर्धारित करेगी। प्रमुख संस्थान और हितधारक जो आईसीएम की निगरानी, कार्यान्वयन और मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, वे इस प्रकार हैं (तालिका 1):

तालिका VI.1: भारत में कार्बन बाजार की संस्थागत संरचना

कार्य	संस्थान
शासन, निगरानी और कार्यप्रणाली	भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति
नीति एवं प्रशासक	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
लक्ष्यों का कार्यान्वयनकर्ता	बाध्य इकाई
व्यापार नियामक	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग
रजिस्ट्री	ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (जीसीआईएल)
व्यापार मंच	पावर एक्सचेंज आईएक्स, पीएक्सआईएल, एचपीएक्स

6.42 सीसीटीएस एक अनुपालन तंत्र की परिकल्पना करता है जिसके माध्यम से तंत्र के तहत अधिसूचित पंजीकृत संस्थाओं, जिन्हें बाध्य संस्थाएं (ओई) कहा जाता है, को प्रक्षेपवक्र अवधि (जिसे अनुपालन वर्ष कहा जाता है) में प्रत्येक वार्षिक वर्ष के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों की अधिसूचना दी जाएगी। प्रक्षेपवक्र अवधि के पूरा होने पर, लक्ष्यों को बाद की अवधि के लिए संशोधित किया जाएगा। बाध्य संस्थाओं को अनुपालन चक्र के पूरा होने से नौ महीने के भीतर सत्यापन और व्यापार प्रक्रिया के बाद निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन करना और अनुपालन स्थिति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अधिसूचित लक्ष्य से अधिक हासिल करने के लिए बाध्य संस्था वास्तविक और लक्ष्य के बीच के अंतर से कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र (सीसीसी) जारी करवा सकती है । इन सीसीसी को कार्बन बाजार में बेचा जा सकता है या अनुपालन वर्ष पूरा होने पर बाध्य संस्था द्वारा बैंक में रखा जा सकता है। इन बैंक में रखे गए सीसीसी को बेचा जा सकता है या आगामी वर्षों में अनुपालन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। लक्ष्यों को पूरा करने में किल बाध्य इकाई को भारतीय कार्बन बाजार में सीसीसी खरीदने होंगे या अनुपालन के लिए उनके बैंक में रखे गए सीसीसी का प्रयोग करना होगा।

स्वैच्छिक कार्बन बाजार (वीसीएम)

6.43 कार्बन बाजार सरकारों या अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा संचालित और विनियमित अनुपालन बाजार हो सकते हैं, जिसमें विशिष्ट उद्योगों को भाग लेने की आवश्यकता होती है (अनुपालन बाजार), या स्वैच्छिक कार्बन बाजार हो सकते हैं - जो सरकारों द्वारा विनियमित नहीं होते हैं और पूरी तरह से स्वैच्छिक होते हैं। वैश्विक स्वैच्छिक कार्बन बाजार का मूल्य 1.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है, और भारत कार्बन ऑफसेट का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।

6.44 वीसीएम संस्थाओं को अन्यत्र परियोजनाओं में या अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त उत्सर्जन में कमी/हटाने/बचने के माध्यम से अपने उत्सर्जन की भरपाई करने की अनुमति देता है – एक प्रक्रिया जिसे 'कार्बन ऑफसेटिंग' कहा जाता है। ऑफसेट क्रेडिट का खरीदार अपने स्वयं के उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों के लिए अंतर्निहित कमी का दावा करने के लिए ऑफसेट को रोक सकता है। तथापि, वीसीएम में दोहरी गणना के बारे में चिंताएं हैं जब विक्रेता और खरीदार कार्बन कटौती का दावा कर सकते हैं। इस बारे में भी अनिश्चितता है कि क्या किसी विदेशी संस्था द्वारा ऑफसेट के रूप में उपयोग किए जा रहे क्रेडिट का दावा किसी ऐसे देश द्वारा जहां क्रेडिट का सृजन हुआ है अपने उत्सर्जन में कमी के विरुद्ध के लिए किया जा सकता है। भारत की महत्वाकांक्षी एनडीसी और नेट जीरो घोषणा के साथ, विदेशी संस्थाओं को बेचे जाने वाले कार्बन क्रेडिट भारत के उत्सर्जन में कमी को और अधिक महंगा और कठिन बना देंगे।

बॉक्स VI.6 : कार्बन बाजारों का विकास

वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने और पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए पहले बाजार-आधारित विनियमन के अस्तित्व का पता 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) अनुमति व्यापार कार्यक्रम से लगाया जा सकता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) ने ओजोन क्षरण की समस्या का समाधान करने के लिए उत्सर्जन परमिट के व्यापार के लिए एक प्रारंभिक अंतरराष्ट्रीय मिसाल के रूप में कार्य किया। यूएनएफसीसीसी (कन्वेंशन) के अनुच्छेद 4.2 (क) ने पार्टियों को संयुक्त रूप से उत्सर्जन में कमी की नीतियों को लागू करने की अनुमति देकर शुरुआती कार्बन बाजारों की नींव रखी।

यूएनएफसीसीसी के पक्षों के सम्मेलन या सीओपी ने इस संबंध में 1997 में एक कानूनी लिखत – क्योटो प्रोटोकॉल (केपी) को अपनाया। केपी ने 38 औद्योगिक देशों और संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाओं (ईआईटी) के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी जीएचजी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित किए – केपी के Annex B। केपी के तहत बाजार आधारित तंत्र ने पक्षों को अन्य पक्षों से खरीदी गई 'क्योटो इकाइयों' के साथ अपने क्योटो कैप का हिस्सा पूरा करने की अनुमति दी। इसमें तीन तंत्र थे – (i) स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) से वाले विकासशील देशों में शमन परियोजनाओं से प्रमाणित उत्सर्जन में कमी (सीईआर) लाना[67], (ii) उत्सर्जन सीमा वाले देशों में परियोजनाओं द्वारा प्राप्त उत्सर्जन में कमी इकाइयों (ईआरयू) का निर्माण करके संयुक्त कार्यान्वयन, (iii) अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार (आईईटी) ने उत्सर्जन सीमा वाले देशों के बीच निर्दिष्ट राशि इकाईयों (एएयू) और अन्य क्योटो इकाईयों के व्यापार को सक्षम बनाया। इन तंत्रों ने अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार में पहली बार किए गए प्रयास की नींव रखी, यद्यपि इसके शुरुआती कार्यान्वयन में सीमित भागीदारी और जटिल नियमों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तथापि, 2005 में यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार योजना (ईयू-ईटीएस) के प्रारंभ के बाद, कार्बन बाजार के महत्व को पहली बार महसूस किया गया। 2000 के दशक के मध्य में ईयू-ईटीएस ने काम करना शुरू किया और स्वैच्छिक कार्बन बाजारों ने गति पकड़नी शुरू कर दी। ईयू-ईटीएस के साथ क्रेडिट की विनिमयशीलता ने क्योटो प्रोटोकॉल को अपनी पहली प्रतिबद्धता अवधि (2008-2012) में एक मजबूत कार्बन मूल्य स्थापित करने में मदद की।

केपी की दूसरी प्रतिबद्धता अवधि दिसंबर 2012 में 2013 से 2020 के लिए अपनाई गई थी, जबकि ईयू-ईटीएस ने 2013-2020 में अपने तीसरे चरण में प्रवेश किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट के संचयी प्रवाह ने यूरोपीय कार्बन बाजार में बड़े अधिशेष को जन्म दिया और कार्बन मूल्य प्रोत्साहन को कमजोर कर दिया। उदाहरण के लिए, कीमतें 2011 में €15/tCO2e से गिरकर 2013-2015 की अवधि में €15/tCO2e की मूल्य सीमा तक आ गई। इसलिए, ईयू ने केपी से सीईआर और ईआरयू को ईयू ईटीएस के भीतर अनुपालन इकाइयां नहीं बनाने का फैसला किया और ईयू ईटीएस उत्सर्जन अनुमतियों के लिए क्योटो इकाइयों का आदान-प्रदान अनिवार्य कर दिया। केपी के कार्बन बाजारों का दूसरा चरण मुख्य रूप से कुछ प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं की गैर-भागीदारी के कारण और क्योंकि क्योटो क्रेडिट की ईयू-ईटीएस के साथ गैर-अंतरपरिवर्तनीयता के कारण विफल रहा।

67. विकासशील देशों की उत्सर्जन सीमा निर्धारण की बाध्यता नहीं थी।

68. 2020 के बाद ईयू ईटीएस में अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट का उपयोग, यूरोपीय आयोग , https://tinyurl.com/55mn5s79.

2020 में केपी की समाप्ति के साथ, सीडीएम भी समाप्त हो गया और इसकी जगह कार्बन बाजार के अनियमित क्रेता और विक्रेता, वीसीएम ने ले ली।

दिसंबर 2015 में अपनाया गया पेरिस समझौताए देशों को एकीकृत वैश्विक कार्बन बाजार के माध्यम से अपने एनडीसी में उच्च महत्वाकांक्षा के लिए स्वैच्छिक रूप से सहयोग करने का विकल्प प्रदान करता है।

क. अनुच्छेद 6.2 में द्विपक्षीय स्तर पर "सहकारी दृष्टिकोण" अपनाने का आह्वान किया गया है, जिसमें एनडीसी को पूरा करनेए सतत विकास को बढ़ावा देनेए तथा दोहरी गणना से बचते हुए पर्यावरणीय अखंडता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित शमन परिणामों (आईटीएमओ)[69] का उपयोग शामिल है।

ख. अनुच्छेद 6.4 शमन परिणामों के विरुद्ध उत्सर्जन क्रेडिट जारी करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को परिभाषित करता है। इस प्रकार पेरिस समझौते के तंत्र का अनुच्छेद 6.4 क्योटो प्रोटोकॉल के सीडीएम का उत्तराधिकारी बन गया।[70] यदि मेजबान देश द्वारा अधिकृत किया जाता है, तो शमन गतिविधियों द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन क्रेडिट (या उत्सर्जन में कमी) आईटीएमओ बन जाते हैं। कोई अन्य देश अपने एनडीसी को पूरा करने या अन्य शमन उद्देश्यों के लिए इनका उपयोग कर सकता है, और किसी भी दोहरी गणना से बचने के लिए मूल देश में इसी तरह के समायोजन की मांग करता है।

अनुच्छेद 6.2 और 6.4 के कार्यान्वयन पर बातचीत अभी भी जारी है।

6.45 2047 तक विकसित भारत और 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य के संदर्भ में भारत में उत्सर्जन में कमी लाने में कार्बन बाजार की प्रभावशीलता इसके विनियमन और कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी, जबकि सीसीटी के तहत विकसित घरेलू अनुपालन बाजार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उद्योग अपने उत्पादन और निवेश निर्णयों में उत्सर्जन लागतों को शामिल करे, हम अन्य देशों के प्रणाली परिवर्तन को सब्सिडी नहीं दे सकते हैं।

6.46 भारत सरकार के मिशन लाइफ को जलवायु परिवर्तन से निपटने और संरक्षण और संयम के सिद्धांतों के आधार पर संधारणीय जीवन को बढ़ावा देने के लिए एक जन आंदोलन के रूप में परिकल्पित किया गया है। सरकार स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों जैसे कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) का समर्थन करती है, जो व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों को पुरस्कार के रूप में ग्रीन क्रेडिट प्रदान करके पर्यावरण-सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। बॉक्स 7 में जीसीपी पर एक संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत की गई है।

बॉक्स VI.7: लाइफ इन एक्शन: भारत का अभिनव ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम[71]

लाइफ आंदोलन जलवायु परिवर्तन से निपटने और संरक्षण और संयम पर आधारित संधारणीय जीवन को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर एक व्यापक पहल है। इस प्रयास को बढ़ावा देने और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को

69. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित शमन परिणाम पेरिस समझौते के पक्षों के बीच उत्सर्जन व्यापार के लिए इकाइयाँ हैं

70. माइकलोवा , ए., समानीगो, एक्स., केसलर, जे., अहोनेन, एच.एम., स्पेंस, सी., और यूरोपीय क्षमता निर्माण पहल। (2022)। अनुच्छेद 6 के लिए पॉकेट गाइड। पेरिस समझौते के तहत। https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/230043/

71. एमओईएफसीसी द्वारा राजपत्र अधिसूचना , 26 जून 2023 https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/246825.pdf

प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दो अग्रणी कार्यक्रम शुरू किए: ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) और इकोमार्क योजना।[72]

जीसीपी के उद्देश्य: जीसीपी एक नवोन्मेषी बाजार-आधारित तंत्र है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों को हरित ऋण जारी करने के माध्यम से स्वैच्छिक पर्यावरणीय सकारात्मक कार्यो में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

कार्यान्वयन और शासन: अक्टूबर 2023 में अधिसूचित ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 के अनुसारांश, जीसीपी को चरणबद्ध और पुनरावृत्त दृष्टिकोण के माध्यम से लागू किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में, यह वन विभागों के नियंत्रण और प्रबंधन के तहत परतीभूमि, बंजर भूमि, जलग्रहण क्षेत्र आदि पर स्वैच्छिक वृक्षारोपण पर केंद्रित है। जीसीपी की शासन संरचना में संबंधित मंत्रालयों, विशेषज्ञों और संस्थानों के संचालन समिति के सदस्य शामिल हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) को जीसीपी प्रशासक के रूप में नामित किया गया है और यह जीसीपी के कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। जीसीपी की डिजिटल प्रक्रियाओं में संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक समर्पित वेब प्लेटफॉर्म और एक ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री शामिल है। पंजीकरण, लेखांकन और ग्रीन क्रेडिट जारी करने की निगरानी जीसीपी की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ग्रीन क्रेडिट नियमए 2023 के तहत ग्रीन क्रेडिट का सृजन, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीमए 2023 के तहत कार्बन क्रेडिट से स्वतंत्र है।

सीओपी-28 के अवसर पर भारत और यूएई द्वारा संयुक्त रूप से 'ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम' की मेजबानी की गई। भारत ने सभी देशों को वैश्विक ग्रीन क्रेडिट पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जिसका उद्देश्य ग्रीन क्रेडिट जैसे कार्यक्रमों धतंत्रों के माध्यम से पर्यावरण-सकारात्मक कार्यों की योजना बनाने, उन्हें लागू करने और निगरानी करने में ज्ञान, अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से वैश्विक सहयोगए सहकारिता और भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है। अध्याय 13, एक विशेष निबंधए लाइफ (एलआईएफई) की अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता को महत्वपूर्ण बनाता है।

जलवायु वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ : घटनाक्रम

6.47 पर्याप्त और किफायती वित्तीय संसाधनों तक पहुंच की कमी विकासशील देशों के लिए अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को लागू करने में एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। वित्त पर स्थायी समिति (यूएनएफसीसीसी के तहत एक निकाय) ने अनुमान लगाया है कि विकासशील देशों द्वारा अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और अन्य संचार में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक 5.8 ट्रिलियन से लेकर 11.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर के संसाधनों की आवश्यकता है। 2023 संयुक्त राष्ट्र अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट ने अनुमान लगाया है कि विकासशील देशों में अनुकूलन लागत 21.3 बिलियन अमरीकी डालर के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलन वित्त प्रवाह से 10 से 18 गुना अधिक है।[73] यूएनएफसीसीसी और इसका पेरिस समझौता यह अधिदेश देता है कि विकसित देश अनुदान या रियायती आधार पर वित्तीय संसाधन प्रदान करें और विकासशील देशों को उनकी जलवायु क्रियाओं को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकियों

72. सतत जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लाइफ पहल के तहत ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) और इकोमार्क योजना के लिए अधिसूचना जारी , 13 अक्टूबर, 2023, पीआईबी, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1967476

73. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (2023)। अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2023: अपर्याप्त वित्त पोषण। अपर्याप्त तैयारी। जलवायु अनुकूलन पर अपर्याप्त निवेश और योजना दुनिया को असुरक्षित बनाती है । नैरोबी। https://doi.org/10.59117/20.500.11822/43796.

तक पहुंच प्रदान करें। प्रथम जीएसटी परिणाम भी विकासशील देशों को सहायता देने में नए और अतिरिक्त अनुदान आधारितए अत्यधिक रियायती वित्त और गैर-ऋण साधनों के महत्व को रेखांकित करता है। विकसित राष्ट्रों से विकासशील देशों को होने वाले वित्तीय प्रवाह बहुत कम रहे हैं। वर्तमान में विकासशील देशों के लिए उपलब्ध अधिकांश अंतरराष्ट्रीय वित्त अनुदानों की बजाय ऋणों के रूप में है।

6.48 समग्र संसाधन आवश्यकता का प्रारंभिक अनुमान 2015-2030 के लिए 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। देश द्वारा प्रस्तुत दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति (एलटी-एलईडीएस) में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत को निम्न-कार्बन विकास पथ की ओर बढ़ने के लिए 2050 तक दसियों ट्रिलियन डॉलर के वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत भारत के पहले अनुकूलन संचार (एसी) में उल्लेख किया गया था कि अनुकूलन के लिए व्यय की संचयी आवश्यकता 2030 तक ₹56.68 ट्रिलियन होगी। तथापि, जलवायु कार्रवाई - शमन और अनुकूलन - के लिए संसाधन प्रवाह का अधिकांश हिस्सा मुख्य रूप से घरेलू संसाधनों से आता है।

6.49 विकासशील देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध, सुगम्यय और वहनीय वित्तीय संसाधन आवश्यक होते हैं। यूएनएफसीसीसी और इसके पेरिस समझौते में यह अनिवार्य किया गया है कि विकसित देश संसाधन उपलब्ध कराएं और विभिन्न स्रोतों के माध्यम से वित्त जुटाने में अग्रणी भूमिका निभाएं। तथापि, विकासशील देशों द्वारा जलवायु कार्रवाई का अधिकांश हिस्सा घरेलू संसाधनों के माध्यम से किया गया है, और विकसित देशों का जोर मुख्य रूप से जलवायु कार्रवाई के वित्तपोषण में निजी वित्त की अगुवाई पर रहा है। वित्तीय आवश्यकताओं के पैमाने को देखते हुए, निजी पूंजी की जरूरतों को आंशिक रूप से भी पूरा करने की क्षमता बहस का विषय बनी हुई है। इसके अलावा, ऐसी पूंजी की लागत का विकासशील देशों की व्यापक आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ेगा। निजी पूंजी के महत्व को पहचानते हुए, सामाजिक और आर्थिक प्रगति केंद्र द्वारा एक कार्य पत्र[74] विकासशील देशों के लिए इसे आकर्षित करने में विभिन्न चुनौतियों की पहचान करता है जैसे कि उनके वित्तीय बाजारों की सीमित गहनता और सुभेद्य कर्ज प्रोफाइल। यह सुझाव देने के लिए और भी साक्ष्य हैं[75] कि एमडीबी ने जलवायु कार्रवाई के लिए एमडीबी द्वारा प्रतिबद्ध वित्त के प्रत्येक डॉलर के लिए निजी क्षेत्र से एक डॉलर से भी कम जुटाया। जैसा कि फाइनेंशियल टाइम्स के एक लेख में दर्शाया गया है- 'बहुत कुछ करना है, और समाधान को सही तरीके से करने की तात्कालिकता और आवश्यकता को देखते हुएए यह ण्ण्ण् पसंदीदा ईएसजी-केंद्रित पोर्टफोलियो प्रबंधक के लिए एक कार्य नहीं है ... भौतिक बुनियादी ढांचे का विशाल पैमाना जिसे पुनर्निर्मित, ध्वस्त या प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, लगभग समझ से परे है। सरकारों, ..., को नेतृत्व करना होगा ... पश्चिमी देशों ने इतना नुकसान किया है कि उन्हें विकासशील दुनिया में परिवर्तन को वित्तपोषित करना होगा - यह आश्चर्यजनक है कि इस विचार पर अभी भी बहस चल रही है।''[76]

सीओपी 28 और वैश्विक स्टॉकटेक

6.50 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के लिए पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी 28) का 28वां सत्र दुबई, यूएई में आयोजित किया गया। सीओपी 28 के प्राथमिक परिणाम में प्रथम वैश्विक स्टॉकटेक के परिणाम पर निर्णय शामिल था, जिसका उद्देश्य दशक के अंत से पहले वैश्विक जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाना है,

74. नटराजन, जी., और अनंत नागेश्वरन, वी., (2023)। वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के लिए निजी पूंजी का उपयोग: मुद्दे, चुनौतियाँ और समाधान (सीएसईपी वर्किंग पेपर 57)। नई दिल्ली: सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, https://csep.org/wp-content/uploads/2023/10/Harnessing-private-capital-for-global&public-goods-1.pdf.

75. बहुपक्षीय विकास बैंकों की जलवायु वित्त पर 2019 संयुक्त रिपोर्ट। (2020)। https://www.ebrd.com/2019-joint-report-on-mdbs-climate-finance.

76. ब्रॉवर, डी., चू, ए. और मैककॉर्मिक, एम., ऊर्जा संक्रमण अस्थिर होगा, द फाइनेंशियल टाइम्स, (2023, 29 जून)। https://www.ft.com/content/86d71297-3f34-48f3-8f3f-28b7e8be03c6.

जिसे पेरिस समझौते और उनकी विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित तरीके से लागू किया जाना है। सीओपी 28 का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम हानि और क्षति कोष और इसके वित्तपोषण व्यवस्था को चालू करने पर समझौता है। पेरिस समझौते के तहत अनुकूलन के लिए एक वैश्विक लक्ष्य (जीजीए) विकसित करने के जनादेश के अनुरूपए सीओपी 28 ने वैश्विक जलवायु लचीलेपन के लिए अमीरात फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया। निर्णय में सभी देशों से 2030 तक अनुकूलन योजनाएँ बनाने का आह्वान किया गया। अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य के लिए लक्ष्यों पर सभी पक्षों ने सहमति व्यक्त की, जो अनुकूलन लक्ष्यों पर वैश्विक आम सहमति और उन्हें प्राप्त करने के लिए वित्तए प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण समर्थन की आवश्यकता को दर्शाता है।

6.51 प्रथम जीएसटी के तहत, पक्षकारों ने जलवायु कार्रवाई के विभिन्न विषयों, जैसे कि शमन, अनुकूलन और कार्यान्वयन के साधनों, जिसमें वित्त, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल हैं, पर निर्णय लिए। वित्त के तहत, जीएसटी निर्णय याद दिलाता है कि विकसित देश पक्ष सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के तहत शमन और अनुकूलन से संबंधित अपने दायित्वों को जारी रखने में विकासशील देश पक्षों की सहायता के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करेंगे। निर्णय में यह भी माना गया है कि अनुकूलन वित्त को विकासशील देशों में अनुकूलन में तेजी लाने और लचीलापन बनाने की तत्काल और उभरती हुई आवश्यकता का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। शमन के तहत, निर्णय में पार्टियों से वैश्विक अक्षय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने, निरंतर कोयला बिजली को चरणबद्ध तरीके से कम करने, अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त करने आदि के प्रयासों में तेजी लाने में योगदान देने का आह्वान किया गया है। ये निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित तरीके से कार्यान्वित किए जाने के अधीन हैंए जिसमें पक्षकारों की विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों, प्रक्रियाओं और दृष्टिकोणों को ध्यान में रखा जाता है। निर्णय में यह भी कहा गया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उठाए गए कदमए जिनमें एकतरफा उपाय भी शामिल हैं, मनमाने या अनुचित भेदभाव या अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रच्छन्न प्रतिबंध नहीं होने चाहिए।

नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी)

6.52 यूएनएफसीसीसी के तहत जलवायु वित्त पर एक नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी) पर बातचीत की जा रही है, ताकि 2025 से विकासशील देशों के लिए विकसित देशों द्वारा जुटाए जाने वाले जलवायु वित्त का वार्षिक लक्ष्य तय किया जा सके। अधिदेश 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष की न्यूनतम सीमा से एक नया परिमाणित लक्ष्य निर्धारित करना है, जिसमें विकासशील देशों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर विचार किया जाएगा, जिसका उद्देश्य सतत विकास और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करना है। विकासशील देश चाहते हैं कि क) महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो पर्याप्त रूप से उनकी आश्यकताओं को संबोधित करे, ख) अनुदान-आधारित या अत्यधिक रियायती, और सुलभ वित्तीय संसाधन हों, और ग) शमन और अनुकूलन के वित्तपोषण के बीच संतुलन हो। इन पहलुओं को G20 की भारतीय अध्यक्षता में चर्चाओं में भी स्पष्ट किया गया है और दिल्ली घोषणा में विधिवत प्रतिबिंबित किया गया है।

जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के समाधान के लिए भारत की अंतरराष्ट्रीय पहल

6.53 भारत ने जलवायु परिवर्तन शमन और लचीलापन निर्माण की दिशा में महत्वाकांक्षी घरेलू उपायों के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय पहलों का नेतृत्व किया है। इनमें से कुछ की चर्चा इस प्रकार है:

1 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की स्थापना भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल द्वारा 2015 में सौर ऊर्जा समाधानों को लागू करने के लिए की गई थी। यह 119 सदस्यों और हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ एक संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन है। संगठन का लक्ष्य गारंटियों के माध्यम से निजी क्षेत्र निवेश बढ़ाकर, क्षमता निर्माण करके

तथा प्रौद्योगिकी अंगीकरण की लागत में कमी लाने से उपायों के माध्यम से 2030 तक सौर ऊर्जा में एक ट्रिलियन अमरीकी डालर का निवेश प्राप्त करना है। इसके कार्यक्रम समर्थन ने अपने सदस्य देशों में 9.5 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की पाइपलाइन की पहचान की है। आईएसए अपने सदस्यों को कम विकसित देशों (एलडीसी) या छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) के रूप में वर्गीकृत अपने सदस्यों के लिए 50,000 अमरीकी डालर के अनुदान के साथ सौर ऊर्जा प्रदर्शन परियोजनाओं की स्थापना में सहायता करता है। मार्च 2024 तक, 19 सौर ऊर्जा प्रदर्शन परियोजनाएँ कार्यान्वयन के अधीन हैं। आईएसए क्षमता निर्माण पर भी काम करता है और इस प्रयास के भाग के रूप में, दुनिया भर के लगभग 4,000 पेशेवरों को सौर ऊर्जा उद्योग के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षित किया गया है। आईएसए ने इथियोपिया और सोमालिया में सौर प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग संसाधन केंद्र (एसटीएआर-सी) की सफलतापूर्वक स्थापना की है।

2 एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड (ओएसओडब्ल्यूओजी) भारत और ब्रिटेन के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को आपस में जोड़ना है। ओएसओडब्ल्यूओजी के पीछे का दृष्टिकोण यह मंत्र है कि 'सूर्य कभी अस्त नहीं होता', और विचार यह है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों से सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का दोहन किया जाए, जहां हर समय सूर्य चमक रहा हो, और उस बिजली को कुशलतापूर्वक उन क्षेत्रों में पहुंचाया जाए जहां इसकी आवश्यकता है। ओएसओडब्ल्यूओजी पहल को तीन चरणों में पूरा किया जाना है। पहले चरण में, भारतीय ग्रिड को एक सामान्य ग्रिड विकसित करने के लिए मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया ग्रिड से जोड़ा जाएगा। दूसरा चरण कार्यात्मक पहले चरण को अफ्रीका में नवीकरणीय संसाधनों के भंडार से जोड़ेगा, और अंत में, तीसरे चरण में 2050 तक 2600 गीगावाट इंटरकनेक्शन के लक्ष्य के साथ वास्तविक वैश्विक इंटरकनेक्शन प्राप्त करने पर ध्यान दिया जाएगा।[77]

3 आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) की शुरुआत भारत ने 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान की थी। यह राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और वित्तपोषण तंत्रों, निजी क्षेत्र और शैक्षणिक और ज्ञान संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है जिसका उद्देश्य सतत विकास के समर्थन में जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए नए और मौजूदा बुनियादी ढाँचे की प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देना है। सीडीआरआई का उद्देश्य क्षमता निर्माण, सूचनाप्रद नीति, योजना और प्रबंधन के माध्यम से बुनियादी ढाँचे के लचीलेपन को बढ़ाना है, जिससे 2050 तक तीन अरब से अधिक लोगों के पर्यावरण, आजीविका और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। संगठन ने 2023 में वैश्विक अवसंरचना लचीलेपन पर अपनी पहली द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी की। यह एसडीजी, पेरिस समझौते और सेंडाई फ्रेमवर्क लक्ष्यों की निगरानी में सीडीआरआई का योगदान है। अन्य हस्तक्षेपों में सहकर्मी के साथ सीखना (पीयर लर्निंग) और क्षमता विकास के अवसरों के लिए वित्तीय सहायता तथा बिजली, परिवहन, दूरसंचार, स्वास्थ्य और शहरी अवसंरचना पर क्षेत्रीय कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा, 2023 में यूएसएआईडी और मियामोटो इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (जीआरआई) कनेक्ट के तहत 13 एसआईडीएस में 11 प्रोजेक्ट दिए गए, जो एक वन-स्टॉप डिजिटल नॉलेज एक्सचेंज, लर्निंग और को-क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएशन एकेडमिक एक्सचेंज (आईआरएएक्स) प्रोग्राम की कल्पना वैश्विक शैक्षणिक संस्थानों के साथ एक संरचित जुड़ाव पहल के रूप में की गई है ताकि डीआरआई पर मूल्यवर्धित शिक्षा, शोध के अवसर और पेशेवर विकास की पेशकश की जा सके। इसके हिस्से के रूप में, 2023 में, डीआरआई पर शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और पेशेवर विकास के अवसर प्रदान करने के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों और भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच साझेदारी का समर्थन करने के लिए यूएसएआईडी द्वारा 5 मिलियन अमरीकी डालर प्रदान किए गए थे।[78]

77. एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड (ओएसओडब्ल्यूओजी), अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, https://isolaralliance.org/work/osowog/

78. आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) से प्राप्त जानकारी के आधार पर

4 भारत के नेतृत्व में लचीले द्वीप राज्यों के लिए अवसंरचना(आईआरआईएस) सीडीआरआई और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) की एक प्रमुख रणनीतिक पहल है, जिसे एसआईडीएस के लिए लचीलापन और जलवायु अनुकूलन समाधान प्राप्त करने और वितरित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो सबसे कमजोर और उजागर देशों में से हैं। 2021 में लॉन्च किए गए आईआरआईएस को पहले से ही ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूरोपीय संघ और यूके से 35 मिलियन अमरीकी डालर की प्रतिबद्धताओं का समर्थन प्राप्त है, जिसका लक्ष्य 2030 तक एसआईडीएस का समर्थन करने के लिए 50 मिलियन अमरीकी डालर को जुटाना और परिनियोजित करना है।[79]

5 नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और उद्योग के बीच साझेदारी के महत्व को समझते हुए, भारत और स्वीडन की सरकारों द्वारा सितंबर 2019 में उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह (लीडआईटी) का शुभारंभ किया गया था। लीडआईटी पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध देशों और कंपनियों को एक साथ लाता है। सीओपी28 में, भारत और स्वीडन ने 2024-26 के लिए दूसरा लीडआईटी (लीडआईटी 2.0) चरण शुरू किया, जो एक समावेशी उद्योग परिवर्तन के लिए नीति रूपरेखा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आकार देने के लिए सदस्य देशों और कंपनियों की संयुक्त प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह नया चरण समावेशी और न्यायसंगत उद्योग परिवर्तन, सह-विकास और निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उद्योग परिवर्तन के लिए वित्तीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करेगा।

निष्कर्ष

6.54 भारत अपने महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, इसलिए इसे कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए ऊर्जा की मांग को पूरा करने की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है। ऊर्जा खपत और विभिन्न सामाजिक संकेतकों के बीच घनिष्ठ संबंध को देखते हुए, सरकार की प्राथमिकता संधारणीय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों तक पहुँच सुनिश्चित करना है। गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोत भारत के महत्वाकांक्षी एनडीसी और नेट जीरो प्रतिबद्धता के लिए महत्वपूर्ण हैं। तथापि, गैर-जीवाश्म स्रोतों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की अपनी चुनौतियाँ हैं - नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित रुकावटें, परमाणु और सौर पैनल कचरे का निपटान, खाद्य सुरक्षा पर जैव ईंधन उत्पादन के निहितार्थ, आदि। उभरते और महत्वाकांक्षी एनडीसी लक्ष्यों और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य के आधार पर, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि भारत को ऊर्जा स्रोतों के विविध सेट को लक्षित करने की आवश्यकता है। इस तरह के विविधीकरण से राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप कम उत्सर्जन वाले मार्गों का अनुसरण करते हुए ऊर्जा प्रणालियों से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी। परमाणु ऊर्जा और जैव ईंधन की खोज के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक मार्ग प्रस्तुत करता है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उपयोग का समर्थन करने के लिए आधार-भार प्रदान करने में ताप विद्युत, विशेष रूप से कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका भी शामिल होगी ।

6.55 ऊर्जा सुरक्षा के परिदृश्य की खोज में, यह स्पष्ट हो गया है कि जोखिम केवल बाधाएँ ही नहीं हैं, बल्कि अवसरों के अग्रदूत भी हैं। अनिश्चितताएँ मंडरा रही हैं, लेकिन वे भारत के लिए नवाचार, अनुकूलन और विकास के अवसर प्रस्तुत करती हैं। जहाँ तक संभव हो नवीकरणीय ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से अपनाना अनिवार्य है, वहीं अल्पावधि से मध्यम अवधि में, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को सक्रिय रूप से अपनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। (स्वच्छ) कोयले के लिए सरकार की पहल, जैसे कि कोयला गैसीकरण मिशन, कोल बेड मीथेन गैसों का निष्कर्षण, कोयले से हाइड्रोजन की खोज, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (सीसीएस), और वाशरी के माध्यम से कोयला लाभकारीकरण, आदि

79. लचीले द्वीपीय राज्यों के लिए बुनियादी ढांचा (आईआरआईएस), संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, सतत विकास, https://sdgs.un.org/partnerships/infrastructure-resilient-island-states-iris.

उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। कोयला बिजली संयंत्रों के लिए अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ, उत्सर्जन को कम करना और उच्च दक्षता प्राप्त करना संभव होगा।

6.56 भारत की सफल अक्षय ऊर्जा विकास की कहानी सुस्थापित है। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 2014 से 2023 के बीच 25 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। तथापि, अक्षय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर चरणबद्ध तरीके से उपयोग के साथ कई जोखिम जुड़े हुए हैं, जैसे कि रुकावट, ग्रिड एकीकरण, बैकअप बिजली उत्पादन, भंडारण, आदि। परमाणु, जैव ईंधन और हाइड्रोजन जैसे अन्य गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों के साथ पूरक करना महत्वपूर्ण है।

6.57 ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत की अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए मुख्य रूप से पेट्रोलियम के आयात पर निर्भरता, सौर पीवी पैनलों और महत्वपूर्ण खनिजों (प्रणालीगत जोखिम) के लिए उच्च आयात निर्भरता में बदल जाए, जिनकी आपूर्ति श्रृंखला और भूराजनीति और भी पेचीदा हो सकती है। भारत को नवीकरणीय (सौर, पवन, बड़े और छोटे हाइड्रो) हरित हाइड्रोजन, परमाणु और जैव ईंधन सहित विविध ऊर्जा स्रोतों को लक्षित करने की आवश्यकता है। इस तरह के विविधीकरण से राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप कम उत्सर्जन वाले मार्गों का अनुसरण करते हुए ऊर्जा प्रणालियों से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी। इस विविधीकरण में नवीकरणीय ऊर्जा की बड़े पैमाने पर परिनियोजन का समर्थन करने के लिए आधार भार प्रदान करने में थर्मल पावर की महत्वपूर्ण भूमिका भी शामिल होगी।

6.58 वैश्विक नेट जीरो के लिए आवश्यक कई प्रौद्योगिकियां व्यावसायिक रूप से अनुपलब्ध हैं, जैसे हाइड्रोजन-ईंधन वाले स्टील व सीमेंट, सीसीयूएस के साथ स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादन, आदि। अनुसंधान एवं विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से वितरित आरई, अपतटीय पवन, भूतापीय, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ईंधन, संपीड़ित जैव गैस, हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रोलाइजर और परमाणु ऊर्जा (छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर सहित) के क्षेत्र में।

6.59 वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, सामर्थ्य और सुगमता हरित परिवर्तन को गति प्रदान करेगी। जबकि भारत ने अब तक अपने संसाधनों पर भरोसा किया है, यह महत्वपूर्ण है कि विकसित देशों से संसाधन और बाद में जुटाए गए संसाधन यूएनएफसीसीसी और उसके पेरिस समझौते के उद्देश्यों के अनुरूप विकासशील देशों में प्रवाहित हों। नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य पर बातचीत से पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक परिणाम प्राप्त होने चाहिए। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वैश्विक आख्यान, इसे जलवायु आपातकाल के रूप में वर्णित करते हुए, समान रूप से, यदि अधिक नहीं, तो महत्वपूर्ण विकासात्मक समस्याओं से ध्यान हटाता है और घबराहट पैदा कर सकता है।[80,81] विश्व को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अधिक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसे वैश्विक जलवायु प्रबंधन के एक बड़े, दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ अत्यधिक व्यस्त होने के बजाय मानव कल्याण में सुधार के निकट-अवधि के नीतिगत लक्ष्यों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

****

80. हुल्म, एम. (2023). जलवायु परिवर्तन ही सब कुछ नहीं है: जलवायु राजनीति को अलार्मवाद से मुक्त करना। जॉन विले एंड संस।

81. वी. अनंथा नागेश्वरन, जलवायु परिवर्तन: लोगों को डराने से केवल निशान ही मिलेंगे और कोई समाधान नहीं, एमआईएनटी, (16 अप्रैल, 2024), https://www.livemint.com/opinion/online-views/climate-change-scaring-people-will-only-yield-scars-and-no-solutions-11713237716747.html.

07

अध्याय

सामाजिक क्षेत्रः कल्याण जो सशक्त करे

हाल के वर्षों में भारत की उच्च और सतत आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक और संस्थागत प्रगति भी हो रही है, जो सशक्तीकरण के साथ सरकारी कार्यक्रमों के परिवर्तनकारी और प्रभावी कार्यान्वयन पर आधारित है, जो कल्याण के लिए एक परिवर्तित दृष्टिकोण की पहचान बन गया है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, स्वच्छता हो, डिजिटल सशक्तिकरण हो या ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता हो, सामाजिक अवसंरचना तंत्र के प्रत्येक पहलू ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी योजना और वितरण के माध्यम से प्रगति की है। सभी के लिए जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के परिणाम और सफलता की कहानियाँ स्पष्ट हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और पहुँच में महत्वपूर्ण मोड़ आ रहे हैं। सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 360 डिग्री सक्षम हस्तक्षेपों के साथ महिला-नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। पारदर्शी और डिजिटल ग्रामीण शासन के लिए कई कार्यक्रमों के साथ-साथ जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2047 तक एक विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए, प्रभावी और कुशल सरकारी कार्यक्रम और राज्य-स्तरीय पहल, सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण हैं।

परिचय

7.1 भारत 2047 तक विकास की सीढ़ी के अगले स्तर 'विकसित भारत' के सोपान (विकसित भारत@2047) तक बढ़ने की राह पर है। आर्थिक विकास सामाजिक, तकनीकी और संस्थागत प्रगति सहित विकास के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मार्ग है। तथापि, सार्वजनिक नीति की दिशा और उसका कार्यान्वयन भी विकास को समग्र मानव विकास में बदलने में सहायक होता है। 18 प्रतिशत मानवता का घर होते हुए,[1] भारत के सामाजिक बुनियादी ढांचे को संस्कृतियों, भाषाओं और भौगोलिक क्षेत्रों से परे एक विविध और विस्तृत आबादी तक पहुँचना चाहिए। एक युवा और आकांक्षी समाज का दावा करते हुए, भारत का लक्ष्य उच्च आर्थिक विकास द्वारा प्रदान किए गए अवसरों को हासिल करना है, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, स्वच्छ जल, स्वच्छता सुविधाएँ, किफायती आवास, बिजली और इंटरनेट की सुविधाओं वाला समाज सुनिश्चित करना है। टिकाऊ और न्यायसंगत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए व्यापक आयोजन किया गया है, और यह यात्रा चुनौतियों, पुरानी और नई, और केंद्रीकृत और स्थानीय समाधानों के साथ जारी है।

7.2 पिछले दशक के बाद, भारतीय कल्याणकारी अवधारणा को महत्वपूर्ण रूप से एक अधिक दीर्घकालिक उन्मुख, कुशल और सशक्त अवतार में बदल दिया गया है। इसने कल्याणकारी पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत बनाया है और देश में मानव विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में मदद की है। इसके अलावा, सरकार का सामाजिक क्षेत्र का व्यय इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व के साथ तालमेल रखता रहा है। सामाजिक सेवाओं पर सरकार के खर्च में वित्त वर्ष 2016 से वृद्धि का रुझान दिखा है, जिसमें देश के नागरिकों के सामाजिक कल्याण के कई पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसा कि तालिका VII.1 से स्पष्ट है। वित्त वर्ष 2018 और वित्त वर्ष 2024 के बीच में, नाममात्र जीडीपी लगभग 9.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी है। कुल मिलाकर, कल्याण व्यय 12.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। शिक्षा पर व्यय 9.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है- जो कि जीडीपी वृद्धि-दर के लगभग बराबर है। स्वास्थ्य पर व्यय जैसा नीचे तालिका में दिखाया हैं 5.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है।

1 संयुक्त राष्ट्र का अनुमान https://www.un.org/en/global-issues/population

तालिका VII.1: सामान्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवा व्यय में रुझान

(संयुक्त केंद्र और राज्य)

(₹ करोड़)

मदें	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (स. अ.)	2023-24 (बीई)
कुल व्यय	45,15,946	50,40,747	54,10,887	63,53,359	70,98,451	83,76,972	90,45,119
सामाजिक सेवाओं पर व्यय[2]	11,39,524	12,78,124	13,64,906	14,79,389	17,87,019	21,49,346	23,50,584
जिसका कि:							
शिक्षा[3]	4,83,481	5,26,481	5,79,575	5,75,834	6,39,436	7,68,946	8,28,747
*शिक्षा (शिक्षा मंत्रालय का अनुमान)**	6,621,51	7,36,581	8,63,118 (RE)	9,19,145 (BE)			
स्वास्थ्य[4]	2,43,388	2,65,813	2,72,648	3,17,687	4,56,109	5,12,742	5,85,706
अन्य	4,12,655	4,85,829	5,12,683	5,85,868	6,91,474	8,67,659	9,36,131
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में							
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	6.7	6.8	6.8	7.5	7.6	8.0	7.8
जिसका कि:							
शिक्षा	2.8	2.8	2.9	2.9	2.7	2.9	2.7
*शिक्षा (शिक्षा मंत्रालय का अनुमान)**	3.9	3.9	4.3 (स. अ.)	4.6 (स. अ.)			
स्वास्थ्य	1.4	1.4	1.4	1.6	1.9	1.9	1.9
अन्य	2.4	2.6	2.6	3.0	2.9	3.2	3.1
कुल व्यय के प्रतिशत के अनुसार							
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	25.2	25.4	25.2	23.3	25.2	25.7	26.0
जिसका कि:							
शिक्षा	10.7	10.4	10.7	9.1	9.0	9.2	9.2
स्वास्थ्य	5.4	5.3	5.0	5.0	6.4	6.1	6.5
अन्य	9.1	9.6	9.5	9.2	9.7	10.4	10.3
सामाजिक सेवाओं के प्रतिशत के अनुसार							
शिक्षा	42.4	41.2	42.5	38.9	35.8	35.8	35.3

2 सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति; चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण; जल आपूर्ति और स्वच्छता; आवास; शहरी विकास; अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, श्रम और श्रमिक कल्याण; सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, पोषण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत आदि शामिल हैं।

3 'शिक्षा' पर व्यय 'शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति' पर व्यय से संबंधित है।

4 'स्वास्थ्य' पर व्यय में 'चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य', 'परिवार कल्याण' और 'जलापूर्ति और स्वच्छता' पर व्यय शामिल हैं।

स्वास्थ्य	21.4	20.8	20.0	21.5	25.5	23.9	24.9
अन्य	36.2	38.0	37.6	39.6	38.7	40.4	39.8

स्रोत: आरबीआई

नोट: (i) वर्तमान बाजार मूल्यों पर जीडीपी के अनुपात 2011-12 के आधार पर 2021-22 तक आधारित हैं। 2022-23 के लिए जीडीपी केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार है।

(ii) भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय (एमओई) शिक्षा पर सामान्य सरकारी खर्च की भी गणना करता है। जबकि शिक्षा व्यय पर आरबीआई के आंकड़ों में केंद्र और राज्यों द्वारा शशिक्षा, खेल, कला और संस्कृतिश पर किए गए खर्च को शामिल किया गया है, शिक्षा मंत्रालय के अनुमानों में चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि अनुसंधान और शिक्षा, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का कल्याण, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास, सामाजिक सुरक्षा के तहत शिक्षा, मिड-डे मील के तहत पौष्टिक भोजन पर खर्च, पुलिस को प्रशिक्षण देने पर खर्च, श्रम रोजगार और कौशल विकास व्यय, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत शिक्षा/प्रशिक्षण व्यय आदि पर किया गया खर्च भी शामिल है। इससे शिक्षा पर खर्च का उच्च अनुमान निकलता है, जो 2020-21(नवीनतम उपलब्ध) में सकल घरेलू उत्पाद का 4.64 प्रतिशत है।

7.3 यह अध्याय हाल के वर्षों में उच्च आर्थिक वृद्धि का देश के नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रस्तुत करता है। शुरूआत में जनसंख्या के जीवन स्तर के व्यापक क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण परिणामों पर चर्चा की गई है। स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों को कुछ विस्तार से कवर किया गया है। नारी शक्ति पर जोर देने के मद्देनजर, अगले भाग में देश में बढ़ती महिला की शक्ति और इस संबंध में सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की सक्रिय भूमिका पर चर्चा की गई है। देश की एक बड़ी आबादी ग्रामीण भारत में रहती है। जमीनी स्तर पर हो रहे विकास और ग्रामीण भारत के लिए सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की भूमिका को आखिरी भाग में प्रस्तुत किया गया है।

विकास को सशक्त कल्याण के साथ जोड़ना

7.4 लेह में डेमचोक गांव, जो 13,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पारा माइनस 40 डिग्री तक गिर सकता है, को जल जीवन मिशन के तहत जुलाई 2022 में अपना पहला नल जल कनेक्शन मिला, जिससे महिलाओं को पानी लाने के झंझट से मुक्ति मिली। महाराष्ट्र के बुलुमगवन के एक सुदूर आदिवासी गांव को आजादी के 70 साल बाद 2018 में ही बिजली मिली।

7.5 ऐसी कई कहानियाँ हैं जहाँ आम नागरिकों को सरकार के कल्याण के लिए सशक्त बनाने वाले दृष्टिकोण का लाभ मिल रहा है। भारत के पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ, औसत भारतीयों का जीवन एक दशक पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10.3 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, 52.6 करोड़ जन धन खाते खोले गए हैं, पीएम-आवास योजना के तहत गरीब लोगों के लिए 3.47 करोड़ पक्के घर बनाए गए हैं, जल जीवन मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरों में नल का जल कनेक्शन दिया गया है और आयुष्मान भारत योजना के तहत 6.9 करोड़ अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इन संख्याओं के पीछे बेहतर जीवन की कई कहानियाँ छिपी हैं।

7.6 भारत का सामाजिक और आर्थिक परिवेश कई ताकतें, अवसर और चुनौतियां प्रस्तुत करता है। इसकी ताकतों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को गिना जा सकता है, जो सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण और विस्तार के माध्यम से अपने लोगों को कल्याण और अवसर प्रदान करने में बड़ी प्रगति कर रही है। अवसर इस तथ्य में परिलक्षित होते हैं कि भारत की औसत आयु 28.2 वर्ष है,[5] और 18 प्रतिशत आबादी 15-24 वर्ष की आयु वर्ग में है (वैश्विक औसत 15.4 प्रतिशत की तुलना में)। युवा भारत सामाजिक और वित्तीय प्रगति की सीढ़ी तेजी से चढ़ना चाहता है। इन ताकतों और अवसरों को स्कूलों में सीखने के परिणामों में सुधार, कुपोषण को खत्म करने, अंतर्देशीय क्षेत्रों की क्षमता को दिशा देने, क्षेत्रीय, जाति और लिंग असमानताओं से निपटने और सरकार के सभी स्तरों पर जवाबदेही और पारदर्शिता स्थापित करने सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों से भी संतुलित किया जाता है। सीमित राजकोषीय संसाधनों के मद्देनजर, उभरते सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में जनता की अपेक्षाओं के लिए एक संवेदनशील, व्यावहारिक और विवेकपूर्ण कल्याणकारी नीति की आवश्यकता है।

5 संयुक्त राष्ट्र, विश्व जनसंख्या संभावनाएँ (2022), https://ourworldindata.org/grapher/population-by-agegroup

7.7 इसके लिए दृष्टिकोण को दीर्घकालिक, कुशल और सशक्त बनाने वाले दृष्टिकोण में बदलना आवश्यक था, जो समावेशी विकास के लिए एक शुरुआत के रूप में बुनियादी सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच पर केंद्रित था, इस प्रकार प्रमुख पहलों की एक श्रृंखला को प्रेरित किया। दुर्लभ संसाधनों के बार-बार वितरण की आवश्यकता वाले अल्पकालिक उपायों के विपरीत, ऐसा दृष्टिकोण न केवल आने वाले दशकों के लिए सामाजिक बुनियादी ढाँचा तैयार करता है, बल्कि व्यक्तियों को जीवन स्तर की सीढ़ी पर चढ़ने और विकास के साथ आने वाले अवसरों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। नागरिकों को सामाजिक रूप से सशक्त बनाना सामाजिक संबंधों और सिद्धांतों को बदलकर स्वायत्तता और आत्मविश्वास की भावना पैदा करता है ताकि समाज के अब तक बहिष्कृत वंचित वर्ग भी दुनिया में जगह पा सकें। लोगों को कल्याण के ट्रेडमिल से विकास के ट्रेडमिल पर लाना केवल वित्तीय दूरदर्शिता का मामला नहीं है। जब जनता के सदस्य कल्याण-निर्भरता से दूर होकर विकास में भाग लेते हैं और योगदान देते हैं, तो आत्म-सम्मान और व्यक्तिगत गरिमा बढ़ जाती है। जैसा कि रमा बीजापुरकर ने कहा है, सामाजिक रूप से वंचित लोगों के बीच भी, "एक विशिष्ट और बढ़ता हुआ वर्ग है, जो नेटवर्क, सूचना, सरकारी सहायता और व्यक्तिगत परिस्थितियों के संयोजन से, बेहतर जीवन के अवसरों की तलाश करने के लिए प्रयास करने की क्षमता और ऊर्जा पाता है।"[6]

नए कल्याणकारी दृष्टिकोण के आधार

7.8 नए कल्याणकारी दृष्टिकोण में यह बात ध्यान में रखी गई है कि केवल खर्च करने से परिणाम की गारंटी नहीं मिल सकती। यह सरकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता को बदलने पर जोर देता है, जिससे खर्च किए गए प्रति रुपये का प्रभाव बढ़ता है। अकादमिक साहित्य में भी लागत-प्रभावशीलता पर तेजी से ध्यान दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए, मुरलीधरन (2024)[7] का अनुमान है कि जब तक खर्च को परिणामों में बदलने की दक्षता में पर्याप्त सुधार नहीं किया जाता, तब तक न तो वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है और न ही विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है (अर्थात, सामाजिक क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन में वृद्धि) जिससे बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने, स्कूलों में सीखने की प्रक्रिया में सुधार करने, शिशु मृत्यु दर को कम करने में संतोषजनक परिणाम मिल सकते हैं। इस उद्देश्य से, सरकार प्रक्रिया सुधारों और जवाबदेही पर जोर दे रही है, जो प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ जुड़ी हुई है।

7.9 स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शासन का डिजिटलीकरण कल्याणकारी कार्यक्रम पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपए के लिए एक बल गुणक रहा है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना और जन धन योजना-आधार-मोबाइल (जेएएम) ट्रिनिटी राजकोषीय दक्षता और रिसाव को कम करने में सहायक रही है, 2013 में इसकी शुरुआत के बाद से डीबीटी के माध्यम से 38 लाख करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए गए हैं।[8]

7.10 सरकार ने बजटीय आबंटन के लिए एक लक्ष्य-उन्मुख दृष्टिकोण तंत्र भी लागू किया गया है, जिसमें योजनाओं के अपेक्षित आउटपुट और परिणाम शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2018 से पारंपरिक वार्षिक बजट के साथ आउटकम बजट भी शामिल किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020 से नीति आयोग द्वारा प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 'आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क' विकसित किया गया है। इसके अलावा, सामाजिक सेवा व्यय के भीतर पूंजीगत व्यय में तेजी से उत्पादकता और सामाजिक परिसंपत्तियों के निर्माण में वृद्धि का संकेत मिलता है। यह प्रमुख योजनाओं में सर्वव्यापी, उपयोगकर्ता के अनुकूल डैशबोर्ड और प्रबंधन सूचना प्रणालियों (एमआईएस) की पृष्ठभूमि में स्थापित किया गया था, जो साथ-साथ निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। बॉक्स VII.1 शासन में डेटा के बढ़ते महत्व पर गहराई से चर्चा करता है।

6 'दो भारत की नई कहानी', बिजनेस स्टैंडर्ड, 25 जून 2024 https://tinyurl.com/35p9ukf8

7 मुरलीधरन, कार्तिक। 2024. भारत के विकास को गति देना: प्रभावी शासन के लिए राज्य-नेतृत्व वाली रोडमैप। पेंगुइन इंडिया वाइकिंग, आईएसबीएन: 9780670095940, अध्याय 10।

8 15 जुलाई 2024 तक, स्रोत: https://dbtbharat.gov.in/

बॉक्स VII.1: भारत में डेटा गवर्नेंस में बदलाव: डीजीक्यूआई 2.0 और उससे आगे

पिछले कुछ दशकों में, भारत सरकार ने डेटा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और उपयोग करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हाल के दशकों में एमआईएस और सुगमता राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और पहुंच नीति और data.gov.in जैसी नीतियों के माध्यम से केंद्रीकृत डेटा एक्सेस के साथ डिजिटल परिवर्तन देखा गया है। जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियाँ (दिशा), प्रयास और आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क जैसे डैशबोर्ड सिस्टम और प्लेटफॉर्म ने सार्वजनिक नीति में जवाबदेही में सुधार किया है।

आज, अधिकांश सरकारी कार्यक्रम आंतरिक एमआईएस का उपयोग करते हैं जो विशाल मात्रा में डेटा को कैप्चर करते हैं। आज के डिजिटल युग में, इस डेटा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना, निर्णय लेने के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि निकालना, पाठ्यक्रम सुधारों की सुविधा प्रदान करना और सरकारी डेटा इकाइयों में अंतर-संचालन सुनिश्चित करना, विकसित भारत की दिशा में भारत की डेटा रणनीति के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। यह निर्णय लेने के लिए डेटा की उपलब्धता को बढ़ाएगा और सरकारी सेवाओं तक पहुँचने वाले लाभार्थियों के लिए एक सहज अनुभव के लिए सिस्टम इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देगा।

इस संदर्भ में, आगे की राह तय करने और सुधार के उपाय सुझाने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों (एम/डी) की वर्तमान डेटा तैयारी के स्तर की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता थी। इस पृष्ठभूमि में, विभिन्न एम/डी की डेटा तैयारी का आकलन करने के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई) अभ्यास शुरू किया गया था ताकि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके और सर्वोत्तम प्रथाओं से सहकारी सहकर्मी सीखने को बढ़ावा दिया जा सके।

चार्ट: डीजीक्यूआई के घटक

यह अभ्यास समय-समय पर आयोजित किया जाता है, जहां मंत्रलयों से डीजीक्यूआई डैशबोर्ड पर एक मानक प्रश्नावली के उत्तर मांगे जाते हैं। यह अभ्यास एक रिपोर्ट है जिसमें सभी एम/डी और उनकी योजनाओं की रैंकिंग शामिल हैं, जो आगे सुधार और सीखने के लिए विश्लेषण प्रदान करती है। सूचकांक 2020 में पहले दौर में 2.29/5 से बढ़कर नवीनतम दौर में 3.95/5 हो गया है, यानी, लगभग 75 एम/डी और 567 हस्तक्षेप/योजनाएं शामिल हैं।

आशा है कि दीर्घकाल में डीजीक्यूआई सभी एम/डी की सभी सीएस/सीएसएस योजनाओं की मजबूत, डाटा निगरानी प्रणाली, की नींव रखने में सहायक होगा जिससे अंततः अत्याधुनिक डेटा-संचालित निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा।

7.11 इस दृष्टिकोण में अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने के लिए लक्षित कार्यान्वयन सुधार भी शामिल हैं, ताकि "कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे" के सिद्धांत को सही मायने में साकार किया जा सके। आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी), सरकार के विभिन्न स्तरों पर 'अभिसरण', नागरिक समाज और सरकार के बीच 'सहयोग', तथा मासिक प्रगति की निगरानी करने वाले डैशबोर्ड के माध्यम से राज्यों और जिलों के बीच 'प्रतिस्पर्धा' के 3सी दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा जैसे कई संकेतकों में पर्याप्त सुधार हुआ है तथा बिजली कनेक्शन, सभी मौसम के अनुकूल सड़कें, बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं आदि जैसे बुनियादी ढांचे में संतृप्ति की रिपोर्टिंग हुई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा कार्यक्रम के मूल्यांकन में निष्कर्ष निकाला गया कि कार्यक्रम के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय विकास और शासन और प्रशासन में सुधार हुआ है।[9] बॉक्स VII.2 एडीपी की सफलता के दो उदाहरण प्रस्तुत करता है। अन्य लक्षित कार्यक्रमों में 2023 में शुरू किया जाने वाला आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए जीवंत गांव कार्यक्रम, और हाल ही में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा शामिल है, जिसमें 15 नवंबर 2023 से शुरू होकर दो महीनों में 15 करोड़ लोगों की भागीदारी देखी गई, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं की संतृप्ति के लिए अतिरिक्त प्रयास के अन्य उदाहरण हैं।

बॉक्स VII.2: बारामूला और गुमला की 'आकांक्षा' से 'परिवर्तन' की ओर प्रगति

जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला और झारखंड के गुमला जिलों ने एडीपी श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित पीएम पुरस्कार 2022 जीता। गुमला और बारामूला में की गई पहल एडीपी के तहत लक्षित हस्तक्षेपों के परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाती है, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

बारामूला ने अपनी चुनौतीपूर्ण स्थलाकृति और खराब मौसम की उरी और बोनियार में प्रसव प्रतीक्षा वार्ड स्थापित करके, स्थितियों का निपटान किया जिससे 20,000 गर्भवती महिलाओं को लाभ हुआ। पोषण ट्रैकर टैब के साथ निगरानी के माध्यम से गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) और एमएएम की दर लगभग शून्य स्तर तक गिर गई। शैक्षिक पहलों में 18 प्रयोगशाला स्कूल शामिल थे जो नवीन शिक्षण तकनीकों और सीखने के परिणामों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते थे। हाइब्रिड लर्निंग और आईसीटी टूल्स ने छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया। अन्य प्रयासों में फसल विविधीकरण, मशरूम की खेती, जैविक खेती और डेयरी इकाइयाँ शामिल थीं। शासन उपायों में डिजिटल गैप विश्लेषण, बायोमेट्रिक उपस्थिति और शिक्षा के लिए एक नवाचार सेल शामिल थे।

9 आकांक्षी जिला कार्यक्रमः एक मूल्यांकन, यूएनडीपी, दिसंबर 2020, https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-03/Aspirational-Districts-Programme-An-Appraisal.pdf पर उपलब्ध , 18 जून 2024 को अभिगमित किया गया

गुमला ने रागी की खेती को बढ़ावा देकर एनीमिया और कुपोषण की समस्या का समाधान किया, आजीविका के अवसरों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में महिलाओं को सशक्त बनाया। इस पहल ने जिले की कम आय, खराब उत्पादकता और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की कमी की चुनौतियों का समाधान किया है। आदिवासी महिलाओं ने रागी की खरीद, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन को संभाला। शासन की पहलों में सार्वजनिक शिकायतों के लिए एक ओपन डोर की नीति, नियमित बैठकें और इष्टतम निधि आवंटन शामिल थे। अभिनव रागी मिशन ने रागी की खेती के क्षेत्र को 3500 एकड़ तक बढ़ाकर स्थिर मोनोक्रॉपिंग प्रथा को तोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2021-22 में उत्पादन में 219 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 4349 एकड़ से अधिक क्षेत्र को कवर करने वाली सौर-आधारित लिफ्ट और ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्षेत्र में पूरे साल कृषि पद्धति सुनिश्चित करती है।

7.12 कल्याण के प्रति इस परिवर्तित दृष्टिकोण में सामाजिक सक्षमताओं को प्राथमिकता देना भी शामिल है। तदनुसार, स्वास्थ्य और स्वच्छता में निवेश पर जोर दिया गया। उदाहरण के लिए, मिशन इंद्रधनुष के तहत बाल टीकाकरण और ओडीएफ और ओडीएफ प्लस और स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्वच्छता उपाओं के कारण कम बीमारी की घटनाओं, बीमारी के कारण स्कूल से कम अनुपस्थिति और कम सुविधा प्राप्त लोगों के बीच लंबे समय में अधिक प्रभावी पोषक तत्व अवशोषण को बढ़ावा दिया है। पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के अनुसार, 12-23 महीने की आयु के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण 2015-16 में 77.9 प्रतिशत से बढ़कर 2019-21 में 83.8 प्रतिशत हो गया।

7.13 देश की जनसांख्यिकी और व्यवसाय प्रोफाइल को देखते हुए सरकार की एक और नीति असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ प्रदान करना रही है। अटल पेंशन योजना (एपीवाई), पीएम जीवन ज्योति योजना (पीएमजेएवाई), और पीएम सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (तीनों को 2015 में लॉन्च किया गया) सार्वभौमिक बैंक खाता पैठ से सुसज्जित एक विस्तारित सामाजिक सुरक्षा जाल की सफलता की कहानियाँ हैं। जबकि पीएम-जेजेवाई और पीएम-एसबीवाई अपनी तरह की पहली योजनाएँ थीं, एपीवाई ने अपने पूर्ववर्ती, स्वावलंबन योजना की तुलना में उल्लेखनीय सुधार किया।

7.14 कल्याण के प्रति दृष्टिकोण समग्र और समाज के लिए है, जिसमें कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है। वर्ष 2014 में, कंपनी अधिनियम, 2013[10] की धारा 135 के तहत एक नए प्रावधान के माध्यम से सामाजिक उद्देश्य कार्यक्रमों पर कंपनियों द्वारा खर्च करना अनिवार्य कर दिया गया था। 2014 के बाद सीएसआर खर्च की प्रवृत्ति का विवरण बॉक्स टप्.3 में प्रस्तुत किया गया है। अर्थव्यवस्था के मजबूत विकास के साथ, भारत में कॉर्पोरेट मुनाफे और, इसलिए, अनिवार्य सीएसआर पूल में वृद्धि जारी रहेगी, जिससे सतत और समावेशी विकास को बल मिलेगा, जिसे गैर-लाभकारी संगठन जमीनी स्तर पर अपनी अंतिम-मील उपस्थिति के साथ गति देने के लिए विशिष्ट रूप से स्थित हैं।

10 सीएसआर पर कानूनी अधिदेश उन कंपनियों पर लागू होता है जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या वार्षिक कारोबार 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या निवल लाभ 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है। सीएसआर अधिदेश के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत सामाजिक प्रभाव कार्यक्रमों पर खर्च करना आवश्यक है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची टप्प में सूचीबद्ध किसी भी कारण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

बॉक्स VII.3: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व - लाभ और उद्देश्य के बीच सेतु का निर्माण

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के आंकड़ों के अनुसार सीएसआर गतिविधियों की सीमा के कुछ रुझान नीचे प्रस्तुत हैं।

(क) 2014 से 2022 तक के आठ वर्षों में सीएसआर पर 1.53 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए और पिछले तीन वर्षों में खर्च सीएसआर की शुरुआत से अब तक खर्च की गई कुल राशि का 50 प्रतिशत से अधिक है। पिछले कुछ वर्षों में सीएसआर अनुपालन में वृद्धि देखी गई है, जिसमें आधी से अधिक कंपनियां अपने दायित्व से भी आगे निकल गई हैं। पिछले तीन वर्षों से सालाना सीएसआर खर्च 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक रहा है, जिसमें आठ वर्षों में सालाना सीएसआर खर्च 1.5 गुना बढ़ा है।[11]

चार्ट VII.1: (क) भारत में वार्षिक सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)

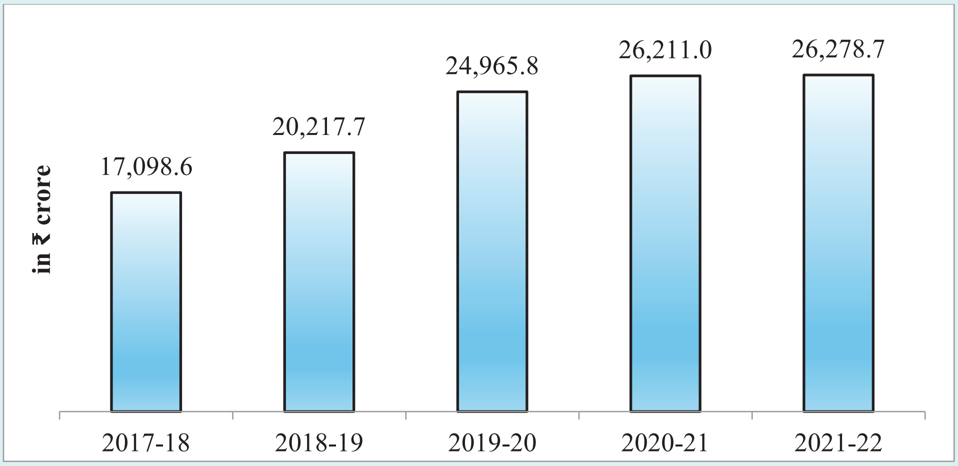

स्रोत: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का वेब पोर्टल https://www.mca.gov.in/content/csr/global/master/home/home.html

चार्ट VII.1: (ख) कुल सीएसआर व्यय: शीर्ष पांच राज्य, वित्तीय वर्ष 22

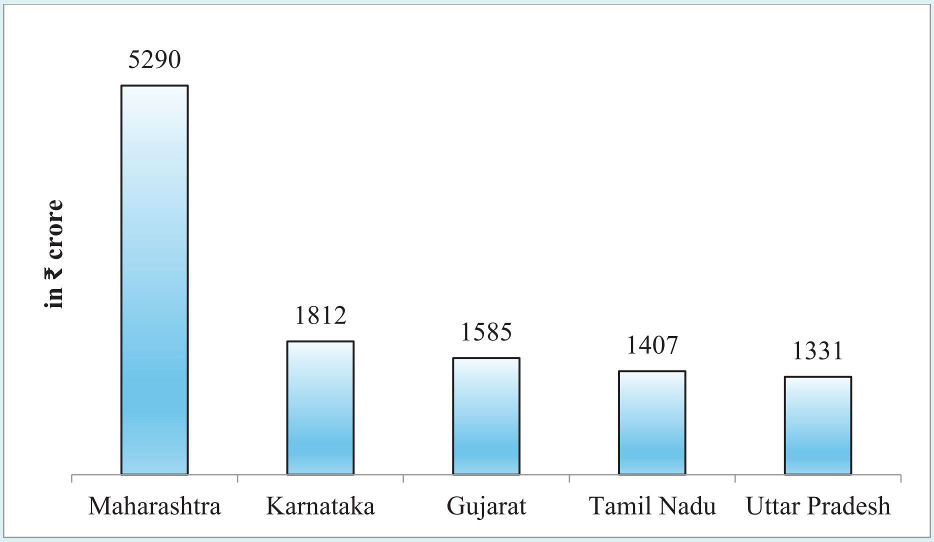

स्रोत: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का वेब पोर्टल https://www.mca.gov.in/content/csr/global/master/home/home.html

11 स्रोत: इंडिया डेटा इनसाइट्स, सत्व कंसल्टिंग https://indiadatainsights.com/theme/csr-in-india/

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, सीएसआर अधिदेश के अंतर्गत आने वाली कंपनियों का लगभग 2 प्रतिशत हिस्सा हैं, तथा वे कुल सीएसआर राशि में लगभग 17 प्रतिशत का योगदान देती हैं।

(ग) क्षेत्रवार, कुल सीएसआर व्यय का तीन-चौथाई से अधिक हिस्सा शीर्ष चार विकास क्षेत्रों में है, अर्थात शिक्षा (32.4 प्रतिशत), स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता (38.4 प्रतिशत), ग्रामीण विकास (6.9 प्रतिशत), और पर्यावरण, पशु कल्याण और संरक्षण (10.9 प्रतिशत)।

(घ) सीएसआर फंड का लगभग आधा कार्यान्वयन गैर-लाभकारी संगठनों के साथ साझेदारी में होता है। कंपनियों द्वारा अपनाए गए इस कार्यान्वयन मॉडल ने देश में गैर-लाभकारी पारिस्थितिकी तंत्र को एक उत्कृष्ट बढ़ावा दिया है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विचारों के क्रॉस-पॉलिनेशन को सक्षम किया है। जबकि गैर-लाभकारी संस्थाएँ साझेदार कंपनियों से विश्लेषणात्मक और प्रक्रिया-आधारित कठोरता सीखती हैं, बाद वाली कंपनियों को समाज के कॉर्पोरेट नागरिकों के रूप में सामुदायिक जुड़ाव और समावेशी दृष्टिकोण से लाभ हुआ है।

(ङ) सीएसआर निवेश का वितरण मुख्य रूप से देश में कॉर्पोरेट मुख्यालयों के केंद्रों के आसपास केंद्रित है, जबकि अविकसित क्षेत्रों में अपर्याप्त वित्त पोषण है। आकांक्षी जिलों में सीएसआर खर्च बहुत कम है, और इसका आधा हिस्सा पीएसयू से आता है। क्षेत्रीय रूप से संतुलित सीएसआर खर्च के लिए, अविकसित क्षेत्रों में काम करने वाले गैर-लाभकारी संगठनों के संगठनात्मक विकास और क्षमता निर्माण में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।

समग्र प्रगति और परिणाम

बहुआयामी गरीबी में सुधार

7.15 केवल आय पर ध्यान केंद्रित करना गरीबी की वास्तविक सत्यता को पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह हर दिन लाखों व्यक्तियों द्वारा अनुभव की जाने वाली सटीक वंचना को छिपा सकता है। यहाँ, बहुआयामी गरीबी का माप गरीबी की घटना और तीव्रता को मापने के लिए मूल्यवान है क्योंकि यह बताता है कि कौन गरीब है और वे किस तरह के विभिन्न नुकसानों का अनुभव करते हैं।

7.16 नीति आयोग द्वारा भारत के लिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) का अनुमान लगाया गया है, जो[12] यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित वैश्विक एमपीआई के अनुरूप है, जिसमें भारतीय संदर्भ के लिए कुछ अनुकूलन हैं।[13] नीति आयोग द्वारा अनुमानित एमपीआई में तीन समान रूप से भारित आयाम हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, जो 12 भारित संकेतकों में विभाजित हैं। ये अभाव बहुत बुनियादी हैं और इसलिए, वास्तविक गरीबी के प्रतीक हैं, साथ ही नीति निर्माताओं को देश में अभावों के बारे में भी बताते हैं।[14]

7.17 जबकि हेडकाउंट अनुपात बहुआयामी गरीबी के प्रसार को मापता है, वंचना स्कोर बहुआयामी गरीबी की तीव्रता को मापता है (अर्थात, एक गरीब व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए वंचना की संख्या)। एमपीआई-गरीब के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक परिवार के लिए 0.33 का भारित वंचना स्कोर आवश्यक है। इस प्रकार एमपीआई सूचकांक हेडकाउंट अनुपात (एचसीआर) और तीव्रता के उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है।

एमपीआई में भारत की प्रगति: 2019-21 बनाम 2015-16

7.18 एचसीआर अनुपात में तीव्र गिरावट आई है, साथ ही गरीबी की तीव्रता में भी कमी आई है, एमपीआई 2015-16 में 0.117 से लगभग आधा घटकर 2019-21 में 0.066 हो गया है, जिससे भारत 2030 की निर्धारित समय-सीमा से बहुत पहले एसडीजी लक्ष्य 1.2 (बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधे से कम करने) को प्राप्त करने के मार्ग पर

12 https://hdr.undp.org/content/2023-global-multidimensional-poverty-index-mpi#/indicies/MPI

13 https://www.niti.gov.in/index.php/whats-new/national-multidimentional-poverty-index-2023

14 इस सूचकांक को विकसित करने के लिए उल्किरे-फोस्टर पद्धति को अपनाया गया है। इसमें कई स्वयंसिद्ध लाभ हैं जैसे कि एकरसता, पैमाना और प्रतिकृति अपरिवर्तनशीलता, समरूपता, गरीबी और अभाव फोकस, आदि, जो इसे विश्व स्तर पर स्वीकृत पद्धति बनाते हैं। यह यूएनडीपी और ओपीएचआई द्वारा वैश्विक एमपीआई के समान ही है, जिसमें एमएफएचएस के आंकड़ों का उपयोग करते हुए 2 अतिरिक्त संकेतक, यानी मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता शामिल हैं।

अग्रसर है। परिणामस्वरूप, अनुमान है कि 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह गिरावट पोषण, स्कूली शिक्षा के वर्षों, स्वच्छता और खाना पकाने के ईंधन में वंचन में कमी के कारण हुई है, जो बड़े पैमाने पर नीतिगत ध्यान के कारण है। क्षेत्रवार, यह प्रवृत्ति ग्रामीण भारत द्वारा संचालित है, जिसमें बिहार, एमपी, यूपी, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई, जहां 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। उल्लेखनीय रूप से, बहुआयामी गरीबी में रहने वाले 10 प्रतिशत से कम लोगों वाले राज्यों की संख्या 2016 में 7 से बढ़कर 2021 में 14 हो गई।

चार्ट VII.2: बहुआयामी गरीबी में कमी

(क) बहुआयामी गरीबी का हैडकाउंट अनुपात

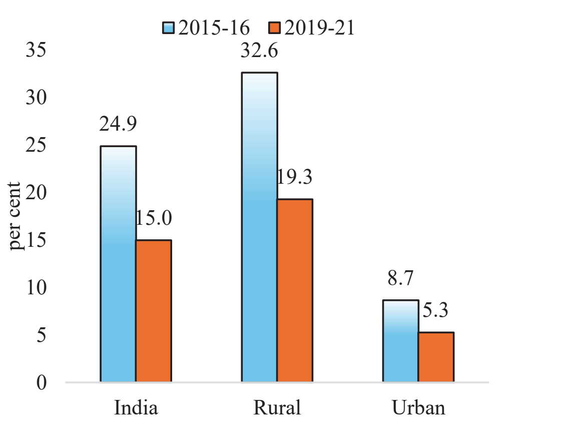

(ख) बहुआयामी गरीबी की तीव्रता

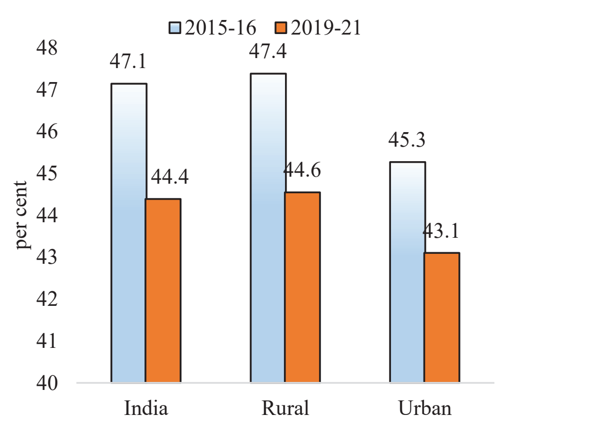

स्रोत: नीति आयोग एमपीआई रिपोर्ट 2023

चार्ट VII.3: बहुआयामी गरीब आबादी में अभावों में कमी

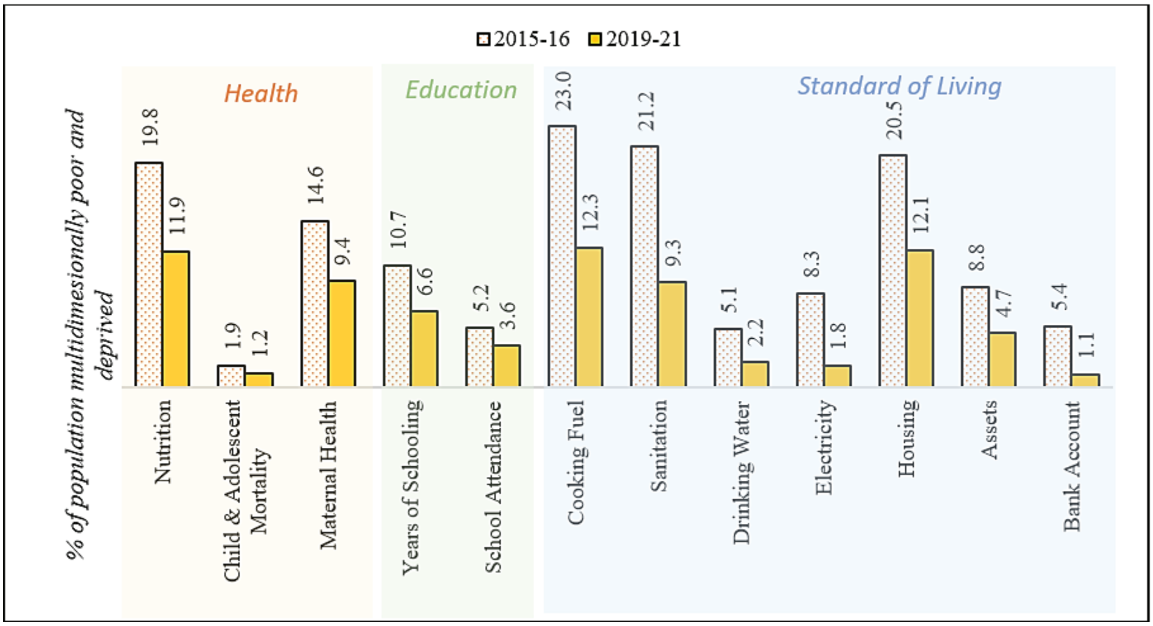

स्रोत: नीति आयोग एमपीआई रिपोर्ट 2023

7.19 नीति आयोग के परिचर्चा पत्र, 'भारत में 2005-06 से बहुआयामी गरीबी'[15] में पाया गया है कि 2013-14 और 2022-23 के बीच 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। 2013-14 और 2022-23 में गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए, इन विशिष्ट अवधियों के लिए डेटा सीमाओं के कारण परिवर्तन की चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर आधारित प्रक्षेपित अनुमानों का उपयोग किया गया है। नीति आयोग के पेपर के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी में व्यक्तियों के अनुपात में 2013-14 में 29.17 प्रतिशत से 2022-23 में 11.28 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है, अर्थात 17.89 प्रतिशत अंकों की कमी।

7.20 पेपर में यह भी बताया गया है कि यूपी में गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जहाँ पिछले नौ वर्षों के दौरान 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, इसके बाद बिहार में 3.77 करोड़, एमपी में 2.30 करोड़ और राजस्थान में 1.87 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। कुल मिलाकर, 2015-16 और 2019-21 के बीच गरीबी एचसीआर में गिरावट (10.66 प्रतिशत वार्षिक दर) 2005-06 से 2015-16 (7.69 प्रतिशत कमी की वार्षिक दर) की तुलना में बहुत तेज थी।

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23

7.21 सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न पहलों के परिणाम असमानता में कमी और उपभोग व्यय में वृद्धि के रूप में सामने आए हैं, जैसा कि 24 फरवरी 2024 को जारी नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) 2022-23 (अगस्त 2022 से जुलाई 2023 तक आयोजित) के परिणामों से स्पष्ट है।[16] परिणाम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर के मौद्रिक पहलू के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जिसका अनुमान मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के रूप में लगाया जाता है। परिणाम मोटे तौर पर नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट में जीवन स्तर में पर्याप्त वृद्धि की पुष्टि करते हैं।

7.22 एचसीईएस ने पिछले दशक में समावेशी विकास पर कई निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। 2022-23 में एमपीसीई वास्तविक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 2011-12 की तुलना में 40 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 33.5 प्रतिशत बढ़ा है। असमानता का सूचक गिनी गुणांक ग्रामीण क्षेत्र के लिए 0.283 से घटकर 0.266 और देश के शहरी क्षेत्र के लिए 0.363 से घटकर 0.314 हो गया है। ग्रामीण-शहरी विभाजन में भी काफी कमी आई है, क्योंकि ग्रामीण और शहरी एमपीसीई के बीच का अंतर 2011-12 में 83.9 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 71.2 प्रतिशत हो गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, एमपीसीई आबादी के सबसे निचले 5 प्रतिशत वर्ग की खपत शीर्ष 5 प्रतिशत वर्ग की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी, जो पिछले दशक में आर्थिक असमानता में गिरावट का संकेत है। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली मुफ्त वस्तुओं के आरोपण से एमपीसीई में और अधिक प्रगतिशील वृद्धि होती है, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एमपीसीई के अनुपात के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में शीर्ष 5 प्रतिशत वर्ग के लिए 0.8 प्रतिशत और सबसे निचले 5 प्रतिशत वर्ग के लिए 5.0 प्रतिशत है (शहरी क्षेत्रों के लिए, संबंधित आंकड़े क्रमशः 0.1 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत थे)। एमपीसीई संख्याओं को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (पीसीआई) के साथ तुलना करने पर आर्थिक विकास में एक समावेशी प्रवृत्ति का पता चलता है, जहां ग्रामीण भारत में शीर्ष 5 प्रतिशत और शहरी भारत में शीर्ष 10 प्रतिशत को छोड़कर सभी उपभोग वर्गों के लिए एमपीसीई/पीसीआई अनुपात में वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय रूप से, यह प्रगति कोविड-19 महामारी के संकट के बावजूद हुई।

15 https://tinyurl.com/f48k757c.
16 https://tinyurl.com/t8s5unut

चार्ट VII.4: एमपीसीई में सीएजीआर: 2011-12 से 2022-23

(क) वास्तविक और नाममात्र दोनों दृष्टियों से सकारात्मक वार्षिक वृद्धि

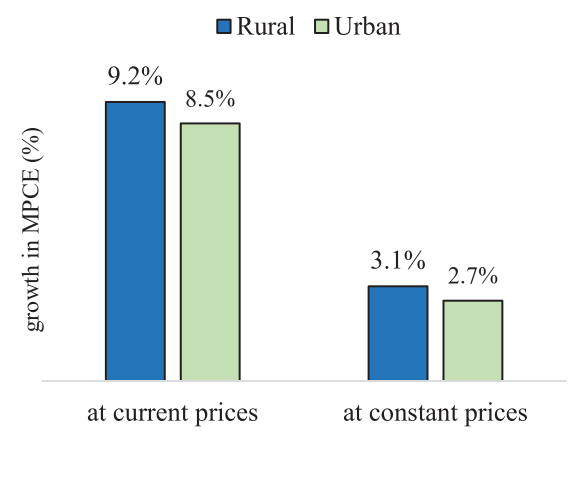

(ख) निचले 5% फ्रैक्टाइल में शीर्ष 5% फ्रैक्टाइल की तुलना में अधिक वृद्धि देखी गई

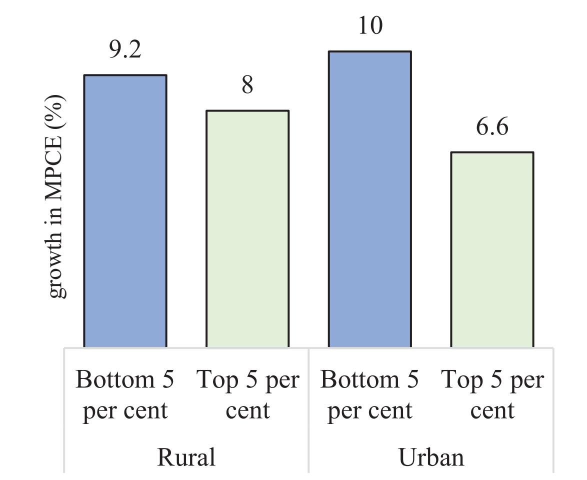

स्रोत: HCES 2022-23 की फैक्टशीट, MoSPI

सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा

7.23 मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। एक सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार दीर्घकालिक कारकों से जुड़ी हुई है, जैसे कि मानव पूंजी और श्रम उत्पादकता की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, घरेलू बचत, स्वास्थ्य व्यय के कारण गरीबी के जाल से बचना और कोविड-19 जैसे स्वास्थ्य झटकों का सामना करने की क्षमता का निर्माण करना। इसी भावना से, भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली को लगातार नया रूप दिया गया है।

7.24 सभी आयु वर्गों के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रही है। प्रमुख पहल और उनकी प्रगति तालिका VII.2 में सूचीबद्ध हैं।

तालिका VII.2: प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएं

कार्यक्रम/उद्देश्य (प्रारंभ का वर्ष)	प्रगति/परिणाम
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) (2018) अस्पताल में भर्ती के लिए वंचित परिवारों को ₹5 लाख/वर्ष का स्वास्थ्य बीमा कवर	• 34.73 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए • इस योजना के अंतर्गत 7.37 करोड़ अस्पताल में भर्ती हुए। • 49 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं (8 जुलाई, 2024 तक)[17]
पीएम जन औषधि केंद्र गुणवत्तापूर्ण दवाइयां बाजार मूल्य से 50-90 प्रतिशत सस्ती	• एम्स देवघर में 10,000 वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। • 1965 दवाइयां और 293 सर्जिकल उपकरण उपलब्ध

17 https://dashboard.pmjay.gov.in/pmj/#/

कार्यक्रम/उद्देश्य (प्रारंभ का वर्ष)	प्रगति/परिणाम
अमृत (उपचार के लिए सस्ती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण) गंभीर बीमारियों के लिए सब्सिडी वाली दवाइयाँ	विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 300 से अधिक अमृत फार्मेसियां संचालित
आयुष्मान भव: अभियान (सितंबर 2023) प्रत्येक गांव/कस्बे में चयनित स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना तथा नागरिकों को सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में सूचित करना।	• 16.96 लाख लोगों ने स्वास्थ्य, योग, ध्यान, सत्र, 1.89 करोड़ टेली परामर्श, 11.64 करोड़ लोगों ने मुफ्त दवाइयां और 9.28 करोड़ लोगों ने मुफ्त निदान सेवाओं का लाभ उठाया • एएनसी[18] के तहत 82.10 लाख माताओं और 90.15 लाख बच्चों ने जांच और टीकाकरण का लाभ उठाया • सात प्रकार की जांच (टी.बी., उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुख कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर और मोतियाबिंद) का लाभ 34.39 करोड़ लोगों ने उठाया। • 2.0 करोड़ मरीजों ने सामान्य ओपीडी से परामर्श लिया, जबकि 90.69 लाख मरीजों ने विशेषज्ञ ओपीडी से परामर्श लिया, तथा 65,094 बड़ी सर्जरी और 1,96,156 छोटी सर्जरी की गई। • 13.48 करोड़ एबीएचए खाते खोले गए, 9.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए और 1.2 लाख आयुष्मान सभाएं आयोजित की गई। • 25.25 लाख स्वास्थ्य मेलों में कुल 20.66 करोड़ लोग आए (31 मार्च 2024 तक)
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) (2021) पूरे देश में एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना	• 64.86 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (एबीएचए) बनाए गए • 3.06 लाख स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्रियां • 4.06 लाख स्वास्थ्य पेशेवर • 39.77 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड एबीएचए से जुड़े[19]
ई-संजीवनी (2019) दूरदराज के क्षेत्रों में आभासी (वर्चुअल) डॉक्टर परामर्श के लिए टेलीमेडिसिन	• 15,857 केंद्रों के माध्यम से 1.25 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (प्रवक्ता के रूप में) पर 128 विशेषज्ञों के माध्यम से 26.62 करोड़ रोगियों को सेवा प्रदान की गई।[20] (9 जुलाई 2024 तक)

18 पूर्ण न्यूट्रोफिल गणना
19 स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी
20 https://esanjeevani.mohfw.gov.in/#/

मानसिक स्वास्थ्य परिदृश्य

7.25 मानसिक स्वास्थ्य कम दिखाई देने वाला तथापित व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास का प्रमुख रूप से प्रभावपूर्ण चालक है। बहुत पहले डा. ब्रॉक चिसहोम विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) के प्रथम महानिदेशक ने कहा था, ''मानसिक स्वास्थ्य के बिना शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं हो सकता।''

7.26 मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य के सभी पहलुओं, जैसे शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक, से जुड़ा हुआ है और इसे कल्याण की ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसमें व्यक्ति दैनिक जीवन के तनावों से निपटने में सक्षम होता है, उत्पादक बना रहता है और अपने समुदाय में योगदान देता है। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में मानसिक विकार और मनोसामाजिक अक्षमताएँ शामिल हैं, साथ ही मानसिक स्थितियाँ जो महत्वपूर्ण संकट, कामकाज में कमी या खुद को नुकसान पहुँचाने के जोखिम से जुड़ी हैं। मामूली तनाव से लेकर गंभीर विकारों तक, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ व्यक्तियों के पूरे जीवनकाल में प्रभाव डाल सकती हैं।

मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बढ़ता प्रचलन

7.27 डब्ल्यूएचओ के अनुसार, 2019 में,[21] हर आठ में से एक व्यक्ति या वैश्विक स्तर पर 970 मिलियन लोग मानसिक विकार से पीड़ित थे,[22] जिसमें चिंता और अवसाद सबसे आम स्थिति थी। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में वैश्विक स्तर पर प्रमुख भवसादग्रस्तता विकारों के मामलों में 27.6 प्रतिशत और चिंता विकारों के मामलों में 25.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।[23] हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा सह-नेतृत्व में किए गए एक बड़े पैमाने के अध्ययन के अनुसार, दुनिया में हर दो में से एक व्यक्ति अपने जीवनकाल में मानसिक स्वास्थ्य विकार से पीड़ित रहेगा (मैकग्राथ और अन्य 2023)।[24]

7.28 भारतीय संदर्भ में, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएमएचएस) 2015-16 से[25] पता चला है कि भारत में 10.6 प्रतिशत वयस्क मानसिक विकारों से पीड़ित हैं, जबकि मानसिक विकारों के लिए उपचार में अभाव विभिन्न विकारों के लिए 70 से 92 प्रतिशत के बीच है। इसके अलावा, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएमएचएस) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों (6.9 प्रतिशत) और शहरी गैर-मेट्रो क्षेत्रों (4.3 प्रतिशत) की तुलना में शहरी मेट्रो क्षेत्रों (13.5 प्रतिशत) में मानसिक रुग्णता का भार अधिक था। दूसरा और अधिक विस्तृत एनएमएचएस वर्तमान में प्रगति पर है। ध्यानी और अन्य (2022) के अनुसार, 25-44 वर्ष की आयु के व्यक्ति मानसिक बीमारियों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।[26]

बच्चों और युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य

7.29 बच्चों और किशोरों का अच्छा मानसिक स्वास्थ्य उनके समग्र विकास की नींव है और गुणवत्तापूर्ण आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शैक्षणिक दबाव, सोशल मीडिया, पारिवारिक गतिशीलता और सामाजिक-आर्थिक वातावरण के कारण युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बढ़ते प्रचलन के मद्देनजर

---

21 विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, https://www.who.int/health-topics/mentalhealth#tab=tab_1.

22 विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मानसिक विकार किसी व्यक्ति की अनुभूति, भावनात्मक विनियमन या व्यवहार में नैदानिक रूप से महत्वपूर्ण गड़बड़ी के कारण होता है।

23 कोविड-19 मानसिक विकार सहयोगी। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में 204 देशों और क्षेत्रों में अवसाद और चिंता विकारों का वैश्विक प्रसार और बोझ। लैंसेट। 2021 नवंबर 6;398(10312):1700-1712

24 मैकग्राथ, जॉन एट अल. मानसिक विकारों की शुरुआत की उम्र और संचयी जोखिम: 29 देशों के 156,331 उत्तरदाताओं पर आधारित जनसंख्या सर्वेक्षण डेटा का एक क्रॉस-नेशनल विश्लेषण, द लैंसेट साइकियाट्री, खंड 10, अंक 9, 2023, पृष्ठ 668-681, आईएसएसएन 2215-0366,

25 भारतीय राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2015-16: मानसिक स्वास्थ्य प्रणालियाँ। बेंगलुरु, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, निमहंस प्रकाशन संख्या 130, 2016

26 ध्यानी ए, गैधाने ए, चौधरी एसजी, दवे एस, चौधरी एस. भारत में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में प्रतिक्रिया को मजबूत करना: एक कथात्मक समीक्षा। क्यूरियस। 2022 अक्टूबर 18;14(10):e30435

यह अत्यावश्यक हो जाता है। वैश्विक स्तर पर, 10–19 वर्ष के बच्चों में से सात में से एक मानसिक विकार से पीड़ित है (WHO 2021)।[27] यूनिसेफ की चेंजिंग चाइल्डहुड रिपोर्ट के लिए गैलप द्वारा किए गए शोध के अनुसार, 21 देशों में 15 से 24 वर्ष के 19 प्रतिशत लोगों ने 2021 की पहली छमाही में स्वयं रिपोर्ट किया कि वे अक्सर उदास महसूस करते हैं या उन्हें काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है।[28]

7.30 भारत में, एनसीईआरटी के स्कूली छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण सर्वेक्षण से[29] पता चला है कि किशोरों में खराब मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता जा रहा है, जो कोविड–19 महामारी के कारण और बढ़ गया है। 11 प्रतिशत छात्रों ने चिंता महसूस करने की बात कही, 14 प्रतिशत ने अत्यधिक भावुक होने का अनुभव किया और 43 प्रतिशत ने मनोदशा में उतार–चढ़ाव का अनुभव किया। 50 प्रतिशत छात्रों ने चिंता का कारण अध्ययन बताया और 31 प्रतिशत ने परीक्षा और परिणामों का हवाला दिया।

7.31 बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि अक्सर इंटरनेट और विशेष रूप से सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से जुड़ी होती है। बच्चों द्वारा इंटरनेट का अनियंत्रित और अपर्यनोमित उपयोग कई तरह की समस्याओं को जन्म दे सकता है, जिसमें सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग से लेकर[30] साइबरबुलिंग जैसी गंभीर स्थितियों तक शामिल हैं।[31] प्रसिद्ध अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक और लेखक जोनाथन हैडट ने अपनी पुस्तक 'द एंग्जियस जेनरेशन: हाउ द ग्रेट रीवायरिंग ऑफ चिल्ड्रन इज कॉजिंग एन एपिडेमिक ऑफ मेंटल इलनेस' में युवाओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर बढ़ते स्क्रीन टाइम और कम होते फ्री प्ले के प्रभाव की पड़ताल की है। सोशल मीडिया, अति सुरक्षात्मक पालन–पोषण और बच्चों के भावनात्मक कल्याण पर अनियंत्रित आउटडोर खेल के प्रभाव की चर्चा करते हुए, पुस्तक में बताया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों की महामारी ने 2010 के दशक की शुरुआत में मोबाइल फोन के आगमन के साथ दुनिया को प्रभावित किया। बचपन के इस 'ग्रेट रीवायरिंग ऑफ चाइल्डहुड' ने बच्चों के सामाजिक और तंत्रिका संबंधी विकास में हस्तक्षेप किया है, जिसमें नींद की कमी से लेकर ध्यान विखंडन, लत, अकेलापन, सामाजिक संसर्ग, सामाजिक तुलना और पूर्णतावाद तक सब कुछ शामिल है।

7.32 अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति ने सोशल मीडिया को तंबाकू के समान बताया और तकनीकी प्लेटफॉर्म पर चेतावनी लेबल लगाने का सुझाव दिया, उनका तर्क है कि ये किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य संकट को बढ़ावा दे रहे हैं। वे युवाओं को ऑनलाइन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने के लिए कानून बनाने की वकालत करते हैं।[32] हाल ही में, लॉस एंजिल्स यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने अपने 429,000 छात्रों के लिए स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया, ताकि उन्हें विचलित करने वाली चीजों, सोशल मीडिया और सीखने और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों से बचाया जा सके।[33] भारतीय संदर्भ में, मानसिक स्वास्थ्य पर इंटरनेट के बढ़ते उपयोग का संकेत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 'बच्चों द्वारा मोबाइल फोन और इंटरनेट पहुंच वाले अन्य

27 डब्ल्यूएचओ, नवंबर 2021, किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य https://tinyurl.com/37s3s5ku

28 यूनिसेफ (2021), द चेंजिंग चाइल्डहुड प्रोजेक्ट, यूनिसेफ, न्यूयॉर्क।

29 एनसीईआरटी (2022), स्कूली छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण – एक सर्वेक्षण, यहाँ उपलब्ध है: Mental_Health_WSS_A_Survey_new-pdf (ncert-nic-in) । सर्वेक्षण में देश भर के स्कूलों के सभी लिंगों, कक्षा VI-VIII (मध्य चरण) और IX-XII (माध्यमिक चरण) के छात्रों को शामिल किया गया। जनवरी से मार्च 2022 के बीच देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 3,79,013 छात्रों ने सर्वेक्षण में भाग लिया।

30 ओलिविन, ए. (2023, 27 जून)। डूमस्क्रॉलिंग: परिभाषा, प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य सहायता। वेरीवेल हेल्थ। https://www.verywellhealth.com/doomscrolling-7503386

31 साइबरबुलिंग को एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या माना जाता है, जो किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और विकास से निकटता से संबंधित है। ऑनलाइन बदमाशी करने वालों में अवसाद, चिंता और अकेलेपन के गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं। आत्म-सम्मान के मुद्दे और स्कूल से अनुपस्थिति। देखें झू, सी., हुआंग, एस., इवांस, आर., और झांग, डब्ल्यू. (2021)। किशोरों और बच्चों के बीच साइबरबुलिंग: वैश्विक स्थिति, जोखिम कारकों और निवारक उपायों की एक व्यापक समीक्षा। फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ, 9(1)।

32 'क्या सोशल मीडिया नया तंबाकू है?', न्यूयॉर्क टाइम्स, 17 जून 2024 https://tinyurl.com/5n8y96r8

33 ट्रोट्टा, टी., और ओ'ब्रायन, बी., 19 जून 2024, "लॉस एंजिल्स स्कूल बोर्ड ने स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए वोट किया", रॉयटर्स https://www.reuters.com/world/us/los-angeles-schools-consider-ban-smartphones-2024-06-18/

उपकरणों के उपयोग के प्रभाव' पर 2021 के एक अध्ययन से मिला है, जिसके अनुसार 23.8 प्रतिशत बच्चे बिस्तर पर रहते हुए स्मार्ट फोन का उपयोग करते हैं और 37.2 प्रतिशत बच्चे स्मार्ट फोन के उपयोग के कारण एकाग्रता के स्तर में कमी का अनुभव करते हैं।[34]

अर्थशास्त्र के नजरिए से मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे

7.33 मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं और क्षमता के विकास को बाधित करती हैं। समग्र आर्थिक स्तर पर, मानसिक स्वास्थ्य विकार अनुपस्थिति, उत्पादकता में कमी, स्वास्थ्य सेवा लागत में वृद्धि आदि से होने वाली उत्पादकता हानि से जुड़े हैं।[35] मानसिक स्वास्थ्य से आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ने के साथ आर्थिक अभाव भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। गरीबी तनावपूर्ण जीवन स्थितियों, वित्तीय अस्थिरता, आर्थिक अवसरों की कमी के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को जोखिम में डालती है।[36] इसके अलावा, बढ़ता शहरीकरण और प्रवास सामाजिक सामंजस्य, पारंपरिक सहायता प्रणाली और स्थिरता को बाधित कर सकता है, जिससे काफी मानसिक तनाव हो सकता है (त्रिवेदी, सरीन और ध्यानी 2008)।[37]

7.34 विकास पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव को देखते हुए, उसमें निवेश पर रिटर्न भी अधिक है। 36 देशों में 2016 के एक अध्ययन के अनुसार, 2016-30 में अवसाद और चिंता के बड़े पैमाने पर उपचार के लाभ-लागत अनुपात का अनुमान केवल आर्थिक लाभों पर विचार करते हुए 2.3-3.0 गुना था, और 3.3-5.7 गुना जब स्वास्थ्य रिटर्न का मूल्य भी शामिल किया जाता है (चिशोलम और अन्य 2016)।[38] भारतीय संदर्भ में, मैथ और अन्य (2019) ने सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के कार्यान्वयन में निवेश पर रिटर्न का अनुमान 6.5 गुना लगाया है।[39]

सकारात्मक नीति कार्रवाई के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है

7.35 भारत मानसिक स्वास्थ्य को समग्र कल्याण के मूलभूत पहलू के रूप में मान्यता देते हुए नीति विकास में सकारात्मक गति पैदा कर रहा है। सरकार मानसिक स्वास्थ्य नीति (2014), राष्ट्रीय युवा नीति (2014) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) जैसी राष्ट्रीय नीतियों को लागू कर रही है, जो पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देती हैं, खासकर बच्चों और किशोरों के संबंध में। इसके अलावा, आयुष्मान भारत - पीएमजेएवाई स्वास्थ्य बीमा के तहत 22 मानसिक विकार शामिल हैं। कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

---

34 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1779250

35 गोएट्ज़ेल आरजेड, रोमर ईसी, होलिंगु सी, फॉलिन एमडी, मैक्लेरी के, ईटन डब्ल्यू, एग्न्यू जे, एजोकार एफ, बैलार्ड डी, बार्टलेट जे, ब्रागा एम, कॉनवे एच, क्राइटन केए, फ्रैंक आर, जिनेट के, केलर-ग्रीन डी, राउच एसएम, सेफर आर, सपोरिटो डी, शिल ए, शेर्न डी, स्ट्रेचर वी, वाल्ड पी, वांग पी, मैटिंगली सीआर। कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य: कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य-सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन से कार्यवाही का आह्वान। जे ऑक्यूप एनवायरन मेड। 2018 अप्रैल;60(4):322-330

36 एलेग्रिया एम, नेमोयर ए, फाल्गस बगुए आई, वांग वाई, अल्वारेज के. मानसिक स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक: हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए। कर्र साइकियाट्री रिपोर्ट। 2018 सितम्बर 17;20(11):95

37 त्रिवेदी जे.के., सरीन एच., ध्यानी एम. तीव्र शहरीकरण - मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव: एक दक्षिण एशियाई परिप्रेक्ष्य। इंडियन जे साइकियाट्री। 2008 जुलाई;50(3):161-5

38 चिशोल्म डी, स्वीनी के, शीहान पी, रासमुसेन बी, स्मिट एफ, क्यूइजपर्स पी, एट अल. अवसाद और चिंता के उपचार को बढ़ाना: निवेश पर वैश्विक रिटर्न का विश्लेषण। लैंसेट साइकियाट्री.2016;3:415–24.

39 मैथ एसबी, गौड़ा जीएस, बसवराजू वी, मंजूनाथ एन, कुमार सीएन, एनारा ए, गौड़ा एम, थिरथल्ली जे. मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017 के कार्यान्वयन के लिए लागत अनुमान। इंडियन जे साइकियाट्री। 2019 अप्रैल;61(सप्ल 4):एस650-एस659

तालिका VII.3: भारत में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

कार्यक्रम/उद्देश्य	प्रगति/परिणाम
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम[40]	
जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम *प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य को एकीकृत करने और मानसिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिलों को केंद्रीय निधि*	• 1.73 लाख से अधिक एसएचसी, पीएचसी, यूपीएचसी और यूएचडब्ल्यूसी को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अपग्रेड किया गया • प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है • जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाली इन-पेशेंट सुविधा का प्रावधान • मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को कलंकमुक्त करने और उपचार चाहने वाले व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए समुदाय, स्कूलों, कार्यस्थलों में सामुदायिक भागीदारी के साथ जागरूकता सृजन गतिविधियाँ
राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम *टोल-फ्री नंबर (14416/1800-89-14416) के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य परामर्श तक सार्वभौमिक पहुंच*	• 20 से अधिक भाषाओं में 1600 से अधिक प्रशिक्षित परामर्शदाता • 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए गए • अक्टूबर 2022 से 30.03.2024 तक 8.07 लाख से अधिक कॉल संभाले गए
मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में वृद्धि	• पीजी छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए 25 उत्कृष्टता केन्द्रों को मंजूरी दी गई • 47 पीजी विभागों को मजबूत करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को सहायता • 22 एम्स के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान • तीन डिजिटल अकादमियां सामान्य स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा और पैरा-मेडिकल पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान कर रही हैं • राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद द्वारा 15.1.2024 को जारी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताएं- 2023।
बच्चे और युवा केंद्रित कार्यक्रम[41]	
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम *किशोर जनसंख्या का समग्र विकास*	किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसी), सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम माता-पिता, शिक्षकों और समुदाय को शामिल करते हुए परामर्श सेवाएँ प्रदान करना

40 स्रोत: लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 13 विषय "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति", 2 फरवरी 2024 को उत्तर दिया गया
41 स्रोत: लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 935 विषय "ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं", 8 दिसंबर 2023 को उत्तर दिया गया

कार्यक्रम/उद्देश्य	प्रगति/परिणाम
मनोदर्पण *कोविड-19 के दौरान परामर्श*	छात्रों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्राप्त करने हेतु वेबपेज और राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन
आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम *स्वास्थ्य एवं कल्याण राजदूतों (शिक्षकों) को संवेदनशील बनाना एवं प्रशिक्षित करना*	एनसीईआरटी द्वारा विकसित "भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य" मॉड्यूल
अन्य कदम	• स्कूली बच्चों के लिए एनसीईआरटी परामर्श सेवाएं, जिसमें देश भर के 270 परामर्शदाता शामिल हैं • पीएम ईविद्या डीटीएच चौनलों के माध्यम से लाइव इंटरैक्टिव सत्र सहयोग, योग सत्र आदि। • केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) टोल-फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से परीक्षा पूर्व और पश्चात टेली-काउंसलिंग। • स्कूल जाने वाले बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप पर मॉड्यूलर हैंडबुक पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित की गई है।

7.36 राष्ट्रीय पहलों के अलावा, राज्य अपने स्तर पर अनूठी, स्वतंत्र पहलों को लागू कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मेघालय की राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति बच्चों और किशोरों को लक्षित सहायता प्रदान करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और स्कूल कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की योजना की रूपरेखा तैयार करती है। एनसीटी दिल्ली की सरकार ने नर्सरी से ग्रेड 8 तक के छात्रों के लिए हैप्पीनेस पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसमें स्कूल पाठ्यक्रम में माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और मूल्य-आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। इसी तरह, केरल के कोझिकोड में शुरू की गई 'बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेदारी' पहल में शिक्षक, सहकर्मी और सामाजिक सलाह, जीवन कौशल शिक्षा और स्कूलों के भीतर विशेष जरूरतों वाले बच्चों देखभाल और सहायता शामिल है। ये राज्य-स्तरीय पहल बच्चों और किशोरों के बीच मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को संबोधित करने के राष्ट्रीय प्रयासों का पूरक हैं।

मानसिक स्वास्थ्य पर नीतिगत सिफारिशें

7.37 जबकि नीति का अधिकांश डिजाइन तैयार है, उचित कार्यान्वयन से जमीनी स्तर पर सुधार में तेजी आ सकती है। तथापि, मौजूदा कार्यक्रमों में कुछ कमियाँ हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है ताकि उनकी प्रभावशीलता को अधिकतम किया जा सके। उदाहरण के लिए, मनोचिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के प्रयासों को बढ़ाना, 2021 में प्रति लाख जनसंख्या पर 0.75 मनोचिकित्सकों से बढ़ाकर[42] WHO के प्रति लाख जनसंख्या पर 3 मनोचिकित्सकों की संख्या करना (गर्ग, कुमार और चंद्रा 2019)।[43]

42 स्रोत: राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1015 विषय "देश में मानसिक स्वास्थ्य रोगी एवं चिकित्सक", 7 दिसंबर 2021 को उत्तर दिया गया।
43 गर्ग के, कुमार सीएन, चंद्रा पीएस. भारत में मनोचिकित्सकों की संख्या: आगे की ओर छोटे कदम, लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। इंडियन जे साइकियाट्री। 2019 जनवरी-फरवरी;61(1):104-105. doi: 10.4103/psychiatry-IndianJPsychiatry;7;18. PMID: 30745666; PMCID: PMC6341936.

7.38 मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों और उपयोगकर्ताओं के साथ उत्कृष्टता केंद्रों की सेवाओं के लिए व्यापक दिशा-निर्देश विकसित करने से उनकी जरूरतों को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही, उपयोगकर्ताओं, पेशेवरों और हितधारकों से प्रतिक्रिया एकत्र करके कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करने से आवश्यक परिवर्तन करने और व्यापक आबादी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। सहकर्मी सहायता नेटवर्क, स्वयं सहायता समूह और समुदाय-आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने से मानसिक विकारों को दूर करने और अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद मिल सकती है। प्रयासों को बढ़ाने, ज्ञान साझा करने और भविष्य की नीतियों को बढ़ाने के लिए संसाधनों का लाभ उठाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी करने से सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। निर्णय लेने, सेवा नियोजन और वकालत के प्रयासों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के साथ व्यक्तिगत अनुभव वाले व्यक्तियों को शामिल करने से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यक्ति-केंद्रितता और पुनर्प्राप्ति-उन्मुखता बढ़ सकती है (मेघाराजानी और अन्य 2023)।[44] प्रीस्कूल, आंगनवाड़ी स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता विकारों की शुरुआती पहचान प्रदान कर सकती है। मानसिक स्वास्थ्य स्टार्ट-अप में वृद्धि देखभाल की कमी को दूर करने के लिए निजी क्षेत्र की सकारात्मक प्रतिक्रिया का संकेत देती है, लेकिन ऐसी सेवाओं के लिए मानकीकरण दिशा-निर्देशों की भी मांग करती है।

7.39 स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों को एकीकृत करने के लिए प्रभावी मार्गों में शिक्षकों और छात्रों के लिए आयु-उपयुक्त मानसिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम विकसित करना, स्कूलों में प्रारंभिक हस्तक्षेप और सकारात्मक भाषा को प्रोत्साहित करना, समुदाय-स्तर पर बातचीत को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी की भूमिका को संतुलित करना, शामिल हो सकता है।

7.40 तथापि, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता की कमी और इससे जुड़ी नकारात्मक सोच का मूल मुद्दा किसी भी कार्यक्रम को अव्यवहारिक बना सकता है। इसलिए, मानसिक स्वास्थ्य के विषय को संबोधित करने में एक आदर्श बदलाव लाने और एक निचले स्तर से ऊपर, पूरे समुदाय के दृष्टिकोण का उपयोग करने की आवश्यकता है। नकारात्मकता को हटाने की शुरुआत शारीरिक बीमारियों को स्वीकार करने और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में इनकार करते हुए उसी के लिए उपचार की तलाश करने की प्राकृतिक मानवीय प्रवृत्ति का संज्ञान लेने से होती है। एक हद तक, यह नकारात्मक सोच सामाजिक दृष्टिकोण और मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को साझा करने के बाद सामाजिक स्वीकृति के बारे में डर का परिणाम है। व्यक्तिगत स्तर पर भी इसे सामान्य मानने और संबोधित करने में अनिच्छा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, इस मौलिक अनिच्छा को स्वीकार करने और समाधान करने की आवश्यकता है। यकीनन, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे व्यक्तियों के शारीरिक स्वास्थ्य मुद्दों की तुलना में पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता को अधिक व्यापक रूप से कम करते हैं। इसलिए, समाज में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान देना स्वास्थ्य और आर्थिक दोनों के लिए जरूरी है।

स्वास्थ्य सांख्यिकी में प्रभाव प्रकट

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती भूमिका दर्शाता है

7.41 पिछले कुछ वर्षों में, स्वास्थ्य सेवा आम जनता के लिए अधिक सस्ती और सुलभ हो गई है, जैसा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) के अनुमानों से पता चलता है।[45] नवीनतम एनएचए (वित्त वर्ष 20 के लिए) कुल जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय (जीएचई) के हिस्से के साथ-साथ कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) में जीएचई के हिस्से में वृद्धि दर्शाता है।

---

44 मेघराजनी वी.आर., मराठे एम., शर्मा आर., पोटदुखे ए., वंजारी एम.बी., ताकसांडे ए.बी. भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का व्यापक विश्लेषण और मानसिक आश्रयों की भूमिका। क्यूरियस। 2023 जुलाई 27;15(7):e42559. doi: 10.7759/cureus.42559.

45 भारत के लिए एनएचए अनुमान 2019-20 एनएचएसआरसी द्वारा तैयार की गई लगातार सातवीं एनएचए अनुमान रिपोर्ट है, जिसे 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय के रूप में नामित किया गया था। इसे अप्रैल 2023 में जारी किया गया था।

7.42 पिछले कुछ वर्षों में, स्वास्थ्य व्यय समग्र स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण खंड के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की ओर झुका है। अनुसंधान ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व को स्वास्थ्य परिणामों में सुधार, कई प्राथमिक और माध्यमिक रोग स्थितियों को रोकने और बहुत कम लागत पर रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए महत्वपूर्ण के रूप में स्थापित किया है, जिससे माध्यमिक और तृतीयक देखभाल की आवश्यकता में काफी कमी आई है। नतीजतन,[46] प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यय का हिस्सा वित्त वर्ष 2015 में जीएचई के 51.3 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 20 में जीएचई का 55.9 प्रतिशत हो गया है। जीएचई में प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल का हिस्सा वित्त वर्ष 2015 में 73.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 20 में 85.5 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर, निजी स्वास्थ्य व्यय में प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल का हिस्सा इसी अवधि के दौरान तृतीयक रोगों का बढ़ता बोझ और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सरकारी सुविधाओं का कम उपयोग के कारण 83.0 प्रतिशत से घटकर 73.7 प्रतिशत हो गया।

7.43 स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय, जिसमें सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ और सरकारी कर्मचारियों को की जाने वाली चिकित्सा प्रतिपूर्ति शामिल है, वित्त वर्ष 2015 में 5.7 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 20 में 9.3 प्रतिशत हो गया है। जीएचई और स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक सुरक्षा व्यय में वृद्धि वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 20 के बीच टीएचई के प्रतिशत के रूप में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओओपीई) में गिरावट के साथ-साथ होती है (चार्ट VII.5(क))।

चार्ट VII.5(क): कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय और जेब से किया गया व्यय

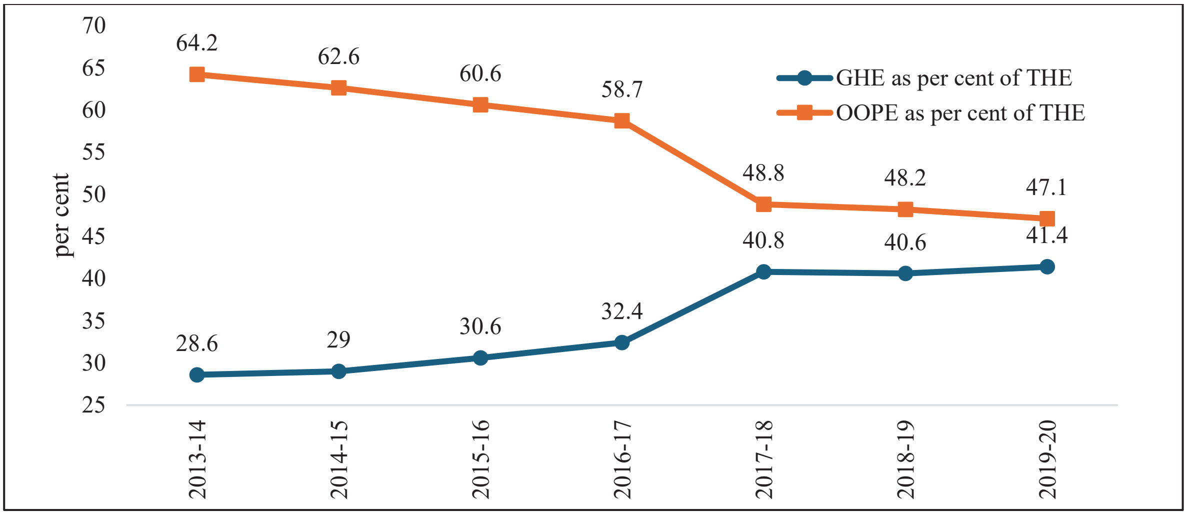

स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा, 2019-20, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

46 उदाहरण के लिए देखें, (i) हक, एम., एट.अल. (2020)। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में दीर्घकालिक (जीर्ण) गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण में मदद करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत करना। जोखिम प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवा नीति, 13, 409ख्र426. (ii) बीगलहोल आर, एट. अल. (2008)। निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों में जीर्ण रोग की रोकथाम और प्रबंधन में सुधार: प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्राथमिकता। लैंसेट। 13 सितंबर; 372(9642):940-9.

चार्ट VII.5 (ख): कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सुरक्षा व्यय और निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय

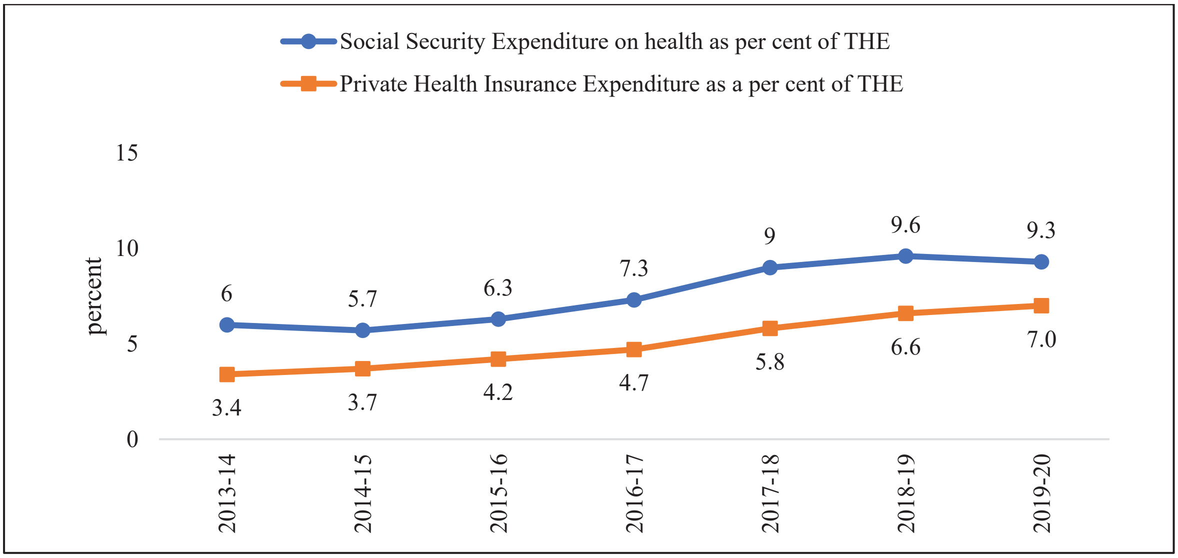

स्रोतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा, 2019-20, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

7.44 उपर्युक्त विकास के साथ-साथ प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में भी सुधार हुआ है, जैसे कि शिशु मृत्यु दर (जो 2013 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 39 से घटकर 2020 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28 रह गई) और मातृ मृत्यु दर (जो 2014 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 167 से घटकर 2020 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 97 रह गई)।

7.45 परिवारों पर स्वास्थ्य सेवा लागत के घटते बोझ के उदाहरण के रूप में, आयुष्मान भारत के प्रभाव का उल्लेख करना उचित है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार, यदि लाभार्थी ने एबी पीएम-जय के दायरे से बाहर अपने दम पर यही उपचार करवाया होता, तो उपचार की कुल लागत 1.5 - 2 गुना अधिक होती। कम लागत के इस गुणक प्रभाव को शामिल करने पर, यह योजना गरीब और वंचित परिवारों के ओओपीई से 1.25 लाख करोड़ से अधिक के खर्च को बचाती है (12 जनवरी 2024 तक)।[47] इसलिए, बाजार की कमजोरियों से जनता को बचाने के अलावा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सूक्ष्म-आर्थिक झटकों से भी बचाता है।

7.46 स्वास्थ्य संकेतकों और ओओपीई पर सीधे प्रभाव के अलावा, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कई दूसरे क्रम के प्रभाव भी हैं। उदाहरण के लिए, आयुष्मान भारत को बेहतर ऋण बाजार परिणामों से जोड़ा गया है, जैसा कि बॉक्स VII.4 में विस्तार से बताया गया है।

47 पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 14 जनवरी 2024, रिलीज आईडी: 1996010 https://tinyurl.com/mvpp9as6

बॉक्स VII.4: स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम और ऋण बाजार के परिणामों पर प्रभाव

विनाशकारी, अप्रत्याशित स्वास्थ्य व्यय व्यक्तियों और परिवारों की गरीबी का कारण बन सकते हैं। यह संसाधन-विहीन व्यक्तियों/परिवारों को उपचार छोड़ने या उपचार के लिए ऋण लेने के लिए मजबूर कर सकता है। स्वास्थ्य सेवा लागत को कम करने से वित्तीय स्थिरता और ऋण चुकौती क्षमता में सुधार होने की उम्मीद है।

हाल ही में प्रकाशित एक शोधपत्र[48] में भारत में ऋण बाजार की गतिशीलता पर दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना, पीएमजेएवाई के प्रभाव की जांच की गई है। उन राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों की तुलना करना, जिन्होंने कार्यक्रम को लागू नहीं किया, उन राज्यों से सम्बन्धित निकटवर्ती क्षेत्रों के साथ, जिन्होंने अलग-अलग भिन्नता फ्रेमवर्क के साथ कार्यक्रम को लागू किया, इसमें परिकल्पना की गई है कि पीएमजेएवाई के व्यापक कवरेज से स्वास्थ्य सेवा लागत के कारण वित्तीय तनाव में कमी आएगी, जिससे ऋण चूक दरों जैसे ऋण व्यवहार पर असर पड़ेगा। अध्ययन में पीएमजेएवाई के प्रभाव को अन्य कारकों से अलग करने के लिए एक मजबूत अनुभवजन्य रणनीति का उपयोग किया गया है। यह समष्टि वित्त ऋण प्रदर्शन को शामिल करने वाले एक महत्वपूर्ण भारतीय क्रेडिट ब्यूरो से प्रशासनिक डेटा का उपयोग करता है। इस नमूने में भारत के 636 जिलों में लगभग 12 मिलियन ऋणों का डेटा शामिल है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

ऋण निष्पादन पर प्रभाव: पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन से माइक्रोफाइनेंस ऋणों में एनपीए दरों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। अध्ययन में कहा गया है कि पीएमजेएवाई-कार्यान्वित जिलों में एनपीए दर गैर-कार्यान्वित क्षेत्रों की तुलना में 3.7 से 4.0 प्रतिशत तक कम हुई। यह औसत एनपीए दरों के सापेक्ष 34.6 प्रतिशत से 34.1 प्रतिशत की कमी दर्शाता है, जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव है।

लघु कृषि ऋणों पर प्रभाव : पात्र लघु कृषि ऋणों में भी एनपीए दरों में इसी प्रकार की कमी देखी गई, जो पीएमजेएवाई के व्यापक आर्थिक प्रभाव को रेखांकित करता है।

नीति और वित्तीय बाजारों के लिए निहितार्थ

सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और आर्थिक स्थिरता: अध्ययन सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों के व्यापक आर्थिक प्रभावों पर प्रकाश डालता है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए, जहाँ आबादी के बड़े हिस्से के पास स्वास्थ्य बीमा तक पहुँच की कमी हो सकती है, पीएमजेएवाई जैसे कार्यक्रम आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

स्वास्थ्य देखभाल नीति और घरेलू वित्त: ये निष्कर्ष विशेष रूप से ऐसे देशों के लिए प्रासंगिक हैं जो समान स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर विचार कर रहे हैं, तथा इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ऐसे कार्यक्रम घरेलू वित्तीय व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन ने भारत में ऋण बाजार के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार किया है, जो स्वास्थ्य बीमा और वित्तीय स्थिरता के बीच परस्पर क्रिया को उजागर करता है। यह स्वास्थ्य सेवा से परे महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ पैदा करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों की क्षमता को रेखांकित करता है।

48 तंत्री, प्रसन्ना एल., 500 मिलियन गरीबों को कवर करने वाला स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ऋण बाजार के नतीजों को कैसे प्रभावित करता है? (22 मार्च, 2022)। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस WP

7.47 भविष्य में देश के स्वास्थ्य और रोग प्रोफाइल के लिए दो रुझान निर्णायक होंगे। सबसे पहले, सरकार और आम जनता को स्वस्थ खान-पान और मानसिक स्वास्थ्य पर उचित ध्यान देने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, एनएफएचएस के आंकड़ों के अनुसार, 2019-21 में 24.0 प्रतिशत महिलाएँ और 22.9 प्रतिशत पुरुष अधिक वजन वाले/मोटे थे, जबकि 2015-16 में क्रमशः 20.6 प्रतिशत और 18.9 प्रतिशत थे। 50 वर्षों में, टाइप-II मधुमेह की के रोगियों की संख्या 1970 के दशक में 2 प्रतिशत से कम से बढ़कर 20 प्रतिशत से अधिक हो गई है।[49] भारत में बढ़ते मोटापे के संज्ञान में, राष्ट्रीय पोषण संस्थान और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जारी आहार संबंधी दिशा-निर्देशों के साथ स्वस्थ खान-पान के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरे, लोक स्वास्थ्य एक राज्य का विषय होने के कारण, राज्य और स्थानीय स्तर का शासन राष्ट्रीय कार्यक्रमों को 'कम से कम प्रतिरोध के मार्ग' के माध्यम से अंतिम उद्देश्य पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण है।

शिक्षा

7.48 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी 4) के तहत लक्ष्य 4 के रूप में सूचीबद्ध 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' का लक्ष्य 2030 तक ''समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना'' है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), जिसे 2020 में लॉन्च किया गया और वर्तमान में अपने कार्यान्वयन के चौथे वर्ष में है, एक नीति दस्तावेज है जो न केवल शिक्षा पर एसडीजी लक्ष्यों को शामिल करता है बल्कि भारत के युवाओं को 21वीं सदी की ज्ञान-संचालित अर्थव्यवस्था से उभरने वाली चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए तैयार करता है।

विद्यालय शिक्षा

7.49 भारत में सरकारी और निजी स्कूलों वाली स्कूली शिक्षा प्रणाली विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लगभग 26 करोड़ छात्रों को शिक्षा प्रदान करती है। एनईपी 2020 का उद्देश्य 3-18 वर्ष की आयु के सभी विद्यार्थियों को उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच प्रदान करना है, ताकि एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली बनाई जा सके जो भारतीय संस्कृति में निहित हो और जिसमें भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की क्षमता हो।

7.50 एनईपी का उद्देश्य सभी के लिए बेहतर शिक्षण परिणाम उत्पन्न करने के लिए सर्वत्र स्कूली शिक्षा को नया रूप देना है। सीखने पर जोर देने की गंभीरता को विभिन्न रिपोर्टों में महसूस किया जा सकता है, जो कक्षा के मानक और सीखने के स्तर के बीच के अंतर को उजागर करती हैं, जो कोविड के बाद से और भी बढ़ गया है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2017 की तुलना में, एनएएस 2021 में छात्रों के प्रदर्शन में काफी गिरावट आई है।[50] कक्षा 10 के अंकों में गणित में 13.4 प्रतिशत, विज्ञान में 18.6 प्रतिशत और सामाजिक विज्ञान में 9.1 प्रतिशत की कमी आई, जबकि कक्षा 3 के अंकों में भाषा में 3.9 प्रतिशत, गणित में 4.7 प्रतिशत और पर्यावरण अध्ययन में 4.4 प्रतिशत की कमी आई।

7.51 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा या ईसीसीई (ईसीसीई में उल्लेखनीय पहल के लिए बॉक्स VII.5 देखें) को लागू करना, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को मजबूत करना, अनुभवात्मक शिक्षा, बहुभाषी शिक्षा, अंत:विषयक और बहुविषयक दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित करना, समग्र मूल्यांकन आदि, एक नई प्रणाली विकसित करने के लिए एनईपी 2020 की प्रमुख स्तंभ हैं जो 21वीं सदी के प्रेरणादायक लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

---

49 विश्वनाथन मोहन, वासुदेवन सुधा, शनमुगम शोभना, राजगोपाल गायत्री, कमला कृष्णस्वामी, क्या अस्वास्थ्यकर आहार भारत में टाइप 2 मधुमेह के तेजी से बढ़ने में योगदान दे रहे हैं?, जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन, खंड 153, अंक 4, 2023, पृष्ठ 940-948, आईएसएसएन 0022-3166

50 एनएएस केंद्र सरकार के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर किया जाने वाला मूल्यांकन है जो कक्षा 3, 5, 8 और 10 के अंत में श्छात्र क्या जानते हैं और क्या कर सकते हैं, इसका एक स्नैपशॉटश प्रदान करता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के 720 जिलों के 1.18 लाख स्कूलों के लगभग 34 लाख छात्रों ने एनएएस 2021 में भाग लिया। राष्ट्रीय, राज्य और जिला रिपोर्ट कार्ड nas-gov-in पर उपलब्ध हैं।

बॉक्स VII.5: 'पोषण भी पढ़ाई भी': आंगनवाड़ियों में प्री-स्कूल नेटवर्क की स्थापना

एनईपी 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, मई 2023 में 'पोषण भी पढाई भी' (पीबीपीबी) शुरू किया गया। यह एक अग्रणी ईसीसीई कार्यक्रम है, जो भारत को आंगनवाड़ी केंद्रों पर दुनिया का सबसे बड़ा, सार्वभौमिक, उच्च गुणवत्ता वाला प्रीस्कूल नेटवर्क विकसित करने में मदद करता है। पहली बार, 0-3 साल के बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रेरणा को एक सरकारी कार्यक्रम द्वारा कवर किया जा रहा है।

पीबीपीबी के बारे में

कार्यक्रम के माध्यम से, प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन कम से कम दो घंटे उच्च गुणवत्ता वाली प्रीस्कूल शिक्षा प्रदान की जाएगी। सभी राज्य खेल-आधारित, गतिविधि-आधारित शिक्षण पद्धति के लिए राष्ट्रीय ईसीसीई टास्क फोर्स की सिफारिशों का पालन करेंगे, जो स्पष्ट रूप से 0-3 वर्ष और 3-6 वर्ष के बच्चों के विकासात्मक मील के पत्थरों पर लक्षित है, जिसमें दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सहायता भी शामिल है।

पीबीपीबी की मुख्य विशेषताएं

- दृश्य सामग्री (ब्लैकबोर्ड, पोस्टर, फ्लैशकार्ड, गतिविधि पुस्तकें, आदि), ऑडियो सामग्री (रेडियो) और ऑडियो-विजुअल (वीडियो, फिल्म), स्थानिक सामग्री (ड्राइंग, पेंटिंग, पहेलियाँ), आदि सहित शिक्षण-अधिगम सामग्री का उपयोग।
- प्राथमिक शिक्षक शिक्षण माध्यम के रूप में मातृभाषा
- जन आंदोलन देश की भावी पीढ़ियों की नींव को मजबूत करने में समुदायों को शामिल करेगा।

देश भर में आंगनवाड़ियों के नेटवर्क को मजबूत बनाना

देश भर में करीब 13.9 लाख आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं, जो 6 वर्ष से कम आयु के लगभग आठ करोड़ लाभार्थी बच्चों को पूरक पोषण, प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे यह वैश्विक स्तर पर ऐसी सेवाओं का सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रावधान बन गया है। वैश्विक साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि 6 वर्ष की आयु तक 85 प्रतिशत मस्तिष्क विकास हो जाता है, आंगनवाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनके आधार का निर्माण करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहुंच बिंदु बन जाता है।

आंगनवाड़ियों के माध्यम से पीबीपीबी को साकार करने के लिए, आंगनवाड़ियों को उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, खेल के उपकरण और अच्छी तरह से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/शिक्षकों के साथ मजबूत करना होगा। इस संबंध में, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 40,000 मास्टर प्रशिक्षकों के माध्यम से गतिविधियों, खेल और स्वदेशी और डीआईवाई खिलौनों का उपयोग करने सहित ईसीसीई सिद्धांतों पर प्रशिक्षित किया जाना है। जनवरी 2024 तक, 25 राज्यों और 182 जिलों को कवर करते हुए 95 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 3735 राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

एक उपयोगी रोजगार सृजन संस्थान

के रूप में और भविष्य के एक मजबूत और उत्पादक भारत के निर्माण के लिए आंगनवाड़ियों की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

7.52 सरकार की प्रमुख योजनाएं जो एनईपी 2020 के लक्ष्यों और नीतियों को क्रियान्वित कर रही हैं, उनका उल्लेख तालिका VII.4 में किया गया है।

तालिका VII.4: स्कूली शिक्षा में सरकारी पहल

	कार्यक्रम	उद्देश्य	प्रगति
1.	*समग्र शिक्षा अभियान*[51]		
	निष्ठा	एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	सभी स्तरों पर शिक्षकों को कवर करने के लिए विस्तारित 126208 मास्टर ट्रेनर को निष्ठा ईसीसीई में प्रमाणित किया गया।
	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIETs)	स्कूल शिक्षा और शिक्षक शिक्षा का मार्गदर्शन करने वाली जिला स्तरीय नोडल संस्थाएँ	अगले पांच वर्षों में सभी 613 क्रियाशील डाइट को उत्कृष्ट डाइट में उन्नत किया जाएगा उन्नयन के इस पहले चक्र (वित्त वर्ष 24) में, देश भर में 125 डीआईईटी के लिए ₹92,320.18 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, वित्त वर्ष 24 में पहली किस्त के रूप में 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उन्नयन के लिए ₹27923.53 लाख जारी किए गए हैं।
	ब्लॉक स्तर पर कैरियर परामर्श		प्रत्येक ब्लॉक/यूएलबी में करियर काउंसलिंग के लिए एक अकादमिक संसाधन व्यक्ति के प्रावधान के लिए अगस्त 2023 में दिशानिर्देश जारी किए गए
	विद्या प्रवेश	प्रीस्कूल शिक्षा वाले और बिना शिक्षा वाले सभी ग्रेड-1 के छात्रों के लिए 3 महीने का खेल-आधारित 'स्कूल तैयारी मॉड्यूल'	36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित 2023-24 में 8.46 लाख स्कूलों के 1.13 करोड़ छात्र कवर किए जाएंगे
	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवि)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे के वंचित समूहों की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय	वर्तमान में देश भर में 5,116 केजीबीवी में 7.07 लाख छात्राएं नामांकित हैं।

51 समग्र शिक्षा अभियान को मौजूदा सी.एस.एस. योजनाओं को मिलाकर वित्त वर्ष 2019 में शुरू किया गया था; जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा को कवर करने वाला सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा को कवर करने वाला राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और पूर्व-विद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक तक शिक्षा को एक निरंतरता के रूप में मानने के लिए शिक्षक शिक्षा।

	कार्यक्रम	उद्देश्य	प्रगति
	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा (सीडब्ल्यूएसएन)	शिक्षा की सुगम्यता	प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक विशेष आवश्यकता वाले 18.50 लाख बच्चों को कवर किया गया 5.57 लाख सी.डब्लू.एस.एन. बालिकाओं को सालाना दस महीने के लिए 200 रुपये प्रति माह वजीफा 3.65 लाख से अधिक पात्र सी.डब्लू.एस.एन. को सहायता एवं उपकरण प्रदान किए गए गंभीर एवं/या बहुविकलांगता वाले 72,186 बच्चों को गृह-आधारित शिक्षा सी.डब्लू.एस.एन. की शिक्षण आवश्यकताओं को उचित रूप से पूरा करने के लिए 32,196 विशेष शिक्षक भारतीय सांकेतिक भाषा में शिक्षण अधिगम संसाधन, अभिगम्यता पुस्तिका, स्पर्शनीय मानचित्र पुस्तकें, बोलने वाली पुस्तकें, डेजी पुस्तकें 21 विकलांगता स्थितियों की प्रारंभिक जांच के लिए स्कूलों के लिए प्रशस्त पूर्व-मूल्यांकन समग्र स्क्रीनिंग चेकलिस्ट
2.	राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र - परख	परख के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं: क) स्कूल शैक्षिक बोर्डों का मार्गदर्शन करना ख) बड़े पैमाने पर उपलब्धि सर्वेक्षण ग) छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक, मानदंड और दिशानिर्देश तय करना घ) मूल्यांकन के लिए व्यावसायिक और संस्थागत क्षमता का निर्माण करना	हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद स्कूल बोर्डों में समतुल्यता के लिए नीतिगत सिफारिशें तैयार की जा रही हैं। राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण[52] नवंबर 2023 में आयोजित किया गया जाएगा, 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 6416 ब्लॉकों के 4 लाख स्कूलों के लगभग 84 लाख शिक्षार्थी शामिल होंगे। आधारभूत, प्रारंभिक और मध्य चरणों के लिए 'समग्र प्रगति कार्ड' का विकास और प्रसार। एनईपी वर्ष 2020 में सुझाए गए योग्यता आधारित मूल्यांकन पर शिक्षक प्रशिक्षकों और शिक्षकों को परिचित कराने के लिए प्रोजेक्ट विद्यासागर के तहत कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

52 राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण का उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर सीखने की कमियों को समझना है, जो जिला स्तर से कहीं अधिक गहराई तक जाती है। जबकि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण हर तीन साल में किया जाना है, SEAS को अंतरिम वर्षों में आयोजित किया जाना है।

	कार्यक्रम	उद्देश्य	प्रगति
3.	ज्ञान साझाकरण के लिए डिजिटल अवसंरचना (दीक्षा)	एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म	शिक्षार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों आदि के लिए 36 भारतीय भाषाओं में नि:शुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल 3,53,063 ई-सामग्री उपलब्ध कराई गई 1.71 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता, 2.5 लाख दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता
4.	राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणाम का सुदृढ़ीकरण (स्टार्स)	छह राज्यों (हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान) में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुध ार करना	स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी (आईवीए) को संवितरण संबद्ध संकेतकों (डीएलआई) के अनुसार परिणामों को सत्यापित करने के लिए शामिल किया गया था, जैसे कि भाषा दक्षता में वृद्धि, माध्यमिक विद्यालय पूर्णता दर, शासन सूचकांक, आदि। पहले दो वर्षों में 6/6 लक्ष्य हासिल किये गये।
5.	प्रधानमंत्री- उभरते भारत के लिए स्कूल (पीएम-श्री)	एनईपी कार्यान्वयन को दर्शाते हुए 14,500 आदर्श विद्यालय स्थापित करना	स्कूल चयन के तीन चरण पूरे हो चुके हैं। 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केवीएस/एनवीएस से 10,858 स्कूलों का चयन किया गया। वित्त वर्ष 2024-25 में 10,080 पीएम-श्री स्कूलों के लिए 5942.21 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। तीसरे चरण में चयनित पीएम श्री स्कूलों के लिए पीएबी की बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी।
6.	उल्लास- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम	15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षरों के लिए आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता	एक ऐप के माध्यम से 22 स्थानीय भाषाओं में ऑनलाइन सामग्री (उल्लास प्राइमर्स) बनाई गई है जो दीक्षा पोर्टल पर पुनर्निर्देशित करती है 1.33 करोड़ शिक्षार्थी और 35 स्वयंसेवी शिक्षक पंजीकृत 77 लाख शिक्षार्थी साक्षरता परीक्षा में बैठे और 65 लाख से अधिक उत्तीर्ण होकर नव-साक्षर बन गए।
7.	पीएम पोषण (पोषण शक्ति निर्माण) योजना	सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा I से VIII तक के विद्यार्थियों के लिए एक गर्म पका हुआ भोजन	वित्त वर्ष 24 में (दिसंबर 2023 तक) 10.7 लाख स्कूलों में 11.6 करोड़ बच्चों को लाभ मिला। 24.8 लाख रसोइया-सह-सहायक नियुक्त किए गए और 9.1 लाख रसोई-सह-भंडार बनाए गए।

	कार्यक्रम	उद्देश्य	प्रगति
8.	राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना ताकि उनका बीच में पढ़ाई छोड़ना रोका जा सके	योजना के तहत पात्रता मानदंड के आधार पर कक्षा IX के नए छात्रों को एनएमएमएसएस परीक्षा उत्तीर्ण करने और कक्षा XII तक जारी रखने के लिए प्रति वर्ष ₹12,000 की एक लाख नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2023-24 में 250089 छात्रों को कुल ₹300.10 करोड़ स्वीकृत किए गए।

7.53 स्कूली शिक्षा में एनईपी 2020 को शामिल करने के लिए उपर्युक्त पहलों के अलावा, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को मजबूत करने में समुदाय, निजी क्षेत्र और पूर्व छात्रों की भागीदारी के लिए एक अभिनव कार्यक्रम को बॉक्स VII.6 में गहराई से बताया गया है।

बॉक्स VII.6: विद्यांजलि: एक स्कूल स्वयंसेवी कार्यक्रम

विद्यांजलि कार्यक्रम 7 सितंबर, 2021 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य स्कूली बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सामुदायिक भागीदारी, सीएसआर और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से देश भर में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, जैसा कि एनईपी 2020 में परिकल्पित है। यह कार्यक्रम कंपनियों/संगठनों/ट्रस्टों और समूहों को पोर्टल पर एक समर्पित सीएसआर मॉड्यूल के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और स्वायत्त निकायों द्वारा बनाई गई परियोजनाओं में भाग लेकर अपनी पसंद के कई स्कूलों का समर्थन करने का अवसर प्रदान करता है। यह सरकार की जिम्मेदारी को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं है, बल्कि सर्वोत्तम संभव तरीके से अंतिम मील तक पहुंचने के लिए सरकारी प्रयासों को मजबूत करने के लिए है।

विद्यांजलि पोर्टल (vidyanjali.education.gov.in) स्वयंसेवकों - शैक्षणिक संस्थानों के पूर्व छात्र, सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षक, वैज्ञानिक, सरकारी/अर्ध-सरकारी अधिकारी, सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मी, स्व-नियोजित और वेतनभोगी पेशेवर, गृहणियां, भारतीय प्रवासी और किसी अन्य संगठन/समूह या कंपनी के व्यक्ति - को सीधे उनकी पसंद के स्कूलों से जोड़कर एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करता है।

स्वयंसेवक नवीन शिक्षण पद्धतियों और इंटरैक्टिव गतिविधियों को लाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो छात्रों के बीच रचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, संसाधन संपन्न स्कूल भी अपनी विशेषज्ञता और संसाधनों का योगदान उन स्कूलों को दे सकते हैं जिन्हें कार्यक्रम के तहत स्कूल की विशेषताओं के युग्मन के तहत अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।

वर्ष भर में विद्यांजलि की वृद्धि (2021 में लॉन्च के बाद से संचयी)

शामिल किए गए स्कूलों की कुल संख्या	पंजीकृत व्यक्तिगत स्वयंसेवकों की कुल संख्या	कुल पंजीकृत सीएसआर/एनजीओ	प्रभावित बच्चे
7,47,133	4,58,511	2,881	1,44,35,995

स्रोत: स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

विद्यांजलि का प्रभाव

विद्यांजलि पहल ने व्यापक सामुदायिक जुड़ाव की सुविधा प्रदान करके और विभिन्न क्षेत्रों में स्वयंसेवी योगदान का लाभ उठाकर 1.44 करोड़ से अधिक छात्रों के शैक्षिक अनुभवों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें

विषय सहायता और मार्गदर्शन और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल उपकरणों का प्रावधान शामिल है। इस व्यापक स्वयंसेवी भागीदारी ने छात्रों के सीखने को विविध संसाधनों के साथ समृद्ध किया है, जिसमें विषय सहायता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए मार्गदर्शन से लेकर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल उपकरणों जैसे मोबाइल फोन और कंप्यूटर का प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त, स्वयंसेवकों ने प्राथमिक चिकित्सा किट और खेल उपकरण जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की है और स्मार्ट कक्षाओं और उन्नत रसोई उद्यानों के साथ सीखने की जगहों का नवीकरण किया गया है।

इस पहल ने कई परिसंपत्ति अनुरोधों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसमें 26,268 अनुरोध पूरे किए गए हैं। इन अनुरोधों में शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुएँ और सुविधाएँ शामिल हैं, जैसे कि बुनियादी विद्युत अवसंरचना, कक्षा की जरूरतें, स्वास्थ्य और सुरक्षा सहायताएँ, आदि। परिसंपत्ति अनुरोधों के अलावा, कार्यक्रम ने 13,100 गतिविधियाँ पूरी की हैं, जिनमें से प्रत्येक संभवत: कई दिनों या कार्यों तक फैली हुई है। सफलता की कहानियों में दिल्ली शामिल है, जिसने 2969 पंजीकृत स्कूलों में से 2883 के साथ 14,882 सक्रिय स्वयंसेवकों के साथ अनुकरणीय भागीदारी का प्रदर्शन किया है।

स्कूल बुनियादी ढांचे में प्रगति

7.54 वित्त वर्ष 23 में स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में पिछले वर्षों की तुलना में सुधार जारी रहा। अब ज्यादातर सरकारी स्कूलों में शौचालय (लड़कियों या लड़कों के लिए), पीने का पानी और हाथ धोने की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। समग्र शिक्षा योजना और स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्कूलों में पीने के पानी और स्वच्छता को प्राथमिकता देना जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने और इन स्कूल परिसंपत्तियों को बनाने में सहायक रहा है। समग्र शिक्षा योजना के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईटी) घटक के तहत, सरकार स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और आईटी लैब की स्थापना का समर्थन करती है, जिसमें हार्डवेयर, शैक्षिक सॉफ्टवेयर और शिक्षण के लिए ई-सामग्री का समर्थन शामिल है।

तालिका VII.5: स्कूल के बुनियादी ढांचे की स्थिति

(सभी स्कूलों की प्रतिशत के अनुसार बुनियादी सुविधाएओं सहित स्कूल)

वर्ष	2012-13	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (पी)
लड़कियों के लिए शौचालय	88.1	96.9	97.3	97.5	97.0
लड़कों के लिए शौचालय	67.2	95.9	96.2	96.2	95.6
हाथ धोने की सुविधा	36.3	90.2	91.9	93.6	94.1
पुस्तकालय/पठन कक्ष/पठन कोना	69.2	84.1	85.6	87.3	88.3
बिजली	54.6	83.4	86.9	89.3	91.7
विद्यालय में एक वर्ष में चिकित्सा जांच	61.1	82.3	50.4*	54.6*	74.3
कंप्यूटर	22.2	38.5	41.3	47.5	47.7
इंटरनेट	6.2	22.3	24.5	33.9	49.7

* कोविड-19 के कारण स्कूल बंद थे। इसलिए, कम मेडिकल जांच की गई। पी: प्रोविजनल
स्रोत: UDISE+, https://dashboard.udiseplus.gov.in/#/home

स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) 2023

7.55 अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया एनसीएफ-एसई 2023 एनईपी 2020 के उद्देश्यों और प्रतिबद्धता को जीवंत करता है, ताकि इसके कार्यान्वयन को सक्षम बनाया जा सके। एनसीएफ का मसौदा 12 सदस्यीय राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा तैयार किया गया था और इसमें देश भर के शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों, शैक्षणिक संस्थानों, नव- और निरक्षरों, विषय विशेषज्ञों, विद्वानों, आंगनवाड़ी कर्मियों आदि सहित लगभग 16 लाख विविध हितधारकों से इनपुट मांगे गए थे।

7.56 एनसीएफ-2023 अपने पूर्ववर्ती एनसीएफ-2005 से कई मायनों में बेहतर है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, योग्यता-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना,[53] ग्रेड 9 के बजाय ग्रेड 3 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करना, भारत की मूल भाषाओं को सीखना और ईसीसीई और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी (एफएलएन)/ मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करना शामिल है। यह परिवर्तनकारी है क्योंकि मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता स्कूली शिक्षा में आगे के वर्षों को सार्थक करने के लिए आवश्यक है (मुरलीधरन 2024)।[54] इसके अलावा, यह स्कूल के पाठ्यक्रम में स्वदेशी ज्ञान को एकीकृत करने, आईसीटी सहित शिक्षा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और रटने की प्रथा से दूर जाने पर अधिक स्पष्टता, विवरण और दिशा लाता है।

व्यावसायिक शिक्षा

7.57 एनईपी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें सभी संस्थानों को मुख्यधारा में लाने का प्रावधान है, जिसमें कौशल अंतर विश्लेषण और स्थानीय नौकरी के अवसरों की मैपिंग पर आधारित फोकस क्षेत्र शामिल हैं। इसमें फाउंडेशनल और प्रारंभिक चरणों में बच्चों में पूर्व-व्यावसायिक क्षमताओं का विकास और मध्य चरण में काम करने का अनुभव शामिल है, जिससे उन्हें माध्यमिक चरण में उनकी योग्यता, क्षमता और आकांक्षाओं के अनुसार व्यवसाय-विशिष्ट क्षमता/कौशल प्राप्त करने के लिए तैयार किया जा सके।

7.58 समग्र शिक्षा योजना के तहत, स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और व्यावसायिक शिक्षा को समायोजित करने के लिए फर्नीचर, कंप्यूटर आदि सहित उपकरण और उपकरण खरीदने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक गैर-आवर्ती अनुदान दिया जाता है। शिक्षकों/कौशल प्रशिक्षकों की क्षमता निर्माण, योग्यता-आधारित पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्री के विकास, प्रबंधन सूचना प्रणाली के विकास आदि के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 22 क्षेत्रों में एनएसक्यूएफ-अनुपालक 113 जॉब रोल्स में से चुन सकते हैं।[55]

7.59 प्राप्त प्रगति के संदर्भ में, वित्त वर्ष 19 से वित्त वर्ष 24 (मार्च 2024 तक) तक 29,342 स्कूलों को कौशल शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया है। वित्त वर्ष 24 तक 88 नौकरी भूमिकाओं वाले 22 क्षेत्रों को कौशल शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया। हब और स्कोप मॉडल के तहत वित्त वर्ष 24 में कुल 25 नई नौकरी भूमिकाएँ शुरू की गईं, जिसके तहत हब स्कूलों के बुनियादी ढाँचे का उपयोग आस-पास के स्पोक स्कूलों द्वारा किया जा सकता है, 1011

53 योग्यता-आधारित शिक्षा एक ऐसा दृष्टिकोण है जो केवल रटने पर निर्भर रहने के बजाय विशिष्ट कौशल, ज्ञान, योग्यता और स्वभाव के विकास और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है।

54 मुरलीधरन, कार्तिक। 2024. भारत के विकास को गति देना: प्रभावी शासन के लिए राज्य-नेतृत्व वाली रोडमैप। पेंगुइन इंडिया वाइकिंग, आईएसबीएन: 9780670095940, अध्याय 10

55 ये 22 क्षेत्र हैं: एयरोस्पेस और विमानन, कृषि, परिधान और होम फर्निशिंग, ऑटोमोटिव, बैंकिंग वित्त और बीमा सेवाएं (बीएफएसआई), सौंदर्य और कल्याण, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, हस्तशिल्प और कालीन, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आईटी/आईटीईएस), प्रबंधन और उद्यमिता, मीडिया और मनोरंजन, खाद्य उद्योग, शारीरिक शिक्षा और खेल, प्लंबर, बिजली, खुदरा, सुरक्षा, दूरसंचार, पर्यटन और आतिथ्य, परिवहन रसद और भंडारण।

स्पोक स्कूलों को मंजूरी दी गई है। वित्त वर्ष 25 के लिए 1,08,418 स्कूलों के लिए उच्च प्राथमिक छात्रों को कौशल शिक्षा का एक्सपोजर स्वीकृत किया गया है, और 3643981 छात्रों को एक्सोपज दिया गया है। संचार कौशल, स्व-प्रबंधान कौशल, आईसीटी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल सहित रोजगार मॉड्यूल को नौकरी की भूमिका पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।

उच्च शिक्षा

7.60 उच्च शिक्षा क्षेत्र, जिसमें विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में तृतीयक और स्कूल के बाद की शिक्षा शामिल है, ने पिछले आठ वर्षों में कुल नामांकन में तेजी के साथ-साथ श्नामांकन इक्विटीश में वृद्धि देखी है। एआईएसएचई 2021-22 के अनुसार,[56] उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वित्त वर्ष 22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया है, जो वित्त वर्ष 21 में 4.14 करोड़ और वित्त वर्ष 15 में 3.42 करोड़ था (वित्त वर्ष 15 से 26.5 प्रतिशत की वृद्धि)।

चार्ट VII.6: उच्च शिक्षा में कुल छात्रों का नामांकन

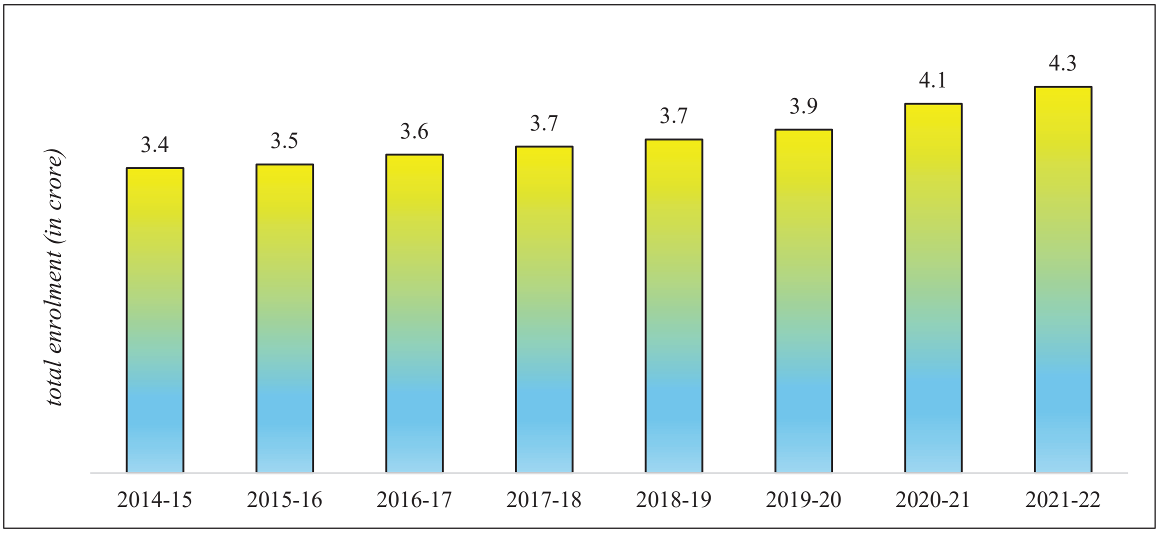

स्रोत: उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट 2021-22, शिक्षा मंत्रालय

उच्च शिक्षा में बढ़ती समानता

7.61 उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे वंचित वर्गों द्वारा संचालित की गई है, और सभी वर्गों में महिला नामांकन में तेज वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 2014 वित्त वर्ष 2015 में 1.57 करोड़ से बढ़कर 2021 वित्त वर्ष 22 में 2.07 करोड़ हो गया, यानि 2014 वित्त वर्ष 15 से 31.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उच्च शिक्षा में बढ़ती समानता का अर्थ है कि अब तक पिछड़े वर्गों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त होना।

56 उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा 2011 से देश में उच्चतर शिक्षा पर डेटा एकत्र करने के लिए किया गया एकमात्र व्यापक सर्वेक्षण है, जिसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा के लिए एक मजबूत और समावेशी डेटाबेस तैयार करना है।

तालिका VII.6: विभिन्न श्रेणियों से उच्च शिक्षा में नामांकन संख्या लाख में

	2014-15 में नामांकन	2021-22 में नामांकन
समस्त	342	433
सभी महिला	157	207
अनुसूचित जाति	46.1	66.2
एससी महिला	21	31.7
अनुसूचित जनजाति	16.4	27.1
एसटी महिला	7.5	13.5
अन्य पिछड़ा वर्ग	113	163
ओबीसी महिला	52.4	78.2

स्रोतः एआईएसएचई 2021-22, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय

चार्ट VII.7: 2014-15 और 2021-22 के बीच उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन में वृद्धि (प्रतिशत)

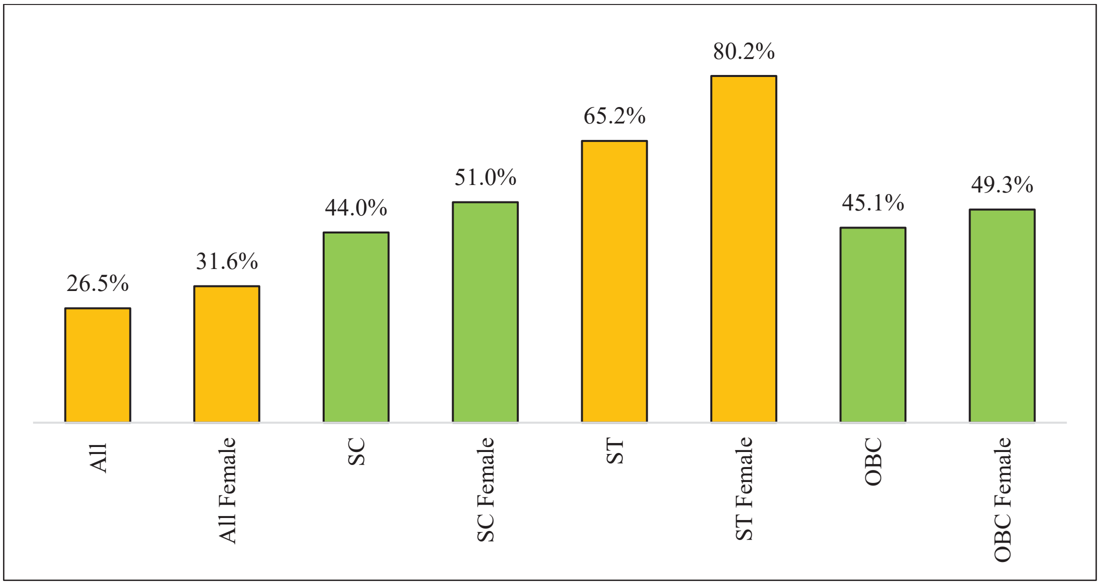

स्रोतः एआईएसएचई 2021-22, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय

डिजिटल प्रिज्म के माध्यम से आजीवन शिक्षा की पुनःकल्पना

7.62 भारत में 26.52 करोड़ छात्र स्कूल में हैं, 4.33 करोड़ उच्च शिक्षा में हैं और 11 करोड़ से ज्यादा छात्र कौशल विकास संस्थानों में पढ़ रहे हैं। शिक्षा के विशाल क्षेत्र में 14.89 लाख स्कूल, 1.50 लाख माध्यमिक विद्यालय, 1.42 लाख उच्च माध्यमिक विद्यालय,[57] 1,168 विश्वविद्यालय, 45,473 कॉलेज, 12,002 स्वतंत्र संस्थान,[58] स्कूली शिक्षा में 94.8 लाख शिक्षक और उच्च शिक्षा में 15.98 लाख शिक्षक शामिल हैं।

7.63 ये व्यापक आंकड़े चुनौती की व्यापकता और भारत के शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए एनईपी 2020 की अंतर्निहित महत्वाकांक्षा को परिप्रेक्ष्य में रखते हैं। एनईपी शिक्षा और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में आजीवन सीखने को शामिल करने के लिए संस्थागत क्षमता को मजबूत करने की दिशा में प्रयासों के केंद्र में है। यह सीखने की प्रणालियों को अधिक समग्र, बहु-विषयक और व्यापक बनाने के लिए औपचारिक, अनौपचारिक और अनौपचारिक तरीकों में पहलों के परस्पर जुड़ाव का आह्वान करता है ताकि विविध सीखने की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

7.64 अप्रैल 2023 में एनईपी के तहत घोषित नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) आजीवन शिक्षा को आधार प्रदान करने वाले विनियामक ढांचे का आधार बनाता है। विनियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए डिजिटल समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जैसे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई), जो बल गुणक के रूप में कार्य करती है। भारत के शैक्षिक डीपीआई में सबसे प्रमुख एपीएएआर अर्थात स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री है, जो शिक्षा क्षेत्र में प्रत्येक हितधारक के लिए अद्वितीय पहचान और आजीवन शैक्षणिक प्रमाण-पत्र बनाकर संस्थानों, छात्रों और संकाय के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री के रूप में कार्य करती है। एपीएएआर को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) द्वारा पूरक किया जाता है, जो अकादमिक क्रेडिट का एक ऑनलाइन भंडार है जो क्रेडिट मान्यता, संचय, स्थानांतरण और मोचन की औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में छात्रों की गतिशीलता की सुविधा प्रदान करता है। एक बार एपीएएआर आईडी बन जाने के बाद, एचईआई छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट को उनकी आईडी से मैप करते हैं, और ऐसे सभी क्रेडिट एबीसी में डीमैट रूप में संग्रहीत होते हैं।

7.65 एपीएएआर और एबीसी का दोहरा समाधान, पहचान और शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के वास्तविक समय के सत्यापन की अनुमति देकर, कई उपयोग के मामलों का मार्ग प्रशस्त करता है। इनमें छात्रों द्वारा किसी विशेष योग्यता (अब एक वास्तविकता) के लिए विभिन्न संस्थाओं से क्रेडिट कोर्स करने या अकादमिक प्रोफाइल का उपयोग करके छात्रवृत्ति/इंटर्नशिप/शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने की संभावना शामिल है। इन डीपीआई में निर्मित डेटा कंसेंट लेयर के साथ, संभावनाओं की एक रोमांचक दुनिया खुलती है जहाँ डेटा प्रिंसिपल (छात्र) इंटर्नशिप, नौकरी या सहयोगी अवसरों के लिए संभावित नियोक्ताओं या संस्थानों के साथ अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्र साझा कर सकते हैं। जुलाई 2024 तक, 2037 उच्च शिक्षा संस्थानों ने एबीसी को शामिल कर लिया है, और उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा और कौशल संस्थानों के छात्रों के लिए 30.13 करोड़ एपीएएआर आईडी बनाई गई हैं।[59]

7.66 भारत की ऑनलाइन शिक्षण संरचना क्रेडिटीकरण में सहायक रही है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों के अनुसार छात्रों को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से 40 प्रतिशत तक क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति है। नीचे दिए गए बॉक्स VII.7 में इस संबंध में प्रमुख पहलों की विस्तृत सूची दी गई है।

57 https://dashboard.udiseplus.gov.in/#/reportDashboard/sDashboard
58 https://tinyurl.com/4sp5tkpz
59 https://www.abc.gov.in/

बॉक्स VII.7: भारत की ऑनलाइन शिक्षण संरचना

स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयं), स्वयं प्रभा और स्वयं प्लस के संयोजन से संचालित, स्वदेशी रूप से तैयार किए गए प्लेटफॉर्म डिजिटल विभाजन को पाटने और एनईपी के प्रमुख सिद्धांतों अर्थात पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने में शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में उभरे हैं।

- स्वयं, एक ओपन लर्निंग डव्ळ प्लेटफॉर्म है, जो पूरे भारत में छात्रों को उच्च-गुणवत्ता वाली सामग्री तक पहुँच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रहा है, जिससे उन्हें ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में मुख्यधारा में लाया जा सके। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों में 13140+ कोर्स उपलब्ध हैं, जिनमें AI, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उभरती हुई तकनीकें शामिल हैं। 4.3 करोड़ नामांकन के साथ, स्वयं आज सबसे लोकप्रिय ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म में से एक के रूप में उभरा है।
- स्वयंप्रभा, एक डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) सैटेलाइट टीवी सेवा है जिसमें 48 से अधिक डीटीएच चौनल शामिल हैं, जिसने विभिन्न विषयों पर यूजी/पीजी स्तर की शिक्षा सामग्री प्रदान की है, जो एक संरचित शेड्यूल के साथ 24×7 उपलब्ध है। इस सेवा की पहुंच उल्लेखनीय है, जिसने 1.2 मिलियन से अधिक छात्रों को आकर्षित किया है और 143,000 से अधिक अद्वितीय वीडियो देखे हैं, कुल मिलाकर 86,000 घंटे देखने का समय है।
- स्वयं प्लस आईआईटी मद्रास द्वारा संचालित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो अकादमिक और एलएंडटी तथा माइक्रोसॉफ्ट जैसे उद्योग जगत के नेताओं के सहयोग से क्रेडिट मान्यता के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य उद्योग के साथ साझेदारी में विकसित पाठ्यक्रमों के माध्यम से, विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में कॉलेज के छात्रों और आजीवन शिक्षार्थियों के बीच रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना है, जो विनिर्माण, ऊर्जा, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग/आईटी/आईटीईएस, प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य और पर्यटन, तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पहल गतिशील उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए एक अवसर प्रदान करती है।
- एनईपी उच्च शिक्षा में गतिशीलता, लचीलापन और विकल्प बढ़ाने पर जोर देती है। शिक्षा मंत्रालय और भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान के सहयोग से विकसित ई-गवर्नेंस समाधान समर्थ का उद्देश्य एचईआर में प्रवेश से लेकर डिग्री देने तक की प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से बदलना है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, आईआईटी, आईआईएम आदि सहित 3500 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों ने अपनाया है, जो पूरे भारत में डिजिटल रूप से सक्षम परिसरों का एक नेटवर्क स्थापित करने में योगदान दे रहा है।
- पीएम ई-विद्या पहल डिजिटल शिक्षा प्रयासों को एकीकृत करती है, जो दीक्षा और साथी प्लेटफॉर्म के माध्यम से विविध सामग्री तक पहुँच प्रदान करती है। दीक्षा में 30+ भाषाओं[60] में 3.5 लाख से अधिक ई-सामग्री और 6854 एनर्जाइज्ड पाठ्यपुस्तकें हैं। साथी प्लेटफार्म प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए संसाधन प्रदान करता है, जिसमें लगभग 2000 वीडियो व्याख्यान, 80,000+ समस्याएँ, मॉक टेस्ट, एक एआई चौटबॉट और नीट और जेईई उम्मीदवारों के लिए आईआईटी और एम्स के छात्रों से मार्गदर्शन शामिल है।

60 https://tinyurl.com/2xj6ra8h

शिक्षा में आगे का मार्ग

7.67 चूंकि शिक्षा भारत के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, इसलिए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए और उद्देश्यगत कार्यक्रमों का मिशन-मोड और लागत-प्रभावी कार्यान्वयन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आवश्यक है, खासकर प्राथमिक शिक्षा, जिसके बिना शिक्षा के आगे के वर्षों का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसे साकार करने के लिए, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों में उद्देश्य की एकता और प्रयासों के अभिसरण की आवश्यकता है, क्योंकि सार्वजनिक शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है।

7.68 सीखने की सीढ़ी पर व्यावसायिक शिक्षा को क्रियान्वित करने के लिए, एक गैर सरकारी संगठन लेंड ए हैंड इंडिया (LAHI) का मॉडल एक अच्छा उदाहरण है। LAHI मॉडल में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य पाठ्यक्रम घटक के रूप में पेश करने, प्रयोगशालाएँ स्थापित करने, व्यावसायिक प्रशिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण देने, इंटर्नशिप आयोजित करने और प्लेसमेंट सहायता प्रदान करने के लिए सरकारों के साथ नागरिक समाज का सहयोग शामिल है। व्यापक व्यावसायिक शिक्षा सेवाएँ प्रदान करके और प्रमुख हितधारकों के साथ जुड़कर, नागरिक समाज छम्च 2020 की नवीन विशेषताओं को लागू करने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है।

7.69 शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय की लागत-प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षण और शासन पर खर्च करना आवश्यक है। इसमें शिक्षण गुणवत्ता की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक पदों को भरना, अच्छे और बुरे शिक्षक प्रदर्शन की पहचान करना और 'सही स्तर पर शिक्षण' सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों को नियुक्त करना शामिल हो सकता है क्योंकि पाठ्यपुस्तकों को पूरा करने का कोई मतलब नहीं है अगर बच्चे पाठ्यक्रम मानकों से बहुत पीछे हैं (मुरलीधरन 2024)[61]

भारत अनुसंधान एवं विकास में प्रगति कर रहा है

7.70 अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) किसी अर्थव्यवस्था में नवाचार, प्रगति और उत्पादकता में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अर्थशास्त्र में, अंतर्जात विकास सिद्धांत तकनीकी प्रगति की दर से निर्धारित होने वाले दीर्घकालिक आर्थिक विकास पर प्रकाश डालता है, जो किसी राष्ट्र की प्रगति पर आर एंड डी के अंतिम प्रभाव की ओर इशारा करता है। आर एंड डी व्यवसायों को उत्पादकता में सुधार, परिचालन लागत को कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करता है।[62] एआई, पर्यावरण विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में आर एंड डी आर्थिक और रणनीतिक दोनों हितों की पूर्ति करता है।

61 मुरलीधरन, कार्तिक। 2024. भारत के विकास को गति देना: प्रभावी शासन के लिए राज्य-नेतृत्व वाली रोडमैप। पेंगुइन इंडिया वाइकिंग, आईएसबीएन: 9780670095940, अध्याय 10

62 जोशी, पी एल. (2023). भारत को अपनी वैश्विक ताकत बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) में निवेश बढ़ाने की जरूरत है (वॉल्यूम 4 नंबर 1, 2023)। Vol 4 No 1, 2023. 4. 1-13. 10.47509/GJAER.2023.v04i01.01.

7.71 भारत अनुसंधान एवं विकास में तेजी से प्रगति कर रहा है,[63] वित्त वर्ष 2020 में 25,000 से कम पेटेंट अनुदान की तुलना में वित्त वर्ष 24 में लगभग एक लाख पेटेंट दिए गए।[64] WIPO के अनुसार, भारत ने 2022 में पेटेंट फाइलिंग में सबसे अधिक वृद्धि (31.6 प्रतिशत) देखी,[65] जो इसके विकसित नवाचार परिदृश्य और बौद्धिक संपदा निर्माण में आगे बढ़ने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। GII (2023) के अनुसार[66] भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2015 में 81 वें स्थान से 2023 में 40 वें स्थान पर अपनी रैंक में लगातार सुधार किया है। मानव संसाधन के मामले में, भारत में कुल पीएचडी नामांकन वित्त वर्ष 2015 (1.17 लाख) से वित्त वर्ष 2022 (2.13 लाख) में 81.2 प्रतिशत बढ़ा है।[67] देश में अनुसंधान एवं विकास (जीईआरडी) पर सकल व्यय पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रहा है और यह 2010-11 में ₹60,196 करोड़ से दोगुना होकर वित्त वर्ष 21 में 127,381 करोड़ ₹ हो गया है (चार्ट VII.8)।

चार्ट VII.8: अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय

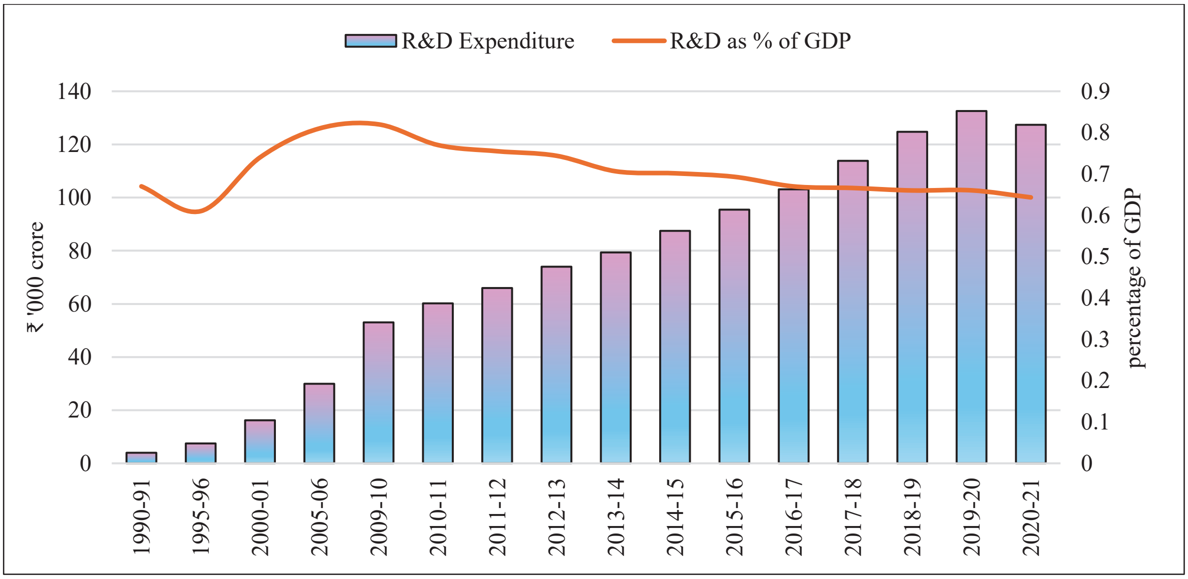

स्रोत: अनुसंधान एवं विकास सांख्यिकी एक नजर में, 2022-23, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

7.72 उच्च गुणवत्ता वाले शोध में भारत की उन्नति के संकेत के रूप में, देश नेचर इंडेक्स 2023 में[68] ऑस्ट्रेलिया और स्विटजरलैंड को पछाड़ते हुए 9वें स्थान पर पहुंच गया है।[69] उच्च गुणवत्ता वाले शोध लेखों में भारत की हिस्सेदारी[70] (प्रतिशत के बजाय पूर्ण संख्या के संदर्भ में मापी गई) पिछले चार वर्षों में 44 प्रतिशत बढ़ी है, अर्थात 2019 में 1039. 7 से 2023 में 1494.7 हो गई। तथापि, चीन और अमेरिका की 20,000 से अधिक हिस्सेदारी की तुलना में भारत की हिस्सेदारी काफी कम है।

63 पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 16 मार्च 2024 https://tinyurl.com/34dz2bfh
64 पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 12 अप्रैल 2022 https://tinyurl.com/2j4p533n
65 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) (2023)। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023। जिनेवा: WIPOA DOI: 10.34667/tind.48541, पृष्ठ 30, प्रदर्शनी I.18
66 PIB release dated 29 December 2023 https://tinyurl.com/2w2zuefr
67 पीआईबी द्वारा एआईएसएचई रिपोर्ट जारी, दिनांक 25 जनवरी 2024 https://tinyurl.com/43fh85v2
68 नेचर इंडेक्स संस्थागत और राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित लेखों की पूर्ण संख्या और आंशिक हिस्सेदारी की संख्या प्रदान करता है, और इस प्रकार यह वैश्विक उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान आउटपुट और सहयोग का एक संकेतक है।
69 बेंजामिन प्लैकेट, 18 जून 2024, नेचर इंडेक्स न्यूज https://tinyurl.com/yc8syskb 25 जून 2024 को एक्सेस किया गया
70 शेयर एक मीट्रिक है जो किसी देश में रहने वाले लेखकों द्वारा इंडेक्स में पेपर में योगदान को मापता है, लेख के सभी लेखकों की तुलना में। उदाहरण के लिए, यदि किसी लेख के 4 लेखक हैं और सभी 4 भारत से हैं, तो यह भारत के हिस्से में 1.0 जोड़ देगा। यदि 4 में से 2 लेखक भारत से हैं, तो यह भारत के हिस्से में 0.5 जोड़ देगा।

चार्ट VII.9: नेचर इंडेक्स में शीर्ष दस देशों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले शोध पत्रों में योगदान

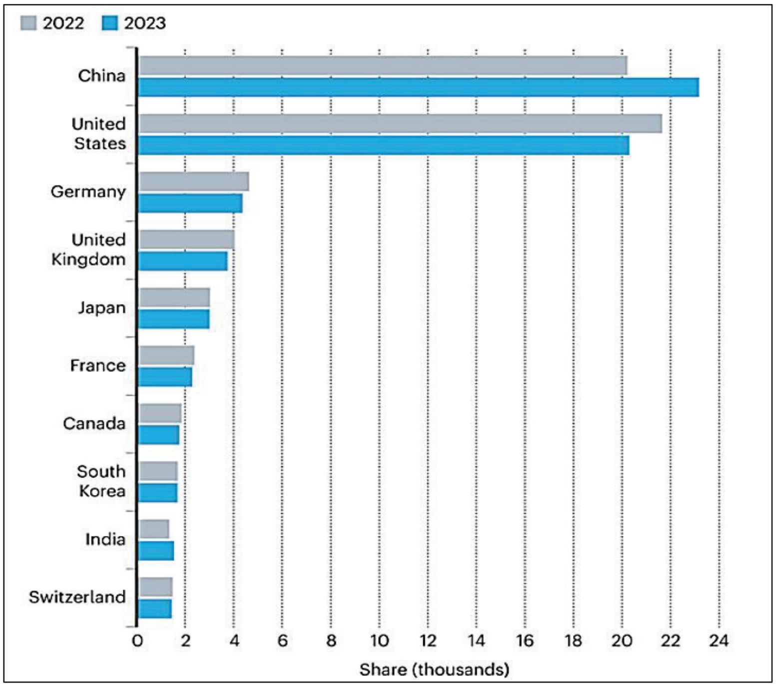

स्रोत: नेचर इंडेक्स 2024 रिसर्च लीडर्स

चार्ट VII.10: सरकार, व्यवसाय उद्यम और उच्च शिक्षा क्षेत्र की भागीदारी, 2020

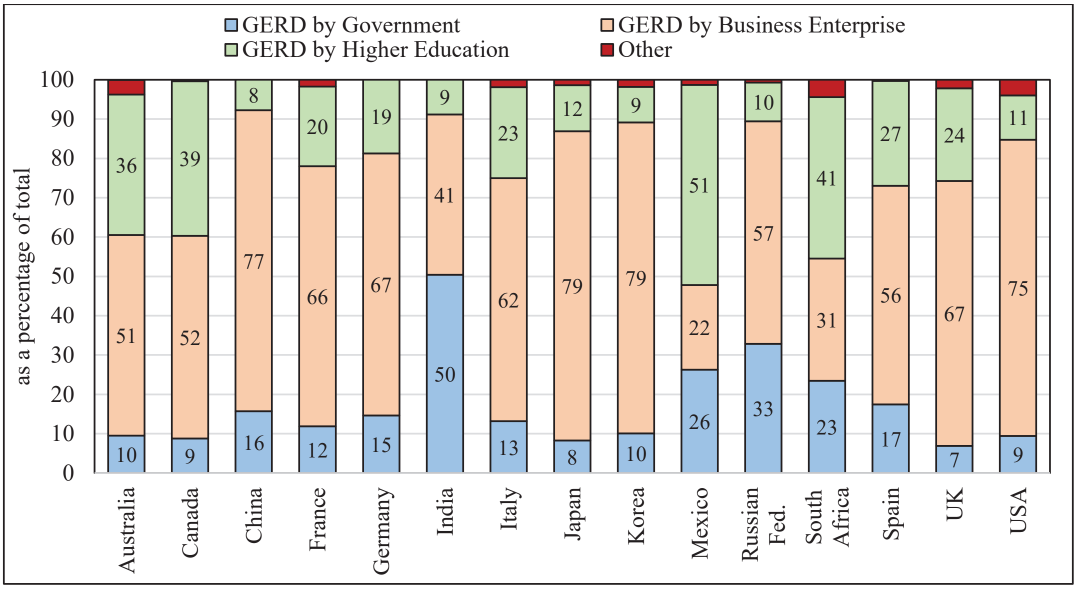

स्रोत: अनुसंधान एवं विकास सांख्यिकी एक नजर में, 2022-23, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

7.73 तथापि, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत का आरएंडडी निवेश 0.64 प्रतिशत है, जबकि चीन (2.41 प्रतिशत), अमेरिका (3.47 प्रतिशत), इजरायल (5.71 प्रतिशत) है। इसके अलावा, आरएंडडी में निजी क्षेत्र का योगदान देश के जीईआरडी के 36.4 प्रतिशत पर कम है, जबकि चीन (77 प्रतिशत), अमेरिका (75 प्रतिशत) आदि में यह योगदान कम है।[71]

71 https://dst.gov.in/document/reports/rd-statistics-glance-2022-23

7.74 जीईआरडी को शोध आउटपुट में बेहतर ढंग से अनुवाद करने के लिए, उच्च शिक्षा, उद्योग और अनुसंधान के बीच संबंध को मजबूत किया जाना चाहिए। एक और चुनौती 'भूमि से प्रयोगशाला' तक का कम समय है। भारत में संस्थान तकनीक विकसित करते हैं, लेकिन लोगों के लाभ[72] के लिए प्रयोगशाला से समाज तक उनके परिवर्तन की दर कम है।

7.75 शोध कर्मियों को आकर्षित करने और राष्ट्र के शोध पारिस्थितिकी तंत्र में पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए कई प्रयास चल रहे हैं। पेटेंट अनुदानों को सुव्यवस्थित करके शोध करने की आसानी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे पेटेंट आवेदन की जांच के लिए लगने वाले औसत समय[73] में भारी कमी आई है, जो 2015 में 72 महीनों से घटकर 2022 में 5 से 23 महीने के बीच रह गया है, जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों पर निर्भर करता है। सरकार ने हाल ही में पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल शोध करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा, भारत ने[74] विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम, 2023 अधिनियम के तहत) द्वारा संचालित[75] श्अनुसंधानश नामक अपना स्वयं का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन शुरू किया है।[76] यह फाउंडेशन एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा जिसका उद्देश्य राष्ट्र के आर एंड डी इकोसिस्टम को मजबूत करना और बढ़ावा देना है। सरकार ने "जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान" के नारे को अपनाते हुए देश में अनुसंधान और नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के कोष के वित्त वर्ष 25 के अंतरिम बजट की भी घोषणा की है।

महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण

7.76 भारत एक ऐसे नए भारत के निर्माण के लिए महिला विकास से महिला-नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ रहा है, जहाँ महिलाएँ विकास और राष्ट्रीय प्रगति की कहानी में समान भागीदार हैं। नारी शक्ति के आह्वान को साकार करने के लिए, सरकार ने विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विधायी हस्तक्षेप और सक्षम प्रावधान किए हैं।

7.77 2023 में भारत की जी-20 प्रेसीडेंसी ने भी अपनी छह प्राथमिकताओं में से एक के रूप में श्महिलाओं के नेतृत्व वाले विकासश को सूचीबद्ध किया है, जो कि महिलाओं की कार्यबल भागीदारी के प्रति बढ़ते वैश्विक ध्यान के बीच है। श्रम बाजार में लैंगिक अंतर के प्रमुख चालकों पर उनके काम के लिए प्रो. क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने के साथ, लैंगिक मुद्दों की व्यापक मान्यता स्पष्ट है।

7.78 (घर के नजदीक) भारतीय महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे बुनियादी जरूरतों जैसे कि स्वच्छता, पाइप से पानी, मासिक धर्म स्वच्छता, आदि की कमी, सुरक्षा, उचित पोषण, आर्थिक और राजनीतिक अवसर की समानता और व्यक्तिगत पहचान की भावना से लेकर हैं। महिला विकास से महिला-नेतृत्व वाले विकास में संक्रमण के लिए मुद्दों की 360-डिग्री समीक्षा और उनसे निपटने के लिए एक ईमानदार, व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

7.79 इस इरादे से, भारत सरकार ने सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ में महिलाओं की भलाई में सुधार के लिए बहुआयामी पहल की है।

72 नए भारत के लिए रणनीति/75, नीति आयोग https://tinyurl.com/bdzdzb2u
73 पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 30 मार्च 2022 https://tinyurl.com/y4s82kts
74 पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 16 मार्च 2022 https://tinyurl.com/5h5buk9y
75 https://dst.gov.in/anusandhan-national-research-foundation-anrf
76 अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम, 2023 भारत की संसद का एक अधिनियम है। यह भारत में प्राकृतिक विज्ञान प्रतिष्ठानों के क्षेत्र में सभी अनुसंधान और विकास को विनियमित करने का प्रयास करता है। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 को निरस्त करता है और एसईआरबी को भंग करता है।

जेंडर बजट में लगातार वृद्धि

7.80 पिछले कुछ वर्षों में, सरकारी पहलों में महिला-केंद्रित तत्व बढ़ रहा है, जो विस्तारित जेंडर बजट में स्पष्ट है। वित्त वर्ष 2014 में, सरकार ने महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए योजनाओं पर ₹97,134 करोड़ (बीई) का प्रावधान किया, जो पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ता रहा है और वित्त वर्ष 2025 में ₹3.10 लाख करोड़ तक पहुँच गया। यह वित्त वर्ष 2024 के बीई की तुलना में जेंडर बजट स्टेटमेंट (जीबीएस)[77] में 38.7 प्रतिशत की वृद्धि और वित्त वर्ष 2014 के बीई की तुलना में 218.8 प्रतिशत की वृद्ध्रि दर्शाता है। कुल केंद्रीय बजट में जेंडर बजट का हिस्सा वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गया, जो वित्त वर्ष 2006 में जीबीएस की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है।[78]

महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण

7.81 महिलाओं के नेतृत्व में विकास बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को सुनिश्चित करने से शुरू होता है। ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' पर जोर देने से बालिकाओं को पालने, शिक्षित करने और उनके लिए बचत करने (सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से)[79] के प्रति सामूहिक चेतना जागृत हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) 918 (2014-15) से बढ़कर 930 (2023-24, अनंतिम)[80] हो गया है और मातृ मृत्यु दर 2014-16 में 130/लाख जीवित जन्मों से घटकर 2018-20 में 97/लाख[81] जीवित जन्म हो गई है।

7.82 पिछले दशक में, संस्थागत प्रसव का प्रचलन 2015-16 में 78.9 प्रतिशत से बढ़कर 2019-21 में 88.6 प्रतिशत हो गया है।[82] आय में वृद्धि और स्वास्थ्य प्रथाओं के बारे में जागरूकता के अलावा, सकारात्मक प्रवृत्ति पीएम जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के कार्यक्रम के कारण है। पीएम मातृ वंदना योजना,[83] जिसमें पहले बच्चे के जन्म के लिए ₹5000 का नकद भुगतान और दूसरा बच्चे के लिए 6000 रु जो लड़की है, किसी भी मजदूरी के नुकसान की आंशिक रूप से भरपाई करके नई माताओं को उचित आराम के लिए प्रोत्साहित करता है। भारत का अब तक का सबसे बड़ा सशर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रम कहा जाने वाला यह कार्यक्रम लोक स्वास्थ्य सेवाओं के दीर्घकालिक उपयोग में वृद्धि और जन्मों के बीच अंतराल बढ़ाने के सकारात्मक दुष्प्रभावों से अनुभवजन्य रूप से जुड़ा हुआ है (हैरेन और क्लोनर 2021)।[84]

आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की पोषण सुरक्षा

7.83 महिलाओं की पोषण स्थिति दोगुनी महत्वपूर्ण है - पहला, उनके अपने स्वास्थ्य, उत्पादकता और कल्याण के लिए, और दूसरा, उनके बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए। इस प्रकार महिलाओं का स्वास्थ्य सामाजिक स्वास्थ्य का आधार बनता है। इसे मान्यता देते हुए, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम कुपोषण मुक्त भारत को प्राप्त करने के लिए जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों और किशोरियों में कुपोषण को दूर करने का प्रयास करता है।

---

77 जेंडर बजट विवरण मंत्रालयों/विभागों के लिए एक रिपोर्टिंग तंत्र है, जिसके माध्यम से वे अपने कार्यक्रमों की जेंडर परिप्रेक्ष्य से समीक्षा करते हैं तथा महिलाओं और बालिकाओं के लिए आबंटन पर सूचना प्रस्तुत करते हैं।

78 स्रोत: बजट दस्तावेज, केंद्र सरकार

79 सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए वित्तीय नियोजन हेतु एक प्रमुख लघु जमा योजना है। इस योजना के अंतर्गत 3.1 करोड़ से अधिक खाते हैं

80 स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस)

81 स्रोत: नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण

82 स्रोत: एनएफएचएस-5, भारत तथ्य पत्रक https://rchiips.org/nfhs/NFHS-5_FCTS/India.pdf .

83 यह योजना 2017 में शुरू की गई थी। 31 मार्च 2023 तक 3.32 करोड़ लाभार्थियों को नामांकित किया गया है, जिनमें से 3.05 करोड़ लाभार्थियों को घ13,460 करोड़ का कुल संवितरण प्रदान किया गया है।

84 वॉन हारेन पी, क्लोनर एस. सीखे गए सबक? भारत की दूसरी पीढ़ी की मातृ नकद हस्तांतरण योजना के इच्छित और अनपेक्षित प्रभाव। हेल्थ इकॉन। 2021 सितंबर;30(10):2468-2486.

7.84 एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में,[85] यह केवल कैलोरी की पर्याप्तता से ध्यान हटाकर सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्तता के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा पर केंद्रित करता है। इसमें शिशु और छोटे बच्चों के आहार प्रथाओं (स्तनपान और पूरक पोषण सहित), मातृ एवं किशोर पोषण, कुपोषित बच्चों के उपचार और आयुष प्रथाओं को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता पैदा करना भी शामिल है। कार्यक्रम प्रक्रिया में सुधार (विकास माप उपकरण ों का उपयोग करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन से लैस करना,[86] वास्तविक समय की प्रगति और कुपोषण की गतिशील पहचान के लिए पोषण ट्रैकर का उपयोग करना) और पोषण माह और पोषण पखवाड़ा जैसे समुदाय-आध ारित कार्यक्रमों के माध्यम से व्यवहार में बदलाव और स्वास्थ्य प्रथाओं पर परामर्श पर जोर देता है। अपने दायरे को और व्यापक बनाने के लिए, आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी में अपग्रेड किया जा रहा है, जो[87] सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए एलईडी स्क्रीन, ऑडियो-विजुअल शिक्षण सहायक सामग्री, पोषण वाटिका, वर्षा जल संचयन संरचनाएं आदि से लैस हैं।

7.85 कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में पंचायत और महिला समूहों की भागीदारी से लाभ मिलता है, जैसा कि ओडिशा के मामले में देखा जा सकता है, जहां आईसीडीएस कार्यक्रम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की निगरानी और उन्हें मजबूत करने के लिए गांव स्तर पर जांच समितियां और माताओं की समितियां स्थापित की गई हैं। माताओं की समितियां आंगनवाड़ी केंद्रों में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करती हैं, जबकि जांच समितियां भोजन कार्यक्रमों की गुणवत्ता और मात्रा मान्यता की देखरेख करती हैं। यह व्यवस्था स्वयं सहायता समूहों की जवाबदेही बढ़ाती है और प्रदान किए जाने वाले भोजन की सुरक्षा में विश्वास बढ़ाती है।[88]

7.86 बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुँच: महिलाओं के नेतृत्व में विकास की शुरुआत करने के लिए, ग्रामीण और निम्न आय वाले परिवारों की महिलाओं के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाली लिंग-विशिष्ट कमियों से सबसे पहले निपटना होगा। इस लक्ष्य की ओर, 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत शौचालयों का निर्माण, 'उज्जवला योजना' के तहत स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन का प्रावधान और श्जल जीवन मिशनश के तहत नल के पेयजल कनेक्शन के प्रावधान ने महिलाओं के जीवन को बदल दिया है, जिससे उनकी मेहनत और देखभाल का बोझ कम हो गया है। ये पहल, सुरक्षा और सम्मान की चिंताओं को संबोधित करने के अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के माध्यम से महिलाओं के सामूहिक कार्यों में भागीदारी जैसे उत्पादक कार्यों के लिए समय और ऊर्जा भी मुक्त करती हैं।

7.87 संबल के माध्यम से सुरक्षा:[89] लैंगिक हिंसा और सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए, वन-स्टॉप सेंटर[90] या सखी केंद्र नियमित और आपातकालीन चिकित्सा और कानूनी सहायता, पुलिस सुविधा, अस्थायी आश्रय और परामर्श की सुविधा प्रदान करते हैं, ताकि हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को न्याय पाने और विपत्ति से उबरने में सशक्त बनाया जा सके। 24 घंटे की टोल-फ्री महिला हेल्पलाइन श181श[91] सरकारी योजनाओं और आपातकालीन सेवाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करती है।

85 मिशन तीन मौजूदा योजनाओं, यानी आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को एकीकृत करता है, जिसे 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान लागू किया जाएगा।

86 31 मई 2023 तक 10.06 करोड़ लाभार्थी (गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और 6 वर्ष तक के बच्चे) पोषण ट्रैकर के अंतर्गत पंजीकृत हैं।

87 कार्यक्रम के अंतर्गत, 2025-26 तक 40,000 प्रतिवर्ष की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्रों में उन्नत किया जाएगा।

88 कृति कपूर और शोभा सूरी, "कुपोषण मुक्त भारत की ओर: पोषण अभियान से सर्वोत्तम अभ्यास और नवाचार," ओआरएफ विशेष रिपोर्ट संख्या 103, मार्च 2020, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन।

89 मिशन शक्ति को महिलाओं की सुरक्षा, पुनर्वास और सशक्तिकरण की आवश्यकता के व्यापक समाधान के रूप में शुरू किया गया है। मिशन में दो उप-योजनाएँ शामिल हैं, महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए 'संबल' और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 'सामर्थ्य'। सामर्थ्य के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), उज्ज्वला और स्वाधार गृह का नाम शक्ति सदन रखा गया है; कामकाजी महिला छात्रावास का नाम सखी निवास रखा गया है; लिंग बजटिंग; राष्ट्रीय क्रेच योजना (पालना); साथ ही राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए हब के एक नए घटक को शामिल किया गया है।

90 801 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1 अप्रैल 2015 से देश भर में 733 चालू हैं।

91 अभी तक 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में महिला हेल्पलाइन चालू हैं। महिला हेल्पलाइन ने अब तक 1.26 करोड़ से अधिक कॉल संभाले हैं और मार्च 2023 तक 63.95 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है।

7.88 शिक्षा और कौशल: भारत में महिला शिक्षा की वकालत करने वाले सामाजिक सुधार आंदोलनों का एक लंबा इतिहास रहा है, सावित्रीबाई फुले ने[92] 19वीं शताब्दी में कहा था कि ‘... शिक्षा के बिना एक महिला जड़ों और पत्तियों के बिना बरगद के पेड़ की तरह है।’ महिलाओं की शिक्षा निर्णय लेने, घर के भीतर सौदेबाजी की शक्ति, संसाधनों पर नियंत्रण और राजनीतिक भागीदारी के मामले में सशक्तिकरण का एक साधन बनी हुई है (एनगिडा 2017)।[93] सिन्हा, 2023 भारत के दक्षिणी राज्यों में मानव विकास संकेतकों की उच्च दर का श्रेय माध्यमिक शिक्षा में उच्च महिला नामांकन को देते हैं, जिसने विकास कार्यों और स्वयं सहायता समूहों में जागरूक और आत्मविश्वासी महिलाओं के एक बड़े हिस्से की भागीदारी को बढ़ावा दिया।[94]

7.89 स्कूलों में नामांकन के मामले में,[95] सर्व शिक्षा अभियान (2000 में शुरू) और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के साथ सभी स्तरों पर लैंगिक समानता हासिल की गई है। उच्च शिक्षा में, लगातार पाँच वर्षों से महिला जीईआर पुरुष जीईआर से अधिक रही है।[96] जबकि इसका अर्थ है लड़कियों की शिक्षा का बढ़ता महत्व, आर्थिक सशक्तीकरण में इसके अनुवाद के लिए बेहतर शिक्षण परिणाम, रोजगार, श्रम शक्ति भागीदारी और अनुकूल बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता होगी।

7.90 कौशल योजनाओं में महिलाओं को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित लोगों में महिलाओं की भागीदारी वित्त वर्ष 2016 में 42.7 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 52.3 प्रतिशत हो गई है। धन शिक्षण संस्थान योजना (जेएसएस) के तहत, कुल लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 82 प्रतिशत थी। दीर्घकालिक पारिस्थितिकी तंत्र में, अर्थात, आईटीआई और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में, महिलाओं की भागीदारी वित्त वर्ष 2016 में 9.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 13.3 प्रतिशत हो गई है। एनएपीएस के तहत, महिलाओं की भागीदारी भी वित्त वर्ष 2017 में 7.7 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 20.8 प्रतिशत हो गई। तथापि, कौशल कार्यक्रमों से लाभ को मूर्त रूप देने के लिए , उन्हें सुरक्षित और किफायती परिवहन और संभारतंत्र, क्रेच और दीर्घकालिक कैरियर परामर्श जैसे सहायक बुनियादी ढांचे के साथ पूरक करने की आवश्यकता है।

7.91 विज्ञान में महिलाएँ: विश्व बैंक के 2018 के आंकड़ों के अनुसार,[97] भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) स्नातकों का अनुपात सबसे अधिक 42.7 प्रतिशत है। हालाँकि, अनुसंधान और विकास में महिला वैज्ञानिकों की हिस्सेदारी केवल 18.6 प्रतिशत है।[98] इस विपरीतता को दूर करने के लिए, छत्र योजना ‘विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएँ- किरण (WISE KIRAN)’ STEM क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। 2018 और 2023 के बीच, लगभग 1962 महिला वैज्ञानिकों को महिला वैज्ञानिक योजना के तहत लाभ हुआ, जो महिला वैज्ञानिकों, विशेष रूप से करियर ब्रेक वाली महिलाओं के लिए अवसर प्रदान करती है। 2020 में शुरू किए गए विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में लड़कियों के कम प्रतिनिधित्व को दूर करना है। दिसंबर 2023 तक, 250 जिलों की कक्षा IX-XII की लगभग 21,600 छात्राएँ इस कार्यक्रम के अंतर्गत नामांकित हैं। अप्रैल 2023 में, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने CSIR-ASPIRE के तहत महिला वैज्ञानिकों के लिए विशेष अनुसंधान अनुदान शुरू किया और एक विशेष पोर्टल समर्पित किया। चंद्रयान-3 और आदित्य-एल1 सौर मिशन जैसे अत्याधुनिक अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों में महिलाओं का नेतृत्व विशिष्ट वैज्ञानिक क्षेत्रों में चल रहे लैंगिक परिवर्तन को दर्शाता है।

92 सावित्रीबाई फुले आधुनिक भारतीय शिक्षा की अग्रणी, समाज सुधारक और कवि थीं। अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने 1948 में पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया।

93 एनगीडा, वाईएम (2021)। महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा की त्रि-आयामी भूमिका। जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज।

94 अमरजीत सिन्हा, द लास्ट माइल। अक्टूबर 2023। पहला संस्करण। रूटलेज इंडिया। अध्याय 11, पूर्ण रोजगार के लिए कौशल पर पुनर्विचार

95 स्कूल शिक्षा विभाग के UDISE+ डैशबोर्ड पर डेटा देखें, https://dashboard.udiseplus.gov.in/#/reportDashboard/sReport

96 शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट के अनुसार, अर्थात 2017-18 से 2021-22 तक।

97 https://tinyurl.com/mr4btwfx

98 पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 7 फरवरी 2024 https://tinyurl.com/5n8p8y29

7.92 पुरुषों के गढ़ में सेंध: सरकार ने गैर-परंपरागत क्षेत्रों जैसे भारतीय वायु सेना में लड़ाकू पायलट, कमांडो, केंद्रीय पुलिस बलों, सैनिक स्कूलों में प्रवेश आदि में महिलाओं की भागीदारी को सक्षम बनाने के प्रावधान भी किए हैं।

7.93 राजनीतिक सशक्तिकरण: जन जीवन और राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में, नारी शक्ति वंदन अभियान, 2023 (एनएसवीए) महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की दिशा में एक छलांग है, जो अनुभवजन्य रूप से बेहतर संस्थानों और अधिक अखंडता से जुड़ा हुआ है। भारतीय इतिहास में, पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण 1991 में संवैधानिक रूप से लागू किया गया था, और तीन दशक बाद, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 46 प्रतिशत महिलाएँ हैं। शोध के अनुसार, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण ने सार्वजनिक वस्तुओं में अधिक निवेश को बढ़ावा दिया है, जो महिलाओं की चिंताओं से निकटता से जुड़ी हैं, जैसे कि पीने का पानी और सार्वजनिक सड़कें।[99] इसके अलावा, महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व बेहतर बाल स्वास्थ्य[100] और प्राथमिक शिक्षा परिणामों से भी जुड़ा हुआ है।[101] इन पंक्तियों के साथ, एनएसवीए लैंगिक समानता का प्रतीक होने के अलावा समावेशी विकास के लिए नई संभावनाएं खोलता है।

7.94 स्त्री पहचान में परिवर्तन: नारी शक्ति की शुरुआत महिलाओं को एक स्वतंत्र पहचान वाले व्यक्ति के रूप में मान्यता देने से होती है। इसका महत्व इतिहास में एक दिलचस्प उदाहरण में देखा जा सकता है। 1952 में, जब भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनावों की तैयारी कर रहा था, तब लगभग 28 लाख महिलाओं ने अपने वास्तविक नामों का उपयोग न करके बल्कि किसी की माँ/पत्नी के रूप में नामांकन कराया, जिसके कारण उनका मतदाता पंजीकरण अमान्य हो गया।[102] आज का भारत बहुत आगे निकल गया है और महिला नागरिकों की पहचान को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें हाल ही में NFSA, 2013 के तहत घर की सबसे बड़ी महिला के नाम पर राशन कार्ड जारी करना,[103] पीएम आवास योजना के तहत निर्मित घरों में महिलाओं के संयुक्त या एकमात्र स्वामित्व की आवश्यकता,[104] जन धन योजना के माध्यम से 25 करोड़ से अधिक बैंकिंग सेवाओं से वंचित महिलाओं तक पहुँचना[105] और स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) के तहत लगभग 10 करोड़ ग्रामीण महिलाओं का सामूहिकीकरण शामिल है।[106]

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

7.95 श्रम बल में बढ़ती भागीदारी : शिक्षा और कौशल विकास तक बढ़ती पहुंच के साथ-साथ महिला सशक्तीकरण की अन्य पहलों ने राष्ट्र के विकास और प्रगति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया है। महिला एलएफपीआर 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 37 प्रतिशत हो गई। तथापि, ग्रामीण भारत ने इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया है, जहां लगभग तीन-चौथाई महिला श्रमिक कृषि से संबंधित कार्यों में लगी हुई हैं। इस प्रकार, एलएफपीआर में वृद्धि को ग्रामीण महिला कार्यबल की जरूरतों और योग्यताओं के अनुकूल उच्च मूल्यवर्धन क्षेत्रों में लगाने की जरूरत है और कृषि प्रसंस्करण इसके लिए एक अच्छा दावेदार बनकर उभर रहा है, जैसा कि रोजगार पर अध्याय में चर्चा की गई है। लड़कियों की छवि को बोझ से कमाने वाले में बदलने में मूल्यवान रोजगार की भूमिका तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले की कहानी में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसकी चर्चा बॉक्स VII.7 में की गई है।

---

99 चट्टोपाध्याय, आर और डुफ्लो, ई (2004), ''नीति निर्माता के रूप में महिलाएं: भारत में एक यादृच्छिक नीति प्रयोग से साक्ष्य'', इकोनॉमेट्रिका, खंड 72, संख्या 5, 2004, पृष्ठ 1409-431।

100 भालोत्रा, एस. और आई. क्लॉट्स-फिगुएरस. 2010. "स्वास्थ्य और महिलाओं की राजनीतिक एजेंसी," माइमियो, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय.

101 क्लॉट्स-फिगुएरस, इरमा, 2007. ''क्या महिला नेता शिक्षा के लिए अच्छी हैं? : भारत से साक्ष्य,'' यूसी3एम वर्किंग पेपर्स। अर्थशास्त्र we077342, यूनिवर्सिडाड कार्लोस III डी मैड्रिड।

102 द हिंदू, 19मार्च 2024, https://tinyurl.com/ytsy4d3z

103 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013.

104 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्मित 2.41 करोड़ घरों में से 26.6 प्रतिशत घर पूरी तरह से महिलाओं के नाम पर हैं, तथा 69 प्रतिशत घर संयुक्त रूप से पत्नी और पति के नाम पर हैं।

105 https://tinyurl.com/bd7234z6

106 स्रोत: पीआईबी रिलीज 6 फरवरी 2024, रिलीज आईडी: 2003170 https://tinyurl.com/3nh99vnb

बॉक्स VII.8: महिला सशक्तीकरण के लिए रोजगार की प्रमुखता: कृष्णगिरि की लड़कियां वित्तीय स्वतंत्रता की स्याही से अपनी किस्मत खुद लिख रही हैं[107]

पिछले दशक में हुए औद्योगिक निवेश के कारण तमिलनाडु के सुदूरवर्ती जिले कृष्णागिरि में महिलाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा हुए हैं, जिससे एक सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक श्रृंखला प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई है।

यह जिला बाल विवाह, जन्मपूर्व लिंग चयन, कम बाल-लिंग अनुपात (राज्य औसत 946 की तुलना में 920)[108] और कम महिला साक्षरता (65 प्रतिशत) की उच्च घटनाओं से जूझ रहा था।[109] अनुभव से पता चलता है कि महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता उनके समग्र विकास के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, साथ ही सामाजिक परिवर्तन के लिए एक धुरी भी है।

इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल असेंबली, इलेक्ट्रिक स्कूटर, फुटवियर इत्यादि में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना ने महिलाओं के बड़े पैमाने पर रोजगार को बढ़ावा दिया है, क्योंकि निर्माताओं का मानना है कि महिला श्रमिक अधिक उत्पादक और निपुण होती हैं। इससे मानसिकता में बदलाव आया है क्योंकि जो परिवार लड़कियों को बोझ मानते थे, वे अब उन्हें कमाने वाली के रूप में देखते हैं, साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी कल्याणकारी प्रयासों को भी बढ़ावा मिला है। इसके परिणामस्वरूप लड़कियों के बाल विवाह और स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है, विवाह की औसत आयु में वृद्धि हुई है, साथ ही पॉलिटेक्निक संस्थानों में महिलाओं के नामांकन में भी वृद्धि हुई है।

कृष्णगिरि के अनुभव ने राज्य और कॉरपोरेट्स से दूसरे क्रम के प्रभावों को भी प्रेरित किया। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से ही कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करने , औद्योगिक छात्रावास स्थापित करने, माता-पिता को परामर्श देने आदि की नीतियाँ शुरू कीं। महिला कर्मचारियों की बढ़ती माँग ने कंपनियों के बीच भर्ती प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा दिया है, जो ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण, पिक-अप और ड्रॉप सुविधाएँ, डे केयर सुविधाएँ आदि शुरू करके अपने कर्मचारियों को बेहतर वेतन और शिक्षा मानदंडों में छूट का लालच देती हैं।

7.96 बढ़ती हुई शिक्षित और कुशल महिला आबादी द्वारा कार्यबल में भागीदारी के लैंगिक लाभांश को सही मायने में प्राप्त करने के लिए, देखभाल अर्थव्यवस्था का समुचित विकास आवश्यक है और यह लम्बे समय से लंबित है, जैसा कि रोजगार पर अगले अध्याय में चर्चा की गई है।

7.97 वित्तीय समावेशन: वित्तीय सेवाओं तक पहुँच से घरेलू संसाधनों पर महिलाओं का नियंत्रण बेहतर होता है और यह ऋण और बीमा तक पहुँचने का एक प्रवेश द्वार है। पीएम जन धन योजना ने 52.3 करोड़ बैंक खाते खोलने में मदद की है, जिनमें से माई 2023 तक 55.6 प्रतिशत खाताधारक महिलाएँ हैं। इसके साथ ही औसत जमा राशि में लगभग चार गुना वृद्धि हुई है, जो मार्च 2015 में ₹1,065 से बढ़कर मार्च 2023 में ₹4,398 हो गई है।

7.98 ग्रामीण सूक्ष्म वित्त: दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो कि सरकार का स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)[110] कार्यक्रम है, जो 8.3 मिलियन एसएचजी में 89 मिलियन से अधिक महिलाओं को कवर करता है,[111] अनुभवजन्य रूप से महिला सशक्तीकरण, आत्मसम्मान वृद्धि, व्यक्तित्व विकास, सामाजिक बुराइयों में कमी और बेहतर शिक्षा, गांव की संस्थाओं में उच्च भागीदारी और सरकारी योजनाओं तक बेहतर पहुंच के संदर्भ में मध्यम प्रभावों से जुड़ा हुआ है। मिशन सामाजिक पूंजी और अंतर-क्षेत्रीय ज्ञान को साझा करने और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) द्वारा सहायता प्रदान करने पर भी जोर देता है, जो ऐसी महिलाएं हैं जो कड़ी मेहनत और उद्यम के माध्यम से गरीबी

107 102. मीडिया लेख से स्रोत: एन माधवन, 27 फरवरी 2024, "क्यों एक बार नजरअंदाज की गई महिलाओं को कृष्णगिरि में संजोया जा रहा है" लाइवमिंट, https://tinyurl.com/57pkyrra accessed on 4 June 2024.

108 भारत की जनगणना, 2011.

109 https://krishnagiri.nic.in/about-district/district-at-a-glance/ accessed 4 जून 2024 को एक्सेस किया गया।

110 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) अधिकतम 20 व्यक्तियों का एक सामाजिक और आर्थिक रूप से समरूप समूह है, जो बचत और ऋण के सामूहिक उद्देश्य के लिए स्वैच्छिक रूप से गठित किया जाता है, जिसमें ऋण और ऋण के अंतिम उपयोग के लिए संपार्श्विक पर कोई जोर नहीं दिया जाता है।

111 PIB release dated 14 March 2023 https://tinyurl.com/4a4eruau

से बाहर निकली हैं। आजीविका आंदोलन के पैदल सैनिक कहे जाने वाले[112] 3.5 करोड़ से अधिक सीआरपी (कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीमा सखी, बैंकिंग संवाददाता सखी शामिल हैं) एसएचजी को लागू करने और बढ़ाने में सहायक हैं। सफलता की कहानियों में केरल में कुडुम्बश्री, बिहार में जीविका, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महिला मंडल और हाल ही में लद्दाख के लूम्स शामिल हैं। इस अध्याय के खंड VII.10 में इस कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की गई है।

7.99 उद्यमिता: स्टार्ट-अप और स्टैंड-अप इंडिया के माध्यम से उद्यमिता की लहर में महिलाओं की भागीदारी काफी उत्साहजनक रही है। पीएम मुद्रा योजना के तहत लगभग 68 प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं, और स्टैंड-अप इंडिया के तहत 77.7 प्रतिशत (माई 2024)[113] लाभार्थी महिलाएँ हैं। डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करते हुए, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए) के 53 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएँ हैं (जुलाई 2023 तक)। बैन एंड कंपनी (2020) का अनुमान है कि भारत में लगभग 13.5-15.7 मिलियन महिला-स्वामित्व वाले व्यवसाय हैं, जो देश के कुल उद्यमों का 17-20 प्रतिशत है। अधिक प्रोत्साहन और समर्थन के साथ, यह संख्या 2030 तक 31.5 मिलियन, अर्थात सभी उद्यमों का एक तिहाई तक बढ़ सकती है।[114]

परिसंपत्ति स्वामित्व की समानता की ओर

7.100 यद्यपि महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से पुरुषों के अधिकारों वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने की सामाजिक स्वीकृति बढ़ रही है, जैसे लड़ाकू विमान उड़ाना, यूनिकॉर्न कंपनी चलाना, या जिले/विभाग का नेतृत्व करना, और ऐसी खबरों का जश्न मनाया जाना, महिलाओं के बीच संपत्ति के स्वामित्व को बढ़ाने और महिला संपत्ति अधिकारों को सामान्य बनाने की बहुत गुंजाइश है। समानता के अंतर्निहित नैतिक मूल्य के अलावा, भूमि/संपत्ति पर महिलाओं का स्वामित्व उनकी वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक अवसरों के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को खेती और संबंधित ऋणों के लिए संसाधनों पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है, और संसाधनों के व्यक्तिगत उपयोग के बजाय परिवार-उन्मुख के माध्यम से घरेलू कल्याण होता है (अग्रवाल 1994)।[115] संपत्ति के स्वामित्व को वैवाहिक हिंसा में कमी से भी जोड़ा गया है (अग्रवाल और पांडा 2007)।[116] उत्तराधिकार[117] पर महिला-हितैषी कानूनों के बावजूद, शोध का अनुमान है[118] केवल भारत के नौ नमूना राज्यों में केवल 14 प्रतिशत भूमालिक महिलाएं थी (अग्रवाल, अंषवाल, और महेश, 2021) यहां तक कि भूमि मालिक महिलाओं को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे एकल स्वामित्व तक सीमित पहुंच, छोटी और घटिया गुणवत्ता वाली भूमि[119] (जैन, सक्सेना, सेन और सैनन, 2023)।

7.101 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित घरों के स्वामित्व की महिला की आवश्यकता[120] राज्य द्वारा लैंगिक समानता की दिशा में सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। फिर भी, व्यापक प्रगति जमीनी स्तर से उभरनी होगी, और आधी सदी पहले प्रकाशित साहित्य के ज्ञान से उधार लेते हुए, ''भविष्य के लिए निर्धारित किसी भी लक्ष्य की सामाजिक स्वीकृति के संकेतकों में पुरुषों और महिलाओं के दृष्टिकोण के साथ-साथ संस्थागत बुनियादी ढांचे

112 पीआईबी विज्ञप्ति 6 दिसंबर 2023, RU-33-01-335-061223/EXPLAINER https://tinyurl.com/4a4eruau

113 Source: Inputs from Dept of Financial Services

114 बैन एंड कंपनी (2020), पॉवरिंग द इकोनॉमी विद हर: वूमेन आंत्रप्रेन्योरशिप इन इंडिया, https://tinyurl.com/43cw2vky 21 जून 2024 को एक्सेस किया गया

115 अग्रवाल, बीना, 1994. ''लिंग और संपत्ति पर नियंत्रण: दक्षिण एशिया में आर्थिक विश्लेषण और नीति में एक महत्वपूर्ण अंतर,'' विश्व विकास, एल्सेवियर, खंड 22(10), पृष्ठ 1455-1478, अक्टूबर।

116 अग्रवाल, बी. और पांडा, पी. (2007) श्घरेलू हिंसा से मुक्ति की ओर: उपेक्षित स्पष्टश, जर्नल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, 8(3), पृ. 359-388. कवप: 10. 1080/14649880701462171.

117 इन नौ राज्यों में दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश (जिसे 2014 में विभाजित कर आंध्र प्रदेश श्नयाश और तेलंगाना बना दिया गया) और कर्नाटक; पश्चिमी और मध्य भारत में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश; तथा पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और ओडिशा शामिल हैं।

118 अग्रवाल, बीना, अंथवाल, परवेश, और महेश, मालविका। (2021)। श्भारत में कितनी और कौन सी महिलाएँ जमीन की मालिक हैं? अंतर-लिंग और अंतर-लिंग अंतर, जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, अप्रैल, ओपन एक्सेस ीजजचेः//कवप.वतह/10.1080/00220388.2021.1887478 .

119 चारु जैन, दिशा सक्सेना, सोमनाथ सेन, दीपक सानन, भारत में महिलाओं का भूमि स्वामित्व: डिजिटल भूमि रिकॉर्ड से साक्ष्य, भूमि उपयोग नीति, खंड 133, 2023, 106835, आईएसएसएन 0264-8377

120 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्मित 2.41 करोड़ घरों में से 26.6 प्रतिशत घर पूरी तरह से महिलाओं के नाम पर हैं, तथा 69 प्रतिशत घर संयुक्त रूप से पत्नी और पति के नाम पर हैं।

की उपलब्धता भी शामिल होनी चाहिए जो ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति का समर्थन करते हैं''।[121] संपत्ति के स्वामित्व में पर्याप्त समानता वास्तव में महिलाओं की स्वतंत्र पहचान को साकार करने में एक उच्च बिंदु होगी। महिलाओं द्वारा विकास का नेतृत्व करने के लिए, इसका स्वामित्व भी उनके पास होना चाहिए।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था: विकास इंजन को गति देना

7.102 ग्रामीण भारत का एकीकृत और सतत विकास सरकार की शासन रणनीति का केंद्र है। विकेंद्रीकृत नियोजन, ऋण तक बेहतर पहुंच, युवाओं का कौशल विकास, आजीविका के बेहतर अवसर, महिलाओं का सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा जाल प्रावधान, बुनियादी आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाएं आदि के माध्यम से समग्र आर्थिक बेहतरी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्कूल के बुनियादी ढांचे, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों, शासन के मुद्दों के लिए प्रौद्योगिकी समाधान, परिवहन और संचार के बेहतर साधनों आदि जैसी कल्याणकारी सेवाओं पर जोर दिया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों को उनके जीवन जीने के लिए दीर्घकालिक क्षमताओं से लैस करना है। इस भाग में सरकार की कुछ ग्रामीण विकास नीतियों और कार्यक्रमों का विवरण दिया गया है।

ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता में सुधार

7.103 सरकार कई योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। इस संबंध में प्रगति का सारांश नीचे दिया गया है।

तालिका VII.7: ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता

साधारण सुविधाएं 	• स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत (10 जुलाई 2024 तक)[122] 11.57 करोड़ शौचालय और 2.39 लाख सामुदायिक शौचालय परिसरों का निर्माण किया गया। • जल जीवन मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया (10 जुलाई 2024 तक)[123] • पीएम-आवास -ग्रामीण के अंतर्गत पिछले नौ वर्षों में (10 जुलाई 2024[124] तक) गरीबों के लिए 2.63 करोड़ घरों का निर्माण किया गया। • पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10.3 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए (2 जून 2024[125] तक) • सौभाग्य के अंतर्गत 2015 से 21.4 करोड़ ग्रामीण परिवारों का विद्युतीकरण किया गया (31 मार्च 2019 तक)[126] • डिजिटल इंडिया: ग्रामीण क्षेत्रों में 4.29 लाख कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे (जुलाई 2024 तक)[127] • 2014-15 से ग्राम सड़क योजना के तहत 15.14 लाख किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा हुआ (6 जून 2024 तक)[128]

121 "समानता की ओर, भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट", 1974, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ 4, पैरा 1.20।
122 https://sbm.gov.in/sbmgdashboard/statesdashboard.aspx
123 https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx
124 https://dashboard.rural.nic.in/dashboardnew/pmayg.aspx
125 https://www.pmuy.gov.in/index.aspx
126 https://saubhagya.gov.in/
127 https://csc.gov.in/
128 https://omms.nic.in/dbweb/Home/TimeSeries

बैंकिंग और वित्तीय समावेशन	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अंतर्गत 9.79 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत (26 जून 2024 तक)[129] • 0.19 करोड़ लाभार्थी ग्रामीण सहकारी बैंकों के तहत पंजीकृत (22 मई 2024[130] तक) • 465.42 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन मंजूर किए गए हैं। (जनवरी 2024[131] तक) • सितंबर 2023 तक विभिन्न डीबीटी योजनाओं के तहत[132] 104.02 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत होंगे • पीएमजेडीवाई के तहत 35.7 करोड़ रुपये डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। (26 जून 2024[133] तक) • पीएफएमएस ई-ग्रामस्वराज को भुगतान लेनदेन के लिए 2.79 लाख में से 2.63 लाख पंचायतों के साथ एकीकृत किया गया[134] (10 जुलाई 2024 तक)
शिक्षा	• समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल के बुनियादी ढांचे में वृद्धि, मुफ्त ऑनलाइन चौनलों और अध्ययन सामग्री आदि के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना (शिक्षा अनुभाग में विस्तृत जानकारी)
स्वास्थ्य	• 1.58 लाख उपकेंद्र • 24,935 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र • 5480 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र • 1.6 लाख से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उन्नत की गईं[135] (पूर्ववर्ती एबी-एचडब्ल्यूसी) (13.12.2023 तक)

7.104 नाबार्ड के अर्थशास्त्रियों द्वारा हाल ही में एक वर्किंग पेपर (पटनायक, गुप्ता और जाधव, 2024) में निर्मित[136] ग्रामीण गतिविधि के समग्र संकेतक में देखा गया है कि 2023-24 में ग्रामीण मांग बढ़ रही है।[137] सूचकांक से संकेत मिलता है कि कोविड लहरों के दौरान ग्रामीण मांग कमजोर हुई और 2023-24 के दौरान इसमें विस्तार हुआ। आम तौर पर, ग्रामीण मांग हर साल अक्टूबर के त्यौहार के तुरंत बाद चरम पर होती है, खरीफ की बुवाई से पहले कम हो जाती है।

129 https://pmjdy.gov.in/account
130 https://pmjdy.gov.in/account
131 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2002012
132 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1990746
133 https://pmjdy.gov.in/account
134 https://egramswaraj.gov.in/pfmsDashboardNew.do
135 इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास देखभाल शामिल है, जो गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करती है। नीचे दिया गया आंकड़ा आयुष्मान आरोग्य मंदिर की वर्ष-वार प्रगति और उपलब्धि को दर्शाता है।
136 समग्र संकेतक में तेरह उच्च आवृत्ति संकेतक शामिल हैं, जिनका उपयोग किया जाता है, अर्थात, ग्रामीण वास्तविक मजदूरी, वास्तविक कृषि ऋण, वास्तविक कृषि निर्यात (सभी सीपीआई-ग्रामीण द्वारा अपस्फीति), व्यापार की शर्तें (अर्थात, थोक मूल्य सूचकांक से प्राप्त खाद्य और गैर-खाद्य की सापेक्ष कीमतें), कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण उपभोक्ता भावना, मनरेगा मांग, जलाशय स्तर, आईआईपी-खाद्य, उर्वरक बिक्री, ट्रैक्टर बिक्री और दोपहिया वाहनों की बिक्री।
137 पटनायक, एस., गुप्ता, एन., और जाधव, वी., 2024, "भारत में ग्रामीण मांग और ग्रामीण मुद्रास्फीति के बीच गतिशील अंतरक्रिया से नीतिगत अंतर्दृष्टि", नाबार्ड

चार्ट VII.11: ग्रामीण गतिविधि का समग्र संकेतक

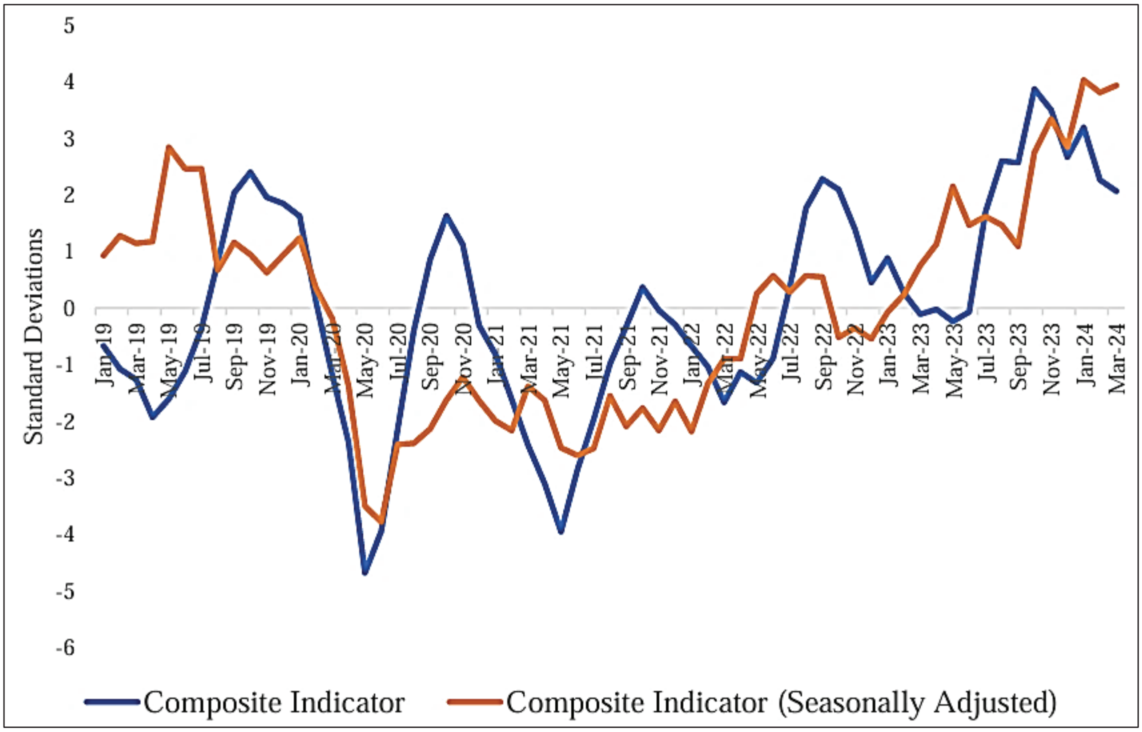

स्रोत: पटनायक, गुप्ता, और जाधव, 2024

मनरेगा के सुरक्षा तंत्र को मजबूत और आधुनिक बनाना

7.105 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (महात्मा गांधी नरेगा) का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार होते हैं।[138]

7.106 व्यक्ति-दिवस संतति, प्रति परिवार औसत व्यक्ति-दिवस और महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में मनरेगा योजना जिसके माध्यम से मनरेगा को लागू किया जाता है। भौतिक प्रगति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका VII.8: एमजीएनआरईजीएस पर प्रमुख संकेतक

सूचक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24*
सृजित व्यक्ति-दिवस (करोड़ में)	265.4	389.1	363.3	293.8	309.2
प्रति परिवार औसत व्यक्ति-दिन	48.4	51.52	50.1	47.8	52.1
महिला भागीदारी दर (% आयु)	54.8	53.19	54.7	57.5	58.9

*एमआईएस के अनुसार (31.03.2024 तक)

138 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया यह अधिनियम शुरू में देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों को कवर करता था। इसे 2007-2008 के दौरान दूसरे चरण में अतिरिक्त 130 जिलों में लागू किया गया था। इस अधिनियम को देश के शेष ग्रामीण जिलों में तीसरे चरण में 1 अप्रैल 2008 से अधिसूचित किया गया था।

7.107 योजना का पूरा लाभ उठाने के लिए कई दक्षता सुधार शुरू किए गए हैं। ईमानदारी सुनिश्चित करने और लीकेज को खत्म करने के लिए, काम शुरू होने से पहले, काम के दौरान और काम पूरा होने के बाद जियोटैगिंग की जाती है,[139] 99.9 प्रतिशत भुगतान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं, मजदूरी डीबीटी के तहत हस्तांतरित की जाती है, कुल सक्रिय श्रमिकों में से 98.6 प्रतिशत में आधार-आधारित भुगतान सक्षम किया गया है और 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।

7.108 जबकि एमजीएनआरईजीएस की शुरुआत एक मजदूरी रोजगार योजना के रूप में हुई थी, यह स्थायी आजीविका विविधीकरण के लिए एक परिसंपत्ति निर्माण कार्यक्रम के रूप में विकसित हुई है, जैसा कि व्यक्तिगत लाभार्थी 'व्यक्तिगत भूमि पर काम' की हिस्सेदारी में वृद्धि से देखा जा सकता है, जो वित्त वर्ष 14 में कुल पूर्ण किए गए कार्यों के 9.6 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 73.3 प्रतिशत हो गई (व्यय के संदर्भ में हिस्सेदारी बहुत कम है, फिर भी वित्त वर्ष 14 में 6.1 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में 32.1 प्रतिशत हो गई)। बेयर फुट टेक्नीशियन (बीएफटी)[140] और उन्नति[141] कौशल परियोजना जैसी पहलों से श्रमिकों की क्षमता विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है।

7.109 इसके अलावा, योजना से अधिकतम प्रभाव प्राप्त करने के लिए, इसे विभिन्न पहलों के साथ एकीकृत किया गया है जैसे कि राज्य योजनाओं और एनआरएलएम के साथ व्यक्तिगत लाभार्थियों और समुदाय के लिए न्यूट्री-गार्डन, पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) के साथ चारा फार्म, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ बागवानी को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय औषधीय रोपण बोर्ड, आयुष मंत्रालय के साथ औषधीय रोपण को बढ़ावा देना, पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिशन मोड में ग्राम पंचायत भवन का निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) - चरण - II के साथ सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण, और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), रक्षा मंत्रालय के साथ सीमा क्षेत्रों में सभी मौसम की सड़क संपर्कता का निर्माण।

7.110 बॉक्स VII.9 में जांच की गई है कि क्या एमजीएनआरईजीएस पर खर्च ग्रामीण संकट का सूचक है।

बॉक्स VII.9: क्या मनरेगा व्यय ग्रामीण संकट का सूचक है?

राज्यों में मनरेगा के प्रदर्शन में उल्लेखनीय भिन्नता है। परिणामों में इस तरह की असमानता का एक निश्चित कारण खोजने के लिए कई शोध अध्ययन[142,143,144] किए गए हैं, लेकिन संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। कुछ रिपोर्ट[145,146] बताती हैं कि मनरेगा की मांग ग्रामीण संकट का संकेत है। अगर वास्तव में ऐसा है तो डेटा ट्रेंड से पता चलेगा कि अधिक गरीबी और उच्च बेरोजगारी दर वाले राज्य अधिक योजना निधि का उपयोग करते हैं और अधिक रोजगार व्यक्ति-दिन पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त, मनरेगा फंड के उपयोग और कम बेरोजगारी के बीच एक संबंध

139 2016 में इसके शुभारंभ के बाद से 5.73 करोड़ से अधिक परिसंपत्तियों को जियो-टैग किया गया है (31 मार्च 2024 तक) और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है।

140 अब तक 20 राज्यों में 9387 बीएफटी को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

141 उन्नति कौशल परियोजना का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2018-19 में महात्मा गांधी नरेगा के तहत 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवार के एक वयस्क सदस्य (18-45 वर्ष की आयु) को प्रशिक्षण प्रदान करके मनरेगा श्रमिकों को कुशल बनाना है। वेतन हानि क्षतिपूर्ति के विरुद्ध वजीफे का पूरा खर्च पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह परियोजना वित्त वर्ष 20 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य तीन वर्षों में यानी वित्त वर्ष 20, वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 22 में 2 लाख महात्मा गांधी नरेगा लाभार्थियों के कौशल आधार को बढ़ाना है। अब तक लगभग 59,350 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

142 'An Evaluation of India's National Rural Employment Guarantee Act', World Bank, accessed 3 July 2024, https://tinyurl.com/27farpke

143 Sami, L. and Khan, A. (2016) 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA): A Tool for Employment Generation', *International Journal of Social Sciences and Management* 3: 281

144 Turangi, S. (2022): "MGNREGS Performance (2006–21): An Inter-State Analysis", South Asia Research 42, no. 2 (July 2022): 208–32, https://doi.org/10.1177/02627280221085195.

145 Nitnaware, H., 7 July 2022, 'Demand of Record 30 million Jobs for MGNREGS Reflects Rural Distress', Down to Earth, accessed 5 July 2024, https://tinyurl.com/3a2kj643

146 Ghildiyal, S., 2 April 2022, 'Rural Distress: Despite Dip in 2021, NREGA Generates around 100 Crore Persondays More than Pre-Pandemic 2019', The Times of India, https://tinyurl.com/884vsy5f

हो सकता है। मनरेगा मजदूरी राज्य की गरीबी के स्तर को दर्शा सकती है। पिछले अध्ययनों[147] ने वास्तविक समय के ग्रामीण संकट को इंगित करने के लिए मौसम के आंकड़ों के साथ मनरेगा की मांग को सहसंबंधित करने का प्रयास किया है, लेकिन परिकल्पना को सत्यापन की आवश्यकता है।

एमजीएनआरईजीएस डेटा से प्राप्त जानकारी

वित्त वर्ष 2024[148] के आंकड़ों से पता चलता है कि हालांकि तमिलनाडु में देश की गरीब आबादी[149] का 1 प्रतिशत से भी कम हिस्सा है, लेकिन जारी किए गए सभी एमजीएनआरईजीएस फंड का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा तमिलनाडु का है। इसी तरह, गरीब आबादी के केवल 0.1 प्रतिशत के साथ केरल ने देश के एमजीएनआरईजीएस फंड का लगभग 4 प्रतिशत इस्तेमाल किया। इन राज्यों ने मिलकर 51 करोड़ व्यक्ति-दिन रोजगार पैदा किया। इसके विपरीत, गरीब आबादी के लगभग 45 प्रतिशत (क्रमश: 20 प्रतिशत और 25 प्रतिशत) के साथ बिहार और यूपी ने केवल 17 प्रतिशत (क्रमश: 6 प्रतिशत और 11 प्रतिशत) एमजीएनआरईजीए फंड के लिए जिम्मेदार थे और 53 करोड़ व्यक्ति-दिन रोजगार पैदा किया (चार्ट VII.12)।

राज्यवार बहुआयामी गरीबी सूचकांक और सृजित व्यक्ति-दिनों के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना केवल 0.3[150] की गई है, जो दर्शाता है कि एमजीएनआरईजीएस निधि का उपयोग और रोजगार सृजन गरीबी के स्तर के अनुपात में नहीं हैं।

चार्ट VII.12: राज्यों को जारी की गई एमजीएनआरईजीएस निधि का अनुपात और उनकी गरीब आबादी का अनुपात[151]

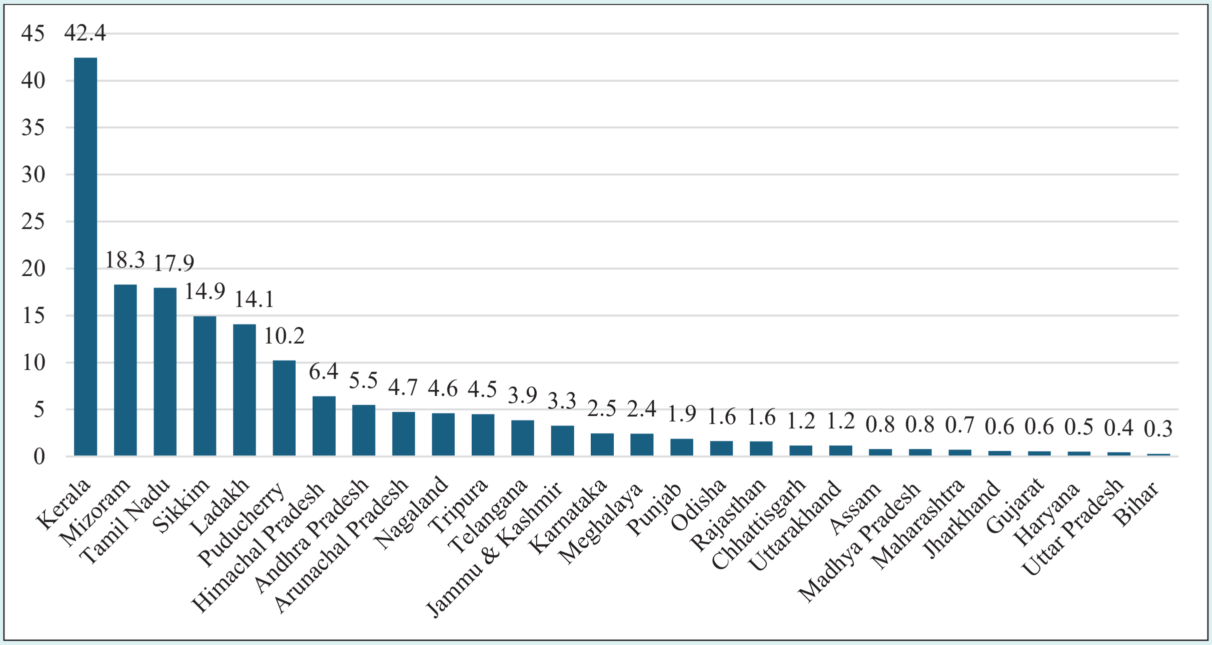

Source: DoRD,NFHS

147 Shagun, 'Can MGNREGA Data Serve as Real-Time Index for Rural Distress?', Down To Earth, 29 July 2019, https://tinyurl.com/5ewuhubx
148 As per data from Department of Rural Development (DoRD) and NFHS-5.
149 Poor population figures calculated from Head Count Ratio (HCR) data from Niti Aayog MPI report.
150 Own calculations. A coefficient of 1 would indicate that the poorer a state, greater the number of person-days it generates and a coefficient of 0 would indicate no relationship between poverty and person-days.
151 Data for West Bengal, Manipur, Lakshadweep, A&N, DD&DNH and Goa not included because no/negligible fund was released to these states/UTs for NREGS in FY24

इसके अतिरिक्त, गणना से पता चलता है कि डळछत्म्ळै फंड के उपयोग और ग्रामीण बेरोजगारी दरों के बीच बहुत कम संबंध है। FY23[152] के डेटा से पता चलता है कि सबसे ज्यादा ग्रामीण बेरोजगारी दर वाले राज्यों ने जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा डळछत्म्ळै फंड का इस्तेमाल किया हो। लोकप्रिय कथन के विपरीत, डेटा इस विचार का समर्थन नहीं करता है कि FY22 में उच्च ग्रामीण बेरोजगारी दर वाले राज्यों ने FY23 में ज्यादा MGNREGS फंड की मांग की (चार्ट VII.13)।

मनरेगा के तहत, जब तक कि राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं किया जाता (जिसकी अनुमति अधिनियम देता है), राज्य अपना न्यूनतम वेतन निर्धारित कर सकते हैं। इस निर्धारण में आदर्श रूप से स्थानीय रोजगार के अवसरों, प्रति व्यक्ति आय और वैकल्पिक आय स्रोतों पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, योजना के आंकड़ों[153] से पता चलता है कि न्यूनतम वेतन निर्धारण तदर्थ है और प्रति व्यक्ति आय या गरीबी दर के अनुपात से संबंधित नहीं है। हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अन्य राज्यों में मनरेगा में उनकी प्रति व्यक्ति आय के सापेक्ष अपेक्षाकृत उच्च अधिसूचित मजदूरी दरें हैं (चार्ट VII.14)। यह राज्यवार मनरेगा निधि उपयोग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि मजदूरी घटक पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

चार्ट VII.13: बेरोजगारी दर (प्रति 1000) और वित्त वर्ष 23 में जारी एमजीएनआरईजीएस फंड

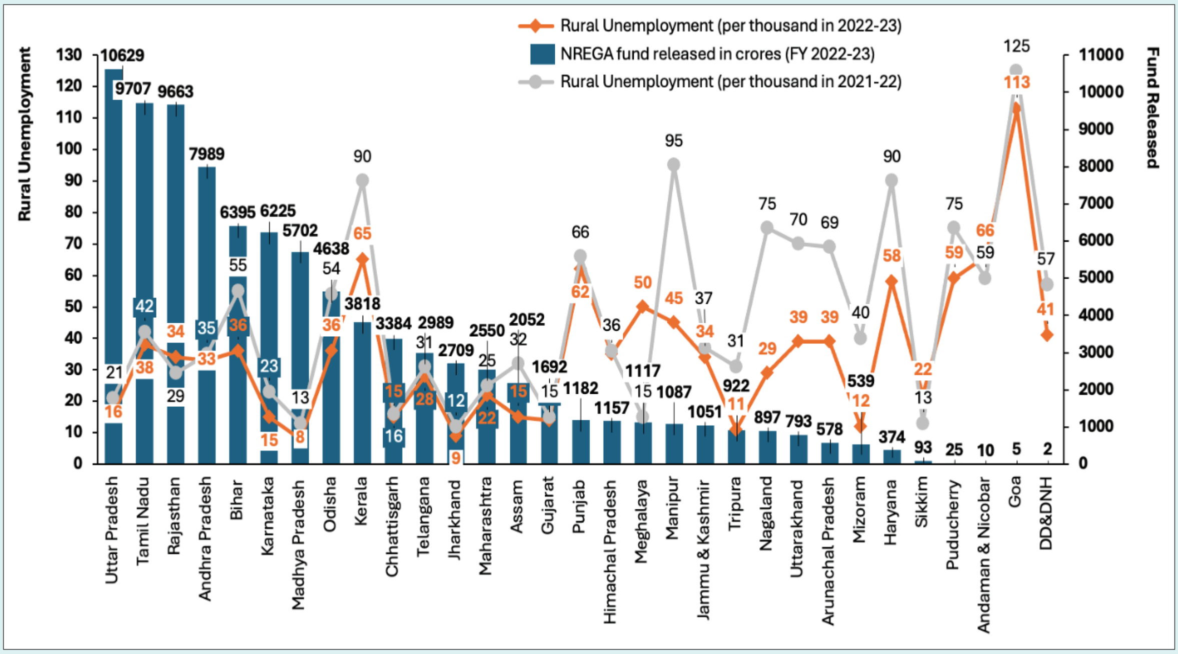

नोट: रोजगार के आंकड़े प्रमुख स्थिति और सहायक स्थिति का योग हैं।
स्रोत: DoRD, एनएसएसओ रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण रिपोर्ट; पीएलएफएस, एनएसओ

152 Fund release data from DoRD and unemployment data from RBI Handbook of Statistics on Indian States at https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=22079

153 Data from DoRD

Chart VII.14: प्रति व्यक्ति आय और अधिसूचित मजदूरी दरों की तुलना

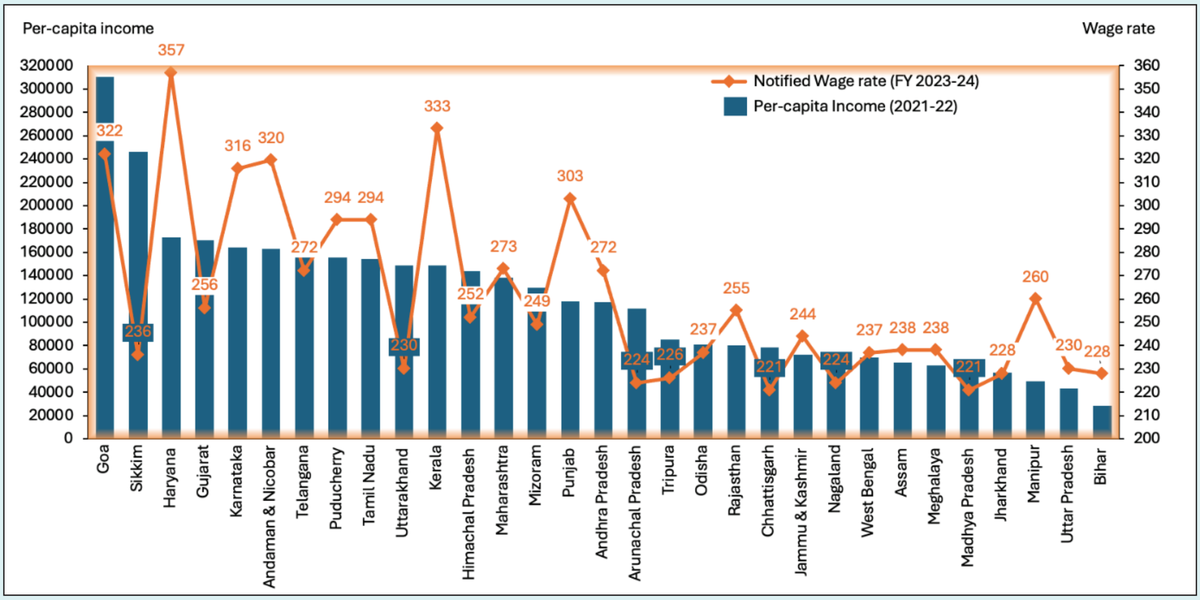

नोटः हिमाचल प्रदेश के लिए अधिसूचित मजदूरी दर को अनुसूचित क्षेत्रों और गैर-अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अधिसूचित मजदूरी दरों के औसत के रूप में माना गया है।
- ए एंड एन के लिए, अधिसूचित मजदूरी दर को अंडमान और निकोबार के लिए अधिसूचित दरों का औसत माना जाता है

राज्यों में मनरेगा कार्य की मांग में अंतर को स्पष्ट करने वाले कारकों का निदान

उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि एमजीएनआरईजीएस कार्य की मांग सीधे तौर पर सूक्ष्म स्तर पर ग्रामीण संकट में वृद्धि से संबंधित नहीं है। गांव में रहने वाले परिवारों के अंतिम विकल्प से लेकर घरेलू संपत्ति निर्माण और स्थायी आय सृजन के लिए एक स्मार्ट विकल्प बनने तक एमजीएनआरईजीएस कार्य के उल्लेखनीय विकास को पहले भी देखा जा चुका है।[154] यह दर्शाता है कि फंड के उपयोग में राज्य स्तर के अंतर को समझाने के लिए अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इनमें से कुछ पर नीचे चर्चा की गई है।

आपूर्ति पक्ष के मुद्दे

विभिन्न राज्यों को धनराशि जारी करने में डीओआरडी द्वारा लिए गए समय में अंतर- डीओआरडी द्वारा स्वचालित प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न राज्यों को धनराशि जारी करने में लगने वाले समय में कोई महत्वपूर्ण अंतर न हो, जो यह दर्शाता है कि यह धनराशि के उपयोग में राज्यवार अंतर का कारण नहीं है।

राज्यों के बीच मनरेगा बजट का विनियोजन- मनरेगा फंड के उपयोग में अंतर संभवतः सहमत श्रम बजट में अनुमानित वार्षिक मांगों से उत्पन्न हो सकता है। वित्त वर्ष 25[155] के अनुमानों से पता चलता है कि यूपी, एमपी और बिहार जैसे उच्च ग्रामीण गरीब आबादी[156] वाले राज्यों में वार्षिक व्यक्ति-दिवस अधिक होंगे। इस प्रकार, यह अंतर संभवतः पूर्ण किए गए कार्य के आधार पर वास्तविक निधि उपयोग के कारण है।

154 Nageswaran, V.A. et.al 'Why We Must Re-Examine Narrative of Rural Distress', mint, 22 August 2022, https://tinyurl.com/5n76hbfx
155 व्यक्ति-दिवस रोजगार डेटा DoRD के द्वारा प्रस्तुत किया गया है
156 Rural Population data based on RBI's Handbook of Statistics on Indian Economy 2021-22- https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=21248.

मांग-पक्ष संबंधी मुद्दे

मनरेगा के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य की संस्थागत क्षमता- मनरेगा फंड का उपयोग करने के लिए, राज्य सरकारों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए श्रम बजट को अग्रिम रूप से अंतिम रूप देना चाहिए, एक बॉटम-अप प्लानिंग प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इसमें ग्राम पंचायत की बैठकें, ब्लॉक और जिला स्तर पर अनुमोदन और राज्य स्तर पर संकलन शामिल हैं। राज्यों को पिछले वर्ष के कम से कम 75 प्रतिशत फंड का उपयोग करना चाहिए, फंड किश्तों के लिए आवेदन करने के लिए उपयोग प्रमाण पत्र, व्यय विवरण और सामाजिक लेखा परीक्षा उपलब्धियां प्रदान करनी चाहिए।[157] बेहतर संस्थागत क्षमता और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं वाले राज्य इस प्रक्रिया को समय पर पूरा कर सकते हैं।

साहित्य,[158,159,160] प्रति व्यक्ति आय और संस्थागत गुणवत्ता के बीच एक संबंध स्थापित करता है। कम प्रति व्यक्ति आय और उच्च गरीबी स्तर वाले राज्यों में अक्सर कमजोर संस्थान होते हैं, जिससे निष्पादित किए गए प्रत्येक कार्य के लिए कम धनराशि मिलती है और ग्रामीण गरीबों के लिए प्रति व्यक्ति कम रोजगार पैदा होता है।[161] FY24 [162] के डेटा से पता चलता है कि यूपी (~10 लाख काम), कर्नाटक जैसे राज्य (~9 लाख कार्य), और एमपी (~7.77 लाख कार्य) ने कई कार्य किए लेकिन प्रति कार्य कम मनरेगा निधि का उपयोग किया (क्रमशः ₹0.93 लाख, ₹0.55 लाख और ₹0.72 लाख)। इसके विपरीत, पुडुचेरी (प्रति कार्य ₹8.96 लाख), हरियाणा (₹4.89 लाख), राजस्थान (₹2.76 लाख), और तमिलनाडु (₹2 लाख) जैसे राज्यों ने प्रति कार्य अधिक निधि का उपयोग किया।

ग्रामीण गरीबों के प्रति व्यक्ति सृजित व्यक्ति-दिवस रोजगार के मामले में भी यही प्रवृत्ति है, तमिलनाडु (69), केरल (62), राजस्थान (42) और पुडुचेरी (30) ने यूपी (7), एमपी (10) और बिहार (6) से बेहतर प्रदर्शन किया है। उच्च संस्थागत क्षमता वाले राज्य बेहतर योजना बनाते हैं और बेहतर समन्वय करते हैं, ग्रामीण बुनियादी ढांचे या प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में महंगे कामों को अंजाम देते हैं। इसके विपरीत, असम, झारखंड, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान जैसे कम आय वाले राज्यों में 'व्यक्तिगत कार्यों'[163] (50 प्रतिशत या उससे अधिक) का अनुपात अधिक है, जो कम खर्चीले हैं और जिनके लिए कम योजना की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार, एमजीएनआरईजीएस निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए राज्य की संस्थागत क्षमता महत्वपूर्ण है।

मांग दर्ज करने में अंतर- 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सरकारों को बेरोजगारी भत्ता देने के प्रावधानों के बावजूद, सभी राज्यों[164] में वित्त वर्ष 24 में केवल ₹90,000 और वित्त वर्ष 23 में ₹7.8 लाख जारी किए गए। इसके अलावा,[165] मूल्यांकन रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि मांगे जाने पर अक्सर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। इससे पता चलता है कि ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता वास्तविक समय में मांग दर्ज नहीं कर सकते हैं। नतीजतन, एमजीएनआरईजीएस कार्य मांग को दर्शाने वाला औपचारिक डेटा वास्तविक मांग और वर्तमान ग्रामीण आर्थिक संकट

157 Detailed guidelines in Annual Master Circular 2024-25 (https://tinyurl.com/2msf4fpf).
158 Alonso, J.A., Garcimartin, C. and Kvedaras, V. (2020): "Determinants of Institutional Quality: An Empirical Exploration", Journal of Economic Policy Reform 23, no. 2 (2 April 2020): 229–47
159 Rodrik, D., Subramanian, A. and Trebbi, F. (2004): "Institutions Rule: The Primacy of Institutions Over Geography and Integration in Economic Development", Journal of Economic Growth 9, no. 2 (2004): 131–65.
160 Acemoglu, D., Johnson, S. and Robinson, J.A. (2001): "The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation", American Economic Review 91, no. 5 (December 2001): 1369–1401
161 Rural poor population data is taken from RBI Handbook of Statistics on Indian Economy 2021-22-https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=21248
162 Data on number and category of works and fund usage as furnished by DoRD
163 Data on category of works as furnished by DoRD- these include individual, and community works for vulnerable sections
164 Unemployment allowance data furnished by DoRD.
165 'An Evaluation of India's National Rural Employment Guarantee Act'.

को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि मांगे गए काम की रिपोर्ट पोर्टल पर तभी की जाती है जब वास्तव में रोजगार प्रदान किया जाता है (संभवत: बेरोजगारी भत्ते के प्रति राज्य सरकार की देनदारी को बचाने के लिए)।

लीकेज में वृद्धि- एमजीएनआरईजीएस फंड के उपयोग में भिन्नताएं राज्यों में देखी गई अनियमितताओं और लीकेज से उत्पन्न होती हैं। विस्तृत दस्तावेजीकरण की कमी के बावजूद, समाचार रिपोर्ट,[166] सामाजिक ऑडिट[167] और वास्तविक साक्ष्य बताते हैं कि अक्सर फंड इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाता है, जिससे मांग एक अविश्वसनीय संकट सूचक बन जाती है। चार वर्षों में, सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों ने पाया कि एमजीएनआरईजीएस के तहत 935 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई। विभिन्न क्षेत्रों से श्रमिकों द्वारा ठेकेदारों को भुगतान करने और जॉब कार्ड[168] छोड़ने, श्रम के बजाय मशीनों का अवैध उपयोग, अवास्तविक श्रम बजट, फंड जारी करने में देरी,[169] जॉब कार्ड अपडेट की कमी और असत्यापित बिलों के मामले सामने आए हैं। सामाजिक जवाबदेही मंच के ऑडिट[170] ने 2018-20 में 658 करोड़ रुपये की हेराफेरी की सूचना दी, जिसमें वेतन के मुद्दों, जॉब कार्ड और कार्यस्थलों पर ध्यान केंद्रित करने वाली शिकायतें थीं। इसने यह भी नोट किया कि एमजीएनआरईजीए कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और रिकॉर्ड रखने की प्रक्रियाओं का अक्सर उल्लंघन किया जाता था।

उपरोक्त निदानात्मक विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एमजीएनआरईजीएस के तहत मांग ग्रामीण संकट का वास्तविक संकेतक नहीं है, बल्कि यह मुख्य रूप से राज्य की संस्थागत क्षमता और कुछ हद तक अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी और अन्य बातों से भी जुड़ी हुई है।

जमीनी स्तर पर ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना

7.111 सरकार ने किफायती वित्त तक निर्बाध पहुंच और आकर्षक बाजार अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान देते हुए जीवंत योजनाबद्ध हस्तक्षेपों का एक गुलदस्ता तैयार किया है, जिसका उद्देश्य अंतत: ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना है। सरकार ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और आजीविका सृजन, वित्त और विपणन तक आसान पहुंच प्रदान करने और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक सामान्य बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से कई योजनाओं को लागू करने में सबसे आगे रही है। कुछ योजनाओं और कार्यक्रमों का उल्लेख नीचे बॉक्स टप्.9 में किया गया है।

बॉक्स VII.10: ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली पहल

(क) उदाहरण के लिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को सार्थक स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुँच प्रदान करना है। डीएवाई-एनआरएलएम ने महिलाओं को अपनी आजीविका में सुधार करने और नई गतिविधियों में उद्यम करने के लिए नई ऊर्जा को प्रेरित करने और प्रज्वलित करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान, विशेष कौशल और मूल्यवान अनुभव तक पहुँचने में मदद की है। उन्होंने सैनिटरी पैड, साबुन, डिटर्जेंट, फेस मास्क, सैनिटाइजर, फेंसिंग सामग्री आदि तैयार करने के लिए सौर पैनल जैसे उद्यम शुरू किए हैं। वर्ष 2011 में शुरू किए गए इस मिशन का दायरा 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 742 जिलों के 7135 ब्लॉकों तक फैला हुआ है। प्रमुख घटकों पर कार्यक्रम की प्रगति का सारांश नीचे दिया गया है।

166 Singh, S., 2 October 2023, The Hindu 'RTI Queries Reveal Several Irregularities in MGNREGA Scheme in West Bengal'

167 Nitnaware, H., 24 January 2023, "MGNREGA Graft: Social Audit Finds Irregularities Worth Rs 54 Lakh in Rajasthan" Down to Earth accessed 24 June 2024, https://tinyurl.com/3bnjbv3r

168 Bhattacharyya, D. (2023): "Of Conflict and Collaboration", Economic and Political Weekly', Vol 58, Issue no. 36, 9 September 2023, https://www.epw.in/journal/2023/36/special-articles/conflict-and-collaboration.html.

169 'Audit Reports | Comptroller and Auditor General of India', https://cag.gov.in/en/audit-report/details/118182.

170 Social Accountability Forum for Action and Research, 'MGNREGA Social Audit Report', November 2020.

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत प्रगति

सूचक	संचयी प्रगति (जून 2024 तक)
कवर किए गए ब्लॉकों की संख्या	7135
प्रमोट किये गये स्वयं सहायता समूहों की संख्या (लाख में)	90.86
संगठित परिवारों की संख्या (करोड़ में)	10.05
स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की गई पूंजी सहायता (करोड़ रुपये में)	43,610
स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्राप्त बैंक ऋण की राशि (₹ लाख करोड़ में)	8.85
एसवीईपी के अंतर्गत स्थापित व्यक्तिगत उद्यमों की संख्या (लाख में)	2.98
एजीईवाई के तहत तैनात वाहनों की संख्या	2333
महिला किसानों की संख्या (करोड़ में)	3.71
स्थापित कस्टम हायरिंग केंद्रों की संख्या	32709
घरेलू बचत रसोई उद्यान की संख्या (करोड़ में)	2.28

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ख) लखपति दीदी पहल

लखपति दीदी पहल का लक्ष्य तीन साल के भीतर तीन करोड़ एसएचजी परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय ₹1 लाख तक पहुंचाना है। यह विविध आजीविका गतिविधियों, जिला-स्तरीय योजना, घरेलू सहायता, सरकारी विभागों के अभिसरण और कर्मचारियों और समुदाय के सदस्यों की क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।

(ग) स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई) को डीएवाई-एनआरएलएम के तहत गैर-कृषि आजीविका रणनीतियों के रूप में लागू किया जा रहा है। एसवीईपी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों का समर्थन करता है। इस रणनीति का उद्देश्य व्यवसाय व्यवहार्यता प्रबंधन के बारे में ज्ञान को बढ़ावा देना, स्टार्ट-अप ऋण वित्त तक पहुँच प्रदान करना और मौजूदा उद्यम को आगे बढ़ाना है। 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 221 ब्लॉकों में लगभग 2.97 लाख उद्यम बनाए गए हैं। एजीईवाई ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, सस्ती और समुदाय-निगरानी वाली परिवहन सेवाएँ प्रदान करता है। 26 राज्यों में लगभग 2333 वाहन चालू हैं, जो दूरदराज के ग्रामीण गाँवों को जोड़ने के लिए परिवहन सेवाएँ प्रदान करते हैं।

(घ) सरस आजीविका पोर्टल और ई-सरस मोबाइल ऐप (2023 में लॉन्च) स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए प्रामाणिक दस्तकारी उत्पादों, जैसे लिनेन आइटम, फर्नीचर, परिधान, अचार आदि की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं। स्वदेशी रूप से तैयार किए गए उत्पादों के लिए एक समर्पित बाजार बनाकर, यह प्लेटफॉर्म ग्रामीण महिलाओं को नए युग के उद्यमियों के रूप में प्रेरित करता है।

(ङ) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) योजना, जो एनआरएलएम की एक उप-योजना है, का उद्देश्य भी ग्रामीण उद्यमिता को मजबूत करना है। आरएसईटीआई मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जिला-स्तरीय स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनका प्रबंधन बैंकों द्वारा किया जाता है और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। वे 18-45 वर्ष की आयु के ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण, ऋण सहायता और सलाह प्रदान करते हैं, जिसमें उद्यमियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण और दीर्घकालिक सहायता प्रदान करने का दृष्टिकोण शामिल है। उनका अनुकूलित पाठ्यक्रम कृषि अर्थव्यवस्था और छोटे ग्रामीण व्यवसायों की स्थानीय मांगों से मेल खाने के लिए डिजाइन किया गया है। 2009 में योजना की शुरुआत के बाद से, 50.72 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, और जून 2024 तक 36.23 उम्मीदवारों को उद्यमी/प्रशिक्षु के रूप में बसाया गया है, जिसमें सेटलमेंट दर 72 प्रतिशत से अधिक है।

(च) ग्रामीण उद्यमिता को वित्तपोषित करना: ग्रामीण उद्यमियों को समर्थन देने के लिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एमईडीपी) और आजीविका एवं उद्यम विकास कार्यक्रम (एमईडीपी) को बढ़ावा देता है, जिसमें वित्त पोषण और कौशल सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नाबार्ड एसएचजी, जेएलजी, पीओ और सूक्ष्म उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पर अपने उत्पाद बेचने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, ऑफ-फार्म उत्पादक संगठनों (ओएफपीओ) को ओएनडीसी में शामिल होने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। 31 मार्च 2023 तक, 20,174 एमईडीपी से लगभग 5.85 लाख एसएचजी सदस्य लाभान्वित हुए, जिन्हें ₹52.39 करोड़ का अनुदान मिला, और 2149 एलईडीपी से 2.67 लाख एसएचजी सदस्य लाभान्वित हुए, जिन्हें ₹106.10 करोड़ का अनुदान मिला।

(छ) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 'सरस मेला' स्वयं सहायता समूहों के लाभार्थियों को अपने उत्पाद सीधे शहरी बाजारों में बेचने में मदद करता है, जिससे बिचौलियों का सफाया होता है और कारीगरों के मार्जिन में सुधार होता है। यह ग्रामीण उत्पादकों को खरीदारों से जुड़ने, उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार उत्पाद तैयार करने और अपने विपणन कौशल को निखारने का अवसर देता है।

(ज) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई): डीडीयू-जीकेवाई एक राज्य-नेतृत्व वाला, परिणाम-संचालित कौशल कार्यक्रम है जो ग्रामीण युवाओं पर केंद्रित है, जिसमें सतत रोजगार, पीपीपी और सेक्टर कौशल परिषदों के माध्यम से परिणामों के स्वतंत्र तृतीय-पक्ष प्रमाणन पर जोर दिया जाता है। यह कार्यक्रम गरीब ग्रामीण युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने और पोस्ट-प्लेसमेंट ट्रैकिंग, प्रतिधारण और कैरियर प्रगति को दी गई प्रमुखता और प्रोत्साहन के माध्यम से सतत रोजगार पर जोर देने के कारण अन्य कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बीच एक अद्वितीय स्थान रखता है। रोशनी और हिमायत नामक विशेष उप-योजनाएँ भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

7.112 भविष्य की ओर देखते हुए, आरएसईटीआई (देश के 577 जिलों में कार्यरत 591 आरएसईटीआई)[171] की व्यापक स्थानीय उपस्थिति और बैंकों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की त्रि-पक्षीय-साझेदारी का लाभ सरकारी कार्यक्रमों जैसे कौशल विकास और आजीविका विविधीकरण, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषि मशीनीकरण, रोजगार मेले, एसएचजी, कृषि उत्पादक संगठनों, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां आदि में प्रयासों को एकजुट करने के लिए उठाया जा सकता है। जमीनी स्तर पर कौशल और ऋण संपर्क के आधार के रूप में कार्य करके, आरएसईटीआई जिला स्तरीय उद्यम केंद्रों के रूप में उभर सकते हैं।[172]

7.113 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की क्षमता का दोहन करने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें पेशेवर सहायता और प्रबंधन का लाभ उठाकर बड़े उद्यमों में तब्दील किया जा सके। उदाहरण के लिए, डूंगरपुर, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं को सोलर लैंप कारखानों और खुदरा सोलर दुकानों के संचालन, प्रबंधन और स्वामित्व में लाना आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर चेतन सोलंकी के मार्गदर्शन और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से संभव हो पाया।[173] उचित प्रशिक्षण और पेशेवर मार्गदर्शन के साथ, महिला समूह बड़े पैमाने पर आत्मनिर्भर उद्यम के रूप में उभर सकते हैं।

ग्रामीण शासन: जमीनी स्तर पर डिजिटल परिवर्तन की कहानी

7.114 बेहतर ग्रामीण शासन से ग्रामीण विकास को बहुत लाभ मिल सकता है, जो कार्यक्रम आधारित प्रभाव सृजन और बढ़ते अवसरों के व्यक्तिगत उपयोग दोनों के लिए आधार और गुणक शक्ति के रूप में काम कर सकता है। 2015 और

171 पीआईबी रिलीज आईडी 1983115, 6 दिसंबर 2023 https://tinyurl.com/4e68kcjr
172 अमरजीत सिन्हा, द लास्ट माइल। अक्टूबर 2023। पहला संस्करण । रूटलेज इंडिया। अध्याय 11, पूर्ण रोजगार के लिए कौशल पर पुनर्विचार
173 http://durgaenergy.com/About.

2021 के बीच ग्रामीण इंटरनेट सब्सक्रिप्शन में 200 प्रतिशत की वृद्धि के साथ,[174] शासन का डिजिटलीकरण गांव और प्रशासनिक मुख्यालय के बीच की दूरी को कम करने के लिए एक आसान काम है, जो क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण है।[175] इस पहलू में, ग्रामीण भारत में कई डिजिटलीकरण पहल सामने आ रही हैं।

बॉक्स VII.11: ग्रामीण शासन में सुधार के लिए डिजिटलीकरण पहल

ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना

ई-पंचायत परियोजना का उद्देश्य लगभग 2.71 लाख पंचायतों या समकक्ष निकायों की आंतरिक कार्यप्रवाह प्रक्रियाओं को स्वचालित करना है, जिससे लगभग 30 लाख निर्वाचित सदस्यों और लगभग दस लाख पीआरआई कार्यकर्ताओं को लाभ होगा। इसके अलावा, सरकार ने पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की सुविधा के लिए ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के तहत ऑडिटऑनलाइन नामक एक एप्लिकेशन शुरू की है और आंतरिक और बाहरी ऑडिट के विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखती है।[176]

ई-ग्राम स्वराज

24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर, ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल पंचायतों को पेश करने के लिए ई-ग्राम स्वराज (https%@@egramswaraj-gov-in@) लॉन्च किया गया। यह प्लेटफॉर्म ग्राम पंचायत का पूरा प्रोफाइल देता है, जिसमें जनसांख्यिकीय विवरण, वित्त और ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में उल्लिखित गतिविधियाँ शामिल हैं। यह वास्तविक समय पर भुगतान और बेहतर वित्तीय प्रबंधन को सक्षम करने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ भी एकीकृत है। 2.52 लाख ग्राम पंचायतों ने 2023-24 के लिए अपने जीपीडीपी तैयार करके ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड कर दिए हैं।[177]

भू-आधार

पहचान पार्सल संख्या (यूएलपीआईएन) या भू-आधार एक 14-अंकीय पहचान संख्या है जो किसी भूमि खंड को उसके देशांतर और अक्षांश निर्देशांक के आधार पर दी जाती है। इसका उद्देश्य भूमि खंडों के सीमांकन, पहचान और मानकीकरण को सुगम बनाना है, जिससे विभिन्न सरकारी विभागों को बहु-विभागीय सेवाओं सहित नागरिकों को भूमि-संबंधी सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके। यूएलपीआईएन के माध्यम से उचित भूमि सांख्यिकी और भूमि लेखा भूमि बैंकों और एक एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईएलआईएमएस) को विकसित करने में मदद करेगा। यूएलपीआईएन को 29 राज्यों में शुरू किया गया है, जिससे लगभग 14.94 करोड़ यूएलपीआईएन तैयार हुए हैं।[178]

स्वामित्व योजना

स्वामित्व (गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण) ग्रामीण घरेलू मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करने के लिए 2020 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य संपत्ति के मुद्रीकरण को सक्षम करना, विवादों को कम करना और व्यापक ग्राम-स्तरीय योजना को सुविधाजनक बनाना है। 2.90 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और 1.06 लाख गांवों के लिए 1.66 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। यह योजना हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गोवा में लागू की गई है।[179]

174 आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, अध्याय 12, भौतिक और डिजिटल अवसंरचना: संभावित विकास को बढ़ावा देना।
175 अशर, एस., नागपाल, के., नोवोसाद, पी. (2018)। दूरी की लागत: ग्रामीण भारत में भूगोल और शासन। विश्व बैंक वर्किंग पेपर, 2018
176 पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार।
177 पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार।
178 पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार।
179 पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 6 जनवरी 2024, रिलीज आईडी: 1993736

संधारणीय विकास की ओर

7.115 संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए छह वर्ष से भी कम समय शेष रह गया है, भारत सरकार अपने नागरिकों के कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एसडीजी को स्वीकार करने,अपनाने, और उनका समर्थन करने में सबसे आगे रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने कई विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद, भारत ने 2030 एजेंडा को प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रगति की है, जो एसडीजी के प्रति देश के लचीलापन और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के माध्यम से नीति आयोग द्वारा एसडीजी पर प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत ने इन लक्ष्यों को पूरा करने में काफी सुधार किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएम-मुद्रा योजना, सौभाग्य और स्टार्ट-अप इंडिया जैसे लक्षित हस्तक्षेपों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और तेजी से सुधार हुआ है।

7.116 संधारणीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की प्रगति हर साल आगे बढ़ी है। इस कार्य प्रदर्शन को 16 मात्रात्मक लक्ष्यों के लिए मापा जाता है, तथा लक्ष्य 17 के लिए गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स द्वारा मापा गया देश का ओवरआल स्कोर/कम्पोजिट स्कोर[180] 2018 में 57 से बढ़कर 2019-20 में 60, 2020-21 में 66 से बढ़कर 2023-24 में 71 हो गया है। भारत ने सूचकांक के 2020-21 और 2023-24 संस्करणों के बीच एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

7.117 2018 से, भारत ने कई प्रमुख एसडीजी में पर्याप्त प्रगति देखी है। लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन), 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण), 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा), 9 (उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा) और 11 (टिकाऊ शहर और समुदाय) में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है (चार्ट VII.13)।

चार्ट VII.15 एसडीजी में भारत की प्रगति

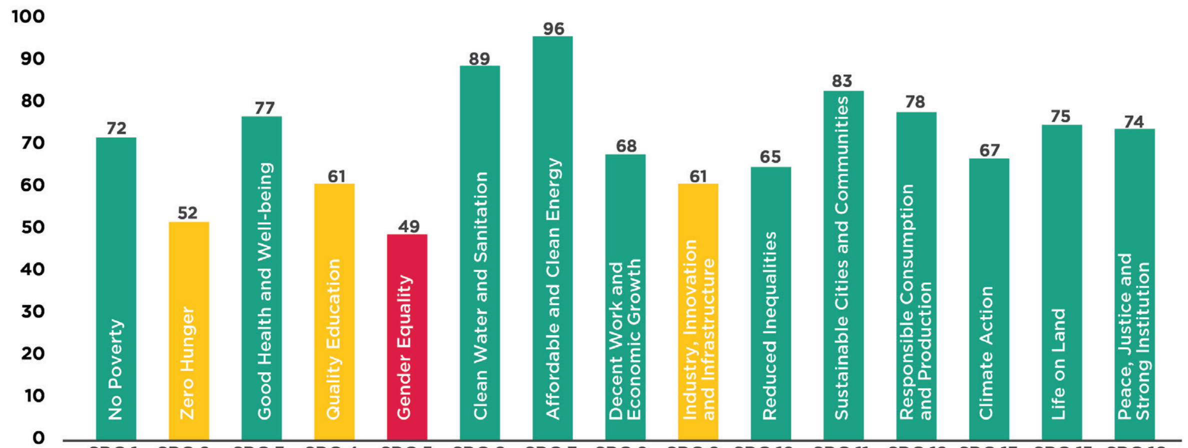

	SDG 1	SDG 2	SDG 3	SDG 4	SDG 5	SDG 6	SDG 7	SDG 8	SDG 9	SDG 10	SDG 11	SDG 12	SDG 13	SDG 15	SDG 16
2023-24	72	52	77	61	49	89	96	68	61	65	83	78	67	75	74
2020-21	60	47	74	57	48	83	92	61	55	67	79	74	54	66	74
2019-20	50	35	61	58	42	88	70	64	65	64	53	55	60	66	72
2018	54	48	52	58	36	63	51	65	44	71	39			90	71

Aspirant (0-49) Performer (50-64) Front Runner (65-99) Achiever (100)

स्रोत: नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24

180 समग्र स्कोर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए 16 लक्ष्यों के लिए लक्ष्य स्कोर का अंकगणितीय औसत है, जिसमें प्रत्येक लक्ष्य को समान महत्व दिया गया है।

नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स, 2023-24 पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रदर्शन

7.118 एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के एसडीजी प्रगति में प्रदर्शन में सकारात्मक रुझान की रिपोर्ट दी गई है। राज्यों के लिए अंक अब 57 से 79 के बीच हैं, जबकि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अंक 65 से 77 के बीच हैं। इस वर्ष, 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 65 से 99 के बीच अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 2020-21 के संस्करण में यह संख्या 22 थी।

चार्ट VII.16 वर्षों से नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्सपर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रदर्शन

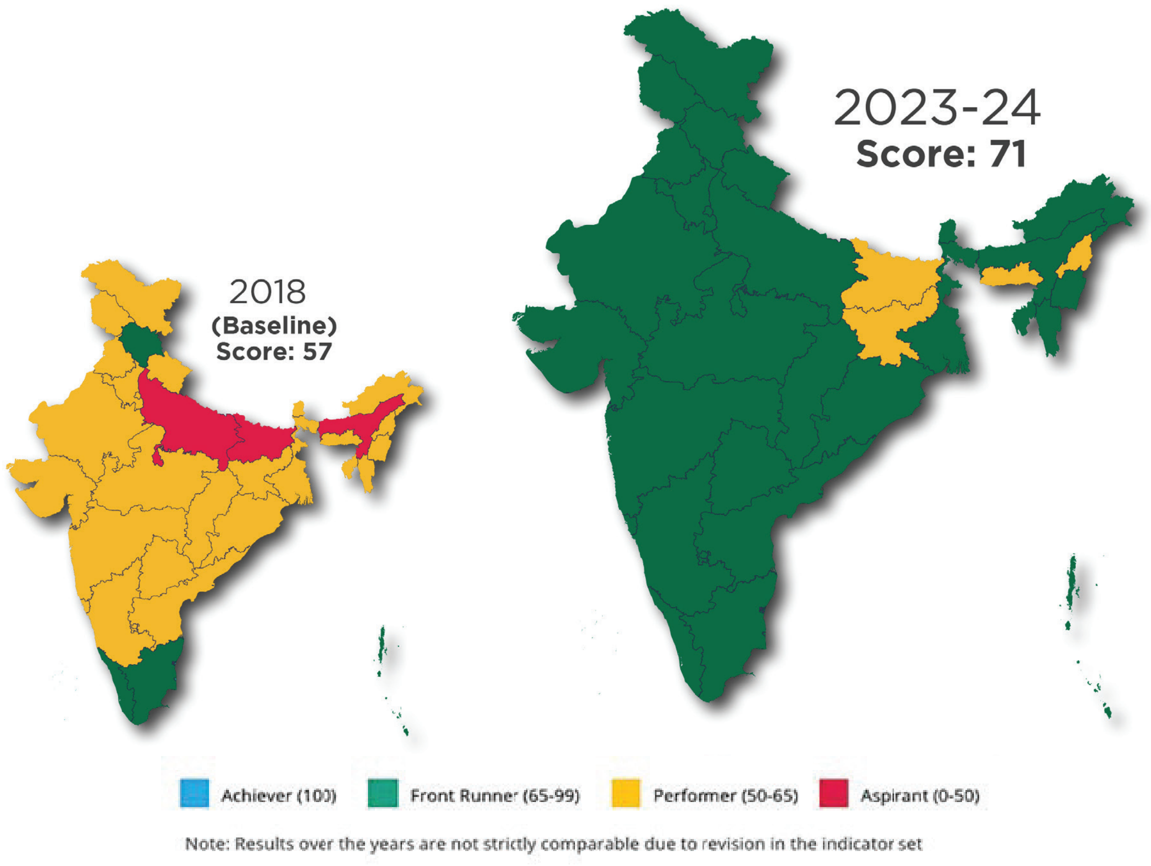

स्रोत: नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24

7.119 गौरतलब है कि फ्रंट रनर श्रेणी में 10 नए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 सभी राज्यों में कंपोजिट स्कोर में वृद्धि को दर्शाता है, जिसमें 1 से 8 अंकों तक का सुधार हुआ है।

7.120 2018 और 2023-24 के बीच, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य उत्तर प्रदेश (स्कोर में 25 की वृद्धि) हैं, इसके बाद जम्मू-कश्मीर (21), उत्तराखंड (19), सिक्किम (18), हरियाणा (17), असम, त्रिपुरा और पंजाब (16), मध्य प्रदेश और ओडिशा (15) हैं।

निष्कर्ष और आगे का मार्ग

7.121 भारतीय अर्थव्यवस्था कल्याण के लिए कल्याणकारी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है, जो सशक्तिकरण, सेवाओं के वितरण में दक्षता और निजी क्षेत्र और नागरिक समाज की भागीदारी पर केंद्रित है। पहुंच के संदर्भ में, बुनियादी आवश्यकताओं की संतृप्ति को अर्थव्यवस्था में प्रत्येक नागरिक की उत्पादक भागीदारी के लिए पहला कदम माना गया है, जो निरंतर मध्यम अवधि के विकास के लिए अनिवार्य है। दक्षता के संदर्भ में, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शासन का डिजिटलीकरण कल्याण कार्यक्रम पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपये के लिए एक बल गुणक है।

7.122 शिक्षा क्षेत्र में एनईपी 2020 द्वारा शुरू किए गए व्यापक परिवर्तन से हलचल मची हुई है, जिससे निकट भविष्य में तीसरी कक्षा पास करने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए बुनियादी साक्षरता और अंकगणित प्राप्त होने की उम्मीद है। ऐसा कहा जाता है कि सीखने के परिणामों में सुधार करना और कोविड के कारण हुई सीखने की हानि को दूर करना पहले से कहीं अधिक जरूरी है। स्वास्थ्य सेवा में, आयुष्मान भारत न केवल जीवन बचा रहा है, बल्कि पीढ़ियों को कर्ज के जाल से भी बचा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने की चुनौती आंतरिक और आर्थिक रूप से मूल्यवान है। सोशल मीडिया और श्बचपन के महान जुड़ावश के युग में, इस चुनौती का सामना करने के साथ, निर्मल तरीके से, सामुदायिक भागीदारी और विशेष मानव संसाधनों को मजबूत करने के साथ किया जाना चाहिए।

7.123 महिलाओं के नेतृत्व में विकास उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण से उत्पन्न होता है, जो नीति और सामाजिक परिवर्तन के रचनात्मक मिश्रण के माध्यम से होता है। फिर भी, महिलाओं के बीच संपत्ति के स्वामित्व को बढ़ाने के लिए बहुत गुंजाइश है, जिसमें निष्पक्षता और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आंतरिक और साधन लाभ सुरक्षित किए जाने हैं।

7.124 कई सक्षम कार्यक्रमों के माध्यम से दूरदराज के इलाकों में जीवन की बेहतर गुणवत्ता को मजबूत किया जा रहा है। स्व-सहायता आंदोलन अपनी पहुंच के मामले में काफी आगे बढ़ चुका है और विपणन और प्रबंधन में पेशेवर सहायता से सामाजिक पूंजी को लाभ मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, आरएसईटीआई का उपयोग कौशल विकास और उद्यम के जिला केंद्रों के रूप में किया जा सकता है।

7.125 इसके अलावा, कोई भी योजना, चाहे कितनी भी अच्छी तरह से डिजाइन की गई हो और उसका निर्माण कितना भी बढ़िया क्यों न हो, उसका क्रियान्वयन उतना ही अच्छा होता है। सरकार के सभी स्तरों पर शासन और उद्देश्य की एकता ही सामाजिक कार्यक्रम की सफलता की कुंजी है। खर्च को परिणामों में बदलने की इस दक्षता को अधिकतम करने के लिए, जमीनी स्तर पर कई चौनलों को खोलना होगा।

7.126 आर्थिक विकास के मूल में मानव विकास निहित है, जो आर्थिक विकास का साधन और साध्य दोनों है। अपनी प्रतिबद्धता में अटल, भारत के पास संतुष्ट होने के लिए बहुत कुछ है और इसके लिए अधीर होने के लिए भी बहुत कुछ है।

****

यह पृष्ठ खाली छोड़ दिया गया है

08

अध्याय

रोजगार और कौशल विकास: गुणवत्ता की ओर

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2 प्रतिशत हो जाने के साथ पिछले छह वर्षों में भारतीय श्रम बाजार संकेतकों में सुधार हुआ है। कार्यबल में बढ़ती युवा और महिला भागीदारी जनसांख्यिकीय और लैंगिक लाभांश का दोहन करने का अवसर प्रस्तुत करती है। फैक्ट्री रोजगार डेटा वित्त वर्ष 22 में संगठित विनिर्माण क्षेत्र की बाउंस-बैक को दर्शाता है, जिसमें रोजगार में निरंतर वृद्धि और कारखानों की वृद्धि होती है. ईपीएफओ के तहत शुद्ध पेरोल वृद्धि पिछले पांच वर्षों में दोगुनी हो गई है, जो औपचारिक रोजगार में स्वस्थ वृद्धि का संकेत है। आर्थिक गतिविधि के कई क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जड़ें जमा रही है, जिसके चलते नौकरी बाजार को सामूहिक कल्याण की दिशा में तकनीकी विकल्पों को अनुकूलित और संचालित करना महत्वपूर्ण है। गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा करने और बनाए रखने के लिए, कृषि-प्रसंस्करण और देखभाल अर्थव्यवस्था दो आशाजनक उम्मीदवार हैं, जिसमें श्रम बाजार में महिलाओं के लिए समान अवसर बनाने हेतु देखभाल अर्थव्यवस्था एक जरूरत है। कौशल विकास को बढ़ावा देने से प्रगति हुई है, जबकि इसमें और गुंजाइश बनी हुई है, क्योंकि केवल 4.4 प्रतिशत युवा कार्यबल औपचारिक रूप से कुशल है। कई विनियामक संशोधन रोजगार सृजन के सुलभ अवसरों के रूप में सामने आते हैं, जिसमें भूमि के उपयोग से संबंधित कई राज्य-स्तरीय कानून, महिला श्रमिकों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र और प्रशिक्षुता को बढ़ावा देना शामिल है।

परिचय

8.1 रोजगार विकास और समृद्धि के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है, और इसकी मात्रा और गुणवत्ता यह निर्धारित करती है कि आर्थिक उत्पादन किस हद तक आबादी के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता में तब्दील होता है। रोजगार को बढ़ावा देने का अर्थ है मांग-आधारित विकास के इंजन को शक्ति देना, जिसे एक ऐसी आबादी द्वारा चलाया जाता है जो अपने गरिमापूर्ण अस्तित्व और निर्वाह के लिए सरकार पर उत्तरोत्तर कम निर्भर रहती है। भारत के युवाओं की वैध आकांक्षाओं के अनुरूप रोजगार के उपयुक्त अवसरों का सृजन भी जीवनकाल में एक बार मिलने वाले देश के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है।

8.2 यह अध्याय देश में रोजगार और कौशल विकास के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करता है। पहला खंड देश में रोजगार की स्थिति पर केंद्रित है, विशेष रूप से महिलाओं और युवा रोजगार पर ध्यान केंद्रित करता है। ईपीएफओ के पेरोल में वृद्धि और ग्रामीण मजदूरी में प्रवृत्ति के अलावा कार्यबल के संरचनात्मक परिवर्तन और फैक्ट्री रोजगार में प्रवृत्ति पर चर्चा की गई। यह रोजगार सृजन को सुविधाजनक बनाने और श्रमिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कार्यक्रमों का एक विहंगम दृश्य भी प्रस्तुत करता है। दूसरा खंड श्रम बाजार को आकार देने वाली नई ताकतों को देखता है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), गिग वर्क, जलवायु परिवर्तन आदि शामिल हैं, इसके बाद कामकाजी उम्र की बढ़ती आबादी को पूरा करने के लिए आवश्यक रोजगार सृजन में वार्षिक वृद्धि, श्रम बल में बढ़ती महिला भागीदारी और कृषि से बाहर निकलने वाले श्रम का इन-हाउस अनुमान लगाया गया है। इसके बाद, कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र को व्यावहारिक और विकेंद्रीकृत तरीके से रोजगार सृजन के लिए एक फलदाई क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अगले खंड में एक अच्छी तरह से विकसित देखभाल अर्थव्यवस्था की महसूस की गई आवश्यकता पर चर्चा की गई है, जो महिलाओं द्वारा कार्यबल की भागीदारी का समर्थन करने और बढ़ते उम्र की आबादी को पूरा करने की कुंजी है। अंतिम खंड देश के कौशल बुनियादी ढांचे और रोजगार के लिए कौशल बढ़ाने में नीतियों के परिणामों का विवरण प्रस्तुत करता है।

वर्तमान रोजगार परिदृश्य

8.3 पिछले दशक में, भारत ने अपने रोजगार परिदृश्य में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है, जो आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में योगदान देने वाले कई सकारात्मक रुझानों द्वारा चिह्नित है। यह विकास परिणाम विभिन्न कारकों के फलस्वरूप है, जिसमें आर्थिक सुधार, तकनीकी प्रगति और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। पिछले दशक में व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने वाले संरचनात्मक सुधारों का एक भाग और जारी कार्यकलाप वर्तमान दशक में उत्पादक रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण बना रहता है।

8.4 राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर (यूआर)[1] में (सामान्य स्थिति[2] के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति) कोविड-19 महामारी के बाद से गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा रही है। इसके साथ श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर)[3] और श्रमिक-से-जनसंख्या अनुपात (डबल्यूपीआर)[4] में वृद्धि हुई है। यहां तक कि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस)[5] के अपेक्षाकृत सख्त मानकों के अनुसार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार महामारी से उबर गया है।

चार्ट VIII.1: वार्षिक श्रम बाजार संकेतकों में सुधार (जुलाई-जून अवधि)

(क) सामान्य स्थिति, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु

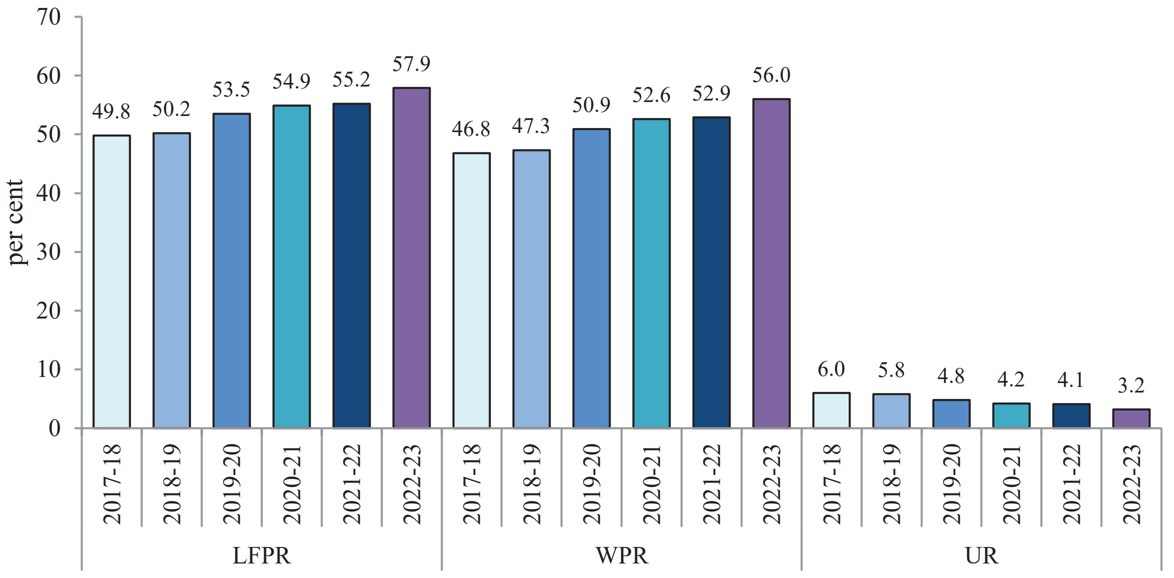

1 यूआर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

2 किसी व्यक्ति को सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार नियोजित के रूप में वर्गीकृत करने के लिए, उसे सर्वेक्षण की तिथि से पहले 365 दिनों के दौरान कम से कम 30 दिनों के लिए आर्थिक गतिविधि करनी होगी।

3 पीएलएफएस के अनुसार, एलएफपीआर कामकाजी आयु वर्ग की आबादी का प्रतिशत है जो काम में लगी हुई है या 'काम' की तलाश करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है या 'काम' उपलब्ध होने पर उसके लिए उपलब्ध है। 'काम' में स्व-रोजगार (जीविका कृषि और स्वयं के उपभोग के लिए जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना, मुर्गी पालन, आदि), नियमित मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार और आकस्मिक श्रम शामिल हैं।

4 डब्ल्यूपीआर को कुल आबादी में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

5 सीडब्ल्यूएस के मामले में, गतिविधि की स्थिति सर्वेक्षण की तिथि से पहले पिछले 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है।

(ख) वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु

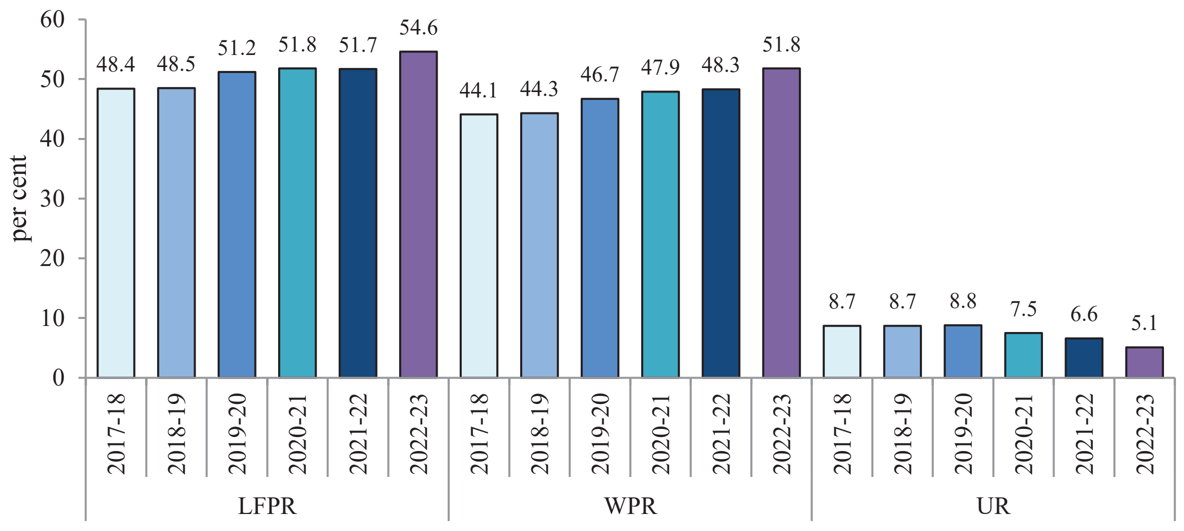

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई
नोट: 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के आंकड़े, 2022-23 के सर्वेक्षण की अवधि जुलाई 2023 से जून 2024 है, और इसी तरह अन्य वर्षों के लिए।

8.5 शहरी क्षेत्रों के लिए त्रैमासिक पीएलएफएस रिपोर्ट रोजगार की अधिक अद्यतन तस्वीर प्रस्तुत करती है। मार्च 2024 को समाप्त तिमाही में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिये त्रैमासिक शहरी बेरोजगारी दर घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 6.8 प्रतिशत थी, साथ ही डब्ल्यूपीआर और एलएफपीआर में वृद्धि हुई।

चार्ट VIII.2: तिमाही शहरी बेरोजगारी दर में गिरावट

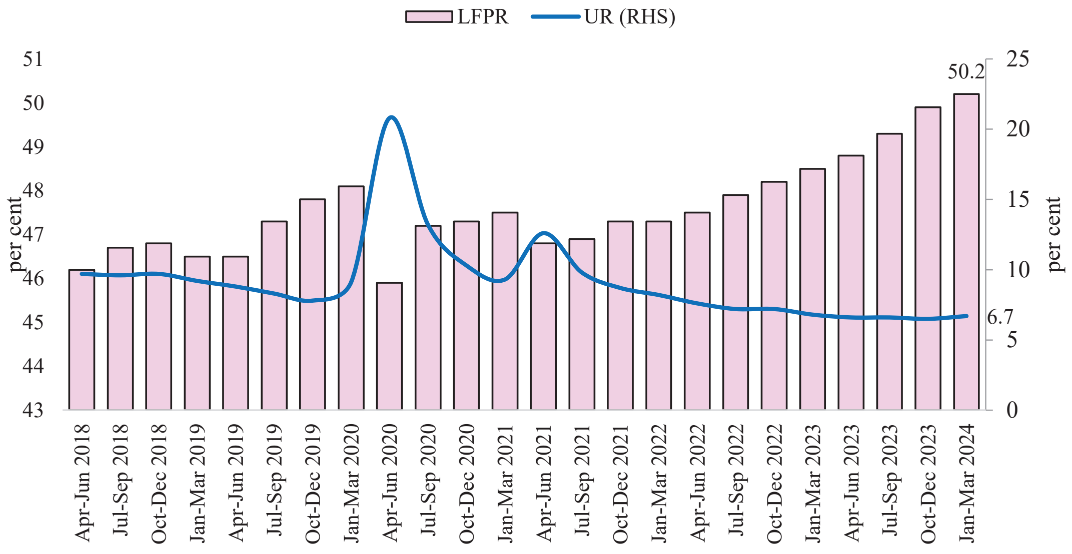

स्रोत: त्रैमासिक पीएलएफएस, एमओएसपीआई
नोट: वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, 15 वर्ष और उससे अधिक के आंकड़े

8.6 पीएलएफएस और एमओएचएफडब्ल्यू के जनसंख्या अनुमान के आधार पर 2022-23 में भारत का कार्यबल लगभग 56.5 करोड़ होने का अनुमान है। पीएलएफएस के अनुसार, 45 प्रतिशत से अधिक कार्यबल कृषि में, 11.4 प्रतिशत विनिर्माण में, 28.9 प्रतिशत सेवाओं में और 13.0 प्रतिशत निर्माण में कार्यरत है। लगभग आधी जनसंख्या, विशेषकर

महिलाओं को रोजगार प्रदान करने में कृषि की प्रधानता एक चुनौती और अवसर दोनों है, जैसा कि इस अध्याय में कृषि-प्रसंस्करण खंड में स्पष्ट किया गया है।

चार्ट VIII.3: व्यापक उद्योग प्रभागों द्वारा श्रमिकों का वितरण, 2022-23

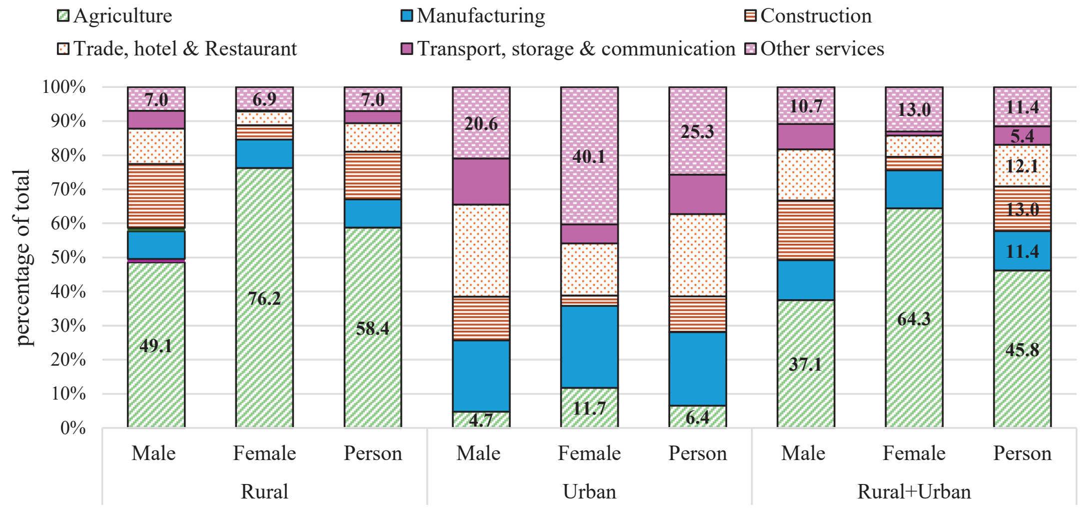

स्रोत: वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट 2022-23, एमओएसपीआई

टिप्पणी अन्य सेवाओं की श्रेणी में प्रकाशन, परामर्श सेवाएं, सूचना सेवाएं, वित्तीय और बीमा सेवाएं, स्थावर संपदा, विधि एवं लेखा, विज्ञापन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं, भ्रमण एवं यात्रा, कला, मनोरंजन एवं मनोविनोद आदि से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं।

8.7 श्रमिकों के रोजगार की स्थिति के संदर्भ में, कुल कार्यबल का 57.3 प्रतिशत स्व-नियोजित है, और 18.3 प्रतिशत घरेलू उद्यमों में अवैतनिक श्रमिकों के रूप में काम कर रहा है। नैमित्तिक श्रमिक कुल कार्यबल का 21.8 प्रतिशत और नियमित वेतन/वेतनभोगी श्रमिक कुल कार्यबल का 20.9 प्रतिशत हैं। लिंग-वार, यह महिला कार्यबल है, जो स्वरोजगार की ओर अभिमुख हो रही है, जबकि पुरुष कार्यबल का हिस्सा स्थिर रहा है। यह पिछले छह वर्षों में महिला एलएफपीआर में तेजी से वृद्धि से स्पष्ट है (इस अध्याय में बाद में चर्चा की गई है), जो ग्रामीण महिलाओं द्वारा कृषि और संबंधित गतिविधियों में शामिल होने से प्रेरित है।

चार्ट VIII.4: व्यापक श्रेणीवार रोजगार की स्थिति में रुझान

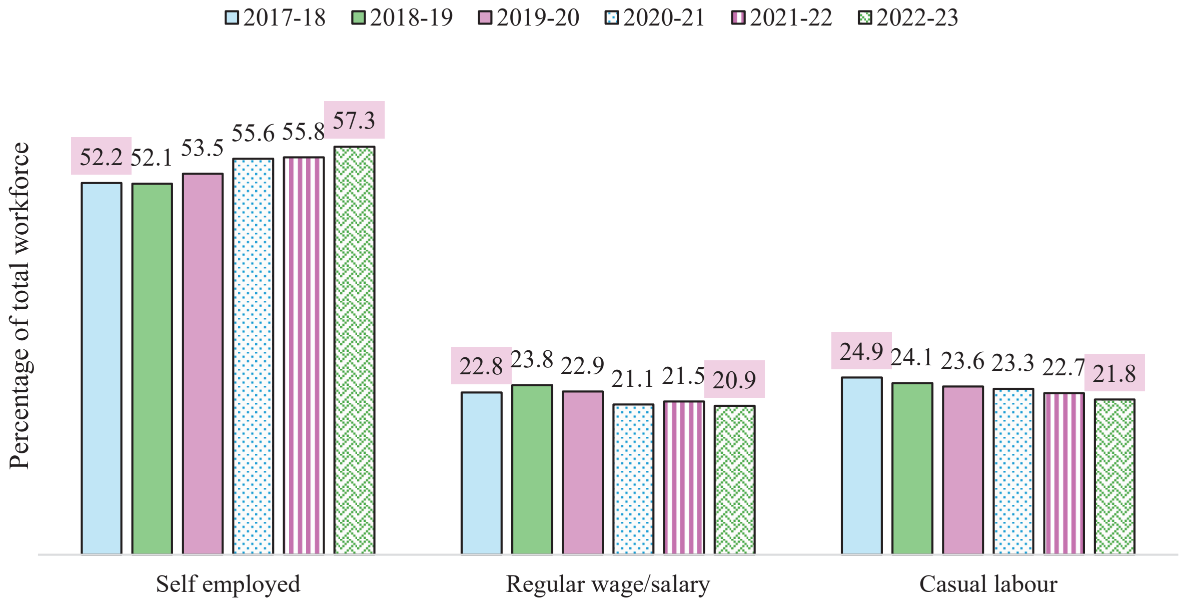

चार्ट VIII.5: स्वरोजगार में महिला कार्यबल की हिस्सेदारी

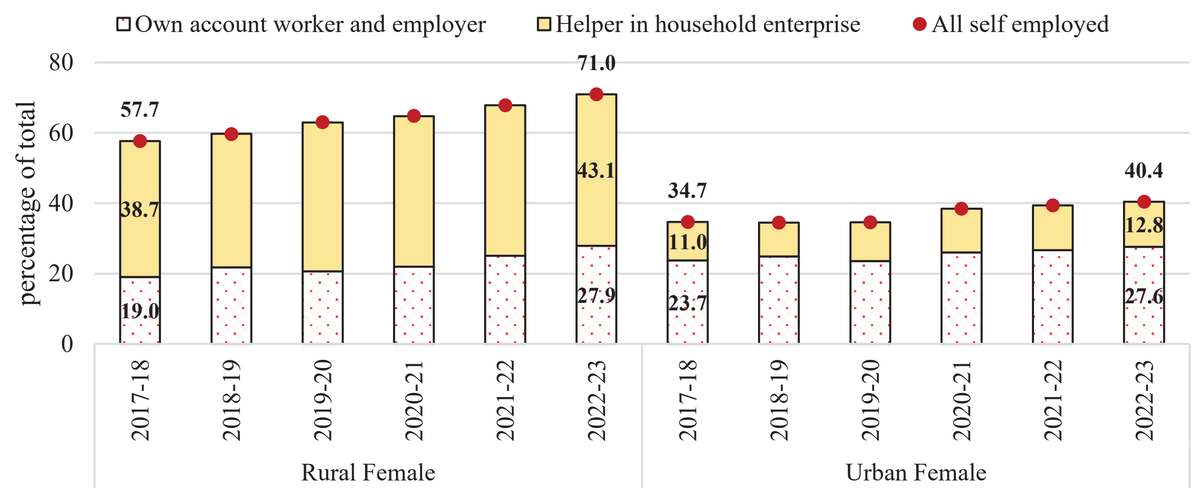

स्रोत: वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट, एमओएसपीआई

युवा और महिला रोजगार

युवाओं का बढ़ता रोजगार

8.8 भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश विनिर्माण और सेवाओं में निरंतर उच्च विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एक कदम है। श्रम बल में अधिक युवा भागीदारी के साथ वार्षिक युवा बेरोजगारी दर में गिरावट इस गतिशील संसाधन के बेहतर उपयोग का संकेत देती है।

8.9 पीएलएफएस के अनुसार, युवा (15-29 वर्ष की आयु) बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 10 प्रतिशत हो गई है, जबकि समय के साथ अन्य संकेतकों में भी सुधार हुआ है। अध्याय के उत्तरार्ध में प्रस्तुत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंकड़ों के अनुसार, युवा रोजगार में वृद्धि औपचारिक रोजगार के आंकड़ों में भी परिलक्षित होती है। कोविड-19 महामारी के दौरान गिरावट देखने के बाद 18-28 वर्ष की आयु के वार्षिक नए ईपीएफ भुगतानकर्ता ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ईपीएफओ के वेतनभोगी नए अंशधारकों में से करीब दो तिहाई 18 से 28 वर्ष आयु वर्ग के हैं। इस प्रकार, युवा आबादी के साथ युवा रोजगार बढ़ रहा है।

चार्ट VIII.6: युवा रोजगार संकेतक

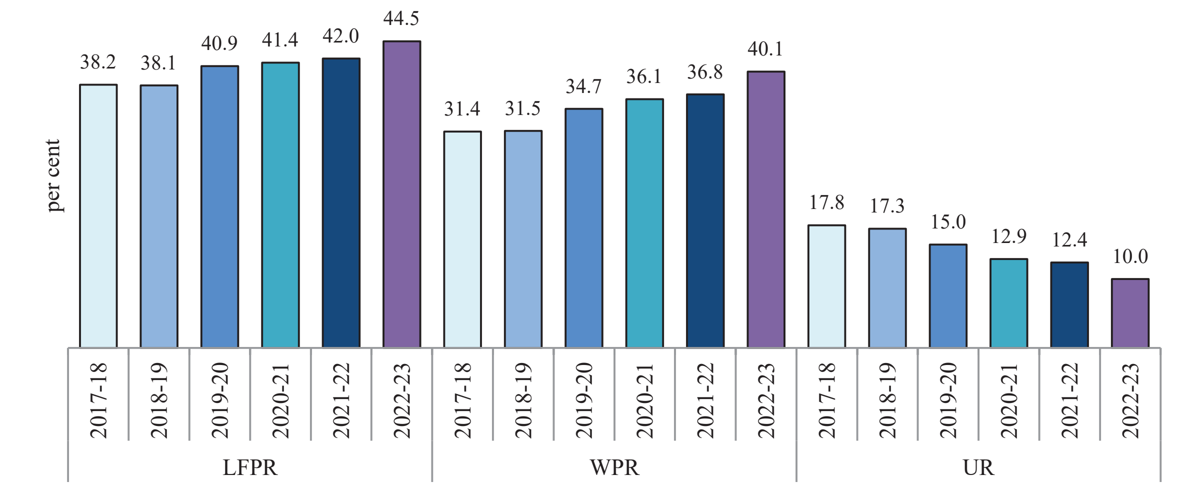

स्रोत: पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट, एमओएसपीआई

महिला एलएफपीआर में वृद्धि: लैंगिक लाभांश का विकास

8.10 लैंगिक दृष्टिकोण से, महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) छह वर्षों से बढ़ रही है। जबकि शहरी एफएलएफपीआर भी बढ़ रहा है, ग्रामीण एफएलएफपीआर में 2017-18 और 2022-23 के बीच 16.9 प्रतिशत अंकों की भारी वृद्धि देखी गई है, जो ग्रामीण उत्पादन में महिलाओं के बढ़ते योगदान को दर्शाता है। यह कई कारकों के कारण हो सकता है, जिसमें कृषि उत्पादन में निरंतर उच्च वृद्धि और पाइप पेयजल, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच के पर्याप्त विस्तार के कारण महिलाओं के समय को मुक्त करना शामिल है। दूसरी ओर, संकट से उपजी एफएलएफपीआर में वृद्धि की संभावना बहुत अधिक आधार नहीं रखती है क्योंकि संकट-चालित एफएलएफपीआर को कोविड-19 के दौरान चरम पर होना चाहिए था और 2017-18 के बाद से लगातार बढ़ने के बजाय बाद में गिरावट आई थी। एफएलएफपीआर में संकट-संचालित वृद्धि की थीसिस को अस्वीकार करने वाले अन्य कारणों को जनवरी 2024 में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'भारतीय अर्थव्यवस्था - एक समीक्षा' में विस्तृत किया गया था।[6]

चार्ट VIII.7: ग्रामीण महिला एलएफपीआर में वृद्धि

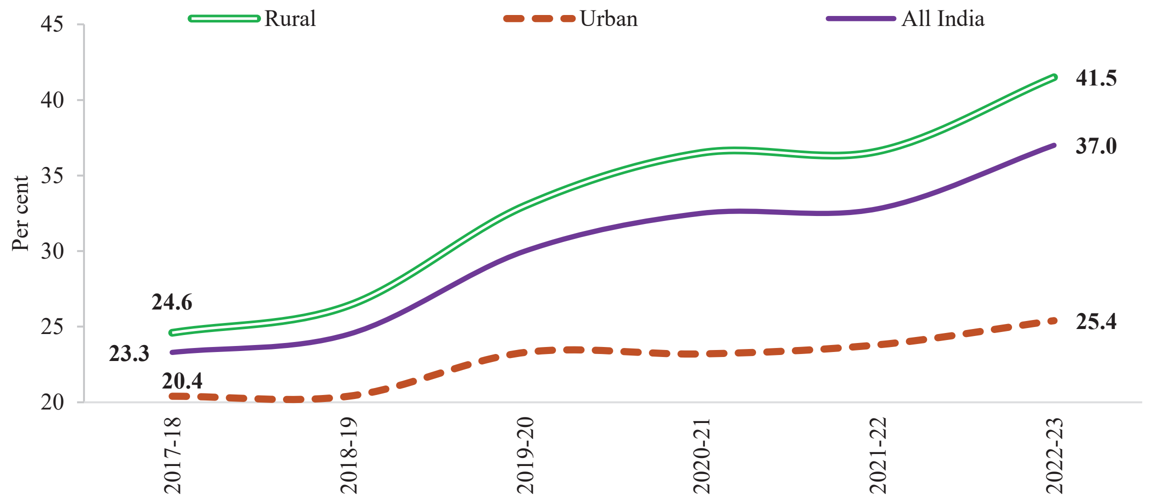

स्रोत: पीएलएफएस रिपोर्ट, एनएसओ
नोट: सामान्य स्थिति के लिए, 15 वर्ष और उससे अधिक

फैक्ट्री में रोजगार

8.11 2020-21 के महामारी वर्ष में रोजगार में मामूली गिरावट के बाद इसके बदलाव को देखते हुए 2020-21 और 2021-22 के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण[7] (एएसआई) के परिणामों ने भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के लचीलेपन को प्रदर्शित किया। एएसआई 2021-22 के अनुसार, संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार, पूर्व-महामारी स्तर से ऊपर हो गया, प्रति कारखाने रोजगार में पूर्व-महामारी वृद्धि जारी रही। प्रति श्रमिक मजदूरी में वृद्धि एक संक्षिप्त अंतराल के बाद फिर से शुरू हुई। इसके साथ-साथ पिछले पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों[8] में उच्च मजदूरी वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग सृजन के लिए शुभ संकेत है। वित्त वर्ष 15-वित्त वर्ष 22 के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति श्रमिक मजदूरी शहरी क्षेत्रों में इसी 6.1 प्रतिशत सीएजीआर की तुलना में 6.9 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ी।

---

6 https://dea.gov.in/sites/default/files/Monthly-20Economic-20Review-20January-202024.pdf पर उपलब्ध है।

7 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित एएसआई अर्थव्यवस्था के संगठित विनिर्माण क्षेत्र को कवर करता है। इसका कवरेज पूरे फैक्ट्री सेक्टर तक फैला हुआ है, जिसमें फैक्ट्री अधिनियम, 1948 की धारा 2(एम)(आई) और 2(एम)(आईआई) के तहत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां (जिन्हें फैक्ट्री कहा जाता है) शामिल हैं, जिनमें दस या उससे अधिक कर्मचारी बिजली के साथ काम करते हैं या बीस या उससे अधिक कर्मचारी बिजली के बिना काम करते हैं।

8 यह ध्यान दिया जा सकता है कि, FY22 तक, 42 प्रतिशत कारखाने और 45 प्रतिशत कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

चार्ट VIII.8: संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार की प्रवृत्ति

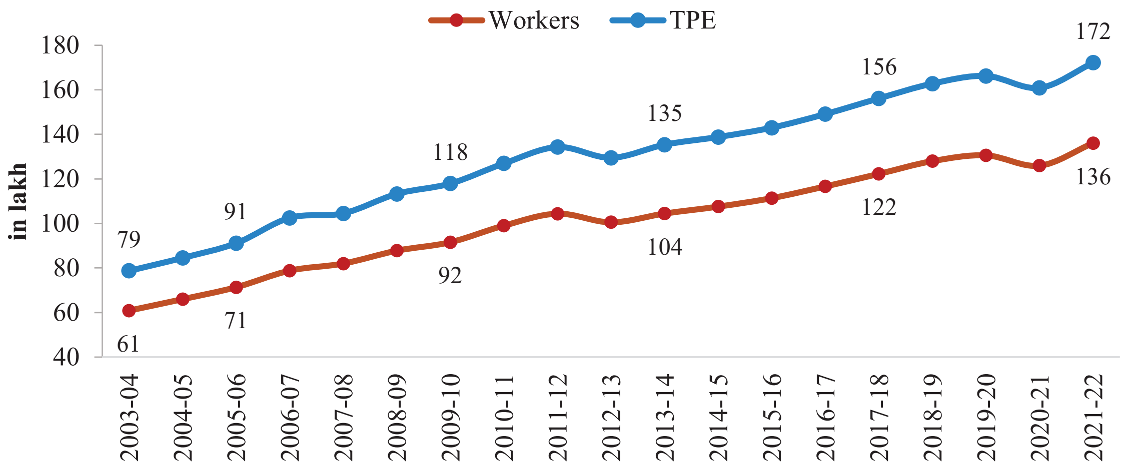

चार्ट VIII.9: प्रति कारखाना रोजगार में रुझान

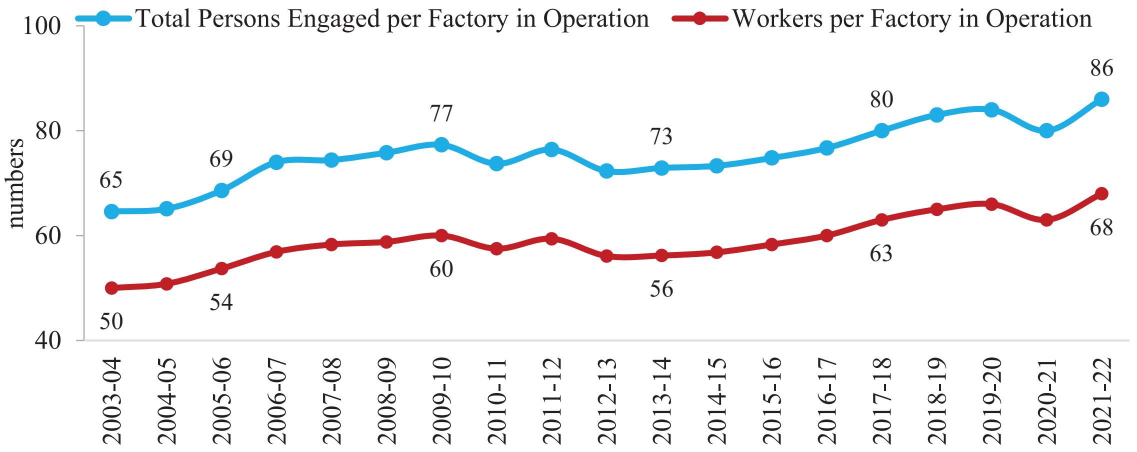

चार्ट VIII.10: प्रति श्रमिक मजदूरी में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि

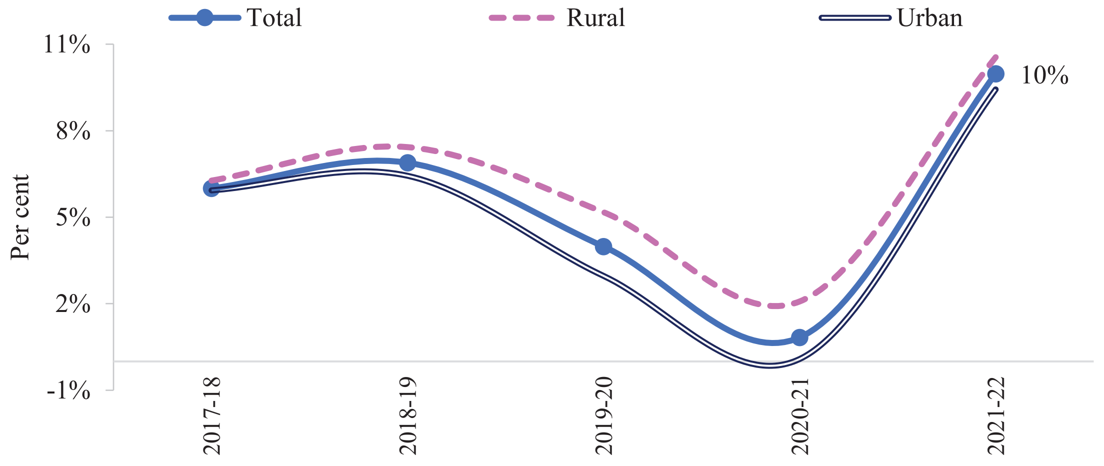

स्रोत: उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, एमओएसपीआई
नोट: टीपीई: कुल नियोजित व्यक्ति

चार्ट VIII.11: कारखानों और रोजगार की संख्या में शीर्ष छह राज्य

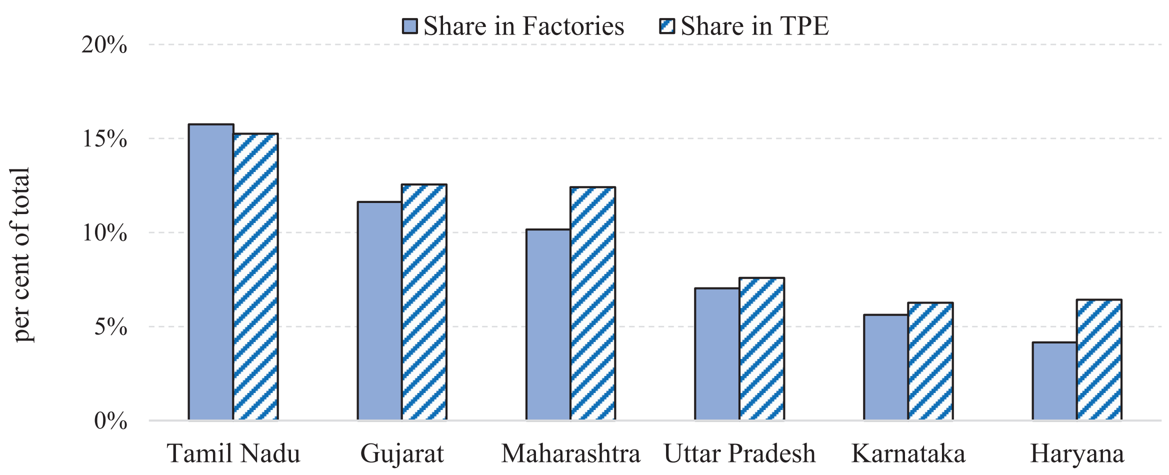

चार्ट VIII.12: पांच वर्षों (FY18-FY22) में शीर्ष छह राज्यों में कारखानों में रोजगार में वृद्धि

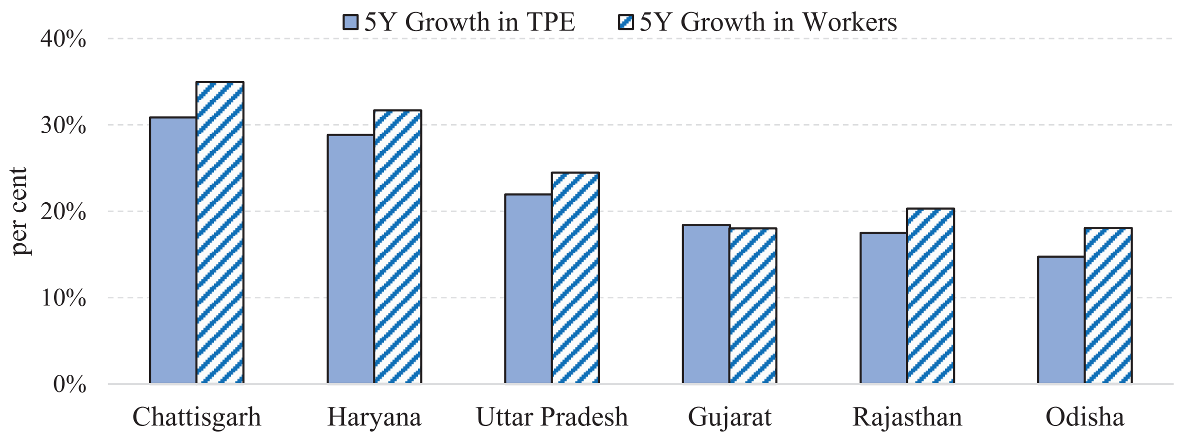

स्रोत: उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, एमओएसपीआई
नोट: टीपीईः कुल नियोजित व्यक्ति

8.12 राज्य-वार, कारखानों की संख्या के मामले में शीर्ष छह राज्य, कारखाने रोजगार के सबसे बड़े निर्माता भी थे। 40 प्रतिशत से अधिक कारखाने का रोजगार तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में था। इसके विपरीत, वित्त वर्ष 18 और वित्त वर्ष 22 के बीच सबसे अधिक रोजगार वृद्धि छत्तीसगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित युवा आबादी की उच्च हिस्सेदारी वाले राज्यों में देखी गई।[9]

9 छत्तीसगढ़ में 30 वर्ष से कम आयु की आबादी का अनुमानित हिस्सा 55.5%, हरियाणा में 52.8% और उत्तर प्रदेश में 60.1 प्रतिशत है। स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुमान https://tinyurl.com/2knzk5xe पर उपलब्ध हैं

चार्ट VIII.13: छोटे कारखानों की प्रधानता जबकि बड़े कारखाने अधिक रोजगार पैदा करते हैं

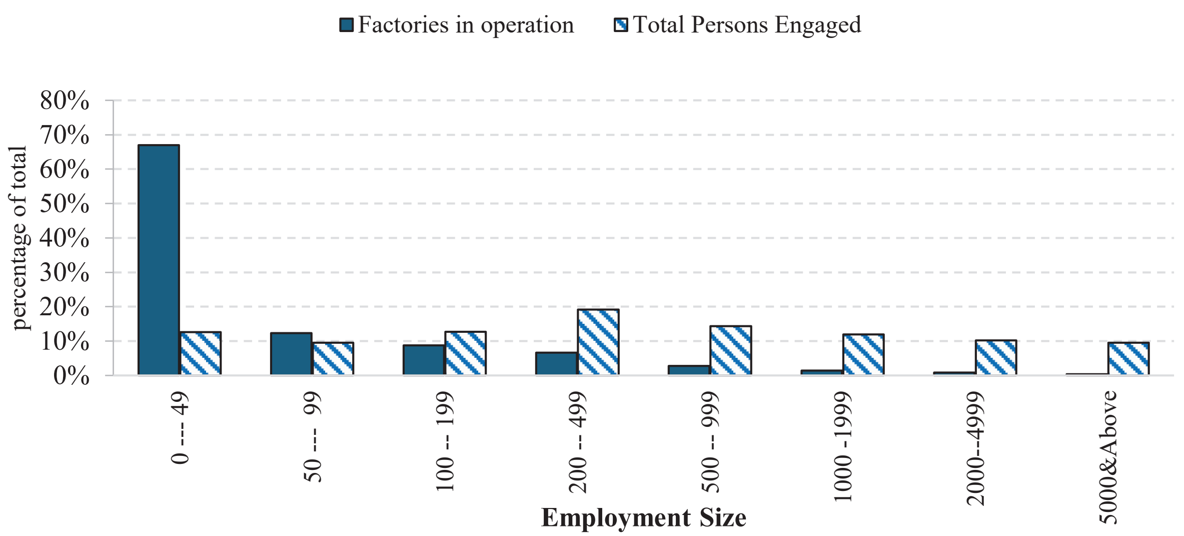

चार्ट VIII.14: बड़े कारखाने बेहतर मजदूरी का भुगतान करते हैं

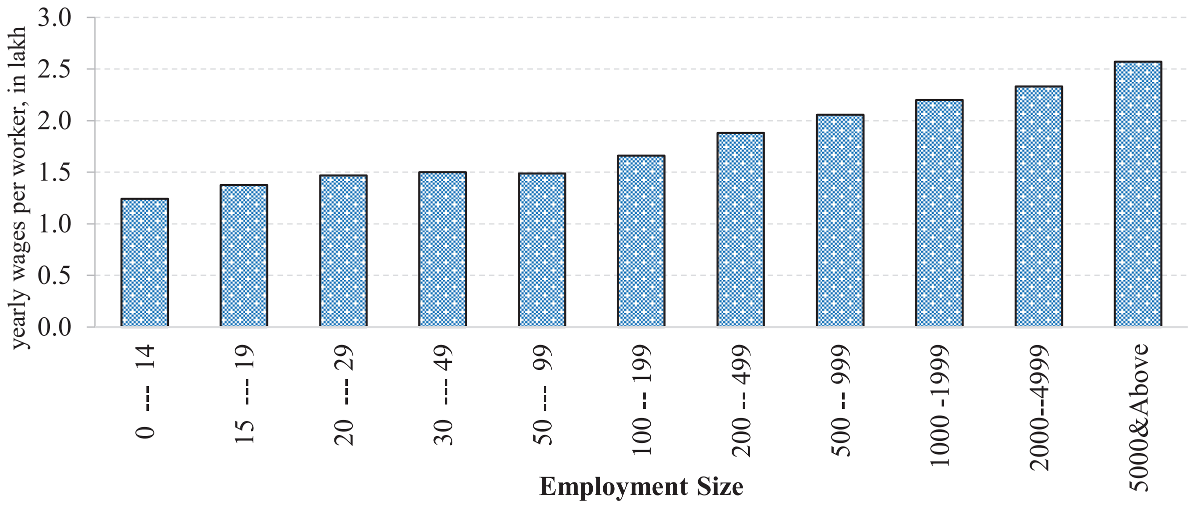

स्रोत: उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, एमओएसपीआई
नोट: टीपीई: कुल लगे हुए व्यक्ति

चार्ट VIII.15: बड़े कारखानों में उच्च रोजगार वृद्धि

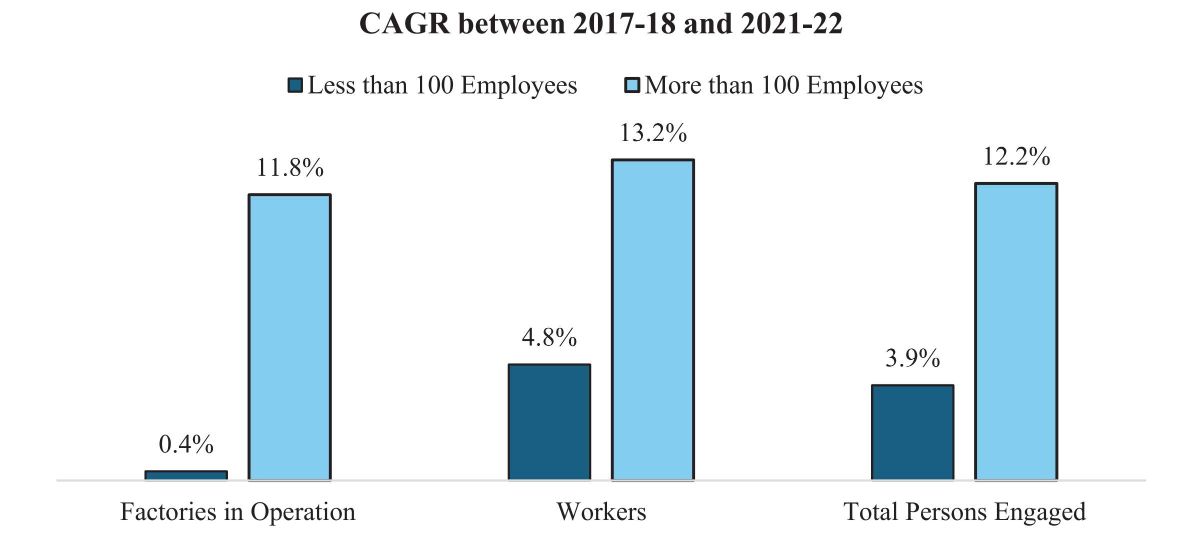

स्रोत: उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, एमओएसपीआई
नोट: टीपीई: कुल लगे हुए व्यक्ति

8.13 प्रतिष्ठानों की संख्या के संदर्भ में, संगठित विनिर्माण परिदृश्य में छोटे कारखानों का वर्चस्व है। 2021-22 में, 100 से कम लोगों को रोजगार देने वाले कारखाने, सभी कारखानों का 79.2 प्रतिशत थे, जबकि कुल नियोजित व्यक्ति केवल 22.1 प्रतिशत और श्रमिक 20.9 प्रतिशत थे। समय के साथ इसमें सुधार हो रहा है क्योंकि बड़े कारखानों में वृद्धि की ओर एक स्पष्ट प्रवृत्ति है। छोटे कारखानों की व्यापक रूप से संख्या की तुलना में, 100 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले कारखानों की संख्या में वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 22 तक 11.8 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। इस प्रकार, कुल नियोजित व्यक्तियों के संदर्भ में, छोटे कारखानों की तुलना में बड़े कारखानों (100 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले) में रोजगार बढ़ रहा है, जो विनिर्माण इकाइयों के स्केलिंग का सुझाव देता है। यह रोजगार की गुणवत्ता के संदर्भ में एक सकारात्मक विकास है, क्योंकि कारखानों के रोजगार के आकार के साथ प्रति श्रमिक मजदूरी बढ़ती है।

चार्ट VIII.16: वित्त वर्ष 22 में फैक्ट्री रोजगार में हिस्सेदारी

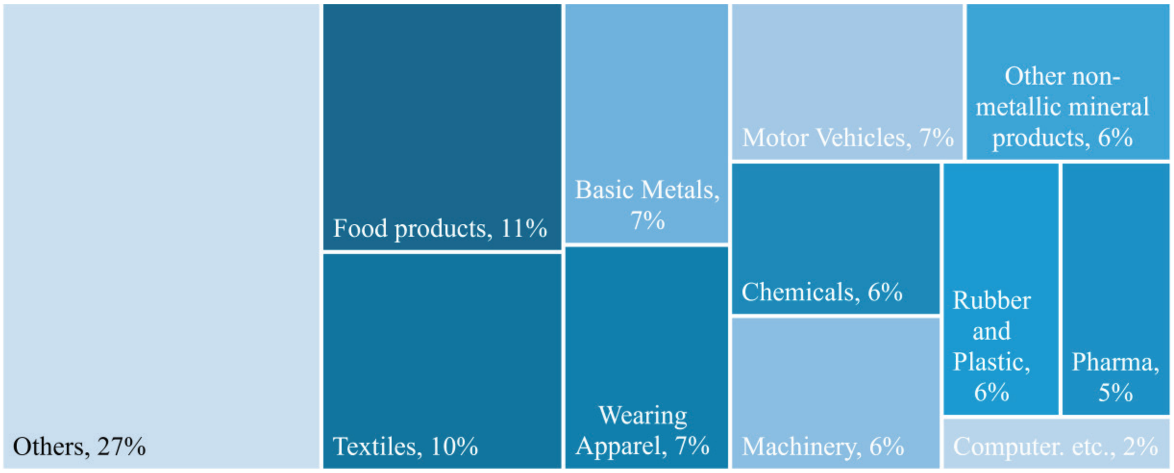

स्रोत: उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, एमओएसपीआई

चार्ट VIII.17: 5 वर्षों में रोजगार में कुल वृद्धि: वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 22

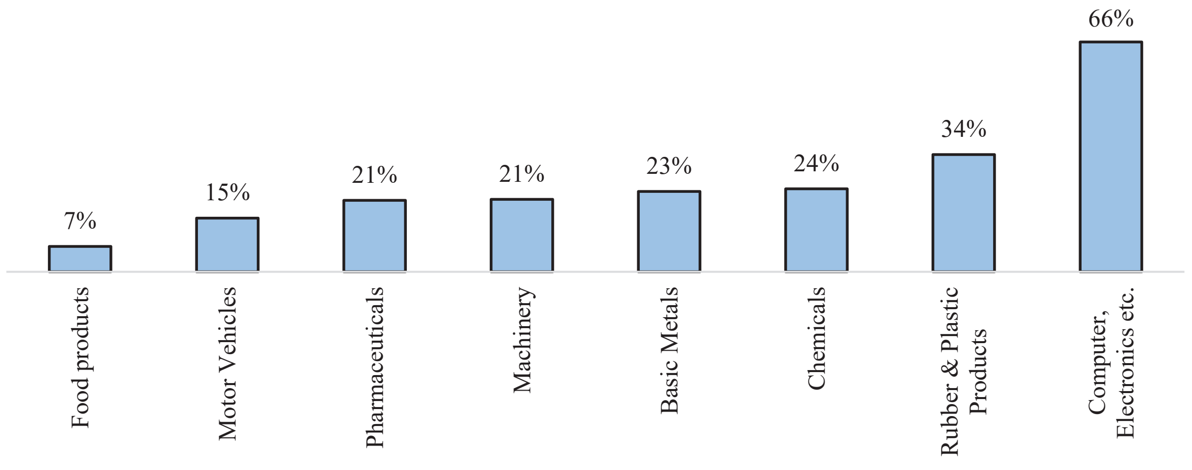

स्रोत: उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, एमओएसपीआई
नोट: रोजगार से तात्पर्य कुल लगे हुए व्यक्तियों से है

8.14 कारखाने के रोजगार (कार्यरत कुल व्यक्ति) के क्षेत्रीय हिस्से के संदर्भ में, खाद्य उत्पाद उद्योग (11.1 प्रतिशत) सबसे बड़ा नियोक्ता बना रहा, इसके बाद कपड़ा, प्राथमिक धातु, परिधान और मोटर वाहन, ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर रहे। तथापि, पिछले पांच वर्षों में रोजगार में वृद्धि के संदर्भ में, कम्प्यूटर और इलेक्ट्रॉनिकी, रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों और रसायनों की बढ़ती हुई संख्या यह दर्शाती है कि भारतीय विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ रहा है और विनिर्माण रोजगार सृजन के लिए उभरते क्षेत्रों के रूप में उभरा है।

ईपीएफओ में नामांकन

8.15 ईपीएफओ के पेरोल डेटा द्वारा मापी गई संगठित क्षेत्र की नौकरी बाजार की स्थितियों से वित्त वर्ष 19 के बाद से पेरोल वृद्धि में लगातार साल-दर-साल (वाईओवाई) वृद्धि का संकेत मिलता है (डेटा उपलब्ध होने के बाद से सबसे पहले)। ईपीएफओ में वार्षिक निवल पेरोल वृद्धि वित्त वर्ष 19 में 61.1 लाख से दोगुनी से अधिक होकर वित्त वर्ष 24 में 131.5 लाख हो गई, जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) द्वारा सहायता प्राप्त महामारी से तेजी से उबर रही है। ईपीएफओ सदस्यता संख्या (जिसके लिए पुराना डेटा उपलब्ध है) वित्त वर्ष 15 और वित्त वर्ष 24 के बीच 8.4 प्रतिशत से सालाना बढ़ी है।

चार्ट VIII.18: बढ़ती ईपीएफओ सदस्यता

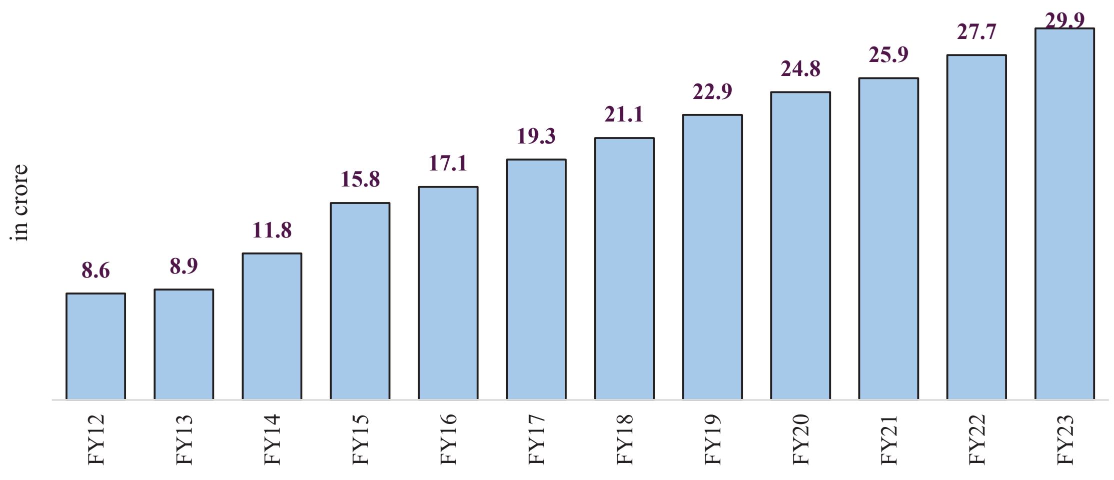

स्रोत: ईपीएफओ वार्षिक रिपोर्ट

चार्ट VIII.19: EPFO में निवल पेरोल वृद्धि

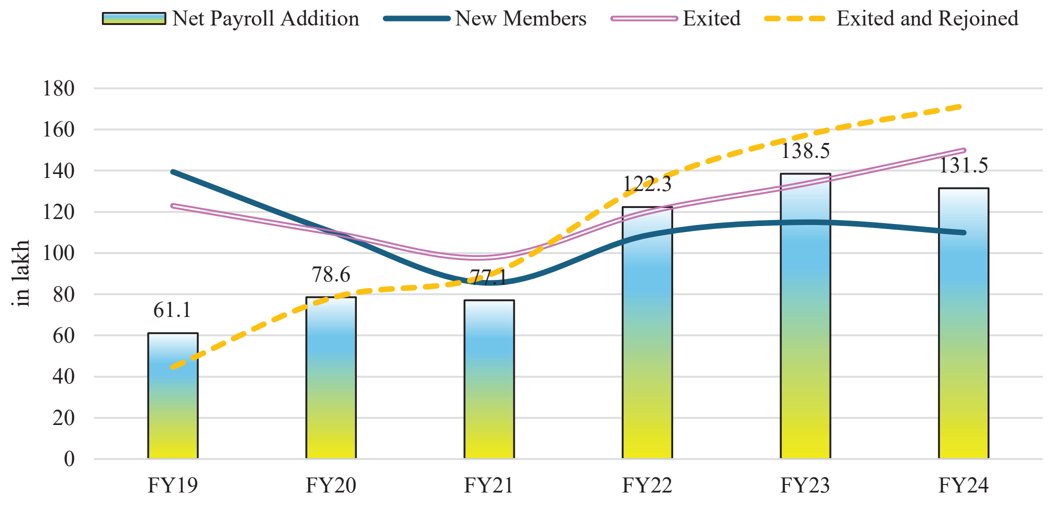

स्रोत: ईपीएफओ मासिक रिपोर्ट

रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल

8.16 सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों को लागू किया है, जैसे कि भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, पूंजीगत व्यय में वृद्धि आदि के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का रोलआउट और श्रमिक कल्याण को बढ़ावा देना। इसके साथ ही ऋण तक पहुंच को आसान बनाने और कई प्रक्रिया सुधारों के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है। रोजगार सृजन और रोजगार सृजनकर्ताओं दोनों को बढ़ावा देने वाली कुछ योजनाओं को बॉक्स VIII.1 में संक्षेपित किया गया है।

बॉक्स VIII.1: रोजगार सृजन और श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने की पहल

- 2015 में शुरू किया गया, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल रोजगार और करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। 31 मार्च 2024 तक, इसे 4.1 करोड़ नौकरी चाहने वालों और 25.6 लाख नियोक्ताओं ने उपयोग किया है। इस पहल में 407 मॉडल करियर सेंटर और 46,000 से अधिक जॉब फेयर शामिल हैं, जिसमें वित्त वर्ष 23 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में नौकरियों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो अधिक प्रतिस्पर्धी जॉब मार्केट का संकेत देता है।

चार्ट VIII.20: एनसीएस के जरिये जुटाई गई रिक्तियां

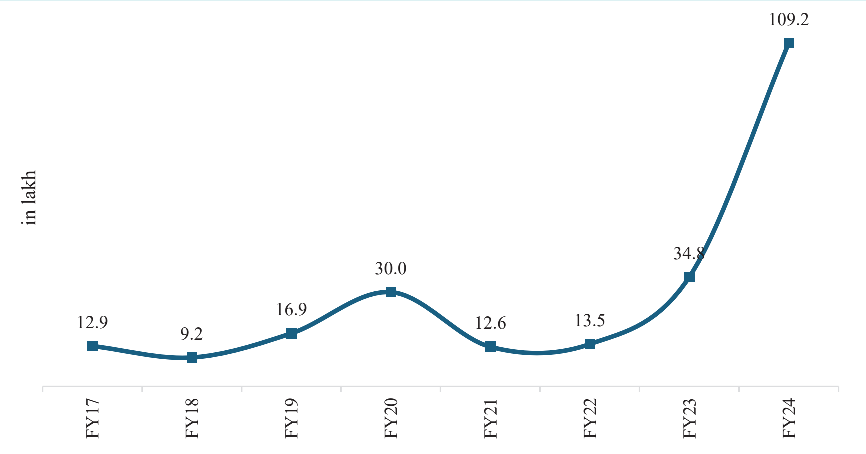

- अक्टूबर 2020 में, सरकार ने कोविड-19 से रोजगार समाप्त होने के बाद सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) की शुरुआत की। 31 मार्च 2024 तक, इस योजना से 1.5 लाख प्रतिष्ठानों में 60.5 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए।[10]
- ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है जिसमें 29 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं। इस पोर्टल को रोजगार सर्च को सुविधाजनक बनाने के लिए एनसीएस पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अन्य प्रासंगिक पोर्टलों के साथ एकीकृत करना है ताकि असंगठित कामगारों को एक ही स्थान पर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं तक पहुंच की सुविधा मिल सके।
- सरकार ने सभी कामगारों के लिए न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए दो महत्वपूर्ण अंशदायी पेंशन योजनाएं शुरू की हैं। 2015 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अब 6.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं।[11] 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना के तहत 50 लाख से अधिक श्रमिकों ने नामांकन करवाया है।[12]
- **किफायती बीमा कार्यक्रम:** प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से केवल 436 और 20 के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख का जीवन और विकलांगता कवर प्रदान किया जाता है।
- नए श्रम कोड अब सामाजिक सुरक्षा कोष के माध्यम से गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करते हैं, जो केंद्र और राज्य सरकारों, एग्रीगेटर्स और पेनाल्टी के योगदान से वित्तपोषित होते हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर-राज्य प्रवासी श्रम की परिभाषा को सरल बनाया गया है।
- स्ट्रीट वेंडर्स को कोलेट्रल फ्री कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा के लिए जून 2020 में शुरू की गई पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के 64 लाख से अधिक लाभार्थी हैं।[13]
- 2019 में शुरू किए गए वन नेशन वन राशन कार्ड कार्यक्रम ने पूरे भारत में पोर्टेबल खाद्य सुरक्षा प्रदान करके प्रवासी श्रमिकों के कल्याण को बढ़ाया है। दिसंबर 2023 तक, इसने 124 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन की सुविधा प्रदान की।[14]
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** सरकार गैर-कृषि क्षेत्र में नई इकाइयों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता करने के लिए पीएमईजीपी का कार्यान्वयन कर रही है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को घर पर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। 2018-19 से 30.01.2024 तक, अनुमानित रोजगार सृजित (व्यक्तियों की संख्या) 37.46 लाख है।

10 एबी-आरपीवाई की सफलता, लिंक यहाँ उपलब्ध है: https://labour.gov.in/aatmanirbhar-bharat-rojgar-yojana-abry
11 पीएफआरडीए से प्राप्त जानकारी के अनुसार
12 इसमें 506603 का थोक नामांकन शामिल है।
13 https://www.pmsvanidhi.mohua.gov.in/Home/PMSDashboard
14 लोकसभा अतारांकित प्रश्न 1784 दिनांक 13.12.2023.

- **दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशनः (डीएवाई-एनयूएलएम):** मिशन का उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाकर उनकी गरीबी और संवेदनशीलता को कम करना है, जिसके परिणामस्वरूप स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में काफी सुधार होगा। वर्ष 2018-19 से दिनांक 30.01.2024 तक, डीएवाई-एनयूएलएम के तहत कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की अनुमानित संख्या 5.48 लाख है।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई):** स्वरोजगार को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा पीएमएमवाई का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पीएमएमवाई के तहत, सूक्ष्म/लघु व्यवसाय उद्यमों और व्यक्तियों को 10 लाख रुपये तक के कोलेट्रल फ्री ऋण दिए जाते हैं ताकि वे अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को स्थापित करने या विस्तार करने में सक्षम हो सकें। 29.03.2024 तक योजना के तहत लगभग 47.7 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए थे।
- **स्टैंड अप इंडियाः** 5 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, ताकि व्यापार, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और कृषि से संबद्ध गतिविधियों में ग्रीनफील्ड उद्यमों की स्थापना के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक एससी/एसटी ऋण प्राप्तकर्ता और एक-महिला ऋण प्राप्तकर्ता को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच के बैंक ऋण की सुविधा मिल सके। 2019-20 में, स्टैंड-अप इंडिया योजना को वर्ष 2020-25 में 15 वें वित्त आयोग की अवधि के साथ पूरी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। 20.5.2024 तक, योजना के तहत 2.29 लाख से अधिक खातों में 51,724 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।[15]
- **स्टार्ट अप इंडियाः** सरकार द्वारा 'सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग', 'फंडिंग सपोर्ट और इंसेंटिव्स' और 'इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप एंड इनक्यूबेशन' के निरंतर प्रयासों के कारण उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2016 में 300 से बढ़कर 31 दिसंबर 2023 तक 1,17,254 हो गई है।[16] इन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ने महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव डालते हुए 12.42 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं।[17] डीएवाई-एनआरएलएम, आरएसईटीआई आदि सहित ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम, जैसा कि सामाजिक अवसंरचना संबंधी अध्याय में चर्चा की गई है।
- **फ्लैगशिप कार्यक्रमः** इन पहलों के अलावा, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास और औद्योगिक कॉरिडोर जैसे सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर पैदा करने की ओर उन्मुख हैं।

8.17 कामगारों की सामाजिक सुरक्षा हेतु सक्रिय पहलों के अतिरिक्त, सरकार ने वर्ष 2002 में राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार श्रम कानूनों के सरलीकरण को भी बढ़ावा दिया है। सरकार ने 2015 से 2019 तक हितधारकों और जनता के साथ व्यापक परामर्श के बाद 2019 और 2020 में 29 केंद्रीय कानूनों को चार श्रम संहिताओं में तर्कसंगत बनाया और समामेलित किया। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और श्रमिकों को ऐसे विधानों के जाल से मुक्त करना था, जिनमें से कई की उत्पत्ति स्वतंत्रता-पूर्व काल में हुई थी, श्रम से संबंधित परिभाषाओं और प्राधिकरणों की बहुलता को कम करना और श्रम कानूनों को लागू करने में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करना और प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रेरित करना था। इसके बाद, चार श्रम संहिताएं; अर्थात्, वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020; अधिनियमित किए गए हैं। वेतन संहिता, 2019 को 8 अगस्त, 2019 को अधिसूचित किया गया था और शेष तीन संहिताओं को 29 सितंबर, 2020 को अधिसूचित किया गया था।

15 स्रोतः वित्तीय सेवा विभाग से इनपुट
16 पीआईबी रिलीज दिनांक 12 फरवरी 2024 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2005206
17 पीआईबी रिलीज दिनांक 2 फरवरी 2024 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2002100

8.18 एक विषय के रूप में श्रम भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है और संहिताओं के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति केन्द्र सरकार, समुचित सरकार और राज्य सरकारों को सौंपी गई है। सार्वजनिक परामर्श के लिए राज्यों द्वारा अपने संबंधित आधिकारिक राजपत्र में नियमों के पूर्व-प्रकाशन की भी आवश्यकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 32, 30, 31 और 31 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने क्रमशः वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 पर अपने मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है।

8.19 हालांकि, राज्यों द्वारा श्रम संहिताओं के अधिनियमन में तेजी लाने की गुंजाइश बनी हुई है। इसके अलावा, रोजगार सृजन के लिए अन्य नियामक बाधाएं मौजूद हैं, जिनमें से कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सख्त हैं, जैसा कि बॉक्स VIII.2 में विस्तार से बताया गया है।

बॉक्स VIII.2: रोजगार को बढ़ावा देने के लिए श्रम विनियमों का पुनर्संतुलन

मौजूदा श्रम नियमों में सामान्य कार्यबल और विशेष रूप से महिलाओं दोनों के लिए अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम हैं। यद्यपि इसे महिलाओं की सुरक्षा और सभी कर्मचारियों के लिए कठोर मानकों को लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है, ये नियम अनजाने में रोजगार के अवसरों को प्रतिबंधित करते हैं और समग्र रोजगार सृजन को बाधित करते हैं। इन नियमों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

समकक्ष और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उच्च ओवरटाइम वेतन प्रीमियम

अन्य देशों के साथ तुलना करने पर पता चलता है कि भारत के सख्त ओवरटाइम वेतन नियम संभावित रूप से कम ओवरटाइम लागत वाले देशों में उत्पादन को बढ़ाकर विनिर्माण क्षेत्र के विकास में बाधा डाल रहे हैं (दांडेकर और रॉय, 2023)।[18]

चार्ट VIII.21: भारत में ओवरटाइम वेज प्रीमियम अधिक है

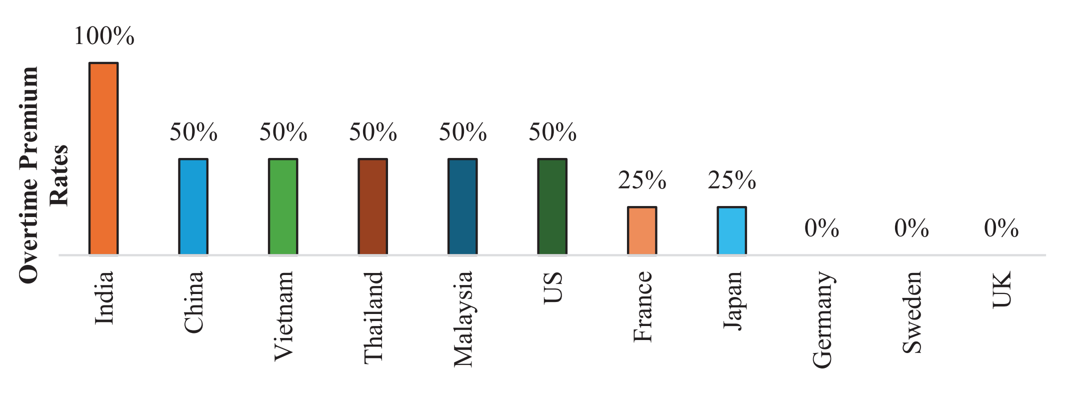

स्रोत: दांडेकर और रॉय (2023)

महिलाओं के लिए नौकरी के अवसरों के लिए व्यवस्थित बाधाएं

10 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों ने सामूहिक रूप से महिलाओं पर फैक्टरी प्रक्रियाओं जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पेट्रोलियम उत्पादन, कीटनाशकों, कांच, रिचार्जेबल बैटरी आदि जैसे उत्पादों के निर्माण में भाग लेने पर 139 प्रतिबंध लगाए हैं (सिंह, 2023)।[19]

18 दांडेकर, एस. और रॉय, एस. (2023, 23 अगस्त)। डबल या नथिंग। प्रॉसपेरिटी इनसाइट्स। https://prosperiti.substack.com/p/double-or-nothing

19 सिंह, ए. (2023, 30 अप्रैल)। भारत में महिलाओं के रोजगार को सीमित करने वाले कानून। इंडिया डेवलपमेंट रिव्यू। https://idronline.org/article/gender/laws-that-limit-womens-employment-in-india/

चार्ट VIII.22: राज्यों में महिलाओं के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों की संख्या

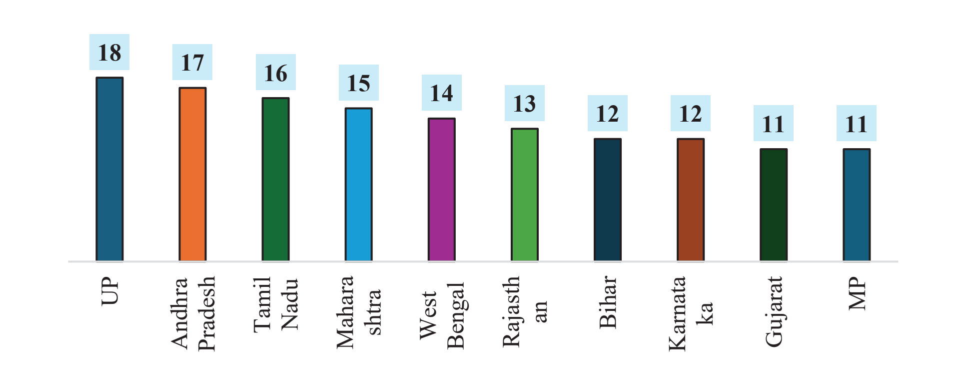

स्रोत: सिंह (2023)

कल्याण की मांग विकास को हतोत्साहित करती है

भारत अन्य देशों की तुलना में फैक्ट्री फ्लोर पर प्रति श्रमिक हायर फ्लोर स्पेस निर्धारित करता है। यदि भारत मलेशिया के मानक को अपनाता है तो 1,000 वर्ग मीटर (वर्गमीटर) उपयोग करने योग्य फ्लोर स्पेस के साथ एक भारतीय कारखाना 82 और श्रमिकों को रोजगार दे सकता है। इसके अतिरिक्त, स्थान संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि कारखानों के विस्तार को हतोत्साहित कर सकती है। उदाहरण के लिए, 500 श्रमिकों वाले एक भारतीय राज्य में एक कारखाने में 5.0 श्रमिकों के लिए प्रति श्रमिक 5.0 वर्गमीटर स्थान होना चाहिए, जबकि 50 श्रमिकों वाले कारखाने के लिए 3.5 वर्गमीटर स्थान होना चाहिए।[20]

तालिका VIII.1: भारतीय कारखाने प्रतिस्पर्धी प्रति-श्रमिक स्थान मानकों को अपनाकर अधिक श्रमिकों को काम पर रख सकते हैं

देश	प्रति कार्यकर्ता स्थान (वर्गमीटर)	अतिरिक्त नौकरियां सृजित
भारत	3.38	लागू नहीं
सिंगापुर	2.88	52
स्विट्जरलैंड	2.86	54
मलेशिया	2.65	82
जर्मनी	'पर्याप्त' स्थान	लागू नहीं
नॉर्वे	'पर्याप्त' स्थान	लागू नहीं

स्रोत: कौर, कौर और रॉय (2023)

काम के घंटों में गैर-लचीलापन

कई देश काम के घंटों को व्यवस्थित करने में अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं और भारत की तुलना में अधिक ओवरटाइम की अनुमति देते हैं। यह भारतीय श्रमिकों के लिए मौद्रिक समय को सीमित कर रहा है और उनके परिवारों और देश की समृद्धि को प्रभावित कर रहा है (रॉय, सक्सेना और सिंह, 2023)।[21]

20 कौर, ई., कौर, एस., और रॉय, एस. (2023, 20 सितंबर)। (नो) रूम टू ग्रो। प्रॉसपेरिटी इनसाइट्स। https://prosperiti.substack.com/p/no-room-to-grow

21 आनंद, बी., रॉय, एस., सक्सेना, पी., और सिंह, ए. (2023, 04 अक्टूबर): "सीमा कम करें, कमाई बढ़ाएं", प्रॉसपेरिटी इनसाइट्स। https://prosperiti.substack.com/p/lower-the-bar-increase-the-earnings

देश	एक कारखाने में काम के घंटे की सीमा
भारत	10.5
बांग्लादेश	11
वियतनाम	12
चीन	कोई सीमा नहीं
डेनमार्क	कोई सीमा नहीं
इंडोनेशिया	कोई सीमा नहीं
नॉर्वे	कोई सीमा नहीं
दक्षिण कोरिया	कोई सीमा नहीं
स्वीडन	कोई सीमा नहीं
स्विट्जरलैंड	कोई सीमा नहीं
स्रोत: रॉय, सक्सेना और सिंह (2023)	

निष्कर्ष

नई श्रम संहिताएं उपरोक्त कुछ टिप्पणियों में मामूली सुधार करती हैं। कुछ मामलों में, राज्यों द्वारा बनाए जाने वाले नियमों की सीमाएं कानून से हटा दी गई हैं। हालाँकि, कोड अभी भी पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया गया है और कई राज्य नए कानूनों के तहत पुराने प्रतिबंध को फिर से लागू करते हुए पाए गए हैं ।

विनिर्माण क्षेत्र में आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहनों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए श्रम कानूनों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। अधिक लचीले श्रम कानूनों को लागू करने से पर्याप्त आर्थिक क्षमता प्राप्त हो सकती है, लिंग समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक निवेश बढ़ेगा।

8.20 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए भी राज्य बेहतर प्रयास करेंगे। एमएसएमई में व्यवसाय बढ़ाने, नए बाजारों की तलाश करने, धन प्राप्त करने और श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रबंधन बैंडविड्थ सीमित है, और यह सीमित बैंडविड्थ अनुपालन के लिए असमान रूप से खर्च की जाती है। जबकि केंद्र सरकार नियम बनाती है, कार्यान्वयन या पर्यवेक्षण निरीक्षकों और पर्यवेक्षकों के हाथों में होता है जो राज्यों में संबंधित विभागों से आते हैं। यह वह जगह है जहां केंद्र और राज्यों में नौकरशाही के वरिष्ठ स्तर व्यवसायों के लिए समय और अन्य संसाधनों से निचोड़े बिना अनुपालन करना आसान बनाने के लिए सहयोग कर सकते हैं।

ग्रामीण मजदूरी में रुझान

8.21 वित्त वर्ष 24 में, ग्रामीण मजदूरी प्रत्येक माह 5 प्रतिशत से अधिक बढ़ी, वर्ष-दर-वर्ष औसतन, कृषि में नाममात्र मजदूरी दर पुरुषों के लिए 7.4 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 7.7 प्रतिशत बढ़ी, जो इस अवधि के दौरान सुदृढ़ कृषि विकास से लाभान्वित हुई। इसी अवधि के दौरान गैर-कृषि गतिविधियों में मजदूरी वृद्धि अपेक्षाकृत कम थी, पुरुषों के लिए 6.0 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 7.4 प्रतिशत। आगे बढ़ते हुए, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों और घरेलू खाद्य कीमतों में कमी के साथ मुद्रास्फीति में कमी आने की संभावना है, इसलिए वास्तविक मजदूरी में निरंतर वृद्धि होने की संभावना है।

चार्ट VIII.23 (क): ग्रामीण मजदूरी में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि, पुरुष (वर्तमान मूल्यों पर)

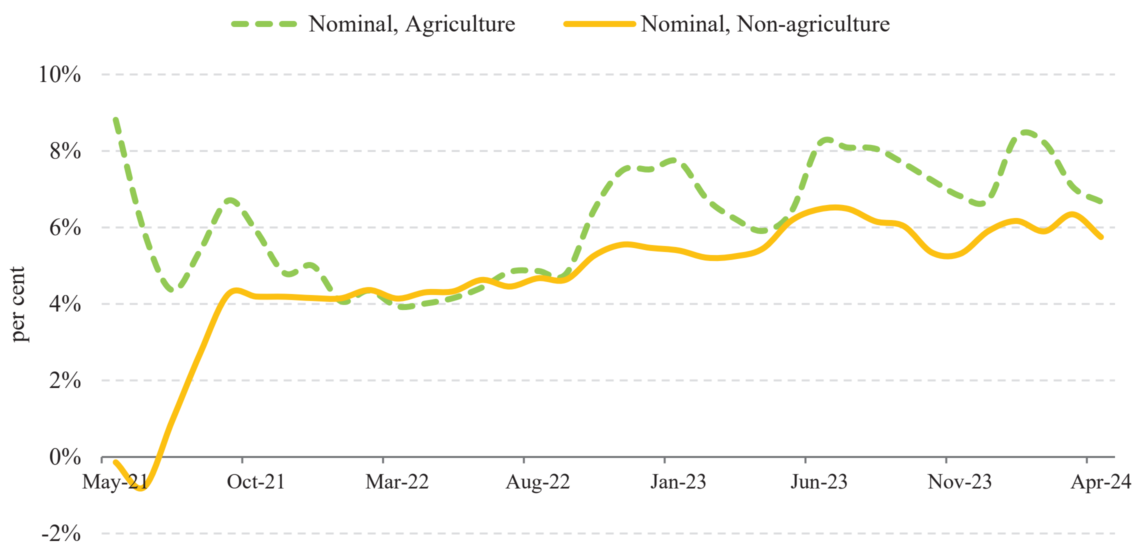

चार्ट VIII.23 (ख): ग्रामीण मजदूरी में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि, पुरुष (स्थिर मूल्यों पर)

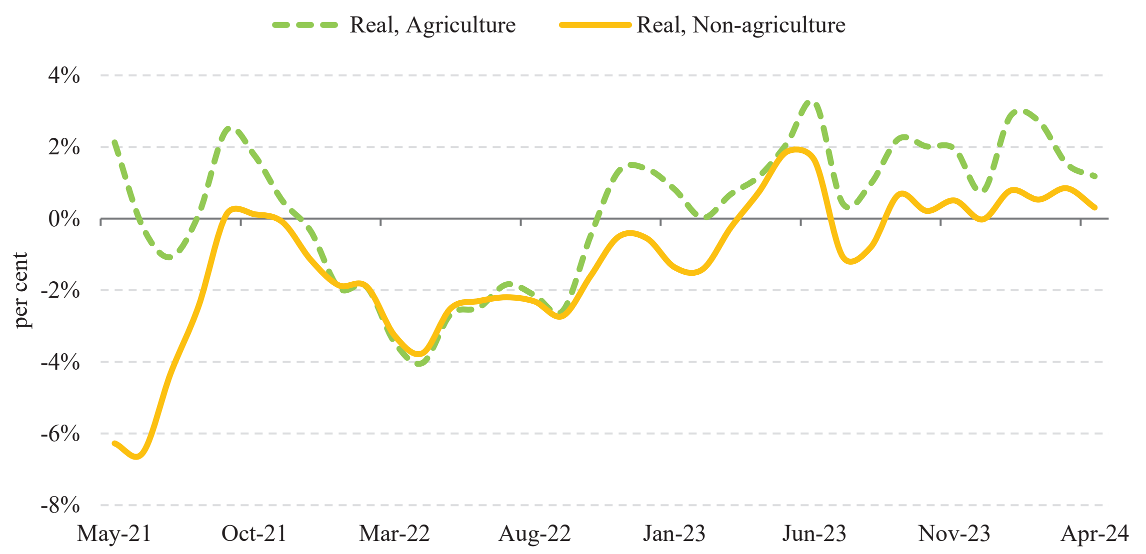

स्त्रोत श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक ग्रामीण मजदूरी दरें

नोट: वास्तविक मजदूरी की गणना के लिए, नाममात्र मजदूरी को सीपीआई-ग्रामीण श्रम से विभाजित किया जाता है

भारत में नौकरियों का विकसित परिदृश्य

8.22 मूल्यवर्धन उत्पन्न करने में विभिन्न उत्पादन कारकों की परस्पर क्रिया एक ऐसी अर्थव्यवस्था में लगातार विकसित हो रही है जो मध्यम-आय की स्थिति में बाधा में है। इस प्रगति को लाने वाले मानव संसाधनों को भी बदले हुए परिदृश्य में रोजगार योग्य होने के लिए इसके अनुकूल होना चाहिए। वैश्विक श्रम बाजार एक 'व्यवधान' के बीच है, जिसे लगातार चौथी औद्योगिक क्रांति द्वारा फिर से रूप दिया जा रहा है, सभी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा एक उभरते जलवायु संकट और अन्य भू-राजनीतिक उलटफेर के मद्देनजर डीकार्बोनाइज करने के ठोस प्रयास। हाल के एक अध्ययन में, डेविड ऑटोर[22]

22 डेविड ऑटोर (2019), 'अतीत का काम, भविष्य का काम', एनबीईआर वर्किंग पेपर नंबर 25588 http://www.nber.org/papers/w25588.

ने लिखा है कि पिछले कुछ दशकों में काम की प्रकृति में परिवर्तन-मुख्य रूप से तकनीकी-गैर-कॉलेज श्रमिकों के लिए अधिक विघटनकारी और कम लाभकारी रहे हैं।

8.23 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, 2023[23] के अनुसार, अगले पांच वर्षों में, वैश्विक स्तर पर 23 प्रतिशत नौकरियों में बदलाव होने की संभावना है। इस परिवर्तन में 10.2 प्रतिशत नौकरियों में वृद्धि और 12.3 प्रतिशत नौकरियों में गिरावट शामिल होने की संभावना है। नियोक्ता 69 मिलियन नई नौकरियों के सृजन और 83 मिलियन को समाप्त करने की उम्मीद करते हैं - 14 मिलियन नौकरियों की शुद्ध कमी, या वर्तमान रोजगार का 2 प्रतिशत। निम्नलिखित कुछ तरीके हैं जिनमें काम का माहौल विकसित हो रहा है।

चौथी औद्योगिक क्रांति

8.24 18 वीं शताब्दी से शुरू होने वाली तीन औद्योगिक क्रांतियों (आईआर) द्वारा प्रकट आर्थिक संरचनाओं में युगांतरकारी परिवर्तनों ने तकनीकी व्यवधान और महत्वपूर्ण रोजगार विस्थापन का कारण बना है। प्रत्येक के परिणामस्वरूप फर्मों और व्यक्तियों के श्रम बाजारों के साथ वार्ता करने के माध्यमों में परिवर्तन हुआ है, प्रौद्योगिकी के बीच संबंधों को फिर से परिभाषित करना और काम कैसे किया जाता है।[24] प्रत्येक आईआर ने उन श्रमिकों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण नुकसान किया जिनके कार्य स्वचालन के लिए अतिसंवेदनशील थे और जो जल्दी से नई तकनीक के अनुकूल नहीं हो सकते थे। लोगों को श्रम बाजारों में अपना स्थान बनाए रखने के लिए कौशल और कौशल को फिर से कौशल प्रदान करना पड़ा है।

8.25 विश्व एक चौथी औद्योगिक क्रांति के मध्य में है, जिसमें उपन्यास तरीकों की विशेषता है जिसमें प्रौद्योगिकी श्साइबर-भौतिक प्रणालियों,श इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), बड़े डेटा, नैनो-प्रौद्योगिकी और नेटवर्क के माध्यम से समाजों के भीतर अंतर्निहित हो रही है। मशीन लर्निंग, एआई, ब्लॉकचेन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, उन्नत एनालिटिक्स, स्वचालन और उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी के विकसित रूप इस तकनीकी क्रांति का गठन करने वाले कुछ उदाहरण हैं। इस उभरती क्रांति की पृष्ठभूमि में, भारत में नौकरी बाजारों का भविष्य एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जैसा कि विश्व के शेष भागों में हो रहा है।

8.26 डिजिटल भूमिकाओं की मांग बढ़ रही है, कोविड-19 महामारी और इसके सुस्त प्रभाव से और तीव्र हो गई है। तकनीकी प्रगति बड़े डेटा, एआई और मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षित तकनीक-प्रेमी पेशेवरों की बढ़ती मांग की ओर अग्रसर है। डब्ल्यूईएफ के अनुसार, अगले पांच वर्षों में सबसे तीव्रता से बढ़ने वाली नौकरियां एआई और मशीन लर्निंग विशेषज्ञों, स्थिरता विशेषज्ञों, व्यापार खुफिया विश्लेषकों और सूचना सुरक्षा विशेषज्ञों की होंगी; शिक्षा, कृषि और डिजिटल कॉमर्स में सबसे बड़ी पूर्ण वृद्धि की संभावना है।

एआई को अपनाने के कारण व्यवधान

8.27 कार्य के भविष्य के लिए सबसे बड़ा व्यवधान एआई में त्वरित वृद्धि है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने के लिए तैयार है। भारत भी इस परिवर्तन से अछूता नहीं रहेगा। एआई को बिजली और इंटरनेट जैसी सामान्य प्रयोजन वाली तकनीक के रूप में पहचाना जा रहा है, जो नवाचार की तीव्र गति और प्रसार में आसानी में अभूतपूर्व है। जैसे-जैसे एआई सिस्टम स्मार्ट होते जाएंगे और गोद लेने में वृद्धि होगी, कार्य का भविष्य नया रूप लेगा। जबकि एआई में उत्पादकता बढ़ाने की काफी क्षमता है, इसमें कुछ क्षेत्रों में रोजगार को बाधित करने की क्षमता भी है। ग्राहक सेवा सहित नियमित कार्य, संभवत: उच्च स्तर के स्वचालन का गवाह बनेंगे; रचनात्मक क्षेत्रों में छवि और वीडियो निर्माण के लिए एआई उपकरणों का व्यापक उपयोग दिखाई देगा; व्यक्तिगत एआई ट्यूटर शिक्षा को नया आकार दे सकते हैं और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्र त्वरित दवा की खोज देख सकते हैं। रोजगार पर एआई के प्रभाव पर, बॉक्स VIII.3 में प्रस्तुत ऐसमोग्लू और जॉनसन के काम से अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है।

---

23 https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/

24 उदाहरण के लिए, डिडिएर, एन. (2024)। टुकड़ों को लेंस में बदलना: तकनीकी परिवर्तन, औद्योगिक क्रांतियाँ और श्रम। समाज में प्रौद्योगिकी, 77, 102497, प्रस्तुत करते हैं कि तकनीकी परिवर्तन के संदर्भ में श्रम बाजार कैसे विकसित हुआ है।

बॉक्स VIII.3: रिकार्डो की धुरी और तकनीकी विकल्पों की केंद्रीयता

पारंपरिक आर्थिक ज्ञान यह सुझाव देगा कि तकनीकी परिवर्तन उत्पादकता[25] लाभ उत्पन्न करते हैं जिससे लंबे समय में उच्च मजदूरी और अधिक आर्थिक अवसर मिलते हैं। हालाँकि, ऐसमोग्लू और जॉनसन (2024)[26] के अनुसार, "...इस तरह के एक लंबे दृश्य लेने के लिए नई मशीनरी द्वारा संभव समृद्धि के अपने उचित हिस्से को सुरक्षित करने के लिए श्रमिकों के संघर्ष की अनदेखी करता है। 'लेखक वर्तमान में उत्पादकता और रोजगार में एआई-प्रेरित वृद्धि के बीच संबंधों को समझने के लिए ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से एक क्यू लेते हैं। विशेष रूप से, लेखक 18 वीं शताब्दी के अंत में कताई जेनी की प्रारम्भ के माध्यम से कपास कताई के स्वचालन के उदाहरण लेते हैं, 19 वीं शताब्दी में पावर लूम द्वारा बुनाई का स्वचालन, और 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रेलवे और भारी उद्योगों का आगमन।

स्पिनिंग जेनी[27]

एक कारखाने में पावरलूम[28]

जबकि कताई जेनी ने यार्न की लागत को कम कर दिया और हथकरघा बुनकरों की उत्पादकता और मांग में वृद्धि की, पावरलूम ने 1806 और 1820 के बीच कारीगरों के वास्तविक वेतन के श्रम प्रतिस्थापन और आधे हिस्से का नेतृत्व किया। पावरलूम के आगमन के बाद बुनकरों की वास्तविक मजदूरी में गिरावट को 1819 में ष्मशीनरी ने श्रम की मांग को कम नहीं कियाष से 1821 में 'यदि मशीनरी वह सब काम कर सकती है जो श्रम अब करता है, तो श्रम की कोई मांग नहीं होगी' के पीछे कहा जाता है। इसी तरह, 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर रेलवे के आने से आधुनिक विनिर्माण में नए रोजगारों को बढ़ावा मिला, जिसमें डिजाइन, मरम्मत, रखरखाव और लिपिक कार्य शामिल थे।

लेखक मजदूरी पर स्वचालन के प्रभाव की व्याख्या करने के लिए आर्थिक कारकों की अपर्याप्तता को उजागर करते हैं और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की ताकतों, यानी श्रम और पूंजी के बीच शक्ति संतुलन पर बल देते हैं। यहां एक अंग्रेज इतिहासकार ईपी थॉम्पसन की व्याख्या बुनकरों पर पावरलूम के प्रभाव की व्याख्या करने में उनके लिए अधिक उपयुक्त लगती है। थॉम्पसन के अनुसार, कारखानों में श्रमिकों के आंदोलन ने उनकी स्वायत्तता का नुकसान किया, और, किसी भी नीतिगत समर्थन या सौदेबाजी की शक्ति के अभाव में, मजदूरी और श्रमिक स्थितियों में गिरावट आई। सरल शब्दों में, यह है कि हम प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करते हैं- चाहे हम इसे स्वचालन, निगरानी और नियंत्रण के लिए उपयोग करें या हम इसका उपयोग सूचित निर्णय लेने, समस्या-समाधान और वृद्धि[29] के लिए करें, जो यह तय करता है कि एआई रोजगार सृजन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएगा या इसके लिए बाधा होगी। रिकार्डो के

25 उत्पादकता से तात्पर्य है कि किसी दिए गए इनपुट सेट से कितना उत्पादन किया जा सकता है। उत्पादकता तब बढ़ती है जब समान मात्रा में इनपुट से अधिक उत्पादन किया जाता है या जब कम इनपुट से समान मात्रा में आउटपुट का उत्पादन किया जाता है।

26 ऐसमोग्लू, डारोन और जॉनसन, साइमन, रिकार्डो और थॉम्पसन से सीखना: प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति में मशीनरी और श्रम, और एआई के युग में (मई 2024)। NBER ofdZax isij uacj w32416, SSRN% https://ssrn.com/abstract=4826001.

27 स्त्रोत: https://kids.britannica.com/students/article/spinning-jenny/630347

28 स्त्रोत: https://historyofinformation.com/detail.php\id=42

29 https://www.project-syndicate.org/commentary/i-automation-threatens-workers-lessons-from-industrial-revolution-and-david-ricardo-by-daron-acemoglu-and-simon-johnson-2024-04

समय में, यह विकल्प कारखाने के मालिकों, नियोक्ताओं और उद्योगपतियों द्वारा किया गया था, जबकि मजदूरों को कठोर कार्य की स्थिति, निगरानी और नियंत्रण से गुजरना पड़ता था। अब समय बदल गया है, श्रमिक निश्चित रूप से अधिक स्वतंत्र हैं, और सख्त श्रम कानूनों और ट्रेड यूनियनों के माध्यम से सत्ता में हैं। आज कई रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि एआई रोजगारों को खत्म नहीं करेगा बल्कि उन्हें परिवर्तित कर देगा। अध्ययन इस एआई संक्रमण का मार्गदर्शन करने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता पर बल देते हैं।[30,31]

पेपर का निष्कर्ष है कि स्वचालन अच्छा या बुरा हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे लागू करते हैं, और प्रौद्योगिकी की दिशा में अनुपालन किया जा रहा है। नई प्रौद्योगिकी श्रम की सीमान्त उत्पादकता को कम करके श्रम[32] हितों को नुकसान पहुंचा सकती है जबकि समग्र उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है, जिससे मशीनों द्वारा श्रम का प्रतिस्थापन हो सकता है, जैसा कि हथकरघा बुनकरों के मामले में है। इसी समय, स्वचालन श्रम को दो माध्यमों से लाभान्वित कर सकता है। सबसे पहले, अगर यह सही क्षेत्रों में श्रम की सीमांत उत्पादकता में काफी वृद्धि करता है जिससे गैर-स्वचालित कार्यों में या पूरक उत्पादों का उत्पादन करने वाले उद्योगों में श्रम की मांग बढ़ जाती है, जैसा कि जेनी के मामले में है। दूसरे, जब स्वचालन नए कार्यों के निर्माण और रेलवे उदाहरण (ऐसमोग्लू और जॉनसन 2023) जैसी नई गतिविधियों में श्रम की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि के साथ होता है। उस ने कहा, राजनीतिक अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकी से साझा समृद्धि सुनिश्चित करने में निर्णायक बनी हुई है। इसे 'तकनीकी विकल्पों की केंद्रीयता' कहा जाता है।

8.28 अमेरिका के संदर्भ में किए गए शोध से पता चलता है कि जनरेटिव एआइ (जेनएआई) का रोजगारों को बदलने की तुलना में रोजगारों को फिर से आकार देने पर कहीं अधिक प्रभाव पड़ सकता है।[33] आईएमएफ (2023)[34] और आईएमएफ (2024)[35] के अनुसार, वैश्विक रोजगार का लगभग 40 प्रतिशत एआई के संपर्क में है, संज्ञानात्मक-कार्य-उन्मुख रोजगारों की व्यापकता के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का जोखिम 60 प्रतिशत है। अध्ययन संभावित एआई पूरकता का एक सूचकांक विकसित करता है, जिससे ज्ञात होता है कि इनमें से लगभग आधे एआई से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही, शेष एआई एकीकरण के माध्यम से बढ़ी हुई उत्पादकता से लाभान्वित हो सकते हैं। इसमें पाया गया है कि एआई के अत्यधिक संपर्क में रोजगार भारत के लिए 26 प्रतिशत है, जो उच्च पूरकता वाले व्यवसायों के लिए 14 प्रतिशत और कम पूरकता वाले लोगों के लिए 12 प्रतिशत में विभाजित है।[36,37]

8.29 भारत, अपने गहन जनसांख्यिकीय लाभांश और बहुत युवा आबादी के साथ, विशिष्ट रूप से स्थित है क्योंकि एआई जोखिम और अवसर दोनों का सृजन करता है। कैपिटल इकोनॉमिक्स (2024) के अनुसार, भारत में एआई का वर्तमान प्रसार और अनुकूलन अमेरिका, यूरोप और एशियाई टाइगर्स की तुलना में कम है। विनिर्माण क्षेत्र एआई के संपर्क में कम है क्योंकि औद्योगिक रोबोट न तो मानव श्रम के रूप में फुर्तीले हैं और न ही लागत प्रभावी हैं। इन्वेंट्री और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में, एआई अनुप्रयोग श्रम के पूरक हो सकते हैं। फिर भी, विशेष जोखिम में बीपीओ क्षेत्र है, जहां जेनएआई चैटबॉट्स के माध्यम से नियमित संज्ञानात्मक कार्यों के प्रदर्शन में क्रांति ला रहा है, और अगले दस वर्षों में इस क्षेत्र में रोजगार में काफी गिरावट का अनुमान है। हालांकि, अगले दशक में, एआई के क्रमिक प्रसार से उत्पादकता

30 https://www.ilo.org/resource/news/generative-ai-likely-augment-rather-destroy-jobs

31 https://hbr.org/2021/11/automation-doesnt-just-create-or-destroy-jobs-it-transforms-them

32 श्रम की सीमांत उत्पादकता को उस मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उत्पादन में वृद्धि होगी यदि श्रम की एक और इकाई को नियोजित किया जाता है, जबकि बाकी सब कुछ समान रहता है।

33 फॉरेस्टर का 2023 जनरेटिव एआई जॉब्स इम्पैक्ट फोरकास्ट, यूएस, https://www.forrester.com/report/forresters-2023-generative-ai-jobs-impact-forecast-us/RES179790.

34 पिजिनेली, सी., ए. पैंटन, एम. एम. तवारेस, एम. कैजानिगा, और एल. ली, (2023) 'श्रम बाजार का एआई से संपर्कः क्रॉस-कंट्री अंतर और वितरण संबंधी निहितार्थ।' आईएमएफ वर्किंग पेपर 23/216

35 कैजानिगा और अन्य। 2024. जेन-एआईः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और काम का भविष्य। आईएमएफ स्टाफ चर्चा नोट एसडीएन2024/001

36 एआई के लिए ष्एक्सपोजरष् को एआई अनुप्रयोगों और प्रत्येक व्यवसाय में आवश्यक मानवीय क्षमताओं के बीच ओवरलैप की डिग्री के रूप में परिभाषित किया गया है।

37 2023 आईएमएफ पेपर एआई एक्सपोजर के मानक माप को आगे बढ़ाता है, जिसमें एआई की क्षमता को श्रम के पूरक या विकल्प के रूप में माना जाता है, जहां पूरकता नौकरी विस्थापन के कम जोखिम को दर्शाती है।

में वृद्धि होने की उम्मीद है। डिजिटल स्वास्थ्य डेटा से स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान करने, मौसम की भविष्यवाणी करने और ग्रेडिंग परीक्षणों और ग्रंथों का अनुवाद करने में शिक्षकों को पूरक करने के लिए एआई का उपयोग कुछ विकास अंतराल हैं जिन्हें एआई प्लग कर सकता है।[38]

8.30 सेवा क्षेत्र में एआई को व्यापक रूप से अपनाने से रोजगार को काफी नया आकार मिल सकता है और यहां तक कि उनका स्थान भी ले सकता है। भारत का सबसे बड़ा रोजगार वेबसाइट, कोपस्टेक, ए. ईटी. एएल. (2023) 2016 के बाद से एआई से संबंधित कौशल की मांग में लगभग घातीय वृद्धि की व्याख्या करता है। वे पाते हैं कि व्यवसायों द्वारा एआई कौशल की मांग का गैर-एआई भूमिकाओं की आवश्यकता और मजदूरी के शीर्ष प्रतिशत पर उच्च कुशल, प्रबंधकीय पदों और गैर-नियमित, बौद्धिक कार्यों के विस्थापन के कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।[39]

8.31 प्रौद्योगिकी के साथ काम करने के लिए भारत की आबादी की आत्मीयता को देखते हुए, जैसा कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ देखा गया है, सरकार और उद्योग द्वारा सक्रिय हस्तक्षेप भारत को एआई युग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थान दे सकता है। कर्मचारियों या रोजगार चाहने वालों को संचार, सहयोग और प्रस्तुति से परे कौशल की आवश्यकता होगी, जैसे विश्लेषणात्मक सोच और नवाचार; जटिल समस्या समाधान, महत्वपूर्ण सोच; सीखने और आत्म-विकास; प्रौद्योगिकी डिजाइन और प्रोग्रामिंग; और एआई चुनौती का सामना करने के लिए लचीलापन और अनुकूलनशीलता।

भारत में एआई का अधिकतम लाभ उठाना

8.32 भारत विश्व स्तर पर एआई में अग्रणी होने के बावजूद, मौजूदा साहित्य की समीक्षा से ज्ञात होता है कि भारत में बहुत पहले शोध नहीं किया गया है। यह अंतर इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की आवश्यकता को सामने लाता है। 2019 में चीन द्वारा प्रकाशित एआई संबंधित शोध पत्र 102,161 थे, इसके बाद अमेरिका में 74,386 और भारत में 23,398 थे, जो चीन के एक-चौथाई से कम है। एआई अनुसंधान और विकास में आउटपुट केवल कुछ देशों में एकाग्रता के साथ अत्यधिक विषम हैं।[40,41]

8.33 एआई आर एंड डी आउटपुट में अग्रणी होने के नाते अमेरिका ने स्पष्ट रूप से अपने एआई क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित कार्यनीतिक योजना तैयार की है। योजना में 9 चरण शामिल हैं, जैसा कि इसकी राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद[42] की नवीनतम 2023 रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, अर्थात, एआई अनुसंधान में दीर्घकालिक निवेश करना, मानव-एआई सहयोग के लिए प्रभावी तरीके विकसित करना, एआई के निहितार्थों को समझना और संबोधित करना, एआई सिस्टम की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना, एआई प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए डेटासेट विकसित करना, एआई सिस्टम को मापना और मूल्यांकन करना, राष्ट्रीय एआई आर एंड डी कार्यबल की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझें, निजी-सार्वजनिक भागीदारी का विस्तार करें, और एआई अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण स्थापित करें। यह कार्यनीति उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए अमेरिकी सरकार के एक महत्वपूर्ण पहल को चिह्नित करती है जिन्हें केवल क्षेत्रों द्वारा हल नहीं किया जा सकता है।

8.34 विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) द्वारा एक नीति संक्षिप्त सुझाव दिया गया है कि एआई के लिए एक अंतर-एजेंसी समन्वय प्राधिकरण की आवश्यकता है जो एआई और रोजगार सृजन पर अनुसंधान, निर्णय लेने, नीति नियोजन का मार्गदर्शन करने वाले केंद्रीय संस्थान के रूप में कार्य करेगा।[43] संक्षेप में यह भी सुझाव दिया गया है कि एआई अधिक रोजगार का सृजन करेगा लेकिन इसका नकारात्मक अल्पकालिक प्रभाव हो सकता है, और इस प्रभाव का मुकाबला करने के लिए क्षमता निर्माण, अपस्किलिंग, प्रशिक्षण और नीतियों के निर्माण में निवेश

38 शिलान शाह, एआई के युग में भारत की अर्थव्यवस्था, कैपिटल इकोनॉमिक्स, 23 जनवरी 2024

39 कॉपस्टेक, ए., मार्कजिनेक, एम., पोपल, ए., और स्टेपलटन, के. (2023)। एआई और सेवा-आधारित विकास: भारतीय नौकरी विज्ञापनों से साक्ष्य।

40 https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2e658ef2144a05f30e254221ccaf7a42-0200022021/original/DD-Analytical-Insights-Note-4.pdf

41 https://www.nature.com/articles/d41586-020-03409-8 (सैवेज 2020)

42 राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद व्हाइट हाउस https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/05/National-Artificial-Intelligence-Research-and-Development-Strategic-Plan-2023-Update.pdf

43 https:///www.ris.org.in/sites/default/files/Publication/Policy%20brief-104_Amit%20Kumar.pdf

करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम कुशल श्रमिकों को किसी भी संभावित रोजगार के नुकसान का सामना न करें।

8.35 एआई ने भारत में कृषि-तकनीक, उद्योग और मोटर वाहन, स्वास्थ्य सेवा, बीएफएसआई और खुदरा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक में इंटेलो लैब्स द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा बागवानी एक्सचेंज प्रमाण एक्सचेंज शामिल है, जो बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता को मैप करने के लिए कंप्यूटर विजन का उपयोग करता है। प्रमाण की तकनीक 95 प्रतिशत सटीकता के साथ गुणवत्ता मूल्यांकन प्राप्त करती है, जो 70 प्रतिशत की मैनुअल मूल्यांकन दर को पार करती है। यह ठेकेदारों को विश्व में कहीं से भी व्यवसाय करने के लिए आवश्यक समय और माहौल देता है।[44]

8.36 सरकार ने एआई सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने और एआई को देश के युवाओं से जोड़ने के लिए कई पहल शुरू की हैं। इनमें से कुछ में श्फ्यूचर स्किल्स प्राइमश, 'युवाई: यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विद एआई' स्कूली छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम और 'रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ 2022' शामिल हैं।[45] भारत एआई मिशन के लिए 2024 में 10,300 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया गया है, जो एआई पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।[46]

गिग इकोनॉमी की ओर शिफ्ट

8.37 रोजगार परिदृश्य में एक उल्लेखनीय परिवर्तन ने वैश्विक स्तर पर गिग अर्थव्यवस्था का उदय किया है। इसमें फ्रीलांसर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, सेल्फ-नियोजित, ऑन-कॉल वर्कर्स और क्रिएटिव टेक टैलेंट शामिल हैं। भारत में, गिग इकॉनमी का उदय तकनीक-सक्षम प्लेटफार्मों के उद्भव, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विकास द्वारा समर्थित इंटरनेट तक पहुँच में वृद्धि, सुगम कार्य व्यवस्था की मांग और कौशल पर ध्यान केंद्रित करने से प्रेरित है। राष्ट्रीय श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर नीति आयोग के सांकेतिक अनुमानों के अनुसार, 2020-21 में, 77 लाख (7.7 मिलियन) श्रमिक गिग इकॉनमी में कार्यरत थे। वे गैर-कृषि कार्यबल का 2.6 प्रतिशत या भारत में कुल कार्यबल का 1.5 प्रतिशत थे।[47]

8.38 शोध अध्ययनों से पता चला है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं (एक से चार प्रतिशत के बीच) की तुलना में विकासशील देशों (5 से 12 प्रतिशत के बीच) में गिग अर्थव्यवस्था में भागीदारी अधिक है, और इनमें से अधिकांश रोजगार निम्न आय वाले रोजगारों के प्रकारों में हैं, जैसे कि डिलीवरी, राइडशेयरिंग, माइक्रोटास्क, केयर एंड वेलनेस (बीसीजी 2021)।[48] ऐसी सेवाओं और रोजगार के सुगमता की निरंतर उच्च मांग टियर-2 और टियर-3 शहरों में प्रवेश स्तर के रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रही है, जिसमें रोजगार के बाजार में प्रवेश करने वाले छात्रों के लिए अंशकालिक काम या अस्थायी बेरोजगारी के मामले में सदमे अवशोषक के रूप में शामिल है, जिसमें प्लेटफॉर्म अनुभव (एनसीएईआर 2023) के बाद श्रमिकों के बेहतर भुगतान वाली नौकरियों में जाने की उच्च संभावना है।[49]

8.39 2029-30 तक गिग कार्यबल के 2.35 करोड़ (23.5 मिलियन) तक बढ़ने की उम्मीद है। 2029-30 तक गिग वर्कर्स के गैर-कृषि कार्यबल का 6.7 प्रतिशत या भारत में कुल आजीविका का 4.1 प्रतिशत होने की उम्मीद है।[50] जबकि गिग इकॉनमी युवाओं, विकलांग व्यक्तियों और महिलाओं सहित श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए रोजगार के अवसर खोल सकती है, भारतीय संदर्भ में और विश्व स्तर पर गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए प्रभावी सामाजिक सुरक्षा पहल का निर्माण एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को शामिल करने के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों के दायरे का विस्तार करना एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

---

44 https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/artificial-intelligence-powering-indias-growth-story

45 संसद प्रश्न "एआई का प्रभाव" https://labour.gov.in/sites/default/files/pib2002657.pdf

46 पीआईबी https://pib.gov.in/PressReleasePage-aspx?PRID=2012375

47 नीति आयोग, जून 2022, भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था

48 बीसीजी रिपोर्ट "भारत में गिग अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को खोलना" India-Gig-Economy-Report.pdf (bcg.com)

49 एनसीएईआर, अगस्त 2023, खाद्य वितरण प्लेटफॉर्म श्रमिकों का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव आकलन

50 इबिड. फुटनोट 47

जलवायु परिवर्तन की समस्या

8.40 जलवायु परिवर्तन से वर्तमान समय की एक कठोर वास्तविकता है और मौसम की चरम घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि का अनुमान करते, सहवर्ती परिणाम नौकरियों और उत्पादकता का संभावित नुकसान है। गर्मी एक व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार, 21 वीं सदी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस के वैश्विक तापमान वृद्धि और श्रम बल के रुझानों के आधार पर अनुमानों से पता चलता है कि 2030 में, दुनिया भर में कुल कामकाजी घंटों का 3.8 प्रतिशत उच्च तापमान में खो जाएगा - 136 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों के बराबर - और 2,400 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान।[51] रिपोर्ट में कहा गया है कि उष्णकटिबंधीय अक्षांश के भीतर कृषि और निर्माण रोजगार और स्थान के अपने अधिकतम हिस्से को देखते हुए, भारत की उत्पादकता में कमी सबसे कमजोर देशों में से एक है।

8.41 जलवायु परिवर्तन का एक अन्य पहलू हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाकर और हरित ऊर्जा विकल्पों में संक्रमण करके इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास है। यह प्रवृत्ति उन व्यवसायों की ओर ले जा रही है जो निवेश द्वारा संचालित एक मजबूत रोजगार-सृजन का प्रभाव देख रहे हैं जो व्यवसायों के हरित संक्रमण और ईएसजी मानकों के लागू की सुविधा प्रदान करते हैं।

8.42 उदाहरण के लिए, भारत का हरित संक्रमण अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में नौकरी के अवसरों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की अधिक संभावना है। त्यागी एवं अन्य (2021)[52] का मानना है कि 2030 तक, स्वच्छ ऊर्जा पहल संभावित रूप से 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए 238 गीगावॉट सौर और 101 गीगावॉट नई पवन क्षमता स्थापित करके लगभग 3.4 मिलियन नौकरियां (लघु और दीर्घकालिक) पैदा कर सकती है। ये नौकरियां पवन और ऑन-ग्रिड सौर ऊर्जा क्षेत्रों में बनाई गई नौकरियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन हरित नौकरियों को लेने के लिए लगभग दस लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकता है।[53]

8.43 जलवायु परिवर्तन श्रमिकों की भलाई को भी प्रभावित करता है, जैसा कि हाल ही में आईएलओ की एक रिपोट[54] में बताया गया है, जो दुनिया के 70 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरों का ‘कॉकटेल’ बना रहा है। इस प्रकार श्रमिकों, विशेष रूप से शारीरिक श्रम संबंधी कार्यों में लगे कामगारों को अपने स्वास्थ्य और आय को हीटवेव, बाढ़, चक्रवात आदि की अनियमितताओं से बचाने के लिए उपयुक्त रूप से बनाए गए नीतिगत समर्थन और निजी बीमा उत्पादों की आवश्यकता होती है। यहां, स्व-नियोजित महिला संघ (सेवा) द्वारा एक अभिनव पायलट कार्यक्रम उल्लेखनीय है। 2023 में शुरू किए गए, 22,000 असंगठित श्रमिकों को कवर करने वाला एक हीट-लिंक्ड पैरामीट्रिक बीमा आंशिक मजदूरी भुगतान पर जोर देता है जिसमें तापमान 43.60 ब से अधिक होने पर श्रमिक द्वारा आंशिक रूप से प्रीमियम वहन किया जाता है और बाकी दान के माध्यम से होता है। श्रमिकों की भोजन और दवा की आवश्यकता को कवर करने के लिए, भुगतान चिलचिलाती गर्मी के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करता है। अंतत:, सेवा ने 29 लाख सदस्यों को साइन अप करने की योजना बनाई है जो प्रीमियम को पूरी तरह से श्रमिकों द्वारा स्वयं वित्त पोषित करने की अनुमति देगा।[55]

8.44 संक्षेप में, जैसा कि देश वैश्विक रुझानों के साथ-साथ भविष्य के नौकरी बाजार की जटिलताओं को नेविगेट करता है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, स्वीकृति और परिवर्तन के अनुकूल और नवाचार को प्रोत्साहित करना अवसरों

---

51 आईएलओ (2019), गर्म ग्रह पर काम करना: श्रम उत्पादकता और सभ्य कार्य पर ताप तनाव का प्रभाव। https://tinyurl.com/axn9bx8z

52 त्यागी, आकांक्षा और अन्य (2021)। भारत का बढ़ता स्वच्छ ऊर्जा कार्यबल। नई दिल्ली: ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद, प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद और ग्रीन जॉब्स के लिए कौशल परिषद।

53 सृजित नौकरियाँ आवश्यक कार्यबल से भिन्न हैं, क्योंकि एक कर्मचारी एक से अधिक काम कर सकता है।

54 बदलते जलवायु में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, ILO, अप्रैल 2024, https://www.ilo.org/publications/ensuring-safety-and-health-work-changing-climate

55 राठी, ए., इकोनॉमिक टाइम्स, 12 जून 2024, ‘‘एक ‘कवच’ ने 46,000 भारतीय महिलाओं को गर्मी की लहरों के दौरान जानलेवा काम से बचने में मदद की’’, 24 जून 2024 को एक्सेस किया गया https://tinyurl.com/4asjw7cw

का दोहन करने और हमारे सामने प्रस्तुत चुनौतियों से निपटने की कुंजी होगी। नौकरी के बाजारों में इन रुझानों में गहन अन्वेषण करने से और सावधानीपूर्वक योजना और कार्यान्वयन के माध्यम से लागत प्रभावी समाधान खोजने से नौकरी के पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभावों को कम करने में एक लंबा रास्ता तय होगा।

2036 तक रोजगार सृजन की आवश्यकता

8.45 यह खंड एक सरल मॉडल और कुछ मान्यताओं का उपयोग करके गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन की आवश्यकता का व्यापक अनुमान लगाने का प्रयास करता है। 2022-23 में मौजूदा कार्यबल का अनुमान पीएलएफएस से 2022-23[56] के लिए डब्ल्यूपीआर (सामान्य स्थिति, सभी आयु) और स्वास्थ्य मंत्रालय[57] द्वारा संगत जनसंख्या अनुमानों का उपयोग करके लगाया गया है। कार्यबल में वृद्धि का अनुमान पुरुषों के लिए स्थिर डब्ल्यूपीआर (2023 में 54.4 प्रतिशत) और महिलाओं के लिए बढ़ती डब्ल्यूपीआर (2023 में 27.0 प्रतिशत से 2036 में 40.0 प्रतिशत तक, हर साल 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि)[58] मानते हुए लगाया गया है। इसके अलावा, संरचनात्मक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि कार्यबल में कृषि का हिस्सा धीरे-धीरे 2023[59] में 45.8 प्रतिशत से घटकर 2047[60] में एक-चौथाई हो जाता है, और कृषि छोड़ने वाले संगत कार्यबल को कार्यबल में वृद्धि में जोड़ा जाता है। रोजगार में कृषि की प्रबलता और उच्च मूल्य वाली कृषि और संबद्ध गतिविधियों की लाभकारी रोजगार पैदा करने की क्षमता को देखते हुए यह एक उचित धारणा है, खासकर महिलाओं के लिए। नतीजतन, भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ते कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है (नीचे चार्ट देखें)।

चार्ट VIII.24: गैर-कृषि रोजगार सृजन के लिए वार्षिक आवश्यकता 2024-2036

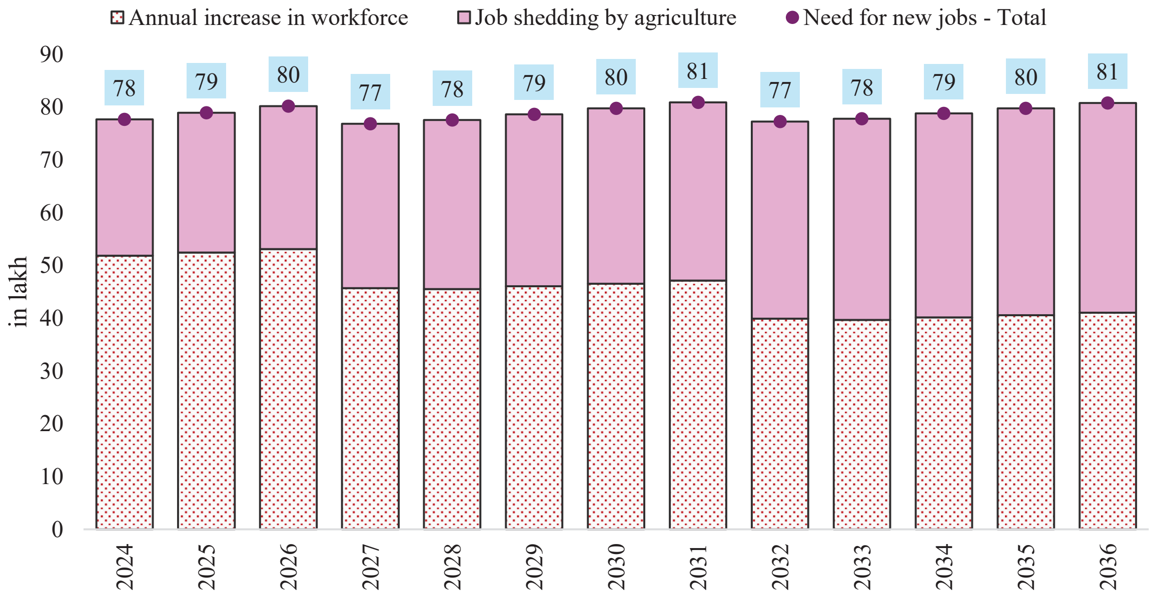

स्रोतः पीएलएफएस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जनसंख्या अनुमान का उपयोग करके गणना की गई।

56 2022 और 23 को अनुभाग में 2023 के रूप में संदर्भित किया गया है।

57 मार्च के जनसंख्या अनुमान को रैखिक विधि का उपयोग करके 1 जनवरी के अनुमान में परिवर्तित कर दिया गया है, क्योंकि जनवरी पीएलएफएस द्वारा उपयोग की जाने वाली जुलाई-जून समय सीमा का मध्य बिंदु है।

58 इस दर पर, महिला डब्ल्यूपीआर 2047 तक 51 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।

59 स्रोतः पीएलएफएस 2022-23 वार्षिक रिपोर्ट

60 इसका तात्पर्य 0.87 प्रतिशत अंक की वार्षिक गिरावट है।

8.46 प्रति वर्ष गैर-कृषि क्षेत्र में 78.5 लाख नौकरियों की मांग को पूरा करने के लिए, पीएलआई (5 वर्षों में 60 लाख रोजगार सृजन),[61] मित्र टेक्सटाइल योजना (20 लाख रोजगार सृजन),[62] मुद्रा आदि की मौजूदा योजनाओं को पूरक बनाने की गुंजाइश है, साथ ही उनके कार्यान्वयन को बढ़ावा देने की भी। निम्नलिखित अनुभागों में, आगे रोजगार सृजन के लिए दो क्षेत्रों की पहचान की गई है और उन पर विस्तार से चर्चा की गई है। रोजगार की मात्रा के अलावा, इसकी गुणवत्ता और सामाजिक सुरक्षा पहलू का अपना महत्व है। स्टाफिंग कंपनियों के माध्यम से फ्लेक्सी श्रमिकों का बढ़ता रोजगार अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक चौनल हो सकता है, जैसा कि बॉक्स VIII.4 में संक्षेप में बताया गया है।

बॉक्स VIII.4: भारत में फ्लेक्सी जॉब मार्केट

भारत में लगभग 5.4 मिलियन औपचारिक अनुबंध कर्मचारी या फ्लेक्सी श्रमिक संगठित अनुबंध/अस्थायी स्टाफिंग कंपनियों के माध्यम से कार्यरत हैं, जो अपने अनुबंध कर्मचारियों को वेतन/मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा/चिकित्सा बीमा का समय पर भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि वे एक अनुबंध पर काम करते हैं, लेकिन ये श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के साथ पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और अनुबंध की औसत अवधि 2023 में छह महीने से अधिक समय से 75 प्रतिशत से अधिक अनुबंधों के साथ बढ़ रही है। फ्लेक्सी कार्यबल 2023 को समाप्त होने वाले दशक में 13.2 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा है, और कोविड महामारी के दौरान भी सकारात्मक रहा है. हालांकि, कुल कार्यबल के हिस्से के रूप में, अनुबंध स्टाफिंग कार्यबल केवल 1 प्रतिशत है, जबकि यूरोप और एशिया प्रशांत में यह 2.2 प्रतिशत है। भारत में फ्लेक्सी नौकरियों का कम प्रतिशत इंगित करता है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र ने फ्लेक्सी श्रमिकों के साथ पूर्णकालिक श्रमिकों को प्रतिस्थापित नहीं किया है।

चार्ट VIII.25: पिछले 10 वर्षों में अनुबंधित कर्मचारियों के कार्यबल की बढ़त

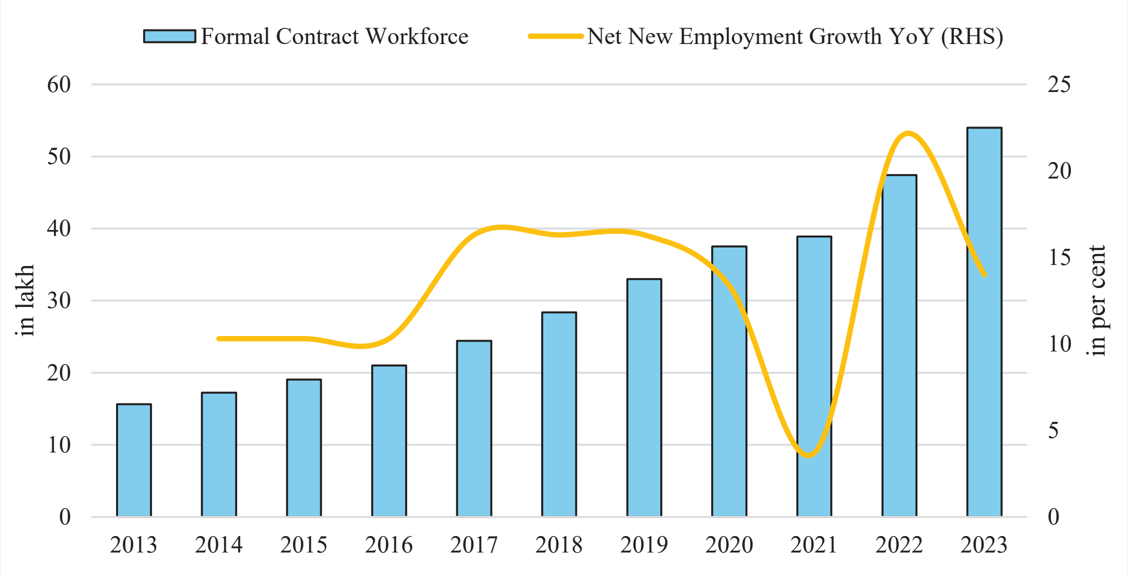

स्रोत: भारतीय कर्मचारी संघ से प्रविष्टि

61 पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 05 फरवरी 2024 https://tinyurl.com/jr5e4m4v

62 पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 21 दिसंबर 2023 https://tinyurl.com/desnm7um

चार्ट VIII.26: फ्लेक्सी कार्यबल का क्षेत्रीय वितरण मिलियन में

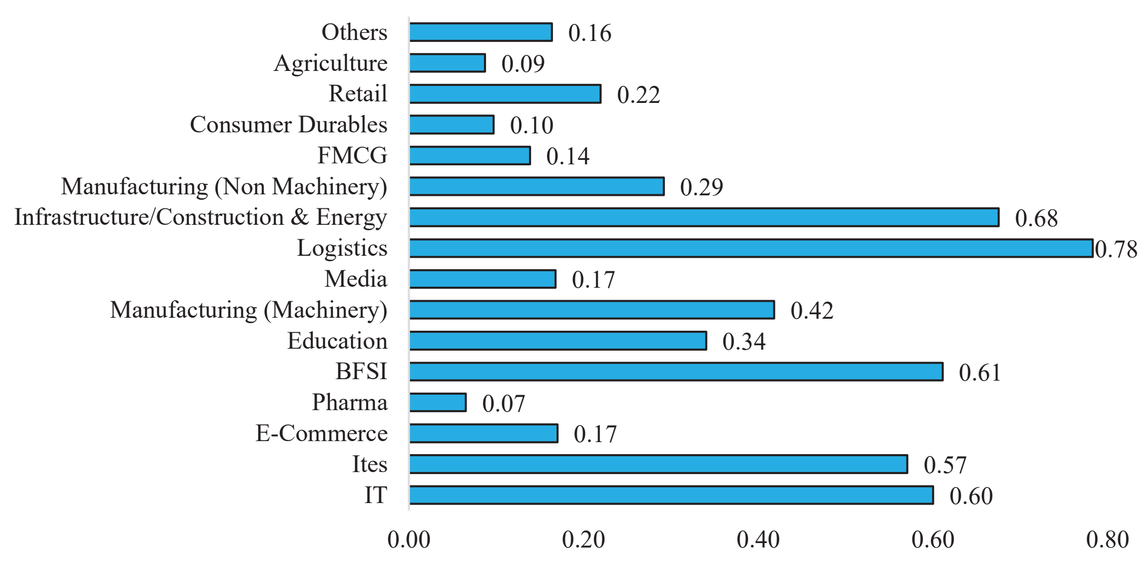

स्रोतः भारतीय कर्मचारी संघ से प्रविष्टि

फ्लेक्सी वर्कर्स में से 80 फीसदी 21-30 आयु वर्ग के हैं, जिनका औसत वेतन 20,000-22,000 रुपये मासिक है। भारत में ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट/फ्लेक्सी जॉब्स स्किल स्पेक्ट्रम के निचले हिस्से में होते रहते हैं, जैसे आंकड़ा परिचालन, लेखा, विक्रय, बैक-एंड ऑपरेशंस, प्रशासन और मार्केटिंग। लगभग 60 प्रतिशत फ्लेक्सी नौकरियां लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचे/निर्माण और ऊर्जा, बीएफएसआई, आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं में हैं।

ग्रामीण रोजगार और विकास के लिए एक उभरते हुए क्षेत्र के रूप में कृषि-प्रसंस्करण

8.47 कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र 'खेत से कारखाना' संक्रमण के लिए एक मध्यवर्ती क्षेत्र होने के अलावा ग्रामीण विकास के लिए कई अवसरों के चौराहे पर स्थित है। निम्नलिखित पैरा भारत के विकास के चरण को देखते हुए रोजगार सृजन के लिए कृषि-प्रसंस्करण की उपयुक्तता पर विस्तार से बताते हैं।

8.48 **ग्रामीण नौकरियों की मांगः** मनरेगा के आंकड़े कम कौशल वाली ग्रामीण नौकरियों (विशेष रूप से महिलाओं द्वारा, जो मनरेगा कार्यबल के आधे से अधिक का गठन करते हैं) की पर्याप्त मांग दिखाते हैं, और मनरेगा श्रम को अधिक उत्पादक और कम वित्तीय रूप से तनावपूर्ण उद्यमों में स्थानांतरित करने की पर्याप्त गुंजाइश है। यह देखते हुए कि कृषि और संबंधित उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बने हुए हैं, रोजगार सृजन के लिए इस क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाना अनिवार्य है। कृषि-प्रसंस्करण पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में फसल विविधीकरण में भी तेजी ला सकता है, जहां धान की खेती भूजल की कमी से संबंधित गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

8.49 **कृषि में कम मूल्यवर्धनः** जबकि भारत दुनिया में कुल कृषि योग्य भूमि का 11.2 प्रतिशत के साथ संपन्न है और दूध, दालों और जूट के उत्पादन में पहले स्थान पर है, फलों और सब्जियों में दूसरे स्थान पर है और अनाज[63] में तीसरे स्थान पर है, कृषि में मूल्य संवर्धन कम रहा है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण के स्तर (डेलॉइट, 2020-21)[64] पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में प्रसंस्करण स्तर फलों के लिए 4.5 प्रतिशत, सब्जियों के लिए 2.7 प्रतिशत, दूध के

63 वार्षिक रिपोर्ट, MoFPI, 2021-22

64 https://tinyurl.com/4fmx4kjs

लिए 21.1 प्रतिशत, मांस के लिए 34.2 प्रतिशत और मत्स्य पालन के लिए 15.4 प्रतिशत है। इसके विपरीत, चीन में पश्चिमी देशों में 60-80 प्रतिशत की तुलना में 30 प्रतिशत भोजन संसाधित किया जाता है (लियू एवं अन्य 2007)।[65]

8.50 **विविध और स्थानीय खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग:** खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के साथ किसानों का बेहतर संबंध बाजार में कृषि उत्पादों का एक अधिक व्यापक और विविध पूल ला सकता है, जिसकी मांग भारत और विदेशों में संपन्नता और आहार-चेतना के साथ बढ़ रही है। इन्वेस्टइंडिया[66] की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण बाजार 2025 तक 535 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 15.2 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ रहा है। टियर-2 और टियर-3 शहर आने वाले वर्षों में अधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का उपभोग करके महानगरीय क्षेत्रों में दिखाई देने वाले रुझान को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। इसके अलावा, कृषि-निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2015 में 13.7 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 25.6 प्रतिशत हो गई है।

8.51 **पूर्व की स्थिति का उधाहरण:** कृषि-प्रसंस्करण के लिए बॉटम-अप दृष्टिकोण का अनुकरण करने के लिए कई सफलता की कहानियां हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री किसान उत्पादक कंपनी (बॉक्स VIII.5 देखें), आंध्र प्रदेश में आदिवासियों द्वारा अराकू कॉफी बागान, महिंद्रा एग्रो द्वारा समर्थित महाराष्ट्र में महाग्रेप्स, और केरल में संश्लेषित मसाला-प्रसंस्करण समूह।

बॉक्स VIII.5: कृषि-प्रसंस्करण में सह्याद्री की सफलता

नासिक, महाराष्ट्र में स्थित एक कृषि-प्रसंस्करण इकाई सह्याद्री किसान उत्पादक कंपनी (एसएफपीसी) इस क्षेत्र में कृषि नवाचार और सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रतीक के रूप में उभरी है। इस उद्योग में 12 से अधिक वर्षों का अनुभव रखते हुए, सह्याद्री ने वित्त वर्ष 23 में 1000 करोड़ का उल्लेखनीय कारोबार को पार किया।[67] प्रभावशाली विकास प्रक्षेपवक्र को मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, कुशल प्रौद्योगिकी और विश्व स्तरीय अवसंरचना के साथ एक किसान-केंद्रित दृष्टिकोण के लिए उत्तरदायी माना जाता है।

सह्याद्री फार्म्स में के प्रतिनिधित्व ने 1300 पूर्णकालिक रोजगार और अतिरिक्त 4000 मौसमी रोजगारों[68] का सृजन किया है, जिससे इस क्षेत्र के रोजगार के अवसरों में योगदान दिया है। 31,000 एकड़ भूमि में फैले अवसंरचना के साथ, एसएफपीसी ताजे अंगूर और टमाटर, आम, मक्का (स्वीट कॉर्न) और काजू जैसे प्रसंस्कृत फलों का भारत का सबसे बड़ा निर्यातक होने का दर्जा रखता है।

एसपीएफसी की नैतिकता का केंद्र छोटे पैमाने के किसानों के लिए अपने अटूट समर्थन में निहित है, जिसमें 95 प्रतिशत से अधिक संबद्ध किसान एक हेक्टेयर से कम भूमि के मालिक हैं।[69] यह न केवल स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देता है बल्कि स्थानीय समुदायों के भीतर आय के स्तर को बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है।

इस क्षेत्र में, एसएफपीसी ने काजू जो एक महत्वपूर्ण फसल है मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक कार्यनीतिक कदम में, नासिक में अपने मोहादी परिसर में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी काजू प्रसंस्करण सुविधा स्थापित की है।[70] यह पहल क्षेत्र में काजू उत्पादन के मूल्य प्रस्ताव में सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अतिरिक्त, सह्याद्री ने अनुमान लगाया है कि यह पहल क्षेत्र में 300 से अधिक महिलाओं के लिए रोजगार की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान होगा।[71]

---

65 लियू, ई., टेलर, डी., और झांग, एस. (2007)। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना खाद्य प्रसंस्करण सामग्री क्षेत्र। ळ।प्छ रिपोर्ट। विदेशी कृषि सेवा, संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग।

66 https://www.investindia.gov.in/siru/indian-food-processing-sector-untapped-growth-opportunity

67 https://www.sahyadrifarms.com/pr-media-products/sahyadri-farms-crosses-the-1-000-crore-turnover-milestone

68 सह्याद्री फार्म्स आधिकारिक वेबसाइट: https://www.sahyadrifarms.com/

69 प्रोपार्को ग्रुप की रिपोर्ट: https://www.proparco.fr/en/actualites/grand-angle/report-india-sahyadri-farms-vines-are-joint-initiative

70 https://agrospectrumindia.com/2023/08/20/nashik-based-fpc-sahyadri-farms-kicks-off-the-biggest-cashew-processing-plant.html

71 भोसले, जे., 18 अगस्त 2023, इकनॉमिक टाइम्स, "अग्रणी अंगूर निर्यातक सह्याद्री एफपीओ काजू प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रवेश करता है", https://tinyurl.com/wd344p4x

8.52 **कृषि-संसाधित उत्पादन की नियत मांग के लिए अवसरः** स्थानीय इकाइयां स्कूलों में आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन की आपूर्ति कर सकती हैं, जबकि यह समूह (अग्लामरैशन) शहरी उपभोक्ताओं को बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और श्वोकल फॉर लोकल के प्रतिश भावना प्रदान कर सकते हैं। विशेष उत्पादों को निर्यात आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ा जा सकता है, और ऐसे सभी उत्पादों को सूचीबद्ध करने वाले एक राष्ट्रीय पोर्टल को ई-कॉमर्स संस्थाओं से जोड़ा जा सकता है।

8.53 **कई मौजूदा कार्यक्रमों का संमिलनः** श्रम, लॉजिस्टिक्स, क्रेडिट और विपणन के लिए मेगा फूड पार्क, स्किल इंडिया, मुद्रा, एक जिला-एक उत्पाद आदि के बीच तालमेल का उपयोग करने से इस क्षेत्र को लाभ हो सकता है। इस तरह के प्रयासों के संमिलन से ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला प्रशासन को शामिल करने वाले पूरे सरकारी दृष्टिकोण से अत्यधिक लाभ होगा। नाबार्ड, केंद्रीय भण्डारण निगम, कृषि विज्ञान केंद्र आदि जैसे संगठनों को उनकी विशेषज्ञता और अवसंरचना को देखते हुए, त्वरित हैंडहोल्डिंग और समस्या निवारण के लिए शामिल किया जा सकता है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह ब्लॉक- या पंचायत स्तर की योजनाओं को तैयार करने और लागू करने में, उनकी विश्वसनीयता, अच्छे पुनर्भुगतान रिकॉर्ड और खेती में महिलाओं के लिए बढ़ती प्रासंगिकता को देखते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

8.54 इस प्रकार, कृषि की दृष्टि से प्रदत्त देश होने के नाते भारत अपने विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित उत्पादों की श्रेणी का उपयोग कर सकता है और उत्पादक रूप से बड़ी संख्या में ग्रामीण कार्यबल को रोजगार दे सकता है, जिसमें ऐसी महिलाएं शामिल हैं जो लाभकारी अंशकालिक रोजगार चाहती हैं और शिक्षित युवा जो छोटे से मध्यम स्तर के कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों को संभालने के लिए तकनीकी रूप से कुशल हो सकते हैं।

विकास के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करनाः भारत में सुविकसित केयर अर्थव्यवस्था की आवश्यकता और संभावनाएं

8.55 केयर अर्थव्यवस्था अब तक आर्थिक विकास और कल्याण के लिए कम ज्ञात है, फिर भी संभावित रूप से महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से भारत जैसे युवा देश के लिए, जिसके पास लाभ उठाने के लिए जनसांख्यिकीय और जेंडर दोनों तरह के लाभांश हैं। एक केयर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की परस्पर संबद्ध गतिशीलता लैंगिक इक्विटी, मानव विकास और आर्थिक विकास में योगदान देती है। एक गुणवत्ता और विश्वसनीय केयर क्षेत्र का विकास इस प्रकार मानव संसाधनों के सर्वोत्तम आवंटन को सुविधाजनक बनाने में एक महत्वपूर्ण दक्षता अंतराल को भर सकता है, जो जेंडर द्वारा निर्धारित के बजाय तुलनात्मक लाभ और चयन से प्रेरित होता है। यह उप-खंड केयर को प्राथमिकता देने के दीर्घकालिक लाभों की रूपरेखा की जांच करता है और इस क्षेत्र को और विकसित करने के लिए कुछ समाधान प्रस्तावित करता है।

केयर कार्य को परिभाषित करना - केयर को 'काम' के रूप में स्वीकार करने का पहला कदम

8.56 आईएलओ के अनुसार, देखभाल संबंधी कार्य में वयस्कों और बच्चों, वृद्ध और युवा, कमजोर और सक्षम शरीर की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने में शामिल कार्यकलापों और संबंध स्थापना शामिल हैं। देखभाल संबंधी कार्य की श्रेणियां हैं: मुआवजा और अवैतनिक / देखभाल करने और सामाजिक सहायता प्रदान करने से संबंधित अवैतनिक या कम भुगतान वाले काम अक्सर महिलाओं द्वारा घरों के भीतर किए जाते हैं और आमतौर पर इसमें बाल-देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, घरेलू काम आदि शामिल होते हैं। वैतनिक देखभाल कार्य में पारिश्रमिक के लिए नर्सों, देखभाल करने वालों आदि द्वारा किया जाने वाला श्रम शामिल है।

सुविकसित केयर अर्थव्यवस्था की बढ़ती आवश्यकता

जनसांख्यिकीय परिगमन – बढ़ती उम्र में व्यक्तियों की आबादी की भविष्य की केयर आवश्यकताओं के लिए तैयार करने की आवश्यकता है

8.57 अगले 25 वर्षों में भारत की देखभाल संबंधी कार्य की जरूरतों में काफी विस्तार होने की संभावना है, क्योंकि बढ़ती उम्र की आबादी चल रहे जनसांख्यिकीय परिगमन का अनुसरण करती है जबकि बच्चों की आबादी अपेक्षाकृत

अधिक रहती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए)[72] के अनुसार वर्ष 2022 तक भारत की एक-चौथाई जनसंख्या 0-14 वर्ष (अर्थात 36 करोड़ व्यक्ति) की आयु के है, जबकि दसवां भाग 60 वर्ष से अधिक आयु का है (यानी, 14.7 करोड़ व्यक्ति)। वर्ष 2050 तक, बच्चों का हिस्सा घटकर 18 प्रतिशत (यानी, 30 करोड़ व्यक्ति) होने का अनुमान है, जबकि बुजुर्गों का अनुपात 20.8 प्रतिशत (यानी 34.7 करोड़ व्यक्ति) तक बढ़ जाएगा। इस प्रकार, वर्ष 2022 में 50.7 करोड़ व्यक्तियों की तुलना में, देश को 2050 में 64.7 करोड़ व्यक्तियों की देखभाल संबंधी कार्य करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि अधिक महिलाएं वैतनिक काम में भाग लेने, एकल परिवारों की बढ़ती व्यापकता, आदि के कारण देखभाल के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को और बढ़ाया जाएगा।[73]

महिलाओं के लिए समान अवसर - जेंडर और अवैतनिक देखभाल संबंधी कार्य को अलग करना

8.58 एक उचित केयर अर्थव्यवस्था विकसित करना महत्वपूर्ण है जब भुगतान किए गए कार्य में भाग लेने के समान अवसर प्रदान करके एफएलएफपीआर को बढ़ाने की निष्पक्षता और दक्षता की दृष्टि के माध्यम से देखा जाता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि घरेलू काम, बाल-देखभाल और बुजुर्गों की देखभाल सहित अवैतनिक देखभाल संबंधी कार्य के काम का प्रमुख बोझ महिलाओं पर पड़ता है, जो तब रोजगार के अवसरों में पूरी तरह से भाग लेने के लिए 'समय-की कमी' होती हैं। यह एक वैश्विक परिघटना है, जो भारत के लिए भी लागू होती है। महिलाओं पर देखभाल संबंधी कार्य का अनुपातहीन बोझ भारत सहित दुनिया भर में कम एफएलएफपीआर के परिणामस्वरूप है।[74] सिन्हा एवं अन्य (2024) के अनुसार, प्रति दिन देखभाल संबंधी कार्य करने का एक अतिरिक्त घंटा महिलाओं की श्रम बाजार भागीदारी को 20 प्रतिशत अंक कम कर देता है, जिसका पुरुषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।[75]

8.59 एनएसओ के टाइम यूज स्टैटिस्टिक्स फॉर 2019 के अनुसार, भारत में कामकाजी उम्र की महिलाएं प्रति दिन 5.6 घंटे अवैतनिक कार्यों पर खर्च करती हैं, जबकि पुरुषों द्वारा प्रति दिन केवल 30 मिनट खर्च किए जाते हैं। यहां तक कि वैतनिक रोजगार में महिलाएं वैतनिक रोजगार में पुरुषों की तुलना में अवैतनिक देखभाल संबंधी कार्य पर लगभग 6 गुना समय खर्च करती हैं, जो वैतनिक काम और अवैतनिक देखभाल जिम्मेदारियों दोनों को करने के 'दोहरे बोझ' में परिणत होती है। भारत में उच्च शिक्षा नामांकन में जेंडर अंतर के समापन के साथ देखभाल के कारण हुई असमानता शिक्षा में अवसर की बढ़ती समानता के विपरीत है।

8.60 विशेष रूप से, प्रसव और बाल-देखभाल के प्रभाव को महिलाओं के करियर पर एक महत्वपूर्ण कीमत पाई जाती है, जिसे 'मातृत्व दंड' कहा जाता है, जिसे प्रसव के वर्षों के आसपास एफएलएफपीआर में गिरावट और आय की हानि के रूप में दर्शाया गया है। रोजगार की गुणवत्ता के संबंध में, मातृत्व दंड महिलाओं में खेती और अनौपचारिक नौकरियों में केंद्रित होने के लिए प्रकट होता है, क्योंकि वे कार्यक्षेत्र उनकी व्यक्तिगत देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों (पलरीवाला और नीथा (2012)) के अनुकूल हैं।[76] भले ही शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रति दिन अवैतनिक देखभाल संबंधी कार्य पर बिताया गया समय केवल 9 मिनट अधिक है, उच्च ग्रामीण एफएलएफपीआर को रोजगार के समय और निकटता के संदर्भ में लचीलेपन द्वारा समझाया जा सकता है, जो बाल पर्यवेक्षण की अनुमति देता है, जो ग्रामीण नौकरियां आमतौर पर प्रदान करती हैं (गौतम 2022)।[77]

---

72 अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, "भारत एजिंग रिपोर्ट 2023", https://india.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/20230926_india_ageing_report_2023_web_version_.pdf

73 उपभोक्ता सर्वेक्षण कंपनी कांतार के आंकड़ों के अनुसार, 2008 में कुल परिवारों में एकल परिवारों की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में कुल परिवारों में 50 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।

74 एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी)। (2022)। महिला श्रम बल भागीदारी और देखभाल। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अर्थव्यवस्था।

75 सिन्हा, ए.; सेदाई, ए.के.; राहुत, डी.बी., सोनोबे, टी. (2024)। अवैतनिक देखभाल की कल्याण लागत: भारत में एक प्रासंगिक समय-उपयोग सर्वेक्षण से लिंग आधारित साक्ष्य। विश्व विकास, 173, आईएसएसएन 0305&750X, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106419

76 पलरीवाला, आर. और नीता, एन. 2012. श्राज्य, बाजार और परिवार के बीच: भारत में देखभाल की संरचनाएँ, नीतियाँ और अभ्यासश, एस. रजावी और एस. स्टाब (संपादक), 'देखभाल की राजनीतिक और सामाजिक अर्थव्यवस्था में वैश्विक विविधताएँ: अलग-अलग दुनियाएँ' (पृष्ठ 176-197),

77 यूएनआरआईएसडी यूके: रूटलेज।

गौतम, एल. 2022. ष्इट टेक्स अ विलेज: चाइल्डकैअर एंड वीमेन्स पेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया,ष पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट रिव्यू, द पॉपुलेशन काउंसिल, इंक., खंड 48(3), पृष्ठ 795-828, सितंबर। https://ideas.repec.org/a/bla/popdev/v48y2022i3p795-828.html

आर्थिक क्षमता - मानव पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग करके मूल्य सृजन

8.61 महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह अवैतनिक/अदृश्य घरेलू काम, जिसे आमतौर पर श्रम शक्ति और सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय नजरअंदाज कर दिया जाता है, को विभिन्न तरीकों से अत्यधिक मूल्यवान लेकिन अदृश्य माना गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की एक हालिया रिपोर्ट भारत में महिलाओं के अवैतनिक घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों के आर्थिक मूल्य का अनुमान लगाने के लिए एक मानकीकृत इनपुट-मूल्य पद्धति का उपयोग करती है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 15-17 प्रतिशत है।[78]

8.62 केयर क्षेत्र विकसित करने का आर्थिक मूल्य दो गुना है - एफएलएफपीआर (जिस पर पहले चर्चा की गई थी) को बढ़ाना और आउटपुट एवं रोजगार सृजन के लिए एक आशाजनक क्षेत्र को बढ़ावा देना। आईएलओ (2018) के अनुसार, केयर क्षेत्र वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है, और केयर सेवा क्षेत्र में निवेश से वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर 475 मिलियन रोजगार पैदा होने का अनुमान है। भारत के मामले में, सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत के बराबर प्रत्यक्ष सार्वजनिक निवेश से 11 मिलियन रोजगार सृजन होने की संभावना है, जिनमें से लगभग 70 प्रतिशत महिलाओं को मिलेंगी।[79]

क्रेच का बहुआयामी प्रभाव - अनुभवजन्य साक्ष्य

8.63 कई तरह के शोधों ने इस बात पर जोर दिया है कि किफायती और भरोसेमंद बाल-देखभाल का महिलाओं के लिए वैतनिक रोजगार के लिए समय निकालने, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और बच्चों की शिक्षा और पोषण में सुधार लाने पर असर पड़ता है। हालाँकि, शोध सामग्री मुख्य रूप से विदेशी है और भारत पर किए गए अनुभवजन्य अध्ययन दुर्लभ हैं।

चार्ट VIII.27: बाल देखभाल व्यवस्था की कमी का प्रभाव: एक वैचारिक मॉडल

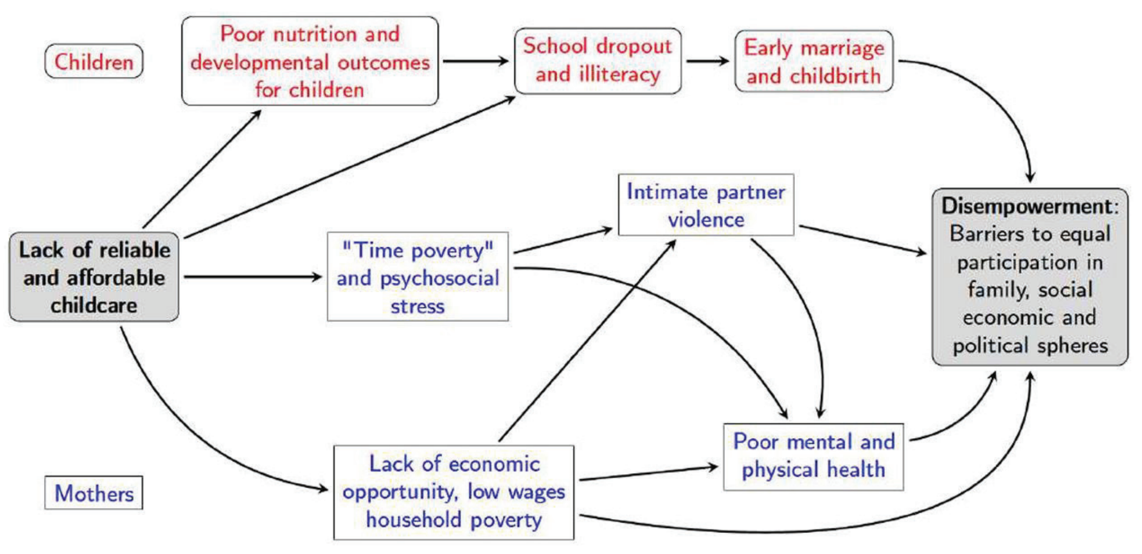

स्रोतः नंदी एट अल. (2020)

78 भारत की देखभाल अर्थव्यवस्था के लिए रणनीति तैयार करना: अवसरों को खोलना, मार्च 2024, सीआईआई, https://tinyurl.com/4y4eh462 पर उपलब्ध है

79 सभ्य कार्य के भविष्य के लिए देखभाल कार्य और देखभाल नौकरियां, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 2018, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf.

8.64 उदाहरण के लिए, मेक्सिको में सार्वजनिक बाल देखभाल सेवाओं की उपलब्धता आपूर्ति-पक्ष और मांग-पक्ष प्रोत्साहनों के माध्यम से - जैसे कि कम आय वाली महिलाओं को सब्सिडी और बाल देखभाल सुविधाओं के लिए अनुदान - ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी पर दोहरा प्रभाव डाला। सबसे पहले, कम आय वाली माताओं को सवेतन रोजगार खोजने में सहायता मिली। दूसरा, इस पहल से देखभाल करने वालों और उनके सहायकों के लिए लगभग 45,000 सवेतन पद का सृजन हुआ - जिनमें से अधिकांश महिलाएँ थीं (ओईसीडी 2012)[80]

8.65 ब्राजील में, कम आय वाले इलाकों में रहने वाले 0-3 वर्ष की आयु के बच्चे रियो डी जेनेरो पब्लिक डे केयर कार्यक्रम के माध्यम से एकीकृत सामाजिक, स्वास्थ्य और शैक्षिक सेवाओं तक पहुँच सकते हैं। बैरोस एट अल. (2011) के अनुसार, महिला रोजगार में 27 प्रतिशत तक उल्लेखनीय रूप वृद्धि हुई है, और इस कार्यक्रम पहुँच के परिणामस्वरूप बहुत अधिक उपयोग दर हुई है।[81] जबकि चाइल्डकेयर तक पहुँच के प्रभाव पर भारत-विशिष्ट शोध बहुत सीमित है, भारत में स्थिति की जाँच करने वाले कुछ अध्ययन नीचे प्रस्तुत किए गए हैं।

8.66 मोबाइल क्रेच एनजीओ द्वारा दिसंबर 2021-फरवरी 2022 में 4 राज्यों (गुजरात, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक)[82] में किए गए एक गुणात्मक अध्ययन के अनुसार, क्रेच का लाभ उठाने वाली 61 प्रतिशत कार्यरत महिलाएँ एनजीओ पर निर्भर थीं, जबकि सरकारी क्रेच का हिस्सा अपेक्षाकृत छोटा (21 प्रतिशत) था। क्रेच का लाभ न उठाने वाली कार्यरत महिलाएँ मुख्य रूप से वयस्क परिवार के सदस्यों (41 प्रतिशत) और बड़ी बेटियों (11 प्रतिशत) पर निर्भर थीं। अध्ययन में पाया गया कि गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधाओं का महिलाओं की भलाई, आय, बच्चे की भलाई और परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

8.67 सेवा बाल देखभाल केन्द्रों[83] पर किए गए अध्ययन से पता चला है कि लाभार्थी महिलाएं दिन में अधिक घंटे तथा महीने में अधिक दिन काम कर सकती हैं, जिससे उनकी आय और बचत में वृद्धि होगी।

8.68 राजस्थान में स्थानीय एनजीओ द्वारा संचालित क्रेच या बालवाड़ियों के हाल ही में किए गए यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण के अनुसार, डे केयर की पेशकश की गई लगभग आधी महिलाओं ने इसका उपयोग किया। क्रेच ने कुपोषण को कम करने, तनाव को कम करने और माताओं की स्वयं-रिपोर्ट की गई खुशी को बढ़ाने में मदद की (नंदी एट अल.)[84]

सरकारी कार्यक्रमः क्रेच के लिए पालना योजना का नवीनीकरण

8.69 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पालना योजना के तहत आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पहल में संशोधन किया गया और इसे अप्रैल 2022 में मिशन शक्ति में शामिल किया गया। इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में मौजूद उस अंतर को दूर करना है, जहाँ परिवार के सदस्यों से बच्चों की देखभाल के लिए सहायता उपलब्ध नहीं है, और अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को सुविधाजनक बनाने के लिए संस्थागत समर्थन की आवश्यकता है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के तहत 17,000 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच स्थापित करना है, जिनमें से दिसंबर 2023[85] तक 5222 को मंजूरी दे दी गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक कवरेज से इस योजना को काफी लाभ मिल सकता है।

---

80 ओईसीडी। 2012. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। लैंगिक समानता पर ओईसीडी डीएसी नेटवर्क (जेनडरनेट) (पेरिस)

81 महिलाओं के क्रेच की आवश्यकता, 2022 रीता मिश्रा, निरूपमा सारथी, नैनी राव: मोबाईल क्रेच https://ecdan.org/wp-content/uploads/2022/10/MC_WomenNeedCreches_Final-Study-Report_2022.pdf

82 महिलाओं को क्रेच की जरूरत है, 2021; रीता मिश्रा, निरुपमा सारथी, नैनी राव; मोबाइल क्रेच, https://ecdan.org/wp-content/uploads/2022/10/MC_WomenNeedCreches_Final-Study-Report_2022.pdf

83 एसोसिएशन फॉर स्टिमुलेटिंग नॉलेज हाउ(2011), "सेवा चाइल्ड्केयर: वर्ष 2011 के लिए प्रभाव आकलन रिपोर्ट'। गुड़गाँव: भारत

84 नंदी, अरिजीत, पारुल अग्रवाल, अनुष्का चंद्रशेखर और सैम हार्पर। 2020. 'किफायती डेकेयर तक पहुंच और महिलाओं को आर्थिक अवसर: भारत में क्लस्टर-रैंडमाइज्ड हस्तक्षेप से साक्ष्य।' जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इफेक्टिवनेस 12, नंबर 3: 219-239।

85 पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 22 दिसंबर 2023https://tinyurl.com/yknf7u6d

भारत में वरिष्ठ देखभाल सुधारः वरिष्ठ देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना

8.70 भारत 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन साथ ही उसकी उम्र भी बढ़ती जाएगी। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की 'एजिंग वेल इन एशिया' रिपोर्ट[86] के अनुसार, वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात 2022 में 20 प्रतिशत से कम से बढ़कर 2050 तक 30 प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद है। बढ़ती उम्रदराज आबादी से जुड़ी देखभाल की जिम्मेदारी के लिए भविष्य के लिए तैयार बुजुर्ग देखभाल नीति विकसित करने के लिए वरिष्ठ देखभाल के बारे में शुरुआती बातचीत शुरू करना जरूरी है।

वृद्धों की देखभाल की बढ़ती आवश्यकता

8.71 यूएनएफपीए और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज द्वारा इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023[87] में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि बुजुर्ग आबादी का एक बड़ा हिस्सा पुरानी बीमारियों, कार्यात्मक सीमाओं, अवसादग्रस्त लक्षणों और कम जीवन संतुष्टि से पीड़ित है। चूंकि बुजुर्ग आबादी में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है और वे ग्रामीण इलाकों में रहती हैं, इसलिए बुजुर्गों का स्त्रीकरण और ग्रामीणीकरण गरीबी, निर्भरता और अकेलेपन से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट की सिफारिशें इस प्रकार हैं।

- साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और भारत की जनगणना में प्रासंगिक प्रश्नों को शामिल करना है।
- वृद्ध व्यक्तियों के लिए मौजूदा योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सभी वृद्धाश्रमों को नियामक दायरे में लाना, तथा वृद्ध स्वयं सहायता समूहों के निर्माण और संचालन को प्रोत्साहित करना।
- बहु-पीढ़ी वाले घरों में रहने वाले बुजुर्ग लोगों के महत्व पर जोर देना। ऐसी नीतियों को प्रोत्साहित करना जो इसमें रहने की व्यवस्था को सुविधाजनक और समर्थन प्रदान करें।
- क्रेच या डे-केयर सुविधाओं जैसी अल्पकालिक देखभाल सुविधाएं बनाकर यथासंभव घर पर ही वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करना।

बुजुर्गों की देखभाल के लिए एक समग्र नीति की आवश्यकता

8.72 नीति आयोग[88] द्वारा वरिष्ठ देखभाल सुधारों पर हाल ही में जारी किए गए स्थिति पत्र के अनुसार, वर्तमान में बुजुर्गों की देखभाल उद्योग 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (57,881 करोड़) होने का अनुमान है, फिर भी बुजुर्गों की बीमारी के प्रबंधन, निगरानी तंत्र और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों के लिए बुनियादी ढांचे, शोध और जानकारी में गंभीर अंतराल बने हुए हैं। इसलिए, भारत को एक संरचित बुजुर्ग देखभाल नीति ढांचे की आवश्यकता है।

8.73 एडीबी रिपोर्ट[89] के अनुसार, वृद्ध लोगों की कार्य क्षमता एक बड़ा आर्थिक संसाधन है। 60-69 वर्ष की आयु की आबादी की अप्रयुक्त कार्य क्षमता के इस 'सिल्वर डिविडेंड' का उपयोग करने से एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए जीडीपी में औसतन 1.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में उम्र के अनुकूल नौकरियों की वकालत की गई है, जिसमें जीवन भर सीखने और कौशल विकास को शामिल करते हुए धीरे-धीरे काम से सेवानिवृत्ति तक का मार्ग अपनाया जाता है। देखभाल के दृष्टिकोण से, वृद्ध आबादी के लिए उपयुक्त नौकरी की भूमिकाएँ सामाजिक जुड़ाव,

---

86 एजिंग वैल ईन एशिया, एडीबी नीति रिपोर्ट, मई 2024। रिपोर्ट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम; अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान; हार्वर्ड टी. एच. चौन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ; और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा भारत में अनुदैर्ध्य वृद्धावस्था अध्ययन (एलएएसआई) 2017-19 का उपयोग किया गया है; https://www.adb.org/publications/asian-development-policy-report-2024

87 https://tinyurl.com/5n8rdehz ij miyC/ gSA

88 नीति आयोग का पेपर षसिनियर केयर रिफॉर्म इन इंडिया- रिंइमेजिंग द सिनियर केयर पेरडाइल-ए पोजिशन पेपर फरवरी, 2024

89 पूर्वोक्त नोट 70

वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं, साथ ही समग्र देखभाल की आवश्यकता को कम कर सकती हैं। बॉक्स VIII.6 देश में देखभाल अर्थव्यवस्था पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर कुछ सुझाव प्रस्तुत करता है।

बॉक्स VIII.6: बेहतर देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण

देखभाल अर्थव्यवस्था की ठोस संरचना बनाने के लिए रणनीतिक सुधारों की आवश्यकता है। इसमें सुधार निम्नलिखित दिशा में हो सकते हैं: (i) माता-पिता की छुट्टी नीतियों के लिए समर्थन; (ii) देखभाल सेवाओं के लिए सब्सिडी; (iii) देखभाल के अवसंरचना के निर्माण में सार्वजनिक और निजी निवेश; (iv) देखभाल श्रमिकों के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए तंत्र; और (v) सेवा की गुणवत्ता और बेंचमार्क की निगरानी के लिए तंत्र; देखभाल और घरेलू काम में लैंगिक असमानताओं को दूर करने और महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। इनमें कुछ विशिष्ट नीतिगत हस्तक्षेप हो सकते हैं:

- देखभाल सेवाओं के लिए सेक्टर कौशल परिषद की स्थापना की जा सकती है ताकि देखभाल क्षेत्र के लिए कौशल प्रशिक्षण ढांचा विकसित करने, कौशल मॉड्यूल तैयार करने और अंतरराष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी करने में मदद मिल सके। एक समर्पित देखभाल क्षेत्र कौशल परिषद की आवश्यकता है।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) देखभाल की अवसंरचना, विशेष रूप से बाल देखभाल और बुजुर्गों के लिए संस्थानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कार्यालयों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में मोबाइल क्रेच में निवेश करने के लिए नीतियां बनाई जा सकती हैं, जिससे महिलाओं को वेतनभोगी रोजगार के अवसर लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- सार्वजनिक रूप से संचालित या निजी तौर पर संचालित सुविधाओं में देखभाल सेवाओं के प्रावधान के लिए संस्थागत निगरानी और निरंतर निगरानी की आवश्यकता होगी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अवसंरचना का रखरखाव अच्छी तरह से किया जाता है और देखभाल सेवाएँ संतोषजनक हैं। कुछ देशों में, देखभाल सुविधाओं में अवसंरचना और सेवा प्रावधान के परिभाषित न्यूनतम मानकों को बनाए रखने के लिए औपचारिक नियामक तंत्र हैं।[90]
- समुदाय-आधारित और नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) के साथ सहयोग से सिस्टम को जमीनी स्तर की वास्तविकता से परिचित कराया जा सकता है और देखभाल के अवसंरचना और वित्तीय बाधाओं के साथ परिचालन संबंधी मुद्दों को हल करने में मदद मिल सकती है।
- देखभाल सेवाओं को सब्सिडी देने पर विचार किया जा सकता है। इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील और यूएसए के सफल अंतरराष्ट्रीय मॉडल भारत के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। ये देश देखभाल करने वाले कर्मचारियों को उनकी आय, बच्चे की आयु, संतानों की संख्या आदि के आधार पर वाउचर और कर छूट के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
- स्वयं सहायता समूहों की उद्यमशीलता की मजबूत भावना के कारण, स्व-प्रबंधित संस्थानों के मॉडल, उदाहरण के लिए, बिहार में जीविका, का पालन किया जा सकता है, ताकि देखभाल करने वाले कर्मचारियों के लिए एक समर्पित बाल देखभाल सेवा कार्यक्रम और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान किया जा सके।
- अनौपचारिक श्रमिकों की सस्ती बाल देखभाल की अव्यक्त मांग को पूरा करने के लिए क्रेच के बारे में जागरूकता पैदा करना।

90 उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम में, शिक्षा, बाल सेवा और कौशल मानकों का कार्यालय (ओएफएसटीईडी) बच्चों और युवाओं के लिए देखभाल सेवाओं का निरीक्षण और विनियमन करता है। इसी तरह, भारत में भी देखभाल सेवा प्रावधान की गुणवत्ता आश्वासन के लिए संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है।

- सामुदायिक समूहों और स्थानीय निर्णयकर्ताओं के साथ जमीनी स्तर पर काम करने से गुणवत्ता और स्थिरता के लिए प्रासंगिक प्रबंधन नवाचार सामने आएंगे।
- अभिनव व्यवसाय मॉडल विकसित करना – स्टार्ट-अप इंडिया का उपयोग अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए बाल देखभाल सहायता को पायलट और बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक और समुदाय-आधारित मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है।
- क्रेच और बुजुर्ग घरों की रेटिंग प्रणाली – यूके के ओएफएसटीईडी (शिक्षा, बच्चों की सेवाओं और कौशल में मानकों के लिए कार्यालय) की तर्ज पर है।

8.74 गैर-सरकारी क्षेत्र ने बुजुर्गों की देखभाल प्रदान प्रदान करने वालों की बढ़ती जरूरत के लिए नवाचार समाधान विकसित किए हैं। टाटा द्वारा वित्तपोषित स्टार्ट-अप गुडफेलो[91] एक अग्रणी पहल है जो अकेलेपन की चुनौती से निपटने का प्रयास कर रही है, जिसे एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या कहा गया है जो व्यक्तियों को मनोभ्रंश और मानसिक गिरावट के अधिक जोखिम में डालती है।[92] यह स्टार्ट-अप भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति रखने वाले युवा लोगों को 'ग्रैंडपाल' कहकर काम पर रखता है ताकि वे संगति की चाह रखने वाले अकेले वरिष्ठ नागरिकों से बातचीत कर सकें। यह पारस्परिक लाभ के साथ बहु-पीढ़ी संचार और समझ को मजबूत करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है।

8.75 देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को साकार करने के अन्य प्रेरक उदाहरणों में वेदांता की नई माताओं के लिए 12 महीने की छुट्टी और वेदांता लिमिटेड द्वारा मातृत्व अवकाश के बाद लचीले काम के घंटे की व्यापक पेरेंटहुड नीति, और सेवा के संगिनी मॉडल के तहत अनौपचारिक महिला श्रमिकों के छह साल की उम्र तक के 3639 बच्चों को पूर्णकालिक शिशू-देखभाल का प्रावधान शामिल है।[93] अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, स्वीडिश सरकार द्वारा नीतिगत उप-लक्ष्य के रूप में 'अवैतनिक घरेलू काम और देखभाल के काम के समान वितरण' को मान्यता देना प्रेरणादायक है। अपने देश में, हरियाणा की हालिया क्रेच नीति भारतीय राज्यों में अग्रणी होने के लिए उल्लेखनीय है, जिसके अनुसार कामकाजी महिलाएं अपने छह महीने से छह साल की उम्र के बच्चे को आठ से दस घंटे तक क्रेच में रख सकती हैं, जहाँ कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात होंगे।[94]

8.76 संक्षेप में, देखभाल अर्थव्यवस्था 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत की टू-डू सूची में शीर्ष-स्तरीय प्रविष्टि है। देखभाल के अवसंरचना एवं सेवाओं की उपलब्धता न केवल महिलाओं की समय की गरीबी को कम करती है और एफएलएफपीआर को बढ़ाती है, बल्कि देखभाल के अवसंरचना और सेवाओं का प्रावधान एक स्वतंत्र व्यवसाय के अवसर के रूप में भी कार्य करता है, जो विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाली उद्यमिता और महिलाओं के रोजगार के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार देखभाल क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए एक विशाल क्षमता प्रदान करता है। जबकि माता-पिता की जिम्मेदारियों को लिंग-तटस्थ साझा करने की ओर दृष्टिकोण में बदलाव धीरे-धीरे होगा, इस बदलाव को नीतियां बढ़ा सकती हैं। इसके लिए सस्ती देखभाल सेवाओं का एक निष्पक्ष, कुशल और प्रासंगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता है। आधी सदी से भी अधिक समय से छोटे पैमाने की देखभाल मॉडल (जैसे मोबाइल क्रेच[95]) का प्रचलन बताता है कि यह संभव है।

91 https://www.thegoodfellows.in

92 मुश्ताक आर, शोएब एस, शाह टी, मुश्ताक एस. अकेलेपन, मानसिक विकारों और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संबंध अकेलेपन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर एक समीक्षा। जे क्लिन डायग्नोसिस रिसर्च। 2014 सितंबर;8(9):WE01-4।

93 मुश्ताक आर, शोएब एस, शाह टी, मुश्ताक एस. अकेलेपन, मानसिक विकारों और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संबंध अकेलेपन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर एक समीक्षा। जे क्लिन डायग्नोसिस रिसर्च। 2014 सितंबर;8(9):WE01-4।

94 अधिसूचना-हरियाणा राज्य क्रेच नीति 2022 | महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा | भारत (wcdhry.gov.in)

95 https://www.mobilecreches.org/

कौशल निर्माण में विकास और प्रगति

8.77 जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त करने के लिए, हमारे कार्यबल को रोजगार योग्य कौशल और ज्ञान से लैस करना आवश्यक है जो वैश्विक श्रम बाजार और उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। भारत के युवाओं की आकांक्षाओं और क्षमताओं के अनुरूप नौकरी और उद्यमशीलता के अवसरों को सक्षम करके भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को उत्पादकता लाभांश में बदलने के लिए सरकार द्वारा उपाय किए जा रहे हैं। यह रोजगार के साथ कौशल बढ़ाने के लिए उद्योग के साथ साझेदारी कर रहा है (बॉक्स VIII.7 देखें)।

8.78 वर्ष 2017-18 से 2022-23 की अवधि में, ग्रामीण, शहरी और लिंग वर्गीकरण सहित सभी सामाजिक-आर्थिक वर्गीकरणों में कुशल लोगों के अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जैसा कि नीचे चार्ट में दर्शाया गया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, 15-29 वर्ष की आयु वर्ग के 4.4 प्रतिशत युवाओं ने औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि अन्य 16.6 प्रतिशत ने अनौपचारिक स्रोतों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

चार्ट VIII.28: औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 15-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के प्रतिशत में वृद्धि

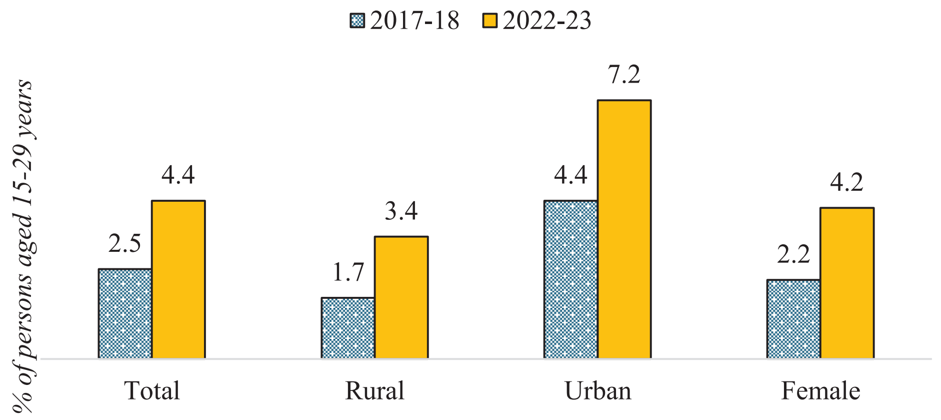

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 2022-23, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, एनएसओ

चार्ट VIII.29: विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत

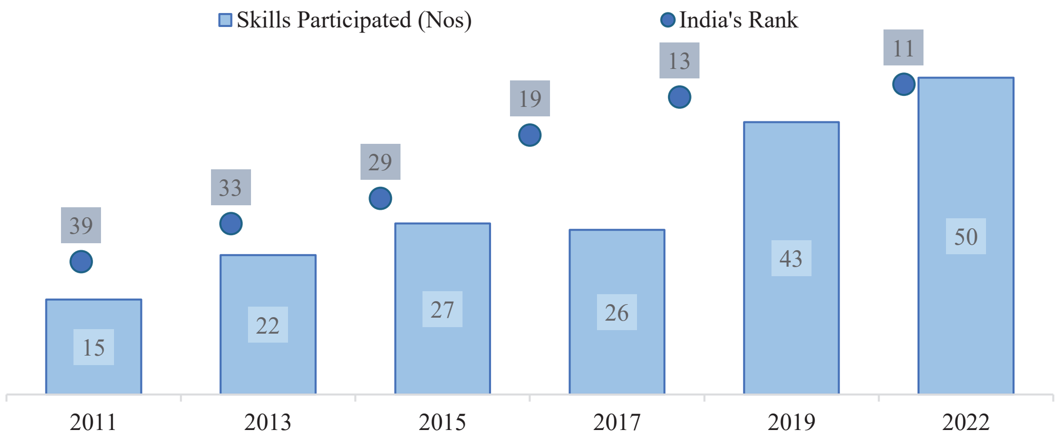

स्रोत: एमएसडीई वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

8.79 कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से हाल ही में शुरू किए गए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म[96] ने भारत में 'कौशल प्राप्त करने में आसानी' की दिशा में एक और कदम उठाया

96 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1957139

है। सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास से गुजरने वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि ने 'कौशल भारत' पर जोर दिया है, जैसा कि तालिका VIII.2 में दर्शाया गया है। कौशल विकास में व्यापक प्रगति हर दो वर्ष[97] में आयोजित होने वाली विश्व कौशल प्रतियोगिताओं में भारत की बढ़ती स्थिति में प्रकट हुई है।

कौशल विकास के लिए विभिन्न योजनाएं

8.80 कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं में प्रगति का विवरण नीचे[98] दिया गया है। बॉक्स VIII.7 में कौशल कार्यक्रमों में उद्योग की भागीदारी के संवर्धन का विस्तार किया गया है।

तालिका VIII.2: कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रगति

एमएसडीई के तहत योजनाएं	समग्र प्रगति
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) *निः शुल्क लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन*	वर्ष 2015 में योजना की शुरुआत के बाद से, 1,42,67,888 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है, और 1,13,72,668 व्यक्तियों को इसके अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी), विशेष परियोजनाओं (एसपी) और पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) घटकों के तहत प्रमाणित किया गया है। ● अधिक प्रासंगिकता और उद्योग कनेक्ट के लिए किए गए सुधार ● अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण का अनिवार्य समावेश ● देश भर में 1,000+ शैक्षणिक संस्थानों को स्किल इंडिया सेंटर के रूप में शामिल किया गया है। ● आठ क्षेत्रों में 119 नए युग और भविष्य के कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए गए। ● स्थायी व्यावसायिक अवसंरचना के बिना संस्थाओं को प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र से समाप्त कर दिया गया था। ● सभी योग्यताओं में 'रोजगार कौशल' को शामिल करना। ● पीएमकेवीवाई के तहत, प्रशिक्षित लोगों में महिलाओं की भागीदारी वर्ष16 में 42.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 24 में 52.3 प्रतिशत हो गई है।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना *14,955 आईटीआई के नेटवर्क के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण*	● वर्ष 2014 और 2023 के बीच दीर्घकालिक प्रशिक्षण में नामांकित 1.24 लाख व्यक्ति ● दीर्घकालिक कौशल के क्षेत्र में, अर्थात आईटीआई और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में, महिलाओं की भागीदारी वित्त वर्ष 16 में 9.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 13.3 प्रतिशत हो गई है। आईटीआई के लिए नई ग्रेडिंग व्यवस्था ● सत्र 2023-24 से लागू एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर उपलब्ध पैरामीटर/जानकारी का उपयोग करते हुए डेटा-संचालित ग्रेडिंग पद्धति (डीडीजीएम)
जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) गैर/नव साक्षरों और अल्पविकसित स्तर की शिक्षा वाले व्यक्तियों में कौशल विकास के लिए	● वित्त वर्ष 19 से वित्त वर्ष 24 तक, 26,36,769 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है, और 24,94,807 व्यक्तियों को प्रमाणित किया गया है। जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) का क्षमता निर्माण ● प्रयोगशालाओं को नए जमाने के उपकरणों के साथ उन्नत करके 30 मॉडल जेएसएस की स्थापना, 150 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण ● प्रबंधन, संचार कौशल आदि में कर्मचारियों की क्षमता निर्माण। ● जेएसएस के तहत, महिलाएं कुल लाभार्थियों का लगभग 82 प्रतिशत थीं।

97 वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता, वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो हर दो साल में आयोजित किया जाता है, यह सबसे बड़ा व्यावसायिक शिक्षा और कौशल उत्कृष्टता कार्यक्रम है। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 2022 का आयोजन वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल द्वारा सितंबर से नवंबर 2022 तक यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पूर्वी एशिया में किया गया था, जिसमें 61 कौशल में 58 देशों के 1,000 से अधिक प्रतियोगी शामिल हुए थे। भारत ने 56 प्रतियोगियों और 50 विशेषज्ञों के साथ 50 कौशल (6 नए भविष्य के कौशल सहित) में भाग लिया, जो निर्माण और भवन प्रौद्योगिकी, रचनात्मक कला और फैशन, विनिर्माण और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी आदि से संबंधित थे। 23 वर्ष से कम आयु के 1000 से अधिक प्रतियोगी, चार दिनों की अवधि में परीक्षण परियोजनाओं (16-22 घंटे) पर काम करते हैं, जो समकालीन उद्योग मानकों और अवसंरचना पर आधारित होते हैं।

98 स्रोत: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से प्राप्त इनपुट

एमएसडीई के तहत योजनाएं	समग्र प्रगति
राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) *आंशिक वजीफे की प्रतिपूर्ति करके प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना*	• वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 24 के बीच 32.38 लाख प्रशिक्षु लगे हुए हैं। • एनएपीएस पोर्टलः पंजीकृत श्प्रतिष्ठानोंश की संख्या मार्च 2017 में 17,608 से बढ़कर मार्च 2024 तक 2.21 लाख हो गई • एनएपीएस के तहत, महिलाओं की भागीदारी वर्ष 2016-17 में 7.74% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 20.77% हो गई है। • प्रशिक्षुओं का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण वजीफा सहायता • एनएपीएस-2: शिक्षुओं के बैंक खाते में सीधे वजीफे के 25 प्रतिशत (1,500 तक) की प्रतिपूर्ति • अगस्त 2023 में लॉन्च होने के बाद से मार्च 2024 तक 22.46 लाख लेनदेन के माध्यम से वजीफे के रूप में ₹320.88 करोड़ जारी किए गए
उद्यमिता प्रशिक्षण	• नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट (एनआईईएसबीयूडी) ने वर्ष 19 और वर्ष 24 के बीच 3.21 लाख लाभार्थियों के लिए उद्यमिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया। • भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी ने वित्त वर्ष 19 और वित्त वर्ष 24 के बीच 1.43 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग सेवाएं प्रदान कीं। ◻ आईआईई नोडल इकाई थी जिसने प्रधान मंत्री वन धन योजना, ओआईएल जीविका, एसएफयूआरटीआई, आदि जैसी परियोजनाओं के तहत 1.78 लाख से अधिक लाभार्थियों को आजीविका सहायता प्रदान की।
स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म कन्वर्जेंस प्लेटफॉर्म एआई/एमएल तकनीक के माध्यम से कौशल, क्रेडिट और रोजगार तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है।	• अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया • कौशल योजनाओं का एकीकरण, 690 ऑनलाइन पाठ्यक्रम, 1650 क्यूपी-आधारित ई-पुस्तकें, ईश्रम/ईपीएफओ/एनसीएस, उद्यम, डिजिलॉकर, गतिशक्ति, यूएमएएनजी, एग्रीस्टैक, पीएलआई योजनाएं, ओडीओपी, आदि। • 60 लाख शिक्षार्थियों का पंजीकरण और 8.4 लाख ऐप डाउनलोड
नए युग और भविष्य के कौशल	• एनसीवीईटी ने वर्ष के दौरान 200+ नए युग और भविष्य के कौशल पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी • विभिन्न कॉलेजों में 100 नए युग के कौशल पाठ्यक्रम और प्रयोगशालाओं की पेशकश करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ सहयोग • आईटीआई में 23 नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए। नए आईटीआई की संबद्धता के लिए 4 पाठ्यक्रमों में से कम से कम एक श्नए युगश पाठ्यक्रम का चयन करने के लिए दिशानिर्देश।
अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता	
जी2जी समझौता ज्ञापन	सूचना विनिमय, मानक निर्धारण, अर्हताओं की पारस्परिक मान्यता आदि में सहयोग के लिए आठ देशों अर्थात आस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और यूके के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

एमएसडीई के तहत योजनाएं	समग्र प्रगति
स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (एसआईआईसी)	• बजट वर्ष 24 ने 30 एसआईआईसी की स्थापना की घोषणा की • वाराणसी और एसडीआइ भुवनेश्वर में दो केन्द्रों को चालू कर दिया गया है • बाकी एसआईआईसी के स्थानों को अंतिम रूप दे दिया गया है, और जल्द ही चरण 1 के तहत सात केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड कुशल भारतीयों की नैतिक और पारदर्शी अंतरराष्ट्रीय भर्ती के लिए वर्ष 2021 में स्थापित किया गया।	• सूचना प्रौद्योगिकी, निर्माण, आतिथ्य, आदि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्किल इंडिया इंटरनेशनल मिशन को संचालित करता है। • क्षमता निर्माण के लिए 20 एनएसडीसी से संबद्ध प्रशिक्षण केंद्र, भाषा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 12 केंद्र • प्रयासों के परिणामस्वरूप कई देशों में 26,000 से अधिक उम्मीदवारों की तैनाती हुई।
एमएसडीई योजनाओं से परे लक्षित कौशल	
जल जीवन मिशन	एमएसडीई द्वारा बहु-कौशल पाठ्यक्रम का समग्र मार्गदर्शन और समन्वय
पीएम विश्वकर्मा	एमएसडीई द्वारा आधुनिक टूलकिट के उपयोग सहित विश्वकर्मों का बुनियादी और 'उन्नत' कौशल प्रशिक्षण
ग्रीन हाइड्रोजन	स्किलिंग, अपस्किलिंग और री-स्किलिंग के लिए 50 नई अल्पकालिक योग्यताओं का विकास
पीएम-जेएएनएमएएन	• उद्यमिता और कौशल विकास, क्षमता निर्माण और एनआईईएसबीयूडी और आईआईई द्वारा पहचाने गए पीवीटीजी लाभार्थियों की हैंडहोल्डिंग • मार्च 2024 तक 5096 लाभार्थियों का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, वर्ष 2025-26 तक 44,608 लाभार्थियों तक पहुंचने की उम्मीद
अग्निवीरों के लिए विशेष कौशल प्रावधान	• डीजीटी ने सेना, नौसेना और वायु सेना के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं • 4 साल की सेवा के बाद उद्योगों में रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उनकी योग्यता और अनुभवात्मक शिक्षा के आधार पर अग्निवीरों का कौशल प्रमाणन • अग्निवीर सेवा मॉड्यूल: बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण; व्यापार प्रशिक्षण; सुरक्षा प्रशिक्षण और सेवा/ओजेटी

बॉक्स VIII.7: कौशल के लिए उद्योग के साथ साझेदारी

किसी भी बड़े पैमाने पर कौशल कार्यक्रम के लिए उद्योग कनेक्शन महत्वपूर्ण है, जो समकालीन प्रासंगिकता और रोजगार क्षमता को सक्षम बनाता है और नए कुशल कार्यबल को अवशोषित करने की मांग का पता लगाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, कौशल भारत मिशन कौशल विकास, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) द्वारा संचालित साझेदारी के माध्यम से उद्योग के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है। मार्च 2024 तक (जोड़ने की प्रारंभिक तिथि), एनएसडीसी द्वारा 131 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें 62 कारपोरेट संगठनों ने 42 आकांक्षी जिलों सहित देश भर में 3.10 लाख से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित किया है।

स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड

वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया, स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड कौशल विकास, नौकरी प्रतिधारण और प्रतिधारण के लिए निजी क्षेत्र के धन और विशेषज्ञता को आकर्षित करने के लिए एक अभिनव और परिणाम-आधारित वित्त तंत्र - डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड[99] मॉडल का लाभ उठाता है। एनएसडीसी और उसके गठबंधन सहयोगियों[100] की यह पहल चार वर्षों में चयनित और निगरानी वाले एनएसडीसी से संबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से यह सुनिश्चित करते हुए कि इसमें कम से कम 60 प्रतिशत महिलाएं हैं, 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखती है।, नवंबर वर्ष 2021 और मार्च वर्ष 2024 के बीच, पांच समूहों में 29,365 उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है, 23,464 प्रमाणित किए गए हैं, 19,209 को रखा गया है और 13,853 ने जॉब प्रतिधारण की सूचना दी है। कार्यक्रम ने अब तक 74% महिलाओं के नामांकन की सूचना दी है।

- इसके अलावा, प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने उद्योग भागीदारी के तहत निम्नलिखित पहल भी की हैं जैसे:

  मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, गुरुग्राम, एनएमडीसी छत्तीसगढ़, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड आदि जैसे प्रमुख उद्योग भागीदारों के साथ फ्लेक्सी एमओयू योजना में - मार्च 2019 से मार्च 2024 तक इस पहल के तहत लगभग 9600 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है।
- प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) पहल के तहत, कौशल संस्थान प्रशिक्षुओं को प्रत्यक्ष कार्यस्थल अनुभव मिलता है। वर्ष 2022 सत्र के दौरान, लगभग 978 आईटीआई और 37,865 प्रशिक्षुओं को डीएसटी के तहत कवर किया गया था।
- डीजीटी ने आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, एडोब, अमेजॅन वेब सर्विसेज आदि जैसे आईटी फ्रंटलाइन के साथ सहयोग किया है, ताकि प्रशिक्षुओं को आईआर 4.0 के अनुसार उद्योग के लिए तैयार किया जा सके और नवंबर 2019 और मार्च 2024 के बीच इन सहयोगों के तहत 21.5 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है।
- प्रशिक्षक प्रशिक्षुओं के अनिवार्य प्रशिक्षण के अलावा, एनएसटीआई इसरो, ओएनजीसी, भारतीय रेलवे, नौसेना जहाज मरम्मत यार्ड, नौसेना जहाज डॉकयार्ड और बीएचईएल के साथ साझेदारी करके मौजूदा उद्योग कार्यबल का कौशल / पुनः कौशल / अपस्किलिंग भी कर रहे हैं। इस पहल के तहत, वर्ष 24 सत्र के दौरान लगभग 1400 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।
- डीजीटी एनएसटीआई/आईटीआई में अवसंरचना के विकास/उन्नयन के लिए उद्योग भागीदारों के साथ भी सहयोग कर रहा है। उल्लेखनीय सहयोगियों में एयरोनॉटिकल स्ट्रक्चर और इक्विपमेंट फिटर के लिए डसॉल्ट, प्लंबिंग सेक्टर के लिए पिडिलाइट और जगुआर, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए स्कोडा और उन्नत सीएनसी मशीनरी प्रशिक्षण के लिए एचएएल और सीमेंस शामिल हैं।

8.81 कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना एक नई योजना है (बॉक्स VIII.8 में संक्षिप्त) कारीगरों की विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए अपने उद्यम को उन्नत करने के लिए, इस प्रकार पारंपरिक व्यवसायों को गतिशीलता के साथ प्रभावित करती है।

99 इम्पैक्ट बॉन्ड इनपुट से ध्यान हटाकर प्रदर्शन और परिणामों पर केंद्रित करते हैं। सरकार या दानकर्ता द्वारा किसी परियोजना को पहले से वित्तपोषित करने के बजाय, निजी निवेशक शुरू में पहल को वित्तपोषित करते हैं और 'परिणाम निधिदाताओं' द्वारा तभी चुकाया जाता है, जब सहमत परिणाम प्राप्त होते हैं। यह तंत्र प्रत्येक भागीदार को न कि केवल सेवाएं प्रदान करने के लिए बल्कि अधिगम के परिणाम प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहन देता है।

100 भागीदारों में चिल्ड्रन्स इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन (सीआईएफएफ), जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन, एचएसबीसी इंडिया और दुबई केयर्स आउटकम फंडर्स के रूप में, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट ट्रांजैक्शन मैनेजर के रूप में, यूएसएआईडी और एफसीडीओ (यूके सरकार) तकनीकी भागीदार के रूप में, ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजर स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता के रूप में, और एनएसडीसी और डालबर्ग एडवाइजर्स प्रदर्शन प्रबंधक के रूप में शामिल हैं। एनएसडीसी और एमएसडीएफ जोखिम निवेशक हैं जिन्होंने सेवा प्रदाताओं को अग्रिम कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए 4 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है।

बॉक्स VIII.8: पीएम विश्वकर्मा योजना: प्रगति हो रही है

पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम सितंबर 2023 में पारंपरिक उपकरणों के साथ काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों/शिल्पकारों को मान्यता, कौशल उन्नयन, संपार्श्विक मुक्त ऋण और विपणन सहायता के लिए शुरू किया गया था। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 ट्रेड कवर किए गए हैं, जिनमें दर्जी, नाई, राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार, टोकरी बुनकर, कुम्हार, मोची, पारंपरिक खिलौने बनाने वाले, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले आदि शामिल हैं। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें व्यावहारिक रूप से उपयोगी घटक हैं जिनमें पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता, कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, क्रेडिट समर्थन, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता शामिल हैं। कौशल उन्नयन मॉड्यूल के तहत, 5-7 दिनों का बुनियादी कौशल प्रशिक्षण और उन्नत 15 दिनों का वैकल्पिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें मजदूरी के नुकसान की भरपाई के लिए 500 प्रति दिन का वजीफा और 1000 का यात्रा भत्ता प्रदान किया जाता है।

वर्तमान में 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 365 जिलों को कवर करते हुए 1,533 केंद्र प्रशिक्षण का कार्यान्वयन कर रहे हैं और अतिरिक्त 2000 केंद्र तैयार हैं। ऋण में आसानी के लिए, अखिल भारतीय आधार पर सभी 766 जिलों में प्रत्येक में दो बैंक अधिकारियों को पंजीकृत विश्वकर्मा को योजना के तहत ऋण प्राप्त करने की जानकारी के लिए नामित किया गया है। 27 मई 2024 तक, 2.14 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं और योजना की अव्यक्त मांग को दर्शाते हुए 3-स्तरीय सत्यापन के माध्यम से 11.5 लाख का सत्यापन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4.37 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

8.82 कौशल पहलों से प्राप्त परिणामों को अधिकतम करने के लिए, अभिसरण और अन्य रोजगार-केंद्रित कार्यक्रमों के साथ तालमेल का उपयोग दोनों कार्यक्षेत्रों को पारस्परिक रूप से लाभान्वित करेगा। कौशल विकास को पीएलआई योजना और खिलौना, परिधान, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, कपड़ा, चमड़ा क्षेत्र आदि जैसे उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं से जोड़ने से कौशल उन्नयन में मदद मिलेगी क्योंकि उत्पादन मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ता है। प्रशिक्षुता संवर्धन के क्षेत्र में, विनियामक ढांचे में लचीलापन समाहित होने की काफी गुंजाइश है, जैसा कि बॉक्स VIII.9 में विस्तार से बताया गया है।

बॉक्स VIII.9: शिक्षुता ढांचे को पुनः अंशांकित करना

करते समय सीखना सीखने का सबसे अच्छा तरीका माना गया है और सिद्धांत से अभ्यास तक की खाई को पाटने का यह सबसे अच्छा तरीका है। विनिर्माण/उद्योग की भाषा में, इसे षशिक्षुताष कहा जाता है और ज्ञान-आधारित व्यवसायों में इसे ष्इंटर्नशिपष कहा जाता है। इस तरह के सीखने के अवसर सेतु के रूप में कार्य करते हैं जो लोगों को अनौपचारिक काम से औपचारिक रोजगार की ओर अभिमुख होने या शैक्षणिक क्षेत्र से कार्यस्थल तक जाने में सहायता करता है। वे कौशल पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनिवार्य घटक हैं जो रोजगार और उद्यमिता दोनों के लिए रीढ़ है।

शिक्षु अधिनियम, 1961 (अधिनियम) में 30 से अधिक कर्मचारियों वाले विनिर्माण और सेवाओं के सभी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य रूप से अपने कार्यबल के 2.5 - 15 प्रतिशत के दायरे में शिक्षुता संचालित करने का प्रावधान है[101]। 14 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो न्यूनतम 5वीं कक्षा तक शिक्षित हो, शिक्षुता लेने का पात्र है। उक्त नियम प्रशिक्षुओं को 5000 - 9000 प्रति माह के न्यूनतम वजीफे के साथ 6 – 36 महीने की अवधि के शिक्षुता कार्यक्रम प्रदान करते हैं और दर उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता से जुड़ी होती है। अधिनियम और नियमों को 2014, 2015 और 2019 में संशोधित किया गया है, ताकि इसे प्रतिष्ठानों और प्रशिक्षुओं के लिए और अधिक उदार बनाया जा सके।

101 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षुता https://nsdcindia.org/sites/all/themes/ibees/pdf/apprenticeship-faqs.pdf पर उपलब्ध है

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना[102] (एनएपीएस) अगस्त 2016 में एक कुशल कार्यबल की मांग को पूरा करने, औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवाओं को अनुभवात्मक सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना अधिनियम के तहत प्रशिक्षुओं की नियुक्ति को नियंत्रित करती है और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित है। यह निर्धारित वजीफे के 25 प्रतिशत (अधिकतम ₹1500 प्रति माह के अधीन) की प्रतिपूर्ति करके प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करता है और आंशिक रूप से बुनियादी प्रशिक्षण की लागत में भी समर्थन करता है। इस योजना में प्रशिक्षण महानिदेशक और राज्य सरकारों के माध्यम से प्रबंधित 261 से अधिक नामित ट्रेडों और 37 से अधिक उद्योग क्षेत्रों में एनएसडीसी द्वारा प्रबंधित 200 से अधिक वैकल्पिक ट्रेडों में शिक्षुता शामिल है। इस योजना के तहत[103], प्रशिक्षुओं को शामिल करने के लिए 2.21 लाख से अधिक प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं और वित्त वर्ष 17 से वित्त वर्ष 24 तक 32.38 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को नियोजित किया गया है।

जबकि एनएपीएस उन प्रशिक्षुओं की सहायता करता है जिनके पास न्यूनतम औपचारिक शिक्षा है, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना[104] (एनएटीएस) में 6 महीने से 1 वर्ष तक की अवधि के साथ व्यावहारिक, हैन्ड्स ऑन-द-जॉब-ट्रेनिंग आधारित कौशल अवसरों के लिए स्नातक, डिप्लोमा छात्रों और व्यावसायिक प्रमाणपत्र धारकों को शामिल किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू की गई इस योजना में 43,000 से अधिक पंजीकृत प्रतिष्ठान और 28.66 लाख छात्र हैं, जो इस योजना के तहत लगे कार्य कर रहे हैं। यह प्रतिष्ठानों को ऐसे शिक्षुता वजीफे की लागत का 50 प्रतिशत प्रदान करता है।

चुनौतियां

भारत में शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कार्यबल में कौशल के अंतर को पाटने और व्यावसायिक छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने की क्षमता है। अनुभवजन्य साक्ष्य से पता चलता है कि, एक सुचारू रूप से काम करने वाले शिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र में, फर्मों का एक बड़ा हिस्सा (जर्मनी में 30 प्रतिशत और स्विट्जरलैंड में 60 प्रतिशत) प्रशिक्षण अवधि के अंत तक एक प्रशिक्षु को काम पर रखने के अपने निवेश की भरपाई करता है, जबकि प्रशिक्षुओं को काम पर रखने में उनके लागत-लाभ विश्लेषण द्वारा निर्देशित किया जाता है (मुहलेमैन और वोल्टर 2014)[105]। फर्म सबसे योग्य प्रशिक्षुओं को भी रखते हैं जबकि अन्य कहीं और रोजगार की तलाश करते हैं।

भारतीय शिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र में महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ मौजूद हैं, जैसे कि शिक्षा संस्थानों और उद्योग के बीच समन्वय की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे, नियामक ढाँचे में अंतराल (रविचंद्रन 2023)[106]। इसके अलावा, व्यावसायिक प्रशिक्षण को अकादमिक शिक्षा से कमतर मानने की नकारात्मक धारणा सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है (गुप्ता और धारप 2022)[107]।

शिक्षुता योजनाओं के परिणाम सुधार की गुंजाइश का संकेत देते हैं। एनएपीएस 2.0 ने 2022-23 से 2025-26 तक चार वर्षों में 46 लाख प्रशिक्षुओं को भर्ती करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया, जबकि 2016-17 से 2021-22 तक नामांकन 15.96 लाख था। एक एकीकृत पोर्टल होने और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली में भुगतान को स्थानांतरित करने की तकनीकी पहल ने वित्त वर्ष 21 में 2.90 लाख से वित्त वर्ष 22 में 5.80 लाख तक नामांकन

102 राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना-2 (एनएपीएस-2) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश फाइल पर उपलब्ध हैं: ///C:/Users/Dell/Downloads/NAPS$2 0_Guidelines_25-08&2023.pdf

103 एनएपीएस डैशबोर्ड https://dashboard.apprenticeshipindia.org/ पर उपलब्ध है।

104 सामग्री यहां से प्राप्त की गई है:: राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस)::(education.gov.in)

105 मुहलेमैन, एस., वोल्टर, एस.सी. उद्यमों के लिए प्रशिक्षुता प्रणालियों के निवेश पर प्रतिफल: लागत-लाभ विश्लेषण से साक्ष्य। आईजेडए जे लेबर पॉलिसी 3, 25 (2014)। https://doi.org/10.1186/2193-9004-3-25

106 रविचंद्रन, आर., 2023, ब्रिजिंग द गैप: प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम की भूमिका, जर्नल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन स्टडीज, वॉल्यूम 6, नंबर 1, मई 2023 DOI: https://doi.org/10.12928/joves.v6i1.8006

107 गुप्ता, आर., और धरप, ओ. (2022). भारत अपने युवाओं को किस तरह कौशल प्रदान कर रहा है? एक व्यापक अध्ययन. जर्नल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, 1-27

बढ़ाने में मदद की है, लेकिन लक्ष्य हासिल करने के लिए कुछ प्रणालीगत कमजोरियों को दूर करने की आवश्यकता है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि काम कर रहे 50 प्रतिशत से कम प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण पूरा किया है। प्रशिक्षुओं के लिए लाभकारी रोजगार के अंतिम परिणाम के बारे में जानकारी का अभाव है। 2.21 लाख प्रतिष्ठानों में से केवल 47,000 के लगभग सक्रिय कार्यक्रम हैं, जो प्रशिक्षुता में नियोक्ताओं की रुचि पैदा करने की आवश्यकता का संकेत देता है।[108]

इस प्रकार शिक्षुता ढांचे को काम के घंटे, मुआवजे और विघटन में लचीलापन और परक्राम्यता प्रदान करने के लिए पुनः अंशांकित करने की आवश्यकता है, शिक्षुता के स्विस और जर्मन मॉडल का अनुकरण करते हुए जहां छात्र पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर सप्ताहांत पर प्रशिक्षुओं के रूप में काम करते हैं। नियामक ढांचे को स्थानीय फर्मों के लिए प्रशिक्षुओं को काम पर रखने के लागत-लाभ अनुपात को ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि यह स्पष्ट है, प्रशिक्षुओं की उत्पादकता और काम के घंटे भिन्न हो सकते हैं और अनुबंध की शर्तों में लचीलापन किसी भी नियोजन के लिए रास्तें बंद करने के बजाय पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यवस्था को सक्षम कर सकता है। कार्यक्रम में देरी को दूर करने और प्रतिष्ठानों की अनुपालन आवश्यकताओं को आसान बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों की भूमिका को कम करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षुता में अर्जित कौशल को पंजीकृत प्रतिष्ठानों और उद्योग समूहों के बीच नेटवर्किंग द्वारा लाभकारी रोजगार में बदलने के लिए एक तंत्र स्थापित करना, उद्यमिता योजनाओं के साथ अग्र संबंध आदि भी उपयोगी होंगे। स्थानीय स्तर जैसे कि जिला या शहरों के अनुषंगी क्षेत्रों आदि में अवसरों और मांग के मिलान को क्रियान्वित करने से परिणामों में सुधार होगा।

गायत्री और अन्य के अनुसार (2019), अल्पावधि में, विभिन्न क्षेत्रों और खण्डों में शिक्षुता योजना के कामकाज को समझने के लिए सांख्यिकीय डेटा एकत्र करना महत्वपूर्ण है। यह डेटा उन प्रशिक्षुओं की संख्या का अनुमान लगाने में मदद करेगा जिन्हें उद्योगों और कार्यस्थलों द्वारा समाहित किया जा सकता है। लंबे समय में, जागरूकता बढ़ाने, उद्योगों को प्रोत्साहित करने और प्रमुख हितधारकों को शामिल करके प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए[109]।

रोजगार में अनौपचारिक क्षेत्र का बड़ा हिस्सा एक चुनौती और अवसर दोनों है। अनौपचारिक क्षेत्र में कौशल विकास और कौशल उन्नयन को लक्षित करने वाले पहलों से इन नौकरियों में उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है और अकुशल और अर्ध-कुशल कार्यबल के समूह के लिए कमाई में सुधार हो सकता है। शिक्षुता ढांचे को मजबूत करना और पुनर्गणना करना इस अवसर का प्रभावी उपयोग करने का साधन हो सकता है।

निष्कर्ष और आगे की राह

8.83 संक्षेप में, औपचारीकरण, कौशल विकास, उद्यमिता, उद्योग विविधीकरण और समावेशी विकास में उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ भारत में रोजगार की स्थिति में पिछले दशक में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। इन रुझानों और तकनीकी प्रगति तथा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए देश की प्रतिबद्धता ने भारत को वैश्विक नौकरी बाजार में एक गतिशील और मजबूत किरदार के रूप में स्थापित किया है। सरकार व्यापार करने में आसानी, कम लॉजिस्टिक लागत, सार्थक कौशल विकास और उद्यमिता के लिए आसान ऋण का पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर रोजगार सृजन की नींव को पोषित करने का प्रयास कर रही है। इस दृष्टिकोण के परिणाम आने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन दृढ़ प्रयासों और अच्छे इरादों के साथ, यह देश में सभी के लिए स्थायी रोजगार सृजन की सुविधा प्रदान करेगा।

8.84 फिर भी, एक वृद्धिमान कार्यबल को औपचारिक रूप देने, उन क्षेत्रों जो कृषि से स्थानांतरित होनेवाले कामकारों को नियोजित कर सकते है और नियमित वेतन/वेतनभोगी रोजगार में उन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करने (पीएलएफएस 2022-23 के अनुसार, नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारियों का 53 प्रतिशत किसी भी सामाजिक

108 https://dashboard.apprenticeshipindia.org/

109 गायत्री, के., तंत्री, एम.एल., राजशेखर, डी., 2019 "भारत में प्रशिक्षुता नीति की आलोचनात्मक समीक्षा", सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बैंगलोर, कार्य पत्र 440, आईएसबीएन 978-81-7791-296-8।

सुरक्षा लाभ के लिए पात्र नहीं हैं) की दीर्घकालिक चुनौतियां बनी हुई। राज्य सरकारें विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप अनुपालन बोझ को कम करके और भूमि संबंधी कानूनों में सुधार आदि करके व्यवसायों द्वारा काम पर रखने की गति को तेज कर सकती हैं।

8.85 कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए उत्पादक, मध्यवर्ती और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की भारत की आवश्यकताओं के ओवरलैप पर स्थित है, जिसमें योजनाओं के सम्मिलन से प्राप्त करने के लिए समृद्ध लाभांश और राष्ट्रीय स्तर पर मिशन-मोड दृढ़ फोकस है। सह्याद्री किसान उत्पादक कंपनी सफलता की कहानियों की एक लंबी सूची से एक ज्वलंत उदाहरण है।

8.86 साथ ही, दुनिया भर में रोजगार परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और भारत, जो 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखता है को एआई के पास उपलब्ध नौकरियों के व्यापक पुनर्विकास में भाग लेना चाहिए और आगे बढ़ने की संभावना है। श्रमिकों पर स्वचालन का प्रभाव जटिल और अनिश्चित होने के कारण, तकनीकी परिवर्तन की दिशा राजनीतिक अर्थव्यवस्था की ताकतों के लिए अतिसंवेदनशील बनी हुई है। इस प्रकार भारत को अनुसंधान में निवेश करने और साझा समृद्धि की दिशा में एआई बैंडवागन को चलाने की आवश्यकता है। साथ ही, अवैतनिक देखभाल कार्य के रूप में बुनियादी और सदियों पुरानी चीज पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक सस्ती, विश्वसनीय और गुणवत्ता वाले क्रेच और बुजुर्ग देखभाल बुनियादी ढांचे का विकास भुगतान किए गए काम में महिला भागीदारी के लिए कमजोर पक्ष है, जिसे लिंग द्वारा निर्धारित करने के बजाय तुलनात्मक लाभ और पसंद द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

8.87 अंततः, निजी क्षेत्र में नौकरियां सृजित होती हैं। भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर में अब इतना अच्छा कभी नहीं रहा है, वित्त वर्ष 24 में 15-वर्ष की ऊंचाई पर लाभप्रदता के साथ. वित्त वर्ष 20 और वित्त वर्ष 23 के बीच लाभ चौगुना हो गया था. व्यवसाय कभी-कभी मांग दृश्यता की कमी का हवाला देते हुए निवेश करने के लिए अनिच्छुक होते हैं। यह बाह्य कारकों और आंतरिक कारकों जैसे कमजोर रोजगार वृद्धि और आय वृद्धि के कारण हो सकता है। उस हद तक, मांग दृश्यता की कमी एक अंतर्जात कारक है। श्रम पर पूंजी का विशेषाधिकार दीर्घकालिक कॉर्पोरेट विकास संभावनाओं के लिए प्रतिकूल है। व्यवसायों का स्वयं के लिए एक दायित्व है कि वे पूंजी के निवेश और श्रम की तैनाती के बीच सही संतुलन बनाएं। महत्वपूर्ण रूप में, आय पूंजी और श्रम शेयरों को उचित होना चाहिए। एआई के प्रति अपने आकर्षण और प्रतिस्पर्धा के क्षरण के डर से, व्यवसायों को रोजगार सृजन के लिए अपनी जिम्मेदारी और सामाजिक स्थिरता पर परिणामी प्रभाव को ध्यान में रखना होगा।

8.88 कौशल के संबंध में भी, यह एक प्राथमिकता है जो खुद को बाजार आधारित समाधानों के लिए उधार देती है। एक कौशल साधक है जो बेहतर कौशल से आर्थिक रूप से लाभान्वित होता है; एक कौशल-प्रदाता है जो इसे प्रदान करने के लिए शुल्क आय अर्जित करता है और ऐसे नियोक्ता हैं जो एक कुशल और उत्पादक कार्यबल से लाभान्वित होते हैं। इसलिए, यह एक चुनौती है जिसे बाजार हल कर सकता है और इस हद तक कि नियामक बाधाएं (उदाहरण के लिए, कौशल सुविधाओं की स्थापना के लिए भूमि की उपलब्धता) इस समस्या को हल करने के लिए बाजार के मार्ग में खड़ी हैं, यह सरकारों की जिम्मेदारी है - संघ और राज्यों – जिन्हें वे दूर कर सकते हैं।

8.89 इस अध्याय में अर्थव्यवस्था द्वारा सृजित की जाने वाली नौकरियों की संख्या का अनुमान लगाया गया है। बेशक, उनमें से सभी नौकरी की तलाश नहीं करेंगे। उनमें से कुछ स्व-नियोजित होंगे और उनमें से कुछ नियोक्ता भी होंगे। नौकरियों से अधिक, आर्थिक विकास आजीविका पैदा करने के बारे में है। तकनीकी परिवर्तन, भू-राजनीतिक मंथन और जलवायु परिवर्तन मिलकर इसे एक विकट चुनौती बनाते हैं। इसके लिए हमें - सभी स्तरों पर सरकारों और निजी क्षेत्र - को एक साथ प्रयास करने की आवश्यकता है।

****

कृषि और खाद्य प्रबंधन : यदि हम सही कर लें तो कृषि में बढ़ोत्तरी अवश्य है

09

अध्याय

पिछले पाँच वर्षों में, कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष औसतन 4.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देश में खाद्यान्न का भी पर्याप्त भंडार है, जिसका लगभग 40 प्रतिशत[1] हिस्सा दो-तिहाई आबादी को नि:शुल्क वितरित किया जाता है। भारत अपने खाद्यान्न का 7 प्रतिशत[2] से अधिक निर्यात करता है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में सकारात्मक योगदान दिया है।

हालाँकि, विशिष्ट चुनौतियाँ बनी हुई हैं। कम उत्पादकता स्तर, मौसम में परिवर्तनशीलता का प्रभाव, खंडित भूमि जोत और अपर्याप्त विपणन अवसंरचना कृषि प्रदर्शन को प्रभावित करती है। अध्याय में इन पहलुओं पर चर्चा की गई है, साथ ही निवेश और उत्पादकता बढ़ाने, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से किसानों को उचित रिटर्न प्रदान करने, उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट तक पहुँच में सुधार करने और बेहतर विस्तार सेवाओं को सक्षम करने के लिए फसल, पशुधन, पशुपालन और मत्स्य पालन में सरकारी हस्तक्षेप पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। भविष्य को देखते हुए, कृषि में डिजिटलीकरण पहल से बेहतर निर्णय लेने वाले उपकरणों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने की उम्मीद है। इस अध्याय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) जैसी कल्याणकारी योजनाओं और खाद्य खरीद और आवंटन सहित भारत के खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई है।

परिचय

9.1 भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3 प्रतिशत आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद[3] में वर्तमान मूल्य पर इसकी हिस्सेदारी 18.2 प्रतिशत है। यह क्षेत्र उछाल वाला रहा है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि इसने पिछले पांच वर्षों में स्थिर कीमतों पर 4.18 प्रतिशत[4] की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। एमएसपी के माध्यम से सुनिश्चित लाभकारी मूल्य, फसल विविधीकरण को सक्षम करना, डिजिटलीकरण एवं यंत्रीकरण को बढ़ावा देना, जैविक और प्राकृतिक खेती के माध्यम से टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करना और उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के रूप में सरकार द्वारा की गई कई पहलों और उपायों का इस क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 2023-24 के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 1.4 प्रतिशत[5] रही, जो कि 2022-23[6] में 4.7 प्रतिशत से कम है, जिसका मुख्य कारण अल नीनो के कारण विलंबित और खराब मानसून के कारण खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट है। संबद्ध गतिविधियों - पशुधन और मत्स्य पालन ने अनाज[7] जैसी पारंपरिक फसलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, जो मौजूदा कीमतों पर कृषि सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में उनकी हिस्सेदारी में वृद्धि से स्पष्ट है, जो

1 चंद, आर., जोशी, पी., और खड़का, एस. (2022). 2030 की ओर भारतीय कृषि: किसानों की आय, पोषण सुरक्षा और टिकाऊ खाद्य और कृषि प्रणालियों को बढ़ाने के लिए मार्ग (पृष्ठ 311)। स्प्रिंगर नेचर लिंक https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-19-0763-0 पर उपलब्ध है।

2 अशोक गुलाटी और रितिका (2022) 2030 की ओर भारतीय कृषि: किसानों की आय, पोषण सुरक्षा और टिकाऊ खाद्य और कृषि प्रणालियों को बढ़ाने के लिए मार्ग (पृष्ठ 311)। स्प्रिंगर नेचर लिंक https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-19-0763-0 पर उपलब्ध है।

3 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

4 पूर्वोक्त

5 पूर्वोक्त

6 पूर्वोक्त

7 कृषि अधिनियमों को समझना, कार्य पत्र 1/2020, नीति आयोग, नवंबर 2020

2014-15 में 24.38 प्रतिशत और 4.44 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23[8] में क्रमश: 30.23 प्रतिशत और 7.25 प्रतिशत हो गई है। 2022-23[9] में मौजूदा कीमतों पर कृषि जीवीए में फसल क्षेत्र की हिस्सेदारी 2014-15 के 61.75 प्रतिशत की तुलना में 55.28 प्रतिशत है।

9.2 हालांकि देश एक प्रमुख कृषि उत्पादक है चावल, गेहूं, कपास और गन्ना सहित अन्य फसलों का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दूध, दालों और मसालों[10] का सबसे बड़ा उत्पादक है फिर भी देश में फसल की पैदावार अन्य प्रमुख उत्पादकों की तुलना में बहुत कम है (चित्र IX.2)। यह इस तथ्य के बावजूद है कि सरकार का अधिकांश समर्थन चावल और गेहूं को जाता है, जो चिंतन का विषय है। खंडित भूमि जोत, कम कृषि निवेश, कृषि मशीनीकरण की कमी, गुणवत्ता वाले इनपुट तक अपर्याप्त पहुंच और अपर्याप्त विपणन बुनियादी ढांचे के कारण फसल उत्पादन के बाद नुकसान होता है, बारिश पर निर्भरता और फसल उत्पादन के अल्पावधिक मौसम कम पैदावार के कुछ कारण हैं।

चार्ट IX-1: कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि

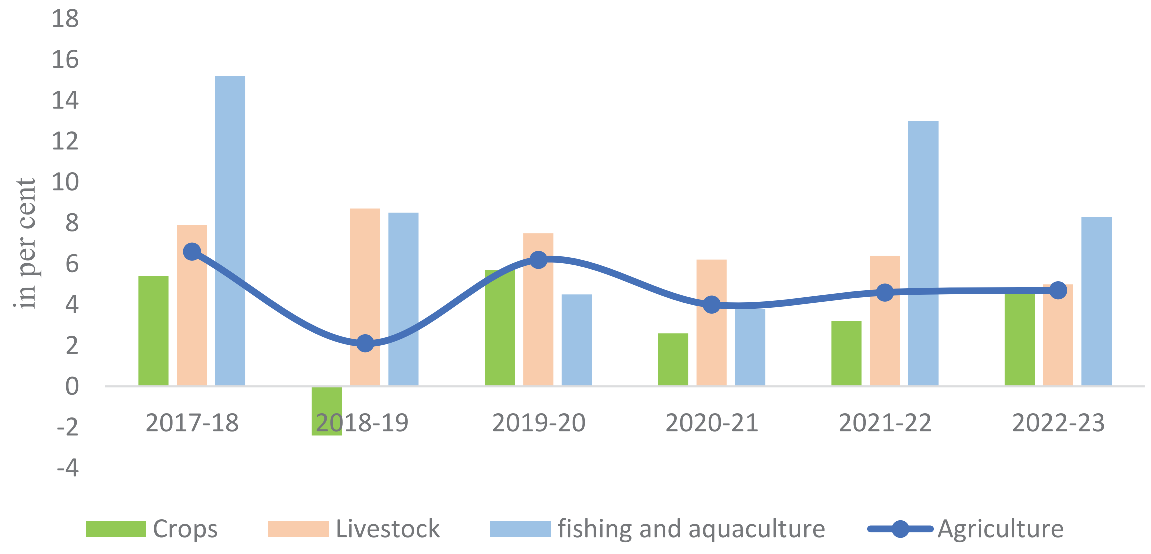

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

9.3 किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी रिपोर्ट (डीएफआई) 2016 की सिफारिशों के अनुरूप कृषि में उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कई पहलें की जा रही हैं, जिनमें फसल और पशुधन उत्पादकता बढ़ाने, फसल की सघनता बढ़ाने, उच्च-मूल्य वाली कृषि और किसानों की उपज पर लाभकारी मूल्य देने हेतु विविधीकरण की रणनीतियों की पहचान की गई है। 2018-19 में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का डेढ़ गुना एमएसपी तय करने का निर्णय किसानों को सुनिश्चित लाभकारी मूल्य प्रदान करने की दिशा में एक कदम था। अन्य पहलों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के माध्यम से आय सहायता शामिल है, जो किसान को प्रति वर्ष ₹6000/- का प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ देती है। प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी), एक सूक्ष्म सिंचाई योजना और वैकल्पिक और जैविक उर्वरकों के उपयोग सहित राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत कार्रवाई के माध्यम से इनपुट और टिकाऊ उत्पादन विधियों के उपयोग में अधिक दक्षता को बढ़ावा देना उत्पादकता और स्थिरता में सुधार के लिए की जा रही अन्य पहलों के कुछ उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सुविधा प्रदान करने के लिए डिजिटल कृषि मिशन और ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) जैसी डिजिटल पहल भी शुरू की गई हैं, जिससे बेहतर मूल्य प्राप्ति संभव हो सकेगी।

8 पशुपालन एवं डेयरी विभाग (मत्स्य पालन और पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय)
9 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
10 https://www.fao.org/india/fao-in-india/india-at-a-glance/en/

चार्ट IX-2: प्रमुख खरीफ फसलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकता तुलना (2022)

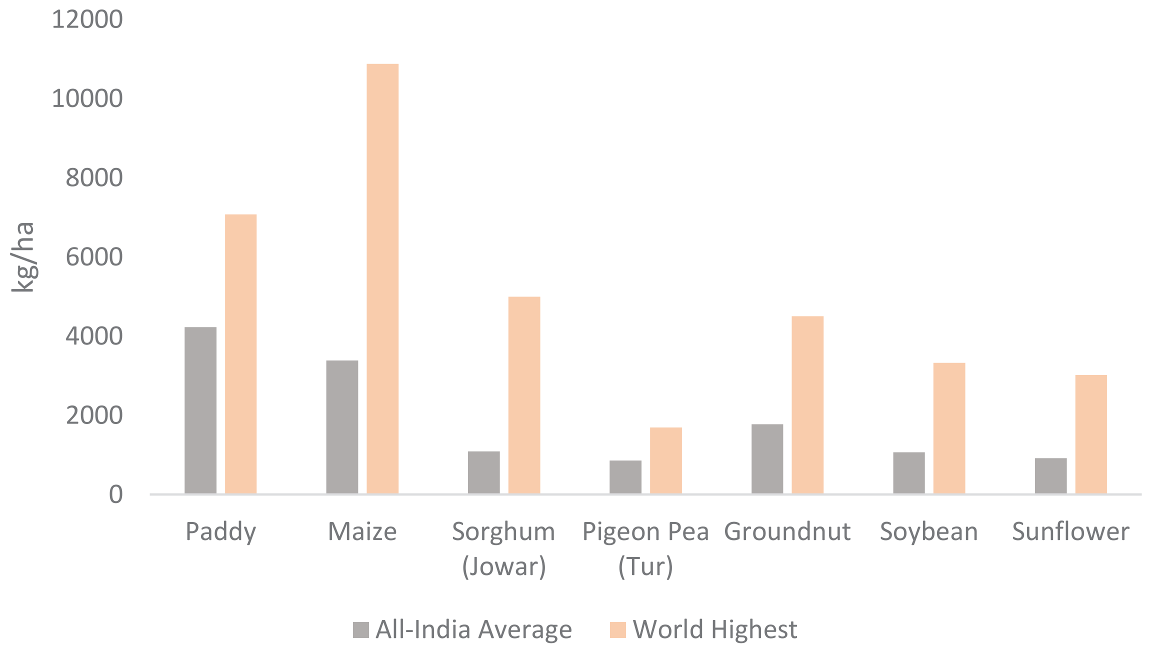

स्रोत: खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति रिपोर्ट 2024-25

9.4 किसानों की आय बढ़ाने में पशुपालन और मत्स्यपालन की भूमिका को उचित रूप से मान्यता दी गई है, खासकर तब जब कृषि जोत कम हो जाती है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम), राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (एनडीएलएम) और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) जैसी योजना में गुणवत्ता में सुधार, संगठित बाजारों तक पहुंच को सक्षम बनाने और स्वदेशी नस्लों के विकास के लिए पहलें शामिल हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र को उत्पादकता में सुधार, संस्थागत ऋण तक पहुंच और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मत्स्य पालन बुनियादी ढांचे विकास निधि (एफआईडीएफ) के माध्यम से कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थन दिया गया है, जिसका कुल निधि आकार 7.52 हजार करोड़ रुपये है। उसी प्रकार मई, 2020 में शुरू की गई प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) का उद्देश्य मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, प्रौद्योगिकी सम्मिश्रण को सक्षम करना और इष्टतम जल प्रबंधन को बढ़ावा देना है ताकि 2020-21 से 2022-23 में मछली उत्पादन में 7.4 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हो सके[11]।

कृषि उत्पादन: प्रदर्शन और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना

9.5 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन 329.7 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया और तिलहन उत्पादन 41.4 मिलियन टन तक पहुंच गया। 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन 328.8 मिलियन टन[12] से थोड़ा कम है, जिसका मुख्य कारण खराब और विलंबित मानसून है। अन्य फसलों जैसे श्री अन्ना/पोषक अनाज और कुल तिलहन के उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई। पोषक अनाज में पिछले वर्ष की तुलना में 1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई, जैसा कि तुअर में हुआ, जिसका उत्पादन पिछले वर्ष के 33.12 लाख टन उत्पादन की तुलना में 33.85 लाख टन (एलटी) होने का अनुमान है। चूंकि कटाई अभी भी जारी है, इसलिए क्रमिक अनुमानों में और बदलाव हो सकते हैं। मसूर का उत्पादन 17.54 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष के 15.59 लाख टन उत्पादन से 1.95 लाख टन अधिक है।

11 मत्स्य पालन विभाग

12 तीसरा अग्रिम अनुमान, कृषि मंत्रालय, https://desagri.gov.in/wpcontent/uploads/2024/06/English.pdf पर उपलब्ध

चार्ट IX.3: प्रमुख फसलों का उत्पादन

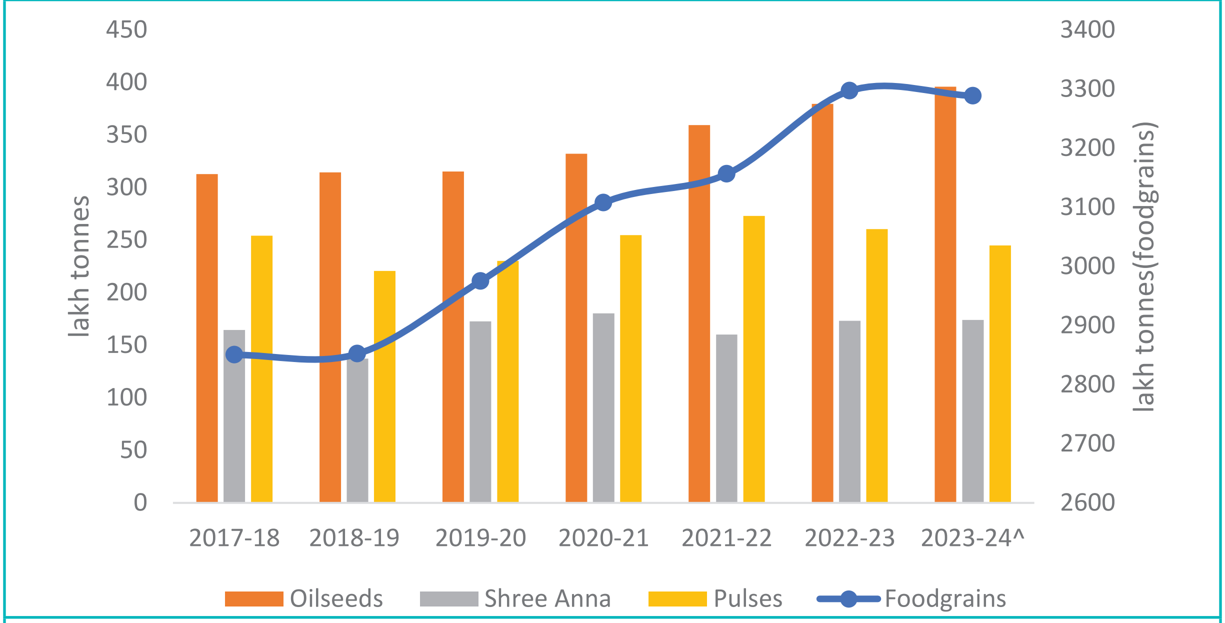

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
^तीसरा अग्रिम अनुमान के अनुसार

9.6 हाल के वर्षों में, सरकार ने स्थायित्व संबंधी चुनौतियों का समाधान करने और पानी की अधिक खपत वाली फसलों से उत्पादन को दलहन, तिलहन और पोषक-अनाज/श्री अन्न जैसी अन्य दूसरे फसलों की ओर अभिमुख करने के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया है। सरकार धान की खेती के लिए वैकल्पिक फसलों की बेहतर उत्पादन तकनीकों का प्रदर्शन और प्रचार करने तथा दलहनी फसलों की खेती के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता को बहाल करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) को लागू कर रही है। फसल उत्पादन और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन, उच्च उपज वाली किस्मों तक पहुंच, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीक, कुशल जल बचत उपकरणों और किसानों की क्षमता निर्माण आदि के माध्यम से खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) लागू किया गया है। फसल विविधीकरण की ओर सरकार का जोर तिलहन और दलहन के लिए उत्पादन की औसत लागत पर एमएसपी में अधिक वृद्धि के माध्यम से सुगम हुआ है, जिसमें दालों (मसूर) को 2023-24 में उत्पादन लागत से 89 प्रतिशत अधिक, उसके बाद तुअर को 58 प्रतिशत जबकि मोटे अनाज/बाजरा जैसे बाजरा के लिए एमएसपी उत्पादन लागत से 82 प्रतिशत अधिक था। कुसुम और सोयाबीन (पीला) के लिए एमएसपी में 2023-24 में उत्पादन लागत से 52 प्रतिशत की वृद्धि की गई। चावल और गेहूं के उत्पादन तथा दलहन और तिलहन के उत्पादन के बीच असंतुलन को दूर करने के लिए इसे जारी रखने की आवश्यकता है।

9.7 सरकार बेहतर उत्पादकता और खेती के तहत क्षेत्रफल में वृद्धि के माध्यम से वनस्पति तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 2018-19 से केंद्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- तिलहन एवं पाम ऑयल (एनएफएसएम-ओएसएंडओपी) को लागू कर रही है। सरकार की इन पहलों के कारण, सभी तिलहनों के कुल कवरेज क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से विस्तार हुआ है, जो 2014-15 में 25.60 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 में 30.08 मिलियन हेक्टेयर हो गया है (17.5 प्रतिशत की वृद्धि)। खाद्य तेल की घरेलू उपलब्धता 2015-16 में 86.30 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में 121.33 लाख टन हो गई है। इससे घरेलू मांग और खपत पैटर्न में वृद्धि के बावजूद आयातित खाद्य तेल का प्रतिशत हिस्सा 2015-16 में 63.2 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 57.3 प्रतिशत हो गया है। रेपसीड और सरसों के लिए लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (जो 2022-23 में लागत से 98 प्रतिशत अधिक था) भी किसानों को उत्पादन में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है[13]।

13 कृषि मंत्रालय

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में निवेश एवं ऋण तक पहुंच को बढ़ावा देना

9.8 सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) एक विशिष्ट अवधि में भौतिक परिसंपत्तियों में कुल निवेश को संदर्भित करता है। इसमें नई और मौजूदा अचल संपत्तियां शामिल हैं, जैसे कि मशीनरी, भवन, भूमि सुधार, उपकरण खरीद और इन्वेंट्री परिवर्तन[14]। यह मीट्रिक कृषि के आधुनिकीकरण, उत्पादकता बढ़ाने और स्थिरता सुनिश्चित करने में निवेश का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। बुनियादी ढांचे का विकास, विशेष रूप से कटाई के बाद की सुविधाएं, अपशिष्ट को काफी कम कर सकती हैं, उपज की गुणवत्ता को संरक्षित कर सकती हैं और किसानों की आय बढ़ा सकती हैं। कृषि क्षेत्र का जीसीएफ और सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) के प्रतिशत के रूप में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में जीसीएफ का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण सार्वजनिक निवेश में वृद्धि है। 2022-23 में कृषि क्षेत्र का जीसीएफ 19.04 प्रतिशत की दर से बढ़ा और जीवीए के प्रतिशत के रूप में जीसीएफ 2021-22 में 17.7 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 19.9 प्रतिशत हो गया, जो कृषि में निवेश में वृद्धि का संकेत देता है[15]। 2016-17 से 2022-23 तक जीसीएफ में औसत वार्षिक वृद्धि 9.70 प्रतिशत थी[16]।

9.9 तथापि, जीसीएफ में बढ़ती प्रवृत्ति के बावजूद, विशेष रूप से किसानों की आय दोगुनी करने के संदर्भ में कृषि निवेश को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। डीएफआई 2016 की रिपोर्ट ने संकेत दिया कि 2016-17 से 2022-23 की अवधि में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, कृषि क्षेत्र की आय में 10.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि होनी चाहिए, जिसके लिए कृषि निवेश में 12.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर की आवश्यकता होगी[17]। इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चुनौती कृषि भूमि का विखंडन है, जिसने किसानों के निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। दूसरी ओर, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से नीचे रही है[18]।

चार्ट IX.4: कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का (जीसीएफ) एवं जीसीफ की कृषि जीवीए में वृद्धि प्रतिशता के रूप में

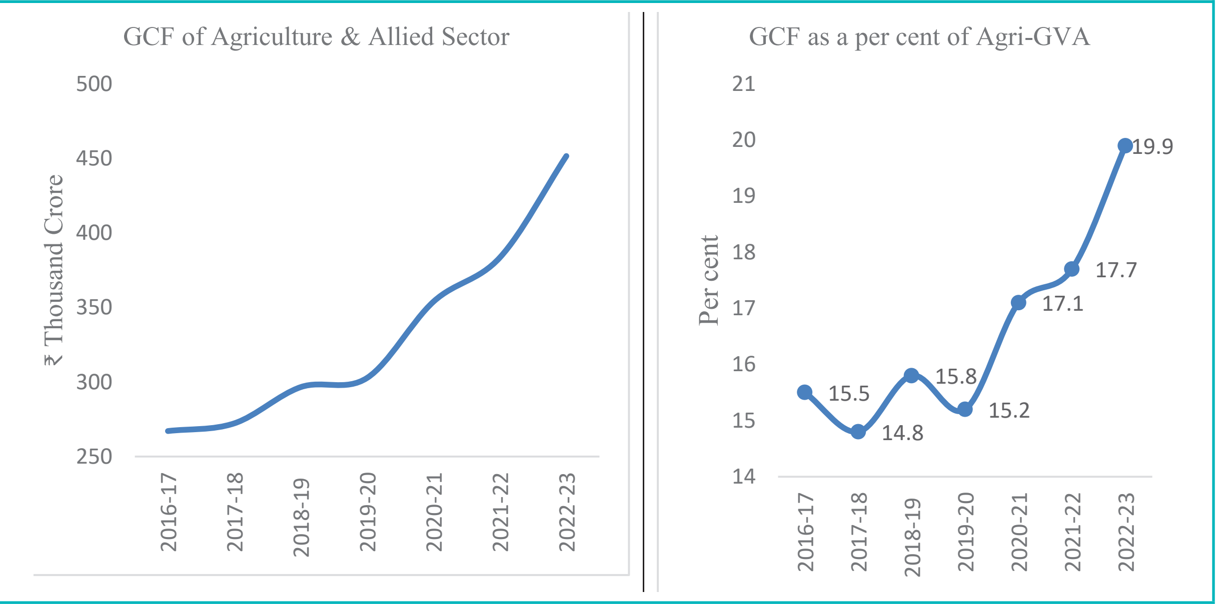

स्रोत: राष्ट्रीय आय का दूसरा अग्रिम अनुमान, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति (विभिन्न अंक कार्यालय

9.10 सब्सिडी ने किसानों के व्यवहार को बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों को अपनाने, उर्वरक के उचित संघटक और मात्रा के उपयोग को प्रोत्साहित करने और कस्टम हायरिंग केंद्रों से कृषि मशीनों तक पहुंच में सुधार करने में भी महत्वपूर्ण

14 विश्व बैंक (https://databank.worldbank.org/metadataglossary/world-development indicator/series/NE-GDI-TOTL-ZS)

15 कृषि में निवेश मुख्य रूप से भूमि, इनपुट और उत्पादन से संबंधित निवेश को संदर्भित करता है। इसमें बाजार, भंडारण, परिवहन, ग्रेडिंग और अन्य कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में निवेश शामिल नहीं है।

16 सर्वेक्षण गणना एनएसओ के डेटा पर आधारित है

17 किसानों की आय दोगुनी करने की रिपोर्ट 2018 का खंड XIV (https://foodprocessingindia.gov.in/uploads/publication/MoFPI1609496430agriculture2.pdf)

18 चाँद, आर. और सिंह, जे. (2023)। हरित क्रांति से अमृत काल तक। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, भारत सरकार।

भूमिका निभाई है। 2011-12 और 2020-21 के बीच कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी दोगुनी से अधिक हो गई, जिसमें सबसे तेज वृद्धि उर्वरक और बिजली में देखी गई। नतीजतन, यद्यपि सार्वजनिक निवेश सब्सिडी की समान दर से बढ़ा, तथापि वे सब्सिडी के लगभग एक-तिहाई पर ही रहे[19]।

9.11 इनपुट सब्सिडी कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में अल्पकालिक वृद्धि में सहायता प्रदान करती है [20]। दूसरी ओर, इस क्षेत्र के दीर्घकालिक आधुनिकीकरण के लिए उच्च निवेश स्तर की आवश्यकता है और निजी कॉर्पोरेट संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, विशेष रूप से कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में।

9.12 निजी निवेश को आकर्षित करने की आवश्यकता को पहचानते हुए सरकार 2014 से एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) उप-योजना को लागू कर रही है, जिसके तहत भंडारण अवसंरचना की सीमा में सुधार करने के उद्देश्य से पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह मांग-संचालित, ऋण-संबद्ध योजना है जो व्यक्तियों, किसानों, एफपीओ, सहकारी समितियों और राज्य एजेंसियों को 25 प्रतिशत (मैदानी इलाकों के लिए) और 33.33 प्रतिशत (पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए) की सब्सिडी प्रदान करती है। 30 अप्रैल, 2024 तक स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 48357 परियोजनाओं[21] को मंजूरी दी गई थी, जिसमें ₹4570 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में जारी किए गए थे और 20878 अन्य परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं, जिनमें 2084 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में जारी किए गए हैं। फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र को अधिक सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) को वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 के बीच वितरित किए जाने वाले 1 लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा के साथ लॉन्च किया गया था, जिसके समर्थन सहित वित्त वर्ष 2032-33 तक बढ़ाया जाएगा। एआईएफ फसल कटाई के बाद के प्रबंधन और सामुदायिक खेती परियोजनाओं के लिए मध्यम अवधि के ऋण वित्तपोषण प्रदान करता है, ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान करता है। 5 जुलाई, 2024 तक, एआईएफ ने 17,196 कस्टम हायरिंग केंद्रों, 14,868 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों, 13,165 गोदामों, 2,942 छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयों, 1,792 कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं और 18,981 अन्य परियोजनाओं का समर्थन करते हुए ₹73194 करोड़ का निवेश जुटाया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) ने खेत से लेकर खुदरा तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन बनाने के लिए अनुदान के माध्यम से ऋण-संबद्ध वित्तीय सहायता की शुरुआत की ताकि जल्दी खराब होने वाली उपज की बर्बादी को कम किया जा सके और खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। पीएमकेएसवाई के तहत मार्च 2024 के अंत तक 1044 परियोजनाएं पूरी हो गई। मार्च 2024 के अंत तक ₹32.78 हजार करोड़ की परियोजना लागत और ₹9.3 हजार करोड़ की स्वीकृत सब्सिडी वाली कुल 1685 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

किफायती एवं उन्नत ऋण पहुंच के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना

9.13 भारतीय कृषि पर छोटे भूमिधारकों का वर्चस्व बना हुआ है। लगभग 89.4 प्रतिशत कृषि परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है[22]। किसानों की अपनी कृषि भूमि में निवेश करने की क्षमता सीधे तौर पर किफायती ऋण तक पहुँच पर निर्भर करती है। सरकार की प्राथमिकता समय पर, लागत प्रभावी और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना रही है जो गैर-संस्थागत ऋण पर निर्भरता को कम करता है और निवेश को बढ़ाता है। इन उपायों ने गैर-संस्थागत ऋण की हिस्सेदारी को 1950 में 90 प्रतिशत से घटाकर 2021-22 में 23.40 प्रतिशत कर दिया है।[23] 31 जनवरी 2024 तक, कृषि को संवितरित कुल ऋण ₹22.84 लाख करोड़ था, जिसमें ₹13.67 लाख करोड़ फसल ऋण (अल्पकालिक) और ₹9.17 लाख करोड़ सावधि ऋण के लिए आवंटित किए गए थे[24]।

9.14 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ने कृषि ऋण पहुंच को सुव्यवस्थित किया है। 31 जनवरी, 2024 तक बैंकों ने 9.4 लाख करोड़ की सीमा के साथ 7.5 करोड़ केसीसी जारी किए। एक और उपाय के रूप में, 2018-19 में

19 पूर्वोक्त

20 चंद, आर. (2017)। अध्यक्षीय भाषण: किसानों की आय दोगुनी करना: रणनीति और संभावनाएँ। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, 71(1), 1-23 और चंद, आर. (2022)। 21वीं सदी के लिए कृषि चुनौतियाँ और नीतियाँ। नाबार्ड रिसर्च एंड पॉलिसी सीरीज, (2), 36

21 अन्य परियोजनाएं भंडारण अवसंरचना से संबंधित हैं, जिसमें सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकिंग आदि शामिल हैं।

22 स्थिति आकलन सर्वेक्षण, एनएसओ, एनएसएस 77वां दौर

23 नाबार्ड राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2.0

24 https://www.rbi.org.in/scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=942

मत्स्य पालन और पशुपालन गतिविधियों की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ाया गया, साथ ही संपार्श्विक-मुक्त ऋण की सीमा को बढ़ाकर ₹1.6 लाख कर दिया गया। उधारकर्ताओं, दुग्ध संघों और बैंकों के बीच त्रिपक्षीय समझौते (टीपीए) के मामले में, संपार्श्विक-मुक्त ऋण ₹3 लाख तक जा सकता है[25]। 31 मार्च, 2024 तक, मत्स्य पालन और पशुपालन गतिविधियों के लिए क्रमशः 3.49 लाख केसीसी और 34.5 लाख केसीसी जारी किए गए। इसके अलावा, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)[26] पट्टेदार किसानों के लिए ऋण के एक आवश्यक स्रोत के रूप में उभरे हैं। पिछले पांच वर्षों में जेएलजी खातों में 43.76 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से वृद्धि हुई है, जो पट्टेदार किसानों और हाशिए पर पड़े वर्गों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरा है।

9.15 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) जैसी बीमा योजनाएं प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण फसल के नुकसान के विरुद्ध सुरक्षा जाल प्रदान करती हैं, जिससे किसानों के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है। ये योजनाएं किसानों की आजीविका की रक्षा करती हैं और उन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। पीएमएफबीवाई किसान नामांकन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है और बीमा प्रीमियम के मामले में तीसरी सबसे बड़ी योजना है। यह योजना किसानों को बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक सभी गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध फसलों के लिए व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित करने के लिए एक सरल और किफायती फसल बीमा उत्पाद प्रदान करती है। 2023-24 में कुल बीमित क्षेत्र 2022-23 में 500.2 लाख हेक्टेयर की तुलना में 610 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया। वर्ष 2016-17 से अब तक इस योजना के तहत कुल 5549.40 लाख किसानों के आवेदनों का बीमा किया गया है और दावों के रूप में ₹150589.10 करोड़ का भुगतान किया गया है। बीमा दावों की तुलना में प्रीमियम की उच्च लागत, दावों के निपटान में देरी, पारदर्शिता की कमी और राज्यों में अलग-अलग स्थितियों के लिए एक समान प्रीमियम दरें शामिल न होने के कारण योजना के निष्पादन पर असर पड़ा है[27]। एक अन्य अध्ययन से यह भी संकेत मिलता है कि प्रीमियम भुगतान की बोझिल प्रक्रिया, गाँव के पास बैंक सुविधाओं की कमी और छोटे और सीमांत किसानों के बीच योजना के बारे में कम जागरूकता ने योजना के प्रभाव को सीमित कर दिया है।[28]

चार्ट IX.5: प्रमुख फसलों के लिए प्रति टन खाद्यान्न जल उपयोग (2022) भारत और विश्व औसत

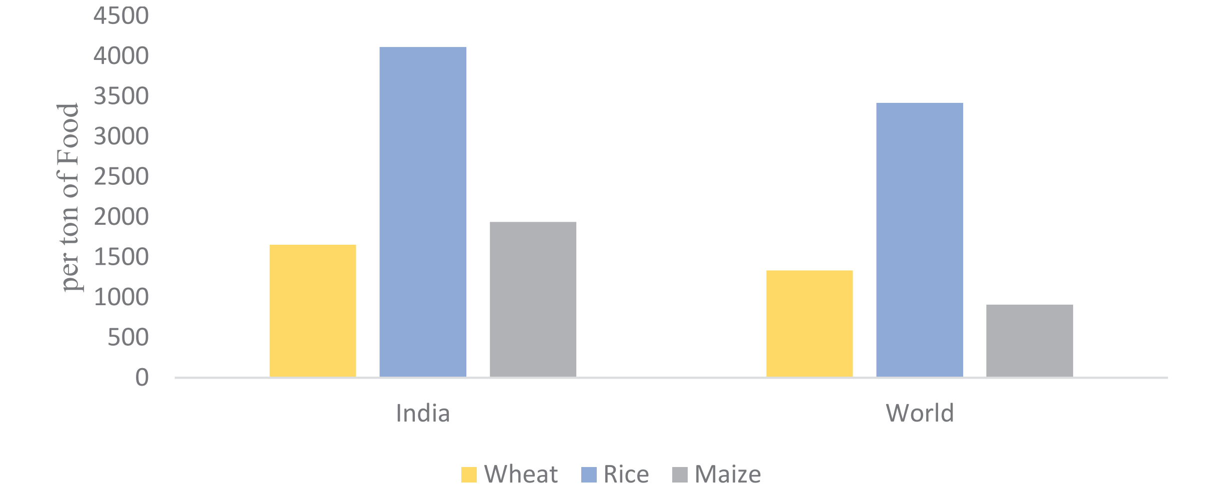

स्रोतः एफएओएसटीएटी, डब्ल्यूडीआई, यूनेस्को (पानी के लिए)

25 https://financialservices.gov.in/beta/en/agriculture-credit

26 संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) अनौपचारिक संघों के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें चार से दस व्यक्ति शामिल होते हैं, जो साझा गारंटी के तहत सामूहिक या व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से बैंक ऋण प्राप्त करने के सामान्य लक्ष्य से एकजुट होते हैं।

27 कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करने तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत जोखिम कवरेज के लिए संवेदनशील जिलों की पहचान करने के लिए उपयुक्त तंत्र की सिफारिश करने के लिए फसल व्यवहार्यता अध्ययन पर रिपोर्ट (2022)।

28 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मेगा जागरूकता अभियान के मूल्यांकन पर एक अध्ययन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (2023)।

बॉक्स: IX.1 पीएमएफबीवाई में हाल ही में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप

- **डिजी-क्लेम-पेमेंट मॉड्यूल:** राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी) को सार्वजनिक वित्तीयप्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ अंत-से-अंत तक एकीकृत करने के लिए एक नया मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। अब, सरकार को पात्र दावों की मात्रा, बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किए गए दावों और लाभार्थी किसानों को हस्तांतरित वास्तविक दावों की जानकारी होगी।
- **प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान (यस-तकनीक):** एक प्रौद्योगिकी-आधारित उपज अनुमान तंत्र है जिसे दो साल के कठोर परीक्षण और देश के 100 जिलों में चलने वाले पायलट के बाद विकसित किया गया है। नौ राज्य, अर्थात् असम, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक और ओडिशा, खरीफ 2023 सीजन से यस-तकनीक को लागू कर रहे हैं।
- **मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम (डब्ल्यूआईएनडीएस):** तालुक/ब्लॉक और ग्राम पंचायत (जीपी) स्तरों पर स्वचालित मौसम स्टेशनों और वर्षा गेज का एक नेटवर्क स्थापित करने की एक अग्रणी पहल है, जिसका उपयोग सभी किसान और खेती-उन्मुख सेवाओं के लिए किया जा सकता है। यह प्रस्तावित है कि पीएमएफबीवाई के तहत आने वाले प्रत्येक जीपी में एक स्वचालित वर्षा गेज (एआरजी) और प्रत्येक ब्लॉक में एक स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस) स्थापित किया जाए।
- **फसलो के वास्तविक समय के अवलोकन और तस्वीरों का संग्रह (क्रोपिक):** एक पहल है जो उनके जीवन चक्र के दौरान फसलों की आवधिक तस्वीरें एकत्र करने के लिए शुरू की गई है। ये तस्वीरें बोई गई और बीमित फसलों को मान्य करेंगी, किसी भी स्थानीय और व्यापक आपदा या जलवायु की स्थिति से नुकसान का आकलन करेंगी और प्रौद्योगिकी- आधारित उपज अनुमान मॉडल के लिए एक इनपुट के रूप में काम करेंगी।

कृषि विपणन-समृद्धि प्राप्त करना

9.16 एक व्यापक और विविधतापूर्ण विपणन नेटवर्क किसान को अपनी उपज को सबसे कुशलतापूर्वक और समय पर बाजार में लाने में सक्षम बनाता है। यह फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करता है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है और कीमतें खोजने की अनुमति देता है। विपणन योग्य अधिशेष में वृद्धि के साथ, कृषक समुदाय को बेहतर विपणन सुविधाएँ प्रदान करना और भी अधिक आवश्यक हो गया है। कृषि मूल्य विपणन समिति (एपीएमसी) में सरकारी खरीद सहित औपचारिक संस्थानों तक किसानों की पहुँच में देरी, बिचौलियों पर निर्भरता बढ़ाती है[29]।

9.17 देश में मंडियों द्वारा सेवा प्रदान किया जाने वाला औसत क्षेत्रफल 434.48 वर्ग किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय किसान आयोग (2006) ने 5 किलोमीटर के दायरे में विनियमित बाजार की आवश्यकता की सिफारिश की है (समरूपी बाजार क्षेत्र लगभग 80 वर्ग किलोमीटर है)। इसके अलावा, उपज को मंडियों तक ले जाने में भौतिक बाधाएं एक और कठिनाई पेश करती हैं, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए जिन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है[30]।

9.18 कृषि विपणन में दक्षता को बढ़ावा देने और मूल्य खोज में सुधार करने के लिए सरकार ने ई-एनएएम योजना को लागू किया। ई-नाम योजना के तहत, सरकार गुणवत्ता परखने वाले उपकरण और सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकेजिंग आदि के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित संबंधित हार्डवेयर के लिए प्रत्येक एपीएमसी मंडी को मुफ्त सॉफ्टवेयर और ₹75 लाख की सहायता प्रदान करती है। 14 मार्च, 2024 तक ई-नाम पोर्टल पर 1.77 करोड़ से अधिक किसान और 2.56 लाख व्यापारी पंजीकृत हो चुके हैं। भारत सरकार ने 2027-28 तक ₹6.86 हजार करोड़ के बजट परिव्यय के साथ 2020 में 10,000 एफपीओ बनाने और बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) शुरू की। 29 फरवरी 2024 तक, नई एफपीओ योजना के तहत 8,195 एफपीओ पंजीकृत हो चुके हैं और 3,325 एफपीओ को ₹157.4 करोड़ का इक्विटी अनुदान जारी किया गया। 1185 एफपीओ को ₹278.2 करोड़ रु. की क्रेडिट गारंटी कवर जारी किया गया था।

29 कृषि संबंधी स्थायी समिति (2018-19): कृषि विपणन और साप्ताहिक ग्रामीण हाटों की भूमिका, बासठवीं रिपोर्ट
30 सुधारों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विपणन के प्रभारी राज्य मंत्रियों की समिति की अंतिम रिपोर्ट (2013)

9.19 अध्ययनों ने ई-नाम[31] के प्रदर्शन और संभावनाओं का मूल्यांकन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि इस पहल का आम तौर पर किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी फसलों के लिए अधिक कीमत मिल सकी है और इस प्रकार इसका एक प्राथमिक उद्देश्य पूरा हुआ है। ई-नाम में भाग लेने वाले किसानों ने बताया कि कार्यान्वयन के बाद उन्हें अपनी फसलों के लिए अधिक कीमत मिली है। सर्वेक्षण किए गए राज्यों के लगभग 66 प्रतिशत किसानों ने गुणवत्ता परीक्षण प्रक्रियाओं को पारदर्शी पाया[32]। गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में किसानों के एक महत्वपूर्ण अनुपात (क्रमशः 82 प्रतिशत, 79 प्रतिशत, 64 प्रतिशत और 89 प्रतिशत) ने बेहतर मूल्य निर्धारण और कम लेनदेन लागत देखी। कुल मिलाकर, किसानों ने सफाई, सुखाने, वजन, परख, बोली प्रबंधन और ई-नीलामी सहित ई-नाम सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया। इसी तरह, यह देखा गया है कि 54 प्रतिशत किसान इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाले कई लाभों के कारण पारंपरिक बाजारों की तुलना में ई-नाम पोर्टल के माध्यम से लेनदेन करना पसंद करते हैं[33]। ई-एनएएम के कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, जैसे सीमित जागरूकता, विश्वास की कमी और परख सुविधाएं स्थापित करने से संबंधित बुनियादी ढांचे संबंधी समस्याएं।

बॉक्स IX.2: भारत में कृषि जिंसों के लिए भावी बाजार

वस्तुओं में वायदा बाजार की स्थापना इस मान्यता से प्रेरित थी कि कृषि उत्पादों का उत्पादन काफी हद तक मौसमी था और विभिन्न जोखिमों के अधीन था, जबकि उपभोग ऐसा नहीं था। वायदा बाजार एक तंत्र के रूप में कार्य करता है जो भविष्य के उत्पादन और उपभोग की संभावनाओं को तार्किक तरीके से आज की कीमत को प्रभावित करने के लिए लाता है। यह प्रक्रिया, अन्य बातों के अलावा, वर्तमान और भविष्य के उत्पादन और उपभोग चक्रों के बीच एक कड़ी स्थापित करती है, जिससे कीमतों के अंतर-कालिक समतलीकरण की सुविधा मिलती है। वायदा बाजार की यह समझ भारतीय कृषि जिंस बाजारों के विकास और वर्तमान स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण है (भट्टाचार्य, 2007)।

विकास: भारतीय कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार का एक लंबा इतिहास है। 1940 के दशक के दौरान भारत में लगभग 300 कमोडिटी एक्सचेंज थे। 1952 तक, इन एक्सचेंजों में व्यापार किसी मानक नीति या बाजार नियामक द्वारा विनियमित नहीं था। स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने 1952 का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स (विनियमन) अधिनियम बनाया और 1953 में नियामक के रूप में कार्य करने के लिए फॉरवर्ड मार्केट कमीशन (एफएमसी) की स्थापना की। 1966 में, मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए वायदा कारोबार पर व्यापक प्रतिबंध लगाया गया था। अलग-अलग समय पर, भारत सरकार ने कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग को फिर से शुरू करने की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए अलग-अलग समितियों की नियुक्ति की।

भारत में कृषि वायदा कारोबार को 2003 में राष्ट्रीय कमोडिटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स), मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) और नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एनएमसीई) जैसे राष्ट्रीय एक्सचेंजों की स्थापना के साथ एक बड़ा पुनरुद्धार मिला। भारतीय कमोडिटी विनियामक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण विकास 2015 में हुआ जब भारत सरकार ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1952 (एफसीआरए) को निरस्त कर दिया और कमोडिटी डेरिवेटिव बाजारों को सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट (एससीआरए), 1956 के तहत लाया गया

31 नुथलापति, सी.एस.आर. (2020)। आर्थिक विकास संस्थान। एक्सेस करने के लिए लिंक
https://desagri.gov.in/wp-content/uploads/2024/04/2020-21-Electronic-National-Agricultural-Market-e-NAM-A-Review-of-Performance-and-Prospects.pdf
शाह, बी एट अल (2023)। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम): गेम चेंजिंग मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की समीक्षा। https://www.researchgate.net/publication/374975907_Electronic_National_Agriculture_Market_e-NAM_A_Review_of_the_game_changing_Marketing_Platform तक पहुंचने के लिए लिंक
ई-नेशनल
कृषि बाजार का प्रदर्शन मूल्यांकन (2020) सीसीएस राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान: पहुंचने के लिए लिंक: https%@@ccsniam-gov-in@images@pdfs@Evaluation.pdf

32 https://desagri-.gov.in/wp-content/uploads/2024/04/2020-21-Electronic-National-Agricultural-Market-e-NAM-A-Review-of-Performance-and-Prospects.pdf

33 https://ccsniam.gov.in/images/pdfs/Evaluation.pdf

था, जिसमें सितंबर, 2015 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने फॉरवर्ड मार्केट कमीशन से कमोडिटी मार्केट रेगुलेटर का कार्यभार संभाला था। समानांतर में, इलेक्ट्रॉनिक किसानों को कृषि उपज के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन बाजार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) की शुरुआत की गई थी। वस्तुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट बाजार स्थानीयकृत भौतिक बाजारों को एकीकृत करने, खरीदार और विक्रेता के बीच सीधा संबंध स्थापित करने और एक पारदर्शी मूल्य खोज तंत्र प्रदान करने में महत्वपूर्ण है।

वर्तमान स्थिति: कमोडिटी वायदा बाजार मूल्य खोज में प्रभावी रूप से तभी योगदान दे सकता है जब कई उपभोक्ता, उत्पादक, व्यापारी और एग्रीगेटर अपने जोखिम को कम करने के लिए इन बाजारों का उपयोग करते हैं। इन प्रतिभागियों, सट्टेबाजों और मध्यस्थों के परस्पर क्रिया से तरलता मिलती है और लंबी अवधि के लिए मूल्य खोज में मदद मिलती है। हालाँकि, यह देखते हुए कि अधिकांश भारतीय किसान खंडित भूमि जोत के साथ सीमांत हैं, उन्हें अक्सर इन बाजारों में प्रभावी रूप से शामिल होने/भाग लेने के लिए आवश्यक साधन के बिना छोड़ दिया जाता है, जिससे भारतीय कमोडिटी वायदा बाजार में गहराई कम हो जाती है। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि निर्दिष्ट गुणवत्ता मापदंडों और डिलीवरी आवश्यकताओं के साथ मानकीकृत विनिमय अनुबंधों की आवश्यकता ने भी अधिकांश भारतीय किसानों को कमोडिटी वायदा बाजार में प्रभावी रूप से शामिल होने से रोक दिया है क्योंकि भारतीय किसान विभिन्न भौगोलिक, मौसम और मिट्टी की स्थितियों के कारण व्यापक रूप से अलग-अलग गुणवत्ता वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त, खाद्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के उपायों में से एक के रूप में कृषि-वस्तुओं पर वायदा कारोबार पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए आवधिक प्रतिबंधों ने भी भारतीय कमोडिटी और डेरिवेटिव एक्सचेंजों में कारोबार मूल्य और मूल्य मात्रा पर प्रभाव डाला है।

आगे की राह: अध्ययनों से पता चलता है कि कृषि-वायदा पोर्टफोलियो के अनुक्रमिक विविधीकरण के माध्यम से भारतीय कमोडिटी बाजार को मजबूत किया जा सकता है। जैसा कि 2008 की अभिजीत सेन समिति की रिपोर्ट में बताया गया है, ष्संदेह के लाभ के साथ विवेक को जोड़ते हुए, सबसे अच्छा तरीका उन वस्तुओं की पहचान करना होगा जहां वायदा कारोबार की संभावना है जो आवश्यक वस्तुओं में मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकती है और उन्हें वायदा से अलग कर सकती है।ष संवेदनशील वस्तुओं (जैसे, सामान्य चावल, गेहूं, अधिकांश दालें, आदि) को वायदा बाजार के दायरे से बाहर रखा जा सकता है जब तक कि बाजार विकसित न हो जाएं और नियामक को पोर्टफोलियो में विविधता लाने में अधिक सहजता न हो। कृषि वायदा बाजार कम संवेदनशील वस्तुओं जैसे तिलहन कॉम्प्लेक्स (तिलहन, भोजन और तेल), चारा (मक्का), कपास, बासमती चावल, मसाले आदि पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

कमोडिटी डेरिवेटिब्स बाजार को व्यापक बनाने के लिए हाल की नीतिगत पहलों के हिस्से के रूप में, भारत सरकार ने 1 मार्च, 2024 को डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए पात्र कमोडिटीज की सूची को 91 से बढ़ाकर 104 कर दिया है। सूची में शामिल की गई नई कमोडिटीज में सेब, काजू, लहसुन, स्किम्ड मिल्क पाउडर, सफेद मक्खन, मौसम, प्रसंस्कृत लकड़ी उत्पाद, प्रसंस्कृत बांस उत्पाद आदि शामिल हैं।

एक बार जब नियामक वस्तुओं के चयन के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं, तो उन्हें न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ एक स्थिर नीति अपनाकर अपने रास्ते पर बने रहना चाहिए। किसान उत्पादक संगठन भारत में छोटे और बिखरे हुए किसानों और कमोडिटी बाजार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावी ढंग से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देश भर में कृषि-वस्तुओं के विभिन्न क्षेत्रों में एफपीओ को बढ़ावा देने में सरकार, सेबी और कमोडिटी एक्सचेजों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वित्तीय साक्षरता पहल के माध्यम से एफपीओ को कौशल प्रदान करना और उनका समर्थन करना किसानों को कृषि-व्युत्पन्न बाजारों से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने में काफी मदद कर सकता है। जैसे-जैसे लंबे संमय में कृषि-व्युत्पन्न बाजार में गहराई और तरलता बढ़ती है, कीमतों को स्थिर करने के लिए वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाने की अब आवश्यकता नहीं हो सकती है, जब तक कि वायदा कारोबार से मूल्य में अस्थिरता बढ़ने के डेटा समर्थित सबूत न हो। घरेलू उत्पादन, खपत और वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए नियामक को वायदा बाजार पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए और नियमित समीक्षा करनी चाहिए।

सुनिश्चित लाभकारी मूल्य और अन्य आय सहायता उपाय

9.20 कृषि मूल्य समर्थन किसानों को लाभकारी रिटर्न का आश्वासन देता है और सरकार को उचित मूल्य पर स्टेपल की एक समान आपूर्ति सुनिश्चित करने की अनुमति देता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एक ऐसा कारक है जिसे किसान बुवाई

का निर्णय लेते समय ध्यान में रखते हैं। भारत में, सरकार ने खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और पोषक अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्य नीतियों को लागू किया है। ये नीतियां किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी देकर सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई हैं, इस प्रकार उन्हें बाजार की कीमतों की अस्थिरता से बचाती हैं। 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई थी कि भारत में किसानों को उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना एमएसपी दिया जाएगा। तदनुसार, सरकार कृषि वर्ष 2018-19 से उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत के मार्जिन के साथ सभी 22 खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी बढ़ा रही है।

चार्ट IX.6: 2021-22 से 2023-24 तक प्रमुख फसलों का एमएसपी

स्रोतः कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी)

9.21 किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक और पहल पीएम-किसान है - यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे कुछ अपवादों के अधीन 24 फरवरी, 2019 को भूमि-धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में तीन बराबर चार-मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6000/- का आर्थिक लाभ हस्तांतरित किया जाता है। 10 जुलाई, 2024 तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को ₹3.24 लाख करोड़ से अधिक की राशि जारी किए जा चुके हैं।

9.22 सबसे कमजोर किसान परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सरकार प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) को लागू करती है। यह योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर नामांकित किसानों को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है, जो आवेदक (18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में) द्वारा भुगतान किए गए 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के बीच मामूली प्रीमियम पर आधारित है, जो अपवर्जन मानदंडों के अधीन है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, 07 जुलाई, 2024 तक, 23.41 लाख किसानों ने इस योजना के तहत नामांकन किया है।

कृषि मशीनीकरण-कृषि को सशक्त बनाना

9.23 साधारण हाथ के औजारों से लेकर अधिक जटिल मशीनरी को कवर करने वाला कृषि यंत्रीकरण आधुनिक कृषि के लिए आवश्यक हो गया है और उत्पादकता में योगदान देता है। यह देखते हुए कि भारत में अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं, कस्टम हायरिंग के माध्यम से मशीनरी प्रदान करने से इन किसानों के बीच और उन क्षेत्रों में कृषि मशीनीकरण को अपनाया जा सकता है जहाँ मशीनीकरण का स्तर वर्तमान में कम है। कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम) राज्य सरकार को कृषि मशीनरी के प्रशिक्षण और प्रदर्शन, कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करता है। 2014-15 से 2023-24 तक एसएमएएम के तहत आवंटित कुल धनराशि ₹7.26 हजार करोड़ थी। 2023-24 में आवंटन ₹859.45 करोड़ था। इसके अलावा, फार्म मशीनरी बैंक छोटे और सीमांत कृषि जोतों और कम मशीनीकरण वाले चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों के तहत कृषि जोतों के लिए उच्च तकनीक वाली मशीनरी तक पहुँच को

बढ़ावा देते हैं। 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान, इस योजना के तहत 25,527 सीएचसी स्थापित किए गए, और 2023-24 में 607 सीएचसी स्थापित किए गए।

कृषि को संधारणीय बनाना

9.24 कृषि में बढ़ती चुनौती संधारणीयता के मुद्दों से संबंधित है जैसे अतिदोहन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर ध्यान करना। उपयोग की जाने वाली कृषि पद्धतियों और इनपुट का भी संधारणीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए उर्वरक और रसायनों का बढ़ता उपयोग, अत्यधिक दोहन और जल संसाधनों का असंवहनीय उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता को प्रभावित करता है। मौसम की स्थिति में परिवर्तनशीलता और वर्षा आधारित कृषि की सापेक्षिक प्रबलता भी उत्पादन और उत्पादकता को प्रभावित करती है। कृषि में स्थिरता भूमि जोतों की दीर्घकालिक उत्पादकता को सुरक्षित रखने, पर्याप्त कृषि-आधारित आय और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में से 11 सीधे कृषि से जुड़े हैं, इसलिए फसल की पैदावार में सुधार सुनिश्चित करना और आय स्थिरता सुनिश्चित करना देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एजेंडा 2030 लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

9.25 सरकार द्वारा किया गया जलवायु परिवर्तन प्रभाव का मूल्यांकन इस क्षेत्र में अनुकूलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अनुकूलन उपायों को अपनाने के अभाव में, भारत में वर्षा आधारित चावल की पैदावार 2050 में 20 प्रतिशत और 2080 के परिदृश्यों में 47 प्रतिशत घटने का अनुमान है, जबकि सिंचित चावल की पैदावार 2050 में 3.5 प्रतिशत और 2080 के परिदृश्यों में 5 प्रतिशत घटने का अनुमान है। जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 में गेहूं की पैदावार में 19.3 प्रतिशत और 2080 के परिदृश्यों में 40 प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है[34]।

9.26 जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का एक हिस्सा, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक लचीला बनाने के लिए रणनीतियों को विकसित करना और उन्हें लागू करना है। बदलती जलवायु के सामने सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि कृषि भूमि को सुनिश्चित सिंचाई मिले। इस संदर्भ में, उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एनएमएसए के तहत कार्यान्वित वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी) प्रासंगिक है। ₹1.74 हजार करोड़ की राशि जारी की गई है और आरएडी कार्यक्रम के तहत 7.33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), जिसमें दो प्रमुख घटक, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) शामिल हैं, सिंचाई और जल दक्षता के तहत क्षेत्रों के विस्तार को बढ़ावा देते हैं। सिंचाई क्षेत्र कवरेज 2015-16 में सकल फसली क्षेत्र (जीसीए) के 49.3 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 55 हो गया। इसी तरह, सिंचाई तीव्रता (सकल सिंचित क्षेत्र और शुद्ध सिंचित क्षेत्र का अनुपात) में 10.3 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जो 2015-16 में 144.2 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में लगभग 154.5 प्रतिशत हो गई, जबकि इस अवधि के दौरान फसल तीव्रता में 12.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई[35]। सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज का विस्तार करने के लिए संसाधन जुटाने में राज्यों की सुविधा के लिए नाबार्ड के साथ 5 हजार करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि का एक लघु सिंचाई कोष (एमआईएफ) भी बनाया गया है। इसके अलावा, पीडीएमसी योजना लघु स्तर पर जल संचयन, भंडारण, प्रबंधन आदि का भी समर्थन करती है। 6 फरवरी 2024 तक 2015-16 से 2023-24 तक पीडीएमसी के तहत देश में लघु सिंचाई के तहत 90.0 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।[36]

34 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1909206

35 खरीफ मूल्य नीति 2024-25 पर सीएसीपी की रिपोर्ट

36 पूर्वोक्त

बॉक्स IX.3: जल प्रबंधन में सुधार के लिए नीतिगत हस्तक्षेप-राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव[37]

सिंचाई प्रणाली का स्वचालन: नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर प्रणाली (कर्नाटक)

कर्नाटक में नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर (एनएलबीसी) प्रणाली अपर्याप्त जल विनियमन, गेटों का मैनुअल नियंत्रण और असमान जल वितरण जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही थी। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए, सरकार ने एक स्वचालन प्रणाली लागू की जिसमें 4,000 से अधिक स्वचालित नियंत्रण और विनियमन द्वार, सौर ऊर्जा से चलने वाले एकीकृत द्वार और एक मास्टर वीएसएटी संचार प्रणाली शामिल थी। इन हस्तक्षेपों ने जल उपयोग दक्षता को अनुकूलित किया है, समान वितरण में सुधार किया है और क्षेत्र में समग्र कृषि उत्पादकता को बढ़ाया है।

डायवर्सन-आधारित सिंचाई प्रणाली

मध्य प्रदेश के बड़वानी और खरगोन जिलों के पहाड़ी और उतार-चढ़ाव वाले क्षेत्रों में, आगा खान ग्रामीण सहायता कार्यक्रम (एकेआरएसपी) ने डायवर्सन-आधारित सिंचाई (डीबीआई) प्रणालियों के विकास की पहल की है। ये प्रणालियाँ धाराओं से कृषि क्षेत्रों में पानी को मोड़ने के लिए गुरुत्वाकर्षण प्रवाह का उपयोग करती हैं। 2016 से अब तक 13 डीबीआई सिस्टम चालू हो चुके हैं, जिससे 111 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अंतर्गत आ गई है और 93 किसानों को लाभ हुआ है। इन सिस्टम की लागत-प्रभावी प्रकृति, जिसके लिए प्रति रनिंग मीटर लगभग 300 रुपये की आवश्यकता होती है, उन्हें पहाड़ी इलाकों में सिंचाई कवरेज बढ़ाने के लिए एक व्यवहार्य समाधान बनाती है।

हाइड्रोपोनिक्स में वर्टिकल फार्मिंग का उपयोग करके बिना मिट्टी के टमाटर उगाना

हाइड्रोपोनिक्स के साथ वर्टिकल फार्मिंग मिट्टी के बिना टमाटर की खेती की अनुमति देती है, जिससे अंतरिक्ष दक्षता, कम पानी का उपयोग और साल भर उत्पादन जैसे कई लाभ मिलते हैं। इस पद्धति को पोर्ट ऑगस्टा फार्म, साउथ ऑस्ट्रेलिया में लागू किया गया है, जिसमें 51,500 वर्ग मीटर के केंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा संचालित 4.5 हेक्टेयर का ग्रीनहाउस है। इस संयंत्र में 23,000 दर्पण शामिल हैं जो 234 टन वजन वाले 127 मीटर ऊंचे टॉवर पर सीधे सूर्य की रोशनी डालते हैं। उत्पन्न ऊष्मा तीन उद्देश्यों को पूरा करती है: 20 हेक्टेयर ग्रीनहाउस में इष्टतम तापमान बनाए रखना, टर्बाइन के माध्यम से बिजली पैदा करके कृषि प्रणालियों को बिजली देना और पास के स्पेंसर खाड़ी से खींचे गए समुद्री जल को विलवणीकरण करना। यह फार्म 3 किलोमीटर दूर से समुद्री जल को विलवणीकरण करके प्रतिदिन एक मिलियन लीटर ताजा पानी पैदा करता है। यह शुष्क भूमि पर सालाना 7,000 टन टमाटर उगाता है, जो ऑस्ट्रेलिया की कुल फसल का 15 प्रतिशत है। इसके अलावा, 180,000 टमाटर मिट्टी के बिना ढेर में हाइड्रोपोनिक रूप से उगाए जाते हैं, जिससे 2 मिलियन लीटर डीजल की बचत होती है और पारंपरिक खेती के तरीकों की तुलना में CO_2 उत्सर्जन में 15,000 टन की कमी आती है।

इस विधि में पौधों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित पोषक तत्वों से भरपूर पानी के घोल में उगाना शामिल है। शहरी क्षेत्रों में वर्टिकल हाइड्रोपोनिक प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, जिससे परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है और स्थानीय रूप से प्राप्त ताजा उपज की पेशकश की जा सकती है।

मध्य टिस्ज़ा नदी बेसिन में कृषि क्षेत्रों में अस्थायी बाढ़ जल भंडारण

मध्य टिस्ज़ा नदी बेसिन में, कृषि क्षेत्रों में अस्थायी बाढ़ जल भंडारण का उपयोग बाढ़ के जोखिम को कम करने और अतिरिक्त सिंचाई प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। विशिष्ट कृषि क्षेत्रों में अतिरिक्त बाढ़ के पानी को संग्रहीत करके, क्षेत्र जल स्तर को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता है, जिससे नीचे की ओर बाढ़ का जोखिम कम हो जाता है। यह विधि न केवल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करती है, बल्कि बाढ़ के पानी से पोषक तत्वों को जमा करके मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार करती है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है।

ये हस्तक्षेप विशिष्ट क्षेत्रीय चुनौतियों को अनुकूलित समाधानों के साथ संबोधित करते हुए नवीन जल प्रबंधन और कृषि उत्पादकता के दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं।

37 जल प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं का संग्रह नीति आयोग (2023): पहुंच के लिए लिंक; https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-08/COMPENDIUM-OF-BEST-PRACTICES-IN-WATER-MANAGEMENT-3-0_Water-Resources-Vertical_2_8_23.pdf

9.27 हस्तक्षेप का एक अन्य क्षेत्र भारतीय कृषि में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने पर केंद्रित है। हालांकि भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि रसायनों का उपयोग अधिकांश विकसित देशों की तुलना में काफी कम है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ा है[38]। वास्तव में, यहां यह ध्यान देने योग्य है कि मौजूदा सब्सिडी संरचना ने यूरिया के बढ़ते उपयोग में योगदान दिया है, जिसने प्रमुख पौधों के पोषक तत्वों, नाइट्रोजन-फास्फोरस-पोटेशियम (एनपीके) के उपयोग में पोषक असंतुलन को प्रभावित किया है, जिससे उर्वरक उपयोग की दक्षता, मिट्टी और उत्पादन की गुणवत्ता[39] और पर्यावरण प्रभावित हुआ है। सभी प्रमुख पोषक तत्वों (एन,पी,के) का समर्थन करने के लिए सब्सिडी नीतियों को संशोधित करने से किसानों को अधिक संतुलित दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। जबकि संरचना महत्वपूर्ण है इसलिए अनुप्रयोग की मात्रा भी महत्वपूर्ण है। किसानों के बीच ज्ञान और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से, कई राज्यों में 1.79 लाख से अधिक ड्रोन के साथ सटीक उर्वरक आवेदन को प्रशासित करने के लिए प्रदर्शन किए गए।

9.28 मातृभूमि के पुनरुद्धार, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम) पहल राज्यों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और जैविक उर्वरक जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग जैसे संधारणीय तरीकों को बढ़ावा देता है। उक्त योजना के तहत किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किसी विशेष वित्तीय वर्ष में पिछले तीन वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत में कमी के माध्यम से बचाई गई उर्वरक सब्सिडी का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को दिया जाएगा। इन पहलों के अलावा, पोषक तत्वों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। "यूरिया गोल्ड" की शुरूआत, जो सल्फर की कमी को दूर करने के लिए सल्फर युक्त यूरिया है, मिट्टी में पोषक तत्व संतुलन को बेहतर बनाने का एक और उपाय है।

9.29 जैविक और प्राकृतिक खेती रसायन मुक्त उर्वरक और कीटनाशक मुक्त खाद्यान्न और अन्य फसलें प्रदान करती है, जिससे मिट्टी की सेहत में सुधार होता है और पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। 2022-23 तक लगभग 68.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया। सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया और त्रिपुरा और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों ने भी इसी तरह के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सरकार 2015 से क्लस्टर/एफपीओ गठन के माध्यम से दो समर्पित योजनाओं, यानी परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) को लागू करके जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। पीकेवीवाई योजना को क्लस्टर मोड में लागू किया जा रहा है (न्यूनतम 20 हेक्टेयर आकार के साथ) । तीन वर्षों के लिए प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें से 15,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से सीधे प्रदान किए गए जैविक इनपुट के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। पीकेवीवाई के तहत, 2022-23 तक, कुल 13.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 48,144 क्लस्टर और 24.22 लाख किसान शामिल किए जा चुके हैं।

बॉक्स IX.4: लचीला, किसान-हितैषी और पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ उर्वरक सब्सिडी: आगे बढ़ने का सुझाया गया तरीका

रासायनिक और उर्वरकों पर लोकसभा की स्थायी समिति ने 29 मार्च, 2023 को प्रस्तुत अपनी उनतालीसवीं रिपोर्ट, जिसका शीर्षक था 'टिकाऊ फसल उत्पादन और मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए नैनो-उर्वरक', में निम्नलिखित मुद्दे की तात्कालिकता को रेखांकित किया: "भारत में उर्वरक की खपत असंतुलित है और अधिकांश फसलों में इस्तेमाल किए जाने वाले नाइट्रोजन उर्वरकों में यूरिया का हिस्सा 82 प्रतिशत से अधिक है। परिणामस्वरूप, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैशियम (एनपीके) की खपत का अनुपात 2009-10 में 4:3.2:1 से बढ़कर 2019-20 में 7:2.8:1 हो गया है।" यह असंतुलन, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को जन्म देता है, जिससे कृषि में यूरिया सब्सिडी प्रबंधन की तत्काल पुन: जांच करने की आवश्यकता है साथ ही दीर्घावधि में स्थिरता के पहलुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।

38 चंद, आर., और सिंह, जे. (2023)। हरित क्रांति से अमृत काल तक। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, भारत सरकार।

39 https://www.epw.in/journal/2023/52/letters/nutrition-imbalance-india.html

भारत में उर्वरक सब्सिडी का वर्तमान स्वरूप: प्रत्येक राज्य[40] द्वारा गणना की गई पोषक तत्वों की अनुशंसित खुराक (आरडीएन) के आधार पर, भारत सरकार उर्वरक की अनुशंसित खुराक (आरडीएफ) की गणना करती है और प्रत्येक मौसम के लिए राज्यों को उर्वरक आवंटित करती है। बदले में, राज्य पीओएस उपकरणों का उपयोग करके डीलरों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उर्वरक बेचते हैं। किसानों को बेचे गए उर्वरकों की मात्रा के आधार पर उर्वरक विभाग उर्वरक कंपनियों को उर्वरक सब्सिडी का भुगतान करता है। हालाँकि, वर्तमान डिजाइन के साथ कुछ गंभीर मुद्दे हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- उर्वरक दुकानों पर पीओएस डिवाइस भूमि रिकॉर्ड डेटा के साथ एकीकृत नहीं हैं
- आधार रखने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसान हो या न हो, कितनी भी मात्रा में उर्वरक खरीद सकता है
- एक व्यक्ति या एक परिवार को उर्वरक की बिक्री पर कोई सीमा नहीं
- प्रतिकूल वित्तीय और पारिस्थितिक प्रभाव जैसे कि सब्सिडी वाले उर्वरक को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए डायवर्ट करना; उर्वरकों का अधिक प्रयोग जो मृदा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है; उर्वरक की कमी; सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी और स्वास्थ्य संबंधी खतरे।

उर्वरक सब्सिडी के लक्ष्यीकरण में सुधार के लिए एग्री स्टैक का उपयोग करना: एग्री स्टैक सरकार द्वारा स्थापित डिजिटल नींव है, जो भारत में कृषि को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना आसान बनाती है और डेटा और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करके किसानों के लिए बेहतर परिणाम और नतीजे सक्षम करती है। यह अब प्रमुख भारतीय राज्यों में काफी विकसित है और सही माध्यम प्रदान कर सकता है जिसके माध्यम से उर्वरक सब्सिडी को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि सब्सिडी वाले उर्वरक केवल उन लोगों को बेचे जाएं जिन्हें किसान के रूप में पहचाना जाता है या किसान द्वारा अधिकृत किया जाता है और सब्सिडी वाले उर्वरक की मात्रा भूमि स्वामित्व और जिले की प्रमुख फसलों (एक सीजन में बोए गए क्षेत्र का कम से कम 70 प्रतिशत) जैसे मापदंडों के आधार पर तय की जाती है। बाद में, उगाई गई फसल और मृदा पोषकता की स्थिति (भारत सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अनुरूप) के आधार पर मापदंडों को परिष्कृत किया जा सकता है तथा एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के अनुरूप, मौसम की स्थिति में अस्थिरता के कारण फसल क्षति या आपदाओं के मामले में टॉप-अप पात्रता प्रदान करने के प्रावधान किए जा सकते हैं।

ई-रुपी, एक सहज एकमुश्त भुगतान प्रणाली है, जिसका उपयोग किसान को सीधे आवश्यक सब्सिडी प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सब्सिडी का उपयोग केवल अधिकृत उर्वरक दुकानों पर पंजीकृत पीओएस उपकरणों के माध्यम से किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई किसान अपनी पात्रता से कम मात्रा में उर्वरक खरीदता है। उस स्थिति में, शेष सब्सिडी का उपयोग अन्य कृषि इनपुट, जैसे बीज और कीटनाशक खरीदने के लिए किया जा सकता है, जो इन दुकानों पर भी बेचे जाते हैं। वर्ष के अंत में किसी भी अप्रयुक्त सब्सिडी को किसान के नाम पर डाकघर में एक छोटी बचत साधन में परिवर्तित किया जा सकता है। यह प्रणाली न केवल सब्सिडी वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है बल्कि गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए सब्सिडी के दुरुपयोग को भी रोकती है। इससे किसान को अन्य एनपीके उर्वरकों की तुलना में सस्ता होने के कारण अत्यधिक यूरिया का उपयोग नहीं करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और फसल और मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों का संतुलित उपयोग हो सकता है।

नए तंत्र की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कुछ मूलभूत पहलुओं की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार होंगे:

- एग्री स्टैक में किसान रजिस्ट्री के साथ पीओएस उपकरणों का एकीकरण और किसान रजिस्ट्री में प्रत्येक किसान का आधार नंबर, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (आरओआर) के अनुसार किसान के स्वामित्व वाली सभी कृषि भूमि का विवरण और म्यूटेशन मॉड्यूल के माध्यम से भूमि स्वामित्व डेटा का गतिशील अद्यतन शामिल होगा

40 आर.डी.एन. की गणना प्रत्येक राज्य द्वारा उगाई गई फसलों और मृदा पोषकता की स्थिति के आधार पर की जाती है।

- परिवार के सदस्यों और सब्सिडी वाले उर्वरक खरीदने के लिए अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के नाम, आधार संख्या और अन्य विवरण शामिल करने की सुविधा
- किसानों, परिवार के सदस्यों और अधिकृत व्यक्तियों के बैंक विवरण, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण अपडेट करने की सुविधा
- डिजिटल फसल सर्वेक्षण के आधार पर फसल बोई गई रजिस्ट्री को बाद के चरण में एकीकृत किया जाएगा

आगे की राह

अन्य देशों में उर्वरक संबंधी अनुप्रयोगों में सुधार किए गए हैं, जहाँ उर्वरक की आवश्यकता मानक मानदंडों पर आधारित है। भारत में, चूंकि इसमें प्रतिमान बदलाव शामिल है और उर्वरक एक संवेदनशील विषय है, इसलिए कुछ राज्यों के एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट चलाना समझदारी भरा हो सकता है, जहां अपेक्षाकृत मजबूत और अच्छी तरह से विकसित कृषि-स्टैक प्रणाली हैं। इन पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर, सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए उर्वरक सब्सिडी प्रशासन के भविष्य के तरीके पर निर्णय लिया जा सकता है।

9.30 सरकार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के वायु प्रदूषण को दूर करने के प्रयासों में सहायता प्रदान करने और फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए 2018-19 से फसल अवशेष प्रबंधन योजना लागू कर रही है। इस योजना के तहत, किसानों के खेतों पर बायो-डीकंपोजर के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है, जो फंगल प्रजातियों का एक माइक्रोबियल संघ है जो धान के भूसे के इन-सीटू अपघटन को तेज करता है। 2023 की अवधि के दौरान, राज्यों द्वारा लगभग 7.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बायो-डीकंपोजर का उपयोग किया गया था। 2018-19 से 2023-24 की अवधि के दौरान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के एनसीटी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) आदि जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों को 3.34 हजार करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। राज्यों ने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के 40,000 से अधिक सीएचसी स्थापित किए हैं और इन राज्यों में इन सीएचसी और व्यक्तिगत किसानों को 2.95 लाख से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें आपूर्ति की गई हैं। धान की पराली के इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन के लिए सरकार की इन पहलों के माध्यम से, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में धान की पराली जलाने की घटनाएँ 2023 की अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत कम रहीं।

बॉक्स IX.5: डिजिटल कृषि: डिजिटल क्रांति का मार्ग

भारत का कृषि क्षेत्र डिजिटल प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है। डिजिटल कृषि मिशन 2021-2025 का उद्देश्य एआई, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन आदि जैसी उन्नत तकनीकों के माध्यम से कृषि को आधुनिक बनाना है। इसके अलावा, 2023-24 के बजट घोषणा के अनुसार, सरकार ने कृषि के लिए एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर-संचालन योग्य सार्वजनिक वस्तु के रूप में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) बनाने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। डीपीआई फसल नियोजन और स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक सूचना सेवाओं, कृषि इनपुट, ऋण और बीमा तक बेहतर पहुँच, फसल आकलन के लिए सहायता, बाजार की जानकारी और कृषि-तकनीक उद्योग और स्टार्ट-अप के विकास के लिए समर्थन के माध्यम से समावेशी, किसान-केंद्रित समाधान सक्षम करेगा।

एग्री स्टैक तीन मूलभूत रजिस्ट्री (डेटाबेस) यानी किसानों की रजिस्ट्री/डेटाबेस, भू-संदर्भित गांव के नक्शे और फसल बोई गई रजिस्ट्री/डेटाबेस के साथ-साथ कई सहायक रजिस्ट्री/डेटाबेस के साथ प्रमुख डीपीआई में से एक है। 3 मूलभूत रजिस्ट्री किसान आईडी, जियो-टैग किए गए खेत के भूखंड और बोई गई फसल के डेटा के रूप में किसान के लिए डिजिटल रूप से प्रामाणिक पहचान और गैर-अस्वीकार्य डिजिटल संपत्ति सक्षम करेगी। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (कृषि-डीएसएस) एक अन्य डीपीआई है, जिसका उद्देश्य प्रासंगिक भू-स्थानिक और गैर-भू-स्थानिक डेटा, जैसे रिमोट-सेंसिंग डेटा, मौसम डेटा, मिट्टी डेटा, क्रॉप सिग्नेचर लाइब्रेरी, जलाशय डेटा, भूजल डेटा और सरकारी योजनाओं से संबंधित डेटा को एक मानकीकृत रूप में एकीकृत और संग्रहीत करना है।

इसके अलावा, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अन्य पहल की गई हैं, जैसे (i) कृषि मैपर – सभी भूमि-आधारित योजनाओं के लिए एक भू-स्थानिक मोबाइल एप्लिकेशन, जो सर्वेक्षण/निरीक्षण के वर्तमान स्थान से जियो-टैग की गई तस्वीरों को शामिल करते हुए जियो-फेंसिंग (बहुभुज निर्माण / अक्षांश-देशांतर) कैप्चर को सक्षम बनाता है, (ii) व्यापक मृदा उर्वरता और प्रोफाइल मानचित्रण – उपयुक्त मृदा स्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेपों के लिए, (iii) डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण – यादृच्छिक रूप से चयनित भूखंडों पर फसल कटाई प्रयोगों के माध्यम से फसल की पैदावार को सटीक रूप से मापता है।

भारत में डिजिटल कृषि की दिशा में आगे बढ़ने को एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन प्राप्त है, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 1,000 से अधिक कृषि-तकनीक स्टार्टअप के समर्थन की कल्पना करता है। 9 फरवरी 2024 तक, 387 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप सहित 554 कृषि-स्टार्टअप कृषि और संबद्ध क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

संबद्ध क्षेत्र: पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन महत्वपूर्ण विकास उत्प्रेरक हैं

9.31 भारतीय कृषि के संबद्ध क्षेत्र लगातार मजबूत विकास केंद्रों और कृषि आय में सुधार के आशाजनक स्रोतों के रूप में उभर रहे हैं। 2014-15 से 2022-23 तक, पशुधन क्षेत्र स्थिर कीमतों पर 7.38 प्रतिशत की प्रभावशाली चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कुल जीवीए (स्थिर मूल्यों पर) में पशुधन का योगदान 2014-15 में 24.32 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 30.38 प्रतिशत हो गया। 2022-23 में, पशुधन क्षेत्र ने कुल जीवीए में 4.66 प्रतिशत का योगदान दिया, जिससे दूध, अंडे और मांस की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला मत्स्य पालन क्षेत्र कृषि जीवीए का लगभग 6.72 प्रतिशत बनाता है और 2014-15 और 2022-23 (स्थिर मूल्यों पर) के बीच 8.9 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा है। यह 'सनराइज सेक्टर' लगभग 30 मिलियन लोगों, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े और कमजोर समुदायों को सहायता प्रदान करता है।

चार्ट IX.7: अनाज और पोल्ट्री उत्पादों की वृद्धि

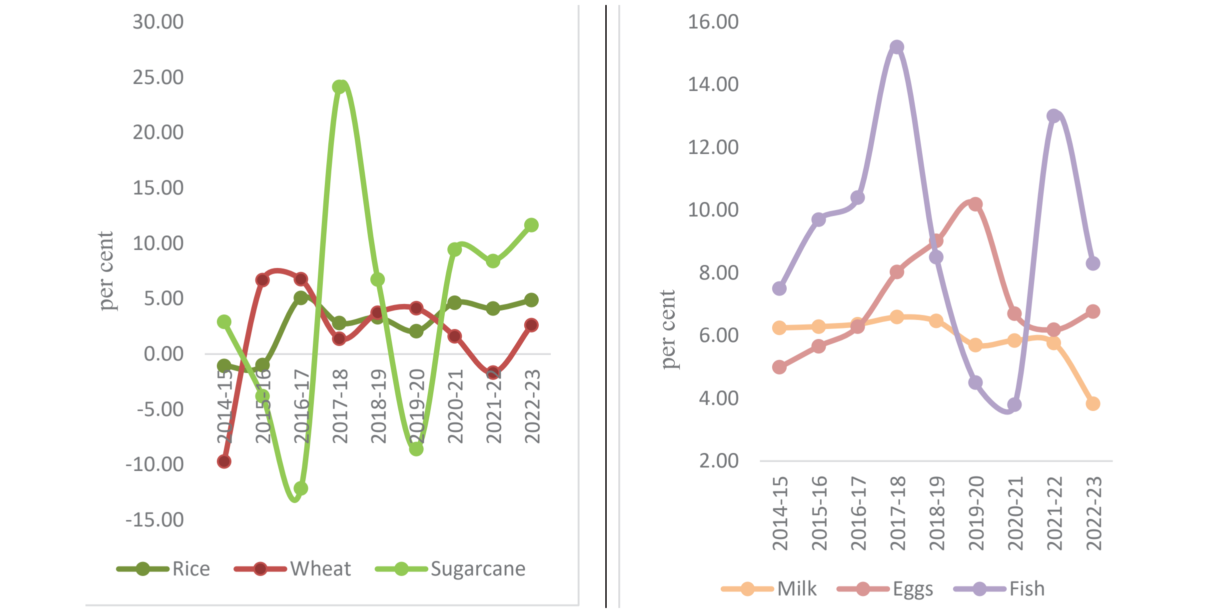

स्रोत: तीसरा अग्रिम अनुमान, कृषि मंत्रालय और पशुपालन विभाग तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग

9.32 कृषि विकास में संबद्ध क्षेत्र की बढ़ती प्रासंगिकता और कृषि आय के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में मान्यता देते हुए, उत्पादकता बढ़ाने, पशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और बुनियादी ढांचे के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए कई सरकारी पहलों को लागू किया जा रहा है। हस्तक्षेपों में पशु स्वास्थ्य (पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम)

में सुधार, उद्यमिता विकास और प्रति-पशु उत्पादकता (राष्ट्रीय पशुधन मिशन) को बढ़ावा देना और एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना शामिल है। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एफपीओ और धारा 8 कंपनियों और डेयरी सहकारी (एएचआईडीएफ में डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि को विलय करके शामिल) से डेयरी प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण, पशु चारा संयंत्र और नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की सुविधा प्रदान करती है। सरकार उधारकर्ता को 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान और कुल उधार के 25 प्रतिशत तक की ऋण गारंटी प्रदान करती है। मई 2024 तक, ऋणदाता बैंकों, नाबार्ड/एनडीडीबी द्वारा ₹13.861 करोड़ मूल्य की 408 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे 40,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और 42 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ है।

9.33 2022-23 में भारत ने 17.54 मिलियन टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन हासिल किया, जो वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है और वैश्विक उत्पादन का 8 प्रतिशत है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बीज और मछली उत्पादन और अन्य विस्तार सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के रूप में एक व्यापक कार्यक्रम पहल तैयार किया गया है। इस क्षेत्र की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए, 2018-19 में मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ) की शुरुआत की गई जिसका कुल निधि आकार 7.52 हजार करोड़ है। अब तक रियायती दर पर ₹5.59 हजार करोड़ के लिए 121 प्रस्तावों की सिफारिश की गई है[41]।

सहकारी समितियाँ- समुदायों को मजबूत करके किसानों को सशक्त बनाना

9.34 सहकारी समितियाँ उपज को एकत्र करने, सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाने और छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहतर बाजार पहुँच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं, जिससे बिचौलियों और व्यापारियों द्वारा शोषण को रोका जा सके। यह डेयरी सहकारी आंदोलन के मामले में देखा गया था, जो छोटे ग्रामीण उत्पादकों (जिनके पास 1-2 हेक्टेयर भूमि है) पर केंद्रित था[42]। ऐसा समझा जाता है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पैक्स) किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के अभिसरण को सुविधाजनक बनाने, विकास कार्यक्रमों में छोटे और सीमांत किसानों की बेहतर भागीदारी के माध्यम से उनकी प्रभावशीलता और पहुँच में सुधार करने के लिए उपयोगी साधन हो सकती हैं। सरकार ने 2023 में एक योजना को मंजूरी दी जिसका लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में उन पंचायतों/गाँवों में पैक्स स्थापित करना है, जिन्हें अभी कवर किया जाना है।

9.35 एकल-राज्य और बहु-राज्य सहकारी समितियों (एमएससीएस) की संख्या में भी वृद्धि हुई है[43]। मार्च 2024 तक 8.03 लाख एकल-राज्य और 1614 बहु-राज्य सहकारी समितियां हैं। इसके अलावा, बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत तीन एमएससीएस राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल), भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) और राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल)-राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की गई हैं। नई सहकारी समितियां निर्यात को बढ़ावा देना, एकल ब्रांड नाम के तहत उन्नत बीजों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना और प्रमाणित और प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन की दिशा में काम करना चाहती हैं। 31 मार्च 2024 तक एनसीईएल को 19 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों से सदस्यता के लिए 7,318 आवेदन प्राप्त हुए। तीन राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों की स्थापना की प्रतिक्रिया सदस्यता के लिए प्राप्त आवेदनों से स्पष्ट स्वीकृति और कई देशों में अनाज के निर्यात के लिए पहले से प्राप्त अनुमति के संदर्भ में आशाजनक रही है। इसे अब तक 16 देशों को 15.02 लाख मीट्रिक टन गैर-बासमती सफेद चावल, 07 देशों को 9.99 लाख मीट्रिक टन टूटे चावल, दो देशों को 50,000 मीट्रिक टन चीनी और एक देश को 14,184 मीट्रिक टन गेहूं अनाज, 5326 मीट्रिक टन गेहूं का आटा और 15.22 लाख मीट्रिक टन मैदा/सूजी के निर्यात की अनुमति मिल चुकी है। 31 मार्च 2024 तक बीबीएसएसएल को 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सदस्यता के लिए 16,775 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 31 मार्च, 2024 तक 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सदस्यता के लिए 5,154 आवेदन प्राप्त हुए हैं। एनसीओएल ने भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत 11 उत्पाद- अरहर, चना, मूंग, काबुली चना, मसूर, राजमा, गुड़ पाउडर, चीनी, बेसन, दलिया और ज्वार आटा लॉन्च किए हैं।

41 मत्स्य पालन विभाग

42 https://amul.com/m/a-note-on-the-achievements-of-the-dairy-cooperatives

43 केवल एक राज्य तक सीमित उद्देश्यों वाली सहकारी समितियाँ संबंधित राज्य सरकार के सहकारी कानूनों द्वारा शासित होती हैं और एक से अधिक राज्यों तक सीमित उद्देश्यों वाली सहकारी समितियाँ केंद्रीय कानून, अर्थात् बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम द्वारा शासित होती हैं।

बॉक्स IX.6: पैक्स के कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली को संबोधित करने के लिए पहल

पैक्स के कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की गई हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- कार्यकुशलता में सुधार के उद्देश्य से पैक्स/वृहद क्षेत्र बहुउद्देशीय समितियों (एलएएमपी) को एकल राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से जोड़ा जा रहा है। अब तक, 30 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 67009 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं, तथा राज्यों को 654 करोड़ रुपये और नाबार्ड को 141 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और बर्बादी को कम करने के लिए सहकारी क्षेत्र में एक अनाज भंडारण कार्यक्रम की योजना बनाई गई है जो दुनिया का सबसे बड़ा विकेन्द्रीकृत भंडारण कार्यक्रम होगा। इस योजना के तहत, पैक्स स्तर पर भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ, उचित मूल्य की दुकानें आदि जैसे कृषि बुनियादी ढाँचे का निर्माण किया जा रहा है। 11 राज्यों की 11 पैक्स में पायलट परियोजना शुरू की गई है जबकि 500 अतिरिक्त पैक्स में गोदामों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
- पैक्स के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया गया है, ताकि उन्हें ई-सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में काम करने की अनुमति मिल सके, रोजगार के अवसर बढ़ाने और पैक्स की वित्तीय मजबूती में सुधार करने के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान की जा सके, पैक्स द्वारा संचालित थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा दुकानों में परिवर्तित किया जा सके और नए पेट्रोल/डीजल पंप डीलरशिप को प्राथमिकता दी जा सके।
- पैक्स जन औषधि केंद्र और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में काम करेंगे, जिसमें ड्रोन उद्यमी भी शामिल हैं। इसके अलावा, पैक्स पाइप से जलापूर्ति के लिए परिचालन और रखरखाव का काम करने के लिए 'पानी समिति' के रूप में पात्र होंगे और पंचायत स्तर पर विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

9.36 उपरोक्त के अलावा, सहकारी समितियों के प्रशासन को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। बहुराज्य सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2023, जो 03 अगस्त 2023 को प्रभावी हुआ, मौजूदा कानून को पूरक बनाकर और 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को शामिल करके बहुराज्य सहकारी समितियों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने और चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने का प्रयास करता है, जो लोकपाल की नियुक्ति, समवर्ती लेखा परीक्षा की शुरूआत और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के मानदंडों को निर्धारित करने जैसे कई पहलुओं को संबोधित करता है।

चार्ट IX.8: प्रमुख राज्यों द्वारा पंजीकृत एकल राज्य और बहु-राज्य सहकारी समितियों की संख्या

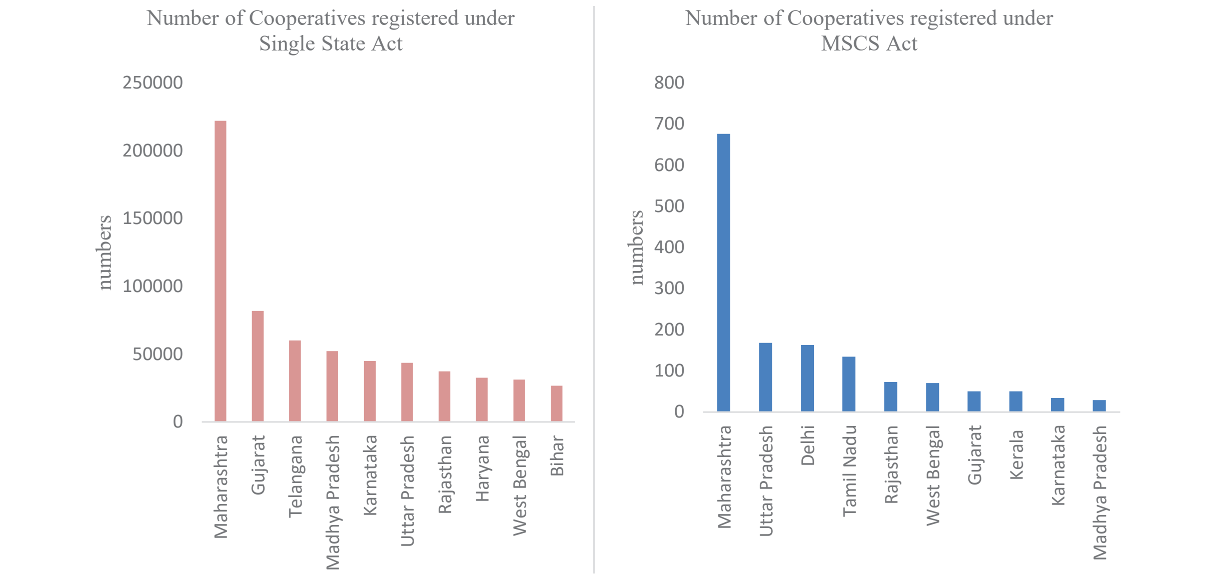

स्रोत: सहकारिता मंत्रालय

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा: प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाना

9.37 कृषि अनुसंधान में निवेश और सक्षम नीतियों के समर्थन ने खाद्य सुरक्षा में काफी योगदान दिया है। अनुमान है कि कृषि अनुसंधान (शिक्षा सहित) में निवेश किए गए प्रत्येक रुपए पर ₹13.85 का लाभ मिलता है। 2022-23 में कृषि अनुसंधान पर ₹19.65 हजार करोड़ खर्च किए गए, जो कृषि जीवीए के 0.43 प्रतिशत के बराबर है[44]। कृषि क्षेत्र के सामने मौजूद अजैविक और जैविक दबावों को देखते हुए अनुसंधान को मजबूत करने की आवश्यकता है।

9.38 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) देश में कृषि अनुसंधान में शीर्ष संगठन है। इसने फसल और बीज उत्पादन, अनाज और तेलों की जैव-फोर्टिफाइड किस्मों, बाजरा को बढ़ावा देने, पशु उत्पादन और स्वास्थ्य, कृषि मशीनीकरण और कटाई के बाद प्रबंधन, और मत्स्य पालन को कवर करने वाले अनुसंधान के विविध क्षेत्रों में काम किया है। कृषि प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और कौशल उन्नयन के लिए किसानों तक पहुँच आईसीएआर द्वारा किए गए कार्यों के महत्वपूर्ण पहलू हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान 44 फसलों की 347 किस्में/संकर जारी की गई तथा बागवानी फसलों की 99 किस्मों को व्यावसायिक खेती के लिए अधिसूचित किया गया। इसके अलावा चावल, गेहूं, मक्का, रागी, सरसों, सोयाबीन और मूंगफली की 27 जैव-फोर्टिफाइड किस्में जारी की गई। भारत अब दुनिया के बाकी हिस्सों को जिन चावल किस्मों का निर्यात करता है, उनमें से कई किस्में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में किए गए शोध से निकली हैं। यह याद दिलाता है कि कृषि अनुसंधान निवेश पर सबसे अधिक लाभ प्रदान करता है। इसलिए, मानव और वित्तीय संसाधनों के साथ कृषि अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने से किसानों और राष्ट्र को भरपूर लाभ मिलता रहेगा।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र (एफपीआई): प्रसंस्करण क्षमता

9.39 भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और फलों, सब्जियों और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उचित मूल्य पर कृषि इनपुट की उपलब्धता, विशाल श्रम शक्ति और लगातार बढ़ती उपभोक्ता मांग एक मजबूत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करते हैं। यह क्षेत्र खराब होने वाले कृषि उत्पादों की बर्बादी को कम करने, खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने, कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करने और कृषि के विविधीकरण और व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सच है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित विनिर्माण में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, जिसका संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार में 12.02 प्रतिशत हिस्सा है [45]। 2022-23 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात सहित कृषि-खाद्य निर्यात का मूल्य 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो भारत के कुल निर्यात का लगभग 11.7 प्रतिशत है। प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात का हिस्सा भी 2017-18 में 14.9 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 23.4 प्रतिशत हो गया।

9.40 यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है क्योंकि इसका कृषि क्षेत्र के साथ मजबूत संबंध है और यह कृषि क्षेत्र से निकलने वाले अधिशेष कार्यबल को रोजगार दे सकता है। 2022-23 तक समाप्त होने वाले पिछले आठ वर्षों के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र 2011-12 की कीमतों पर लगभग 5.35 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर (एएजीआर) से बढ़ रहा है। श्रम-प्रधान होने के कारण, महामारी ने इस क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और अब यह ठीक हो रहा है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जीवीए 2013-14 में 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में ₹1.92 लाख करोड़ रुपये हो गया है। 2011-12 की कीमतों पर 2022-23 में विनिर्माण में जीवीए का 7.66 प्रतिशत हिस्सा इस क्षेत्र का था।

44 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई)
45 खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय (एमओएफपीआई)

चित्र IX.9: विनिर्माण जीवीए में एफपीआई की हिस्सेदारी और प्रतिशत में एफपीआई की वृद्धि

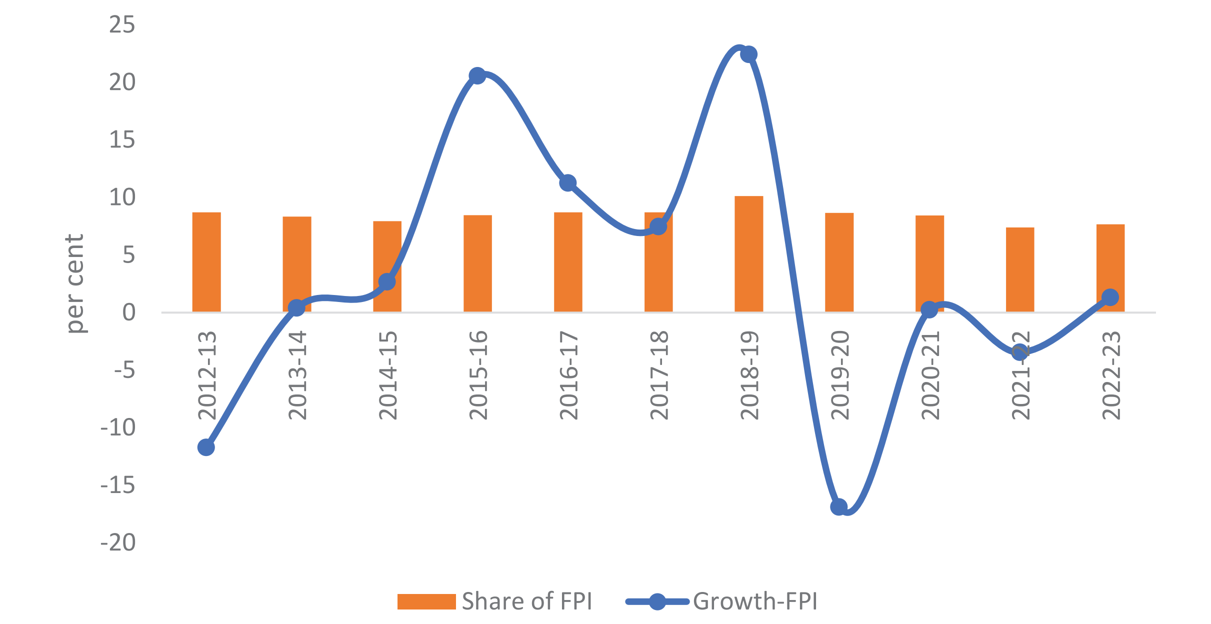

स्रोत: एनएडी, सीएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

9.41 सरकार ने खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कई पहलें की हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) वैश्विक खाद्य विनिर्माण चौंपियन बनाने, ब्रांडिंग और विदेशों में विपणन का समर्थन करती है। इससे ऑफ-फार्म रोजगार पैदा होने और कृषि उपज के लिए बेहतर मूल्य और किसानों को अधिक आय मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में, पीएलआई योजना के तहत 173 आवेदन शामिल हैं। योजना के लाभार्थियों ने ₹7.69 हजार करोड़ का निवेश किया है। वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 में ₹1.07 हजार करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी की गई।

9.42 ₹10 हजार करोड़ के कुल परिव्यय के साथ केंद्र प्रायोजित पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएमएफएमई) योजना मार्केटिंग और ब्रांडिंग सहायता सहित ऋण-लिंक्ड सब्सिडी और क्षमता निर्माण प्रदान करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, एक जिला एक उत्पाद, एआईएफ और पीएमकेएसवाई कार्यान्वयन जैसी अन्य योजनाओं का समर्थन और पूरक करने के लिए मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र के साथ अभिसरण की कोशिश की जा रही है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के कार्यान्वयन के लिए एक राज्य नोडल एजेंसी नियुक्त की है तथा राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति और जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 2 राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी संस्थानों और 44 राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों को भी मंजूरी दी गई है। दो लाख के लक्ष्य के मुकाबले 3,53,608 आवेदन प्राप्त हुए और 86,342 आवेदकों को 6.94 हजार करोड़ रुपये की ऋण राशि मंजूर की गई। 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 522 मास्टर ट्रेनर और 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 1068 जिला स्तरीय प्रशिक्षक और 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 70,936 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

9.43 टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) मूल्य श्रृंखला विकसित करने की योजना 2018-19 में शुरू की गई थी। ऑपरेशन ग्रीन का दायरा 3 फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) से बढ़ाकर 22 खराब होने वाली फसलों तक कर दिया गया है, जिसमें 10 फल, 11 सब्जियां (टीओपी सहित) और एक समुद्री यानी झींगा शामिल है। योजना के उद्देश्यों में किसानों की मूल्य प्राप्ति को बढ़ाना, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, खाद्य प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाना और मूल्य संवर्धन करना शामिल है। इस योजना की दो-आयामी रणनीतियां हैं: मूल्य स्थिरीकरण उपाय (अल्पकालिक उपाय) और एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं (दीर्घकालिक)। योजना के अल्पकालिक हस्तक्षेपों के तहत, अधिक उत्पादन की स्थिति के दौरान उत्पादन केंद्रों से अधिशेष उत्पादन की निकासी के लिए फलों और सब्जियों के परिवहन

और भंडारण की लागत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। दीर्घकालिक हस्तक्षेपों के लिए प्रमुख उत्पादक राज्यों में पहचाने गए उत्पादन क्लस्टरों में पात्र फसलों के लिए खाद्य प्रसंस्करण परियोजना स्थापित करने के लिए 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की दर से अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

खाद्य प्रबंधन[46]: खाद्य सुरक्षा के लिए सामाजिक जाल

9.44 खाद्य प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य किसानों से लाभकारी मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद, उपभोक्ताओं को विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को किफायती मूल्य पर खाद्यान्न का वितरण तथा खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता के लिए खाद्य बफर स्टॉक का रखरखाव करना है। इसके लिए किसानों से एमएसपी पर खरीद और उपभोक्ताओं के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) का उपयोग किया जाता है। खाद्यान्न की खरीद, वितरण और भंडारण का कार्य करने वाली नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) है। खाद्यान्न स्टॉक के विवेकपूर्ण प्रबंधन और केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार एक विकेंद्रीकृत खरीद योजना लागू करती है।

9.45 24 मई 2024 तक, रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2024-25 के दौरान गेहूं की खरीद देश भर में प्रमुख खरीद करने वाले राज्यों में सुचारू रूप से चल रही है, जिसमें केंद्रीय पूल के लिए 263.33 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जो पिछले साल की कुल खरीद 262.02 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। आरएमएस 2024-25 के दौरान कुल 22.42 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह, खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2023-24 के दौरान 98.26 लाख किसानों से सीधे 489.20 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा गया। उपरोक्त खरीद मात्रा के साथ, केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल का संयुक्त स्टॉक 600 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया है जो देश को खाद्यान्न की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सुविधाजनक स्थिति में रखता है।

9.46 खाद्यान्न का वितरण मुख्य रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) और पीएमजीकेएवाई सहित भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत किया जाता है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ-साथ एनएफएसए 2013 के अधिनियमन के माध्यम से घरेलू स्तर पर खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को लंबे समय से संबोधित किया है। इसके अलावा, सरकार ने 01 जनवरी 2024 से प्रभावी पांच साल की अवधि के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों (यानी अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) लाभार्थियों) को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना जारी रखने का विनिश्चय किया है, जिसका अनुमानित कुल वित्तीय परिव्यय ₹11.80 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह योजना देश भर में एक समान कीमतों और मात्राओं के साथ एक एकीकृत संस्थागत तंत्र प्रदान करती है और वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के तहत लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासियों के लिए कठिनाइयों को दूर करती है। इस प्रणाली के माध्यम से, प्रवासी लाभार्थी देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से मौजूदा/समान राशन कार्ड के आधार पर बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के बाद अपने राशन कार्ड या आधार नंबर का उपयोग करके सहज तरीके से दावा कर सकते हैं।

9.47 एमएसपी पर खाद्यान्न की खरीद और आर्थिक लागत[47] से कम पर खाद्यान्न का वितरण सरकार के लिए वित्तीय निहितार्थ हैं। एमएसपी में वृद्धि और आकस्मिक खर्चों में आनुपातिक वृद्धि के कारण पिछले कुछ वर्षों के दौरान गेहूं और चावल दोनों की आर्थिक लागत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। वर्ष 2023-24 (आरई) के लिए चावल और गेहूं की आर्थिक लागत क्रमशः ₹3931.34 प्रति क्विंटल और ₹2709.59 प्रति क्विंटल है[48]।

46 खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति को अध्याय 5- मूल्य और मुद्रास्फीति के अंतर्गत कवर किया गया है

47 खाद्यान्न की आर्थिक लागत में तीन घटक शामिल हैं, अर्थात् अनाज की संयुक्त लागत, खरीद आकस्मिक व्यय और वितरण की लागत।

48 अप्रैल, 2024 के एफसीआई खाद्य बुलेटिन डेटा के आधार पर

चित्र: IX.10: जारी की गई खाद्य सब्सिडी

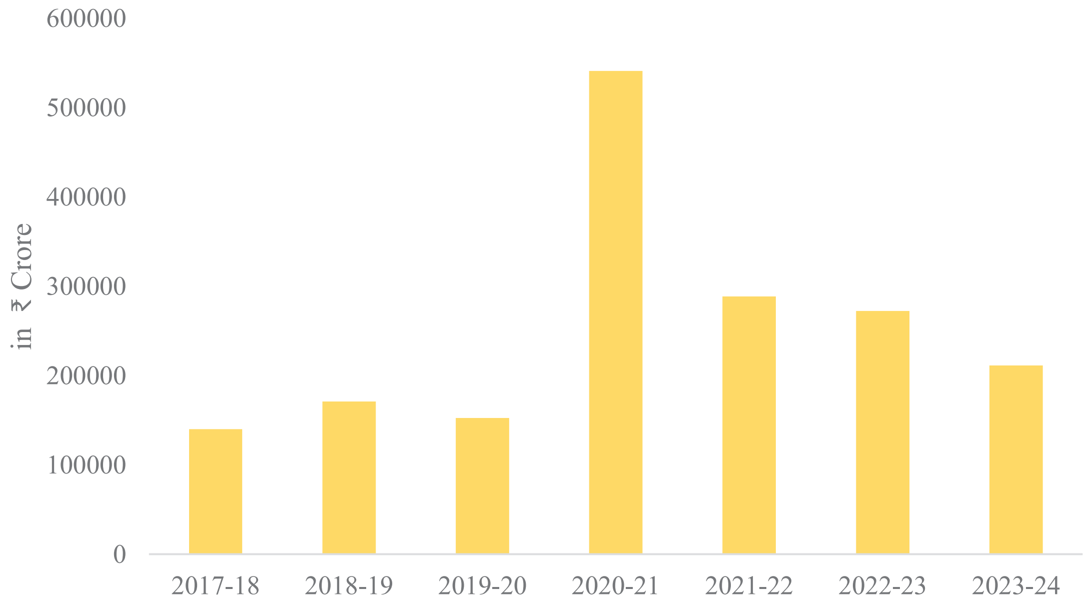

स्रोत: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

नोट:

- एफसीआई को जारी शुद्ध सब्सिडी के अलावा, एफसीआई द्वारा वित्त वर्ष 2016-17 में 25,000 करोड़, वित्त वर्ष 2017-18 में 40,000 करोड़, वित्त वर्ष 2018-19 में 70,000 करोड़ और वित्त वर्ष 2019-20 में 44,164.02 करोड़ के एनएसएसएफ ऋण का पुनर्भुगतान किया गया। खाद्य सब्सिडी से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी 3,39,236 करोड़ को एनएसएसएफ ऋण के पुनर्भुगतान के लिए समायोजित किया गया है। इसमें डीसीपी राज्य शीर्ष से एफसीआई को चुकाए गए 11,436 करोड़ शामिल नहीं हैं।
- संशोधित अनुमान, 2019-20 33508.35 करोड़ था। जारी की गई सब्सिडी में 11,436 करोड़ (एनएसएसएफ ऋण के हिस्से के रूप में) शामिल है, जो एफसीआई से डीसीपी राज्यों को जारी किया गया और 2020-21 में एफसीआई को वापस कर दिया गया।
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, केंद्रीय सहायता के लिए एनईएसए डिवीजन के पक्ष में 336.64 करोड़ का पुनर्वियोजन किया गया।

निष्कर्ष

9.48 कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है और पिछले पाँच वर्षों में यह औसतन 4.18 प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़ रहा है। किसानों की आय बढ़ाने में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों का बढ़ता महत्व यह सुझाव देता है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए इन गतिविधियों की क्षमता का दोहन करने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। चावल, गेहूँ या यहाँ तक कि बाजरा, दालें और तिलहन पैदा करके छोटे किसानों की आय नहीं बढ़ाई जा सकती। उन्हें उच्च मूल्य वाली कृषि - फल और सब्जियाँ, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, डेयरी और भैंस के मांस की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। एक बार जब छोटे किसानों की आय बढ़ जाती है, तो वे विनिर्मित वस्तुओं की माँग करेंगे, जिससे विनिर्माण क्रांति को बढ़ावा मिलेगा। 1978 और 1984 के बीच चीन में यही हुआ था, जब किसानों की वास्तविक आय केवल 6 वर्षों में दोगुनी हो गई थी। भारत इसका अनुकरण करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

9.49 तिलहन, दलहन और बागवानी की ओर फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि-बुनियादी ढांचे में निवेश, ऋण की सुलभता और उचित बाजार संस्थाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एमएसपी ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया है और इस बात के प्रमाण हैं कि एमएसपी का सभी फसलों की खुदरा कीमतों पर सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उन फसलों के लिए अधिक प्रभाव पड़ता है जिनकी खरीद पर्याप्त होती है, जैसे धान और गेहूं[49]। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पादन पैटर्न और प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाने चाहिए जो उनकी कृषि-जलवायु विशेषताओं और प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप हों। कृषि

49 https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/AnnualReport/PDFs/0ANREPORT201718077745EC9A874DB38C991F580ED14242.PDF

में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास और संवर्धन, साथ ही जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने सहित बीजों की गुणवत्ता में सुधार, टिकाऊ कृषि प्रथाओं की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जो कृषि आय में कुशलतापूर्वक सुधार करते हैं और किसान व्यवहार को प्रभावित करते हैं।

9.50 कृषि क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए कृषि में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी, उत्पादन विधियों, विपणन बुनियादी ढांचे और कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी के लिए निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है। फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास पर अधिक ध्यान देने से बर्बादी/नुकसान कम हो सकता है और भंडारण की अवधि बढ़ सकती है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकता है। निजी क्षेत्र सहित अधिक निवेश के माध्यम से फसल क्षेत्र की उत्पादकता भी बढ़ाई जा सकती है।

9.51 ई-नाम, एफपीओ को बढ़ावा देना और सहकारी समितियों को कृषि-विपणन में भाग लेने की अनुमति देना बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार कर सकता है और बेहतर मूल्य खोज की अनुमति दे सकता है। राज्यों को प्रोत्साहित करके बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार की संभावना तलाशी जा सकती है। राज्यों को रैंक करने के लिए एक सूचकांक बनाकर, सहकारी समितियों की भागीदारी की अनुमति देकर और उनके एपीएमसी और अन्य बाजार संस्थानों के कामकाज के अनुसार निवेशकों को लाभकारी रिटर्न सक्षम करके ऐसा किया जा सकता है। ऐसा प्रतिस्पर्धी ढांचा राज्यों को बेहतर कृषि विपणन के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकता है। 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कृषि विपणन को आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप करने के लिए राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने पर भी विचार करना उचित है।

****

10

अध्याय

उद्योगः मध्यम एवं लघु दोनों अपरिहार्य

वित्त वर्ष 2024 में औद्योगिक विकास में तेजी आई, जिसमें विनिर्माण और निर्माण सबसे आगे रहे। वित्त वर्ष 2024 में स्थिर कीमतों पर औद्योगिक जीवीए कोविड-पूर्व वित्त वर्ष 20 के स्तर से 25 प्रतिशत अधिक रहा, जो व्यापक आधार पर सुधार और समेकन की पुष्टि करता है। इसे अधिक ऋण उठाव, बुनियादी ढाँचा-उन्मुख क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए पूंजी निर्माण पर जोर और एक सहायक नीति ढाँचे द्वारा सहायता प्रदान किया गया।

पिछले दशक में, भारत के विनिर्माण परिदृश्य की क्षेत्रीय संरचना में काफी बदलाव हुए हैं। ऑटोमोबाइल, लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर और फार्मास्यूटिकल्स जैसे कुछ उपभोक्ता-उन्मुख उद्योगों ने उत्पादन हिस्सेदारी में बड़ी बढ़त हासिल की है और मशीनरी, रसायन, गैर-धातु खनिज, और रबर और प्लास्टिक उत्पादों जैसे उत्पादन-उन्मुख क्षेत्रों में भी हिस्सेदारी बढ़ी है, जिससे विकास की गतिशीलता संतुलित हुई है। इसी समय, पेट्रोलियम उत्पाद, कपड़ा, पेय और तंबाकू जैसे क्षेत्रों में उनके उत्पादन हिस्सेदारी में धीरे-धीरे गिरावट देखी गई है।

विकास की ओर अग्रसर होते हुए, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और एमएसएमई जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों को अधिक दक्षता, कौशल और गतिशीलता प्रदान करने के लिए चल रहे प्रयासों को बढ़ावा देने से औद्योगिक विस्तार को अधिक संतुलन मिलेगा। अनुसंधान एवं विकास निवेश को प्रोत्साहित करना, छोटे निर्माताओं का अधिक औपचारिकीकरण, उनकी आपूर्ति श्रृंखला की अड़चनों को दूर करना, बाजार तक पहुंच को सुगम बनाना और वित्तीय सहायता तक पहुंच में सुधार करना भी औद्योगीकरण को बढ़ावा देगा। एमएसएमई के लिए अनुपालन बोझ में और कमी से उनकी विकास संभावनाओं में काफी सुधार होगा।

खपत और निवेश के कारण घरेलू मांग की स्थिति मजबूत है और निकट भविष्य में औद्योगिक उत्पादन के सुचारू विस्तार के लिए अनुकूल है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापार अपेक्षाओं और औद्योगिक दृष्टिकोण पर किए गए एक दूरदर्शी सर्वेक्षण में सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। हालांकि, अनिश्चित वैश्विक मांग की स्थिति और प्रमुख इनपुट की कीमतों के मामले में प्रतिकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिसके लिए भारत आयात पर निर्भर है।

परिचय

10.1 वित्त वर्ष 24 में 8.2 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि 9.5 प्रतिशत की औद्योगिक वृद्धि से प्रेरित थी[1]। उद्योग के चार उप-क्षेत्रों में से, विनिर्माण और निर्माण ने दोहरे अंकों की वृद्धि हासिल की, जबकि खनन और उत्खनन तथा बिजली और जल आपूर्ति ने भी वित्त वर्ष 24 में मजबूत सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। यह औद्योगिक उत्पादन के व्यापक-आधार वृद्धि को दर्शाता है। विनिर्माण के लिए एचएसबीसी इंडिया परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) भी वित्त वर्ष 24 के सभी महीनों में लगातार 50 के सीमा मूल्य से ऊपर रहा, जो भारत के विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर विस्तार और स्थिरता का संकेत देता है।

10.2 वित्त वर्ष 23 में वर्तमान मूल्य के कुल सकल मूल्य वर्धन में विनिर्माण का हिस्सा 14.3 प्रतिशत था। हालांकि, आउटपुट शेयर 35.2 प्रतिशत है, जो दर्शाता है कि इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पिछड़े और आगे के संबंध हैं जो इसके

1 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 30 मई 2024 को जारी जीडीपी के अनंतिम अनुमानों के अनुसार। यह फरवरी 2024 में जारी जीडीपी के दूसरे अग्रिम अनुमानों में अनुमानित 9 प्रतिशत औद्योगिक विकास से अधिक है, जो वित्त वर्ष 24 के उत्तरार्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन के प्रत्याशित विस्तार से अधिक तेज होने का संकेत देता है।

मूल्य-वर्धित हिस्से में पूरी तरह से शामिल नहीं हैं। देश में कुल उत्पादन मूल्य का लगभग 47.5 प्रतिशत उत्पादक गतिविधियों (अंतर-उद्योग उपभोग)[2] में इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है। विनिर्माण गतिविधियां अंतर-उद्योग खपत का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा हैं, तथा साथ ही, ये सभी उत्पादक गतिविधियों (कृषि, उद्योग और सेवाएं) में प्रयुक्त इनपुट का लगभग 50 प्रतिशत आपूर्ति करती हैं।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 30 मई 2024 को जारी जीडीपी के अनंतिम अनुमानों के अनुसार। यह फरवरी 2024 में जारी जीडीपी के दूसरे अग्रिम अनुमानों में अनुमानित 9 प्रतिशत औद्योगिक विकास से अधिक है, जो वित्त वर्ष 24 के उत्तरार्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन के प्रत्याशित विस्तार से अधिक तेज होने का संकेत देता है।

चार्ट X.1: कुल जीवीए में उद्योग और उसके घटकों का हिस्सा (स्थिर मूल्य में)

चार्ट X.2: उद्योगों और उसके घटकों की वार्षिक वृद्धि (स्थिर मूल्यों में)

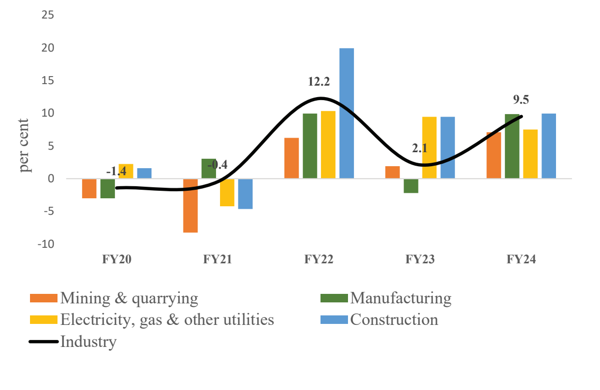

स्रोतः राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2024 (विवरण 8.6.1 और 8.6.2) पर आधारित सर्वेक्षण गणना, एमओएसपीआई

चार्ट X.3: भारत विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक

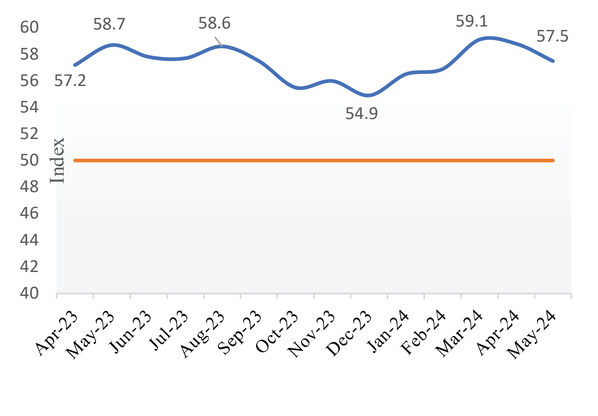

स्रोतः आईएचएस मार्किट

नोटः 'इसमें विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर और परिवहन उपकरण शामिल नहीं हैं

चार्ट X.4: स्थिर मूल्यों पर विनिर्माण जीवीए के घटकों में औसत वार्षिक वृद्धि (वित्त वर्ष 14 से वित्त वर्ष 23 तक)

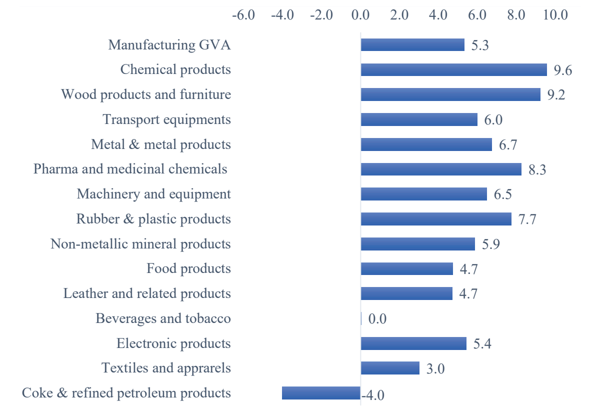

स्रोतः राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2024 (विवरण 8.6.1 और 8.6.2) पर आधारित सर्वेक्षण गणना, एमओएसपीआई

10.3 महामारी और उसके परिणामस्वरूप विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं की हानि के बावजूद, विनिर्माण क्षेत्र ने पिछले दशक में 5.2 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल की। पिछले दशक में विनिर्माण उप-क्षेत्रों ने उत्पादन हिस्सेदारी में काफी पुनर्निर्धारण देखा। पिछले दशक में विनिर्माण वृद्धि के उत्प्रेरकों में रसायन, लकड़ी के उत्पाद और फर्नीचर,

2 वित्त वर्ष 20 के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित आपूर्ति और उपयोग तालिकाओं के अनुसार।

परिवहन उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स और मशीनरी और उपकरण शामिल थे। उनमें से, इस्पात, मशीनरी और उपकरण, लकड़ी के उत्पाद और परिवहन उपकरण, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण पर जोर देता है।

चार्ट X.5: वित्त वर्ष 14 से वित्त वर्ष 23 के बीच कुल जीवीए में निर्मित उत्पादों के जीवीए के हिस्से में परिवर्तन (स्थिर मूल्यों पर)

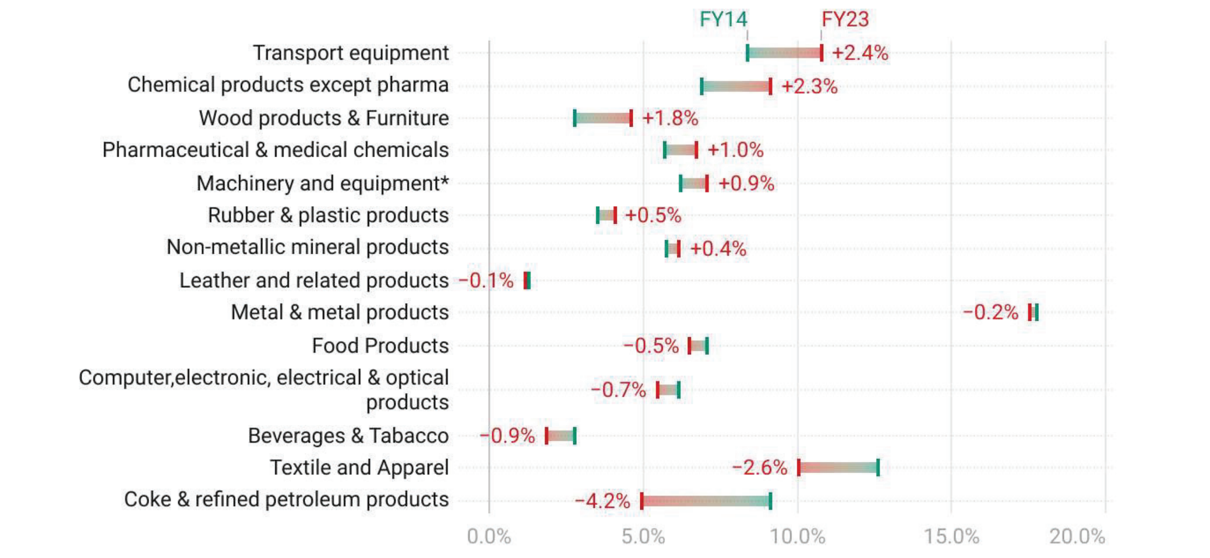

स्रोतः राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2024 (विवरण 8.6.1 और 8.6.2) पर आधारित सर्वेक्षण गणना, MoSPI
नोटः 'इसमें विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर और परिवहन उपकरण शामिल नहीं हैं

10.4 भारत का औद्योगिकीकरण भौतिक अवसंरचना और रसद की कमी के साथ-साथ क्षमता निर्माण और विस्तार पर हस्तक्षेप करने वाली और बोझिल लाइसेंसिंग आवश्यकताओं के कारण रुका हुआ था। इसके अलावा, विशिष्ट वस्तुओं का निर्माण छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिए आरक्षित था। इनमें से अधिकांश प्रतिबंध अब हटा दिए गए हैं, और भौतिक अवसंरचना का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। वस्तु एवं सेवा कर ने कई वस्तुओं के लिए एकल बाजार बनाया है, जिससे बड़े पैमाने पर विनिर्माण संभव हो पाया है। हालांकि, भारत को अपने विनिर्माण आधार को बढ़ाने में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सार्वजनिक नीति को प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कार्रवाई मुख्य रूप से विनियमन में निहित है। निजी क्षेत्र को दीर्घकालिक सोचना चाहिए और अनुसंधान एवं विकास खर्च के माध्यम से गुणवत्ता में निवेश करना चाहिए। ये पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक शर्तें हैं। विनिर्माण में अभी भी कम और अर्ध-कुशल नौकरियां पैदा करने और लोगों के करीब विकास लाने की क्षमता है। भारत को इस क्षेत्र को प्राथमिकता देने की जरूरत है।

10.5 अध्याय के शेष भाग निम्नलिखित तरीके से व्यवस्थित हैं। अगला भाग विभिन्न औद्योगिक खंडों, जैसे कि प्रमुख औद्योगिक मध्यवर्ती और उपभोक्ता-उन्मुख उद्योगों में प्रगति, चुनौतियों और नीतिगत पहलों की जांच करता है[3]। इसके बाद उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), औद्योगिक वित्तपोषण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और नवाचार जैसे क्रॉस-कटिंग विषयों पर संक्षिप्त चर्चा की गई है। अंतिम सत्र में चर्चा का समापन होता है तथा आगे का रास्ता बताया जाता है।

3 उर्वरक को कृषि और खाद्य प्रबंधन पर अध्याय 8 में शामिल किया गया है

प्रमुख क्षेत्रों का प्रदर्शन और संबंधित मुद्दे

प्रमुख औद्योगिक घटक

सीमेंट: भविष्य का निर्माण

10.6 सीमेंट उद्योग भारत में निर्माण क्षेत्र में लगभग 11 प्रतिशत इनपुट लागत का योगदान देता है[4]। 1991 में डी-लाइसेंसिंग के बाद से, सीमेंट उद्योग ने क्षमता और प्रक्रिया प्रौद्योगिकी दोनों में उल्लेखनीय प्रगति की है, इतनी कि भारत चीन[5] के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है।

10.7 भारतीय सीमेंट उद्योग में 159 एकीकृत बड़े सीमेंट संयंत्र, 120 ग्राइंडिंग इकाइयाँ और 62 मिनी सीमेंट संयंत्र शामिल हैं। भारत में सीमेंट उद्योग की वर्तमान वार्षिक स्थापित क्षमता लगभग 622 मिलियन टन है, जिसमें वित्त वर्ष 24 में सीमेंट उत्पादन लगभग 427 मिलियन टन है। भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थित हैं। सीमेंट उद्योग का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्यों में केंद्रित है।

10.8 उद्योग के पास घरेलू सीमेंट की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है; वित्त वर्ष 23 में आयातित सीमेंट की मात्रा कुल घरेलू सीमेंट उत्पादन का लगभग 0.2 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2019 तक क्लिंकर और अन्य सीमेंट का निर्यात बढ़ा और फिर वैश्विक मांग में कमी और अन्य देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अन्य हाइड्रोलिक सीमेंट को छोड़कर इसमें गिरावट शुरू हो गई। वित्त वर्ष 23 में भारत ने केवल नाम मात्र में क्लिंकर का निर्यात किया।

चार्ट X.6: सीमेंट उद्योग की स्थापित क्षमता, उत्पादन क्षमता उपयोग

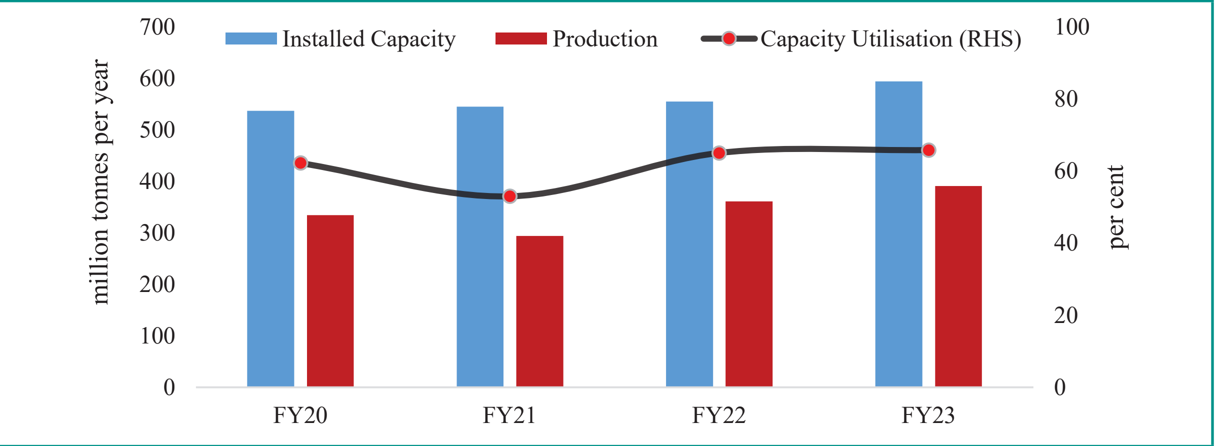

स्रोत: उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)

10.9 उद्योग ने हाल के वर्षों में लगभग 60-65 प्रतिशत की क्षमता उपयोग दर बनाए रखी है। रिपोर्टों में यह भी उम्मीद जताई गई है कि 2024-2030 के दौरान सीमेंट की वैश्विक मांग स्थिर रहने की संभावना है, जिसमें केवल भारत, अफ्रीका, मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका से ही मांग में कुछ हद तक सुधार देखने को मिलेगा। फिर भी सीमेंट उद्योग में सकल मार्जिन वैश्विक स्तर पर मजबूत रहने की संभावना है, जिसे उच्च कीमतों और कम ईंधन लागतों से मदद मिलेगी[6]।

10.10 भारत में घरेलू सीमेंट की खपत लगभग 260 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, जबकि वैश्विक औसत 540 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, जो वृद्धि की संभावना को दर्शाता है। पिछले दस वर्षों में क्लिंकर का आयात बढ़ा है। हालाँकि, आयात की मात्रा अभी भी कम है

4 राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, 2023-24, विवरण 8.8: निर्माण से उत्पादन और मूल्य वर्धन,
5 डीपीआईआईटी
6 ग्लोबल सीमेंट इंडस्ट्री आउटलुक: रुझान और पूर्वानुमान। लिंक: https://www.worldcementassociation.org/blog/news/global-cement-industry-outlook-trends-and-forecasts.

10.11 सीमेंट उद्योग मुख्य रूप से मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास और शहरीकरण से प्रेरित है। राजमार्गों, रेलवे, आवास योजनाओं और स्मार्ट शहरों जैसी मेगा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकार का ध्यान सीमेंट की मांग को काफी बढ़ावा देगा। ग्रामीण विकास पर जोर और औद्योगिक और वाणिज्यिक निर्माण में निवेश में वृद्धि से विकास की संभावनाओं को समर्थन मिलता है।

10.12 वैश्विक स्तर पर, सीमेंट क्षेत्र कुल मानवजनित उत्सर्जन का लगभग 7 प्रतिशत उत्पन्न करता है। भारतीय सीमेंट उद्योग इस मुद्दे पर काम कर रहा है। अनुमान है कि 2023 में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 0.56 टन CO_2 प्रति टन सीमेंट तक कम हो जाएगा। जैसा कि सीमेंट उद्योग प्रौद्योगिकी रोडमैप में अनुमान लगाया गया है, 2050 तक CO_2 उत्सर्जन को 0.35 टन CO_2 प्रति टन सीमेंट तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।[7]

इस्पात क्षेत्र विकास पथ पर

10.13 निर्माण क्षेत्र में सभी इनपुट में लोहा और इस्पात का योगदान लगभग 47 प्रतिशत है[8]। यह मशीनरी और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में भी कार्य करता है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान इस्पात क्षेत्र ने उत्पादन और खपत का उच्चतम स्तर हासिल किया।

10.14 भारत पिछले दशक में तैयार इस्पात का शुद्ध निर्यातक बन गया है, जिसमें निर्यात वृद्धि आयात से अधिक हो गई है। वित्त वर्ष 24 में, भारत ने Q1 में शुद्ध निर्यातक के रूप में शुरुआत की। हालाँकि, वित्त वर्ष 24 की दूसरी और तीसरी तिमाही में, यह शुद्ध आयातक बन गया। यह मुख्य रूप से तैयार स्टील की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कीमतों के बीच मूल्य अंतर से प्रेरित था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम कीमतों के कारण निर्यात के लिए लाभ मार्जिन कम हो गया और आयात अधिक किफायती हो गया, जिससे स्टील में व्यापार संतुलन प्रभावित हुआ। हालाँकि, इस्पात उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल, कोकिंग कोयले पर आयात निर्भरता वित्त वर्ष 2023 में 56.1 मीट्रिक टन से घटकर वित्त वर्ष 24 में 58.1 मीट्रिक टन हो गई।

10.15 जैसे-जैसे दुनिया निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है, हरित इस्पात इस्पात उद्योग के भविष्य को नया आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत के इस्पात क्षेत्र की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत[9]है, जिसकी उत्सर्जन तीव्रता 2.5 टन CO_2 प्रति टन कच्चे इस्पात की है, जबकि वैश्विक औसत 1.9 टन CO_2 प्रति टन कच्चे इस्पात की है।

चार्ट X.7: तैयार इस्पात की औसत वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत में)

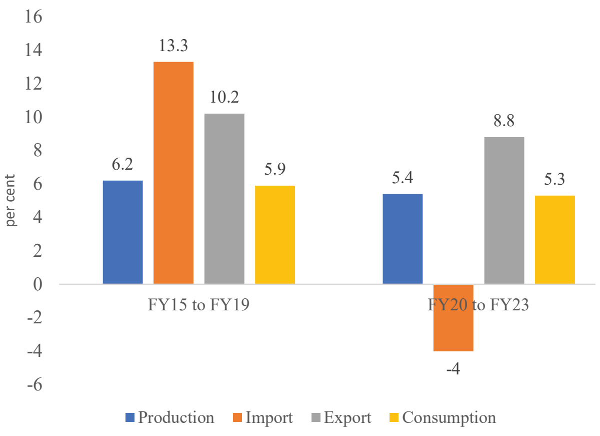

चार्ट X.8: वित्त वर्ष 24 में तैयार इस्पात की वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत में)

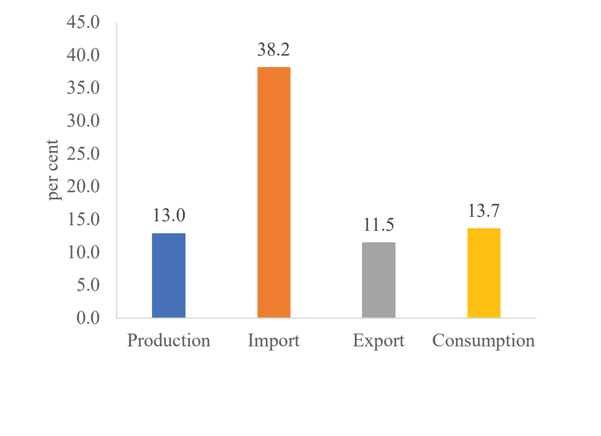

स्रोत: इस्पात मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण गणना

7 सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद, 2018

8 राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, 2023-24, विवरण 8.8: निर्माण से उत्पादन और मूल्य वर्धन, एमओएसपीआई I

9 इस्पात मंत्रालय

चार्ट X.9: भारत पिछले 5 वर्षों में से 4 वर्षों में तैयार इस्पात का निवल निर्यातक रहा

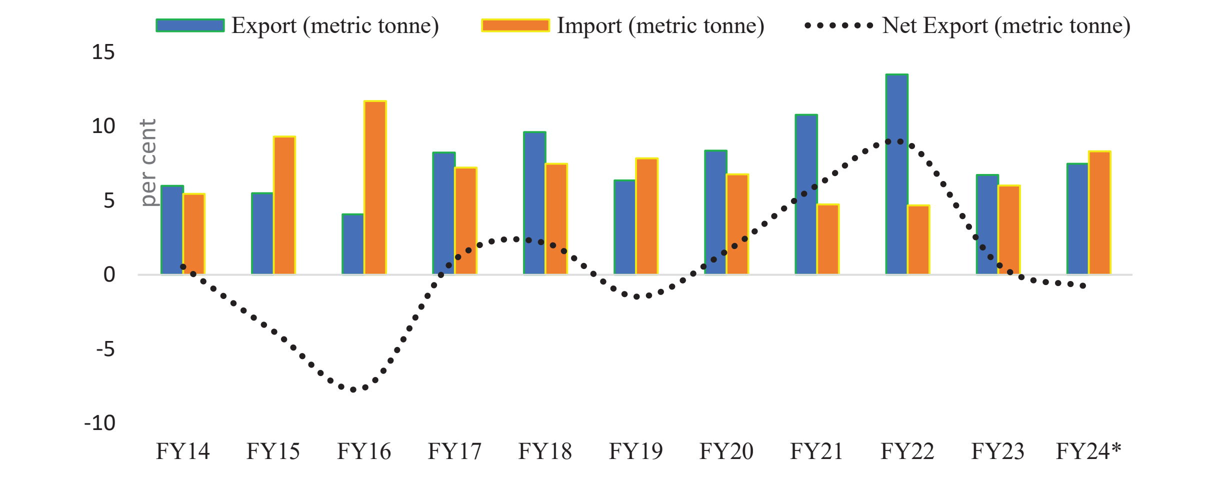

स्रोतः इस्पात मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण गणना
नोटः 'अनंतिम

बॉक्स X.1: इस्पात क्षेत्र की पहल

आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने अक्टूबर 2023 में बस्तर जिले में नगरनार इस्पात संयंत्र की स्थापना की, जो भारत की इस्पात उत्पादन क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड परियोजना से उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन होने की उम्मीद है, जो क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देगा और भारत को वैश्विक इस्पात बाजार में एक प्रमुख किरदार के रूप में स्थापित करेगा। संयंत्र को फ्लैट स्टील उत्पादों की एक श्रृंखला का उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्त वर्ष 24 में, संयंत्र ने 4.93 लाख टन हॉट-रोल्डकॉइल का उत्पादन किया। स्टील सीपीएसई के बीच, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 24 में हॉटमेटल, क्रूड स्टील और बिक्री योग्य इस्पात का अब तक का सबसे अच्छा उत्पादन हासिल किया।

वर्ष 2021 में स्वीकृत स्पेशियलिटी स्टील के लिए पीएलआई योजना ने 24 मई तक ₹15,519 करोड़ का निवेश आकर्षित किया है। 17.03.2023 को, इस्पात मंत्रालय ने 57 आवेदनों वाली 27 चयनित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस योजना से 24,780 हजार टन की क्षमता वृद्धि के साथ कुल ₹29,531 करोड़ का निवेश आकर्षित होगा।

स्रोतः इस्पात मंत्रालय

कोयलाः बाहरी निर्भरता कम करना

10.16 भारत की प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा में कोयले का योगदान 55 प्रतिशत से अधिक है। कोयले से चलने वाली बिजली उत्पादन कुल बिजली उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत है। पिछले पाँच वर्षों में कोयले के उत्पादन में तेजी आई है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है। वित्त वर्ष 24 में, भारत ने 997.2 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, 261 मीट्रिक टन का आयात किया और 1233.86[10] मीट्रिक टन की खपत की। पिछले दशक में कोयले के घरेलू उत्पादन और खपत के अनुपात में धीरे-धीरे सुधार हुआ क्योंकि उत्पादन में वृद्धि ने खपत में वृद्धि को पीछे छोड़ दिया

10 कोयला मंत्रालय

चार्ट X.10: घरेलू खपत के प्रतिशत के रूप में कोयला उत्पादन

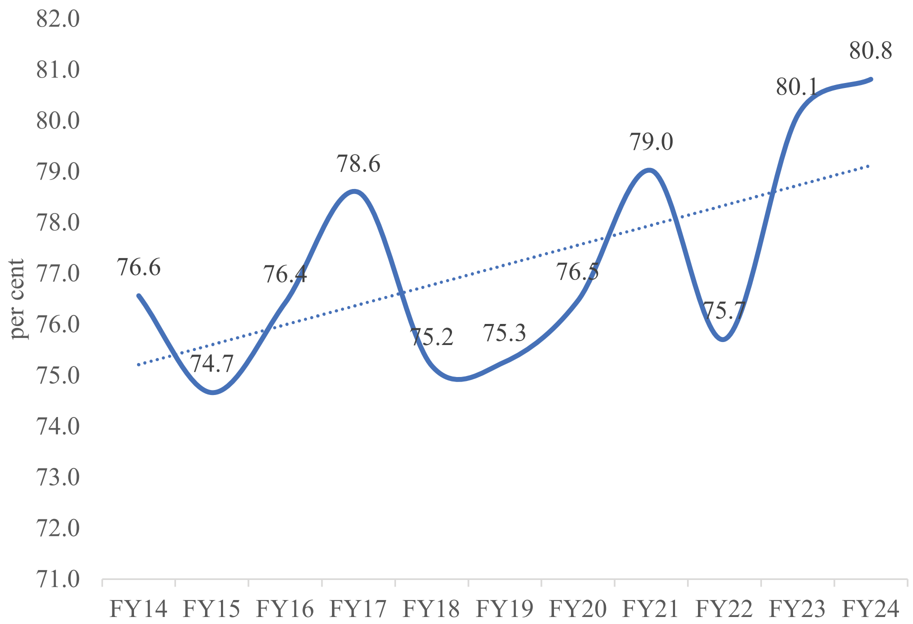

स्रोत: कोयला मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण गणना

तालिका X.1: कोयले के उत्पादन, खपत और आयात में वृद्धि (सीएजीआर प्रतिशत में)

वर्ष	उत्पादन	खपत	आयात
वित्त वर्ष 14 से वित्त वर्ष 19	5.2	5.6	7.1
वित्त वर्ष 19 से वित्त वर्ष 24	6.5	5.0	2.1
वित्त वर्ष 24 (वर्ष दर वर्ष)	11.7	10.7	9.8

स्रोत: कोयला मंत्रालय

बॉक्स X.2: कोयला क्षेत्र में हालिया पहल, चुनौतियां और अवसर

हालिया पहल	चुनौतियाँ, अवसर और विकल्प
• सरकार ने आयात कम करने के लिए 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयले को गैसीफाई करने का लक्ष्य रखा है। • कोयला/लिग्नाइट गैसीफिकेशन परियोजनाओं को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण प्रदान करने के लिए 2023-24 के दौरान 8500 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक योजना शुरू की गई है। • कोयला निकासी के लिए तकनीकी रूप से सक्षम, एकीकृत और लागत प्रभावी रसद विकसित करने के लिए फरवरी 2024 में एकीकृत कोयला रसद नीति और योजना शुरू की गई। • मई 2023 में संशोधित कोयला ब्लॉक आवंटन नियम, 2017 को अधिसूचित किया गया।	• स्वदेशी निर्माताओं से आधुनिक खनन उपकरणों की सीमित उपलब्धता के कारण तकनीकी कठिनाइयाँ। • खनन परियोजनाओं के समय पर विकास के लिए वानिकी और पर्यावरण मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और कब्जे को प्राप्त करने में प्रक्रियात्मक जटिलताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। • वैश्विक पर्यावरण सक्रियता के बीच स्थायी समाधानों की आवश्यकता • चुनौतियों को कम करने के लिए, उद्योग उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

- कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) 2025-26 तक बिजली खनन कार्यों के लिए 3,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का उपक्रम कर रही है। 2023-24 के दौरान, दिसंबर 2023 तक सौर प्रतिष्ठानों से कुल 8.60 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया।
- सीआईएल धीरे-धीरे उच्च क्षमता वाली कोयला निकासी प्रणाली की ओर बढ़ रहा है, जो अपनी 'फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी' परियोजनाओं के तहत कोयला हैंडलिंग प्लांट/साइलो स्थापित करके इसे अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बना रहा है।
- यह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला परिवहन और पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं में तकनीकी परिवर्तन अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।
- सीआईएल भारत और विदेशों में लिथियम और कोबाल्ट जैसी महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण का प्रयास कर रहा है।
- थर्मल कोयले की पर्याप्त घरेलू आपूर्ति के बावजूद, आयात का केवल प्रतिस्थापन योग्य हिस्सा ही बदला जा सकता है। कोकिंग कोल की बढ़ती मांग कोकिंग कोल के आयात को बढ़ाएगी। 'कोकिंग कोल मिशन' के तहत आयातित कोयले के साथ मिश्रण के लिए कोकिंग कोयला के लाभ को बढ़ाने की जरूरत है।
- कोयले का उपयोग हरित ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है, जैसे कोल माइन मीथेन (सीएमएम), कोल बेड मीथेन (सीबीएम), कोल टू लिक्विड और कोल टू मेथनॉल। सीएमएम और सीबीएम का उत्तरोत्तर उपयोग किया जाना चाहिए।

स्रोत: कोयला मंत्रालय

प्रमुख उपभोक्ता-उन्मुख उद्योग

फार्मास्यूटिकल्स: बढ़ती और वैश्विक उपस्थिति

10.17 भारत का दवा बाजार वर्तमान में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और यह मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। जेनेरिक दवाओं, सक्रिय दवा सामग्री, बल्क ड्रग्स, ओवर-द-काउंटर दवाओं, टीकों, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर को कवर करने वाले बेहद विविध उत्पाद आधार के साथ, भारतीय दवा उद्योग की वैश्विक स्तर पर मजबूत उपस्थिति है। इसे 'दुनिया की फार्मेसी' कहा जाता है, जो 60 चिकित्सीय श्रेणियों में लगभग 60,000 जेनेरिक ब्रांड प्रदान करती है, जो मात्रा के हिसाब से वैश्विक जेनेरिक दवा निर्यात का 20 प्रतिशत है। आश्चर्य की बात नहीं है कि शीर्ष 20 वैश्विक जेनेरिक कंपनियों में से आठ भारत में स्थित हैं।

10.18 भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र में गुणवत्ता अनुपालन की उच्च दर है, जिसमें 703[11] यूएस एफडीए-अनुमोदित सुविधाएं (अप्रैल 2023 तक), 386[12] यूरोपीय जीएमपी-अनुपालक संयंत्र (नवंबर 2022 तक) और 2418[13] डब्ल्यूएचओ-जीएमपी-अनुमोदित संयंत्र हैं। विनियामक ढांचे को और मजबूत करने के लिए, दिसंबर 2023 में, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से संबंधित अनुसूची-एम के तहत संशोधित फार्मा विनिर्माण नियमों को अधिसूचित किया गया, जो एक अनिवार्य आवश्यकता है जो गुणवत्ता की रक्षा करती है और मौजूदा व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाती है।[14]

11 फार्मास्युटिकल एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, हैंडबुक, 2023 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जोड: https://pharmexcil.com/uploads/files/Hand_Book_Design.pdf

12 फार्मास्युटिकल एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, हैंडबुक, 2023। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। लिंक: https://pharmexcil.com/uploads/files/Hand_Book_Design.pdf

13 https://cdsco.gov.in/opencms/opencms/system/modules/CDSCO.WEB/elements/industry_download.jsp\num_id¾MTcyNQ¾4¾

14 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 28 दिसंबर, 2023 https://pharmadocx.com/wp- content/uploads/2024/01/Notified-Schedule-M-dt-28.12.2023-1.pdf

चार्ट X.11: वित्त वर्ष 24 में फार्मा क्षेत्र का कारोबार, निर्यात और आयात	चार्ट X.12: फार्मा क्षेत्र में घरेलू कारोबार वृद्धि
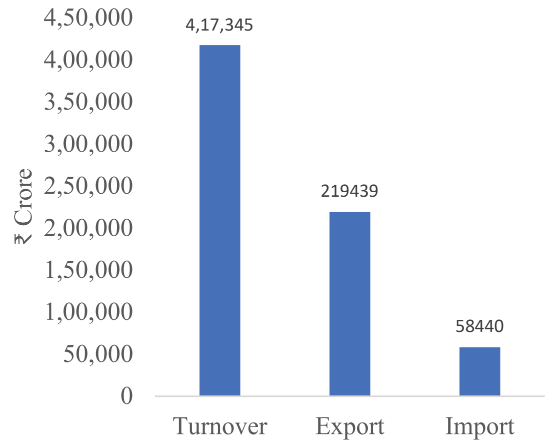	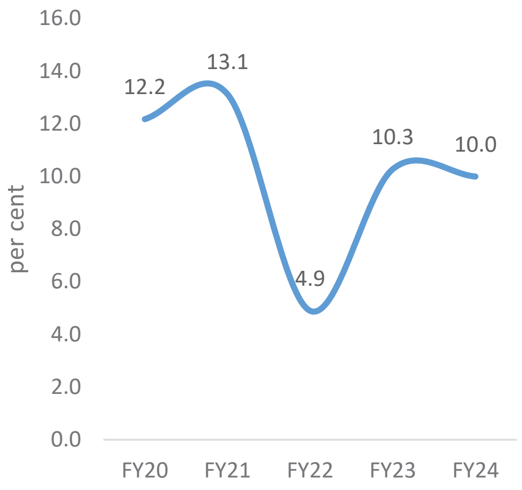

स्रोत: फार्मास्युटिकल विभाग

10.19. भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग पारंपरिक रूप से एक देश से एपीआइ आयात पर निर्भर रहा है। बल्क ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के लिए पीएलआई योजनाओं ने बल्क ड्रग्स के आयात को स्थिर करने और हमारी आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन में सुधार करने में मदद की है। इस योजना के तहत, पेनिसिलिन जी और क्लैवुलैनिक एसिड जैसे एंटीबायोटिक्स के उत्पादन के माध्यम से किण्वन-आधारित विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत किया गया। वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 24 के बीच बल्क ड्रग्स के आयात का सीएजीआर 2.3 प्रतिशत था, जबकि उनके निर्यात में सीएजीआर 5.9 प्रतिशत था। भारत बल्क ड्रग्स का शुद्ध निर्यातक बन गया है। वित्त वर्ष 24 के दौरान, बल्क ड्रग्स के निर्यात और आयात का मूल्य क्रमशः 39,632 करोड़ और 37,722 करोड़ था।

10.20 चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना सकारात्मक प्रोत्साहन प्रदान करने लगी है, जैसा कि चिकित्सा उपकरणों के निर्यात और आयात के बीच कम होते अंतर में परिलक्षित होता है। देश में सीटी-स्कैन मशीन, लीनियर एक्सेलेरेटर (एलआईएनएसी), रोटेशनल कोबाल्ट मशीन, सी-आर्म, एमआरआई आदि जैसे कई चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन शुरू हो गया है।[15]

बॉक्स X.3: फार्मा क्षेत्र की हालिया पहल, चुनौतियां और दृष्टिकोण

आत्मनिर्भरता का अनुसरण	प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि	चुनौतियां और दृष्टिकोण
• इसका उद्देश्य बड़े निवेश को आकर्षित करके और महत्वपूर्ण एपीआई पर आयात निर्भरता को कम करके पहचाने गए केएसएम, डीआई और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। • थोक दवाओं के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत 3938.6 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ 48 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।	• इसका उद्देश्य सभी को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना है। • प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए खुले हैं। अब तक सभी जिलों को कवर करते हुए 12500 से अधिक पीएमबीजेके खोले जा चुके हैं।	• भारत किण्वन के माध्यम से निर्मित कई एंटीबायोटिक एपीआई के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। भारत की आयात निर्भरता काफी हद तक आयात की तुलना में घरेलू एपीआई विनिर्माण में लागत प्रभावी विकल्पों की कमी के कारण है। हाल के वर्षों में घरेलू बुनियादी ढांचे और अनुसंधान एवं विकास

15 पीआईबी जारी 17 जनवरी 2024 लिंक: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1996964

- बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना विश्व स्तरीय सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण के लिए तीन बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती है। इससे बल्क ड्रग की विनिर्माण लागत में कमी आएगी और भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता और दवा सुरक्षा में सुधार होगा।
- इसने किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध करवा कर आम जनता और गरीबों पर प्रभाव डाला है।
- वित्त वर्ष 23-24 में, फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने ₹1470 करोड़ मूल्य की जन औषधि दवाएं बेचीं, जिससे लगभग ₹7350 करोड़ की बचत हुई।
- इस योजना से विशेष रूप से पुरानी बीमारियों के लिए दवाओं पर अधिक बचत हो रही है। औसतन, प्रतिदिन 10-12 लाख लोग जन औषधि केंद्रों पर आते हैं।

क्षमताओं में काफी सुधार हुआ है, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं (बॉक्स X.10)।

- पिछले 5-6 दशकों में लगातार नवाचार के कारण निर्यात में वृद्धि हुई है। बायोफार्मास्युटिकल्स विनिर्माण में क्षमताओं को बढ़ाकर निर्यात वृद्धि को बनाए रखा जा सकता है।
- फार्मा उद्योग के 2030 तक 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- फार्मा में विकास के अगले चरण के लिए कौशल उन्नति, नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग और एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना की आवश्यकता है।

स्रोत: फार्मास्युटिकल विभाग

बॉक्स X.4: फार्मा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाने और पुनर्कल्पित करने की आवश्यकता

दुनिया भर में फार्मास्युटिकल उद्योग को इनोवेटर या जेनेरिक निर्माता में विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, 'इनोवेटर' फर्म दुनिया में बीमारियों के लिए नई दवाएं या उपचार लाने के लिए व्यापक शोध करती हैं। समय और संसाधनों की सीमा और इस प्रक्रिया में शामिल जोखिम को ध्यान में रखते हुए, ऐसी दवाओं की कीमतें आमतौर पर बहुत अधिक होती हैं। ऐसी कंपनियाँ इन नई दवाओं के लिए उनके स्वामित्व वाले बौद्धिक संपदा अधिकारों के माध्यम से बनाए गए एकाधिकार पर फलती-फूलती हैं। हाल के वर्षों में, बड़ी इनोवेटर फार्मा कंपनियों ने छोटी, अधिक सक्रिय अनुसंधान-उन्मुख फर्मों में निवेश करने के लिए एक रणनीतिक कदम उठाया है। 2021 और 2023 के बीच छोटी बायो-टेक फर्मों में 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ।[16]

फार्मास्युटिकल क्षेत्र में भारत की ताकत मौजूदा पेटेंट रहित दवाओं का लागत प्रभावी और कुशल उत्पादक होने में निहित है- जिसे जेनेरिक उद्योग भी कहा जाता है। फिर भी शोध और विकास मूल दवा की लागत के एक अंश पर पेटेंट से मुक्त होने के बाद उन्हीं दवाओं का उत्पादन करने की कुंजी है। वे प्रतिस्पर्धा पर पनपते हैं। दुनिया को नवोन्मेषकों और उन लोगों की जरूरत है जो उचित मूल्य पर दवाएँ उपलब्ध करा सकते हैं, जिसमें सामाजिक लाभ बढ़ाने में बाद वाले की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए, उद्योग की ताकत नवोन्मेषकों और जेनेरिक उत्पादकों के विविध संयोजन में निहित है।

जैसे-जैसे हम विकसित भारत के विजन को साकार करने की ओर बढ़ रहे हैं, नवाचार को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। भारत में दवाओं और फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास व्यय वित्त वर्ष 20 और वित्त वर्ष 21 में बिक्री कारोबार का औसतन लगभग 5 प्रतिशत रहा।[17] अनसुलझे स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से नई दवाओं के विकास से आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुँच की व्यापकता और गुणवत्ता में सुधार होगा, साथ ही निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलेगा।

रिपोर्ट "भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्रीय नवाचार प्रणाली"[18] निम्नलिखित की आवश्यकता को रेखांकित करती है:

i) उद्योग जगत के प्रवर्तकों के बीच संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी के बजाय रणनीतिक रूप से अधिक सहयोगात्मक बनाना है।

16 द इकोनॉमिस्ट, अप्रैल 30 2024, क्या बायोटेक स्टार्टअप एली लिली और नोवो नॉर्डिस्क को आगे बढ़ा सकते हैं? पहुँच के लिए लिंक: (https://www.economist.com/business/2024/04/30/can-biotech-startups-upstage-eli-lilly-and-novo-nordisk)

17 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से अनुसंधान एवं विकास व्यय; और फार्मास्यूटिकल्स विभाग से बिक्री कारोबार।

18 https://dst.gov.in/sites/default/files/Indian%20Pharmaceutical%20Sectorial%20System%20of%20Innovation%20%28IPSSI%29%20Report_0.pdf

ii) अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए उद्योग-अकादमिक संपर्क को बढ़ावा देना, विशेष रूप से सार्वजनिक ज्ञान-आधारित संस्थानों की बेहतर भागीदारी।

iii) अनुसंधान के क्षेत्रों में बेहतर ज्ञान विनिमय और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान-आधारित संस्थानों विशेष रूप से टियर2 और टियर3 संस्थानों को शामिल करके इनके बीच बातचीत की कठोरता को कम करना।

iv) मानव पूंजी विकास को बेहतर ढंग से उन्मुख करने के लिए ज्ञान-आधारित संस्थानों और उद्योग के बीच सेकंडमेंट और प्लेसमेंट का समर्थन करना।

v) ज्ञान-आधारित संस्थानों और मध्यस्थों, विशेष रूप से उद्योग संघों के बीच संचार चौनलों को मजबूत करना।

vi) विचार-विमर्श से लेकर बाजार तक की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए उद्यम पूंजी और एंजेल निवेशकों से वित्त पोषण के चौनलों को बढ़ाना।

vii) नवाचार के लिए 'सरकार के समग्र दृष्टिकोण' को बढ़ावा देने के लिए सरकारी निकायों के बीच बेहतर ज्ञान साझा करना, जिससे रणनीतिक क्षेत्रों में अधिक समन्वित संयुक्त अनुसंधान हो सके।

सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने वाले एक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने और विकसित करने के लिए कई उपाय किए हैं। यह दवा क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और स्वास्थ्य क्षेत्र सहित कृत्रिम बुद्धिमत्ता में परिलक्षित होता है। हाल ही में शुरू किए गए फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने से दवा क्षेत्र में नवाचार की दिशा में बदलाव की उम्मीद है।

कपड़ा उद्योगः चुनौतियों का सामना करना

10.21 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय खातों के अनुसार, परिधान क्षेत्र सहित वस्त्रों ने वित्त वर्ष 23 में ₹3.77 लाख करोड़ का सकल मूल्य वर्धित किया, जो वर्ष के दौरान मौजूदा कीमतों पर विनिर्माण जीवीए का लगभग 10.6 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2013 में इस क्षेत्र की कुल गैर-कॉर्पोरेट विनिर्माण जीवीए में 29.3 प्रतिशत और कॉर्पोरेट विनिर्माण जीवीए में 7.9 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी।

10.22 भारत के पास कपड़ा उद्योग में एक मजबूत एंड-टू-एंड वैल्यू चेन है, जो प्राकृतिक और एमएमएफ फाइबर जैसे कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद तक फैली हुई है और इसमें परिधान, घरेलू वस्त्र और तकनीकी वस्त्र शामिल हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है और शीर्ष पांच निर्यातक देशों में से एक है। वित्त वर्ष 24 में, हस्तशिल्प सहित वस्त्र और परिधान का निर्यात 1 प्रतिशत बढ़कर ₹2.97 लाख करोड़ तक पहुंच गया। यह क्षेत्र विविधतापूर्ण है, जिसमें वित्त वर्ष 24 में कुल निर्यात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी (41 प्रतिशत) रेडीमेड कपड़ों की है, जिसका निर्यात ₹1.2 लाख करोड़ था, इसके बाद सूती वस्त्र (34 प्रतिशत) और मानव निर्मित वस्त्र (14 प्रतिशत) का स्थान है।

चार्ट X.13: कुल कपड़ा (परिधान सहित) जीवीए में गैर-कॉर्पोरेट जीवीए का हिस्सा

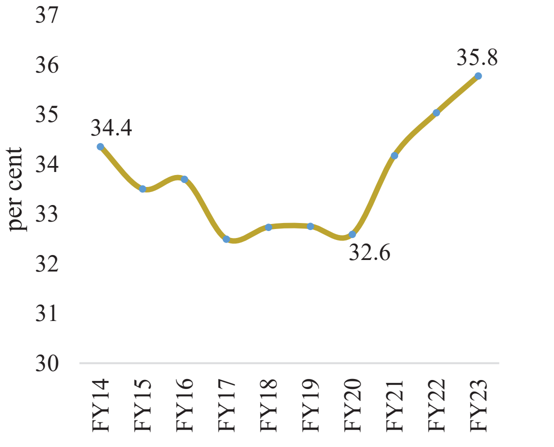

स्रोतः राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2024, एमओएसपीआई

चार्ट X.14: वस्त्र उत्पादों का कुल निर्यात

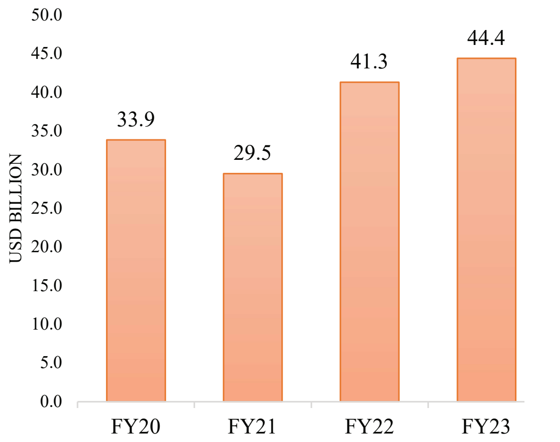

स्रोतः वस्त्र मंत्रालय

बॉक्स X.5: कपड़ा उद्योग में चुनौतियां और सहायक पहल

उद्योग संदर्भ और चुनौतियाँ	सहायक पहल
• भारत की कपड़ा और परिधान उत्पादन क्षमता का अधिकांश हिस्सा एमएसएमई के कारण है, जो इस क्षेत्र में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है, और परिचालन का औसत पैमाना अपेक्षाकृत छोटा है। इस प्रकार, बड़े पैमाने पर आधुनिक विनिर्माण से दक्षता और पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ सीमित हैं। • भारत के परिधान क्षेत्र की विखंडित प्रकृति, जिसमें कच्चे माल मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु से प्राप्त होते हैं, जबकि कताई क्षमताएँ दक्षिणी राज्यों में केंद्रित हैं, उच्च परिवहन लागत और देरी में योगदान देता है। • अन्य कारक, जैसे कि कताई क्षेत्र को छोड़कर आयातित मशीनरी पर भारत की भारी निर्भरता, कुशल जनशक्ति की अपर्याप्त उपलब्धता, तकनीकी अप्रचलन आदि भी महत्वपूर्ण बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। • नीति आयोग की सिफारिशों में इस क्षेत्र के लिए एटीयूएफएस जैसी पहलों के माध्यम से घरेलू मशीन निर्माताओं का समर्थन करना, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है। • प्राथमिकताओं में प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय कपड़ा बुनियादी ढाँचा बनाना भी शामिल है। तकनीकी उन्नयन, स्थिरता और परिपत्रता, गुणवत्ता और मानकों और हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार पर भी ध्यान दिया जाएगा।	• तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 28 तक ₹4,445 करोड़ रुपये के बजट के साथ सात पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। • पार्कों में 1,000 एकड़ का औद्योगिक बुनियादी ढांचा और 'प्लग एंड प्ले' सुविधाएं होंगी। • सभी सात राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, पांच राज्यों में संयुक्त उद्यम और एसपीवी स्थापित किए गए। • सरकार ने मानव निर्मित फाइबर परिधान और कपड़े और तकनीकी वस्त्रों के लिए पांच वर्षों में 10,683 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी दी। इससे 19,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित होने और 2.5 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। • वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2024 के लिए 1,480 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया गया राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है। • इसके चार घटक हैं: अनुसंधान, नवाचार और विकास, संवर्धन और बाजार विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, तथा निर्यात संवर्धन। इसे मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें मार्च 2028 तक का सनसेट क्लॉज है। • अब तक ₹474 करोड़ की 137 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। • वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 26 के लिए ₹998 करोड़ के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) को मंजूरी दी गई है। • वित्त वर्ष 24 में 96 छोटे हथकरघा क्लस्टर स्थापित करने की पहल की गई। नौ मेगा हथकरघा क्लस्टर भी स्थापित किए गए हैं।

स्रोत: वस्त्र मंत्रालय

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग: भविष्य को सशक्त बनाना

10.23 भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र ने 2014 से उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जो वित्त वर्ष 22 में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का अनुमानित 3.7 प्रतिशत है। वहीं, वित्त वर्ष 22 में उद्योग ने भारत के कुल सकल घरेलू

उत्पाद में 4 प्रतिशत का योगदान दिया। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का घरेलू उत्पादन उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 8.22 लाख करोड़ हो गया, जबकि वित्त वर्ष 23 में निर्यात बढ़कर 1.9 लाख करोड़ हो गया। भारत तेजी से इस क्षेत्र में निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है, और पिछले पांच वर्षों में देश में पर्याप्त विनिर्माण क्षमताएं स्थापित की गई हैं। कई प्रमुख ब्रांड, विदेशी और घरेलू दोनों ने या तो अपनी खुद की विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की हैं या भारत में काम कर रही इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवा कंपनियों को विनिर्माण आउटसोर्स किया है।

चार्ट X.15: इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

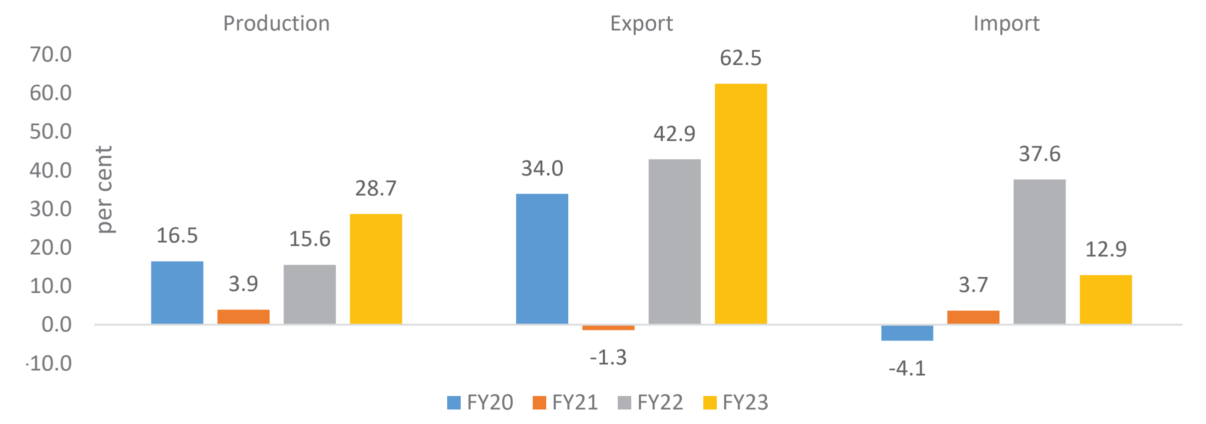

स्रोत: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)

10.24. सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज[19] के शोध से पता चलता है कि भारत ने वित्त वर्ष 2017 से मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए), रोजगार, मजदूरी और वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। मोबाइल फोन उत्पादन में डीवीए की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2019 (चरण 1) में औसतन 8.7 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 2022 (चरण 2) में 22 प्रतिशत हो गई, जो स्थानीय भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत है। जबकि निर्यात के अनुपात के रूप में डीवीए कम हो सकता है, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में भागीदारी से विशाल वैश्विक बाजार के लिए विनिर्माण में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के कारण समग्र मूल्य संवर्धन में वृद्धि होती है। मोबाइल फोन के उत्पादन में प्रत्यक्ष कार्यबल वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2022 के बीच तीन गुना से अधिक हो गया है, जिसका विशेष रूप से महिला ब्लू-कॉलर श्रमिकों को लाभ हुआ है। चरण 1 और चरण 2 के बीच मजदूरी और वेतन में 317 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अध्ययन से पता चलता है कि जीवीसी में निर्बाध भागीदारी के लिए सेवा लिंक लागत को कम करना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए लेनदेन लागत को कम करने के प्रयासों की आवश्यकता है। यह अन्य क्षेत्रों में सफलता को दोहराने के लिए मध्यवर्ती इनपुट के लिए कम आयात शुल्क सहित एक व्यापक नीति दृष्टिकोण की सिफारिश करता है।

बॉक्स X.6: इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने की पहल

भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण को उच्च प्राथमिकता देती है, जो 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' दोनों पहलों का एक प्रमुख पहलू है। इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण निवेश को आकर्षित करने और प्रोत्साहित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं: (i) बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई), (ii) पीएलआई आईटी हार्डवेयर, (iii) इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों (एसपीईसीएस) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना, और (iv) संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0)। ये योजनाएं देश के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विकास को गति देने में सहायक रही हैं। नतीजतन, वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 223 तक इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के उत्पादन में सीएजीआर 16.19 प्रतिशत रहा, जबकि इसी अवधि में निर्यात में 35.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

19 वीरमणि, सी. (2024 आगामी) ष्वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में पिछड़ी भागीदारी के माध्यम से भारत में मोबाइल फोन विनिर्माण से लाभष, विकास अध्ययन केंद्र (सीडीएस), तिरुवनंतपुरम, भारत

देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों (एसपीईसीएस) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना 2020 में शुरू की गई थी। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की डाउनस्ट्रीम मूल्य श्रृंखला बनाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामानों की एक विशिष्ट सूची के लिए पूंजीगत व्यय पर 25 प्रतिशत का पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। मार्च 2024 तक, इस योजना के तहत ₹12,638 करोड़ के प्रस्तावित निवेश और ₹1758 करोड़ के प्रतिबद्ध प्रोत्साहन को मंजूरी दी गई है।

आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0	इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी/ईएमसी 2.0) योजना
➢ मई 2023 में अधिसूचित इस योजना का उद्देश्य बिक्री और निवेश सीमा से जुड़े घटकों और उप-असेंबली के स्थानीयकरण को प्रोत्साहित करके विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक और गहरा बनाना है। ➢ यह योजना छह वर्षों के लिए भारत में निर्मित पात्र वस्तुओं की निवल वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 5 प्रतिशत का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। योजना की प्रगति: कुल उत्पादन: ₹3367.63 करोड़ अतिरिक्त निवेश: ₹269.44 करोड़ अतिरिक्त प्रत्यक्ष नौकरियाँ: 3493	➢ 2012 में शुरू की गई ईएमसी योजना भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को आकर्षित करने के लिए ईएमसी परियोजनाओं और सामान्य सुविधा केंद्रों का समर्थन करती है। ➢ अप्रैल 2020 में अधिसूचित ईएमसी 2.0 योजना उपरोक्त परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसके लिए आवेदन मार्च 2024 तक खुले हैं और मार्च 2028 तक वितरण किया जाएगा। ➢ योजना की प्रगति: योजना के तहत ₹184.91 करोड़ जारी किए गए हैं और इससे ₹40,429 करोड़ का निवेश आकर्षित होने और 5.02 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।

स्रोत: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)

मोटर वाहन उद्योग

10.25. भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में विभिन्न श्रेणियों में प्रमुख वैश्विक ऑटो निर्माता शामिल हैं, साथ ही एक जीवंत ऑटो कंपोनेंट उद्योग भी शामिल है जो विभिन्न ऑटो पार्ट्स, बॉडी और चेसिस का उत्पादन करता है। पिछले पाँच वर्षों की तुलना में वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 23 के दौरान ऑटोमोटिव पार्ट्स के घरेलू उत्पादन और खपत के मूल्य में वृद्धि कम हुई है। ऑटो कंपोनेंट का उत्पादन घरेलू और निर्यात बाजारों की गतिशीलता पर निर्भर करता है। ऑटो कंपोनेंट सेक्टर ऑटोमोबाइल उत्पादन के रुझानों का बारीकी से अनुसरण करता है। जैसा कि नीचे देखा गया है, महामारी ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र को काफी प्रभावित किया, जिससे ऑटोमोटिव पार्ट्स की मांग कमजोर हुई और इसलिए, उनके विस्तार की गति कम हुई।

10.26 पिछले दशक की पहली छमाही में, यात्री वाहनों, जैसे कि कारों और उपयोगिता वाहनों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। हालाँकि, महामारी का ऑटोमोटिव उद्योग के सभी क्षेत्रों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। जबकि यात्री वाहनों में जल्दी सुधार हुआ, दोपहिया, तिपहिया और वाणिज्यिक वाहनों के लिए रिकवरी की अवधि लंबी है। चार्ट X.17 से पता चलता है कि कारें और यूटिलिटी वाहन (यूवी), तिपहिया, दोपहिया और वाणिज्यिक वाहन वर्तमान में विस्तार कर रहे हैं, जैसा कि हाल के वर्षों की वृद्धि दरों में देखा गया है। वित्त वर्ष 24 में, देश ने लगभग 49 लाख यात्री वाहन, 9.9 लाख तिपहिया, 214.7 लाख दोपहिया और 10.7 लाख वाणिज्यिक वाहन बनाए।

चार्ट X.16: ऑटोमोटिव पार्ट्स उद्योग का प्रदर्शन

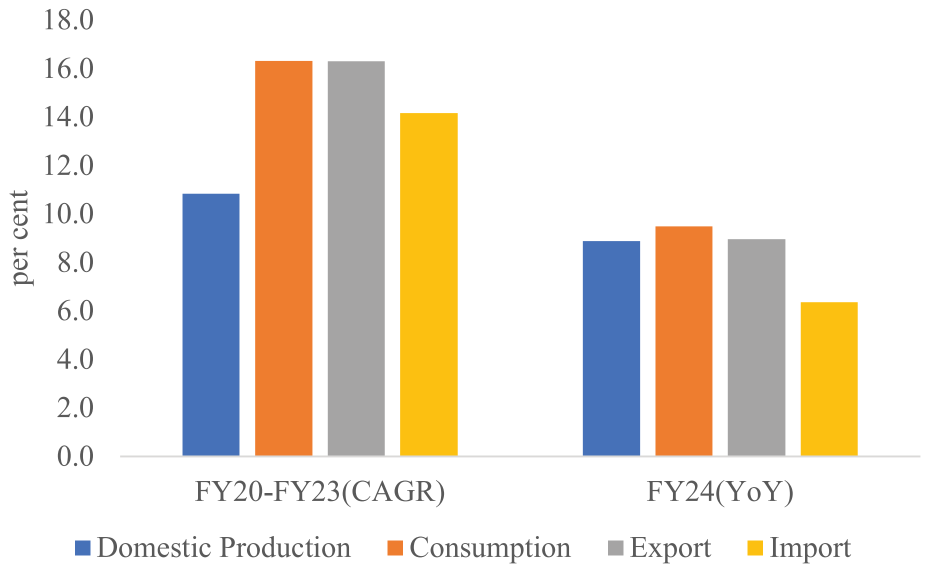

स्रोत: भारी उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण गणना

चार्ट X.17: विभिन्न श्रेणियों के ऑटोमोबाइल के उत्पादन में वार्षिक वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)

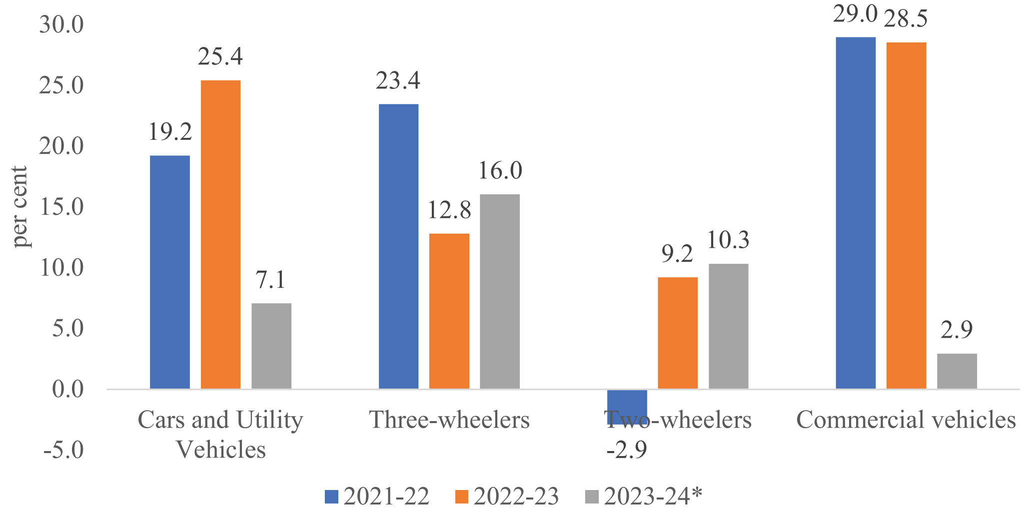

स्रोत: भारी उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण गणना

बॉक्स X.7: ऑटोमोबाइल और ई-मोबिलिटी के लिए नीतिगत समर्थन

	ई-मोबिलिटी के लिए	
पीएलआई योजना के तहत	**बैटरी भंडारण**	**फेम योजना का चरण II**
• ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए पीएलआई योजना में वित्त वर्ष 23 से वित्त वर्ष 27 तक ₹25,938 करोड़ का बजटीय परिव्यय है।	• आवेदकों ने 1.48 लाख रोजगार सृजन का प्रस्ताव दिया है, जिसके सापेक्ष 31/03/2024 तक 28,884 रोजगार सृजन हो चुका है।	• सरकार ने 24 जनवरी 2024 को 10 गीगावाट घंटा की कुल विनिर्माण क्षमता के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी किया। 70 गीगावाट घंटा की संचयी क्षमता के लिए बोलियाँ प्राप्त हुई।

• चौंपियन ओईएम प्रोत्साहन योजना और घटक चौंपियन प्रोत्साहन योजना में उप-विभाजित। • 85 आवेदकों को मंजूरी दी गई है। • 67,690 करोड़ का प्रस्तावित निवेश आकर्षित किया गया, जिसके लिए मार्च 2024 के अंत तक 14,043 करोड़ का निवेश किया जा चुका है। • इस योजना को वित्त वर्ष 28 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।	• मई 2021 में 18,100 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी। • गीगा स्केल एसीसी और बैटरी विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना करके एसीसी की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। • एसीसी के लिए 50 गीगावॉट घंटे की संचयी एसीसी विनिर्माण क्षमता और आला एसीसी प्रौद्योगिकियों के लिए 5 गीगावॉट घंटे की संचयी क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। • एसीसी पीएलआई बोली का पहला दौर मार्च 2022 में संपन्न हुआ, जिसके तहत 30 गीगावॉट घंटे की क्षमता आवंटित की गई। • सरकार ने 24 जनवरी 2024 को 10 गीगावाट घंटा की कुल विनिर्माण क्षमता के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी किया। 70 गीगावाट घंटा की संचयी क्षमता के लिए बोलियाँ प्राप्त हुई।	• वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 24 के दौरान 5 वर्षों के लिए 11500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्वीकृत। • इसका उद्देश्य 7000 ई-बसों, 5 लाख ई-3 पहिया वाहनों, 5 से वित्त वर्ष 5000 ई-4 पहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-2 पहिया वाहनों की सहायता से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग पैदा करना है। ई-वाहनों में प्रगति तालिका X.2 में प्रस्तुत की गई है। • भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई) को मार्च 2024 में मंजूरी दी गई थी। • जुलाई 2024 तक 4 महीने की अवधि के लिए ₹500 करोड़ के परिव्यय के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (ईएमपीएस 2024)। इसका उद्देश्य पंजीकृत ई-रिक्शा, ई-कार्ट और एल5 सहित ई2 व्हीलर्स और ई3 व्हीलर्स को तेजी से अपनाना है।

तालिका X.2: फेम योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत प्रोत्साहित वाहनों की संख्या ('000 में)

खंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
e-2W	11.4	29.3	116.6	208.8	804.2	1170.2
e-3W	3.4	9.1	21.8	19.8	76.2	130.3
e-4W	0.7	0.7	0.7	2.1	1.4	16.6
e-bus	0.0	0.4	0.7	1.6	1.9	4.6
Total	15.6	39.6	139.8	232.2	894.6	1321.8

स्रोत: भारी उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण गणना

क्रॉस-कटिंग थीम

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

10.27. भारत के आत्मनिर्भर बनने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए ₹1.97 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की घोषणा की गई। मई 2024 तक ₹1.28 लाख करोड़ से अधिक का निवेश दर्ज किया गया, जिससे ₹10.8 लाख करोड़ का उत्पादन/बिक्री हुई और 8.5 लाख से अधिक (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) रोजगार सृजन हुआ। निर्यात

में ₹4 लाख करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण और दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों जैसे क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

10.28. सरकार ने ₹6,238 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी लाइट्स) के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। मई, 2024 तक पीएलआई योजना के तहत व्हाइट गुड्स (एसी, एलईडी) द्वारा प्राप्त संचयी निवेश ₹3181 करोड़ था, जिससे ₹13320 करोड़ की संचयी बिक्री हुई। शेष क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना संबंधित क्षेत्र अनुभागों के अंतर्गत आती है।

चार्ट X.18: पीएलआई योजना के तहत वास्तविक क्षेत्रवार निवेश

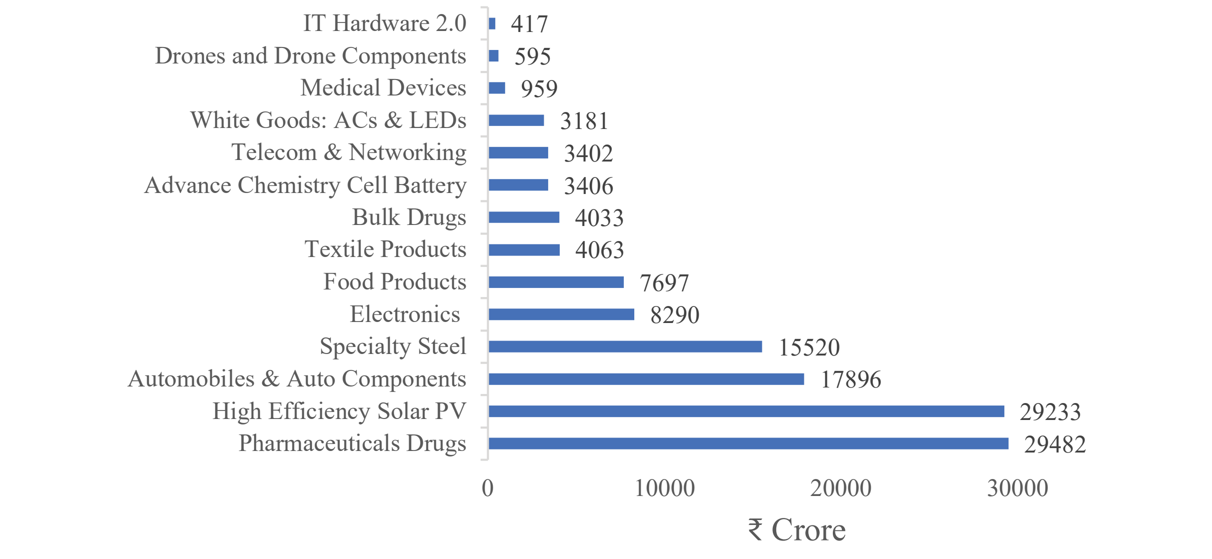

स्रोत: नीति आयोग

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

10.29. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2022 के दौरान अखिल भारतीय विनिर्माण उत्पादन में एमएसएमई की हिस्सेदारी 35.4 प्रतिशत थी। वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) के डेटा प्रसार पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2023-24 में अखिल भारतीय निर्यात में एमएसएमई-निर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात की हिस्सेदारी 45.7 प्रतिशत थी।

10.30. वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23[20] के लिए असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, अप्रैल, 2021-मार्च 2022 की तुलना में अक्टूबर 2022-सितंबर 2023 की अवधि के दौरान भारत में असंगठित उद्यमों की संख्या में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान, प्रति कर्मचारी सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) ₹1,38,207 से बढ़कर ₹1,41,769 हो गया और प्रति प्रतिष्ठान सकल उत्पादन मूल्य (जीवीओ) ₹3,98,304 से बढ़कर ₹4,63,389 हो गया। यह श्रम सहित संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग के साथ उत्पादकता में वृद्धि को दर्शाता है, जो निरंतर आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है।

10.31. जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया उद्यम पंजीकरण पोर्टल, स्व-घोषणा के आधार पर एक सरल, ऑनलाइन और नि:शुल्क पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान करके एमएसएमई को औपचारिक बनाने में सहायक रहा है। 05 जुलाई 2024 तक, उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 4.69 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत हैं, जिनमें उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम भी शामिल हैं। उद्यम पंजीकरण एमएसएमई को एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं का लाभ उठाने में मदद

20 एमएसएमई गो डिजिटल: कोविड-19 संकट के दौरान बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, आईसीआरआईईआर, 2022, पृष्ठ 10 (MSMEs_Go_Digital.pdf (icrier.org))

करता है। उद्यम-पंजीकृत एमएसएमई बैंकों से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए भी पात्र हैं। उद्यम पोर्टल का 37 अन्य पोर्टलों के साथ एपीआई लिंकेज है और इसके माध्यम से डेटा साझा करने की सुविधा है। इससे एमएसएमई क्षेत्र को काफी फायदा हुआ है।

10.32. केंद्रीय बजट 2023-24 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) को ₹9,000 करोड़ आवंटित किए गए, जिसका लक्ष्य कम लागत के साथ अतिरिक्त ₹2 लाख करोड़ का ऋण उपलब्ध कराना है। वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 24 तक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए गारंटी की राशि और संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई (चार्ट X.19)।

बॉक्स X.8: एमएसएमई ऋण योजनाएं

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	ऋण गारंटी योजना (सीजीएस)
• वित्त वर्ष 23 के दौरान, ₹2,722.17 करोड़ की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ 85,167 सूक्ष्म इकाइयों को सहायता प्रदान की गई, जिससे लगभग 6.81 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए। • वित्त वर्ष 24 में, यह सहायता ₹3,093.87 करोड़ की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ 89,118 सूक्ष्म इकाइयों तक बढ़ा दी गई, जिससे लगभग 7.13 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए।	• सीजीटीएमएसई द्वारा प्रशासित • 85 प्रतिशत तक की गारंटीकृत कवरेज के साथ ₹5 करोड़ तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋण की पेशकश करके एमएसएमई द्वारा सामना की जाने वाली ऋण बाधाओं को कम करने का लक्ष्य। • इस योजना ने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक ₹6.78 लाख करोड़ की राशि की 91.76 लाख गारंटी को मंजूरी दी है। अकेले वित्त वर्ष 24 में, ₹2.03 लाख करोड़ की 17.24 लाख गारंटी को मंजूरी दी गई।

चार्ट X.19: सीजीटीएमएसई के तहत स्वीकृत गारंटियों में काफी वृद्धि हुई

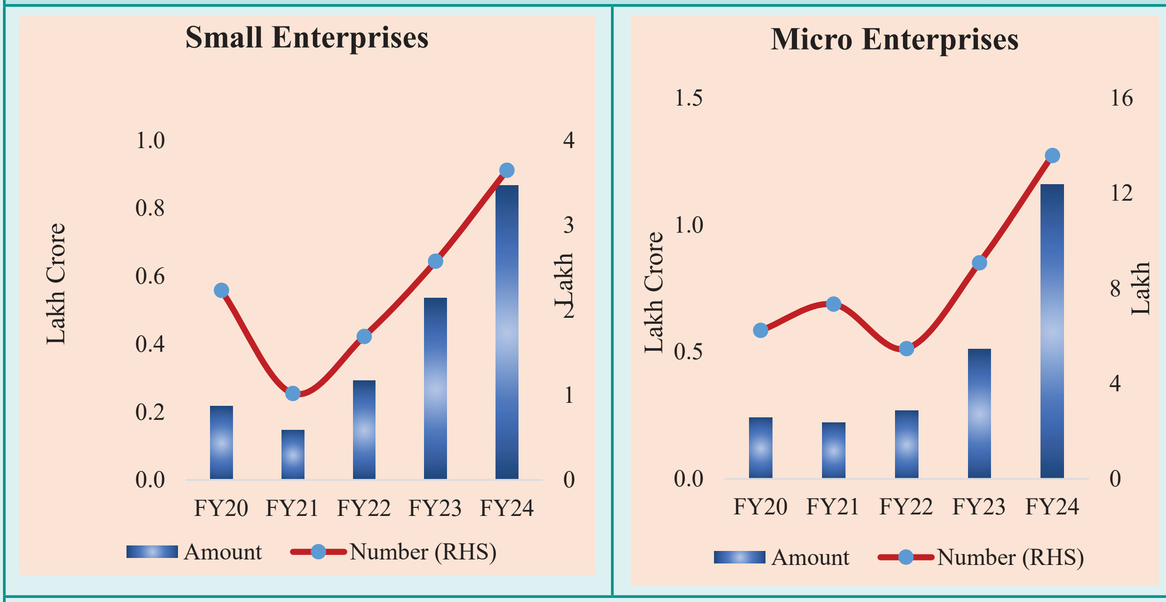

स्रोत: एमएसएमई मंत्रालय

10.33. **चुनौतियाँ और अवसर:** एमएसएमई को औपचारिकता और समावेशन, वित्त, बाजार, प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण तक सीमित पहुँच, बुनियादी ढाँचे की अड़चनें और कौशल विकास सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार ने औपचारिकता, पंजीकरण में आसानी और शिकायत निवारण के लिए

पहल और प्लेटफॉर्म लागू किए हैं, जैसे समाधान पोर्टल, संबंध पोर्टल और चौंपियंस पोर्टल, जो भुगतान में देरी, खरीद की निगरानी और शिकायतों के त्वरित समाधान में सहायता करते हैं। वैश्विक मूल्य श्रृंखला विकास रिपोर्ट (2019) इस बात पर प्रकाश डालती है कि यद्यपि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एसएमई का प्रतिनिधित्व कम है, लेकिन डिजिटल अर्थव्यवस्था उन्हें महत्वपूर्ण नए अवसर प्रदान करती है। यह भारत के एमएसएमई क्षेत्र में स्पष्ट है, जहाँ 2020-21 में कुल ई-कॉमर्स बिक्री का लगभग 70 प्रतिशत[21] एमएसएमई से था, जो साल-दर-साल 60-70 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता है। इसके अलावा, शोध से पता चलता है कि फैक्ट्री स्पेस के उपयोग पर विनियमन के स्तर को पुनः परिभाषित करने से, जैसे कि सेटबैक से संबंधित विनियमनों से, विनिर्माण क्षमता में वृद्धि होगी, विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु फर्मो की (बॉक्स X.9)।

बॉक्स X.9: विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए भवन विनियमों की पुनर्कल्पना

मौजूदा औद्योगिक भवन विनियम फैक्ट्री भूमि उपयोग को सीमित करते हैं, भूमि उपयोगिता को कम करते हैं और परिणामस्वरूप अनिर्धारित लागतें होती हैं। विनियमन की स्थितिः नौकरियों और विकास के लिए भवन मानक सुधार शीर्षक वाली रिपोर्ट[22] बताती है कि कैसे भूमि कवरेज, सेटबैक, पार्किंग और फ्लोर एरिया अनुपात से संबंधित चार भवन विनियमों का अनुपालन करते हुए भूमि अप्रयुक्त रहती है।

1. **ग्राउंड कवरेज के कारण भूमि का नुकसानः** रिपोर्ट से पता चलता है कि फैक्ट्री भूखंडों पर ग्राउंड कवरेज नियमों के तहत, घनत्व को नियंत्रित करने और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, एक फैक्ट्री की इमारत प्लॉट के 40-60 प्रतिशत से अधिक को कवर नहीं कर सकती है, जो इस पर निर्भर करता है कि वह किस राज्य में अपने फैक्ट्री का परिचालन करता है। इसकी तुलना में, हांगकांग में, किसी फैक्ट्री के भूखंड का कोई भी हिस्से का नुकसान नहीं होता; फिलीपींस में, भूखंड का केवल 30 प्रतिशत नुकसान होता है।

2. **आग के कारण भूमि का नुकसानः** राज्य-स्तरीय नियम आग के जोखिम को कम करने और वेंटिलेशन और प्रकाश सुनिश्चित करने के लिए क्षैतिज भवन विस्तार को सीमित करते हैं। हालांकि, उपर्युक्त रिपोर्ट से पता चलता है कि नियम प्रौद्योगिकी और विनिर्माण प्रक्रियाओं में आधुनिकीकरण को ध्यान में नहीं रखते हैं। उदाहरण के लिए, आग प्रतिरोधी सामग्री और स्वचालित अग्निशमन उपकरणों का उपयोग भूमि को बंद किए बिना खतरों को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है। इसके अलावा, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ उद्योगों में प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन प्रतिकूल हो सकता है। कुछ राज्यों में सूक्ष्म और लघु कारखानों के लिए आग विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हैं। इन नियमों को पूरा करने के लिए कुछ राज्यों में कारखानों को अपनी 60-90 प्रतिशत भूमि भी खोनी पड़ती है। भारतीय राज्य में एक मेगा फैक्ट्री फिलीपींस की तुलना में आग के कारण लगभग 2 गुना अधिक भूमि खोती है और सिंगापुर की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक भूमि खोती है।

3. **पार्किंग नियमों के कारण भूमि का नुकसानः** राज्य सरकारें सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग अनिवार्य करने वाले नियम लागू करती हैं। हालाँकि, शोध से पता चलता है कि ये अनिवार्यताएँ वास्तव में और अधिक भीड़भाड़ में योगदान दे सकती हैं। पार्किंग की आवश्यकताएँ वास्तविक माँग के अनुरूप नहीं हैं, जिसके कारण कारखानों को काफी मात्रा में भूमि खोनी पड़ रही है। रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत भर में कारखानों को पार्किंग की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी लगभग 12-70 प्रतिशत भूमि खोनी पड़ रही है। भारत में एक कारखाने को हांगकांग, फिलीपींस या सिंगापुर की तुलना में कम से कम दोगुनी संख्या में कार पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं।

4. **फ्लोर रेशियो के कारण भूमि का नुकसानः** राज्य निर्दिष्ट भूमि के भाग पर ऊर्ध्वाधर विस्तार को प्रतिबंधित करने के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को विनियमित करते हैं, जिसका उद्देश्य घनत्व का प्रबंधन करना, यातायात की भीड़ को कम करना और पानी और बिजली जैसी आवश्यक उपयोगिताओं के प्रावधान को

21 एमएसएमई गो डिजिटलः कोविड-19 संकट के दौरान बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, आईसीआरआईईआर, 2022, पृष्ठ 10 (MSMEs_Go_Digital.pdf (icrier.org))

22 भुवाना, ए., कौर, एस., और रॉय, एस., दिसंबर 2023। 'विनियमन की स्थितिः नौकरियों और विकास के लिए मानकों में सुधार का निर्माण'। प्रोस्पेरिटी,

सुविधाजनक बनाना है। हालाँकि, ऐसे नियम अनजाने में शहरी फैलाव में योगदान दे सकते हैं, जिससे सड़क की भीड़ बढ़ जाती है और उपयोगिता के प्रावधान का खर्च बढ़ जाता है। औसतन, राज्यों में कारखानों को प्लॉट के आकार से 1.3 गुना तक ही फ्लोर स्पेस बनाने की अनुमति है। 1000 वर्ग मीटर के प्लॉट के साथ, मुंबई में एक कार्यालय भवन 5000 वर्ग मीटर तक बनाया जा सकता है, जबकि जापान में यह 13,000 वर्ग मीटर और सिंगापुर और हांगकांग में 15,000 वर्ग मीटर तक बनाया जा सकता है।

विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए भवन विनियमों की जांच करने और उन्हें तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है। भूमि के बेहतर उपयोग से प्रति इकाई उत्पादन की निश्चित लागत आएगी, जिससे उद्यमी को अधिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के अलावा, अंतर-राज्यीय तुलना राज्यों को सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने और उचित नीतियां अपनाने में मदद कर सकती है।

बॉक्स X.10: ओडीओपी: क्षेत्रीय गौरव और आर्थिक सशक्तिकरण का निर्माण

वर्ष 2018 में, सरकार ने क्षेत्रीय आर्थिक विभाजन को पाटने और भारत के विविध जिलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में उत्पादित एक एकल, प्रतिष्ठित उत्पाद के माध्यम से प्रत्येक जिले की विशिष्ट शक्तियों की पहचान, ब्रांडिंग और प्रचार करने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल शुरू की। जिन जिलों में एक से अधिक उत्पादों की पहचान की गई है, उन्हें द्वितीयक या तृतीयक उत्पादों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये उत्पाद कृषि, विनिर्माण, हथकरघा और वस्त्र, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री और सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हैं। इस पहल ने अब तक देश भर के 761 जिलों से 1102 उत्पादों की पहचान की है।

ओडीओपी पहल को बढ़ावा देने के लिए, वित्त वर्ष 24 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई कि राज्यों को अपने स्वयं के ओडीओपी, जीआई उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए अपने राज्य की राजधानी या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र या वित्तीय राजधानी में एक "यूनिटी मॉल" स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और अन्य सभी राज्यों के ऐसे उत्पादों के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। इन "पीएम-एकता मॉल" का उद्देश्य ओडीओपी के कारीगरों और उपभोक्ताओं को जोड़ना है। ये मॉल देश के अनूठे उत्पादों के लिए एक जीवंत बाजार बना रहे हैं, जिसका लक्ष्य घरेलू और विदेशी दोनों बाजार हैं।

सरकार ओडीओपी को बढ़ावा देने और सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए कई पहल कर रही है। केंद्र और स्थानीय विक्रेताओं के बीच सहयोग को सुगम बनाने और स्वदेशी उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए 15 राज्यों में 'ओडीओपी संपर्क' कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान देश भर में आयोजित विभिन्न जी20 कार्यक्रमों में ओडीओपी ने दुनिया के सामने भारत को प्रदर्शित किया, जहाँ कार्यक्रमों के दौरान कारीगरों, विक्रेताओं और बुनकरों को वैश्विक मंच पर काफी पहचान मिली।[23]

ओडीओपी की कुछ सफलता की कहानियाँ

- विभिन्न सरकारी पहलों द्वारा वित्तपोषित पैक शेड और सिंचाई के परिणामस्वरूप कश्मीर के शोपियां में सेब के उत्पादन में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- उत्तरकाशी जिले में गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय प्रशासन और 700 से अधिक किसानों को 15 विशेष प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से जैविक खेती के कौशल से सशक्त बनाया गया है। 1000 से अधिक लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों से सुसज्जित, इस जिले में लाल चावल का उत्पादन काफी बढ़ गया है।
- आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में लगभग 1,50,000 आदिवासी परिवारों ने गिरिजन सहकारी निगम के ऋणों से कॉफी उत्पादन में 20 प्रतिशत की वृद्धि की है।

23 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2000801

- ओडिशा के कंधमाल जिले में 5,000 से अधिक प्रशिक्षित श्रमिकों ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हल्दी बाजारों को आकर्षित करने के लिए 1,300 किसानों के साथ मिलकर काम किया है। मसाले की सरकारी खरीद में भी लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पंजाब के भटिंडा जिले में त्वरित परीक्षण प्रयोगशालाओं, सब्सिडी, ऋण के रूप में वित्तीय सहायता और औपचारिकीकरण के लिए समर्थन के कारण शहद उत्पादन[24] में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई)

10.34. 31 मार्च, 2023 तक 254 सीपीएसई प्रचालन में थे। लगभग 66 प्रतिशत सीपीएसई सेवा क्षेत्र में संचालित थे; बाकी विनिर्माण, प्रसंस्करण और उत्पादन तथा खनन और अन्वेषण में। सीपीएसई ने वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 में मजबूत वित्तीय मापदंड हासिल किए। भारत के स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार करने वाले 63 सीपीएसई का कुल बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 31 मार्च, 2023 तक ₹16.69 लाख करोड़ था, जबकि 31 मार्च, 2022 तक यह ₹15.46 लाख करोड़ था, जो 7.95[25] प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 23 में परिचालन करने वाले सीपीएसई का कुल निवल लाभ ₹2.12 लाख करोड़ था। सीपीएसई के प्रमुख वित्तीय मापदंड नीचे दिए गए चार्ट में प्रस्तुत किए गए हैं।

चार्ट X.20: वित्त वर्ष 19 और वित्त वर्ष 23 के बीच सीपीएसई के प्रदर्शन में सुधार (सीएजीआर)

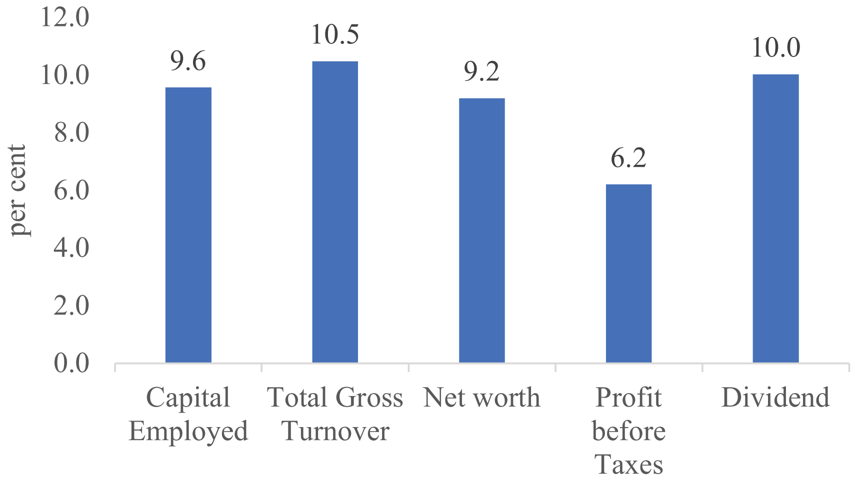

स्रोत: पीई सर्वेक्षण रिपोर्ट, लोक उद्यम विभाग

चार्ट X.21: लाभ कमाने वाले सीपीएसई की संख्या में सुधार हुआ है

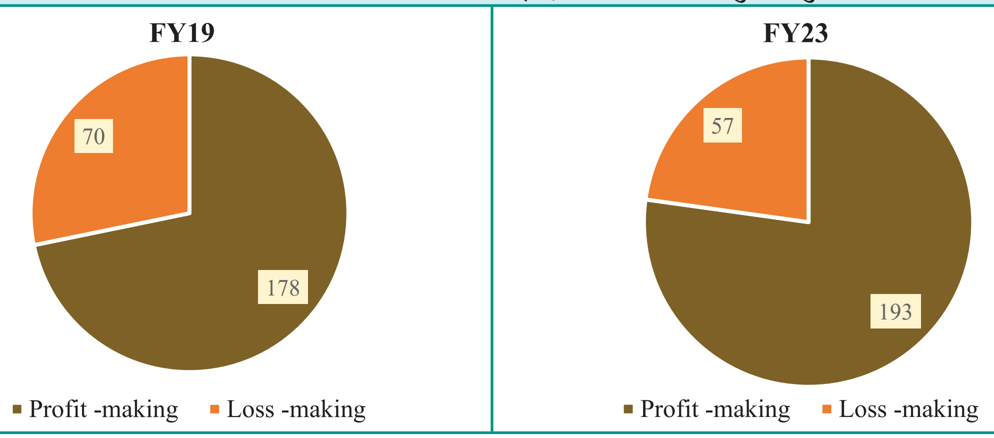

स्रोत: पीई सर्वेक्षण रिपोर्ट, लोक उद्यम विभाग

24 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की 2 फरवरी 2024 की पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति, लिंक यहां उपलब्ध है: https://pib.gov.in/FeaturesDeatils.aspx?NoteId=151807-ModuleId%20=%202

25 https://dpe.gov.in/sites/default/files/PES%202022-23_E.pdf

औद्योगिक ऋण

10.35. औद्योगिक ऋण वृद्धि कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें आर्थिक गतिविधि की चक्रीयता, बैंक फंड और अन्य बाजार विकल्पों की उपलब्धता और लागत में सापेक्षता, औद्योगिक उद्यमों के अपने संसाधनों की स्थिति और बैंकिंग प्रणाली की अपनी जोखिम क्षमता शामिल है। वित्त वर्ष 21 में महामारी के कारण मंदी से उबरते हुए, अगले वर्ष औद्योगिक ऋण में जोरदार वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 23 में, ऋण वृद्धि मुख्य रूप से बड़े उद्योगों द्वारा संचालित थी; हालाँकि, कुछ क्षेत्रों को ऋण में कमी के कारण यह वृद्धि बाधित हुई।

चार्ट X.22: उद्योग में सकल बैंक ऋण के परिनियोजन में वृद्धि

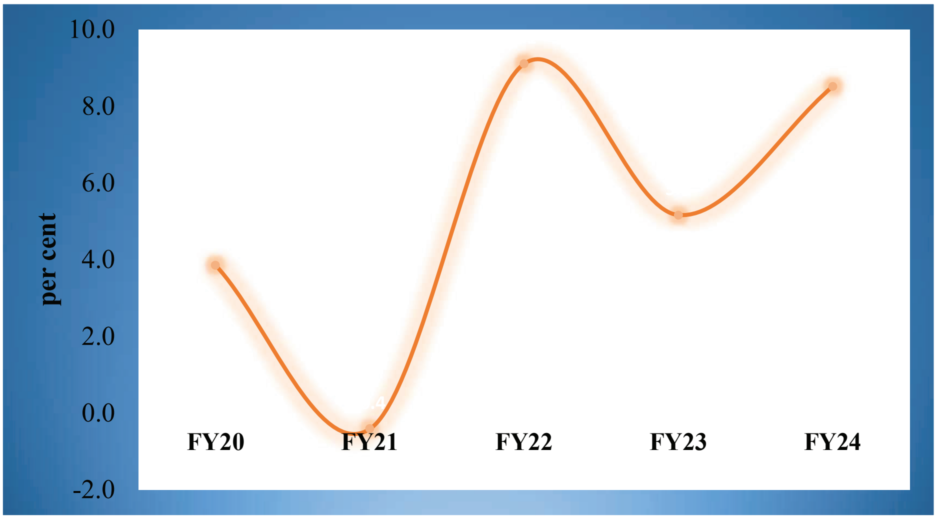

स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस, सकल बैंक ऋण की उद्योगवार परिनियोजन, आरबीआई

नोट 1: मार्च 2019 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा एक संशोधित प्रारूप पर आधारित है, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मूल्यों और विकास दरों में बदलाव आया है।

नोट 2: मार्च 2022 के लिए चुनिंदा एससीबी द्वारा पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए क्रेडिट डेटा समायोजित किया जाता है।

नोट 3: 2023-24 के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

तालिका X.3: ऋण परिनियोजन में उद्योग-वार वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

न्यूनतम	कम ... अधिकतम मार्च 2020 से मार्च 2024 तक सीएजीआर	मार्च-24 में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)
खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	4.5	-10.1
खाद्य प्रसंस्करण	9.7	14.9
पेय पदार्थ और तम्बाकू	14.6	30.9
वस्त्र	7.3	11.2
चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	4.7	5.4
लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	15.0	12.4
कागज और कागज के उत्पाद	9.2	4.9
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन	13.4	-11.4
रसायन और रासायनिक उत्पाद	5.8	11.3
रबर, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	14.5	7.6
कांच और कांच के बने पदार्थ	15.4	26.3

सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	-0.5	2.9
मूल धातु और धातु उत्पाद	3.5	12.2
सभी इंजीनियरिंग	4.8	10.5
वाहन, पुर्जे और परिवहन उपकरण	5.9	11.4
रत्न और आभूषण	6.2	8.0
निर्माण	1.1	6.9
बुनियादी ढांचा	4.7	6.6
अन्य उद्योग	3.7	18.4
कुल उद्योग	5.5	8.5

स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस, सकल बैंक ऋण की उद्योगवार परिनियोजन, आरबीआई

औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और नवाचार

10.36. चूंकि मुख्य विनिर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति केवल लगभग 7 प्रतिशत तक सीमित है, इसलिए औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास में भी इसकी हिस्सेदारी सीमित है। वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) 2023 संकेतक की प्रारंभिक समीक्षा से पता चलता है कि कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास में अमेरिका सबसे आगे है, उसके बाद चीन और जर्मनी का स्थान है। भारत, तुर्की, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे मध्यम आय वाले देशों ने भी अपने अनुसंधान एवं विकास[26] में वृद्धि का अनुभव किया है। चूंकि भारत में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास कुछ क्षेत्रों में ही केंद्रित है, इसलिए शीर्ष पांच क्षेत्रों की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक है।

तालिका X.4: भारत में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथ्य: वित्त वर्ष 19 से वित्त वर्ष 21 औसत

भारत में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास व्यय (करोड़ रुपये)	44720
विनिर्माण GVA के प्रतिशत के रूप में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास	1.61
निजी क्षेत्र द्वारा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास, निजी क्षेत्र के विनिर्माण GVA के प्रतिशत के रूप में	1.53
सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास, सार्वजनिक क्षेत्र के विनिर्माण GVA के प्रतिशत के रूप में	2.67
औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाइयों की संख्या: निजी क्षेत्र	1866
औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाइयों की संख्या: सार्वजनिक क्षेत्र	94

चार्ट X.23: भारत में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास व्यय में उप-क्षेत्रों की हिस्सेदारी: वित्त वर्ष 19 से वित्त वर्ष 21

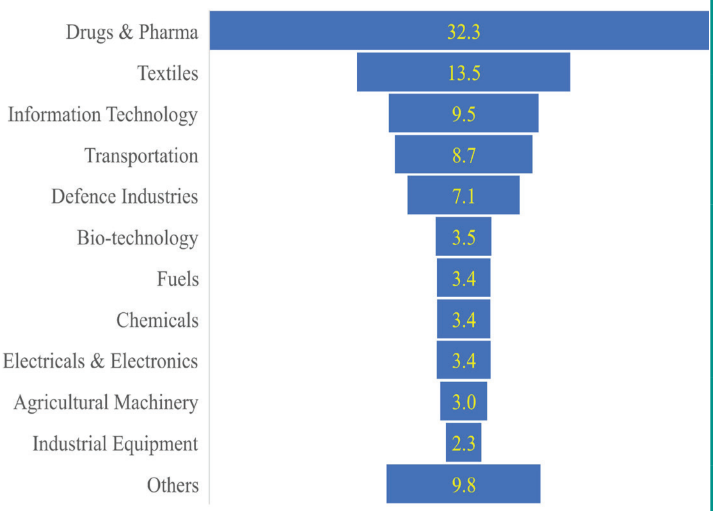

स्रोत: अनुसंधान एवं विकास सांख्यिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

26 वैश्विक नवाचार सूचकांक (2023) विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ)

10.37. समावेशी, टिकाऊ और नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक समग्र नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। नवाचार प्रणाली हितधारकों और संस्थानों के बीच प्रणालीगत बातचीत पर जोर देती है जो नवाचार प्रक्रियाओं[27] को प्रभावित करती है। इसमें अनौपचारिक और जमीनी स्तर के नवाचार से अंतर्दृष्टि शामिल है, जो विशिष्ट मांगों को पूरा करने की उनकी क्षमता को उजागर करती है। भारत में नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई सबसे महत्वपूर्ण पहलों में शामिल हैं:

बॉक्स X.11: भारत में स्टार्टअप और नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयास

पेटेंट और अनुसंधान	स्टार्ट-अप्स	प्रतिस्पर्धा
• पेटेंट नियम, 2024 को अधिसूचित किया गया, जिससे पेटेंट अधिग्रहण और प्रबंधन सरल हो गया। • स्वीकृत पेटेंट की संख्या 2014-15 में 5978 से सत्रह गुना बढ़कर 2023-24 में 103057 हो गई। • पंजीकृत डिजाइन 2014-15 में 7147 से बढ़कर 2023-24 में 30672 हो गए। • अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) विधेयक 2023 पारित किया गया। 2023-28 के दौरान इसकी अनुमानित लागत ₹50,000 करोड़ है। • एएनआरएफ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा। यह उद्योग, शिक्षा, सरकारों और अनुसंधान निकायों के बीच सहयोग स्थापित करेगा और इंटरफेस की सुविधा प्रदान करेगा।	• 2016 में लगभग 300 स्टार्ट-अप से, मार्च 2024 के अंत तक डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप की संख्या बढ़कर 1.25 लाख से अधिक हो गई। • मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप में से 45 प्रतिशत से अधिक टियर 2/3 शहरों से उभर रहे हैं। • मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप में से 47 प्रतिशत से अधिक में कम से कम एक महिला निदेशक हैं। • स्टार्ट-अप ने 2016 से जनवरी 2024 तक 13,000 से अधिक पेटेंट आवेदन दायर किए। वित्त वर्ष 24 के अंत तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में 13,000 से अधिक डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप हैं। • स्टार्ट-अप के लिए फंड ऑफ फंड्स के तहत, 135 से अधिक वैकल्पिक निवेश फंडों को 10,500 करोड़ से अधिक की प्रतिबद्धता जताई गई है, जिन्होंने वित्त वर्ष 24 के अंत तक स्टार्ट-अप में 18,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया है। • भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री का उद्देश्य स्टार्टअप इकोसिस्टम में विविध हितधारकों को एक साथ लाना है।	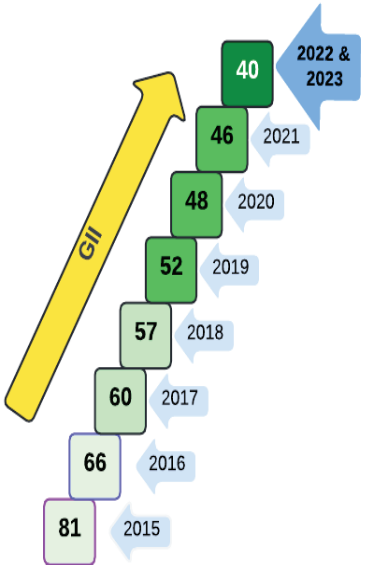 • ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) के तहत भारत की रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ है। • भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों और मध्य और दक्षिणी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर है। • भारत घरेलू बाजार पैमाने के संकेतक में वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान पर है।

स्रोत: डीपीआईआईटी

27 लुंडवैल, बी. ए., जोसेफ, के. जे., चौमिनेड, सी., वांग, जे. (2009)। 'नवाचार प्रणाली और विकासशील देशों की पुस्तिका' चेल्टेनहैम: एडवर्ड एल्गार्ड

निष्कर्ष एवं दृष्टिकोण

10.38. उपर्युक्त विश्लेषण भारतीय औद्योगिक परिदृश्य में उभरते रुझानों का संकेत देता है। सबसे पहले, पिछले दशक में, औद्योगिक खंडों के बीच उत्पादन हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। रसायन, लकड़ी के उत्पाद और फर्नीचर, फार्मास्यूटिकल्स, परिवहन उपकरण, इस्पात और मशीनरी और उपकरण जैसे क्षेत्रों में मजबूती आई है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक मध्यवर्ती और उपभोक्ता सामान हैं, जबकि अन्य पूंजी निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दूसरी ओर, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, पेय पदार्थ और तंबाकू और पेट्रोलियम उत्पाद और चमड़ा जैसे क्षेत्रों ने अपनी सापेक्ष स्थिति खो दी है।

10.39 दूसरे, पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न औद्योगिक खंडों का निर्यात-आयात संतुलन काफी हद तक अलग-अलग रहा है। लगातार, प्रमुख शुद्ध निर्यातकों में इस्पात, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसे उद्योग शामिल हैं। दूसरी ओर, कोयला, पूंजीगत सामान और रसायन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आयात निर्भरता जारी है।

10.40 तीसरा, पूंजीगत वस्तुओं और इस्पात तथा सीमेंट जैसे प्रमुख निर्माण इनपुट की मांग पर मध्यम अवधि का दृष्टिकोण सकारात्मक रहने की संभावना है, क्योंकि इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि निजी क्षेत्र में पूंजी निर्माण गति पकड़ रहा है। वैश्विक अनिश्चितताएं कोयला, पेट्रोलियम, इस्पात और मशीनरी जैसे महत्वपूर्ण आयातित इनपुट पर निर्भरता के कारण निर्यात मांग और उत्पादन की घरेलू लागत पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं।

10.41 सरकार ने व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने, अनुपालन बोझ को कम करने और लॉजिस्टिक तथा अवसंरचना संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए कई पहल की हैं। प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं ने महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है, उत्पादन, बिक्री और निर्यात को बढ़ावा दिया है और रोजगार पैदा किए हैं, विशेष रूप से सफेद वस्तुओं के मामले में। देश भर की सरकारें जहाँ मदद कर सकती हैं, वह है उन नियमों की समीक्षा, संशोधन, शिथिलता और निरस्तीकरण करना जो अव्यवस्थित, खराब, अनुत्पादक हैं और बिना किसी लोक हित के व्यवसायों के संचालन की लागत बढ़ाते हैं। उद्यमियों के लिए सबसे अच्छे निर्णय कानून द्वारा अनिवार्य हैं, जिससे अभियोजन का डर पैदा होता है। भारत में आगे के औद्योगीकरण का मार्ग विनियमन से प्रशस्त होता है।

10.42 उद्योगों में दो सामान्य आवश्यकताएँ अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने और कार्यबल के कौशल स्तरों में सुधार लाने से संबंधित हैं। दोनों के संबंध में, उद्योग को नेतृत्व करना चाहिए। किसी भी वित्तीय प्रोत्साहन के बगैर, अनुसंधान एवं विकास के प्रति प्रतिबद्धता उद्योग के डीएनए में होनी चाहिए, क्योंकि यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा और लाभप्रदता के बारे में है। उद्योग और शिक्षाविदों के बीच सक्रिय सहयोग और पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देने के साथ, भारत अब तक की तुलना में कौशल की कमी को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है।

10.43 कपड़ा जैसे व्यापक रूप से बिखरी उत्पादन इकाइयों वाले क्षेत्र और सामान्य रूप से एमएसएमई क्षेत्र, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, बाजार पहुंच और औपचारिकता की बाधाओं के समाधान की तलाश में हैं। एमएसएमई के भाग में उल्लिखित इन मुद्दों को हल करने के लिए कई केंद्रित नीतिगत पहल की गई हैं; सहकारी संघवाद मोड में उपयुक्त सरकारों के स्तर पर निम्नलिखित दिशा में आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है:

(क) एमएसएमई परियोजनाओं को विकसित करने के लिए सहायता प्रणाली सुनिश्चित करना और ऐसी परियोजनाओं के लिए उनकी बैंकिंग क्षमता और पर्याप्त वित्तपोषण व्यवस्था सुनिश्चित करना।

(ख) रोजगार-प्रधान एमएसएमई खंडों के लिए लक्षित सुविधा और प्रोत्साहन।

(ग) मंजूरी के लिए एकल-खिड़की तंत्र के साथ अनुपालन आवश्यकताओं को उत्तरोत्तर आसान बनाना, प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और एमएसएमई को इन प्रक्रियाओं को आसानी से संभालने के लिए सुसज्जित करना।

(घ) एमएसएमई उत्पादों के लिए बाजार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर की सुविधा प्रदान करना।

(ङ) कार्यबल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार-उद्योग-अकादमिक सहयोग।

10.44 निम्नलिखित आधार पर उद्योग के आंकड़ों को उन्नत करने से नीति निर्माण में सहायता मिलेगी:

(क) औद्योगिक उत्पादन का अद्यतन सूचकांक, जिसमें भारत के विनिर्माण परिदृश्य में हुए व्यापक बदलावों को शामिल किया गया है। ऐसे सूचकांकों के राज्य स्तरीय रूपांतर उभरते भौगोलिक पैटर्न को समझने में मदद करेंगे।

(ख) एमएसएमई में उत्पादन और रोजगार की गतिशीलता के नियमित संकेतक।

(ग) उद्योग-वार बैंक ऋण के सकल संवितरण (वर्तमान में उपलब्ध बकाया ऋण के आंकड़ों के विपरीत) की जानकारी, घरेलू और बाहरी इक्विटी और ऋण मार्गों के साथ-साथ अन्य वित्तपोषण स्रोतों के माध्यम से उद्योग-वार मासिक सकल वित्तीय प्रवाह।

****

11

अध्याय

सेवाएँ: विकास के अवसरों को बढ़ावा देना

पिछले तीन दशकों के उतार-चढ़ाव के दौरान, सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए एक मजबूत आधार के रूप में खड़ा रहा है। महामारी के बाद की इसकी गतिशीलता, विशेष रूप से वित्त वर्ष 24 के दौरान उभरे और मजबूत हुए रुझान और पैटर्न, घरेलू सेवा वितरण प्रणालियों और उनकी मांगों में चल रहे परिवर्तन का संकेत देते हैं। नीति और प्रक्रियात्मक सुधारों, भौतिक अवसंरचना और संभार-तंत्र पर ध्यान केंद्रित करने से, सभी महत्वपूर्ण व्यवसाय, व्यक्तिगत, वित्तीय और अवसंरचना-आधारित सेवाएँ महामारी से मजबूती से उभरी हैं। हालाँकि, यह परिवर्तन ऑनलाइन भुगतान, ई-कॉमर्स और मनोरंजन प्लेटफॉर्म जैसी डिजिटल सेवाओं की दिशा में तेजी से हो रहे बदलावों के साथ-साथ अन्य उत्पादक गतिविधियों में इनपुट के रूप में उच्च तकनीकी सेवाओं की मांग में वृद्धि में निहित है। भारत की युवा और तकनीक-प्रेमी आबादी देश के व्यावसायिक और शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र को और बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती है। इससे श्रम बल को समयबद्ध तरीके से आवश्यक डिजिटल और उच्च तकनीक कौशल से लैस किया जा सकेगा, जिससे भारत को इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

परिचय

11.1 भारत के सेवा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिन्हें मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: संपर्क-गहन सेवाएं और गैर-संपर्क-गहन सेवाएँ। पहली श्रेणी में व्यापार, आतिथ्य, परिवहन, रियल एस्टेट, सामाजिक, सामुदायिक और व्यक्तिगत सेवाएँ शामिल हैं। दूसरी में वित्तीय, सूचना प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाएँ, संचार, प्रसारण और भंडारण सेवाएँ शामिल हैं। इस क्षेत्र में लोक प्रशासन और रक्षा सेवाएँ भी शामिल हैं।

11.2 सेवा क्षेत्र भारत की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 24 में अर्थव्यवस्था के कुल आकार का लगभग 55 प्रतिशत है। मांग और आपूर्ति संबंधी कई कारक सेवा क्षेत्र के निष्पादन को निर्धारित करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वित्त, पर्यटन, आतिथ्य और मनोरंजन जैसी सेवाओं की महत्वपूर्ण घरेलू मांग एक बड़ी और युवा आबादी पर आधारित है। तेजी से हो रहा शहरीकरण परिवहन, आवास, स्वच्छता और उपयोगिता सेवाओं का समर्थन करता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के विस्तार ने संभार-तंत्र, डिजिटल भुगतान और संबंधित सेवाओं के लिए बढ़ी हुई आवश्यकताएँ उत्पन्न की हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक सेवाएँ मध्यावधि में अपनी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति बनाए रखने की संभावना रखती हैं। हालाँकि, अध्ययनों से पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के अनुप्रयोग से व्यावसायिक सेवाओं के विकास के अवसरों में उत्तरोत्तर कमी आने की संभावना है और इसलिए, यह दीर्घकालिक स्थिरता और रोजगार सृजन के लिए एक चुनौती है। इस प्रकार, बड़े और सुस्थापित शहरों के संचयी प्रभावों का लाभ उठाने के लिए मानव पूंजी पर ध्यान केंद्रित करना सेवाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से वैश्विक बाजार क्षमता वाली सेवाओं के लिए।[1]

1. द इकोनॉमिस्ट (24 जून 2024)। क्या सेवाएँ दुनिया को समृद्ध बनाएंगी? https://www.economist.com/finance-and-economics/2024/06/24/will-services-make-the-world-rich

11.3 सरकार ने एक समर्थकारी वातावरण बनाकर, निवेश को बढ़ावा देकर, कौशल बढ़ाकर और बाजार तक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, डिजिटल इंडिया अभियान ने डिजिटल सेवाओं में वृद्धि को बढ़ावा दिया है, निर्यात संवर्धन योजनाओं ने सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित किया है, बुनियादी ढांचे के विकास ने संभार-तंत्र, पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को बढ़ावा दिया है, और कौशल विकास पहलों ने कार्यबल के लिए अधिक अवसर प्रदान किए हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन में लक्षित प्रयासों ने पहुंच और विकास को बढ़ाया है, जिससे भारत के सेवा क्षेत्र के लिए एक आशाजनक भविष्य सुनिश्चित हुआ है।

11.4 अध्याय के शेष खंड देश में उभरते सेवा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित किए गए हैं, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है। निम्नलिखित खंड घरेलू उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार गतिविधि के संदर्भ में सेवा क्षेत्रों के निष्पादन का अवलोकन प्रदान करता है, इसके बाद सेवा क्षेत्र में वित्तीय प्रवाह पर एक खंड है। इसके बाद विभिन्न सेवा उप-क्षेत्रों और संबंधित नीतिगत पहलों के निष्पादन पर गहन चर्चा की गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस सर्वेक्षण के अध्याय 7 में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाओं में विकास पर चर्चा की गई है। अंतिम खंड में भविष्य के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई है।

सेवा क्षेत्र के निष्पादन का अवलोकन

सेवा क्षेत्र में सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए)

11.5 महामारी से प्रभावित वित्त वर्ष 2021 को छोड़कर पिछले दशक के सभी वर्षों में सेवा क्षेत्र में 6 प्रतिशत से अधिक की वास्तविक वृद्धि दर देखी गई। वैश्विक स्तर पर, वर्ष 2022 में भारत का सेवा निर्यात दुनिया के वाणिज्यिक सेवा निर्यात का 4.4 प्रतिशत रहा।

चार्ट XI-1: सेवा क्षेत्र में जीवीए की बढ़ती प्रवृत्ति (स्थिर मूल्यों में)

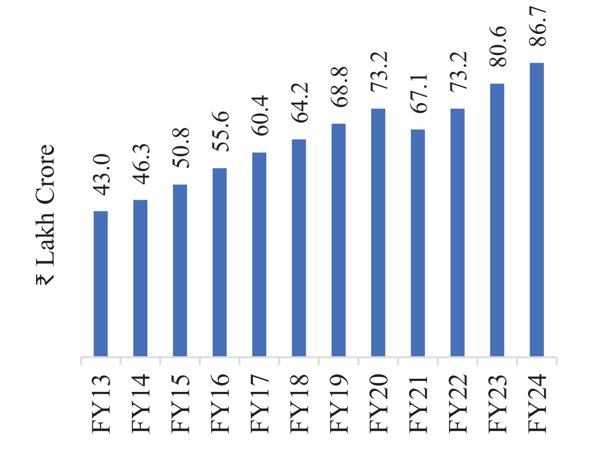

चार्ट XI-2: सेवा क्षेत्र जीवीए में वर्ष-दर-वर्ष (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि में मजबूत गति

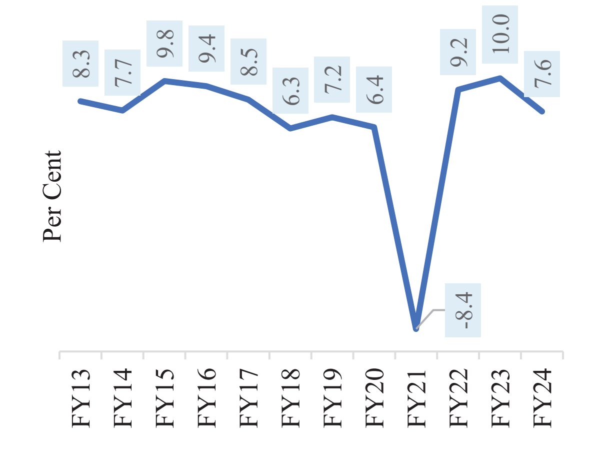

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)
नोट: वित्त वर्ष 23 के लिए प्राक्कलन प्रथम संशोधित प्राक्कलन हैं, और वित्त वर्ष 24 के लिए अनंतिम प्राक्कलन हैं।

11.6 पिछले दशक में समग्र जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान काफी बढ़ गया है। महामारी से प्रेरित संकुचन के कारण वित्त वर्ष 21 में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट आई। हालाँकि, जैसा कि चार्ट XI-3 में दिखाया

गया है, इस क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग कोविड-पूर्व स्तर पर पहुँच गई है।

चार्ट XI-3: कोविड के बाद समग्र जीवीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में मजबूती

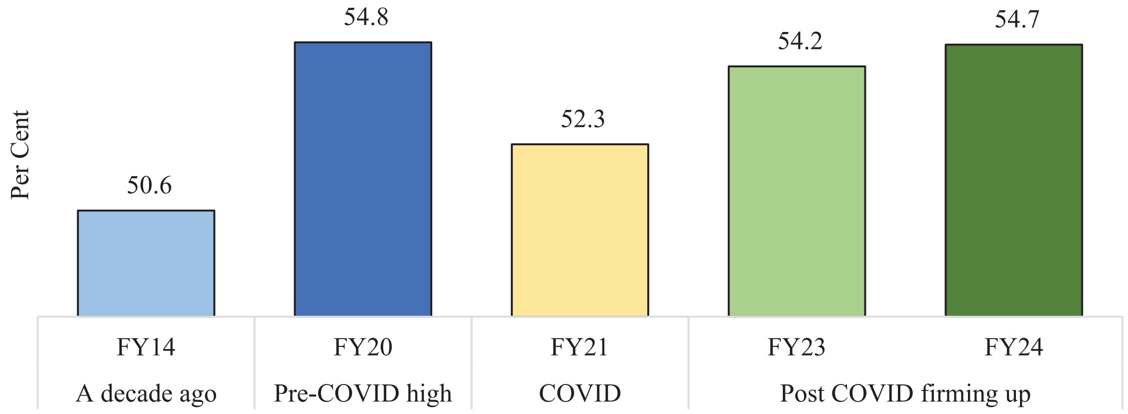

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस), एमओएसपीआई
नोट: जीवीए – सकल मूल्य सवर्धन। वित्त वर्ष 23 के लिए प्राक्कलन प्रथम संशोधित प्राक्कलन हैं, और वित्त वर्ष 24 के लिए अनंतिम प्राक्कलन हैं।

11.7 कोविड से पहले एक दशक तक, सेवा क्षेत्र की वास्तविक वृद्धि दर लगातार समग्र आर्थिक वृद्धि से अधिक रही। हालांकि, वित्त वर्ष 21 में, सेवा क्षेत्र में 8.4 प्रतिशत का तीव्र संकुचन देखा गया, जबकि समग्र जीवीए में 4.1 प्रतिशत की गिरावट आई। गैर-संपर्क गहन सेवाओं, मुख्य रूप से वित्तीय, सूचना प्रौद्योगिकी और पेशेवर सेवाओं ने कुछेक व्यवधानों और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण धनात्मक और स्थिर वृद्धि का अनुभव किया। लॉकडाउन, यात्रा प्रतिबंध और निवारक उपायों के कारण आतिथ्य, मनोरंजन और व्यक्तिगत सेवाओं की मांग में कमी के कारण संपर्क-गहन सेवाओं में संकुचन केंद्रित था। जैसे ही प्रतिबंध हटाए गए, इन क्षेत्रों ने सहायक नीतिगत माहौल की मदद से वापसी की। इसलिए, कोविड के बाद, सेवा क्षेत्र की वृद्धि ने वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 में समग्र जीवीए वृद्धि को पीछे छोड़ दिया, जिससे अर्थव्यवस्था के ऊपर की ओर बढ़ाने में पुनः इसकी भूमिका रही।

चार्ट XI-4 सेवा क्षेत्र में व्यापक-आधारित वृद्धि

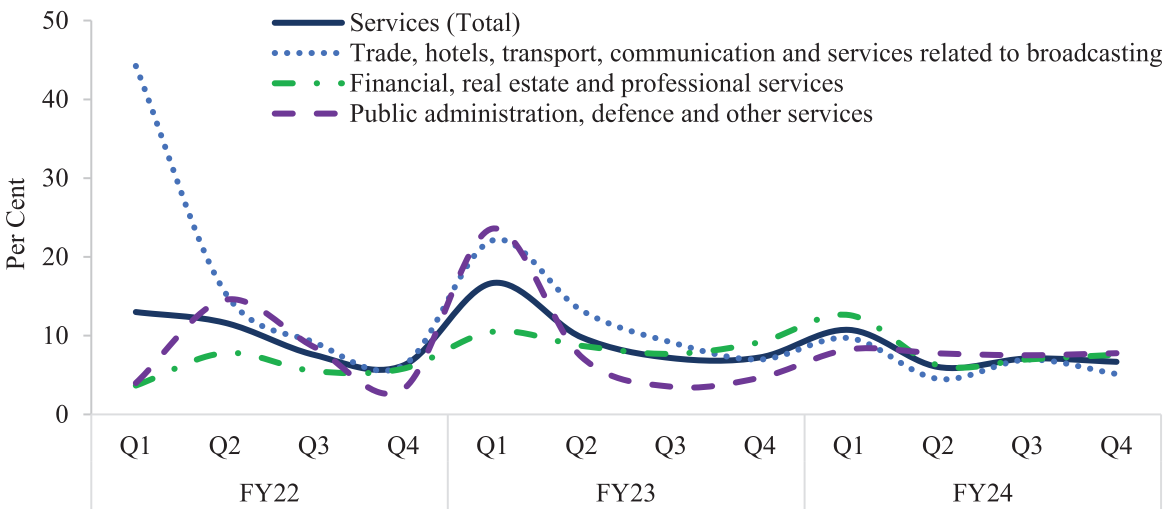

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस), एमओएसपीआई

11.8 अनंतिम अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 24 में सेवा क्षेत्र में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतक सेवा क्षेत्र की वृद्धि की कहानी का समर्थन करते हैं। जीएसटी संग्रहण और ई-वे बिल निर्गम करने दोनों ने थोक और खुदरा व्यापार को दर्शाते हुए दोहरे अंकों की वृद्धि प्रदर्शित की। वित्त वर्ष 24 में सकल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़[2] रूपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, और मजबूत घरेलू व्यापार गतिविधि को रेखांकित करता है। औसत दैनिक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, प्रबंधित कुल हवाई यात्री और रेल माल-भाड़ा यातायात ने वित्त वर्ष 24 में वर्ष-दर-वर्ष क्रमशः 18.9 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 5.3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की, जो परिवहन सेवाओं की स्थिर वृद्धि का समर्थन करती है। हालांकि व्यापार, होटल और परिवहन क्षेत्र के स्तरों में महामारी-पूर्व की प्रकृत्ति में रही कमी को प्राप्त किया जाना बाकी है जैसाकि इस सर्वेक्षण के अध्याय 1 के बॉक्स XI.1 में दर्शाया गया है। मार्च, 2024 तक बैंक ऋण और जमाओं में वर्ष-दर-वर्ष क्रमशः 20.2 प्रतिशत और 12.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वित्तीय सेवाओं में निरंतर उछाल का संकेत देती है। आवासीय संपत्ति बाजार ने भी 2023 में एक आशाजनक प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया, जिसमें मांग और नई आपूर्ति में दोहरे अंकों की वृद्धि का देखी गई।[3]

बॉक्स XI-1: पंजीकृत कंपनियों की संख्या में सेवा क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक बना हुआ है।

31 मार्च 2024 तक भारत में कुल 16,91,495 सक्रिय कंपनियाँ मौजूद हैं। सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय कंपनियाँ (65 प्रतिशत) हैं। सेवा क्षेत्र में, व्यावसायिक सेवा में सबसे ज्यादा सक्रिय कंपनियाँ (28 प्रतिशत) हैं, उसके बाद ट्रेडिंग (13 प्रतिशत) और सामुदायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएँ (11 प्रतिशत) हैं। अकेले वित्त वर्ष 24 में 1,85,312 नई कंपनियाँ पंजीकृत हुई, जिनमें से 71 प्रतिशत सेवा क्षेत्र की कंपनियाँ थीं।[4]

चार्ट XI-5: सक्रिय कंपनियों का आर्थिक गतिविधि-वार वितरण

(31 मार्च 2024 को यथास्थिति)

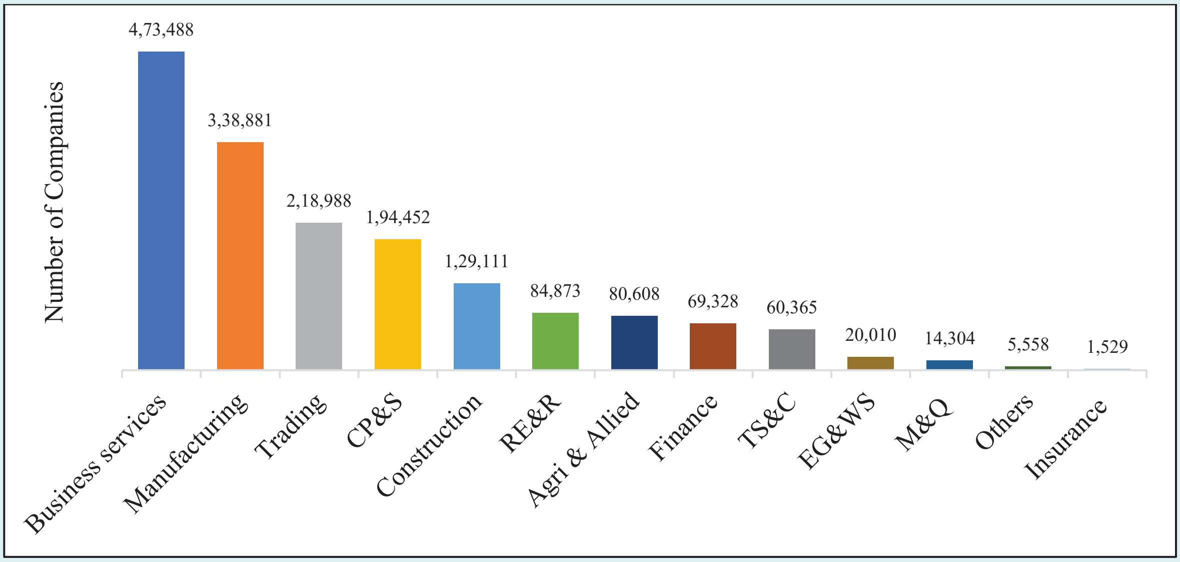

स्रोत: मासिक सूचना बुलेटिन (मार्च 2024), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

नोट: सीपीएंडएस - सामुदायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएँ, कृषि और संबद्ध - कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ, आरईएंडआर - रियल एस्टेट और किराए-दारी, टीएसएंडसी - परिवहन, भंडारण और संचार, ईजीएंडडब्ल्यूएस - बिजली, गैस और जल आपूर्ति कंपनियाँ, एमएंडक्यू - खनन और उत्खनन। सेवा क्षेत्र की कंपनियों में ट्रेडिंग, व्यावसायिक सेवाएँ, सीपीएंडएस, टीएसएंडसी, आरईएंडआर, वित्त और बीमा शामिल हैं।

2. वित्त मंत्रालय की दिनांक 01 अप्रैल 2024 की पीआईबी रिलीज। https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2016802

3. प्रॉप टाइगर (04 जनवरी 2024)। 2023 में नए घरों की बिक्री में 33% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई: प्रॉप टाइगर.कॉम रिपोर्ट। https://www.proptiger.com/guide/post/new-home-sales-record-33-yoy-growth-in-2023-proptiger-com-report

4. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय. मासिक सूचना बुलेटिन (मार्च, 2024). https://www.mca.gov.in/bin/dms getdocument?mds=jRBDSS%252FnmHQx-90z9wOfBCA%253D%253D&type=open

सेवा क्षेत्र में रुचि बढ़ाने वाला एक प्रमुख कारक डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं की बढ़ती हिस्सेदारी है, जिसने वैश्विक निर्यात में तेजी से वृद्धि देखी है। सेवा क्षेत्र का तेजी से औपचारिकीकरण, डिजिटल, वित्तीय और मनोरंजन सेवाओं की बढ़ती मांग, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकरण और स्टार्ट-अप के लिए कुशल पेशेवरों की उपलब्ध ता अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा दे रही है।

क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) - सेवाएं

11.9 भारत में सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि ने दुनिया भर में महामारी और अन्य व्यवधानों और बाधाओं को पार कर लिया। अप्रैल, 2023 से इस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और पूरे वित्तीय वर्ष में यह लचीला बना रहा। एचएसबीसी का इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई)[5] एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उच्च-आवृत्ति संकेतक है जो समग्र सेवा क्षेत्र की वृद्धि के विचार का समर्थन करता है। मार्च 2024 में, सेवा पीएमआई बढ़कर 61.2 हो गई, जो लगभग 14 वर्षों में इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण बिक्री और व्यावसायिक गतिविधि विस्तार में से एक है। यह मुख्य रूप से स्वस्थ मांग दशाओं, दक्षता लाभ और सकारात्मक बिक्री घटनाक्रमों के कारण व्यावसायिक गतिविधि में मौजूदा उछाल के परिणामस्वरूप हुआ। वित्त वर्ष 2024 में पीएमआई सेवाओं का औसत पूरे वर्ष के लिए 60.3 रहा, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 57.3 था।[6] जैसा कि चार्ट XI.6 से देखा जा सकता है, अगस्त, 2021 से सेवा पीएमआई 50 से ऊपर बनी हुई है, जिसका अर्थ है पिछले 35 महीनों से निरंतर विस्तार होना। गतिशील बाजार स्थितियों के बीच इस क्षेत्र का विस्तार जारी रहा है।

चार्ट XI-6: वैश्विक उतार-चढ़ाव के बीच वित्त वर्ष 24 में पीएमआई सेवाओं ने नई ऊंचाइयों को छुआ

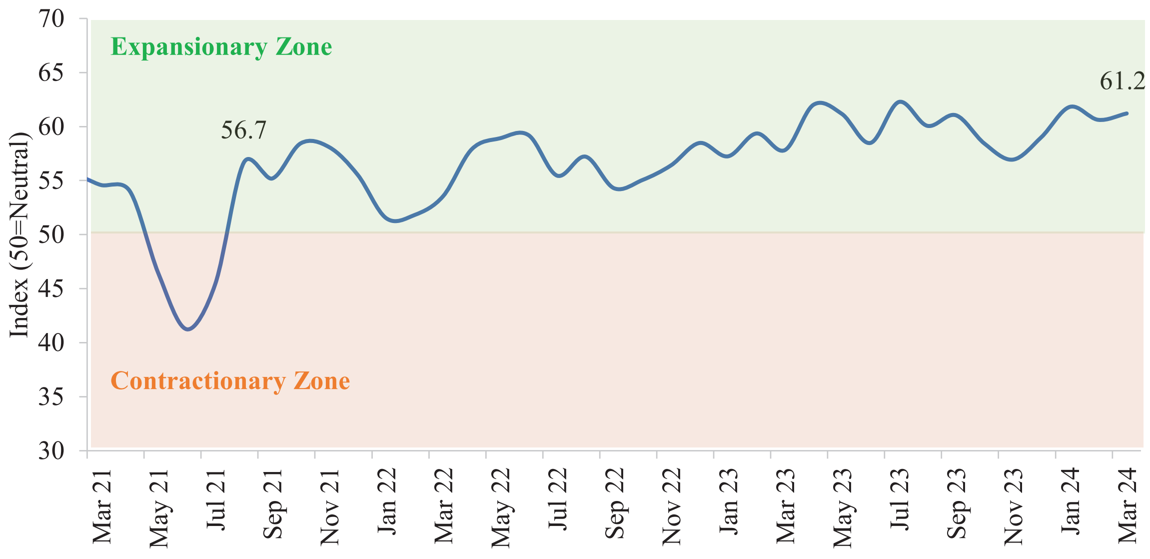

स्रोत: विभिन्न मासिक एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई रिपोर्टों से संकलित

नोट: यह सूचकांक 0 से 100 के बीच भिन्न-भिन्न है और 50 से ऊपर रीडिंग पिछले मास की तुलना में समग्र वृदिध और 50 से नीचे रीडिंग समग्र कमी का संकेत करती है।

5. सेवा पीएमआई में उपभोक्ता (खुदरा को छोड़कर), परिवहन, सूचना, संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं शामिल हैं।
6. एसएंडपी ग्लोबल (04 अप्रैल 2024)। एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई। https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/5964f1602e374900a1b109fcefe7e2f3

सेवा क्षेत्र में व्यापार

11.10 पिछले तीन दशकों में भारत के सेवा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात से आगे निकल गया है और वैश्विक निर्यात का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। महामारी के बाद, सेवा निर्यात ने स्थिर गति बनाए रखी है। वित्त वर्ष 24 में भारत के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान 44 प्रतिशत था।

11.11 वैश्विक व्यापार के कमजोर पड़ने से वित्त वर्ष 24 के दौरान भारत के सेवा निर्यात पर असर पड़ा, जिसमें वृद्धि एक साल पहले 27.8 फीसदी से घटकर 4.8 फीसदी रह गई। हालांकि, सेवा निर्यात में भारत पांचवें[7] स्थान पर रहा और अन्य देश यूरोपीय संघ (इंट्रा-ईयू व्यापार को छोड़कर), संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चीन हैं। कंप्यूटर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में भारत के सेवा निर्यात का लगभग 73 प्रतिशत हिस्सा है और वित्त वर्ष 24 तक वर्ष-दर-वर्ष इसमें 9.6 प्रतिशत वृद्धि देखी गई। यात्रा सेवाओं के निर्यात में 24.6 प्रतिशत की वार्षिक उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसे महामारी प्रतिबंधों के बाद पर्यटन में निरंतर सुधार का लाभ मिला। इसके विपरीत, परिवहन प्राप्तियों में 19.1 प्रतिशत की गिरावट आई, जो मुख्य रूप से वैश्विक माल ढुलाई दरों में कमी के कारण थी, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स[8] के औसत मैं भी गिरावट देखी गयी, जिसमें वित्त वर्ष 24 के दौरान किसी वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 3.9 प्रतिशत तक गिरावट आई।

चार्ट XI.7: सेवाओं के अंतर्गत चार प्रमुख उप-क्षेत्रों का निर्यात में योगदान

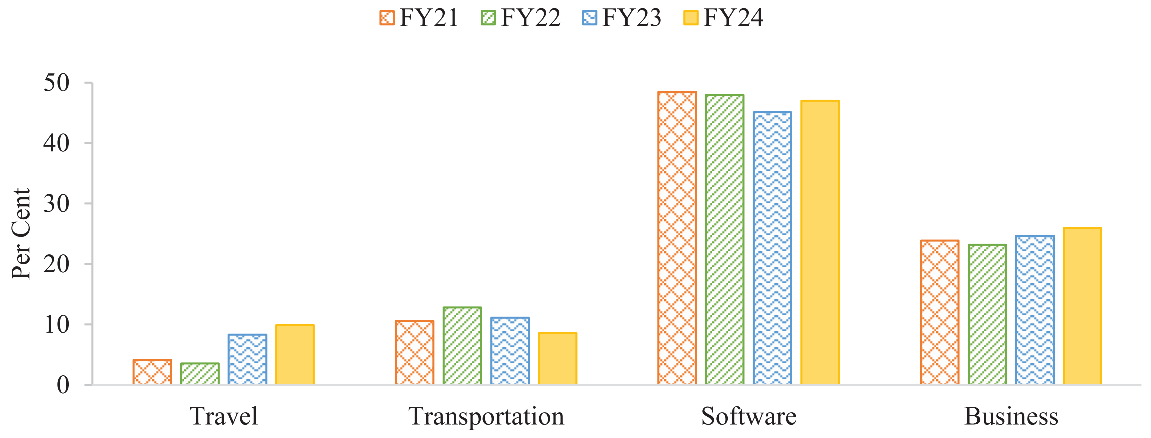

स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था पर आरबीआई सांख्यिकी पुस्तिका (तालिका संख्या 196 - भारत का समग्र भुगतान संतुलन- त्रैमासिक- अमेरिकी डॉलर), आरबीआई-भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस
नोट: चार्ट में प्रस्तुत नहीं की गई अन्य सेवाओं में शामिल हैं- बीमा, सरकार अन्यत्र शामिल नहीं (जी.एन.आई.ई.), विविध, वित्तीय और संचार सेवाएं।

11.12 हाल ही में, 'अन्य व्यावसायिक सेवाओं' खंड में वृद्धि मुख्य रूप से व्यापार और प्रबंधन परामर्श, जनसंपर्क, इंजीनियरिंग सेवाओं, विज्ञापन, व्यापार मेला सेवाओं और वैज्ञानिक और अंतरिक्ष सेवाओं सहित अन्य तकनीकी सेवाओं जैसे क्षेत्रों द्वारा उत्प्रेरित है। दक्षता लाभ और कम व्यावसायिक लागत की आशा करने वाले बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा ने सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात को काफी बढ़ावा दिया है। पिछले कुछ वर्षों में, यात्रा और व्यावसायिक सेवाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है जबकि परिवहन में मामूली गिरावट आई है। इसके अलावा, महामारी ने डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं की ओर

7. विश्व व्यापार संगठन। (2023)। विश्व व्यापार सांख्यिकीय समीक्षा 2023 (पृष्ठ 63)। https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wts-r_2023_e.pdf

8. बाल्टिक ड्राई इंडेक्स (बीडीआई) एक ऐसा इंडेक्स है जो सीमेंट, कोयला, लौह अयस्क और अनाज जैसे ड्राई बल्क कार्गो को बल्क फ्रेटर पर ले जाने की कीमत को ट्रैक करता है। चूंकि इनमें से कई वस्तुएं कच्चे माल के रूप हैं जो तैयार माल के उत्पादन में इस्तेमाल होती हैं, इसलिए बीडीआई को अक्सर आर्थिक विकास और उत्पादन का संकेतक माना जाता है। यह संकेतक लंदन स्थित बाल्टिक एक्सचेंज द्वारा अनुरक्षित किया जाता है।

वैश्विक मांग में संरचनात्मक बदलाव को उत्प्रेरित किया है। परिणामस्वरूप, वैश्विक स्तर पर डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2019 में 4.4 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 6.0 प्रतिशत हो गई।[9]

11.13 वित्त वर्ष 24 के दौरान, सेवाओं का आयात 178.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 2.1 प्रतिशत की कमी हुई और वैश्विक माल ढुलाई दरों में कमी के कारण इसमें कमी आई है। सेवाओं के निर्यात में वृद्धि और आयात में गिरावट के कारण वित्त वर्ष 24 के दौरान पिछले साल के मुकाबले निवल सेवा प्राप्तियों में वृद्धि हुई, जिससे भारत के चालू खाता घाटे को थामने में मदद मिली।

सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के लिए वित्तपोषण स्रोत

11.14 सेवा क्षेत्र घरेलू स्तर पर घरेलू बैंकों और पूंजी बाजारों से ऋण के माध्यम से और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के माध्यम से अपनी वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करता है। निम्नलिखित खंड विस्तार से बताता है कि सेवा क्षेत्र किस प्रकार अपना वित्तपोषण प्राप्त करता है।

बैंक ऋण

11.15 वित्त वर्ष 24 में सेवा क्षेत्र में ऋण प्रवाह में तेजी देखी गई, जिसमें अप्रैल, 2023 से प्रत्येक माह वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर 20 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर गई। वित्तीय वर्ष 22.9 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ मार्च, 2024 में 45.9 लाख करोड़ रुपये के बकाया सेवा क्षेत्र ऋण के साथ समाप्त हुआ।[10]

चार्ट XI.8: वित्त वर्ष 24 में मजबूत बैंक ऋण निर्माण और वृद्धि

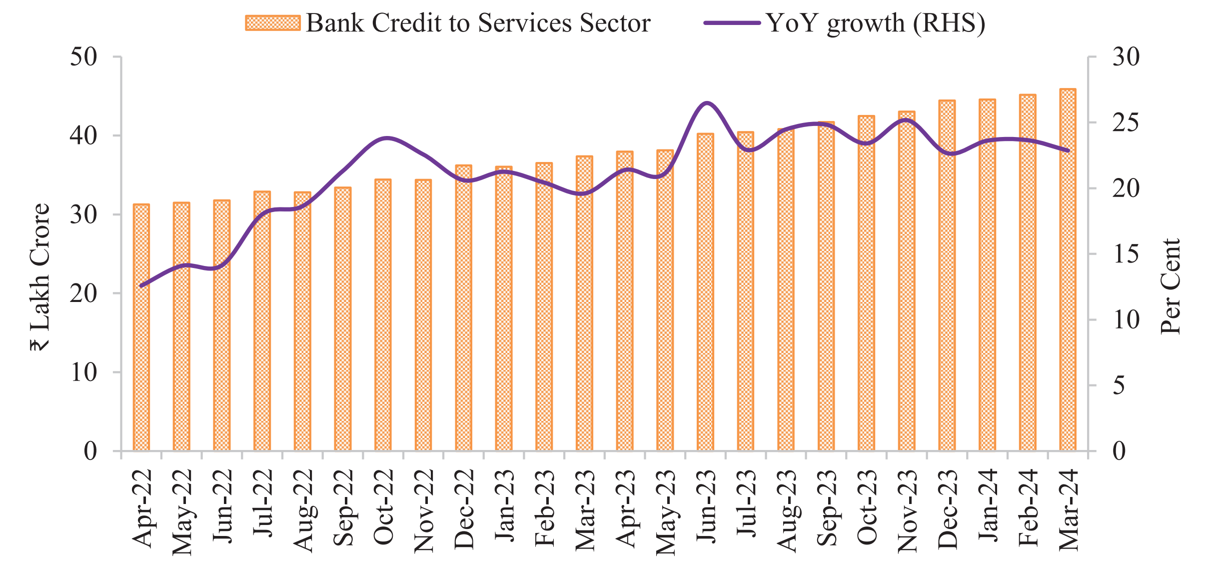

स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था पर आरबीआई की सांख्यिकी पुस्तिका (तालिका संख्या 170 प्रमुख क्षेत्रों द्वारा बैंक ऋण का अभिनियोजन), भारतीय अर्थव्यवस्था पर आरबीआई-डेटाबेस

9. विश्व व्यापार संगठन। (2024)। व्यापार दृष्टिकोण 2024। (परिशिष्ट तालिका 5: डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के अग्रणी निर्यातक, 2023) https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtsr_2023_e.pdf

10. आरबीआई की मौद्रिक नीति रिपोर्ट (अप्रैल, 2024) https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=22435

11.16 सेवा क्षेत्र को ऋण, परिवहन संचालकों, पर्यटन, होटल और रेस्तरां, विमानन, व्यावसायिक सेवाओं, व्यापार और वाणिज्यिक रियल इस्टेट जैसे उप-क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हुआ। विमानन क्षेत्र में 56 प्रतिशत की सबसे महत्वपूर्ण वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई, जिसका श्रेय विमान पट्टाकरण, किराएदारी और धनात्मक माध्यम से दीर्घकालिक विकास संभावना में वृद्धि को दिया जाता है।

बाह्य वित्तपोषण

11.17 व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 (डब्ल्यू आई आर 2024) प्रकाशित की है और वर्ष 2023 के लिए एफडीआई अंतवृद्धि (शीर्ष 20 मेजबान अर्थव्यवस्थाएं) के संबंध में भारत को 15वां स्थान दिया है। डब्ल्यूआईआर 2024 के अनुसार, भारत अंतरराष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों की संख्या के संबंध में दूसरा सबसे बड़ा और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट घोषणाओं की संख्या के संबंध में चौथा सबसे बड़ा मेजबान देश है।

11.18 वित्त वर्ष 2024 में सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में गिरावट देखी गई (चार्ट XI-9), जैसा कि भारत में समग्र एफडीआई इक्विटी प्रवाह के मामले में हुआ। यह गिरावट कई कारणों का परिणाम थी। उच्च ब्याज दरें, भू-राजनीतिक संघर्ष, बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितताएं और घरेलू सोर्सिंग के पक्ष में बढ़ते संरक्षणवाद, इन सभी की इस क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह को कम करने में भूमिका है।

चार्ट XI.9: सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में नरमी

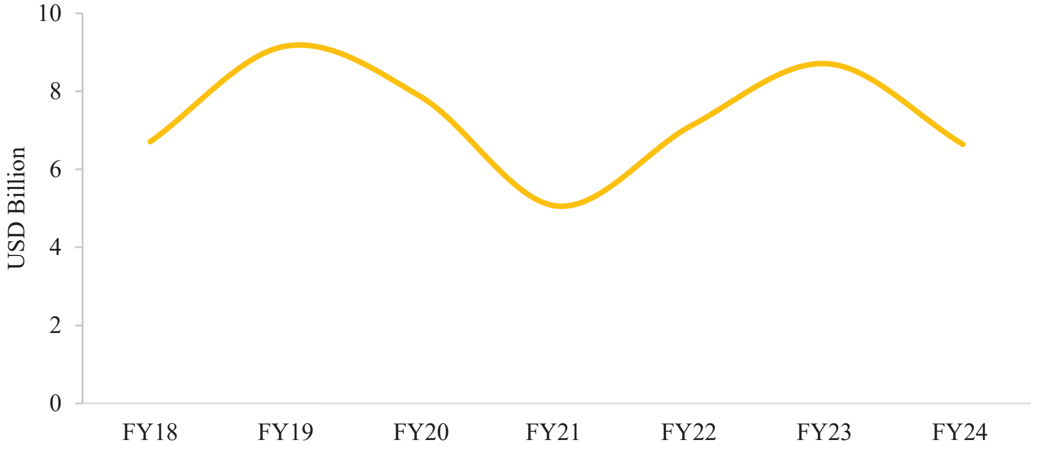

स्रोत: डीपीआईआईटी प्रकाशन- त्रैमासिक एफडीआई सांख्यिकी से प्राप्त।
नोट: (i) सेवा क्षेत्र में वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय/व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कूरियर, तकनीकी परीक्षण एवं विश्लेषण, अन्य शामिल हैं। (ii) वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 के लिए मान अनंतिम हैं।

11.19 वित्त वर्ष 2024 में कुल बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) प्रवाह में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 53 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2024 में इस क्षेत्र को 14.9 बिलियन अमरीकी डॉलर का अंतर्वाह हुआ, जिससे वित्त वर्ष 2023 में 23.3 प्रतिशत की वृद्धि के विपरीत 58.3 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।[12]

प्रमुख सेवाएँ: क्षेत्रवार निष्पादन

भौतिक कनेक्टिविटी-आधारित सेवाएँ

11.20 विविध अवसंरचना नेटवर्क में माल, लोगों और सूचनाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अनेक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। परिवहन सेवाओं में व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है, जिसमें ट्रेनों, बसों, टैक्सियों और एयरलाइनों

11. संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)। (2023)। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023। https://unctad.org/publication/world-investment-report-2023

12. स्रोत : आरबीआई डेटा की निकटम संभव औद्योगिक वर्गीकरण से मैपिंग की जाती है।

के माध्यम से यात्री परिवहन से लेकर शिपिंग कंपनियों, फ्रेट फॉरवर्डर्स और कूरियर सेवाओं द्वारा सुगम माल परिवहन शामिल है। वाहन रखरखाव और विमानपत्तनों की ग्राउंड हैंडलिंग जैसी सहायक सेवाएँ इन परिवहन पेशकशों को और भी बेहतर बनाती हैं। आपूर्ति श्रृंखलाओं को अनुकूलित करने में संभार-तंत्र सेवाएँ महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित खंड सड़क, रेलवे, जलमार्ग और वायुमार्ग में दी जाने वाली सेवाओं पर प्रकाश डालते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि इन क्षेत्रों में भौतिक अवसंरचना के निर्माण में प्रगति को अध्याय 12 में शामिल किया गया है और यहाँ दोहराया नहीं गया है।

सड़क मार्ग

11.21 भारत में माल का एक बड़ा हिस्सा सड़क मार्ग से परिवहन किया जाता है। इसलिए, राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर उपयोगकर्ता सुविधा में सुधार करना समग्र एनएच गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। टोल डिजिटलीकरण ने टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को काफी हद तक कम कर दिया है, जो 2014 में 734 सेकंड से घटकर 2024 में 47 सेकंड रह गया है। स्वचालित नंबर प्लेट पहचान और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से फ्री फ्लो टोलिंग जैसी पहलों ने टोलिंग दक्षता को बढ़ाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए एक व्यापक '4ई' रणनीति - इंजीनियरिंग (सड़कें और वाहन), एनफोर्समेंट (प्रवर्तन), इमरजेंसी केयर (आपातकालीन देखभाल) और एजुकेशन (शिक्षा) - भी तैयार की है। सरकार ने नेटवर्क नियोजन और संकुलता के अनुमानों के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल का उपयोग किया है, जो भविष्य की परिवहन मांग का अनुमान लगाने और संभार-तंत्र की दक्षता बढ़ाने के लिए ई-वे बिल और फास्टैग से बड़ी मात्रा में डेटा का लाभ उठाता है। एक्सेस नियंत्रित उच्च गति कोरिडोर के विकास पर फोकस से एनएच नेटवर्क की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा है। एक्सप्रेसवे और आर्थिक गलियारों के विकास से यात्रा का समय काफी कम हो रहा है और इस प्रकार आर्थिक विकास बढ़ रहा है।[13] राजमार्गों के विकास में असाधारण सुधारों का विवरण इस समीक्षा के अध्याय 12 में सड़क परिवहन खंड में दिया गया है।

11.22 भारत में सड़क सेवाओं को राजमार्गों के किनारे निरंतर रिबन विकास और डिजिटल भूमि अभिलेखों की धीमी गति जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे परियोजना के निष्पादन में देरी होती है। हालाँकि, सड़क परिवहन और सरकार इन मुद्दों का सक्रिय रूप से समाधान कर रहा है, जिसमें पहुँच-नियंत्रित राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने और मौजूदा राजमार्गों को उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रवर्तन के लिए समर्पित ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था लागू करना और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस को अपनाना भारत के परिवहन नेटवर्क में सड़क सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों का समाधान करने से सड़क अवसंरचना की पूरी क्षमता का उपयोग करने में मदद मिलेगी।

भारतीय रेलवे

11.23 भारतीय रेलवे (आईआर) उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, रेल प्रणाली को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और विकसित भारत के लिए क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से कई सेवाएँ प्रदान करता है। वित्त वर्ष 24 में भारतीय रेलवे से यात्री यातायात 673 करोड़ था (अनंतिम वास्तविक), जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5.2 प्रतिशत अधिक है। भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 24 में 158.8 करोड़ टन राजस्व-अर्जक माल ढोया (कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को छोड़कर), जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। क्षमता वर्धन, नए चल स्टॉक और प्रचालनिक दक्षताओं में सुधार पर विशेष गौर के साथ भारतीय रेलों के मालभाड़ा लदानों ने वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 24 के दौरान 7.1 प्रतिशत की सीएजीआर प्राप्त की। भारतीय रेल से संबंधित अन्य विवरण इस समीक्षा के अध्याय 12 के रेल परिवहन खंड में दिया गया है।

13. पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 5 जनवरी, 2024। एमओआरटीएच। https://pib-gov-in/PressRelease/framePage.asox?PRID=1993425

चार्ट XI.10: रेलवे माल यातायात में निरंतर प्रगति	चार्ट XI.11: कोविड के बाद रेलवे यात्री यातायात में सुधार
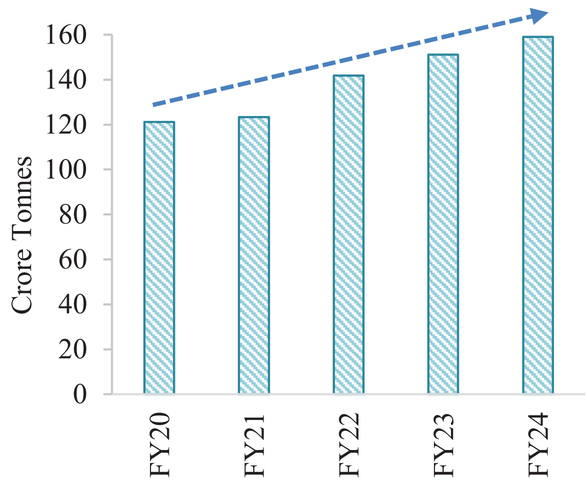	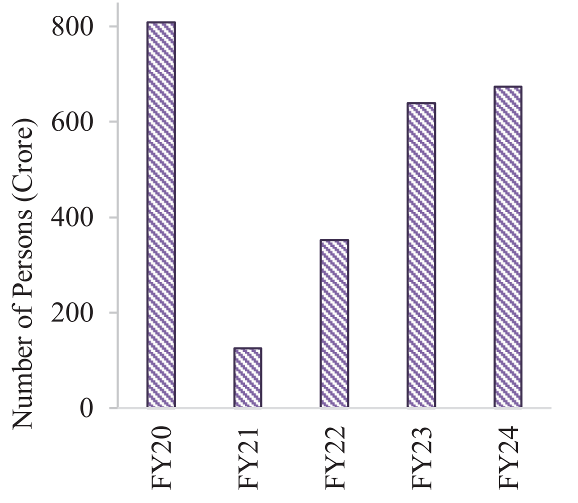

स्रोत: रेल मंत्रालय
नोट: वित्त वर्ष 24 के मान अनंतिम हैं और विवरण 7क के अनुसार, भारतीय रेलवे का मासिक सांख्यिकीय विवरण है।

11.24 यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए रेलवे ने 6108 स्टेशनों पर वाई–फाई की सुविधा शुरू की है, जिससे ग्रामीण और शहरी नागरिकों के बीच डिजिटल खाई को पाटा जा रहा है। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली देश और एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी ई–कॉमर्स वेबसाइटों में से एक बन गई है, और यह वेबसाइट, मोबाइल ऐप और आईआरसीटीसी अधिकृत एजेंटों के माध्यम से आसानी से सुलभ है। माल–भाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली माल–भाड़ा परिचालन के सभी पहलुओं का व्यापक रूप से प्रबंधन करती है, जिसमें बुकिंग, इलेक्ट्रॉनिक मांग पंजीकरण, रेलवे रसीदों का हस्तांतरण और माल की ट्रैकिंग शामिल है। ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेल सुगम ऐप और फ्रेट बिजनेस डवलपमेंट पोर्टल भी बनाया गया है।

11.25 भारतीय रेलवे की रेलगाड़ी प्रबंधन प्रणाली रियल टाइम ट्रेन आईडी के साथ चलने वाली ट्रेनों का व्यापक दृश्य प्रस्तुत करती है। यह बेहतर नियोजन और आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया के माध्यम से ट्रेन की समयबद्धता में योगदान देता है। लोकोमोटिव, कोच और वैगनों को लोकोमोटिव एसेट मैनेजमेंट, कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम और फ्रेट वैगन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे अनुप्रयोगों द्वारा डिजिटल किया गया है। रेलवे की वित्त प्रणाली आईटी–सक्षम है। बिल पासिंग पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें 99.9 प्रतिशत व्यय और 90 प्रतिशत से अधिक राजस्व लेनदेन कैशलेस हैं। भारतीय रेल ने सामग्री प्रबंधन के लिए एक व्यापक आईटी प्रणाली के माध्यम से अपनी खरीद को डिजिटल कर दिया है जिसे भारतीय रेलवे ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम और एकीकृत सामग्री प्रबंधन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। रेलवे की मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पूरी तरह से स्वचालित और केंद्रीकृत पेरोल, पेंशन, कर्मचारी स्व–सेवा, निष्पादन मूल्यांकन, पास, ई–सेवा रिकॉर्ड, भविष्य निधि आदि प्रदान करती है।

11.26 क्षमता निर्माण के लिए, भारतीय रेलवे ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने कर्मियों के लिए आठ अखिल भारतीय रेलवे–केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। वित्त वर्ष 24 में लगभग 6.5 लाख रेलवे कर्मिकों ने प्रशिक्षण लिया है। रेलवे ने आई–जीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर रेलवे–विशिष्ट शिक्षण सामग्री भी विकसित की है, जहाँ इसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारी ऑन–बोर्ड हैं, और वर्तमान में, लगभग 12 प्रतिशत कम–से–कम एक पाठ्यक्रम में नामांकित हैं।

पत्तन, जलमार्ग और पोत परिवहन

11.27 निर्णयन प्रक्रिया के बढ़ते विकेंद्रीकरण, पेशेवर विशेषज्ञता के एकीकरण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल को अपनाने से पत्तनों के प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार हुआ है और मजबूती मिली है। पत्तन क्षेत्र दैनिक पोत और कार्गो संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए सागर सेतु एप्लिकेशन का लाभ उठा रहा है, जो सभी समुद्री व्यवसायों के लिए एक केंद्रीय हब बनने की आकांक्षा रखता है। सागर सेतु भारत के सभी 13 प्रमुख बंदरगाहों के साथ-साथ 22 गैर-प्रमुख बंदरगाहों और 28 निजी टर्मिनलों के साथ भी एकीकृत है।

11.28 राष्ट्रीय जलमार्गों पर नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। मालवाहक जहाजों के विकास से पर्यटक जहाजों को भी लाभ मिलता है, क्योंकि बेहतर जलमार्ग और सुविधाओं से उनके प्रचालनों में वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 24 के दौरान क्रूज यात्राओं में 100 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। लाइटहाउस भी महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण के रूप में उभर रहे हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, समुद्र तट के किनारे 75 लाइटहाउसों और संग्रहालयों के निर्माण की योजना पर काम चल रहा है।

चार्ट XI.12: पोत परिवहन टन भार में निरंतर वृद्धि

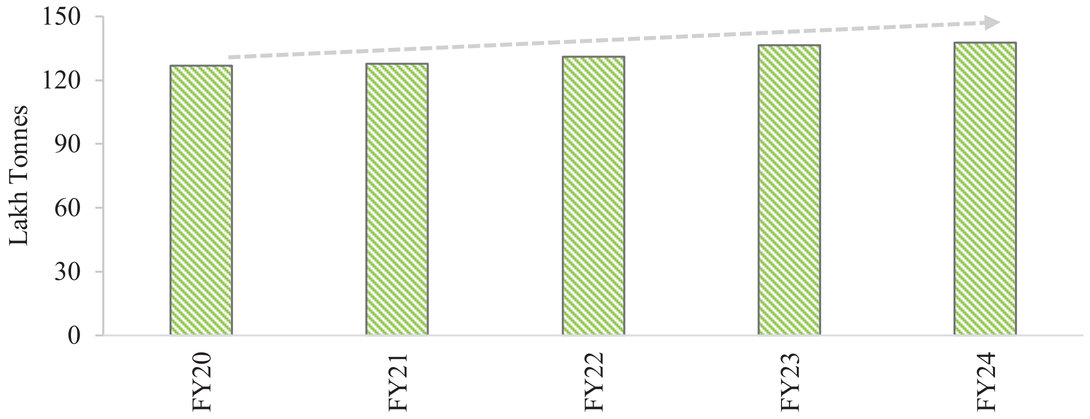

स्रोत: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

वायुमार्ग

11.29 भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है और वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रमुख विमानन बाजारों में से एक है। भारत में विमानन क्षेत्र ने काफी वृद्धि दिखाई है, वित्त वर्ष 2024 में भारतीय हवाई अड्डों पर कुल हवाई यात्रियों की संख्या में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 37.6 करोड़ हो गया है।

11.30 वित्त वर्ष 2024 में प्रबंधित घरेलू हवाई यात्री यातायात में 13 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई और यह 30.6 करोड़ हो गया और अंतरराष्ट्रीय प्रबंधित हवाई यात्रियों की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष आधारित 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 7 करोड़ हो गई। कोविड-19 के प्रभाव से वित्त वर्ष 23 में अंतरराष्ट्रीय संपर्क में कम सुधार के कारण अंतरराष्ट्रीय यातायात में वृद्धि घरेलू यातायात वृद्धि की तुलना में अधिक रही। कोविड-पूर्व स्तरों की तुलना में वित्त वर्ष 23 में घरेलू यात्री यातायात में 98 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुधार 86 प्रतिशत रहा। वित्त वर्ष 24 में भारतीय हवाई अड्डों पर एयर कार्गो की हैंडलिंग वर्ष-दर-वर्ष आधारित 7 प्रतिशत से बढ़कर 33.7 लाख टन हो गई।

11.31 भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में बढ़ती मांग, बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि, पर्यटन, उच्च प्रयोज्य आय, अनुकूल जनसांख्यिकी और विमानन अवसंरचना की अधिक पैठ के कारण जबरदस्त संभावनाएं हैं। प्रगति-मूलक सरकारी नीतियां इस विकास गति को और अधिक समर्थन देती हैं। सरकार ने देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है और

एक ठोस पूंजीगत व्यय योजना द्वारा समर्थित यात्री हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने के लिए नए टर्मिनल भवनों का संचालन किया है। क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के लिए, 2016 में शुरू की गई 'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान) योजना[14] ने अपनी शुरुआत से ही 85 अनारक्षित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों को जोड़ने वाले विभिन्न 579 क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) मार्गों पर 141 लाख से अधिक घरेलू यात्रियों को यात्रा की सुविधा प्रदान की।

चार्ट XI.13: हवाई माल यातायात में वृद्धि

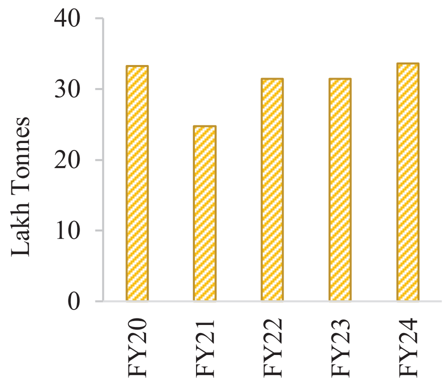

चार्ट XI.14: हवाई यात्री यातायात में तीव्र वृद्धि

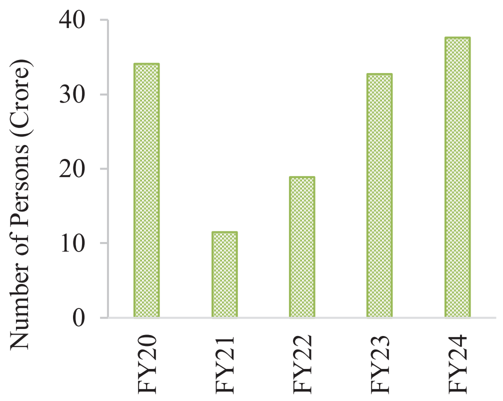

स्रोत: नागर विमानन मंत्रालय

11.32 डिजी-यात्रा[15] जैसी पहल तकनीक के माध्यम से दक्षता बढ़ा रही है। इसके लॉन्च होने के बाद से, 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को इस कार्यक्रम से लाभ मिला है। इसे सभी हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना है।

11.33 भारत में विमानन सेवाओं का भविष्य रखरखाव, मरम्मत और प्रचालन (एमआरओ) क्षेत्र और तेजी से बढ़ते ड्रोन उद्योग के विकास पर टिका हुआ है। भारत का लक्ष्य 2030 तक उदार नियमों और प्रोत्साहनों के साथ वैश्विक ड्रोन हब बनना है। हाल की प्रगति में प्रशिक्षण संगठनों में वृद्धि, रिमोट पायलट प्रमाणपत्र, पंजीकृत ड्रोन और स्वीकृत ड्रोन मॉडल शामिल हैं। गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के प्रोत्साहन ने विमानन पट्टाकरण और वित्तपोषण की सुविधा प्रदान की है, जिसका उदाहरण एयर इंडिया द्वारा हाल ही में विमान अधिग्रहण है। 31 मार्च 2024 तक, 27 संस्थाओं ने विमान पट्टे पर देने के व्यवसाय के लिए पंजीकरण कराया है और 20 से अधिक विमानों का पट्टाकरण किया है, जो इस क्षेत्र के आशाजनक परिदृश्य को दर्शाता है।

11.34 आर्थिक विकास के लिए विमानन उद्योग का विकास और हवाईअड्डों की क्षमता का विस्तार करना आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप स्थिरता संबंधी चिंताएँ और अधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता उत्पन्न होती है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अनुसार, भारत में विभिन्न एयरलाइनों में लगभग 10,000 पायलट हैं।[16] भारतीय विमानन क्षेत्र सकारात्मक रूप से आगे निकल गया है, और देश के पायलटों में महिलाओं की संख्या 15 प्रतिशत है, जो वैश्विक औसत से लगभग तीन गुना अधिक है, इस प्रकार इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए अधिक अवसर प्रस्तुत होते हैं।[17]

---

14. उड़ान योजना का उद्देश्य छोटे और मध्यम शहरों को हवाई सेवा के माध्यम से बड़े शहरों से जोड़ना है। उड़ान योजना के तहत, 'फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट' से एक घंटे की यात्रा या हेलीकॉप्टर से लगभग 500 किलोमीटर की आधे घंटे की यात्रा के लिए हवाई किराया ₹4000 तय किया गया है।
15. डिजी यात्रा विभिन्न जांच चौकियों, जैसे चेक-इन, सुरक्षा और बोर्डिंग गेट पर यात्रियों की पहचान सत्यापित करने के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग करती है, और इसके लिए भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती।
16. पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 23 मार्च 2023, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)। https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1909941
17. पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी 2024, प्रधानमंत्री कार्यालय। https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1997799

वर्ष 2023 में कुल 1622 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस जारी किए गए, जिनमें से 18 प्रतिशत महिलाओं को जारी किए गए। नागर विमानन मंत्रालय और उससे जुड़े संगठनों ने देश में पायलटों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पहले चरण में पांच हवाई अड्डों अर्थात् बेलगावी, जलगांव, कलबुर्गी, खजुराहो और लीलाबाड़ी पर नौ नए उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) के लिए और दूसरे चरण में पांच हवाई अड्डों अर्थात् भावनगर, हुबली, कडप्पा, किशनगढ़ और सेलम पर छह और एफटीओ के लिए अवार्ड पत्र जारी किए।[18] इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं, जिसके लिए सरकार, उद्योग हितधारकों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। अवसंरचना, कौशल विकास और संधारणीयता पहलों में निवेश भारत में विमान क्षेत्र के भविष्य के विस्तार को बढ़ावा देगा।

पर्यटन

11.35 भारत में पर्यटन क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक (टीटीडीआई) 2024 में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है।[19] महामारी के बाद पुनरुद्धार के सकारात्मक संकेत दिखाते हुए, इस उद्योग ने 2023 में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों[20] का आगमन देखा, जो कि वर्ष-दर-वर्ष 43.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। भारत ने पर्यटन के माध्यम से 2.3 लाख करोड़ रूपये से अधिक की विदेशी मुद्रा प्राप्तियां अर्जित की हैं, जो कि वर्ष-दर-वर्ष 65.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। विश्व पर्यटन प्राप्तियों में भारत की विदेशी मुद्रा आय का हिस्सा 2021 में 1.38 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 1.58 प्रतिशत हो गया।

चार्ट XI.15: अंतरर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (आईटीए) भारत की रैंकिंग में लगातार प्रगति

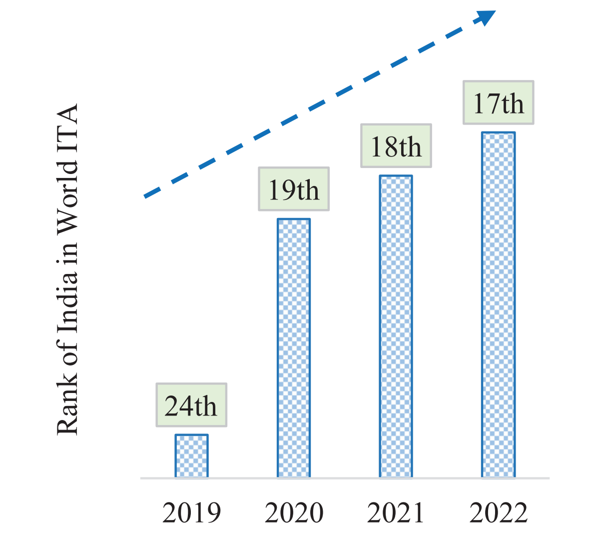

चार्ट XI.16: अंतरर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (आईटीए) की लचीली बहाली

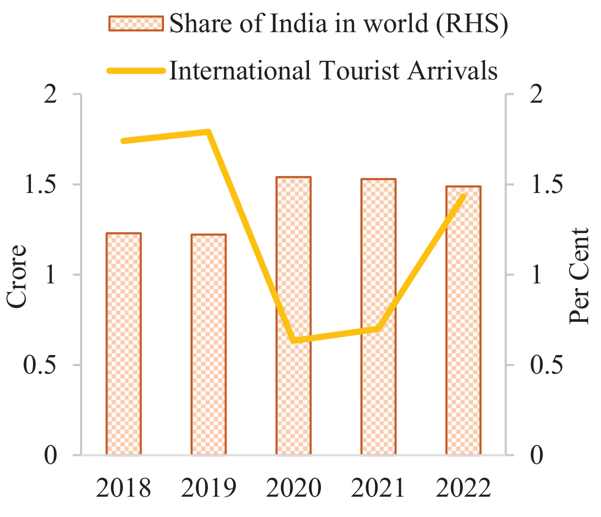

स्रोत: 2019 और 2020 के आंकड़े ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन स्रोत से लिए गए हैं। 2021 और 2022 के आंकड़े जनवरी 2024 के यूएनडब्ल्यूटीओ बैरोमीटर से लिए गए हैं।
नोट: (i) चार्ट XI.15 के लिए, 2021 और 2022 के मान अनंतिम हैं
(ii) चार्ट XI.16 के लिए, 2022 का मूल्य अनंतिम है।

18. पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 05 फरवरी 2024, नागर विमानन मंत्रालय। https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2002542
19. विश्व आर्थिक मंच (2024)। विश्व आर्थिक मंच यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024.। https://www3.weforum.org/docs/WEF_Travel_and_Tourism_Development_Index_2024.pdf
20. यूएनडब्ल्यूटीओ की परिभाषा के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (आईटीए) में दो घटक शामिल हैं, अर्थात् विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) और अनिवासी नागरिकों का आगमन।

11.36 आतिथ्य उद्योग पर्यटकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और समग्र अतिथि अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ा है। वर्ष 2023 में, 14,000 अतिरिक्त कमरों के साथ सर्वाधिक संख्या में नई आपूर्ति की गई, जिससे भारत में श्रृंखला-संबद्ध कमरों की कुल सूची 183,000 हो गई।[21] होटल व्यवसायी अतिथि अनुभव को मूर्तरूप देने और परिचालन क्षमता में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी का तेजी से लाभ उठा रहे हैं। होटल भी नवोन्मेषी परिचालन रणनीतियाँ अपना रहे हैं, जैसे बाहरी रेस्तराँ, स्पा और लाउंज ब्रांड को पट्टे पर देना या प्रबंधित करना, ताकि होटल निवासियों को आकर्षित करने वाली स्थापित अवधारणाओं का लाभ उठाया जा सके, जिससे राजस्व में वृद्धि हो।[22] वित्त वर्ष 24 में, औसत दैनिक दर 6704 रूपये से बढ़कर 7616 रूपये हो गई, जो कि वर्ष-दर-वर्ष आधारित 13.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।[23]

11.37 भारत में पर्यटन के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं और कई सरकारी पहल इस क्षेत्र की प्रगति का समर्थन करती हैं। 'तीर्थयात्रा पुनर्नवीकरण और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान' (प्रसाद)[24] योजना के तहत पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए 29 नए स्थलों की पहचान की गई है और 12 का उद्घाटन किया गया है। स्वदेश दर्शन 2.0, एकीकृत पर्यटन गंतव्य विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, 32 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 55 गंतव्यों को लक्षित करता है। भारत ने पहले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की अध्यक्षता की, जिसमें एससीओ सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोगी रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया। मंत्रालय ने पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 11वें अंतरर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट और भारत पर्व 2023 का आयोजन किया। इन प्रयासों के साथ-साथ सरकार ने पर्यटन उद्योग को समर्थन देने के लिए नीतिगत सुधारों और बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न उपायों को लागू किया है।

चार्ट XI.17: आतिथ्य सांख्यिकी

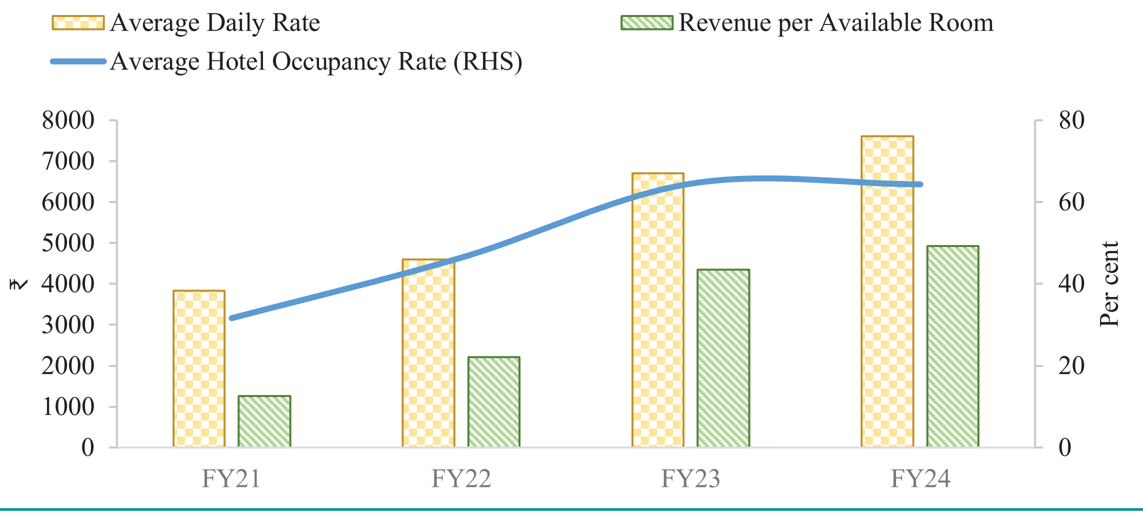

स्रोत[25] : एनारॉक – 'एचवीएस एनारॉक होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी ओवरव्यू' की मासिक रिपोर्ट से समेकित

21. होर्वाथ एच.टी.एल. (फरवरी 2024). भारत होटल बाजार समीक्षा रिपोर्ट 2023. https://horwathhtl.com/wp-content/uploads/sites/2/2024/02/India-Hotel-Market-Review-Report-2023.pdf

22. होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बेनोरी नॉलेज। विजन 2047: भारतीय होटल उद्योग। https://hotelassociationofindia.com/Vision%202047%20-%20March%2030.pdf

23. मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक एनारॉक (एचवीएस एनारॉक होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी ओवरव्यू) की मासिक रिपोर्टों से समेकित।

24. यह योजना धार्मिक पर्यटन के अनुभव को समृद्ध करने के लिए भारत भर में तीर्थ स्थलों को विकसित करने और उनकी पहचान करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य तीर्थ स्थलों को प्राथमिकता, योजनाबद्ध और टिकाऊ तरीके से एकीकृत करना है ताकि संपूर्ण धार्मिक पर्यटन का अनुभव प्रदान किया जा सके।

25. इसे अप्रैल 2020 से मार्च 2024 तक मासिक रिपोर्ट (एचवीएस एनारॉक होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी ओवरव्यू) का उपयोग करके समेकित किया गया है। वार्षिक औसत की गणना संबंधित महीनों की रिपोर्ट से मासिक डेटा का उपयोग करके की जाती है।

11.38 पर्यटन क्षेत्र ने डिजिटल क्रांति को अपनाया है। ऐसी ही एक पहल है ई-मार्केटप्लेस, जिसे वेब और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पर्यटकों और प्रमाणित पर्यटक सुविधा-दाताओं और मार्गदर्शकों के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों के सहयोग से, राष्ट्रीय एकीकृत आतिथ्य उद्योग डेटाबेस (निधि) पोर्टल में देश भर में आवास इकाइयों को पंजीकृत करने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। यह डेटाबेस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नीतियों और कार्य-नीतियों को तैयार करने में सहायता करेगा। एक अन्य उल्लेखनीय पहल साथी (सिस्टम फॉर असेसमेंट, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री) है, जिसका उद्देश्य सरकारी कोविड नियमों पर आतिथ्य उद्योग को जागरूक करके वायरस के आगे के संचरण को रोकना है।

टेबल XI.1 : यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, 2024 में भारत की रैंकिंग 39 हुई

Enabling Environment					T&T Policy and Enabling Conditions			Infrastructure and Services			T&T Resources			T&T Sustainability		
Business Environment	Safety and Security	Health and Hygiene	Human Resources and Labour Market	ICT Readiness	Prioritisation of T&T	Openness to T&T	Price Competitiveness	Air Transport Infrastructure	Ground and Port Infrastructure	Tourist Services and Infrastructure	Natural Resources	Cultural Resources	Non-Leisure Resource	Environmental Sustainability	T&T Socioeconomic Impact	T&T Demand Sustainability
3.79	5.06	3.47	2.85	3.84	4.11	4.13	5.66	4.59	4.43	1.6	5.8	5.62	5.05	3.64	4.01	4.55

स्रोत: डब्ल्यूईएफ की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक (टीटीडीआई) 2024 रिपोर्ट[26]
नोट: टीएंडटी-यात्रा और पर्यटन

11.39 भारत का यात्रा एवं पर्यटन (टीएंडटी) क्षेत्र वैश्विक मुद्रास्फीति दबावों से प्रभावित रहा है और टीएंडटी क्षमता के सुधार में विलंब अन्य अर्थव्यवस्थाओं के समान है। हालांकि 2021 से कीमत प्रतिस्पर्धा में कमी अपने समकक्षों की तुलना में 0.7 प्रतिशत गिरावट के साथ न्यूनतम रही है। भारत की गिरावट 2021 में स्तरों से मात्र 0.1 प्रतिशत पर बहुत कम रही है जो कोविड-19 महामारी से आई मंदी के बावजूद स्थिरता बनाए रखने के सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। डब्ल्यूईएफ की टीटीडीआई, 2024 रिपोर्ट पर्यटन सेवाओं और अवसंरचना और कुशल कार्यबल के विकास में सुधार की आवश्यकता पर बल देती है। बढ़ते संरक्षणवाद, परिवहन लागत और आपूर्ति चिंताओं के कारण एआई के उदय और विनिर्माण के कारण सेवाओं में रोजगार सृजन के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल में, पर्यटन क्षेत्र रोजगार सृजन के लिए अपेक्षाकृत सुगमता से परिणाम प्रदान कर सकता है। भारत को इस अवसर का लाभ उठाना होगा। इस क्षेत्र में रोजगार को औपचारिक बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत पर्यटन सुविधाप्रदाता प्रमाणपत्र कार्यक्रम शुरू किया है।[27] इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक डिजिटल मंच, जो आनलाइन लर्निंग के अवसर और प्रमाणन पाठ्यक्रम प्रदान कर सके, के माध्यम से राष्ट्रव्यापी पर्यटन सुविधाप्रदाताओं का एक कुशल संवर्ग सृजित करना है।[28]

26. विश्व आर्थिक मंच (मई 2024)। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक (टीटीडीआई) 2024. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Travel_and_Tourism_Development_Index_2024.pdf
तालिका में उल्लिखित 17 स्तंभों को दिए गए अंक कार्यकारी राय सर्वेक्षण (सर्वेक्षण) से प्राप्त आंकड़ों और अन्य स्रोतों से प्राप्त मात्रात्मक आंकड़ों के आधार पर गणना किए गए हैं। सर्वेक्षण डेटा का मान 1 (सबसे खराब) से 7 (सबसे अच्छा) तक होता है और मात्रात्मक डेटा संकेतकों को कार्यकारी राय सर्वेक्षण के परिणामों के साथ संरेखित करने के लिए 1 से 7 के पैमाने पर सामान्यीकृत किया जाता है।
27. वेबसाइट का लिंक - https://iitf.gov.in/
28. पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 21 जुलाई 2024, पर्यटन मंत्रालय। https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1843507

रियल एस्टेट

11.40 पिछले दशक में रियल एस्टेट और आवासों के स्वामित्व ने कुल जीवीए में सात प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया है, जो अर्थव्यवस्था में उनकी अभिन्न भूमिका को दर्शाता है। महामारी से प्रेरित लॉकडाउन और आर्थिक अस्थिरता के दो चुनौतीपूर्ण वर्षों के बाद, रियल एस्टेट क्षेत्र ने एक मजबूत रिकवरी का अनुभव किया है। महामारी ने घर खरीदने वालों की प्राथमिकताओं को अतिरिक्त सुविधाओं के साथ बड़े, टिकाऊ स्थानों की ओर स्थानांतरित कर दिया है, जो दूरस्थ और हाइब्रिड कार्य प्रवृत्तियों द्वारा संचालित है। इस बदलाव ने शहर के केंद्रों के करीब परिधीय क्षेत्रों में भी रुचि पैदा की है। इस सेक्टर के विकास में योगदान देने वाले कारकों में तेजी से शहरीकरण, आय के बढ़ते स्तर, एकल परिवारों का उदय, बाजार में नए प्रवेशकर्ता और डेवलपर्स और घर खरीदने वालों के लिए बेहतर वित्तीय विकल्प शामिल हैं। महामारी के दौरान घर के मालिक होने की प्रबल इच्छा को बल मिला, जिसने उत्प्रेरक का काम किया।

11.41 वर्ष 2023 में, भारत में आवासीय रियल एस्टेट की बिक्री 2013 के बाद से सबसे अधिक थी, जिसमें 33 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देखी गई, जिसमें शीर्ष आठ शहरों में कुल 4.1 लाख यूनिटों की बिक्री हुई। नई आपूर्ति ने अब तक का उच्चतम स्तर देखा, जिसमें 2023 में 5.2 लाख यूनिट लॉन्च किए गए, जबकि 2022 में 4.3 लाख यूनिट लॉन्च किए गए थे। वर्ष 2024 की पहली तिमाही में यही गति बनी रही, जिसमें 1.2 लाख यूनिट की रिकॉर्ड-तोड़ बिक्री देखी गई, जिसमें 41 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही से नई आपूर्ति लगातार एक लाख यूनिट से अधिक रही है, जो आवसन बाजार में निरंतर मांग-आपूर्ति की गतिशीलता को रेखांकित करती है।[29]

11.42 इसके अलावा, आवसन ऋण की बढ़ती मांग रियल एस्टेट की अंतर्निहित मांग को दर्शाती है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आवास ऋण वित्त वर्ष 12 से वित्त वर्ष 24 तक बढ़ा (चार्ट XI-18)। परंपरागत रूप से, आवसन वित्त क्षेत्र में सबसे बैंक महत्वपूर्ण घटक रहे हैं। हालांकि, आवसन वित्त कंपनियों (एचएफसी) ने पिछले कुछ वर्षों में इस परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने पिरामिड के निचले हिस्से में आवास ऋण उपलब्ध कराने में बैंकों के साथ पूरक भूमिका निभाई। एचएफसी के कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में बकाया आवास ऋण की हिस्सेदारी 31 मार्च 2024 तक 70.8 प्रतिशत थी।

चार्ट XI.18: व्यक्तिगत गृह ऋण (आईएसएल) में वृद्धि

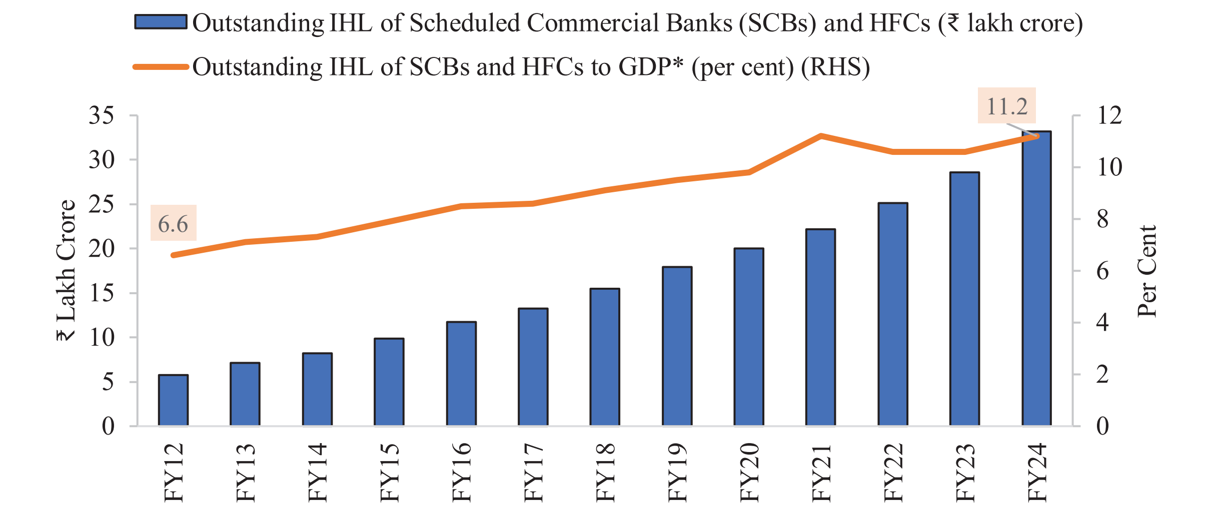

स्रोत: आरबीआई और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)
नोट: मौजूदा कीमतों पर जीडीपी पर विचार किया जाता है

29. प्रॉप टाइगर. (04 जनवरी 2024). 2023 में नए घरों की बिक्री में 33% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई: प्रॉपटाइगर.कॉम रिपोर्ट https://www.proptiger.com/guide/post/new-home-sales-record-33-yoy-growth-in-2023-proptiger-com-report

11.43 आवसन क्षेत्र की वृद्धि कई प्रमुख कारकों के कारण हुई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) ने शहरी लाभार्थियों के लिए 1.2 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी है, जिससे टिकाऊ आवासन सुनिश्चित हुआ है। माल एवं सेवा कर, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता जैसे नीतिगत सुधारों ने रियल एस्टेट में पारदर्शिता और निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है। किफायती आवास निधि और किफायती एवं मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो (एसडब्ल्यूएएमआईएच) निवेश निधि जैसी पहलों ने किफायती आवास परियोजनाओं का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम ब्याज अनुदान प्राथमिक मांग-पक्ष का प्रेरक रहा है, जिसमें राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने मार्च, 2024 तक 21.1 लाख से अधिक परिवारों को लाभान्वित करने वाली सब्सिडी में ₹49,460.1 करोड़ जारी किए हैं। एचएफसी के साथ बैंक लिक्विडिटी को मिलाकर सह-उधार मॉडल का उद्देश्य कम आय वाले समूहों सहित व्यापक क्षेत्र में आवास ऋण का विस्तार करना है। एनएचबी द्वारा ₹10,000 करोड़ की प्रारंभिक निधि से प्रबंधित शहरी अवसंरचना विकास निधि ने शहरी अवसंरचना में सुधार किया है, तथा रियल एस्टेट में निवेश को आकर्षित किया है।

बॉक्स XI.2: विश्वास का निर्माण: रेरा किस प्रकार रियल एस्टेट को नया आकार दे रहा है

भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) को भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में बहुत जरूरी सुधार लाने के लिए अधिनियमित किया गया था। रेरा का मुख्य उद्देश्य अधिक पारदर्शिता, नागरिक-केंद्रितता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करना है, जिससे घर खरीदारों को सशक्त बनाया जा सके और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित किया है, सिवाय नागालैंड जो नियमों को अधि सूचित करने की प्रक्रिया में है।

रेरा के कार्यान्वयन द्वारा प्रमुख उपाय और परिणाम

- **विकासकर्ता की जवाबदेही:** डेवलपर्स अक्सर वादा किए गए प्रोजेक्ट फीचर, लेआउट और सुविधाएं देने में विफल रहे, जिससे घर खरीदने वाले भ्रमित हो गए। रेरा अब पंजीकरण के समय 'बिक्री के लिए समझौता' अनिवार्य करता है और किसी भी लेआउट परिवर्तन के लिए आवंटियों/घर खरीदने वालों से दो-तिहाई सहमति की आवश्यकता होती है। दायित्व उल्लंघन के मामलों में रेरा सभी हितधारकों पर लागू होने वाले रिफंड, मुआवजे और दंड के प्रावधानों को भी निर्दिष्ट करता है।

- **निष्पक्ष लेनदेन:** रेरा लागू होने से पहले, ऐसे कई मामले सामने आए थे, जब बिल्डर्स घर खरीदारों से पूरा भुगतान करने के बावजूद फ्लैट या घर नहीं दे रहे थे। इस समस्या के समाधान के लिए, रेरा के अंतर्गत यह अनिवार्य किया गया है कि किसी परियोजना के लिए घर खरीदने वालों से एकत्रित धनराशि का 70 प्रतिशत, परियोजना निर्माण और भूमि लागत के लिए समर्पित एक अलग बैंक खाते में रखा जाना चाहिए।
- **प्रकटीकरण और अनिवार्य पंजीकरण:** रेरा ने डेवलपर्स और प्रोजेक्ट प्रमोटरों के लिए प्रोजेक्ट के बारे में सभी आवश्यक प्रकटीकरण करना भी अनिवार्य कर दिया है, जिसमें अधिकारियों से प्राप्त अनुमति, लॉन्च की तिथि, परिदान की वादा की गई तिथि, प्रोजेक्ट विशिष्टियां और सुख-सुविधाएँ शामिल हैं।[30] इसके अलावा, घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा की जाती है क्योंकि केवल रेरा के साथ पंजीकृत प्रोजेक्ट (500 वर्ग मीटर से ऊपर और आठ अपार्टमेंट से ऊपर) ही लॉन्च किए जा सकते हैं, जिससे डेवलपर्स द्वारा किसी भी तरह की गलत बयानी या झूठे वादों की संभावना समाप्त हो जाती है।[31] दिनांक 1 जुलाई 2024 तक, 1,30,186 से अधिक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और 88,461 रियल एस्टेट एजेंट रेरा के तहत पंजीकृत हो चुके हैं।

---

30. पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 12 अक्टूबर 2018, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx-?PRID=1549548

31. पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 01 नवंबर 2021, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/nov/doc202111121.pdf

- **विवाद समाधान:** रेरा विवादों के निपटारे के लिए फास्ट-ट्रैक विवाद समाधान तंत्र की स्थापना का प्रावधान करता है। 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की है, और 1 जुलाई 2024 तक 1,24,947 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है।

रेरा के लागू होने के बाद 2022 में ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत 36वें स्थान पर है।

11.44 रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए संभावनाएं उत्साहजनक हैं। बढ़ते शहरीकरण के साथ, आवसन उद्योग एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 2050 तक भारत की आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी, जबकि 2011 में यह 31 प्रतिशत थी।[32] इससे आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने तथा व्यवहार्य, लागत प्रभावी, टिकाऊ समाधान प्रदान करने के लिए रणनीतियों और नीतियों को अनुकूलित करने की आवश्यकता को बल मिलता है।

11.45 भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण से भूमि लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ेगी, संपत्ति के स्वामित्व संबंधी विवादों में कमी आएगी और भूमि प्रबंधन की दक्षता बढ़ेगी। निर्माण संबंधी मंजूरी के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली लागू करने से निर्माण प्रक्रियाओं में भी तेजी आएगी, जिससे विलंब और अनिश्चितताएं कम होंगी। मंजूरी को सरल बनाने से भारत के आवासीय रियल एस्टेट क्षेत्र के और अधिक समेकित और व्यवस्थित होने की उम्मीद है।

11.46 रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की विरासत एक चुनौती है। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के अनुमान के अनुसार, लगभग 4.1 लाख तनावग्रस्त आवासीय इकाइयाँ, जिनकी कीमत ₹4.1 लाख करोड़ है, प्रभावित हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने इस मुद्दे को हल करने के लिए रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समाधान सुझाने के लिए एक समिति की स्थापना की।[33] इस समिति ने दबाव के प्राथमिक कारण की पहचान वित्तीय व्यवहार्यता की कमी के रूप में की, जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि और देरी हुई। इसकी सिफारिशों में रेरा के साथ अनिवार्य परियोजना पंजीकरण, कब्जे वाली इकाइयों के लिए पंजीकरण/उप-पट्टा विलेखों का निष्पादन, काफी हद तक पूरी हो चुकी परियजनाओं का कब्जा सुनिश्चित करना, प्रमोटर के नेतृत्व वाले संकल्पों के लिए राज्य सरकार के पुनर्वास पैकेज का प्रस्ताव करना, रेरा और प्रशासक के नेतृत्व वाली परियोजना पुनरुद्धार के लिए रूपरेखा स्थापित करना, रुकी हुई परियोजनाओं को वित्तपोषित करना और परियोजनाओं के समाधान के लिए अंतिम उपाय के रूप में आईबीसी का उपयोग करना शामिल है। इनमें से कई सिफारिशें राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। एक पैकेज के रूप में उनके कार्यान्वयन से रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं के समाधान में मदद मिल सकती है।

11.47 क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में आवास ऋण बाजार वित्त वर्ष 2018 से वित्त वर्ष 23 तक लगभग 13 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा। इसके 13 से 15 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ते रहने की उम्मीद है, जो वित्तीय वर्ष 26 तक 42 लाख करोड़ रुपये से 44 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। एनएचबी ने वित्तपोषण विकल्पों की सीमाओं का समाधान करने के लिए एक आवासीय बंधक-समर्थित प्रतिभूति (आरएमबीएस) मंच पेश किया है। इस मंच का उद्देश्य पेंशन फंड और बीमा फंड सहित विविध निवेशक समूहों से दीर्घकालिक संसाधनों को आकर्षित करना है, ताकि आवास वित्त के विस्तार का समर्थन किया जा सके और प्राथमिक बंधकों के लिए ऋण बाजार को गहन बनाया जा सके। आरएमबीएस मंच ऋण देने वाली संस्थाओं के लिए परिसंपत्ति-देयता विषमताओं को कम करने में मदद करेगा, जिससे आवास वित्त क्षेत्र में पर्याप्त तरलता सुनिश्चित होगी।

32. संयुक्त राष्ट्र। (2018)। विश्व शहरीकरण परिप्रेक्ष्य: 2018 संशोधन - मुख्य बिंदु (पृष्ठ 23). https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Highlights.pdf

33. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। (जुलाई 2023)। विरासत में मिली रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए समिति की रिपोर्ट। https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/report(1).pdf

11.48 भविष्य में, आवास की मांग के वहनीयता और ऋण तक बढ़ती पहुंच से प्रेरित होने की उम्मीद है। बकाया व्यक्तिगत आवासन ऋणों में दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी राज्यों की हिस्सेदारी क्रमश: 35.4 प्रतिशत, 31.2 प्रतिशत और 26.2 प्रतिशत है। पूर्वी राज्यों में 6.9 प्रतिशत और आठ पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 0.95 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो पहुंच में सुधार के लिए पहल करने का अवसर प्रदान करती है।

11.49 वहनीयता और प्रौद्योगिकी रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अवरोधक के रूप में उभरे हैं। वहनीयता हरित निर्माण प्रथाओं और ऊर्जा-कुशल डिजाइनों को प्रभावित करेगी, जबकि प्रौद्योगिकी स्मार्ट घरों और डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि में क्रांति लाएगी। अधिक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सरोकारों के साथ, ऊर्जा-दक्ष प्रणालियों, वर्षा जल संचयन और स्मार्ट बिल्डिंग प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ, तकनीकी स्टार्ट-अप और वैश्विक क्षमता केंद्र

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाएँ

11.50 पिछले दशक में, सूचना और कंप्यूटर से संबंधित सेवाएं तेजी से महत्वपूर्ण हो गई हैं, कुल जीवीए में उनकी हिस्सेदारी वित्त वर्ष 13 में 3.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 5.9 प्रतिशत हो गई है। महामारी से प्रेरित आर्थिक मंदी के बावजूद, इस क्षेत्र ने वित्त वर्ष 21 में 10.4 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि दर हासिल की। कोविड-19 महामारी ने प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों की उन्नति और तेजी को बढ़ावा दिया, जिससे इस क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा मिला। आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं ने निर्यात आय के माध्यम से देश के बाहरी संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो आगे और बढ़ने वाली है। आईटी सेवाओं के तेजी से विकास ने भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) और तकनीकी स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार में भी सहयोग दिया है।

वैश्विक क्षमता केंद्र

11.51 भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यह संख्या वित्त वर्ष 15 में 1,000 से अधिक केंद्रों से बढ़कर 1,580 से अधिक केंद्रों हो गए और वित्त वर्ष 23 तक 2,740 से अधिक इकाइयों तक हो गई। ये केंद्र उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार प्रदान करके आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। वित्त वर्ष 23 में, भारतीय जीसीसी में नियोजित कुल प्रतिभाएं 16.6 लाख से अधिक हो गईं। इस कार्यबल में से 42 प्रतिशत से अधिक इंजीनियरिंग, अनुसंधान और विकास (ईआरएंडडी), 34.5 प्रतिशत से अधिक व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन (बीपीएम) और 23.4 प्रतिशत आईटी सेवाओं में लगा हुआ है। सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र सामूहिक रूप से भारत की आईटी जीसीसी प्रतिभा का लगभग 58 प्रतिशत हिस्सा हैं। भारत के जीसीसी से राजस्व वित्त वर्ष 15 में 19.4 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 46 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है, जो 11.4 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रहा है।

चार्ट XI.19: कार्यों के अनुसार जीसीसी के राजस्व का विभाजन (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

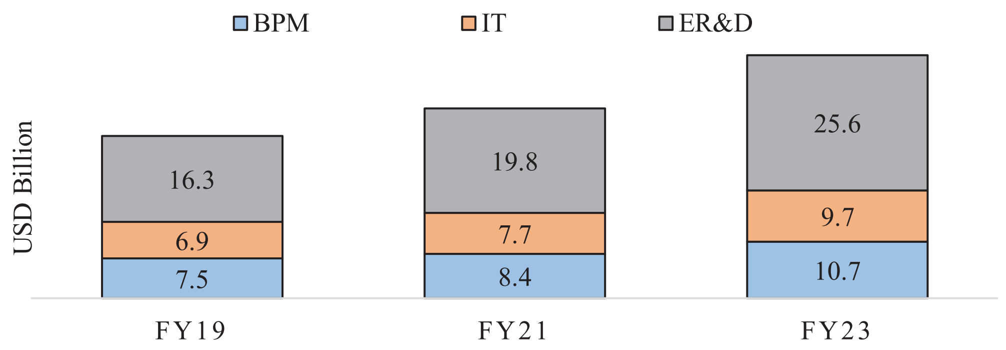

स्रोत: नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (NASSCOM)

11.52 नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) के अनुसार, भारत में ईआरएंडडी के विकास के लिए प्रमुख चालकों में रणनीतिक दीर्घकालिक साझेदारी, व्यापक डिजिटलीकरण और क्लाउड प्रौद्योगिकियों को अपनाना शामिल है। अनुप्रयोग आधुनिकीकरण, क्लाउड माइग्रेशन, प्लेटफॉर्म विकास और संबर्धित साइबर सुरक्षा उपायों की बढ़ती मांग के कारण आईटी सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ है। भारतीय जीसीसी में बीपीएम क्षेत्र पारंपरिक सेवाओं से अधिक बुद्धिमान संचालन और डेटा-संचालित समाधानों में व्यवस्था परिवर्तन करके विकसित हुआ है।

11.53 प्रौद्योगिकी क्षेत्र गतिशील हैं और लगातार विकसित हो रहे हैं, जिससे वे कर्मचारियों और व्यवसायों के लिए आकर्षक बन गए हैं। वैश्विक नौकरी बाजार में आईटी पद सबसे अधिक मांग वाली भूमिकाओं में से एक हैं। उच्च मांग के बावजूद, इन क्षेत्रों में आईटी, डेटा विज्ञान और साइबर सुरक्षा कर्मचारियों की कमी के साथ प्रतिभा की कमी का सामना करना पड़ रहा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार[34], 2024 की तीसरी तिमाही के लिए, 76 प्रतिशत आईटी नियोक्ताओं ने वैश्विक स्तर पर आवश्यक कुशल प्रतिभाओं को खोजने में कठिनाई की सूचना दी। भारत में जीसीसी को प्रोत्साहित करने के लिए, उच्च शिक्षा में विशेषज्ञता को बढ़ावा देना आवश्यक है। फोकस क्षेत्रों में ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबरसिक्यूरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, 3डी प्रिंटिंग और वेब और मोबाइल डेवलपमेंट शामिल होने चाहिए।

11.54 प्रतिभा की कमी को दूर करने के लिए कई पहल की गई हैं। अपनी तरह की पहली पहल के रूप में परिकल्पित 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम', जो कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटीवाई) और नेस्कॉम की एक संयुक्त पहल है, का उद्देश्य आईटी पेशेवरों की अभिरूचियों और योग्यता के अनुरूप उनके कौशल में निरंतर वृद्धि की सुविधा के लिए फोकस क्षेत्रों में अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग इकोसिस्टम बनाना है।[35] सरकार ने उभरती और भविष्य की तकनीकों में डिजिटल कौशल कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका लक्ष्य इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और रोजगार के अवसरों के माध्यम से एक करोड़ छात्रों को कौशल, पुनः कौशल और कौशल उन्नयन प्रदान करना है।[36] प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 4.0) युवाओं के बीच कौशल

34. मैनपावरग्रुप (2024)। वैश्विक रोजगार परिदृश्य: तीसरी तिमाही 2024. https://go.manpowergroup.com/hubfs/GLOBAL_EN_MEOS_Report_3Q24.pdf

मैनपावरग्रुप रोजगार परिदृश्य सर्वेक्षण एक अग्रगामी रोजगार सर्वेक्षण है जिसका उपयोग वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख आर्थिक संकेतक के रूप में किया जाता है। यह सर्वेक्षण 42 देशों और क्षेत्रों में 40,374 सार्वजनिक और निजी नियोक्ताओं के साक्षात्कारों पर आधारित है, ताकि प्रत्येक तिमाही में प्रत्याशित रोजगार प्रवृत्तियों को मापा जा सके। https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Highlights.pdf

35. पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 29 अक्टूबर 2021, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx-?PRID=1767604

36. शिक्षा मंत्रालय की दिनांक 06 जून 2022 की पीआईबी विज्ञप्ति। https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1831624

विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, जो उद्योग 4.0[37], एआई, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन[38] जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करती है।

भारत में प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप

11.55 कोविड-19 महामारी ने उपभोक्ता और उद्यम की प्रौद्योगिकी समर्थित समाधानों की मांग को बढ़ावा दिया है। भारत में प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप की संख्या 2014 में लगभग 2,000 से बढ़कर 2023 में लगभग 31,000 हो गई है। नैसकॉम के अनुसार, इस क्षेत्र में 2023 में लगभग 1000 नए टेक स्टार्ट-अप्स की शुरुआत हुई है।

11.56 वर्ष 2023 में स्टार्ट-अप के लिए शीर्ष क्षेत्र एडटेक (16 प्रतिशत), एंटरप्राइजटेक (12 प्रतिशत), बीएफएसआई (10 प्रतिशत), विज्ञापन और विपणन (7 प्रतिशत), रिटेलटेक (6 प्रतिशत), मीडिया और मनोरंजन (5 प्रतिशत), कंज्यूमरटेक (5 प्रतिशत), पेशेवर सेवाएं (4 प्रतिशत) और गेमिंग (4 प्रतिशत) थे।

11.57 विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्ट-अप के उदय में कई कारकों ने योगदान दिया है। उपभोग पैटर्न में बदलाव और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच ने रिटेल टेक स्टार्ट-अप के लिए रास्ता तैयार किया। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की शुरूआत जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण 2016 से बीएफएसआई क्षेत्र में स्टार्ट-अप में उछाल देखा गया। स्केलेबल और कुशल क्लाउड समाधानों की मांग ने 'सॉफ्टवेयर ऐज अ सर्विस' (एसएएएस) स्टार्ट-अप के विकास को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप 2014 से 21 यूनिकॉर्न बने। कोविड-19 महामारी ने हेल्थटेक और एडटेक जैसे क्षेत्रों में विकास को गति दी, जो टेली-कंसल्टिंग और रिमोट लर्निंग समाधानों की बढ़ती जरूरत से प्रेरित था।

11.58 नैसकॉम के अनुसार, भारत का टेक स्टार्ट-अप इकोसिस्टम विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है और इसने अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है।[39] भारतीय टेक स्टार्ट-अप इकोसिस्टम की ताकत इसके स्टार्ट-अप, यूनिकॉर्न और मापने की क्षमता में निहित है। विश्व की 16 प्रतिशत एआई प्रतिभा के साथ, भारत स्वयं को एक नवाचार हब के रूप में स्थापित करता है, जो एआई कौशल को तेजी से अपना रहा है।

11.59 भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों में स्टार्ट-अप इंडिया पहल और स्टार्ट-अप हब ने टेक स्टार्ट-अप के विकास में सहायता की है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलों में राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्ट-अप नीति, ड्रोन शक्ति कार्यक्रम और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) से संबंधित पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के लिए सीमा शुल्क छूट शामिल हैं। इस स्टार्ट-अप क्षमता का और अधिक दोहन करने के लिए किए गए लक्षित प्रयासों का विवरण नीचे दिया गया है।

- **डीप-टेक इकोसिस्टम को गति देना और मजबूत करना:** 31 मार्च 2024 तक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में 1.25 लाख से अधिक डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप हैं, जिनमें से 13,000 से अधिक स्टार्ट-अप ऐसे हैं जो एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स एंड नैनोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्ट-अप नीति (एनडीटीएसपी)[40] का मसौदा डीप टेक स्टार्ट-अप की चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। यह नीति सीमित वित्तपोषण, संसाधन और बुनियादी ढाँचे की कमी जैसी महत्वपूर्ण बाधाओं का समाधान करती है और अत्याधुनिक तकनीकों से जुड़े जोखिमों को समझती है। यह वित्तपोषण तंत्र को डिजाइन करके हस्तक्षेप करती है जो 'डिजाइन द्वारा विफल' की अवधारणा को अपनाता है, स्टार्ट-अप संस्थापकों के लिए अपने वित्तपोषण के स्रोतों

37. उद्योग 4.0 एक शब्द है जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में स्वचालन, अंतसंयोजनीयता और डेटा विनिमय की वर्तमान प्रवृत्ति को दिया गया है।

38. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की दिनांक 26 दिसंबर 2023 की पीआईबी विज्ञप्ति। https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx-?PRID=1990495

39. नैसकॉम और जिनोव (2023)। चुनौतियों का सामना करना - भारतीय टेक स्टार्ट-अप परिदृश्य रिपोर्ट 2023. https://www.nasscom.in/knowledge-center/publications/weathering-challenges-indian-tech-start-landscape-report-2023

40. ड्राफ्ट नेशनल डीप टेक स्टार्ट-अप पॉलिसी 2023 (पेज 3). https://psa.gov.in/CMS/web/sites/default/files/process/NDTSP.pdf

में विविधता लाने के लिए वित्तपोषण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है, अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और बौद्धिक संपदा संरक्षण की सुविधा के लिए एक केंद्रीकृत प्रमुख मिशन कार्यालय की स्थापना करता है, टियर 2 और 3 शहरों में जागरूकता बढ़ाता है, और प्रमुख निष्पादन संकेतकों की मैपिंग के आधार पर एक निगरानी तंत्र अभिकल्पित करता है।

चार्ट XI.20: भारत के टेक स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में डीपटेक का उपयोग मुख्यधारा में आ रहा है

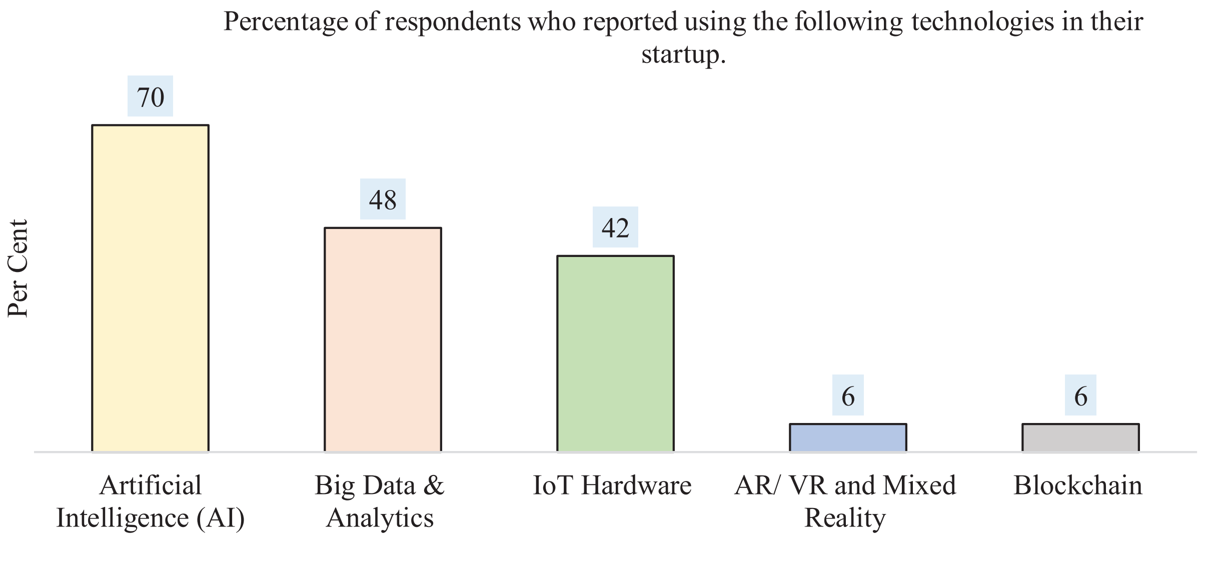

स्रोत: टेक स्टार्ट-अप सर्वेक्षण 2023, नैसकॉम और जिनोव रिपोर्ट - चुनौतियों का सामना - भारतीय टेक स्टार्ट-अप परिदृश्य रिपोर्ट 2023
नोट: (i) कुल प्रतिशत 100 से अधिक है क्योंकि उत्तरदाता विविध विकल्प चुन सकते हैं।
(ii) आईओटी-इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआर-ऑगमेंटेड रियलिटी, वीआर-वर्चुअल रियलिटी

- **घरेलू पूंजी प्रवाह को मजबूत करना:** सरकार ने स्टार्ट-अप की वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रूपये के कोष के साथ स्टार्ट-अप के लिए फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की है। इसने न केवल शुरुआती चरण, बीज चरण और विकास चरण में स्टार्ट-अप के लिए पूंजी उपलब्ध कराई है, बल्कि घरेलू पूंजी जुटाने, विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम करने और घरेलू और नए उद्यम पूंजी कोष को प्रोत्साहित करने में भी उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। उद्यम विकास के लिए प्रारंभिक चरण के समर्थन के महत्व को पहचानते हुए, 2021 में शुरू की गई स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम का उद्देश्य अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्ट-अप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।[41]

- **स्टार्ट-अप इंडिया जैसी पहलों का लाभ उठाना:** स्टार्ट-अप इंडिया पहल भारतीय स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने में मदद करती है। स्टार्ट-अप इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय ज्ञान विनिमय प्रणाली बनाने और सीमा-पार ऊष्मायन और त्वरण कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों में भाग लिया है।[42]

41. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, दिनांक 29 मार्च, 2023 की पीआईबी विज्ञप्ति। https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1911913

42. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)। राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग 2022 (पृष्ठ 25) https://www.startupindia.gov.in/srf-2022/SRF_2022_Result_page/National_Report_14_01_2024.pdf

दूरसंचार

11.60 दूरसंचार भारत में डिजिटल सेवाओं के तेज विकास का प्रवेश द्वार है। भारत में कुल टेलीघनत्व (प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोन की संख्या) मार्च, 2014 में 75.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 2024 में 85.7 प्रतिशत हो गया।[43] मार्च, 2024 के अंत में वायरलेस टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 116.5 करोड़ थी। सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के अंग के रूप में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड के विकास पर काफी जोर दिया है। परिणामस्वरूप, इंटरनेट ग्राहकों की संख्या मार्च, 2014 में 25.1 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2024 में 95.4 करोड़ हो गई, जिनमें से 91.4 करोड़ वायरलेस फोन के जरिए इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। मार्च, 2024 में इंटरनेट घनत्व भी बढ़कर 68.2 प्रतिशत हो गया। डेटा की लागत में काफी कमी आई है, जिससे प्रति ग्राहक औसत वायरलेस डेटा उपयोग में काफी सुधार हुआ है।

11.61 भारत में 5जी सेवाएँ पहली बार अक्टूबर, 2022 में शुरू की गई थीं। वर्तमान में, भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते 5जी नेटवर्कों में से एक है। 5जी सेवाओं के प्रारंभ के बाद, मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड में भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंक 118 से बढ़कर 15 (मार्च, 2024) हो गई है। यह '5जी टेस्ट बेड', जिसे 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया, एक एंड-टू-एंड परीक्षण सुविधा प्रदान करता है, जिससे भारतीय शिक्षा और उद्योग में अनुसंधान एवं विकास समूहों को अपने उत्पादों, प्रोटोटाइप और एल्गोरिदम को मान्य करने और विभिन्न सेवाओं का प्रदर्शन करने में मदद मिलती है। भारत 5जी पोर्टल भारत की 5जी क्षमताओं को बढ़ावा देता है और दूरसंचार क्षेत्र के भीतर नवाचार, सहयोग और ज्ञान-साझाकरण को बढ़ावा देता है।

11.62 6जी पर प्रौद्योगिकी नवाचार समूह की सिफारिशों के आधार पर, भारत में 6जी नेटवर्क प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और उपयोजित करने के लिए मार्च, 2023 में भारत 6जी विजन दस्तावेज लॉन्च किया गया था। इसके फलस्वरूप 6जी मिशन के चरण-वार उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए भारत 6जी मिशन और एक शीर्ष परिषद का गठन भी किया गया। जुलाई, 2023 में भारत 6जी गठबंधन भी सार्वजनिक और निजी कंपनियों, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों और मानक विकास संगठनों के एक सहयोगी मंच के रूप में लॉन्च किया गया था ताकि भारत को किफायती 5जी और 6जी और भविष्य के अन्य दूरसंचार समाधानों के आईपी, उत्पादों और समाधानों का एक अग्रणी वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनने में सक्षम बनाया जा सके।

11.63 देश में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए संशोधित भारत नेट प्रोग्राम की शुरुआत की जाती है। 31 मार्च, 2024 तक 6,83,175 किलोमीटर तक ऑप्टीकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछा दिए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप भारत नेट चरण-I और II में ओएफसी द्वारा कुल 2,06,709 ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है।

11.64 सरकार ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर विनियामक बोझ को कम करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कई संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधार भी लागू किए हैं। इनमें समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा को तर्कसंगत बनाना, स्पेक्ट्रम से संबंधित सुधार जैसे स्पेक्ट्रम को साझा करने और व्यापार करने की अनुमति देना और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क को तर्कसंगत बनाना, सुरक्षा उपायों के अधीन स्वचालित मार्ग के तहत दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देना आदि शामिल हैं। दूरसंचार अधिनियम, 2023 दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क, स्पेक्ट्रम के आवंटन आदि से संबंधित कानूनों को संशोधित और समेकित करता है।

11.65 दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास तथा व्यावसायीकरण के लिए व्यापक और अध्यवसायी पूंजी की आवश्यकता होती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए, सरकार ने निर्णय लिया है कि दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के वित्तपोषण के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ)[44] से वार्षिक संग्रहण का 5

43. प्रेस विज्ञप्ति संख्या 36 दिनांक 04 जुलाई 2024। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण https://www.trai.gov.in/sites/default/files/PR_No.36of2024.pdf

44. सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) का उद्देश्य देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और किफायती मोबाइल और डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है, जिससे मोबाइल और नेटवर्क सेवाओं तक गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच के साथ-साथ ज्ञान और सूचना प्रसार तक समान पहुंच हो सके, जिससे जीवन स्तर में सुधार के साथ तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके।

प्रतिशत आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2022 में तैयार किए गए दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष में स्टार्ट-अप, एमएसएमई, शिक्षाविदों और उद्योग की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई है।

11.66 इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में इंजीनियरिंग कार्यक्रमों को उद्योग में उभरती जरूरतों के साथ जोड़ने के लिए नए पाठ्यक्रमों का सुझाव दिया गया है। 5जी और 5जी-सक्षम प्रौद्योगिकी से संबंधित कौशल पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा अनुमोदित किया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने संकाय विकास कार्यक्रम के लिए एआईसीटीई प्रशिक्षण और शिक्षण अकादमी योजना में 5जी को एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में शामिल किया है।

11.67 मई, 2023 में शुरू किया गया संचार साथी पोर्टल[45], मोबाइल ग्राहकों को सशक्त बनाने, उनकी सुरक्षा को सुदृढ़ करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नागरिक-केंद्रित पहल है। संचार साथी पोर्टल में कई घटक हैं, जिनमें मार्च, 2024 में शुरू की गई चक्षु सुविधा भी शामिल है, जिसका उपयोग संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। प्राप्त शिकायतों के आधार पर उचित कार्रवाई की जा रही है।

ई-कॉमर्स

11.68 भारतीय ई-कामर्स उद्योग के 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर पार करने की संभावना है। भारतीय खुदरा बाजार काफी हद तक असंगठित है। हालाँकि, अगले 3 से 5 वर्षों में आधुनिक खुदरा (ई-कॉमर्स सहित) की हिस्सेदारी कुल खुदरा बाजार में 30-35 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।[46]

11.69 तकनीकी प्रगति, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, यूपीआई, एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल, डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क (ओएनडीसी), नई विदेश व्यापार नीति, एफडीआई सीमा में छूट और उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियम 2021 जैसी सरकारी पहलों के साथ-साथ विकसित हो रहे नए जमाने के व्यापार मॉडल के कारण भारत के ई-कॉमर्स बाजार ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण गति प्राप्त की है। ई-कॉमर्स के तेजी से विस्तार के केंद्र में पारंपरिक ब्रिक-और-मोर्टार बाजारों की तुलना में ई-मार्केटप्लेस द्वारा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को प्रदान किए जाने वाले लाभों की विविधता है।

11.70 ऑनलाइन बिक्री के लिए आवश्यक कौशल की अपर्याप्रता, जैसे कैटलॉगिंग, के कारण ई-कॉमर्स का उदय बाधित है। डेटा गोपनीयता के मुद्दे और ऑनलाइन धोखाधड़ी में वृद्धि भारत में ई-कॉमर्स के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन गई है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के सुरक्षित उपयोग के बारे में उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करना अनिवार्य हो जाता है। शुरुआत के लिए, सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कई पहलों को लागू किया है। प्रमुख विनियमों में ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं से उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 शामिल हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 एक व्यापक डेटा संरक्षण ढांचा प्रदान करता है, जो उपभोक्ता जानकारी को और अधिक सुरक्षित बनाता है।

11.71 जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार जागो-ग्राहक-जागो अभियान चलाती है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और सुरक्षित ई-कॉमर्स प्रथाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच)

45. वेबसाइट का लिंक- https://sancharsaathi.gov.in/

46. इन्वेस्ट इंडिया. ई-कॉमर्स: दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता ई-कॉमर्स बाजार। https://www.investindia.gov.in/sector/retail-e-commerce

मार्गदर्शन प्रदान करती है और उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करती है।[47] डिजिटल साक्षरता कार्यशालाओं और साइबर सुरक्षा सत्रों सहित विभिन्न उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ इंटरैक्टिव सत्र और वेबिनार उपभोक्ताओं को ई-कॉमर्स क्षेत्र में नवीनतम रुझानों और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरुक रखते हैं।

11.72 भारत में खरीदार पारिस्थितिकी-तंत्र बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, और सेवा अपेक्षाओं, मूल्य संवेदनशीलता और भाषा आवश्यकताओं के संबंध में विविध दुकानदारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यवसाय मॉडल में नवाचार की आवश्यकता होगी। स्थानीय भाषा प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है क्योंकि दुकानदारों का आधार टियर-2 और टियर-3 शहरों तक फैल रहा है। बढ़ते स्टार्ट-अप और नवोन्मेषी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अद्वितीय व्यवसाय मॉडल की परख करने का अवसर प्रदान करते हैं जिन्हें विशिष्ट जनसांख्यिकीय समूहों को लक्षित किया जा सकता है।[48] ई-कॉमर्स का भविष्य एआई, सहज डिजिटल भुगतान विधियों, यूपीआई जैसे नवाचारों और व्यवसाय संचालन और संवर्द्धन के लिए व्यवसाय इंजीनियरिंग डेटा विश्लेषिकी के माध्यम से बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव पर आधारित है। इसके अलावा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) जैसे प्लेटफॉर्म ई-कॉमर्स क्षमताओं की पहुँच बढ़ाते हैं।

बॉक्स XI.3: ओएनडीसी - डिजिटल वाणिज्य का लोकतंत्रीकरण

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक अग्रणी पहल है, जिसका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना और छोटे व्यवसायों को समान अवसर प्रदान करके डिजिटल कॉमर्स के लाभों का फायदा उठाने में सक्षम बनाना है। ओएनडीसी नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के विभिन्न घटकों को अलग-अलग करने और उन्हें आपस में जोड़ने के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। ओएनडीसी की शुरुआत जनवरी, 2022 में हुई और इसने गतिशीलता और खाद्य एवं पेय पदार्थों के अपने दोहरे डोमेन को किराना, फैशन, सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल, घर और रसोई, ऑन-नेटवर्क लॉजिस्टिक्स, कृषि, उपहार कार्ड, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और कारीगरी के कामों जैसे विभिन्न डोमेन में तेजी से विस्तार किया।

ओएनडीसी का विकास मानचित्र

68 million Transactions since inception	**1200+** Cities	**65** Seller Applications	**12** Logistic Service Providers
85% Small sellers	**535,000+** Sellers	**9** million Transactions per month	**22** Buyer Applications

प्रमुख डोमेनों की अद्यतन स्थिति

- **खाद्य और पेय:** यह नेटवर्क रेस्टोरेंट भागीदारों को लागत प्रभावी लाभ प्रदान करता है, जिससे प्रमुख एग्रीगेटर्स द्वारा लगाए जाने वाले उच्च शुल्क का बोझ कम होता है। वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही के दौरान, 347 शहरों में सेवा देने वाले 95,000 से अधिक रेस्टोरेंट और शीर्ष ब्रांडों के मजबूत नेटवर्क के कारण ऑर्डर में 18 प्रतिशत

47. पीआईबी विज्ञप्ति, दिनांक 06 दिसंबर 2023, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1983226

48. बैन एंड कंपनी. (13 दिसंबर 2023). हाउ इंडिया शॉप्स ऑनलाइन 2023 https://www.bain.com/insights/how-india-shops-online-2023/#

की वृद्धि हुई। टाटा न्यू, डोमिनोज और ओला जैसे बड़े ब्रांड नामों ने अपने ऐप में खाद्य सेवाएँ जोड़ी हैं, जबकि मैजिकपिन और पेटीएम जैसे अन्य प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और विशेष सौदों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह नेटवर्क दिल्ली-एनसीआर और लखनऊ में 350 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षित करके अपनी पहुँच का विस्तार कर रहा है।

- **किराना:** वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में, किराना ऑर्डर में 52 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की गई, जिसे 665 से अधिक शहरों में 12,585 विक्रेताओं के नेटवर्क द्वारा सुगम बनाया गया। पेटीएम और ओटिपी जैसे प्रमुख ब्रांड उन्नत डिजिटल स्टोरफ्रंट और क्यूआर कोड तकनीक में निवेश कर रहे हैं। कैच जैसे ब्रांडों के साथ सहयोग से उत्पाद की पेशकश में वृद्धि हो रही है, जिसमें वर्तमान में 6.3 मिलियन स्टॉक-कीपिंग यूनिट (एसकेयू) शामिल हैं। किको लाइव जैसी पहल स्थानीय किराना स्टोरों को सक्रिय रूप से डिजिटल बना रही है, जिसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और आईटीसी जैसी प्रमुख कंपनियों का समर्थन प्राप्त है, जो ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर 1.3 मिलियन किराना स्टोरों को डिजिटल बनाने की रणनीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं।

- **फैशन, सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल:** वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में 6400 से अधिक विक्रेताओं के समर्थन से 11 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो लगभग 900 शहरों में 15 लाख से अधिक एसकेयू की व्यापक पसंद पेश करते हैं। तिमाही के दौरान, जॉकी, कल्याण सिल्क, बेला वीटा और इमामी ब्यूटी जैसे प्रमुख ब्रांड नेटवर्क में शामिल हुए।

- **कृषि:** ओएनडीसी नेटवर्क किसानों और कारीगरों की आजीविका में काफी सुधार लाने की संभावना रखता है। अब तक लगभग 5,700 एफपीओ इस नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं, और उन्होंने वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही के दौरान सामूहिक रूप से 23,000 से अधिक लेन-देन किए हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) और लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ (एसएफएसी) के डिजिटल अनुप्रयोगों को भी नेटवर्क में एकीकृत किया गया है।

डिजिटल रूप से सशक्त समावेशी कहानियां

- तमिलनाडु के कांचीपुरम में श्री विद्या हैंडलूम्स ने ओएनडीसी के माध्यम से डिजिटल कॉमर्स में बदलाव किया। इस पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसाय ने अपनी पहुंच 54 शहरों तक बढ़ाई और अपनी उत्पाद लिस्टिंग को 20 से 400 डिजिटल कैटलॉग तक बढ़ाया। मुख्यधारा के प्लेटफॉर्म पर 10,000 रूपये से 20,000 रूपये की पिछली आय की तुलना में मासिक राजस्व बढ़कर लगभग 2 लाख रूपये हो गया। ओएनडीसी पर कमीशन की कम दरों ने लाभप्रदता को बढ़ाया।

- ओएनडीसी ने मन देशी फाउंडेशन और कुदुम्बश्री सहित 76 स्वयं सहायता समूहों की दस लाख से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाया है, जिससे 1,200 से अधिक ऑर्डर पूरे हुए हैं। नवोन्मेषी विपणन और टिकाऊ प्रथाओं ने ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दिया है। औसत ऑर्डर वॉल्यूम और राजस्व मार्जिन में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- महाराष्ट्र में कल्पनिल नेचुरल्स कोल्ड-प्रेस्ड तेलों का उत्पादन करता है और अप्रैल, 2023 में ओएनडीसी में एकीकृत हो गया। 13 एसकेयू सूचीबद्ध होने के साथ, ब्रांड का विस्तार 44 शहरों में हुआ और सितंबर, 2023 तक 2.5 लाख रुपये का राजस्व सृजित किया। संस्थापक ने बिचौलियों को हटा कर लाभ मार्जिन को बढ़ाने और व्यापार वृद्धि को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में ओएनडीसी की भूमिका पर जोर दिया।

- नम्मा यात्री, एक सवारी-उठाने (राइड हेलिंग) वाला मंच जो ओएनडीसी के साथ एकीकृत है, कमीशन को समाप्त करता है और सदस्यता शुल्क पर काम करता है। बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा चालक संघ के सहयोग से शुरू की गई इस योजना ने चालकों की आय में वृद्धि की और कैंसिलेशन दरों में कमी की।

चुनौतियाँ और अवसर

11.73 यह खंड विभिन्न सेवा क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों और विकास के अवसरों का सारांश प्रस्तुत करता है, जिन्हें ऊपर विभिन्न खंडों में प्रस्तुत किया गया है।

- सेवा क्षेत्र में तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण के कारण तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए कुशल कार्यबल की आवश्यकता है। हालांकि, प्रासंगिक डिजिटल और उच्च तकनीक कौशल वाले श्रमिकों की उपलब्धता में कमी है। सरकार कौशल भारत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास पहलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि कार्यबल को आवश्यक कौशल से लैस किया जा सके। उद्योग के सहयोग से सरकारी पहलों द्वारा प्रोत्साहित किए गए पारिस्थितिकी-तंत्र के माध्यम से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौशल विकास से भारत को साइबर सुरक्षा, उद्यम प्रबंधन, वित्तीय जोखिम प्रबंधन और बीमा जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले उच्च-मान वाले भागीदार के रूप में उभरने में मदद मिल सकती है।

- आर्थिक गतिविधि के लिए संभार-तंत्र और परिवहन सेवाओं के महत्व को पहचानते हुए, बुनियादी ढांचे की बाधाओं, संभार-तंत्र लागत और विनियामक अनुपालन को कम करने के लिए कई पहल की गई हैं। इसके अतिरिक्त, बंदरगाह संचालन और अंतर्देशीय जलमार्ग जैसी उन्नत सेवाओं के लिए भारत की व्यापक तटरेखा और नदी नेटवर्क का लाभ उठाने से परिवहन मार्गों को सुव्यवस्थित करने, लागत कम करने और दक्षता में सुधार करने की महत्वपूर्ण क्षमता हासिल होने की आशा है। नीदरलैंड में यूरोप के अंतर्देशीय जलमार्गों का सबसे घना नेटवर्क है, जो लगभग 6,000 किलोमीटर की नदियों और नहरों को कवर करता है। ये जलमार्ग जल निकासी और नेविगेशन सहित विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। कुल 2,200 किलोमीटर के, प्रमुख वाणिज्यिक मार्ग (श्रेणी IV और उच्चतर), अंतरराष्ट्रीय माल ढुलाई का लगभग 40 प्रतिशत और देश के भीतर घरेलू माल ढुलाई का 20 प्रतिशत संभालते हैं।[49] केरल द्वारा कोच्चि जल मेट्रो पर्यटन, वाणिज्य और परिवहन के लिए अपने बैकवाटर का सफल उपयोग करने से 33,000 द्वीपवासियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता को रेखांकित करता है।[50] देश भर में इसी प्रकार की रणनीति अपनाने से भारत की अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली को बढ़ावा मिल सकता है, सतत विकास को बढ़ावा मिल सकता है तथा भीड़भाड़ कम हो सकती है।

- विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में कार्यरत लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए वित्त तक पहुंच बनाना कठिनाइयां पैदा कर सकता है।[51] ऋण सुलभता को आसान बनाने के लिए मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया जैसी कई पहलों को लागू किया गया है। इन प्रयासों के आधार पर, ऋण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, ऋण गारंटी योजनाओं की पहुँच बढ़ाने, वैकल्पिक ऋण मूल्यांकन विधियों को अपनाने और आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण में नवाचार लाने पर ध्यान केंद्रित करके इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह को और बढ़ाया जा सकता है। सरकार उचित स्तरों पर परियोजना दस्तावेजीकरण में सहायता करने तथा परियोजनाओं की बैंकिंग क्षमता में सुधार करने के लिए एजेंसियां भी स्थापित कर सकती हैं।

- सेवा क्षेत्र में विनियामक परिदृश्य, जो पहले जटिल हुआ करता था, सकारात्मक परिवर्तनों से गुजर रहा है। जीएसटी सरलीकरण, स्टार्ट-अप इंडिया और भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम जैसी क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों जैसी पहलों से और अधिक अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा मिल रहा है। एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से प्रक्रियाओं के सरलीकरण को और बढ़ाना, कानूनी प्रावधानों को सुव्यवस्थित करना और सभी प्रशासनिक स्तरों पर सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना आर्थिक दक्षता को काफी हद तक बढ़ा सकता है।

---

49. विश्व की नहरें। नीदरलैंड, 30 जून 2024 को को निम्नलिखित लिंक से प्राप्त: http://worldcanals.org/english/netherlands.html#:~:text=About%206000km%20of%20rivers%20and,Rhine%20Canal%2C%20completed%20in%201953

50. कोच्चि वाटर मेट्रो। 30 जून 2024 https://watermetro.co.in/about

51. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। भारत के एमएसएमई को वित्तपोषित करना - भारत में एमएसएमई की ऋण आवश्यकता का अनुमान (पृष्ठ 65) https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/financing-india-s-msmes-estimation-of-debt-requirement-of-msmes-in-india.pdf

- सेवाओं के बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गए हैं। इसे देखते हुए, सरकार उपभोक्ता डेटा की सुरक्षा और सेवा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए डेटा सुरक्षा कानूनों और साइबर सुरक्षा नीतियों की दक्षता बढ़ा रही है। प्रौद्योगिकी को और अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनाने के लिए, मजबूत सुरक्षा उपायों को अपनाना, गोपनीयता विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देना आवश्यक है।

निष्कर्ष और भावी परिदृश्य

11.74 ऐतिहासिक रूप से, भारत का सेवा क्षेत्र कम लागत वाली पेशकशों पर फलता-फूलता रहा है। सेवाओं के डिजिटलीकरण और उचित नीतिगत पहलों ने पिछले दशक के शुरुआती दौर में सेवा वितरण की प्रकृति को लगभग अनुत्क्रमणीय रूप से लगातार रूपांतरित किया है। महामारी के बाद यह प्रवृत्ति और तेज हो गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एक और विशिष्ट पैटर्न जो उभरा है, वह यह है कि संपर्क-गहन व्यवसाय और व्यक्तिगत सेवाएँ - मुख्य रूप से व्यापार, परिवहन, रियल एस्टेट और उनकी सहायक सेवाएँ - जो महामारी के दौरान भारी गिरावट के दौर से गुजरी थीं, अब सुधार कर रही हैं, और उनमें ज्यादा तकनीक और डिजिटल सामग्री समाविष्ट हो गई है। साथ ही, भारत के सेवा-निर्यात में सॉफ्टवेयर से आगे बढ़कर मानव संसाधन (एचआर), कानूनी और डिजाइन सेवाओं को शामिल करने के लिए विविधता आ रही है, जो उभरती वैश्विक माँगों के अनुरूप है। इस प्रकार, दो महत्वपूर्ण परिवर्तन घरेलू सेवा वितरण का तेज तकनीक-संचालित परिवर्तन और भारत के सेवा-निर्यात का विविधीकरण भारत के सेवा परिदृश्य को नया आकार दे रहे हैं।

11.75 देश वैश्विक क्षमता केंद्रों के हब के रूप में उभर रहा है। घरेलू स्तर पर, स्टार्ट-अप नवाचार को बढ़ावा देते हैं, ऋण, कच्चे माल और बाजारों तक पहुंच में सुधार करते हैं। गहन प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी-तंत्र और लगातार नीतिगत समर्थन की सहायता से, कई प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप विनिर्माण और अन्य सेवाओं का डिजिटलीकरण कर रहे हैं। गैर-सेवा आर्थिक गतिविधियों की अंतर्निहित सेवा सामग्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जैसा कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी द्वारा प्रमाणित हुआ है। इन गतिविधियों में उत्पादन के बाद का मूल्य संवर्धन भी ई-कॉमर्स, नवोन्मेष पैकेजिंग और विज्ञापन और आधुनिक संभार-तंत्र सेवाओं जैसी सेवाओं पर तेजी से निर्भर हुआ है।

11.76 जैसा कि भारत 2030 तक करोड़ों नौकरियां पैदा करने की उम्मीद कर रहा है, सेवाओं की मांग-आपूर्ति की गतिशीलता में इस परिवर्तन को मध्यम अवधि में भर्ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। सेवा क्षेत्र में उभरती नौकरी की माँग वृहत्तर और अधिक विशिष्ट कौशल को आवश्यक बनाती है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट[52] संज्ञानात्मक योग्यताओं (जैसे जटिल समस्या-समाधान और रचनात्मक सोच), डिजिटल साक्षरता और एआई और बड़े डेटा में दक्षता पर बढ़ते फोकस पर प्रकाश डालती है। यह बदलाव व्यवसायों और कार्यबल के लिए तकनीकी प्रगति के अनुकूल होने और वैश्विक बाजार की माँगों को पूरा करने के लिए रणनीतिक अनिवार्यता को रेखांकित करता है। फोकस क्षेत्रों में ब्लॉकचेन, एआई, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता, 3डी प्रिंटिंग और वेब और मोबाइल विकास शामिल होना चाहिए। अतः भारत में कौशल विकास कार्यक्रम का तात्कालिक कार्य इन आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए योजना बनाना और खुद को सुसजित करना है। कैपिटल इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि एआई के कारण भारत के सेवा-निर्यात की वृद्धि दर धीमी हो सकती है, तथा अगले दशक में इसमें प्रति वर्ष 0.3-0.4 प्रतिशत अंकों की कमी आ सकती है।[53] यह रोजगार सृजन के लिए अपेक्षाकृत कम कौशल-निर्भर पर्यटन क्षेत्र के महत्व को रेखांकित

52. विश्व आर्थिक मंच। (2023)। डब्ल्यूईएफ नौकरियों का भविष्य 2023 (पृष्ठ 7)। https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf

53. द इकोनॉमिस्ट (24 जून 2024)। क्या सेवाएं दुनिया को समृद्ध बनाएंगी? https://www.economist.com/finance-and-economics/2024/06/24/will-services-make-the-world-rich

करता है। इसलिए, सार्वजनिक नीति द्वारा पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सभी स्तरों पर सरकारों और निजी क्षेत्र को इस क्षेत्र की क्षमता को साकार करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।[54]

11.77 अल्पावधि में, अस्थायी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और कमोडिटी मूल्य अनिश्चितताएं इनपुट लागत और सेवाओं की मांग के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करती हैं।[55] इस प्रकार, सकारात्मक मांग प्रवृत्तियों को बनाए रखना और बढ़ती लागतों और प्रतिस्पर्धी दबावों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना आगामी वर्ष में सेवा क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण होगा। अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से सेवा क्षेत्र द्वारा दिखाई गई महामारी के बाद की गतिशीलता, इन अनिश्चितताओं और चुनौतियों को पार करने में मदद करेगी।

****

54. होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बेनोरी नॉलेज। विजन 2047: भारतीय होटल उद्योग (पृष्ठ 29)। https://hotelassociationofindia.com/Vision%202047%20-%20March%2030.pdf

55. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित 2019-20 के लिए नवीनतम आपूर्ति और उपयोग तालिकाओं के अनुसार, भारत में सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट कमोडिटी-उत्पादन (कृषि और औद्योगिक) क्षेत्रों से आते हैं। इसलिए, कमोडिटी की कीमतों पर दबाव सेवाओं की इनपुट लागत को और फलस्वरूप उनकी मांग को काफी प्रभावित कर सकता है।

यह पृष्ठ खाली छोड़ दिया गया है

12

अवसंरचना: संभावित विकास को प्रोत्साहन

अध्याय

अर्थव्यवस्था में महामारी से प्रेरित मंदी को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रतिक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय में वृद्धि थी, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाली भौतिक और सामाजिक बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना था। पिछले पांच वर्षों में गति को बनाए रखते हुए, केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में वित्त वर्ष 20 स्तरों के सापेक्ष वित्त वर्ष 24 में लगभग तीन गुना वृद्धि देखी गई है. इस कदम के प्रमुख लाभार्थी सड़क और रेलवे जैसी प्रमुख मूलभूत संपत्तियां हैं।

बढ़ते सार्वजनिक निवेश को संस्थागत और प्रक्रियात्मक सुधारों के एक समूह द्वारा पूरक किया गया है जो परियोजना निष्पादन और समय पर जारी करने के समाधान की सुविधा प्रदान करते हैं। इनमें पीपीपी के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की पहल, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और परियोजना निगरानी समूह जैसे सुविधाजनक उपाय, पीएम-गतिशक्ति जैसी बाधाओं को दूर करने और अवसंरचना के निवेश के लिए आवश्यक दीर्घकालिक वित्त पर बाधाओं को कम करने के लिए आरईआईटीएस और इनविट्स जैसे नए उपकरण शामिल हैं।

अध्याय से पता चलता है कि, पिछले पांच वर्षों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के साथ, भारत ने भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी और स्वच्छता और पानी की आपूर्ति सहित सामाजिक अवसंरचना में महत्वपूर्ण विस्तार देखा है, जिससे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिली है। साथ ही, केन्द्र और राज्य सरकारों की राजकोषीय बाध्यताओं और समेकन योजनाओं को देखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड पर व्यवहार्य परियोजनाएं सामने आएं और निष्पादित हों।अवसंरचना निवेश पर क्षेत्र-वार, स्त्रोत-वार सूचना का नियमित संग्रहण, बॉटम-अप अध्ययन और अवसंरचना की आवश्यकताओं का एकत्रीकरण तथा सृजित परिसंपत्तियों के उपयोग के आवधिक मूल्यांकन से देश के विकासात्मक पथ पर मध्यावधि सुधार करने में सहायता मिलेगी।

परिचय

12.1. एक लचीला, विश्व स्तरीय अवसंरचना-भौतिक, सामाजिक, वित्तीय और डिजिटल-का निर्माण विकसितभारत @ 2047 बनने के लिए भारत की नीति रणनीति का एक प्रमुख मुद्दा है। तथापि, एशियाई विकास बैंक[1] और विश्व बैंक[2] द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययनों और सीआरआईएसआईएल[3] जैसी एजेंसियों द्वारा किए गए हाल के अनुमानों में विभिन्न क्षेत्रों में अवसंरचना निवेश में अंतरों की पहचान की गई है। इस पृष्ठभूमि के आधार पर यह अध्याय वित्त वर्ष 24 में प्राप्त प्रगति पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत के अवसंरचना के क्षेत्र में हाल के विकास की जांच करता है।

1 भारत की अवसंरचना की जरूरतों को पूरा करना, एडीबी, 2017
2 भारत की शहरी अवसंरचना की जरूरतों को वित्तपोषित करना विश्व बैंक, 2022
3 क्रिसिल द्वारा प्रकाशित इंफ्रास्ट्रक्चर ईयरबुक 2023

12.2. अध्याय को छह खंडों में विभाजित किया गया है। खंड II डेटा की सीमाओं के भीतर अवसंरचना के वित्तपोषण के सवाल की जांच करता है और निजी पूंजी और सार्वजनिक निवेश के बीच अधिक संतुलन की आवश्यकता पर बल देता है, जो सामान्य सरकार द्वारा राजकोषीय समेकन की आवश्यकताओं से विवश होगा। खंड III में क्षेत्रीय विकास, चुनौतियों और दृष्टिकोण पर चर्चा की गई है। वित्तीय अवसंरचना तथा स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसी सामाजिक अवसंरचनाओं पर विवेचन इस अध्याय में शामिल नहीं है क्योंकि इन विषयों की विवेचना क्रमशः अध्याय 2, 7 तथा 8 में की गई है। चौथा खंड अवसंरचना क्षेत्र में चुनौतियों और अवसरों की झलक दिखाता है। खंड V भारत के इन्फ्रा क्षेत्र में बाधाओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की जांच करता है। खंड VI चर्चाओं को सारांशित करता है और आगे बढ़ने के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रस्तुत करता है।

अवसंरचना वित्तपोषण: सार्वजनिक व्यय को बढ़ावा देना

12.3. यह खंड भारत में अवसंरचना के वित्तपोषण के बारे में दो महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने लाता है। पहला, हाल के वर्षों में अवसंरचना के वित्तपोषण में कई वित्तीय नवाचारों के बावजूद, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय की अभी भी बड़े पैमाने पर अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण में केंद्रीय भूमिका है। दूसरे, अनेक नए निधियन लिखतों और कार्यनीतियों के उभरने से अवसंरचना वित्तपोषण का स्थान जटिल हो गया है और विभिन्न एजेंसियों द्वारा आंकड़ों के रख-रखाव में अपनाई जाने वाली भिन्न-भिन्न परिभाषाओं और पैटर्नों को देखते हुए, किसी दिए गए वर्ष में अवसंरचना के सृजन के लिए निधियों के कुल प्रवाह को एकत्रित करना कठिन है।

12.4. भले ही बजटीय पूंजीगत व्यय को अवसंरचना के खर्च[4] के बराबर नहीं किया जा सकता है, केंद्र सरकार के अवसंरचना के जोर ने पूंजीगत व्यय में अभूतपूर्व वृद्धि की है। चार्ट XII.1 से पता चलता है कि केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 24 (पीए) तक 2.2 गुना बढ़ गया, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य सरकारों का पूंजीगत व्यय 2.1 गुना बढ़ गया।

12.5. केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में मोटे तौर पर दो घटक शामिल होते हैं - इसके लाइन विभागों द्वारा खर्च और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को दी गई सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)। केंद्र सरकार के कुल पूंजीगत व्यय में दो प्रमुख कनेक्टिविटी खंडों, यानी रेलवे और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सकल बजटीय सहायता का हिस्सा वित्त वर्ष 21 में 36.4 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 24 (आरई) में 42.9 प्रतिशत हो गया। पूंजीगत व्यय के इन दो घटकों में वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 24 (आरई) तक उनके पूर्ण मूल्यों में 2.6 गुना वृद्धि हुई।

12.6. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के समग्र निवेश योग्य संसाधनों में जीबीएस तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा स्वयं जुटाए गए संसाधन शामिल हैं। केंद्र सरकार और सीपीएसई की संयुक्त उधार लागत को अनुकूलित करने के लिए, दो प्रमुख अवसंरचना-सीपीएसई-एनएचएआई और भारतीय रेलवे वित्त निगम (आई आर एफ सी) की उच्च-लागत वाली उधारी को वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 24 तक उत्तरोत्तर कम कर दिया गया था। यह काफी हद तक चार्ट XII.1 में सीपीएसई के अपने संसाधनों में कमी से परिलक्षित होता है। हालांकि, यह कमी विस्तारवादी जीबीएस द्वारा ऑफसेट कर दी गई जिससे वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 24 के बीच सड़कों और रेलवे में निवेश को काफी हद तक बढ़ाने की अनुमति मिली।

4 सरकार के पूंजीगत व्यय में किसी भी पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए किया गया व्यय शामिल है, जिसे अवसंरचना की सामंजस्यपूर्ण परिभाषा के तहत अवसंरचना के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र के अंतर्गत नहीं बनाया जा सकता है।

चार्ट XII.1: केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय और सीपीएसई और राज्य सरकारों के लिए इसकी सहायता में काफी विस्तार हुआ है	चार्ट XII.2: राज्य सरकारों के संयुक्त पूंजीगत व्यय* में भी जोरदार विस्तार होता है
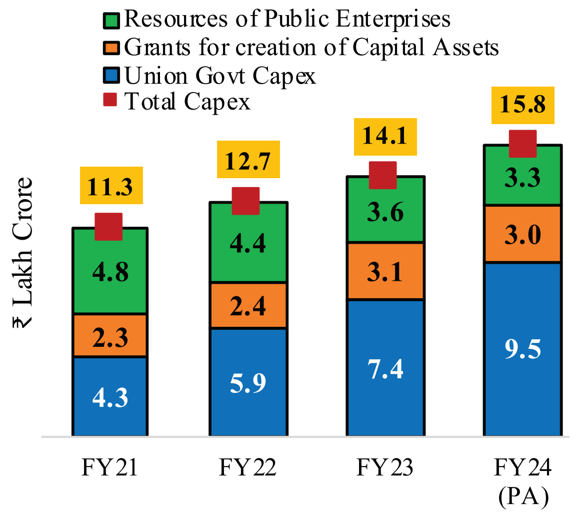	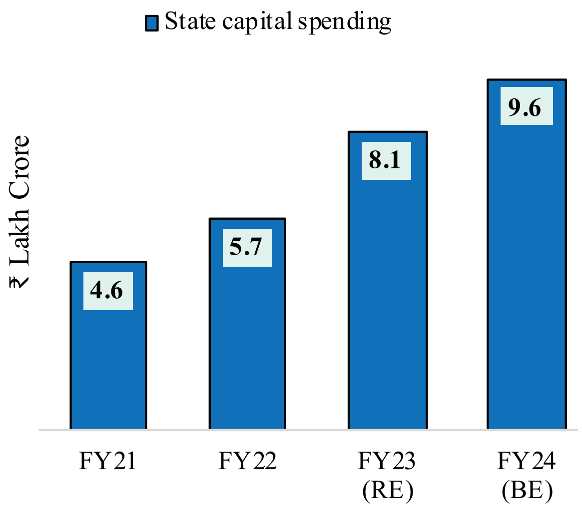

स्रोत: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रकाशित संघ सरकार के लिए संघ सरकार बजट दस्तावेज और राज्य वित्त खाते एवं राज्य सरकारों के लिए राज्य बजट।

नोट: (i) RE का अर्थ संशोधित अनुमान है, BE का अर्थ बजट अनुमान है, PA का अर्थ अनन्तिम खाते हैं।

(ii) * राज्य के पूंजीगत व्यय में पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

(iii) वित्त वर्ष 2024 के लिए सार्वजनिक उद्यमों के संसाधनों का डेटा एक संशोधित अनुमान है।

12.7. वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 24 के दौरान राज्य सरकारों और संस्थानों के पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार का समर्थन 31.6 प्रतिशत बढ़ गया। राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय का और विश्लेषण संभव नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) को जीबीएस संबंधी आंकडे और स्वयं एसपीएसई द्वारा जुटाए गए संसाधन समेकित रूप में उपलब्ध नहीं हैं।

12.8. वित्त पोषण के महत्वपूर्ण गैर-सरकारी स्रोतों पर चार्ट XII.3 से XII.9 इस तथ्य को दोहराता है कि भारत में हाल ही में अवसंरचना पर जोर, विशेष रूप से कनेक्टिविटी परियोजनाओं में वृद्धि, मुख्य रूप से सार्वजनिक व्यय पर निर्भर है। मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच बैंक ऋण के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्रों में धन का शुद्ध प्रवाह केवल ₹79,000 करोड़ के आसपास था, जो केंद्र सरकार द्वारा रेलवे या सड़कों के लिये जीबीएस से बहुत कम था। चार्ट XII.3 से XII.5 यह भी दर्शाता है कि मार्च 2020 और मार्च 2024 के बीच बैंक ऋण का शुद्ध प्रवाह केवल कुछ क्षेत्रों, सड़कों, हवाई अड्डों और बिजली में केंद्रित था। हालांकि, वित्त वर्ष 24 में अवसंरचना क्षेत्रों में ऋण वृद्धि वित्त वर्ष 23 में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 6.5 प्रतिशत तक सुधर गई।

12.9. अवसंरचना क्षेत्रों के लिए बाहरी वाणिज्यिक उधार का सकल प्रवाह भी वित्त वर्ष 24 में USD 9.05 बिलियन तक बढ़ गया, जबकि वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 23 के दौरान औसतन USD 5.91 बिलियन था। पूंजी बाजार में ऋण और इक्विटी जारी करने के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्रों[5] द्वारा संसाधन जुटाना वित्त वर्ष 24 के दौरान केवल ₹1,00,000 करोड़ से अधिक था. रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट आरईआईटी) ने वर्ष 2019 से 2024 तक 18,840 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जबकि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इनविट्स) ने पिछले पांच वर्षों (2019-2024) में कुल 1,11,294 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

चार्ट XII.3: इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बकाया क्रेडिट: मार्च 2024

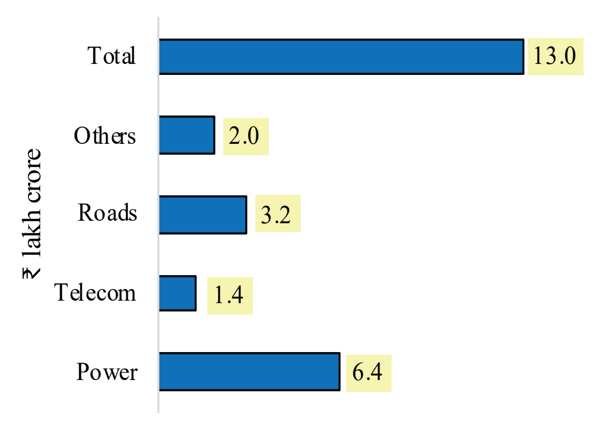

चार्ट XII.4: मार्च 2020 से मार्च 2024 तक औसत वार्षिक वृद्धि दर

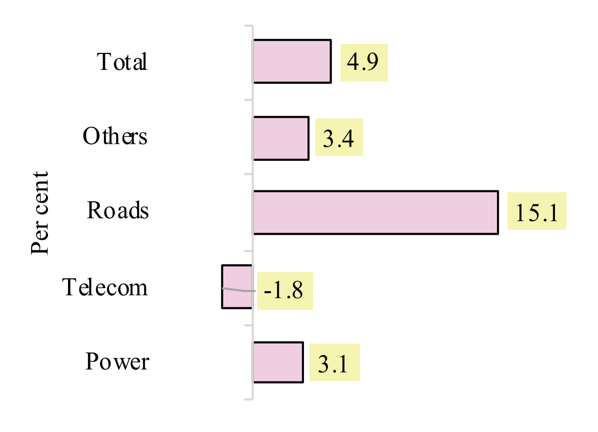

चार्ट XII.5: मार्च 2020 से मार्च 2024 तक बकाया ऋण में परिवर्तन में हिस्सा

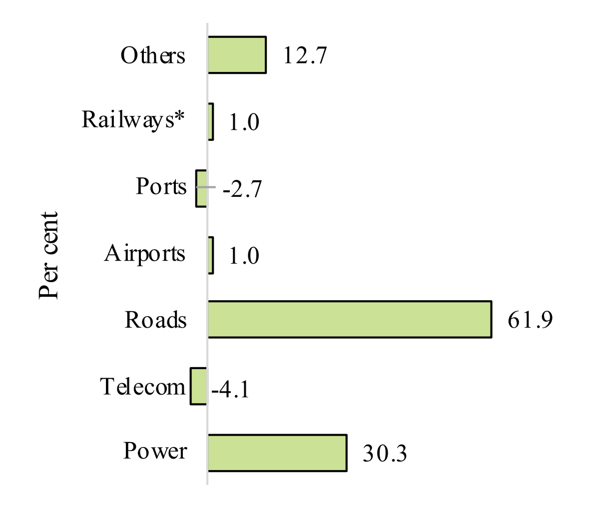

चार्ट XII.6: अवसंरचना क्षेत्रों में विदेशी वाणिज्यिक उधार का अंतर्वाह

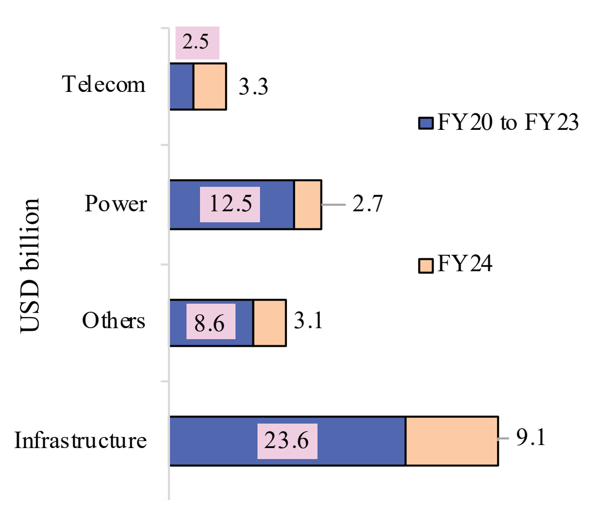

5 नोट: अवसंरचना क्षेत्र को निम्नलिखित उप-क्षेत्रों के आधार पर माना गया है - इक्विटी के लिए: हवाई अड्डा और हवाई अड्डा सेवाएं, सिविल निर्माण, शिक्षा, ई-लर्निंग, हेल्थकेयर रिसर्च, एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी, होटल और रिसॉर्ट, बंदरगाह और बंदरगाह सेवाएं, बिजली - ट्रांसमिशन, बिजली वितरण, बिजली उत्पादन, रेलवे वैगन, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी), रियल एस्टेट से संबंधित सेवाएं, आवासीय, वाणिज्यिक परियोजनाएं, सड़क संपत्ति-टोल, वार्षिकी, हाइब्रिड-वार्षिकी, सड़क परिवहन, जहाज निर्माण और संबद्ध सेवाएं, शिपिंग, दूरसंचार - अवसंरचना, अपशिष्ट प्रबंधन और जल आपूर्ति और प्रबंधन ऋण के लिए: निर्माण, अवसंरचना (विद्युत, दूरसंचार, सड़क, हवाई अड्डा, बंदरगाह, रेलवे और अन्य अवसंरचना), सिविल निर्माण, ऊर्जा, हेल्थकेयर, होटल और रिसॉर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित सेवाएं, सड़क संपत्ति-टोल, वार्षिकी, हाइब्रिड-वार्षिकी, दूरसंचार-अवसंरचना एवं आवासीय वाणिज्यिक परियोजनाएं।

चार्ट XII.7: घरेलू पूंजी बाजार ऋण स्रोतों के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्रों का वित्तपोषण

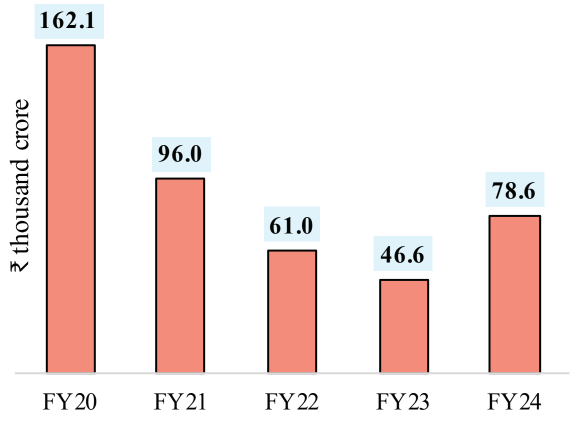

चार्ट XII.8: इक्विटी जारी करने के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्रों का वित्तपोषण

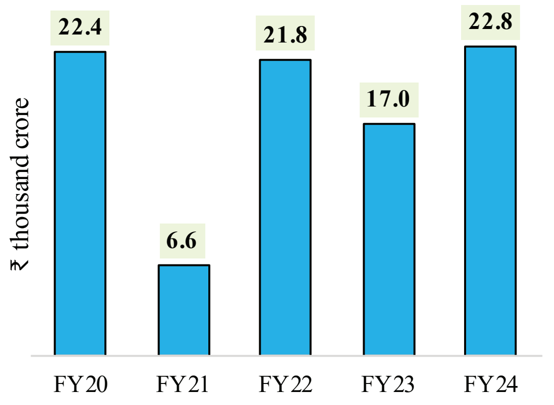

स्रोत: क्रेडिट और बाहरी वाणिज्यिक उधार पर डेटा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त किए गए थे। घरेलू ऋण और इक्विटी निर्गम के आंकड़े भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से प्राप्त किए गए थे

टिप्पणी (*): XII.5 में रेलवे के संदर्भ में भारतीय रेल शामिल नहीं है।

चार्ट XII.9: वित्त वर्ष 24 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में एफडीआई इक्विटी इनफ्लो

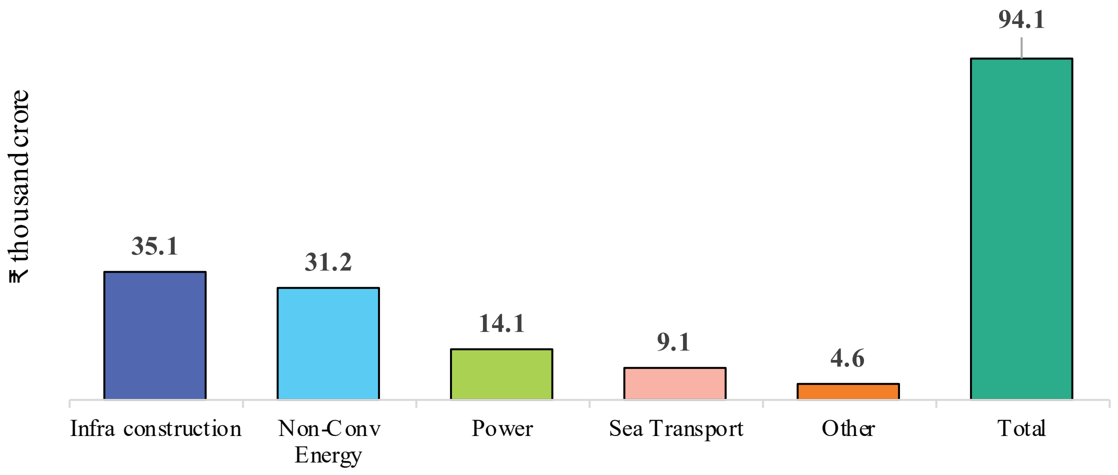

तालिका XII.1: अवसंरचना से संबंधित एफडीआई: प्रमुख अनुपात

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अवसंरचना क्षेत्रों में एफडीआई इक्विटी प्रवाह: वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 24	0.28
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अवसंरचना क्षेत्रों में एफडीआई इक्विटी प्रवाह: वित्त वर्ष 24	0.32
कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह के प्रतिशत के रूप में अवसंरचना क्षेत्रों में एफडीआई इक्विटी प्रवाह: वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 24	17.3
कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह के प्रतिशत के रूप में अवसंरचना क्षेत्रों में एफडीआई इक्विटी प्रवाह: वित्त वर्ष 24	25.6

स्रोत: औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गणना

नोट: जिन क्षेत्रों पर विचार किया गया है उनमें अवसंरचना निर्माण, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, दूरसंचार, बिजली, समुद्र और हवाई परिवहन, रेलवे घटक शामिल हैं

बॉक्स XII.1: सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख तंत्र

सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी)

- केंद्रीय क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए शीर्ष निकाय
- वित्त वर्ष 15 से वित्त वर्ष 24 तक 2.4 लाख करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 77 परियोजनाओं की सिफारिश की गई थी।

व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ)

- वित्तीय रूप से अव्यवहार्य किन्तु सामाजिक/आर्थिक रूप से वांछनीय पीपीपी परियोजनाओं को सहायता।
- 64,926.1 करोड़ रुपये की लागत वाली 57 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई और वित्त वर्ष 15 से वित्त वर्ष 24 तक 25,263.8 करोड़ रुपये की लागत वाली 27 परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी दी गई।
- वित्त वर्ष 15 से वित्त वर्ष 24 तक ₹5,813.6 करोड़ (केंद्र सरकार और राज्य दोनों की हिस्सेदारी) की कुल वीजीएफ स्वीकृति।

भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि योजना

- पीपीपी परियोजनाओं के परियोजना विकास के लिए वित्तीय सहायता
- नवंबर 2022 में वित्त वर्ष 23 से वित्त वर्ष 25 तक तीन वर्षों के लिए ₹150 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया।
- 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

अन्य सहायक उपकरण

- राज्य पीपीपी इकाइयों की स्थापना, पीपीपी परियोजना मूल्यांकन और परियोजना कार्यान्वयन मोड चयन के लिए संदर्भ मार्गदर्शिकाएँ बनाई गई हैं। वेब-आधारित टूलकिट, पोस्ट-अवॉर्ड अनुबंध प्रबंधन टूलकिट और परियोजना प्रायोजक प्राधिकारियों के लिए आकस्मिक देयता को पीपीपी संरचना में उनकी सहायता के लिए विकसित किया गया है।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी)

12.10. एनएमपी की घोषणा अगस्त 2021 में 'मुद्रीकरण के माध्यम से संपत्ति निर्माण' के सिद्धांत पर की गई थी, अर्थात, नए अवसंरचना के निर्माण के लिये निजी क्षेत्र के निवेश का दोहन। एनएमपी के तहत कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के माध्यम से वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025[6] तक चार वर्षों में ₹6.0 लाख करोड़ लगाया गया था। पाइपलाइन में 12 मंत्रालयों में 20 से अधिक परिसंपत्ति वर्ग शामिल थे।

12.11. मंत्रालय पाइपलाइन विकसित करने पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और उनकी रणनीतिक पहलों के अनुरूप लेनदेन किए गए हैं। पहले दो वर्षों के दौरान, यानी 2021-22 और 2022-23, कोर एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत प्रोद्भवन या निजी निवेश में लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन पूरे किए गए। इसके अलावा, 2023-24 में, प्रोद्भवन या निजी निवेश में कुल 1.51 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन पूरे किए गए, जो 2021-22 में हासिल किए गए से 1.55 गुना थे।

अवसंरचना क्षेत्रों में विकास

12.12. इस खंड में भौतिक संपर्क, बिजली, पानी और स्वच्छता, शहरी विकास, रणनीतिक और डिजिटल अवसंरचना को कवर करने सहित दृष्टिकोण और चुनौतियों के साथ-साथ प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों में प्रगति पर चर्चा की गई है।

6 एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन.pdf (niti.gov.in) -https://tinyurl.com/mw3bdr74

इस अध्याय में केवल अवसंरचना विकास से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, अवसंरचना संबंधी सेवाओं पर चर्चा को सेवाओं के अध्याय पर छोड़ दिया गया है।

भौतिक कनेक्टिविटी अवसंरचना

सड़क परिवहन

12.13. रणनीतिक योजना और सार्वजनिक निवेश में तेजी के परिणामस्वरूप सड़क नेटवर्क प्रणाली का एक लचीला और कुशल अवसंरचना में उन्नयन हुआ है। केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा पूंजी निवेश वित्त वर्ष 15 में 0.4 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.0 प्रतिशत (लगभग 3.01 लाख करोड़ रुपये) हो गया। इस क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2024 में अपने अब तक के सबसे अधिक निजी निवेश को आकर्षित किया है क्योंकि निजी क्षेत्र अनुकूल नीति वातावरण पर पूंजीकरण करता है. इसके अलावा, निजी निवेश पर दोहन, सड़क क्षेत्र में परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से प्राप्त धन वित्त वर्ष 19 से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। विशेष रूप से, सरकार ने वित्त वर्ष 24 में ₹40,314 करोड़ का अपना अब तक का सबसे अधिक एसेट मोनेटाइजेशन राजस्व हासिल किया।

12.14. पिछले दस वर्षों में, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जो 2014 से 2024 तक 1.6 गुना बढ़ गई है। भारतमाला परियोजना ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का काफी विस्तार किया है, 2014 और 2024 के बीच हाई-स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 12 गुना और 4-लेन सड़कों की लंबाई 2.6 गुना बढ़ा दी है। इसके अलावा, गलियारे आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास दृष्टिकोण के माध्यम से व्यवस्थित प्रयासों के कारण राजमार्ग निर्माण की दक्षता में सुधार हुआ है। एनएच निर्माण की औसत गति वित्त वर्ष 14 में 11.7 किमी प्रति दिन से ~ 3 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 24 तक ~ 34 किमी प्रति दिन हो गई। एनएच नेटवर्क के उल्लेखनीय सुधार ने रसद दक्षता में पर्याप्त प्रगति की है। यह विश्व बैंक के 'लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स' में भारत की रैंकिंग में लगातार बढ़ती रैंकिंग से स्पष्ट है, जो 2018 में 44 और 2014 में 54 से बढ़कर 2023 में 38 हो गई है।

चार्ट XII.10: सड़क परिवहन में निवेश के लिए कुल पूंजी परिव्यय

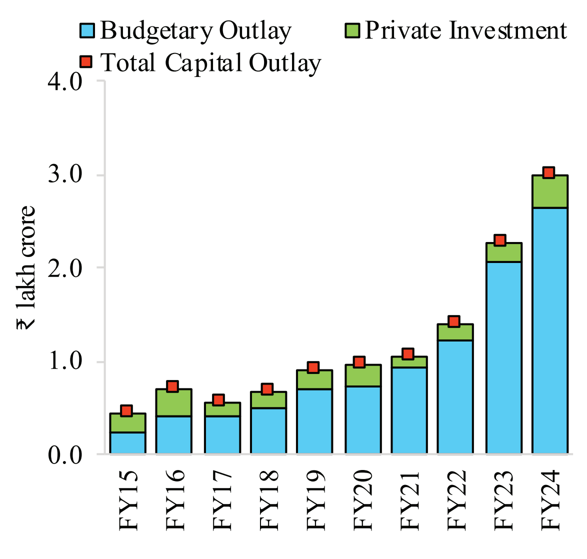

चार्ट XII.11: NH नेटवर्क - लेन ऑग्मेंटेशन (मान किलोमीटर में)

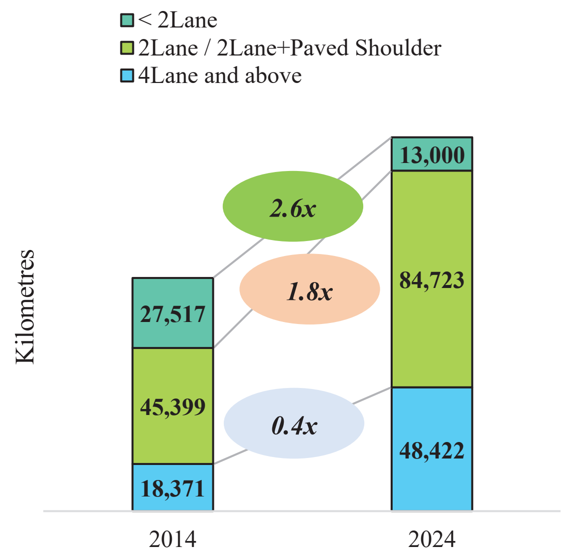

स्रोत केन्द्रीय बजट दस्तावेज, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त जानकारी

12.15. लॉजिस्टिक दक्षता को और बढ़ाने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) समर्पित किए हैं। वित्त वर्ष 2024 तक कुल छह मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) प्रदान किए गए हैं, और वित्त वर्ष 2024 में समर्पित मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) के लिए ₹2,505 करोड़ प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025 में सात एमएमएलपी प्रदान करने की योजना है।

बॉक्स XII.2: सड़क संपर्क बढ़ाने वाली प्रमुख पहल

- टोल डिजिटलीकरण ने 2014-24[7] के दौरान टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 734 सेकंड से लगभग 16 गुना घटाकर 47 सेकंड कर दिया है। स्वचालित नंबर प्लेट मान्यता/वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली के माध्यम से फ्री फ्लो टोलिंग भी शुरू की गई है।
- विश्व स्तरीय सुविधाएं और सुख-सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगभग 900 मार्गस्थ सुविधाएं (डब्ल्यूएसए) स्थापित करने की योजना है। 322 डब्ल्यूएसए पहले ही अवार्ड किए जा चुके हैं जिनमें से 50 कार्य कर रहे हैं। अकेले वित्त वर्ष 2024 में, 162 डब्ल्यूएसए को आवंटित किए गये हैं।
- संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के प्रत्येक किमी के लिए संविदात्मक अनुरक्षण एजेंसी नियुक्त करके राष्ट्रीय राजमार्ग अनुरक्षण के लिए एक सक्रिय नीति अपनाई गई है। संविदात्मक रखरखाव या तो प्रदर्शन-आधारित रखरखाव अनुबंधों या अल्पकालिक रखरखाव अनुबंधों के माध्यम से किया जाता है। इन दो अनुरक्षण अनुबंधों के अंतर्गत लगभग 37,500 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क शुरू किया गया है। लगभग 20 वर्षों के विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर टोल ऑपरेट ट्रांसफर और अवसंरचना निवेश ट्रस्ट मोड के माध्यम से दीर्घकालिक रखरखाव अनुबंध भी किए गए हैं।
- टिकाऊ कच्चे माल और नए युग की निर्माण तकनीकों को राजमार्ग विकास में शामिल किया गया है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के शहरी विस्तार रोड-II और स्पर में लैंडफिल स्थलों से प्राप्त 13.79 लाख टन निष्क्रिय सामग्री का उपयोग किया गया है। बिटुमेन और डामर का पुनर्चक्रण राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्राउनफील्ड उन्नयन के दौरान किया जाता है।
- उच्च तकनीक मशीनरी और क्लाउड-आधारित डेटा-संचालित निर्माण के परिणामस्वरूप समय और लागत में कमी आई है।
- अंतिम मील तक धार्मिक और पर्यटक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए "पर्वतमाला परियोजना" के तहत, छह रोपवे परियोजनाओं को आवंटित किया गया है। अन्य दो परियोजनाओं के लिए निविदाएं प्राप्त हुई हैं।

12.16. दृष्टिकोण: एक्सप्रेसवे और गलियारों के विकास के साथ-साथ उपयोगकर्ता सुविधा और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तनकारी पहलों को अपनाना, हाल ही में सड़क क्षेत्र की विकास यात्रा का मुख्य आकर्षण रहा है। तथापि, विकसित राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ निरंतर रिबन विकास एक नई समानांतर सड़क/बाइपास के निर्माण के लिए एक चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। अब, सरकार ने पहुंच-नियंत्रित एनएच के विकास पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। सरकार सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को पेव्ड शोल्डर मानकों के साथ न्यूनतम दो लेन बनाने का भी लक्ष्य बना रही है। एक अन्य चुनौती डिजिटल भूमि अभिलेखों की धीमी ऑनबोर्डिंग है, जिससे भूमि अधिग्रहण में देरी होती है। यह वन और अन्य पर्यावरणीय मंजूरियों के अनुमोदन में देरी से और प्रभावित होता है।

7 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पीआईबी, जून 2023 - https://tinyurl.com/yh6m7nrx

बॉक्स XII.3: सड़क विकास के लिए प्रमुख पहल

ग्रामीण सड़कों का विकास - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

- ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से न जुड़ी पात्र बसावटों को आवश्यक पुलियों और आर-पार जल निकासी संरचनाओं के साथ बारहमासी सड़क के माध्यम से जोड़ने के लिए दिसंबर 2000 में पीएमजीएसवाई-I शुरू की गई थी।
- PMGSY-II को 2013 में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50,000 किलोमीटर के चयनित थ्रू-रूट्स और प्रमुख ग्रामीण लिंक (MRLs) को अपग्रेड करने के लिए लॉन्च किया गया था।
- 2016 में, पीएमजीएसवाई के तहत एक अलग ऊर्ध्वाधर के रूप में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए एक सड़क संपर्क परियोजना शुरू की गई थी।
- PMGSY-III को 2019 में मार्गों और MRLs के माध्यम से 1,25,000 किलोमीटर के समेकन के लिये शुरू किया गया, जो अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से बस्तियों को जोड़ता है।
- पीएमजीएसवाई के तहत कुल 8,29,409 किलोमीटर लंबी सड़क को मंजूरी दी गई है, जिसमें से पीएमजीएसवाई के विभिन्न हस्तक्षेपों/वर्टिकल के तहत 18 जून 2024 तक 7,63,308 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 3.23 लाख करोड़ रुपये (राज्य के हिस्से सहित) के व्यय से पूरा किया जा चुका है।
- पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत लक्षित बसावटों में से 99.6 प्रतिशत को सड़क संपर्क मुहैया करा दिया गया है।

औद्योगिक गलियारों का विकास

- केंद्र सरकार चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 11 औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं का विकास कर रही है। इनमें दिल्ली-मुंबई, चेन्नई-बेंगलुरु, अमृतसर कोलकाता, पूर्वी तट और विजाग चेन्नई कॉरिडोर, बेंगलुरु-मुंबई, कोयंबटूर से होते हुए कोच्चि तक सीबीआईसी का विस्तार, हैदराबाद-नागपुर, हैदराबाद-वारंगल, हैदराबाद-बेंगलुरु, दिल्ली-नागपुर और ओडिशा आर्थिक कॉरिडोर को जोड़ने वाले औद्योगिक कॉरिडोर शामिल हैं।
- कार्यक्रम का उद्देश्य लचीले और टिकाऊ भविष्य के लिए तैयार शहरों के साथ प्लॉट स्तर तक पूर्ण "प्लग एंड प्ले" अवसंरचना के साथ मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
- चार शहरों में मार्च 2024 तक कुल 308 भूखंड (1,789 एकड़) आवंटित किए गए हैं।
- वर्तमान में, लगभग 2,104 एकड़ विकसित औद्योगिक भूमि और 2,250 एकड़ वाणिज्यिक/आवासीय/अन्य भूमि उपयोग आवंटन के लिए आसानी से उपलब्ध हैं।

रेल परिवहन

12.17. भारतीय रेलवे, 68,584 रूट किमी (31 मार्च 2024 तक) और 12.54 लाख कर्मचारियों (1 अप्रैल 2024 तक) के साथ, एकल प्रबंधन के तहत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। नई लाइनों के निर्माण, गेज रूपांतरण और दोहरीकरण में महत्वपूर्ण निवेश के साथ, पिछले पाँच वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय 77 प्रतिशत बढ़ गया है (वित्त वर्ष 2024 में 2.62 लाख करोड़ रुपये)।

चार्ट XII.12: रेलवे पर पूंजीगत व्यय

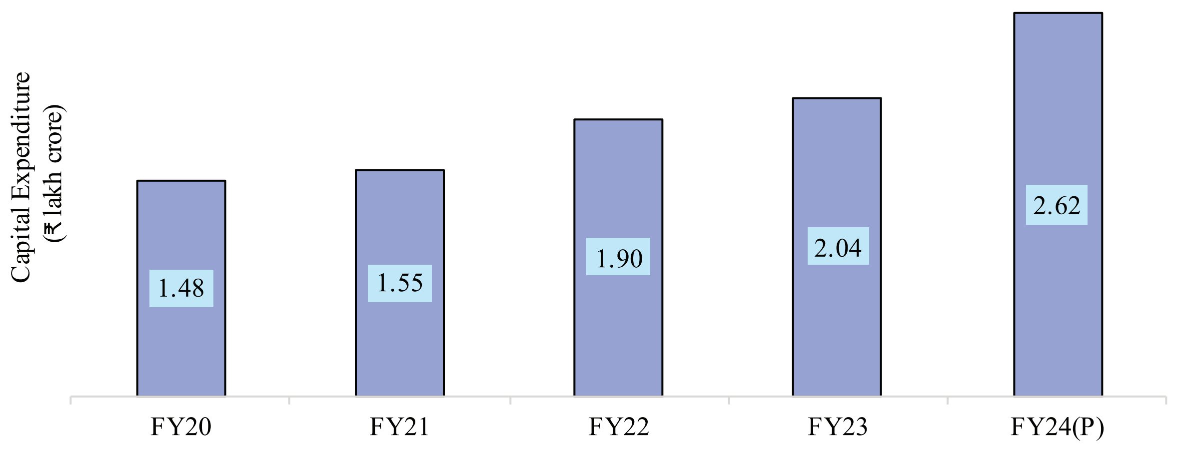

स्रोत: रेल मंत्रालय
नोट: P का पूर्ण रूप अनंतिम है

बॉक्स XII.4: रेलवे संवर्धन के लिए पहल

अमृत भारत स्टेशन योजना	मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी)
◆ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास के लिये अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया। ◆ सुविधाओं में सुधार, भवन सुधार, मल्टीमॉडल एकीकरण और स्थिरता में सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और इसके चरणबद्ध कार्यान्वयन को शामिल करना शामिल है। ◆ अब तक उन्नयन के लिए 1,324 स्टेशनों की पहचान की गई है।	◆ जापान सरकार के सहयोग से निष्पादित इस 508 किलोमीटर परियोजना के तहत, भूमि अधिग्रहण और नागरिक आचरण आवंटन पूरा कर लिया गया है। ◆ 41.7 प्रतिशत की समग्र भौतिक प्रगति हासिल की जा चुकी है और 31 मार्च 2024 तक 59,291 करोड़ रुपये का वित्तीय व्यय किया गया है।	◆ दो समपत मालभाड़ा गलियारे 1,337 किलोमीटर लंबे मार्ग वाले पूर्वी डीएफसी और 1,506 किलोमीटर लंबे पश्चिमी डीएफसी का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ◆ वित्त वर्ष 24 के अंत तक, कुल डीएफसी मार्ग लंबाई का 96.1 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

12.18. रेलवे ने वित्त वर्ष 2024 में लोकोमोटिव और वैगन दोनों के लिए अपना अब तक का सबसे अधिक उत्पादन हासिल किया। मार्च 2024 तक वंदे भारत के 51 जोड़े पेश किए गए हैं। अवसंरचना संवर्धन की तीव्र गति वित्तीय आवंटन में पर्याप्त वृद्धि के साथ-साथ परियोजना की गहन निगरानी और शीघ्र भूमि अधिग्रहण तथा स्वीकृतियों के लिए स्टेकहोल्डरों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई का परिणाम है।

चार्ट XII.13: कोच, लोकोमोटिव और वैगनों का वर्षवार उत्पादन	चार्ट XII.14: वंदे भारत ट्रेनें और कोचों का उत्पादन (2018-19 से 2023-24)
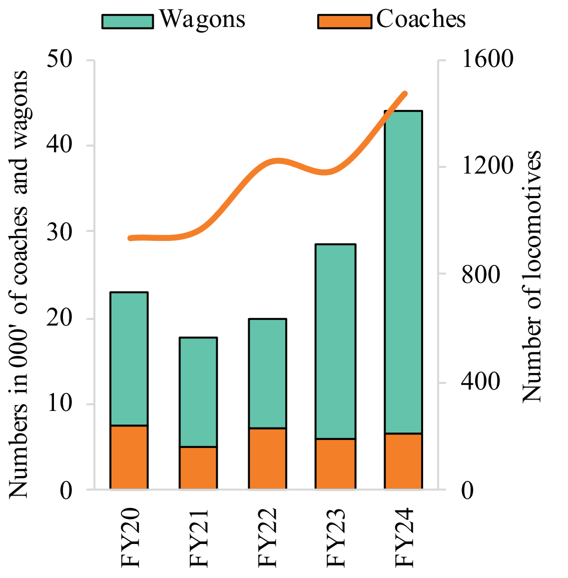	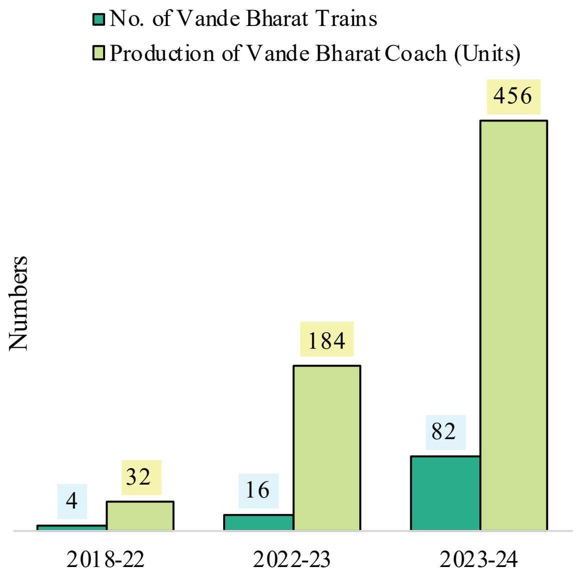

स्रोत: रेल मंत्रालय

12.19 तीव्र गति, लम्बी दूरी के वंदे स्लीपर ट्रेनसेट कोचों का विकास किया जा रहा है, जिनमें त्वरित त्वरण, विसरित प्रकाश, स्वचालित दरवाजे और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित यात्री सूचना प्रणाली जैसी विशेषताएं होंगी। रेलवे वंदे मेट्रो ट्रेन सेट कोच शुरू करने की भी योजना बना रहा है, जिसमें सीलबंद चौड़े गैंगवे, केंद्रीय नियंत्रित स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे, सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी, रूट मैप इंडिकेटर, यात्री सूचना और मनोरंजन प्रणाली, अग्नि पहचान प्रणाली और एरोसोल आधारित अग्नि शमन प्रणाली जैसी सुविधाएं होंगी। पहला लॉट वित्त वर्ष 2025 में तैयार होने की उम्मीद है।

12.20 रेलवे ने रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों के आसपास स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कई पहल की हैं, जैसे कोचों में पारंपरिक शौचालयों के स्थान पर जैव-शौचालय लगाना, जिससे पटरियां स्वच्छ बनी रहें, बायोडिग्रेडेबल और नॉन-बायोडिग्रेडेबल (जैव-निम्नीकरणीय/गैर-जैव-निम्नीकरणीय) अपशिष्टों को अलग करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करना।

बॉक्स XII.5: रेलवे क्षेत्र में प्रमुख पहल

- उद्योग की मांग और कार्गो यातायात की क्षमता के आधार पर रेलवे और गैर-रेलवे भूमि पर निजी खिलाड़ियों द्वारा गतिशक्ति मल्टी-मोडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) विकसित किया जा रहा है। 77 जीसीटी चालू किए गए हैं और 31 मार्च 2024 तक गैर-रेलवे भूमि पर 186 स्थानों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन जारी किया गया है।
- पार्सल स्पेस की ऑनलाइन बुकिंग के लिए 'वर्चुअल एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म' लॉन्च किया गया, जिससे विभिन्न कार्गो ट्रांसपोर्टरों को मांग की लाइव दृश्यता प्राप्त करने की अनुमति मिली।
- रेलवे स्टेशन परिसरों में 50 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र स्थापित करने के लिए एक नीतिगत ढांचा लागू किया।

- मैकेनिकल सिग्नलिंग को इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ रखा जा रहा है। अब तक आठ जोन मैकेनिकल सिग्नलिंग से मुक्त हो चुके हैं।
  - वित्त वर्ष 2024 के दौरान 443 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) सिस्टम प्रदान किए गए हैं। 31 मार्च 2024 तक, 3,424 स्टेशनों पर EI प्रदान किया गया है
  - दक्षिण मध्य रेलवे पर 1,465 रूट किलोमीटर (आरकेएम) पर स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली के रूप में कवच को तैनात किया गया है।
  - स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग (एबीएस), वित्त वर्ष 2024 के दौरान 582 मार्ग किमी पर एक सिद्ध कम लागत वाला सिग्नलिंग समाधान प्रदान किया गया है। 31 मार्च 2024 तक, उच्च घनत्व वाले नेटवर्क मार्गों पर 4,431 आरकेएम पर एबीएस चालू किया गया है।
- मिशन 100 प्रतिशत विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत, आईआर के विद्युतीकृत नेटवर्क को 63,456 किलोमीटर (96.4 प्रतिशत) तक बढ़ा दिया गया है। पिछले पांच वर्षों (2019-24) में विद्युतीकरण प्रति वर्ष लगभग 5,594 आरकेएम की गति से आगे बढ़ा है।

चार्ट XII.15: रेलवे विद्युतीकरण की गति

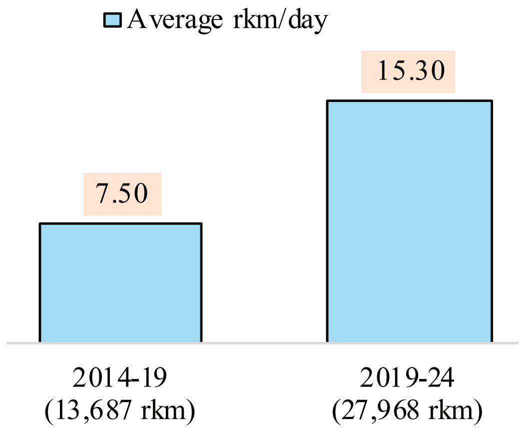

चार्ट XII.16: चालू ट्रैक लंबाई (नई लाइन, मल्टी-ट्रैकिंग और गेज रूपांतरण)

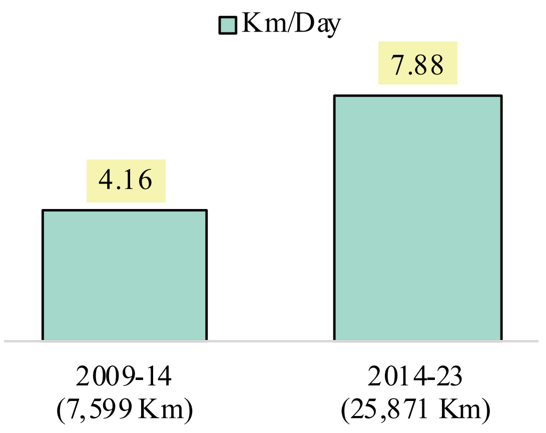

स्रोत: रेल मंत्रालय

12.21. दृष्टिकोण: रेलवे के लिए जिन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा उनमें तेजी से क्षमता बढ़ाना, चल स्टॉक का आधुनिकीकरण और रखरखाव, सेवाओं की गुणवत्ता और ऊर्जा दक्षता में सुधार करना शामिल है। इसके अनुरूप, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, हाई-स्पीड रेल, वंदे भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस, आस्था स्पेशल ट्रेन, उच्च क्षमता वाले रोलिंग स्टॉक और लास्ट-माइल रेल लिंकेज जैसी आधुनिक यात्री सेवाओं जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जाती है। तीन प्रमुख गलियारों अर्थात (1) उच्च यातायात घनत्व गलियारों, (2) ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारों और (3) रेल सागर (बंदरगाह कनेक्टिविटी) गलियारों के लिए परियोजनाओं की भी योजना बनाई गई है ताकि रसद लागत और कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके। 2029-30 तक नवीकरणीय क्षमता की स्थापना की अपेक्षित आवश्यकता लगभग 30 गीगावाट है। अन्य रणनीतियों में डीजल से विद्युत कर्षण में स्थानांतरण, ऊर्जा दक्षता और वनीकरण को बढ़ावा देना शामिल है। सामान्य व्यवसाय के अनुसार 2029-30 तक कार्बन उत्सर्जन 60

मिलियन टन[8] होने का अनुमान है। मार्च 2024 तक, ~231 मेगा वाट (एमडब्ल्यू) सौर संयंत्र (छतों और भूमि दोनों पर) और लगभग 103 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किए गए हैं। इसके अलावा, लगभग 5,750 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता के साथ भी करार किया गया है।

जल परिवहन

12.22. बढ़ते व्यापार को पूरा करने के लिए भारतीय बंदरगाह तेजी से क्षमता का विस्तार कर रहे हैं। 2014 के बाद से प्रमुख बंदरगाह क्षमता लगभग दोगुनी हो गई है। पीएम गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत समन्वित योजना के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने से विश्व स्तर पर भारत की समुद्री प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की रैंक 2014 में 44वें से बढ़कर 2023 में 22वें स्थान पर पहुंच गई है। इसके अलावा, नीतिगत सुधारों और नई प्रौद्योगिकी को शामिल करने से बंदरगाह दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। जैसा कि बाहरी क्षेत्र पर अध्याय 4 में उल्लेख किया गया है, कंटेनर टर्नअराउंड समय 2014 और 2023-24 के बीच 50 प्रतिशत कम हो गया है। बंदरगाहों, पोत परिवहन और जलमार्ग क्षेत्र के लिए केंद्रीय पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 के बीच 27 प्रतिशत बढ़ गया है.

चार्ट XII.17: बंदरगाहों, पोत परिवहन और जलमार्गों के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय

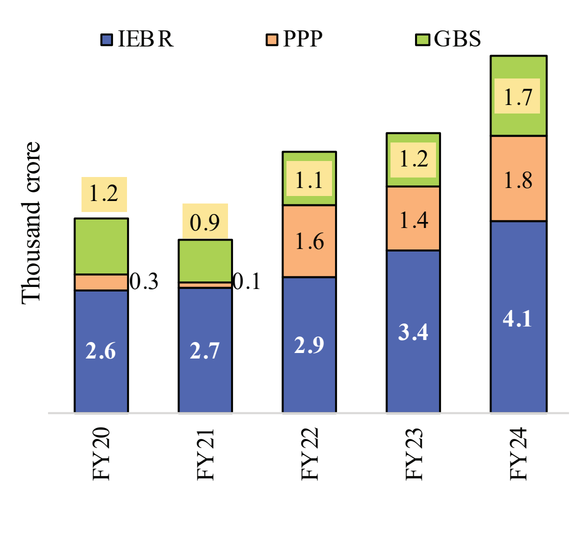

चार्ट XII.18: प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता

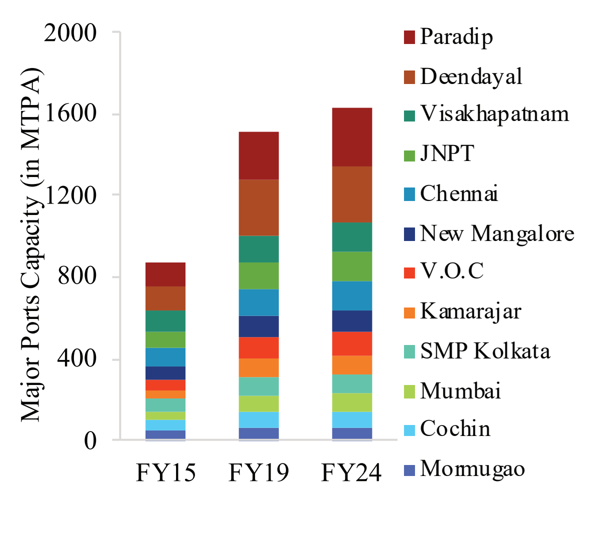

स्रोत: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय; अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार बर्थिंग नीति के आधार पर पोर्ट क्षमता का पुनर्मूल्यांकन किया गया था।

12.23. 2015 में शुरू किए गए सागरमाला राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत, 5.8 लाख करोड़ रुपये की कुल 839 परियोजनाएं बंदरगाह आधुनिकीकरण और नवीन विकास, कनेक्टिविटी वृद्धि, बंदरगाह के नेतृत्व वाले औद्योगिकीकरण, तटीय समुदाय विकास और तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जल परिवहन के पांच प्रमुख क्षेत्रों में शुरू की गई हैं। इस कार्यक्रम के तहत, 1.4 लाख करोड़ रुपये की 262 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 1.65 लाख करोड़ रुपये की 217 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं और 2.7 लाख करोड़ रुपये की 360 परियोजनाएं विकास के अधीन हैं।

8 पीआईबी दिनांक 07 अक्टूबर 2022, रेल मंत्रालय - https://tinyurl.com/89u3brm4

चार्ट XII.19: सागरमाला के तहत प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर परियोजना लागत का हिस्सा	चार्ट XII.20: सागरमाला के तहत प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित परियोजनाओं का हिस्सा
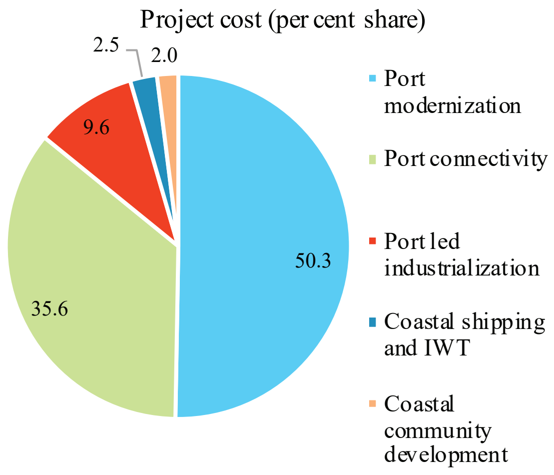	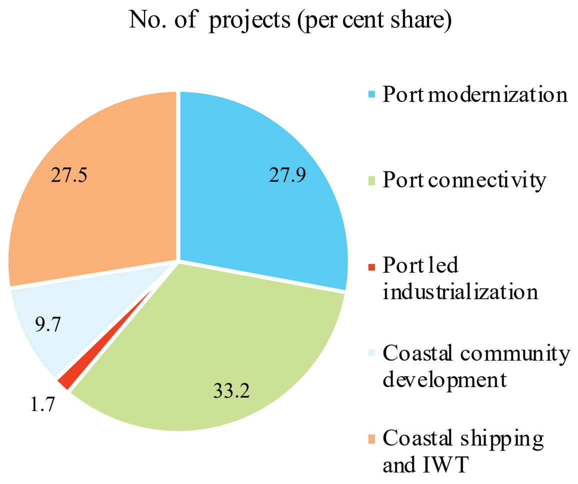

स्रोत: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

बॉक्स XII.6: बंदरगाहों में प्रमुख पहल

- विकेंद्रीकृत निर्णय लेने, व्यावसायिकता और PPP मॉडल पर ध्यान देने के साथ प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 ने प्रमुख बंदरगाहों की दक्षता और बेहतर शासन को बढ़ाया है।
- 'हरित सागर'- ग्रीन पोर्ट दिशानिर्देश मई 2023 में लॉन्च किए गए थे - जिसके तहत चार प्रमुख बंदरगाह पहले से ही अपनी मांग से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा पैदा कर रहे हैं।
- 'सागर आंकलन', सभी भारतीय बंदरगाहों पर लागू भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन का एक राष्ट्रीय बेंचमार्किंग फरवरी 2024 में जारी किया गया था।
- लोथल में बनाया जा रहा एक विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर समुद्री कलाकृतियों और भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का एक विशाल संग्रह प्रदर्शित करेगा।
- आईआईटीएम, चेन्नई में बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र के डिस्कवरी परिसर का उद्घाटन किया गया।
- महाराष्ट्र के वधावन में एक सभी मौसम के अनुकूल ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह के विकास को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। भूमि अधिग्रहण घटक सहित कुल परियोजना लागत ₹76,220 करोड़ है। इस परियोजना का निर्माण जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गठित एक एसपीवी वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसमें पीपीपी मोड में कोर अवसंरचना, टर्मिनल और अन्य वाणिज्यिक अवसंरचना शामिल होंगे। परियोजना[9] प्रति वर्ष 298 मिलियन मीट्रिक टन की संचयी क्षमता का निर्माण करेगी।

9 कैबिनेट पीआईबी दिनांक 19 जून 2024 - https://tinyurl.com/2ydtzb4k

12.24 **द्वीप विकासः** अमृत काल विजन 2047 में, द्वीप विकास आने वाले वर्षों के लिए एक प्रमुख फोकस होगा। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह को पर्यटन और अन्य पहलों के लिए चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना है। अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक बंदरगाह अवसंरचना का विकास करेगा और संचालन के लिए स्थानीय बंदरगाह विभागों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार और गुजरात में शॉर्टलिस्ट किए गए द्वीपों को अगले दशक में इको-टूरिज्म, जहाज मरम्मत, सीप्लेन निर्माण और मरम्मत, समुद्री प्रशिक्षण संस्थान, मुक्त व्यापार क्षेत्र और बंकरिंग टर्मिनलों के विषयों के आसपास विकसित करने का प्रस्ताव है। इस तरह के विकास को देश[10] के अन्य द्व ीपों तक बढ़ाया जा सकता है।

12.25 **जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रणः** 1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2026 के बीच हस्ताक्षरित जहाज निर्माण अनुबंधों के लिए भारतीय शिपयार्ड को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति योजना शुरू की गई थी। कुल 39 शिपयार्ड पंजीकृत हैं, और 18 शिपयार्ड ने लाभ का उपयोग किया है। मई 2023 में, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत निर्मित पाँच गहरे समुद्र में टूना लॉन्ग लाइनर कम गिल नेटर मछली पकड़ने वाले जहाजों को हरी झंडी दिखाई। जनवरी 2024 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में एक अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। नया ड्राई डॉक में भविष्य के विमान वाहक सहित बड़े जहाजों के निर्माण और मरम्मत की जा सकती है।

12.26 जहाजों के पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 और इसके तहत नियमों का उद्देश्य जहाज पुनर्चक्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करना और हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सही प्रथाओं को सुनिश्चित करना है। अधिनियम के तहत, सरकार ने शिपिंग महानिदेशालय को जहाजों के पुनर्चक्रण के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया है, जिसमें जहाज पुनर्चक्रण से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रशासन, पर्यवेक्षण और निगरानी करने का अधिकार है।

12.27 **दृष्टिकोणः** भारत का समुद्री विजन 2030 बंदरगाहों, शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों में सुधार के लिए 150 से अधिक पहलों की रूपरेखा तैयार करता है और 3-3.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की कल्पना करता है। मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 में भारत के तटीय क्षेत्रों में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए 11 प्रमुख क्षेत्रों में 300 से अधिक पहलों की रूपरेखा दी गई है। इसकी दृष्टि का उद्देश्य 2020 में 25 घंटे से 2030 में 20 घंटे से कम समय तक औसत पोत टर्नअराउंड समय (कंटेनर) को कम करना है। इसी तरह, इसका उद्देश्य 2020 में 16,000 से 2030 में 30,000 से अधिक जहाज दैनिक उत्पादन (सकल टन भार) को बढ़ाना है।

तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जल परिवहन

12.28 तटीय शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के फोकस के साथ, इस मोड के माध्यम से सकल टन भार 1 अप्रैल, 2014 को 846 जहाजों के साथ 1.19 मिलियन जीटी से बढ़कर 1 अप्रैल, 2024 तक 1039 जहाजों के साथ 1.72 मिलियन जीटी हो गया है।

10 पत्तन, पोत परिवहन मंत्रालय पीआईबी दिनांक 24 नवंबर 2023 - https://tinyurl.com/ytfb3jy9

चार्ट XII.21: तटीय शिपिंग और आई डब्ल्यू टी

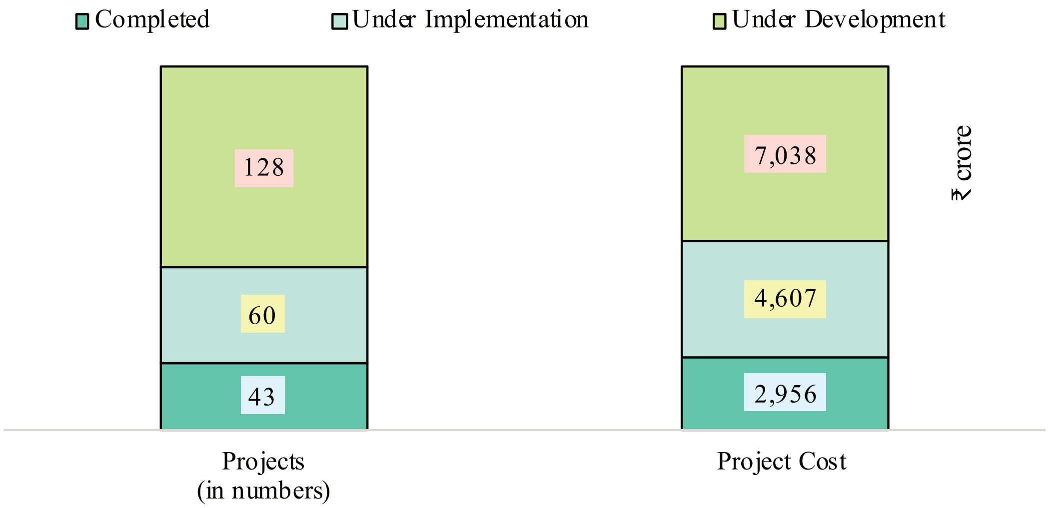

स्रोत: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

12.29 भारत में नदियों, नहरों और अन्य जलमार्गों की एक बड़ी बंदोबस्ती है, जिनकी कुल नौगम्य लंबाई लगभग 14,500 किमी[11] है। अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 की अधिसूचना का उद्देश्य 1917 के 100 साल से अधिक पुराने अंतर्देशीय पोत अधिनियम को बदलना था, जिससे विधायी ढाँचा उपयोगकर्त्ता के अनुकूल हो गया।

12.30 वित्त वर्ष 2024 के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा पूंजीगत व्यय ₹1010.5 करोड़ था। 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए व्यवहार्यता और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने के आधार पर सुरक्षित नौचालन और तकनीकी रूप से व्यवहार्य जलमार्गों पर पोत परिवहन के लिए तकनीकी हस्तक्षेप की योजना बनाई गई है। एनडब्ल्यू-1 पर जल मार्ग विकास परियोजना का 63 प्रतिशत से अधिक मार्च 2024 तक पूरा हो चुका है। एनडब्ल्यू-3, एनडब्ल्यू-4, एनडब्ल्यू -5 और 13 नए एनडब्ल्यूएस के विकास चरण-I को 2025-2026 के लिए ₹267 करोड़ की लागत से अनुमोदित किया गया था।

12.31 भारत और बांग्लादेश द्वारा सयुंक्त रूप से 305.84 करोड रुपए, की अनुमानित लागत से विकसित इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग गुवाहाटी से सभी पूर्वोत्तर राज्यों और जोगीधोपा से कोलकाता तथा हलदिया पोर्ट के लि, वैकल्पिक संपर्कता उपलब्ध कराता है। पिछले 9 वर्षों में की गई पहड़ों की वजह से आईबीपी रूट के जरिए, संभाले जाने वाले कार्गो में काफी वृद्धि हुई है।

नागर विमानन

12.32. भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक है। सरकार की वित्त वर्ष 2020 से 2025 के दौरान 26,000 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत व्यय की योजना है ताकि अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए हवाई अड्डों का विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण किया जा सके। नियोजित व्यय में से, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 24 के दौरान लगभग ₹23,000 करोड़ हासिल किए हैं। पीपीपी और अन्य हवाई अड्डा ऑपरेटरों ने इसी अवधि के दौरान लगभग 49,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है, जिससे पिछले 5 वर्षों के दौरान हवाई अड्डा क्षेत्र में लगभग 72,000 करोड़ रुपये का कुल पूंजीगत व्यय हुआ है।

11 राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की रिपोर्ट 1980 के अध्याय 15 के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग लगभग 14,500 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जिनमें विभिन्न नदी प्रणालियाँ, नहरें, बैकवाटर, खाड़ियाँ और ज्वारीय इनलेट शामिल हैं। इनमें देशी नावों द्वारा नौगम्य सभी जलमार्ग शामिल हैं। स्रोत: भारत सरकार, शिपिंग और परिवहन मंत्रालय, राष्ट्रीय जलमार्ग समिति की रिपोर्ट, 1974, पृष्ठ 58९

12.33. 21 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था, जिनमें से 12 हवाईअड्डों को प्रचालनिक कर दिया गया है। वित्त वर्ष 24 के दौरान, 21 हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवनों का संचालन किया गया है, जिससे इन हवाई अड्डों की यात्री हैंडलिंग क्षमता में प्रति वर्ष लगभग 62 मिलियन यात्रियों की समग्र वृद्धि हुई है। पिछले सात वर्षों के दौरान, उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के शुरू होने के बाद, विभिन्न एयरलाइनों को 1,390 वैध अवार्ड किए गए मार्ग आवंटित किए गए हैं। इनमें से 85 असेवित तथा कम सेवित हवाईअड्डों को जोड़ने वाले 579 आरसीएस मार्गों को प्रचालनात्मक कर दिया गया है।

बॉक्स XII.7: नए खंड – ड्रोन, लीजिंग और एमआरओ

- ड्रोन कृषि, स्वास्थ्य सेवा, आपदा राहत, निगरानी और रक्षा जैसे क्षेत्रों में व्यापक लाभ प्रदान करते हैं। सरकार ने 2021 में उदारीकृत ड्रोन नियम पेश किए। अन्य उपायों में ड्रोन हवाई क्षेत्र के नक्शे प्रकाशित करना, पीएलआई योजना को लागू करना और ड्रोन प्रमाणन योजना शुरू करना शामिल है। प्रमुख प्रगति में 109 प्रशिक्षण संगठनों की स्थापना और 10,603 रिमोट पायलट प्रमाण पत्र, पंजीकृत ड्रोन के लिए 22,943 विशिष्ट पहचान संख्या और ड्रोन मॉडल के लिए डीजीसीए-अनुमोदित 67 टाइप-सर्टिफिकेट जारी करना शामिल है।
- सरकार गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) के जरिए एयरक्राफ्ट लीजिंग को बढ़ावा दे रही है। 28 से अधिक विमान पट्टेदार पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं, जिन्होंने एक साथ 20 से अधिक विमानों और 49 विमान इंजनों को पट्टे पर लिया है। हाल ही में, एअर इंडिया ने आईएफएससी जोन से अपने बड़े आकार के विमानों को पट्टे पर लेना शुरू किया है तथा अन्य एयरलाइनें भी आईएफएससी में पट्टे पर कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं।
- भारत में एमआरओ उद्योग की क्षमता को महसूस करते हुए, सरकार ने भारत के एमआरओ क्षेत्र को वैश्विक साथियों के बराबर लाने के लिए कई नीतियां और नियम पेश किए हैं। भारत में एमआरओ ने एयरफ्रेम जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है और उद्योग वैश्विक ओईएम के सहयोग से इंजन जैसे अन्य एमआरओ सेगमेंट में शाखा लगा रहा है। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (एनसीएपी- 2016) की घोषणा के बाद, भारत में एमआरओ की संख्या 2016 में 114 से बढ़कर 147 हो गई है। नए एमआरओ की स्थापना से इस क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हुई है। अधिक हवाईअड्डे क्षमता बढ़ाने के लिए एमआरओ सुविधाओं का निर्माण कर रहे हैं जिससे अवसंरचना संबंधी बाधाओं का समाधान हो रहा है।

दृष्टिकोण: भारत में हवाई अड्डों की संख्या 2014 से दोगुनी से भी अधिक हो गई है। हालांकि, अगले पांच वर्षों में अधिक हवाई अड्डों को जोड़ने के साथ-साथ मौजूदा हवाई अड्डों के विस्तार/उन्नयन के जरिए इस क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। भारतीय विमानन बाजार में पिछले दशक में प्रभावशाली वृद्धि के बावजूद, अभी भी काफी हद तक अप्रयुक्त क्षमता है। प्रति व्यक्ति[12] लगभग 0.13 हवाई यात्राओं के साथ, वर्तमान यात्री हवाई यातायात भारत की क्षमता का एक अंश है। एमआरओ और कौशल विकास इस क्षेत्र के विकास को और बढ़ावा देंगे। अंतर्राष्ट्रीय विमानन हब रणनीति और वैश्विक निकायों के साथ जुड़ाव जैसी पहल वैश्विक विमानन परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने के भारत के इरादे का संकेत देती हैं। भारत को विमानन में नेतृत्व की स्थिति लेने के लिए, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए एयरलाइनों की दक्षता और व्यवहार्यता में सुधार लाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लंबी अवधि के लिए भारतीय अंतरर्राष्ट्रीय यातायात का एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में कनेक्टिविटी केंद्रों के माध्यम से जाता है। भारतीय एयरलाइनों को मजबूत करके भारत से पर्याप्त लंबी दूरी की कनेक्टिविटी प्रदान करने की भी आवश्यकता है।

12 नागरिक उड्डयन मंत्रालय

ऊर्जा अवसंरचना

विद्युत क्षेत्र

12.34. भारत में बिजली पारेषण 1,18,740 मेगावाट स्थानांतरित करने की अंतर-क्षेत्रीय क्षमता के साथ एक आवृत्ति पर चलने वाले एक ग्रिड से जुड़ा हुआ है। यह दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत बिजली ग्रिडों में से एक के रूप में उभर रहा है। 31 मार्च 2024 तक, ट्रांसमिशन सिस्टम का विस्तार 4,85,544 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों और 12,51,080 मेगा वोल्ट एम्पियर (एमवीए) ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता तक हो गया है।

12.35. वित्त वर्ष 24 में पीक बिजली की मांग 13 प्रतिशत बढ़कर 243 गीगावॉट हो गई। भारत सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ाने और देश में ऊर्जा की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 के बीच, उपयोगिताओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में बिजली उत्पादन में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई थी।

बॉक्स XII.8: पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

आरडीएसएस को 2021 में लॉन्च किया गया था ताकि वितरण कंपनियों को पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति अवसंरचना को मजबूत करने के लिए परिणाम-लिंक्ड वित्तीय सहायता प्रदान करके परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद मिल सके।

- आरडीएसएस का वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2026[13] तक लगभग ₹3.04 लाख करोड़ का परिव्यय है, जिसमें लगभग ₹0.98 लाख करोड़ का अनुमानित सरकारी बजटीय समर्थन शामिल है।
- आरडीएसएस का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025 तक कुल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को 12-15 प्रतिशत तक कम करना, आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व प्राप्त अंतर को वित्त वर्ष 2025[14] तक शून्य तक कम करना और वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है।
- आरडीएसएस के तहत 19.79 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर, 52 लाख वितरण ट्रांसफार्मर मीटर और 1.88 लाख फीडर मीटर स्वीकृत किए गए हैं।

12.36 विभिन्न योजनाओं के तहत अक्टूबर 2017 में सौभाग्य काल की शुरुआत के बाद से कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। इसके अलावा, बिजली (देर से भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 के कार्यान्वयन ने डिस्कॉम के साथ-साथ बिजली उपभोक्ताओं और उत्पादन कंपनियों को भी राहत दी है। कार्यान्वयन के बाद से, 02 अप्रैल 2024 तक, मई 2022 से ₹8.7 लाख करोड़ की कुल बिल राशि के सापेक्ष ₹8.1 लाख करोड़ की कुल बिल राशि का निपटान किया गया है (विरासत बकाया राशि के खिलाफ ईएमआई भुगतान को छोड़कर और विवादित चालान सहित)।

13 पीआईबी दिनांक 11 अगस्त 2023, विद्युत मंत्रालय - https://tinyurl.com/yc6e8wev
14 पीआईबी दिनांक 11 अगस्त 2023, विद्युत मंत्रालय - https://tinyurl.com/yc6e8wev

बॉक्स XII.9: विद्युत क्षेत्र में कुछ प्रमुख पहल	
समर्थ मिशन	**वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड इनिशिएटिव**
◆ 2021 में शुरू किया गया, थर्मल पावर प्लांट में कृषि-अवशेष के उपयोग पर सतत कृषि मिशन (समर्थ) में कार्यान्वयन के समन्वय और निगरानी के लिए एक पूर्णकालिक मिशन निदेशालय है। ◆ एनसीआर थर्मल पावर प्लांटों में बायोमास को-फायरिंग 1.68 प्रतिशत तक पहुंच गई है; इसे 5 प्रतिशत तक ले जाने के प्रयास चल रहे हैं।	◆ एक कार्यबल अक्षय ऊर्जा के आदान-प्रदान के लिए क्षेत्रीय ग्रिडों अर्थात दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप के इंटरकनेक्शन की व्यवहार्यता का अध्ययन कर रहा है। ◆ वर्तमान में, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर आदि के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।
उजाला योजना	**स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम**
◆ 2015 में लॉन्च किए गए सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला), पारंपरिक और अक्षम वेरिएंट को बदलने के लिए एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूब लाइट और ऊर्जा-कुशल पंखे बेचे जाते हैं। ◆ विद्युत मंत्रालय के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 48.42 बिलियन kWh की अनुमानित ऊर्जा बचत हुई है, जिसमें 9,789 मेगावाट की पीक डिमांड और प्रति वर्ष 39.30 मिलियन टन CO_2 की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और उपभोक्ता बिजली बिलों में ₹19,335 करोड़ की वार्षिक मौद्रिक बचत हुई है।	◆ यह कार्यक्रम 2015 में पारंपरिक स्ट्रीटलाइट्स को स्मार्ट और ऊर्जा-कुशल एलईडी स्ट्रीटलाइट्स से बदलने के लिए शुरू किया गया था। अब तक 1.31 करोड़ से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी हैं। ◆ विद्युत मंत्रालय के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप 1,467 मेगावाट की पीक डिमांड और प्रति वर्ष 6.06 मिलियन टन CO_2 की GHG उत्सर्जन में कमी और नगरपालिकाओं के बिजली बिलों में 6,162 करोड़ रुपये की अनुमानित वार्षिक मौद्रिक बचत के साथ प्रति वर्ष 8.80 बिलियन kWh की अनुमानित ऊर्जा बचत होने का अनुमान है।

नवीकरणीय क्षेत्र

12.37. भारत ने 26 अगस्त 2022 को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में अपने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत किए और 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगा वाट (जीडब्ल्यू) स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। 31 मार्च 2024 तक देश में कुल 190.57 गीगा वाट अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षमता स्थापित की जा चुकी है। देश में कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता में अक्षय ऊर्जा का हिस्सा 43.12 प्रतिशत है।

चार्ट XII.22: नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश

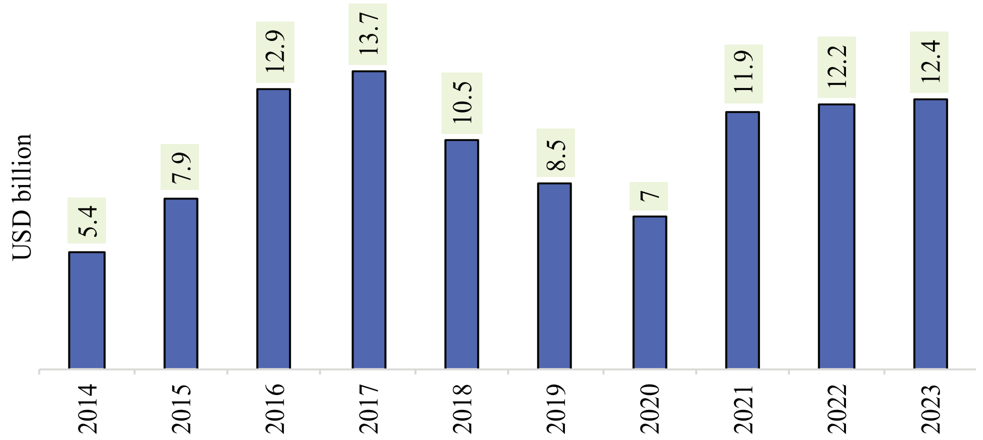

स्रोत: आरईएन21 नवीकरणीय 2024 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट

12.38. भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र ने 2014 और 2023[15] के बीच ₹8.5 लाख करोड़ (102.4 बिलियन अमरीकी डॉलर) का नया निवेश देखा। आरई क्षेत्र से 2024 और 2030[16] के बीच भारत में लगभग 30.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। यह मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर पैदा करेगा। आरई क्षेत्र को अप्रैल 2000 से मार्च 2024[17] तक एफडीआई के रूप में लगभग 17.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए।

बॉक्स XII.10: नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख कार्यक्रम, परियोजनाएं और पहल

- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम): 31 मार्च 2024 तक, 166 मेगावाट विकेन्द्रीकृत सौर क्षमता स्थापित की गई है और योजना के तहत 3.26 लाख कृषि पंपों को सौर ऊर्जा दी गई है।

- उच्च दक्षता सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना: ₹24,000 करोड़ के परिव्यय के साथ उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल में गीगा वाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करना। 31 मार्च 2024 तक, चार निर्माताओं ने सौर पीवी मॉड्यूल का निर्माण शुरू कर दिया है।

- सौर पार्क योजना: सभी वैधानिक मंजूरियों के साथ आवश्यक अवसंरचना की सुविधा प्रदान करके सौर ऊर्जा डेवलपर्स को प्लग एंड प्ले मॉडल प्रदान करना। इस योजना में 13 राज्यों में 56 सौर पार्कों के विकास के लिए 39.7 गीगावॉट की स्वीकृत क्षमता है। इन पार्कों में 11.59 गीगावॉट क्षमता की सौर परियोजनाएं चालू की गई हैं और शेष क्षमता कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

- प्रधानमंत्री-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना: 75,021 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य है और इसे वित्त वर्ष 2027 तक लागू किया जाएगा। इससे वित्त वर्ष 2027 तक लगभग 30 गीगावॉट आवासीय रूफटॉप सौर क्षमता और 40-45 गीगावॉट की समग्र रूफटॉप सौर क्षमता वृद्धि की स्थापना को सक्षम करने की उम्मीद है।

15 आरईएन21. नवीकरणीय ऊर्जा 2024 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट- ऊर्जा आपूर्ति में नवीकरणीय ऊर्जा
16 भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा निवेश अनुमान
17 एफडीआई प्रवाह फैक्टशीट, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार

- सीपीएसयू योजना चरण- II (सरकारी निर्माता योजना): इसका उद्देश्य पीएसयू और सरकारी संगठनों द्वारा ग्रिड से जुड़ी सौर PV विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करना है, जो घरेलू रूप से निर्मित सौर पीवी सेल और मॉड्यूल का उपयोग करते हैं, जिसमें सरकार या सरकारी संस्थाओं द्वारा स्व-उपयोग या उपयोग के लिए वीजीएफ समर्थन है। सौर पीवी बिजली संयंत्रों की 8.2 गीगावॉट क्षमता में से लगभग 1.66 गीगावॉट क्षमता चालू की जा चुकी है और शेष 31 मार्च 2024 तक कार्यान्वयन के अधीन है।

- पवन ऊर्जा: पवन ऊर्जा का नेतृत्व स्वदेशी पवन ऊर्जा उद्योग और मजबूत परियोजना पारिस्थितिकी तंत्र, संचालन क्षमताओं और प्रति वर्ष 18 गीगावॉट[18] के विनिर्माण आधार द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2024 तक, पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता पिछले 10 वर्षों के दौरान लगभग 2.1 गुना बढ़कर लगभग 45.89 गीगावाट हो गई है। आरईएन 21 रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया में पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पर है।[19]

- नई सौर ऊर्जा योजना (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए बस्तियां/गांव: ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के प्रावधान द्वारा 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक लाख गैर-विद्युतीकृत पीवीटीजी घरों के विद्युतीकरण के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 04 जनवरी 2024 को शुरू किया गया, जहां ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से संभव नहीं है।

- हरित ऊर्जा गलियारा (जीईसी) परियोजनाएँ: अक्षय ऊर्जा निकासी की सुविधा के लिए शुरू किया गया और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए ग्रिड को फिर से आकार दिया गया। जीईसी-I 9,111 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनों और 21,303 एमवीए सबस्टेशनों की संचयी उपलब्धि के साथ आठ राज्यों में कार्यान्वयनाधीन है। जीईसी-II सात राज्यों में कार्यान्वयनाधीन है।

- जैव ऊर्जा कार्यक्रम: नवंबर 2022 में अधिसूचित राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक दो चरणों में लागू किया जाएगा। 31 मार्च 2024 तक, बायोमास बिजली और सह-उत्पादन परियोजनाओं की स्थापित क्षमता लगभग 9.4 गीगावाट (ग्रिड से जुड़ी) और 0.92 गीगा वाट eq (ऑफ-ग्रिड) थी, अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं की क्षमता 249.74 मेगावाट (ग्रिड से जुड़ी) और 336.06 मेगावाट eq थी। (ऑफ ग्रिड) थी। बायोगैस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 51.04 लाख लघु बायोगैस संयंत्र और 349 मध्यम आकार के बायोगैस संयंत्र (10.6 मेगावाट eq) संस्थापित किए गए हैं।

- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: जनवरी 2023 में ₹19,744 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृत। मिशन का लक्ष्य लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता, लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, कुल निवेश में ₹8 लाख करोड़ और वर्ष 2030 तक 50 एमएमटी CO_2 वार्षिक उत्सर्जन को टालने की उम्मीद है।

18 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमान
19 आरईएन 21. 2024. नवीकरणीय ऊर्जा 2024 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट - ऊर्जा आपूर्ति में नवीकरणीय ऊर्जा

बॉक्स XII.11: नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख नीतियाँ

ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ढांचा (ईएसएस)

- ईएसएस का उपयोग आरई स्रोतों से उपलब्ध ऊर्जा के भंडारण के लिए किया जा सकता है जिसका उपयोग दिन के अन्य समय में किया जा सकता है।
- यह अक्षय ऊर्जा स्रोतों में उत्पादन की परिवर्तनशीलता को कम कर सकता है, ग्रिड स्थिरता में सुधार कर सकता है, ऊर्जा/पीक शिफ्टिंग को सक्षम कर सकता है, सहायक सहायता सेवाएं प्रदान कर सकता है और बड़े नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को सक्षम कर सकता है।
- पीक घाटे, पीक टैरिफ, कार्बन उत्सर्जन में कमी, ट्रांसमिशन और वितरण कैपेक्स के स्थगन और ऊर्जा मध्यस्थता को कम करके उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना।

पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश

- भंडारण और सहायक सेवाओं की उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रौद्योगिकियों में से पंप स्टोरेज परियोजनाएं स्वच्छ, मेगावाट स्केल, घरेलू रूप से उपलब्ध, समय की कसौटी पर खरी उतरी और अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य हैं।
- बिजली मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2023 में पीएसपी के विकास को बढ़ावा देने के लिये दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

चार्ट XII.23: ऊर्जा भंडारण क्षमता आवश्यकता

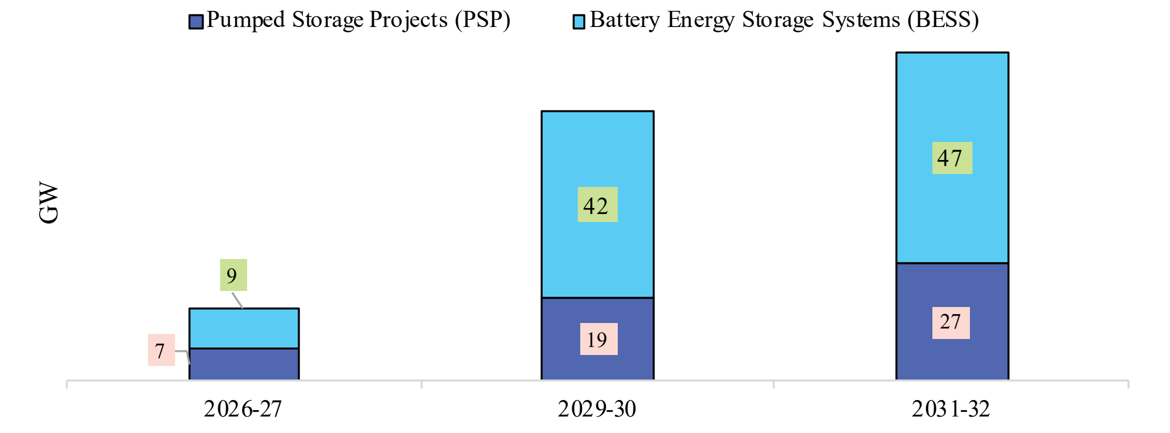

स्रोत: राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) 2023 और इष्टतम उत्पादन मिश्रण 2030 संस्करण 2.0 पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट

बॉक्स XII.12: नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में चुनौतियाँ

- प्रतिस्पर्धी शर्तों पर आवश्यक वित्त और निवेश जुटाना: बड़े तैनाती लक्ष्यों के लिए वित्त की व्यवस्था करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को तैयार करना, कम ब्याज दर, दीर्घकालिक अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण की खोज करना, और तकनीकी और वित्तीय बाधाओं दोनों को संबोधित करके जोखिम शमन या साझाकरण के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करना।
- भूमि अधिग्रहण: आरई क्षमता के साथ भूमि की पहचान, इसका रूपांतरण (यदि आवश्यक हो), भूमि सीलिंग अधिनियम से मंजूरी, भूमि पट्टा किराए पर निर्णय, राजस्व विभाग से मंजूरी और ऐसी अन्य मंजूरियों में समय लगता है। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में राज्य सरकारों को प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए।

12.39. दृष्टिकोण: भारत पारंपरिक स्रोतों से गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों तक क्रमिक संक्रमण के साथ गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है। भारत ने 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से विद्युत उत्पादन के लिए 50 प्रतिशत संचयी स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य[20] रखा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, गैर-जीवाश्म ईंधन (हाइड्रो, परमाणु, सौर, पवन, बायोमास, लघु हाइड्रो, पंप स्टोरेज पंप) आधारित क्षमता जो 2023-24 में कुल स्थापित क्षमता के 441.9 गीगावॉट में से लगभग 203.4 गीगावॉट (कुल का 46 प्रतिशत) है, 2026-27 में बढ़कर 349 गीगावॉट (57.3 प्रतिशत) होने की संभावना है। और 2029-30 में 500.6 गीगावॉट (64.4 प्रतिशत)। भारत ने पहले ही अपने ऊर्जा मिश्रण में गैर-जीवाश्म ईंधन के योगदान को बढ़ाने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं।

चार्ट XII.24: बिजली की स्थापित क्षमता में विभिन्न स्रोतों की प्रतिशत हिस्सेदारी

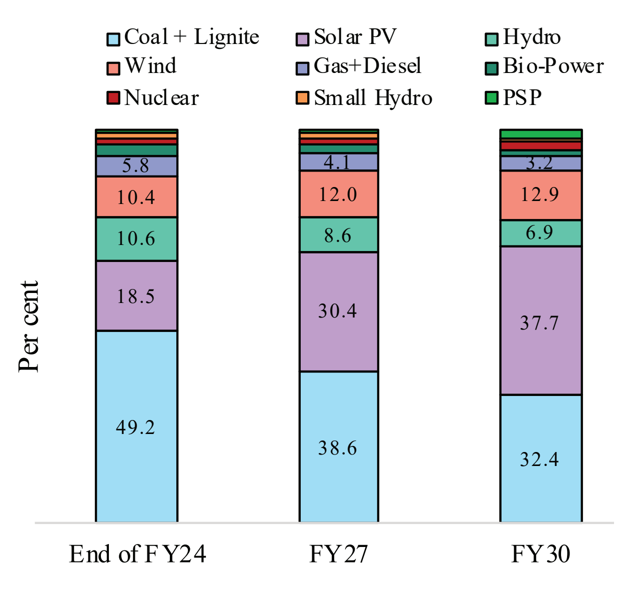

चार्ट XII.25: बिजली उत्पादन में प्रतिशत हिस्सेदारी

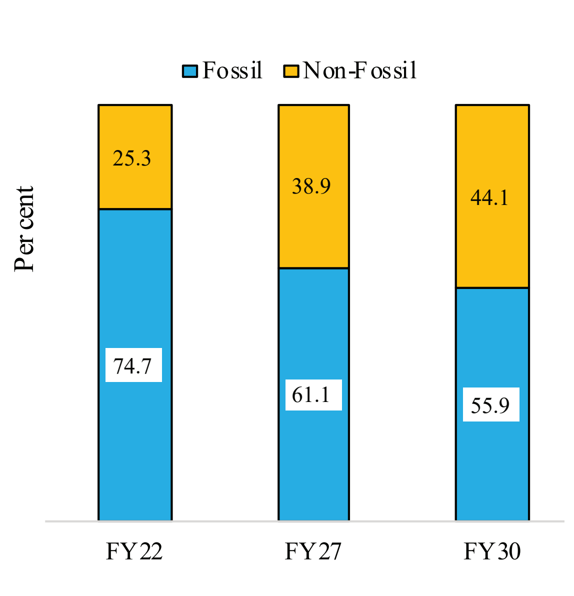

स्रोत: विद्युत मंत्रालय

सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना

खेल क्षेत्र

12.40. केन्द्र सरकार देश में खेल अवसंरचना में महत्वपूर्ण अंतरालों को पाटने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके प्रयासों में सहायता प्रदान कर रही है।

20 पेरिस समझौते (2021-2030) के तहत भारत का अद्यतन पहला राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, अगस्त 2022यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत किया गया - https://tinyurl.com/2p9ncj48

बॉक्स XII.13: खेल क्षेत्र में प्रमुख कार्यक्रम, परियोजनाएं और पहल

- खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (खेलो इंडिया) कार्यक्रम: 3,073.7 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 323 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वित्त वर्ष 2024 में, 38 नई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई और 58 प्रोजेक्ट पूरे किए गए।
- राष्ट्रीय खेल विकास कोष: वित्त वर्ष 2024 में दस (सात खेल अवसंरचना और तीन खेल प्रोत्साहन) परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- भारतीय खेल प्राधिकरण: वित्त वर्ष 2024 में विभिन्न केंद्रों के लिए नौ अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। वित्त वर्ष 2024 के दौरान 13 अवसंरचना परियोजनाएं पूरी हुईं।
- राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, इम्फाल: भारत के खेल अवसंरचना को बढ़ाने और खेल शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं बनाने के लिए विकास चल रहा है। परियोजना की स्वीकृत लागत 611.74 करोड़ रुपये है, जो 56 प्रतिशत की समग्र भौतिक प्रगति तक पहुंच गई है।
- मॉडल रियायत करार (एमसीए): खेल अवसंरचना के विकास में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए खेल विभाग ने अवसंरचना वित्त सचिवालय, आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के परामर्श से पीपीपी मोड पर एकीकृत खेल स्टेडियम परिसर (ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड) के विकास के लिए डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर एकीकृत बहु खेल क्षेत्र के विकास के लिए एमसीए का मसौदा तैयार किया है। एक बार अंतिम रूप देने के बाद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र सरकार के विभाग खेल अवसंरचना के विकास के लिए निजी खिलाड़ियों को शामिल करने में तेजी लाने के लिए एमसीए का उपयोग कर सकते हैं।

जल और स्वच्छता क्षेत्र

12.41. वर्ष 2024 में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), चरण I के 10 साल पूरे हो रहे हैं, जिसे अक्टूबर 2014 में भारत को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिए धन प्रदान किया गया था। ओडीएफ प्राप्त करने के बाद, संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के लिये एसबीएम-जी चरण II शुरू किया गया है, अर्थात, ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना, 2024-25 तक ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करना और सभी गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस मॉडल में बदलना। एसबीएम-जी चरण-II का कुल अनुमानित परिव्यय 1.4 लाख करोड़ रुपये है जिसे वित्त पोषण के विभिन्न क्षेत्रों और भारत सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के बीच अभिसरण के माध्यम से जोड़ा जाना है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान, 1,61,525 गांवों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था के साथ कवर किया गया, 2,83,998 गांवों को ग्रे वाटर प्रबंधन के साथ, 2,070 ब्लॉकों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों और सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं से जोड़ा गया और 159 जिलों को मल कीचड़ प्रबंधन व्यवस्था के साथ शुरू किया गया। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024 में, एसबीएम-जी को 7,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिनमें से 6,802.58 करोड़ रुपये (97 प्रतिशत) का उपयोग किया गया है।

बॉक्स XII.14: स्टील (बर्तन) बैंक:[21] तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले का विचार

यह अवधारणा एक रचनात्मक और टिकाऊ समाधान के माध्यम से सिद्दीपेट जिले में प्लास्टिक कचरे, विशेष रूप से डिस्पोजेबल बर्तनों के प्रबंधन की चुनौती को संबोधित करने के इर्द-गिर्द घूमती है। यह पहल 2022 में कांति-वेलुगु कार्यक्रम के दौरान शुरू हुई, जो एक राज्यव्यापी सार्वभौमिक नेत्र परीक्षण कार्यक्रम था, जहां गांवों में चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए थे, जिसमें 15-20 स्टाफ सदस्यों के लिए दैनिक भोजन की व्यवस्था की आवश्यकता थी।

- स्टील बैंक की अवधारणा में विभिन्न प्रकार के स्टील के बर्तन जैसे प्लेट, चम्मच, गिलास, कटोरे और बेसिन प्रदान करना शामिल है, जिन्हें ग्राम पंचायत कार्यालय में बैंक के रूप में संग्रहीत किया जाता है।
- इस पहल के लाभ प्लास्टिक कचरे के संचय में कमी, प्लास्टिक की खपत के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में सामुदायिक जागरूकता में वृद्धि, जैसे कि सूक्ष्म प्लास्टिक की अप्रत्यक्ष खपत के कारण कैंसर और पाचन संबंधी मुद्दे, समुदायों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और ग्राम पंचायतों के लिए अतिरिक्त आय स्रोत हैं, जिनका उपयोग परिचालन, रखरखाव और विस्तार उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- इसका प्रमुख परिणाम प्लास्टिक कचरे के संग्रह, डंपिंग और जलाने में कमी आई है, जिसमें प्रति घटना 6-8 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे और प्रति माह 28 क्विंटल की कमी की उम्मीद है।
- बर्तन बैंक की पहल को कई अन्य राज्यों के स्थानीय निकायों में लागू किया गया है।

12.42. जल जीवन मिशन (जेजेएम) अगस्त 2019 में 3.6 लाख करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का जल कनेक्शन प्रदान करने के लिये शुरू किया गया था। इस परिव्यय में से केन्द्रीय अंश 2.08 लाख करोड़ रुपए है और शेष 1.58 लाख करोड़ रुपए राज्यों द्वारा वहन किए जाने हैं। मिशन की शुरुआत के समय लगभग 19.30 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों (17 प्रतिशत) के पास नल के पानी के कनेक्शन की सुविधा थी जो अब बढ़कर 14.89 करोड़ ग्रामीण परिवारों (76.12 प्रतिशत) से अधिक हो गई है।

बॉक्स XII.15: सैलम:[22] टिकाऊ ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए मिजोरम का एक आदर्श गांव

- जेजेएम के तहत, सैलम पानी की कमी से एक जल-पर्याप्त मॉडल गांव में बदल गया। सैलम अब एक 'हर घर जल' गांव है, जिसमें 24×7 समुदाय-प्रबंधित जल आपूर्ति प्रणाली है। एक 900 केएलडी क्षमता का जल भंडारण टैंक बनाया गया था, और पास के झरने से एकत्र किए गए पानी को सौर पंपों के माध्यम से जलाशय में पंप किया गया था। जलाशय का पानी अलग-अलग घरों के साथ-साथ गुरुत्वाकर्षण प्रणाली द्वारा 700 केएलडी क्षमता के एक जोनल जलाशय में भेजा जाता है। मौजूदा स्रोतों के साथ-साथ अवसंरचना को नई योजना के साथ अच्छी तरह से एकीकृत किया गया है ताकि लागत को अनुकूलित किया जा सके और नाममात्र की लागत पर 24×7 पर्याप्त और पीने योग्य पानी सुनिश्चित किया जा सके।

21 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
22 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय

- ग्रामीणों द्वारा स्वयं पानी के मीटर लगाए गए हैं। वे वास्तविक खपत के आधार पर @ ₹0.04/लीटर/प्रति माह उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान कर रहे हैं। प्रत्येक ग्रामीण घर में पानी उपलब्ध कराने के काम से प्रोत्साहित होकर, समुदाय अब दीर्घकालिक स्रोत स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा वसंत स्रोतों के जलग्रहण क्षेत्र के तहत 30 एकड़ जंगल की रक्षा कर रहा है। कुछ ग्रामीणों ने वाटरशेड विकास के लिए स्वेच्छा से अपनी जमीन दान की है। साथ ही, एक स्थानीय पंप ऑपरेटर को प्रशिक्षित किया गया है, जो जल आपूर्ति प्रणाली के ओ एंड एम के लिए जिम्मेदार है। ऑपरेटर पानी की खपत के आधार पर बिल तैयार करने, प्रत्येक घर से मासिक जल सेवा एकत्र करने, ओ एंड एम में दैनिक पानी की खपत और व्यय का रिकॉर्ड रखने, फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) के माध्यम से पानी की गुणवत्ता परीक्षण करने और शिकायत रजिस्टर आदि बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है।

जल संसाधन प्रबंधन क्षेत्र

12.43. नमामि गंगे कार्यक्रम- 2014-15 में शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) एक प्रमुख एकीकृत संरक्षण मिशन है जो गंगा नदी के प्रदूषण उपशमन, संरक्षण और कायाकल्प पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कार्यक्रम का बजट ₹20,000 करोड़ (2014-2020) से बढ़ाकर ₹22,500 करोड़ (2021-2026)[23] कर दिया गया है।

12.44. नमामि गंगे इस पहल के तहत स्थापित किए जा रहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के लिए व्यापक रूप से लोकप्रिय हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) का उपयोग कर रहा है। एचएएम सीवरेज अवसंरचना क्षेत्र के लिए पीपीपी-आधारित दृष्टिकोण है, जिसमें निर्माण के दौरान 40 प्रतिशत पूंजीगत व्यय का भुगतान किया जाता है और शेष 60 प्रतिशत का भुगतान 15 साल की वार्षिकी में ब्याज के साथ किया जाता है, जिसमें ओ एंड एम के लिए अलग से भुगतान किया जाता है। आज की तारीख तक 33 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा, 'वन सिटी-वन ऑपरेटर' का दृष्टिकोण भी अपनाया गया है और इस मॉडल का पालन एचएएम परियोजनाओं के लिए किया गया है जहां कस्बों में मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को नई स्वीकृत परियोजनाओं के साथ एकीकृत किया जा रहा है और एचएएम आधारित पीपीपी मोड के तहत निविदा दी जा रही है।

बॉक्स XII.16: प्रमुख कार्यक्रम जल संसाधन क्षेत्र

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) अटल भूजल योजना

- डीआरआईपी को प्रणाली-व्यापी प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ बांध सुरक्षा संस्थागत सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ चयनित मौजूदा बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता के साथ लागू किया जा रहा है।
- डीआरआईपी चरण- I (2012-21) में, 2,567 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 223 बांधों का पुनर्वास किया गया था। इस योजना में छह राज्यों और दो केंद्रीय एजेंसियों ने भाग लिया।
- डीआरआईपी चरण II और चरण III (2021-31) में 10,211 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ 736 बांधों के पुनर्वास के लिए सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार की परिकल्पना की गई है; इस योजना में 19 राज्य और 3 केंद्रीय एजेंसियां भाग ले रही हैं।

23 पीआईबी दिनांक 13 फरवरी 2023, जल शक्ति मंत्रालय - https://tinyurl.com/3dx3prp5

अटल बहुजल योजना

- विश्व बैंक ने 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना को 1 अप्रैल 2020 से पांच साल तक लागू किया। सात राज्यों के 80 जिलों के 229 प्रशासनिक ब्लॉकों/तालुकों की 8,213 जल-संकट ग्राम पंचायतों (जीपी) में योजनाबद्ध।
- केवल मांग पक्ष भूजल प्रबंधन को लक्षित करने वाला कार्यक्रम, समुदाय के व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना। जीपी जल स्तर, पानी की गुणवत्ता, वर्षा और भूजल निष्कर्षण की निगरानी के लिए उपकरणों से लैस हैं।
- सभी 8,213 ग्राम पंचायतों का जल बजट और जल सुरक्षा योजनाएं समुदाय द्वारा तैयार और अद्यतन की गई हैं। 47 ब्लॉकों और 813 ग्राम पंचायतों ने भूजल की गिरावट की दर में सुधार दर्शाया है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना

- खेतों पर पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्रों का विस्तार करने, खेत पर जल उपयोग दक्षता में सुधार करने और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करने के लिए 2015-16 में शुरू किया गया।
- पीएमकेएसवाई एक अम्ब्रेला योजना है, जिसमें दो प्रमुख घटक शामिल हैं, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)।
- एआईबीपी के तहत, 2016-24 के दौरान 14,372 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 99 परियोजनाओं में से 58 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। परिणामस्वरूप, 2016-17 से 2023-24 के दौरान 25.80 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र का सृजन हुआ।
- एचकेकेपी - सतही लघु सिंचाई उप-घटक के तहत, 2016-17 से 2023-24 के दौरान 266.49 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के निर्माण के साथ 4,305 में से 2,497 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। एचकेकेपी - जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और बहाली उपघटक के तहत, 2016-17 से 2023-24 के दौरान 109.14 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता की बहाली के साथ 3,450 योजनाओं में से 1,489 पूरी हो चुकी हैं।

नदी जोड़ो परियोजना

- इस परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत 30 संपर्कों (प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14) अभिनिर्धारित किए गए हैं।
- पांच-लिंक परियोजनाओं की पहचान प्राथमिकता लिंक परियोजनाओं के रूप में की गई है; केन बेतवा संपर्क परियोजना, आशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल संपर्क परियोजना और गोदावरी-कावेरी संपर्क परियोजना (3 संपर्क खंडों को शामिल करते हुए)
- केन बेतवा लिंक परियोजना कार्यान्वयनाधीन एनपीपी की पहली कड़ी है जिसे वर्ष 2021 में 39,317 करोड़ रुपये के केंद्रीय समर्थन के साथ कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया था और इसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाना है।

बॉक्स XII.17: जल प्रबंधन क्षेत्र में प्रमुख पहल

- यमुना, गंगा और उनकी सहायक नदियों (प्रयाग) के वास्तविक समय विश्लेषण के लिये एक मंच, नदी की गुणवत्ता और सीवेज उपचार अवसंरचना की निरंतर निगरानी के लिये एक ऑनलाइन डैशबोर्ड अप्रैल 2023 में शुरू किया गया है
- एनएमसीजी के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस नदी संरक्षण और टिकाऊ जल प्रबंधन की दिशा में 11 देशों में 275 से अधिक वैश्विक नदी शहरों, अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों और ज्ञान प्रबंधन भागीदारों को कवर करने वाला एक अनूठा और अपनी तरह का पहला गठबंधन है।
- भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएमआर) योजना के तहत, देश भर में फैले लगभग 26,000 भूजल निगरानी स्टेशनों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर भूजल शासन की निगरानी की जाती है। 5,000 से अधिक स्टेशन वास्तविक समय की निगरानी के लिए टेलीमेट्री के साथ डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर से लैस हैं। देश के विभिन्न भागों में लगभग 300 प्रदर्शनात्मक कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाएं बनाई गई हैं।
- देश में जल निकायों की पहली जनगणना 2023 में पूरी और प्रकाशित हुई थी। देश में 24,24,540 जल निकायों की गणना की गई है, जिनमें से 97.1 प्रतिशत (23,55,055) ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और 2.9 प्रतिशत (69,485) शहरी क्षेत्रों में हैं।
- बांध सुरक्षा मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए, सरकार ने दिसंबर 2021 में बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांध की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव प्रदान करने और उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक बांध सुरक्षा अधिनियम लागू किया है। देश के सभी बड़े बांध बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के दायरे में आते हैं। बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर 2023 के अनुसार, देश में 6,281 बांध हैं।
- डेटा-आधारित जल शासन में सुधार के लिए डब्ल्यूक्यूएमआईएस, भारत-डब्ल्यूआरआईएस पोर्टल, पीएम गतिशक्ति एनएमपी पोर्टल आदि जैसे तकनीकी नवाचार विकसित किए गए हैं।

शहरी क्षेत्र

12.45. **सभी के लिए आवास:** 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के कार्यान्वयन के द्वारा शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराने की दृष्टि से कार्य किया जा रहा है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए मांग सर्वेक्षण के आधार पर, 1.18 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से लगभग 1.14 करोड़ घरों के निर्माण की नींव रखी गई है और 84 लाख से अधिक घरों को पूरा कर लिया गया है/वितरित किया जा चुका है। सभी स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए इस योजना को दो साल के लिए 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत कुल निवेश 8.07 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसमें केंद्र, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और लाभार्थी का योगदान शामिल है। इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित 2.00 लाख करोड़ रुपए में से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1.64 लाख करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता पहले ही जारी की जा चुकी है।

12.46 आवासीय स्थिति में सुधार लाने और शहरी प्रवासियों/गरीबों को मलिन बस्तियों, अनौपचारिक बस्तियों या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने से बचाने के लिए देश में पहली बार किफायती किराया आवास परिसरों (एआरएचसी) की पहल की जा रही है। अब तक मॉडल 1 के तहत कुल 5,648 घरों का संचालन शुरू हो चुका है और अन्य 7,413 घरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मॉडल-2 के तहत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 173.89 करोड़ रुपये के प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (टीआईजी) के साथ 7 राज्यों में 82,273 नई एआरएचसी इकाइयों के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें से 44,116 एआरएचसी इकाइयों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इन स्थापित इकाइयों में से श्रीपेरंबदूर में 3,969 इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है।

बॉक्स XII.18: कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT)

- जून 2015 में 500 शहरों में शुरू की गई एएमआरयूटी का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक रूप से सुरक्षित और सुनिश्चित पेयजल आपूर्ति प्रदान करना था।

चार्ट XII.26: अमृत 1.0 और 2.0 के लिए कुल परिव्यय

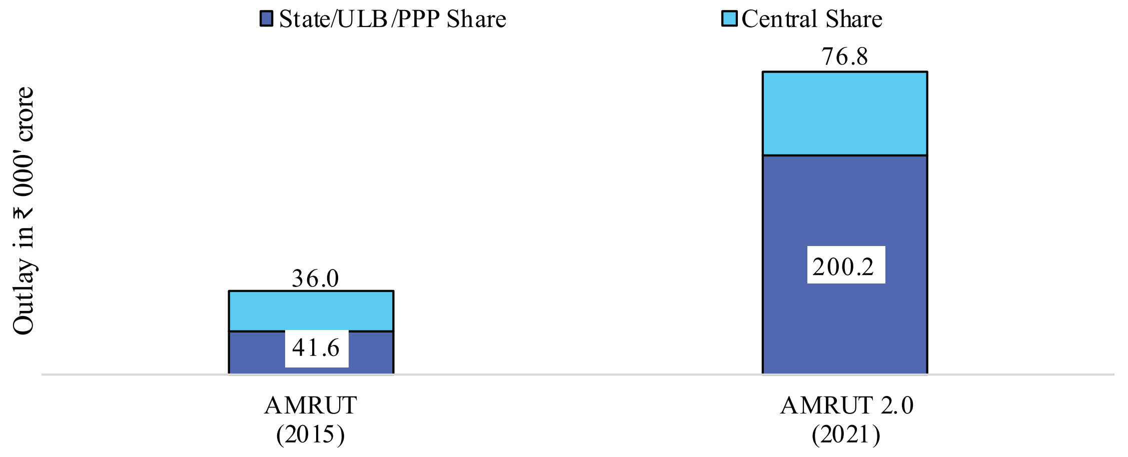

स्रोत: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

- 83,327 करोड़ रुपये की लागत वाली 5,999 परियोजनाओं के लिए अनुबंध प्रदान किए गए, जिनमें से 51,434 करोड़ रुपये की लागत वाली 5,304 परियोजनाएं (62 प्रतिशत) पूरी हो चुकी हैं।
- अमृत में ग्यारह सुधार शामिल हैं, जिनमें 54 लक्ष्य शामिल हैं, जिन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार वर्षों में हासिल करना है। इनका उद्देश्य सेवा वितरण में सुधार करना, संसाधन जुटाना और नगर निगम के कामकाज को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
- अमृत 2.0 को अक्टूबर 2021 में पांच साल के लिए लॉन्च किया गया, जिसका फोकस शहरों को आत्मनिर्भर और जल सुरक्षित बनाने और 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने पर है। जल निकायों और कुओं का कायाकल्प इस मिशन के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है।
- अमृत 2.0 के तहत प्रमुख सुधारों में संपत्ति कर और उपयोगकर्ता शुल्क की अधिसूचना, शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिरता और जल सुरक्षा को बढ़ाना, 20 प्रतिशत उपचारित उपयोग किए गए पानी का पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग, दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली और कुशल नगर नियोजन आदि शामिल हैं। पीपीपी को प्रोत्साहित करने के लिए, दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आवंटन के 10 प्रतिशत मूल्य की परियोजनाओं को पीपीपी मोड में लागू करना अनिवार्य है।

12.47. वर्तमान में, कुल 27 शहरों में 945 किलोमीटर मेट्रो रेल या क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) लाइनें चालू हैं, और 939 किलोमीटर निर्माणाधीन हैं। वित्त वर्ष 24 में लगभग 86 किलोमीटर मेट्रो रेल/आरआरटीएस लाइनें चालू हो चुकी हैं। मार्च 2024 तक चालू मेट्रो रेल/आरआरटीएस लाइनों के लिए प्राप्त दैनिक सवारियों की संख्या 1.01 करोड़ थी।

बॉक्स XII.19: स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम)

- जून 2015 में एससीएम की शुरुआत ऐसे शहरों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी जो श्स्मार्ट समाधानोंश के इस्तेमाल के जरिए अवसंरचना, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को एक सभ्य जीवन स्तर देते हैं।
- कुल 100 शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। 20 जून 2024 तक, 100 एसपीवी ने लगभग ₹1.64 लाख करोड़ की लागत वाली 8,011 बहु-क्षेत्रीय परियोजनाएँ शुरू की हैं; जिनमें से ₹1.43 लाख करोड़ (87 प्रतिशत) की लागत वाली 7,153 परियोजनाएँ (89 प्रतिशत) पूरी हो चुकी हैं।

चार्ट XII.27: स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पूरी की गई परियोजनाओं का मूल्य (वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024)

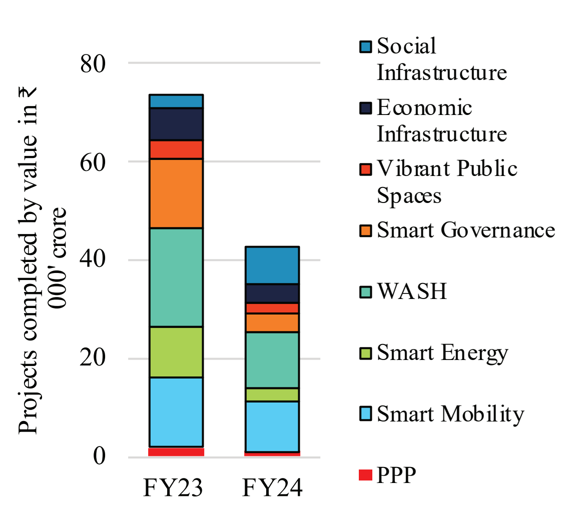

चार्ट XII.28: स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या (वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024)

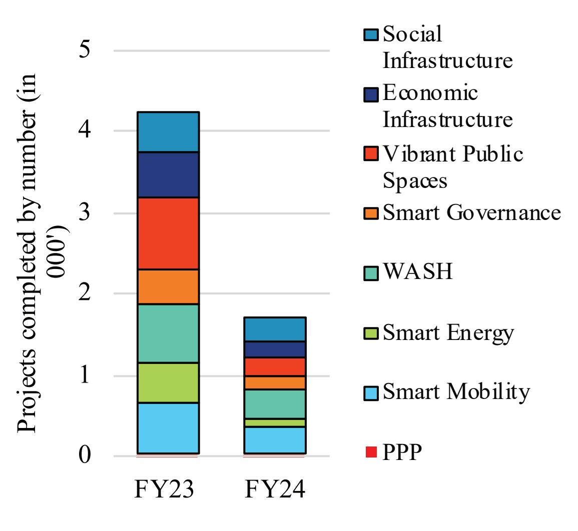

स्रोत: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

12.48 **स्वच्छ भारत मिशन शहरी (एसबीएम-यू):** शहरी भारत के गरीब परिवारों सहित प्रत्येक नागरिक की स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। एसबीएम-यू का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाना और 100 प्रतिशत स्रोत पृथक्करण, डोर टू डोर संग्रह और कचरे के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से सभी शहरों को कचरा मुक्त[24] बनाना है। एसबीएम-यू की उपलब्धियों में 63.07 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) इकाइयों का निर्माण शामिल है, जो लक्ष्य से 113.75 प्रतिशत अधिक है और 6.37 लाख सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, जो लक्ष्य से लगभग 128 प्रतिशत अधिक है।

24 आवासन और शहरी कार्यमंत्रालय पीआईबी दिनांक 21 दिसंबर 2023 - https://tinyurl.com/yxzxeufu

बॉक्स XII.20: स्वच्छ भारत मिशन शहरी (एसबीएम-यू) पर केस स्टडीज

जैविक अपशिष्ट प्रबंधन

- इंदौर में पीपीपी मॉडल के तहत 500 टन प्रतिदिन (टीपीडी) बायो-मीथेनेशन प्लांट स्थापित किया गया: नवंबर 2021 में, इंदौर नगर निगम (आईएमसी) ने 500 टीपीडी बायो-मीथेनेशन प्लांट स्थापित किया। यह प्लांट डीबीएफओटी मॉडल पर संचालित होता है, जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के रूप में डिजाइन-निर्माण-वित्त-संचालन-हस्तांतरण है। यह प्लांट प्रतिदिन लगभग 44,000 - 45,000 एम 3 कच्ची बायोगैस उत्पन्न करता है, जिससे प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम बायो-सीएनजी का उत्पादन होता है। सीबीजी प्लांट ने सालाना 1,30,000 CO2 उत्सर्जन को कम करने में योगदान दिया है।
- गीले कचरे के उपचार के लिए मैंगलोर में ब्लैक सोल्जर फ्लाईज (बीएसएफ) का उपयोग किया जा रहा है: मैंगलोर में सालाना लगभग 10,000 टन गीले कचरे के उपचार के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के हिस्से के रूप में एक सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। बीएसएफ ब्रीडिंग में नवीन प्रौद्योगिकी शहर के सभी गीले कचरे की मात्रा का उपभोग करने के लिए तीव्र गति से बड़े पैमाने पर तैनाती का लाभ प्रदान करती है और इस प्रकार गीले कचरे के प्रबंधन की समस्या को हल करती है। गीले कचरे को बीएसएफ के माध्यम से खाद में बदलने में 12-14 दिन लगते हैं, जबकि एरोबिक खाद बनाने में 45-60 दिन लगते हैं।
- इंदौर बायो सीएनजी: प्लांट में प्रति दिन 400 मीट्रिक टन प्रसंस्करण क्षमता है, जो एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत संचालित है। प्लांट जैविक कचरे को संसाधित करता है, जिससे परिवहन ईंधन के रूप में उपयोग के लिए 14.8 मीट्रिक टन बायो-सीएनजी और प्रतिदिन 80 मीट्रिक टन किण्वित जैविक खाद प्राप्त होती है।

कचरे से बिजली

- पिंपरी-चिंचवाड़ नगर निगम में कचरे से बिजली बनाने का प्लांट: बायोडिग्रेडेबल कचरे को खाद में बदल दिया जाता है और आस-पास के किसानों को बेचा जाता है। इस परियोजना में 1000 टीपीडी की क्षमता वाली एक मटेरियल रिकवरी सुविधा शामिल है, जिसमें 500 टीपीडी की मशीनीकृत विंडरो कंपोस्टिंग की सुविधा है। कचरे से ऊर्जा बनाने वाले प्लांट से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग नगर निगम के उद्देश्यों और निगम की सहमति से किसी अन्य उपयोग के लिए किया जा सकता है। इस परियोजना को डीबीएफओटी (डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण) के आधार पर पीपीपी मॉडल पर संचालित किया जा रहा है।

12.49. **दृष्टिकोण:** यह उम्मीद की जाती है कि 2030 तक भारत की 40 प्रतिशत[25] से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी, शहरों को केंद्र, राज्य और शहरी स्थानीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से भविष्य के लिए तैयार शहरी अवसंरचना का निर्माण करके विकास के आर्थिक केंद्रों में बदलने की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों की कुशलतापूर्वक योजना बनाकर, मजबूत परियोजना ढांचे का विकास करके और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को मजबूत करके इसे हासिल किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से रिंग-फेंस्ड राजस्व धाराओं के साथ परियोजना-आधारित फंडिंग मॉडल न केवल व्यवहार्यता अंतर-आधारित फंडिंग बल्कि बाजार उधार और ऋण वृद्धि संरचनाओं का भी प्रभावी ढंग से दोहन कर सकते हैं। यूएलबी और परियोजना-कार्यान्वयन एजेंसियों को मूल्य-के-पैसे का विश्लेषण करने और परियोजनाओं को लागू करने के लिए इष्टतम मोड प्राप्त करने के लिए वाटरफॉल तंत्र को लागू करने की आवश्यकता है।

25 नीति आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुट

पर्यटन क्षेत्र

12.50. प्रसाद योजना के तहत जो तीर्थ और विरासत स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना के संवर्धन को पूरा करती है, विकास के लिए 29 नए स्थलों की पहचान की गई है। योजना के तहत परियोजनाओं के लिए स्वीकृत कुल 1,621.14 करोड़ रुपये में से 62.7 प्रतिशत राशि वितरित की जा चुकी है। सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना को भी स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में 3,800 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ नया रूप दिया है। इस मिशन का उद्देश्य पर्यटन स्थलों के एकीकृत विकास के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना है। इस योजना के तहत, अब तक 32 राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के 57 स्थलों की पहचान की गई है। कुल 644 करोड़ रुपये की लागत से 29 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

रणनीतिक अवसंरचना

अंतरिक्ष क्षेत्र

12.51. पिछले कुछ वर्षों में, अंतरिक्ष क्षेत्र ने अंतरिक्ष अन्वेषण और जमीनी अवसंरचना के लिए उपयोग किए जाने वाले रॉकेट, उपग्रह और अंतरिक्ष यान के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। वर्तमान में, भारत के पास 55 सक्रिय अंतरिक्ष संपत्तियाँ हैं जिनमें 18 संचार उपग्रह, नौ नेविगेशन उपग्रह, पाँच वैज्ञानिक उपग्रह, तीन मौसम संबंधी उपग्रह और 20 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह शामिल हैं। इसरो के पास मौजूदा लॉन्च व्हीकल यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी) और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (जीएसएलवी) के अलावा, संगठन ने अपने बेड़े में दो और लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (एलवीएम3) और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (एसएसएलवी) को शामिल किया है।

12.52. अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों की एक श्रृंखला संचालित की गई है जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन (2014), एस्ट्रोसैट (2015), चंद्रयान-2 ऑर्बिटर (2019) और उसके बाद, चंद्रयान-3 का चंद्रमा पर उतरना (2023) और आदित्य-L1 मिशन (2023)। इसके अलावा, स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन तारामंडल यानी NavIC श्रृंखला को 2016 में पूरा और चालू किया गया। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड [NSIL] ने एलवीएम3, M2 और M3 मिशनों के माध्यम से वनवेब के 72 उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने के अपने अनुबंध को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है, जिससे एलवीएम3 वैश्विक वाणिज्यिक लॉन्च सेवा बाजार में एक विश्वसनीय लॉन्च व्हीकल के रूप में स्थापित हुआ है।

बॉक्स XII.21: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी

2020 में घोषित अंतरिक्ष क्षेत्र सुधार भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने में परिवर्तनकारी रहे हैं। निजी भागीदारी को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कुछ प्रमुख पहल नीचे दी गई हैं:

- भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) - अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने और अधिकृत करने के लिए एक एकल खिड़की एजेंसी का उद्घाटन जून 2022 में अहमदाबाद में किया गया था। IN-SPACe को 1 जनवरी 2024 तक 300 से अधिक भारतीय संस्थाओं से प्राधिकरण, सहायता, सुविधा समर्थन और परामर्श, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुविधा उपयोग से संबंधित 440 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
- अंतरिक्ष गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आवश्यक समर्थन बढ़ाने के लिए 1 जनवरी 2024 तक विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ 51 समझौता ज्ञापनों और 34 संयुक्त परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- निजी क्षेत्र की कई संस्थाओं ने बाह्य अंतरिक्ष में संचालन के लिए उपग्रह और कार्यात्मक पेलोड विकसित किए हैं, जैसे कि पिक्सलस्पेस, दिगंतरा, ध्रुव स्पेस, अजिस्ता बीएसटी एयरोस्पेस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, आदि।

- हैदराबाद स्थित मेसर्स स्काईरूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के सबऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम-एस (प्रारंभ मिशन) का प्रक्षेपण 18 नवंबर 2022 को पूरा हुआ।
- पहला निजी लॉन्चपैड और मिशन नियंत्रण केंद्र 25 नवंबर 2022 को एसडीएससी, SHAR में इसरो परिसर में मेसर्स अग्निकुल कॉसमॉस प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई द्वारा स्थापित किया गया।
- पांच पीएसएलवी के एंड-टू-एंड उत्पादन के लिए एचएएल और एलएंडटी कंसोर्टिया को भारतीय उद्योग भागीदार के रूप में चुना गया है।
- छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

12.53. अंतरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकी और सेवाओं को अपनाना अक्सर सामाजिक अनुप्रयोगों में उनके पर्याप्त एकीकरण से संबंधित होता है, जो अंतिम उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में होता है। प्रमुख तकनीकी क्षेत्र जिनमें विकासात्मक अंतर मौजूद है, उनमें कार्बन फाइबर की प्राप्ति के लिए स्वदेशी क्षमता का विकास, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए समर्पित कैप्टिव सेमीकंडक्टर फैब, प्रमुख मिश्र धातु तत्वों की उपलब्धता आदि शामिल हैं। प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण से संबंधित चुनौतियों में बहुत ही विशिष्ट और/या प्रतिस्पर्धी बाजार की उपस्थिति, मूल्य निर्धारण की बाधाएँ, आम तौर पर सीमित माँग जो बड़े पैमाने पर व्यावसायीकरण को बाधित करती है, दीर्घकालिक माँग की दृश्यता की कमी आदि शामिल हैं।

डिजिटल अवसंरचना

12.54. निर्माण क्षेत्र भारत के वार्षिक जीवीए (2023-24) का लगभग 9 प्रतिशत है, हालाँकि, यह सबसे कम डिजिटल क्षेत्रों में से एक है। हाल के वर्षों में, अवसंरचना विकास के विभिन्न पहलुओं को अवसंरचना योजनाओं, डिजाइनों और परिसंपत्तियों की दक्षता में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत किया गया है। प्रौद्योगिकी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण उपयोग पीएम गतिशक्ति, भुवन, भारतमैप्स, सिंगल विंडो सिस्टम, परिवेश पोर्टल, नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति), इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड (आईआईजी) और लगभग सभी मंत्रालयों के लिए इसी तरह के कई डैशबोर्ड और डेटा स्टैक के माध्यम से किए गए हैं।

बॉक्स XII.22: बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग (BIM)

- ओसीएमएस[26] के अनुसार, लगभग 27% परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई है, जबकि 45% में समय में वृद्धि हुई है। सबसे कम डिजिटल क्षेत्रों में से एक, यह अनुमान है कि अवसंरचना और निर्माण क्षेत्र में प्रासंगिक जानकारी खोजने में 20% समय बर्बाद होता है।
- यह अनुमान है कि भारत में जटिल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, ठप्ड को अपनाने से औसत परियोजना देरी 39 महीने कम हो सकती है, अवसंरचना के निर्माण की लागत 30 प्रतिशत तक कम हो सकती है, रखरखाव की लागत 20 प्रतिशत तक कम हो सकती है, सूचना और प्रणालीगत अकुशलता 20 प्रतिशत तक कम हो सकती है, निर्माण क्षेत्र से संबंधित कार्बन उत्सर्जन 38 प्रतिशत तक कम हो सकता है, पानी की खपत 10 प्रतिशत तक हो सकती है और निर्माण अनुसंधान एवं विकास में निवेश में एक प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, और अतिरिक्त अवसंरचना में बचत को फिर से निवेश करके चार मिलियन से अधिक कुशल पेशेवर रोजगार और लगभग 2.5 मिलियन अतिरिक्त निर्माण क्षेत्र की नौकरियां पैदा हो सकती हैं।

26 परियोजनाओं और अवसंरचना निगरानी के लिए ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएस एंड पीआई) में परियोजना निगरानी प्रभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विंग की पहल जो 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन और अवसंरचना क्षेत्रों के प्रदर्शन पर नवीनतम जानकारी प्रदान करके प्रबंधन सेवाएं प्रदान करती है।

- बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन एंड मॉडलिंग टेक्नोलॉजी (BIM) का आदर्श वाक्य भौतिक रूप से निर्माण करने से पहले डिजिटल रूप से निर्माण करना है। नीति आयोग ने BIM कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियों, समाधानों और सक्षमताओं की पहचान की है। प्रासंगिक सार्वजनिक/निजी और शैक्षणिक हितधारकों की पहचान की गई है और उन्हें शामिल किया जा रहा है। भारत में BIM को तेजी से अपनाने की दिशा में एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए रोडमैप के आधार पर, सेंट्रल विस्टा, नई संसद और केंद्रीय सचिवालय सहित अवसंरचना परियोजनाओं को मार्गदर्शन और रणनीति प्रदान की जा रही है।

- बीआईएम का अब कुछ मंत्रालयों और विभागों द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग और लाभ उठाया जा रहा है, जैसे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, सभी मेट्रो रेल, चुनिंदा जटिल औद्योगिक और पर्यटन परियोजनाएं, विभिन्न हवाई अड्डे, साथ ही केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में संगठनवार स्वीकृति और एनएचएआई में डेटा लेक के रूप में व्यापक डिजिटलीकरण, जिसे अब पूरे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तक विस्तारित किया जा रहा है।

दूरसंचार क्षेत्र

12.55. दूरसंचार के उपयोग और अंतर्निहित प्रौद्योगिकियों में, विशेष रूप से पिछले दशक में, बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए हैं। दूरसंचार अधिनियम 2023 को दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क, स्पेक्ट्रम के आवंटन और संबंधित मामलों पर कानूनों को संशोधित और समेकित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

12.56. जून 2024 तक देश में मोबाइल टावरों की कुल संख्या 8.02 लाख है, जबकि बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की संख्या 29.37 लाख और 5जी बीटीएस की संख्या 4.5 लाख है। सरकार ने दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में 24,680 अछूते गांवों में 26,316 करोड़ रुपये की कुल लागत से 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति के लिए परियोजना भी शुरू की है। केवल 2जी/3जी कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांवों को 4जी में अपग्रेड किया जाएगा।

बॉक्स XII.23: भारतनेट परियोजना

- भारतनेट परियोजना को देश की सभी (2,50,000) ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। नेटवर्क के निर्माण, उन्नयन और रखरखाव के लिए पेशेवर एजेंसियों का उपयोग करके सेवाओं के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ परियोजना के दायरे का विस्तार करने के लिए संशोधन किया गया है।

- 30 अप्रैल 2024 तक 6,85,501 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है, 2,11,021 जीपी को ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) से जोड़ा जा चुका है और कुल 2,12,229 जीपी सेवा के लिए तैयार (ओएफसी+ सैटेलाइट) हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा उपयोग को बढ़ाने के लिए फाइबर टू होम (एफटीटीएच) कनेक्शन और पायलट परियोजनाओं की भी योजना बनाई गई है।

12.57. दूरसंचार उपकरणों के लिए परीक्षण प्रयोगशालाएँ दूरसंचार उपकरणों की कार्यक्षमता, विश्वसनीयता और अंतर-संचालन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये विशेष सुविधाएँ विभिन्न दूरसंचार उपकरणों जैसे राउटर, स्विच, बेस स्टेशन और संचार प्रोटोकॉल के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए उन्नत परीक्षण अवसंरचना से सुसज्जित हैं। 69 से अधिक प्रयोगशालाओं को ईएमआई/ईएमसी, सुरक्षा मूल्यांकन, तकनीकी आवश्यकताओं और दूरसंचार उत्पादों के RF परीक्षण के लिए अनुरूपता मूल्यांकन निकायों के रूप में नामित किया गया है।

12.58. सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने, व्यापार करने में आसानी बढ़ाने, दूरसंचार क्षेत्र में "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा देने के लिए मिलेनियम एसआरएस पहल के हिस्से के रूप में स्पेक्ट्रम विनियामक सैंडबॉक्स (एसआरएस), या वायरलेस परीक्षण क्षेत्रों (वाईटीई क्षेत्रों) के लिए दिशानिर्देश पेश किए हैं। यह पहल अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने, स्पेक्ट्रम बैंड की खोज को बढ़ावा देने और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक सरलीकृत नियामक ढांचा प्रदान करती है। वाईटीई जोन को विभिन्न आवृत्ति बैंडों में प्रयोग के लिए शहरी या दूरदराज के क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें शैक्षणिक, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, दूरसंचार प्रदाताओं और अन्य को पात्रता प्रदान की गई है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र

12.59. सरकार ने सामाजिक प्रभाव के लिए समावेशन, नवाचार और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए एक मिशन-केंद्रित दृष्टिकोण के रूप में भारत एआई कार्यक्रम की कल्पना की है। भारत एआई के स्तंभों में शासन में एआई, एआई आईपी और नवाचार, एआई कंप्यूट और सिस्टम, एआई के लिए डेटा, एआई में कौशल और एआई नैतिकता और शासन शामिल हैं। 'भारत में एआई और भारत के लिए एआई' के निर्माण के हिस्से के रूप में, भारत एआई का पहला संस्करण अक्टूबर 2023 में जारी किया गया था।

12.60. भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी (जीपीएआई) का संस्थापक सदस्य है, जो जून 2020 में बहु-हितधारक पहल में शामिल हुआ था। तब से, भारत ने जीपीएआई के लक्ष्यों और उद्देश्यों में योगदान दिया है और एआई के जिम्मेदार विकास, परिनियोजन और अपनाने के लिए विभिन्न घरेलू पहलों पर काम कर रहा है। भारत ने 2023 में जीपीएआई के आने वाले परिषद अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, उसके बाद 2024 में प्रमुख अध्यक्ष और 2025 में निवर्तमान अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एआई नवाचार स्तंभों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने और भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक भारत एआई मिशन के लिए ₹10,300 करोड़ से अधिक के आवंटन को मंजूरी दी है।

12.61. एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म (एरावत) जो कि एक एआई सुपरकंप्यूटर है, जिसे सी-डैक, पुणे में स्थापित किया गया है, ने जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में घोषित शीर्ष 500 वैश्विक सुपरकंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान हासिल किया है।

12.62. भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए जुलाई 2015 में शुरू किए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी के लिए विभिन्न डिजिटल पहल की गई हैं। मेरी पहचान,[27] एक राष्ट्रीय एकल साइन-ऑन (एनएसएसओ) एक उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण सेवा है जिसमें क्रेडेंशियल्स का एक सेट कई ऑनलाइन एप्लिकेशन या सेवाओं तक पहुँच प्रदान कर सकता है। वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों/राज्यों की 9,600 से अधिक सेवाएँ एनएसएसओ के साथ एकीकृत हैं। डिजिलॉकर[28] प्लेटफॉर्म जो नागरिकों को दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के डिजिटल भंडारण, जारी करने और सत्यापन में आसानी प्रदान करता है, अब 26.28 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं और 674 करोड़ से अधिक दस्तावेजों तक पहुँच चुका है। नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग) प्लेटफॉर्म जिसे एक ही मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रमुख सरकारी सेवाएँ देने के लिए विकसित किया गया है, में अब 207 केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों की 2,019 सेवाएँ हैं।

27 https://meripehchaan.gov.in/
28 https://www.digilocker.gov.in/

बक्सा XII.24: जीआई क्लाउड – 'मेघराज'

- क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभों का उपयोग करने के लिए, सरकार ने एक महत्वाकांक्षी पहल – 'जीआई क्लाउड' शुरू की है।
- इस पहल का उद्देश्य देश में क्लाउड पारिस्थितिकी तंत्र के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी विभागों/मंत्रालयों को क्लाउड पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सेवाएं प्रदान करना है।
- वर्तमान में, 25,806 वर्चुअल मशीनें जीआई क्लाउड पर चल रही हैं और इसका उपयोग सरकारी विभागों के 1,767 से अधिक अनुप्रयोगों द्वारा किया जा रहा है।
- मेघराज पारिस्थितिकी तंत्र के प्रसार के लिए, सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्लाउड सेवा प्रदाताओं (सीएसपी) की क्लाउड सेवा पेशकशों को भी सूचीबद्ध किया है। आज तक, 22 सीएसपी सूचीबद्ध हैं और अब तक, 250 से अधिक केंद्रीय और राज्य विभाग सूचीबद्ध सीएसपी की क्लाउड सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।

चुनौतियाँ और अवसर

12.63. जैसा कि इस अध्याय के विभिन्न खंडों से पता चलता है, पिछले पांच वर्षों में अवसंरचना के निर्माण में भारी उछाल आया है। हालांकि, इस खंड में प्रस्तुत किए गए सुधारात्मक और सामूहिक कार्रवाई के लिए कुछ क्षेत्र हैं।

12.64. **भूमि संबंधी:** कनेक्टिविटी अवसंरचना और ऊर्जा से संबंधित परिसंपत्तियों के बड़े पैमाने पर निर्माण के बावजूद, दोनों क्षेत्रों ने भूमि अधिग्रहण और भूमि से संबंधित मंजूरी में देरी में सुधार की आवश्यकता बताई। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के धीमे ऑन-बोर्डिंग के बारे में भी मुद्दे उठाए गए हैं। इस चुनौती का समाधान करने के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों पर समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है।

12.65. **कौशल की मांग:** विमानन क्षेत्र ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) संचालन और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए तकनीकी ज्ञान सीमित संख्या में मूल उपकरण निर्माताओं के पास केंद्रित है। एयरलाइन उद्योग एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र है, जो तेल की कीमतों, विनिमय दरों, महामारी, युद्धों और उपकरण मुद्दों जैसे बाहरी आघातों के प्रति संवेदनशील है। ये आघात किसी एयरलाइन के संचालन को प्रभावित कर सकते हैं और इसकी व्यवहार्यता को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए एयरलाइनों को और अधिक समर्थन देने के लिए एमआरओ, लीजिंग और कौशल जैसे क्षेत्रों में क्षमताओं का विकास आवश्यक है। अवसंरचना परियोजनाओं के मामले में परियोजना विकास, व्यवहार्यता मूल्यांकन, वित्तीय रिटर्न विश्लेषण और परियोजना प्रबंधन के विभिन्न चरणों से संबंधित कई पहलुओं में विशेष तकनीकी कौशल शामिल हैं जिन्हें व्यवस्थित आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर पोषित करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रभावी सार्वजनिक-निजी भागीदारी आवश्यक है।

12.66. **निजी भागीदारी में सुधार की आवश्यकता:** पिछले पांच वर्षों में अवसंरचना के स्टॉक में वृद्धि मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तपोषण के कारण हुई है। निजी क्षेत्र की भागीदारी अपेक्षित सीमा तक नहीं हो रही है। साहित्य से पता चलता है कि कई कारक अवसंरचना के निर्माण में निजी भागीदारी को बाधित कर रहे हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं:

क. भारी पूंजी निवेश और लंबी चुकौती अवधि और सस्ती लागत पर बड़ी इक्विटी और ऋण जुटाने में कठिनाई। इस बाधा को कम करने के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जैसे कई नए पीपीपी वित्तपोषण मॉडल पेश किए गए हैं। लेकिन इन तरीकों के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी अभी तक सड़क और पानी जैसे कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रही है।

ख. जोखिम आकलन, आवंटन और शमन से संबंधित परियोजना संरचना के मुद्दे

ग. मंजूरी और भूमि अधिग्रहण में देरी

घ. बुनियादी ढांचा क्षेत्रों आदि के लिए एक स्वतंत्र नियामक की कमी

ङ. संविदात्मक मुद्दे और विवाद समाधान और मध्यस्थता के लिए अपर्याप्त व्यवस्था, जिससे लंबे समय तक मुकदमेबाजी होती है।

12.67. **भौतिक संपर्क और ऊर्जा अवसंरचना के अनुभाग में चर्चा** के अनुसार, जलवायु और पर्यावरणीय स्थिरता का प्रश्न अवसंरचना के निर्माण में तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। विमानन क्षेत्र के लिए एक उभरती चुनौती 2027 से अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना (सीओआरएसआईए) के अनिवार्य चरण का अनुपालन होगा। चूंकि भारत आईसीएओ का सदस्य राज्य है, इसलिए ऑफसेटिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बाध्य है, यानी या तो टिकाऊ विमानन ईंधन (एसएएफ) का उपयोग करें या आईसीएओ अनुमोदित उत्सर्जन इकाई कार्यक्रमों से कार्बन क्रेडिट खरीदकर अपने उत्सर्जन को ऑफसेट करें। हालांकि, एयरलाइन ऑपरेटरों की ऑफसेटिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सीओआरएसआईए-योग्य उत्सर्जन इकाइयों की आपूर्ति करने के लिए भारत में कोई आईसीएओ-अनुमोदित उत्सर्जन इकाई कार्यक्रम नहीं हैं। एसएएफ[29] की लागत जीवाश्म एटीएफ की लागत से लगभग 3 से 5 गुना अधिक होती है, जो एसएएफ के उत्पादन के लिए प्रयुक्त फीडस्टॉक और पाथ वे पर निर्भर करती है।

12.68. **अवसंरचना में वित्तीय प्रवाह के एकत्रीकरण का अभाव:** अवसंरचना के वित्तपोषण की संरचना जटिल है, जिसमें सरकार के सभी स्तरों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, वाणिज्यिक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, विशेष प्रयोजन वाहनों, पूंजी बाजार के खिलाड़ियों, विकास वित्तीय संस्थानों और विदेशी निवेशकों सहित कई हितधारकों की भागीदारी है। संसाधन जुटाने के साधन कई हैं, जैसे कि ऋण, बांड, इक्विटी, म्यूचुअल फंड जैसे हाइब्रिड साधन, विदेशी पूंजी प्रवाह और इनविट्स और आरईआईटीएस जैसे साधन। निम्नलिखित कुछ मुद्दे हैं जो ध्यान देने योग्य हैं:

क. एक सामान्य मुद्दा वित्तपोषण के विभिन्न स्रोतों में अलग-अलग रिपोर्टिंग प्रारूपों और क्षेत्रीय विभाजनों के बारे में है। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए आवश्यक विस्तृत जानकारी सीजीए एवं सीएण्डएजी द्वारा बनाए गए व्यय के वस्तु शीर्षों से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन प्रकाशित नहीं की जाती है। हालांकि, क्षेत्रीय वित्तीय प्रवाह पर ऐसी विस्तृत जानकारी लगभग सभी अन्य स्रोतों के लिए प्राप्त करना कठिन है। इसके अलावा, बैंक ऋण की जानकारी पूंजी बाजार प्रवाह, बाहरी वाणिज्यिक उधार और एफडीआई डेटा की तुलना में एक अलग प्रारूप में रिपोर्ट की जाती है। रिपोर्टिंग की आवधिकता और यहां तक कि प्रयुक्त 'अवसंरचना' शब्द की परिभाषा भी अलग-अलग है। कुछ डेटा, जैसे बैंक ऋण पर डेटा, केवल एक विशेष तिथि पर बकाया आंकड़े के रूप में उपलब्ध हैं।

ख. सरकारी स्रोतों के बीच, स्थानीय स्व-सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय पर उपलब्ध जानकारी काफी अपर्याप्त है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का शहर वित्त पोर्टल शहरी स्व-सरकारों के वित्त पर जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी तरह, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बनाए रखा गया ई-ग्रामस्वराज पोर्टल, ग्रामीण स्व-सरकारों के वित्त पर एक उभरता हुआ स्रोत है। हालाँकि, क्षेत्रीय विभाजन के साथ पूंजीगत व्यय की जानकारी इन पोर्टलों से अच्छी स्थिति में उपलब्ध नहीं है।

29 एसएएफ, एलसीएएफ और अन्य विमानन स्वच्छ ऊर्जा, संबंधित सहायता और वित्त, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, 2023 पर वैश्विक ढांचे पर विचारों पर कार्य पत्र - https://tinyurl.com/yck3bwbs

ग. राज्य सरकारों द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसईज़) को बजटीय सहायता की जानकारी सीएण्डएजी रिपोर्ट में उपलब्ध है। हालांकि, सार्वजनिक उपक्रमों से अवसंरचना में धन प्रवाह के बारे में जानकारी का कोई तैयार स्रोत नही है।

घ. निजी निगमों (और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों) द्वारा पूंजीगत व्यय पर जानकारी का एक संपूर्ण स्रोत एमसीए डेटाबेस है। हालांकि, कंपनियों द्वारा पर्याप्त डेटा फाइलिंग केवल एक अंतराल के बाद ही उपलब्ध हो पाती है, जिसके लिए किसी भी एकत्रीकरण का प्रयास करने से पहले कठोर स्थिरता जांच की भी आवश्यकता होती है।

ङ. विभिन्न अवसंरचना के वित्तपोषण स्रोतों के बीच धन के प्रवाह के कई रूप हैं, जो सभी स्रोतों के सरल एकत्रीकरण को काफी हद तक निरर्थक बना देता है। इस तरह के वित्तीय प्रवाह सरकार के विभिन्न स्तरों, सरकारों और उनके सार्वजनिक उद्यमों, बैंकों और एनबीएफसी आदि के बीच होते हैं। इसलिए, वित्तीय प्रवाह की दोहरी गणना से बचने के लिए विभिन्न डेटासेट की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता होती है।

12.69. **अवसंरचना की परियोजनाओं में भौतिक प्रगति की पूरी तस्वीर का अभाव:** पिछले दशक में सरकार की ओर से ऐसे संस्थानों और संरचनाओं का निर्माण करने के लिए गंभीर प्रयास किए गए जो अवसंरचना में प्रगति की निगरानी करते हैं और बाधाओं को दूर करते हैं। इन उपायों पर चर्चा इस खंड में की गई है। हालाँकि, ऐसा कोई एकल स्रोत नहीं है जो देश में विभिन्न स्तरों पर किए गए बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की सूची देता हो ताकि संबंधित लक्ष्यों के मुकाबले क्षेत्रवार और उप-क्षेत्रवार प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। इस सीमा को पार करने के लिए केंद्र, राज्य और सरकार के तीसरे स्तर के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और निजी भागीदारों सहित परियोजना प्राधिकरणों के साथ काम करते हैं।

सुविधा प्रदान करना और बाधाओं को दूर करना

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी)

12.70. यह पोर्टल मंत्रालयों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सभी प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को एक ही स्थान पर एकत्रित करने का अवसर प्रदान करता है, इस प्रकार यह सभी आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना उप-क्षेत्रों में परियोजना प्रगति को ट्रैक करने और समीक्षा करने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल के रूप में कार्य करता है। यह पोर्टल परियोजना-प्रायोजक प्राधिकरणों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने में भी सक्षम बनाता है।

12.71. सरकार ने देश भर में उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2020-2025 के दौरान लगभग ₹111 लाख करोड़ के अनुमानित अवसंरचना निवेश के साथ एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ एनआईपी शुरू किया।[30] एनआईपी में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड निवेश को कवर करते हुए प्रत्येक ₹100 करोड़ से अधिक की अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं। 12 अप्रैल 2024 तक, एनआईपी के तहत कुल पूंजीगत व्यय में से परिवहन क्षेत्र का योगदान 58 प्रतिशत है, इसके बाद ऊर्जा क्षेत्र का योगदान 24 प्रतिशत, जल एवं स्वच्छता क्षेत्र का योगदान 12 प्रतिशत है, तथा शेष पांच प्रतिशत सामाजिक अवसंरचना, संचार आदि जैसे अन्य क्षेत्रों का है।

12.72. एनआईपी में वर्तमान में 37 उप-क्षेत्रों (12 अप्रैल 2024 तक) को कवर करने वाली 9,666 से अधिक परियोजनाएं और योजनाएं हैं, जिन्हें इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड (एनआईपी-पीएमजी) एकीकृत पोर्टल के माध्यम से होस्ट और मॉनिटर किया जाता है। इन परियोजनाओं में से 4,413 परियोजनाएं (46 प्रतिशत) कार्यान्वयन के अधीन हैं, जबकि 2,062 परियोजनाएं (21 प्रतिशत) पूरी हो चुकी हैं।

30 टास्क फोर्स नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) की रिपोर्ट, 2020 - https://tinyurl.com/3j48tuhj

प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी)

12.73. पीएमजी 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं में मुद्दों और नियामक बाधाओं के शीघ्र समाधान के लिए एक संस्थागत तंत्र है। पीएमजी तंत्र परियोजना समर्थकों को संबंधित सरकारी एजेंसियों के समक्ष उन मुद्दों को उठाने की अनुमति देता है जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

12.74. पीएमजी ने ₹46.1 लाख करोड़ की लागत वाली 1,443 परियोजनाओं में 6,867 मुद्दों के समाधान की सुविधा प्रदान की है। पीएमजी पोर्टल ने मार्च 2024 तक ₹62.5 लाख करोड़ की लागत वाली 2,457 परियोजनाओं को शामिल किया है, जिसमें उच्च प्रभाव वाली पीएम गतिशक्ति परियोजनाओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा अंतराल परियोजनाओं सहित सभी महत्वपूर्ण मेगा बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ शामिल हैं।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस-एनएमपी)

12.75. पीएमजीएस-एनएमपी एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण है जिसे संबंधित मंत्रालयों के बीच सहयोग के माध्यम से मल्टीमॉडल अवसंरचना की एकीकृत योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनाया गया है। पीएमजीएस-एनएमपी को राज्य और केंद्र स्तर पर अंतिम-मील कनेक्टिविटी अंतराल का आकलन करने और लोगों और वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है। यह आर्थिक नोड्स के लिए मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की योजना बनाने के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है, जिससे लॉजिस्टिक्स दक्षता आती है।

12.76. मार्च 2024 तक, 43 मंत्रालयों को पीएमजीएस-एनएमपी पोर्टल पर शामिल किया गया है। मंत्रालयों और राज्यों के 1,530 डेटा लेयर (642 मंत्रालय डेटा लेयर और 888 राज्य डेटा लेयर) पीएमजीएस-एनएमपी पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। 16 मंत्रालयों के पास एक समर्पित पीएमजीएस सेल है जिसने परियोजना नियोजन को सुव्यवस्थित किया है। पोर्टल पर मैप किए गए 200 से अधिक डेटा लेयर के साथ 22 सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों को शामिल किया गया है। सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने राज्य स्तरीय संस्थागत तंत्र और राज्य मास्टर प्लान पोर्टल बनाए हैं और एनएमपी पर 533 परियोजनाओं की योजना बनाई गई है। पीएमजीएस-एनएमपी के केंद्रीय स्तरीय संस्थागत तंत्र नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने 149 परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन किया है, जिनकी कुल अनुमानित परियोजना लागत 13.3 लाख करोड़ रुपये है।

बॉक्स XII.25: एनएलपी का कार्यान्वयन गति पकड़ रहा है

लॉजिस्टिक्स अवसंरचना में सुधार पर भारत के फोकस के कारण विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में 139 देशों में भारत की रैंकिंग 2018 के 44वें स्थान से छह पायदान ऊपर चढ़कर 2023 में 38वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

सितंबर 2022 में पीएमजीएस-एनएमपी के पूरक के रूप में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सर्वोत्तम तकनीक और प्रक्रियाओं का लाभ उठाकर एकीकृत, कुशल, टिकाऊ और लागत प्रभावी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के माध्यम से व्यावसायिक

प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना, लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार करना और एक कुशल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के लिए डेटा-संचालित निर्णय समर्थन तंत्र बनाना है। एनएलपी को एक व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इनमें से प्रत्येक कार्य क्षेत्र के तहत प्रगति नीचे दी गई है:

i. **एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम:**

- एकीकृत लॉजिस्टिक्स एकीकृत प्लेटफॉर्म, एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म, जो आठ मंत्रालयों में 36 लॉजिस्टिक्स-संबंधित डिजिटल सिस्टम/पोर्टल को एकीकृत करता है और 1,800 डेटा फील्ड पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है, विकसित किया गया है।
- भारत के कंटेनरीकृत एक्सिम कार्गो के 100 प्रतिशत पर नजर रखने के लिए, एक लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक विकसित किया गया है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी), आईओटी और बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करता है और इसे भारत के 28 पोर्ट टर्मिनलों, 95 से अधिक टोल प्लाजा, 407 कंटेनर फ्रेट स्टेशन/अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और खाली यार्ड, 56 SEZs तीन एकीकृत चेक पोस्ट के साथ एकीकृत किया गया है।

ii. **सेवा गुणवत्ता मानक:** भारतीय मानक ब्यूरो और वेयरहाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा जारी मौजूदा मानकों को रेखांकित करते हुए वेयरहाउसिंग मानकों पर एक ई-बुक विकसित की गई है।

iii. **क्षमता निर्माण:** लॉजिस्टिक्स और पीएमजीएस-एनएमपी पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को केंद्रीय और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों के साथ एकीकृत किया जा रहा है।

iv. **राज्य की भागीदारी:** राज्य स्तर पर नीतिगत फोकस देने के लिए राज्य एनएलपी के साथ संरेखित राज्य लॉजिस्टिक्स योजनाएं विकसित कर रहे हैं। 26 राज्यों ने अपनी राज्य लॉजिस्टिक्स नीतियों को अधिसूचित किया है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक वार्षिक "लॉजिस्टिक्स ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (एलईएडीएस)" सर्वेक्षण भी किया जाता है।

v. **एक्जिम लॉजिस्टिक्स:** एक्जिम लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करने के लिए, राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति (एनसीटीएफ) द्वारा विकसित कार्य योजनाओं के माध्यम से अवसंरचना की कमियों को दूर किया जाता है। एनसीटीएफ कार्य समूहों ने राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना 2020-23 तैयार की। 2024-26 के लिए कार्य योजना विकसित की जा रही है।

vi. **सेवा सुधार ढांचा:** 30 से अधिक व्यापारिक संघों की भागीदारी के साथ सेवा सुधार समूह की स्थापना की गई है। ई-लॉग्स प्लेटफॉर्म पर संघों द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते हैं।

vii. **कुशल लॉजिस्टिक्स के लिए क्षेत्रीय योजनाएँ:** इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स क्षेत्र, विशेष रूप से बल्क और ब्रेकबल्क कार्गो की जरूरतों और चुनौतियों का समाधान करना है। कोयला लॉजिस्टिक्स योजना और नीति फरवरी 2024 में शुरू की गई थी। 2022 में व्यापक बंदरगाह संपर्क योजना तैयार की गई थी, जिसमें बंदरगाहों, रेलवे, सड़क मार्ग और अंतर्देशीय जलमार्गों के बीच संपर्क को मजबूत करने के लिए 107 बंदरगाह परियोजनाओं की पहचान की गई थी।

viii. **लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास की सुविधा:** मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा की जा रही है

निष्कर्ष और दृष्टिकोण

12.77. पिछले दशक में भारत के अवसंरचना के परिदृश्य में सुविधापूर्ण संस्थागत वास्तुकला और अवसंरचना की संपत्तियों की गुणवत्ता और स्टॉक के संदर्भ में परिवर्तनकारी बदलाव आए हैं। सड़क, रेल और हवाई संपर्क, स्वच्छता और डिजिटल अवसंरचना पर लगातार ध्यान केंद्रित करने से इन क्षेत्रों में संपत्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

12.78. हालांकि, भारत में अवसंरचना के निर्माण के प्रयास मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व में हैं। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब और विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटर 2023 के अनुसार, अवसंरचना में भारत का निवेश बड़े पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा वित्त पोषित किया गया था – जिसमें सरकारी एजेंसियां और राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाएं और बैंक शामिल हैं।[31] वित्तीय वर्ष 2019 और 2023 के बीच, केंद्र और राज्य सरकारों ने क्रमशः कुल निवेश में 49 प्रतिशत और 29 प्रतिशत का योगदान दिया, जबकि निजी क्षेत्र ने 22 प्रतिशत का योगदान दिया।[32]

12.79. भारत को गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना के निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो निजी क्षेत्र के वित्तपोषण का उच्च स्तर और नए स्रोतों से संसाधन जुटाना महत्वपूर्ण होगा। इसे सुगम बनाने के लिए न केवल केंद्र सरकार से नीतिगत और संस्थागत समर्थन की आवश्यकता होगी, बल्कि राज्य और स्थानीय सरकारों को भी समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हमें दिखाता है कि उप-राष्ट्रीय स्तर पर पहल कैसे अवसंरचना के विकास के लिए संसाधन जुटाने में मदद कर सकती है। उदाहरणों में नगरपालिका परियोजनाओं[33] के लिए पूल किए गए वित्तपोषण तंत्र, विशेष नगरपालिका मध्यस्थ,[34] परिसंपत्ति पुनर्चक्रण कार्यक्रम,[35] कर वृद्धि वित्तपोषण[36] और भूमि बिक्री और विकास अधिकार[37] जैसे अन्य अभिनव दृष्टिकोण शामिल हैं। प्रत्येक उपाय का व्यापक-आधारित कार्यान्वयन देखा गया, जिससे महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाने में सफलता मिली।

12.80. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विभिन्न परियोजनाओं में इसके संयोजन के साथ-साथ विभिन्न उपकरणों और क्षेत्रों में अवसंरचना में निवेश के लिए डेटा कैप्चर और रिपोर्टिंग तंत्र में सुधार की आवश्यकता है। अवसंरचना के सांख्यिकी पर रंगराजन आयोग की रिपोर्ट (2001) ने अवसंरचना के क्षेत्र के लिए एक विश्वसनीय सांख्यिकीय डेटाबेस एकत्र करने और बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया था। तब से नीति दिशा, संस्थागत ताकत, परियोजना प्रदर्शन और निगरानी पर डेटा एकत्र करने के लिए प्रमुख प्रगति की गई है। हालांकि, कुछ प्रमुख क्षेत्रों में डेटा अंतराल अभी भी बना हुआ है।

क. मौजूदा डेटाबेस अवसंरचना की मांग का आकलन करने और उप-क्षेत्रों में निर्मित सुविधाओं के उपयोग को ट्रैक करने में कम पड़ते हैं। मांग एकत्रीकरण उप-क्षेत्रों और क्षेत्रों के आधार पर अवसंरचना परियोजनाओं की मांग के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है, जबकि उपयोग दरों को ट्रैक करने वाले एक सूचकांक का निर्माण उन उप-क्षेत्रों पर प्रकाश डालेगा जहां आवश्यक अवसंरचना सुविधाओं की अधिक आपूर्ति या कमी है। इन दो अंतरालों को संबोधित करने से नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों को दुर्लभ संसाधनों को इष्टतम रूप से आवंटित करने में सक्षम बनाने के लिए अतिरिक्त नैदानिक उपाय प्रदान किए जा सकते हैं।

---

31 इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटर 2023: इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश के वैश्विक रुझान, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब

32 क्रिसिल इंफ्रास्ट्रक्चर ईयरबुक 2023

33 यूनाइटेड स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का म्यूनिसिपल पूल्ड फाइनेंसिंग: अनुभव और सबक, विश्व बैंक समूह, जून 2017. म्यूनिसिपल बॉन्ड बैंक छोटी नगरपालिकाओं को सामूहिक रूप से वित्तीय बाजारों तक पहुंचने की अनुमति देता है, जिससे उधार ली गई निधियों की लागत कम हो जाती है।

34 म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए अभिनव दृष्टिकोण, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी (वियतनाम के अनुभव पर आधारित)। स्थानीय विकास निवेश निधि प्रांतीय सरकारों के लिए धन जुटाने और निजी क्षेत्र के साथ अनुबंध करने के लिए परिचालन और कानूनी साधन हैं।

35 मजबूत क्षेत्र-विशिष्ट पाइपलाइन प्रभावी परिसंपत्ति-पुनर्चक्रण कार्यक्रम को सक्षम बनाती है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब, नवंबर 2015 (ऑस्ट्रेलियाई अनुभव पर आधारित। यह तंत्र राज्य सरकार को सार्वजनिक परिसंपत्तियों को निजी क्षेत्र को बेचने और नए अवसंरचना के विकास के लिए आय का उपयोग करने की अनुमति देता है।

36 टैक्स इंक्रीमेंट फाइनेंसिंग के उपयोग पर रिपोर्ट, गवर्नर के नियोजन और अनुसंधान कार्यालय, कैलिफोर्निया राज्य, दिसंबर 2020 के लिए तैयार की गई। यह पुनर्विकास, अवसंरचना और अन्य सामुदायिक-सुधार परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली सब्सिडी है।

37 मरीना बे में व्यवसाय और वित्तीय जिले का विकास, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, 2016 (सिंगापुर के अनुभव के आधार पर)। स्थानीय सरकार ने जमीन के टुकड़े बेचे और निजी प्रतिभागियों को आवासीय, वाणिज्यिक और मिश्रित-उपयोग विकास के लिए विकास अधिकार दिए।

ख. वर्तमान में, अवसंरचना के क्षेत्र के आँकड़े कई उपलब्ध डेटाबेस जैसे कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, पीपीपी इंडिया पोर्टल, बजट खातों के प्रमुख और संबंधित अवसंरचना केंद्रित मंत्रालयों की रिपोर्ट, केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निधि प्रवाह और गैर–सरकारी संस्थानों जैसे कि बैंक, एनबीएफसी और पूंजी बाजार से अवसंरचना के क्षेत्र में वित्तीय प्रवाह से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये डेटाबेस परियोजना स्तर पर अवसंरचना के आँकड़ों का आकलन करने और क्षेत्रीय स्तर पर वित्तीय प्रवाह को ट्रैक करने के लिए उपयोगी हैं। हालाँकि, जब मैक्रो–लेवल अवलोकन के लिए हार्मोनाइज्ड लिस्ट (एचएमएल) वर्गीकरण के आधार पर समय के साथ अवसंरचना के खर्च और विकास का आकलन करने का प्रयास किया जाता है, तो ये डेटाबेस डेटा संग्रह की आवृत्ति में निरंतरता की कमी, अपनाई गई कार्यप्रणाली में एकरूपता की कमी और संस्थानों के बीच क्रॉस फंड प्रवाह के कारण कम पड़ जाते हैं जिससे दोहरी गिनती हो सकती है। इससे विभिन्न स्रोतों से डेटा की तुलना करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए, आगे बढ़ते हुए, यह उपयोगी होगा यदि एचएमएल वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न स्रोतों से अवसंरचना के विकास और वित्तीय प्रवाह के डेटा को एक ही एक्सेस पॉइंट के तहत समेकित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाए, जिसे नियमित आवृत्ति पर अपडेट किया जाता है। यदि समेकित आंकड़े सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन के साथ दर्ज किए जाएं तो यह नीति निर्माताओं के लिए भी उपयोगी होगा।

****

जलवायु परिवर्तन और भारतः हमें इस समस्या को अपने नजरिए से क्यों देखना चाहिए

13

अध्याय

मानवजनित जलवायु परिवर्तन से निपटना शीर्ष वैश्विक प्राथमिकता के रूप में उभरा है, तथा बहुपक्षीय निकाय, विशेषज्ञ और मीडिया दुनिया भर के देशों से आह्वान कर रहे हैं कि वे बहुत देर होने से पहले 'जलवायु आपदा' को कम करने के लिए प्रयास करें। सामूहिक प्रयास में भाग लेते हुए भारत ने पिछले दशक में बड़ी प्रगति की है, फिर भी इसे दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषकों में से एक माना जाता है और पर्याप्त कदम न उठाने के लिए अक्सर इसकी आलोचना की जाती है। हालाँकि, भारतीय दृष्टिकोण की आलोचना दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने में विफल रही है ।पहला, भारत को अपने विकासशील समकक्षों की तरह ही आर्थिक विकास के साथ-साथ सार्थक जलवायु कार्रवाई में संतुलन बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, और दूसरा, जलवायु परिवर्तन के लिए प्रस्तावित समाधान, जो भारत की आलोचना का आधार बनते हैं, इस बात की अनदेखी करते हैं कि भारतीय जीवनशैली में संधाराणीय जीवन शैली को कैसे शामिल किया गया है।

जीविका के सिद्धांतों में निहित, भारत का लोकाचार प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध पर जोर देता है, जो विकसित दुनिया के अन्य हिस्सों में प्रचलित अति उपभोग के बिल्कुल विपरीत है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के समाधान बाजार समाज के सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो अति उपभोग को कम करने के स्थान पर अति उपभोग को प्राप्त करने के साधनों को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। इस प्रकार, ऐसा दृष्टिकोण उनकी जीवनशैली में बदलाव लाने के बजाय उस लेबल को महत्व देता है जिसके तहत उनकी जीवनशैली जारी रह सकती है।

पिछले कुछ वर्षों में, इससे नीतियों में पृथ्वी के लिए अनिश्चित परिणाम रखने वाला एक झुकाव उत्पन्न हुआ है। यदि भारत, अपनी बड़ी आबादी के साथ, इस रास्ते पर चलने का विकल्प चुनता है, तो देश और दुनिया के लिए जलवायु परिणाम बेहद नकारात्मक होंगे। इसलिए, यदि भारत को आर्थिक विकास के माध्यम से अपने नागरिकों को सशक्त बनाना है और साथ ही जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का भी समाधान करना है, तो उसे अपना स्वयं का रास्ता अपनाना होगा और समस्या को अपने नजरिए से देखना होगा।

इन विचारों ने 'मिशन लाइफ' की नींव रखी, जो 2021 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एक अनूठी पहल है। 'मिशन लाइफ' का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में व्यक्तिगत जिम्मेदारी को सबसे आगे लाना है। प्राचीन भारतीय दर्शन से प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर, इस दृष्टिकोण वाले सिद्धांत जीवन की गुणवत्ता से समझौता किए बिना पृथ्वी के अनुकूल विकल्प बनाने पर आधारित हैं। यह वर्तमान में सोच-समझकर चुनाव करने तथा आने वाली पीढ़ियों के प्रति सचेत रहने के बारे में है। मिशन लाइफ का उद्देश्य लोगों की 'इच्छाओं' का समाधान उन्हें ऐसी 'जरूरतों' में बदले बिना करना है जिनको पूरा करने से प्रकृति को हानि पहुंच सकती है।

परिचय

माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः
पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ

13.1 संपोषण भारतीय लोकाचार का मूल है। यह सिद्धांत प्रकृति, अन्य लोगों, भौतिक वस्तुओं और स्वयं के साथ हमारे संबंधों का आधार है। आज की दुनिया में ऐसे लोकाचार को मान्य करना और उसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अब एक नए चमकदार आवरण और सीमित दायरे में इसके सम्मुख है, विडंबना यह है कि यह दायित्व दुनिया के उस हिस्से से आया है जो अन्यथा विकास के मार्ग के रूप में अति उपभोग पर निर्भर रहा है। जबकि विश्व भर में संधारणीयता के लिए आवाज उठ रही है, भारत स्वयं को इस बात पर आश्चर्यचकित पाता है कि उसे आर्थिक रूप से उसी बात पर ध्यान देना होगा, जिस पर वह हमेशा से दार्शनिक दृष्टि से विश्वास करता रहा है और जिसका वह अभ्यास करता रहा है।

13.2. विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। स्वाभाविक रूप से, इसका अर्थ यह है कि अगले 30 वर्षों[1] में हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं वैश्विक औसत से लगभग 1.5 गुना तेजी से बढ़ने की संभावना है। देश के सामने मौजूद कार्य और अब तक प्राप्त उपलब्धियों (बॉक्स XIII.1) की सराहना करने के बजाय, भारत को सबसे बड़े प्रदूषणकर्ताओं[2] में से एक कहा जा रहा है, तथा और अधिक कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि इस दिशा में विश्व का एक बड़ा हिस्सा बहुत कम कार्य कर रहा है।

बॉक्स XIII.1: जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों के सापेक्ष भारत की उपलब्धियाँ

- 2005 और 2019 के बीच सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में उत्सर्जन तीव्रता को 33% तक सफलतापूर्वक कम किया, इस प्रकार 2030 के लिए प्रारंभिक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी लक्ष्य को निर्धारित समय से 11 साल पहले हासिल किया।
- गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों के माध्यम से 40% विद्युत स्थापित क्षमता भी हासिल की, जो 2030 के लक्ष्य से नौ साल पहले है। 2017 और 2023 के बीच, भारत ने लगभग 100 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता को जोड़ा है, जिसमें से लगभग 80% में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों का योगदान है।
- भारत का जलवायु कार्रवाई में योगदान उसके अंतर-राष्ट्रीय प्रयासों जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा रोधी अवसंरचना के लिए संघ (सीडीआरआइ), लीडआईटी का सृजन, प्रतिस्कंदी द्वीपीय राज्यों के लिए अवसंरचना (आईआरआईएस), और बिग कैट एलायंस के माध्यम से महत्वपूर्ण रहा है।

13.3. जलवायु परिवर्तन को विश्व के लिए नया ध्रुव तारे जितना स्थायी मानते हुए, अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि 196 देशों को कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' के तहत अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होगा ताकि 'वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सके'[3]। चूंकि वैश्विक स्तर पर सभी सुविचारित प्रयास इस कृत्रिम स्वर्णिम उपाय को प्राप्त करने के लिए बहुमूल्य संसाधनों को दिशा देने पर केंद्रित हैं, तथा इस बात का स्पष्ट विचार नहीं है कि ऐसा न होने पर क्या होगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है - 'कि क्या अपनाई गई रणनीति इष्टतम तथा सभी के हित में है?'

13.4. इस लेख का उद्देश्य तीन खंडों के अंतर्गत इस विचित्र स्थिति की जांच करना है - जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक तौर तरीकों का मूल्यांकन, वैश्विक रणनीति में अंतर्निहित असंगति, और अस्तित्व के प्रमुख सिद्धांतों (मिशन लाइफ) पर केंद्रित एक पूरक लेकिन अधिक संधारणीय रणनीति की आवश्यकता।

जलवायु परिवर्तन और वैश्विक दृष्टिकोण

13.5. जैसा कि इस साहित्य में कहा गया है, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन में मुख्य रूप से योगदान करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी)[4] ने एक भयावह तस्वीर पेश की है कि उत्सर्जन एक गंभीर खतरा पैदा करता है, क्योंकि एक बार वायुमंडल में छोड़ी गई CO_2, 300 से 1000 वर्षों[5] तक निलंबित रह सकती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और ध्रुवीय बर्फ के पिघलने जैसी पर्यावरणीय विनाश की आशंका बनी रहती है।

13.6. उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, विश्व ने एक रणनीति अपनाई है जिसमें विभिन्न समाधानों का एक समूह शामिल है, जिसे लोकप्रिय रूप से 'जलवायु अनुकूलन' और 'जलवायु शमन' कहा जाता है। इसमें अधिकांशत: जीवाश्म ईंधन के इतर अन्य ऊर्जा स्रोतों की ओर रुख करना, नवीन और पर्यावरण अनुकूल डिजाइन के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना, पुनर्योजी

1 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी

2 जलवायु आपदा को रोकने में भारत की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, येल क्लाइमेट कनेक्शन्स, मई 2024 (https://tinyurl.com/yfvvahws)

3 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP21) में 196 पक्षकारों द्वारा अपनाया गया पेरिस समझौता, दिसंबर 2015

4 जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल की छठी आकलन रिपोर्ट (आईपीसीसी एआर 6) में कहा गया है, "मानव-जनित जलवायु परिवर्तन पहले से ही कई मौसमी और जलवायु संबंधी चरम सीमाओं को प्रभावित कर रहा है। इससे खाद्य और जल सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्थाओं और समाज पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है" यदि हम तापमान वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप होने वाली पर्यावरणीय क्षति को सीमित करना चाहते हैं, तो CO_2 की अर्धायु तथा पहले से हो चुकी क्षति के निवारण के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है।

5 द एटमोस्फीयर : गैटिंग अ हैंडल ऑन कार्बन डाइऑक्साइड, एलन बुइस, नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला, अक्टूबर 2019 (https://tinyurl.com/4hjfzxev)

और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील कृषि पद्धतियों को अपनाना और साथ ही प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा और पुनर्स्थापना करना शामिल है (बॉक्स XIII.2 देखें)।

बॉक्स XIII.2: डब्ल्युईओ आउटलुक -2023, 2030 तक दुनिया को पटरी पर लाने के लिए एक वैश्विक रणनीति का प्रस्ताव करता है

इस प्रस्ताव के पांच प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

- वैश्विक अक्षय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करना।
- ऊर्जा दक्षता सुधार की दर को दोगुना करना।
- जीवाश्म ईंधन परिचालन से होने वाले मीथेन उत्सर्जन में 75 प्रतिशत की कमी लाना।
- उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में स्वच्छ ऊर्जा निवेश को तीन गुना करने के लिएनवोन्मेषी, बड़े पैमाने पर वित्तपोषण तंत्र स्थापित करना।
- जीवाश्म ईंधन के उपयोग में क्रमबद्ध कमी सुनिश्चित करने के उपाय करना, जिसमें कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को नए अनुमोदन पर रोक लगाना शामिल है।

वर्तमान दृष्टिकोण दोषपूर्ण क्यों है?

13.7. उत्सर्जन को सीमित करने के तरीकों का अभिकल्प सूचित करने के लिए, आईपीसीसी ने उपलब्ध शेष कार्बन स्पेस को ष्कार्बन बजटष् के रूप में प्रमात्रिकृत किया है। उनके अनुमानों के अनुसार, 2020 की शुरुआत से, दुनिया में 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के लिए लगभग 500 GtCO2 और 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के लिए 1150 GtCO2 (क्रमश: 50% और 67% की संभावना के साथ) शेष है। प्रत्येक बीतते वर्ष के साथ यह बजट छोटा होता जाता है, तथा कार्य करने के लिए उपलब्ध समय हाथ से निकलता जाता है। इसके बाद राष्ट्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे विकासात्मक मांगों की कड़ी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ते हुए ष्वरित और न्यायसंगत शमन मार्गोष के प्रति प्रतिबद्ध हों। यह आशंका काफी भयावह लगती है, क्योंकि आईपीसीसी ने कहा है कि, ष्सभी के लिए एक रहने योग्य और संधारणीय भविष्य सुरक्षित करने का अवसर तेजी से समाप्त हो रहा हैष। ऐसी आशंकाओं के बावजूद, कथित जलवायु समाधान में कुछ बुनियादी मुद्दे हैं।

जीवन के नियमों की अल्प सैद्धांतिक समझ

13.8. जीवन केवल उसी रूप में मौजूद है जैसा कि हम आज जानते हैं। इसलिए, कोई भी रणनीति जो मानव-निर्मित कार्यों को अपने आप में ही संपूर्ण समाधान मानने लेकर को भ्रमित करती है, वह अत्यंत अदूरदर्शी प्रकृति की होती है। मूलत:, हम इस वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हम प्रकृति से आये हैं, और जीवन के लिए आवश्यक प्रणालियों को अनिवार्यत: प्रकृति और जीवन के जैविक प्रवाह से जुड़ा होना चाहिए। कोई भी कृत्रिम व्यवस्था पूरी तरह से काम करने योग्य प्रणाली नहीं होती है, क्योंकि हम विनिर्माण प्रक्रियाओं के साथ चाहे जितनी भी चतुराई से छेड़छाड़ कर लें, दो सरल सिद्धांत सर्वोपरि रहते हैं- 1) मनुष्य कोई नया तत्व नहीं बना सकते हैं, प्रकृति के किसी भी नियम को नहीं बदल सकते हैं, और कोई ऐसी प्रक्रिया को संश्लेषित नहीं कर सकते जो पर्यावरण को प्रभावित न करे। 2) अस्तित्व के मूल सिद्धांत हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को ऑक्सीजन, पानी और भोजन उसी रूप में चाहिए होगा जिस रूप में हम उसे जानते हैं। फिर भी, हम अपने और अन्य प्रजातियों के लिए इन्हें नष्ट करते जा रहे हैं। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनाई गई रणनीति बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त है।

13.9. भौगोलिक, आर्थिक और जलवायु संबंधी दृष्टिकोण से भिन्न देशों के लिए जलवायु परिवर्तन कार्यनीतियां स्वीकार्य अधिदेशों में चिरकालिक बनी हुई है। क्रॉस-लर्निंग के अभाव में, सतत विकास से संबंधित बहुत से प्राकृतिक विचारों, जैसे उपभोग पैटर्न, जीवन शैली, शाकाहार बनाम मांस आधारित आहार, आदि को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

13.10. वैश्विक स्तर पर, बिजली और परिवहन उद्योगों का जीएचजी उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान है, इसके बाद औद्योगिक दहन, कृषि और अपशिष्ट उद्योग हैं। परवर्ती घटकों में बीफ की खपत में प्रति किलोग्राम खाद्य उत्पाद में सबसे अधिक उत्सर्जन होता है जैसा कि तालिका XIII.1 में दर्शाया गया है। इसके बावजूद, बदलाव की कोई मांग नहीं की गई है, अधिदेश तो दूर की बात है।

चार्ट XIII.1: विभिन्न खाद्य उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (2018)

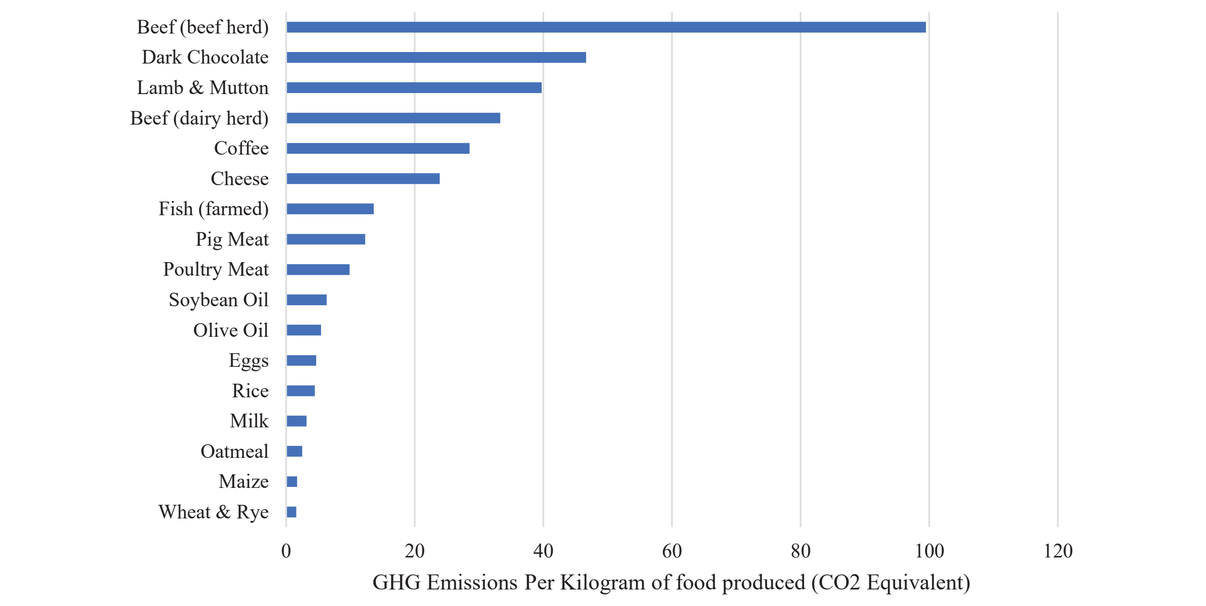

स्रोतः पूअरे, जे., और नेमेसेक, टी. (2018)। उत्पादकों और उपभोक्ताओं के माध्यम से भोजन के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना। साइंस, 360(6392), 987-992.– आवर वर्ल्ड इन डेटा द्वारा संसाधित (https://tinyurl.com/3xja4ajs)

13.11. संपूर्ण विकसित दुनिया हर दिन, कई बार, सबसे नियमित शारीरिक गतिविधि के लिए 'वर्जिन वुड' से बने टॉयलेट पेपर का उपयोग करती है। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक स्थिरता ब्लॉगों में से एक 'ट्रीहगर' बताता है कि 'टॉयलेट पेपर का एक रोल बनाने में 1.5 पाउंड लकड़ी[6], 37 गैलन पानी और 1.3 किलो वाट घंटा बिजली का उपयोग होता है। कई एशियाई देश इनके बारे में मूल्यवान सबक देते हैं, फिर भी उनकी गैर-पूंजीवादी रणनीतियाँ अक्सर मुख्यधारा की चर्चाओं से बाहर ही रहती हैं क्योंकि व्यवहार और जीवनशैली में बदलाव जलवायु परिवर्तन से अधिक कठिन लगता है।

13.12. पुरुष और प्रकृति (सांख्य परम्परा में पुरुष और प्रकृति के स्थूल रूप) अविनाशी सत्ताएं हैं जो वास्तविकता के रूप में चेतना को अर्थ प्रदान करने के लिए परस्पर क्रिया करती हैं, जैसा कि हम जानते हैं। इसलिए, कोई भी रणनीति जिसका उद्देश्य मनुष्य की समझ या नियंत्रण से परे चीजों को बदलना है, जैसे कि यह सुनिश्चित करना कि धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो, उसे बाहर की ओर नहीं, बल्कि भीतर की ओर यात्रा करनी होगी।

अस्तित्व की परस्पर संबद्ध प्रकृति की अनदेखी करना

13.13. जलवायु प्रकृति की वास्तविकता है जो इस तरह से अंतर्निहित रूप में अंतर्संयोजित है कि विज्ञान अभी तक इसकी बारीकियों को नहीं खोज पाया है। हैरानी की बात है कि हमारे स्वीकृत मार्ग इस अपरिहार्य वास्तविकता को अनदेखा करते हुए अलग-अलग समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो प्राकृतिक मूल्य श्रृंखलाओं से एकीकृत नहीं हैं। इसका एक उदाहरण जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा में ऊर्जा का प्रतिस्थापन है।

13.14. एक संसाधन की अपेक्षा दूसरे संसाधन के लिए पृथ्वी से निष्कर्षण करने वालों के बीच मूलतः कोई असमानता नहीं होती है। सौर पैनल अक्षय ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन सौर बैटरी पृथ्वी की ऊपरी तह[7] से निकाले गए पदार्थों से बनती हैं, विशेष

6 स्टॉप यूजिंग टॉयलेट पेपर ;गेट द ब्लू बिडेट,, ट्रीहगर, अक्टूबर 2018 (ीजजचेः//जपदलनतस.बवउ/3तउग्र8द)

7 निकाले गए अधिकांश खनिज, कठोर चट्टान की खदानों या भूमिगत खारे पानी के भण्डारों से, एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से निकाले जाते हैं, जिसके लिए CO_2 उत्सर्जित करने वाले जीवाश्म ईंधनों से उत्पन्न ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

रूप से लिथियम, कोबाल्ट, निकल और कुछ दुर्लभ पृथ्वी खनिजों से।[8] कुछ अनुमानों के अनुसार[9], इससे न केवल 'पृथ्वी परिदृश्य पर बड़े निशान' रह जाते हैं, बल्कि इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जिससे प्रति टन खनिज से लगभग 15 टन CO_2 उत्सर्जित होती है।[10] निकाले गए अयस्क को उपयोगी रूप में लाने के लिए 800-1000 डिग्री सेल्सियस[11] के बीच तापमान की आवश्यकता होती है, विडंबना यह है कि इस तापमान को केवल जीवाश्म ईंधन को जलाकर ही लागत प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। (चार्ट XIII.2)

13.15. कोबाल्ट और कॉपर, जिनका उपयोग लिथियम-आयन बैटरियों, इलेक्ट्रिक वाहनों और मोबाइल फोन में बड़े पैमाने पर किया जाता है, उनके निष्कर्षण के मूल में एक गंभीर स्थायित्व संकट है। विश्व की कोबाल्ट आपूर्ति का लगभग 4/5वां हिस्सा एक ही देश में दबा हुआ है, जो विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है - कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (जिसे आगे कांगो कहा गया है) । देश के लगभग 80% कोबाल्ट उत्पादन पर चीनी कंपनियों का नियंत्रण है, जो चीन में इसका शोधन करती हैं और बाद में इसे विश्व स्तर पर बैटरी निर्माताओं को बेचती हैं। हार्वर्ड के टी.एच. चौन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के फेलो सिद्धार्थ कारा ने अपनी पुस्तक 'कोबाल्ट रेड' में बताया है कि कांगो में कोबाल्ट का अधिकांश निष्कर्षण 'कारीगर खनिकों' द्वारा किया जाता है - जो कि स्वतंत्र श्रमिकों के लिए एक नए युग का हानिरहित शब्द है, जो प्रतिदिन[12] कुछ डॉलर के बराबर वेतन पर खतरनाक खदानों में काम करते हैं। यह दुखद और विडंबनापूर्ण है कि यह सब टिकाऊ इलेक्ट्रिक वाहनों के नाम पर किया जा रहा है, जिनमें जीवाश्म ईंधन इंजन[13] की तुलना में 3.5 गुना अधिक तांबा हो सकता है।

चार्ट XIII.2: प्रणाली परिवर्तन की ऊर्जा तीव्रता

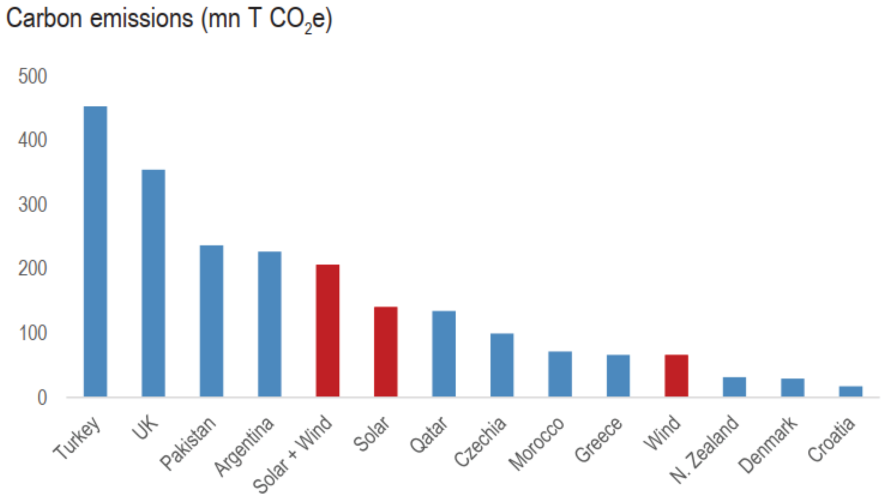

स्रोत: जे.पी. मॉर्गन वैश्विक ऊर्जा रणनीति: ऊर्जा संक्रमण (अप्रैल 2024), चित्र 8: संक्रमण की ऊर्जा तीव्रता, पृष्ठ 6

13.16. सौर पैनल और पवन चक्कियों जैसे 'स्वच्छ ऊर्जा' उत्पादों की उत्पादक मूल्य श्रृंखला, खनन से लेकर विनिर्माण, परिवहन, उपयोग से लेकर निपटान के अंतिम चरण तक फैली हुई है, इसमें अन्य ईंधनों की तरह ही उत्सर्जन प्रभाव होता है, जो सामग्री और यात्रा की गई दूरी पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, इसमें दशकों से बनी मौजूदा आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और नए रास्ते बनाना शामिल है, जिसमें पर्यावरण संबंधी भारी बाहरी प्रभाव शामिल हैं, जैसे कि निष्कर्षण, परिवहन, नई भूमि से जुड़ी नई फैक्ट्रियों की स्थापना, मशीनरी उत्पादन, सहायक विकास, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं तक मोबाइल अक्षय इकाइयों का परिवहन, जिससे मौजूदा बुनियादी ढांचे और रास्ते बेकार हो जाते हैं।

8 उनके उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कुछ चुम्बकों में नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन (NdFeB) और सैमरियम कोबाल्ट (SmCo) जैसे दुर्लभ पृथ्वी खनिज शामिल हैं। वे शब्द के वास्तविक अर्थ में 'दुर्लभ' नहीं हैं, लेकिन पृथ्वी की पपड़ी में प्रचुर मात्रा में हैं। हालाँकि, चूँकि वे अन्य सामान्य रूप से निकाले जाने योग्य धातुओं की तुलना में अयस्कों में अपेक्षाकृत कम सांद्रता में पाए जाते हैं, इसलिए वे खनन और शोधन में महत्वपूर्ण कठिनाई पैदा करते हैं, जिससे फिर से पर्यावरण और स्थिरता को भारी नुकसान होता है

9 ग्रीन लिथियम के लिए नई 'गोल्ड रश', बीबीसी, नवंबर 2020 (https://tinyurl.com/mrjsuw9w)

10 लिथियम और भूतापीय ऊर्जा फर्म वल्कन एनर्जी रिसोर्सेज के लिए कच्चे माल विशेषज्ञ मिनविरो द्वारा किया गया विश्लेषण।

11 बैटरी निर्माण से कितनी CO_2 उत्सर्जित होती है?, एमआईटी क्लाइमेट पोर्टल, मार्च 2022 (https://tinyurl.com/pvbxkx44)

12 कांगो में 'आधुनिक दासता' कैसे रिचार्जेबल बैटरी अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करती है, एनपीआर, फरवरी 2023 (https://tinyurl.com/28nuum3e)

13 कांगो की कोबाल्ट खानों में, निकोलस नियार्कोस, द न्यूयॉर्क रिव्यू, दिसंबर 2023 (https://tinyurl.com/tfphf988)

13.17. उदाहरण के लिए - ईवी में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए पेट्रोल पंपों के मौजूदा नेटवर्क के उन्मूलन और उपरोक्त सभी को शामिल करते हुए चार्जिंग स्टेशनों का एक नया नेटवर्क बनाना आवश्यक है। दुर्भाग्य से, नवीकरणीय विकल्पों के साथ जीवाश्म ईंधन के विस्थापन की वकालत करते समय मौद्रिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इन सभी षछिपी हुई लागतों को जीवनचक्र लागतों में शामिल नहीं किया जाता है। उनका सबसे बड़ा 'जलवायु-अनुकूल' उत्सर्जन नियंत्रण केवल अंतिम उपयोगकर्ता उत्सर्जन में निहित है, जो विकल्पों में जलवायु लागतों की तुलना को अतुलनीय बनाता है।

13.18. इस बात पर पर्याप्त शोध नहीं हुआ है कि एंड-टू-एंड लाइफसाइकिल की लागत कितनी है। भूमि सीमित है, लेकिन मांग सीमित नहीं है। सौर ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा की तुलना में 300 गुना अधिक जगह की आवश्यकता हो सकती है और बायोमास को 8,000 गुना से अधिक की आवश्यकता हो सकती है।[14] साथ ही, पवन टरबाइन ब्लेड और सौर पैनलों को हर दो दशक में बदलना होगा, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से भारी अपशिष्ट की समस्याएँ हो सकती हैं। स्थान और अपशिष्ट संबंधी समस्याओं के अलावा, त्वरित प्रणाली परिवर्तन को रोकने वाली मुख्य चुनौती यह है कि सौर और पवन ऊर्जा जीवाश्म ईंधन की तुलना में केवल तभी सस्ती होती है जब सूर्य चमकता है और हवा चलती है। औद्योगीकरण और विकास के लिए 24/7 बिजली और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहां तक कि चार घंटे के भंडारण को ध्यान में रखते हुए भी सौर और पवन ऊर्जा सबसे सस्ती उपलब्ध ऊर्जा से गैस और कोयला ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक महंगी हो जाती है (चार्ट XIII.3)।

चार्ट XIII.3: भंडारण लागत से नवीकरणीय ऊर्जा जीवनचक्र लागत बढ़ती है

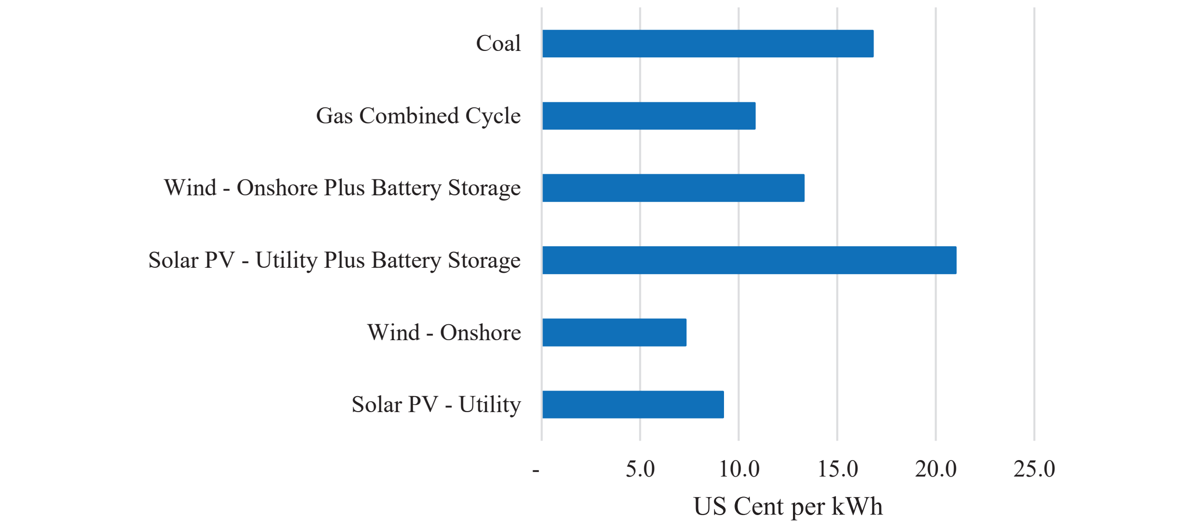

स्रोत : ऊर्जा की स्तरीकृत लागत तुलना - संस्करण 17.0, लाजार्ड लेव्लाइज्ड कास्ट ऑफ एनर्जी लागत+ जून 2024

13.19 इसके अलावा, मजबूती से विश्वसनीय बिजली प्रदान करने के लिए, अध्ययनों[15] से पता चलता है कि 100% सौर और पवन प्रणाली के लिए विशाल भंडारण क्षमता की आवश्यकता होगी, जो असंभव रूप से महंगी है। कुल मिलाकर, पवन टर्बाइन, सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, इलेक्ट्रिक वाहन और लिथियम-आयन बैटरी के उत्पादन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण स्थिरता मुद्दे हैं, जैसे कि कनफ्लिक्ट खनिजों का उपयोग, विषाक्तता, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों, कोबाल्ट और लिथियम की सीमित उपलब्धता या आपूर्ति श्रृंखला प्रयोग के मुद्दे[16]। रणनीति में जो शामिल नहीं है वह वास्तव में उतना ही उल्लेखनीय है जितना कि इसमें शामिल बातें है।

विहित प्रयोजन के लिए अपर्याप्त

13.20. आम बोलचाल में, ऊर्जा और शक्ति को अक्सर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि, उनका अंतर एक और कारक है जो जलवायु परिवर्तन रणनीति का पालन करना मुश्किल बनाता है: स्वतंत्र ऊर्जा विश्लेषक मैथ्यू एल वाल्ड ने

14 जलवायु कार्रवाई: हमारे ऊर्जा परिवर्तन को पूर्व निर्धारित मार्गों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, वी. अनंथा नागेश्वरन और ब्योर्न लोम्बर्ग, 21 फरवरी 2024 (https://tinyurl.com/5bv5272t)

15 फेकेटे, बी.एम., बेक्सको, एम., झांग, जे., और चेन, एम. (2023)। स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स टू मिटीगेट इंटरमिटेंट रिनुअबल एनर्जी सोर्सेज : एनलिसिस फॉर द यूएस नार्थईस्ट। फ्रंटियर्स इन एनवायरनमेंटल साइंस, 11, 1076830

16 ह्यूबर, एस. टी., और स्टीनिंगर, के. डब्ल्यू. (2022)। पवन और सौर बिजली उत्पादन के साथ-साथ भंडारण सुविधाओं संबंधी महत्वपूर्ण संधारणीयता और संभावित समाधान मुद्दे। जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन।

'द मिथ ऑफ सोलर पावर' में कहा

''नवंबर 2022 में, फ्रांस ने एक कानून पारित किया, जिसके अनुसार 80 या उससे ज़्यादा जगहों वाले सभी पार्किंग स्थलों की छतों पर कम से कम आधे स्थानों को कवर करने के लिए सौर पैनल लगाने होंगे। अनुमानों के अनुसार, इस पहल से 11 गीगावाट बिजली पैदा होगी - एक ऐसा परिमाण, जिसके बारे में ग्रिस्ट ने खुशी-खुशी बताया कि यह 8 मिलियन घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त होगी। वास्तव में, यह शून्य घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है।''

यदि आपके पास छत पर लगा एक छोटा - सा सौर पैनल है जो 50 वाट बिजली पैदा कर सकता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनरेटर कितनी देर तक चलता है या यह कितनी ऊर्जा पैदा करता है और संग्रहीत करता है - उदाहरण के लिए, गर्मियों में एरिजोना में बहुत धूप वाले दिन, यह 24 घंटे की अवधि में 300 वाट-घंटे या 0.3 किलोवाट-घंटे का उत्पादन करने में सक्षम हो सकता है - किसी भी समय, यह केवल दो प्रकाश बल्बों को बिजली देने में सक्षम होगा।"

13.21. फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित 48-पृष्ठ की रिपोर्ट[17] में वाक्लाव स्माइल यहां तक कहते हैं, 'नेट जीरो कार्बन एक बेहद असंभव परिणाम है'।

'अंतिम ऊर्जा उपयोगों और विशिष्ट ऊर्जा कन्वर्टर्स के संदर्भ में, सामने आ रहे परिवर्तन को बड़े कोयला और गैस से चलने वाले स्टेशनों में अब स्थापित 4 टेरावाट (TW) से अधिक बिजली उत्पादन क्षमता को गैर-कार्बन स्रोतों में परिवर्तित करके बदलना होगा; सड़क और ऑफ-रोड वाहनों में लगभग 1.5 बिलियन दहन (गैसोलीन और डीजल) इंजनों को प्रतिस्थापित करना होगा; सभी कृषि और फसल प्रसंस्करण मशीनरी (लगभग 50 मिलियन ट्रैक्टर और 100 मिलियन से अधिक सिंचाई पंप सहित) को परिवर्तित करना होगा; विभिन्न प्रकार की औद्योगिक प्रक्रियाओं (लोहे के गलाने और सीमेंट और कांच बनाने से लेकर रासायनिक संश्लेषण और खाद्य संरक्षण तक) जो अब जीवाश्म ईंधन के समस्त अंतिम उपयोग के करीब 30 प्रतिशत का उपयोग करती है, में उपयोग की जाने वाली गर्मी, गर्म हवा और गर्म पानी के नए स्रोतों को खोजना घरों और औद्योगिक, संस्थागत और वाणिज्यिक स्थानों को गर्म करने वाली आधे अरब से अधिक प्राकृतिक गैस भट्टियों को हीट पंपों या अन्य ऊष्मा स्रोतों से प्रतिस्थापित करना और लगभग 120,000 व्यापारी बेड़े के जहाजों (अयस्कों, सीमेंट, उर्वरकों, लकड़ी और अनाज के थोक वाहक, और कंटेनर जहाज, जिनमें से सबसे बड़ा लगभग 24,000 इकाइयों की क्षमता वाला है, जो अब ज्यादातर भारी ईंधन तेल और डीजल ईंधन पर चल रहा है) और लगभग 25,000 सक्रिय जेटलाइनरों को बिजली देने के नए तरीके खोजना, जो वैश्विक लंबी दूरी के परिवहन (केरोसिन द्वारा ईंधन) का आधार बनाते हैं... पहली नजर में, और यहां तक कि बिना किसी विज्ञान तकनीकी और आर्थिक विश्लेषण के ही, यह एक असंभव कार्य प्रतीत होता है, क्योंकि:

- *हमारे पास ऐसा करने के लिए केवल एक पीढ़ी (लगभग 25 वर्ष) है;*
- *हम जीवाश्म ईंधन की वैश्विक खपत के शिखर तक भी नहीं पहुँचे हैं;*
- *शिखर के बाद तीव्र गिरावट नहीं आएगी;*
- *हमने अभी भी आवश्यक सामग्रियों के उत्पादन के लिए किसी भी शून्य-कार्बन बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक प्रक्रियाओं को लागू नहीं किया है;*
- *विद्युतीकरण ने, 2022 के अंत तक, केवल लगभग 2 प्रतिशत यात्री वाहनों (40 मिलियन से अधिक) को बैटरी से चलने वाली कारों की विभिन्न किस्मों में परिवर्तित किया है, और उस डीकार्बोनाइजेशन का अभी भी भारी सड़क परिवहन, शिपिंग और उड़ान पर असर पड़ना बाकी है।*

पृथ्वी पर जरूरतों के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन लालच के लिए नहीं

13.22. वर्तमान जलवायु परिवर्तन रणनीति यह कहती प्रतीत होती है कि चूंकि हमारी ऊर्जा की जरूरतें बढ़ती रहेंगी, इसलिए हमें पारंपरिक ईंधन को नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा से बदलने की कोशिश करनी चाहिए - इस प्रकार इसे वैश्विक जीवनशैली के मुद्दे के बजाय प्रतिस्थापन का मुद्दा बनाना चाहिए। यह प्रतिस्थापन केवल उसी तरीके से किया जाना चाहिए जिसे हम जानते हैं - एक पसंदीदा उद्योग को दूसरे से बदलकर, मौजूदा के स्थान पर नए परिवहन और आपूर्ति लाइनों के निर्माण के माध्यम से, कम उत्सर्जन करने वालों को अनुपातहीन रूप से उच्च भुगतान प्रदान करके।

17 क्योटो और 2050 के बीच का आधा रास्ता: नेट जीरो कार्बन एक बेहद असंभव परिणाम है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट, मई 2024.

13.23. यह रणनीति समस्या की जड़ पर चोट नहीं करती है – जो है अति उपभोग की, जो विकसित देशों में अधिक गंभीर है। इसके अलावा, क्या हममें से प्रत्येक को वास्तव में कई स्क्रीन की आवश्यकता है, भले ही वे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से चार्ज हों, या क्या सभी को जलवायु प्रभाव को कम करने पर एक शानदार बातचीत के लिए फैंसी विमानों में किसी शानदार गंतव्य पर जाना चाहिए, या हमें स्वाद के लिए वह खाना चाहिए जो हमें स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए नहीं खाना चाहिए। जैसा कि डेरेक बोवर एफटी[18] में कहते हैं, *''अगर हम चाहते हैं कि तेल कंपनियां जीवाश्म ईंधन बेचना बंद कर दें, तो हमें उनका कम उपभोग करना चाहिए और हमें ऐसी सरकारों को वोट देना चाहिए जो उन्हें कम नहीं बल्कि अधिक महंगा बनाती हैं। हां, हमारा भौतिक बुनियादी ढांचा दशकों से पेट्रोलियम उपयोग के इर्द-गिर्द बना हुआ है। हां, तेल कंपनियों ने इस व्यवस्था को बनाए रखने और विकल्पों को धीमा करने के लिए हमेशा पैरवी की है। लेकिन अमीर दुनिया में कोई भी हम जैसे लोगों को इतना उड़ान भरने, एस्केलेड चलाने, इतना मांस खाने या इतना सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है।''*

13.24. यह प्रकृति के प्रति वास्तविक रूप से शुद्धिकरण करने वाले दृष्टिकोण को प्रोत्साहित नहीं करता है, बल्कि संधारणीयता से एक और उद्योग सृजित करने पर ध्यान केंद्रित करता है - अपने जीवन जीने के तरीके में संधारणीय प्रथाओं को अपनाने के बजाय, हम अपने बैग पर पीईटीए (पेटा) लेबल लगाने के बारे में अधिक चिंतित हैं। इस मामले का तथ्य यह है कि संगठन, लोग और देश उत्पादन की प्रक्रिया में उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के बारे में ज्यादा चिंतित हैं, बल्कि प्रीमियम स्थानों से बाहर होने के डर से 'फेयर ट्रेड' वैश्विक लेबल प्राप्त करने के बारे में चिंतित हैं। यह विशिष्ट क्लब अति उपभोग की ओर बढ़ने पर सवाल नहीं उठाता है - अधिक ऊर्जा, अधिक वीडियो मनोरंजन, अधिक घर, अधिक परिवहन ; लेकिन उन लेबलों पर सवाल उठाता है जिनके तहत ऐसा होता है। आधुनिक जलवायु परिवर्तन रणनीति के अंतर्गत यह पाखंड अंतर्निहित है।

ऊर्जा - खपत वाली प्रौद्योगिकियों का वैश्विक अनुसरण

13.25. एक ओर, विकासशील देशों को जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिए हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसके लिए वे तैयार नहीं हैं। दूसरी ओर, विकसित दुनिया नवीनतम और सबसे व्यापक एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने के लिए पागल 'अफ्रीका के लिए संघर्ष' जैसी होड़ में है। तथ्य यह है कि एआई ऊर्जा की खपत करने वाला है। भले ही डेटा सेंटर ऊर्जा की मांग को बढ़ा रहे हों, लेकिन क्लाउड स्टोरेज सुविधाओं, क्रिप्टो माइनिंग और एआई सभी में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है (चार्ट XIII.4)।

चार्ट XIII.4: डेटा केंद्रों की ओर से बिजली की मांग और अन्य बड़े लोड (टेरा-वाट घंटे में)*

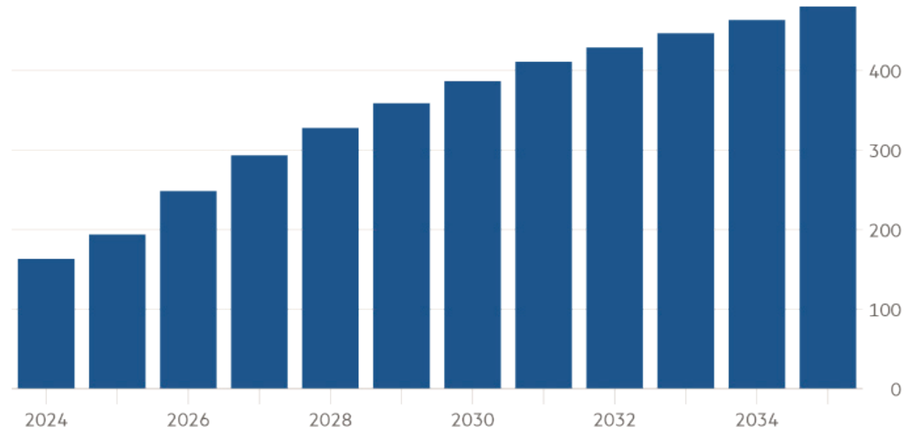

स्रोत : फाइनेंशियल टाइम्स (https://tinyurl.com/4teb29ck); एसएंडपी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स
*इसमें क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग और विनिर्माण सुविधाएं और तेल और गैस संचालनों का विद्युतीकरण शामिल है।

13.26. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के एक व्यापक अनुमान के अनुसार, एक चैट-जीपीटी खोज गूगल पर इसी तरह की क्वेरी की तुलना में 10 गुना अधिक ऊर्जा की खपत करती है। आयोवा में मेटा के स्वामित्व वाले एक बड़े डेटा सेंटर में सिर्फ एक साल में ही उतनी बिजली जलने का अनुमान है, जो 7 मिलियन लैपटॉप के 8 घंटे प्रतिदिन काम करने के बराबर है।[19] एफटी की रिपोर्ट है

18 द एनर्जी ट्रांजिशन विल बी वोलेटाइल, फाइनेंशियल टाइम्स, 25 जून 2024 को एक्सेस किया गया (https://tinyurl.com/52syuz7j)।
19 एआई पावर ग्रिड को खाली कर रहा है। टेक फर्म चमत्कारिक समाधान की तलाश कर रही हैं, द वाशिंगटन पोस्ट, जून 2024।

कि वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर से बिजली की मांग 2026 तक 1,000 TWh तक पहुँच सकती है (चार्ट XIII.4)। इस आंकड़े को परिप्रेक्ष्य में रखने पर - जर्मनी और फ्रांस की आज की शुद्ध बिजली की मांग क्रमशः लगभग 500 TWh है।[20] एलन मस्क ने हाल ही में बॉश कनेक्टेड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैंने कभी किसी तकनीक को इससे ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ते नहीं देखा। चिप की कमी भले ही पीछे छूट गई हो, लेकिन एआई और ईवी इतनी तेजी से फैल रहे हैं कि दुनिया को अगले साल बिजली और ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति में कमी का सामना करना पड़ेगा'। 2034 तक, डेटा सेंटर द्वारा वैश्विक ऊर्जा खपत 1,580 TWh से ऊपर होने की उम्मीद है, जो कि पूरे भारत द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के बराबर है।[21]

13.27. बिजली की यह मांग हरित ऊर्जा उत्पादन की गति से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही है। पहले से ही, हरित प्रतिबद्धताओं को दूर करने और कुछ कोयला आधारित संयंत्रों को बंद करने में देरी करने के लिए एक आंदोलन चल रहा है - साल्ट लेक सिटी क्षेत्र में, एक कोयला संयंत्र को बंद करने की तिथि को एक दशक पीछे धकेल कर 2042 कर दिया गया है और दूसरे को 2036 तक के लिए टाल दिया गया है। टेकलीडर तकनीक की बकासुर[22] भूख को पूरा करने के लिए परमाणु संलयन स्टार्टअप का प्रयास करने की बात कर रहे हैं, जबकि व्यावहारिक रूप से, यह भविष्य में बहुत दूर लगता है, यह देखते हुए कि समाधान अभी तक व्यवहार्य नहीं है।

13.28. पश्चिम द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे दो प्रमुख आंदोलनों एआई और हरित ऊर्जा की असंगति वैश्विक दुनिया द्वारा अनदेखी नहीं की जा सकती है। ऐसा लगता है कि चुनी गई आर्थिक और संधारणीय रणनीतियों में अपरिहार्य असंगति पर बहुत कम विचार किया गया है।

डेटा संचालित होने का दिखावा किन्तु प्रति - व्यक्ति डेटा का छिपाव

13.29. ऐसा कहा जाता है कि भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है और इसलिए, उससे बार-बार जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। जिस बात पर लगातार जोर नहीं दिया जाता है, वह यह है कि समाजों की पहले बसावट के समय से ही, औद्योगिक क्रांति पर आगे की स्थिति वाले पश्चिमी देशों ने जीवाश्म ईंधन से विकास में बेपरवाही से भाग लिया, जिसके कारण आज दुनिया की स्थिति ऐसी हो गई है। विकासशील देशों द्वारा इस पर वकालत के बावजूद, 'ऐतिहासिक उत्सर्जन' का एक साफ-सुथरा संदर्भ अस्पष्ट साहित्य में गहराई से डूबा हुआ है और उभरते देशों के जलवायु लक्ष्यों पर इसकी वास्तविक भूमिका और प्रभाव के प्रति एक आकस्मिक उदासीनता के साथ इसका सामना किया जाता है। यहां तक कि डेटा की प्रचुर मात्रा भी इस बुनियादी तथ्य को नहीं बदल सकती कि ऊर्जा एक प्रति व्यक्ति घटना है। इसे सरल शब्दों में कहें तो:

ऊर्जा खपत (समय T पर) = 1 व्यक्ति (E1) द्वारा खपत की गयी ऊर्जा (E2) × लोगों की संख्या (N) + N के लिए आवश्यक सामान्य गतिविधियों द्वारा खपत की गयी ऊर्जा (EN)

13.30. चूँकि सभी आधुनिक नीति-निर्माण आधारभूत मूल्यांकन से शुरू होते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक देश के लिए जलवायु लक्ष्य उसकी आर्थिक स्थिति के समानुपातिक हो। इसके विपरीत, यह देखा गया है कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जकों में से शीर्ष 10% ने 2021 में औसतन 22 टन CO_2 उत्सर्जित किया, जो कि निचले 10% द्वारा उत्सर्जित CO_2 से 200 गुना अधिक है।[23] वर्तमान में सबसे बड़े उत्सर्जकों में से 85% अमेरिका, यूरोप और चीन जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में रहते हैं, और निचले 10% उत्सर्जक अफ्रीका और दक्षिण एशिया के विकासशील देशों में रहते हैं, जहां बिजली तक पहुंच भी एक चुनौती है।[24] प्रति व्यक्ति खपत और उत्सर्जन में इस भारी अंतर को दर्शाते हुए, द इकोनॉमिस्ट ने रेखांकित किया है कि औसत अफ्रीकी प्रति वर्ष 185 किलोवाट घंटे kWh की खपत करता है, जबकि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका क्रमशः 6500 kWh और 12700 किलोवाट घंटा की खपत करते हैं।[25] इसके विपरीत, भारत का ऐतिहासिक संचयी उत्सर्जन और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक आबादी के 17% से

20 स्टेटिस्टिशेज बूंडसम ग्रोस इलेक्ट्रीसिटी प्रोडक्शन इन जर्मनी और आरटीआई फ्रांस इलेक्ट्रीसिटी एनलिसिस एंड डेटा, 8 जुलाई, 2024 को एक्सेस किया गया।

21 एआई पहले से ही वैश्विक बिजली प्रणालियों पर कहर बरपा रहा है, ब्लूमबर्ग, जून 2024 (https://tinyurl.com/56494s6a)।

24. बकासुर भारतीय पौराणिक कथाओं का एक पात्र है, जो असीमित भूख और लालच का प्रतीक है। यह राक्षस शहर के राजा को हर दिन भोजन की अंतहीन आपूर्ति भेजने के लिए मजबूर करता था, जिसे वह तुरंत ही उन लोगों के साथ खा जाता था जो उसे भोजन पहुंचाते थे।

23 दुनिया के शीर्ष 1% उत्सर्जक निचले 1% की तुलना में 1000 गुना अधिक CO_2 उत्पन्न करते हैं, आईईए, फरवरी 2023 (https://tinyurl.com/bdtf4tda)

24 आईईए के अनुमानों के अनुसार 2022 तक, लगभग 774 मिलियन लोगों की बिजली तक पहुँच नहीं थी, जिनमें से 80 प्रतिशत से अधिक लोग उप-सहारा अफ्रीका में रहते हैं; डेटा और सांख्यिकी ख्र आईईए (https://tinyurl.com/4atwv4d2)

25 अफ्रीका तब तक गरीब बना रहेगा जब तक वह अधिक ऊर्जा का उपयोग नहीं करता, द इकोनॉमिस्ट में प्रकाशित (https://tinyurl-com/yzpkzecm)।

अधिक का घर होने के बावजूद बहुत कम है जहां 1850 और 2019 के बीच वैश्विक संचयी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में इसका हिस्सा केवल 4% है (चार्ट XIII.5)।

चार्ट XIII.5: प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अपने कुल और प्रति व्यक्ति जीएचजी उत्सर्जन (CO_2 समतुल्य) के साथ

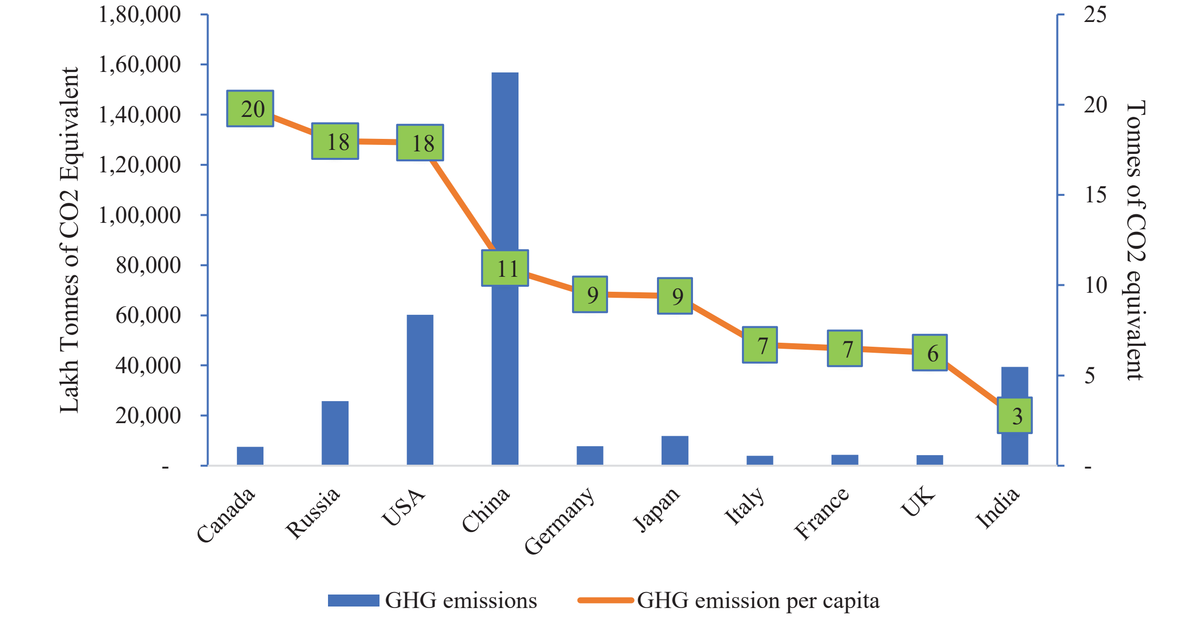

स्रोत: ईडीजीएआर (वैश्विक वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए उत्सर्जन डेटाबेस) सामुदायिक जीएचजी डेटाबेस, यूरोपीय आयोग, संयुक्त अनुसंधान केंद्र (जेआरसी), अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के बीच एक सहयोग, और जिसमें आईईए- ईडीजीएआर सीओ2, ईडीजीएआर सीएच4, ईडीजीएआर एन2ओ, ईडीजीएआर एफ-गैसें शामिल हैं। संस्करण 8.0, (2023) यूरोपीय आयोग, जेआरसी (डेटासेट).

13.31. इस वंडरलैंड में, ऐलिस ने टिप्पणी की होगी, 'क्यूरियसर एंड क्यूरियसर' – क्योंकि यद्यपि देशों की वैश्विक तुलना में प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति खपत जैसे आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, तथापि ऊर्जा उत्सर्जन का आकलन करते समय इसका पालन नहीं किया जाता है, भले ही जब यह सीधे तौर पर प्रति व्यक्ति उपयोग पर निर्भर हो। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों द्वारा अधिक 'हरित' माने जाने वाले देश प्रति व्यक्ति के फिल्टर को लागू करने पर विपरीत स्थिति दर्शाते हैं।

चार्ट XIII.6: निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्थाएं और उनका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (CO_2 समतुल्य)

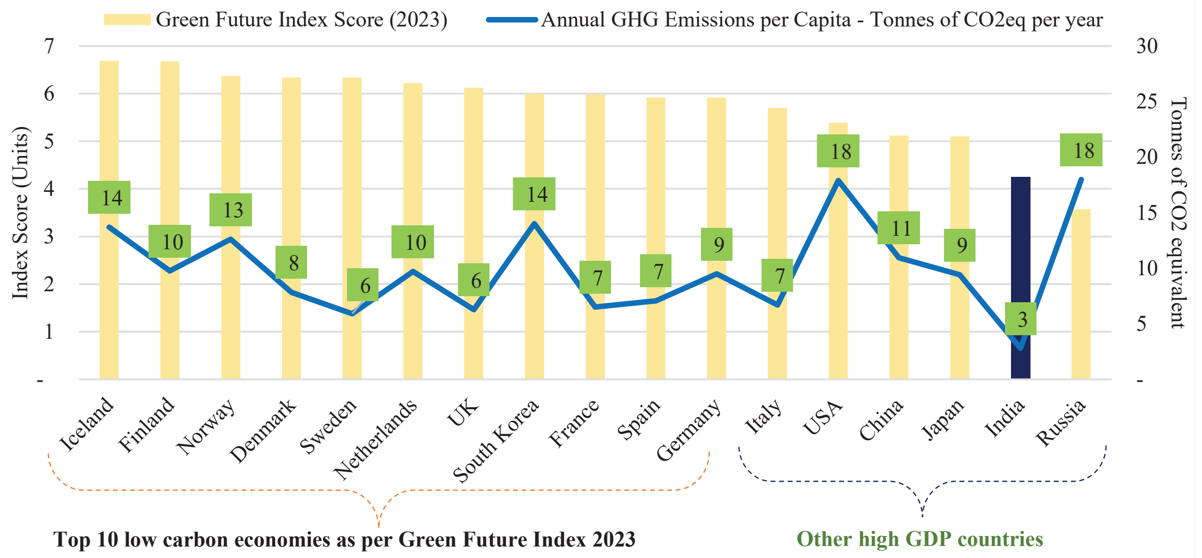

स्रोत: द ग्रीन फ्यूचर इंडेक्स 2023, एमआईटी टेक्नोलॉजी रिव्यू इनसाइट्स और ईडीजीएआर (वैश्विक वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए उत्सर्जन डेटाबेस) सामुदायिक जीएचजी डेटाबेस

13.32. तुलनात्मक रूप से, पिछले दशक में पर्याप्त आर्थिक वृद्धि के बावजूद भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन लगातार 2.5 और 2.8 टन CO_2 समतुल्य/वर्ष के बीच रहकर कम रहा है। यूरोपीय संघ के 27 देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (8 टन CO_2 समतुल्य/वर्ष)[26] भारत के उत्सर्जन का लगभग 3 गुना था। यहां तक कि विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 द्वारा मांग अनुमान के लिए नियोजित तीन परिदृश्यों में, यह बताया गया कि उभरते देशों की प्रति व्यक्ति ऊर्जा मांग, 2030[27] तक भी, विकसित देशों की तुलना में काफी कम रहेगी। यह एक ऐसा मुद्दा है जो जलवायु परिवर्तन के बारे में होने वाली चर्चाओं में अनायास ही शामिल हो जाता है।

13.33 ऐतिहासिक और वर्तमान वैश्विक ऊर्जा खपत में इतनी अधिक विषमताएं तथा बड़ी और लगातार असमानताएं होने के कारण, शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्यों और रणनीतियों को अधिदिष्ट या अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि देश जलवायु समस्या की जिम्मेदारी लें तथा बाह्य दबाव या अत्यधिक आलोचना से मुक्त होकर सार्थक जलवायु कार्रवाई के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से काम करें।

ऐतिहासिक अनिश्चितता (ब्लाइंडस्पॉट) और अपराधबोध का आश्चर्यजनक अभाव

13.34. वैश्विक स्तर पर, अतीत की गलतियों को आज सुधारने की आवश्यकता के कारण स्वयं पर अत्यधिक बोझ डालने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसके साथ ही विकसित देशों द्वारा स्थायित्व सहित विभिन्न धारणाओं वाले देशों के प्रति शासन और नीति पर अपनाए गए नैतिक दृष्टिकोण से भी इसकी पूर्ति होती है। हालांकि, जलवायु परिवर्तन के मामले में, जहां आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं, समस्या की उत्पत्ति और कई दशकों से प्राप्त वास्तविक विशेषाधिकार (आर्थिक प्रगति हासिल करने के लिए संसाधनों का अंधाधुंध दोहन) को भी नजरअंदाज किया जाता है। जैसा कि ऐलिस अपने वंडरलैंड[28] में कहती है, ‘लेकिन मेरे साथ यही परेशानी है। मैं खुद को बहुत अच्छी सलाह देती हूँ, लेकिन मैं शायद ही कभी उसका पालन करती हूँ।’

13.35. विकसित और विकासशील देशों के बीच ऊर्जा की उपलब्धता और कार्बन उत्सर्जन में काफी अंतर देखा जा सकता है। विकसित देशों ने अपने बुनियादी ढांचे का निर्माण एक सुविधाजनक गति से और निर्बाध गति से किया है, जबकि अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कई देश अभी भी शहरी क्षेत्रों में नियमित बिजली आपूर्ति प्राप्त करने के लिए जूझ रहे हैं। कम विकसित देशों में लगभग 55% आबादी के पास अभी भी बिजली की सुविधा नहीं है।[29] शोध से पता चलता है कि उच्च आय वाले देश निम्न आय वाले देशों[30] की तुलना में 6 गुना अधिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और 10 गुना अधिक जलवायु प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यह असमानता विभिन्न देशों के लिए शून्य उत्सर्जन हेतु एक ही समय-सीमा निर्धारित करना अनुचित बनाती है।

13.36. निम्न और मध्यम आय वाले देशों को ऊर्जा की बढ़ती मांग, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की अप्राप्य लागत और जीवाश्म ईंधन पर अधिक निर्भरता के संदर्भ में तिहरे खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि विकसित राष्ट्र पर्यावरण क्षरण में अपनी ऐतिहासिक भूमिका को वास्तविक रूप से स्वीकार करें तथा विकासशील देशों को संसाधन, प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी क्षमता हस्तांतरित करें, ताकि वित्तपोषण अंतराल को कम करने तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के साझा लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिले।

अपर्याप्त जलवायु वित्तपोषण

13.37 पश्चिम एक मार्च हेयर बन जाता है[31] – मेरे पास एक बढ़िया विचार है! चलो विषय बदलते हैं –हर बार जब ऐतिहासिक पुनर्मूल्यांकन के कारण वास्तविक जलवायु वित्तपोषण का विषय सामने आता है तब ऐसा ही होता हैं । शोध से पता चलता है कि विकासशील देशों को अपने मौजूदा एनडीसी लक्ष्यों का लगभग आधा हिस्सा हासिल करने के लिए 2030 तक लगभग 6 ट्रिलियन

26 वैश्विक वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए उत्सर्जन डेटाबेस, विश्व के सभी देशों की जीएचजी उत्सर्जन 2023 रिपोर्ट

27 "आज प्रति व्यक्ति वैश्विक ऊर्जा मांग लगभग 80 गीगाजूल (जीजे) है,और यह स्तर पिछले दशक में मोटे तौर पर स्थिर रहा है (चित्र 3.3)। यह 2030 तक एसटीईपीएस (घोषित नीति परिदृश्य) में स्थिर रहता है, लेकिन एपीएस (घोषित प्रतिज्ञा परिदृश्य) में यह 7% और एनजेडई (नेट जीरो एमिशन) परिदृश्य में 15% तक घट जाता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, 2030 तक सभी परिदृश्यों में प्रति व्यक्ति मांग में गिरावट आएगी। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, यह एसटीईपीएस में वृद्धिशील है क्योंकि आर्थिक विकास ऊर्जा सेवाओं की मांग में वृद्धि को बढ़ावा देता है।" आईईए विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023, चित्र 3.3: घोषित नीतियों और घोषित प्रतिज्ञा परिदृश्यों, 2022 और 2030 में चयनित क्षेत्रों में ऊर्जा तीव्रता और प्रति व्यक्ति ऊर्जा।

28 लुईस कैरोल द्वारा रचित एलिस इन वंडरलैंड।

29 यूएनसीटीएडी की गणना अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और यूएनसीटीएडी सांख्यिकी के आंकड़ों पर आधारित है। (https://tinyurl.com/53cx cstz)

30 ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक 2024, यूएनईपी।

31 लुईस कैरोल द्वारा रचित एलिस इन वंडरलैंड

अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। इसके मुकाबले विकसित देशों ने 2020[32] तक केवल 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया था, जिसमें से केवल 83.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही उपलब्ध कराए गए।[33] वित्तपोषण का यह स्तर अभी भी सामने आई चुनौती के पैमाने से मेल नहीं खाता है क्योंकि विकासशील देशों की जलवायु अनुकूलन आवश्यकताओं के 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2050[34] तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो वर्तमान निधि प्रवाह से 5-10 गुना अधिक है।

13.38. रॉबर्ट बर्न्स अपनी कविता में कहते हैं, 'ऐसी कोई अनिश्चितता नहीं होती जो कि निश्चित रूप में हो'। इस तरह की जलवायु प्रतिज्ञाओं की सुनिश्चितता लेंस को ज़ूम करने(नजदीक से देखने पर) पर कहीं अधिक समस्याग्रस्त लगती है। वर्तमान वित्तपोषण का अधिकांश हिस्सा मध्यम आय वाले देशों को दिए जाने वाले ऋणों के रूप में है, जो अपनी आवश्यक सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहले से ही भारी सार्वजनिक ऋण बोझ से जूझ रहे हैं। 2015 और 2020 के बीच मध्यम आय वाले देशों द्वारा प्राप्त जलवायु वित्त का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा ऋणों के रूप में था।[35] इसके अलावा, निधि आवंटन के दौरान अक्सर दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता पर लाभ और निवेश पर प्रतिफल को प्राथमिकता दी जाती है।

13.39. वे कहते हैं कि "कमियों का पता विश्लेषण से चलता है"। 100 बिलियन डॉलर के प्रतिबद्ध वित्तपोषण के सुनहरे आवरण के नीचे, यक्षगण वितंडो को चमकाने का काम कर रहे हैं, जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा रिपोर्ट किए गए इस छोटे से तथ्य से स्पष्ट होता है[36] – एट द कार्टाजेना एड हॉक वर्क प्रोग्राम (एएचडबल्यूपी)- पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी) में वास्तविक वार्ता की होड़ में - संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने कथित तौर पर न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल (एनसीक्यूजी) योगदान को उन लोगों के लिए 'स्वैच्छिक' बनाने पर जोर दिया है जो 'भुगतान करना चुनते हैं'। उन्होंने विकासशील देशों को उनकी "आर्थिक वास्तविकताओं" और "वर्तमान उत्सर्जन हिस्सेदारी" के आधार पर शामिल करने के लिए योगदानकर्ताओं के पूल को व्यापक बनाने की भी वकालत की है। इसलिए, 'भुगतान कौन करेगा' इस पर इस झिझक के पीछे का कारण बॉक्स XIII.3 के माध्यम से अच्छी तरह से इंगित किया गया है।

बॉक्स XIII.3: पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय नीतियों के लिए बदलाव करने की इच्छा और भुगतान करने की इच्छा

व्यक्ति कल्पना कर सकता है कि चूंकि जलवायु स्थिरता पर अधिकांश बहस विकसित देशों से ही आती है, इसलिए वे अपनी उपभोग-उन्मुख जीवनशैली में परिवर्तन के वित्तीय प्रभाव को स्वीकार करने वाले पहले देश होंगे। हालाँकि, शोध कुछ और ही कहते हैं। 2022 में ओईसीडी पर्यावरण नीतियों और व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन सर्वेक्षण (17,000 से अधिक घरों में किया गया) के लगभग 63% उत्तरदाताओं का मानना है कि संधारणीय विकल्पों से उन पर वित्तीय रूप से कोई असर नहीं पड़ना चाहिए और इसलिए 'वे अतिरिक्त भुगतान करने के लिए तैयार नहीं हैं'। इसकी तुलना सीधे सीबीएएम कर से करें जिसे यूरोपीय संघ विकासशील देशों से आयातित स्टील जैसे उत्पादों पर उत्पादन के दौरान तथाकथित उत्सर्जित कार्बन पर 'उचित मूल्य' के आधार पर लगाने को तैयार है। इसी सर्वेक्षण में, लगभग 43% उत्तरदाताओं ने बताया कि वे नियमित रूप से रेड मीट का सेवन करते हैं तथा इस जीवनशैली विशेषता को बदलने के प्रति प्रतिरोध प्रदर्शित किया, जिसका जलवायु परिवर्तन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि पर्यावरण के प्रति घरों की सामान्य प्रवृत्ति, रेड मीट के उपभोग की उनकी आवृत्ति को प्रभावित नहीं करती है।

इस दर पर, यह प्रश्न संधारणीय विकल्पों के बारे में कम, बल्कि पूंजीवाद के लिए एक नए खेल के बारे में अधिक प्रतीत होता है। मौजूदा औद्योगिक नेटवर्क और उत्पाद उपभोग में संतृप्ति के समाप्त हो जाने के बाद, केवल औद्योगिक उपभोग की एक पूरी तरह से नई गतिशीलता के लिए ही जगह बनाई जा सकती है – नए औद्योगिक उत्पाद, नए बाजार और उन लोगों पर कर लगाने के नए तरीके जो अभी भी जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ताकि पुरानी यथास्थिति बनी रहे और 'उभरतेश लोग हमेशा सवालों के घेरे में रहें।

32 जलवायु वित्त लक्ष्य जो विकासशील देशों के लिए काम करता है, यूएनसीटीएडी, जून 2023 (https://tinyurl.com/2vpxe86k)।

33 जलवायु वित्त और 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य, ओईसीडी (https://www.oecd.org/en/topics/climate-finance-and-the-usd-100-billion-goal-html)

34 यूएनईपी अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2020

35 जलवायु वित्त कार्यक्रम अमीर देशों को अरबों डॉलर वापस भेज रहे है, फ्रंटलाइन रिसर्च, मई 2024 (https://tinyurl.com/ycyp7ybv)

36 हिंदुस्तान टाइम्स से पुनर्प्राप्त (https://tinyurl.com/2zpr2rfn)

पश्चिमी पद्धतियों को अपनाने से विकासशील दुनिया पर नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा

13.40. दुनिया में सबसे बड़ी आबादी के बावजूद भारत क्षेत्रफल में 7वां सबसे बड़ा देश है, जहां संसाधनों की काफी कमी है। और फिर भी यह देश न केवल अपनी विशाल आबादी को बनाए रखने में बल्कि एक आकांक्षी समाज के शिखर को छूने में भी निरंतर सफल हो रहा है। लेखक यह तर्क देना चाहते हैं कि देश की आर्थिक, सामाजिक और ऐतिहासिक चुनौतियों के प्रति लचीला होने की इस अंतर्निहित क्षमता का एक प्रमुख कारण इसकी अंतर्निहित 'धार्मिक' प्रकृति है, जो इसे एक कुशल बाजार अर्थव्यवस्था तो बनते देखना चाहती है, लेकिन एक बाजारीय समाज नहीं। दोनों[37] के बीच अंतर को सबसे पहले कार्ल पोलानी ने वर्णित किया था, जिन्होंने दोनों का वर्णन इस प्रकार किया:

"इस संस्थागत उपकरण ने, जो अर्थव्यवस्था में प्रमुख शक्ति बन गया, जिसे अब बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में औचित्यपूर्वक वर्णित किया जाता है, फिर एक, और भी अधिक चरम विकास स्थिति को जन्म दिया, एक ऐसी स्थिति जिसमें एक सम्पूर्ण समाज जो अपनी अर्थव्यवस्था के तंत्र में अंतर्निहित है अर्थात् एक बाजार समाज।"

13.41. सरल शब्दों में कहें तो, बाजार अर्थव्यवस्था - जो आज विश्व अर्थव्यवस्था पर हावी है - इस धारणा पर केंद्रित है कि आपूर्ति और मांग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को प्रेरित करती है, और कीमतें 'मुक्त बाजारों के अदृश्य हाथ' से निर्धारित होती हैं। बाजार समाज अक्सर बाजार अर्थशास्त्र की दीर्घकालिक संस्कृति की परिणति होता है, जिसके तहत सामाजिक रीति-रिवाज बाजार मूल्यों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों का वस्तुकरण हो जाता है जो पारंपरिक रूप से गैर-बाजार मानदंडों द्वारा शासित होते थे।

13.42. भारत न केवल बाजारी समाज नहीं है, बल्कि मूलतः एक अनूठा समाज है जहां हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक मानदंड और पर्यावरण एक दूसरे से परस्पर रूप में जुड़े हुए हैं। चूंकि विदेशी ताकतें हमारी विचार प्रक्रिया को आकार दे रही हैं, इसलिए भारत को हमसे भिन्न समाजों से जीवनशैली और उपयोगकर्ता व्यवहार दोनों तरह की सीख के अनुसार स्वयं को बदलने में सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि भविष्य में इसका प्रभाव 3ई - समता, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर न पड़े।

13.43. ऐसे बाजार अर्थशास्त्र को सार्वभौमिक रूप से अभिकल्पित आकर्षक उपाय का अनुसरण नहीं करना चाहिए और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल समायोजन करना चाहिए, यह बात कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्पष्ट रूप से सामने लाई गई है, जैसे कि 2005 और उसके बाद की जी20 घोषणाएं, 2010-13 का संयुक्त राष्ट्र समझौता, जिन्होंने वन-साइज-फिट-आल (ओएसएफए) और 2015 एमडीजी लक्ष्यों (चार्ट XIII.7) को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।

चार्ट XIII.7: विभिन्न विचारों के प्रति प्रतिबद्धता वाली अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएँ

- 2005 G20 meet discarded one size fit all model [OSFA] of development
- In 2010-13 UN which had proposed OSFA in 1951 explicitly discarded it
- In 2015 MDG goals explicitly said Economic Development has to be founded on culture
- In 2015 NITI Aayog formation resolution the Union cabinet said that we need Bharatiya Model of Development and do what works in and for India

13.44. उत्सर्जन शमन स्थिति को प्राप्त करने में बाजार अर्थव्यवस्था की सीमाओं को स्वीकार करने का समय आ गया है। बाजार अनुशासन सैद्धांतिक रूप में मौजूद है जैसा कि कई वित्तीय बाजार में गिरावट में देखा गया है। बाजार तंत्र प्रो-साइक्लिकल है। इसलिए, यह स्थिरता के लिए एक बल होने के बजाय अस्थिरता को बढ़ावा देता है। सिधांततः शायद ही यह कभी मुख्य रूप से 'अच्छे विकल्प' को प्रोत्साहित करता है, लेकिन हमेशा अच्छे विकल्प को वित्तीय रूप से प्रोत्साहित करता है।

37 इस विषय पर अधिक विवरण के लिए, फ्रैंक कनिंघम का पेपर एक रहस्योद्घाटनकारी पाठ के रूप में कार्य करता है: http://individual.utoronto.ca/frankcunningham/marketEco.pdf

मांस उत्पादन प्रक्रिया और भोजन-चारा संतुलन का ह्रास

13.45. मांस, अपनी कैलोरी घनत्व के कारण, मनुष्यों के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता[38] रहा है और लगभग 10,000 साल पहले कृषि का विकास होने तक पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। जैसे-जैसे समाज बनते गए और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कृषि पर आधारित सभ्यताएँ उभरीं गईं, मानव जाति समय के साथ पौधे-और पशु-आधारित व्यंजनों के मिश्रण की ओर बढ़ने लगी। समय के साथ, कृषि अनुसंधान में सुधार ने उपलब्ध पादप-आधारित खाद्य विकल्पों के महत्वपूर्ण विस्तार की सुविधा प्रदान की, जो कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। कृषि अनुसंधान ने इसे ऐसा बना दिया कि आज, यदि कोई ऐसा करना चाहता है, तो मनुष्य के लिए अपने शरीर की सभी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को, विशेष रूप से पादप-आधारित आहार से पूरा करना और एक लंबा, स्वस्थ जीवन जीना पूरी तरह से संभव है।

13.46. चूँकि मांस के लिए वरीयता हमारी विकासवादी प्रक्रिया का हिस्सा है और हमारा पाचन तंत्र भी स्पष्ट रूप से सर्वाहारी आहार के लिए सुयोग्य है, इसलिए मांस पोषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना चुका है। जैसे-जैसे समाज समृद्धि की ओर बढ़ा, मांस की माँग की मात्रा भी बढ़ी। 1961 और 2000 के बीच[39] उत्तरी अमेरिका और यूरोप में मांस उत्पादन में क्रमशः 2.5 गुना और 1.7 गुना वृद्धि हुई। अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि बड़े पैमाने पर आधुनिक फीड उद्योग के उद्भव से सुगम हुई, जो अब दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा के लिए एक विश्वसनीय और महत्वपूर्ण खतरा प्रस्तुत करता है।

13.47. फीड उद्योग एक ऐसे विशाल उपक्रम के रूप में उभरा है कि प्लानेट पर कुल कृषि योग्य भूमि का 33 प्रतिशत अब फीड फसल उत्पादन के लिए उपयोग किया जा रहा है,[40] और नई भूमि वनों की कटाई[41] या मौजूदा कृषि भूमि[42] के पुनः उपयोग के माध्यम से जोड़ी जा रही है। इसके अलावा, मांस उत्पादन की पश्चिमी पद्धति के तहत मानव-खाद्य फसलों पर निर्भरता ने खाद्य-चारा प्रतिस्पर्धा[43] को गति दी है क्योंकि उत्पादित वैश्विक अनाज का एक तिहाई से अधिक पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। वहीं, दस में से एक व्यक्ति को अभी भी पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है।[44]

13.48. 'नेचर' में प्रकाशित एक हालिया विश्लेषण में बताया गया है कि प्रमुख फसलों के केवल 37 प्रतिशत काटे गए क्षेत्र का ही प्रत्यक्ष खाद्य उपभोग[45] के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि मानव-खाद्य फसलों का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से पशुधन उद्योग से अब प्रतिस्पर्धी उपयोगों का सामना कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 किलोग्राम गोमांस के लिए 25 किलोग्राम चारा फसल की आवश्यकता होती है, जबकि 1 किलोग्राम भेड़ के बच्चे के लिए 15 किलोग्राम चारा फसल[46] की आवश्यकता होती है। पश्चिमी पशुधन उद्योग में चारे के प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करने वाली फसलों में मक्का (मकई), सोयाबीन, फलियां, चोकर और तिलहन शामिल हैं। ये पांच फसलें उन दस वैश्विक फसलों में शामिल हैं, जो सभी काटे गए खाद्य कैलोरी का 83 प्रतिशत प्रदान करती हैं।[47]

13.49. इसके अलावा, जबकि दुनिया भर में फसल भूमि और फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है, खाद्य उपभोग के लिए उगाई जाने वाली फसलों का अनुपात 1960[48] के दशक से घट रहा है उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका को, अपनी कृषि भूमि

---

38 हमारे पूर्वज 'शिकारी-संग्राहक' होने के बावजूद, अक्सर यह माना जाता है कि जब मांस की उपलब्धता कम होती थी, तो चारा पौधों पर विकल्प के रूप में भरोसा किया जाता था।

39 संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन

40 पशुधन की लंबी छाया: पर्यावरण संबंधी मुद्दे और विकल्प, संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन।

41 मांस की मांग अमेजन को नष्ट कर रही है, द वाशिंगटन पोस्ट, मार्च 2022। (https://www.washingtonpost.com/climate-solutions/2022/03/09/amazon-rainforest-deforestation-beef/)

42 पशुधन और परिदृश्य, संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन। (https://www.fao.org/4/ar591e/ar591e.pdf)

43 मक्कड़, एच.पी.एस. (2018)। खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के लिए फीड मांग परिदृश्य और भोजन-नहीं फीड रणनीति के निहितार्थ। पशु, 12(8), 1744-1754।

44 हन्ना रिची, पाब्लो रोसाडो और मैक्स रोजर (2023) - 'भूख और अल्पपोषण' ऑनलाइन OurWorldInData.org पर प्रकाशित। यहाँ से प्राप्त: (https://ourworldindata.org/hunger-and-undernourishment)

45 रे, डी. के., स्लोट, एल. एल., गार्सिया, ए. एस., डेविस, के. एफ., अली, टी., और जी, डब्ल्यू. (2022)। प्रत्यक्ष खाद्य उपयोग के लिए फसल की कटाई संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सुरक्षा लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। नेचर फूड, 3(5), 367-374।

46 अलेक्जेंडर एट अल. (2016), भोजन के लिए भूमि हेतु मानव विनियोग: आहार की भूमिका. वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन.

47 टिलमैन, डी., बाल्जर, सी., हिल, जे., और बेफोर्ट, बी.एल. (2011)। वैश्विक खाद्य मांग और कृषि की सतत गहनता। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की कार्यवाही, 108(50), 20260-20264।

48 दुनिया अधिक फसल उगा रही है - लेकिन भोजन के लिए नहीं, विश्व संसाधन संस्थान, दिसंबर 2022 (https://www.wri.org/insights/crop-expansion-food-security-trends)

की प्रचुरता के कारण कभी 'खाद्य टोकरी' के रूप में माना जाता था, लेकिन आज, चारा फसलों के लिए कृषि योग्य भूमि के बड़े पैमाने पर विनियोजन के कारण, इसे ष्चारा टोकरीष कहे जाने की प्रबल संभावना है।[49]

चार्ट XIII.8: 'खाद्य, चारा और खाद्य प्रसंस्करण' के लिए उपयोग की जाने वाली फसल का औसत अंश (1964-1968)

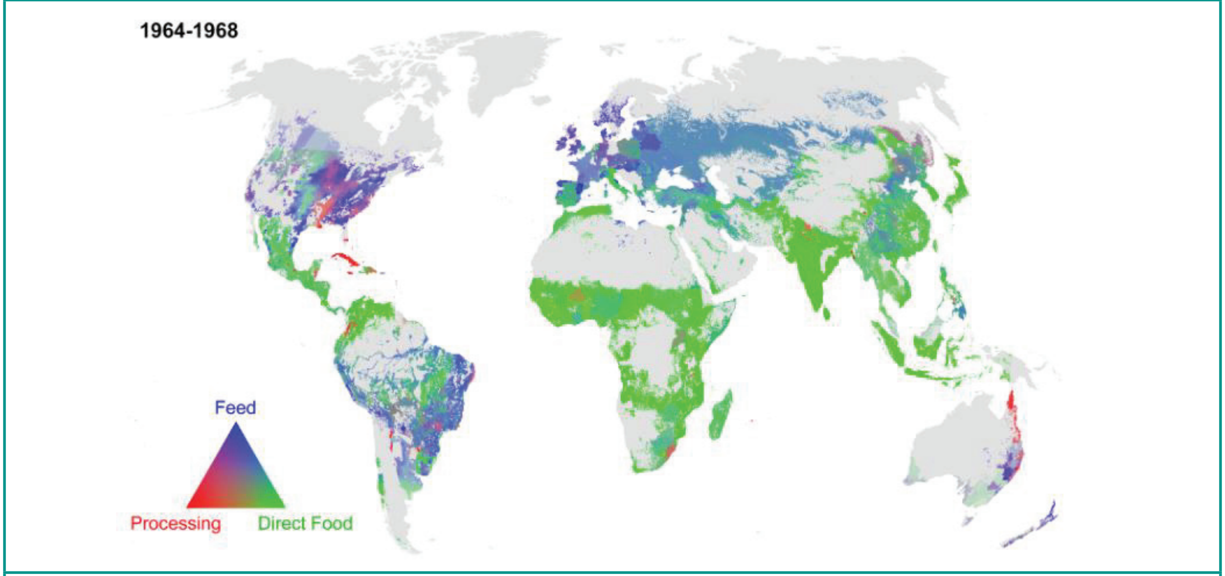

स्रोत: रे, डी. के., स्लोट, एल. एल., गार्सिया, ए. एस., डेविस, के. एफ., अली, टी., और जी, डब्ल्यू. (2022)। प्रत्यक्ष खाद्य उपयोग के लिए फसल की कटाई संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सुरक्षा लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। नेचर फूड, 3(5), 367-374।

चार्ट XIII.9: 'खाद्य, चारा और खाद्य प्रसंस्करण' के लिए उपयोग की जाने वाली फसल का औसत अंश (2009-2013)

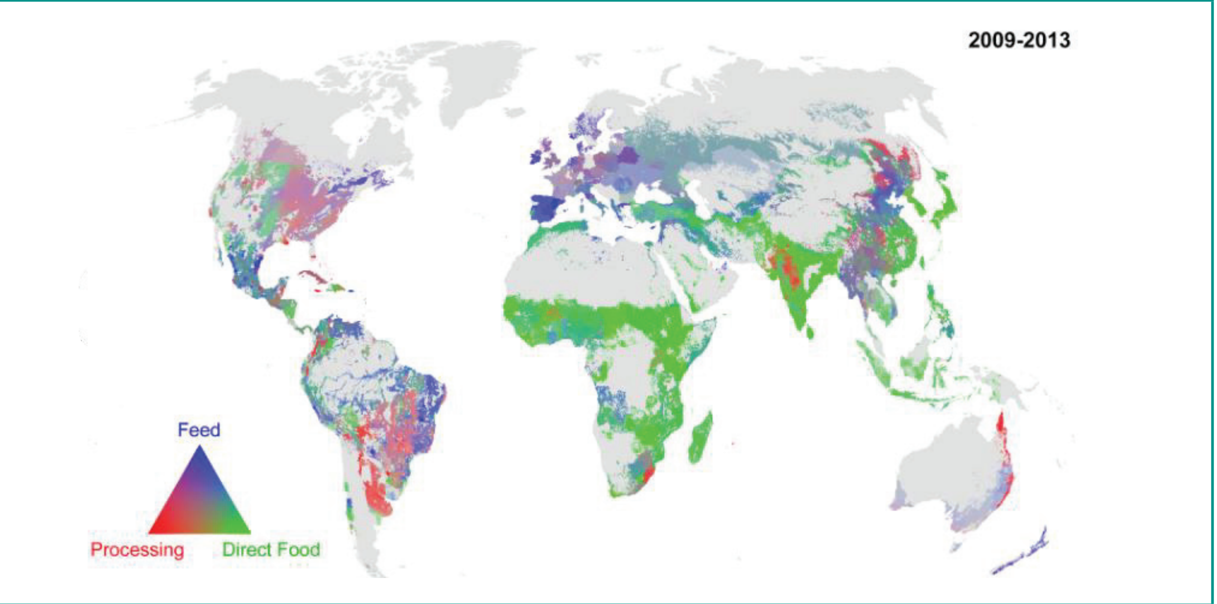

स्रोत: रे, डी. के., स्लोट, एल. एल., गार्सिया, ए. एस., डेविस, के. एफ., अली, टी., और जी, डब्ल्यू. (2022)। प्रत्यक्ष खाद्य उपयोग के लिए फसल की कटाई संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सुरक्षा लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। नेचर फूड, 3(5), 367-374।

49 रे, डी. के., स्लोट, एल. एल., गार्सिया, ए. एस., डेविस, के. एफ., अली, टी., और जी, डब्ल्यू. (2022)। प्रत्यक्ष खाद्य उपयोग के लिए फसल की कटाई संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सुरक्षा लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। नेचर फूड, 3(5), 367-374।

13.50. पशुपालन के पश्चिमी तरीकों को अपनाने वाले अन्य विकासशील देशों में भी इसी तरह के रुझान उभरने लगे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और कृषि पद्धतियों को चारा फसल की खेती की ओर स्थानांतरित करना खासकर अनुमानित जनसंख्या वृद्धि के रुझान के साथ विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। 2030 तक, कई विकासशील देश प्रत्यक्ष खाद्य फसलों के रूप में प्राप्त कैलोरी में कमी के कारण बढ़ती आबादी के पोषण के लिए आवश्यक कैलोरी की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। कई गैर-प्रत्यक्ष खाद्य फसलें[50] जो अमीर देशों में नहीं उगाई जाती हैं, उन्हें पश्चिमी शैली के आहार (जैसे मांस उद्योग के लिए चारा)[51]के पूरक के रूप में अमीर देशों को निर्यात करने के लिए विकासशील देशों में उगाया जाता है। यह गंभीर मामला है क्योंकि भूमि पहले से ही दुर्लभ है, और कृषि योग्य भूमि और भी अधिक दुर्लभ है।

13.51. भूमि की यह कमी अब दुनिया भर में भूमि की कमी की ओर ले जा रही है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या को खिलाने के लिए 2050 तक[52] अतिरिक्त 600 मिलियन हेक्टेयर (भारत के आकार का लगभग दोगुना) भूमि की आवश्यकता होगी। भूख[53] से प्रभावित 828 मिलियन कुपोषित लोगों में से प्रत्येक को खिलाने के बजाय अधिक से अधिक भूमि पशु चारा उगाने के लिए समर्पित की जा रही है, क्या अब इस प्रवृत्ति को रोकने का समय नहीं आ गया है? हमें एक मिनट के लिए खुद से पूछना चाहिए कि क्या यह वास्तव में हमारे दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग है?

13.52. संसाधनों की कमी और भविष्य में मंडरा रहे खाद्य सुरक्षा खतरों के अलावा, पशुधन, खेती के स्थापित तरीके भी पर्यावरण के लिए अत्यधिक अस्थिर हैं। उद्योग मानक प्रथाओं जैसे मोनोक्रॉपिंग, प्रतिबंधित फसल चक्र, निरंतर मीठे पानी की निकासी[54], अत्यधिक जुताई, स्थानीय जैव विविधता[55] को खतरा, और सिंथेटिक कीटनाशकों और शाकनाशियों[56] के उपयोग के माध्यम से चारा उगाना सुगम हो गया है। जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, इस तरह की प्रथाएं कृषि भूमि से पोषक तत्वों को स्थायी रूप से समाप्त कर रही हैं, जिससे मिट्टी का कटाव हो रहा है और पानी की गुणवत्ता[57] खराब हो रही है।

13.53. ये प्रथाएं विकसित दुनिया में जारी नहीं रह सकतीं। विकासशील देशों में बढ़ती आय के कारण 2050 तक मांस की मांग बढ़ने की उम्मीद के साथ, वे निश्चित रूप से पश्चिमी फीड उद्योगों द्वारा स्थापित प्रथाओं को नहीं अपना सकते हैं। इन चिंताओं को 22 साल पहले गेर्बेंस-लीन्स और नॉनहेबेल (2022)[58] ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा, *''पश्चिमी देशों में, संबंधित भूमि आवश्यकता पर खाद्य उपभोग पैटर्न का प्रभाव पर्याप्त है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े क्षेत्रीय और साथ ही अंतर-पीढ़ीगत अंतर होते हैं... वैश्विक स्तर पर, यह महसूस किया जाना चाहिए कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा कुपोषित है... यदि विकासशील देशों में पैटर्न पश्चिमी देशों के समृद्ध मेनू की ओर स्थानांतरित हो जाता है, तो संबंधित प्रति व्यक्ति भूमि की आवश्यकताएं काफी बढ़ जाएंगी''*

13.54. विकासशील देशों की पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ, जहाँ कई कृषि गतिविधियाँ पशुधन पालन के साथ एकीकृत होती हैं, इस समस्या का एक समाधान प्रस्तुत करती हैं। भारत का उदाहरण लें तो हमारा कृषि क्षेत्र, मुख्य रूप से छोटे और मध्यम कृषि उपक्रम जो कृषि और पशुधन पालन में संलग्न हैं, दशकों से टिकाऊ खेती (जिसे एकीकृत कृषि प्रणाली भी कहा जाता है) का अभ्यास कर रहे हैं। अन्य कृषि गतिविधियों से उत्पन्न कृषि अपशिष्ट और उप-उत्पादों को किसी अन्य गतिविधि (खेतों से निकाली गई

50 दुनिया अधिक फसलें उगा रही है - लेकिन भोजन के लिए नहीं, विश्व संसाधन संस्थान, दिसंबर 2022 (https://www.wri.org/insights/crop-expansion-food-security-trends)

51 वही

52 वैश्विक भूमि दबाव का प्रबंधन कैसे करें?, विश्व संसाधन संस्थान, जुलाई 2023

53 खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2022, संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन

54 UNFAO द्वारा उजागर किए गए वैश्विक मानव जल उपयोग का 8 प्रतिशत हिस्सा

55 वर्ल्डवाइड फंड फॉर नेचर (WWF) द्वारा पहचाने गए 825 स्थलीय पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से लगभग 306 ने पशुधन को उनके सामने आने वाले प्रमुख खतरों में से एक बताया

56 पूअर, जे., और नेमेसेक, टी. (2018)। उत्पादकों और उपभोक्ताओं के माध्यम से खाद्य के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना। विज्ञान, 360(6392), 987-992।

57 पशुधन की लंबी छाया: पर्यावरणीय मुद्दे और विकल्प, संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन।

58 गेर्बेंस-लीन्स, पी. डब्ल्यू., और नॉनहेबेल, एस. (2002)। भोजन के लिए आवश्यक भूमि पर उपभोग पैटर्न और उनके प्रभाव। पारिस्थितिक अर्थशास्त्र, 42(1-2), 185-199.

घास और खरपतवार जैसे मानव के अखाद्य चारे के स्रोत, कटाई के बाद एकत्र की गई भूसी और ठूंठ और अन्य कृषि अपशिष्ट)[59] के लिए इनपुट के रूप में उपयोग करने से, भारत के कृषि उद्यम प्राकृतिक चक्र को बिगाड़े बिना उत्पादन की लागत कम करने और अपने उपक्रमों की उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम हुए हैं। इसी तरह, अफ्रीकी देशों में परीक्षण की गई एकीकृत कृषि प्रणालियों ने प्रदर्शित किया कि पशुधन आधारित एकीकरण ने न केवल दैनिक कृषि प्रक्रियाओं में मदद की, बल्कि मनुष्यों के साथ-साथ पशुधन में खाद्य सुरक्षा और कुपोषण के जोखिम को कम करने में भी मदद की।[60]

13.55. पशुओं को मानव-अखाद्य चारे में बदलने से वैश्विक कृषि योग्य भूमि का महत्वपूर्ण हिस्सा वैश्विक भूख को दूर करने के लिए मुक्त हो सकता है। अधिक खाद्य फसलों को मानव उपभोग के लिए निर्देशित किया जा सकता है और दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा जोखिमों को कम किया जा सकता है। जबकि इस तरह की रणनीति से जलवायु परिवर्तन शमन के स्पष्ट लाभ हैं, कोई भी इस रणनीति द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुकूलन लाभों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। किसानों की फसल की बर्बादी को कम करने और एक एकीकृत कृषि प्रणाली के माध्यम से कई आय धाराओं की खेती करने के लिए सशक्त बनाना, अधिकांश विकासशील देशों के भीतर एक तनावग्रस्त क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण रोजगार जनरेटर बनाने में मदद करेगा।

13.56. मांस की उत्पादकता किस तरह की जाती है, इसका खाद्य सुरक्षा और हमारे पर्यावरण से जुड़े जोखिमों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, यह मान लेना काल्पनिक है कि दुनिया मांस की खपत को पूरी तरह से छोड़ देगी और पूरी तरह से शाकाहारी भोजन अपना लेगी, इस काल्पनिक परिदृश्य में, ऐसा करने से कृषि के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 4.1 बिलियन हेक्टेयर से घटकर 1 बिलियन हेक्टेयर (उत्तरी अमेरिका और ब्राजील के बराबर क्षेत्र)[61] रह जाएगी। इस काल्पनिक परिदृश्य का उद्देश्य यह सोचना नहीं है कि मांस खाना चाहिए या नहीं, बल्कि यह प्रदर्शित करना है कि आबादी को खिलाने के लिए कई और अधिक कुशल तरीके उपलब्ध हैं।

13.57. वर्ष 2050 तक अपेक्षित 10 बिलियन लोगों को खिलाना कोई मामूली बात नहीं है। मांस उत्पादन प्रक्रियाओं में बिना किसी देरी के बदलाव लाने की जरूरत है, और विकासशील दुनिया को न केवल पश्चिम की पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी अस्थिर प्रथाओं का अनुकरण करने से बचना चाहिए, बल्कि पश्चि की ओर भी इशारा करना चाहिए, जहां सदियों से खाद्य-आहार संतुलन का अभ्यास किया जाता रहा है।

13.58. फिर से दोहराते हुए, बेहतर खाद्य-आहार संतुलन के लिए वर्तमान में खाद्य उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के केवल एक अंश की आवश्यकता होगी। पूरी दुनिया को अभी भी अच्छी तरह से खिलाया जा सकता है और अक्षय ऊर्जा उत्पादन जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए अधिक भूमि छोड़ी जा सकती है। इसके बजाय, हम जिस खतरे या संभावना का सामना कर रहे हैं, वह यह है कि मवेशी पालन की पश्चिमी प्रथाएँ दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल जाएँगी, ठीक वैसे ही जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पश्चिमी जुनून और इसे वास्तव में बुद्धिमान बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में डेटा खपत बहुत अधिक ऊर्जा और पानी की खपत कर रहा है और कई देशों में ऊर्जा उत्पादन योजनाओं को उलट रहा है। विकासशील देश लाइन में पीछे रह रहे हैं, ताकि वे सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों की परवाह किए बिना तकनीकी प्रतिस्पर्धा की काल्पनिक दौड़ में पीछे न रह जाएँ। इससे अधिक अजीब पैरालेल नहीं हो सकती।

आवास

13.59. जैसे-जैसे देश आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उनमें से एक बदलाव समाज के सामाजिक ताने-बाने में भी देखने को मिल रहा है, जो आज की दुनिया में पश्चिमी जीवनशैली का मॉडल है, यानी एकल परिवार और एकल व्यक्ति वाले घर। आज

59 शनमुगम, पी.एम., संगीता, एस.पी., प्रभु, पी.सी., वर्षिणी, एस.वी., रेणुकादेवी, ए., रविशंकर, एन., ... और गोपी, एम. (2024)। फसल-पशुधन-एकीकृत कृषि प्रणाली: कृषि उत्पादन, पोषण सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच तालमेल हासिल करने की रणनीति। सतत खाद्य प्रणालियों में सीमाएँ, 8, 1338299।

60 एरिक, ओ.ओ., म्लिंगी, एफ.टी., न्योनजे, बी.एम., चारो-करिसा, एच., और मुंगुटी, जे.एम. (2013)। क्या एकीकृत पशुधन-मछली संस्कृति पूर्वी अफ्रीका की खाद्य असुरक्षा का समाधान हो सकती है? एक समीक्षा। अफ्रीकन जे. फूड, एग्रीकल्चर न्यूट्र. डेव. 13, 8058–8076। कवप: 10.18697/ रंदिक.59.12920

61 हन्ना रिची (2021) - 'अगर दुनिया ने पौधे आधारित आहार को अपनाया, तो हम वैश्विक कृषि भूमि उपयोग को 4 बिलियन हेक्टेयर से घटाकर 1 बिलियन हेक्टेयर कर देंगे' OurWorldInData.org पर ऑनलाइन प्रकाशित। से लिया गया: (https://ourworldindata.org/land-use-diets)।

अनुमान है[62] कि भारत में लगभग 50% घर एकल (1-4 सदस्य)[63] हैं, जो 2008 आंकड़े से 38 प्रतिशत ज्यादा है। औसतन, भारत में एक सामान्य एकल परिवार में औसतन 3 सदस्य होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में 7 सदस्य होते हैं - उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में एकल परिवार में वृद्धि हो रही है। यह हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के साथ एक ही छत के नीचे रहने वाले बहु-पीढ़ी वाले जीवन के हमारे पुराने सामाजिक मानदंडों से एक बड़ा बदलाव है। भारत के श्रम बाजारों के बारे में इस सर्वेक्षण के अध्याय 8 में बताया गया है, कि यूनाईटेड नेशन पोपुलेशन फंड और अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान की एक रिपोर्ट में बहु-पीढ़ी वाले घरों में रहने वाले बुजुर्ग लोगों के महत्व पर जोर दिया गया है। भारतीयों को वास्तव में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से यह सीखने की जरूरत नहीं थी। यह हमारी परंपरा का हिस्सा था। स्वाभाविक रूप से केन्द्रित जीवन शैली के कारण अतिरिक्त आवास इकाइयों की मांग बढ़ रही है, जो छोटी और अधिक स्वतंत्र प्रकृति की होंगी। यह देखते हुए कि 2050 तक[64] मांग दोगुनी होने की उम्मीद है, तथा शहरी क्षेत्रों के आकार के कारण जटिलताएं बहुत अधिक हो सकती हैं, जिनकी जनसंख्या 15 मिलियन से लेकर कुछ हजार तक है, साथ ही स्थानीय बनाम नई बस्तियां, तथा आवास निर्माण की भिन्न-भिन्न प्रथाएं भी हैं, अतः भारत के सामने आवास की समस्या गंभीर हो सकती है।

13.60. दूसरी ओर, भूमि सीमित है, लेकिन आकांक्षाएँ ऐसी नहीं हैं। कई उच्च आय वाले शहरी केंद्रीकृत बस्तियाँ शहरी फैलाव की प्रवृत्ति को जन्म देती हैं, जो उच्च ऊर्जा खपत, उच्च प्रदूषण स्तर और बढ़ती यातायात भीड़ से जुड़ी होती है, जिससे महत्वपूर्ण नकारात्मक पर्यावरणीय बाहरी[65] प्रभाव पड़ते हैं। दुनिया भर में परिवार के आकार और स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव के बीच संबंध को पहचाना जा रहा है। 2021[66] के एक शोध पत्र में कहा गया है कि पिछले कुछ दशकों में चीन में औसत घरेलू आकार में कमी से स्केल अर्थव्यवस्थाओं का नुकसान हो रहा है।[67] पत्र में आगे कहा गया है, 'छोटे परिवार के आकार के साथ CO_2 उत्सर्जन, जल निकासी, धुआं-राख उत्सर्जन, SO_2 उत्सर्जन, NO_2 उत्सर्जन और औद्योगिक अपशिष्ट जल निर्गमन में वृद्धि पाई गई। उदाहरण के लिए, 2030-2035 तक 0.5 (2.5 सदस्यों तक) की घरेलू आकार में कमी से 2015 के स्तर की तुलना में CO_2 उत्सर्जन में 0.5% की वृद्धि और जल निकासी में 0.3% की वृद्धि हो सकती है। CO_2 उत्सर्जन में वृद्धि पुर्तगाल के पूरे उत्सर्जन के लगभग बराबर है।

13.61. इसके बावजूद, आज हमारे रहने के आवास जीवन के सार्वभौमिक मॉडल की नकल करते हैं - जिसमें कंक्रीट, बंद स्थान, कम वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि पुराने समय में कई पीढ़ियों वाले परिवार के घर हुआ करते थे, एवं पारंपरिक भारतीय तरीके से रहने की जगहें कहीं ज्यादा टिकाऊ तरीके से बनाई गई थीं – बीच में एक आँगन जो हवा, प्राकृतिक रोशनी और ठंडक के लिए जगह देता था, और ज्यादा सह-निवास, स्थानीय निर्माण सामग्री का उपयोग होता था जो लंबी दूरी तक कंक्रीट की उच्च मात्रा को ले जाने की जरूरत को रोकता था, निर्माण पद्धतियाँ जिससे कि अत्यधिक मशीनीकृत वातावरण की आवश्यकता नहीं होती थीं और स्थानीय श्रम की कमी को पूरा करती थीं। दुर्भाग्य से, इनमें से ज्यादातर को 'सस्टेनेबल प्रैक्टिस' के रूप में दर्ज नहीं किया गया है।

13.62 दुनिया संधारणीय आवास को ऐसे आवास के रूप में जानती है जिसकी विशेषता सौर और पवन ऊर्जा है, विशेष रूप से निर्मित कम ऊर्जा वाली विंडो और एलईडी का उपयोग करना है। दुर्भाग्य से, संधारणीयता के उपाय के रूप में केवल इन मानदंडों को रखना दो कारणों से गलत सकारात्मक है - 1) इसके लिए पूरे भवन और निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की पुनः इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है जो संसाधन-विवश वातावरण में कठिन है 2) पारंपरिक भवनों के साथ उच्च घनत्व, गैर-केंद्रित जीवन की जीवन-चक्र लागत के स्थान पर छोटे उपायों के प्रभाव की अधिक गणना की जाती है।

13.63 भारतीय जीवनशैली में अधिकाधिक परिवर्तन के कारण, एक बड़ी आबादी की इन गतिविधियों का पर्यावरणीय प्रभाव जलवायु परिवर्तन की समस्या को और अधिक गंभीर बना देगा।

---

62 कैंटर वर्ल्डवाइड के आंकड़ों के अनुसार 2022 में।

63 जनगणना 2011 के अनुसार 24.88 करोड़ परिवारों में से 12.98 करोड़ एकल परिवार है।

64 विश्व बैंक लेख (https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview)

65 शहरी क्षेत्रों का तेजी से भौगोलिक विस्तार, कम घनत्व वाले आवासीय विकास, एकल-उपयोग जोनिंग और ऑटोमोबाइल पर बढ़ती निर्भरता की विशेषता है।

66 शहरी पदचिह्न का विस्तार आवास विनाश और प्राकृतिक क्षेत्रों के विखंडन की ओर ले जाता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र पर बाहरी लागत आती है।

67 वू, डब्ल्यू., कनामोरी, वाई., झांग, आर., झोउ, क्यू., ताकाहाशी, के., और मसुई, टी. (2021)। चीन में बिजली की खपत और स्थिरता पर घरेलू अर्थव्यवस्थाओं के पैमाने में गिरावट के निहितार्थ। पारिस्थितिक अर्थशास्त्र, 184, 106981

भारतीय पद्धतिः एक संधारणीय जीवनशैली

"माता भूमिः पुत्राहं पृथिव्याः'' [68] ***(पृथ्वी सूक्त, श्लोक 12)***

13.64. जब-जब कोई बड़ी विपत्ति दुनिया को अस्थिर करती है, तब-तब भारतीयों की सापेक्षिक लचीलापन दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय होता है।[69] स्वाभाविक लचीलापन इस भूमि की सृजन और विनाश के चक्रों की अवधारणा की गहरी, आध्यात्मिक और दार्शनिक समझ से निकलती है।

13.65. यह कहीं और नहीं बल्कि 'प्रकृति' के साथ हमारे संबंधों में सबसे अधिक परिलक्षित होता है, जिसमें न केवल जबरदस्त शक्ति है, और इसका अपना मन और स्वभाव भी है। हमें इसके क्रम के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रकृति मनुष्य की कल्पित रणनीतियों के लिए अपने नियमों को बदलने वाली नहीं है। इसलिए, वैश्विक पर्यावरण और संधारणीयता रणनीति प्रकृति के चक्रीय स्वभाव के अनुसार होनी चाहिए, न कि इस गलत धारणा के अनुसार कि हमारी औद्योगिक गतिविधि इसके ताने-बाने को भी बदल सकती है । यहीं पर भारत मदद कर सकता है।

13.66. यद्यपि जलवायु परिवर्तन के प्रति पारंपरिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वागत योग्य है, लेकिन अब समय आ गया है कि भारत भी स्थिरतापूर्ण जीवन जीने के अपने ज्ञान को अपनाए और उसका प्रसार करे। जबकि भारत शीर्ष स्तर पर नीतिगत परिवर्तनों की आवश्यकता से सहमत है, हम छोटे-छोटे व्यक्तिगत कार्यों की सामूहिक शक्ति में भी विश्वास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उत्सर्जन सृजन के साथ-साथ उत्सर्जन में कमी लाने में भी योगदान देता है, यह एक साधारण तथ्य है जिसे हमें नीतियां बनाते समय, जागरूकता कार्यक्रम बनाते समय, या यहां तक कि पर्यावरण से संबंधित आंकड़े तैयार करते समय भी ध्यान में रखना चाहिए।

13.67. शुक्ल यजुर्वेद (36-17) में ऋषियों ने श्लोक दिया है :

"पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः ।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि
शांतिः शांतिः शांतिः

पृथ्वी, जल, पौधे, वृक्ष और देवताओं में शांति और संतुलन हो। आप में, अंतरिक्ष में और हर चीज में संतुलन हो।

मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली)

13.68. यह विचार प्रक्रिया मिशन लाइफ[70] के आधार पर थी, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (यूएनएफसीसी सीओपी 2026) में की थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक जलवायु के कथानक में व्यक्तिगत जिम्मेदारी को सबसे आगे लाना है। यह प्राचीन भारतीय दर्शन से अपना दर्शन प्राप्त करता है जो कि प्रकृति के अनुरूप स्वाभाविक रूप से संधारणीय जीवनशैली का समर्थन करता है, और व्यक्तिगत कार्यों और सामूहिक मांग को प्लैनेट-हितैषी विकल्पों की ओर ले जाता है। इसमें व्यक्तियों द्वारा अधिक संधारणीय रूप से जीवन जीने के लिए अपनाए जाने वाले 75 लाईफ कार्यों की एक व्यापक, किंतु, गैर-संपूर्ण सूची शामिल है।

68 (ऋग्वेद, 1/90/6,7,8) पर्यावरण को आनंदित करने और उसकी रक्षा करने के लिए दैवीय हस्तक्षेप का आह्वान करता है। "मधु वाताः ऋतयते मधु क्षरंति सिन्धवः माद्विः नः सन्तुषादि। मधु नक्तमुतुसासु मधुमात्पार्थिव राजाः मधु क्षोरस्तु सूर्यः मधिर्गबो भवन्तु नः'' (पर्यावरण लोगों को उनके जीवन को पूर्ण रूप से जीने के लिए आनंद प्रदान करता है। नदियाँ हमें पवित्र जल से आनंदित करती हैं और हमें स्वास्थ्य, रात्रि, सुबह, वनस्पति प्रदान करती हैं। सूर्य हमें शांतिपूर्ण जीवन से आनंदित करता है। हमारी गायें हमें दूध प्रदान करती हैं)।

69 The Subprime Crisis (https://tinyurl.com/5hdy2s82), The Covid-19 Pandemic (https://tinyurl.com/yzx5nw72)

70 मिशन 7 विषयों और ऊर्जा और पानी की बचत पर केंद्रित है, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और ई-अपशिष्ट को कम करना, स्थायी खाद्य प्रणालियों को अपनाना, अपशिष्ट को कम करना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना।

चार्ट XIII.10: लाईफ थीम्स

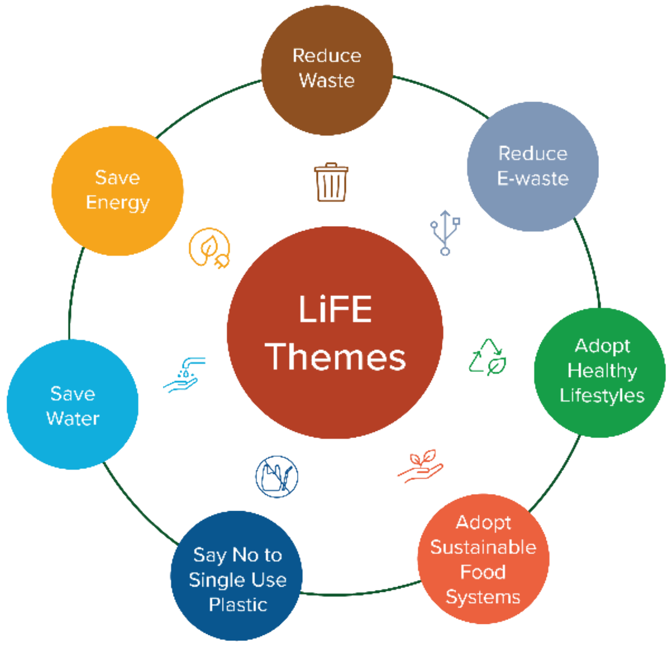

13.69. इस दर्शन को आगे बढ़ाते हुए, लाईफ को विश्व के लिए एक सिद्धांत बनाना चाहिए, जो 5 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित हो।

व्यक्तिगत कार्य जलवायु उत्तरदायित्व का मूल है

13.70. जैसा कि पिछले अनुभागों में वर्णित है, दुनिया की आबादी द्वारा जलवायु और पर्यावरण के प्रति अपना दृष्टिकोण बदले बिना कोई भी आर्थिक या औद्योगिक रणनीति सफल नहीं होने वाली है। इसलिए, गरीब देशों को अपनी विकास यात्रा बदलने के लिए मजबूर करने से पहले, व्यक्तियों के लिए, विशेष रूप से विकसित दुनिया में, सरल व्यवहार परिवर्तनों के पक्ष में अपनी जीवनशैली को बदलना आवश्यक है, जो सभी सीधे तौर पर शमन प्रयासों में योगदान करते हैं।

13.71. व्यक्तिगत नेतृत्व वाले संधारणीय व्यवहारों में भारत के पास बहुत अच्छा अनुभव है – रसोई की सफाई के लिए टिशू पेपर के बजाय कपड़े का उपयोग करना, डिस्पोजेबल प्लेटों और पैकेजिंग सामग्री के बजाय पत्तियों का उपयोग करना, पानी आधारित शौचालय सफाई प्रणाली, घरेलू वस्तुओं का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण, और यहां तक कि कीट नियंत्रण के प्राचीन घरेलू उपचार जो मारने के बजाय मार्ग विचलन पर केंद्रित हैं। एक ऐसी जीवनशैली को अपनाना जिसमें हम 'फास्ट फैशन' में कम लिप्त हों, असुविधा होने की स्थिति में उन चीजों को फेंकने के बजाय उनकी मरम्मत करवाना बेहतर है, कमरे/क्षेत्र का उपयोग न करने पर लाइट बंद कर दें, आदि, तथा बिलों को कागजी बिलों के बजाय ई-बिल के रूप में स्वीकार करने के रूप में डिजिटल चेतना, ऊर्जा-कुशल उत्पादों की खरीद के माध्यम से बिजली की बचत, उपयोग में न होने पर स्विच ऑफ करना, क्लीनटेक उत्पादों को अपनाना, वर्चुअल मीटिंग लेकिन आउटडोर रन जैसी शारीरिक गतिविधियाँ, सोलर वॉटर हीटर का उपयोग शामिल है। हमें यह भी सिखाया नहीं जाता है, और इसे आत्मसात किया जाता है, सीखा जाता है, और आने वाली पीढ़ियों को यही सीख दिया जाता है। दुर्भाग्यवश, यह बाजार समाजों से प्राप्त पूंजीवादी प्रथाओं के पक्ष में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि दुर्भाग्य से उन्हें ऊपर की ओर पलायन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।

13.72 इसके मूल में, अत्यधिक खपत, बीफ खाने और तेज फैशन से प्रेरित वैश्विक जीवनशैली के बारे में कुछ भी बदलाव किए बिना गरीब देशों की स्थिरता के बारे में बात करना दोहरावपूर्ण प्रतीत होता है। व्यक्तियों को स्वेच्छा से इन ऊर्जा पापों को त्यागने और अपने कार्यों को उनके बताए गए उद्देश्य के अनुरूप लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मांग में होने वाले बदलाव से संबंधित उद्योगों द्वारा आपूर्ति में स्वतः बदलाव आएगा।

13.73. स्वैच्छिक त्याग करना भारत में कोई नई बात नहीं है। ऐतिहासिक आश्रम-आधारित[71] संस्कृति में, जहाँ गृहस्थ लोग समाज और ईश्वर की भक्ति की ओर बढ़ने के लिए अपनी भौतिक इच्छाओं को स्वेच्छा से त्याग कर देते हैं, इन सिद्धांतों का उपयोग वर्तमान समय में भी समुदाय के अधिक कल्याण के लिए किया जाता रहा है। 'गिव इट अप' एलपीजी सब्सिडी योजना शायद बड़े पैमाने पर व्यवहार में इस सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण है। वर्ष 2015 में शुरू किए गए 'रुगिव इट अप' अभियान का उद्देश्य 5.7 मिलियन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) उपयोगकर्ताओं को प्रेरित करना था, जो एलपीजी के लिए बाजार मूल्य का भुगतान करने में सक्षम थे, ताकि वे स्वेच्छा से अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ दें, ताकि उन ग्रामीण महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर खरीदने में मदद मिल सके, जो खाना पकाने के लिए जलावन की लकड़ी पर निर्भर थीं। खुली आग पर और अकुशल लकड़ी जलाने वाले चूल्हों पर खाना पकाने से वैश्विक ब्लैक कार्बन उत्सर्जन का लगभग 25% उत्सर्जन होता है। उच्च उद्देश्य के लिए इस शानदार व्यक्तिगत त्याग ने न केवल महिलाओं में बीमारियाँ कम कीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन पर भी सीधा प्रभाव डाला।

13.74. स्वैच्छिक रूप से वृक्षारोपण करना तथा आस-पास के वातावरण को साफ-सुथरा और न्यूनतम रखना पर्यावरण पर सीधे प्रभाव डालता है। पत्तल और बांस की बोतलों जैसे स्थानीय रूप से प्राप्त प्रकृति-आधारित कारीगर विकल्पों का उपयोग, अत्यधिक प्लास्टिक के उपयोग से बचना और, स्थिरता के पक्ष में सचेत विकल्प बनाने से पर्यावरणीय दृष्टिकोण से प्रतिकूल चीजों की बड़े पैमाने पर हो रही मांग पर अंकुश लगाने में काफी मदद मिलेगी।

13.75. एक ऐसा क्षेत्र जहां व्यक्तिगत कार्रवाई सबसे अधिक वांछित है और जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, वह है पानी का पुन: उपयोग, कम बर्बादी और जल संरक्षण। पानी न केवल जीवन का अमृत है, बल्कि अस्तित्व के मामले में भी यह अपरिहार्य है। मंगल ग्रह के बारे में सबसे बड़ी खबर यह थी कि उस ग्रह[72] पर पानी की संभावना है इतना इसका महत्व है। इसलिए, जब सरकारें पानी की आपूर्ति बढ़ाने, दक्षता लाने और गैर-पेय जल को अन्य उपयोगों में पुनर्निर्देशित करने के लिए कदम उठा रही हैं, तो व्यक्तियों का यह कर्तव्य बनता है कि वे इस अत्यंत मूल्यवान संसाधन की बर्बादी को काफी हद तक कम करें। पौधों को पानी देने के लिए रसोई के पानी को इकट्ठा करना, नलों को हमेशा खुला न छोड़ना और वर्षा जल का उपयोग करने के लिए वर्षा जल संचयन का उपयोग करना जैसे छोटे-छोटे कार्य जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में संभव और वांछनीय दोनों हैं।

व्यक्तिगत ग्रह समर्थक विकल्पों को दर्शानेवाली सामूहिक नीति

13.76. संगतता । संयोजन । दो शब्द जब व्यवहार में लाए जाते हैं तो ये साम्राज्य को बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। छोटे लेकिन लगातार किए गए कार्यों का समय के साथ एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। जापानियों के पास इसके लिए एक शब्द भी है - 'काइजेन'। जैसा कि ऊपर वर्णित है, दैनिक आधार पर व्यक्तिगत विकल्प स्थिरता में मदद कर सकते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ग्रह समर्थक में छोटे-छोटे रोजमर्रा के विकल्प चुनने की सामूहिक नीति है, लेकिन सरकार द्वारा प्रेरित और अनिवार्य है। ये निम्नलिखित कई कार्रवाइयों में परिलक्षित होते हैं:

(क) **अधिक इष्टतम और टिकाऊ तापमान पर एयर कंडीशनिंग और थर्मोस्टेट का उपयोग करना:**[73] जैसा कि भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने बताया, तापमान को कृत्रिम रूप से 17-18 डिग्री तक कम रखने और फिर कंबल का उपयोग करने में कोई समझदारी नहीं है। मॉल, कार्यालयों और हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर एसी और तापमान की डिफॉल्ट सेटिंग्स को 18 से 24-25 डिग्री तक बढ़ाया जा सकता है। लोकप्रिय रूप से इसे 'एयर कंडीशनिंग विरोधाभास[74]' कहा जाता है, जैसा कि इस लेख[75] में अच्छी तरह से वर्णन किया गया है, यह कैच-22 की स्थिति है 'जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जैसे-जैसे ग्रह गर्म होता जाएगा, लोगों को ठंडा रहने के लिए जिस तकनीक की आवश्यकता

---

71 व्यक्ति के जीवन में चार आश्रम या चरण (प्रत्येक 25 वर्ष) – बालावस्था (बचपन और शिक्षा), गृहस्थ (भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु गृहस्थ जीवन), वानप्रस्थ (समाज को वापस देना), संन्यास (त्याग और ईश्वर के साथ एकता)

72 नासा से लिया गया (https:/www.nasa/gov/news/release/nasa-confirms-evidence-that-liquid-water-flows-on-todays-mars/)।

73 लगातार एसी के इस्तेमाल से शहर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।

74 एयर कंडीशनिंग विरोधाभास, वॉक्स, मई 2022)। (https://www.vox.com/science-and-health/23067049/heat-wave-air-conditioning-cooling-india-climate-change)।

75 एयर कंडीशनर को ग्रह को गर्म करने से कैसे रोकें, साइंटिफिक अमेरिकन, जून 2021 (https://www.scientificamerican.com/article/how-to-prevent-air-conditioners-from-heating-the-planet/)।

होगी, वह जलवायु को और अधिक गर्म कर देगी।' छोटी जगहों पर बड़ी आबादी के सिमटने के कारण, भारत व्यक्तिगत एयर कंडीशनिंग मार्ग पर जाने का जोखिम नहीं उठा सकता, जहां हर छोटे कमरे में एक एसी होता है और आसपास की हवा को इतना खराब कर देता है कि उन्हें दूसरे की आवश्यकता होती है, इस प्रकार एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। 15 वर्ष पहले भी, भारत में अधिकांश घरों में एसी तक पहुंच नहीं थी और इसके बजाय वे तरीकों के संयोजन पर निर्भर थे - पानी के लिए वाटर कूलर और मिट्टी के बर्तनों के रुक-रुक कर उपयोग के साथ खस ठंडा करना। किसी भी समस्या के समाधान के लिए पूंजीवादी दृष्टिकोण के लिए बड़े पैमाने पर विनिर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे आधुनिक एयर-कंडीशनर का आगमन होता है, जिससे समस्या और भी बदतर हो गई है। भारत को आधुनिक एयर कंडीशनर और हमारे पारंपरिक तंत्र - हवादार निर्माण, बड़ी खिड़कियां, स्थानीय सामग्रियों का उपयोग, जल-आधारित शीतलन प्रणाली और जहां भी संभव हो, पंखे का उपयोग लाने के लिए मतदान करना चाहिए।

(ख) **बार-बार डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग ले जाने की आवश्यकता को कम करना, खपत को कम करके और उन्हें पुनः** उपयोग करने योग्य कपड़े के बैग से बदलना। हर मिनट 1 मिलियन से अधिक बैग इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका औसत कार्य जीवन 15 मिनट होता है, लेकिन जब तक उन्हें रीसाइकिल नहीं किया जाता, वे हमेशा के लिए पृथ्वी की सतह पर रहते हैं।

(ग) **व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव और वर्षा जल संचयन जैसी संरचनाओं के पक्ष में अनिवार्य डिजाइन विनिर्देशों के माध्यम से पानी के पुनः** उपयोग की संस्कृति का निर्माण करना। पानी कम होता जा रहा है। दुनिया के कुछ क्षेत्रों में ताजे पानी की पहुँच लगभग नहीं है। सरकारों को जल-कुशल प्रौद्योगिकियों को अनिवार्य बनाना चाहिए और जल-बर्बाद करने वाली प्रौद्योगिकियों (जैसे, रिवर्स ऑस्मोसिस वॉटर मशीन, सिंगल फ्लश टॉयलेट) की फिर से जाँच करनी चाहिए।

(घ) **स्थानीय बीजों और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का उपयोग करके संधारणीय कृषि का अभ्यास करना।** कृषि अवशेषों का उपयोग मल्चिंग और खाद बनाने के लिए किया जाना चाहिए।

(ङ) **एकल या दो-व्यक्ति वाले परिवारों के बजाय बड़े परिवारों के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन,** अप्रत्यक्ष रूप से समाज को संधारणीय विकल्पों का पक्ष लेने के लिए प्रेरित करते हैं।

13.77. बढ़ी हुई मांग स्थानीय कुशल कामगारों द्वारा बनाए गए टिकाऊ, पारंपरिक उत्पादों के लिए बाजार को फिर से सक्रिय करेगी और उन्हें बनाने के लिए दुनिया भर के उद्योगों की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, हाथीदांत, चमड़े और लुप्तप्राय प्रजातियों से बने उत्पादों को व्यक्तिगत रूप से हतोत्साहित किया जाना चाहिए और नीति-प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अपशिष्ट उत्पादों के परिपत्र और पुनः उपयोग को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका एक अच्छा उदाहरण पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण के लिए सरकार का आदेश होगा, जो 2022 में 10 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करेगा।

13.78. एक अन्य क्षेत्र जहां व्यक्तिगत पसंद और सरकारी कार्रवाई को एक साथ आना चाहिए, वह है फैशन एंड टेक्सटाइल्स। यूएनईपी के अनुसार, फैशन उद्योग पानी का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के 2-8%, कीटनाशकों के 24% और कीटनाशकों के 11% के लिए जिम्मेदार है। कपड़ों के स्वैच्छिक पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के अलावा, भारत में वस्त्रों में परिपत्रता पर नीति की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में भारत में 50% से कम कपड़ा अपशिष्ट किसी भी तरह के पुनः उपयोग, मरम्मत या पुनः निर्माण होता है।

चार्ट XIII.11: प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 2025

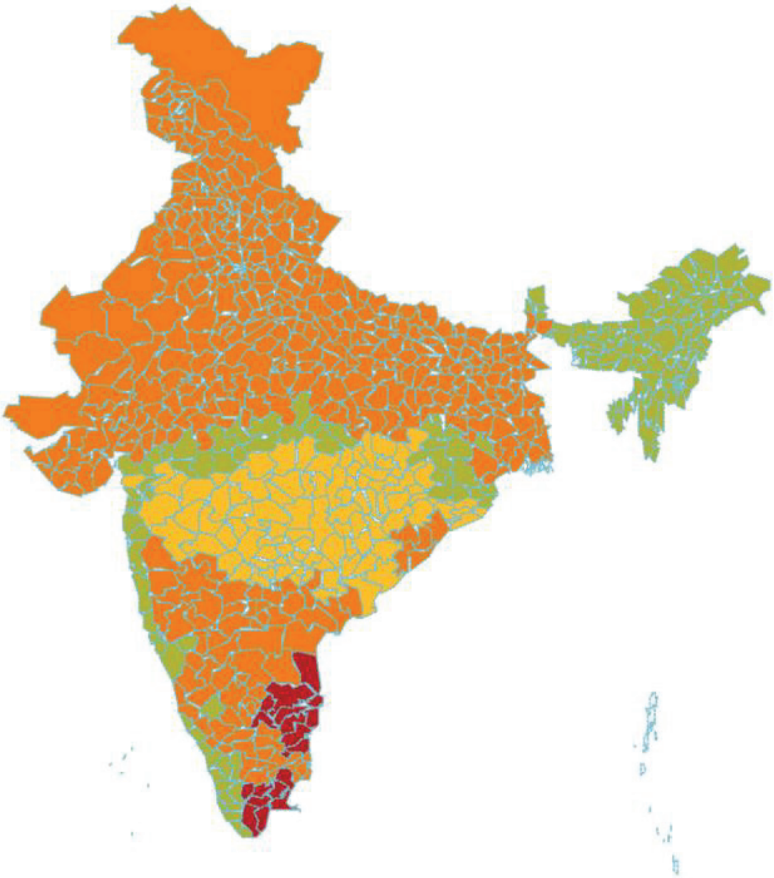

स्रोत: भारत जलवायु एवं ऊर्जा डैशबोर्ड, नीति आयोग

स्थानीय और संधारणीय भूगोल और संस्कृति का समावेश

13.79. 'अन्नं ब्रह्म' या भोजन ही ईश्वर है। प्राचीन भारत ने इसे शास्त्रों में लिखा और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए विचार करने हेतु छोड़ दिया। हालाँकि, हर उस चीज के बेहतर होने की होड़ में जो 'हमारे लिए नहीं' है, स्थानीय भोजन की जगह पैकेज्ड फास्ट-फूड और हमारे अस्तित्व के भूगोल से अलग खाद्य विकल्पों ने ले ली। आज भी, भारतीय व्यंजन मुख्य रूप से पौधों पर आधारित हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई शाकाहारी है; इसका मतलब है कि हमारे भोजन का बड़ा हिस्सा शाकाहारी ही रहता है - चावल, दाल, रोटी और मांस एक अलग व्यंजन है। हमारे पैकेज्ड फूड जैसे चिप्स में भी यही बात लागू होती है जो लगभग 99.99% पौधों पर आधारित होते हैं, क्योंकि इतने बड़े देश में लोग बहुत तरह का खाना खाते हैं। अधिकांश व्यंजन स्थानीय भूगोल पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं जो न केवल भोजन को औषधीय मूल्य प्रदान करता है बल्कि पारिस्थितिकी पदचिह्न को भी कम करता है और ऊर्जा की जरूरतों को भी कम करता है। यह उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए शाकाहार के वैश्विक अभ्यास के विपरीत है, जहां अधिक टिकाऊ भोजन खाने के लिए, दुनिया के आधे हिस्से से उड़ने वाले एवोकाडो या सोया दूध पर निर्भर रहना पड़ता है, जो पहले अमेजन वर्षावन क्षरण का कारण बन चुका है।[76]

13.80. अच्छा स्वास्थ्य आर्थिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा योगदान देता है, क्योंकि अस्वस्थता की सभी घटनाएँ दोहरे आर्थिक नुकसान का कारण बनती हैं - उत्पादक समय में कमी और इससे ठीक होने में खर्च होने वाली लागत। जहाँ आधुनिक चिकित्सा ने रोगाणु-आधारित संक्रमण से उबरने और जैविक इंजीनियरिंग में बहुत बढ़िया काम किया है, वहीं भारत ने वर्षों से आयुर्वेद का अभ्यास किया है, जो प्रकृति के अनुसार अस्तित्व, उपचार के बजाय रोकथाम और नैदानिक पूरकों के बजाय प्राकृतिक उपचारों पर जोर देता है, जिनके दीर्घकालिक नुकसान की अस्पष्ट समझ है। ''गोली गटकने' की संस्कृति के स्थान पर अस्वस्थता के 'कारण'

76 ग्रीनपीस से प्राप्त (https://www.greenpeace.org/usa/victories/amazon-rainforest-deforestation-soy-moratorium-success/)

(जो किसी दुर्घटना/जन्मजात समस्या/विषाक्तता के कारण नहीं है) के बारे में अधिक जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए तथा यह भी जानना चाहिए कि हमारी स्थानीय खाद्य एवं औषधीय प्रणालियां इन बीमारियों को कम करने में क्या भूमिका निभाएं

13.81. अब समय आ गया है कि विश्व इस स्वर्णिम सिद्धांत को अपनाए - स्थानीय भोजन खाएं, ताजा भोजन खाएं, संधारणीय भोजन करें:

- अधिक से अधिक पादप-आधारित आहार लेना।
- स्टायरोफोम और एकल-उपयोग प्लास्टिक के बजाय पत्ती-आधारित डिस्पोजेबल प्लेटों का उपयोग।
- किण्वित उत्पादों का उपयोग (जैसा कि एशियाई संस्कृतियों में प्रमुख है) जो वांछित स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक सूर्य भंडारण का उपयोग करते हैं।
- खाद्य अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, या जैविक खाद खाद्य अपशिष्ट (पनीर के लिए खट्टा दूध और दाल के लिए मट्ठा पानी का पुन: उपयोग)।
- हमारे आसपास तुलसी और नीम जैसी औषधीय जड़ी-बूटियाँ उगाना।
- जल-स्तर को बचाने वाले पेड़ों का वनीकरण।
- मौसमी और स्थानीय भोजन - जैसे क्विनोआ की तुलना में अधिक बाजरा (मिलेट्स) खाना।
- प्राकृतिक किस्मों के उत्पादन और बीजों की कटाई को सार्वजनिक रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

'सही' निर्णय लेने में बाजार नहीं, बल्कि सार्वजनिक नीति सर्वोपरि है

13.82 यह दृष्टिकोण नीतिगत दृष्टिकोणों के माध्यम से व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने पर केंद्रित है। कोई व्यक्ति कैसे व्यवहार करते हैं और उपभोग करना चुनते हैं, यह आस-पास के मानदंडों, नीतियों, प्रोत्साहनों और अवसंरचना द्वारा आकार लेता है, और इसमें सरकारों, सामुदायिक नेताओं और मीडिया की भूमिका होती है।

13.83. ऊर्जा-दक्ष एलईडी लाइटों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2015 में शुरू किए गए उजाला कार्यक्रम के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष लगभग 48 बिलियन किलोवाट की ऊर्जा बचत हुई है और प्रति वर्ष 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित बचत हुई है। लोगों के लिए खरीद लागत को कम करके लोगों को इन एलईडी लाइटों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यह थोक खरीद और आपूर्ति के लिए सरकारी योजनाओं के माध्यम से ही संभव हुआ। बच्चों सहित व्यक्तिगत और सामूहिक जागरूकता प्रयासों का उपयोग करके, इस कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन लाया गया। इस प्रकार, लोगों के व्यवहार में जीवनशैली में बदलाव के दृष्टिकोण ने जलवायु शमन में सीधे तौर पर मदद की।

13.84. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मॉडलिंग के अनुसार, एलआईएफई (लाइफ) पहल द्वारा लक्षित दुनिया भर में की गई कार्रवाई और उपायों को अपनाने से वर्ष 2030 (2030 तक आवश्यक उत्सर्जन कटौती का 20%) में वार्षिक वैश्विक CO_2 उत्सर्जन में 2 बिलियन टन (जीटी) से अधिक की कमी आएगी और उपभोक्ता बचत में लगभग 440 बिलियन डॉलर की कमी आएगी। यह कोई मामूली बात नहीं है।

"... आपूर्ति पक्ष पर परिवर्तन पर्याप्त नहीं होगा; ग्रहीय सीमाओं के भीतर रहने के लिए मांग-पक्ष परिवर्तन भी आवश्यक होगा। वैश्विक आबादी को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकताओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन सबसे दक्ष उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के उपयोग के अलावा, इसका तात्पर्य उपभोग पैटर्न में आमूल-चूल परिवर्तन से है, जिसमें प्रतिस्पर्धी उपभोग दावों[77] के बीच प्राथमिकता तय करने की राजनीतिक प्रक्रियाएँ शामिल हैं।"

13.85. परिवर्तनकारी परियोजनाओं को शुरू करने में सार्वजनिक निवेश के महत्व पर जितना बल दिया जाए, उतना कम है। हमारे विश्व का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है - द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण, अंतरिक्ष की खोज, इंटरनेट (इसके प्रोटोटाइप चरणों के दौरान) का विकास, और साठ के दशक में यूएसए में राजमार्ग निर्माण परियोजना - सरकारी फंडिंग या सार्वजनिक प्राधिकरणों - घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय या बहुपक्षीय - द्वारा फंडिंग के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित और निष्पादित की गई थी। इसी तरह, आज कार्बन पृथक्करण, कार्बन सिंक, बैटरी भंडारण प्रौद्योगिकियों में सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है, और ग्रीन हाइड्रोजन बौद्धिक संपदा अधिकारों की समस्याओं को दूर करेगा और समाधानों की वैश्विक सार्वजनिक प्रकृति को पुष्ट करने में मदद करेगा।

77 एनर्जी डिलेमा, सेड्रिक डूरंड, नवंबर 2021 (https://tinyurl.com/2kekb8dm)

13.86. तथापि, सभी प्रासंगिक क्षेत्रों में मिशन लाइफ के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर इसे समायोजित किया जाना चाहिए, जिसकी शुरुआत विद्यालय से ही की जानी चाहिए, जैसा कि स्वच्छ भारत में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) अभियान के प्रति व्यवहार परिवर्तन के लिए किया गया था।

संसाधनों का विवेकपूर्ण उपभोग, आवश्यकता के आधार पर न कि लालच के आधार पर होना चाहिए

13.87. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी देश के मूल्य का मुख्य आकलन लगातार बढ़ती जीडीपी से आता है, जो मुख्य रूप से पूंजीवादी दुनिया में खपत से प्रेरित है। डेरेक ब्रॉवर, अमांडा चू और माइल्स मैककॉर्मिक ने फाइनेंशियल टाइम्स (एफटी)[78] में कहा, कि ''पूंजीवाद ऊर्जा व्यवस्था परिवर्तन को तेजी से नहीं लाएगा। हाल के दशकों में सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी प्रगति और नवीकरणीय परिनियोजन के बावजूद, कुल वैश्विक ऊर्जा उपयोग में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 86% और 2023 में 82% थी''

13.88. इसलिए देशों को संधारणीय जीवनशैली को प्रोत्साहित करने पर ध्यान देना चाहिए – कम अपव्यय पर जोर देना चाहिए और जीवन को इस तरह से समायोजित करना चाहिए कि 'इच्छाएं' 'श्जरूरतेंश न बन जाएं। यही है अच्छी तरह से लेकिन सामंजस्यपूर्ण तरीके से जीवन जीना। भौतिकवाद की अधिकता से केवल नकारात्मक बाहरी प्रभाव ही होते हैं – अधिक अपव्यय, अधिक कूड़ा-कचरा, पृथ्वी की सतह पर अधिक टिकाऊ कचरा, कम खुशी – खुशी-स्वामित्व वक्र की घटती सीमांत उपयोगिता का नियम रोजमर्रा की जिंदगी में देखा जा सकता है। 30 से 70 वर्ष की आयु के बीच की अधिकांश पीढ़ी ने ऐसा जीवन देखा है जहाँ छोड़ना और परिहार्य करना अस्तित्व का हिस्सा नहीं थे। भौतिकता लंबे समय तक त्याग और दुर्लभ अधिग्रहण से जुड़ी थी जो खुशी की भावनाओं को बढ़ाती थी।

13.89 यह जीवन को समझने के हमारे तरीके से एक दार्शनिक बदलाव है। अनुसंधान[79] के एक बड़े समूह ने श्विकल्प के विरोध ाभासश के सिद्धांत को सामने लाया है जो पूंजीवाद के विचारों के विपरीत है। भले ही चुनाव हमारे लिए अच्छा है, लेकिन संतुष्टि के साथ इसका संबंध काफी जटिल है, और विकल्प[80] का अतिभार नकारात्मक परिणामों के एक बड़े समूह की ओर ले जाता है। इसमें अनिर्णय से लेकर भ्रम, जटिलता और असंतोष तक शामिल हैं। डोरियन ग्रे की तस्वीर में, ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं ष्आजकल, लोग हर चीज की कीमत और किसी भी चीज का मूल्य नहीं जानते हैं।'

13.90. एलआईईएफ का अंतिम सिद्धांत हमें बिना खुद पर अत्यधिक उपभोग का बोझ डाले चीजों और अनुभवों के आंतरिक मूल्य का आनंद लेने के लिए प्रेरित करता है। यह तपस्वी जीवन जीने के बारे में नहीं है, बल्कि सचेत रूप से जीने के बारे में है। जब आप पानी की आधी बोतल छोड़कर दूसरी बोतल उठाते हैं, तो यह याद रखने का समय है कि यह प्लास्टिक न केवल हमसे ज्यादा समय तक जीवित रहेगा, बल्कि हमारे बच्चों और हमारे पोते-पोतियों से भी ज्यादा समय तक जीवित रहेगा, और शायद यह वह भविष्य नहीं है जिसे हम उन्हें देना चाहते हैं।

निष्कर्ष

13.91 इन सिद्धांतों को जीवन में जीवंत करने में सबसे महत्वपूर्ण मानवीय कारक आधुनिक जीवन में सबसे मायावी में से एक है – ठहराव या स्थिरता/संतुष्टि जो समभाव के साथ आती है। यह ठहराव नहीं है, यह स्थिरता नहीं है, और यह समझौता भी नहीं है। यह मनुष्य की क्षमता है कि वह आत्मविश्वास और आंतरिक स्थिरता को चुनने की शक्ति रखता है, ताकि बाहरी परिवर्तन के लिए वह तैयार हो सके और उसे स्वीकार कर सके। यह तभी संभव है जब मनुष्य इस ऊर्जा को दिशा दे सके, तभी वह और अधिक की मांग करना बंद कर सकता है। यह ऐसी संतुष्टि की कमी है जिसने घर में पहले की सामूहिक चीजों को व्यक्तिगत बना दिया है – जैसे, टेलीविजन। अनुपलब्ध चीजों के कारण बड़े लोग रोते नहीं थे और बच्चे दूसरों के साथ खेलने से कतराते नहीं थे। यह आज के उपभोग-उन्मुख जीवन के विपरीत है, जहाँ हर व्यक्ति एक उपभोक्ता है (विशेषकर बच्चे[81]), न कि एक परिवार। यही कारण है कि आज घरों में प्रति व्यक्ति पहले के एक टेलीविजन की तुलना में अधिक उपकरणों की आवश्यकता है। इस एक कथन में सामाजिक रीति-रिवाजों, अति उपभोग, निपटान और कचरे के बढ़ते पहाड़ों के बीच संपूर्ण संबंध निहित है।

78 ऊर्जा संक्रमण अस्थिर होगा, फाइनेंशियल टाइम्स, 25 जून 2024 को एक्सेस किया गया (https://tinyurl.com/52syuz7j)

79 मोर इजनॉट ऑलवेज बेटर, बैरी श्वार्ट्ज, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, जून 2006 (https://hbr.org/2006/06/more-isnt-always-better)

80 रुतस्काजा, ई., अयंगर, एस., फासोलो, बी., और मिसुराका, आर. (2020)। सूचना और विकल्प अधिभार के संज्ञानात्मक और भावात्मक परिणाम। रूटलेज हैंडबुक ऑफ बाउंडेड रेशनलिटी में (पृष्ठ 625-636)। रूटलेज।

81 संचार समिति; बच्चे, किशोर और विज्ञापन। बाल चिकित्सा दिसंबर 2006; 118 (6): 2563–2569। 10.1542/peds.2006-2698

आईएफसी के अनुसार, '*दुनिया में हर वर्ष 2 बिलियन टन से अधिक नगरपालिका ठोस कचरा उत्पन्न होता है, और 2050 तक इसमें 70% की वृद्धि होने की उम्मीद है।*'[82]

13.92. अधिक से अधिक उपभोग करने की भूख का मतलब है कि हम स्थिरता पर वैश्विक चर्चा में चूकते जा रहे हैं, क्योंकि हम समस्या की जड़ पर हमला करने के बजाय नवीकरणीय ऊर्जा के लिए मार्ग को फिर से जोड़ने का सुझाव देते रहते हैं। बढ़ती बीमारी को ठीक करने के लिए लक्षणों का उपचार करना है।

13.93. अब समय आ गया है कि समाजों का पुनर्निर्माण समभाव के साथ किया जाए।

13.94. आंतरिक समभाव दूसरों की अधिक स्वीकार्यता में योगदान देता है और इसलिए बेहतर मानवीय संबंधों में योगदान देता है, जिसे हम अब जानते हैं, यह बड़े, एकजुट परिवारों के लिए भी अधिक अनुकूल है, और परिणामस्वरूप बेहतर सामाजिक और संधारणीय प्रभाव डालता है। अधिक भौतिक विकल्पों और आर्थिक बेहतरी तक पहुँच हमें इतना असंतुलित नहीं कर सकती कि हम भूल जाएँ कि हम प्रकृति से आए हैं और हमें उसी में लौटना चाहिए। हमारे सचेत और अचेतन विकल्पों को पृथ्वी पर जीवन के चालकों से अलग नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक आंदोलन संप्रभु विकल्पों और आर्थिक जरूरतों के अनुकूल होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत व्यवहार – 'लाइफ' पर केंद्रित होना चाहिए।

****

82 विश्व में अपशिष्ट की समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, अप्रैल 2024 (https://www.ifc.org/en/blogs/2024/the-world-has-a-waste-problem)

आर्थिक कार्य विभाग
DEPARTMENT OF
ECONOMIC AFFAIRS

सत्यमेव जयते
Government of India